

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

भारत में उद्योगों का संगठन, वित्त व्यवस्था एवं प्रबन्ध

(ORGANISATION, FINANCE & MANAGEMENT OF
INDUSTRIES IN INDIA)

[भारतीय विश्वविद्यालयों के एम० कॉम० के विद्यार्थियों के लानार्थ
एक विस्तृत एवं आलोचनात्मक अध्ययन]

लेखक

डा० एस्० सी० सक्सेना,
एम० ए०, एम० कॉम०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०,
असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य विभाग,
महाराणी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कॉमर्स,
ग्वालियर (मध्य-प्रदेश)

प्रथम संस्करण

१९६२

आगरा

नवयुग साहित्य सदन,

उच्च कोटि के शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक

मूल्य : १२ रु० ५० न० प०

प्रकाशक—नवयुग साहित्य सदन, ३२७६, लोहामण्डी, आगम ।

मुद्रक —राजेन्द्रकुमार जैन, हिन्द प्रेस, ३२७६, लोहामण्डी, आगम ।

भूमिका

शरम्भिक—

‘भारत में उद्योगों का संगठन, वित्त व्यवस्था एवं प्रबन्ध’ शीर्षक पुस्तक को प्रस्तुत करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष एवं सन्तोष अनुभव होता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की उस माँग को पूरा करने का प्रयास है, जिसके विषय में वे बहुत दिनों से मुझसे पत्र-व्यवहार करते रहे हैं। उनकी यह उत्कृष्ट प्रमिलाया थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस विषय पर एक उच्च स्तरीय पुस्तक लिखी जाय। समयान्वाव के कारण मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों की शीघ्र सेवा न कर सका। कुछ समय मिलने पर अपनी अनेक पुस्तकों की बिलारी हुई सामग्री को एक शृङ्खला में पिरो कर नवीनतम तथ्यों सहित इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाणिज्य-साहित्य का एक बहुत बड़ा अभाव दूर हो जायेगा एवं विद्यार्थी-समुदाय इससे बहुत लाभान्वित होगा।

विशेष आकर्षण—

प्रस्तुत पुस्तक के कुछ उल्लेखनीय आकर्षण, जिनके आधार पर अन्य पुस्तकों की अपेक्षा इसे श्रेष्ठ बही जा सकता है, निम्नलिखित हैं :—

- (१) ‘विषय प्रवेश’ शीर्षक पहली पुस्तिका में औद्योगीकरण के अर्थ एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। इसके एकमात्र अध्ययन से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में औद्योगीकरण की महिमा का चित्र स्पष्ट हो जाता है। अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याओं एवं उनके हल का अध्ययन भी इसी पुस्तिका में किया गया है।
- (२) ‘भारत में उद्योगों का प्रादुर्भाव एवं विकास’ शीर्षक दूसरी पुस्तिका में भारतीय उद्योगों के जन्म की कहानी की चर्चा की गई है। इस पुस्तिका से भारत की प्राचीन आर्थिक समृद्धि का अभास मिलता है एवं यह भी ज्ञात होता है कि बाद में हमारे उद्योगों का क्योंकर पतन हुआ ? प्रथम एवं द्वितीय महायुद्धों तथा सन् १९४७ में होने वाले देश के अनाधिक विभाजन का भारत के उद्योग धन्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विस्तृत अध्ययन भी इस पुस्तिका में किया गया है। दासत्व की शृङ्खलाओं से छूटने के बाद स्वतन्त्रताकाल में हमारे उद्योग धन्यों ने आज तक - जो प्रगति की है, उसके भी दर्शन इस पुस्तिका में होते हैं।

- (३) 'आर्थिक नियोजन एवं भारतीय उद्योग' सम्बन्धी तृतीय पुस्तिका में प्रथम एवं द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश की औद्योगिक प्रगति का आभास मिलना है। इसके अतिरिक्त, इसमें तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित औद्योगिक प्रगति का भी चित्रण किया गया है।
- (४) 'भारत सरकार की औद्योगिक नीति' शीर्षक चौथी पुस्तिका में स्वतन्त्रता के पूर्व भारत सरकार की औद्योगिक नीति का संक्षिप्त परिचय देते हुये सन् १९४८ व सन् १९५६ की औद्योगिक नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, सन् १९५१ के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है।
- (५) 'भारत सरकार की प्रशुल्क नीति' सम्बन्धी पाँचवी पुस्तिका में भारत की वर्तमान प्राथुलिक एवं वारिण्यिक नीति का विश्लेषात्मक अध्ययन किया गया है। एक अध्याय में कसे के स्वरूप एवं उद्योगों पर उनके प्रभाव की भी चर्चा की गई है।
- (६) 'विवेकीकरण एवं औद्योगिक उत्पादकता आन्दोलन' सम्बन्धी छठी पुस्तिका में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि विवेकीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में अभी तक हम बहुत दौरे हैं एवं इसकी आवश्यकता पर बल देते हुये औद्योगिक उत्पादकता आन्दोलन का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है।
- (७) 'भारत में औद्योगिक संयोग' शीर्षक सातवी पुस्तिका में संयोग आन्दोलन की थोड़ी गति के कारणों एवं उसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।
- (८) 'श्रम समस्याएँ' सम्बन्धी आठवी पुस्तिका में अनेक महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं एवं उनके उपचारों का अध्ययन किया गया है।
- (९) 'औद्योगिक वित्त व्यवस्था' सम्बन्धी नवमी पुस्तिका में औद्योगिक संस्थाओं के लिये उपलब्ध पूँजी के विभिन्न साधनों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।
- (१०) 'उद्योगों का स्थानीयकरण' शीर्षक दसवी पुस्तिका में औद्योगिक स्थानीयकरण के विभिन्न घटकों एवं सिद्धान्तों के अध्ययन के उपर यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश में उद्योगों प्रादेशिक वितरण नितान्त आवश्यक है।
- (११) 'उद्योगों के परिमाण' से सम्बन्धित ग्यारहवी पुस्तिका में उद्योगों के परिमाण का अध्ययन किया गया है।

- (१२) 'भारत में उद्योगों का प्रबन्ध' शीर्षक १२वीं पुस्तिका में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का आलोचनात्मक विवरण दिया गया है तथा इसकी वर्तमान स्थिति एवं भविष्य पर भी प्रकाश डाला गया है ।
- (१३) 'राजकीय उद्योगों का प्रबन्ध' शीर्षक तेरहवीं पुस्तिका में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों व समितियों (जैसे गोरवाला, अप्पलबी, गालब्रेथ, इकेफी आदि) की रिपोर्टों के सन्दर्भ में राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था एवं प्रबन्ध का अध्ययन किया गया है ।
- (१४) 'आधुनिक उद्योगों के आधार' शीर्षक अगली पुस्तिका में देश के प्राकृतिक एवं मानवीय प्रसाधनों का विशद विवेचन दिया गया है ।
- (१५) 'भारत के कुटीर एवं लघु उद्योग' से सम्बन्धित पन्द्रहवीं पुस्तिका में कुटीर एवं लघु उद्योगों के गौरवमय अतीत, वर्तमान स्थिति, भविष्य आदि का अध्ययन किया गया है । कर्षे समिति की रिपोर्ट एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यों की भी इसमें चर्चा की गई है ।
- (१६) 'भारतीय संगठित उद्योग' शीर्षक सोलहवीं पुस्तिका में देश के प्रमुख संगठित उद्योगों का विश्लेषणात्मक अध्ययन दिया गया है ।
- (१७) प्रत्येक अध्याय के अन्त में कुछ प्रश्न दिये गये हैं, जिनका चुनाव भारतीय विश्वविद्यालयों के एम० कॉम० के प्रश्न-पत्रों से किया गया है ।

उपयोगिता का क्षेत्र—

यद्यपि यह पुस्तक मुख्यतः एम० कॉम० के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है, किन्तु मेरा विश्वास है कि उद्योगपति, व्यापारी एवं सामान्य जनता भी इससे लाभान्वित होगी ।

आभार प्रदर्शन—

पुस्तक के लिखने में अनेक प्रमाणिक पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा सरकारी रिपोर्टों से सहायता ली गई है, जिनके लेखकों एवं प्रकाशकों के प्रति मैं अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ । कुमारी मधुबाला ने पुस्तक के लेखन कार्य में जो सहयोग दिया है उसके लिये वह आशीर्वाद की पात्र है ।

सुझाव के लिये आमन्त्रण—

पुस्तक की उपयोगिता की वृद्धि के लिये जो भी सुझाव मिलेंगे उनका सहर्ष स्वागत किया जायगा ।

प्रानन्द निवास,
जेकब परेड,
गलियार ।

एस० सी० सबसेना

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ क्र.
१. औद्योगीकरण का अर्थ एवं महत्त्व	१-१
२. अर्द्ध विकसित देशों की समस्याएँ	१६-३
३. प्राचीन युग में भारतीय उद्योग	३६-४
४. अतीत के उद्योगों की अवधि	४१-४१
५. आधुनिक उद्योगों का प्रादुर्भाव एवं विकास	४६-५०
६. प्रथम महायुद्ध से द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक भारतीय उद्योगों का विकास	५६-६६
७. द्वितीय महायुद्ध के युग में भारतीय उद्योगों का विकास	७०-७६
८. देश के विभाजन का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव	८०-८६
९. स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय उद्योगों की प्रगति	८७-९६
१०. प्रथम पञ्च-वर्षीय योजना काल में औद्योगिक प्रगति	९६-१०३
१. द्वितीय पञ्च-वर्षीय योजना काल में औद्योगिक प्रगति	१०४-१०६
२. तृतीय पञ्च-वर्षीय योजना काल में उद्योग	१०६-१२२
एपीएडिस	१२३-१४०
१३. स्वतन्त्रता के पूर्व भारत सरकार की औद्योगिक नीति	१४१-१४७
१४. सन् १९४८ की औद्योगिक नीति	१४४-१५८
१५. सन् १९५६ की औद्योगिक नीति	१४६-१५१
१६. औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम, १९५१	१५६-१६५
१७. भारत में प्राशुक्तिक स्वतन्त्रता का विकास	१६६-१६
१८. विभेदात्मक सरक्षण की नीति	१६६-१८
१९. द्वितीय महायुद्ध युग एवं युद्धोत्तर काल में प्राशुक्तिक नीति	१८६-१८
२०. प्राशुक्तिक आयो १९४६-५० भारत सरकार की वर्तमान प्राशुक्तिक नीति	१९०-२०
२१. करारोपण एवं उद्योग	२१०-२८
२२. भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण	२२३-२१
२३. राज्य एवं विवेकीकरण	२३२-२३१
२४. औद्योगिक उत्पादकता आन्दोलन	२३८-३
२५. औद्योगिक संयोगों के प्रारूप एवं उनका विकास	२४८-१

अध्याय १

औद्योगीकरण का अर्थ एवं महत्त्व

(Meaning & Importance of Industrialisation)

प्रारम्भिक—

वर्तमान युग 'औद्योगिक युग' (Industrial Age) कहा जाता है। आज विश्व के सभी देशों में 'औद्योगीकरण' (Industrialisation) का बड़ा बोलबाला मीत होता है। यदि हम विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति की भाँकी करें, तो प्रतीत होगा कि जिन देशों के सभी राष्ट्र औद्योगिक विकास की दौड़ में एक दूसरे से गाने बढने में निरन्तर प्रयत्नशील हैं, वे औद्योगिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न देश ही हैं। वही वरन् आज वे देश भी औद्योगीकरण की दौड़ में भाग ले रहे हैं, जिनकी अर्थ-व्यवस्था अत्यन्त प्राचीन समय से कृषि प्रधान रही है। उदाहरण के लिये, भारत को ही ले लीजिये, आज से १४-१५ वर्ष पूर्व भारत की ८०% जन-संख्या कृषि पर अवलम्बित थी। परन्तु जब से हम स्वतन्त्र हुए हैं, तब से पंच-वर्षीय आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत देश के औद्योगीकरण के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमारी तृतीय पंच-वर्षीय योजना, जो अभी हाल में प्रारम्भ हुई है, का प्रमुख उद्देश्य तीव्र गति में देश का औद्योगीकरण करना है। इसी प्रकार हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अपने औद्योगिक विकास के लिये प्रयत्नशील है। उसने अपनी औद्योगिक प्रगति के लिये पूँजी एवं विशेषज्ञों को विदेशों से आमन्त्रित किया है। संयुक्त अरब गणराज्य में भी जो अभी तक कृषि-प्रधान देश रहा है, अनेक बृहत उद्योगों की स्थापना की जा रही है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आज विश्व के अधिकांश देशों को औद्योगीकरण का नशा चढ़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतम औद्योगिक विकास की एक 'दौड़' हो रही है, जिसमें कुछ पाश्चात्य राष्ट्र (जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत रूस आदि) अग्रणी हैं और पूर्वी देश भी उनका अनुकरण कर रहे हैं। अब यह सन पैदा होता है कि 'औद्योगीकरण' जिसका आज विश्व में नारा बुलन्द है, का वास्तविक अर्थ क्या है ?

1. 'औद्योगीकरण' से आशय

सामान्यतः 'औद्योगीकरण' से हमारा आशय निर्माणी उद्योगों की स्थापना एवं विकास से है। इस संकुचित आशय के सदर्भ में औद्योगीकरण को विकास की उस व्यापक प्रक्रिया का एक अंग कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य

उत्पादन के साधनों की कुशलता में वृद्धि करके जीवन-स्तरों को ऊँचा उठाना है।¹ यह औद्योगीकरण का सङ्कुचित अर्थ है। इसमें हम औद्योगीकरण के वास्तविक क्षेत्र का आभास नहीं मिलता। यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें एवं जरा गम्भीरता में विचार करें तो यह अनुभव होगा कि विस्तृत अर्थ में 'औद्योगीकरण' का प्रभाव देश के आर्थिक जीवन के समस्त पहलुओं पर पड़ना चाहिये। उदाहरण के लिये, यह कहा जा सकता है कि कृषि उद्योग (Agriculture) भी 'औद्योगीकरण' के द्वारा लाभान्वित किया जा सकता है, यदि इनके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन कला में सुधार, उन्नत औजार एवं कृषि साज-सजा तथा श्रम-विभाजन प्राप्त हो सके, जिससे कृषक भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में समर्थ हो जाय। यूजेन स्टेले² (Eugene Staley) ने इसको कृषि का औद्योगीकरण (Industrialisation of Agriculture) कहा है। औद्योगीकरण के द्वारा ही कृषि की उत्पादन कला में विकास किया जा सकता है। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप हमको ऐसे अनेक उपकरण व यन्त्र उपलब्ध होते हैं, जिनकी सहायता से 'गहन खेती' (Intensive Farming) वरके कृषि उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। उन्नत रासायनिक खाद भी 'औद्योगीकरण' की ही देन है। उन्नत सिंचाई की सुविधाओं, कृषि वर्षा आदि वैज्ञानिक आविष्कारों (जन्होंने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक इकलौत पड़ा कर दिया है) का श्रेय औद्योगीकरण को ही प्राप्त है।

इसी प्रकार, किसी देश का व्यापाराधिक्य (Balance of Trade) भी औद्योगीकरण पर निर्भर करता है। तीव्र औद्योगीकरण उत्पादन की मात्रा प्रोत्साहित करता है और जब उत्पादन अधिक होता है, तो राष्ट्रीय आवश्यकता की सन्तुष्टि के बाद 'वैप' भी बहुत बचता है, जिसको निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी विनिमय कमाया जा सकता है। यही नहीं, यातायात का विकास भी औद्योगीकरण की ही देन है। कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिये एवं कारखानों से उपभोक्ताओं तक निर्मित माल को ले जान के लिये यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है और यह आवश्यकता उतनी ही अधिक बलवती होगी जितना तीव्र औद्योगीकरण होगा। दूसरे शब्दा में, 'औद्योगीकरण' वह क्रिया है, जो उन्नत यातायात को प्रोत्साहित करती है। किसी देश में पूँजी का निर्माण भी औद्योगीकरण की गति पर ही निर्भर करता है। कोई देश जितना अधिक उद्योग-प्रधान होगा, वहाँ पूँजी का निर्माण भी उतना ही अधिक होगा। विश्व का वर्तमान इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जिन देशों में

1 U N Report—'Processes and Problems of Industrialisation in Under developed Countries,' p. 2.

2 Eugene Staley—'The Future of Under developed Countries' p. 300

औद्योगीकरण की गति मन्द है, वहाँ पूँजी का निर्माण भी 'केचुये की चाल' की भाँति होता है।

'औद्योगीकरण' के इस व्यापक स्वरूप के आधार पर ही 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) ने 'औद्योगीकरण व विदेशी व्यापार' शीर्षक पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि औद्योगीकरण की क्रिया केवल निर्माणी उद्योगों की स्थापना तक ही सीमित नहीं है, वरन् इसके द्वारा किसी भी देश का सम्पूर्ण आर्थिक कलेवर परिवर्तित किया जा सकता है।^१ अब हम औद्योगीकरण की कुछ विशिष्ट परिभाषाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं—

(१) पी कांग चॉंग (Pei-Kang-Chang) के शब्दों में —“औद्योगीकरण से तात्पर्य उस क्रिया से है, जिसके अन्तर्गत सामरिक उत्पादन कार्य से सम्बन्धित अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों में कुछ मूलभूत परिवर्तन वे हैं, जिनका सम्बन्ध किसी उद्योग के पजीकरण से होना है तथा जिनके द्वारा किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी नये बाजार की खोज एवं किसी नवीन क्षेत्र का शोषण होना है। एक प्रकार से 'औद्योगीकरण' एक वह साधन है जिसके द्वारा पूँजी का विस्तार एवं विकास किया जाता है।”^२

इस परिभाषा के विश्लेषण में यह स्पष्ट पता लगता है कि औद्योगीकरण वा क्षेत्र केवल निर्माणी उद्योगों की स्थापना तक ही सीमित नहीं है, वरन् व्यापक दृष्टि से, यह एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से किसी भी देश में पूँजी का विस्तार एवं विकास किया जा सकता है। इस व्यापक दृष्टिकोण से यह भी कहा जा सकता है कि 'औद्योगीकरण' एक 'यन्त्रीकरण' एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। 'औद्योगीकरण' 'यन्त्रीकरण' को प्रोत्साहित करता है एवं नये-नये यन्त्रों व उपकरणों के आविष्कार से नवीन उद्योगों की स्थापना को प्रेरणा मिलती है। जब उत्पादन बढ़ता है तो नये बाजारों की खोज भी शुरू हो जाती है। इस प्रकार यन्त्रीकरण, पूँजी का विस्तार, नये बाजारों का अनुसन्धान, आदि सभी औद्योगीकरण के अन्तर्गत आते हैं।

(२) ए० एच० हन्सेन (A. H. Hansen) ने एक स्थान पर लिखा है कि

1. League of Nations—"Industrialisation and Foreign Trade, p. 30"

2 In the words of Pei Kang Chang, "Industrialisation is a process in which changes of a series of strategical production functions are taking place. It involves those basic changes that accompany the mechanisation of an enterprise, the building of a new industry, the opening of a new market and the exploitation of a new territory. This is, in a way, a process of 'deepening' as well as 'widening' of Capital"—"Agriculture and Industrialisation" p. 69.

“किसी देश में पूँजी के निर्माण का निश्चयनीय साधन औद्योगीकरण ही है।”^१

श्री हनसेन के इन थोड़े से शब्दों से भी ‘औद्योगीकरण’ की व्यापकता का परिचय मिलता है। औद्योगीकरण के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है और उत्पादकता में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। फलतः लोगो की ‘बचत’ (Savings) में भी वृद्धि होती है। ‘बचत’ के द्वारा ही पूँजी का निर्माण प्रेरित होता है। इसी आधार पर हनसेन ने लिखा है कि औद्योगीकरण किसी देश में पूँजी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

(३) यूजेन स्टेले (Eugene Staley) के मतानुसार औद्योगीकरण एवं उत्पादकता में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। औद्योगीकरण के बिना उत्पादकता में वृद्धि करना असंभव है। दूसरे शब्दों में, औद्योगीकरण के द्वारा ही उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है एवं उत्पादकता की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं कि (प्र) औद्योगीकरण से उत्पादकता बढ़ती है एवं (व) उच्च उत्पादकता से औद्योगीकरण प्रोत्साहित होता है।^२

कुछ लेखक ने, जिनमें से कोन्डलिफ (Condliffe) व रोसेन्स्टीन (Rosenstein Rodan) प्रमुख हैं, एक वार्थिक दृष्टि से कम विकसित देश के लिये औद्योगीकरण की ही सिफारिश की है, जिसके द्वारा जनसंख्या का भार कम किया जा सकता है, रोजगार के साधनों में वृद्धि की जा सकती है एवं जनसाधारण के रहन-सहन का स्तर ऊँचा किया जा सकता है।

(४) मनुभाई शाह के शब्दों में ‘कृषि का यन्त्रीकरण भी औद्योगीकरण का ही अङ्ग है।

वास्तव में कृषि व औद्योगीकरण में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों ही परस्पर एक-दूसरे के सहायक हैं। स्पष्ट शब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कृषि का विकास औद्योगीकरण पर एवं औद्योगीकरण की सफलता कृषि पर अवलम्बित है। यदि प्रथम वाक्यांश पर हम गम्भीरता से विचार करें, तो पता लगता है कि वास्तव में कृषि की प्रगति औद्योगीकरण के विकास पर निर्भर करती है। यदि किसी देश में उद्योग धन्य बहुत अधिक बढ़े-घड़े व विकसित होंगे, तो हमको उन्नत कृषि के हेतु भी

1 Fiscal Policies and Business Cycles, p 355

2 “The two are parts of an interlinked process, one does not proceed very far without the other. It is equally true to say (i) that high productivity produces industrialisation and (ii) that industrialisation produces high productivity.”

तरह-तरह के उपकरण व यन्त्र उपलब्ध होंगे। इस प्रकार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत सिचाई-साधनों, उन्नत कृषि उपकरणों व यन्त्रों आदि की सहायता से कृषि का भी विकास किया जा सकता है। इसके विपरीत, जब हम दूसरे वाक्यांश पर मनन करते हैं, तो पता लगता है कि औद्योगीकरण भी काफी सीमा तक कृषि पर अवलम्बित है। उद्योग धन्धों का प्रमुख भोजन होता है कच्चा माल। कच्चे माल के बिना हम निर्मित माल की कल्पना भी नहीं कर सकते और यह कच्चा माल हमको उन्नत कृषि से ही उपलब्ध होता है। अतः स्पष्ट है कि कृषि एवं उद्योग दोनों ही परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। अनेक उद्योग प्रधान देशों के आर्थिक विकास के ऐतिहासिक अवलोकन में यह स्पष्ट है कि कृषि में सुधार के द्वारा ही वहाँ की औद्योगिक प्रगति सम्भव हो सकी है।¹ पी-कांग चांग (Pei-Kang Chang) ने तो यहाँ तक लिखा है कि, 'कोई भी देश कितना ही उद्योग-प्रधान क्यों न हो, वह अपनी आर्थिक क्रियाओं को चालू व विकास नहीं कर सकता, यदि वह साथ ही साथ अपनी सीमाओं के अन्तर्गत कृषि एवं उद्योग में उचित सन्तुलन नहीं बनाए रखता है, अर्थात् निर्यात एवं आयात द्वारा अन्य देशों के कृषि सम्बन्धी व्यवसायों से घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रखता है।'² "इस प्रकार औद्योगीकरण, कृषि पुनर्निर्माण (Agricultural Revolution) का एक अध्याय है, अथवा कृषि उत्पादन की उन्नति को ही औद्योगीकरण का एक अध्याय कहा जा सकता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि दोनों ही एक ही समस्या के पारस्परिक सम्बन्धित भाग हैं।"³

संक्षेप में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 'औद्योगीकरण' एक अत्यन्त व्यापक शब्द है, जिसके अन्तर्गत केवल निर्माणी क्रियाओं का ही समावेश नहीं किया जाता, बल्कि कृषि का विकास, व्यापार एवं यातायात की वृद्धि, यन्त्रीकरण, पूँजी का निर्माण आदि सभी बातें इसके अन्तर्गत आती हैं। औद्योगीकरण की सहायता से ही बड़ी मात्रा में वास्तुओं का उत्पादन सम्भव होता है एवं उद्योग में क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू किया जा सकता है।

औद्योगीकरण का उद्गम—

यद्यपि आधुनिक युग में औद्योगीकरण का बड़ा बोलबाला है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सदैव से ही उद्योग प्रधान रहे हैं। औद्योगीकरण का जन्म

1 The Economics of Under developed Countries, By. P. T. Bauer and B. S. Yamey, P. ge 235.

2 Pei Kang Chang, Page 23

3 'Industrialisation is one chapter of agrarian reconstruction or one might treat the improvement of agrarian production as one chapter of industrialisation. What matters is to remember that the two are inter connected parts of one problem.'

वास्तव में १८वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जबकि इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण क्रान्ति हुई, जो औद्योगिक क्रान्ति के नाम से विख्यात है। इस क्रान्ति के पूर्व इंग्लैंड के लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती करना ही था। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति में कृषि को गौण एवं उद्योग धन्धों का प्रमुख स्थान दिया गया। औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ अनेक वैज्ञानिक अनुसन्धानों एवं आविष्कारों के परिणामस्वरूप हुआ जिन्होंने उत्पादन विधियाँ में एक क्रान्ति पैदा कर दी। ये आविष्कार तीन प्रकार के थे—(१) थम वधान वाल, जैसे स्टीम की शक्ति से चलने वाले यन्त्र (२) समय बचाने वाले, जैसे सूत कातने की नई मशीनें और (३) दूरी कम करन वाले आविष्कार जैसे यातायात एवं सन्देशवाहन के साधन। इन समस्त आविष्कारों ने उद्योग, कृषि तथा यातायात के क्षेत्रों में एक क्रान्ति मचा दी। खेतों को छोड़कर लोग कारखानों में काम करने लगे और शर्न शर्न औद्योगीकरण की बल मिलने लगा। यद्यपि औद्योगीकरण की बेल सबप्रथम इंग्लैंड में प्रारम्भ हुई, परन्तु धीरे-धीरे समस्त विश्व में इसका विस्तार हो गया। ज्ञान, विज्ञान व तकनीकी के साथ-साथ औद्योगीकरण की गति भी तेज होती गई। विज्ञान के आधुनिक चमत्कारों ने इसको और भी प्रेरणा प्रदान की और आज तो सब-मगलकारी राष्ट्र की स्थापना के लिए औद्योगीकरण ही एकमात्र साधन समझा जाने लगा है। औद्योगीकरण के ही आधार पर आज हम प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करते बजर भूमि व महसूलों को कृषि योग्य बनाने तथा विश्व से दरिद्रता का उन्मूलन करने, आवि में प्रयत्नशील हैं। हमारे आधुनिक विज्ञान ने स्वचालन (Automation) नामक एक नया आविष्कार प्रदान किया है, जिसके द्वारा औद्योगीकरण की गति और भी तेज हो गई है। आज ऐसा अनुभव होने लगा है कि हम संभवतः एक नवीन औद्योगिक क्रान्ति के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। स्वचालित यंत्र व एलेक्ट्रॉनिक के प्रयोग से हमारी उत्पादन प्रणाली में बहुत अन्तर आगम्य है। एक प्रमुख अमेरिकन उद्योगपति ने कहा है कि सन् २०२० अमेरिका के आधे अधिक उन वस्तुओं का निर्माण भयवा वितरण करते हैं, जिनकी ५० वर्ष पूर्व लक्ष मात्र भी जानकारी नहीं थी। उसने यहाँ तक लिखा है कि सन् १९८० तक अमेरिका में ऐसी वस्तुओं का निर्माण होगा जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते।^१ यह सब कुछ औद्योगीकरण की ही दन है।

औद्योगीकरण का स्वरूप—

देश-देश में औद्योगीकरण का स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाता है। नाचे कुछ प्रमुख स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है—

(१) **प्राथमिक, ताबजनिक एवं मिश्रित अर्थ व्यवस्था**—सरकार अथवा प्राईवेट उपज्म द्वारा की गई पहल (initiative) की मात्रा के अनुसार औद्योगी

करण व्यक्तिगत (Private) हो सकता है या सरकारी अथवा संयुक्त। किसी देश का औद्योगीकरण किस श्रेणी में आना है, इसे निर्दिष्ट कर देना सरल नहीं है क्योंकि औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में सरकार एवं व्यक्ति दोनों के ही प्रयत्न आवश्यक होते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस प्रथम श्रेणी में, सोवियत रूस व चीन द्वितीय श्रेणी में और जर्मनी, जापान एवं भारत तृतीय श्रेणी में आते हैं।

(२) विकासात्मक एवं क्रान्तिकारी औद्योगीकरण—सोवियत रूस में जिस भाँति का औद्योगीकरण हुआ है उसे 'क्रान्तिकारी औद्योगीकरण' (Revolutionary Industrialisation) कहते हैं, जबकि इंग्लैंड का औद्योगीकरण 'विकासात्मक' (Evolutionary) कहा जा सकता है। लेकिन ये दोनों शब्द एक-दूसरे से बिल्कुल पृथक् नहीं हैं। वरन् वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिये, इंग्लैंड में आधुनिक उद्योग के विकास के काल को 'औद्योगिक क्रान्ति' (Industrial Revolution) की सजा दी गई थी जब कि सोवियत रूस में औद्योगीकरण की क्रान्तिमय प्रक्रिया स्वभाव से बहुत कुछ विकासात्मक थी, क्योंकि वह आयात की गई टेक्नोलॉजी से आरम्भ हुई थी।

औद्योगीकरण की गति—

कहा जाता है कि औद्योगीकरण की गति सबों तेज उन देशों में है जहाँ कि औद्योगीकरण देर से आरम्भ हुआ, क्योंकि उन्हें आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के प्रचलन का लाभ प्राप्त है। सामान्यतः किसी देश में औद्योगीकरण की गति निम्न घटकों से प्रभावित होती है—

(१) टेक्नोलॉजिकल विकास का स्तर—जिस टेक्नोलॉजिकल विकास के स्तर पर कोई देश औद्योगीकरण की प्रक्रिया में प्रविष्ट होता है उस पर उसके औद्योगीकरण की गति निर्भर होती है। जो देश इस प्रक्रिया में अन्य देशों की अपेक्षा देर से प्रविष्ट होते हैं उनमें यह गति अधिक तेज होती है, क्योंकि वे आधुनिकतम टेक्नोलॉजिकल आविष्कारों और नवीनतम प्रकार के संगठन का प्रयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं।

(२) सरकार की नीति—सरकार की नीति भी औद्योगीकरण की गति पर प्रभाव डालती है। जब सरकार औद्योगिक विकास में स्वयं भाग लेती है तो औद्योगिक प्रगति की गति उस दशा से अधिक होती है जबकि वह इस प्रकार भाग नहीं लेती।

(३) माल का स्वभाव—यदि औद्योगीकरण की प्रक्रिया उपभोग वस्तुओं के उत्पादन से आरम्भ होती है, तो उसकी गति कम होगी और यदि वह पूँजी-वस्तुओं के उत्पादन से आरम्भ हो, तो उसकी गति तेज होगी।

(४) पूँजी जुटाने का ढंग—जिस ढंग से पूँजी एकत्र की जाती है वह भी औद्योगीकरण की गति को प्रभावित करती है। यदि आन्तरिक साधनों की कमी को

पूरा करने के लिये सही प्रकार की और पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूँजी उपलब्ध हो, तो देश औद्योगीकरण की राह पर तेजी से बढ़ सकता है।

(५) भूमि पर जन-संख्या का भार—अन्य बातें समान रहने पर, जिन देशों में भूमि पर जन-संख्या का भार कम है तथा वृद्धि की दर भी नीचे है वहाँ औद्योगीकरण की गति तेज होगी, किन्तु जिन देशों में जन-संख्या का भार अधिक है और वृद्धि की दर भी ऊँची है वहाँ औद्योगीकरण की गति धीमी होती है।

(६) युद्ध का प्रभाव यह माना जाता है कि युद्ध भी औद्योगीकरण की गति को तीव्र करता है। इस सम्बन्ध में कुछ औद्योगिक देशों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। अमेरिका में सन् १८६५ के गृह युद्ध के पश्चात् औद्योगीकरण आरम्भ किया, जर्मनी में सन् १८७० के फ्रेन्को प्रुसियन युद्ध के बाद और चीन में द्वितीय महायुद्ध के बाद औद्योगीकरण के मार्ग पर कदम रखा। अपनी पुस्तक 'प्रशुल्क नीति' (Eis-ohl policy) में हनसेन ने बताया है कि औद्योगिक क्रान्ति औद्योगीकरण को जितना प्रोत्साहन देती है उतना ही प्रोत्साहन युद्ध भी औद्योगीकरण को देता है। युद्ध माँग पैदा करता है और नई उत्पत्ति के प्रचलन को बढ़ावा देता है, वह रोजगार को प्रोत्साहित करता है तथा टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन करने की आवश्यकता पैदा करता है तथा प्रायः के वितरण एवं सम्पत्ति के स्वामित्व में सम्बन्धित सामाजिक सुधारों के मार्ग में आने वाली रुकावट बाधाओं को दूर करता है। अतः यह निस्कोष कह सकते हैं कि युद्ध आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है तथा विजेता देश के लिये औद्योगीकरण आरम्भ करने के लिये और (यदि औद्योगीकरण आरम्भ हो चुका है तो) उसकी गति तेज करने के लिये अनुकूल दशायें उत्पन्न करता है।

(७) औद्योगीकरण की बाधाएँ एवं औद्योगीकरण के प्रोत्साहन—औद्योगिक प्रगति की बाधाएँ औद्योगिक विकास की गति को घटाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि कुछ कार्य ऐसे किये जा सकते हैं जिनसे विकास की गति बढ़ जाय। औद्योगिक विकास की गति तीव्र होगी या धीमी, यह बहुत कुछ किसी विशेष समय पर प्रस्तुत औद्योगिक बाधाओं के आकार पर निर्भर करता है।

यह उल्लेखनीय है कि गति का सम्बन्ध विकास की दर से है न कि विकास की निरपेक्ष मात्रा से। औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में छोटे नये विकासों के फलस्वरूप विकास की गति तीव्र हो जाती है, जबकि विकास की दर को कायम रखने के लिये नवीन औद्योगिक विनियोग की सदा बढ़ती हुई मात्रा आवश्यक होती है। वास्तव में औद्योगीकरण की सुविधाएँ औद्योगीकरण की गति के साथ-साथ बढ़ती हैं। इस प्रकार औद्योगीकरण एक वृद्धिमूलक प्रक्रिया है। एक उद्योग के मफल संचालन से दूसरे उद्योग को पूँजी प्रादि प्राप्त करना सरल हो जाता है। यही कारण है कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में औद्योगीकरण की गति कुछ धीमी होती है।

(८) कृषि की उन्नति—औद्योगीकरण की गति धृषि उत्पादन की दर से भी प्रभावित होती है, क्योंकि कृषि से ही द्रव्यो के लिये मुख्य वस्त्रे माल प्राप्त होते हैं । कृषि उत्पादन मे तुरन्त या अचानक वृद्धि नही की जा सकती है ।

(९) मानवीय साधन—औद्योगिक विकास की गति समाज द्वारा अपने रहन-सहन के ढंग मे व सम्बन्धो और स्थितियो मे आवश्यक समायोजन कर सकने की क्षमता से भी सीमित होती है । यदि देश मे पर्याप्त पूँजी उपलब्ध है, किन्तु जनता मे उसके प्रयोग करने की योग्यता नही है, तो औद्योगीकरण की गति तेज नही हो सकती है ।

औद्योगीकरण के लाभ

वर्तमान औद्योगिक युग मे औद्योगीकरण की महिमा के विषय मे जो कुछ भी कहा जाय, कम ही होगा । औद्योगीकरण किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के हेतु 'सजीवनी' है । इसके द्वारा केवल आर्थिक विकास ही नही, बरन् सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति भी सम्भव होती है । औद्योगीकरण के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) उत्पादन शक्ति मे वृद्धि—किसी भी देश की उत्पादन-शीलता को बढाने का एकमात्र साधन तीव्र औद्योगीकरण ही है । विश्व का वर्तमान आर्थिक विकास इस बात का साक्षी है कि जिन देशो ने औद्योगीकरण को अपनी आर्थिक समृद्धि का आधार माना है, वे ही आज प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं । औद्योगीकरण के नारे से समस्त देश ने एक चेतनता पैदा हो जाती है, जिससे उत्पादन शक्ति की वृद्धि में बड़ा योग मिलता है ।

(२) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि—उद्योग धन्धो के विकास से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होना स्वाभाविक ही है । उदाहरण के लिये, भारतवर्ष की ही लीजिये, सन् १९१०-११ मे हमारी

औद्योगीकरण के प्रमुख ११ लाभ

- १ उत्पादन शक्ति मे वृद्धि ।
२. राष्ट्रीय आय मे वृद्धि ।
- ३ कृषि पर जन-संख्या के भार मे कमी ।
४. रोजगार के साधनो मे वृद्धि ।
५. सतुलित आर्थिक विकास की सम्भावना ।
६. पूँजी के निर्माण मे वृद्धि ।
- ७ श्रमिको के रहन-पहन के स्तर मे वृद्धि ।
- ८ जन-साधारण के जीवन स्तर मे वृद्धि ।
- ९ कर-देय क्षमता मे वृद्धि ।
- १० राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे वृद्धि ।
- ११ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण ।

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय केवल २६५ रु० थी, परन्तु प्रथम व द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत तीव्र औद्योगीकरण के परिणाम-स्वरूप आज हमारी राष्ट्रीय आय २८६ रु० हो गई है ।^१

(३) कृषि पर जन-संख्या के भार में कमी—औद्योगीकरण के द्वारा कृषि पर जन-संख्या के भार का भी कम किया जा सकता है। औद्योगीकरण के विकास से केवल कृषि पर लोगों की निर्भरता न रहेगी वरन् विभिन्न उद्योग-धन्यो में उनको काम भी मिल सकता है।

(४) रोजगार के साधनों में वृद्धि—औद्योगीकरण का सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है कि इसमें बेरोजगारी को किसी भी समय राष्ट्र के लिए अभिशाप है, दूर की जा सकती है। बृहत् उद्योग, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों में गनेक लोगों को काम मिल सकता है।

(५) सतुलित आर्थिक विकास की सम्भावना—किसी देश की सतुलित आर्थिक प्रगति के लिए भी औद्योगीकरण नितात आवश्यक है। बिना औद्योगीकरण के यह सम्भव है कि जन-संख्या का भार अधिकांशतः कृषि उद्योग पर ही बना रहे। औद्योगीकरण के द्वारा यह बोध दूर किया जा सकता है। किसी राष्ट्र की स्थायी आर्थिक समृद्धि के लिए सतुलित विवास बहुत जरूरी है और यह केवल औद्योगीकरण की योजना द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

(६) पूँजी के निर्माण में वृद्धि—पूँजी का मचय व इमका निर्माण भी काफी सीमा तक औद्योगीकरण की गति पर निर्भर करता है। यदि हम किसी राष्ट्र की विनियोग शक्ति का यथावर पूँजी के निर्माण का प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो इमका एकमात्र उपाय है—औद्योगीकरण।

(७) श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि—औद्योगीकरण के द्वारा श्रम-जीविदों को केवल रोजगार ही नहीं मिलता, वरन् उनके रहन-सहन के स्तर में भी वृद्धि होती है। नगद मजदूरी के अतिरिक्त उनको असल मजदूरी भी मिलती है, जैम—रहने के लिए अच्छे भवान की व्यवस्था, खान व स्थिर सस्ता अनाज, पहनने के लिए मस्ते व अच्छे कपड़े एवं मनोरंजन की सुविधाय इत्यादि। इन सब बातों का सामूहिक प्रभाव उनके रहन-सहन के स्तर पर पड़ता है।

(८) जनसाधारण के जीवन स्तर में वृद्धि—औद्योगीकरण के द्वारा केवल श्रमिक वर्ग ही सामान्यजन नहीं होता, वरन् इस सम्पूर्ण समाज का ही होता है। विभिन्न उद्योग-धन्यो का विकास के देश का स्वस्थ प्रगतिशील प्रगतिशील होता है, जिसके परिणामस्वरूप धन्युधों के मूल्य स्वन कम हो जात है। इस प्रकार जनता को सस्ती

व अन्धरी वस्तुएँ मिलने लगती हैं एवं उनमें उपभोग का स्तर व जीवन स्तर उन्नत हो जाता है।

(६) **कर-देय क्षमता में वृद्धि**—औद्योगीकरण में देश भर की कर-देय क्षमता बढ़ जाती है तथा सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है जिससे वह जन साधारण की अधिक सेवा करने में समर्थ होती है। सरकार के खजाने में जो अतिरिक्त आय आती है उसका उपयोग सड़के बनवाने पटरियाँ बिछवाने आदि जन कल्याण के कार्यों में किया जाता है।

(१०) **व्यापार में वृद्धि**—औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप अमुक्त देश को अतिरिक्त वस्तुएँ उपलब्ध होने लगती हैं जिनको बेचकर वह बहुमूल्य विदेशी विनिमय एकत्रित कर सकता है। औद्योगीकरण के द्वारा केवल आंतरिक व्यापार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रोत्साहित होता है।

(११) **राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण**—औद्योगीकरण के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में भी बड़ा योग मिलता है। विभिन्न उद्योग में काम करने वाले कमचारी तथा उनके सेवायोजक सभी नियत नियमों के अनुसार एक दृढ़ अनुशासन के अन्तर्गत कार्य करते हैं, इससे उनके चरित्र पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है।

औद्योगीकरण के कुछ सामाजिक दोष

राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिये अनिवार्य होते हुए भी औद्योगीकरण के मार्ग में कुछ दुर्बलताएँ भी हैं। यदि इससे एक ओर समाज को सस्ती अन्धरी व अधिक मात्रा में वस्तुएँ उपलब्ध होने लगती हैं तो दूसरी ओर अनेक दोषों का भी शिकार होना पड़ता है। गहन प्रतिस्पर्धा एवं व्यक्तिवाद की भावना बढ़ने से सामूहिक जीवन को बड़ी ठस पहुँचती है। ग्रामीण एकता को औद्योगीकरण के द्वारा बड़ा आघात पहुँचा है। गाँव की आत्म निर्भरता समाप्त होन लगती है और नगर तथा विश्व के अन्य देशों का प्रभाव पड़ने लगता है। औद्योगीकरण के पूर्व गाँव एक सम्पूर्ण इकाई थी और गाँव के सभी लोग एक परिवार के सदस्यों की भाँति जीवन व्यतीत करते थे, परन्तु औद्योगीकरण ने इस पर भी आघात किया। सामूहिक जीवन छिन्न-भिन्न हो गया एवं कारखानों का वातावरण पनपने लगा। कारखाना के विकास से श्रमिकों तथा कारीगरों की भी समस्याएँ बढ़ने लगी। कुटीर एवं दस्तकारी उद्योगों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। विशाल उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में ये लघु उद्योग टिक नहीं पाते। फलतः उनके विनाश व अवनति के कारण अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी के कारण समाज में निराशा का वातावरण पैदा हो जाता है। औद्योगीकरण का एक अन्य दोष यह है कि इससे बीमारी व ग्रह समस्या को भी बढ़ावा मिलता है। जो श्रमिक गाँवों के स्वच्छ वातावरण को छोड़कर नगरों में

आकर कारखानों में काम करते हैं, उनके लिये यहाँ रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। एक छोटे से कमरे में अनेक परिवारों को अपना दुबड़ा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अनेक व्यक्तियों के एक साथ रहने के कारण अस्वास्थ्यप्रद वातावरण रहता है, जिससे तरह-तरह की बीमारियाँ बढ़ती हैं।

उपरोक्त विवरण से हमको ऐसी धारणा नहीं कर लेनी चाहिये कि 'औद्योगीकरण' हानिकारक है। किंचित सामाजिक दोषों के होने हुए भी इससे राष्ट्र का कल्याण ही होता है अहित नहीं। विश्व का आर्थिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन देशों ने औद्योगीकरण का आश्रय लिया, उन्होंने निश्चय प्रगति की ओर आज भी वे ही उन्नति की पराकाष्ठा पर हैं। समुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटिश, सोवियत, रूस, जर्मनी आदि देश की आधुनिक समृद्धि का एकमात्र कारण वहाँ का औद्योगीकरण ही है।

भारत में औद्योगीकरण की आवश्यकता

भारतवर्ष की वर्तमान आर्थिक सामाजिक व राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि हमको औद्योगीकरण की विशेष आवश्यकता है। यद्यपि भारतवर्ष की गणना दुनिया के ८ बड़े-बड़े औद्योगिक देशों में की जाती है किन्तु फिर भी औद्योगिक दृष्टि से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि हम दुनिया के अन्य उन्नतशील देशों के साथ कदम-कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय तीव्र गति में औद्योगीकरण करना ही है। हमारी निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिये औद्योगीकरण बहुत जरूरी है—

भारत में औद्योगीकरण की प्रमुख ६ आवश्यकताएँ

- १ बेरोजगारी को दूर करने के लिये।
- २ सतुलित आर्थिक प्रगति के लिये।
- ३ प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग करने के लिये।
- ४ राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिये।
- ५ श्रमिका व जन-साधारण के रहन सहन के स्तर में वृद्धि के लिये।
- ६ अरुण शक्ति व वृद्धि के लिये।

(१) बेरोजगारी को दूर करने के लिये—किसी भी सभ्य देश के लिये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जिस देश में बेरोजगार लोगों की संख्या अधिक होती है अथवा जो देश अपने यहाँ के निवासियों का पूर्ण रोजगार नहीं दे सकता, वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। हमारे देश में भी आज अनेक व्यक्ति बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का रोग केवल अशिक्षित वर्ग में ही नहीं बल्कि शिक्षित वर्ग में भी है। यदि इस समस्या का पूर्णतः उन्मूलन करना है तो इसका एकमात्र उपाय औद्योगीकरण ही हो सकता है।

(२) संतुलित आर्थिक प्रगति के लिये—भारतवर्ष के आर्थिक विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी आर्थिक प्रगति संतुलित नहीं है। कृषि पर जन-संख्या का अत्यधिक भार है। उद्योग-धन्धों में काम करने वाले लोगो की संख्या बहुत ही कम है। इसी प्रकार विभिन्न सेवाओं में भी देश की कुल जन-संख्या का बहुत थोड़ा भाग लगा हुआ है। संतुलित आर्थिक प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि कृषि, उद्योग-धन्धों, व्यापार, यातायात, सेवाओं आदि सभी का पर्याप्त विकास हो। अतएव कृषि पर जन-संख्या के भार को कम करने के लिये एवं संतुलित आर्थिक विकास के उद्देश्य से भारत का 'औद्योगीकरण' नितांत आवश्यक है।

(३) प्राकृतिक सम्पदा का सदुपयोग करने के लिये—प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से हमारा देश बड़ा धनी है और इस दृष्टि से तो दुनिया के थोड़े ही ऐसे देश होंगे जिनकी तुलना भारत से की जा सकती है। परन्तु दुर्भाग्य का विषय यह है कि सन् १९४७ तक दासत्व की श्रृंखला में जकड़े रहने के कारण हम अपनी प्रकृति-दत्त संपदा का उपयोग नहीं कर सके। इसके पर्याप्त विदोहन (Exploitation) के लिये अभी भी योजना नहीं बनाई गई। हाँ, जब से शासन की बागडोर जन-प्रिय सरकार के हाथों में आई है, तब से अवश्य नियोजित विकास की दशा में हम प्रयत्नशील हैं। अतएव यदि हम अपने प्रकृतिदत्त पदार्थों का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो यह केवल औद्योगीकरण की विस्तृत योजना द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

(४) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिये—देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिये भी औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है। औद्योगीकरण के द्वारा उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी एवं परिणामस्वरूप राष्ट्र की आय भी बढ़ेगी। यही नहीं, पूँजी के निर्माण में भी इससे बड़ी सहायता मिलेगी।

(५) श्रमिकों व जन-साधारण के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि के लिये—औद्योगीकरण की देशव्यापी योजना में श्रमिकों को नहीं भुलाया जा सकता। इससे उनकी रूप-कृतज्ञता ही नहीं बढ़ेगी बल्कि जीवन स्तर भी उन्नत होगा। आजकल श्रमिकों को काम करने की दशाएँ अधिक सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती, यद्यपि उनमें सुधार के लिये अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु फिर भी अब तक जो कुछ भी किया गया है, वह सागर में एक बूँद के समान है। यदि हम भारतीय श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करना चाहते हैं एवं जन साधारण को सस्ती व अच्छी वस्तुएँ प्रदान करना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है—'औद्योगीकरण'।

(६) कर-देय क्षमता में वृद्धि के लिये—भारतवासियों की कर देय क्षमता बहुत ही कम है। मध्यम वर्ग तो कर के भार से बहुत ही दबा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा कर-दाना स्वस्थ व हृष्ट पुष्ट हो एवं सरकारी खजाने में अधिक पैसा जमा कराने में समर्थ हो सके तो यह केवल औद्योगीकरण के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। औद्योगीकरण से केवल कर-दाता ही अधिक कर देने में समर्थ न होगा बल्कि सरकार की यह क्षमता भी बढ़ जायगा। वह भी फिर जनता की सुख-सुविधाओं के लिये अधिक व्यय कर सकेगी।

संक्षेप में देश की जन-संख्या के लगभग ३/४ भाग की कृषि जंसे जोखिम पूर्ण व मौसमी उद्योग पर निर्भरता भूमि पर जन-संख्या का अत्यधिक भार, अत्यन्त निम्न स्तर तथा निर्जीव करने वाली भयानक दरिद्रता शिक्षित मध्यम वर्ग के नव-युवकों में बेकारी तथा कृषकों की अर्द्ध रोजगारी इत्यादि देश को कमी की अर्थ-व्यवस्था से निकाल कर एक बचन की अर्थ-व्यवस्था में लाने के लिये एक आयोजित औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की परम आवश्यकता की ओर सकेन करते हैं।

प्रद्युक्त आयोग मन् १९४६-५० के शब्दों में औद्योगीकरण की देश-व्यापी योजना में भारत को निम्नलिखित लाभ होने की आशा है —

- (अ) औद्योगीकरण से देश की उत्पादन शक्ति बढ़ेगी, जिसमें राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होगी।
- (ब) कृषि के ऊपर वर्तमान जन-संख्या का जो प्रभार है वह कम होकर, कृषि निर्भरता नहीं रहेगी।
- (स) औद्योगीकरण से श्रमिकों को अनेक काम मिलेंगे एवं बेकारी की समस्या दूर हो सकेगी।
- (द) उद्योगों के बढ़ते हुए लाभ से देश में पूँजी का अधिक निर्माण हो सकेगा, जिसमें विनियामक शक्ति बढ़ेगी।
- (घ) औद्योगिक विकास में श्रमिका की नगद मजदूरी बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे विकास में श्रमिका व परिवार का भी काम करने के अवसर मिल सकत है।
- (र) औद्योगीकरण से देश का व-दय क्षमता बढ़ेगी तथा राज्य को अधिक आय हो सकेगी।
- (ल) इन लाभों का हितकर प्रभाव देश के चरित्र-निर्माण पर भी पड़ेगा, क्योंकि सुदृढ़ एवं अच्छे चरित्र निर्माण के लिए देश का औद्योगीकरण एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर प्राप्त होना, ये दोनों बातें आवश्यक हैं।

भारत में औद्योगीकरण के साधन

औद्योगिक विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वे सभी साधन भारत में उपलब्ध हैं। प्रकृति की इस देश पर अत्यन्त अनुकम्पा है, इसी कारण यह कहा जाता है कि "भारत एक धनी देश है, जिसमें निर्धन व्यक्ति रहते हैं।" औद्योगीकरण के लिए कच्चा माल, जन-सम्पत्ति, विद्युत-शक्ति, खनिज-सम्पत्ति, धन-संचय, विस्तृत बाजार, अय-विक्रय की सुविधाएँ, प्रबन्ध एवं साहस आदि साधनों की आवश्यकता पड़ती है और ये सभी प्रचुर मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध हैं। सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार भारत की जन-संख्या ३५०६८२ करोड़ है। जनशक्ति की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा नम्बर भारत का है। कच्चे माल की दृष्टि से भी भारत किसी देश में कम नहीं है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के निर्यात माल में कच्चे मान की ही अधिकता होनी है, जिसको कि औद्योगीकरण द्वारा ही देश में खपाया जा सकता है। भाज्य पदार्थ के उत्पादन में भी देश लगभग सम्पन्न है। यहाँ विश्व के सर्वोत्तम सिंचाई के साधन विद्यमान हैं। पशु सम्पत्ति में भी भारत सर्वश्रेष्ठ है। हमारी वन-सम्पत्ति विस्तृत तथा विशाल है, जिसमें बहुमूल्य लकड़ी का भण्डार है। साख के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से भी भारत धनाढ्य है। भारत-भूमि को रत्नगर्भी कहा जाता है। यहाँ दुनियाँ में सबसे ज्यादा अभ्रक निकलता है। मैंगनीज के उत्पादन में भी इसका विश्व में दूसरा नम्बर है। इसके अलावा यहाँ कोयला, लोहा, बाक्साइट, शोमाइड, चूने का पत्थर, अल्फ़ाइनियम आदि भी अधिक परिमाण में निकलती हैं। जल-विद्युत के लिए भी भारत में अपार धन है। बम्बई में गटर के पानी से जलाने के लिए गैस भी तैयार होती है, जो भागे चलकर औद्योगिक उत्पादन के कार्य में भी धान लगेगी। इसके अतिरिक्त भारत को देशी तथा निकटवर्ती विदेशी विशाल बाजार भी उपलब्ध है।

उपयुक्त विवरण में स्पष्ट है कि प्राकृतिक साधनों का भारत में अभाव नहीं है, किन्तु आवश्यकता है उनके सदुपयोग करने की। विदेशी शासन तथा आर्थिक परतन्त्रता के कारण अभी तक इन स्रोतों का उचित तथा पूर्ण उपयोग नहीं हो सका है। तभी तो यद्यपि भारत की गणना विश्व के आठ बड़े बड़े औद्योगिक देशों में की जाती है, किन्तु फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह प्रगतिशील राष्ट्र नहीं है। अब माशा की जाती है कि राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत हमारा भारत दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा।

STANDARD QUESTIONS

1. Define the term 'Industrialisation'. Discuss its scope and importance

- 2 Summarise carefully the various advantages that are likely to accrue from Industrialisation
- 3 Are there any disadvantages of Industrialisation ? If so, what are they ? How far they are real ?
- 4 Discuss the need and importance of Industrialisation in India How far she is going to be benefitted by it ?
- 5 What do you mean by the term 'Pattern of Industrialisation' ? Discuss the factors which affect the speed of Industrialisation in a country

अध्याय २

अर्द्ध-विकसित देशों की समस्यायें

(Problems Of Underdeveloped Countries)

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था से आशय—

एक अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था (Underdeveloped Economy) से आशय ऐसे देश अथवा देशों की अर्थ-व्यवस्था से है जिनका आर्थिक विकास या तो अभी प्रारम्भ हो नहीं हुआ है, और यदि हुआ भी है, तो अभी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में है। एक अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था वाला देश का अर्थ भली प्रकार समझने के लिये 'विकसित अर्थ-व्यवस्था' (Developed Economy) एवं 'अविकसित अर्थ-व्यवस्था' (Undeveloped Economy) का अर्थ देना आवश्यक है। जैसा कि इन शब्दों से स्पष्ट है 'एक विकसित अर्थ-व्यवस्था वाला देश वह है, जिसने अपनी प्राकृतिक सम्पदा एवं अन्य मयस्त्रियाँ (जैसे, जन-शक्ति, जल-शक्ति, विविध कच्चे पदार्थ, खनिज सम्पत्ति, वन सम्पत्ति, इत्यादि) का भरपूर शोषण किया है। एवं जो तृप्ति के मार्ग पर प्रसरण हो। जिस देश के ऊपर व उद्योग घरों का उत्पन्न उत्पत्ति की पराकाष्ठा पर होता है, अत्यन्त तीव्र गति से पूँजी का निर्माण होता है एवं चारों ओर सुख एवं समृद्धि छाई होती है, ऐसे देश का प्रायः विकसित देश कहा जाता है। ये समस्त वस्तुएँ आज समुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत रूस आदि औद्योगिक राष्ट्रों में

विद्यमान है। यही कारण है कि इन्हे विकसित देश की सजा दी जाती है। इसके विपरीत 'अविकसित देश' उसे कहा जा सकता है जहाँ कि प्राकृतिक सम्पदा बिल्कुल सुप्त दशा में पड़ी हुई हो, जहाँ के निवासियों के रहन सहन के स्तर अत्यन्त निम्न हो और जहाँ सामान्यतः निराशावाद छाया हो। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश इस दृष्टि से अविकसित कहे जा सकते हैं। एक अर्द्ध विकसित देश की अर्थ-व्यवस्था इन दोनों प्रकार के देशों की (विकसित तथा अविकसित) अर्थ-व्यवस्थाओं के मध्य में कही जा सकती है। एक अर्द्ध-विकसित व्यवस्था वाले देश में प्राकृतिक प्रसाधनों का अभाव नहीं होता वरन् उसका पर्याप्त शोषण नहीं हो पाना है। यही कारण है कि वहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम होता है। घरेलू बचत इतनी कम होती है कि आर्थिक विकास के लिये पर्याप्त पूँजी का अभाव होता है।

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषायें—

'अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था' के सम्बन्ध में यहाँ किंचित परिभाषा देना अनावश्यक न होगा—

(१) प्रो० हिक्स (Prof Hicks) के शब्दों में, एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें तांत्रिक एवम् मौद्रिक साधनों की मात्रा उत्पादन एवम् बचत के वास्तविक स्तर से कुछ ही अधिक होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक को पुरूस्कार उस राशि से बहुत कम मिलता है, जो कि उसे तब मिलता जबकि सम्पूर्ण ज्ञान तन्त्र-कला का उत्पादन में उपयोग किया जाता।^१ प्रोफेसर हिक्स द्वारा दी गई यह परिभाषा मुख्यतः औद्योगिक घटकों (Technological Factors) पर अवलम्बित है।

(२) प्रोफेसर वाइनर (Prof Viner) ने अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है—“एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थ-व्यवस्था का है, जिसमें आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का अभी पूर्ण शोषण नहीं हो पाया है।”^२

1 “An underdeveloped country is one in which the technical and monetary ceilings are as low as practically to coincide with the actual level of output and savings, with the result that the average remuneration per unit of labour (or per working person) is lower than what it could be if known technology were applied to known resources”

—A contribution to the theory of Trade Cycle, by Prof Hicks

2 “An underdeveloped economy is one which has good potential prospects for using more capital or more labour or more available natural resources or of all these to support present population in a higher level of living”

—Prof Viner

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषतायें—

उपरोक्त परिभाषाओं का सार यह है कि एक अर्द्ध विकसित देश में आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का पूरा शोषण नहीं होता है। पूँजी का निर्माण या तो बिल्कुल ही नहीं होता या बहुत थोड़ा होता है। उपलब्ध भूमि के क्षयफल एवम् निष्क्रिय जन शक्ति की मात्रा को देखते हुये कृषि की उत्पादकता कम होती है। काम करने वाली जन-संख्या थोड़ी किन्तु चलने वाली जन-संख्या अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप रहन सहन का स्तर बहुत नीचा पाया जाता है। ऐसे देशों में आर्थिक समस्याओं का विकास या तो हुआ नहीं है अथवा वे अभी विकास की प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं। एक अर्द्ध विकसित देश की विशेषतायें इतनी अधिक हैं कि उनको किसी एक परिभाषा के अन्दर स्थान देना कठिन है। इससे तो उस परिभाषा का महत्त्व ही जाता रहेगा। फिर भी एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह वह अर्थ-व्य-स्था है जिसमें जनता का जीवन-स्तर बहुत नीचा होता है विनियोग की विशाल सम्भावनायें उपस्थित हैं किन्तु पूँजी का लगभग अभाव होता है लोगों की उपभोग की वृत्ति ऊँची होती है बचत लगभग शून्य होती है, छिपी हुई बेरोजगारी का बोलबाला होता है कृषि कार्य पुराने तरीका से किया जाता है सहायक उद्योग व्यापार व वाणिज्य का बहुत कम विकास होता है।

बिच में कुछ अर्द्ध-विकसित देश—

बोअर और यामे (Bauer and Yamey) ने शब्दों में 'मोटे तौर पर, एक अर्द्ध-विकसित देश से तात्पर्य उन देशों का है जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और पूँजी उत्तरी अमेरिका पश्चिमी योरोप व आस्ट्रेलिया की तुलना में कम हो।'^१ इससे यह प्रगट होता है कि अधिक विकसित और कम विकसित देशों के बीच अन्तर केवल डिग्री का ही है। अर्द्ध-विकसित देशों में अत्यधिक शरीबी पाई जाती है, जो कि किसी अस्थायी दुर्भाग्य का परिणाम न होकर अर्थ व्यवस्था के स्थायी दोष का फल होती है और वहाँ उत्पादन व सामाजिक संगठन के तरीके बड़े अप्रचलित होते हैं। ऐसे देशों में उन्नत वैज्ञानिक एवम् औद्योगिक तरीकों का किसी बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया जाता है। वास्तव में वहाँ उत्पादन केवल जीवन निर्वाह के लिये किया जाता है और बाजार का क्षेत्र अपक्षित स्कीर्ण होता है। 'अर्द्ध-विकास' शब्द का तात्पर्य केवल आर्थिक और तकनीक सफलता के निम्न स्तर से है, किन्हीं अन्य बातों से इसका

1 "The term 'under developed countries' refers loosely to countries or regions with levels of real income and capital per head of population which are low by the standards of North America Western Europe and Australia "

सात्पयं नहीं होता। उदाहरण के लिये, अर्द्ध-विकसित देश होते हुये भी भारत और चीन की सभ्यताएँ व सस्कृतियाँ ५,००० वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं।

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों को बहुत अधिक विकसित, साधारण रूप से अधिक विकसित एवम् अर्द्ध-विकसित देशों में वर्गित किया जा सकता है। अर्द्ध विकसित देशों में एशिया के समस्त देश (जापान को छोड़कर), अफ्रीका, लेटिन अमेरिका (अर्जेंटीना को छोड़कर) और पूर्वी व दक्षिणी योरोप सम्मिलित किये जाते हैं। इन देशों की कुल जन-संख्या लगभग १,६०० मि० है। साधारण रूप से विकसित देशों में सोवियत रूस, दक्षिणी अफ्रीका सह, योरोप के ७ देश, लेटिन अमेरिका के ५ देश, जापान और इसराइल सम्मिलित हैं और इनकी जन-संख्या ४२५ मि० के लगभग है, जबकि अत्यधिक विकसित देशों (उत्तर-पश्चिम योरोप, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड) की जन-संख्या ३७५ मि० है। इस प्रकार विश्व की लगभग २/३ जन-संख्या उन देशों में निवास करती है जो कि मिलकर विश्व आय का १/६ से भी कम भाग पैदा करते हैं। समुक्त-राष्ट्र के सांख्यिकी विभाग के अनुसार विश्व की आधी जन-संख्या १०० डालर से भी कम की प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में रहती है। ६०० डालर वार्षिक से अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में तो विश्व की केवल १/१० जन-संख्या का ही निवास है। अकेले समुक्त राष्ट्र अमेरिका की राष्ट्रीय आय सन् १९५० में कुल विश्व आय का ४०% थी, किन्तु वहाँ विश्व की लगभग ६% जन-संख्या का ही निवास था।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की मौलिक समस्याएँ

एक अर्द्ध-विकसित अर्थ व्यवस्था की अनेक मौलिक समस्याएँ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(१) पूँजी के निर्माण की मन्द गति—एक अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था वाले देश में अधिकांश जनता की आमदनी इतनी कम होती है कि बचत की बात तो दूर रही, वे लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की भी सन्तुष्टि नहीं कर पाते। इनका रहन-सहन का स्तर इतना नीचा होता है कि यदि आय में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाय, तो बचाने की अपेक्षा उसे अतिरिक्त उपभोग में ही प्रयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार पूँजी के निर्माण की गति बहुत धीमी रहती है। सच बात तो यह है कि पूँजी का जो थोड़ा बहुत निर्माण होता भी है वह बड़े ही

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की मौलिक समस्याएँ हैं चार

१. पूँजी के निर्माण की मन्द गति।
२. बेरोजगारी की समस्या।
३. कृषि-क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तनों की समस्या।
४. उद्योग, व्यापार, यातायात एवं सामाजिक सेवाओं का पिछड़ा होना।

विचित्र ढंग से होता है। अर्थ-शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार अधिक विनियोग तभी संभव हो सकता है जबकि अधिक पूँजी हो, पूँजी उसी दशा में अधिक हो सकती है जबकि अधिक वचन हो और अधिक वचन तभी संभव हो सकती है जबकि नियमित रूप से पर्याप्त आय होती रहे। किन्तु आय स्वयं भी विनियोग पर ही निर्भर करती है। अतः जब तक यह विचित्र दूषित चक्र (Vicious Circle) नहीं तोड़ा जाता, तब तक अर्थ-व्यवस्था का विकास आरम्भ नहीं हो सकता।

इस समस्या को हल करने के लिये घाटे के अर्थ-प्रवन्धन की नीति (Policy of Deficit Financing) को अपनाना होगा अथवा विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी।

(२) बेरोजगारी की समस्या—एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी की है। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रायः छिपी हुई बेरोजगारी दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी तब उदय होती है जबकि लोग किसी न किसी पैने या घन्घे में तो लगे हुये हैं, लेकिन उनकी वास्तविक आय उस आय से बहुत कम है जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिये आवश्यक है। उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति मछली पकड़ने के काम में दिन भर लगा रहता है, लेकिन इसमें उसे इतनी कम आय होती है कि एक दिन के लिये भी पर्याप्त नहीं है। यह छिपी हुई बेरोजगारी है। अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रों की रिपोर्टों में छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार की गई है—“अर्द्ध बेरोजगार व्यक्ति वे हैं जो कि अपनी जोलिंग पर कार्य करते हैं और कार्य में सम्बन्धित प्रसाधनों की तुलना में इतनी अधिक संख्या में हैं कि उनमें से अनेक व्यक्तियों को अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिये हटा लिया जाय, तो जिस क्षेत्र से उन्हें हटाया गया है उस क्षेत्र का उत्पादन बहुत प्रभावित नहीं होगा।”^१ डॉ० राव के शब्दों में, “अर्द्ध बेरोजगारी तब विद्यमान कही जाती है जबकि ऐसे मजदूर हो जिन्हें लगातार रोजगार प्राप्त है, किन्तु यदि उन्हें उस कार्य से हटा दिया जाय, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”^२

1 “The disguised unemployed are those persons who work on their own account and who are so numerous, relatively to the resources with which they work in other sectors of the economy, the total output of the sector from which they were withdrawn would not be diminished even though no significant reorganisation occurred in this sector.”

—U N O. Report on Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries.

2 “Disguised unemployment exists when there are workers who are constantly employed in the sense that their time is occupied but whose contribution to output is nil in the sense that their ceasing to work will leave the total output unchanged.”

—Dr. V. K. R. V. Rao

एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था में व्याप्त रूप से पैली हुई अत्यन्त बेरोजगारी को दूर करने का एक उपाय अर्थ-व्यवस्था का पुनर्गठन करना है ।

(३) कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तनों की समस्या—प्रायः सभी अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि-कार्य करने की प्रणाली अत्यन्त प्राचीन एवं अवज्ञानिक है । अधिक्षित, अज्ञानी एवं रुढ़िवादी होने के कारण वे आधुनिकतम साधनों को अपनाने में सकोच करते हैं । अतः अर्द्ध-विकसित देशों में औद्योगीकरण प्रारम्भ करने के पूर्व यह नितान्त आवश्यक है कि वहाँ के कृषि-क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जायें । कृषि के वैज्ञानिक व यन्त्रीकरण के बिना कृषि की उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती । अतएव कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण व वैज्ञानिकता का होना नितान्त आवश्यक है ।

(४) उद्योग, व्यापार, यातायात एवं सामाजिक सेवाओं का पिछड़ा होना—जैसा कि हम ऊपर सकेत कर चुके हैं, अर्द्ध विकसित देशों में समाज-सेवाओं, उद्योग-धन्धों, उन्नत यातायात आदि का प्रायः अभाव होता है । ऐसे क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि कृषि पर से जन-संख्या का भार कम किया जाय एवं कृषि से उद्योग एवं सामाजिक सेवाओं में कृषि श्रमिकों का स्थानान्तरण किया जाय । वास्तव में कृषि-क्रान्ति एवं औद्योगिक क्रान्ति एक दूसरे की पूरक हैं । यदि कृषि-क्रान्ति श्रमिकों को कार्य से मुक्त करती है, तो औद्योगिक क्रान्ति उनके लिए रोजगार के सुप्रसरो में वृद्धि करती है । यही कारण है कि प्रायः सभी अर्द्ध-विकसित देशों की सरकारें औद्योगिक विकास के साथ-साथ कृषि के कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती हैं । यातायात एवं अन्य सामाजिक सेवाओं का भी बहुत अधिक महत्त्व है ; सड़कों एवं रेलों का विकास न होने के कारण लोग परस्पर मिल-जुल नहीं सकते । इससे व्यापार के विकास में भी बाधा होती है और उद्योगों को कच्चा माल मिलने में असुविधा रहती है । यही नहीं, निर्मित माल के लिए पर्याप्त मण्डियाँ भी सुविधा से नहीं मिल पाती । स्वास्थ्य सम्बन्धी दशाओं के ठीक न होने की दशा में लोगों की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है ।

इन दोषों के निवारणार्थ कृषि एवं उद्योग के विवेकीकरण, यातायात की सुविधाओं के विकास व समुचित योजनाकरण की आवश्यकता है ।

औद्योगीकरण ही अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याओं का हल है—

अर्द्ध-विकसित देशों की उपरोक्त समस्याओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगीकरण से इन देशों की उन्नति में बड़ा योग मिल सकता है । कृषि पर जन-संख्या का जो दबाव है वह श्रमिकों को उद्योगों में काम मिल जाने से कम हो जायगा, आर्थिक संस्थाओं का विकास भी होगा, लोगों की आय में वृद्धि हो जायेगी, पूँजी के निर्माण पर इसका सुप्रभाव पड़ेगा, न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वरन्

ग्रहण बेरोजगारी भी घटेगी तथा अर्थ-व्यवस्था का भुकाव पूर्ण रोजगार के स्तर पर सतुलित होने की ओर हो जायगा ।

औद्योगीकरण के विरुद्ध आपत्तियाँ—

अर्द्ध-विकसित देशों के तीव्र औद्योगिक विकास के विरुद्ध कई आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं—

(१) औद्योगीकरण को प्राथमिकता देना आवश्यक है—यह कहा जाता है कि औद्योगीकरण को आर्थिक अवर्धन और दरिद्रता का प्रचुर इलाज नहीं माना जा सकता । इनके अतिरिक्त, उद्योग केवल एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है । अतः यह आवश्यक नहीं है कि अन्य क्रियाओं की अपेक्षा साधनों को अधिकतम उपयोग करने में इसे ही सफलता मिले । वास्तव में औद्योगीकरण के समर्थक इस भ्रम के शिकार हैं कि चूँकि अधिकांश घनाढ्य देश औद्योगिक देश भी हैं इसलिए उनका देश भी घनी बन सकता है, यदि उसका औद्योगीकरण हो जाय । यह तर्क उसी प्रकार त्रुटिपूर्ण है, जिस प्रकार यह कहना कि चूँकि अधिकांश घनाढ्य ध्वत्ति सिंगार पीते हैं इसलिए घनाढ्य बनने के लिए ध्वत्ति की सिंगार पीना चाहिए । इस प्रकार यह सुझाव दिया गया है कि अर्द्ध विकसित देशों को प्रकृति ने कृषि देश ही बनाया है, इनके लिये औद्योगीकरण को प्राथमिकता देना आवश्यक है ।

किन्तु हम औद्योगीकरण के विरुद्ध एक उचित आपत्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जो देश कृषि सम्बन्धी विशेष सुविधायें रखते हों वे औद्योगिक विकास के लिए अनुपयुक्त होंगे । वास्तव में ऐसे देशों में तो अर्थ-व्यवस्था को सतुलित करने के लिए कृषि और उद्योग दोनों के सह-विकास की आवश्यकता विद्यमान होती है ।

(२) औद्योगीकरण को उच्च आय का कारण नहीं माना जा सकता—यह

औद्योगीकरण के विरुद्ध पाँच

आपत्तियाँ

- १ औद्योगीकरण को प्राथमिकता देना आवश्यक है ।
- २ औद्योगीकरण को उच्च वास्तविक आय का कारण नहीं माना जा सकता ।
- ३ कृषि क्षेत्र के विस्तार से कम व्यय पर ही अधिक रोजगार सम्भव है ।
- ४ अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण ।
- ५ विविधमुखी अर्थ-व्यवस्था में अधिक व्यय ।

भी कहा जाता है कि आर्थिक औद्योगिक देशों में वास्तविक आय का ऊँचा स्तर केवल उनके अधिक औद्योगीकरण के कारण ही नहीं है । वास्तविक आय का ऊँचा स्तर तथा अधिक औद्योगीकरण दोनों एक ही घटक के समूह की प्रतिक्रिया का फल है । (ये घटक हैं—सस्ती शक्ति, सम्पन्न खनिज पदार्थ, पूँजी का अण्डार, टेक्निकल योग्यता आदि ।) [लेकिन यह आलोचना भी सही नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि इन

घटकों के समूह को बढ़ावा देने में औद्योगीकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ।]

(३) कृषि क्षेत्र के विस्तार से कम व्यय पर ही अधिक रोजगार संभव है—जन-संख्या का भूमि पर अधिक दबाव होना औद्योगीकरण की अनिवार्यता प्रमाणित नहीं करता है । जो भूमि विशेष परिस्थितियों के कारण बिना जोती हुई पड़ी है उसे भी पूँजी व्यय करके या टेक्नोलोजी अथवा सरकारी नीति के परिवर्तन द्वारा कृषि कार्य में लाया जा सकता है । इसमें अतिरिक्त जन-संख्या को कम व्यय पर ही रोजगार मिल सकेगा, जबकि नये कारखाने खोलकर रोजगार देने में व्यय अधिक करना पड़ता है । [यह तर्क इस मूलतः मान्यता पर आधारित है कि अर्द्ध-विकसित देशों में बहुत सी बिना जोती भूमि पड़ी हुई है । यही नहीं, इस भूमि के विकास के लिए भी कृषि यन्त्र-औजार आदि बनाने के लिए कारखाने खोलने की आवश्यकता होगी ।]

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण की नीति—औद्योगीकरण के विरुद्ध एक तर्क यह भी दिया गया है कि अर्द्ध-विकसित देशों को अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के नियमों के अनुसार प्रारम्भ उत्पादों (primary products) का निर्यात करने की दिशा में ही अपने प्रयत्न केन्द्रित रखने चाहिए और वह माल आयात करना चाहिए जो कि उनके 'संतुलित भोजन' के लिए आवश्यक हो अर्थात् अर्द्ध-विकसित देशों को कच्चा माल निर्यात करना चाहिए तथा निर्मित माल मँगाना चाहिए, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ इसके लिये विशेष रूप में सुविधाजनक हैं । [यह तर्क देने वाले भूल जाते हैं कि कच्चे माल का निर्यात बढ़ाने की दौड़ आरम्भ होने से विश्व-बाजार में मूल्य सम्बन्धी दशाये बिगड़ने की आशंका है ।]

(५) विविध मुखी अर्थ-व्यवस्था का अत्यधिक व्यय—यदि अर्द्ध-विकसित देशों ने अपने घरेलू अर्थ-व्यवस्थाओं को विविधमुखी बनाया, तो इसमें उनका व्यय बहुत होगा तथा अन्त में इस प्रयत्न के अनाधिक प्रमाणित होने की सम्भावना है । इस बात का भी भय है कि उनकी अर्थ-व्यवस्था के विद्यमान ढाँचे में इनने परिवर्तन हो जायेंगे कि वह छिन्न-भिन्न हो सकती है ।

औद्योगीकरण के विरोध में दिये गये उपरोक्त तर्कों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें कोई सार नहीं है । अधिकांश तर्क उन औद्योगिक देशों के अर्थ-शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जो कि विश्व में अपनी ही प्रमुखता बनाये रखना चाहते हैं । लेकिन यह नहीं मूलना चाहिए कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में उन्नत देशों की उन्नति अर्द्ध-विकसित देशों की उन्नति पर ही निर्भर है । वे दिन बीत गये जबकि अर्द्ध विकसित देशों को शोषण का क्षेत्र माना जाता था । अब तो पारस्परिक लाभ के सिद्धान्त का बोलबाला है । अतः आज का नारा 'सब की प्रगति हमारी प्रगति' होना चाहिए । उन्नत देशों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे उन देशों की

उन्नति में सहायता करें जिनके शोषण द्वारा वे उन्नत हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तभी वास्तविक होंगे जबकि वे बराबरी के आधार पर निर्मित होंगे। हर्ष का विषय है कि विश्व के अधिकांश उन्नत देश इस बात को समझने लगे हैं और अर्द्ध-विकसित देशों को यथासम्भव सहायता देने के लिए प्रयत्नशील हैं।

अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण में बाधा डालने वाले तत्त्व—

अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण में जो बाधाएँ सामने आ रही हैं उनको ४ श्रेणियों में वर्गित किया जा सकता है—(1) आर्थिक बाधावरण, (11) सामाजिक कारण, (111) सार्वजनिक प्रशासन, व (1V) अन्तर्राष्ट्रीय कारण। इन पर नीचे विस्तार से प्रकाश डाला गया है—

(अ) आर्थिक बाधावरण—

आर्थिक बाधावरण के अन्तर्गत निम्न औद्योगिक बाधाओं को सम्मिलित किया जाता है—

(१) मौलिक आर्थिक सुविधाओं की अनुपपुक्तता—अर्द्ध-विकसित देशों में

**औद्योगीकरण में बाधा डालने
वाले विभिन्न कारण**

(अ) आर्थिक बाधावरण—

१. मौलिक आर्थिक सुविधाओं की अनुपपुक्तता।

२. जीवन निर्वाह अर्थ-व्यवस्था।

३. घरेलू बाजार की अपर्याप्तता।

(ब) सामाजिक कारण—

१. जनसंख्या सम्बन्धी कारण।

२. योग्य साहसियों की समस्या।

३. धर्म सम्बन्धी सामाजिक बाधाएँ।

४. पूँजी को प्रवाहित करने वाली बाधाएँ।

(स) सार्वजनिक प्रशासन—

(द) अन्तर्राष्ट्रीयकरण—

१. उन्नत देशों पर निर्भरता।

२. औद्योगिक देशों के प्रतिबन्ध।

३. विदेशी पूँजी का प्रवाह।

उद्योगों के विकास के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा वहाँ कुछ मौलिक आर्थिक सुविधाओं का अभाव होना है। उदाहरणार्थ, यातायात की सुविधाओं का इन देशों में अत्यन्त अभाव है। उद्योगों की दृष्टि से यातायात सुविधाओं का विशेष महत्त्व है, क्योंकि कारखानों के लिए कच्चा माल, मशीनें आदि जुटाना तथा फिर निर्मित माल को मण्डियों में भेजने की विकट समस्या होती है। अतः उद्योगों का स्थानीयकरण यातायात-व्यवस्था की उपलब्धि, लागत और प्रभावपूर्णता पर निर्भर होता है। शक्ति एक अन्य सुविधा है, जिसके अभाव में अर्द्ध-विकसित देशों का औद्योगिक विकास रुका पड़ा है। युद्ध-काल में और युद्धोत्तर काल में कारखानों में बिजली से चलने वाली मशीनें लगने के कारण शक्ति का

अभाव बहुत बढ़ गया है। यातायात और शक्ति-साधनों के विकास के लिए भारी मात्रा में विनियोग करने की आवश्यकता होती है तथा इनका धीरे-धीरे विकास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सम्पूर्ण इकाई एकवारगी जमानी पड़ती है। चूँकि अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी की कमी होती है, इसलिए इन सुविधाओं को बढ़ाना एक कठिन बात है। परेलू उद्योगों का विकास बहुत सीमा तक स्थानीय बाजार के आकार पर निर्भर करता है और बाजार का आकार वितरण-व्यवस्था की कुशलता पर निर्भर है। लेकिन व्यापारिक संस्थाओं की अपर्याप्तता न केवल बाजार तक पहुँचने की समस्या को कठिन बनाती है वरन् कच्चे माल की पूर्ति को भी दुर्लभ कर देती है। साज-सामान व मशीनों का दुहरा-तिहरा स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि भरभराई की सुविधाओं का प्रायः अभाव होता है। इसके अतिरिक्त अमिको को कुशल बनाने वाली संस्थाओं तथा पूँजी के संग्रह में सुविधा देने वाले बैंकिंग, बीमा व अन्य सार्वजनिक संस्थानों के अभाव से भी औद्योगीकरण में बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं।

(२) जीवन निर्वाह अर्थ-व्यवस्था—अर्द्ध-विकसित देशों में प्रायः जीवन निर्वाह भर के लिये ही उत्पादन किया जाता है। इसमें अमिको के विशिष्टीकरण की मात्रा बहुत थोड़ी होती है तथा वे औद्योगिक चतुराई वाले धंधों को अपना देने के अयोग्य होते हैं। उनकी आय थोड़ी होने से वे औद्योगिक उत्पादन को खरीदने में भी असमर्थ होते हैं। विनिमय अर्थ-व्यवस्था के अभाव के कारण अर्द्ध-विकसित देशों की अधिकांश जन-संख्या उन्नत देशों की अपेक्षा बहुत कम उत्पादक, बहुत कम शिक्षित, बहुत अधिक गरीब तथा बहुत कम समायोजनीय होती है। इन्हीं बातों के कारण अर्द्ध-विकसित देशों का औद्योगिक विकास उचित गति से नहीं होने पाता।

(३) घरेलू बाजार की अपर्याप्तता—अर्द्ध-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बहुत कम होती है। आय कम होने के कारण लोग अपने उपभोग पर अधिक व्यय नहीं कर पाते। फल यह होता है कि निर्मित वस्तुओं का बाजार अत्यन्त सीमित हो जाता है। बाजार का सीमित होना तीन तरीकों से औद्योगिक विकास पर प्रभाव डालता है : (i) औद्योगिक पूँजी के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता है, (ii) प्लांट का आकार छोटा रखना पड़ता है, जिससे बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययताओं का लाभ उठाने का अवसर नहीं मिलता, और (iii) वस्तुओं की मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाजारों के लिये प्रायः घटिया व इनी-गिनी किस्मों का उत्पादन किया जाता है।

(४) सामाजिक कारण—

अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण पर सामाजिक कारणों का प्रभाव भी कुछ कम नहीं पड़ता है। सामाजिक कारणों को इस प्रकार बताया जा सकता है—

(१) जन-संख्या सम्बन्धी कारण—एक कम पूँजी और प्रति व्यक्ति कम आय वाले देश में जन-संख्या की तेजी से वृद्धि होना औद्योगिक विकास के लिये बचत व

विनियोग करने की कठिनाइयों में वृद्धि कर देता है। ये कठिनाइयाँ निम्न ५ तरीकों से उदय होती हैं (i) प्रति वर्ष नई पूँजी का काफी भाग प्रति व्यक्ति पूँजी सम्पत्तियों के विद्यमान स्तर को बनाये रखने में ही खर्च कर देना पड़ता है, जिसमें नया औद्योगिक विनियोग के लिए कुछ भी नहीं बचना। (ii) जिन देशों में जन्म-दर बहुत ऊँची है वहाँ उसकी जन-संख्या का बहुत थोड़ा भाग उस आयु-सीमा में होता है, जिसमें व्यक्ति अधिक क्षमता से काम कर सकता है। उत्पादक जन-संख्या की इस सापेक्षिक कमी के कारण उपभोग पर उत्पादन का आधिक्य बहुत थोड़ा बन पाता है। (iii) जन संख्या के बढ़ने की तीव्र गति के प्रभाव उस देश में अधिक भयकर रूप धारण कर लेते हैं जहाँ भूमि सम्बन्धी साधन जन-संख्या की तुलना में कम होते हैं। ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन बहुत कम होता है, जिसमें औसत आय कम रहती है, निर्मित वस्तुओं की माँग बहुत कम होती है और बचत भी कम हो जाती है। इस प्रकार जन-संख्या की तेजी से वृद्धि उपलब्ध पूँजी की मात्रा को घटा कर कम आय वाले देशों के औद्योगीकरण में बाधा डालती है। ऐसे देशों में भोजन पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन की कमी रहती है।

(२) योग्य साहसियों का अभाव—अर्द्ध-विकसित देशों में सामाजिक रचना की विषमताओं के कारण औद्योगिक नेताओं का अभाव होता है। भारत की जाति-प्रथा इस विषय में एक ज्वलन्त उदाहरण है, जिसके अन्तर्गत निम्न जाति के व्यक्तियों को उच्च धन्य करने की स्वतन्त्रता नहीं है, भले ही वे इनके लिए उपयुक्त हों। इस प्रकार सही नेतृत्व से वंचित रहना पड़ता है। कुछ काम विदेशी ही करते आये हैं और स्थानीय जनता उन्हें अपनाने में सकोच अनुभव करती है। आचार-विचार भी औद्योगिक साहस के विकास में बाधक होते हैं। स्वाधरता की भावना भी लोगों को व्यापक दृष्टि में विचार करने में रोकती है और उद्योगों के संचालन में वे सकीर्णता में काम लेते हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि आय का अधिक भाग अपने लिये ही रख लें, धर्मिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी देने की चिन्ता उन्हें नहीं होती। अर्द्ध-विकसित देशों में जमींदार, सामन्त, जागीरदार आदि प्रकृति से ही स्वार्थी होते हैं। वे उत्पादन की टेक्नीक में सुधार करके अपनी आय बढ़ाने के बजाय लगान बढ़ाने को ही अन्धता समझते हैं। अतः ऐसे समाज में जब उद्योगों की स्थापना की जायगी, तो उनमें वह गति न होगी जो कि उन्नत देशों के उद्योगों व उद्योगपतियों में देखी जाती है। एक नया उद्योगपति सम्पूर्ण टेक्नीक को अपनी प्राइवेट सम्पत्ति मानेगा और अन्य लोगों में उसका प्रसार करने के लिए प्रयत्नशील न होगा। यदि सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत भी उद्योगों की स्थापना की जाय, तो साहस सम्बन्धी उक्त समस्याओं में कोई विशेष सुधार होने की आशा नहीं की जा सकती है।

(३) श्रम सम्बन्धी सामाजिक बाधाएँ—श्रम सम्बन्धी निम्न सामाजिक कारण भी अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण में बाधा डालते हैं:—(i) शिक्षा का अभाव होने से श्रमिक अपने आपको पँवटरी कार्य से समायोजित करने में तो असमर्थ रहता ही है, साथ ही वह नगरी जीवन में घुलने-मिलने में भी कठिनाई अनुभव करता है। (ii) श्रमिकों का घिरा हुआ स्वास्थ्य उनकी उत्पादन क्षमता का कम करता है तथा अनुपस्थितियों में वृद्धि करता है। (iii) सामाजिक बन्धनों के कारण उनकी गतिशीलता में भी बाधा पड़ती है। (iv) अमौद्रिक प्रकार के आर्थिक वातावरण में रहने वाले श्रमिक परम्परागत पुरष्कार से, जो कि उन्हें वस्तुमा के रूप में मिलता है, सतुष्ट रहते हैं तथा बारस्तानों में नकद मजदूरी पर जाकर काम करने की प्रच्छा नहीं समझते। इस प्रकार श्रमिकों की पूर्ति सीमित हो जाती है। विचित्र सामाजिक वातावरण के कारण अर्द्ध-विकसित देशों में उद्योगों को स्थायी श्रमिक वर्ग उपलब्ध नहीं होने पाता। नये श्रमिकों को ट्रेनिंग देने में उनका पैसा बेकार हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग पाने के बाद श्रमिक काम छोड़ कर नहीं जायेगे, इसकी गारण्टी नहीं होती है।

(४) पूँजी सम्बन्धी सामाजिक कारण—अर्द्ध-विकसित देशों का सामाजिक वातावरण पूँजी के संग्रह एवं प्रयोग करने में बाधक प्रमाणित हुआ है—(i) इने-गिने धनिक व्यक्तियों को जो अधिक आय हाती है उसे वे शानदार खान-पान में या स्थानीय मनोरंजनों में अथवा विलासिता की वस्तुमा पर खर्च कर देते हैं। इस परम्परागत प्रवृत्ति के कारण समाज के उत्पादक प्रयासों द्वारा जो थोड़ी-बहुत अतिरिक्त आय हाती है वह भी औद्योगिक पूँजी में परिणित नहीं हो पाती। (ii) अधिकांश अर्द्ध विकसित देशों में भूमि के स्वामित्व को बहुत सामाजिक महत्त्व प्राप्त है। परिणाम-स्वरूप बचत का काफी भाग भूमि के क्रय में व्यय कर दिया जाता है। सुरक्षा व सरलता के दृष्टिकोण से बचत को मुद्रा के रूप में ही संचित करके रखने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।

सामाजिक कारणों के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अर्द्ध-विकसित देशों का औद्योगीकरण करने के लिये सामाजिक परिवर्तनों को भी महत्त्व देना होगा।¹

1 "Industrialisation is not merely a technological revolution, it involves profound social changes which must be fully taken into account if the process is to result in higher material standard and a greater degree of human welfare"

(स) सार्वजनिक प्रशासन—

सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration) के दोष भी औद्योगिक विकास में बाधक पाये गये हैं। अनेक अर्द्ध-विकसित देशों में योग्य सिविल सर्विस (Civil Service) का संगठन करना एक कठिन समस्या होती है, जबकि अकुशल या अर्द्ध-कुशल सिविल सर्विस साम की जगह हानि ही अधिक पहुँचा सकती है, क्योंकि एक अकुशल सिविल सर्विस अधिकारी औद्योगिक विकास का उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने में असमर्थ रहता है। यदि सार्वजनिक प्रशासन योग्य और ईमानदार है तो इसका अर्थ-व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसमें स्थिरता आने लगती है। किन्तु इसका अभाव आर्थिक पहलपन (economic initiative) की भावना को गम्भीर ठेस पहुँचा सकता है। अर्द्ध-विकसित देशों में औद्योगिक जानकारी का अभाव होने से भी सरकारी कार्यक्रमों की उपयोगिता कम हो गई है। इसके प्रतिरिक्त सरकार द्वारा भनमाने कदम उठा लेने, कर-नीति में अचानक और बार-बार परिवर्तन कर देने, विदेशी व्यापार सम्बन्धी नियन्त्रणों जुगी, उत्पादन-करो आदि में जब चाहे तब घटा-बढ़ी कर देने ने भी वित्तियोगों को बहुत विस्तृत किया है। मुद्राविज्ञा के बिना औद्योगिक सम्पत्ति छिन जाने की आशंका से असुरक्षा की भावना अधिक बढ़ जाती है। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने की नीति में कड़ाई अपनाना भी औद्योगिक विकास को ठस पहुँचाता है। कभी-कभी अम कानून इस प्रकार लागू किये जाते हैं कि सेवायोजकों के लिये अपने उद्घण्ड व अकुशल कर्मचारियों को भी अलग करना बहुत कठिन हो जाता है। इससे औद्योगिक प्रगति में बहुत बाधा पड़ती है। अनेक अर्द्ध-विकसित देशों में सार्वजनिक प्रशासन के फलस्वरूप अत्यधिक केन्द्रीयकरण भी हो गया है, जिससे सरकार के विभिन्न अंगों पर बहुत भार पड़ा है। जिन देशों में सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी भी ले ली है वहाँ तो इसके नागरिक प्रशासन सेवा अधिकारियों का कार्य बहुत ही बढ़ गया है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय कारण—

निम्न अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी, जो कि उनके नियन्त्रण के बाहर हैं, अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण में बाधक सिद्ध हुई हैं। अर्द्ध-विकसित देशों को अपने पूँजीगत सामान के लिय औद्योगिक देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे पूँजीगत सामान की कमी समय-समय पर उनके औद्योगिक विकास में बाधाएँ डालती

रहती है। यह कभी विदेशों से प्रायः निम्न कारणों से पूरी नहीं होने पाती है :—
 (1) कभी-कभी औद्योगिक देश नई मशीनों के निर्यात को जान-बूझ कर रोक देते हैं, ताकि उनके लिये प्रतिद्वन्द्विता पैदा न हो सके, (ii) कुछ दशाओं में अर्द्ध-विकसित देशों के निर्माताओं को भी नवीनतम मशीनों के विषय में पर्याप्त सूचना नहीं होती है, (iii) औद्योगिक देश कभी-कभी निजी आवश्यकताओं के दबाव के कारण भी अपने आश्रित अर्द्ध विकसित देशों की पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी करने में असमर्थ हो जाते हैं, (iv) अर्द्ध-विकसित देशों को विदेशों से पूँजीगत सामान प्राप्त करने में बहुत व्यय करना पड़ता है, क्योंकि उनके यातायात साधन अधिक विकसित नहीं होते हैं, (v) कभी-कभी पूँजीगत सामान (मशीनों) की रचना उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होती है, (vi) अर्द्ध विकसित देश प्रायः विकसित देशों की अपेक्षा टेक्नीकल प्रगति में बहुत पीछे होते हैं, (vii) विदेशों से मँगवाई हुई मशीनों द्वारा उपयोग में आने वाला विशेष कच्चा माल भी कभी-कभी आयातक देश में उपलब्ध नहीं होता, (viii) औद्योगिक देशों में नई मशीनों के पेटेंट करा लिये जाते हैं, (ix) विकसित देशों की प्रतियोगिता देशी उद्योगों के लिये बहुत असहनीय होती है।

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उपाय

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपायों व नीतियों का सुझाव दिया जाता है। किस विशेष उपाय अथवा नीति को अपनाया जाय, यह प्रत्येक अर्द्ध-विकसित देश की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। किन्तु इतना निश्चित है कि औद्योगिक विकास का कोई प्रभावपूर्ण कार्यक्रम बनाने के लिए कई उपयुक्त नीतियों व उपायों के एक साथ अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाले विभिन्न उपायों को दो मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—(1) घरेलू उपाय, एवं (2) अन्तर्राष्ट्रीय उपाय। नीचे इन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

(अ) घरेलू उपाय (Domestic Measures)—

घरेलू उपायों के अन्तर्गत हम उन उपायों को सम्मिलित करते हैं जो कि उत्पादन के साधनों के प्रवाह की वृद्धि से, टेक्नोलोजिकल उन्नति की समस्याओं व राज्य की नीतियों से सम्बन्ध रखते हैं।

(१) उत्पादन के साधनों के प्रवाह में वृद्धि—

उत्पादन के साधनों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—(१) साहसी

अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाले उपाय

(अ) घरेलू उपाय—

(१) उत्पादन के साधनों के प्रवाह में वृद्धि—

(१) साहसियों की वापस।

(11) प्लान्ट, साज-सामान व अन्य पूँजी।

(111) श्रम आदि।

(1V) कच्चा माल व प्राकृतिक साधन।

(२) उत्पादन-टैक्नीक में सुधार

(३) राज्य-नीतियाँ •

(1) प्रचुल्ल नीति

(11) साख नीति।

(111) मुद्रागत समतुल्य सम्बन्धी नीति।

(1V) औद्योगिक नियोजन।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय उपाय—

(१) उसम देशों का सहयोग •

(1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार।

(11) अन्तर्राष्ट्रीय आवास-प्रवास।

(111) पूँजी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह।

(1V) टेक्नीकल सहायता।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग।

मे बाँटा जा सकता है—(१) साहसी कुशलता, (11) प्लान्ट, साज-सामान व ग्रन्थ पूँजी, (111) श्रम आदि एवं (1V) कच्चा माल व ग्रन्थ प्राकृतिक साधन।

(1) साहसी-कुशलता (Enterpreneurial Ability) साहसी के चार प्रमुख कार्य हैं—व्यापार की स्थापना, पूँजी की पूर्ति, जोखिम उठाना तथा प्रबन्ध संचालन। उन्नत देशों में अलग-अलग व्यक्ति इन कामों को करते हैं, लेकिन अर्द्ध-विकसित देशों में एक ही व्यक्ति को ये सारे कार्य करने पड़ते हैं, और, चूँकि कई बातों का अनुभव व ज्ञान न होते हुए भी उसे सम्पूर्ण जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसलिए उसे बहुत जोखिम का सामना करना पड़ता है। साहसियों को इस समस्या के दो पहलू हैं—

(१) उनकी ट्रेनिंग की इन देशों में कोई व्यवस्था नहीं होती है तथा वहाँ का आर्थिक वातावरण भी इनके लिए उत्साहप्रद नहीं होता, और

(२) यदि ऐसे व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हो तो भी उनके कार्य की जटिलता में कमी नहीं आ सकती है। वास्तव में एक विषम चक्र सा स्थापित हो गया है, क्योंकि आर्थिक विनाश बहुत कुछ साहसियों की कुशलता पर निर्भर करता है और साहसियों की कुशलता आर्थिक विकास

द्वारा प्राप्त अनुभव पर निर्भर होती है। इस विषय चक्र को निम्न उपायों द्वारा तोड़ा जा सकता है—(अ) सामान्य व टैक्नीकल शिक्षा की सुविधायें देकर शिक्षा । स्तर ऊँचा किया जाय, (ब) औद्योगिक विकास निगम जैसी संस्थाएँ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दें, जिन्हें साहसियों को विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त होने लगे, (स) सरकार स्वयं भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करके साहसियों के अभाव की पूर्ति करे। जिन उद्योगों में विशाल विनियोग करना पड़ता है अथवा ऐसा सामान उत्पन्न किया जाता है जोकि सरकार के उपयोग में आया अथवा राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों में, सरकार को विशेष रूप से पहल करनी चाहिए। जैसे-जैसे आर्थिक विकास की गति बढ़ती जायगी वैसे वैसे योग्य साहसी अधिकाधिक संख्या में उपलब्ध होने लगेंगे। लेकिन यह स्मरणीय है कि सरकार द्वारा साहसी की भूमिका बढ़ा करने से प्रबन्ध की समस्या हल नहीं हो जायगी। योग्य प्रबन्धकों का अभाव सरकारी योजना को व्यर्थ कर सकता है। अतः सरकार को साथ ही साथ प्रबन्ध व साहस की ट्रैनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्थानीय साहस का अधिकतम उपयोग करना होगा तथा विदेशी साहस को भी आमन्त्रित करना होगा।

(11) पूँजी (Capital)—निर्माणी उद्योगों के लिए कृषि या व्यापारिक फर्मों की अपेक्षा अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु एक अर्द्ध-विकसित देश में औद्योगिक पूँजी का नितान्त अभाव होता है, क्योंकि (अ) अधिकांश जनता को आय और व्यय के मध्य बिलकुल भौजिन नहीं रहता या बहुत थोड़ा रहता है, (आ) बहुत थोड़े व्यक्तियों को नियमित आय प्राप्त होती है, (इ) जन-संख्या में उस आय के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी होती है जो कि कुछ बचत कर सकता है, क्योंकि जन्म-दर व मृत्यु-दर बहुत ऊँची हुआ करती है, (ई) आय का वितरण भी बहुत असमान होता है, चूँकि अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी की बहुत कमी होती है, इसलिये साहसी ऐसे उद्योग ही अधिक स्थापित करते हैं जिनमें पूँजी की कम आवश्यकता हो। प्रायः उपभोग वस्तुयें बनाने वाले उद्योग ही खाले जाते हैं, क्योंकि इनमें पूँजी की कम किन्तु धन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यदि अर्द्ध-विकसित देश अपने यहाँ पूँजी की कमी दूर करने के लिये विशेष संस्थाएँ स्थापित कर लें, तो उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। निस्संदेह यह कार्य सरल नहीं होगा, किन्तु इस सुझाव का तात्पर्य यह है कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना के लिये प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहन देना चाहिये। इन संस्थाओं के संचालन की सुविधा के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार प्राइवेट विनियोगकों को सयुक्त या मिश्रित इकाइयों में सहयोग देने के लिये अपनी गारन्टी प्रदान करके प्रोत्साहित कर सकती है, विकास निगमों की स्थापना कर सकती है और न्यूनतम आय की गारन्टी दे सकती है।

(iii) श्रम (Labour)—श्रौद्योगीकरण कार्य-श्रम के उपयुक्त एक श्रम-नीति के दो उद्देश्य होने चाहिये—अधिक जनता की ट्रेनिंग का स्तर ऊँचा उठाना तथा भौगोलिक गतिशीलता में वृद्धि करना। अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में सरकार चार तरीकों से उद्योगों को श्रमिक प्राप्त करने में सहायता कर सकती है—(अ) आन्तरिक भर्तों का मगहन व निरीक्षण, (ब) उपयुक्त श्रमिकों की विदेशों से भर्ती, (स) रोजगार कार्यालयों की स्थापना, और (द) पर्याप्त शैक्षिक एवं ट्रेनिंग सुविधाओं की व्यवस्था।

(iv) कच्चा माल एवं प्राकृतिक प्रसाधन (Raw Materials and Natural Resources)—वभिन्न देशों के औद्योगिक विकास में भिन्नता होने का एक कारण स्थानीय प्रसाधनों की मात्रा, किस्म एवं उपलब्धता में भिन्नता होना है। प्राकृतिक साधनों का प्रभाव औद्योगीकरण में बहुत बड़ी भिन्नता है। इसे दूर करने के लिए सरकार जो भी उपाय करेगी उससे औद्योगीकरण में सुविधा ही होगी। सरकार इस सम्बन्ध में निम्न उपाय कर सकती है—(अ) खनिज, जल-शक्ति, मिट्टी, लकड़ी आदि प्राकृतिक प्रसाधनों को सर्वे करावे, (आ) प्रसाधनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में प्राइवेट व्यक्तियों, फर्मों, विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनुसंधान की व्यवस्था की जाय, (इ) कच्चा माल उत्पादन करने वाले साधनों की कुशलता में वृद्धि करके उसकी किस्म व मात्रा में वृद्धि की जाय, (ई) कच्चे माल की कीमत को घटाने के लिए खनिज-कर्म एवं कृषि-रायों की उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए, (उ) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों से बचने के लिए यथासम्भव घरेलू कच्चे माल का ही प्रयोग करना चाहिए, भले ही कुछ अधिक व्यय पड़ जाय। ऐसी दशा में घरेलू कच्चा माल उत्पादन करने वालों का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपनी कुशलता में वृद्धि करके उद्योगों की सहायता करें।

(२) उत्पादन करने की टैक्नीक में सुधार—

अनुकूलतम परिमाण की फर्में स्थापित करके औद्योगीकरण की गति को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बाजार के क्षेत्र के अनुसार फर्म के उत्पादन का पैमाना निश्चित किया जाय। फर्म के आकार में इस प्रकार का संशोधन करने के लिए यन्त्रीकरण को कम करना पड़ सकता है। औद्योगिक देशों के लिए ऐसा करना एक प्रतिक्रियावादी कदम होगा, लेकिन अर्द्ध-विकसित देशों के लिए यह बहुत उचित कदम है। सामान्यतः लागत के दृष्टिकोण से पूँजी का अपेक्षित कम प्रयोग करना आवश्यक होगा। स्थानीय कच्चे माल की विशेषताओं के अनुसार प्लान्ट में कुछ टैक्नीकल परिवर्तन करना भी आवश्यक हो सकता है। स्थानीय श्रमिकों में कुशलता व अनुभव की कमी को ध्यान में रखते हुए जटिल मशीनों की अपेक्षा साधारण मशीनों का प्रयोग करना अधिक उपयोगी प्रमाणित होगा। यद्यपि उत्पादन की प्रक्रिया में संशोधन करने की कुछ टैक्नीकल सीमाएँ होती हैं तथापि इन सीमाओं

के भीतर ही उत्पादन का पैमाना कुछ संशोधित करने से बहुत लाभ होने की सम्भावना है। एक उन्नत देश के लिए जो प्लान्ट बनाया गया है उसे ज्यों का त्यों एक अर्द्ध-विकसित देश में प्रयोग किये जाने से अनेक अड़चनें पैदा हो सकती हैं जैसे अनावश्यक टूट-फूट, बरबादी, पूँजी का दुरुपयोग। इन समस्याओं का हल तभी हो सकता है जबकि उत्पादन की टैक्नीक में उपयुक्त सुधार कर लिये जायें। इस सम्बन्ध में अनुमन्त्रान के लिए बहुत क्षेत्र है, जिसका वैज्ञानिकों, इंजीनियरों व टैक्नीकल विशेषज्ञों को लाभ उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि लघु व कुटीर उद्योगों में आधुनिक टैक्नीक का प्रयोग करने से बहुत लाभ हो सकता है। इन उद्योगों के द्वारा अर्द्ध-विकसित देशों में, जिन्होंने अभी हाल में ही विनिमय अर्थ व्यवस्था में प्रवेश किया है, औद्योगिक संगठन व टैक्नीक का सुविधा से विस्तार किया जा सकता है। यदि इनको व्यापक फ्रंट पर औद्योगिक प्रगति के साथ समन्वित नहीं किया गया, तो ये कम से कम उस देश में जहाँ अधिकांश जन-संख्या इन पर निर्भर है, उद्योग के आधुनिक प्ररूपों के विकास में रोड़ा अटक सकते हैं।

(३) राज्य की नीतियाँ (State Policies) —

इन नीतियों के अन्तर्गत सरकार की उन प्रत्यक्ष कार्यवाहियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका उद्देश्य उत्पादन के साधनों के उचित प्रवाह में पड़ी हुई बाधाओं को हटाना है। ये नीतियाँ निम्नलिखित हैं:—

(1) प्रशुल्क नीति (Fiscal Policy)—एक स्वस्थ प्रशुल्क नीति का उद्देश्य, जो कि औद्योगीकरण के प्रोत्साहन के लिए निर्धारित की जाय, नई व पुरानी दोनों ही औद्योगिक संस्थाओं में विनियोग की वृद्धि करना, अनुत्पादक कार्यों में सट्टे की प्रकृति के विनियोग को निरस्त/रहित करना और उद्योगों में सलग्न उत्पादन के साधनों की उत्पादकता को बढ़ाना होना चाहिए। लाभ को निकाल कर ले जाने के बजाय उद्योग में ही फिर से विनियोग कर देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आय-कर से कुछ छूट दी जा सकती है। ऐसी प्राथुलिक युक्तिगों की जायें जिनसे बचत करने वाले व्यक्तियों को समुक्त स्कन्धीय औद्योगिक संस्थाओं की पूँजी में भाग लेने का प्रोत्साहन मिले तथा एक स्थानीय पूँजी-बाजार का निर्माण हो। यह स्मरणीय है कि कर सम्बन्धी प्रोत्साहनों का सरकार की आय पर और इस कारण विकास योजनाओं के अर्थ-प्रबन्धन पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः उनकी उपयुक्तता पर सावधानी से सोच-विचार करना चाहिए।

(11) साख-नीति—अर्द्ध-विकसित देशों में सरकार को चाहिए कि मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों की रोक-थाम के लिए जो कि अत्यधिक विनियोग वाले औद्योगिक विकास-कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित करने की अवधि में प्रायः उत्पन्न हो जाया करती हैं,

साख नीति का उचित प्रकार से नियमन करे। दुर्भाग्य से अर्द्ध-विकसित देशों में मुद्रा बाजार इतना असंगठित होता है कि उस पर सही-सही नियन्त्रण स्थापित करना कठिन होता है। फिर भी औद्योगिक विकास के लिए साख प्रसार की नीति तो अपनानी ही पड़नी है। साख प्रसार की नीति को, मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों के खतरनाक बनने के पहले, किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा सकता है, यह कई बातों पर निर्भर है, जैसे— देश के निष्क्रिय प्रसाधनों की प्रकृति, उसकी निर्यात क्रियाओं की क्षमता, उसकी औद्योगिक परम्परा आदि। साख का प्रसार करने की नीति को अपनाने समय बजट एवं भुगतान सतुलन सम्बन्धी तत्त्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे औद्योगिक कार्यक्रम द्वारा उत्पन्न की हुई मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति को नियन्त्रण में रखा जा सके।

(111) भुगतान-सतुलन सम्बन्धी नीति—विभिन्न अर्द्ध-विकसित देशों की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत अन्तर पाया जाता है, इसलिये सब के लिये किसी एक भुगतान सतुलन सम्बन्धी नीति का सुझाव नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक देश को अपना बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कोई उपयुक्त नीति निश्चित करनी होगी। औद्योगीकरण योजना के कारण भुगतान सतुलन में जो प्रारम्भिक घाटा हो उसे विदेशों से ऋण लेकर पूरा किया जा सकता है। इसमें निश्चय ही बाद की दशा पर बहुत उत्तर-दायित्व आ जायगा, जबकि उस यह धन व्याज सहित लौटाना होगा। लेकिन, देश को इस भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यदि उधार ली गई पूँजी को निर्यात करने वाले उद्योगों में अथवा आयात की आवश्यकता को कम करने वाले उद्योगों में लगाया गया है, तो देश की आर्थिक अवस्था पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी होगी। औद्योगीकरण के कारण भुगतान सतुलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ तो उस दशा में पैदा होती हैं जबकि विकसित होने वाले उद्योग विक्रय योग्य मूल्य पर माल पैदा करने में अनुकूल प्रमाणित हो अथवा यदि घरेलू बचत की तुलना में अधिक विनियोग कर दिया गया हो। उपयुक्त भुगतान सतुलन की स्थापना के लिये विदेशी विनिमय की माँग करने वाले नये उद्योगों पर नियन्त्रण लगाना अथवा विनिमय नियन्त्रण को समुचित व्यवस्था करना इतना अच्छा उपाय नहीं है जितना कि मौद्रिक स्थिरता और कुशल विनियोग की दिशा में प्रयत्न करना है।

(1V) औद्योगिक नियोजन—औद्योगीकरण में अर्थ-व्यवस्था तो विविधमुखी (Diversified) बन सकती है, लेकिन इसमें ही औद्योगिक विकास की नीति का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। यदि औद्योगीकरण का कार्यक्रम अनियोजित ढंग से कार्यान्वित किया गया, तो उसमें निम्न स्तर पैदा होने की आशंका है—साधनों का दुरुपयोग व वास्तविक आय में कमी आना, एकाधिकारों का निर्माण, भुगतान सतुलन की स्थिति बिगड़ना, मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का उत्पन्न होना। अतः यह आवश्यक है

कि औद्योगिक विकास की एक योजना बनाई जाय और निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाय—अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों का संतुलित विकास; औद्योगिक विकास की उचित गति, उद्योगों की स्थापना में प्राथमिकता का क्रम और औद्योगीकरण की उचित सीमा ।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय उपाय—

अन्तर्राष्ट्रीय उपायों के अन्तर्गत उन्नत देशों द्वारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दिये जाने वाले सहयोग को सम्मिलित किया जाता है । इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है ।

(१) उन्नत देशों का सहयोग—

विश्व के औद्योगिक देश वस्तु एवं साधनों के आदान-प्रदान द्वारा अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण को प्रभावित कर सकते हैं । इस प्रभाव का अध्ययन निम्न चार शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—अर्द्ध-विकसित देशों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार औद्योगीकरण का एक प्रमुख जरिया है । इसकी सफलता प्रत्यक्ष रूप से निर्यात की गई वस्तुओं की प्रकृति, निर्यात से होने वाली आय, करैन्सी जिसमें कि आय प्राप्त होनी है, इस आय की स्थिरता, आयान की गई वस्तुओं का स्वभाव व व्यापार की शर्तों पर तथा अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी के आगमन और आन्तरिक मौद्रिक स्थिरता पर निर्भर होती है ।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय आवास-प्रवास—देश में बाहर से आकर बसने वाले व्यक्ति प्रायः अधिक ज्ञान, योग्यता व पूँजी रखते हैं, जिससे अर्द्ध विकसित देश की समस्याओं का वे अच्छी तरह सामना कर सकते हैं । उन्होंने विद्यमान उद्योगों में नई टेक्नीक का प्रचलन किया है, पूर्णतः नये उद्योग भी स्थापित किये हैं तथा देशवासियों ने भी उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष प्रकार के नये उद्योग आरम्भ किये । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आवास-प्रवास का औद्योगीकरण पर गहरा असर पड़ता है ।

(iii) पूँजी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह—विदेशी पूँजी के आगमन से दो उद्देश्य पूरे होते हैं—(१) इसकी सहायता से उद्योगों में विनियोग करने के लिये स्थानीय साधन खरीदे जा सकते हैं और (२) विदेशी साधनों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक विनिमय उपलब्ध हो जाता है । विदेशी पूँजी धरेलू पूँजी के संकोच को दूर करती है और उसे अपने साथ औद्योगिक संस्थाओं के प्रवर्तन में भाग लेने को प्रोत्साहित करती है । उदाहरण के लिये, भारत में कई नये उपक्रम विदेशी विनियोगकों द्वारा आरम्भ किये गए और इनमें भारतीय पूँजी ने भी सहयोग दिया ।

(iv) टेक्निकल सहायता—उन्नत देश कम विकसित देशों को टेक्निकल सहायता देकर भी उन्हें औद्योगीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं । इस टेक्निकल

सहायता के दो रूप हो सकते हैं—अपने यहाँ के विशेषज्ञों की सेवाएँ उधार देना तथा उनके कर्मचारियों की विशिष्ट ट्रेनिंग के लिये अपने यहाँ सुविधायें देना ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग—

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण में बहुत महत्वपूर्ण सहायता पहुँचा सकते हैं, जिसके निम्न तरीके हो सकते हैं—वित्तीय अथवा टेक्नीकल सहायता देना, विचार-विमर्श के अवसरों की व्यवस्था करना, विभिन्न देशों के अनुभव एक दूसरे को प्रसारित करना व अनुसन्धान की व्यवस्था करना । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक विकास के लिये विशेष समुक्त राष्ट्रीय फण्ड अर्द्ध-विकसित देशों को उनके औद्योगीकरण में अपूर्व सहायता दे सकते हैं और दे रहे हैं, किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साधन बहुत सीमित हैं । इसलिए इसका समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है ।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Define an 'underdeveloped economy' What are the principal characteristics of such an economy ?
- 2 Discuss carefully the basic problems of underdeveloped countries How can they be solved ?
- 3 What are the forces inhibiting the industrialisation of underdeveloped countries ? Suggest measures conducive to their industrialisation

अध्याय ३

प्राचीन युग में भारतीय उद्योग

(Indian Industry In The Past)

भारतीय उद्योग—सन् १८५७ से पूर्व—

भारतीय उद्योगों का अतीत अत्यन्त गौरवमय रहा है । १९वीं शताब्दी के आरम्भ में, हमारे उद्योग-धन्धे उन्नति के शिखर पर थे और हमारे देश का बना हुआ माल दुनियाँ के कोन-कोने में निर्यात किया जाता था । इतिहास हमारे गौरवमय अतीत के प्रमाणों

मे भरा पड़ा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जातक कहानियों तथा मिलिन्द पान्थ आदि ग्रन्थों में प्राचीन भारत की औद्योगिक अवस्था की भलक मिलती है। हीरोडोटस नामक यूनानी लेखक (४८५ ई० पूर्व) का कथन है कि भारत में उत्तम कोटि की कपास जो कि भेड़ की उन से भी श्रेष्ठ है, भारतीयों के वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग की जाती है। मैगस्थनीज के अनुसार भी, "भारतीय अच्छे पदार्थों तथा आभूषणों को पसन्द करते हैं। उनके वस्त्रों पर सुनहला काम होता है तथा बहुमूल्य रत्न जड़े जाते हैं।" १३वीं शताब्दी में श्री मार्कोपोलो हमारे देश में आया था, उसके कथनानुसार "प्राचीन भारत एशिया का सबसे प्रसिद्ध बाजार था।" सन् १६१८ के औद्योगिक आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि—"जिम समय आधुनिक उद्योग-धन्धों की जन्मभूमि पश्चिमी योरोप में अस्म्य जातियाँ निवास करती थी, उस समय भारतवर्ष अपने शासकों की सम्पत्ति व शिल्पियों की उच्चकोटि की कला के लिए प्रसिद्ध था।"

इसी बात की पुष्टि एडवर्ड थॉर्न्टन नामक अर्थज्ञ इतिहासकार ने भी की है, जो यह लिखता है कि, 'नील नदी की घाटी में जब परामिड देखने को न मिलते थे, जब आधुनिक सम्यता के केन्द्र इटली व ग्रीस जगती अवस्था में थे, उस समय भारत वैभव और सम्पत्ति का केन्द्र था।'^१ ह्येनसाग ने ६३० ई० में लिखा था कि सम्राट हर्षवर्द्धन ने प्रयाग में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर सहस्रों रत्नजटित देशी वस्त्र चढ़ाय थे। इसी प्रकार अध्यापक बेवर का कथन है, 'बहुत प्राचीन काल से बारीक कपड़ा बुनने, रंगों का मिश्रण करने, धातुओं और बहुमूल्य रत्नों पर काम करने और इसी भाँति अन्य प्रकार की कलाओं में निपुणता दिखाने में भारतवर्ष के शिल्पी विश्व में प्रसिद्ध रह रहे हैं।' इस प्राचीन इतिहास को देखकर श्री मोन्टगामरी का कहना था कि, "भारत जितना कृषि प्रधान देश है उतना ही उद्योग प्रधान भी। यदि कोई व्यक्ति उसे केवल कृषि देश ही कहता है, तो सम्यता के स्तर में उसे (भारत को) नीचे गिराता है।"

हमारे अतीत का प्रसिद्ध उद्योग सूत व वस्त्र सम्बन्धी था। सन् १८५१ में फ्रांस निवासी श्री एम० ब्लंकी ने देश के कला-कौशल को देख कर उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। उस समय गाँव के प्रत्येक घर में कोई न कोई व्यक्ति चरखा चला कर

1, "At a time when the West of Europe, a birth place of modern industrial system was inhabited by uncivilised tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for the high artistic skill of her craftsmen. And, even at a much later period, when the merchant adventurers from the West made their first appearance in India, industrial advancement of this country was, at any rate, not inferior to those of the more advanced European nations."

—Report of the Indian Industrial Commission 1916 18 Page 6.

2. History of British Empire in India by Edward Thornton.

सूत तैयार करता हुआ पाया जाता था। वस्तुतः भारत में वस्त्र-उद्योग अत्यन्त प्राचीन काल से अपनी उन्नत दशा में था। मोहनजोदडो के ध्वसावशेषों में सूती वस्त्रों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इन अवशेषों के आधार पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स टर्नर व ए० एल० गुलाटी ने यह परिणाम निवाला है कि ऐसे वस्त्र रई के बनाए गए होंगे। मोहनजोदडो की संस्कृति ५ हजार ईसा पूर्व और अनेक इतिहासकारों के अनुसार १० हजार वर्ष पूर्व मानी जाती है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण इत्यादि के कुछ वाक्यांश इस बात को भली भाँति दर्शाते हैं कि उस युग में भी सूती कपड़े का व्यवसाय उन्नति के शिखर पर था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ऋषि विलाप करता है कि मैं धार्मिक कर्त्तव्यों का न ताना जानता हूँ न बाना। ऋग्वेद में विवाह-संस्कार में वस्त्र परिवर्तन के समय बोले जाने वाले मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि हम वह कपड़ा पहने जो देवियों ने अपने हाथ से काना तथा बुना है। वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में कपड़ा सीने की सुई के लिए 'सूची' और 'बेशी' का नाम मिलता है।

वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अन्य अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों से भी प्राचीन भारत में वस्त्र-कला के विकास का उदाहरण मिलता है। अजन्ता की गुफा के कुछ चित्रों में भी इस उद्योग के शौरव-पूर्ण अतीत का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्यश्री के विवाह के लिए तैयार किए गए वस्त्रों का उल्लेख करते हुए दाण्डिग लिखता है, "रेशम, रई, ऊन, साँप की चँचुली के समान महीन रेशम से उड़ जाने वाले, स्पर्श से ही धनुमेय और इन्द्र धनुष के समान रंग वाले कपड़ों से धर धर गया।" मैनचेस्टर के रहने वाले एक कारीगर की दृष्टि से इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा ढाका की मलमल की तुलना में छाया मात्र ही था। ढाका के अतिरिक्त कृष्णनगर, चन्देरी इत्यादि भी वस्त्र-कला के लिए प्रसिद्ध थे। छीटो के लिए सखतऊ प्रसिद्ध था। अहमदाबाद धोती तथा दुपट्टों के लिये प्रसिद्ध था। बेल-बूटेदार काम के लिए बनारस तथा नागपुर अधिक प्रसिद्ध थे। रेशमी वस्त्रों के लिए मुर्शिदाबाद, मालदाह तथा बंगाल के अन्य नगर प्रसिद्ध थे। काश्मीर के दुत्तलों की माँग विदेशों में अधिक थी। फ्रांस के व्यापारियों की इतनी माँग थी कि वे लोग अग्रिम रकमा देकर भी व्यवहार कर लेते थे। ताँबा, पीतल एवं कंसि के बने हुए बर्तनों के लिए बनारस, पूना, नासिक, हैदराबाद, बिसाखा-पत्तम तथा तजीर प्रसिद्ध थे। राजपूताने में पत्थरों की खुदाई तथा रत्नों पर मोनाकारी का उत्तम काम होता था। मंगरमर के काम के लिए भागरा प्रसिद्ध था। चाकू, कंची तथा लोहे की बनी अन्य छोटी-मोटी वस्तुओं के लिए पंजाब का नाम विख्यात था। इसी प्रकार सिन्ध में अस्त्र-शस्त्र का काम उत्तम कारीगरी का था। जहाज उद्योग के सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता ने लिखा है, "समुद्री यात्रायान एवं जहाज

निर्माण में भारत का प्रथम स्थान था। जब वास्कोडिगामा भारत में आया, तब उसने देखा कि यहाँ के लोग जहाजी नौ वहन (Shipping) के विषय में इतने कुशल थे जितना कि वह स्वयं भी नहीं जानता था।

देहली का लोह स्तम्भ हमारे इस्पात उद्योग की उन्नत दशा का प्रतीक है। प्रायःसर्व बेलसन का कथन है कि, “हिन्दुओं के पाम लोहे के गलाने, मोड़ने तथा स्टील बनाने की कला विद्यमान है, जो बहुत वर्षों ग है।” श्री रानाडे के शब्दों में, “लोहे के कारखानों ने न केवल स्थानीय सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की किन्तु विदेशों को निर्यात करन योग्य अवसर भी भारत को दिये। परसिया के व्यापारी हमारे देश से लोहे की वस्तुएँ खरीद कर एशिया के अन्य भागों को निर्यात करते थे। यहाँ के स्पात की माँग इङ्ग्लैंड में चाकू, कैंची आदि कटलरी की वस्तुएँ तैयार करने के लिये बहुत थी।” इसके अतिरिक्त हाथी दाँत का काम, काँच का सामान, चमड़े का काम, कागज बनाने का उद्योग, सुगन्धित तेल, साबुन, इत्र-फुलेल आदि सुगन्धित वस्तुएँ भी इस देश में प्रसिद्ध थी।

यह तो रही मध्य काल के पूर्व की कहानी। मध्य काल में भी भारतीय उद्योग काफी उन्नत दशा में थे। ट्रवनियर नामक यात्री, जिसने मुगल काल में भारत की यात्रा की थी, सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में लिखता है, “भारत निर्मित वस्तुएँ इतनी सुन्दर होती थी कि वे तुम्हारे हाथ में हैं, इसका ज्ञान भी न होता था व वस्त्र अत्यन्त कोमलता से बुने जाते थे एक पीड रुई से २५० मील सम्बा कपड़ा बुना जाता था।” अबुलफजल ने, ‘आइने अकबरी’ में लिखा है कि, “बादशाह सलामत विभिन्न वस्तुओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। कुशल कारीगर व कलाकार इस देश में लोगों को शिल्प तथा कला का प्रशिक्षण देने के लिए आकर बस गये हैं। आगरा, लाहौर, फतहपुर, अहमदाबाद तथा गुजरात आदि नगरों के शाही कारखानों में कला के उत्कृष्ट नमूने उत्पन्न किये जाते हैं व उनके रंग-रूप, प्रकार तथा श्रेष्ठता को देख कर विदेशी यात्री भी चकित हो जाते हैं।” ट्रवनियर ने १७वीं शताब्दी के मध्य में कुछ कारखानों का आँखों देखा हाल इस प्रकार लिखा है, “अनेक स्थानों पर बड़े विशाल भवन बने हुए हैं, जिन्हें ‘कारखाना’ कहा जाता है। किसी भवन में जरी का काम करने वाले व्यक्ति कार्य-सलग्न हैं, जिनका मालिक के द्वारा निरीक्षण हो रहा है, दूसरे में स्वर्ण-कार, तीसरे में चित्रकार, चौथे में रंगसाज, पाँचवें में सिलाई करने वाले दर्जी, मोची तथा अन्य कारीगर और छटवें में रेशमी वस्त्र तथा महीन मलमल बुनने वाले कारीगर दिखाई देते हैं।”

उस समय देश के प्रत्येक गाँव में कारीगरों का एक समुदाय भी रहता है, जो किसी न किसी उद्योग में लगे रहते हैं। इनमें से प्रत्येक गाँव में कुम्हार, सुनार, लोहार, बढई, बुनकर, रंगरेज, तेली आदि मुख्य थे। इनमें से कुम्हार, सुनार, लोहार,

घमार आदि से गाँव के कृषकों के मेवकों की ओरों में आते थे, जिन्हें सेवा के बदले फसलों के पकने पर नियमित अनाज दिया जाता था। इन लोगों को खेती करने के लिये गाँव वालों की ओर से भूमि भी दी जाती थी। नियमित कार्य के प्रतिरिक्त सेवा करने पर उन्हें प्रतिरिक्त मजदूरी मिलती थी। अन्य प्रकार के कारीगरों की आवश्यकता समय-समय पर पड़ा करती थी। अतः उनकी मजदूरी अन्य ढंग से निर्धारित की जाती थी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि प्रत्येक गाँव में सभी कारीगर हों। यदि कोई गाँव छोटा होता, तो वहाँ हो सकता था कि बुनकर, जुलाहा या रंगरेज न हों। इसके विपरीत एक बड़े गाँव में एक से अधिक तेली, जुलाहे व रंगरेज भी हो सकते थे। किन्तु उस समय उन कारीगरों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक का कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न होता था। हमारे देश के प्रत्येक गाँव में यह विशेष प्रकार की व्यवस्था थी, जिसके कारण हमारा प्रत्येक गाँव समृद्ध तथा सबल था। प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी था, किन्तु इसका प्रभाव आभीष्ट उद्योग-धन्धों पर अच्छा नहीं पड़ा। वे पिछड़े ही रह गये।

१६वीं शताब्दी के आरम्भ में कुल जन-संख्या का लगभग १०वां भाग ही नगरों में रहता था। उस समय बड़े नगर वे ही थे जो केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार की राजधानी थे, जैसे - आगरा, देहली, लखनऊ, पूना आदि। दूसरे प्रकार के प्रसिद्ध नगर वे थे, जो धार्मिक तीर्थ स्थान थे, जैसे गया, बनारस, प्रयाग, अयोध्या, हरिद्वार, पुरी, नासिक, कुशक्षेत्र आदि। तीसरे प्रकार के वे नगर थे जो व्यापारिक केन्द्र थे, जैसे मिरजापुर, बंगलौर आदि। उस समय के बड़े नगरों के बनने का कारण व्यापार एवं उद्योग नहीं था। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें व्यापार एवं उद्योग था ही नहीं। यों तो सारे बड़े-बड़े नगरों में कुछ न कुछ धन्धा उभर दशा में था, किन्तु उस समय के नगर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं थे। अनाज एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ आस-पास के गाँवों से आती थी।

उस समय के उद्योग धन्धों का संगठन अच्छा था। बड़े-बड़े नगरों में प्रत्येक व्यवसाय का एक सघ होता था। वास्तव में वह एक प्रकार की मंत्री समितियाँ थी जो सदस्यता, वस्तुओं के गुण आदि पर नियंत्रण रखती थी। इनके पास पूँजी की कमी थी। कारीगर बहुधा अपने ग्राहकों की माँग पर, उनके द्वारा दिए हुए कच्चे माल की सहायता से, उनकी इच्छानुसार वस्तुओं का निर्माण करते थे। नगरों में साख का भी अच्छा प्रबन्ध था, अतः छोटे-छोटे कारीगर अपने-अपने ग्राहकों के, कपड़े, लोकर भी अपना उद्योग छोटे पैमाने पर स्वतन्त्र रूप से चलाते थे। उस समय मध्यस्थ नहीं होते थे। उस समय के कारीगरों का व्यवसाय परम्परागत था, अतः उनका कला-कौशल एवं होशियारी एक प्रकार से पंक्ति संपत्ति का ही रूप है। जितना ज्ञान पिता को होता था, उतना ही ज्ञान उनके बच्चों को प्राप्त होता था। अतः उनके

कार्य करने की पद्धति में कोई विशेष अन्तर नहीं हो पाता था । उस समय के महाजन, साहूकार तथा पैदियाँ कारीगरों को कच्चा माल देते तथा उनके द्वारा बनी हुई वस्तुओं को खरीदने में सहायता देते थे ।

STANDARD QUESTIONS

1. "Indian industries had a glorious past" Discuss it with special reference to the industries which flourished in the past
2. Discuss carefully the organisation of Indian industries in the past

अध्याय ४

अतीत के उद्योगों की अवनति

(Decline of Early Industries)

प्रारम्भिक—

१७वीं शताब्दी के मध्य से भारत के उद्योग धन्यो ने प्रसन्ननीय प्रगति की । योरोपीय देशों में भारत का बना हुआ माल बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया जाता था । इङ्गलैण्ड हमारा प्रमुख खरीददार था । इङ्गलैण्ड में भारतीय वस्त्रों की बहुत माँग थी, और घर-घर में भारतीय वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था । परन्तु कुछ समय बाद भारतीय उद्योगों का एकाधिकार समाप्त होने लगा । इङ्गलैण्ड के व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होने लगी । अपने देशी उद्योगों को संरक्षण देने हेतु सन् १७०१ व १७२० में उन्होंने पार्लियामेंट को प्रभावित करके ऐंभे कानून बनवाये जिनके द्वारा भारतीय वस्त्रों का प्रयोग वर्जित हो गया । उन दिनों भारतवर्ष में विदेशों से इतनी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा आती थी कि विदेशी व्यापारी भारत से ईर्ष्या करने लगे । फलतः उन्होंने अपने देश में औद्योगिक विकास के प्रयत्न शुरू किये एवं भारतीय आयात कम कर दिये । शर्न-शर्न, भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा । भारतीय उद्योग-धन्यो की अवनति के अनेक कारण थे, जिनमें से प्रमुख निम्न-लिखित हैं—

भारतीय उद्योगों की अवनति के कारण

(१) इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति

भारतीय उद्योग धन्धा के एकाधिकार पर सबसे गहरा आघात इंग्लैंड में प्रारम्भ होने वाली औद्योगिक क्रांति का पड़ा। यह क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में १८वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। इस क्रांति ने इंग्लैंड के आर्थिक कलेवर को पूर्णरूपेण बदल दिया। इसके पूर्व इंग्लैंड के लोग का प्रमुख व्यवसाय कृषि करना ही था। परन्तु औद्योगिक क्रांति ने कृषि को गौण एवं उद्योग धन्धों को प्रमुख स्थान दिया। औद्योगिक क्रांति का प्रारम्भ अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं आविष्कारों के परिणामस्वरूप हुआ। उद्योग के क्षेत्र में हुए कुछ प्रमुख आविष्कार निम्न थे—

- (अ) सन् १७६३ में श्रीयुत के (Kay) के 'फ्लाइट शटिल' ने बुनने की कला में एक क्रांति ली मन्दा दी जिससे ताने की बची का अनुभव होने लगा।
- (ब) सन् १७५३ में श्रीयुत हार ग्रीब्स (Har Greaves) की 'स्पिनिंग जेनी' के द्वारा ८ से ५४ ताने एक साथ बुने जाना सम्भव हो गया।
- (स) सन् १७६६ में श्री आर्क राइट (Ark \right) ने वाटर फ्रम का आविष्कार किया जिसके द्वारा स्विनिंग जेनी चलती थी।
- (द) सन् १७८६ में श्री जेम्स वाट (James Watt) ने 'स्टीम इंजन' का आविष्कार किया।
- (य) श्री डर्बी (Derby) ने कोयले के साथ लोहा चलाने की श्री हेनरी कोर्ट (Henry Cort) ने लोहे में से असुद्ध भाग निकालने की नयी युक्ति मालूम की। इसी प्रकार श्री डाडस्ले ने अनेक सुन्दर यन्त्रों व औजारों का आविष्कार किया।

इन विभिन्न आविष्कारों ने उद्योग कृषि तथा यातायात के क्षेत्र में एक क्रांति मचा दी। यन्त्रीकरण की सुविधा ने औद्योगीकरण का विशेष बल दिया। उद्योग धन्धों की स्थापना के लिए पैसों की भी वहाँ कोई कमी नहीं थी। भारत के साथ व्यापार में इंग्लैंड के व्यापारियों ने बहुत धन कमाया जिसको वे विनियोग करना चाहते थे। अतः भारत से कच्चा माल इंग्लैंड में लाकर यन्त्रों की सहायता से उसका यहाँ निर्माण किया जाने लगा। यन्त्र निर्मित वस्तुएँ भारतीय हस्त निर्मित पदार्थों की अपेक्षा अधिक सस्ती थी, इस कारण भारतीय माल इनकी प्रतिद्वन्द्विता में टिक न सका। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन का तो यन्त्रीकरण व औद्योगीकरण होने लगा व भारतीय उद्योग शनैः-शनैः अवनति के गडब में गिरने लगे। यद्यपि कला की दृष्टि से भारतीय माल यन्त्र निर्मित माल की अपेक्षा

कहीं अधिक श्रेष्ठ था, परन्तु अत्यन्त सस्ता होने के कारण यन्त्र-निर्मित माल ही लोक-प्रिय हुआ। पहले तो विदेशी मण्डियों से भारतीय माल हटने लगा और कुछ समय बाद तो भारत के बाजारों में भी विदेशी माल छा गया और यहाँ की हस्त-निर्मित वस्तुएँ लोप होने लगी। यातायात के क्षेत्र में भी अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। भारत के अन्दर रेलों व सड़कों का जाल बिछने लगा। स्वेज नहर के निर्माण से यूरोपीय देश भी भारत के बहुत निकट आ गये। इस यातायात के विकास एवं जहाजी भाड़ों में कमी के परिणाम स्वरूप ग्रेट-ब्रिटेन का यन्त्र-निर्मित माल बड़ी तेजी से भारत के विभिन्न नगरों में आने लगा। औद्योगिक शक्ति के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। उद्योगों में भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। इससे उत्पादन प्रणाली और भी सरल और सुगम हो गयी। इसने विपरीत भारत-वर्ष में उद्योग धंधों परम्परागत प्रणाली के आधार पर चलाए जाते थे। हमारा औद्योगिक संगठन भी अपेक्षाकृत अधिक शिथिल था। यद्यपि इंग्लैंड में भी नए-नए आविष्कारों के कारण उद्योगों के संगठन में विशेष दृढ़ता नहीं थी, किन्तु फिर भी वहाँ के नागरिकों व व्यवसायियों की कार्यकुशलता एवं दृढ़ निश्चय के कारण औद्योगिक विकास बड़ी तेजी से हुआ। उस समय इंग्लैंड व भारत की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक दशाएँ एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति ने सभी लोगों को औद्योगीकरण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उदाहरणार्थ, पूँजीपतियों को नए-नए उद्योगों में निवेश करने का स्वर्ण अवसर मिला, श्रमिकों को कारखानों में ऊँची मजदूरी पर रोजगार मिला विशेषज्ञों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला, इत्यादि। इन सब घटकों का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में बड़ी तेजी के साथ औद्योगिक प्रगति होने लगी। इसके विपरीत भारत में राजनैतिक अशान्ति होने के कारण विकास की गति बहुत धीमी रही। यही नहीं, भारतीय मण्डियों में यन्त्र-निर्मित सस्ता माल आ जाने के कारण देशी उद्योग धंधों पर भी इसका दुप्रभाव पड़ा। हमारे उद्योग-धंधों का उत्पादन गिरने लगा एवं श्रमिकों की छटनी शुरू हो गई। इस छटनी व बेरोजगारी ने समाज में एक हलचल पैदा कर दी एवं चारों ओर निराशा का वातावरण छा गया। अतः स्पष्ट है कि हमारे अतीत के उद्योगों के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव था।

(२) भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश माना गया—

हमारे उद्योगों के विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि ग्रेट ब्रिटेन ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारत को उपनिवेश बनाया। उसकी आर्थिक व औद्योगिक नीति भारतीय हितों के विरुद्ध थी। भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में यन्त्रों की सहायता से उससे विभिन्न प्रकार के निर्मित पदार्थ बनाए जाते थे और फिर बरबस भारतीयों को ही बेचा जाता था। भारत के प्राचीन आर्थिक

व सामाजिक कलेवर को भी उन्होंने बिगाड़ दिया एवं इस देश में भी पूँजीवाद के भ्रम को पैदा कर दिया । पूँजीवाद के विवास के परिणामस्वरूप समाज दो खण्डों में विभक्त हो गया—पूँजीपति और श्रमजीवी । इन दोनों वर्गों में पारस्परिक कलह के कारण औद्योगिक उत्पादन की बड़ी क्षति पहुँची । भारत की सीधी-भादी व्यवस्था पर नवीन परिवर्तनों व पूँजीवाद का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, यहाँ की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई । यहाँ के लोगों के पास न तो तान्त्रिक ज्ञान था और न पर्याप्त पूँजी ही, फलतः हमारे उद्योग नए परिवर्तनों का सामना न कर सके और कुछ समय तक लड़खड़ाने के बाद उनका विनाश होने लगा ।^१

(३) भारतीय माल पर प्रतिबन्धात्मक कर—

इतना ही नहीं, अपितु इंग्लैंड में कानून द्वारा भारतीय वस्तुएँ, जैसे छीट, कैलिको आदि का उपयोग रोकने के लिये प्रयत्न किये गये तथा इन वस्तुओं का उपयोग करने वालों को दण्ड दिया गया । इसका भी एक उदाहरण मिलता है, जब एक श्रेष्ठ महिला ब्रिटिश सभा-गृह में गई, तब उसके पास भारतीय कैलिको का रुमाल था, इसलिये उसे ५० पौंड से दण्डित किया गया । भारतीय हितों के विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक कानून पास कराने में इंग्लैंड के उद्योगपति इस कारण और भी सफल हुए, क्योंकि औद्योगिक क्रान्ति ने उनके हाथ बहुत मजबूत कर दिये थे । इंग्लैंड में पूँजीपतियों का एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग पैदा हो गया था, जो अपनी इच्छानुसार कठपुतली की भाँति शासन को नचा सकता था । ऐसे कानूनों का कुप्रभाव यह हुआ कि भारतीय माल के लिये ब्रिटेन का बाजार बिलकुल बन्द हो गया । इसमें हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा एवं उद्योग-अर्थों का विकास रुक गया । वास्तव में भारतीय निर्माताओं व त्याग के परिणामस्वरूप ही मेनचेस्टर आदि के उद्योग पनपे एवं भारतीय उद्योगों की सवर्धति होती गई ।^२

1 'The sudden impact of the new order of things on the placid and easy going life of India produced disastrous results, its whole internal economy was thrown out of gear and the people had just then neither the knowledge nor the capital to evolve new types of Industry suited to the altered times'

—P P Pillai quoting A K Connel in 'Economic Conditions of India', Page 27.

2 'Had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have stopped in their outset and could hardly have been again set in motion, even by the powers of steam. They were created by the sacrifice of Indian manufacturers'

—Quoted by S C. Kuchhal in the Industrial Economy of India, Page 45.

का अधिकार मिलना चाहिये। फलतः सन् १८३३ में भारतीय व्यापार सवने लिये खुल गया। घरेलू व्यापारिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रस्तित्व समाप्त हो गया। भारत के आर्थिक विकास का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। भारत के साथ व्यापार करने की स्वतन्त्रता की घोषणा के साथ, विदेशी पूँजी व निजी उपक्रम का भारत में आयात शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने तो अपना परंपरागत व्यापारिक क्षेत्र कायम रखा एवं पुराने ढंगों में वह व्यापार करती रही। परन्तु जो नये व्यवसायी व साहसी भारत में आये, उनका उद्देश्य ही भिन्न था। वे केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि वास्तव में भारत में ब्रिटिश माल के लिये बाजार खोजने के लिये आये थे। ये नये उपक्रमी पुराने व्यापारियों की भाँति माल खरीदने के लिये नहीं बल्कि ईंग्लैंड का यन्त्र निर्मित माल बेचने के लिये आये थे। इनकी कुचेष्टाओं ने भारतीय उद्योगों पर बजपास किया। जैसे-जैसे इनको सफलता मिलती गई, वैसे-वैसे भारतीय उद्योगों की अवनति होती गई।

(६) भारतीय अर्थव्यवस्था का विशिष्टीकरण—

लकाशायर व मैनचेस्टर की सूती वस्त्र मिलों के लिये पर्याप्त मात्रा में निरन्तर भोजन (पर्याप्त कपास) प्राप्त करने के लिये भारतीय अर्थ व्यवस्था का कलेवर बदल दिया गया। यद्यपि पहले भारत जितना कृषि-प्रधान था उतना ही उद्योग प्रधान भी था, परन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा इसके बाद ब्रिटिश शासन ने हमारी अर्थ-व्यवस्था के विशिष्टीकरण पर अधिक बल दिया। ऐसा कहा गया कि भारत केवल कृषि-प्रधान देश ही है, अतएव कपास, जूट, चमड़ा, तिलहन आदि कच्चे औद्योगिक पदार्थों के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिये। भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये व उन्नत बीज, उन्नत खाद आदि के लिये अनेक प्रयत्न किये गये। सिंचाई की सुविधाओं की वृद्धि की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि-पदार्थों की किस्म व मात्रा को बढ़ाने की दिशा में समस्त शक्तियाँ केन्द्रित हो गई। इस केन्द्रीय-करण का दुखद परिणाम यह हुआ कि भारत केवल कृषि प्रधान देश ही रह गया और हमारे उद्योग-धन्धे एक-एक करके ^{producing} होने लगे। अधिक आय के कारण भारतीय कृषकों की क्रय-शक्ति भी बहुत बढ़ गई और वे विदेशी वस्तुओं के खरीदने में समर्थ हो गये। अतः देश से कच्चे माल का निर्यात शुरू हो गया एवं विदेशी माल का आयात शुरू हो गया।

(७) विविध कारण—

भारतीय उद्योगों के पतन के उपर्युक्त कारणों के अनिरिक्त कुछ अन्य घटक भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:—

(अ) राजा व नवाबों का अन्त—ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में राजनैतिक शासन जमाने के बाद अपना रुख आर्थिक शासन जमा कर भारत के आर्थिक शापण

की ओर किया। ईस्ट इन्डिया कम्पनी के पास राजनैतिक सत्ता जाने से भारतीय राजा व नवाबों की स्थिति बिगड़ गई। परिणामस्वरूप राजा महाराजाओं द्वारा कलात्मक व दस्तकारी की वस्तुओं की जो माँग थी, वह नष्ट प्रायः हो गयी। इससे भारतीय उद्योगों को गहरा आर्थिक धक्का पहुँचा। लार्ड डलहौजी की विनाशकारी नीति के कारण देश की छोटी-छोटी राजधानियाँ भी लुप्त हो गयीं, जो प्राचीन कला-कौशल की केन्द्र थी और जहाँ हमारे शिल्पियों को आश्रय मिलता था। इससे बची हुई कला-कौशल की माँग भी लुप्त हो गई।

(ब) नये सामन्तवादी वर्ग का उदय—राजनैतिक सत्ता जाने के परिणाम-स्वरूप भारतीय राजा व नवाबों की सत्ता का अन्त हो गया और एक नये समाज का उदय हुआ, जिसे हम सामन्तवादी वर्ग कह सकते हैं, इस वर्ग का उदय ब्रिटिश शासकों ने अपनी शासन-प्रणाली का संचालन करने के लिए किया, जो शरीर से एब जन्म से भारतीय थे, परन्तु उनकी आत्मा व विचारधारा अपने शासकों की भाँति अंग्रेजियत में भ्रष्ट-भ्रष्ट थी।^१ यह सामन्तवादी वर्ग 'काला आदमी' हँसते हुए भी भापा, रहन-सहन तथा अंग्रेजों की अन्धी नकल करने में अपना गौरव समझता था। भारतीय उद्योग-धन्यों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ये लोग 'साहब की मरजी सम्पादन करने के लिए साहबी ठाट-बाट में एब विलायती सिवास में रहने लगे, जिससे देशी वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी वस्तुएँ ही उनके द्वारा अधिक प्रयोग की जाने लगी। यदि इस वर्ग द्वारा कुछ देशी वस्तुएँ खरीदी भी जाती थी तो वे विशेष कलात्मक एब मूल्यवान न होते हुए सस्ते मूल्यों की थी। इन सब कारणों का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय उद्योगों में कलात्मक एब मौलिक वस्तुओं के उत्पादन को गहरा आघात पहुँचा।

(स) व्यापारिक गिल्ड्स का पतन व्यापारिक गिल्ड्स से तात्पर्य उन संस्थाओं का है, जो माल की किस्म, मूल्य, बिक्री का म्यान, श्रमिकों के काम के घण्टे तथा काम की अन्य शर्तें, सभी कुछ निर्धारित करती थी। गिल्ड समान पेशे के लोगों में सहयोग, भ्रातृत्व तथा भैत्री की भावना प्रोत्साहित करते थे एब बाहरी लोगों से अपने सदस्यों की रक्षा करने थे। परन्तु जब से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव जमने लगी तब से व्यापारिक गिल्ड्स का संगठन शिथिल पड़ने लगा। व्यापारिक गिल्ड्स के विनाश में भी हमारे औद्योगिक संगठन को बहुत बड़ा धक्का लगा और उनकी अवनति होने लगी।

(२) यन्त्रों के निर्यात पर प्रतिबन्ध—यदि भारत भी औद्योगिक क्रान्ति द्वारा प्रदान किये हुए यन्त्रों व आविष्कारों का प्रयोग करता तो भी हमारे उद्योगों को दुर्दिन न देखना पड़ते। परन्तु जितने भी नये आविष्कार हुए वे सब ग्रेट-ब्रिटेन तक ही सीमित रहे तथा नयी मशीनों का प्रयोग भी केवल ब्रिटेन के ही कारखानों में किया गया। ब्रिटेन से यन्त्रों के निर्यात पर कठोर नियन्त्रण लगाया गया, परिणाम यह हुआ कि भारत यन्त्रों की सहायता में बड़े पैमाने पर उत्पादन न कर सका, अतः इसका निर्माण व्यय बहुत अधिक होता था जबकि इंग्लैंड में उत्पादन के व्यय बहुत कम थे। इस प्रतिस्पर्धा ने भी भारतीय उद्योगों पर कुठाराघात किया।

(५) यातायात के साधनों में वृद्धि—इसी युग में यातायात व सन्देश-वाहन के क्षेत्रों में भी अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिये सन् १८६६ में स्वेज नहर के निर्माण से योरोपीय देश भारत के बहुत निकट आ गये। भारत में भी सड़कों व रेलों के जाल के कारण प्रायः सभी नगर एक-दूसरे से सम्बद्ध हो गये। फल यह हुआ कि यन्त्र निर्मित विदेशी माल बड़ी सुविधा से भारत में आने लगा एवं भारतीय यातायात के साधनों ने देश के सभी बाजारों में उसे बिछा दिया। इससे भी भारतीय उद्योगपति हतोत्साहित हो गये एवं भारतीय उद्योग अवनति की ओर अग्रसर होने लगे।

इस प्रकार सन् १८८० तक भारतीय हस्तकला का पूर्ण विनाश हो गया और उनकी सुरक्षा के लिये कोई भी माग नहीं रहा। मुक्त व्यापार (Free Trade) की नीति ने जल पर समक छिड़कने का काम किया। रेलवे भाडानीति ने भी भारतीय उद्योगों के विनाश एवं विदेशी वस्तुओं के वितरण में योग दिया।

STANDARD QUESTIONS

1. D fine Industrial Revolution How far it has been responsible for the decay of Indian Industries ?
2. Summarise carefully the various factors which have brought about the decay of Indian Industries
3. 'It is said that the establishment of the East India Company is associated with the down fall of Indian Industries' Comment

आधुनिक उद्योगों का प्रादुर्भाव एवं विकास

(Evolution and Development of Modern Industries)

प्रारम्भिक—

हमारे उद्योग-धन्धों का विनाश गाँवों की अपेक्षा नगरों में ही अधिक प्रबल था। इस विनाश का सबसे भयंकर परिणाम यह हुआ कि जो कारीगर नगरों में रहकर अपने हस्त-कौशल से अपना तथा अपने कुटुम्ब का जीवन निर्वाह कर रहे थे, अब उस साधन के छिन जाने के कारण नगर छोड़कर गाँवों में जाकर बसने लगे। वहाँ जाकर कुछ कारीगर तो अपनी भूमि पर कृषि करने लगे और जो गरीब थे तथा जिनके पास भूमि खरीदने के लिए धन नहीं था, वे खेतों में मजदूरी करने लगे। इस प्रकार कृषि भूमि-पर जन सङ्घा का भार बढ़ने लगा। इंग्लैण्ड में भी औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप वहाँ के हस्त-कौशल कारीगरों को अपने उद्योग-धन्धों का छोड़ना पड़ा था, किन्तु वहाँ हमारे देश की तरह कारीगर गाँवों की ओर नहीं गये। हाँ, कुछ समय के लिए वे बेकार अवश्य हो गये। किन्तु उस देश की औद्योगिक नीति एवं आर्थिक स्थिति दूसरे प्रकार की थी। जब यन्त्रों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होने लगा, तो कारीगरों की अधिक आवश्यकता हुई। अतः कुछ लायाने, जो बेकार हुए, कारखानों में मजदूरी करना आरम्भ कर दिया। यन्त्र निर्माण करने वाले कारखानों में भी बहुत से मजदूर काम पर लग गये। यन्त्रों की सहायता से बनी वस्तुएँ हाथ की बनी हुई वस्तुओं से काफी सस्ती होनी थी। अतः उन वस्तुओं की माँग देश और विदेश में अधिक होने लगी। इस बढ़ती हुई माँग का पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन होना लगा, जिसके लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता हुई। इतना ही नहीं, रेलों के कारखानों में, जहाजों के कारखानों में, रेलों में काम करने के लिए, जहाजों तथा बन्दरगाहों में काम करने के लिए मजदूरों की अधिकोष्क आवश्यकता बढ़ गई। व्यापार में भी वृद्धि हुई। इसी प्रकार खानों में, सड़कें बनाने आदि के लिए भी मजदूरों की माँग बढ़ी। संक्षेप में, वहाँ चारों ओर से मजदूरों की माँग दिन प्रति दिन बढ़ने लगी। अतः जो कारीगर बेकार हुए उन्हें किसी कारखाने में काम न मिला, क्योंकि उस समय कोई भी कारखाना नहीं खोला गया। जिन वस्तुओं की प्रतियोगिता हमारे

देश के बाजारों में होती थी, उनका निर्माण इंग्लैंड में होता था। अतः यहाँ के कारीगरों के लिए कृषि के अनिर्भर अन्य कोई भी व्यवसाय नहीं था जिसको वे अपनाते। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का वहाँ की जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इन लोगों की आर्थिक दशा उन्नत हुई, किन्तु हमारे देश की जनता की स्थिति दिन प्रति दिन गिरने लगी।

आधुनिक उद्योगों का प्रादुर्भाव—

समय परिवर्तनशील है। इसी सिद्धान्त के अनुसार हमारे देश में भी समय की गति के साथ परिवर्तन घटने लगा। सन् १८५० के बाद विदेशियों ने अपने स्वार्थ के लिये लाभ कमाने की दृष्टि से, इस देश के उद्योग-धन्धों में परिवर्तन करना आरम्भ किया और अब यहाँ भी धीरे-धीरे आधुनिक उद्योग बढ़ने लगे। हमें अब देखना है कि इन आधुनिक उद्योगों का जन्म किस प्रकार हुआ और वे धीरे-धीरे किस प्रकार उन्नत हुए।

इन उद्योगों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं—बगीचा उद्योग (Plantation Industry) और निर्माणी उद्योग (Factory Industry)।

■ श्रेणी के उद्योगों में नील, चाय और कॉफी मुख्य हैं। ये तो उपर्युक्त दोनों देश यूरोप की हैं, किन्तु दूसरे प्रकार के उद्योग का सम्बन्ध यूरोप में हुए आर्थिक संक्रमण से है।

बगीचा-उद्योग का श्रोगणेश—

बगीचा-उद्योग का प्रारम्भ यूरोपीय लोगों द्वारा ही हुआ। इन्होंने १६वीं शताब्दी के मध्यकाल के बाद अधिक उत्साह से कार्य करना प्रारम्भ किया, क्योंकि इस समय के पूर्व उन्हें अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था, जिनमें (अ) ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अधिकार पर रोक लगाई जाना, (ब) आवागमन के उपयुक्त साधनों में कमी होना, (स) जन-समूह का दूर-दूर के स्थानों पर रहना, आदि मुख्य थीं।

नील की कृषि भारतीय अनेक वर्षों से करते आ रहे थे और विदेशी व्यापार भी उन्नत दशा में था। जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस देश में आई, तो उसने भी नील के रण का काफी व्यापार किया। कम्पनी ने नील की उन्नति करने के लिए पश्चिमी द्वीप समूह से होशियार लोगों का बगल में लाकर बसाया। किन्तु खेती करने वालों की आर्थिक दशा भी बिगड़ती गई। यूरोपीय लोगों ने जबरदस्ती ग्रामों में रकमे देकर खेती करवाई। चाहे जो हो, सन् १८६० में बगीचा उद्योग उन्नति के शिखर पर पहुँच गया और भारत से निर्यात की जान वाली वस्तुओं में यह भी एक महत्त्वपूर्ण वस्तु गिनी जाती थी। सन् १८८० से सन् १८९५ तक इस उद्योग में स्थिरता रही। सन् १८९४-९५ में नील का व्यापार अपने पिछले वर्षों में सबसे अधिक था। सन् १८९७

के बाद इस उद्योग की खेती और निर्यात का पतन होने लगा । सन् १९१३-१४ में तो नील का निर्यात सन् १८९५ के निर्यात का ३ ही रह गया ।

भारत में चाय की खेती का पहली बार जन्म सन् १८२० में हुआ था । सन् १८३५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रयोग करने के लिए एक खेत लगाया । पाँच वर्ष के पश्चात् यह काम 'आसाम टी कम्पनी' (Assam Tea Company) को दे दिया गया । सन् १८५२ में पहला निजी बगीचा प्रारम्भ हुआ । इसके बाद चाय की कृषि दिन प्रति दिन बढ़ने लगी ।

सन् १८६० के बाद आसाम के चाय के खेतों पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम पड़ने लगी, अतः बंगाल की ओर से मजदूर लाए जाने लगे । उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी । उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार होता था । बहुत से उद्योगों को बड़ा धक्का लगा । किन्तु सन् १८६८ के बाद सुधार होने के कारण चाय की खेती देश के अन्य भागों में, जैसे—पंजाब एवं नीलगिरी की ओर की जाने लगी । १९वीं शताब्दी के अन्तिम तीस वर्षों में न केवल चाय की कुल उत्पादन मात्रा ही बढ़ी, वरन् कृषि के ढंगों में परिवर्तन होने के कारण तथा यन्त्रों के उपयोग से प्रति बीघा उत्पादन मात्रा में भी वृद्धि हुई । संयुक्त राज्य के बाजारों में भारतीय चाय ने चीन की चाय को प्रतियोगिता में बिठा दिया । सन् १९०३ में भारतीय चाय की माँग बहुत बढ़ी । सन् १८९५ के बाद जब उत्पादन अधिक हुआ, तब मूल्य में कमी हो गई, सन् १९०२ से १९०६ तक खेती कम हो गई और बाजार में भी मन्दी छा गई । किन्तु कुछ समय बाद पुनः बगीचा-उद्योग उन्नति करने लगा और भारतीय चाय विदेशों को निर्यात की जाने लगी ।

काँफी की खेती का आरम्भ १७वीं शताब्दी में मूर (Moor) व्यापारियों द्वारा हुआ था और इसकी खेती दक्षिणी भारत के कई भागों में होती थी । यों तो पहला बगीचा यूरोप के लोगों के द्वारा सन् १८४० में लगाया गया, किन्तु सन् १८६० तक कोई विशेष उन्नति नहीं हुई । इसी बीच यूरोप के लोग दक्षिण-पश्चिम शिमोगा, मन्जिराबाद के दक्षिण भाग में, कुर्ग तथा ध्यानद के हिस्सों में बस गये । सन् १८६० से लेकर सन् १८७९ तक काँफी का निर्यात पहले से दस गुना हो गया । इस प्रकार इस अवधि में मयेष्ठ उन्नति हुई । किन्तु सन् १८७९ से १८८८ तक काँफी के पत्तों में बीमारी फैलने से भारत एवं लंका में खेती रुक गई । दूसरी ओर ब्राजील की काँफी भी प्रतियोगिता में आ गई । किन्तु थोड़े समय बाद वहाँ कुछ राजनैतिक अडचनों के कारण, भारतीय काँफी के मूल्य में फिर वृद्धि हो गई । यह उन्नति सन् १८८९ से १८९६ तक होती रही । काँफी के खेतों में काम करने वाले मजदूरों में बहुत से ऐसे

मजदूर थे, जो आसपास के गाँव से अपनी खेती से अवकाश मिलने पर अपनी आय बढ़ाने के लिए आ-जाया करते थे ।

इस सम्बन्ध में एक स्मरणीय बात यह है कि अब तक जो यूरोप निवासी केवल व्यापार तक ही सीमित थे, वे १९वीं शताब्दी के मध्य से उत्पादन में भी प्रत्यक्ष रूप में पूँजी लगाने लगे । इससे पूँजी के साथ भारत को औद्योगिक प्रबन्धों का भी एक नवीन दृष्टिकोण मिलता है ।

निर्माण उद्योगों का श्रीगणेश —

जहाँ तक निर्माण उद्योग (Manufacturing Industries) का सम्बन्ध है, उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में इनकी स्थापना न हो सकी । नील के कुछ कारखानों को छोड़कर शेष सभी उद्योग छोटे स्तर पर कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत होते थे । लेकिन रेल-मार्ग के विकास के साथ एवं यातायात की सुलभता के कारण सन् १८५१ में पहला बड़ा कारखाना 'दी बोम्बे स्प्रिंग एण्ड वीविंग कम्पनी' बनाया गया, जिसने सन् १८५४ में उत्पादन आरम्भ किया । प्रारम्भिक प्रगति इतनी मन्द थी कि सन् १८६१ तक केवल १२ बल्ल-मिल खुल पाये । इसके बाद अमरीकन गृह-युद्ध समाप्त होते ही परिस्थिति में सुधार होने पर इस उद्योग में आश्चर्यातीत उन्नति की, जो १९वीं शताब्दी के अन्त तक जारी रही । सन् १८८५ से सन् १८९० तक पाँच वर्षों के बीच देश में ५० सूती-मिल और खुल गये । सन् १८९६ में अकाल तथा महामारी के कारण बल्ल-मिल उद्योग को क्षति पहुँची । इसी प्रकार सन् १९१४ तक विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए यह उद्योग धीरे-धीरे बढ़ता ही गया ।

सूती-बस्त्र मिल उद्योग के बाद जूट-उद्योग का नम्बर आता है । सन् १८५४ में ही पटसन उद्योग की भी स्थापना आधुनिक ढंग पर की गई तथा सन् १८६३-६४ में उद्योग की प्रगति नग्न उदयन से बनी । सन् १९१४ तक मिलों की संख्या सन् १८९६ में २८ में बढ़कर ६४ हो गई ।

इसी प्रकार खानों में कोयला निखाने में आधुनिक मशीनों का प्रयोग गत शताब्दी के मध्य में होने लगा । यद्यपि रानीगढ़ की खानों से सन् १८२० में ही कोयला निकालना शुरू हो गया था, किन्तु सन् १८५४ तक केवल तीन खानों से ही कोयला निकलता था । इसके बाद देश की प्रगति में इस उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन दिया और सन् १८८० तक रानीगढ़ तथा निहटवर्नी भागों में लगभग ५६ खानों से कोयला निकलने लगा । सन् १८८० में इस उद्योग में लगभग २० हजार अधिक काम करते थे । सन् १९१४ में अम-जीवियों की संख्या १३ लाख में भी ऊपर हो गई ।

इन तीन बृहत्त उद्योगों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योगों की भी स्थापना कारखाना-प्रणाली के आधार पर की गई, जैसे—सन् १८६६ में कानपुर में चमड़े का एक बड़ा कारखाना 'हार्लेस एण्ड सैंडबरी फैक्ट्री' के नाम से सरकार ने खोला । इसके

अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश में एक काँच का कारखाना और मद्रास प्रान्त में लोहे तथा चमड़े के कारखाने खोले गए। इस प्रकार सन् १९१४ तक प्रायः अधिकतर उद्योगों का सूत्रपात कारखाना-प्रणाली के आधार पर हो चला था। हाँ, विकास की गति अवश्य धीमी रही।

सन् १८८० तथा १९०१ के दुर्भिक्ष आयोगों ने एव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए औद्योगीकरण पर दल दिया। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्वदेशी आन्दोलन ने भी देश के औद्योगीकरण के लिए आवाज उठाई। विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार तथा कुटीर-धन्धों के विकास के लिए प्रयत्न किए जाने लगे। परिणामस्वरूप देश में अनेक विनियोग संस्थाएँ खुली, जैसे—बैंक, बीमा कम्पनियाँ आदि और साथ ही कामज, पैसिल, दियामलाई, साबुन, काँच आदि के कारखाने भी खुले।

इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास १९वीं शताब्दी के बाद प्रारम्भ होता है और वह भी मुख्यतः योरोपीय पूँजी एवं योरोपीय विशेषज्ञों द्वारा। सन् १९११ की औद्योगिक गणना के अनुसार, उस समय भारत में ७,११३ कारखाने थे, जिनमें १० लाख से अधिक व्यक्ति काम करते थे। इनमें से ४,५६९ कारखाने ऐसे थे, जिनमें यान्त्रिक या अन्य शक्ति का प्रयोग होता था। इसी गणना के अनुसार उद्योगों पर निर्णय जन-संख्या २१,०५,८२४ थी, जिसमें से बगीचा उद्योग, वस्त्र उद्योग, खान उद्योग तथा यातायात सम्बन्धी उद्योगों में क्रमशः ८,१०,४०७, ५,५७,५८९, २,२४,०८७ और १,२५,११७ व्यक्ति काम करते थे, अर्थात् औद्योगिक जनसंख्या का ८१% भाग केवल इन चार बड़े उद्योगों में लगाया था।^१

औद्योगिक विकास को प्रेरित करने वाले घटक—

वे विभिन्न घटक, जिन्होंने प्रथम महायुद्ध तक भारत में औद्योगिक विकास को प्रेरित किया, निम्न-लिखित थे,—

(१) ग्रामीण सगठन व दस्तकारी का विनाश—जब से पाश्चात्य जगत का औद्योगिक पूँजीवाद भारत में आया, तभी से हमारे कुटीर उद्योग-धन्धों का विनाश शुरू हो गया एव

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले घटक

१. ग्रामीण सगठन व दस्तकारी का विनाश।
२. व्यापारिक केन्द्रों का विकास।
३. अंग्रेजी भाषा का प्रचलन।
४. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार का समापन।
५. यातायात के साधनों में वृद्धि।
६. राजनैतिक घटनाएँ।

हमारा ग्रामीण संगठन भी विघ्न-भिन्न हो गया। कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारीगर बेरोजगार हो गए। परन्तु कारखाना आधार पर खोले गए नए-नए उद्योगों में उनको आश्रय मिला। अतः निर्माणी उद्योगों को श्रम का अभाव प्रतीत नहीं हुआ। इस घटक ने औद्योगिक विकास को बल प्रदान दिया।

(२) व्यापारिक केन्द्रों का विकास—जब से भारत में अंग्रेजी शासन आया, तब से यहाँ व्यापारिक केन्द्रों का विकास शुरू हो गया। अंग्रेजी शासन के पूर्व भारत में अनेक व्यापारी तथा राजनौजिज्ञ हिन्दू राजाओं ने मन्डिर बनवाए, मुगल बादशाहों ने महल तथा मकबरे बनवाए मराठों ने किलों का निर्माण किया, डच व पुर्तगीज ने गिरजाघर बनवाए, परन्तु अंग्रेजों ने औद्योगिक नगरों का निर्माण किया। नए-नए व्यापारिक केन्द्रों व बन्दरगाहों के विकास ने औद्योगीकरण को बड़ा बढ़ावा दिया। यही कारण है कि आज देश में जिन स्थानों पर उद्योग-धन्धों का अधिक घनत्व है, उनका जन्म वास्तव में ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ।^१

(३) अंग्रेजी भाषा का प्रचलन—सन् १८३५ से अंग्रेजी भाषा भारत में बहुत लोकप्रिय होने लगी, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के वैज्ञानिक व अन्य सांख्यिक विषयों को समझना अत्यन्त कठिन था। व्यावसायिक संगठन के सिद्धान्तों को समझने के लिए तथा पाश्चात्य भावधर्मों पर औद्योगिक प्रबन्ध को संचालित करने के लिए अंग्रेजी भाषा की जानकारी बहुत जरूरी थी। भारत में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में अंग्रेजी शिक्षा ने बहुत मदद दी।^२ अंग्रेजी भाषा ने देश में मध्यम वर्ग तथा वकीलों, डाक्टरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों बैंकर्स आदि को भी प्रोत्साहित किया। इन लोगों के सहयोग से औद्योगिक विकास सरलता से घनपने लगा।

1 "We make our appearance in the long list of races who have ruled that splendid empire, not as the temple builders, like the Hindus nor as palace and tomb builders like Musalmans, nor as fort builders like the Marathas, nor as Church builders like Portuguese; but in the more common place capacity of town builders, as a nation that had the talent of selecting sites on which great commercial cities would grow up and who have in this created a new Industrial life for the Indian people"

—W W Hunter, the Indian Empire, Pages 659—60

2 "The best brains of India drank deeply at the well springs of British liberal thoughts. They learnt from Edmund Burke and John Stuart Mill the meaning of liberty, they shared the sympathy of England with the struggles of Mazzini and Cavour, they read of the French Revolution and the hated salt tax and they read, too, of the wrongs of Ireland. There political consciousness was aroused and they soon began to apply their newly acquired ideas of the rights of individuals and of peoples to their own country."

—Percival Griffiths 'Modern India (1957), Page 46

(४) ईस्ट इंडिया कम्पनी के एकाधिकार का समापन—सन् १८३३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया एवं प्रत्येक अंग्रेज व्यापारी को भारत से व्यापार करने का अवसर दिया गया। फल यह हुआ कि भारत में विदेशी पूँजी व उपक्रम का आयात बड़ी तेजी से होने लगा। पहले बगीचा उद्योग प्रारम्भ हुआ और बाद में विशाल एकाधिकृत उद्योग, जैसे फूट व रेल-उद्योग पनपन लगे। इस प्रकार देश में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास होने लगा।

(५) यातायात के साधनों में वृद्धि—देश के अन्दर सड़क व रेल यातायात का बड़ी तेजी से विकास हुआ। इसके अतिरिक्त स्वेज नहर के निर्माण में यूरोपीय देश भी भारत के बहुत निकट आ गए। यातायात के साधनों में वृद्धि से कच्चा माल बड़ी सुविधा से कारखानों को भेजा जाने लगा। इसी प्रकार निर्मित माल के विनरण में भी बड़ी सुविधा हो गई। इससे भी औद्योगीकरण को बड़ा बढ़ावा मिला।

(६) राजनैतिक घटनाएँ—राजनैतिक क्षेत्र की कुछ हल-चलों ने भी औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए अमेरिकन गृह उद्योग ने सूती वस्त्र मिल उद्योग एवं क्रीमियन युद्ध ने जूट-उद्योग को बढ़ावा दिया। भारत में स्वदेशी आन्दोलन ने भी लोगों की आँखें खोल दी और इनका ध्यान औद्योगीकरण की ओर आकर्षित किया। इस सब घटनाओं से भी औद्योगीकरण को बहुत बल मिला।

धीमी औद्योगिक प्रगति के कारण—

यद्यपि उपर्युक्त घटकों के परिणामस्वरूप भारत में औद्योगीकरण की एक लहर आई एवं अनेक उद्योगों की स्थापना भी हुई, परन्तु जो भी विकास हुआ वह पूर्णतः अनियोजित था। यही कारण है कि प्रथम महायुद्ध तक देश में जो भी औद्योगिक प्रगति हुई, उसके परिणाम विशेष उत्साहवर्द्धक नहीं हुए। प्राकृतिक सम्पदा में अत्यन्त घनी होते हुए भी भारत में औद्योगीकरण की गति बहुत धीमी रही।^१ इस धीमी गति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1 With abundant supplies of raw materials, with a redundant population often starving because of lack of profitable employment; with a hoard of gold and silver second perhaps to none in the world, and with access through the British Government to a money market which was lending large quantities of capital to the entire world, with an opening for British business leaders who were developing both at home and abroad all sorts of capitalistic industries, with an excellent market within her own borders India after a century was supporting only about 2% of her population by Factory Industry

—D H Buchanan, The Development of Capitalist Enterprise in India, Pages 450-51

धीमी प्रगति के कारण

१. औद्योगीकरण की योजना का अभाव ।
२. ब्रिटेन की आर्थिक व औद्योगिक नीति से संघर्ष ।
३. पूँजीकृत उद्योगों का अभाव ।
४. औद्योगीकरण के लिए पूँजी की कमी ।
५. स्वार्थ सहित विदेशी पूँजी व उपक्रम का आगमन ।
६. कृषि की पिछड़ी दशा ।
७. औद्योगिक प्रसाधनों के सम्बन्ध में अज्ञानता ।
८. श्रम की अकुशलता ।
९. यातायात के विकास से प्रतिस्पर्धा ।
१०. राजकीय सहयोग का अभाव ।

ही कच्चे माल से निर्मित वस्तुएँ बनाकर भारत के बाजारों में बेची गईं । अतएव औद्योगीकरण की किसी निश्चित योजना के अभाव में हमारे देश में उद्योगों के विकास की गति बहुत धीमी रही ।

(२) ब्रिटेन की आर्थिक व औद्योगिक नीति से संघर्ष—भारतीय हितों का सदैव ब्रिटेन की आर्थिक व औद्योगिक नीति से संघर्ष हुआ । जब कभी किसी आयोग अथवा समिति ने (जैसे दुर्भिक्ष आयोग १८८०) भारत में औद्योगीकरण के विकास पर बल दिया, तो उसकी सिफारिशों को कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया । यही नहीं, सकाशावर व मैन्वैस्टर के उद्योगपतियों व पूँजीपतियों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय हितों की बलि चढ़ाई गई ।^१

(१) औद्योगीकरण की योजना का अभाव—ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने भारत के नियोजित औद्योगिक विकास के लिए कभी भी कोई योजना नहीं बनाई । देश में जो थोड़ा सा औद्योगिक विकास हुआ उसके मुख्य कारण औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम तथा भारत में प्रारम्भ होने वाला स्वदेशी व राजनैतिक मान्दोलन थे । १९वीं शताब्दी तक भारत सरकार की नीति उद्योग-धन्धों में हस्तक्षेप न करने की रही । आधुनिक उद्योगों के प्रवर्तन व उनके विकास के लिए अथवा पुराने उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए कभी भी सक्रिय प्रयत्न नहीं किए गए । इसके विपरीत संयुक्त राज्य, जर्मनी व जापान में उद्योग धन्धों का तीव्र गति से विकास हुआ और हमारे

1 The Government's action upto World War I was limited to "a very imperfect provision of technical and industrial education, and the collection and dissemination of commercial and industrial information. All that was done, however, was due rather to a few farsighted individual officers than to any considered and general policy on the part of Government."

(३) पूँजी उद्योगों का अभाव—प्रारम्भ से ही भारतवर्ष में औद्योगिक प्रगति पूर्णतः अनियोजित रही। यहाँ उपभोक्ता उद्योग (Consumers Industries) की स्थापना की गई परन्तु पूँजीगत उद्योग, जैसे यंत्र निर्माण करने वाले उद्योग, भारी रासायनिक उद्योग, जहाज निर्माण करने वाले उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, आदि की स्थापना की दिशा में नेक मात्र भी प्रयत्न नहीं किए गये। अन्तर्क, मँगनीज, लोहा आदि पदार्थों से इस्पात बनाकर हम अधिकांशतः इनका निर्यात करते रहे। फलतः हमारी औद्योगिक प्रगति धीमी रही।

(४) औद्योगीकरण के लिए पूँजी की कमी—भारत में यद्यपि प्राकृतिक प्रसाधनों की भारमार रही है परन्तु पूँजी की सदैव कमी रही है। अधिकतर लोग जमीन में गाड़ कर अथवा गहनो अथवा माभूषणों के रूप में रुपयों को जोड़कर रखना अधिक अच्छा समझते हैं। औद्योगिक संस्थाओं के अश अथवा करण पत्रों को क्रय करके औद्योगीकरण में योग देना वे हिनकर नहीं समझते। जनसाधारण की इस सामान्य प्रवृत्ति के कारण भी औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी रही।

(५) स्वार्थ सहित विदेशी पूँजी व उपक्रम का आगमन—भारतवर्ष में अनेक उद्योग धंधों की स्थापना की गई और विदेशी पूँजी व उपक्रम ने भी इसमें सराहनीय सहयोग दिया, परन्तु विदेशियों ने अपने स्वार्थ की सदैव प्राथमिकता दी। अधिकांशतः विदेशी पूँजी बगीचा उद्योग, रेल-उद्योग व फूट उद्योग में ही लगाई गई। ऐसे उद्योगों से विदेशी पूँजी दूर ही रही जिनसे विदेशी हितों पर प्रभाव पड़ता।^१

(६) कृषि की पिछड़ी दशा—भारतीय उद्योगों की धीमी प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारण कृषि की पिछड़ी दशा भी रहा है। यद्यपि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, परन्तु उसके दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं किए गये। कृषि की अवनति के कारण भारतीय उद्योगों को बहुत हानि उठानी पड़ी।

(७) औद्योगिक प्रसाधनों के सम्बन्ध में अज्ञानता—अपने प्राकृतिक प्रसाधनों के सम्बन्ध में अज्ञानता के कारण हम तीव्रता से प्रगति न कर सके। औद्योगिक शक्ति का प्रमुख साधन 'कोयला' देश के एक सीमित क्षेत्र में ही पाया जाता है। उस समय जल विद्युत का लोगों को ज्ञान नहीं था। इस कारण भी हमारे विकास की गति बहुत धीमी रही।

(८) श्रम की अकुशलता—जन-शक्ति की दृष्टि से तो भारत सदैव से धनी रहा है, परन्तु कुशल श्रम शक्ति का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा भी रही है। उद्योग

1 "Foreign capital flowed into plantations, railway's and monopolistic industries like jute, rather than into those industries which would compete with the imports from foreign countries"

—Vera Anstey, The Economic Development of India (1952), Pages 24-25.

की तान्त्रिक कला में निपुण श्रमिका की यहाँ बहुत कमी रही है। अशिक्षित, असहनी एवं रुढ़िवादी होने के कारण भी विवेकीकरण अथवा आधुनिकीकरण की योजनाएँ सफल न हो सकी। फलतः विकास की गति धीमी रही।

(६) यातायात के विकास से प्रतिस्पर्धा—भारतवर्ष में यातायात के साधनों के विकास से एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तुओं का लाना ले जाना सुलभ हो गया। इस सुविधा का लाभ विदेशी निर्यातका ने उठाया। भारत की मणियों में विदेशी माल छा गया। देशी उद्योग अपने प्रतिस्पर्धा में टिक न सके एवं हमारे विकास की गति बहुत धीमी रही।

(१०) राजकीय सहयोग का अभाव—न्यून देशों की सरकारों ने अपने उद्योग धंधों के विकास के लिए भरसक प्रयत्न किये। विदेशों में प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों व कारीगरों का भेजा उद्योगों का आर्थिक सहायता प्रदान की परन्तु भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि हमारी औद्योगिक प्रगति धीमी रही।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Write an essay on the Evolution & Development of Modern Industries in India
- 2 Discuss the factors which have encouraged the growth of Indian Industries till World War I
- 3 Briefly discuss the factors that are responsible for the slow growth of Indian Industries in the past

प्रथम महायुद्ध से द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक भारतीय उद्योगों का विकास

(Development of Indian Industries from World War I till World War II)

प्रारम्भिक—

इस युग में निम्नलिखित घटनाओं में विशेष रूप से भारतीय उद्योग-धन्धों को प्रभावित किया:—(१) सन् १९१४-१८ का युद्ध युग, (२) सन् १९२०-२१ में मन्दी का भौका (३) सन् १९२१-२७ तक विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव, (४) सन् १९२६ ३३ तक विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, (५) सन् १९३५ में नए संविधान का प्रचलन, (६) सन् १९३७ में देश में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का बनना, इत्यादि। इस काल में आर्य राष्ट्रीयवाद को भी काफी बढ़ावा मिला। इसी अवधि में सर थॉमस हॉलैंड (Thomas Halland) की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग (सन् १८) से तो सर इब्राहीम रहीमतुल्ला (Sir Ibrahim Rahimtoola) की अध्यक्षता में प्रशुल्क आयोग (सन् १९-१-२२), विदेशी पूँजी समिति (सन् १९२५), जब से शाही कमीशन (Whitely Commission on Labour 1929- लगा। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की स्थापना की गई।

तो (जैसे

प्रथम-विश्व युद्ध एवं उसके बाद—

सन् १९१४ में प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ होते ही भारत की आर्थिक प्रगति को बड़ा आघात पहुँचा, क्योंकि सुरक्षा के लिए यातायात के साधनों का नियोजन होने से औद्योगिक यातायात की असुविधाएँ तथा औद्योगिक आवश्यक माल के आयात में अड़चनें उपस्थित हो गईं। अनेक उद्योगों के लिये, जैसे कोयला, मैंगनीज, वस्त्र-उद्योग आदि के निर्यात में कठिनाइयाँ आ गयीं। परन्तु यह आघात क्षणिक ही था। युद्ध सामग्री की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चारों ओर से मार्गें आईं और यह आवश्यक समझा गया कि सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में ही किया जाय। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बम्बई प्रान्त में इस युद्धकाल में वस्त्र मिल-उद्योग की काफी उन्नति हुई। इसी प्रकार बंगाल में जूट तथा कोयला उद्योग में वृद्धि

हुई, उड़ीसा एवं मध्य-प्रदेश में लोहे के उद्योग का विकास हुआ और मद्रास में चमड़ा, जलयान निर्माण व गाबुन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला। देश तथा विदेशों में भारतीय उद्योग निर्मित वस्तुओं की माँग में वृद्धि होने से उद्योगपतियों ने खूब लाभ कमाये।

सन् १९१६ में युद्ध समाप्त होने ही व्यापारिक क्रियायें बटने लगी तथा बड़ी हुई माँग को पूरा करने के लिये उद्योगों ने अपने पुनर्संरुद्धन तथा विकास की योजनायें बनाईं। अनेक नये उद्योग स्थापित किये गये तथा पुराने उद्योगों का विकास किया गया। युद्ध के पूर्व भारत में २,६२१ कम्पनियाँ थी, जिनकी प्रदत्त पूँजी ७६ करोड़ रु० थी, परन्तु सन् १९१८-१९ में यह संख्या बढ़कर २,७१३ हो गई, इनकी प्रदत्त पूँजी की राशि १०६ करोड़ रु० थी। यही संख्या सन् १९२१-२२ में ४७८१ हो गई तथा इनकी प्रदत्त पूँजी २२३ करोड़ रु० थी। बम्बई की बल मिल कम्पनियों ने सन् १९१८-२१ के चार वर्षों में क्रमशः २३७,४०१, ३५२ तथा ३०'८ प्रतिशत लाभान्वित किया। ऐसी ही स्थिति अन्य उद्योगों की भी रही। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ से ही लागू इस बात का अनुभव करने लगे कि आवश्यक पदार्थों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना घातक होगा।^१

प्रथम महायुद्ध की अवधि में जूट उद्योग ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के कि सैनिक व व्यापार प्रादि की आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु थैलों, बोरो के माँग बहुत बढ़ गई की। सन् १९१३-१४ में केवल ६४ जूट की मिलें थी, १ ३६,०५० लुम्स व ७४४,२८६ स्पिन्डिल्स लगे हुए थे। परन्तु सन् १९१८-१९ मिलों की संख्या ७६ हो गई एवं लुम्स व स्पिन्डिल्स की संख्या क्रमशः २ ० व ८,२३,७०० हो गई। सन् १९१४ में दाटा के लौह व स्पाय के कारखानों की भी अत्यन्त शोचनीय थी, परन्तु युद्ध-काल में इसे सरकार की ओर से भारी ३ प्राप्त हुए। अतएव इस उद्योग ने भी भारी लाभ कमाये। रासायनिक उद्योग, इस काल में सराहनीय प्रगति की। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों, जैसे—कास्टिक सोडा, मैग्नेशियम क्लोराइड, सन्धन का तेल, जिंक क्लोराइड आदि का निर्माण किया गया। चमड़ा कमाने व बनाने के उद्योग में भी पर्याप्त उन्नति की। सन् १९१३ में १७५ करोड़ रु० के मूल्य का कमाया हुआ चमड़ा निर्यात किया

1. "The outbreak of war brought home the realisation that it is dangerous to keep a country dependent for essential manufactures on other countries, particularly when its own self sufficient economic system had been undermined by a policy which was unfavourable to its industrial development."

—I L O : 'Recent Developments in certain Aspects of Indian Economy, Vol III, Page 9.

गया था, जबकि सन् १९१७-१८ में यह सख्या ४८६ करोड रु० हो गई। युद्धकाल में सूती वस्त्र मिल उद्योग ने सबसे अधिक उन्नति की, क्योंकि समस्त पूर्वी-एशियाई देशों की मांग की पूर्ति का भार भारतीय मिलों पर आ पड़ा। सूत का उत्पादन व निर्यात तो कुछ कम हुआ, परन्तु कपड़े का उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ गया। अन्य उद्योग, जिन्होंने युद्धकालीन परिस्थितियों का लाभ उठाकर प्रगति की, निम्न थे— खनिज तेल का निर्माण, सीमेन्ट, ग्लास, साबुन, तेजाब, पेंट व वार्निश, रासायनिक खाद, इ जीनियरी का सामान इत्यादि।

युद्धोपरान्त काल में उद्योग—

समय परिवर्तनशील है। यद्यपि सन् १९१४ से १९१८ के युद्ध युग में हमारे उद्योग धंधों में खूब प्रगति की व लाभ कमाया, परन्तु दुर्भाग्य से यह स्थिति दीर्घकाल तक न रह सकी। सन् १९२० में मन्दी के झुके से पाँसा पलट गया। गिरती हुई क्रय-शक्ति के कारण वस्तुओं की माग बहुत थोड़ी रह गई और उद्योग-पतियों को दिवाल निकालने पड़। सन् १९२१ से १९२७ तक विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव ने भी उद्योगपतियों को हतोत्साहित किया। सन् १९२४ से सन् १९२९ तक प्रायः सभी वस्तुओं के दाम अत्यन्त सस्ते रह गए और सन् १९२९ से तो आर्थिक मंदी ने एक विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया। भारत सरकार की मुद्रा चलन की नीति ने इस देश में आर्थिक मंदी के काल को और भी बढ़ा दिया।^१ हाँ जब से उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया गया तब से उनकी दशा में थोड़ा सुधार होने लगा। सरक्षण की नीति के अन्तर्गत कोपला उद्योग को छाड़कर प्रायः सभी उद्योगों (जैसे लोहा व इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र मिल उद्योग, आदि) ने सतोपजनक प्रगति की। विवेचनात्मक सरक्षण की नीति से विभिन्न उद्योगों को जो लाभ हुए, उनका अनुमान निम्नलिखित तालिका से भली प्रकार लगाया जा सकता है—

1 "The pegging of exchange by Government at a parity even higher than pre-war may be taken as one of the contributing factors to the prolonged period of general post war depression "

विभिन्न उद्योगों की प्रगति (१९२२-२३—१९३६-४०)

वर्ष	स्टील (इनगाइट्स)	काटन (पीस मुड्स)	शक्कर (गन्ना)	दियासलाई	कागज
	१००० टन	मिलियन गज	१००० टन	ग्रास (लाख)	१००० टन
१९२२-२३	१३१	१७२५	२४	८	२४
१९३६-४०	१,०७०	४,०१३	१,२४२	२२०	७०

मदी के युग में इन रक्षित उद्योगों में धरक्षित उद्योगों की प्रपेक्षा मदी का अधिक सुन्दरता से सामना किया और डट रह। अन्य उद्योग मदी का सामना न कर सके और समाप्त हो गये। जिन उद्योगों को संरक्षण मिला उनमें सम्बन्धित अनेक सहायक उद्योग भी उन्नति कर गये। इसने अन्य लोगों को काम मिला तथा बेकारी की समस्या हल हुई।

सन् १९३७ में देश में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बन जाने से हमारे लोकप्रिय मन्त्रियों ने औद्योगिक विकास की ओर अपना ध्यान दिया। उन्होंने औद्योगिक भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए एक 'उद्योग मंत्री सम्मेलन' बुलाया, जिसके प्रस्तावों के अनुसार राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee) का निर्माण हुआ। इस समिति ने विभिन्न विषयों पर छान-बीन करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, जिससे हमारे वर्तमान योजना आयोग के निर्माताओं को भी अनमोल सामग्री मिली है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में गुणात्मक दृष्टि में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ, किन्तु सख्यात्मक दृष्टि से भारत का औद्योगिक विकास सतोंपन्नक रहा। यदि हम सन् १९२२ से १९३६ तक के १४ वर्षों के औद्योगिक विकास की गति का अवलोकन करें, तो पता लगेगा कि उत्पादकता उत्पादन १.२ लाख टन से १०.४२ लाख टन (८०० प्रतिशत) हो गया, सूती वस्त्रों का उत्पादन १,७१४ मिलियन गज से ४,०१६ मिलियन गज (२५० प्रतिशत) हो गया, दियासलाई का उत्पादन १६ मिलियन ग्राँस में बढ़ कर २२ मिलियन ग्राँस हो गया, अर्थात् ३८% की वृद्धि हुई, कागज का उत्पादन २४,००० टन से बढ़ कर ६७,००० टन (१८०%) हो गया, गन्ने का उत्पादन १४,००० टन से ६,३१०,००० टन हो गया इत्यादि। कारखानों की संख्या, जोकि सन् १९१४ में २,६३६ थी, सन् १९३६ में ११,६१३ हो गई एवं श्रमिकों की संख्या ६,५०,००० से बढ़ कर १७,५०,००० हो गई।

इस युग के औद्योगिक विकास की प्रमुख विशेषतायें—

प्रथम महायुद्ध से द्वितीय महायुद्ध तक की अवधि के औद्योगिक विकास की कुछ उल्लेखनीय विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(१) सरकार की औद्योगिक नीति में परिवर्तन—प्रथम महायुद्ध के पूर्व भारत सरकार की आर्थिक नीति उद्योगों के प्रति बड़ी उपेक्षापूर्ण थी। उद्योगों के नियोजित विकास के लिये यदि किंचित प्रयत्न किये भी गये तो वे निजी उद्योगपतियों द्वारा ही किये गये, भारत सरकार ने उनको प्रोत्साहित नहीं किया।^१ देश में जन समाज की धारणा सरकार के प्रति बहुत खराब हो रही थी। उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिये चारों ओर से आंग हो रही थी। इन परिस्थितियों से विवक्ष होकर भारत सरकार ने सन् १९१६ में औद्योगिक आयोग (Industrial Commission) की नियुक्ति की। युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की सतुष्टि के हेतु कमाण्डर-इन-चीफ की सिफारिशों पर सन् १९१७ में एक म्यूनिसनस् बोर्ड (Munitions Board) की नियुक्ति की गई। इस बोर्ड ने अनेक प्राचीन उद्योगों के विकास के लिये सहायता दी। इसके द्वारा प्रदान की गई सहायता के विभिन्न रूप ये थे—(१) भारत में ही कच्चे माल आदि की खरीद करना, (२) यू० के० आदि की आवश्यकताओं की सतुष्टि भारतीय उद्योगों द्वारा करना (३) बाहर से तांत्रिक सहायता व यंत्रों के आयात के लिये आर्थिक सहायता देना, (४) जो व्यक्ति नवीन उद्योगों की स्थापना करना चाहते ह, उनको आवश्यक सलाह व सूचना प्रदान करना। गहन अध्ययन के उपरान्त बोर्ड ने इस बात का पता लगाया कि अभी तक भारत जिन चीजों का विदेश से आयात करता रहा है, उनका निर्माण स्वयं भारत में किया जा सकता है।

(२) औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट—गहन जांच के उपरान्त औद्योगिक आयोग १९१६ ने सन् १९१८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि यद्यपि भारत औद्योगिक प्रसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी है, परन्तु वह अपने आधुनिक उद्योगों की नियोजित प्रगति करने में असमर्थ रहा है, अतएव भारत सरकार को देश की भावी औद्योगिक प्रगति के लिये “रचनात्मक कदम उठाने चाहिये। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी—(१) उद्योग के इम्पेरियल व प्रान्तीय (Imperial and Provincial) विभागों की स्थापना की जाय, (२) वैज्ञानिक व तांत्रिक सेवाओं का संगठन किया जाय, (३) औद्योगिक व तांत्रिक

1 “No such policy had existed hitherto, such efforts as had been made generally owed their inspiration to the enthusiasm of individuals rather than to any consistent purpose on the part of Government”

शिक्षा की सुविधायें बढ़ाई जाएँ; (४) राजकीय स्टोर व्रय नीति में परिवर्तन किया जाय। आयोग ने उद्योगों को आर्थिक सहायता देने तथा कुछ प्रदर्शन कारखानों के खोलने की भी सिफारिश की। आयोग की सिफारिशों को केन्द्र व प्रान्त की सरकारों ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया। सन् १९२१ में उद्योगों के इम्पीरियल विभाग (Imperial Department of Industries) की स्थापना की गई। मोन्टेग्यु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (Montague Chemsford Report) के बाद, कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रान्तीय सरकारों द्वारा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना कठिन हो गया। सन् १९२१ में उद्योगों तथा खनिज ध्वनसाय में ११.९२ लाख श्रमिक लगे हुए थे। ६ लाख से अधिक श्रमिक केवल ४ उद्योगों (वस्त्र मिल-उद्योग, जूट उद्योग, कोयला उद्योग व रेल उद्योग) में लगे हुए थे। जहाज निर्माण, भारी रासायनिक उद्योग, ऑटोमोबाइलस् जैसे—इंजीनियरिंग उद्योग का देश में पूर्णतः अभाव था।

(३) प्राशुत्त्विक स्वतन्त्रता व विवेचनात्मक संरक्षण—सन् १९१४-१८ के प्रथम महायुद्ध में सरकार को अपनी आयात-निर्यात पर अधिक नियन्त्रण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। दूसरे, इन दिनों स्वदेशी आन्दोलन भी जोर पकड़ रहा था, जिसमें ब्रिटिश नीति की कड़ी आलोचना हो रही थी। इसके अतिरिक्त युद्धकाल में औद्योगिक दृष्टि से भारत पिछड़ा होने के कारण, जो अनुभव जर्मनी को हुए, उनमें विवश हो करके, यह आवश्यक समझा गया कि औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तन किया जाय। अतः युद्ध स्थिति में घबरकर ब्रिटिश सरकार ने कुछ भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया। सन् १९१६ के औद्योगिक आयोग ने भी यह सिफारिश की कि औद्योगिक उत्तरदायित्व लेने के लिए सरकार अपने पास वैज्ञानिक एवं तात्त्विक विशेषज्ञों की पर्याप्त नियुक्ति करे, जो उद्योगों को परामर्श दे सकें। परन्तु दुर्भाग्य से आयोग की सिफारिशों को ठाक में रख दिया गया।^१

अगस्त १९१७ में मोन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुई, जिसके अनुसार भारतीयों को स्वयं निष्पन्न का अधिकार (Right of self-determination) मिला। भारत की आर्थिक स्वतन्त्रता की दिशा में यह पहला कदम था। इस स्वयं निर्णय के अधिकार के सम्बन्ध में जोइन्ट सिलेक्ट कमेटी का यह मत था कि, "भारत एवं इंग्लैंड की सरकार के सम्बन्धों को अन्य किसी बात से इतना खतरा नहीं है, जितना इस विश्वास से कि भारत की प्रशुल्क नीति का संचालन ग्रेट ब्रिटेन के व्यापारिक हितों के लिये ह्वाइट हाउस से होता है और आज भी यही विश्वास है, इसमें सन्देह नहीं। इस समस्या का समुचित हल अभी सम्भव है, जब भारत सरकार को ब्रिटिश साम्राज्य का अविच्छिन्न भाग होने के नाते भारत की आवश्यकता के अनुसार

प्रशुल्क व्यवस्था करने की स्वतन्त्रता दी जाय, जिसका विश्वास एक प्रतिज्ञा प्राप्ति (Acknowledgement of Convention) से दिया जा सकता है।^१ इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सन् १९२१ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्राशुल्क स्वतन्त्रता का प्रस्ताव (Fiscal Autonomy Convention) पास किया। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत मन्त्री को प्रशुल्क सम्बन्धी उन मामला में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रहा, जिनको कि भारत सरकार ने स्वयं अपनी विज्ञान सभा की सम्मति से तय कर लिया हो। किन्तु ऐसी स्वतन्त्रता से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि प्रायः सभी प्राशुल्क विषयों पर भारत सरकार पहले भारत मन्त्री से पूछ लेती थी और तत्पश्चात् ही विधान सभा के सम्मुख रखती थी। अतः भारत की प्रशुल्क सम्बन्धी नीति की पूर्ण जाँच तथा साम्राज्य प्राथमिकता के प्रस्ताव पर विचार करके सिफारिश करने के लिए एक प्रशुल्क मण्डल (Fiscal or Tariff Commission) नियुक्त किया गया। इसने विभेदात्मक संरक्षण (Discriminating Protection) के पक्ष में सुझाव दिया। संरक्षण की इस नीति से हमारे उद्योगों को विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इसके द्वारा प्रदान किए हुए “त्रिषुखी सिद्धान्त” की नई शर्तें अत्यन्त कठोर थी।

(४) स्टोर-क्रय नीति में परिवर्तन—सन् १९२० की स्टोर-क्रय नीति समिति (Stores Purchase Committee, 1920) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने अपनी क्रय-नीति में भी परिवर्तन किया। भारत सरकार ने देशी उद्योगों द्वारा निर्मित पदार्थों के क्रय में प्राथमिकता देना शुरू किया। सन् १९२४ से यह अनिवार्य हो गया कि सरकार विदेशों से जो माल खरीदेगी उस पर ‘कर’ देना पड़ेगा, इससे देशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला।

(५) मन्दी होते हुए भी प्रगति—सन् १९२६ से मन्दी का भोका होते हुए भी सन् १९२८ से सन् १९३५ की अवधि में भारतीय उद्योगों ने सराहनीय प्रगति की। उदाहरण के लिए, सूती वस्त्रों के उत्पादन में ४१% की वृद्धि हुई, जबकि जापान में यह प्रतिशत केवल ३४ थी एवं अन्य देशों में तो बड़ी दयनीय दशा थी। इसी प्रकार हमारा स्पात का उत्पादन भी ७५% बढ़ गया, जबकि जापान में केवल ५५% की वृद्धि हुई तथा मरुफुत्, गन्ना, मसूरिका, फाम. व. थोट. त्रिजेज, मे. हो. कपास, ५४%, ३०% व २०% की घटोत्तरी हो गई। इसी प्रकार सीमेन्ट का उत्पादन भी सन् १९२४ में २,६३,७४६ टन की अपेक्षा, सन् १९३३ में ६,२५,८६० टन हो गया।^२ भारतीय उद्योगों की प्रगति, वास्तव में, संरक्षण के कारण हो सकी।

1. "Tariff and Industry" by John Matthal

2 G E Hubbard, 'Eastern Industrialisation and its Effects on the West,' Page 305.

(६) राजनैतिक आन्दोलन—देश तथा विदेश के राजनैतिक आन्दोलनों ने भी औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शुरू होने वाले 'स्वदेशी आन्दोलन' ने घरेलू उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित किया। जिन लोगों में राष्ट्रीयता की थोड़ी भी भावना थी, उन्होंने भारतीय पूँजी व प्रबन्ध द्वारा उद्योगों के विकास पर बल दिया। असहयोग-आन्दोलन से राष्ट्रीयकरण को और भी प्रेरणा मिली।^१

(७) लीग ऑफ नेशन्स व अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सदस्यता—इससे भी भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। जब हमारे प्रतिनिधि लीग ऑफ नेशन्स व अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए गए, तो वे अनेक उन्नतिशील देशों के लोगों के सम्पर्क में आए। इन संस्थाओं के वैज्ञानिक अध्ययन व प्रस्तावों से भी भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। श्रम सन्तुलन का विकास हुआ तथा श्रमिकों के काम की दशाओं में भारी सुधार हुआ। सन् १९३१ में श्रम के शाही कमिशन (Royal Commission on Labour) ने श्रमिकों के काम के घंटों में कमी करने, मौसमी कारखानों में भी कारखाना अधिनियम लागू करने, निरीक्षण में सुधार, सुरक्षा आदि बातों के सम्बन्ध में सिफारिशें की, जिनके पालन करने में भारतीय उद्योगों का काफी विकास हुआ।

औद्योगिक विकास में दुर्बलतायें—

यद्यपि प्रथम महायुद्ध से द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक भारतीय उद्योगों ने काफी उन्नति की, परन्तु हमारे विकास में अनेक दुर्बलतायें रह गईं। एक उल्लेखनीय दुर्बलता तो यह थी कि लौह व स्पात उद्योग को छोड़कर पूँजीकृत वस्तुओं (Capital goods) के निर्माण के हेतु एक भी उद्योग नहीं खोला गया। जिनने भी उद्योग खोले गए, वे उपभोक्ता पदार्थों (Consumers' goods) अथवा कृषि पदार्थों के प्रोसेसिंग से ही सम्बन्ध रखते थे, जैसे, वस्त्र मिल उद्योग, आटे की चक्कियाँ, तेल-पेरने के कारखाने, खनिज उद्योग, जिनम व प्रेसिंग मिल आदि। इन उद्योगों में काम आने वाली मशीनरी व रसायनिक पदार्थों का भी विदेशों से आयात किया जाता था। परिणामस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन-व्यय अधिक होता था एवं युद्ध-काल में मशीनरी के आयात में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह सब कुछ बड़े आश्चर्य का विषय है कि सन् १९१४-१८ के महासमर ने भी उद्योगपतियों व सरकार की, औद्योगिक दुर्बलताओं के प्रति छाँछे उड़ी खोली। फलतः हमारे औद्योगिक कलेवर में अनेक

1 "The Non-cooperation Movement quickened the Indian consciousness to the need for greater control of economic life of the country by the nationals themselves. All this helped indirectly in the growth of Indian Industry."

खाइयाँ रह गईं । हमारे औद्योगिक विकास की कुछ मूलभूत दुर्बलतायें निम्नलिखित थी—

(१) औद्योगिक विकास की परम्परागत पद्धति—भारतीय उद्योगपतियों ने दुनियाँ के साथ कदम-ब-कदम मिलाकर चलना नहीं सीखा । वे अपनी प्राचीन उत्पादन प्रणालियों का ही अनुकरण करते रह । नये यन्त्रों व आविष्कारों का प्रयोग बहुत बाद में किया गया । वे अधिकांश व्यापारी ही रहे, निर्माता नहीं ।

(२) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली—हमारे औद्योगिक कलेवर का दूसरा उल्लेखनीय दोष—प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति है । इसने औद्योगिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहित किया । हमारे सभी बड़-बड़ उद्योग मुट्ठी-भर लागे के हाथों में आ गए । अनेक लोगो (विशेषतः अज्ञधारिया ने) ने इस प्रणाली का घोर विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप सन् १९३६ में भारतीय कम्पनी अधिनियम में अनेक प्रतिबन्धात्मक नियम जोड़ दिए गए । योग्य विशेषज्ञों के अभाव व अकुशल औद्योगिक संगठन के कारण हमारा विकास अनियोजित रहा ।^१

(३) विभेदात्मक संरक्षण की कठिन शर्तें—यद्यपि संरक्षण की विभेदात्मक नीति से कुछ उद्योगों को विशेष लाभ हुआ, तथापि उसे व्यापार व उद्योगों के हित में नहीं कह सकते, क्योंकि संरक्षण की शर्तें बहुत कड़ी थीं । उदाहरणार्थ यह विचार बड़ा हास्यप्रद है कि जब उद्योग को प्राकृतिक सुविधायें प्राप्त हों, तब ही उसे संरक्षण दिया जाय । यदि प्राकृतिक सुविधायें उद्योग को सुलभ हों, तो फिर उसे संरक्षण की आवश्यकता ही क्यों होने लगी ? दूसरे किसी उद्योग को आन्तरिक बाजार न होने की दशा में संरक्षण से वंचित रखना भी अन्याय था, क्योंकि वास्तव में ऐसे ही उद्योग संरक्षण के प्रथम अधिकारी थे । वे उसके बल पर उन्नति करके बाजार बना सकते थे । संक्षेप में, उद्योगों का महत्त्व देश के हित की दृष्टि से कभी भी नहीं आँका गया, जैसा कि मैनेशियम क्लोराइड उद्योग अथवा रासायनिक उद्योग के सम्बन्ध में अपनाई गई अविवेकपूर्ण नीति से स्पष्ट है । मैनेशियम क्लोराइड उद्योग की जाँच सन् १९२४ में की गई, किन्तु उसे इस आधार पर संरक्षण नहीं दिया गया कि वह अन्ततः संरक्षण के अभाव में नहीं टिक सकता । इसके विपरीत जब सन् १९२८ में इस उद्योग में संरक्षण की पुनः माँग की, तो प्रशुल्क बोर्ड ने यह मत दिया कि उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है । किसी भी देश में उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने में इस प्रकार की शर्तें नहीं लगी हैं । यथार्थ में सन् १९४६ के प्रशुल्क आयोग को यह कहना

1 "The Managing Agency System tended at its worst to perpetuate what are, perhaps, the two chief factors preventing the more rapid industrial development in India : i.e., the deficiency of men capable of industrial leadership and inefficient industrial organisation."

पडा है कि सन् १९२२ के प्रस्तुत आयोग ने "रक्षण को आर्थिक विकास के एक सामान्य साधन के रूप में नहीं देखा था, परन्तु उसे केवल एक ऐसा सहारा समझा जिसके द्वारा कुछ उद्योगों को, जब वे रक्षण के लिए प्रार्थना करें, विदेशी प्रतियोगिता सहन करने की शक्ति दी जा सके। परिणाम एक दिशायी विकास है—आधारभूत (Key or Base) व सुरक्षा (Defence) उद्योगों के लिए विकसित होना सम्भव न हो सका। यह भी सम्भव है कि कुछ थोड़े से उद्योगों को उसी समय यह प्रयत्न किए बिना कि उनसे मिलते-जुलते और उनके सहायक उद्योगों को भी सुविधा प्रदान की जाय, संरक्षण दे देने से समाज का सामूहिक भार बढ गया।"।

(४) विदेशी पूँजी व उपक्रम का प्रभुत्व—संरक्षण की नीति व सस्ते धन का लाभ उठाने के लिए भारत की घोर विदेशी पूँजी व उपक्रम आकर्षित हुए, परन्तु उनसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं हुई। लाभ का अधिकांश भाग विदेशों को चला जाता था। प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता व तान्त्रिक ज्ञान की सुविधा भारतीय धर्मिकों को नहीं दी गई। भारतीयों ने अत्यन्त निम्न मजदूरी पर अपने धर्म की 'बलि' दी, इसके विपरीत उन्हें बेतन वाले सभी स्थान योरोपियों को दिए गए। सारांश में, विदेशी पूँजी व उपक्रम ने भारतीय धर्म व प्राकृतिक सम्पदा का खूब शोषण किया।

(५) दूषित पूँजी के कलेवर—औद्योगिक संस्थाओं के पूँजी के कलेवर भी दूषित थे। अति पूँजीकरण (Over capitalization) व निम्न पूँजीकरण (Under capitalization) के दोषों के कारण मन्दी के काल में अनेक संस्थाओं का समापन हो गया। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने सन् १९३१ में अपनी रिपोर्ट में इस बात का संकेत किया कि औद्योगिक संस्थायें वित्तीय योजनाकरण व दूरदर्शिता के अभाव में प्रसिद्ध हैं। अतएव समिति ने विशिष्ट अर्थ संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया।

(६) तान्त्रिक प्रशिक्षण का अभाव—यद्यपि इस अवधि में केन्द्र व प्रान्तीय सरकारों द्वारा कुछ तान्त्रिक संस्थायें खोली गईं, परन्तु भारत की औद्योगीकरण की आवश्यकताओं की 'सन्तुष्टि' के लिए उनकी संख्या सागर में एक बूँद के समान थी। औद्योगिक अनुसन्धान का भी घोर अभाव था।

(७) उद्योगों का आकार व स्थानीयकरण—औद्योगिक संगठन के सिद्धान्तों की जानकारी के अभाव के कारण, अनेक औद्योगिक संस्थाओं का आकार अनाधिक था। स्थानीयकरण भी अत्यन्त दूषित था। बंगाल व बम्बई में क्रमशः हमारे ३८.१% व २८.७% उद्योग केन्द्रित थे। उद्योगों के प्रादेशिक वितरण के हेतु कभी भी रचनात्मक प्रयत्न नहीं किए गए।

(न) राजनैतिक व सामाजिक दोष—विदेशी सरकार के शासन व सामाजिक वातावरण ने भी हमारी औद्योगिक प्रगति पर प्रतिबन्ध लगा दिए । श्रमिका का निम्न जीवन-स्तर, उनकी अक्षमता, अशिक्षा, अज्ञानता व रूढ़ि-वादिता, आदि दोषों के कारण भी औद्योगिक विकास की गति धीमी रही ।

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the development of Indian Industries during World-War I
 2. Discuss the effects of the world wide depression in 1929-30 on Indian Industries How far could the tariff protection save our industries ?
 3. Discuss carefully the salient features of India's industrial development during the period 1914—1939
 4. Point out the principal gaps in the Indian Industrial structure of the country during the period 1914— 1939
-

द्वितीय महायुद्ध के युग में भारतीय उद्योगों का विकास

(Development of Indian Industries during World-War II Period)

(१९३९-४५)

प्रारम्भिक—

सन् १९१९-४५ का काल उद्योगों का 'स्वर्ण-काल' माना जाता है। सन् १९३९ में द्वितीय महासमर प्रारम्भ होते ही, योरोपीय आयात कम हो गए, जिससे हमारे उद्योगों की प्रतियोगिता का डर नहीं रहा। भारतीय अर्थ-व्यवस्था, जो मन्दी के कारण धुँधली पड़ गई थी, पुनः चमकने लगी। युद्ध के आरम्भ होते ही, भारत सरकार, ब्रिटेन की सरकार (His Majesty's Government) तथा मित्र राष्ट्रों (Allied Countries) की ओर से औद्योगिक पदार्थों के लिए भारी मात्रा में आदेश (Orders) आने लगे। अतः बढ़ती हुई युद्ध सामग्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योगों का काफी विकास हुआ। द्वितीय महासमर के वास्तव में, इस बात की द्वितीय चेतावनी (प्रथम महासमर 'प्रथम चेतावनी' था) दी कि अपनी जन व प्राकृतिक सम्पदा के आधार पर भारत एक महान् औद्योगिक राष्ट्र बन सकता है। सर रामास्वामी मुदालियर (Sir A. Ramaswami Mudaliar) ने भारत सरकार की ओर से लोगों को यह आश्वासन दिया कि जो उद्योग-पति युद्धकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देंगे, उसे सरकार अकेला नहीं छोड़ेगी।^१ युद्ध सम्बन्धी सामग्री के निर्माण के हेतु भारत कटौत कर सहयोग दे सकता है एवं इसकी वना क्षमता है, इस बात का अध्ययन करने के लिये हमारे देश में रॉजर व ग्रेडी मिशन (Roger and Grady Missions) आये। पूर्वी देशों में युद्ध सम्बन्धी सामग्री के उत्पादन के समन्वय में व उसकी वृद्धि के लिये ईस्टर्न ग्रुप सप्लाय

1 "In case we, in any form, encourage the development of Industries, for our war needs those entrepreneurs who had come to the assistance of the State, would not be left high and dry to take care of themselves."

—Sir A. Ramaswami Mudaliar.

वाउरिल (Eastern Grain Supply Council) की स्थापना की गई। भारतीय पूर्ति विभाग (Indian Supply Department) ने निर्माण सम्बन्धी बड़े-बड़े पदार्थों व वस्तुओं से लेकर सिगरेट, साबुन, तेल आदि छोटे-छोटे पदार्थों को भी भारतीय उद्योगों से खरीदना शुरू कर दिया। सन् १९४२ तक लगभग साठे पाँच सौ करोड़ रुपये का माल खरीदा गया।

भारतीय उद्योगों पर द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव—

युद्धकाल में भारत के कपड़ा, चीनी, सीमेन्ट, लोहा एवं इस्पात, कागज तथा दियासलाई उद्योग सभी पूर्णतः आत्म-निर्भर हो गये थे। सन् १९४४ उत्पादन की दृष्टि से षोटी का वर्ष माना जाता है, जबकि ४,८४० मिलियन गज कपड़ा, १.२७ मिलियन टन चीनी, १.३७ मिलियन टन लौह पदार्थ, १.२६ मिलियन टन लूट, १.२७ मिलियन हज़ारवेद कागज, २६५ मिलियन टन कोयला तथा २.४२ मिलियन टन सीमेन्ट का उत्पादन हुआ। इस युग में अनेक नये-नये कारखाने व कम्पनियाँ खोली गईं तथा पुरानी औद्योगिक संस्थाओं का विस्तार किया गया। अतिरिक्त प्लान्ट लगाकर तथा उन्नत यंत्रों की सहायता से उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। अनेक उद्योगों ने अतिरिक्त पालियाँ चला कर बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की। अपनी उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने के लिये, कुछ संस्थाओं ने तांत्रिक एवं सगठन सम्बन्धी सुधार किये। अनेक आधारभूत व सुरक्षा उद्योगों की भी स्थापना की गई। लघु उद्योगों के विकास व विस्तार से पूर्ति के नये साधन पैदा हो गये। देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, जैसे—कटलरी का सामान, हैन्ड टूल्स, टेप्स, ड्रेन्स आदि का निर्माण होने लगा।^१ कुछ नवीन उद्योग, जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध की अवधि में ही उत्पादन प्रारम्भ किया, निम्न थे—(अ) फ़ैरी सिलीकोन व फ़ैरी मेगनीज उद्योग, (ब) नोनफ़ेरस मैटल्ल्स व मेटल फ़ैब्रिकेटिंग उद्योग, जैसे—ताँबा, तंबे की चादर, तार आदि सम्बन्धी उद्योग, (स) यंत्र सम्बन्धी उद्योग, जैसे—डीजल इंजन पंप, बाइसिकिल, सिलाई की मशीनें, मशीनों के औजार, इत्यादि, (द) वस्त्र, चाय व तेल के प्रोसेसिंग (Processing) से सम्बन्धित मशीनरी का निर्माण करने वाले उद्योग, (य) रासायनिक पदार्थ, जैसे—कास्टिक सोडा, क्लोरीन, सुपर फॉस्फेट आदि। हाँ, बड़ी मात्रा पर पूँजीकृत उद्योगों की

1 "Industry which were already in existence worked to full capacity and often in more shifts than one. New plants were added in some cases and a few basic industries were established. A rapid expansion of small scale industries all over the country created new sources of supply; a variety of goods like cutlery, skewers, hand tools, tapes, drains and camouflagenets and many other consumer and intermediary goods were manufactured."

स्थापना देश में न हो सकी। भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योगों की युद्ध-कालीन औद्योगिक प्रवृत्ति का अनुमान निम्नलिखित आँकड़ों से लगाया जा सकता है —

औद्योगिक उत्पादन के अंतरिम

सामान्य सूचनाक

(आधार वर्ष १९३७ = १००)

वर्ष

१९३८	१०५.४
१९३९	१०२.७
१९४०	१०६.६
१९४१	११७.८
१९४२	१११.२
१९४३	११७.०
१९४४	११७.०
१९४५	१२०.०

सन् १९३९ में कुल रजिस्टर्ड कम्पनियों की संख्या ११,११४ थी, तथा उसकी प्रदत्त पूँजी २६० करोड़ रु० थी। सन् १९४५ में कम्पनियों की संख्या बढ़कर १४,८५९ तथा प्रदत्त पूँजी की मात्रा ३८६ करोड़ रु० हो गयी। इसके बाद कम्पनियों की संख्या में ३,७४५ और प्रदत्त पूँजी की मात्रा में १०० करोड़ रु० की वृद्धि हुई।

औद्योगिक प्रश्न व्यवस्था पर कु-प्रभाव—

यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के काल में औद्योगिक संस्थाओं की संख्या, इनकी पूँजी की मात्रा तथा औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, परन्तु फिर भी कुछ कुप्रभाव (Adverse effects) भी हुए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(१) यंत्रों का अत्यधिक प्रयोग—द्वितीय महायुद्ध की अवधि में हमारे निर्माता-गण बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिये श्रमरुक्त से हो गये। उनके सम्मुख केवल एक ही उद्देश्य था—बढ़ी माँग की पूर्ति करना। उत्पादन के हेतु तांत्रिक कला एवं यंत्रों में सुधार की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। अधिक मार पड़ने के कारण वे घिस गईं व अप्रचलित हो गईं फिर भी उनके पुनर्स्थापन के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया। अनेक पालियों में काम होने के कारण निरन्तर उनका ह्रास ही होता गया। जब सन् १९४५ में युद्ध के बादल साफ हुए, तब हमारे उद्योगपतियों का नशा उतरा। माँग में कमी हुई एवं केवल अच्छी किस्म की वस्तुओं के लिये माँग की जाने लगी। अतः युद्ध के बाद लोगों का ध्यान आधुनिकीकरण व विवेकीकरण की ओर आकर्षित हुआ।

(२) मुद्रा-स्फीति एवं अभाव की दशाएँ—जैसा कि प्रायः युद्धकाल में होता है, सन् १९३६-४५ की अवधि में भी मुद्रा प्रसार (Inflation) बड़ी तेजी से होने लगा। वस्तुओं के मूल्य गगन की ओर बढ़ते गये। अधिकांश उत्पादकों का ध्यान सैनिक आवश्यकताओं की सतुष्टि की ओर केन्द्रित था, अतः सामान्य उपभोक्ताओं को आधारभूत आवश्यकता की वस्तुएँ भी नहीं मिलती थी। सारे देश में अभाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिये प्राइस कंट्रोल व राशनिंग (Price Control and Rationing) की व्यवस्था की गई। सबसे पहले शक्कर के वितरण व उत्पादन पर नियंत्रण लगाया गया और बाद में यह कंट्रोल अन्य आवश्यक पदार्थों पर भी लागू हो गया। वस्तुओं के अधिक मूल्य होने के कारण हमारे उद्योगपतियों ने भी उद्योगों के आधुनिकीकरण, वित्तीय संगठन, आर्थिक आकार, आदि प्रश्नों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मुद्रा प्रसार की दशाओं के ही कारण उद्योगपतियों ने मनमाने लाभ कमाये।

(३) आधारभूत उद्योगों की उपेक्षा—यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के काल में देश में अनेक नये-नये उद्योग-घरे खोले गये, परन्तु आधारभूत व पूँजीकृत उद्योगों का विकास पिछड़ा ही रहा। हमारे निर्माणागण मुद्रा प्रसार का अनुचित लाभ उठाकर ऊँचे लाभ कमाने में ही व्यस्त रहे, उन्होंने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की। परिणाम यह हुआ कि आधारभूत उद्योगों की दृष्टि से हम पिछड़ गये।

(४) कम्पनियों के निर्माण व प्रबन्ध में अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ—युद्ध युग में ऊँचे लाभ कमाने के उद्देश्य से कम्पनियों का निर्माण तो बड़ी तेजी से हुआ, परन्तु उनके प्रबन्ध व व्यवस्था पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, यही कारण है कि औद्योगिक सत्ता का केन्द्रीयकरण मुट्ठी भर लोगों के हाथों में बढ़ता गया। प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली को अनुचित बढ़ावा मिला। एक स्वस्थ औद्योगिक संस्था में लाभों का दुरुपयोग अस्वस्थ इकाइयों के पालन-पोषण में किया गया। विनियमकों व जन साधारण के हितों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। यही कारण है कि युद्ध समाप्त होते ही अकुशल कम्पनी प्रबन्ध के विरोध में आवाजे लगाई गईं एवं बाद में विवश होकर भारत सरकार को कम्पनी अधिनियम को बदलना पड़ा।

(५) वास्तविक मजदूरी की अपेक्षा लाभों में वृद्धि—द्वितीय महायुद्ध की अवधि में उद्योगपतियों ने तो मनमाने लाभ कमाये, परन्तु श्रमिकों की मांगों की उपेक्षा की गई। उनकी वास्तविक मजदूरी में लाभों की अपेक्षा बहुत कम वृद्धि हुई। इस प्रकार 'श्रम' की बलि पर 'पूँजी' ने लाभ कमाये। औद्योगिक समृद्धि में उनको उचित भाग नहीं दिया गया। निम्नलिखित शालिका इस बात पर प्रकाश डालती है—

सन् १९३६-४५ में औद्योगिक लाभ व श्रमिकों की वास्तविक
 आय के सूचनांक
 (आधार वर्ष १९३६=१००)

वर्ष	वास्तविक आय के सूचनांक	वास्तविक औद्योगिक लाभ के सूचनांक
१९३६	१००	१००
१९४०	१०२	१३२
१९४१	६८	१६३
१९४२	१०१	१५२
१९४३	७४	६६
१९४४	८२	६६
१९४५	८२	६२

युद्धोपरान्त काल (१९४५-४७) (Post-war crisis Period 1945-47)—

अगस्त १९४५ में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया। परन्तु फिर भी भारतीय अर्थ व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। युद्धकाल में हमारी औद्योगिक संस्थाओं में अनेक पालियों में कार्य हुआ। यन्त्र व उपकरण घिसे हुए थे। विदेशों ने मशीनरी के आयात की कठिनाइयों के कारण, पुनर्निर्माण की योजनाएँ (Reconstruction Programmes) कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। युद्धकाल में ममस्त उत्पादकों का ध्यान युद्ध-सम्बन्धी सामग्री के निर्माण की ओर लगा हुआ था, अतः उपभोक्ता पदार्थों का घोर प्रभाव था। मुद्रा प्रसार की दशाओं के कारण स्थिति और भी चिन्ताजनक थी। २१ अप्रैल सन् १९४५ को केन्द्रीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(अ) देश के प्रसाधनों के अधिकतम विदोहन द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना एवं तत्पश्चात् उसका समान वितरण करना।

(आ) सुरक्षा की दृष्टि से देश को अधिक तैयार करना।

(इ) रोजगार के साधनों में वृद्धि करना।

युद्ध-युग में अन्य लेने वाले उद्योगों की पूर्ण जाँच के लिए नवम्बर सन् १९४५ में दो वर्ष के लिए प्रशुल्क बोर्ड की स्थापना हुई। इस अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड (In-

terim Tariff Board, 1945) ने कुछ उद्योगों को सरक्षण देने की स्थिति पर विचार किया। अपने दो वर्ष के जीवन काल में अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड के पास ४६ मामले आए, जिनमें से ४२ को सरक्षण दिया गया। इनमें ३८ उद्योग युद्धकालीन तथा ४ उद्योग (सूती वस्त्र उद्योग, स्पात, कागज तथा चीनी उद्योग) पूर्व-स्थित थे। वास्तव में इसका प्रमुख कार्य उद्योगों की स्थिति की पूर्ण जाँच करके उनके लिए सरक्षण की सिफारिश करना था। किन्तु पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड अपने कर्तव्य का भली-भाँति पालन न कर सका।

औद्योगिक सस्याओं को मध्यम व दीर्घकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) की स्थापना पर भी गम्भीरता से विचार किया गया। १० अगस्त सन् १९४५ की अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक अनुसन्धान योजना समिति (Industrial Research Planning Committee) ने एक केन्द्रीय अनुसन्धान संगठन (Central Research Organisation) जिसका नाम राष्ट्रीय अनुसन्धान परिषद् (National Research Council) हो, की स्थापना पर बल दिया। समिति ने इस बात की भी सिफारिश की कि देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय अनुसन्धान सस्थायें खोली जानी चाहिए। दस वर्षों की अवधि में, औद्योगिक श्रमिकों के हेतु दो मिलियन मकान बनाने की भी एक योजना स्वीकार की गई। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के सम्मुख सामाजिक सुरक्षा की भी एक योजना प्रस्तुत की, जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा, प्रसूति लाभ व दुर्घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था की।

द्वितीय युद्ध ने भारतीय उद्योगों को अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने तथा अपने समस्त साधनों के प्रयोग करने का अवसर दिया था, जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन में दशशतीन वृद्धि हुई, परन्तु सन् १९४५ के बाद देश में अनेक राजनैतिक उलट-फेर हुए तथा सरकार की कर नीति मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये ऐसी रही जिसका उद्योगों की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरे, युद्ध युग में मशीनों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण वह जीर्ण-शीर्ण हो गई थी। फलतः उत्पादन व्यय अधिक हो रहा था। तीसरे, अमजीवी भी ऊँचे मूल्य स्तर के कारण असन्तुष्ट थे। चौथे, समस्त देश में हड़तालों की भी एक लहर आई थी। इन विविध परिस्थितियों में औद्योगिक उत्पादन गिरने लगा। अथलिखित तालिका से इस बात का आभास मिलता है :—

युद्धोपरास्त काल में औद्योगिक उत्पादन

विवरण	सन् १९३६ ४१ का ग्रीसत	वर्ष सहित चोटी का उत्पादन	सन् १९४५-सन् १९४६-४७ ४६	
सूती वस्त्र (मिलियन गज)	४,४१४	४,८७१ (१९४३-४४)	४,६७३	३,८६३
लूट का माल (हजार टन)	१,१०२	१,२५६ (१९४१-४२)	६७३	१,०४२
सीमेट (हजार टन)	२,००४	२,१८३ (१९४२-४३)	२,१४६	२,०१७
सल्फ्यूरिक एसिड (हजार हबरेट)	७८१	८५८ (१९४१-४२)	४८१	५६३
एमोनियम सल्फेट (हजार टन)	२५	३० (१९४१-४२)	२१	२२
चीनी (मिलियन हबरेट)	२१ ८	२२ ५ (१९४३-४४)	१६ ६	१६ १
कागज (हजार हबरेट)	१,८००	१,६५६ (१९४२-४३)	१,६८२	१,४३१
माचिस (मिलि- वन ग्रांस)	१८ ६	२३ १ (१९४०-४१)	२० ०	१५ ६
विंग घायरन (हजार टन)	१,७६८	१,८०४ (१९४२-४३)	१,४०६	१,३६४
स्टील इंगनोट (हजार टन)	१,२७५	१,३६६ (१९४३-४४)	१,३००	१,१६६
सैंगार इस्पात (हजार टन)	१,२५६	१,३५३ (१९४३-४४)	१,३३८	१,१६६

उपरोक्त तालिका के एकमात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि युद्धोपरास्त काल में देश के प्रायः प्रत्येक उद्योग का उत्पादन घिर गया, सूती वस्त्र, लौह-इस्पात, चीनी एवं कागज उद्योग की दशा इस दृष्टि से सबसे अधिक दयनीय थी। इस गिरते हुए उत्पादन के प्रमुख कारण अप्रतिष्ठित थे—

गिरते हुए उत्पादन के कारण—

(१) मशीनरी की प्राप्ति में कठिनाई—युद्ध-काल में मूल्यवर्धक प्रयोग एवं अनेक पातियों में काम होने के कारण हमारे उद्योगों की मशीनरी अप्रचलित होगई व घिस गई थी। उसके नवीनीकरण व प्राधुनिकीकरण के लिए बाहर से मशीनों का प्रायास अत्यन्त कठिन समस्या थी। भारत में मशीनों व अन्य पूँजीवस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था। प्राधुनिकीकरण की बात तो दूर रही, हमारे उद्योगपति

अपनी मशीनों की आवश्यक मरम्मत भी नहीं करा सके। यद्यपि कुछ उद्योगपतियों ने विदेशों से नई-नई मशीनों के आयात के लिये योजना भी बनाई, परन्तु समस्त विश्व में पूँजीकृत माल की कमी के कारण उनके अत्यधिक मूल्य ने उनकी योजनाओं को खटाई में डाल दिया। अतएव घिसी हुई व अप्रचलित मशीनों के द्वारा उत्पादन होने के कारण हमारा औद्योगिक उत्पादन बहुत गिरने लगा।

(२) श्रमिकों में अज्ञान्ति—द्वितीय महायुद्ध के काल में तो श्रमिकों को ऊँची-ऊँची मजदूरियाँ, मँहगाई व भत्ते मिलते रहे, परन्तु युद्धोपरान्त-काल में गिरती हुई माँग के कारण सेवायोजकों के लिये यह सम्भव न रहा कि वे मँहगाई व भत्ते देते रहे। अतएव वस्तुओं के गगनचुम्बी मूल्यों एवं मँहगाई के सामान्य वातावरण ने श्रमिकों को हड़तालों के लिये विवश किया। सन् १९४६-४७ में हड़तालों की एक बाढ़ सी आई। औद्योगिक अज्ञान्ति बढ़ने लगी। श्रम व पूँजी के झगड़ों में वृद्धि हुई। इस अनुशासन-हीनता, श्रमिकों की अनुपस्थिति एवं औद्योगिक अज्ञान्ति के परिणाम-स्वरूप उत्पादन गिरने लगा। अग्रिमिखित तानिका से युद्धकाल एवं इसके बाद की अवधि में हुए औद्योगिक सघर्षों का अनुमान लगाया जा सकता है—

युद्ध एवं युद्धोपरान्त काल में औद्योगिक संघर्ष

वर्ष	सघर्षों की संख्या	श्रमिकों की संख्या हजारों में	जन-दिनों (Man days) की हानि (मिलियन)
१९३६	४०६	४०६	५'०
१९४०	३२२	४५३	७ ६
१९४१	३५६	२६१	३ ३
१९४२	६६४	७७३	५'८
१९४३	७१६	५२५	२'३
१९४४	६५८	५५०	३ ४
१९४५	८२०	७४८	४'१
१९३६-४५ का औसत	५६७	५३५	४ ५
युद्धोपरांत काल—			
१९४६	१,६२६	१,६६२	१२ ७
१९४७	२,२५१	२,३५२	१६ ५

औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर सन् १९४७ में सेवायोजकों तथा श्रम-संघों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिससे कि श्रम व पूँजी के पारस्परिक सम्बन्ध सुधरे तथा गिरता हुआ उत्पादन रोका जा सके।

(३) यातायात की कठिनाई—यातायात की कठिनाईयों के कारण भी हमारे उद्योगों को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। अनेक कठिनाईयों के कारण रेल यातायात की दशा बड़ी खराब थी। वैगन्स का बहुत अभाव था। बाहर से बल पुर्जों के यातायात में कठिनाई होती थी। देश के विभाजन के पूर्व कलकत्ता व पंजाब में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों के कारण भी यातायात में कठिनाईयाँ घागीं। शरणार्थियों के लिये स्पेशल गाड़ियाँ चलाई गईं। शरणार्थी सिविल तक उनको पहुँचाने की व्यवस्था की गई, शरणार्थियों की सुविधा के लिये खाना पकड़ा व अन्य मामान भिजवाने की व्यवस्था की गई इत्यादि। इन सब कामों में यातायात व साधनों के उपभोग होने के कारण उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा एवं उत्पादन गिर गया।

(४) कोयले के यातायात में कठिनाई—कोयला औद्योगीकरण की जननी है, परन्तु यातायात की कठिनाई के कारण उद्योग-मनिया को उसकी प्राप्ति में बहुत असुविधा होने लगी। यद्यपि कोयल के उत्पादन में तो थोड़ी वृद्धि ही हुई, परन्तु मावागमन की कठिनाईयों के कारण इसका प्रयोग नहीं हो सका। कोयल की प्राप्ति की कठिनाई के ही कारण टाटा के लौह इस्पात के कारखाने को अपनी एक विशाल मट्टी को बंद करना पड़ा। इसी प्रकार सीमट, बल्ल व जूट मिल का उत्पादन कोयले की कमी से कुभावित हुआ।

(५) कच्चे माल की कमी—युद्धोपरान्त काल में हमारे कुछ कारखानों को कच्चे माल की कमी के कारण, उत्पादन कम करना पड़ा। उदाहरणार्थ—उत्तर-प्रदेश के अनेक बीनी मिला म तथा बंगाल के टीटागढ़ के कागज के कारखानों में उत्पादन में कमी का प्रधान कारण कच्चे माल का अभाव था।

(६) विनियोग प्रवृत्ति पर तुल्यतापात—औद्योगिक उत्पादन की गिरावट में एक कारण यह भी था कि जनता की उद्योग प्रवृत्ति दिन प्रति दिन कम होती जा रही थी। युद्धोत्तर काल में तो मुद्रा प्रसार के कारण लोगों के पास पैसे का आधिक्य था एवं उनकी क्रय-शक्ति भी बढ़ी हुई थी, अतः किसी भी औद्योगिक संस्था की प्रतिभूतियाँ बड़ी सरलता से बिक जाती थी, परन्तु युद्धोपरान्त काल में विचित्र राजनैतिक वातावरण के कारण सरकार व उद्योगपतियों में जनता का विश्वास नहीं रहा। सारे देश में निराशावाद एवं अनिश्चिन्ता का वातावरण छाया हुआ था। देश की राजनैतिक दशा अगस्त सन् १९४६ के कलकत्ते के उपद्रवों के कारण बहुत खराब हो गई थी। कलकत्ते के उपद्रव के बाद पंजाब में भयङ्क शुरु हो गये। ये भयङ्क समाप्त भी न हुए थे कि काश्मीर युद्ध व हैदराबाद काण्ड प्रारम्भ हो गये। इस बिगड़ती हुई राजनैतिक दशा के कारण देश का व्यापार व औद्योगिक उत्पादन कुप्रभावित हुआ। जान-माल की असुरक्षा के कारण उद्योगपतियों का भी विश्वास जाता रहा। समस्त व्यापारिक क्षेत्रों में निराशावाद छा गया। यातायात की कठिनाईयों, औद्योगिक प्रशान्ति व आर्थिक

नीति की अनिश्चितता ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। ऐसी अनिश्चित वातावरण व मुद्रा प्रसार की दशाओं के कारण निर्मातागण भावी उत्पादन का उचित अनुमान नहीं लगा सके। ऐसे ही वातावरण में सन् १९४६ में भारत में स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार (Interim Government) बनी और शासन की बागडोर भारत को सौंप दी गई। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से भी औद्योगिक उत्पादन को कोई प्रेरणा नहीं मिली। हमारे जिन नेताओं को शासन का कार्य भार सौंपा गया, उनके असमन्वित व 'बना अधिक सोचे-विचारे दिये हुए भाषणों ने भी अनिश्चितता के वातावरण को प्रज्वलित किया। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, लार्जो को सीमित करना, आदि विषयों पर दिए हुए भाषणों ने हमारे उद्योग पतिया के मस्तिष्क में अनिश्चितता का वातावरण ला दिया तथा उन्हें हतोत्साहित किया। इनका भी राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Discuss carefully the effects of the Second World War on Indian Industries
- 2 Despite great progress in the diversity, number and paidup capital of Joint Stock Companies in India during the World War II, there have been some adverse effects on the industrial economy due to certain forces active in this period " Comment and point out those forces and the adverse effects
- 3 Discuss the development of Indian Industries during the Post-War Crisis period 1945-47

देश के विभाजन का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव

(Effects of Partition on Indian Industries)

प्रारम्भिक—

१५ अगस्त सन् १९४७ को हमारा देश स्वतन्त्र हो गया। इस तिथि की अर्द्ध रात्रि को सारे देश में खुशियाँ मनाई जान लगी। परन्तु प्रातःकाल होते ही हमारे अर्थ-शास्त्रियों ने यह चेतावनी दी कि राजनीतिक दृष्टि से देश भले ही स्वतन्त्र हो गया हो, परन्तु आर्थिक दृष्टि से हम और भी परतन्त्र हो गए हैं। १५ अगस्त सन् १९४७ को ही हमारी भारत 'माँ' के दो खण्ड कर दिये गये एवं अविभाजित भारत के दाये-बायें अंगों से एक नया देश बना दिया गया। भारत के वे अंग जो नव निर्मित देश पाकिस्तान में सम्मिलित किये गये, विदेशी कहलाये जाने लगे। दूसरे शब्दों में, राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिये हमको आर्थिक परतन्त्रता मोल लेनी पड़ी। निम्नलिखित विवरण से देश के अनाधिक विभाजन का औद्योगिक अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव का आभास मिलता है—

विभाजन के परिणाम

(१) औद्योगिक क्रियाओं का वितरण—विभाजन के परिणाम-स्वरूप भारत की अविभाजित भारत का ७७% भाग, कुल जन-संख्या का ८२% भाग, समस्त औद्योगिक संस्थाओं का ६१% भाग एवं कुल श्रमिकों की संख्या का ६३% भाग मिला। अप्रतिष्ठित तालिका से हमको उन बड़े-बड़े उद्योगों का ज्ञान होता है, जो केवल भारत में ही रहे—

भारत व पाकिस्तान के बीच बड़ी औद्योगिक संस्थाओं के वितरण का प्रतिशत

विवरण	औद्योगिक संस्थाएँ		श्रमिकों की संख्या	
	भारत %	पाकिस्तान %	भारत %	पाकिस्तान %
कुल उद्योग	६१	६	६३	७
सूती वस्त्र	६८	२	६८	२
जूट मिल	१००	—	१००	—
इजीनियरिंग	८५	१५	८८	१२
लोह एवं इस्पात	१००	—	१००	—
पाककर के कारखाने	६३	७	६६	४
रासायनिक	६३	७	६५	५
दियासलाई	६७	३	६३	७
कागज की मिलें	१००	—	१००	—
सीमेन्ट	६०	१०	६२	८
काँच	६८	२	६८	२
खाल व चमड़ा	६७	३	६५	५

पाकिस्तान में ऐसा कोई भी उद्योग नहीं था, जिसमें १ लाख से अधिक व्यक्ति लगे हुए हों, जबकि भारत में निम्न ६ उद्योग इस श्रेणी में आते हैं—(१) कपास की कटाई व बुनाई-उद्योग, (२) जूट-उद्योग, (३) सामान्य इंजीनियरिंग-उद्योग, (४) रेल्वे वर्कशॉप, (५) आइर्नेस पेंकट्रीज तथा (६) कॉटन जिनिंग-उद्योग। पाकिस्तान में ऐसे उद्योगों की संख्या २३ थी, जिनमें ५०० से कम श्रमजीवी कार्य करते हों, भारत में ऐसे उद्योगों की संख्या केवल ४ थी। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि भारत के कुल उद्योगों में से आठे उद्योगों में १०,००० से अधिक श्रमिक कार्य करते थे, जबकि पाकिस्तान के कुल उद्योगों में से आठे उद्योग ऐसे थे जिनमें १,००० से कम श्रमिक कार्य करते थे। उपर्युक्त विवरण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

(घ) पाकिस्तान ने भारत की अपेक्षा बहुत कम लोगों को उद्योग-धन्यों में रोजगार प्रदान किया।

(घ) भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में उद्योगों का घनत्व बहुत ही कम था।

(ग) पाकिस्तान में एक भी बड़ा उद्योग (Major Industry) नहीं था और जो चार छ्छ उद्योग थे भी उनका आकार भारतीय विभाग उद्योगों की तुलना में बहुत कम था।

(२) खनिज संपदा का वितरण—खनिज संपदा की दृष्टि से भारतवर्ष धनी रहा एवं पाकिस्तान को काफी क्षति उठानी पड़ी क्योंकि लगभग सभी खनिज संपत्ति के भण्डार भारत में ही रहे। उदाहरण के लिये कोयला, अभ्रक, मंगनीज, कच्चा लोहा आदि सभी महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भारत की ही हिस्से में आये। हा निम्न खनिज पदार्थों के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये जिनमें तेल के कुछ भाग सिंध की घाटी व पूर्वी बंगाल में साल्ट रज में नमक व जिप्सम पश्चिमी पंजाब, सिंध व बिलोचिस्तान में कोयला बिलोचिस्तान में ग्रेनाइट व गंधक चित्तल में घटिया किस्म की एंटीमनी साल्ट रज में चूने का पत्थर आदि। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अविभाजित भारत की खनिज संपदा का केवल ३ प्रतिशत भाग पाकिस्तान को गया। जिप्सम के भण्डार व चट्टानी नमक (जिनका प्रयोग भारी रासायनिक उद्योगों में किया जाता है) के क्षेत्रों के चले जाने से भारत को अवश्य थोड़ी सी हानि हुई।

खनिज संपदा के अभाव से पाकिस्तान के औद्योगीकरण को बड़ा आघात पहुँचा। जहाँ तक जल विद्युत संपदा का सम्बन्ध है इस दृष्टि से भी भारत ही धनी रहा। पाकिस्तान की उनके नदीया यद्यपि उनी के क्षेत्र में बह कर समुद्र में जा मिली हैं परन्तु उनका जल काश्मीर, पूर्वी पंजाब व प्रानाम के पवनाय क्षेत्रों से हुआ है जो कि भारत में है। इस कारण पाकिस्तान में कुछ प्रतिनिधित्व का बानावरण पदा हो गया। ऐसा न हो कि भारत उसका नदीया के जल को उद्योग क्षेत्र में ही रोक दे। विभाजन के पूर्व पाकिस्तान के क्षेत्र में युक्त जोगे इनगर शक्ति ग्रुप से बिजली प्राप्त करते थे जो कि अब पूर्वी पंजाब (भारत) में है। भारत में लूट के कारण अब जोगे इनगर शक्ति ग्रुह का सम्बन्ध पाकिस्तान से विच्छेद कर दिया गया है अतः पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) का औद्योगिक जीवन बड़ा कुप्रभावित हुआ।

(३) कृषि पदार्थों का वितरण—भारतवर्ष के विभाजन से हमारे दो प्रमुख उद्योग—जूट तथा सूती वस्त्र मिल उद्योग—को कच्चे माल की पूर्ति की दृष्टि से बड़ी हानि उठानी पड़ी। अविभाजित भारत की जूट के उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त था परन्तु बदवारे के उपरांत पटसन की उपज का ८१/६ भाग पाकिस्तान को चला गया, यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में जो पटसन, जपत्र, रोज, ६ अरब, की दृष्टि से वह उच्चकोटि की है अतः हमारी मित्रों को अच्छे किस्म की पटसन से हाथ धोना पड़ा। नीचे दी हुई तालिका विभाजन के परणामा पर प्रकाश डालती है—

अविभाजित भारत में, कुल क्षेत्रफल, जन-संख्या व प्रमुख
औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत व पाकिस्तान
का प्रतिशत भाग

विवरण	भारत	पाकिस्तान
क्षेत्रफल	७७	२३
जन संख्या—		
कुल	८२	१८
नगरी	८६	११
ग्रामीण	८१	१६
भूमि (Land Utilization)—		
वस्त्राच्छादित क्षेत्र	६४	०६
बुझा हुआ कुल क्षेत्र (area sown)	८४	१६
कुल सिंचित प्रदेश	६६	३१
उत्पादन (कृषि)—		
प्रमुख खाद्य पदार्थ	७५	२५
गन्ना	८४	१६
प्रमुख तिलहन	५५	४५
कपास	६०	४०
पटसन	१६	८१
उत्पादन (बागान)—		
चाय	८५	१५
कॉफी	१००	—
तम्बाकू	७८	२२
उत्पादन (खनिज)	६७	०३

अविभाजित भारत में, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र केवल ३—४ मिलियन बेल्स (Million bales) पटसन का उपयोग करता था, जबकि शेष भारत में ६ मिलियन गाँठों का उपयोग था। अपनी बड़ी हुई आवश्यकताओं को सन्तुष्टि के लिए ही भारत को 'अधिक पटसन उगाओ आन्दोलन' प्रारम्भ करना पड़ा। इसी प्रकार, विभाजन के पूर्व, हमारी थ्रेड कोटि की कपास सम्बन्धी आवश्यकता सिन्ध व पश्चिमी

पाकिस्तान के राज्यों द्वारा पूरी होती थी, परन्तु देश के अनधिक बँटवारे ने कपास के क्षेत्र में भी अभाव की स्थिति पैदा कर दी। विभाजन के पूर्व हमारे देश में कुल ३६४ सूती वस्त्र मिलें थी। बँटवार के बाद भारत व पाकिस्तान के हिस्से में क्रमशः ३८० व १४ मिल पड़ीं। इस प्रकार यद्यपि पाकिस्तान के हिस्से में केवल १४ मिलें या अविभाजित भारत की १% मिलें ही पड़ीं परन्तु कपास की उपज का ४०% भाग उसी को मिला। यही कारण कि अपनी वस्त्र मित्रा की कपास सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय केन्द्रीय कपास समिति को अधिक कपास पैदा करने के लिए चार प्रयत्न करने पड़े। हमारे देश में केवल औद्योगिक कच्चे माल की ही कमी नहीं पड़ गई वरन् खाद्य पदार्थों का भी घोर अभाव था। अतः 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' की अधिष्ठित या कपास उगाओ' आन्दोलन से प्रतिस्पर्धा होने लगी और इस संघर्ष का हमारी अर्थ व्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा।

(४) व्यापारों की क्षति—पाकिस्तान के निर्माण से हमारे अनेक औद्योगिक पदार्थों का एक निश्चित बाजार हाथ में जाता रहा। बँटवारे के पूर्व वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्रों में सूती वस्त्रों, काँच का सामान अल्पभूमिनिष्ठ सेरेमिक्स, वनस्पति तेल की खपत होती थी, परन्तु पाकिस्तान के बन जाने से इन वस्तुओं की माँग बहुत कम हो गई। पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा अन्य देशों से इन वस्तुओं का आयात शुरू कर दिया। अतएव हमको अपना माल बेचने के लिए नई-नई मण्डियों की तलाश करनी पड़ी।

(५) कुशल कारीगरों का चला जाना—पाकिस्तान के बनने से अविभाजित भारत के ऐसे अनेक मुसलमान जोकि दस्तकारों के कामों में दक्ष थे तथा कढ़ाई-बुनाई उद्योग, ऊनी उद्योग, काच उद्योग आदि में लगे हुए थे नव निर्मित देश—पाकिस्तान को चले गए। फलतः हमारे देश में इन कुशल कारीगरों का अभाव हो गया। इसके विपरीत पाकिस्तान में इन्जीनियरों व तकनिक विशेषज्ञों की कमी हो गई, क्योंकि इन्जीनियरिंग संस्थाय अधिवासन भारत में ही रही।

(६) प्रबन्ध सम्बन्धी कला व साहस—जहाँ तक प्रबन्ध सम्बन्धी कला व साहस (Managerial and Entrepreneurial skills) का सम्बन्ध है, भारत को लाभ ही रहा। सभी गृहस्थ उद्योगों के प्रबन्धक, जो पाकिस्तान में थे भारत में चले आए और यहाँ के सागरण थमिक् व कुशल कारीगर पाकिस्तान चले गए। परिणामतः हमारे देश में प्रबन्ध सम्बन्धी कला व साहस का बाहुल्य था जबकि पाकिस्तान में श्रम का। प्रबन्धकों के बाहुल्य से देश (भारत) के औद्योगीकरण को बड़ा बढ़ावा मिला। पाकिस्तान में प्रबन्धना व साहसिता की कमी के कारण सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा एवं उद्योग के क्षेत्र में राजकीय उपक्रम (State enterprise) के विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र पैदा हो गया। हमारे देश में राजकीय उपक्रम के साथ-साथ, निजी उपक्रम भी तज़ा के साथ बढ़ा।

(७) औद्योगिक स्थानीयकरण पर प्रभाव—हमारा औद्योगिक स्थानीयकरण भी विभाजन के प्रभाव से अक्षुण्ण नहीं रहा। विभाजन के परिणामस्वरूप देश के वे क्षेत्र, जोकि भारत व पाकिस्तान की सीमा के निकट थे, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अपना महत्त्व खो बैठे। राजनैतिक कारणों से उनकी स्थिति खतरनाक व जोखिमपूर्ण (risky) हो गई। इस दृष्टि से कलकत्ता की स्थिति बड़ी खराब हो गई। विवश होकर भारत सरकार को औद्योगिक स्थानीयकरण के कलेवर में परिवर्तन करना पड़ा। देश के आन्तरिक भागों में उद्योगों को विवेन्द्रित व आकर्षित करने के लिए यातायात, सन्देशवाहन, कर, वित्त आदि की सुविधायें देनी पड़ी।

(८) पूँजी के आयात में बाधा—देश के विभाजन से सब जगह अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया। भारत की अर्थ-व्यवस्था में विदेशियों को विश्वास नहीं रहा, अतः पूँजी का विनियोग करने में उन्हें बड़ा सकोच होने लगा। इससे देश के औद्योगिकीकरण को गहरा आघात पहुँचा।

(९) यातायात सम्बन्धी असुविधायें—देश के दुखद विभाजन से यातायात पर भी कुप्रभाव पड़ा। विभाजन के पहले कुल भारत में ४१,००० मील लम्बी रेल लाइनें थी, परन्तु विभाजन से पाकिस्तान को केवल ७,००० मील या १७% रेल लाइनें ही मिली। रेल विभाग में लगे हुए कर्मचारियों के आवागमन से भी बड़ी असुविधा हुई। पाकिस्तान से जो कर्मचारी आए, उनमें अधिकतर बलकं, टिकट-चैकर, गार्ड आदि ही थे, परन्तु भारत से पाकिस्तान जाने वा मुसलमानों में अधिकतर ड्राइवर, फायरमैन, लुहार व वर्कशॉप टेक्नीशियन थे। परिणामतः हमारे देश में कुशल कर्मचारियों की कमी होगई, जबकि पाकिस्तान में सामान्य कर्मचारियों का आधिक्य हो गया। रेलवे-यातायात के असंगठन के कारण कोयला उद्योग भी कुप्रभावित हुआ। यद्यपि देश में कोयले की कमी नहीं थी, परन्तु खानों से कारखानों तक कोयला लाने की बड़ी कठिन समस्या थी। खानों के निकट कोयले का ढेर लगने लगा, इसके विपरीत कारखानों में कोयले की कमी के कारण पूर्ण गति से कार्य न हो सका। इससे उत्पादन में कमी आ गई तथा मुद्रा स्फीति (Inflation) की दशाओं को और भी बढ़ावा मिला। बंगाल व पंजाब के पूर्वी व पश्चिमी प्रदेशों में रेल-यातायात बिल्कुल रुक गया। परिणामतः कच्चे माल (जैसे पटसन व कपास) के आयात में बड़ी असुविधा पैदा हो गई।

(१०) भारतीय बन्दरगाहों पर अत्यधिक भार—भारतवर्ष के विभाजन के परिणामस्वरूप कराँची व चिटगाँव के बन्दरगाह विदेशी हो गए। बँटवारे व पूर्व जम्मू व काश्मीर, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि ११ समस्त वैदेशिक व्यापार कराँची के बन्दरगाह के द्वारा ही होता था, परन्तु जबसे कराँची पाकिस्तान में चला गया, उक्त सभी राज्यों के व्यापार का भार बम्बई पर आ पड़ा। इस अत्यधिक भार को कम करने के उद्देश्य से ही भारत सरकार को विवश होकर नए-नए बन्दरगाहों का निर्माण व विकास करना पड़ा। उदाहरण के लिए, कच्छ की खाड़ी पर स्थित काँडला

का बन्दरगाह इसी हेतु विकसित किया गया। काठला को 'भारत का कराँची' इसी कारण कहते हैं, क्योंकि अविभाजित भारत में जो स्थान कराँची को प्राप्त था, आज वही स्थान भारत में काठला को प्राप्त है। भारत सरकार को इस बन्दरगाह के विकास में लगभग ४० करोड़ रु० व्यय करने पड़े। इसी प्रकार पूर्वी भारत में चिटगाँव के चले जाने से कलकत्ता पर भार बहुत बढ़ गया। कलकत्ता-चिटगाँव, जो कि १५ अगस्त सन् १९४७ की अदरान्त के पूर्व एक-दूसरे के पूरक व सहायक थे, इस विधि से प्रतिस्पर्धी बन गए। आसाम का समस्त वैदेशिक व्यापार, जो कि पहिले चिटगाँव के द्वारा होता था, बँटवाने के बाद कलकत्ते की ओर आ गया। भारत सरकार को आसाम व कलकत्ते के बीच सीधी रेल लाइन डालनी पड़ी। इसमें सचमुच बहुत अधिक व्यय हुआ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश के दुखद विभाजन से दोनों ही खण्डों—भारत व पाकिस्तान—को हानि उठानी पड़ी व अनेक आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वास्तविकता तो यह है कि प्राकृतिक दृष्टि से दोनों ही नव-निर्मित देश एक हैं। जलानदियों से ये एक-दूसरे के पूरक व सहयोगी रहे हैं। यही कारण है कि इनके खण्डन से आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं। अपने-अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए हमें सुरक्षा व्यय बढ़ाना पड़ा है। यह अतिरिक्त व्यय यदि जन उपयोगी कार्यों में व्यय होना तो, दोनों ही खण्ड अधिक समृद्धशाली हो सकते थे। अब आवश्यकता एक ऐसे मनोवैज्ञानिक बचाव की है जिससे कि पारस्परिक घृणा ईर्ष्या, भय व अपरिचितता के बदले उठ जाएँ एवं दोनों ही राष्ट्र प्रेम, सहयोग व पारस्परिक विद्वास के साथ रहे।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss carefully the effects of partition on the economy of India and Pakistan. Discuss the effects of partition on (1) the industrial activity, (2) distribution of mineral resources and (3) distribution of agricultural resources of India and Pakistan.
2. "Nature has made both India and Pakistan complementary in the economic field. The Partition of the country has disturbed the economy of both." Comment.

स्व. न्त्रता के पश्चात् भारतीय उद्योगों की प्रगति

(Development of Indian Industries Since Independence)

प्रारम्भिक—

द्वितीय महायुद्ध ने भारतीय उद्योगों को अपनी पूर्ण क्षमता से काम करने तथा अपने समस्त साधनों के प्रयोग करने का अवसर दिया था, जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, परन्तु सन् १९४५ के बाद देश में अनेक राजनैतिक उलट-फेर हुए तथा सरकार की कद-नीति मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए ऐसी रही कि जिसका उद्योगों की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरे, युद्ध-युग में मशीनरी का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण वह जीर्णोद्धार हो गई थी। फलतः उत्पादन व्यय अधिक हो रहा था। इन विविध परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप औद्योगिक उत्पादन गिरने लगा। ऐसे ही वातावरण में सन् १९४६ में भारत में स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार बनी और शासन की बागडोर भारतीयों को सौंप दी गई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति—

कुछ समय पश्चात् लार्ड माउण्टबेटन के प्रयत्न-स्वरूप भारत को अगभग स्वतन्त्रता मिली, जिसने आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में नई-नई समस्याएँ खड़ी कर दी। अनाज की बहुत कमी बढ़ गई और वस्त्र तथा फूट-उद्योग में कच्चे माल की कठिनाई उपस्थित हो गई। शरणार्थियों के आने-जाने से औद्योगिक यातायात में भी अड़चनें आईं, किन्तु हमारी जनप्रिय सरकार ने बड़े धैर्य से उनका सामना किया। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा औद्योगिक नीति में सुधार करने के लिए दिसम्बर सन् १९४७ में उद्योग परिषद् का आयोजन किया, जिसकी सिफारिशों पर उद्योगों को निम्न सुविधाएँ प्रदान की गईं—

उद्योग परिषद्, १९४७ की सिफारिशें—

(१) तीन वर्ष से कम आयु वाले कारखानों को उनकी पूँजी पर ६% तक लाभार्ह आय-कर से मुक्त कर दिया जाय;

(२) नई इमारत, यन्त्र, औजार आदि पर तथा तीन पालियों में काम करने वाले कारखानों को तत्कालीन दर से दुगुने ह्रास का भत्ता मिलेगा,

(३) यन्त्र सामग्री तथा अन्य आवश्यक पूँजीगत माल पर आयात-कर कम कर दिए गए।

इन सुविधाओं के परिणाम-स्वरूप औद्योगिक उत्पादन सन् १९४८ में युद्ध-पूर्व औद्योगिक उत्पादन स्तर से १५% अधिक हो गया। यही सन् १९४७ में युद्ध पूर्व उत्पादन स्तर से ५% कम था।

सन् १९४८ की औद्योगिक नीति—

६ अप्रैल सन् १९४८ को भारत सरकार ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसके अनुसार हमने व्यक्तिगत क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में, उद्योगों के विकास पर बल दिया। इस नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कुछ आधारभूत उद्योग अपने अन्तर्गत रखे, जैसे शस्त्र एवं बालूद का निर्माण, एटम शक्ति का निर्माण एवं रेलों का स्वामित्व व प्रबन्ध। कुछ अन्य उद्योग, जैसे कोयला, लोहा व स्पात, जलयान तथा वायुयान निर्माण, टेलीफोन व टेलीग्राफ तथा वायरलेस सम्बन्धी यन्त्र और इन्जिन, तेल आदि के विकास के काम भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं स्थानीय बाडों के उत्तरदायित्व में रहे। आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत प्रबन्ध से भी इनमें सहायता ली जा सकती थी। शेष उद्योग व्यक्तिगत प्रबन्ध के लिए छोड़ दिये गये। किन्तु उन पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से सरकार ने उद्योग (विकास तथा नियन्त्रण) अधिनियम, १९५१ (Industrial Development and Regulation Act, 1951) बनाया। इसके अन्तर्गत भारत सरकार ने देश में औद्योगिक विकास के लिए और भी तीव्रता से प्रयत्न करने आरम्भ कर दिए।

स्वतन्त्रता युग में औद्योगिक प्रगति

स्वतन्त्रता-युग में हुई औद्योगिक प्रगति का अनुमान निम्नलिखित विवरण से लगाया जा सकता है—

(I) औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति—

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में उपयुक्त औद्योगिक ऋतावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक औद्योगिक शिक्षालय खोले तथा निम्नलिखित औद्योगिक अनुसंधानशालाओं की स्थापना की—

(१) राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधानशाला, नई दिल्ली—यहाँ भौतिकशास्त्र (fundamental) और applied दोनों ही) से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान किये जाते हैं। टेस्ट करने की सुविधाएँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। यह संस्था २१ जनवरी सन् १९५० को खोली गई थी।

(२) राष्ट्रीय रासायनिक अनुसंधानशाला, पूना—यह ३ जनवरी सन् १९५० को खोली गई थी। इसका कार्य रासायनशास्त्र के सम्पूर्ण क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान करना है।

(३) राष्ट्रीय धात्विक अनुसंधानशाला, जमशेदपुर—यह २६ नवम्बर सन् १९५० को स्थापित की गई थी और इसका कार्य धात्विक अनुसंधान करना है।

(४) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधानशाला, जीलघोरा (बिहार)—यह भी २५ अगस्त

सन् १९५० को स्थापित हुई थी। यह संस्था ईंधनो पर—ठोस, द्रव और गैस—अनुसंधान करती है। इसने अपने आधीन ६ कोयला सर्वे रेटेशनो द्वारा भारतीय कोयले का भौतिक एवं रासायनिक सर्वे कराया है।

(५) केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलॉजिकल अनुसंधानशाला, भुवनेश्वर—इसकी स्थापना २१ अक्टूबर सन् १९५० को हुई थी। इसके निम्न कार्य हैं—खाद्य वस्तुओं का प्रोसेसिंग व कन्जर्वेशन तथा फलों से सम्बन्धित टेक्नोलॉजी के सभी पहलुओं पर अनुसंधान।

(६) केन्द्रीय ड्रग अनुसंधानशाला, लखनऊ—यह संस्था १ फरवरी सन् १९५१ को प्रारम्भ की गई थी। इसका कार्य दवाइयों पर सभी प्रकार के अनुसंधान करना है।

(७) केन्द्रीय ग्लास तथा सीरेमिकल अनुसंधानशाला, कटक—यह संस्था २५ अगस्त सन् १९५० को स्थापित हुई। यह ग्लास, सीरेमिकल, पॉटरी, पोरसीलेन, रिफ़्लेक्टर्स व इनेमिल सभी पहलुओं पर अनुसंधान करती है, जैसे—ग्लास व सीरेमिकल के लिये प्रोसेसिंग का विकास, सीरेमिकल उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों का प्रमापीकरण आदि।

(८) केन्द्रीय सड़क अनुसंधानशाला, दिल्ली—इसकी स्थापना १६ जुलाई सन् १९५२ को हुई थी। यह सड़क निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों तथा सड़क की सतहों (road surfaces) पर अनुसंधान करता है।

(९) केन्द्रीय भवन अनुसंधानशाला, रङ्गूनी—यह १३ अप्रैल सन् १९५३ को स्थापित की गई थी। इसका कार्य भवनों की संरचना से सम्बन्धित पहलुओं पर तथा भवनों को मानव-निवास के लिये अधिक से अधिक आरामदेह बनाने के उपायों पर अनुसंधान करना है।

(१०) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधानशाला, मद्रास—यह सन् १९५३ में स्थापित हुई थी। इसका कार्य चमड़े से सम्बन्धित (fundamental एवं applied) टेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करना है।

(११) केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधानशाला, काराईकुडुड़ी—यह जनवरी १५ सन् १९५३ को स्थापित हुई थी और इसका कार्य इलेक्ट्रो रसायन (इलेक्ट्रो मेटलर्जी, इलेक्ट्रो डिपोजीशन व सम्बन्धित समस्याओं को सम्मिलित करते हुये) की सभी समस्याओं पर अनुसंधान करना है।

(१२) केन्द्रीय नमक अनुसंधानशाला, भावनगर—यह १० अप्रैल सन् १९५४ को स्थापित हुई थी। इसका कार्य विशुद्ध नमक का उत्पादन करने के ढंगों का परीक्षण करना है। उत्पादन लागत में कमी करने तथा नमक निर्माण से बचे हुये अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने के उपायों पर अनुसंधान करना भी इस संस्था की जिम्मेदारी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न अनुसंधानशालायें भी कार्यशील हैं—

(१) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, पिलानी।

- (11) नेशनल बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ ।
- (111) सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, धनबाद ।
- (1४) रोजनल रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद ।
- (१) इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ वायोमिस्ट्री एन्ड प्लेन्सपरीमेण्टल मैडीसिन, बलकत्ता ।
- (vi) बिरला इंडस्ट्रियल एन्ड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, बलकत्ता ।
- (vii) रोजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जम्मू काश्मीर ।
- (vi11) सेंट्रल मिनेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दुर्गापुर ।
- (ix) सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर ।
- (८) नेशनल एगोनॉटिक लेबोरेटरी, बंगलौर ।
- (x1) रोजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जोरहट ।
- (x11) सेंट्रल नाइट्रिफिक इन्स्ट्रुमेण्ट्स प्रार्गनाइजेशन, नई दिल्ली ।
- (x111) सेंट्रल इन्डियन मरीमनल प्लान्ट प्रार्गनाइजेशन, नई दिल्ली ।

पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसन्धानशालाओं की प्रगति—

विभिन्न अनुसन्धानशालाओं ने तृतीय पंच-वर्षीय योजनावधि के लिये अपने-अपने कार्यक्रम निश्चित कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ उल्लेखनीय विशेषण निम्नलिखित हैं— राष्ट्रीय भौतिक अनुसन्धानशाला एक पाइलट प्लान्ट स्केल पर रेडियो के भागों का विकास काय करेगी। राष्ट्रीय रासायनिक अनुसन्धानशाला डाइज और इन-ऑर्गेनिक इन्टरमीडियेट्स तथा आवश्यक तेलों के लिये नया डिवाइजन स्थापित करेगी तथा कई नवीन पाइलट प्लान्ट प्रोजेक्ट चलायेगी। राष्ट्रीय धात्विक अनुसन्धानशाला अलॉय स्टील्स के लिये एक नवीन डिवाइजन स्थापित करेगी तथा कुरोजन (CORROSION) सम्बन्धी समस्याओं का विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत अध्ययन करेगी। केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धानशाला भी निम्न श्रेणी के कोयले के प्रयोग सम्बन्धी कार्य का विस्तार करेगी तथा बड़ पमाने पर पाइलट प्लान्ट ट्रायल्स प्रारम्भ करेगी। ग्लास एवं सीरेमिक्स इन्स्टीट्यूट ने आर्टिफिशियल ग्लास के उत्पादन के लिये एक पाइलट प्लान्ट स्थापित करना तय किया है। वह माइक्रा उत्पादन से सम्बन्धित अनुसन्धान के लिये एक पृथक शाखा भी रखेगी। केन्द्रीय ड्रग अनुसन्धानशाला एन्टीबायोटिक्स और फाइन केमिकल्स के लिये एक डिवाइजन प्रारम्भ करेगी। केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलॉजिकल अनुसन्धानशाला फल एवं साग-सब्जी के सुरक्षित सग्रह के लिये क्षैत्रिक स्टेशनों की स्थापना करेगी। केन्द्रीय सड़क अनुसन्धानशाला भी पुलों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक नया डिवाइजन स्थापित करेगी। केन्द्रीय भवन अनुसन्धानशाला न भी पांच क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है। प्रादेशिक विस्तार केन्द्रों के खोलने की एक योजना केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धानशाला द्वारा बनाई गई है। केन्द्रीय इलेक्ट्रो-केमिकल अनुसन्धानशाला भी कुरोजन से सम्बन्धित समस्याओं

पर अनुसन्धान करने के लिये नये डिब्बीजन खोलेगी। केन्द्रीय नमक अनुसन्धानशाला ने एलगोलॉजी पर कार्य प्रारम्भ करना तय किया है। वह नमक (Salt bitterns) में अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग पर भी अनुसन्धान कार्य को अधिक विस्तृत करेगा।

द्वितीय योजना में आरम्भ की गई कुछ अनुसन्धान संस्थाओं को तृतीय योजना-वधि में पूर्ण सुसज्जित किया जायेगा। कई नई संस्थायें भी खोली जायेंगी, जैसे—इन्स्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, नेशनल बायोलॉजिकल रेबोरेटरी एवं एक रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी।

(II) प्रमापीकरण के क्षेत्र में प्रगति—

भारतीय उद्योग-पतियों ने सर्व प्रथम सन् १९४० के १२वें उद्योग सम्मेलन में भारतीय प्रमाप निश्चित करने के लिए भारतीय प्रमाप संस्था खोलने का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा था। परन्तु युद्ध-कालीन परिस्थितियों के कारण उस समय भारत सरकार ने प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। सन् १९४६ में, औद्योगिक योजना के अन्तर्गत प्रमापीकरण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए, भारत सरकार ने प्रमाप संस्था खोलने का निश्चय किया और दिल्ली में इसके केन्द्रीय कार्यालय की स्थापना की गई। इस संस्था का प्रबन्ध एक साधारण परिषद् (General Council) द्वारा होता है। इसके सभापति उद्योग सचिव हैं। प्रमाप संस्था की ४२० समितियाँ हैं। इनका संचालन (अ) इंजीनियरिंग विभाग परिषद्, (ब) निर्माण विभाग परिषद्, (स) वस्त्र विभाग परिषद्, (द) रासायनिक विभाग परिषद् व (य) खाद्य और कृषि उत्पादन विभाग परिषद् द्वारा होता है। प्रत्येक विभाग का नियन्त्रण विभागीय परिषद् (Divisional Council) द्वारा किया जाता है।

भारतीय प्रमाप संस्था का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर विभिन्न वस्तुओं एवं क्रियाओं के प्रमाप निर्धारित करना तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करना, औद्योगिक आँकड़े एवं सूचनाएँ एकत्रित व प्रकाशित करना तथा प्रमापीकरण की उन्नति के लिए पुस्तकालय, म्यूजियम तथा प्रयोगशालायें स्थापित करना और विभिन्न वस्तुओं के प्रमापीकृत चिन्हों का रजिस्ट्रेशन करना। भारतीय प्रमाप संस्था अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापीकरण संगठन की सदस्य है। इस बात से ही इसकी यशस्विता का परिचय मिलता है।

भारतीय प्रमाप संस्था का कार्य अब राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त कर चुका है। संस्था ११ साल पहले सरकार और जनता के समर्थन से आरम्भ की गई थी और यह भारत में खपने और बनने वाली चीजों के नाप, किस्म और काम के प्रमाप निर्धारित करती है। संस्था को केन्द्रीय सरकार सहायता देती है। इसके अलावा राज्य सरकारें, औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाएँ, कारखाने, औद्योगिक शालाएँ, नगरपालिकाएँ और निगम आदि भी संस्था के सदस्य हैं और इसके लिए चन्दा देते हैं। इसके काम की

लोकप्रियता और महत्त्व इसी बात से प्रगट होता है कि अब कारखानों के मालिक अपनी चीजों के प्रमाण निर्धारित करने की मांग स्वयं करने लगे हैं।

भारतीय प्रमाण सन्ध्या के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कदम सन् १९५२ का भारतीय प्रमाण अधिनियम है। इस अधिनियम के बन जाने से प्रमाण सन्ध्या के अधिकार बढ़ गये हैं। सन्ध्या को प्रमाणीकरण चिन्ह देने और कम्पनियों को भारतीय प्रमाणों के अनुसार मास तैयार करने के लाइसेंस देने का अधिकार मिल गया है। इससे उचित किस्म के माल को प्रोत्साहन मिलेगा तथा सस्ते और धनिया माल से प्रतिस्पर्धा का डर कम हो जायगा। केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि जहाँ तक हो, नियत प्रमाण की वस्तुएँ ही खरीदी जायें। ज्यों ज्यों उपभोक्ता प्रमाण वाली वस्तुओं पर विश्वास करके त्यो-त्यो औद्योगिक विकास की गति तीव्र होती जायगी। भारतवर्ष जैसे अविक्तित देश में तो कच्चे माल की बचत का महत्त्व युद्ध और शान्तिकाल दोनों में एक सा है।

(III) औद्योगिक नियमन एवं नियन्त्रण के क्षेत्र में प्रगति—

स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, १९४८ को ध्यान में रखते हुये सविधान म संशोधन किया गया और उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, १९५१ बनाया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी नई एवं विद्यमान संस्थाओं के लिये तथा विद्यमान संस्थाओं के भावी विस्तार के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया। सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी औद्योगिक संस्था के कार्यवाहन की जांच पड़ताल करे और ऐसे निर्देश दे जो कि वह आवश्यक समझे। यदि किसी संस्था का प्रबन्ध जारी रहे, तो सरकार उसके प्रबन्ध या नियन्त्रण को अपन हाथ में ले सकती है। एवं केन्द्रीय परामर्शदाता समिति की स्थापना भी की जानी थी, जिसमें उद्योग, श्रम, उपभोक्ताओं व प्रारम्भिक उत्पादकों के प्रतिनिधि रखे जायेंगे। यह सरकार को उद्योगों के विकास एवं नियन्त्रण में सम्बन्धित सभी मामलों पर परामर्श देगी। पृथक् पृथक् उद्योगों के लिये भी परामर्शदाता परिषदों की स्थापना की जानी थी।

इत अधिकारों के प्रयोग द्वारा सरकार देश के प्रसाधनों का समुचित प्रयोग बड़े व छोटे उद्योगों का अनुलिप्त विकास और विभिन्न उद्योगों का प्रादेशिक वितरण करने का उद्देश्य रखती है। इस समय उक्त अधिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग सम्मिलित हैं। केन्द्रीय परामर्शदाता समिति के अतिरिक्त निम्न उद्योगों के लिये विकास परिषदें भी स्थापित कर दी गई हैं—(I) इन्टरनल कमर्शचन इजित एवं पावर ट्रांसमिशन पम्पस्, (II) हैवी केमीकल्स, (III) बाइसिकल, सीने पिरोने की मशीनें व मोटार, (IV) चीनी, (V) हल्के बिजली का सामान, (VI) भारी बिजली का सामान, (VII) दवाइयाँ, (VIII) अलकली एवं सम्बन्धित उद्योग, (IX) उनी वस्त्र (X) कृत्रिम रेवामी वस्त्र, (XI) मशीन-टूल्स (XII) नॉनफैरस मेटल एवं अलाय, (XIII)

तेल, साबुन एवं रंग, (XIV) साबुन प्रोसेसिंग, (XV) आर्गेनिक केमिकल्स, (XVI) ओटोमोबाइल्स, (XVII) कागज एवं (XVIII) चमड़ा, चमड़े का सामान, पिकर्स ।

कई पेटल एवं विशेषज्ञ समितियाँ भी समय-समय पर विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई है । अक्टूबर सन् १९५६ और सितम्बर सन् १९६० के बीच १,३४६ नए लाइसेन्स (नए सस्थानों की स्थापना के लिये ५३६ सम्मिलित करते हुये) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार किये गये । सन् १९५६ में यह निर्णय किया गया था कि औद्योगिक मशीनरी व कुछ अन्य भेदों के निर्माण सम्बन्धित फर्मों पूँजीगत वस्तुओं के आयात-लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये सीधे ही प्राथना पत्र दे सकती हैं तथा एक बार ऐसा लाइसेन्स मिल जाने पर उद्योग अधिनियम का लाइसेन्स भी स्वतः मिल जायेगा । १०० से कम श्रमिक लगाने वाले छोटे एवं मध्यम आकार वाले उद्योग जिनकी सम्पत्ति १० लाख में कम है, लाइसेन्स लेने के बन्धन से मुक्त कर दिये गये हैं ।

उन महत्त्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिये, जिनको प्राइवेट क्षेत्र में पर्याप्त पूँजी नहीं मिल पा रही है, सरकार विशेष शर्तों पर ऋण देकर या अथवा पूँजी में भाग लेकर सहायता करती है । भारत सरकार का केन्द्रीय स्टोर्स एवं विक्रय संगठन अपनी स्टोर्स क्रय नीति के द्वारा देशी उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहा है । सन् १९५६-६० में कुल व्यय (मूल्य १८३ करोड़ रु०) में १६% आयातित माल था, जबकि सन् १९५५-५६ में यही प्रतिशत ३७% था ।

(IV) औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रगति—

भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जुलाई सन् १९४८ में हुई थी । तब से यह औद्योगिक सस्थाओं को दीर्घकालीन ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता दे रहा है । मार्च सन् १९६० तक निगम ने कुल ७२*१८ करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत किये, जिनमें से ७८४ करोड़ रु० सन् १९५६-६० में ही स्वीकृत किया गया था । लगभग ३० ऋण उन नई सस्थाओं का स्वीकृत किये गये, जिन्होंने स्वतन्त्रता के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया था । ४७४८ करोड़ रु० वास्तविक रूप में ऋण दिया गया है । द्वितीय योजना में निगम की केन्द्रीय सरकार के ऋणों के लिये १३५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी, बाद में यह रकम २२२५ करोड़ रु० तक बढ़ा दी गई ।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, १९५७ का उद्देश्य निगम के प्रसाधनों में वृद्धि करना है, ताकि वह अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत कर सके । अब ऐसी अनेक सथाएँ भी निगम में ऋण प्राप्त कर सकती हैं जो कोई पर्याप्त प्रतिभूति देने में असमर्थ हैं, किन्तु जिन्हें राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से प्रोत्साहन देना उचित है ।

राज्य वित्त निगमों की सत्ता अब १४ हो गई है तथा ये निगम मध्यम एवं लघु पैमाने के उद्योगों की सहायता करते हैं, जो कि अखिल भारतीय निगम के कार्य-

अल्कोहल, सूती, ऊनी कपड़े तथा जमड़े के कारखाने, सीमेंट, चीनी, कागज, समाचार-पत्र का कागज, हवाई तथा समुद्री यातायात तथा सुरक्षा सैनिक उद्योग । नमक, भारी रसायन, चीनी, सीमेंट आदि) अस्तित्व भारतीय महत्व के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का निर्धारण सरकार करेगी ।

- (५) केन्द्रीय सरकार कुटीर एवं लघु उद्योगों का विशाल उद्योगों से समन्वय कराने का प्रयत्न करेगी ।
- (६) भारत विदेशी पूँजी तथा विदेशी साहस का उपयोग करने के लिए सह्य प्रस्तुत है । हाँ, विदेशी कम्पनी को भारतीय विशेषज्ञ प्रशिक्षित करने पड़ेगे । यदि राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसका उचित हर्जाना दिया जायगा । विदेशी पूँजी का नियन्त्रण भारतीय हाथों में ही रहेगा ।
- (७) धमिकों के हिताथ गृह निर्माण की योजना की व्यवस्था भी की गई ।
- (८) प्रभुत्व नीति इस प्रकार प्रभावित होगी कि अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा का अन्त होकर देश के उपलब्ध श्रोतों का पूरा उपयोग होने लगे ।

निश्चित अर्थ-व्यवस्था—

सन् १९४८ की औद्योगिक नीति का वास्तव में निश्चित अर्थ-व्यवस्था में अभिप्राय है । इससे तात्पर्य उस अवस्था का है जिसमें केवल वैयक्तिक उपक्रमी ही नहीं होते, बल्कि सरकार भी उत्पादन का काम करती है और व्यावसायिक तथा उत्पादक संस्थाओं पर नियन्त्रण रखती है । दूसरे शब्दों में, कुछ उद्योगों पर केवल राज्य का स्वामित्व और नियन्त्रण रहता है, कुछ उद्योगों पर वैयक्तिक उपक्रमियों तथा सरकार दोनों का ही भाग रहता है और शेष पर केवल वैयक्तिक उपक्रमियों का ही नियन्त्रण रहता है । किन्तु उद्योगों पर केवल राज्य का अधिकार रहे और किन्तु पर केवल वैयक्तिक उपक्रमियों का, इसे राज्य की सरकार तय करेगी । आधार-रहित आधारभूत और मुख्य उद्योगों पर राज्य का ही नियन्त्रण रहता है । उपभोग की वस्तु तैयार करने वाले उद्योगों पर राज्य और व्यक्तिगत उत्पादक दोनों का ही नियन्त्रण रहता है, लेकिन छोटे और माध्यमिक पैमाने के उद्योगों पर प्राइवेट उत्पादकों का ही नियन्त्रण होना चाहिए ।

भारत के लिये इस नीति का महत्व—

भारत के लिये ता उक्त नीति का बड़ा महत्व है । हमारे देश की स्थिति आज ऐसा तह है कि सारे उद्योगों का आखिरी बन्द करके राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । हम तो आज नष्ट विकसित अवस्था में हैं । हमें अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त किये अभी पूरे १४ वर्ष ही हैं । हमारे देश की सरकार के पास पूँजी, तन्त्र, कुशल कर्मचारी एवं संचालकों की बड़ी कमी है, अतः हमारे देश की जनता में ।

कल्याण इसी में है कि राष्ट्रीय सरकार एक मध्यम मार्ग का अवलम्बन करे, अर्थात् न तो एकदम राष्ट्रीयकरण कर डाले और न राष्ट्रीयकरण की योजनाओं का एकदम त्याग ही कर दे। वह उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे, जहाँ की स्थिति पक्ष में हो, अन्य का नहीं। दिनांक ६ अप्रैल सन् १९४८ को भारत की जो नवीन औद्योगिक नीति घोषित की गई, उसमें इन विचारों को पूरा-पूरा महत्व दिया गया और उद्योगों को तीन क्षेत्रों में रखा गया—(१) राज्य अधिकृत क्षेत्र, (२) राज्य नियन्त्रित क्षेत्र, (३) वैयक्तिक क्षेत्र। अस्त्र-शास्त्र का निर्माण, अणु-शक्ति का उत्पादन एवं नियन्त्रण, रेल यातायात का स्वामित्व एवं प्रबन्ध, प्रतिरक्षा उद्योग, बहु-उद्देशीय नदी योजनाएँ, उर्वरक निर्माणशालाएँ और आवश्यक भेषज एवं सफिल्ट तेल पर राज्य का एकाधिकार हो गया है। औद्योगिक विकास एवं नियन्त्रण अधिनियम (सन् १९५३ में संशोधित) में उन ४२ उद्योगों की सूची दी गई है, जिन पर वैयक्तिक उपक्रम को राज्य की देखरेख में कार्य करने दिया जायगा। शेष उद्योगों पर वैयक्तिक उपक्रम स्वतन्त्र रहेंगे। हाँ, राज्य का साधारण नियन्त्रण बना रहेगा।

उक्त औद्योगिक नीति का मिश्रित भावना से स्वागत किया गया। कुछ लोगों की सम्मति में यह 'जनतन्त्रीय समाजवाद' की बुनियाद थी। इसके विपरीत कुछ लोगों ने इसे इकतरफा तथा पूँजीपतियों के विरुद्ध बताया। यह भी आशका प्रगट की गई थी कि इस नीति को संभवतः प्रान्तों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाय, क्योंकि 'उद्योग' प्रान्तीय विषय था।

इसी प्रकार, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के कार्यवाहन में सघर्ष उत्पन्न होने स्वाभाविक है। वास्तव में इसकी अपेक्षा केवल पूँजीवादी या केवल समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का संचालन करना सरल है। मिश्रित व्यवस्था के सामने अधिक जटिल समस्याएँ हाती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कार्यों में समन्वय होना चाहिये, कुछ दुर्लभ साधनों का दानों में उचित बँटवारा होना आवश्यक है। यही नहीं, मिश्रित व्यवस्था को अनेक नियंत्रणों के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है।

केन्द्रीय सलाहकार समिति—

औद्योगिक नीति सम्बन्धी अस्तित्व के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने सन् १९४८ में औद्योगिक केन्द्रीय सलाहकार समिति (Central Advisory Council of Industries) की स्थापना की है, जिसमें उद्योग, श्रम, व्यापार, राज्य सरकारें तथा संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। इस समिति के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं —

(१) केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक नीति सम्बन्धी सलाह देना।

(२) किसी उद्योग विषय की निश्चित समस्याओं के हल एवं औद्योगिक

उत्पादन की अधिकतम वृद्धि प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का परामर्श देना ।

- (३) बड़ बड़ उद्योगों के उत्पादन का सामयिक परीक्षण करना तथा उनकी पूरा उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ।
- (४) दुर्लभ वच्चे माल के वितरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना ।
- (५) उद्योगों के लिए आवश्यक वच्चे मान एवं पूँजीय वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का सलाह देना ।
- (६) इसके अतिरिक्त जा भी समस्याय समय-समय पर समिति के सम्मुख केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाय उन पर विचार करना ।

औद्योगिक केन्द्रीय सलाहकार समिति के संरक्षण में पृथक्-पृथक् उद्योगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए धनक विकास समितियाँ बनाई गई हैं जो उन उद्योगों का उत्पादन कार्यक्रम निश्चित करेगी तथा विकास योजनाय बनायेगी । औद्योगिक केन्द्रीय सलाहकार समिति का विस्थापन २३ नवम्बर सन् १९५० को औद्योगिक विकास समिति (High Level Development Committee on Industries) के निर्माण से हुआ । यह समिति वर्तमान उद्योगों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने तथा सामान्यतः सभी उद्योगों की विकास योजनाय बनाने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देगी जिससे वर्तमान उद्योगों का उत्पादनक्षमता का पूरा क्षमता से उपयोग हो सके । इस समिति के मुख्य कार्य निम्नांकित हैं —

- (१) यह समिति वर्तमान उद्योगों का उत्पादन कार्यक्रम निश्चित करेगी तथा ऐसे प्रयत्न करेगी जिससे कि श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ एवं उत्पादन का व्यय न्यूनतम हो ।
- (२) उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये सुधार करना ।
- (३) उद्योगों की विविध समस्याओं को हल करने के लिये परामर्श देना ।

Standard Question

- 1 Point out the objectives and special features of India's Industrial Policy 1948

अध्याय १५ सन् १९५६ की औद्योगिक नीति (Industrial Policy Of 1956

भारत सरकार की औद्योगिक नीति सन् १९५६—

भारत सरकार ने ६ अप्रैल सन् १९५६ के प्रस्ताव में उम नीति को प्रतिपादित किया था जिसका वह औद्योगिक क्षेत्र में अनुमरण करना चाहती थी। प्रस्ताव ने इस बात पर जोर दिया कि अथ-अवस्था एसी हो जा उत्पादन में निरन्तर वृद्धि का और उसके न्यायोचित वितरण का प्रयत्न करे। इसमें यह भी इंगित किया कि राज्य को उद्योगों का विकास करने में प्रगतिशील (Progressive) भाग लेना चाहिए। इसने यह निर्दिष्ट किया कि हथियार तथा बाहुद, अणु-शक्ति एवं रेलवे यातायात के अतिरिक्त (जो कि केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार में होंगे) छ मूल उद्योगों में राज्य ही नये कारखाने खोलने के लिए पूर्णतः दायी होगा। हा, जब राष्ट्रीय हित में राज्य स्वयं प्राइवेट साहस के सहयोग की आवश्यकता अनुभव करे तो बात दूसरी है। ये क्षेत्र प्राइवेट साहस के लिए खुला रखा गया है यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य भी इन क्षेत्रों में प्रगतिशील भाग लगे।

इस औद्योगिक धारणा का अब चौदह वर्ष बीत गया है। इन चौदह वर्षों के अन्दर भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हो गए हैं तथा भारत का सविधान बन गया है जिनमें कुछ मौलिक अधिकारों की गारण्टी दी गई है और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों (Directive Principles of State Policy) का उल्लेख किया गया है। योजना काय संगठित आधार पर आरम्भ हो गया है और पच वर्षीय योजना का अभी हाल में पूर्ण हुई है। संसद ने समाजवादी समाज को अपनी सामाजिक एवं आर्थिक नीति का लक्ष्य स्वीकृत कर लिया है। इन परिवर्तनों के कारण नई औद्योगिक नीति की घोषणा आवश्यक हो जाती है, विशेषतः इसलिए कि अब हम तृतीय पच-वर्षीय योजना पर अमल करने जा रहे हैं। इस नीति पर सविधान के सिद्धान्तों, समाजवादी उद्देश्य और इन वर्षों में प्राप्त हुए अनुभवों का नियन्त्रण होना चाहिए।

निर्देशक सिद्धान्त—

भारतीय सविधान यह घोषित करता है कि उसका उद्देश्य अपने सब नागरिकों

रिक्तों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, पूँजी एवं धर्म की स्वाधीनता, स्थिति और अवसर की समानता एवं ऐसी भ्रातृत्व भावना का प्रसार करना है, जो कि व्यक्ति की महत्ता और राष्ट्रीय एकता का आश्वासन दे। राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तों में यह बहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को, जिसमें न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक) राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं को ओत प्रोत करे उपलब्ध और सुरक्षित करके अपनी जनता का अधिक कल्याण करने का प्रयत्न करेगा। यही नहीं, राज्य अपनी नीति को इस प्रकार रखेगा कि —

- (अ) स्त्री व पुरुष सभी नागरिकों को जीवन-यापन के पर्याप्त साधन-बराबर उपलब्ध हो।
- (आ) समुदाय के भौतिक साधनों का व्यापक एवं नियन्त्रण इस प्रकार से विनिरत हाना चाहिए कि अधिक व अधिक सामान्य हित हो।
- (इ) अर्थ व्यवस्था का मंचालन इस प्रकार न हो कि जिसके परिणाम स्वरूप जनहितों के विरुद्ध धन और उत्पादनों के साधनों का केन्द्रीयकरण हो जाय।
- (ई) बराबर काम के लिए, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, बराबर वेतन दिया जाय।
- (उ) स्त्री व पुरुष सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की छोटी अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता के कारण लोग ऐसा करने के लिए विवश न हो जो उनकी आयु या शक्ति के परे हो।
- (ऊ) बच्चों और नौजवानों को शोषण तथा नैतिक व आर्थिक पतन से बचाया जाय।

इन आधारभूत और सामान्य सिद्धान्तों को दिसम्बर सन् १९५४ में (जबकि संसद ने समाजवादी समाज को अपनी सामाजिक और आर्थिक नीति का लक्ष्य मान लिया) अधिक स्पष्ट रूप मिला अतः अन्य नीतियों की भाँति औद्योगिक नीति का नियन्त्रण भी इन्हीं सिद्धान्तों एवं निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जाय और भारी उद्योगों एवं मशीन उद्योगों का विकास किया जाय, सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाय और बड़े तथा वृद्धिशील (Increasing) सहकारी क्षेत्र का निर्माण किया जाय। ये अधिकांश लोगों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एवं रहन-सहन का स्तर और कार्यदशाओं को सुधारने के लिए सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। साथ ही, आय और धन में विद्यमान असन्तुलन को घटाना, प्राइवेट एकाधिकारों को रोकना और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ

ही व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण होने देना भी उतना ही आवश्यक है, अतः राज्य नई औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना और यातायात सुविधाओं के बढ़ाने में अधिक प्रगतिशील भाग लेगा। वह बढ़ते हुए पैमाने पर राज्य व्यापार (State Trading on an Increasing Scale) को हाथ में लेगा। इसके साथ देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में प्राइवेट क्षेत्र को भी एक संगठित राष्ट्रीय विकास की एजेंसी के रूप में विकसित होने का अवसर मिलेगा। सहकारिता का सिद्धान्त यथासम्भव अपनाया जाएगा और प्राइवेट क्षेत्र को सहकारिता के क्षेत्र में यथासम्भव वृद्धिशील भाग मिलेगा।

सरकारी क्षेत्र—

‘समाजवादी समाज’ के राष्ट्रीय ध्येय की पूर्ति और शीघ्र एवं संगठित विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी आधारभूत और सुरक्षा उद्योग या जनहित सेवाएँ (उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए) सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिए। अब अन्य उद्योग, जो कि आवश्यक हैं और जिनके लिए इतना अधिक विनियोग आवश्यक है कि वर्तमान दशाओं में केवल राज्य ही कर सकता है, सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए, अतः राज्य को एक अधिक फैले हुए क्षेत्र में उद्योगों के भावी विकास का प्रत्यक्ष दायित्व लेना होगा। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इस अवस्था पर राज्य के लिए उस क्षेत्र की परिभाषा करना जिसमें वह भावी विकास का पूर्ण दायित्व ग्रहण करेगा और ऐसे उद्योगों का चुनाव काम, जिनके विकास में वह प्रधान भाग लेगा, आवश्यक बना देती हैं। समस्या के समस्त पहलुओं पर योजना कमीशन से विचार-विमर्श करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटने का निर्णय किया है। ये श्रेणियाँ एक दूसरे से बिल्कुल पृथक् तो नहीं रखी जा सकती, अर्थात् कुछ उद्योग दो या अधिक श्रेणियों में भी रखे जा सकते हैं, किन्तु आधारभूत सिद्धान्तों और उद्देश्यों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और सामान्य निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह ध्यान रहे कि राज्य के लिए यह छूट है कि वह किसी भी प्रकार के उत्पादन को अपने हाथ में ले ले।

उद्योगों का वर्गीकरण—

प्रथम श्रेणी में वे उद्योग हैं, जिनके विकास का पूर्ण दायित्व सरकार पर होगा। दूसरी श्रेणी में वे उद्योग होंगे, जिन पर राज्य स्वामित्व बढ़ाता जाएगा और इसलिए नए कारखाने स्थापित करने के लिए सामान्यतः राज्य ही कदम उठाएगा, परन्तु प्राइवेट साहस से भी सरकारी प्रयत्नों में सहायता करने की आशा रखी जायगी। तीसरी श्रेणी में वे अन्य सब उद्योग होंगे और सामान्यतः इनका विकास प्राइवेट क्षेत्र के ऊपर छोड़ दिया जाएगा।

प्रथम श्रेणी के उद्योगों के नाम इस प्रस्ताव की प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। इन उद्योगों में नए कारखाने केवल राज्य ही स्थापित करेगा, किन्तु इसका यह

अथ नहीं है कि विद्यमान प्राइवेट इकाई का विकास पर ध्यान नए कारखाना की स्थापना में प्राइवेट साहस से सहयोग लेने पर कोई रोक होगी। हाँ रेलवे और हवाई यातायात हथियार एवं वाहद तथा अणु शक्ति का विकास केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार में किया जाएगा। जब कभी प्राइवेट साहस के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होगी तो इसे राज्य या तो अधिकांश पूँजी देकर अथवा कारखाने के संचालन एवं नीति पर नियन्त्रण रखकर प्राप्त कर सकता है।

दूसरी श्रेणी में जो उद्योग हैं उनके नाम द्वितीय अनुसूची में दिये गए हैं। इनका भावी विकास तेजी से करने के लिए सरकार इन उद्योगों में अधिक नए कारखाने स्थापित करेगी। साथ में प्राइवेट साहस को भी स्वयं (या राजकीय सहायता से) विकास करने का इस क्षेत्र में अवसर दिया जायगा।

शेष सब उद्योग तीसरी श्रेणी में आने हैं और यह आगामी की जाती है कि उनका विकास सामान्यतः प्राइवेट मध्यम के उद्योगों द्वारा किया जायगा। यद्यपि इस क्षेत्र में भी राज्य विभी भी उद्योग का स्वयं आरम्भ कर सकता है। राज्य की यह नीति होगी कि प्राइवेट क्षेत्र में इन उद्योगों का विकास का पंच वर्षीय योजनाओं में ही कार्यक्रमों के अनुसार प्रोत्साहित किया जाय। इन उद्योगों के लिए राज्य 1. 10 शक्ति एवं अन्य सेवाओं का विकास करेगा और अन्य सहायता देने के लिये 1. 10 सहाय सहायता स्थापित करेगा। औद्योगिक एवं कृषि कार्यों के लिये मर्यादित आश्वासन पर मर्यादित सहायता को विनाश मुविधाय प्रदान की जायगी। उपर्युक्त मामला में तो राज्य स्वयं ही प्राइवेट क्षेत्र का अधिक सहायता दे सकता है।

प्राइवेट क्षेत्र के लिए आश्वासन—

प्राइवेट क्षेत्र की औद्योगिक सहायताओं को सामाजिक एवं आर्थिक नीति के सामान्य ढाँचे के अनुसार कार्य करना होगा और उन पर उद्योग (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित सन्धियों का नियन्त्रण होगा। हाँ भारत सरकार यह अनुभव करती है कि राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों का उचित ध्यान रखते हुए इन उद्योगों के विकास को अधिकतम सम्भव छूट देनी चाहिये। जब किसी उद्योग में प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह के कारखाने विद्यमान हों तो राज्य की यह नीति रहेगी कि वह दोनों के साथ समानता का व्यवहार करे।

दोनों क्षेत्रों में परस्पर स्थानापन्नता—

उद्योगों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजन करने का यह आशय नहीं है कि वे एक दूसरे से विलकुल पृथक् होंगे। कुछ उद्योग दो या अधिक श्रेणियों में रखे जा सकेंगे और साथ ही दोनों क्षेत्रों में स्थानापन्न अधिकार हो सकते हैं अर्थात् राज्य के लिये यह छूट है कि जब राष्ट्रीय योजना की दृष्टि से आवश्यक हो तो वह ऐसा उद्योग आरम्भ करे जो कि प्रथम और दूसरी अनुसूची में नहीं दिया है। इसी प्रकार उपर्युक्त दशाओं में प्राइवेट सहायताओं को भी प्रथम अनुसूची में वर्णित मद के

उत्पादन का (इन्हीं निजी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अधिकांश उत्पाद के रूप में) आज़ा दी जा सकती है। सामान्यतः छोटे प्राइवेट कारखानों द्वारा इसका क़ापट बनाना स्थानीय आवश्यकताओं और छोटे पैमानों की खानों के लिये शक्ति प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग अपने हल्के सामानों की पूर्ति प्राइवेट क्षेत्र से कर सकते हैं जबकि प्राइवेट क्षेत्र अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए सरकारी क्षेत्र पर निर्भर रहेगा। यही सिद्धान्त कम या अधिक, बड़े या छोटे पैमाने के उद्योगों में पारस्परिक सम्बन्ध से लागू होगा।

इस सदर्भ में भारत सरकार राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास में कुटीर एवं ग्राम्य तथा लघु उद्योगों पर जोर देगी। कुछ समस्याओं के सम्बन्ध में, जिनको तुरन्त हल करना आवश्यक है उनके विशेष लाभ है। वे बड़े पैमाने पर जीव्य ही रोजगार प्रदान कर सकते हैं, व राष्ट्रीय आय का अधिक न्यायोचित वितरण करने का साधन है और वे पूँजी एवं निपुणता के साधनों को प्रभावपूर्ण रीति से गतिशील बनाने हैं। अनियोजित शहरी विकास से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ दश भर में छोटे-छोटे उत्पादन केन्द्र स्थापित करके समाप्त की जा सकती हैं—

१ राज्य कुटीर और ग्राम्य एवं लघु कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों का उत्पादन सीमित करके विभेदात्मक कूटनीति और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित कर रहा है। ये सहायता भविष्य में दी जावेगी किन्तु राज्य यह भी ध्यान रखेगा कि विवेचित्र उत्पादन क्षेत्र स्वयं आत्म निर्भर बन सके और उसका बड़े पैमाने के उद्योगों से समन्वय हो सके, अतः राज्य ऐसे कदम उठावेगा, जिनसे छोटे उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा शक्ति में वृद्धि हो। इसके लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन की टेक्नीक में बराबर सुधार होते रहें। टेक्नीकल एवं आर्थिक सहायता का अभाव, कार्य करने की उपयुक्त जगह न होना मरम्मत एवं देख रेख (Maintenance) के लिए अपर्याप्त सुविधायें होना छोटे पैमाने के उत्पादकों के लक्ष्मी दोष हैं, जिन्हें दूर करने के लिए औद्योगिक एस्टेट एवं सामुदायिक कार्यशालायें खोली जा रही हैं। ग्रामों में बिजली का विस्तार किया जा रहा है इससे कारीगरों को सस्ती दर पर शक्ति उपलब्ध हो सकेगी। यदि औद्योगिक सहकारितायें स्थापित हो जायें तो लघु उत्पादन की बहुत-सी समस्याएँ सुलभ सकती हैं। इन्हीं हर तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए।

सन्तुलित विकास—

विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तरों में अन्तर कम करना बड़ा महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि तब ही औद्योगीकरण से देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था लाभान्वित हो सकेगी। देश के विभिन्न भागों में कुछ उद्योगों का अभाव प्रायः आवश्यक कच्चे माल आदि के

उपलब्ध न होने के कारण है। इसी प्रकार विशेष क्षेत्रों में उद्योगों का केन्द्रीयकरण भी शक्ति, जल-पूर्ति और यातायात सुविधाओं के कारण सम्भव होता है। राष्ट्रीय योजना का यह उद्देश्य है। ये सुविधाएँ उन क्षेत्रों को भी प्रदान की जायें, जो आज उनके अभाव से ग्रस्त हैं, अथवा जहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करना अधिक आवश्यक है। हाँ, स्थान अन्य दृष्टियों से उपयुक्त होना चाहिए।

औद्योगिक विकास के उच्च कार्यक्रम को पूरा करने के लिए देश के टैक्नीकल और प्रबंध साधनों पर बड़ा बोझ पड़ेगा, अतः सरकारी सेवाओं में उचित प्रबंध और टैक्नीकल विभाग स्थापित किए जा रहे हैं।

औद्योगिक शान्ति—

औद्योगिक प्रगति के लिए औद्योगिक शान्ति अत्यन्त आवश्यक है। समाजवादी प्रजातन्त्र में श्रम भी विकास काय में एक साझेदार है, अतः उसे उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेना चाहिए। औद्योगिक सम्बन्धों के नियन्त्रण के लिए कुछ सभियम बनाए गए हैं। मजदूरी और टेक्नीशियनों की प्रबंध में अधिकाधिक भाग लेना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इस दशा में उदाहरण स्थापित करना है।

राज्य द्वारा उद्योग और व्यापार में अधिकाधिक भाग लेने की दशा में यह बड़ा महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी क्रियाओं का संचालन उचित रूप से हो। तुरन्त निर्णय और दायित्व ग्रहण की भावना इन संस्थाओं की प्रगति के लिए आवश्यक है। इसके लिए जहाँ-जहाँ सम्भव हो वहाँ अधिकारों का विवेकीकरण किया जाय और प्रबंध व्यापारिक ढंग से चलाया जाय। यह आशा की जाती है कि सरकारी कारखाने राज्य की आय बढ़ावेंगे और नए क्षेत्रों में विकास के लिए धन जुटावेंगे, किन्तु ऐसी संस्थाओं को हानि भी हो सकती है। फिर भी उनके कार्य का कुल पर अनुमान लगाना चाहिए और उसको अधिकतम सम्भव स्वतन्त्रता हो।

भारत सरकार यह आशा करती है कि नई औद्योगिक नीति सभी वर्गों को सन्तुष्ट करेगी और दूसरे, राष्ट्र के दीर्घ औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी।

नीति की आलोचना—

सन् १९५६ की औद्योगिक नीति की निम्न आधार पर तीव्र आलोचनाएँ की गईं —

- (१) जब सरकारी क्षेत्र में कार्य सतोषप्रद नहीं है तो इतने उद्योगों को सरकार के अधीन करना न्यायपूर्ण नहीं है।
- (२) इसके कारण सरकारी अधिकारियों के हाथों में इतनी अधिक शक्ति पहुँच गई है कि वे हमारी स्वाधीनता पर कुठाराघात कर सकते हैं।
- (३) निजी क्षेत्र को किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं दी गई है।
- (४) इस नीति से उद्योग तथा व्यापारी असमजस में पड़ गये हैं कि कौन

उद्योग सरकारी क्षेत्र में तथा कौन निजी क्षेत्र में है। इससे देश का औद्योगिक विकास रुकेगा।

- (५) इस नीति से कृषि तथा औद्योगीकरण में सरकारी पूँजीवाद के दोष पैदा हो जायेंगे।
- (६) नीति बनाने वालों के अनुभवहीन होने के कारण यथार्थ शक्ति सरकारी अधिकारियों के पास चली जायगी।
- (७) आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण राजनीतिज्ञों के हाथों में होना उद्योग-पतियों की अपेक्षा अधिक खतरनाक है।
- (८) मजदूर सस्याओं ने भी इस नीति का स्वागत नहीं किया।

किन्तु नीति की भावना तक पहुँचने पर यह स्पष्ट होगा कि बहुत सारे आरोप केवल आलोचना की दृष्टि मात्र से ही लगाए गए हैं, इसलिए अनेक विचारशील उद्योगपतियों ने भी इस नीति की सराहना की है। यदि हम देश का विकास चाहते हैं, जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं, देश का औद्योगीकरण वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहते हैं तथा देश में सही रूप से समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं तो सरकारी नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप आवश्यक है। किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के लिए सारे समाज का हित नष्ट नहीं कर सकते। फिर नई नीति में निजी क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। सरकार निजी उद्योगों को समुचित सहायता भी दे रही है। यह सच है कि सरकारी मशीनरी अभी अकुशल तथा दोषपूर्ण है, किन्तु सरकार इस ओर जागरूक है और ये दोष दूर किये जा सकते हैं। जहाँ तक सरकारी एकाधिकार का प्रश्न है, जब उद्योगों का प्रबन्ध कॉरपोरेशन पद्धति पर किया जा रहा है तो एकाधिकार संभव नहीं हो सकता। प्रबन्ध में मजदूरों का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व रहेगा।

नीति को सफल बनाने के लिए अनुकूल अधिनियमों तथा संगठन का निर्माण किया गया है, जैसे—औद्योगिक (विकास तथा नियन्त्रण) अधिनियम, लायसेन्स समिति, केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार परिषद्, औद्योगिक विकास परिषद् आदि।

कुछ सुझाव—

नीति की सफलता हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं की सफलता पर निर्भर रहेगी। इसके लिए हमारे निम्न सुझाव हैं —

- (१) मशी आँकड़ों का सकलन कराया जाय। यह कार्य महाविद्यालय तथा विश्व-विद्यालयों के अधीन किया जा सकता है।
- (२) उद्योगों का संगठन इस आधार पर हो कि उनकी गतिविधियों की जानकारी जनता को हो सके।
- (३) सरकारी कम्पनियों के प्रबन्ध के लिए सिविल सर्विस के अधिकारियों की अपेक्षा उचित तांत्रिक योग्यता प्राप्त अधिकारियों की नियुक्त किया जाय तथा इसके लिए समुचित प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें।

- (४) प्रबन्ध में धूमिना का प्रतिनिधित्व या म्प ज समाजवादी दर्शों की पद्धति के अनुसार (भारतीय परिस्थितियाँ के अनुकूल) होना चाहिए ।
- (५) कुटीर उद्योगों का विकास वृद्ध उद्योगों के लिए बाधक न बने और उन पर किसी प्रकार का अनुचित प्रतिबन्ध न लगाया जाय ।
- (६) जिस प्रकार केन्द्रीय आयोग है उसी प्रकार प्रान्ता में स्थायी रूप से प्रांतीय आयोग स्थापित किये जाय ।
- (७) सारे राष्ट्र में उचित शिक्षा का प्रसार नैतिक उत्थान तथा राष्ट्र निर्माण की भावनाये जाग्रत होना आवश्यक है ।

Schedule A

- 1 Arms and ammunition and allied items of defence equipment
2. Atomic Energy
- 3 Iron and Steel
- 4 Heavy Castings and forgings of iron and steel
- 5 Heavy plant and machinery required for iron and steel production for mining for machine tool manufacture and for such other basic industries as may be specified by the Central Government
- 6 Heavy electrical plant, including large hydraulic and steam turbines
- 7 Coal and lignite
- 8 Mineral Oils
- 9 Mining of iron ore manganese ore, chromite ore gypsum, sulphur, gold and diamond
10. Mining and Processing of copper, lead, zinc tin, molybdenum and wolfram
11. Minerals specified in the schedule to the Atomic energy (Control of Production and Use) Order 1953
- 12 Aircraft
13. Air Transport
- 14 Railway Transport
- 15 Ship building, Telephones and Telephone cables, Telegraph and apparatus (excluding radio receiving sets).
- 16 Generation and distribution of electricity.

Schedule B

- 1 All other minerals except minor minerals as defined in the section 3 of the Mineral Concession Rules, 1949
- 2 Aluminium and other non ferrous metals not included in Schedule A
- 3 Machine tools
- 4 Ferro-Alloys and tool steels
- 5 Basic and Intermediate products required by chemical in dustries such as the manufacture of drugs dyestuffs and plastics
- 6 Anti biotics and other essential drugs
- 7 Fertilizers
- 8 Synthetic Rubber
- 9 Carbonisation of Coal
- 10 Chemical pulp
- 11 Road Transport
- 12 Sea Transport

सन् १९४८ एव सन् १९५६ की औद्योगिक नीतियों की तुलना—

दोनों नीतियों के विवरण से यह प्रगट होता है कि उनमें अंतर का निम्न बात है —

(१) सन् १९५६ की नीति में सावजनिक क्षेत्र के विस्तार पर अधिक बल दिया गया है। इसका एक प्रमुख कारण यह था पिछले आठ वर्षों में जो आधारभूत एवं मौलिक उद्योग प्राइवेट क्षेत्र में बने या तो विकसित नहीं हो पाये अथवा उनके विकास की गति लक्ष्य की अपेक्षा बहुत कम थी।

(२) राज्य ने केवल हथियार एवं बारूद अणु शक्ति रेल एवं वायु यातायात के सम्बन्ध में ही एकाधिकारक अधिकार ग्रहण किये हैं। इसके अतिरिक्त सरकार क्षेत्र के सभी उद्योगों में प्राइवेट साहस को कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसा करना राष्ट्रीय हित में हो।

(३) सन् १९५६ के प्रस्ताव में परिभाषित तीनों ही वर्गों में सरकारी उपक्रम के साथ साथ प्राइवेट उपक्रम को भी पनपन की अनुमति दी गई है बशर्ते प्राइवेट उद्योगों का इस प्रकार नियमन होता रहे कि वह ऐसा कोई अनुचित लाभ न कमाय जो कि जन कल्याण के लिए हानिप्रद हो।

(४) सरकार ने सावजनिक क्षेत्र में ग्रान बाल प्राइवेट उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। सन् १९४८ की नीति में उसने यह

अधिकार सुरक्षित रखा था कि सरकारी उपक्रमों के लिए पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र में काम करने वाले प्राइवेट उपक्रमों की स्थिति पर १० वर्षों बाद पुनर्विचार किया जायगा। नये प्रस्ताव में इस अधिकार को छोड़ दिया गया है। यही नहीं, यह आश्वासन भी दिया गया है कि प्रथम चरण में आने वाले प्राइवेट उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। जिस क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के उपक्रम कार्यशील हो वहाँ सरकार उनसे समानता का व्यवहार करेगी।

(५) प्राइवेट सेक्टर का एक बढ़ता हुआ भाग सहकारी आधार पर विकसित किया जायगा।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss carefully the present Industrial Policy of the Government of India
2. Critically examine the 1956 Industrial Policy of the Government of India
3. Compare and contrast the 1948 Industrial Policy with the 1956 Industrial Policy

अध्याय १६

औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, १९५१

(Industries (Development & Regulation) Act, 1951)

प्रारम्भिक—

भारत की औद्योगिक नीति का उद्देश्य उन उद्योगों पर केन्द्रीय नियंत्रण स्थापित करना है, जिनका विकास सम्पूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक घटकों पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने सन् १९५१ में औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम स्वीकृत किया।

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, १९५१ की मुख्य बातें—

मूल रूप में उक्त अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं —

(१) यह अधिनियम जम्मू व काश्मीर को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। प्रथम अनुसूची में दिये हुए ३६ उद्योगों पर (अब यह संख्या बढ़ गई है) यह अधिनियम प्रभावशील होगा।

(२) इन उद्योगों से सम्बन्धित इकाइयों को अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। सरकारी आज्ञा के बिना नया कारखाना नहीं खोला जा सकता और न पुराना कारखाना ही बढ़ाया जा सकता है।

(३) यदि इन औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन कम होने, वस्तु का गुण घटने अथवा मूल्य के बढ़ने की आशंका हो तो केन्द्रीय सरकार उस उद्योग की जाँच कर सकती है और दोष पाने पर निम्न आदेश दे सकती है —

(अ) इकाइयाँ उत्पादन बढ़ाने का यत्न करें।

(आ) इकाइयाँ उद्योग के विकास का यत्न करें।

(इ) वे ऐसा कोई काम न करें जिससे उत्पादन में कमी आवे।

(ई) सम्बन्धित वस्तु के मूल्य और वितरण पर नियन्त्रण रखना।

(४) यदि केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि कोई इकाई उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रही या जन-हित के विरुद्ध चलाई जा रही है तो वह उसका प्रबन्ध वगैरह जाँच किये भी बुद्धि ले सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकती है।

(५) उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए केन्द्रीय परा-

मजदूरी समिति बनाई गई जिसमें अनुमति प्राप्त उद्योगों के स्वामीगण, कमचारी वग, उपभोक्ता वृन्द और अन्य दला के प्रतिनिधि होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी।

(६) औद्योगिक विकास परिषद् का भी निर्माण किया गया है जिसमें सब दलों के प्रतिनिधि हैं। इनके निम्नलिखित वाय हैं

(अ) उत्पादन की सीमा नियन्त्रित करना योजनाओं में सामञ्जस्य रखना और उन्नति के लिए सलाह देना।

(आ) कम कुशल इकाइयों का निपटारा बनाने का यत्न करना।

(इ) उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखने हुए विक्रय और वितरण की उचित प्रणाली व्यवहार में लाना।

(ई) वस्तुओं के प्रमाणीकरण में महानता करना।

(उ) उद्योगों को कच्चा माल मिलान में सहयता देना।

(ऊ) उत्पादन विधियों में अनुसन्धान करना।

(ए) कमचारियों की प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।

(ऐ) उद्योग के निराले हुए कमचारियों को अन्यत्र काम दिवाना।

(ओ) उपभोग के लिए निम्न वस्तुओं और सेवाओं के विषय में खोज करना।

(आ) डिग्री करने की प्रणाली में सुधार करना एवं उपाय प्रमाणित करना।

(अ) आकड़ संग्रह करना।

(भ) श्रमिकों के काम करने की दशाओं में सुधार करना।

(क) औद्योगिक क्रियाओं के विक्रीकरण के विषय में जांच करना और उनसे सम्बन्धित छोटे पैमाने के उद्योग तथा कुटीर धंधों के विकास को प्रोत्साहित करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार जांच करना और सलाह देना।

राष्ट्रीय विकास परिषद् हमारे प्रधान मन्त्री के शब्दों में ऐसा संगठन है जिसके द्वारा राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मध्य राष्ट्रीय सरकार के समस्त कार्यों के विषय में धनियत सहयोग रहता है। परिषद् के तीनों उद्देश्य हैं —

(१) पंच वर्षीय योजना के समन्वय में राष्ट्र के प्रयत्न और साधनों को सुदृढ़ तथा सलम्ब करना।

(२) सम्बन्धित अत्यावश्यक क्षेत्रों में सामाजिक अर्थ नीतियों को प्रगति देना।

(३) देश के सम्बन्धित भागों के मजदूरों और त्वरित विकास को सुनिश्चित करना।

सन् १९५३ के संशोधन—

मई सन् १९५३ में मूल अधिनियमों को अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से इसमें निम्न संशोधन किये गये —

- (१) इस अधिनियम ने अनुसूचित उद्योगों की सूची में ६ अधिक उद्योगों का समावेश कर लिया है ।
- (२) उपरोक्त सूची के अन्तर्गत आने वाले ऐसे कारखानों पर भी यह अधिनियम लागू होगा जिनमें एक लाख रुपये से कम पूँजी का विनियोग है ।
- (३) इस सशोधन से केन्द्रीय सरकार का उद्योगों पर नियन्त्रण एवं प्रबन्ध सम्बन्धी विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं अर्थात् अब सरकार बिना जाच के भी उद्योगों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है तथा ऐसा करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के परामर्श की भी आवश्यकता नहीं है ।
- (४) कोई उद्योग सरकार नियन्त्रण में आने के बाद उसके पापद सीमा नियम तथा पापद अन्तर्नियमों का पालन करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है ।
- (५) सरकार सदन का अनुमति से ५ वर्ष की अवधि से अधिक भी नियन्त्रित उद्योग को अपने अधिकार में रख सकती है ।

सन् १९५६ का सशोधन—

इसके अनुसार सरकार ने ३१ और उद्योगों को अनुसूचित उद्योगों की सूची में ले लिया है । १ मार्च सन् १९५७ को सरकार की एक विशेष उद्घोषणा के द्वारा इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है । इसके द्वारा जो उद्योग ५० मजदूरों का विद्युतशक्ति के महार तथा सौ की बिना शक्ति के महार चलाने हो सम्मिलित कर दिया गया है । इसमें उद्योगों का श्रणीकरण भी एक निश्चित आधार पर किया गया है । भारी उद्योग मंत्रालय की प्रस विज्ञप्ति के अनुसार इनको राजस्व शन सर्टिफिकेट तथा लाइसेंस आदि प्रदान किए जायंग ।

सन् १९६० का सशोधन—

मार्च सन् १९६० में भारत सरकार ने ऐसी कई उपाय अपनाने की घोषणा की, जिनसे नये उपक्रमों की स्थापना सम्बन्धी प्राप्ति पत्रों पर तुरन्त निर्णय दिया जा सके । इससे प्रवक्तों की अनुविज्ञा एवं निराशा में कमी हो जायगी । लाइसेन्सिंग कमेटी ने यह निश्चय किया है कि कुछ उद्योगों में जिनमें नई क्षमता का स्वीकृति का प्रस्ताव नहीं है अगल ६ से १२ महीनों के भीतर सभी सम्भावित प्राप्ति पत्र लौटा दिए जायंग । उन पर कोई विचार नहीं किया जायगा । जिन उद्योगों के लिये लाइसेंस स्वतन्त्रतापूर्वक दिए जा सकते हैं उनकी एक सूची बना ली गई है । १०० से कम श्रमिक रखने वाले तथा १० लाख से कम की स्थायी सम्पत्ति वाली औद्योगिक इकाइयों को किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार अब लाइसेन्सिंग कमेटी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में या क्षेत्रिक महत्व वाले उद्योगों के सम्बन्ध में प्लान निर्णय कर सकेगा ।

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम की कार्य प्रगति—

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुये अधि-
कारों का प्रयोग करके बड़े और छोटे उद्योगों का सतुलित विकास तथा विभिन्न
उद्योगों का समुचित पादेशित वितरण करने का प्रयास किया है। इस समय १६२
उद्योग अधिनियम की ताल सूची में सम्मिलित है। सन् १९५२ में केन्द्रीय सलाहकार
समिति (Central Advisory Council) की स्थापना की गई थी, जो
केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक नियंत्रण तथा नियमन के विषय में परामर्श देती है।
इस समिति ने उद्योगों की सामान्य समस्याओं (Common problems) पर
भी विचार किया, जैसे—उद्योगों का स्थान, पुनर्वास के लिये अर्थ-व्यवस्था, आधु-
निकीकरण आदि। एक लाइसेन्स समिति (Licensing Committee)
का भी गठन किया गया है, जो पंच-वर्षीय योजना के उद्देश्यों व प्राथमिकताओं के
अनुसार औद्योगिक विकास का नियमन करने के लिये लाइसेन्स देती है। अक्टूबर
सन् १९५६ से सितम्बर सन् १९६० के बीच १,३४६ नये लाइसेन्स दिये गये थे। इनमें से
५३६ लाइसेन्स नवीन संस्थाओं की स्थापना से सम्बन्धित है। सन् १९५६ में यह निश्चय
किया गया था कि इन्डस्ट्रियल मशीनरी व अन्य आवश्यक मदों के लिए फर्मों सीधे
ही आयात-लाइसेन्स प्राप्त कर सकती हैं और एक बार ऐसा लाइसेन्स मिल जाने पर
उद्योग अधिनियम सम्बन्धी लाइसेन्स भी स्वतः मिल जायगा। १०० से कम श्रमिक
रखने वाले तथा १० लाख से कम स्थिर सम्पत्ति वाले छोटे एवं मध्यम उद्योगों को
लाइसेन्स लेने के बंधन से मुक्त रखा गया है।

लगभग १६ उद्योगों के लिये विकास परिषद (Development Councils) स्थापित की जा चुकी हैं। इन उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं —

- (1) Heavy chemicals (acids and fertilisers),
- (2) Internal combustion engines and power driven pumps;
- (3) Bicycles, sewing machines and instruments;
- (4) Sugar;
- (5) Light electrical;
- (6) Heavy electrical;
- (7) Drugs and Pharmaceuticals;
- (8) Alkalies and allied industries;
- (9) Woollen Textiles;
- (10) Art silk textiles;
- (11) ~~करना~~
- (12) ~~के संशोधन—~~ s and alloys;
- (13) ~~Orn~~ १९५३ में मूल ~~ग्रान्ट्स~~ ;

- (14) Food processing;
- (15) Organic Chemicals;
- (16) Automobiles, automobiles ancillaries and transport vehicles;
- (17) Paper, pulp and allied industries, and
- (18) Leather, leather goods and pickers.

विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर अनेक पैनल एवं विशेषज्ञ समितियाँ नियुक्त की गई थीं। जिन महत्त्वपूर्ण उद्योगों का विकास प्राइवेट क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी न मिलने के कारण रुकता है उन्हें सरकार विशेष धर्तों पर ऋण देकर या उनकी इक्विटी पूंजी में भाग लेकर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार का केन्द्रीय क्रय संगठन (Directorate General of Supplies and Disposals) अपनी स्टोस क्रय नीति के द्वारा देशी उद्योगों को प्रोत्साहित करता रहता है। सन् १९५९-६० में उसकी कुल खरीद का केवल १६% आयातित माल था, जबकि सन् १९५५-५६ में यह प्रतिशत ३७% था।

इस प्रकार हमारी लोकप्रिय सरकार देश का नियोजित ढंग से औद्योगिक विकास करने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि उसका विश्वास है कि "राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक दायित्व के शीघ्र विस्तार द्वारा ही जनता की उचित आशाओं की पूर्ति संभव होगी। अतः न तो उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करना उचित है और न व्यक्तिगत उपक्रम का बिनाकुल स्वतन्त्र छोड़ना ही उचित है। फिर भी इसका यह अर्थ अवश्य है कि सरकारी क्षेत्र का प्रगतिशील विस्तार तथा प्राइवेट क्षेत्र का नवीनीकरण सुनियोजित एवं अर्थव्यवस्था की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए।

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम का देश

के औद्योगीकरण पर प्रभाव

गुणकारी प्रभाव—

आज भारत की औद्योगिक व्यवस्था अत्यन्त हीन दशा में है। दश में उद्योगों का वितरण बहुत अनुचित और बिना किसी सिद्धांत के अनुरूप हुआ है। जन-संख्या के वितरण से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल बड़े नगरों (विशेषतः समुद्र के निकट वाले) में ही उद्योगों के केन्द्र बन गये हैं। गांवों में उद्योग कहीं भी उन्नति पर नहीं है। विकेन्द्रीयकरण भी केवल अन्दर के बड़े शहरों में ही है। फलस्वरूप नगरों में गन्दगी और अधिक भीड़-भाड़ है। जीवनोपयोगी सामग्रियों के भाव बढ़ गये हैं, अतः यह बड़ा आवश्यक है कि उद्योगों का विकास एक विशेष योजना के अनुसार हो। औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम राज्य को ऐसे अधिकार प्रदान करता है, जिससे वह देश को सन्तुलित विकास की ओर ले जाय। लाइसेन्स प्रवा के कारण अब उद्योगपति अपनी मनमानी

नहीं कर सकेंगे और अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर औद्योगिक संस्था खोलना सम्भव न होगा। फलस्वरूप विकेन्द्रीयकरण के दोष दूर हो जायेंगे। केन्द्रीय सरकार को कुछ दशांशों में उद्योग की जाँच करन और प्रबन्ध ह्रास में लेने का अधिकार मिल जान से भी बड़ा हित होगा। इससे व्यापारीगण और उद्योगपति सदैव सतक रहेंगे। कुछ औद्योगिक संस्थाओं की केन्द्रीय सरकार द्वारा जाँच भी कराई गई है। विकास सभाओं की स्थापना भी औद्योगिक विकास में सहायक होगी और औद्योगिक शान्ति की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।

आलोचना—

(१) कुछ लोगों का आक्षेप है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी हस्तक्षेप से पूँजी की प्राप्ति में रुकावट पड़ेगी, जिसकी दशा को आज प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है। उद्योगों में पूँजी तो वैयक्तिक उपक्रमी ही लगावेंगे, लेकिन उद्योगों पर प्रारम्भ से अन्त तक केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहेगा। ऐसी दशा में बहुत छोटे उपक्रमी पूँजी लगाने को आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न यह है कि पूँजी आयेगी कहाँ? विदेशों में? किन्तु सरकार विदेशी विनिमय पर भी तो नियन्त्रण रखती है। पूँजीपति पूँजी पर लाभ अवश्य चाहेंगे, इसलिये उनका उसका विनियोग कहीं न कहीं करना ही होगा, अतः यह आक्षेप निराधार है।

(२) लोगों का यह भी कहना है कि सरकार ऐसे प्रतिबन्धात्मक अधिनियम बनाकर व्यक्तिगत उपक्रम को जड़ से उखाड़ना चाहती है। यह आक्षेप भी पूँजीवादी दृष्टिकोण का द्योतक है। आलोचनात्मक समाज के असन्तोष में ही भावी क्रान्ति के बीज होते हैं, जिसकी सन्तुष्टि करना सरकार का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होता है, किंचित पूँजीपतियों की सन्तुष्टि नहीं।

(३) कुछ लोगों के मतानुसार इस अधिनियम के परिणामस्वरूप सरकारी एवं वैयक्तिक उपक्रम में तनातनी और बढ़ जायेगी। आलोचकों ने यहाँ यह सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि सरकार उद्योगों पर नियन्त्रण कब करेगी? सरकार को व्यर्थ में नियन्त्रण करने का कोई शौक छोटे ही है। केन्द्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से ही ऐसा नियन्त्रण किया जायेगा और समिति में उद्योगपतियों, श्रमजीवियों तथा उपभोक्ता, सभी के प्रतिनिधि होंगे। फिर सरकार अपनी सनमानी कैसे कर सकती है?

(४) कुछ लोगों का यह भी आक्षेप है कि लाइसेंस लिए बिना नए उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों की विस्तार योजनाएँ कार्यान्वित नहीं की जा सकती हैं और सरकार ऐसी नई कम्पनियों की स्थापना के लिए लाइसेंस नहीं देगी। क्या यह सोचना सरकार के प्रति उद्योगपतियों के अविश्वास का परिचायक नहीं है? हमारी जनप्रिय सरकार ने सितम्बर सन् १९५२ से फरवरी सन् १९५३ तक २५ नये उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए लाइसेंस प्रदान किये हैं, जो सरकार की औद्योगिक विकास की ओर रुचि का परिचायक है।

(५) यह भी कहा जाता है कि क्योंकि विकास-समितियों का संगठन उद्योगों द्वारा न होते हुए सरकार द्वारा किया गया है, इसलिए इनसे इच्छित सुधार की आशा नहीं की जा सकती। साथ ही, उद्योगों के विकास के लिए प्रबन्धनों को स्वतन्त्रता चाहिए, जो विकास समितियों के हस्तक्षेप के कारण नहीं रहेगी। इन आलोचकों ने यह नहीं सोचा कि विकास समितियाँ केवल विशेष परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करेगी, जैसे—जब उत्पादन में भारी कमी हो जाय या वस्तु की किस्म में विशेष हास हो जाय और या हस्तक्षेप इसलिए होगा कि उन उद्योगों का सुदृढ़ आधार पर विकास हो, जो वाछनीय ही नहीं, अनिवार्य भी है। अनार्यिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने का अर्थ है अकुशल प्रबन्ध की घोषणा एवं उपभोक्ताओं का शोषण, जिसका समर्थन कोई भी विवेकी व्यक्ति नहीं करेगा।

(६) सन् १९५३ के सशोधन से तो अब सरकार बिना जाच-पड़ताल के किसी भी उद्योग को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इससे उद्योग को अपने सुधार अथवा स्पष्टीकरण का अवसर नहीं मिलता। यह आलोचना सचमुच महत्त्वपूर्ण है, अतः इस सम्बन्ध में पुनः सशोधन होना आवश्यक है, जिससे केवल उन्हीं उद्योगों को जो देश विरोधी नीति को अपनाये, किसी समय भी सरकार नियन्त्रण में ले सके, अन्यथा संभव है कि व्यक्तिगत उद्योगों को सदैव अपने अस्तित्व का खतरा बना रहे और उनकी भावी प्रगति रुक जाय।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम के विपक्ष में जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं उनमें (केवल अन्तिम आपत्ति को छोड़कर) कोई तथ्य भी नहीं है, क्योंकि किसी देश की सरकार अपनी आर्थिक प्रगति में रोड़े अटकाना नहीं चाहेगी, अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार सन्तुलित दृष्टि से इस अधिनियम की कार्यवाही करेगी, जिससे देश की औद्योगिक प्रगति सुदृढ़ आधार पर हो सके। इस सम्बन्ध में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि अभी हाल में राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में दो नवीन घटनाएँ हुई हैं—(१) स्टेट बैंक की स्थापना और (२) जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। स्टेट बैंक की स्थापना को सरकार द्वारा ग्राम्य क्षेत्रों में साक्षर सुविधायें बढ़ाने की दशा में एक सक्रिय और प्रभावशील कदम कहा जा सकता है। जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण २० जनवरी सन् १९५६ को हुआ। जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता द्वितीय पंच-वर्षीय योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के हेतु जनता की वचते अधिक गतिशील बनाने के लिए हुई।

STANDARD QUESTION

1. Briefly discuss the important provisions and working of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as amended up-to date

भारत में प्राशुलिक स्वतन्त्रता का विकास

(Evolution of fiscal autonomy in India)

प्रारम्भिक—

भारत में, अंग्रेजी राज्य के पूर्व, औद्योगिक आर्थिक एवं व्यापारिक सम्पन्नता का साम्राज्य था। भूतकाल में भारतवर्ष एक समृद्धिशाली देश था, जिसमें छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ दूर-दूर तक फैली हुई थी। विश्व के सभी देशों ने भारत का यह पृष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध थे। बैंकिंग संस्थाओं का विकास हो चुका था और व्यापारियों तथा कारीगरों के समूहों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता दी जाती थी।

जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत से व्यापार प्रारम्भ किया, तो प्रारम्भ में तो उसने भारतीय उद्योगों के उत्थान का प्रयत्न किया, क्योंकि कम्पनी जानती थी कि योरोपीय देशों में भारतीय निर्मित वस्तुओं की काफी माँग थी। परन्तु कुछ समय बाद उसने अपनी नीति बदल दी। अठारहवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् योरोप के प्राचीन आर्थिक विचारों, व्यापार-व्यवस्था तथा उत्पादन रीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। अनेक यांत्रिक आविष्कारों के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन करना संभव हो गया। औद्योगिक क्रान्ति का जन्म सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, जिससे पहले योरोपीय देश अधिक प्रभावित हुये। इस प्रकार मशीनें तो ग्रेट ब्रिटेन तथा योरोप के अन्य देशों में थी। फलतः भारत का आर्थिक विकास इस दृष्टि से किया जाने लगा कि वह इंग्लैंड के उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध कर और उसके तैयार माल के लिये एक सुरक्षित बाजार बना रहे। इस धानक नीति के कारण भारतीय उद्योगों का शनैः शनैः पतन होने लगा, क्योंकि एक ओर तो इंग्लैंड में भारतीय निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन चल रहा था और दूसरी ओर भारत में उनको राज्य का सरक्षण मिलना बन्द हो गया। स्वेज नहर के निर्माण, यातायात तथा सदेशवाहन के साधनों के विकास के कारण भारतीय उद्योगों को योरोप के यंत्र-निर्मित माल से कठिन प्रतियोगिता करनी पड़ी।

19वीं शताब्दी के मध्य से प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक भारत सरकार की प्राशुलिक नीति व्यापार में हस्तक्षेप न करने की थी, अर्थात् व्यापार और उद्योगों पर कोई प्रतिबन्धन नहीं था। यह नीति 1789 के अक्टूबर में 'अबाध व्यापार का युग' (Era of Laissez Faire) की थी। यह नीति इंग्लैंड की थी। प्रारम्भ में आवश्यकता

के आधार पर इने ग्रहण किया गया था, परन्तु धीरे-धीरे यह एक सर्व मान्य सिद्धान्त बन गई। उन दिनों भारत पग-पग पर ब्रिटिश नीति का अनुकरण करता था और यह ब्रिटिश नीति ऐसी थी जिसमें कि अंग्रेजों का ही स्वार्थ सिद्ध होता था। सन् १८१३ में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में श्री टीरने (Tierney) के निम्न भाषण से उस समय भारत के प्रति ब्रिटिश नीति का आभास मिलता है—“हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इंग्लैण्ड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाय और उसके बदले में एक भी भारतीय वस्तु न ली जाय।” इस प्रकार भारत में मुक्त व्यापार नीति का ही पूरी तरह अनुकरण किया गया, जो सन् १८६४ तक रही। इस अवधि में किसी प्रकार के आयात व निर्यात कर नहीं लगाये जाते थे। स्वतन्त्र व्यापार-नीति का इतनी सख्ती से पालन किया गया कि सन् १८५७ के विद्रोह के पश्चात् जब सरकार को आय प्राप्त करने के लिये निरक्राम्य करों के लगाने की आवश्यकता पड़ी, तो इन करों के उद्योग रक्षण प्रभाव को दूर करने के लिये देशी वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाये गये। इस प्रकार भारतीय उद्योगों के विनाश के क्रम को पूरा किया गया और भारत एक कृषि प्रधान देश ही रह गया। भारत से इंग्लैण्ड को कच्चा माल जाता था और वहाँ से निर्मित माल आयात किया जाता था। इस नीति को लार्ड डलहौजी की आनायात नीति से और भी बढ़ावा मिला, जिसमें विदेशी आयात-माल के रेल-यातायात-दर अधिक सस्ते थे, अतः इस अवधि में भारतीय उद्योग अधिक न पनप सके।

पी० दास गुप्ता ने अपनी पुस्तक ‘भारत में प्रभुत्व नीति’ में कहा है कि “उन दिनों भारत सरकार की कोई निश्चित प्रभुत्व नीति नहीं थी और टैरिफ का नियमन केवल सरकारी कोष की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से किया जाता था। देश की आवश्यकताओं, औद्योगिक एवं कृषि-विकास की समस्या तथा ऐसे ही अन्य आवश्यक बातों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था और ग्रेट ब्रिटेन में अनुमरण की जाने वाली मुक्त-व्यापार नीति का भारत में बिना इस बात का विचार किये पालन किया गया कि इससे भारतीय उद्योग-धन्धों को विदेशी माल की तुलना में दाशपातन की कार्य-वाहियों का शिकार होना पड़ेगा।” भारत सरकार की टैरिफ नीति के पीछे जो निर्देशक सिद्धान्त कार्य कर रहा था उसे तत्कालीन वित्त मंत्री (१८७८) के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—“आयात पर ऐसा कोई कर नहीं लगाना चाहिये जो कि देशी उद्योग को संरक्षण प्रदान करे और साथ ही ब्रिटेन में उत्पादित माल पर कोई भी कर, भारतीय उत्पादन पर उतना ही उत्पादन कर लगाये बिना, नहीं लगाना चाहिए।”

भारत में प्राशुलिक स्वतंत्रता का श्रोगणेश—

सन् १९१४—१८ के प्रथम महायुद्ध में सरकार को अपनी आयात-निर्यात नीति पर अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। दूसरे, उन दिनों

स्वदेशी आन्दोलन भी जोर पकड़ रहा था जिसमें ब्रिटिश नीति की बड़ा आलोचनाहार भी थी। तीसरे युद्ध काल में औद्योगिक दृष्टि से भारत के पछड़ा हानक कारण जो अनुभव प्राप्त हुए उनसे विश्लेषण होकर ही यह आवश्यक समझा गया कि औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तन किया जाय। प्रथम युद्ध में अंग्रेज सरकार ने यह अनुभव लिया कि जब तक उद्योगों की विकसित नहीं किया जायगा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सहायक हाने की अपेक्षा एक सतरो बना रहेंगा। अतएव युद्ध स्थिति से घबड़ा कर ब्रिटिश सरकार ने कुछ भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया। सन् १९१६ में एक औद्योगिक कमिशन (Industrial Commission) नियुक्त हुआ जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भविष्य में देश के औद्योगिक विकास में सरकार को सक्रिय भाग लेना चाहिये जिससे भारत मनुष्य एवं सामग्री की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके। कमिशन ने यह भी सिफारिश की थी कि औद्योगिक उत्तरदायित्व लेने के लिये सरकार अपने पास वैज्ञानिक एवं तांत्रिक विशेषज्ञों की पर्याप्त सहायता में नियुक्ति करा कर उद्योगों को सहायता दे सके। परन्तु दमर्ग से कमिशन की सिफारिशों को ताक में रख दिया गया।

अगस्त सन् १९१७ में मोटेथ्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुई जिसके अनुसार भारतीयों का स्वनिर्णय का अधिकार मिला। भारत की शिक्षण प्रणाली की दिशा में यह पहला कदम था। इस स्वनिर्णय के अधिकार के सम्बन्ध में जाइंट सिलेक्ट कमेटी का यह मत था कि भारत एवं इंग्लैण्ड की सरकार के सम्बन्धों को अथवा किसी बात में कितना खतरा नहीं है जितना कि इस विषय में कि भारत की प्रशुल्क नीति का संचालन ग्रेट ब्रिटेन के व्यापारिक हितों के लिये बड़ा हानक होता है और आज भी यही विश्वास है इसमें सन्देह नहीं। इस समस्या का समुचित हल अभी सम्भव है जब भारत सरकार को ब्रिटिश साम्राज्य का एक अविच्छिन्न भाग होने के नाते भारत की आवश्यकता का अनुसार प्राशुल्क व्यवस्था करने की स्वतन्त्रता दी जाय। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सन् १९२० में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्राशुल्क स्वतन्त्रता का प्रस्ताव (Fiscal Autonomy Convention) पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत सचिव (Secretary of S & C for India) को प्रशुल्क सम्बन्धी उन मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रहा जिन्हें भारत सरकार ने स्वयं अपनी विधान सभा की सम्मति से तय कर लिया हो।

किन्तु ऐसी स्वतन्त्रता से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि प्रायः सभी प्राशुल्क विषयों पर भारत सरकार पहले भारत सचिव से पूछ लेती थी और तब पश्चात् ही विधान सभा के सम्मुख रखती थी अतः भारत की प्रशुल्क सम्बन्धी नीति की पूर्ण जाँच करने तथा साम्राज्य प्राथमिकता (Imperial Preference) के प्रस्ताव पर विचार करके सिफारिश देने के लिये एक प्रशुल्क मंडल (Fiscal Commission) नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष श्री इब्राहिम रहीमतुल्ला थे। बतार्थ में

जनमत बड़े अंश तक औद्योगिक संरक्षण के पक्ष में था, इसलिये इस दिशा में कुछ न कुछ करना आवश्यक था ।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Briefly trace the development of tariff policy in India till 1921.
- 2 Briefly discuss the factors which led to Fiscal Autonomy Convention in 1921 Explain its salient features

अध्याय १६

विभेदात्मक संरक्षण की नीति

(Policy of Discriminating Protection)

प्रारम्भिक—

सन् १९२१ में सर इब्राहीम रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में एक प्रशुल्क आयोग नियुक्त किया गया । इस आयोग को भारत सरकार की प्रशुल्क नीति और 'इम्पीरियल प्रिफरेंस' के सिद्धान्त को लागू करने की संभावनाओं की जाँच करने का काम सौंपा गया । सन् १९२१ के प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट सन् १९२२ में प्रकाशित हुई और सन् १९२३ में भारत सरकार ने आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशों स्वीकार कर ली । सम्पूर्ण स्थिति का गहन अध्ययन करने के बाद रहीमतुल्ला आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि भारत का औद्योगिक विकास उसके विस्तार, उसकी जन-संख्या तथा उसके प्राकृतिक साधनों की तुलना में बहुत पीछे था । आयोग ने बताया कि यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है, परन्तु उत्पादन करने के लिये इसमें अनेक प्राकृतिक सुविधाएँ हैं । यहाँ कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, श्रम-शक्ति भी सस्ती है और उद्योगों का विकास करने के लिये पर्याप्त बिजली भी प्राप्त की जा सकती है । सूती कपड़े तथा जूट के दो बड़े उद्योगों ने अनुभव से यह ज्ञात हो गया कि भारत अपने प्राकृतिक

साधनों का पूरा पूरा लाभ उठा सकेने में समर्थ है। आयोग ने अनेक कारणों से सरभरण की नीति अपनाते के लिये सुझाव दिया।

कमीशन ने यह देखा कि गरक्षात्मक प्रशुल्क के पक्ष में साधारण विश्वास प्रचलित था। यह विश्वास भावना जय देशों के उदाहरण में प्रेरित हुई देश भक्ति में निहित थी। ग्रेट ब्रिटेन को प्रोत्साहित विश्व के सभी महान् औद्योगिक देश अपने उद्योगों को एक सरक्षित दीवार खड़ी करके सुरक्षित रखने में तथा उनकी सम्पत्ति इस सरभरण के कारण ही सम्भव हो सकी है। सन् १८७६ में जर्मनी ने निश्चित रूप से एक गरक्षण नीति अपनाई थी जिस पर वह आज तक कायम है और जिसके अंतर्गत उसने अपनी आइसयरजन की उन्नति (युद्ध प्रय) कर दिखाई। सन् १८८१ में फ्रांस ने मुक्त व्यापार की नीति से जिसे कभी भी जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, मुँह मोड़ लिया। सन् १८९६ में जापान ने भी सरभरणात्मक दीवार खड़ी कर ली और सन् १९११ में उसे और भी मजबूत कर लिया। अमेरिका भी जो विश्व का सबसे उच्च कोटि का औद्योगिक राष्ट्र है अपने युद्ध के समय में ही सरक्षण नीति अपनाने लगे हैं और उसे अधिकाधिक तीव्र करता जा रहा है।

प्रशुल्क आयोग का विचार था कि औद्योगिक विकास द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था की अस्थिर प्रवृत्ति जो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उत्पन्न हो गई थी, दूर हो जायगी। सरभरण की नीति से औद्योगीकरण प्रोत्साहित होगा और औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय राजस्व आदि में भी वृद्धि होगी। परन्तु आयोग इस निगाह पर पहुँचा कि सभी उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने की नीति भारत के लिये उपयुक्त नहीं। सरक्षण प्रदान करने में पूर्व प्रत्येक उद्योग विशेष की सावधानी से जाँच करना आवश्यक था रिपोर्ट में लिखा है कि साधारण उपभोक्ताओं और विशेष रूप में जन साधारण के हित में कृषि के हित में निरन्तर प्रगति और अनुकूल व्यापाराधिकार के हित में सरक्षण की नीति विभेदात्मक अथवा विवेचनात्मक होनी चाहिये जिसमें कि समाज पर कम से कम भार पड़े और औद्योगिक तथा वाणिज्य दशांशों में अकस्मात् परिवर्तन न होने पाये। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग को इस बात का विश्वास हो गया था कि उद्योग सरक्षण में निश्चय ही समाज पर भार पड़ेगा जिसको आयोग ने न्यूनतम करने का प्रयत्न किया। आर्थिक दृष्टि से उद्योग्य उद्योगों के विनाश को प्रोत्साहित करने में पक्ष में आयोग नहीं था। अतएव आयोग ने सरक्षण के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये जो विभेदात्मक सरक्षण के सिद्धान्त (Principles of discriminating protection) के नाम से विख्यात हैं—

विभेदात्मक संरक्षण की नीति के सिद्धान्त—

उद्योगों में संरक्षण सम्बन्धी श्रेष्ठ करने के लिये आयोग न निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये। उसमें तीन प्रमुख शर्तें रखी, जो त्रिमुखीगुरु से विख्यात हैं।

त्रिमुखी गुरु (Triple Formula)—

(१) संरक्षण माँगने वाले उद्योग ऐसे होने चाहिये जिनको आवश्यक प्राकृतिक सुविधायें उपलब्ध हों, जैसे कच्चे माल की भारी पूर्ति, रस्ती शक्ति, श्रम की पर्याप्त पूर्ति, देश में विस्तृत बाजार आदि। अलग अलग उद्योगों में इन लाभों का अलग-अलग तुलनात्मक महत्त्व होगा। परन्तु इन सबका माप करके इनके तुलनात्मक महत्त्व का पता लगाना चाहिये। संसार के सभी सफल उद्योगों को कुछ तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनके कारण उनको सफलता मिली है। कोई भी ऐसा उद्योग, जिसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं है, इन उद्योगों में सफल प्रतियोगिता नहीं कर सकता। इसीलिये भारतीय उद्योगों को उपलब्ध प्राकृतिक लाभों की सावधानी से विवेचना करनी चाहिये, जिसमें कि यह निराय किया जा सके कि किसी ऐसे उद्योग को संरक्षण न दिया जाय, जो समाज पर एक स्थायी भार बन जाय।

(२) उद्योग ऐसा होना चाहिये कि जो संरक्षण के अभाव में या तो विवक्षित ही नहीं हो सके अथवा फिर उसकी उन्नति इसनी शीघ्र न होगी कि वह देश के हित की रक्षा कर सके। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य या तो उद्योगों का विकास करना होता है, जो इसके बिना विवक्षित न हो सके अथवा उनका वेगपूर्वक समुन्नत करना होता है।

(३) उद्योग ऐसा होना चाहिये कि अन्त में वह विश्वव्यापी प्रतियोगिता में, बिना संरक्षण, खड़ा हो सके। इस शर्त का पूरा होने का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित प्रथम शर्त में उल्लेखित प्राकृतिक लाभों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिये।

अन्य सिफारिशें—

इसके अतिरिक्त, कमीशन ने कम महत्त्व की कुछ अन्य शर्तें भी लगाई थी, जैसे—

(अ) जो उद्योग बड़े पैमाने पर अधिवृत्ति के साथ कम व्यय पर उत्पादन कर सके उसे संरक्षण के अधिक उपयुक्त समझा जायगा।

(ब) जिस उद्योग में राष्ट्रीय बाजार देश की समस्त आवश्यकतायें पूरी होने की आशा है, उसे संरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

(स) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक उद्योगों तथा आधारभूत उद्योगों को भी संरक्षण पदान किया जाय, चाहे वे उपरोक्त शर्तें भी पूरी न करते हों।

(द) वस्तु राशिपातन किये हुये (अर्थात् बाजार पर एकाधिकार करने के लिये उत्पादन व्यय से कम मूल्य पर बेचे हुये) माल के मुकाबिले में संरक्षण के विशेष उपाय प्रयुक्त हों अथवा यदि माल गवमूर्त्यत चलन वान क्षेत्र से आये और इस

प्रकार भारतीय माल पर अनुचित दबाव डालने की स्थिति में हो तो भी मरक्षण प्रदान किया जाय।

(य) इस प्रकार के कदम राजकीय सहायता प्राप्त विदेशी माल के विरुद्ध भी उठाये जाने चाहिये।

उक्त प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की कि एक तदर्थ प्रशुल्क मंडल (Ad hoc Tariff Board) की रचना की जाय। यह मंडल प्रार्थी उद्योग की मरक्षण सम्बन्धी उद्योग की जाँच करेगा और यह भी देखेगा कि वह उद्योग निम्नीगुर की शर्तों को कहाँ तक पूरा करता है। आयोग के सदस्यों का बहुमत यह चाहेगा या कि भारत का औद्योगिक विकास श्रृंखला हिलो की स्थिति पहुँचा कर न हो। उसने स्पष्ट कहा था कि, "हम भूले नहीं हैं कि यू० के० साम्राज्य का हृदय है इसकी शक्ति पर ही साम्राज्य की एकता व शक्ति आश्रित है जब तक यू० के० अपना निर्यात ध्यातार बनाये न रखे, साम्राज्य का हृदय वमजोर पड़ जायगा और यह ऐसी असामयिक अवस्था होगी कि इसकी आर से साम्राज्य का कोई भी गज्ज उदासीन नहीं रह सकता।" यही कारण है कि रहीमनुल्ला प्रशुल्क आयोग ने भारतीय उद्योगों के सरक्षण के लिये जो सिफारिशें की थी वे बहुत संकुचित दृष्टि की तथा उनमें बहुत सी शर्तें लगा दी।

सरक्षण देने के सम्बन्ध में जो शर्तें लगाई गई थी वे भी कठिनी थी। उदाहरण के लिये, यदि किसी प्रार्थी उद्योग के पास समस्त आवश्यक प्राकृतिक साधन हैं—जैसे, मस्ला थम, कच्चा माल, शक्ति बाजार आदि (गुर न० १), तो दूसरी शर्त बेकार हो जाती है, क्योंकि ऐसी दशा में वह उद्योग बिना सरक्षण के भी खड़ा रह सकता है। तीसरी शर्त अधिकारियों के व्यक्तिगत मत पर आधारित है। इस बात का निर्णय तो प्रशुल्क मंडल के अधिकारी अपने मत के अनुसार करेंगे कि कोई उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेगा या नहीं। इसके विरुद्ध कोई शिशु-उद्योग सरक्षण माँगने के लिये कोई आकड़ अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस प्रकार आयोग की रिपोर्ट में बहुत सी बातें ऐसी थीं जो कि प्रशुल्क मंडल के सदस्यों की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर करती थी। यदि वे चाहते, तो किसी उद्योग के प्रति उदार दृष्टिकोण अपना सकते थे और यदि वे किसी को सरक्षण नहीं देना चाहते थे, तो कठोर दृष्टि ले सकते थे।

साम्राज्य प्राथमिकता के सम्बन्ध में कमिशन ने 'शर्तयुक्त साम्राज्य प्राथमिकता' (Conditional Imperial Preference) की सिफारिश की। इस नीति के अनुसार ब्रिटिश का तो प्रशुल्क करों के सम्बन्ध में कुछ छूट हो जाय, परन्तु ऐसी छूट की आज्ञा भारत ब्रिटेन से न करे। जहाँ तक साम्राज्य के अन्य देशों का सम्बन्ध था, यह सुविधायी पारस्परिक आधार पर अर्थात् यदि भारत को अन्य देशों से सुविधायी मिले, तो भारत भी उनको सुविधायी दे, अन्यथा नहीं।

व्यवहार में विभेदपूर्ण संरक्षण—

रहीमतुल्ला कमीशन की सिफारिशों के अनुसार फरवरी सन् १९२३ से भारत सरकार ने संरक्षण की नीति अपनाई। जुलाई सन् १९२३ में भारत में प्रथम प्रशुल्क बोर्ड का स्थापना हुआ जिसने अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों को संरक्षण दिया। जिन उद्योगों को संरक्षण मिला उनका संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है—

(१) लोहा एवं स्पात उद्योग—

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारतीय लोहा एवं स्पात उद्योग को विदेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अनेक विघ्न होकर उसने संरक्षण की मांग की। सन् १९२४ में इसका मामला भारतीय प्रशुल्क मंडल के सामने रखा गया। मंडल जांच के उपरान्त प्रशुल्क मंडल ने यह निर्णय किया कि आधारभूत उद्योग होने के नाते इसे संरक्षण दिया जाय। फिलहाल स्पात के आयात मूल्य और भारत में उसके बिक्री मूल्य में अधिक अन्तर का दूर करने के उद्देश्य से मंडल में तीन वर्ष के लिये ३० रु० से ४५ रु० प्रति टन तक की दर में शुल्क लगाने की सिफारिश की। समय-समय पर प्रशुल्क मंडल द्वारा उद्योग को जांच होना रही। सन् १९३५ में ७ वर्षों के लिये और संरक्षण जारी रखा गया जो सन् १९४१ तक चालू रहा है। सन् १९४१ में टाटा आइरन एण्ड स्टील कंपनी ने यह कहा कि वह सभी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हो गई है और इन सब परिस्थितियों में संरक्षण का हटा देना भी शामिल है। सन् १९४७ में प्रशुल्क मंडल द्वारा विविध उद्योगों का जो जांच का गई, उसमें लोहा एवं स्पात उद्योगों ने संरक्षण का मांग नहीं की। अतः इस उद्योग पर भी संरक्षण हटा लिया गया। इस उद्योग को २३ वर्षों तक संरक्षण मिला और आज इसकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि अब यह अपने पैरों पर खड़ा रहने में समर्थ हो गया है।

यद्यपि राज्याय औपचारिकताओं के कारण संरक्षण बहुत शकस्त कर दिया गया किन्तु फिर भी भारत में लोहा एवं स्पात उद्योग ने बड़ी तेजी के साथ वृद्धि की है। यह उद्योग संरक्षण देने वाली नीति का मन्त्रालय पुनः निश्चिंत हुआ है। आज भी भारत में लोहा एवं स्पात उद्योग सर्वाधिक उत्पादन कर लेता है और राजकीय आय का प्रमुख साधन है। उपभोक्ताओं को भी कोई अतिरिक्त भार सहन नहीं करना पड़ना क्योंकि उत्पादन व्यय निरन्तर गिरता गया है और टिस्को (Tata Iron & Steel Company) के कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति भी सतोषजनक है। संरक्षण ने हमारे लोहा एवं स्पात उद्योग का इतना बल सरकार ने स्वीकारा कि यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हुआ है या विदेशी प्रतिस्पर्धियों ४५ रु० प्रति टन साथ सामना करने में समर्थ है। एक सहस्रक उद्योग (1000 वर्ष) सन् १९३६ में (1936) भी इसके चारों ओर स्थापित हो गया है। संरक्षण में तत्कीर्ण लुब्धकी पर शुल्क को संरक्षण प्रदान किया गया उससे मन्त्रालय राष्ट्र लाभान्वित सन् १९४७ में जब पुनः

(२) सूती वस्त्र उद्योग—

प्रथम महासमर के युग में सूती वस्त्र मिल उद्योग की स्थिति बड़ी अच्छी थी तथा उस समय इसमें बहुत लाभ कमाया। परन्तु सन् १९२० के लगभग निम्न कारणों से यह उद्योग कठिनाइयों में पड़ गया जैसे—पूँजीकरण (verobment) अथवा कर्मचारी की दर सूत्र में चान के साथ व्यापक समान होना इत्यादि। अतः सन् १९२६ में इसका मामला भारतीय प्रगल्भ मंडल के सामने रखा गया, जिसने निम्न आधारों पर संरक्षण की सिफारिश की—ब्रिटिश सूता कपड़ के आयात पर ५% आयात कर लगाया गया और अन्य देशों के कपड़ पर ११%। इसके बाद जब जापान ने राशिपानन (dumping) द्वारा भारतीय मंडियों में अपना कपड़ा भर दिया तो गैर ब्रिटिश सूती कपड़ पर ५०% आयात शुल्क लगा दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश माल पर कम आयात-कर होने के कारण ब्रिटिश हिता को बहुत लाभ पहुँचा।

यद्यपि लौह एवं स्पात उद्योग की अपेक्षा सूती वस्त्र मिल उद्योग को काफी दूर से संरक्षण मिला और वह भी मुक्त जापानी वस्तु राशिपानन के विरुद्ध शासन के रूप में परन्तु फिर भी संरक्षण से इसे पर्याप्त लाभ हुआ। निम्नलिखित आकड़ों में सूती वस्त्र मिल उद्योग को प्राप्त लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है—

बड़ी हुई सूती डोरी और सूत (१० लाख पौंड में)			सूती कपड़ों के टुकड़े (गजों में)		
वर्ष	देश में तैयार	आयात	वर्ष	देश में तैयार	आयात
१९२६-२७	८०७	४६	१९२६-२७	२२५८	१७८८
१९३८-३९	१,३०३	३६	१९३८-३९	४२६९	६४७

भारत में प्रायः ५०,००० लाख गज सूता कप की उपज होती है। यह सचमुच सौभाग्य का विषय है कि संरक्षण के वरदान स्वरूप इस उद्योग में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। यही नहीं अब हम विदेश का भा निर्यात करने की स्थिति में हो गये हैं।

मिकता' (Conditions)

नीति के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन भारत का एक महत्वपूर्ण सर्वांगीण उद्योग रहा है परन्तु परन्तु ऐसी छूट की आशा के बाद इसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। विशेषी सफलता का सम्बन्ध था यह सुविधाकार कर लिया था। सन् १९३०-३२ में लगभग ५३ लाख देशों में सुविधायें मिलीं, तो भारत चीनी उद्योग का संरक्षण देने के लिये इसका मामला

प्रशुल्क मण्डल के सामने आया। प्रशुल्क मण्डल को यह विश्वास हो गया कि यह उद्योग त्रिमुखी गुर की सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः इसे ७।) ६० प्रति हडरवेट की दर से संरक्षण प्रदान किया गया। जब में चीनी उद्योग को संरक्षण दिया गया, तब में उत्पादन काफी बढ़ा एवं देशीय मावश्यकताओं की सन्तुष्टि के बाद कुछ चीनी निर्यात के लिये भी बचने लगी। अन्तिम-उत्पादन को रोजन के लिये सरकार ने गृह-उत्पादन पर कर लगा दिया और संरक्षण-शुल्क भी उतना ही बढ़ा दिया। इस तरह सन् १९३४ में संरक्षण-शुल्क ७।।) हडरवेट और उत्पादन-कर १।-) था, जिससे कुल आयात-शुल्क ६% हो गया। सन् १९३७ में संरक्षण शुल्क घटा कर ७।।) प्रति हडरवेट कर दिया, परन्तु साथ में २) का एक राजस्व कर भी लगा दिया गया। यह ६।।) का कुल आयात कर सन् १९३६ तक चालू रहा। सन् १९३६ में संरक्षण शुल्क ६।।) रह गया और राजस्व कर सहित कुल आयात कर ८।।) प्रति हडरवेट रहा। सन् १९४६ में इसे पुनः जारी रखा गया और मार्च सन् १९५० तक रहा। अब उद्योग बिना सहायता के अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक हो गया है, ऐसा अनुभव करते हुए सरकार ने सन् १९५० में संरक्षण शुल्क हटा लिया।

इन प्रकार स्पष्ट है कि संरक्षण के अन्तर्गत चीनी उद्योग ने बड़ी उन्नति कर ली है। मन्दी के जमाने में भी केवल चीनी का उद्योग ही समस्त भारतीय उद्योगों में उन्नतिशील उद्योग था। सन् १९३२-३६ की अवधि के बीच चीनी के कारखानों की संख्या ३२ से बढ़कर १३६ हो गयी और इसमें चीनी का आयात भी ५.३ लाख टन से घटकर केवल ३२,००० टन ही रह गया था।

(४) कागज और लुग्दी उद्योग -

अन्य उद्योगों की भाँति प्रथम प्रहायुद्ध के उपरान्त कागज व लुग्दी उद्योग को कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अतः सन् १९३४ में इस उद्योग ने भी संरक्षण की माँग की, ऐसा अनुभव किया गया कि सवाई घास में बने हुए कागज व लुग्दी का उत्पादन अत्यन्त खर्चीला होता है परन्तु बाँस की लुग्दी अधिक सस्ती होती है और पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध है। उससे बने हुए कागज का भविष्य भी उज्ज्वल है। अतः लिखन और छपाई के कागज को १ आ० प्रति पौंड की दर से संरक्षण दिया गया। पैकिंग पपर को किसी प्रकार की प्राबुद्धिक सहायता नहीं दी गई, क्योंकि यह सिद्ध न हो सका कि इसका उत्पादन के लिए भारत में सभी आर्थिक सुविधायें उपलब्ध हैं। इसी आधार पर अख्तियारी कागज को भी संरक्षण नहीं दिया गया। हाँ, प्रशुल्क मण्डल ने यह सिफारिश अवश्य की थी कि प्रयोगात्मक और शोध कार्य के लिए आर्थिक सहायता दी जाय। वित्तीय सहायता की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। सन् १९३५ में आयात की गई लकड़ी की लुग्दी पर ४५ ६० प्रति टन का शुल्क लगा दिया गया, जिससे कि बाँस की लुग्दी का उपयोग बढ़े। सन् १९३६ में अगले तीन वर्षों के लिए संरक्षण जारी रखा गया, परन्तु आयात की गई लुग्दी पर शुल्क घटा कर २५ ६० भूतानुसार कर दिया गया। इसके बाद सन् १९४७ में जब पुनः

मामला प्रशुल्क मण्डल के सम्मुख आया, तो उसने निर्णय किया कि इस उद्योग में सरक्षण हटा लिया जाय।

कागज उद्योग ने सरक्षण की अवधि में काफी उन्नति की। सभी प्रकार के कागज का उत्पादन, जो सन् १९२६ में केवल ०० ००० टन था सन् १९५६ में बढ़ कर १,६२,००० टन हो गया। आज यह उद्योग हमारी कागज सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(५) दियासलाई उद्योग—

सन् १९२० तक भारत अपनी दियासलाई। सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण विदेशों पर निर्भर था जबकि डेढ़ रुपया प्रति श्रोत का राजस्व शुल्क जो मूलानुसार १००% से अधिक था आयात की गई दियासलाई पर लग हुआ था। इस शुल्क से दियासलाई निर्माण करने के कुछ छोटे उद्योग धन्ये शुरू किये गये। भारत की मण्डिया पर स्वीडन की दियासलाई कम्पनी का एकाधिकार छाया हुआ था। उसने सन् १९२४ और १९२६ के बीच में वेस्टन इण्डिया मैच कम्पनी के नाम से भारत में दियासलाई के कारखाने खोले। सन् १९२६ में इस कम्पनी ने भारतीय प्रशुल्क मण्डल से सरक्षण की मांग की और कहा कि कि डेढ़ रुपये के राजस्व शुल्क को सरक्षण शुल्क में बदल दिया जाय। सरकार ने यह स्वीकार कर लिया। इस सरक्षण के परिणामस्वरूप स्वीडन के टस्ट को भारतीय मण्डली पर एकाधिकार प्राप्त करने में बहुत सुविधा हुई। स्वीडिश ट्रस्ट विश्व की ७०% भाग पूरा करता था। यह जमनी के दियासलाई उद्योग को भी एक आर्थिक कम्पनी द्वारा नियन्त्रित करता था। भारतीय प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने के लिये इसने अपने व्यापारियों को रिबेट, रिफण्ड इनाम आदि का सुविधायी दी। फलन दियासलाई से सम्बन्धित छोटे मोटे उद्योग धन्ये समाप्त हो गये। अथवा वे ट्रस्ट के नियन्त्रण में आ गये। दियासलाई उद्योग के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सरक्षण द्वारा एक विदेशी उद्योग प्रतापित हुआ तथा फला फूला।

(६) नमक उद्योग—

सन् १९३० तक भारत के पूर्वी राज्या में नमक नहीं बनता था क्योंकि सरकार का कहना था कि इन प्रांतों में नमक बन ही नहीं सकता। सन् १९०६ में नमक उद्योग का मामला भी प्रशुल्क मण्डल के सामने रखा गया। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि नमक उद्योग का विकास देश की समस्त मांग को पूरा करने के लिये किया जा सकता है। अतः भारत सरकार ने सन् १९३१ में नमक के आयात पर ४६ आ० प्रति टन की दर से आयात शुल्क लगा दिया। नमक उद्योग को इस प्रकार सुरक्षा देने से इसकी शीघ्र उन्नति हुई। सन् १९३२ में भारत और अदन में सीपण दर-युद्ध (rate war) शुरू हो गई। सन् १९३५ में भारत में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा समाप्त करने और नमक के मूल्यों में स्थिरता रखने

के लिये एक 'नमक विक्री मंडल' (salt marketing board) स्थापित किया गया। तब से यह उद्योग निरन्तर प्रगति कर रहा है। अब भारतीय नमक उद्योग को सरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(७) अन्य उद्योग—

उपयुक्त उद्योगों के अलावा प्रशुल्क मंडल ने कुछ अन्य उद्योगों को भी सरक्षण प्रदान किया, जो आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते थे। ऐसे उद्योगों में *य* नाम उल्लेखनीय है—प्लाईवुड उद्योग, मैंगनेशियम क्लोराइड उद्योग, चाय की पेटियाँ और सोने के तार के उद्योग।

सरक्षण से वंचित उद्योग—

सरक्षण से वंचित उद्योगों में से ये नाम उल्लेखनीय हैं— (१) भारी रासायनिक उद्योग, (२) तेल उद्योग, (३) कोयला उद्योग, (४) सीमेन्ट उद्योग और (५) काँच उद्योग।

(१) भारी रासायनिक उद्योग—

भारी रासायनिक उद्योग (heavy chemical industries) को केवल १८ महीने (अक्टूबर १९३१ से मार्च १९३३) तक सरक्षण प्रदान किया गया था और इसके बाद वह बिना किसी वैध कारण के हटा लिया गया। भारी रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—(i) अम्ल सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक तथा उन पर आधारित कम्पाउन्ड्स और (ii) क्षार—जैसे सोडा एश, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फाइड, जिंक क्लोराइड इत्यादि। इनमें से प्रथम प्रकार के रासायनिक पदार्थ तो भारत में बनते थे, परन्तु द्वितीय श्रेणी के पदार्थ भारत में नहीं बनते थे। प्रथम श्रेणी के रासायनिक पदार्थों का उत्पादन भी बहुत छोटी मात्रा में होता था और उनका उत्पादन कम्य भी बहुत अधिक था। यही नहीं, उद्योग को कड़ी विदेशी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ा, जिससे उद्योग कठिनाई में पड़ गया था। जब इस उद्योग का मामला प्रशुल्क मंडल के सामने आया, तो अध्ययन के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि भारत में भारी रासायनिक पदार्थों की घोर आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कागज, काँच, कपड़ा, चीनी मिट्टी, साबुन, रंग, यार्निश, कृत्रिम रेशम आदि अनेक उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है। भारी रासायनिक उद्योग केवल एक आधारभूत उद्योग ही नहीं है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी उसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड व सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग भयंकर विस्फोटक बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक खाद, जैसे सुपर फास्फेट्स तथा अमानिया सल्फेट का निर्माण रासायनिक उत्पादनों पर निर्भर करता है।

प्रशुल्क मंडल के निम्न शब्द उल्लेखनीय हैं—“यह बात नीति विरुद्ध है कि जिस देश में ७०% निवासी कृषक हों, उन्हें कृषि में निधे इतनी आवश्यक वस्तु,

जैसे कृत्रिम खाद के लिये, विदेशी आयात पर आश्रित रहना पड़े।' अतः प्रशुल्क मंडल ने यह सिफारिश की कि—

(अ) वर्तमान राजस्व शुल्क का संरक्षण शुल्क में बदल दिया जाय।

(ब) १८ रु० प्रति टन की सहायता रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग किये जाने वाले सुपर फास्फेटो पर दी जाय।

(स) रेल-भाड़े में कमी की जाय।

किन्तु फिर भी भारत सरकार ने संरक्षण प्रदान नहीं किया और यह दलील दी कि गंधक जैसे आधारभूत पदार्थ की अल्पव्ययता के कारण उद्योग को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर, भारत सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढग से विशेष दबाव डाला गया, जिसके परिणामस्वरूप १८ महीने के लिये उद्योग को संरक्षण मिला। यह संरक्षण भी बाद में यह कह कर हटा लिया गया कि "उद्योग अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है और संयोग (combine) में सम्मिलित होना असम्भव पाया गया है।"

(२) तेल उद्योग—

सन् १९२८ में जबकि बर्मा भारतवर्ष का एक अंग था बर्मा शैल ग्रुप और स्टैंडर्ड ग्रायल कम्पनियाँ हमारे देश में दो प्रधान कम्पनियाँ थीं। अटक ग्रायल कम्पनी भी बर्मा ग्रुप में ही सम्मिलित थी। स्टैंडर्ड ग्रायल कम्पनी बहुत नीची दर पर तेल बेचती थी अतः बर्मा शैल ग्रुप और स्टैंडर्ड ग्रायल कम्पनियों में दर-युद्ध (rate-war) था। प्रशुल्क मंडल को यह भी पता लगा कि एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनी ने बर्मा शैल ग्रुप को यह आश्वासन दिया था कि दर कम करने के परिणामस्वरूप यदि उसको कुछ क्षति पहुँचेगी तो वह उसे पूरा करेगी। अतः, स्पष्ट है कि बर्मा शैल ग्रुप का मुख्य उद्देश्य स्टैंडर्ड ग्रायल कम्पनी को नीचा दिलाना ही था। इसी उद्देश्य से उसने दर-युद्ध शुरू किया था जिससे कि वह स्टैंडर्ड ग्रायल कम्पनी को समझौता करने के लिये विवश करा दे। इस प्रकार अपने दर-युद्ध को वित्तीय सहायता देने के लिए उसने संरक्षण की मांग की थी और स्टैंडर्ड ग्रायल कम्पनी से लड़ाई का भार वह मिट्टी के तेल के भारतीय उपभोक्ताओं पर फेंकना चाहती थी। यह दर-युद्ध भारतीय उपभोक्ताओं के लिये किसी भी दृष्टि से लाभदायक नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि प्रशुल्क मंडल ने भारत सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण देना स्वीकार नहीं किया।

(३) कोयला उद्योग—

सन् १९२६ में कोयला उद्योग ने अपनी कठिन परिस्थितियों को प्रशुल्क मंडल के सामने रखते हुए उससे संरक्षण की मांग की। रेलों का भाड़ा बहुत अधिक था और रेलवे वैनो की बहुत कमी थी। अथवा सहायता प्राप्त दक्षिणी अफ्रीका का कोयला बम्बई तथा कराची की मड़िया में भारतीय कोयले से अधिक प्रतियोगिता

कर रहा था। इस प्रकार भारतीय कोयला उद्योग अत्यन्त सकट की परिस्थिति में था। प्रशुल्क मंडल ने सरक्षण की माँग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि वास्तव में इन उद्योग को सरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। उद्योग का जिस सकट का सामना करना पड़ रहा है उसका कारण इसका तीव्र विकास है। प्रशुल्क मंडल के कुछ सदस्या ने दक्षिणी अफ्रीकी कायन पर १५ स० का शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, परन्तु अधिकांश सदस्या ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्या कि उनकी सम्मति में ऐसा कदम उठाने से दूसरी ओर से प्रतिकार (re action) होने की संभावना थी। भारत सरकार को बहुमत की राय पसन्द आयी और उसने कोयला उद्योग को सरक्षण देने में अस्वीकार कर दिया।

(४) सीमेंट उद्योग—

प्रथम महायुद्ध के युग में सीमेंट उद्योग ने बड़ी तेजी में प्रगति की क्योंकि युद्ध काल ही इसके लिये एक प्रकार से सरक्षण था। परन्तु प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के कुछ दिन बाद सीमेंट उद्योग को सकट का सामना करना पड़ा। सन् १९२४ में विषम ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा के कारण यह उद्योग समापन की स्थिति में पहुँच गया था। भारतीय उपभोक्ताओं को अग्रजों माल के प्रति पक्षपात था यद्यपि दक्षिणी सीमेंट की किस्म विदेशी सीमेंट की अपेक्षा कुछ दुरी न थी। इसके अतिरिक्त सीमेंट को इधर उधर ले जान के लिये रेल-भाड़ा भी बहुत अधिक देना पड़ता था। जब सीमेंट उद्योग का मामला प्रशुल्क मंडल के सामने आया, तो गहन अध्ययन के उपरान्त उसने निर्णय किया कि यद्यपि सीमेंट के उत्पादन के लिए भारतवर्ष में सभी प्राकृतिक सुविधाय उपलब्ध है, परन्तु पारस्परिक संघर्ष के कारण इस उद्योग को सरक्षण देने से विशेष लाभ न होगा। उसने बड़ सकोच के साथ समुद्र तट को भेज जाने वाले सीमेंट पर न्यायन सहायता की सिफारिश की और मूलानुसार शुल्क के स्थान पर आपान क्रिय गय सीमेंट पर एक विशेष शुल्क लगाने को कहा। भारत सरकार ने इन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और किसी प्रकार का सरक्षण देने में इंकार कर दिया।

इस सम्बन्ध में यह निश्चय अनावश्यक न होगा कि सन् १९२४ में सीमेंट उद्योग का सरक्षण देना उतना ही आवश्यक था जितना कि वस्त्र मिल उद्योग अथवा लौह एवं स्पात उद्योग के लिये, क्योंकि यह उद्योग त्रिमुखी गुरु की प्रायः सभी शर्तें पूरी करता था। सरक्षण न देने का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय पश्चात् तीन कम्पनियाँ दिवालिया हो गईं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि यह उद्योग सन् १९२५ में इण्डियन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसियेशन के नाम से और सन् १९३५ में एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज के नाम से आगे को संयुक्त (combine) न करता, तो संभवतः इसका अस्तित्व ही न रहता।

(५) काच उद्योग—

काच उद्योग का मामला प्रशुल्क मंडल के सम्मुख सन् १९३१ में आया।

अध्ययन के उपरान्त मंडल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस उद्योग के लिये आवश्यक सभी कच्चा मान (जैसे सिलिका दानू, बारीकम, चूना, पत्थर और कोयला) पचुर मात्रा में उपलब्ध है। केवल सोडा ऐश की कमी है अतः टैरिफ बोर्ड ने सरक्षण की सिफारिश की, क्योंकि उसकी दृष्टि में भारत में सोडा ऐश के उत्पादन की काफी संभावनाएँ थी। परन्तु दुर्भाग्य से उम समय की सरकार ने इस आधार पर सरक्षण की सिफारिश ठुकरा दी कि सोडा ऐश विदेशों से आयात करना पड़ता है। सच बात तो यह है कि सोडा ऐश का आयात इंग्लैण्ड में किया जाता था, अतः यदि भारतीय कच्चे उद्योग को सरक्षण प्रदान किया जाता तब भारत में ही सोडा ऐश के उत्पादन करने का प्रयत्न किया जाता, तो संभवतः ब्रिटिश हित कुप्रभावित होते। अतः अग्रजों रासायनिक उद्योग की रक्षा करने के लिये भारतीय कच्चे उद्योग को सरक्षण नहीं दिया गया।

अन्त में, यह लिखना अनावश्यक न होगा कि यद्यपि भारत के अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों को प्रमुख मंडल ने सरक्षण नहीं दिया और उसका ऐसा करना अनुचित भी था, परन्तु जिन उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया उनकी बहुत लाभ पहुँचा। उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई, विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने वे टिक सके तथा सरक्षण के सहारे उन्होंने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की। सरक्षण के द्वारा जिन उद्योगों को लाभ हुआ उसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(१) उत्पादन में वृद्धि—अरक्षित उद्योगों ने सन् १९२३ से उत्पादन की दृष्टि से जो प्रगति की उसका अनुमान निम्नलिखित आकड़ों से लगाया जा सकता है।

उत्पादन में वृद्धि

उद्योग	१९२२	१९२६	१९२९	१९५४
स्टील इंगोट्स (००० टन)	३१	१०४२	१,५५५	१,६८५
कॉटन पीसमाल (लाख गज)	१७,१४०	४१,१६०	४५,६४०	४६,६८०
दियासलाई (लाख ग्रास)	१६०	२२०	३००	२७०
कागज और गत्ता (००० टन)	२४	६७	१३७	१५५
ईल चीनी (००० टन)	२४	६३१	१,४८३	१,००८

(२) मदी का दृढतापूर्वक सामना—जिन उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया वे सन् १९२६-३० की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी का दृढतापूर्वक सामना कर सके और उनके पैर डगमगाय नहीं तथा सन् १९३६ तक सफलतापूर्वक जमे रहे। सन् १९३६ के बाद तो युद्ध रूपी सरक्षण प्रारम्भ हो गया, जिसमें अरक्षित उद्योग भी पनपने लगे।

(३) नये उद्योगों का जन्म—सरक्षण ने अप्रत्यक्ष रूप से भी देश के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में अनेक नये उद्योग-धन्धों ने जन्म लिया, जैसे रसायन उद्योग, कीसो व तार का उद्योग, इत्यादि।

(४) रोजगार में वृद्धि—नये उद्योगों की स्थापना तथा पुराने उद्योगों के विस्तार के फलस्वरूप रोजगार के साधनों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ, जबकि सन् १९३१ में केवल १४ लाख व्यक्ति कारखानों में नौकर थे सन् १९३९ में यह संख्या १७ लाख और सन् १९५० में दोगुनी अर्थात् २८ लाख हो गई।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभेदात्मक सरक्षण की नीति ने अपने सङ्कुचित क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की और इन प्रमुख उद्योगों के सरक्षण से समाज को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ, उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले भार से कहीं अधिक है। यदि भूतकाल में सरक्षण की नीति अधिक उदारतापूर्वक अपनाई जाती, तो भारत का विकास एकांगी नहीं रहता, बल्कि औद्योगिक दृष्टि से वह अब तक बहुत आगे बढ़ गया होता।

क्या सरक्षण एक भार है ?—

कुछ लोगों के मतानुसार सरक्षण उपभोक्ताओं के लिये भार स्वरूप होता है, क्योंकि सरक्षण के अभाव में उपभोक्तागण विदेशी वस्तुओं का भी स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग कर सकते हैं। परन्तु यदि हम राष्ट्रीय हित की दृष्टि से विचार करें, तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि सरक्षण 'भार' नहीं होता। इसमें तो सदेह नहीं कि सरक्षण से ऊँचे मूल्यों के परिणामस्वरूप कुछ ता बोझ पड़ता ही है, परन्तु यह बोझ सरक्षण की मात्रा और समय पर निर्भर करता है। इस भार का माप करने के हेतु हमें सरक्षण शुल्क तथा राजस्व शुल्क की उन दरों में तुलना करनी पड़ेगी जो कि सरक्षण न होने पर लगाये जाते। इसके अतिरिक्त हमको यह भी मालूम करना पड़ेगा कि विदेशों से कितना माल आयात किया गया, देश के अन्दर बिजना माल निर्माण किया गया, सरक्षण के पूर्व आन्तरिक मंडियों में माल की कीमत क्या थी और सरक्षण के उपरान्त मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ। इन तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त ही यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अमुक उद्योग को सरक्षण देने से कितना लाभ हुआ।

सरक्षण की प्रत्यक्ष इस आघात पर आलोचना की जाती है कि रक्षित करो का भार गरीब लोगों पर पड़ता है। यह सत्य है कि परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर कुछ भार अवश्य पड़ता है, किन्तु निचले वर्ग ही इसमें प्रभावित होता है, यह ठीक नहीं। दूसरे, क्या होने वाला नुकसान प्रत्याशित लाभ से अधिक है? इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने पर पता चलेगा कि अधिकांश रक्षित वस्तुयें ग्रामीण क्षेत्रों में जानी ही नहीं हैं। उदाहरणार्थ, ऐसी वस्तुयें जैसे रेशमी कपड़ा, शराब, कॉकरी घड़िया, कटलरी, काच का सामान इत्यादि वस्तुओं का उपभोग मट्ठी भर

नगरो मे ही केन्द्रित है, ग्रामीण क्षेत्रो मे इनका उपभोग द्रव्य के बराबर है। गाँव वाले अधिक कागज, बराही या स्पात का भी प्रयोग नहीं करते। सूती पीस मिल पर शुल्क राशिपानन व विदेशी मुद्रा के अवमूल्यन के विरुद्ध लगाया गया था। उसमें केवल वह अनुचित लाभ समाप्त हो गया, जो कि उपभोक्ता निर्माता के अधिकार के विरुद्ध पा सकता था। इसलिए भारत में वास्तव में ग्रामीण जनता संरक्षण का मूल्य भुगत नहीं करती, बरन् मध्यम वर्ग करते है। इससे अतिरिक्त हमारे देश में तो सर-पट्टि (Taxation System) भी अधिक उगलिशील हो गई है। भागे के उपर सुपर टैक्स, विलासिता की वस्तुमा पर विक्रय कर और शुल्क लगन से घनाट्य व्यक्ति प्रतिदिन राजकीय कोष में अधिक से अधिक रुपया दे रहे है। आज हमारी सरकार इस प्रायः स जन कल्याण की अनेक योजनायें कार्यान्वित कर रही है।

ऊँची कृषि आय (agricultural income) पर भी कर लगा दिया गया है। इस बात के भी अनेक प्रमाण है कि रक-रक कर दिये जाने वाले संरक्षण से भी देश लाभान्वित हुआ है। आज हमारे आर्थिक नियोजन में जो वृद्धि हुई है वह संरक्षण का ही परिणाम है। देश की प्राकृतिक सम्पदा, जो अभी तक गुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी उसका अब पूर्ण उपयोग होने लगा है। चीनी उद्योग की प्रगति संरक्षण के लाभों का एक उ्बलन्त उदाहरण है। कागज के निर्माण के लिये वास की लुप्दी का प्रयोग करना बिना संरक्षण के असम्भव था। आज हमारे देश में अनेक ऐसी वस्तुओं का निर्माण होने लगा है (जैसे, बिजली का सामान, प्लास्टिक, रंग बनिश, मशीनें, धौजार, सिलाई की मशीनें, दवाइयाँ, रेडियो रिसीवर इत्यादि) जिनकी पहले हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। संक्षेप में, हम यह कह सकते है कि हमारी औद्योगिक प्रगति, उपभोग के स्तर में वृद्ध तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि बहुत कुछ संरक्षण का ही परिणाम है। अतः संरक्षण से भारतीय जनसाधारण पर कोई भार नहीं पडा।

विभेदात्मक-संरक्षण-नीति की आलोचना—

यद्यपि संरक्षण की विभेदात्मक नीति से कुछ उद्योगों को (जैसे लोहा तथा स्पात, वस्त्र मिल उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि) विशेष लाभ हुआ, किन्तु फिर भी इसे पूर्णतः व्यापार एवं उद्योग के हित में नहीं कह सकते। इस विवेचनात्मक या विभेदपूर्ण नीति की कई लोगो ने आलोचना की है।^१ श्री अदरकर के शब्दों में, “विभेदात्मक संरक्षण की नीति का परिणाम इसमें अधिक श्रेष्ठ नहीं हुआ कि एक निरुत्साहित सहायता जो उदासीनता से और कुछ कर जिन उद्योगों को दी गई उन्हें बोध में अपने हाथ पर छोड़ दिया गया।” कुछ लेखकों ने यहाँ तक लिखा है कि “यह

1. B. P. Adarkar—“Indian Fiscal Policy,” (2) D. K. Malhotra—“Review of Indian Fiscal Policy”, (3) Vakil and Munshi—“Industrial Policy with special references to tariffs”,

पूरी की पूरी भेद-भाव की ही नीति थी, संरक्षण की नहीं ।” इस नीति के परिपालन से राष्ट्रीय हितों की विशेष रक्षा नहीं हुई । हमारी व्यापारिक व औद्योगिक समृद्धि जिस गति में होनी चाहिए थी, नहीं हुई । इस संरक्षण से भारत को जो मिला है वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो कि जापान व रूस को थोड़े ही समय में संरक्षण द्वारा प्राप्त हुआ । भारत में औद्योगिक विकास की अपेक्षाकृत न्यून सफलता का प्रमुख कारण यह है कि यहाँ विदेशी सरकार का अधिकतर स्वार्थ भारत में अग्रजी माल बेचने में निहित था, न कि इस देश के कारखानों में माल बनाने में । यही कारण है कि भारत आज भी मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है और उद्योग-धन्यों का बहुत कम विकास हो सका है ।

विभेदात्मक नीति की प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार हैं:—

(१) संरक्षण प्राप्त करने के लिये प्रशुल्क आयोग ने त्रिमुखी गुर के अन्तर्गत जो शर्तें रखी थी वे इतनी कड़ी थी कि अनेक उद्योग उन्हें पूरा करने में असफल रहे ।

(२) उन्हीं उद्योगों को संरक्षण दिया जाता था, जिन्हें प्राकृतिक सुविधायें पर्याप्त मात्रा में सुलभ होती थी । यह विचार सचमुच बड़ा हास्यप्रद है कि जब उद्योग को समस्त प्राकृतिक सुविधायें प्राप्त हों, तब ही उसे संरक्षण दिया जाय । यदि प्राकृतिक सुविधायें उद्योग को सुलभ हों तो फिर उसे संरक्षण की आवश्यकता ही क्यों होने लगी ? वास्तव में संरक्षण की सुविधा तो उन उद्योगों को देनी चाहिए जिन्हें प्राकृतिक सुविधायें न हों ।

(३) इसी प्रकार त्रिमुखी गुर का दूसरा सिद्धान्त भी हास्यप्रद प्रतीत होता है, क्योंकि जब कोई उद्योग अन्य किसी मार्ग में उन्नति नहीं कर सकता, तब ही तो वह संरक्षण के लिये इच्छुक होता है ।

(४) उद्योग का आन्तरिक बाजार न होने की दशा में संरक्षण से बचन रखना भी अन्याय है । वास्तव में ऐसे ही उद्योग संरक्षण के प्रथम अधिकारी हैं, क्योंकि वे इसके बल पर ही उन्नति करके बाजार बना सकते हैं ।

(५) विश्व के अन्य किसी भी देश ने संरक्षण प्रदान करने में ऐसी कड़ी शर्तें नहीं बरती, जैसी कि रद्दीमतुल्ला आयोग ने लगाई ।

(६) एक कृषि प्रधान देश के लिये ऐसी कड़ी नीति से लाभ की अपेक्षा हानि होने की अधिक आशंका रहती है, और वास्तव में ऐसा हुआ भी । औद्योगिक दृष्टि से हम इतनी प्रगति न कर सके, जितनी हमको करनी चाहिए थी अथवा हम कर सकते थे ।

(७) प्रोफेसर अदारकर के अनुसार भारतीय संरक्षण प्रदान करने की शर्तों ने संरक्षण के क्षेत्र को बहुत संकुचित कर दिया ।

(८) सरक्षण प्रदान करते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि किस उद्योग को सरक्षण देने से राष्ट्र का अधिक हित होगा। उदाहरणार्थ, मैग्नेशियम क्लोराइड उद्योग की जाँच सन् १९२४ में की गई, किन्तु उसे इस आधार पर सरक्षण नहीं दिया गया कि वह अत्यन्त सरक्षण के अभाव में नहीं टिक सकता। सन् १९२८ में जब इस उद्योग ने पुनः सरक्षण की माँग की, तो प्रशुल्क मण्डल ने यह मत दिया कि उद्योग को सरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। विदेशी स्वार्थों की वेदी पर राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाई गई।

(९) सन् १९२२ के आयोग ने एक स्पाई बोर्ड नियुक्त करने के सम्बन्ध में सिफारिश की थी, परन्तु तत्कालीन सरकार ने प्रत्येक उद्योग की जाँच के लिये पृथक्-पृथक् बोर्ड बनाये, जिसके फलस्वरूप कोई भी ऐसी नीति नहीं बन सकी, जो कि लम्बे समय तक अपनाई जा सके।

(१०) प्रशुल्क मण्डल को अपना कार्य करने में पूर्ण स्वतन्त्रता भी नहीं थी, जिससे वह विधिवत् सही जाँच कर सकता।

(११) साधारणतः प्रशुल्क अधिकारियों और सरकार की विलम्बकारी कार्य-प्रणाली से, जो सरक्षण मिलता था वह भी बेकार साबित होता था।

(१२) उपर्युक्त दोषों के कारण ही सन् १९४६ के प्रशुल्क आयोग को यह कहना पड़ा है कि सन् १९२२ के प्रशुल्क आयोग ने सरक्षण की नीति को आर्थिक विकास के एक सामान्य साधन के रूप में नहीं देखा था। उसने इसे केवल ऐसा सह-रा समझा जिसके द्वारा कुछ उद्योगों का, जब वे सरक्षण के लिये प्रार्थना करें, तब विदेशी प्रतियोगिता सहने की शक्ति दी जा सके। इसी का परिणाम एक दिशाहीन विकास है। आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं हो सका। यह भी सम्भव है कि कुछ थोड़े से उद्योगों को, उसी समय यह प्रयत्न किये बिना कि उनसे मिलते-जुलते और उनके सहायक उद्योगों को भी सुविधा प्रदान की जाय, सरक्षण देने में समाज का सामूहिक भार बढ़ जाता।

विभेदात्मक नीति की आलोचना करते हुये श्री बी० पी० अद्वारकर ने लिखा है कि विभेदपूर्ण सरक्षण का सारा फार्मूला ही बदल जाना चाहिए। इसके स्थान पर अधिक सादा, विवेकशील और सीधा फार्मूला होना चाहिये। इस फार्मूले की कड़ी शर्त बदली जानी चाहिए। कच्चे माल के विषय में जो शर्त है उसे अवश्य हटा देना चाहिये। तीसरी शर्त भी हटा देनी चाहिए, क्योंकि वह पूर्व-स्थिर प्रमाणिक शर्त नहीं होकर भविष्यवाणी के समान है। इसके अतिरिक्त प्रशुल्क मण्डल की मशीनरी और विधि बिल्कुल बदल देनी चाहिए तथा प्रतिवन्द्यों की वर्तमान प्रणाली समाप्त करके प्रशुल्क मंडल के पास सीधे पहुँचने की सुविधा दी जानी चाहिये तथा उसे स्वयं जाँच प्रारम्भ करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। मंडल के सदस्यों को भी लोकमत के प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिये और सरकारी नामांकित सदस्यों का प्रभुत्व कम

देना चाहिये । विकास संरक्षण, सुरक्षा और राजस्व-सट कर में स्पष्ट अन्तर करना चाहिये । प्रत्येक का प्रयोजन व कार्य साफ-साफ निर्धारित किया जाना चाहिये । समय-समय पर सरकार को आवश्यक नये उद्योगों का विकास प्रोत्साहित करने के लिये प्रायोगिक सट कर लगाना चाहिए । यदि सट कर के लगाने पर भी उद्योग न तप सकें, तो सरकार को संरक्षण वापिस लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ।”

STANDARD QUESTIONS

1. What do you understand by the 'Tariff Formula, as enunciated by the Fiscal Commission 1921-22 ? Critically examine the various provisions of this Formula.
2. "In spite of criticism, certain Indian industries were highly benefitted by the protection granted to them according to the provisions of Rahimatullah Commission Report." Discuss briefly the benefits derived by the favoured industries.
3. "The discriminating protection has vouchsafed nothing better than a prefatory assistance, indifferently and grudgingly rendered to industries whose subsequent development has been left to its own course." Discuss this statement of Prof. Adarker with special reference to any two industries to which protection was granted after 1924.
4. Critically examine the policy of discriminating protection.
5. Is protection a burden on consumers ? Comment with special reference to Indian Conditions.

द्वितीय महायुद्ध-युग एवं युद्धोत्तर काल में प्रशुल्क-नीति

(Fiscal Policy During World War II and Post-war Period)

द्वितीय महायुद्ध-युग—

सन् १९३९ में द्वितीय महासमर प्रारम्भ हो गया, जो स्वयं उद्योगों के लिए एक संरक्षण मित्र हुआ। महायुद्ध प्रारम्भ होते ही देश की औद्योगिक स्थिति स्वतः सुधर गई। भारत में अनेक छोट बड़ उद्योगों का जन्म होन लगा। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत एक बड़ा निर्माता बन गया। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये युद्ध काल में संरक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठा क्योंकि 'नष्टार्थ' के कारण विदेशों से आना आता अपने आप बन्द हो गया। अतएव विदेशी प्रतिस्पर्धा पूर्णतया समाप्त हो गई। जो उद्योग रक्षित थे उनके लिए संरक्षण जारी रहा।

सन् १९४५ में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के पश्चात् देश के सम्मुख आर्थिक नव निर्माण का प्रश्न आया। द्वितीय महायुद्ध के प्रथम चरण में यह अनुभव किया गया था कि भारत में अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों का अभाव है। चूंकि युद्धकालीन आवश्यकताओं को सन्तुष्टि के लिये इन उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक था, अतः सन् १९४० में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि युद्ध काल में स्थापित उद्योगों का यदि ठोस व्यावसायिक आधार पर संयोजन किया गया, तो उन्हें उपयुक्त संरक्षण दिया जाएगा। इस आश्वासन के परिणामस्वरूप देश में बड़ी तेजी से उद्योगों का विकास हुआ। सन् १९४० की घोषणा में प्राशुल्किक संरक्षण का कार्य क्षेत्र बढ़ गया और सरकार की नीति को भी नया रूप मिला। परन्तु दीर्घकालीन प्राशुल्क नीति निर्धारित करने में तथा उसके संचालन के लिए स्थाई संस्था का निर्माण करने में काफी समय लग जाता। इसलिए भारत सरकार ने २ नवम्बर सन् १९४५ को अस्थाई तट कर या प्राशुल्क मण्डल स्थापित किया और इसे युद्ध काल में स्थापित किए गये उद्योगों का संरक्षण दिये जाने के दावा की जाँच पड़ताल करने का कार्य सौंपा गया।

अन्तरिम प्राशुल्क बोर्ड सन् १९४५—

प्रथम प्राशुल्क बोर्ड (First Tariff Board) सन् १९२३ में नियुक्त किया गया था, जिसका विवेचन हम शत अध्याय में कर चुके हैं। यह दूसरा प्राशुल्क बोर्ड

है, जिसकी नियुक्ति ३ नवम्बर सन् १९४५ को की गई। इसका निर्माण केवल दो वर्ष के लिए किया गया। यह बोर्ड किसी उद्योग को अधिक से अधिक ३ वर्ष के लिये संरक्षण देने की 'सफाई' कर सकता था। किन्तु पूर्व की भाँति अन्तिम निर्णय सरकार के ही हाथ में रहा। इस बोर्ड को पहले बोर्ड की अपेक्षा अधिक अधिकार दिए गये। इसका प्रमुख कार्य युद्ध-जनित तथा अन्य उद्योगों की जाँच करना तथा उन उद्योगों को संरक्षण देने की सिफारिश करना था।

अन्तरिम बोर्ड सन् १९४५ का कार्य—

सन् १९४५ में नियुक्त हुये अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड ने कुछ उद्योगों को संरक्षण देने की स्थिति पर विचार किया। जो उद्योग राजकीय संरक्षण चाहता था, उसे निम्न-लिखित बातों का पालन करना पड़ता था—

(१) कि वह दृढ़ व्यापारिक आधार पर संचालित होना है।

(२) (अ) उद्योग द्वारा नैसर्गिक व आर्थिक सुविधायें प्राप्त करने तथा उसके वास्तविक व सम्भावित व्यय को ध्यान में रखते हुए उद्योग उचित समय के भीतर भली प्रकार विकसित हो जायेगा और फिर उसे राजकीय संरक्षण या सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

(आ) वह एक ऐसा उद्योग है जिसे संरक्षण या सहायता प्रदान करना राष्ट्र के हित में है और इस संरक्षण या सहायता का सम्भावित व्यय जनता के ऊपर अधिक नहीं पड़ेगा।

संरक्षण सम्बन्धी उपर्युक्त बातों के एक मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लड़ाई के उपरान्त भी भारत सरकार ने प्राशुल्क सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में किसी स्थाई नीति का अनुकरण नहीं किया। अपने दो वर्ष के जीवन-काल में अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड के पास संरक्षण प्रदान करने के लिए कुल ४६ मामले आये, जिनमें से ४२ को संरक्षण दिया गया। इनमें से ३८ उद्योग युद्धकालीन तथा ४ उद्योग (सूती वस्त्र उद्योग, स्पात उद्योग, कागज तथा चीनी उद्योग) पूर्व स्थित थे। वास्तव में इस बोर्ड का प्रमुख कार्य उद्योगों की स्थिति जाँच करके उनके संरक्षण की सिफारिश करना था। किन्तु पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड अपने कर्तव्य का भली-भाँति पालन न कर सका।

पुनर्संज्ञित प्रशुल्क बोर्ड सन् १९४७ —

१५ अगस्त सन् १९४७ को भारत आजाद हुआ और इसी समय देश का विभाजन भी हुआ। देश के विभाजन ने कुछ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न कर दी जिनको सुलझाने के लिए तथा भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए सन् १९४७ में प्रशुल्क मंडल का पुनर्संज्ञित करना भी अनिवार्य हो गया। इस पुनर्संज्ञित बोर्ड के सभापति श्री जी० एल० मेहता थे तथा डा० एच० एल० डे० एच० डा० वी० वी० नारायणस्वामी नायडू इसके अन्य सदस्य थे।

इस बोर्ड के कार्य—

पुनर्सं गठित प्रशुल्क बोर्ड १९४७ के दो प्रमुख कार्य थे—

(१) सरकार को उन तथ्यों की सूचना देना जिनके कारण भारत निर्मित वस्तुओं का उत्पादन-व्यय विदेशों से आयात की हुई वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है, और—

(२) न्यूनतम व्यय पर देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिए सुझाव देना ।

बाद में मन् १९४८ में इस बोर्ड को निम्न अन्य कार्य भी सौंप दिये गये—

(३) उन उद्योगों की जाँच करना जो सरकार को सुरक्षा देने के लिए प्रार्थना-पत्र दें ।

(४) जिन उद्योगों को सुरक्षा मिल गया है, वे उन्नति कर रहे हैं अथवा नहीं, इसकी जाँच करना ।

(५) देश में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन-व्यय की जाँच करना तथा वस्तुओं के थोक व खेरीज मूल्य निश्चित करना ।

(६) राशिपातन (dumping) के विरुद्ध भारतीय उद्योगों के सुरक्षा के लिए सुझाव देना ।

(७) सरकार द्वारा लगाये हुए विभिन्न आयात व निर्यात करों का देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात का अध्ययन करना तथा सरकार को रिपोर्ट देना ।

(८) संयुक्तीकरण (Combines), प्रत्यास (trust) तथा एकाधिकृत मस्थाओं (Monopolies) के विषय में सरकार को सूचित करना और उनके दोषों को दूर करने के लिए सुझाव भी देना ।

(९) देश का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को सहाय देना ।

(१०) ऐसे उपायों को सरकार को बताना जिनके उपयोग में देश के आन्तरिक व्यापार के उत्पादन में अधिक व्यय न हो

(११) व्यापार की उन्नति में बाधा डालने वाली क्रियाओं की सरकार को सूचना देना ।

(१२) सुरक्षित उद्योगों पर सदैव निगाह रखना और आवश्यकतानुसार उनके लिए समय-समय पर सुरक्षा तथा प्रशुल्क नीति में परिवर्तन करना ।

यह बोर्ड केवल ऐसे ही उद्योगों के सुरक्षा के लिए सिफारिश करता था जो उचित रीति से कार्य रहे हों और जिनके पास पर्याप्त प्राकृतिक साधन हों, जो एक निश्चित अवधि के भीतर प्रगति करने की क्षमता रखते हों तथा जिसे सुरक्षा देना राष्ट्र के हित में हो ।

उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रशुल्क बोर्ड ने अनेक पुराने व नये उद्योगों की जाँच की और उसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप ३४ युद्ध-

जनित उद्योगों को सुरक्षण प्रदान किया गया। निम्नलिखित ६ पुराने उद्योगों पर से सुरक्षण हटा लिया गया—(१) सूती वस्त्र मिल उद्योग, (२) लोहे व स्पात का उद्योग, (३) कागज उद्योग, (४) मैंगनेशियम क्लोराइड उद्योग, (५) सिल्वर थ्रैड व वायर उद्योग एवं (६) शक्कर उद्योग। शक्कर उद्योग को पुनः १ वर्ष के सुरक्षण दिया गया, जो सन् १९५० में वापिस लिया गया।

इस बोर्ड के पक्ष में दिये गये तर्क—

(१) सन् १९४७ का प्रशुक्त मण्डल उद्योगों की जांच करते समय सर्वत्र इस बात का ध्यान रखता था कि सुरक्षण प्रदान करने में राष्ट्र का हित होगा अथवा नहीं।

(२) इस मंडल ने उदार सुरक्षण नीति का अनुकरण किया और राष्ट्र के अतिरिक्त उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखता।

(३) प्रथम बोर्ड ने १६ वर्ष की अवधि में कुल ५० उद्योगों की हो जांच की थी, परन्तु इस बोर्ड ने ५ वर्षों में लगभग ६१ उद्योगों की जांच की। इससे स्पष्ट है कि इस बोर्ड ने बड़े परिश्रम तथा लगन से कार्य किया।

(४) इस बोर्ड के कार्यों ने देश, समाज व उद्योगों के हितों की बहुत सीमा तक रक्षा की।

STANDARD QUESTIONS

- 1) Briefly describe the Tariff Policy of the Govt of India during the World war II
- 2) Discuss the circumstances, which led to the formation of the Tariff Board 1945 What were its functions ?
- 3) Discuss briefly the functions of the reconstituted Tariff Board 1947 How far it has protected the interests of Indian industries ?

प्रशुल्क आयोग १९४९-५०

भारत सरकार की वर्तमान प्राशुलिक नीति

(Fiscal Commission 1949-50 and the Present Tariff Policy)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशुल्क नीति —

१५ अगस्त सन् १९४७ का भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अप्रैल सन् १९४८ में राष्ट्रीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस औद्योगिक नीति में इस बात का भी संकेत किया गया कि सरकार का प्रशुल्क नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर बिना किसी प्रकार का अनुचित बोझ दिए विषम वैदेशिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना तथा देश की साधनों के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। सन् १९४९ की औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत सरकार पर जो उत्तरदायित्व आया उसको पूरा करने के लिये २८ अप्रैल सन् १९४९ के एक प्रस्ताव द्वारा सरकार ने एक प्रशुल्क आयोग (Tariff Commission) की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी थे। सन् १९४९-५० के प्रशुल्क आयोग अथवा कृष्णमाचारी आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे—

कृष्णमाचारी आयोग सन् १९४९-५० के कर्तव्य —

(१) सभी सम्बन्धित हितों की दृष्टि में सन् १९२१ के प्रशुल्क बोर्ड की नियुक्ति से लेकर अब तक भारत सरकार द्वारा उद्योगों की पररक्षण दान की नीति की जांच करना तथा

(२) निम्न सिफारिश करना—

- (क) पररक्षण व वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति क्या होनी चाहिये और पररक्षित व सहायता प्राप्त उद्योगों के साथ कसा व्यवहार हो व उनके कल्याण का नभारण किस प्रकार करना चाहिये।
- (ख) इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक यन्त्र (necessary machinery) का निर्माण करना और

1 The Tariff Policy of the Govt of India will be designed to prevent unfair foreign competition and to promote the utilization of India's resources without imposing unjustifiable burden on the consumer

(ग) इस नीति से सम्बन्ध रखने वाली कोई अन्य बात ।

(३) इन विषयों पर विचार करने में आयोग की समस्या के अल्पकालीन व दीर्घकालीन पक्षों पर विचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी तथा देश की आवश्यकता को देखते हुये यह सलाह देना कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रशुल्क व व्यापार के सामान्य सिद्धांतों या अन्तराष्ट्रीय प्रशुल्क व व्यापार संगठन व चाटर के अनुसार कार्य करना कहा तक वाछनीय होगा ।

प्रशुल्क आयोग सन् १९४६-५० की रिपोर्ट—

कृष्णमाचारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहले अपना कार्य क्षेत्र तथा आधारभूत उद्देश्यों का वर्णन करते हुये यह बतलाया कि निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है—

- (१) बेकारी अथवा अर्द्ध बेकारी से बचना और उत्पादन व मांग को बढ़ाना ।
- (२) देश के प्राकृतिक प्रसाधनों का पूर्ण सदुपयोग करना ।
- (३) उत्पादन शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा श्रमिकों की अवस्था में सुधार करना ।
- (४) कृषि तथा पशुविज्ञान का आधुनिक आधार पर विकास करना तथा खाद्य पदार्थों एवं उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल उत्पन्न करना ।
- (५) सहकारी अथवा व्यक्तिगत आधार पर कुटीर उद्योगों व लघु उद्योगों के लिय विशेष प्रवर्ध करना ।
- (६) वृहदस्तरीय औद्योगीकरण की गति बढ़ाना तथा इस हेतु मिश्रित अर्थ व्यवस्था (Mixed economy) की नीति अपनाना ।
- (७) सभी प्रकार के साधनों के नैसर्गिक गुणों का उपयोग करने के लिये एक बहुमुखी अर्थ व्यवस्था लागू करना ।

कृष्णमाचारी आयोग ने संरक्षण की समस्या पर अधिक संतुलित एवं विस्तृत दृष्टिकोण से विचार किया तथा इस बात पर जोर दिया कि संरक्षण को एक व्यावसायिक नीति का विकल्प मात्र न मानकर राष्ट्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र समझना चाहिये । चूंकि संरक्षण की नीति देश के आर्थिक विकास की योजना का एक अङ्ग है अतः इस प्रश्न पर पृथक् रूप से विचार नहीं किया जा सकता । उद्योगों में संरक्षण प्रदान करने की नीति का देश के आर्थिक नियोजन से घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए, अन्यथा इससे देश में असंतुलित आर्थिक विकास को अनुचित प्रोत्साहन मिलेगा । किन्तु इस प्रकार की व्यापक नीति के निर्धारण में समय लगेगा, अतः आयोग ने संरक्षण का एक सामान्य नीति की सिफारिश की । इस हेतु कृष्णमाचारी आयोग ने आयोजित क्षेत्र के उद्योगों को निम्न लिखित तीन वर्गों में विभाजित किया है —

- (१) प्रतिरक्षा एवं युद्ध-सम्बन्धी उद्योग (defence and other strategic industries),
- (२) आधारभूत और प्रमुख उद्योग (basic and key industries),
- (३) अन्य उद्योग (other industries) ।

सरक्षण सम्बन्धी सिफारिशें

(१) प्रतिरक्षा एवं युद्ध सम्बन्धी उद्योग—

प्रतिरक्षा तथा युद्ध सम्बन्धी उद्योगों के सम्बन्ध में आयोग ने यह सिफारिश की कि इनको अवश्य सुरक्षा दिया जाय, चाहे जनता पर इसका कितना ही भार क्यों न पड़े। इन उद्योगों के विषय में वास्तव में ऐसी उदार नीति आवश्यक भी है। देश में शान्ति व सुरक्षा बनाय रखने के लिये इन उद्योगों का अत्यन्त महत्त्व है। इनकी लागत चाहे कितनी ही हो। परन्तु सकल का सामना करने के लिये इनका विकास करना बहुत जरूरी है।

(२) आधारभूत और प्रमुख उद्योग—

द्वितीय श्रेणी के आधारभूत व प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में आयोग ने सिफारिश की कि इन उद्योगों को दिये जाने वाले सरक्षण का प्रकार, उनकी मात्रा और शर्तों को निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार प्रशुल्क मण्डल (Tariff Board) को देना चाहिये। प्रशुल्क मण्डल इसमें आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवर्तन कर सकता है।

(३) अन्य उद्योग—

तृतीय श्रेणी के अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न दो शर्तें निश्चित की—

(1) उद्योग को उपलब्ध आर्थिक सुविधाओं और उनकी वास्तविक या सम्भावित लागत को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित हो कि उचित अवधि के भीतर उद्योग अपना पर्याप्त विकास कर लेगा तथा बिना सरक्षण एवं सहायता के वह सफलतापूर्वक चलाया जा सकेगा।

(2) उद्योग ऐसा होना चाहिये जिसे सरक्षण प्रदान करना राष्ट्रीय हित में वाञ्छित हो, और उसकी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के सरक्षण वा अथवा अन्य प्रकार की सहायता का जनता पर अधिक भार न पड़ेगा।

आवोजित क्षेत्र के बाहर वाले उद्योगों पर तृतीय श्रेणी के अन्य उद्योगों पर लागू होने वाली शर्तें ही लागू होंगी।

अन्य सिफारिशें—

आयोग ने अनेक अन्य बातों पर भी अपनी राय प्रकट की है, जिसमें कि

प्रशुल्क मण्डल को सरक्षण सम्बन्धी किसी मामले को सुलझाने में सुविधा हो । इसकी अन्य सिफारिशों निम्नलिखित हैं—

(१) आयोग ने यह सुझाव दिया कि यदि किसी उद्योग के लिये थम, बाजार, शक्ति तथा यातायात के साधन आदि की सुविधायें उपलब्ध हो, तो केवल देश में कच्चा माल नहीं होने के कारण उसे सरक्षण की सुविधा प्रदान करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

(२) यद्यपि साधारणतः एक सरक्षण प्राप्त उद्योग को अपनी स्वदेशी बाजार की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ होना चाहिये, परन्तु इसे सरक्षण देने की अनिवार्य शर्त नहीं बना देना चाहिये । प्रशुल्क अधिकारियों के लिये अल्पकाल में केवल इस मान पर ही विचार करना उचित होगा कि उद्योग के विकास की सम्भावना कैसी है, जिससे कि निश्चित अवधि के भीतर वह देश की अधिकांश मांग को पूरा कर सके । दूसरे शब्दों में, किसी उद्योग को सरक्षण प्रदान करने के समय उससे यह आशा नहीं करनी चाहिये कि उद्योग सम्पूर्ण आन्तरिक मांग को पूरा कर सकता है ।

(३) किसी उद्योग को उपलब्ध बाजार की सुविधाओं पर विचार करते समय देश एवं विदेश में स्थित वर्तमान एवं सम्भावित सभी प्रकार के बाजारों पर विचार करना चाहिये ।

(४) उन उद्योगों को, जो किसी सरक्षित उद्योगों की वस्तुओं को कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं, क्षतिपूर्क संरक्षण (Compensatory Protection) दिया जा सकता है ।

(५) राष्ट्रीय हित में कृषि उद्योगों को भी सरक्षण प्रदान किया जा सकता है ।

(६) नये उद्योगों को भी उसी प्रकार सरक्षण की सुविधा देनी चाहिये जैसी कि विद्यमान उद्योगों को दी जाती है । उन नये उद्योगों में जिनका भविष्य उज्ज्वल है तथा जिनकी स्थापना में बहुत अधिक पूँजी एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो, सरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक है ।

(७) आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि एक पृथक विकास कोष (development fund) होना चाहिये, जिसमें प्रशुल्क करो का एक निश्चित भाग प्रतिवर्ष खालना चाहिये और इस कोष में से उद्योगों को निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित आर्थिक सहायता दी जाय—

(अ) जबकि देश के अन्दर का उत्पादन देश की माँग के केवल कुछ अंश को ही पूरा करता हो ।

(आ) जब कि उद्योग की वस्तुएँ प्रमुख कच्चे माल की हो ।

(इ) जब कि उद्योग की अनेक विशिष्ट श्रेणी हो, जो कि एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती और केवल उन्हीं के लिये सरक्षण की आवश्यकता हो ।

(८) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये आयोग ने यह भी अनिवार्य कर दिया कि रक्षित उद्योग के उत्पादन की मात्रा तथा उसकी वस्तुओं की किस्म की पूर्ण जांच होनी चाहिये। रक्षित उद्योग फिर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो समाज के हित में बाधक हो।

(९) रक्षित उद्योग प्रशुल्क बोर्ड को इस बात का विश्वास दिलाए कि वह संरक्षण से कोई अनुचित लाभ नहीं उठाएगा।

(१०) आयोग ने सिफारिश की है कि सामान्य परिस्थिति में परिमाण सम्बन्धी निर्वन्ध कम लगाने चाहिये और केवल असामान्य आघात के विरुद्ध सशान्त चाहिये। इसका कहना है कि किसी उद्योग के विकास की वह स्थिति निश्चय करना कठिन है जिस पर तटकर-काटा (tariff quota) योजना लगाना उपयुक्त होगा। जहाँ तक संरक्षण की मात्रा का प्रश्न है यह सुझाव दिया गया है कि प्रशुल्क अधिकारियों को एक न तथा प्रमाणिक नियम बना लेना चाहिये। उदाहरण के लिये, उद्योगों को उचित लम्बी अवधि के लिये संरक्षण का आश्वासन देना चाहिये, जिससे कि उनकी ओर पूँजी आकर्षित हो तथा उद्योगों का एक उपयुक्त कार्यक्रम बनाया व क्रियान्वित किया जा सके।

(११) आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार की भण्डार क्रय-नीति (stores purchase policy) में विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा देशी वस्तुओं की प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

स्थायी प्रशुल्क आयोग की सिफारिश—

कुण्ठाभाचारी आयोग ने एक स्थायी प्रशुल्क आयोग (Tariff Commission) की स्थापना के लिये सिफारिश की। यह आयोग एक वैधानिक संस्था है। इसमें सभापति का सम्मिलित करते हुये पाँच सदस्य होंगे। विशेष मामलों के लिये आयोग अन्य सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है। सदस्यों की नियुक्ति उनका गुणों के आधार पर होनी चाहिये, न कि किसी अन्य विशेषता के आधार पर, सदस्यों को उनकी नियुक्ति के पूर्व किसी निजी कंपनी से सम्बन्ध रहने पर उसे व्यक्त करना चाहिये तथा आयोग की सदस्यता छोड़ने के तीन वर्ष बाद तक इन्हें किसी प्रकार की निजी औद्योगिक संस्था में कोई प्रबंध-व्यवस्था सम्बन्धी पद भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं स्वीकार करना चाहिये।

आयोग की सिफारिश के आधार पर सन् १९५१ के प्रशुल्क आयोग अधिनियम (Tariff Commission' Act 1951) के अन्तर्गत एक स्थायी प्रशुल्क आयोग स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने २१ जनवरी सन् १९५२ को प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति भी कर दी है। इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षों के लिये की गई, किन्तु वे पुनः नियुक्त किये जा सकते हैं। इसके तीन सदस्य हैं। इस आयोग को अतीत की सभी संरक्षण निर्धारण समितियों से अधिक अधिकार दिये गये हैं।

प्रशुल्क आयोग के प्रमुख कार्य—

प्रशुल्क आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है—

(१) प्रशुल्क आयोग पूर्व स्थापित उद्योगों के अतिरिक्त उन उद्योगों की सरक्षण सम्बन्धी मांग पर भी विचार कर सकता है, जिनमें अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है, परन्तु सरक्षण के उपरान्त उत्पादन आरम्भ करने की आशा है। अतीत में आयोग केवल पूर्व-स्थापित उद्योगों की मांग पर ही विचार कर सकता था।

(२) प्राथमिक सरक्षण और विशेष वस्तुओं की कीमतों के अतिरिक्त चाहे वे वस्तुएं सरक्षित उद्योग की हों, अथवा असरक्षित उद्योग की, आयोग ग्रन्थ मामलों में स्वयं जाँच पड़ताल कर सकता है। प्रथम दो अपवादों के सम्बन्ध में केवल सरकार के कहने पर ही जाँच की जा सकती है।

(३) आयोग सरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रार्थी उद्योगों की स्थिति की जाँच करेगा तथा समय-समय पर इसकी रिपोर्ट सरकार को देगा।

(४) सरक्षण निर्धारित करने तथा सरक्षित उद्योगों के कर्तव्यों को निश्चित करने के सामान्य नियमों को बनाने तथा उनमें संशोधन आदि करने का आयोग को पूर्ण अधिकार रहेगा।

(५) आयोग प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार सरक्षण की अवधि निश्चित करने को स्वतन्त्र है और इस पर युद्ध के पश्चात् स्थापित प्रशुल्क बोर्डों की भाँति यह प्रतिबन्ध नहीं लगा है कि सरक्षण की अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो।

(६) प्रशुल्क आयोग अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आयोग द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के तीन माह के अन्दर सरकार ससद को सूचित करे कि उसने रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है और किसी प्रकार की कार्यवाही न करने की दशा में सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकी।

(७) प्रशुल्क आयोग अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकार अनेक महत्वपूर्ण मामलों की जाँच करने तथा उन पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग से कह सकती है। ऐसे मामलों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

(1) भारत के किसी उद्योग को सरक्षण प्रदान करना,

(11) सरक्षणात्मक करों में परिवर्तन करना,

(111) विदेशों में पदार्थों के सस्ते मूल्यों पर आयात (Dumping) को रोकने के लिए उचित कार्यवाही करना,

(1V) यदि कोई उद्योग सरक्षण से अनुचित लाभ उठा रहा हो, जैसे वह अनावश्यक ही अधिक मूल्य वसूल करता है अथवा इस प्रकार व्यवहार कर रहा है कि जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएँ, अथवा किसी अन्य ढङ्ग से जनहित के प्रतिकूल कार्य कर रहा हो, तो आयोग उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही के लिए सुझाव दे सकता है,

(V) मूल्य-भ्रष्टाली, रहन-सहन के व्यय तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के अन्य भागों पर सरक्षण के प्रभाव की जाँच करना,

- (vi) व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत प्रशुल्क सुविधाओं का उद्योगों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच करना,
 (vii) कर्तव्य पालन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों पर विचार करना ।

किसी भी उद्योग के संरक्षण का विचार करते समय आयोग को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए—

- (अ) भारत एवं प्रतिस्पर्धी देशों में उस वस्तु का उत्पादन-व्यय,
 (आ) प्रतियोगी वस्तुओं का आयात मूल्य,
 (इ) प्रतिनिधि उचित बिजली मूल्य,
 (ई) माँग, स्थानीय उत्पादन तथा आयात का स्तर, और
 (उ) कुटीर, लघु तथा अन्य उद्योगों पर किसी उद्योग के संरक्षण का प्रभाव ।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों का भूत्पादन—

भूतकाल में हमारे उद्योगों को संरक्षण देने सम्बन्धी नीति पर ब्रिटिश हितों की छाप रहती थी । केवल कभी-कभी आलाचकों के मुद्दे को बन्द करने के लिए ही किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान कर दिया जाता था । उस समय का प्रशुल्क बोर्ड प्रशस्त तथा व्यावहारिक दृष्टि में महत्वहीन था और उसकी सिफारिशें रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती थी ।

परन्तु अब यह सब प्राचीन इतिहास हो गया । आज हमारी प्रशुल्क नीति के पीछे एक प्रयोजन है । भारत सरकार ने कृष्णमाचारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार २१ जनवरी सन् १९५२ को एक प्रशुल्क आयोग (Tariff Commission) नियुक्त किया है, जिसने इण्डियन टैरिफ बोर्ड का स्थान ले लिया । प्रशुल्क आयोग एक वैधानिक संस्था है, जो अपने प्रशासकीय मामलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त है । इस आयोग की सिफारिशें लगभग सदैव ही मान ली जाती हैं । आज हमारा देश स्वतन्त्र है और विश्व में अन्य राष्ट्र हमें सम्मान की दृष्टि से देखने हैं । तीव्र औद्योगीकरण हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख लक्षण है । हम अपनी व्यापार नीति का निर्धारण स्वयं करते हैं जो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रख कर बनाई जाती है ।

हमारे वर्तमान प्रशुल्क आयोग ने संरक्षण को आर्थिक विकास की सामान्य योजना का एक अंग माना है या संरक्षण की समस्या को कोई प्रथम रूप नहीं दिया जा सकता है । आयोग की विकारता में प्रतिष्ठा एवं आधारभूत उद्योगों को परान महत्त्व दिया गया है । देश की आर्थिक उन्नति एवं सुरक्षा की दृष्टि से इनका विचार करने के लिए इसे विशेष सुविधा देना अनिवार्य भी था । आयोग ने नवीन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भी आवश्यक साधनों का प्रस्तावन किया है । नये उद्योगों को इन प्रकार की सुविधा का प्रसार आवश्यक संरक्षण की नीति

का सबसे बड़ा दोष था। संरक्षण प्रदान करने की शर्तें भी अपेक्षाकृत अधिक उदार हैं। विभेदात्मक संरक्षण का सबसे बड़ा दाव यह था कि संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों का बहुत सकीर्ण अर्थ लिया था। अब तो उद्योगों के विकास एवं उन्नति के सम्बन्ध में नियमित रूप से जाँच की भी व्यवस्था की गई है। संरक्षित उद्योगों पर निश्चित रूप से उत्तरदायित्व भी रखा गया है, जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिलने की आशा की जाती है।

इस सम्बन्ध में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि आयोग द्वारा 'अन्य उद्योगों' के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें बहुत कुछ सन् १९२१ के 'विमुखी-गुरु' के अनुरूप ही जान पड़ती हैं। 'उद्योगों को प्राप्त आर्थिक व प्राकृतिक सुविधाओं' की शर्तें सन् १९२१ के आयोग द्वारा निर्धारित प्रथम शर्तों की भाँति हैं। इसी प्रकार 'उद्योग से यह आशा करना कि वह उचित समयावधि में पर्याप्त उन्नति कर लेगा' तथा 'कुछ समय बाद इस योग्य हो जाएगा कि बिना संरक्षण के अपने पैरों खड़ा हो सके', क्रमशः सन् १९२१ की दूसरी व तीसरी शर्तों से मिलनी-जुलती हैं। इन शर्तों के सम्बन्ध में 'अस्पष्टता' का भी आरोप लगाया जाता है तथा प्रशुल्क के लिये कभी-कभी एक निश्चित निराय पर पहुँचना कठिन हो जाता है। अतः सुझावस्वरूप यह कहा जा सकता है कि आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों की ही भाँति 'अन्य उद्योगों' को भी संरक्षण प्रदान करने या न करने का अधिकार प्रशुल्क आयोग के हाथ में छोड़ देना, इन अस्पष्ट तथा अनिश्चित शर्तों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होगा।

नवीन प्रशुल्क आयोग १९५२ (New Tariff Commission, 1952)

भारत सरकार ने फिस्कल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार २१ जनवरी सन् १९५२ को, टैरिफ कमीशन एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत एक टैरिफ कमीशन (बेयरमैन सहित तीन सदस्य) नियुक्त किया, जिसने इण्डियन टैरिफ बोर्ड का स्थान ले लिया। चूँकि कमीशन एक वैधानिक संस्था है इसलिये एक्जीक्यूटिव या अन्य गुटों के हस्तक्षेप से वह मुक्त है। कमीशन के अधिकार और कर्तव्य भी गत टैरिफ बोर्ड की अपेक्षा बहुत व्यापक हैं। सरकार उसमें कई बातों में परामर्श ले सकती है, जैसे किसी उद्योग को संरक्षण देना, किसी उद्योग की रक्षा के लिए करो में हेर-फेर करना, राशिपातन और संरक्षित उद्योग के दोषों के विरुद्ध कार्यवाही करना, सामान्य मूल स्तर एवं रहन-सहन की लागत पर संरक्षण का प्रभाव, टैरिफ रियायतों का किसी विशेष उद्योग पर पड़ने वाला प्रभाव तथा संरक्षण से सम्बन्धित कोई अन्य समस्या।

कमीशन को इस बात का अधिकार है कि न केवल चालू उद्योगों से बल्कि उन उद्योगों से भी, जो कि उत्पादन अभी आरम्भ कर सकते हैं जबकि उन्हें संरक्षण मिल जाय, संरक्षण सम्बन्धी उनके दावों के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल करे। कमीशन अपनी ओर से भी किसी उद्योग को संरक्षण देने के प्रश्न पर विचार कर सकता है।

कमीशन सरक्षित उद्योग के सम्बन्ध में व्यापक सिद्धान्त एवं नियम बनाने का अधिकार रखता है। उदाहरण के लिये, युद्धोत्तर टैरिफ बोर्ड को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये सरक्षण देने का अधिकार नहीं था, लेकिन टैरिफ कमीशन को सरक्षण की अवधि निश्चित करने के सम्पूर्ण अधिकार हैं। उपभोक्ताओं के हितों का सुरक्षित रखने के लिए टैरिफ बोर्ड का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह सरक्षित उद्योग की प्रगति (जैसे उत्पादन व्यय उत्पत्ति की मात्रा व किस्म भावी विवास की सम्भावनाएँ आदि) पर निगाह रखे और इस विषय में अपनी रिपोर्ट सरकार को देता रहे।

कमीशन को तथ्यों के निर्धारण एवं सन्तुल्यता के निष्कर्ष बनाने व परामर्श देने की स्वतन्त्रता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सरकार उनको कार्यान्वित करे ही। वास्तव में कमीशन का कर्तव्य आर्थिक नियमों के सन्दर्भ में तथ्यों का अध्ययन करना है। जीव पड़ताल करते समय जिन नियमों का पालन करना कमीशन के लिए आवश्यक है उनका उल्लेख टैरिफ कमीशन एक्ट में किया गया है। इन नियमों के अनुसार, उद्योग की प्रतिनिधि इकाइयों में वास्तविक लागत की गणना की जाती है और उनकी भावी उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण उद्योग के लिए उत्पत्ति के अनुमानित उचित कारखाना मूल्य (Fair ex-works price) की तुलना आयात किये जाने वाले उसी प्रकार के सामान के भारत भूमि पर मूल्य (C I F. Price) से, कर शामिल न करते हुए, की जाती है और इस तुलना के आधार पर संरक्षण की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ किराया इत्यादि भी कारखाना मूल्य में जोड़ लिया जाता है। कभी-कभी स्थायी सम्पत्तियों या स्थायी पूँजी की गणना करने में कठिनाई अनुभव की जाती है। साधारणतः स्थायी सम्पत्तियों को मूल रकम पर मूल्यांकित किया जाता है और बिसाई श्रय कर की दरों से निकासी जाती है। कुछ दशाओं में विशेष कोष बनाने में सुविधा देने की दृष्टि से उद्योग को विशेष बिसाई भी स्वीकृत की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पूँजी के सम्बन्ध में है। वर्तमान प्रथा स्थायी सम्पत्तियों के प्रारम्भिक मूल्य (Gross block) पर ८ से १०% तक लाभांश देने की है और कार्यशील पूँजी पर प्रायः बैंक-दर से १% अधिक व्याज दिया जाता है। कार्यशील पूँजी की गणना उद्योग की ३ से ६ माह की उत्पादन लागत के आधार पर की जाती है।

टैरिफ कमीशन एक्ट के अन्तर्गत सरकार के लिये यह आवश्यक है कि कमीशन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के ३ माह के भीतर वह पार्लियामेंट को उस रिपोर्ट पर अपने द्वारा किये गये कार्य का ब्योरा प्रस्तुत करे। यदि उसने रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न की हो, तो ऐसी असमर्थता का कारण बताना होगा।

टैरिफ कमीशन के कर्तव्यों का ब्योरा—

जनवरी १९५२ में टैरिफ बोर्ड से टैरिफ कमीशन को निम्न मामले विचारार्थ मिले—

(१) बाल बियरिंग और स्टील बाल्स, ऊनी होजरी, ट्रान्सफारमर्स, फ्लैक्स का सामान व छोटे औजारों में सम्बन्धित ५ मामले ।

(२) कोमनों के निर्धारण से सम्बन्धित ३ मामले ।

(३) सरक्षित उद्योगों की प्रगति से सम्बन्धित ४२ मामले ।

सन् १९५२-५४ के मध्य, कमीशन ने निम्नलिखित को सरक्षण देने के नये मामलों पर विचार किया — बालबियरिंग एव स्टील बाल्स इन्डस्ट्री, ऊनी होजरी, ओटोमोबाइल्स, ट्रान्सफारमर्स, फ्लैक्स गुड्स और टिटैनियम डायोक्साइड । सरकार ने बालबियरिंग उद्योग को कमीशन की सिफारिशों पर सन् १९६० तक सरक्षण देना स्वीकार कर लिया है । ऊनी होजरी की सरक्षण सम्बन्धी प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि कमीशन ने सरकार को ऐसा ही सुझाव दिया था । ओटोमोबाइल्स उद्योग के सम्बन्ध में सरकार ने कमीशन की इस मुख्य सिफारिश को मान लिया कि 'अमेम्बलिंग' का कार्य रोक दिया जाय और व्हीकल्स की मांग उन्हीं फर्मों पर सीमित रखी जाय, जिनके पास कोई निर्माण कार्यक्रम हो । इस उद्योग को सरक्षण जारी रखने की अवधि के बारे में कोई निर्देश नहीं है । ट्रान्सफारमर्स को सरक्षण सन् १९५३-५४ में दिया गया था और सन् १९६० के अन्त तक बढ़ा दिया गया है । फ्लैक्स गुड्स को सरक्षण देना इस आधार पर मना कर दिया गया कि वर्तमान रेवेन्यू ड्यूटी ही इतनी काफी थी कि यह उद्योग विदेशी माल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था । टिटैनियम डायोक्साइड को भी सन् १९५४ तक के लिए सरक्षण दिया गया और अब सन् १९६१ तक बढ़ा दिया गया है ।

सन् १९५४-५५ में टैरिफ कमीशन ने कुल २५ जाँच-पड़तालें, जिनमें से ५ मामले उन उद्योगों से सम्बन्धित थे, जो कि पहली बार सरक्षण माँग रहे थे, १७ मामले सरक्षण की अवधि बढ़ाने की माँग करने वाले उद्योगों के थे और १ कीमत सम्बन्धी मामलों का था । कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने सभी नये मामलों में सरक्षण देना स्वीकार कर लिया और १३ पुराने मामलों में सरक्षण की अवधि बढ़ाने को सहमत हो गई । सरक्षण पाने वाले नये उद्योगों में ओटोमोबाइल के कुछ भाग बनाने वाले उद्योग थे, जैसे—ओटोमोबाइल लोक स्प्रिंग, ओटोमोबाइल स्प्रारिंग प्लग व ओटोमोबाइल हैड टायर इन्स्टेल्स । डाईस्टफ इण्डस्ट्री को भी जैसा कि कमीशन ने कहा था, सरकार ने सन् १९६४ के अन्त तक सरक्षण देना स्वीकार किया ।

सन् १९५५-५६ में टैरिफ कमीशन ने कुल २० इन्क्वायरियाँ संचालित की, जिनमें से २ कीमत सम्बन्धी इन्क्वायरियाँ थी । ३ इन्क्वायरियाँ पहली बार सरक्षण माँगने वाले उद्योगों से और शेष सरक्षण की अवधि बढ़ाने के इच्छुक उद्योगों से सम्बन्धित थी । नये ३ मामलों में दो ओटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाले उद्योग ही थे, जिन्हें क्रमशः सन् १९५६ व १९६० तक सरक्षण स्वीकार किया गया । तीसरा मामला इन्जीनियर्स स्टील फाइल्स इण्डस्ट्री का था, जिसे कमीशन की सिफारिशों पर

सन् १९५६ के अन्त तक सरक्षण दिया गया। पुराने १७ मामलों में से ६ के लिये सरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई।

सन् १९५६-५७ में, कमीशन ने ६ टैरिफ इन्क्वायरियाँ और ४ मूल्य इन्क्वायरियाँ की। २ टैरिफ इन्क्वायरियाँ उन उद्योगों से सम्बन्धित थी जिन्होंने पहली बार सरक्षण माँगा था और दोष अवधि बढ़वाने के इच्छुक उद्योगों की थी। नये प्रार्थनापत्र कैंल-क्षियम कारबाइड और ब्राइसोनिआजिड उद्योगों से प्राप्त हुए थे। टैरिफ कमीशन रिपोर्ट पर सरकार ने कैंलक्षियम कारबाइड उद्योग को ३१ दिसम्बर सन् १९५८ तक सरक्षण देना स्वीकार कर लिया, किन्तु जैसा कि कमीशन ने सिफारिश की थी, ब्राइसोनिआजिड उद्योग को सरक्षण देना मना कर दिया, क्योंकि इससे एक जीवन रक्षण ड्रग की कीमत के बढ़ने का भ्रंश हो सकेगा।

सन् १९५७-५८ में कमीशन ने २२ टैरिफ इन्क्वायरियाँ और १ मूल्य इन्क्वायरी संचालित की। सभी टैरिफ इन्क्वायरियाँ सरक्षण की अवधि बढ़ाने वाले उद्योगों से सम्बन्धित थी।

सन् १९५६-६० में प्रचलित आयोग ने सरक्षण को जारी रखने से सम्बन्धित १४ प्रचलित जाँच-पड़तालें तथा ३ मुख्य मूल्य सम्बन्धी जाँच पड़तालों की थी। निम्न उद्योगों के सम्बन्ध में प्राचलिक जाँच पड़तालों (Tariff enquiries) की गई थी.—Sago, hydroquinone, grinding wheels, machine screws, cotton and hair belting, automobile leaf spring, stearic and oleic acids, diesel fuel injection equipment, plastics (phenol formaldehyde moulding powder and buttons), non-ferrous metals, automobile hand tyre inflators, Mswood screws, calcium lactate and piston assembly. इनमें से प्रथम १० उद्योगों के सम्बन्ध में कमीशन की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार इनमें से प्रथम ६ उद्योगों को जनवरी सन् १९६० से सरक्षण मिलना बन्द हो गया है, २ उद्योगों को सरक्षण क्रमशः ३ और ४ वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है, नवें उद्योग को बटनों के सम्बन्ध में सरक्षण बढ़ कर दिया गया है, जबकि पाउडर के लिए वह सन् १९६२ तक जारी रहेगा। दसवें उद्योग के अन्तर्गत भी कुछ मदों को सरक्षण देना बन्द कर दिया गया है और कुछ तीन वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। मुख्य सम्बन्धी जाँच पड़तालों (Price inquiries) सूत, कागज और चीनी से सम्बन्धित थी।

टैरिफ कमीशन के कार्य की आलोचना

जैसा कि निम्न तालिका से प्रकट होता है, कमीशन ने सन् १९५२-५८ की अवधि में सरक्षण की माँग पहली बार करने वाले १४ प्रस्तावों के सम्बन्ध में इन्क्वायरी की थी, जिनमें से ६ तो ओटोमोबाइल इंडस्ट्री या ओटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाले

उद्योगों से सम्बन्धित थी, ४ नये प्रार्थना पत्र, जो कि उम्मी होजरी, फ्लैक्स गुड्स और डाइसोनब्राजिड उद्योगों से सम्बन्धित थे, इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये कि विद्यमान छूटी ही पर्याप्त थी और इसे बढ़ाने से देशी वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने की आशंका थी। सरक्षण पाने वाले नये उद्योगों में वाल्व बियरिंग्स, ट्रांस-फार्मर्स, टिटैनियम हायड्रोसाइड, डाइस्टफ, इजीनियम स्टील फाइल्स और वैलशियम कारबाइड है। सन् १९५७-५८ में किसी नये उद्योग से सरक्षण की मांग नहीं आई। सम्भवतः विदेशी विनिमय के अभाव के कारण आयातों पर जो प्रतिबन्ध रहे उनसे हमारे नये उद्योगों को अप्रत्यक्ष सरक्षण प्राप्त हो गया था, जिसमें उन्होंने सरक्षण की मांग पर बहुत ध्यान नहीं दिया।

प्रशुल्क आयोग का कार्य १९५२-५८

वर्ष	टैरिफ इन्क्वायरियाँ		कुल	मूल्य इन्क्वायरियाँ
	नवीन	सरक्षण चालू रखने के लिए		
१९५३-५४	४	११	१५	३
१९५४-५५	५	१७	२२	१
१९५५-५६	३	१७	२०	२
१९५६-५७	२	६	=	४
१९५७-५८	-	२२	२२	१
कुल	१४	७३	८७	११

विद्यमान उद्योगों को सरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में कुल ७१ इन्क्वायरियाँ की गईं। यह अधिक संख्या इस कारण थी कि कमिशन ने केवल अल्प अवधियों के लिये ही सरक्षण दिया था, जिससे उन्हें बढ़वाने की आवश्यकता उदय हुई। सरक्षित उद्योगों की सूची से, जो कि आगे दी गई है, यह प्रगट होगा कि केवल चार उद्योगों को ही ३१ दिसम्बर सन् १९६० तक, १ उद्योग को सन् १९६१ तक तथा कुछ उद्योगों को अनिर्दिष्ट काल तक सरक्षण दिया गया था।

प्रारम्भ में अल्प अवधि के लिये ही सरक्षण देने के कुछ निश्चित गुण दीये हैं। अल्पकालीन सरक्षण का लाभ यह है कि कमिशन को समय-समय पर सरक्षित उद्योग की प्रगति का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, जिसके फलस्वरूप वह उद्योग को किस्म सुधारने तथा मूल्य घटाने के लिये प्रेरित कर सकता है। इसके अनिर्दिष्ट उद्योग असामाजिक कार्यवाहियों में भाग लेने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हें सरक्षण जारी न रखे जाने का भय रहता है। इसके विपरीत, अल्पकालीन सरक्षण उद्योगपतियों को नये उद्योगों में विनियोग करने के लिये प्रोत्साहित नहीं करता। ऐसी परिस्थितियों में, सरक्षण से देशी माल का उत्पादन बढ़ने के बजाय उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है, क्योंकि उन्हें आयात-वस्तुओं के लिये

अधिक मूल्य देने पड़ा करे। अतः टैरिफ कमिशन को सावधानी में अल्पकालीन संरक्षण के परणामों का विस्तृत परीक्षण करना चाहिये। इस सम्बन्ध में फिक्शन कमिशन (१९४६५०) के निम्न कथन का नाम संहित उल्लेख किया जा सकता है— आधुनिक वर्षों में संरक्षण के प्रभाव का निम्न करने वाली सबसे मुख्य बात अल्प अवधि के लिये संरक्षण देना है। इसमें संरक्षित उद्योग अपनी मशीन आदि का प्रतिस्थापन एवं आधुनिकीकरण करने की दिशा में बड़ा निम्नमाहिन है।

संरक्षित उद्योगों की सूची से यह भी मालूम होगा कि संरक्षित उद्योगों को चार वर्गों में बांटा गया है—पूँजी सामान वाले उद्योग (मसूदा ८) उपभोग्य माल वाले उद्योग (३) औद्योगिक बच्चे माल वाला वर्ग (१६) और व्यापारिक वर्ग (७)। इस प्रकार २१ मार्च सन् १९५८ को लगभग ३७ उद्योगों को संरक्षण प्राप्त था।

द्वारा के औद्योगिक विकास में संरक्षण का जो महत्त्व रहा है उतना उन उद्योगों की सूची के विस्तार से जाना जा सकता है जो कि गत वर्षों में संरक्षण से मुक्त हो गई है।

विभिन्न उद्योगों को संरक्षण का लाभ २ से १ वर्ष तक मिला है। आधिकांश दशकों में संरक्षण की अवधि ६ वर्ष रही है। युद्ध-पूर्व संरक्षण पाने वाले उद्योग संरक्षण के अन्तर्गत युद्धोत्तर संरक्षण पाने वाले उद्योगों की तुलना में अधिक समय तक रहे। तबिन यह नहीं समझना चाहिये कि जिन उद्योगों से संरक्षण हटा लिया गया है वे विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने लायक बन गये हैं। अनेक दशकों में तो संरक्षणामक ड्यूटी का स्थान स्वयं ड्यूटी ने ले लिया है।

तालिका

संरक्षित उद्योगों की सूची—३१-३-१९५८

क्रम	उद्योग का नाम	संरक्षण स्वीकार करने की तिथि	संरक्षण समाप्त होने की तिथि
------	---------------	------------------------------	-----------------------------

(१) पूँजी वस्तुएं

१	बाल विवरण	१०-१-१९५३	३१-१२-१९६०
२	काटन व हेयर ब्रैटिंग	१२-६-१९४८	३१-१२-१९५६
३	सूती वस्त्र मिल मशीनरी	१७-१२-१९४६	३१-१२-१९६०
४	इलेक्ट्रिक मोटर्स	१-४-१९४८	३१-१२-१९५८
५	इजीनियर्स स्टाल फाब्रिक्स	१९५५-५६	३१-१२-१९५६
६	ग्राइंडिंग ह्वील्स	१०-५-१९४७	३१-१२-१९५६
७	मशीन स्कूज	१-१२-१९५१	३१-१२-१९५६
८	पावर एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स	३०-५-१९५३	३१-१२-१९६०

क्रम संख्या	उद्योग का नाम	सरक्षण स्वीकार करने की तिथि	सरक्षण समाप्त होने की तिथि
----------------	---------------	--------------------------------	-------------------------------

(२) उपभोग वस्तुयें

६ बटन (प्लास्टिक)	१३-१-१९५१	३१-१२-१९५६
१० कोका पाउडर और चाकलेट	१-२-१९४७	३१-१२-१९५८
११ दियासलाई	१९२८	अनिर्दिष्ट

(३) औद्योगिक कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुयें

१२ अल्यूमीनियम	१५-५-१९४८	३१-१२-१९५८
१३ एन्टीमोनी	२२-३-१९४७	३१-१२-१९५८
१४ बायफ्लोमेट	२१-१२-१९४६	३१-१२-१९५८
१५ कैल्शियम कारबाइड	१९५६-५७	३१-१२-१९५८
१६ कैल्शियम लेफ्टेट	१२-८-१९५०	३१-१२-१९६०
१७ वास्तिक सोडा व ब्लोबिंग पाउडर	२८-१-१९५५	३१-१२-१९५८
१८ डाइस्टफ	२-२-१९५५	३१-१२-१९६४
१९ हाइड्रामिनोन	२८-७-१९५१	३१-१२-१९५६
२० नान फॅरस शैटल	११-६-१९४८	३१-१२-१९५६
२१ अलेथिक एव स्टियमिक एसिड	४-६-१९४८	३१-१२-१९५६
२२ प्लास्टिक	७-१-१९५०	३१-१२-१९५६
२३ प्लाइवुड टीचर्सटैस	१२-४-१९४८	३१-१२-१९६०
२४ सैरीकल्चर	१९३४	३१-१२-१९५८
२५ कृत्रिम रेशम	१९३४	३१-१२-१९५८
२६ सैगो	१६-६-१९५०	३१-१२-१९५८
२७ शीट ग्लास	२५-२-१९५०	३१-१२-१९६०
२८ मोडा एश	२२-१-१९५०	३१-१२-१९५८
२९ टिटैनियम डायोक्साइड	६-१२-१९५३	३१-१२-१९६१
३० वुड स्क्रू	२२-३-१९४७	३१-१२-१९६०

(४) यातायात उद्योग

३१ ओटोमोबाइल्स	१९५४	३१-१२-१९६७
३२ ओटोमोबाइल हैन्ड टायर इन्फ्लेटर्स	१४-२-१९५५	३१-१२-१९६०
३३ ओटोमोबाइल लीफ स्प्रिंग	६-१०-१९५४	३१-१२-१९५६
३४ ओटोमोबाइल स्पार्किंग प्लग	२२-१-१९५५	३१-१२-१९६०
३५ बायसकिल	--- २२-३-१९४७	३१-१२-१९६०
३६ डीजल फ्यूल इंजैक्शन इन्वैल्वमेंट	१९५५-५६	३१-१२-१९६०
३७ पिस्टन असम्बली	--- १९५५-५६	३१-१२-१९५६

टैरिफ कमीशन को चाहिये कि उद्योगों की प्रगति पर निगाह रखे, क्योंकि इनका समाज के प्रति जिसने इनके विकास की लागत वहन की है वडा दायित्व है। टैरिफ कमीशन इनको अपनी वस्तुओं का मात्रा तथा किम्मे के सुधारन में सहायता दे सकता है। उन्हें विदेशी फर्मों से जो (व) बेची ही वस्तुयें बनानी हैं लागत विश्लेषण दिलाया जा सकता है जिसमें उनका अपने लागत व्यय कम करने की प्रेरणा मिले। इन उद्योगों को असामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से भी रोक्ना चाहिये। इसका इन उद्योगों में निवृत्त सम्भव उद्योगों में नियम लाभदायक सिद्ध होगा। उनका जो भाग यह पता पड़ सकता है कि जिन उद्योगों के विकास के लिए उसने त्याग दिया था उनकी प्रशंसा क्या दशा है। इस हेतु टैरिफ कमीशन को इन उद्योगों में सम्बन्धित विवरण समय समय पर प्रकाशित कराते रहना चाहिये।

सरक्षण का भविष्य—

निस्सन्देह यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति सन् १९५६ की घोषणा में देश के औद्योगिक विकास में सरक्षण की जो महान् भूमिका है उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। सन् १९५८ की औद्योगिक घोषणा में भारत सरकार की सरक्षण नीति की चर्चा निम्न शब्दों में की गई थी— देश की प्रशुल्क नीति का मंचालन इस प्रकार किया जायगा कि अनुचित विदेशी प्रतस्पर्धा को रोक धाम हो और भारतीय साधनों का उपभोक्ता पर अनुचित भार डाले बिना अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। प्रथम पंच वर्षीय योजना में केवल इतना कहा गया था कि टैरिफ कमीशन द्वारा विचार करने के बाद उन उद्योगों को जिनमें पूँजी का भारी विनियोग होगा तथा नई टेक्नीक प्रयुक्त होगी पहले से ही सरक्षण का भरोसा दिया जायगा। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी सरक्षण के महत्त्व पर कम ध्यान दिया गया है।

लेकिन नियोजित अथ व्यवस्था प्रशुल्क नीति को कई प्रकार से प्रभावित करती है जिससे सरक्षण का नियोजित अथ व्यवस्था स्पष्ट सम्बन्ध होने का पता चलता है। प्रशुल्क नीति पर नियोजित अथ व्यवस्था के निम्न प्रभाव पहले हैं—

(१) उद्योगों के विकास के लिये पंच वर्षीय योजनाओं में प्राथमिकताओं का जो क्रम निर्धारित किया गया है उसमें प्रशुल्क अधिकारियों को अपनी नीति का निर्माण करने में सहायता मिलती है।

(२) नियोजन के अन्तर्गत जिन सीमा तक औद्योगिक विनियोग कम आर्थिक लाभ वाले उद्योगों से हटकर अधिक आर्थिक लाभ वाले उद्योगों में लगता है उन सीमा तक समाज में सरक्षण से पहले वाले भार में कमी आ जाती है।

(३) प्रशुल्क आयोग को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि चूँकि नियोजन से विकेन्द्रीयकरण और प्रादेशिक विकास का प्रोत्साहन मिलता है इसलिए भी सरक्षण का समाज पर भार कम हो जाता है।

(४) चूँकि देश ने राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में समाजवादी समाज की रचना स्वीकार कर ली है, इसलिए सरकार के ऊपर आधारभूत एवं 'बुन्जी'—उद्योगों के विकास का दायित्व विशेष रूप से आ पड़ा है। अतः इस सीमा तक निर्भर उद्योगों को दी जाने वाली सहायता में स्वतः कमी होकर जनता के ऊपर सरक्षण का भार कम हो जायगा।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरक्षण का प्रश्न को औद्योगिक विकास की योजना में एक निश्चित स्थान दिया जाना चाहिये। इसमें कोई सदेह नहीं है कि प्रशुल्क नीति औद्योगिक विकास का एकमात्र साधन नहीं है, लेकिन प्रायः सरकार द्वारा औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस पर अत्यधिक निर्भरता रखी गई है। जैसा कि १९४६-५० के प्रशुल्क आयोग (Fiscal Commission) की रिपोर्ट में कहा गया था, उद्योगों के सरक्षण के प्रश्न को आर्थिक विकास की योजना से स्पष्ट रूप में सम्बन्धित कर देना चाहिए, अन्यथा सरक्षण का भार असमान रूप में वितरित होगा और उद्योगों के विकास में समन्वय नहीं हो पायेगा। केवल सरक्षणात्मक करों के लगाने से ही पूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हो सकेगा।

टैरिफ कमिशन को चाहिये कि सरक्षित उद्योगों की प्रगति का विस्तार से विश्लेषण एवं अध्ययन करे। जो उद्योग संरक्षण पाने के लिये बड़ा प्रयत्न करते हैं और सरक्षण मिल जाने पर वस्तु-स्थिति से लापरवाह हो जाते हैं उन पर कमीशन को विशेष कार्यवाही करनी चाहिये। यद्यपि शिशु उद्योगों के सरक्षण की समस्या देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथापि सरक्षण जारी रखने के लिए इन पर यह प्रतिबन्ध लगाना उचित होगा कि उनका उत्पादन की किस्म एवं मात्रा में बराबर सुधार होता जाना चाहिए। उपभोक्ताओं से यह प्रार्थना नहीं की जा सकती कि वे अनार्थिक उद्योगों के विकास का भार उठाएँ। ऐसा वे तभी कर सकते हैं जबकि उन्हें निकट भविष्य में उनके अपने ही पैरों पर खड़े होने की सम्भावना प्रतीत हो।

विदेशों में प्रशुल्क सम्बन्धी कार्य प्रणाली, नियमों एवं संस्थाओं का अध्ययन, प्रशुल्क नीति के अन्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन, विश्लेषण एवं अध्ययन करना भी कमीशन का एक उचित कर्तव्य है। कमीशन को चाहिये कि जनता के लाभार्थ इन निष्कर्षों का प्रकाशित करता रहे। इन अध्ययनों से कमीशन को भी इस बात की जानकारी हो सकेगी कि प्रशुल्क नीति में कौन कौन सी दुर्बलताएँ हैं और इसमें क्या उचित परिवर्तन किये जा सकते हैं।

अतः यह ठीक ही कहा गया है कि 'प्रशुल्क सरक्षण और मूल्य नियन्त्रण की सुविचारित एवं सुसंवाहित नीतियाँ औद्योगिक विस्तार एवं स्थायित्व के काम में महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं। प्रशुल्क सरक्षण के कारण ही भारत के उद्योगों की विद्यमान दशा प्राप्त हुई है और जैसे-जैसे नियोजित आगार पर औद्योगिक विकास

की प्रगति होती जायेगी वैसे-वैसे टैरिफ कमीशन के कर्तव्यों की सीमा और महत्व में वृद्धि होती जायेगी ।

भारत में वर्तमान वाणिज्यिक नीति

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी व्यापारिक व वाणिज्यिक नीति का स्वरूप ऐसा हो जो देश के नियोजन में सक्रिय रूप से सहभाग दे सके । द्वितीय व तृतीय योजना अवधि में हमें अधिक मशीनरी, उपकरण, धातुएं, कपास तथा रासायनिक पदार्थों का आयात करना पड़ेगा । प्रथम योजना की अपेक्षा हम कम मात्रा में खाद्यान्न, चीनी, कागज आदि का निर्यात करेंगे । हमारी आयात नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वस्तु का कोटा निश्चित है, न केवल आन्तरिक उपयोग के लिये वस्तु की आवश्यकता के आधार पर बल्कि इस बात पर भी कि यह आवश्यकता पूर्णतः अथवा अंशतः देश के उत्पादन से ही पूरी हो सकती है, अथवा नहीं । सामान्य नियम यह है कि यदि भारत किसी वस्तु के सम्बन्ध में कुल मांग को पूरा करने में समर्थ है, तो वह प्रशुल्क कर ६६% या १००% तक बढ़ा दिया गया है, और यदि अमुक भारतीय उद्योग बचल अवस्था में ही मांग को पूरी कर सकता है तो वहां आयात कोटा निर्धारित किया गया है । यदि उद्योग को अधिक संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह प्रशुल्क आयोग से प्रार्थना कर सकता है । ऐसी योजना के अन्तर्गत कुछ उद्योगों में अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आई है । उदाहरण के लिये, हमारा साइकिल उद्योग आज ६६ लाख साइकिल प्रतिवर्ष बनाता है, जबकि सन् १९५१ में केवल १ लाख साइकिलों का निर्माण होता था ।

आज हमारे निर्यात का स्वरूप भी बदल गया है । हम केवल कच्चा माल ही नहीं, बल्कि निर्मित व अर्द्धनिर्मित पदार्थ भी निर्यात करने लगे हैं । अनेक भविष्य में हमें दुनिया के अन्य औद्योगिक राष्ट्रों (विशेषतः जापान, चीन, यू० के० आदि) से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा । इसी हेतु निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (Export Promotion Councils) की स्थापना की गई । लाख-प्रतिभूतियों का चलन किया जा रहा है । द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते किये जा रहे हैं । जिन देशों में व्यापार राज्य के हाथ में है, उनके साथ अधिक अनुकूल शर्तों पर व्यापार करने के लिये राजकीय व्यापार निगम (State Trading Corporation) की स्थापना की गई है । हमारे विदेश-स्थित व्यापार दूतावास भी इस दशा में प्रयत्नशील हैं तथा राष्ट्रीय उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

हमारी भावी वाणिज्यिक नीति के निम्न लक्ष्य होने चाहिये—

- (1) द्वितीय व तृतीय योजनाओं में औद्योगीकरण, उत्पादन व उपभोग के लक्ष्य पूरे होने चाहिये ।
- (ii) निर्यात का स्तर ऊँचा रहना चाहिये ।

- (111) व्यापार-संतुलन का घाटा उपलब्ध विनिमय-क्षेत्रों से बहुत अधिक नहीं होना चाहिये ।
- (112) आयात-निर्यात के उद्देश्यों व योजना के उद्देश्यों में एकरूपता रहनी चाहिये ।
- (113) अन्य देशों के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बार-बार टूटने नहीं चाहिये ।

व्यापार एवं प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते

(General Agreement on Trade and Tariffs)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सच के चार्टर को द्वितीय धारा के उद्देश्य (कि सदस्यगण आयात निर्यात करो तथा व्यापारिक प्रतिबन्धों को न्यूनतम करेंगे) को सम्मुख रख कर विभिन्न सदस्य देशों ने सन् १९४७ में ही एक सम्मेलन किया और उसके जो निर्णय हुये उनका समावेश जी० ए० टी० टी० में कर लिया गया । यह समझौता १ जनवरी सन् १९४८ में व्यवहार में लाया गया । इस समझौते में यह निश्चय किया गया कि यदि एक देश किसी दूसरे देश को प्राशुल्किक करो म कुछ छूट देता है, तो उसे यह छूट अन्य सदस्य देशों को भी देनी पड़गी । अर्थात् सदस्य देश किसी भी देश के साथ पक्षपात-पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते ।

इस समझौते के अनुसार निम्न लक्ष्य सामने रखे गये—

जी० ए० टी० टी० के लक्ष्य—

(१) विश्व के विभिन्न देशों में पारस्परिक भेद-भाव को हटाकर मित्रता की भावना पैदा करना ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्न-भिन्न देशों द्वारा आयातों पर लगे हुये करों को हटवा कर व्यापार की उत्थिति करना ।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिये सभी सम्भव नियमों को बनाना ।

प्रिपरेटरी कमेटी के १८ सदस्यों के अतिरिक्त पाकिस्तान, बर्मा लका, सीरिया और दक्षिणी रोडेजिया ने भी समझौते में भाग लिया । बाद में कुल सदस्यों की संख्या ३६ हो गई । इसके अनुसार भिन्न भिन्न देशों के बीच १२६ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते हुए और सभी सदस्यों ने अपने प्रशुल्क में भिन्न भिन्न प्रतिशत में कमी की है । ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व अन्य देशों ने अपने प्राशुल्किक दरा में इतनी कमी की कि अन्त में वे न्यूनतम सीमा तक पहुँच गई । इन समझौतों ने यह सिद्ध कर दिया कि सभी दल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के पक्ष में है ।

सन् १९४९ में, दूसरी कान्फ्रेंस एनेकी (फ्रांस) में हुई, जिसमें निम्नलिखित नये देशों ने भी भाग लिया —

डेन्मार्क, ग्रीस, फिनलैंड, स्वीडन, इटली, हेटी, साइप्रिया, निकारागुए, डोमिनियन रिपब्लिक, टर्कमेनी। इन नये सदस्यों को समझौते में सम्मिलित करने

के लिये एक प्रोटोकल पर हस्ताक्षर किये गये और २० मई सन् १९५० से यह किमा गया। भारत ने इन दोनों सम्मेलनों में भाग लेकर विभिन्न देशों में व्यापार सम्झौते किये और उनके अनुसार रियायतें दी और प्राप्त की।

तत्पश्चात् अप्रैल सन् १९५१ में टोरन्टो (कैनाडा) में तृतीय सम्मेलन हुआ। १२ देशों ने भाग लिया था और १२७ द्विपक्षीय सम्मेलन हुए। भारत ने भी सम्मेलन में भाग लिया। पुराने देशों के अनिश्चित ६ नये देश भी इस सम्मेलन सम्मिलित हुये। पुराने सम्मेलनों (जेनेवा और एनेकी) की अवधि बढ़ा कर सन् १९६० तक कर दी गई। कुछ पुरानी रियायतें वापस कर ली गईं तथा कुछ नवीन रियायतें विषय में सम्मेलन हुए।

भारत और जी० ए० टी० टी०—

जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत भारत को प्रशुल्क सम्बन्धी जो रियायतें हैं उनकी भारतीय प्रशुल्क मण्डल ने पूर्ण रूप से जाँच कर ली है। इस मण्डल के अनुसार निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता है कि उन रियायतों का भारत के व्यपार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मण्डल ने इनका अवश्य निश्चय के साथ कह दिया है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि (I. T. T.) का भविष्य जब तक स्पष्ट ज्ञात न हो। भारत को जी० ए० टी० टी० के विरुद्ध न जाना चाहिये। प्रशुल्क मण्डल ने यह कहा है कि प्रत्येक व्यवहार में भारत निम्नलिखित सिद्धान्तों का ध्यान रखे,—

(१) निम्नलिखित वस्तुओं पर रियायतें देने की चेष्टा करनी चाहिये,—

(अ) कच्चे माल की अपेक्षा निर्मित माल-पर,

(आ) उन वस्तुओं पर जो विश्व की वैसी ही वस्तुओं से प्रतिद्वन्द्वता कर

(इ) इन वस्तुओं के सम्बन्ध में जो विश्व में उनकी स्थानापन्न वस्तुओं प्रतिद्वन्द्वता करे।

(२) निम्नलिखित वस्तुओं पर ही रियायतें देनी चाहिये :—

(अ) उत्पादक माल।

(ब) अन्य मालीनरी तथा साजसामान।

(स) प्रमुख कच्चा माल।

प्रशुल्क मण्डल ने निम्नलिखित सुझाव और दिये —

(१) व्यापारिक सम्मेलन करते समय भारत का इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगों की उन्नति परमावश्यक है। अतः उनके विषय में अधिक से अधिक रियायतें देने का प्रयत्न करना चाहिये।

(२) जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारिक सम्मेलन (जी० ए० टी० टी० सम्मेलन) हुआ था, उनके प्राधान्य व निशान पर विशेष निगाह रखनी चाहिये प्रति ६ माह के पश्चात् उनसे सम्बन्धित जाँचें भी छापने चाहिये।

भारत को जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की छूट मिली—सूती वषड़ा, चमड़ा, नारियल की चटाइयाँ, मसाले, जूट का सामान, अभ्रक, कालीन काजू आदि । भारत ने निम्न देशों के साथ इसी समझौते के अनुसार व्यापारिक सन्धियाँ की हैं—चीन, कनाडा, सं० रा० अमेरिका, जेकोस्लोवाकिया, लेवनान, सीरिया, क्यूबा, न्यूजीलैण्ड, इटली, स्वीडन, फिनलैण्ड, डेन्मार्क इत्यादि ।

भारत में निम्न लिखित वस्तुओं के आयात पर इसी समझौते के अनुसार छूट मिली है । ताबा, पेट्रोल, रागा अभ्रक, पत्थर शक्कर बनाने की मशीन, ट्रैक्टर, तेल पेरने की मशीन हल, मोटर हवाई जहाज, चावल, घड़ियाँ आदि ।

भारत को जी० ए० टी० टी० के सदस्य बनने से काफी लाभ प्राप्त हुआ है और भविष्य में अधिक लाभ मिलने की आशा है ।

STANDARD QUESTIONS

- 1 In what respects does the new policy of developmental protection of the Fiscal Commission of 1949-50 differ from old policy of Discriminating Protection ?
- 2 Carefully examine the present Tariff Policy of the Govt of India. Is it conformity with the interests of the country ?
- 3 Briefly examine the functions and working of the Tariff Commission 1952, and comment upon the future of Protection
- 4 Write an essay on the "Present Tariff and Commercial Policy" of the Govt of India
- 5 Write a full note on G A T. T

करारोपण एवं उद्योग

(Taxation and Industry)

प्रारम्भिक—

किसी अर्द्ध-विकसित देश की सरकार द्वारा औद्योगीकरण के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपनाए गए आर्थिक एवं वित्तीय साधनों में प्राशुत्तिक प्रेरणाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जो कि विकास में सहायक हो। इस प्रकार की कर प्रणाली के मुख्य उद्देश्य निम्न होने चाहिए — (i) सावजनिक क्षेत्र के प्रोजेक्टों के लिए पर्याप्त धन जुटाना, (ii) नये व पुराने दोनों ही उद्योगों में विनियोग की वृद्धि कराना (iii) द्वितीय-त्मक उद्योगों (Secondary industries) में लगे हुए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की उत्पत्ति में वृद्धि करना, (iv) आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को कायम रखना, (v) अनुत्पादक कार्यों में सट्टे के व्यवहारों को निरुत्साहित करना, और (vi) प्राइवेट सेक्टर को चालू एवं विनियोग दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने में सहायता देना। ये उद्देश्य तब ही पूरे हो सकते हैं जबकि कर सम्बन्धी कानून वैज्ञानिक ढंग पर बनाए जायें। इसके लिए पर्याप्त सांख्यिकी नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विशेषतः अर्द्धविकसित देशों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से प्राशुत्तिक प्रेरणाओं (Fiscal incentives) का महत्त्व बहुत बढ़ गया। प्रस्तुत अध्याय में उद्योग और कर प्रणाली के सम्बन्ध की विस्तृत व्याख्या की गई है।

कर प्रेरणाओं के रूप (Forms of Tax Incentives)—

कर-प्रेरणाओं के अनेक रूप हो सकते हैं। कौन सी कर प्रेरणा दी जाय, इसका निर्णय कई बातों पर निर्भर होता है, जैसे कर सार्वभौमिक कर का स्थान, बजट-स्थिति, देश की आर्थिक परिस्थितियाँ आदि। कर-रियायतों से सरकारी आय पर प्रभाव तो पड़ता ही है, विकास योजनायें भी अप्रभावित नहीं रहती हैं।

कर-प्रेरणाओं से सरकारी आय में होने वाली हानि को तभी उचित ठहराया जा सकता है जबकि वह उत्पादक पूँजी की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि ला सके। इसके अतिरिक्त कर-संरचना में पर्याप्त लोच भी होनी चाहिए, ताकि बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े। बार-बार संशोधन करने से औद्योगिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

कर सम्बन्धी रियायतों का उद्देश्य विनियोग सम्बन्धी निर्णयों को प्रभावित करना हो सकता है। इन रियायतों का सम्बन्ध लागत की मदों से हो सकता है, जैसे लाइसेन्स फीस, उत्पादन कर, सम्पत्ति कर। ऐसी दशा में उत्पादन व्यय कम हो जायेंगे। यदि लाभ पर करों के सम्बन्ध में रियायत दी जाय, तो विनियोगों से आय अधिक होने लगेंगी। यदि हानि को अगले वर्षों में दिखाने की छूट मिले, तो इसका प्रभाव नई समस्याओं से सम्बन्धित जोखिम को कम करना होता है। यदि पुनर्विनियोजित लाभों पर आय कर न लिया जाय, तो औद्योगिक विकास को बहुत प्रोत्साहन मिलता है।

कर की दर (Tax rate) में कमी समान रूप से हो सकती है या विभिन्न उपक्रमों अथवा क्रियाओं के लिए विभिन्न मापदण्डों में की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जो सस्याय एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय कमाती हैं उनको यह कमी नहीं की जाय अथवा पुनर्विनियोजित लाभ के अनुपात की वृद्धि के साथ बढ़ा दी जाय। कर-आधार (Tax base) में कमी का उद्देश्य निर्धारित वांछित व्ययों को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार का प्रोत्साहन निम्न ४ तरीकों से दिया जा सकता है—(अ) कुछ विनियोगों के लिए ह्रास की ऊँची दर स्वीकार करना, (ब) पूँजीगत व्ययों के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक छूट देना, (स) विशेष विनियोगों को जल्दी ही अपलिखित कर देने की अनुमति देना, तथा (द) अनुसंधान आदि के लिए छूट स्वीकृत करना।

कर सम्बन्धी प्रेरणाओं का उद्देश्य कभी-कभी भावी विनियोगों को प्रभावित करने का भी होता है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों के पास बचत है उन्हें औद्योगिक समस्याओं में विनियोग के लिए प्रेरित करके एक स्थानीय पूँजी बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के हेतु विशेष प्रासुक्तिक उपाय किये गये हैं। लेकिन जो कर-प्रेरणाएँ (Tax incentives) वितरित लाभों पर कर रियायतें देकर बाहरी विनियोगों को आकर्षित करने का उद्देश्य रखती हैं वे उन कर-प्रेरणाओं के विपरीत हैं जिनके उद्देश्य लाभ के वितरण को अप्रोत्साहित करके पुनर्विनियोजन की वृद्धि करना है। किसी भी विशेष दशा में कौन सी कर-प्रेरणा उपयुक्त होगी, यह परिस्थितियों पर निर्भर है।

अर्द्धविकसित देशों में कर प्रणाली विदेशी विनियोगों का ध्यान रखकर बनाई जाती है। अर्द्धविकसित देशों में औद्योगीकरण की गति बढ़ाने के हेतु

विदेशी पूँजी के आगमन को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक प्रेरणाएँ देना आवश्यक हो जाता है। यह देना गया है कि जहाँ विदेशी विनियोजक स्थानीय सहायक कम्पनियों के द्वारा कार्यशील होते हैं वहाँ कर सम्बन्धी रियायतें अधिक अमर दिखलानी हैं क्योंकि सहायक कम्पनियों की आय पर विनियोजक के गृह-देश में प्रायः कर नहीं लगता। यही कारण है कि इस प्रकार का संगठन उन्नत देशों में अधिक बनाया जाने लगा है। इनमें धरेलू करों से बचत हो जाती है।

पैनल्टी कर तब लगाए जाते हैं जब कि सरकार की औद्योगीकरण सम्बन्धी नीति के विरुद्ध कार्य किया जाय। परिवर्तनीय व्यवहारों के सम्बन्ध में पैनल्टी कर लगाना और वसूल करना एक कठिन समस्या है, क्योंकि ऐसे अधिकांश व्यवहार छिपा कर किये जाते हैं।

भारत में कर-संरचना (Tax Structure in India)—

भारत में वर्तमान कर-संरचना निम्न घटकों पर आधारित है — (i) वह पञ्च-वर्षीय योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिये अधिकतम कोषों का संग्रह करने में सहायता करती है। (ii) यह विकास व्यय से उदय होने वाली आय की वृद्धि में सहायता देती है। (iii) आय और सम्पत्ति के वितरण की असमानता को दूर करने में उमसे सहायता मिलती है। (iv) यह वांछित उद्योगों में ही विनियोजन करने के लिए प्रोत्साहन देती है और (v) कर से बचन के सब अवसरों को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य है। वास्तव में करारोपण सरकार का एक प्रभावशाली साधन है, जिसके द्वारा वह राष्ट्रीय प्रसाधनों को नियोजित प्रोजेक्टों में लगवा सकती है। किन्तु इस साधन का प्रयोग करने के लिए चतुरता व सूझ-बूझ की आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार ने एक 'समन्वित कर प्रणाली' (Integrated Tax System) अपनाई है, जिसने करारोपण के क्षेत्र को विस्तृत करने के साथ-साथ गहरा भी किया है, अर्थात् नए कर लगाने के साथ-साथ पुराने करों की दरें भी बढ़ाई गई हैं। यह सच है कि विकास की गति को तीव्र करने के लिए करों से आय में वृद्धि होनी चाहिए, किन्तु इसके साथ ही करदान क्षमता को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

भारत में करा में कुल आय राष्ट्रीय आय की ७ या ८% है, जब कि यह प्रतिशत जापान में २३, इंग्लैंड में ३५, आस्ट्रेलिया में २२ और लक्सा में २३% है। यदि करों की आय का प्रतिशत भारत में इतना ही कम बना रहा, तो विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएँ पूरी न हो सकेंगी। यही मत कर जांच आयोग ने प्रगट किया था।^१ किन्तु अन्य देशों में कर-भार की तुलना करते समय यह बात ध्यान में रखनी

* "Indian taxation on the basis of its existing structure and rates has not fully tapped the taxable resources of the country" (Taxation Enquiry Commission).

चाहिए कि भारत में करदाताओं की प्रतिगत सराया अन्य प्रगतिशील देशों की अपेक्षा बहुत कम है।

उद्योगों पर करारोपण में सरकार को काफी आय हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार सन् १९५८-५९ में केन्द्र एवं राज्यों की सरकारों को करो से होने वाली कुल आय (१,०५० करोड़ रु०) में से ८३७ करोड़ रु० की आय औद्योगिक क्षेत्र से ही प्राप्त हुई थी। औद्योगिक क्षेत्र पर कर भार बराबर बढ़ रहा है, किन्तु उसका अधिकांश भाग उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है। इसका प्रमाण यह है कि कर बढ़ने के साथ-साथ वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते जा रहे हैं। करो का उद्योगपतियों अथवा उद्योगों के लाभ पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

संस्थागत करारोपण (Corporate Taxation) —

औद्योगिक उपक्रमों का करारोपण एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस पर गत वर्षों में बड़ी चर्चा हुई है। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि संस्थागत उपक्रम (Corporate enterprises) देश के औद्योगिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अतः करारोपण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जोकि इनको कुप्रभावित न करे। नीचे संस्थागत उपक्रमों की करारोपण व्यवस्था के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

कर-योग्य आय की गणना —

आय कर अधिनियम के अनुसार जिस आय पर कर लगाया जाता है उसकी गणना इस प्रकार की जाती है कि कम्पनी को कई लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त, उन व्ययों की भी छूट दी जाती है जो कि कम्पनी प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यापार के सम्बन्ध में करती है। नीचे कुछ प्रमुख कर सम्बन्धी रियायतों का उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। —

(१) नई औद्योगिक संस्थाओं को छूट (Exemption for new Industrial undertakings) —

नई औद्योगिक संस्थाओं को एक महत्वपूर्ण छूट दी गई है, जो यह है कि जिस वर्ष में उन्होंने व्यापार आरम्भ किया है उससे अगले ५ वर्षों के लिये उसको ६% पूँजी के बराबर लाभ पर कोई आय कर या अतिरिक्त

- देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली ६ मुख्य कर-छूटें
१. नई औद्योगिक संस्थाओं को छूट।
 २. कारपोरेशन टैक्स से छूट।
 ३. विकास सम्बन्धी छूट।
 ४. ह्रास सम्बन्धी छूट।
 ५. अनुसंधान व्यय की अनुमति।
 ६. सम्पत्ति कर से मुक्ति।

कर नहीं लगेगा। इस छूट को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त

संस्था भारत में ही कार्य करती हो तथा एक विद्यमान संस्था का विभाजन करके निर्मित न हुई हो।

(२) कारपोरेशन टैक्स से छूट (Exemption from Corporation Tax)--

कम्पनियों अपने कोषों को भारत में कुछ आधारभूत उद्योगों में विनियोज करने के लिए उत्साहित हो, इस हेतु यह आयोजन किया गया है कि कम्पनियों को ३१ जनवरी सन् १९५२ के बाद स्थापित हुई किसी भारतीय कम्पनी से प्राप्त होने वाले लाभों पर कारपोरेशन टैक्स (कानूनी भाषा में सुपर टैक्स—अतिरिक्त कर) नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते वह भारतीय कम्पनी कुछ निर्दिष्ट उद्योगों में ही पूर्णतः या अंशतः संलग्न हो। इस समय निम्न उद्योग उक्त भाष्य के लिये निर्दिष्ट किए गए हैं—कोयला, लोहा एवं स्पात, मोटर, स्प्रूस रसायन, प्लूम मशीनरी, शक्ति उत्पादन के लिए मशीनरी व साज-सामान, कागज, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन्जन, रॉलिंग स्टाक आदि। समय-समय पर इस सूची में आवश्यकतानुसार वृद्धि भी कर दी जाती है। सन् १९५७-५८ में एक नई छूट यह दी गई कि किसी भारतीय सहायक कम्पनी से प्राप्त होने वाले लाभों पर विनियोजित कम्पनी अथवा प्रधान कम्पनी (Principal company) को १०% की दर से कारपोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, जब कि उसे अपनी अन्य आय पर २० या ३०% टैक्स देना पड़ता है।

(३) विकास सम्बन्धी छूट (Development Rebate)--

मार्च सन् १९५४ के पश्चात् उद्योग में लगाई गई समस्त नई मशीनरी पर सन् १९५५ से २५% लागत के बराबर विकास सम्बन्धी छूट दी जा रही है। यह छूट घिसाई की छूट के अलावा है। जहाजी कम्पनियों को विकास सम्बन्धी छूट ४०% लागत के बराबर दी जाती है। जबकि घिसाई छूट का प्रभाव तो कर-दायित्व को स्थगित करना है, विकास सम्बन्धी छूट विनियोजक के लिये एक प्रत्यक्ष कर-छूट है, क्योंकि भावी घिसाई छूट मालूम करने के उद्देश्य से उसे सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य (Written down value) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। घिसाई छूट एवं विकास सम्बन्धी छूट दोनों का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि कर-दाता अपलिखित करने की गति को तेज करने के लिए प्रोत्साहित होता है तथा रेवेन्यू से सम्पत्ति की पूर्ण लागत काटने के अलावा २५% अधिक छूट भी प्राप्त कर लेता है।

(४) घिसाई सम्बन्धी छूट (Depreciation Allowance)--

सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई इमारतों, मशीनों व प्लान्टों पर 'साधारण घिसाई' के रूप में निर्दिष्ट दरों से छूट देने का आयोजन किया है। इस छूट के अतिरिक्त घिसाई सम्बन्धी कुछ अतिरिक्त छूट भी दी गई है जो सम्पत्तियों के क्रय एवं व्यापार में उनके प्रयोग की तिथि से ५ कर-वर्षों के भीतर प्राप्त की जा सकती

है, बाद में नहीं। अतिरिक्त छूट सामान्य छूट के बराबर दी जाती है। कुछ विशेष प्रकार की मशीनों के लिए भी, जो कि ओवर टाइम कार्य करती है, अतिरिक्त छूट देने की व्यवस्था है। यदि किसी वर्ष के लाभ इतने पर्याप्त नहीं है कि उक्त दोनों ही प्रकार की छूट दी जा सके, तो न्यूनता को असीमित अवधि तक आगे ले जाया जा सकता है। इन सब छूटों का सामूहिक प्रभाव कर योग्य आय को, जिस पर कर की दर लागू की जाती है सीमित रखना है।

(५) अनुसंधान व्यय की अनुमति (Expenditure on Research Allowed)—

व्यापारिक सस्थाओं द्वारा वैज्ञानिक, साहित्यिकीय एवं सामाजिक अनुसंधानों पर, जो कि उनके व्यवसाय से सम्बन्ध रखते हैं, जो व्यय किया जाय, उसे पांच वर्षों में काटने की अनुमति दी गई है।

(६) सम्पत्ति कर से मुक्ति (Exemption from Wealth Tax)—

नई औद्योगिक सस्थाओं को सम्मेलन से ५ वर्षों के भीतर अपनी वास्तविक कीमत पर सम्पत्ति कर देने से मुक्त रखा गया है।

उक्त रिषायतों के कारण भारत में औद्योगिक उपक्रमों पर कर-प्रभाव कुछ सीमा तक हलका हो गया है। ये रिषायतें विदेशियों और विदेशी उपक्रमों को भी प्राप्त हैं।

सामूहिक करों का प्रभाव (Incidence of Corporate Taxes)—

भारत में औद्योगिक सामूहिक उपक्रमों (Corporate enterprises) को अपने लाभों एवं सम्पत्तियों पर निम्न कर चुकाने पड़ते हैं, जिनकी बारे प्रतिवर्ष फाइनेन्स एक्ट द्वारा निश्चित की जाती है —

(१) आय कर (Income Tax)—

कम्पनियों को उनके सम्पूर्ण कर-योग्य लाभों पर बेसिक दर से जो कि इस समय ३०% है, आय कर देना पड़ता है। आय कर पर ५% सर-चार्ज भी लगाया गया है। इस प्रकार कर-योग्य आय पर आय-कर की वास्तविक दर ३१.५% है। इसके अतिरिक्त कम्पनियों को सुपर टैक्स भी देना पड़ता है। सुपर टैक्स का ही दूसरा नाम कारपोरेशन टैक्स है। सुपर टैक्स की बेसिक दर ५०% है, लेकिन इसमें से कुछ छूट दी जाती है। सुपर टैक्स पर कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ता। यदि छूट देने के बाद सुपर टैक्स की कुछ दर २०% मानी जाय, तो आय कर एवं सुपर टैक्स का सम्मिलित भार इस समय ५१.५% होता है, जबकि पिछले वर्षों में वह ४५% रहता था।

(२) विशेष पैनल्टी-कर (Special Penalty Taxes)—

कम्पनियों पर तीन विशेष पैनल्टी कर लगे हुए हैं —

(i) अतिरिक्त लाभांश-कर (Excess Dividends Tax)—

कम्पनियों को अपने घोषित लाभांश पर १०% की दर से, जबकि लाभांश

६% से १०% के बीच में हो, और २०% की दर से जबकि लाभार्जित दत्त पूँजी के १०% अधिक हो, अतिरिक्त लाभार्जित कर देना पड़ता है ।

(ii) धारा २३-अ वाली कम्पनियों पर अतिरिक्त सुपर टैक्स (Additional Super Tax on Sec. 23-A Companies)—
 आय कर अधिनियम की धारा २३-अ में वर्णित कम्पनियों को जिनमें जनता का कोई महत्वपूर्ण हित नहीं है, अपने 'वितरण योग्य लाभों' का प्राद्विष्ट दर में (४५% से १००% तक) लाभार्जितों के रूप में अनिवार्य वितरण करना होगा । यदि ऐसा नहीं किया गया तो न्यूनतम सीमा से ऊपर अवितरित लाभों पर ३७ ½% एवं ५०% की दर से अतिरिक्त सुपर टैक्स जुर्माने के रूप में देना होगा । इस धारा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कम्पनियों के लिये न्यूनतम प्रतिशत इस प्रकार निर्धारित किए गये हैं — विनियोजित कम्पनी १००%, निर्माणी कम्पनी, खनिज कम्पनी या शक्ति उत्पादन कम्पनी ४५%, स्थिर सम्पत्तियों की वास्तविक लागत या कम्पनी की दत्त पूँजी (शेयर होल्डरों की ऋण पूँजी को सम्मिलित करते हुए) से अधिक कोष एवं एकत्रित लाभ रखने वाली कम्पनी ६०%, अन्य कोई कम्पनी ६०% । इस नियम का उद्देश्य कम्पनियों को अपने कोषों का निर्माण करने के लिए एक विशेष प्रतिशत से अधिक लाभ रखने से रोकना है ।

अनेक उद्योगपतियों ने धारा २३-A को समाप्त करने की मांग की है । उनका कहना है कि धारा २३-A कम्पनियाँ कोरपोरेट सेक्टर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और उद्योग व वाणिज्य के विकास में तथा पूँजी के निर्माण में भी बहुत सहयोग दे रही हैं । उक्त धारा इन कम्पनियों के लिये बहुत हानिकारक है ।^१ इसके विपरीत, कर आयोग ने इस धारा का समर्थन करते हुए कहा है कि इन कम्पनियों के प्रबंधकों को कम्पनी के लाभों के बटवारे को इस प्रकार घटाने या स्थगित करने के अधिकार प्राप्त हैं कि उनका अपना कर दायित्व काफी सीमा तक कम हो जाय । विभाजन से बचाया गया लाभ बाद में उनके उपभोग की वित्त-व्यवस्था करने में या विनियोगों के इन्टरलॉकिंग में सुविधा के लिये प्रयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त इन कोषों को, उनके वास्तविक स्वामियों को लागू होने वाली वैयक्तिक दरों पर टैक्स का भुगतान किये बिना ही, निमित्त होने देने का अर्थ है कुछ लोगों के हाथों में सम्पत्ति केन्द्रित होने देना ।

* "There is more mischievous piece of legislation in the field of taxation on the Statute Book today than section 23-A. This Section is causing untold harm particularly to medium scale industries since the operation of this Section drains away the resources of 1,000 companies." (A D. Shroff)

(iii) बोनस शेयरों पर कर (Tax on bonus shares) —

कम्पनियों को अपने गिजवों या एकनिष्ठ लाभों में से अग्रधारियों को बांटे गये बोनस शेयरों के मूल्य ने २०% की दर से सुपर टैक्स भी देना पड़ता है। यह दर सन् १९५६ के फाइनेंस एक्ट में १२½% थी। सरकार ने कर की मात्रा बढ़ाने के समर्थन में यह तक दिया था कि इसका उद्देश्य अतिरिक्त लाभालाभ पर टैक्स देने से बचने की रोक-थाम करना है। किन्तु यह तक तभी तक साम्यपूर्ण है जब तक कि लाभालाभ दर की गणना दत्त पूँजी के आधार पर की जाय। वास्तव में लाभालाभ दर की गणना कुल नियोजित पूँजी (Total capital employed) के आधार पर की जानी चाहिए क्योंकि कुल पूँजी के नियोजन द्वारा ही लाभ उदय होते हैं। यदि यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जाय तो फिर बोनस शेयरों पर टैक्स लगाने का कोई प्रोचित्य नहीं मिलेगा। यही नहीं बोनस शेयरों पर ऊँचा कर लगाने से कम्पनियाँ लाभों का पूँजीकरण करने में हिचकिचायगी तथा इससे बजाय शयर होल्डरों को अधिक लाभालाभ देना पसन्द करगी। इससे उन्हें हानि पहुँचाने के साथ साथ पूँजी के निर्माण को भी प्रभावित पहुँचेगा। अतः यह कर अधिक प्रगति में बाधक है।

(३) कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax)—

सन् १९४९ के पूर्व कारपोरेट संस्थाओं को पूँजी लाभ कर भी देना पड़ता था। यह कर निम्न कारणों से समाप्त किया गया है—(i) इससे अधिक आय प्राप्त नहीं हो रही थी (कारण सम्पत्तियों के मूल्यों में गिरावट आ रही थी) (ii) विनियोगों पर इसका प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था और (iii) इसके कारण पूँजी बाजार में प्रतिभूतियों के स्वतन्त्र आवागमन में बाधा पड़ती थी। अब सन् १९५६ के फाइनेंस एक्ट द्वारा इसे कुछ परिवर्तनों के साथ पुनः आरम्भ कर दिया गया है। इसका समर्थन करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अब तक इस वर्ग की आय करारोपण से बची हुई थी और वह आर्थिक असमानता को बढ़ाने में प्रमुख कारण है तथा इसकी आय से विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त धन मिल सकेगा।

(४) सम्पत्ति कर (Wealth Tax)—

सभी कम्पनियों को चाहे वे प्रायवट हो या पब्लिक देशी हो या विदेशी सम्पत्ति कर देना पड़ता है। यह कम्पनियों की शुद्ध सम्पत्ति पर लगता है। शुद्ध सम्पत्ति से तात्पर्य कम्पनी की सम्पत्तियों के कुल मूल्य में से कम्पनी के कुल दायित्वों को घटाने के बाद बचने वाली रकम से है। शुद्ध सम्पत्ति के प्रथम ५ लाख रु० पर कोई कर नहीं लगता। इसके बाद शेष कुल रकम पर १% की दर से कर लगता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस कर का समर्थन इस आधार पर किया है कि इससे काफी आय हो जायेगी। किन्तु यह तक सही नहीं है। प्रोफसर काल्डार भी इस टैक्स के विरुद्ध थे। इस वर से न तो अधिक आय होती है और न ही उसे उचित ठहराया जा सकता है। एक ओर तो कम्पनियों को लाभालाभ दर कम रखने के लिए

कहा जाता है, ताकि वे अपने व्यापार के विस्तार के लिए पर्याप्त साधन जुटा सकें, किन्तु, दूसरी ओर उन पर सम्पत्ति कर लगा कर उत्त साधन कम करने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं कम्पनियों की उत्पादन सम्पत्ति पर यह कर लगाना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता।

यह अनुमान लगाया गया है कि सभी प्रत्यक्ष करो से भारत में कोरपोरेट सस्थाओं के कुल लाभों का ६० से ६०% तक कर वी आय के रूप में सरकार को मिल जाता है।

अप्रत्यक्ष करारोपण (Indirect Taxation)—

प्रत्यक्ष करो के अतिरिक्त करारोपण की नवीन व्यवस्था में अनेक उत्पादन-कर (Excise duties) भी सम्मिलित है। पिछले १० वर्षों में उत्पादन-करो से आय ५०.६३ करोड़ से बढ़ कर ३०४ करोड़ रु० हो गई। ये कर अनेक वस्तुओं पर लगे हुए हैं—चीनी, सीमेंट, स्टील इनगोट्स, तम्बाकू, दियासलाई, तिप्रेट, कागज, वनस्पति तेल, मोटर स्पिट आदि। इनमें से अनेक वस्तुएं जीवन की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। उत्पादन करो की वृद्धि के अथ-व्यवस्था पर दो बुरे प्रभाव हुए हैं—प्रथम सभी वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं तथा देश में मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति बढ़ गई है। दूसरे, मध्य वर्गीय एवं स्थिर आय वाले लोगों को अपार कष्ट उठाना पड़ रहा है।

सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जनता पर एक सीमा से अधिक कर नहीं लादे जा सकते। इस सीमा के परे उनके उग्र विरोध का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, वस्त्र व्यवसाय को ही लीजिए। सन् १९५६ तक वस्त्र बाजार में समृद्धि का काल था। उत्पादन बढ़ रहा था मिल वाले धडाधड बिक्री कर रहे थे तथा एक औसत मिल के पास एक या दो हफ्ते के उत्पादन का स्टॉक रहता था। लेकिन उत्पादन करो में अधिक वृद्धि किए जाने पर स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। उपभोक्ता द्वारा इतना विरोध किया गया है कि न केवल कीमतें पहले से भी कम स्तर तक गिर गईं वरन् वस्त्र की मांग में भी काफी बमी हो गई और वस्त्र मिलों के पास काफी स्टॉक एकत्र रहते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पादन कर न केवल पुराने एवं सुस्थापित उद्योगों पर लगाया गया वरन् रेयन सूत उद्योग जैसे नवीन उद्योगों पर भी लगाया गया है। जैसे ही कोई उद्योग लाभ कमाने लगता है वैसे ही सरकार उस पर उत्पादन कर लगाने का प्रयास करती है तथा एक बार लगाने के पश्चात् उसे हटाने में सकोच करती है, भले ही उस उद्योग को हानि होने लगी हो। उत्पादन करो से प्राप्त आय को ऐसे उद्योगों की सहायतायें प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें असाधारण परिस्थितियों के फलस्वरूप हानि उठानी पड़ रही हो।

बिक्री-कर का उद्योग की लांगत सरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

जिन दशाश्रो में औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति के वितरण का मार्ग लम्बा है उन दशाश्रो में बहुत बिन्दु कर लगाने वाले राज्यों में कच्चे माल की लागतें १०% तक बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त बिजली कर एवं मोटर स्ट्रिट कर भी लगे हुये हैं। बिजली कर को 'औद्योगीकरण पर कर' बताया गया है। इस कर के फलस्वरूप एक साधारण व्यक्ति को टैक्नीकल प्रगति के लाभों से वंचित रहना पड़ता है। मोटर स्ट्रिट पर कर भी वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह कर यातायात के विकास में बाधक है।

अधिक अप्रत्यक्ष करों के कारण जनता का जीवन स्तर नीचा हो जाता है, वह अधिक मजदूरी की मांग करती है, इससे उत्पादन-लागतें एवं मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार मुद्रा प्रसार की एक कुप्रवृत्ति कायम हो जाती है।

करारोपण की वर्तमान व्यवस्था की आलोचना—

करारोपण की वर्तमान व्यवस्था में निम्न दोषों के कारण उसकी बड़ी आलोचना की गई है —

(१) यह अस्थिर एवं अनिश्चित है—करारोपण की वर्तमान व्यवस्था बहुत अस्थिर एवं अनिश्चित है। उदाहरण के लिये, आय कर को ही लीजिये। ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जबकि भारतीय आय कर अधिनियम, १९२२ में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता हो। कभी-कभी तो छ महीने भी पूरे नहीं हो पाते कि कोई न कोई संशोधन हो जाता है। यह सच है कि सन्निधिम को अधिक व्यापक ढंग से प्रशासित करने के लिये अथवा उसकी कुरादियों को दूर करने के लिये परिवर्तन किये जा सकते हैं, तथापि अनेक बार परिवर्तन इन आधारों पर नहीं हुये। जैसे, सन् १९५५ के पूर्व करदाता अपनी व्यापारिक हानि की पूर्ति अगले ६ वर्षों तक कर सकता था, लेकिन सन् १९५५ के फायनेन्स एक्ट के एक संशोधन द्वारा व्यापारिक हानियां किसी भी अवधि तक पूरी की जा सकती थीं। सन् १९५७ में पुनः संशोधन किया गया और ८ वर्षों की नई समय-सीमा निर्धारित की गई। वास्तव में करारोपण सम्बन्धी सनियम के क्षेत्र इतने अधिक प्रयोग नहीं होने

करारोपण की वर्तमान व्यवस्था के प्रमुख ६ दोष

- (१) यह अस्थिर एवं अनिश्चित है।
- (२) यह विविधमुखी एवं जटिल है।
- (३) इसमें न्याय एवं औचित्य का अभाव है।
- (४) इसमें व्यावहारिकता की उपेक्षा की गई है।
- (५) इसने अर्थव्यवस्था को मनोबैज्ञानिक हानि पहुंचाई है।
- (६) विदेशी पूँजी के आगमन में बाधक है।

चाहिये, क्योंकि अस्थिरता व अनिश्चितता के कारण सनियम के कुशल कार्यवाहन में बाधा पड़ती है।

(२) यह विविध-मुखी एवं जटिल है—हमारी कर-व्यवस्था अत्यन्त जटिल एवं विविध-मुखी है। इसी कारण कर-प्रशासन की सामान्य कुशलता उचित स्तर की नहीं है। वास्तव में एक कुचक्र या स्थापित हो गया है—अधिक जटिल कर एवं अधिक प्रचार के कर अधिक प्रशासन-व्ययवागी अधिक मानवशक्ति का क्षय अधिक मार्बेजनिक् व्यय एवं अधिक वगारोपण की आवश्यकता। अच्छा हो यदि सरकार कालडार रिपोर्ट (Kaldar Report) की उस मिफारिश को स्वीकार कर ले जिसमें कम्पनियों की आय पर विभिन्न प्रकार के करो का हटा कर केवल एक ही कर ७ आना प्रति रुपया के हिसाब से लगाने को कहा गया है।

(३) इसमें न्याय एवं औचित्य का अभाव है—कर-व्यवस्था में न्याय एवं औचित्य का भी अभाव प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए फायनेन्स एक्ट, १९५८ के अन्तर्गत, एक व्यापारिक मस्या अपनी सम्पत्ति को १० वर्ष के भीतर नहीं बेच सकती। यदि वह १० वर्ष के भीतर अपनी सम्पत्ति को बेच दे, तो उसे विकास सम्बन्धी छूट (Development Rebate) नहीं मिलेगी। व्यवहार में किसी सम्पत्ति को बेचना या रखना व्यापार के लिये सम्पत्ति की उपयोगिता पर निर्भर होता है। अतः सम्पत्ति चाहे उपयोगी रहे या नहीं, १० वर्ष तक न बेचने की शर्त लगाना अनुचित है। यही नहीं इस सम्बन्ध में अपील करने का अधिकार भी छीन लिया गया है।

(४) इसमें व्यावहारिकता की उपेक्षा की गई है—वर्तमान कर-व्यवस्था के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वह भारत में पूँजी के निर्माण की दर पर बुरा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि इसके अन्तर्गत सामूहिक बचत एवं विनियोग के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलता। पिछले ७-८ वर्षों में सस्थागत लाभों के अनुपात में कर की वृद्धि अधिक हुई है। यदि करारोपण इसी गति से बढ़ता रहा, तो, जैसा कि भारत सरकार के कानून मंत्री श्री ए० के० सेन ने बताया है, घटती हुई उपज का नियम लागू होने लगेगा। अर्थात्, यदि कर एक सीमा में अधिक लगाये गये, तो सरकार को अधिक आय प्राप्त होने के बजाय कम आय होने लगेगी। दूसरी ओर, ऊँचे कर साहसियों को निरस्तसाहित भी करते हैं।

(५) इसने गृह्य व्यवस्था को मनोवैज्ञानिक हानि पहुँचाई है—इस मनो-वैज्ञानिक हानि के फलस्वरूप ही लोग भविष्य के सम्बन्ध में अविश्वासी हो गये हैं और आधिक्य कोप रखते हुए भी विनियोग करने में हिचकिचाने हैं। अतः यह आवश्यक है कि कानून इतने अच्छे व उचित हो कि नागरिक प्रसन्नतापूर्वक उनके प्रशासन में सहयोग दें व कि इतने बुरे व अन्यायपूर्ण हो कि कानून के

अनुसार चलने के इच्छुक नागरिक भी उनका पालन करने में कठिनाई अनुभव करें।

(६) यह विदेशी पूँजी के आगमन में बाधक है—अक्टूबर मन् १९५७ में नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च ने विदेशी पूँजी एवं टेक्नीकल ज्ञान के आगमन पर प्रभाव डालने वाले घटकों का बड़ी सावधानी से सर्वे किया और यह पता लगाया है कि भारत में एक विदेशी पूँजी जो लाभ अर्जित करती है उसका केवल ३७.८% (छात्रा के लिए) और ४१.०% (सहायक के लिये) ही वह रख सकती है, जबकि ब्रिटेन में दोनों के लिए ५४.५%, फ्रान्स में ६२.०% और ४६%, अमेरिका में ४८% एवं ३३.६%, जर्मनी में ४१.७% एवं ३०.६%, आस्ट्रेलिया में ६०% एवं ३६% तथा पाकिस्तान में ५०% एवं ६०% रखा जा सकता है। इस प्रकार भारत में विदेशी कम्पनी की विनियोग आय पर विश्व में प्रायः सबसे अधिक कर लगा हुआ है। इससे विदेशी पूँजी के प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई होती है। सन् १९४७-५७ के वर्षों में कुल अमेरिकन प्राइवेट विनियोग (विदेशों में) ४,४०० करोड़ डॉ. था, किन्तु भारत को इसका ५% भी प्राप्त नहीं हो सका।

अभी हाल में भारत का औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को गया था और हमारे वित्त मन्त्री भी विदेशी पूँजी प्राप्त करने की संभावनाओं की छानबीन के लिए विदेशों की यात्रा पर गये थे। इन्होंने जो रिपोर्टें दी हैं उनमें विदेशी विनियोगों को आकर्षित करने तथा धरेलू बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए कर सम्बन्धी उचित सुधार करने पर बल दिया गया है। अभी हाल ही में दोहरे करारोपण को रोकने के लिये भारत सरकार ने कई विदेशी सरकारों के साथ समझौते किये हैं तथा विदेशी विनियोजकों को कर प्रोत्साहन भी दिये हैं।

उपसंहार—कर-व्यवस्था का विवेकीकरण—

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान कर-व्यवस्था में अविलम्ब सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं—

(१) 'एक-कर'—राल्डार रिपोर्ट के सुझावानुसार कम्पनियों की आय पर तरह-तरह के छोटे व अनेक कर न लगा कर एक ही कर ऊँची दर से (जैसे ७ आ० प्रति रुपया) लगा दिया जाय। इससे विभिन्न कर-नियमों की जटिलता में कमी हो जायेगी।

(२) कर सनियम के प्रशासन में सुगमता—कर सनियम के प्रशासन को सुगम बना देना चाहिए, जिससे कर सम्बन्धी मुद्दमैवाजी कम हो जाय। भारत में विदेशी विनियोगों को निरुत्साहित करने वाला सबसे मुख्य घटक कानूनी अडचने ही बताया जाता है।

(३) कर-अधिकारियों के ऐच्छिक अधिकारों में कमी—वर्तमान कर व्यवस्था के अन्तर्गत कर-अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिये हुए हैं, जिनका वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। अतः इन ऐच्छिक अधिकारों में कमी की जानी चाहिए, ताकि करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों में भ्रष्टाचार को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

(४) कर अधिकारियों के वेतन में वृद्धि—कर-अधिकारियों के वेतन में उचित वृद्धि की जाय। इससे उनका नैतिक-स्तर ऊँचा होगा तथा कार्य-कुशलता भी बढ़ेगी।

(५) कर प्रणाली का आर्थिक आधार—सरकार को कर प्रणाली की व्यापक जाच करानी चाहिए। केवल सुविधा के आधार पर कर न लगाकर आर्थिक सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए।

जून सन् १९५८ में भारत सरकार ने एक प्रमुख कर-प्रशासन जाच समिति (Direct Taxes Administration Enquiry Committee) नियुक्त की थी। इसे कर व्यवस्था एवं विधियों की जाच करने तथा उपयुक्त सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इसकी सिफारिशों के अनुसार एक समन्वित कर योजना (integrated scheme of direct taxation) लागू की जा रही है। कमेटी ने कर-अधिकारियों की संख्या, उनके अधिकारों, प्रत्यक्ष कर परामर्शदाता समिति के संगठन आदि के बारे में भी उपयोगी सुझाव दिये हैं। आशा है कि इनको कार्यान्वित करने से स्थिति में पर्याप्त सुधार हो सकेगा।

STANDARD QUESTIONS

1. Outline the main purposes of a tax policy designed to encourage industrialisation. Discuss the various forms of tax incentives.
2. Write a brief note on the present pattern of taxation in India.
3. What are the usual concessions allowed in the computation of taxable income to promote industrial development in India?
4. Discuss the incidence of corporate taxes in India.
5. Write a note on Indirect Taxation and its effect on industry.
6. Critically examine the present pattern of taxation in India. Give your suggestions for its improvement.

भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण

(Rationalisation in Indian Industries)

भारत में आन्दोलन की गति घीमी क्यों ?

भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की घोर आवश्यकता होत हुए भी इसकी प्रगति बहुत मन्द गति से हुई है। भारत में ऐसे उद्योग बहुत थोड़े हैं जिनमें विवेकीकरण का अनुसरण किया गया है। सन् १९२९ की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी से छुटकारा पाने के लिये विदेशी उद्योगों ने जो राशिपातन (Dumping) शुरू किया उसके परिणाम-स्वरूप भारतीय उद्योगपतियों ने विवेकीकरण की आवश्यकता को समझा और द्वितीय महायुद्ध के युग में तथा इसके बाद इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये। इस आन्दोलन की घीमी गति के प्रधान कारण निम्नलिखित हैं—

(१) पूँजी का अभाव—

अभिनवाकरण का माजनादो का कार्यान्वित करने के लिए भारतीय उद्योगपतियों के पास धन का अभाव है। मशीनों के सम्बन्ध में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। अतः विदेशों में आयात करने में बहुत धन खर्च होता है। इसलिए मशीनों के अप्रचलित तथा बेकार होने पर भी उन्हें बदला नहीं जा सका।

भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की
घीमी प्रगति क्यों ?

- १ पूँजी का अभाव।
- २ सद्भावना का अभाव।
- ३ विदेशी सरकार की उपेक्षा।
- ४ आद्योगिक अशान्ति।
- ५ भारतीय श्रमिकों का अशिक्षित, अज्ञान और रूढ़िवादी होना।

(२) सद्भावना का अभाव—भारतीय उद्योगपतियों में पारस्परिक मैत्री एवं सद्भावना के अभाव के कारण लोग किसी समझौते पर राजी ही नहीं होते थे। समय के साथ वे जो किञ्चित् समझौते हुए भी वे अल्पकालीन रहे एवं व्यक्तिगत स्वार्थ का सघष होने के कारण अचक सफल न हो सके।

(३) विदेशी सरकार—सन् १९४७ के पूर्व तक विदेशी शासन के कारण हमारे देश की कोई नियोजित औद्योगिक नीति नहीं थी। अतः भारतीय उद्योगों की वैज्ञानिक ढंग से प्रगति नहीं हो सकी।

(४) औद्योगिक अज्ञान्ति—श्रम एवं पूँजी व धोच चमनस्य भी विवेकीकरण की अमफलता का एक कारण है। श्रमजीवी मिल भाद्रिका को अपना पोषक नहीं वरन् शोषक समझते हैं। इसी प्रकार मेवाशेज भी भजदूरो को उद्योग का प्रतिपाद्य अंग नहीं मानते। अतः श्रम संगठन विवेकीकरण की योजनाओं का प्रायः विरोध करते हैं।

(५) उद्योगपतियों का विरोध—भारतीय उद्योगपति भी परम्परावादी हैं। वे अभिनवीकरण की योजनाओं को अधिक खर्चीली होना व कारण अपमानने में हिचकिचाते हैं।

(६) भारतीय श्रमिक अशिक्षित अज्ञानों एवं रुढ़िवादी हैं—हमारे कारखानों में काम करने वाले अधिकतर श्रमिक गाँवों से आते हैं। इन गाँवों का वातावरण ही वैज्ञानिक विकास के विपरीत है। ग्रामवासी अपने गतिरिक्त समय में काम की दलाल में नगरो की ओर चले जाते हैं और फल के बिना में काम छोड़ कर वापिस लौट जाते हैं। इस कारण कारखानों के काम में उन्हें कोई विशेष चाव नहीं होता। उनकी भरती भी किसी नीति प्रथवा सिद्धान्त के अनुसार नहीं होती। भरती का काम कर्मचारियों का (Jobbers) के हाथ में रहता है। श्रमिकों की उचित शिक्षा के सम्बन्ध में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उनमें संगठन का भी अभाव है।

विशिष्ट उद्योगों में विवेकीकरण

(Rationalisation in Specific Industries)

प्रमुख भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण से सम्बन्धित प्रयत्नों का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है —

(१) सीमेन्ट उद्योग—सन् १९३० में सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी स्थापित हुई, जिसने अपने मद्दसा के अन्तर्गत उत्पादन को आर्थिक मूल्य पर वेचना शुरू किया। सीमेन्ट के प्रत्येक कारखाने के लिए उत्पादन का ठोस निश्चित कर दिया गया। रेलवे कम्पनियों से भी भाड सम्बन्धी उचित ठहराव कर लिए गये। भिन्न भिन्न प्रकार के सीमेन्ट के लिए बाजार बाँट दिया गया। इस प्रकार सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी ने प्रतिस्पर्धा की भावना को अन्त कर दिया। यानत्रयों के व्यय को कम कर दिया तथा उत्पादन पर नियन्त्रण करके आवश्यकता से अधिक उत्पादन की सम्भावना को भी समाप्त कर दिया। उपभोक्ताओं का भासते दामों पर वस्तुय मिलना सुलभ हो गया। अतएव सन् १९३६ में एससियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज के रूप में सीमेन्ट के अनेक प्रमण्डलों का संयुक्तीकरण हुआ। फिर १९४१ में एससियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज ने डालमिया ग्रुप के साथ गठबन्धन कर लिया।

(२) शक्कर उद्योग—इसी प्रकार शक्कर उद्योग में भी पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता की भावना को समाप्त करने की दृष्टि से सुगर मार्केटिंग बोर्ड सन् १९३२ में स्थापित किया गया। फिर शक्कर के उत्पादन एवं उसका वितरण पर नियन्त्रण रखने

की दृष्टि से सन् १९३७ में सुगर सिंडीकेट स्थापित किया गया। अब कुछ समय से 'केन्द्रीय शक्कर समिति' बना दी गई है। इस समिति के परिणामस्वरूप शक्कर के उद्योग में अनेक उपयोगी अनुसंधान हो रहे हैं। गन्ने की उपज में वृद्धि होने के अतिरिक्त शक्कर के उत्पादन तथा उनके विक्रय की रीति में भी बहुत उन्नति हो गई है। किन्तु आज भी शक्कर उद्योग में अनेक निरर्थक क्षय होते हैं, जिनका यदि उपयोग किया जाय तो मेथीलेटिड स्प्रिट, शराब इत्यादि उत्पाद (Bye-products) बनाये जा सकते हैं। आज शीरा तथा बगेसेज का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। अतएव उद्योग के अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उत्पादन एवं उत्पादन क्रियाओं का विवेकीकरण करने की आवश्यकता है, जिससे मितव्ययिता आकर संरक्षण की जरूरत न रहे।

(३) जूट उद्योग—जूट उद्योग भारत का सबसे संगठित उद्योग है, क्योंकि इसमें हम उत्पादन का सबसे अच्छा नियन्त्रण देखते हैं। किन्तु ग्रन्थ बातों पर इस उद्योग में भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसका प्रधान कारण यह था कि अभी तक भारतवर्ष को इस उद्योग का एकाधिकार प्राप्त था। पारस्परिक सहयोग लावे तथा उत्पादन का नियन्त्रण करने के लिये इण्डियन जूट मिल एसोसियेशन की स्थापना की गई। विवेकीकरण काम के घण्टों में कमी करने तक ही सीमित रहा। भारतीय जूट उद्योग आज नाहि-नाहि कर रहा है। भारत के बँटवारे के कारण हमारे मिलों को पर्याप्त मात्रा में एवं उचित मूल्य पर पाट नहीं मिल रहा है। दूसरे, हमारे जूट की माँग भी विदेशों में कम हो रही है, क्योंकि आज जूट के स्थान में अन्य चीजों का प्रयोग होने लगा है। तीसरे, अवमूल्यन के बाद जूट का मूल्य भी बहुत बढ़ गया है। अतः जूट उद्योग को सुरक्षित रखने के लिये विवेकीकरण का अनुसरण अनिवार्य है।

(४) लोहा एवं इस्पात उद्योग—इस उद्योग में विवेकीकरण की जो प्रगति हुई वह केवल सराहनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय भी है। ऐसे अनेक प्रयोग किये गये हैं जिनके फलस्वरूप उत्पादन क्रियाओं में सरलता आ गई है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। निरर्थक क्षय कम हो गया है। थम-वचत के अनेक साधनों का उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि द्वितीय महायुद्ध के युग में तो इस्पात बनाने में 'स्कैप-कादन-प्रोसेज' का उपयोग किया गया है, जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

(५) सूती वस्त्र उद्योग—सूती वस्त्र मिल उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं महान् उद्योग है। द्वितीय महायुद्ध के पहले इस उद्योग में विवेकीकरण के कुछ प्रयत्न किये गये, किन्तु वे सराहनीय नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनमें से अधिकांश प्रयत्न असफल रहे। इस उद्योग में विवेकीकरण में सम्बन्धित प्रयत्न प्रबन्ध-अधिकर्ताओं

के विरोध एवं असहयोग के कारण अभी तक प्रायः अमफल ही रहै हैं। सन् १९३६ में मिलों के पारस्परिक समन्वय के लिये अनेक प्रयत्न किये गये, किन्तु वे सफल नहीं हुये। जब द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तो कपड़े की माँग दिन पर दिन बढ़ने लगी। इस कारण उद्योग की उन्नति का बड़ा अवसर मिला। उन दिना भारत में चारों ओर वस्त्र संकट था, अतएव उपयोगिता के मन्त्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा वस्त्र की कमी की समस्या को हल करने के हेतु सन् १९४५ में भारत-सरकार ने उत्पादन के विवेकीकरण से सम्बन्धित एक सनियम (Textile Industry-Rationalisation of Products Order) बनाया जिसके फलस्वरूप तरह-तरह के वस्त्रों का बनाना बन्द कर दिया गया। मिल केवल ऐसा ही कपड़ा तैयार करने लगी, जिसकी सबसे अधिक उपयोगिता थी। सन् १९४५ के आदेशानुसार उत्पादन एवं वितरण पर भी नियन्त्रण रखा गया। बम्बई तथा अहमदाबाद की मिलों में विवेकीकरण का अनुसरण विशेष रूप में किया गया। फायेट कमेटी के अनुसार कोहेनूर मिल्स और सैसून तथा फिनले ग्रुप की मिलों में कुछ 'कुशलता वृद्धि योजनाएँ' (Efficiency Schemes) प्रचलित की गईं। प्रोफेसर सी० एन० बकल ने कपास के जूय तथा वस्त्र के वितरण में विवेकीकरण से निम्नलिखित लाभ के लिए संयुक्त केन्द्रीय सभा (Joint Central Board) की स्थापना को आवश्यक बताया है।

सन् १९४८ के अन्त में मिल मालिक संघ की सिफारिशों पर भारत सरकार ने श्री भवानीशंकर एम० बोरकर को सूती कपास उद्योग के सम्बन्ध में तात्त्विक एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने जापान भेजा। यह प्रयत्न भी विवेकीकरण की दशा में ही किया गया। उद्योग की उन्नति के लिए, अभी कुछ दिन हुए यन्त्रों के आधुनिकीकरण (Modernisation) की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार भारतीय प्रमाण संस्था द्वारा प्रमाण एवं निर्देशन (Specification) के अनुसार उत्पादन क्रियाया का प्रमापीकरण करने की सिफारिश की गई है।

वर्तमान काल में विवेकीकरण की आवश्यकता—

आजकल हमारे देश में विवेकीकरण व अभिनवीकरण की विशेष आवश्यकता है। इसके प्रधान कारण निम्नलिखित हैं—

(१) विदेशी प्रतियोगिता—आज दुनिया का सभी देश अभिनवीकरण की दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ चले जा रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद सभी पाश्चात्य देशों, चीन, जापान, रूस, ने अपने देश में अनेक यन्त्रोन्नीय वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं। यदि हम चाहते हैं कि अन्य प्रगतिशील देशों के साथ कदम-कदम मिलाकर चलें तथा प्रतिस्पर्धा में किसी देश से पीछे न रहें तो विवेकीकरण को अपनाना होगा।

(२) विदेशी बाजारों का छिनना—हमारे विदेशी व्यापार में भी शून्य-शून्य कमी होती जा रही है। युद्ध युग में भारतीय उद्योगों में काफी विस्तृत बाजार

तैयार कर लिया था। उदाहरणार्थ, युद्धकाल में भारतीय कपड़ा ईरान, ईराक, मिथ्र, अरब, इण्डोनेशिया, वर्मा इत्यादि देशों में जाता था। परन्तु जापान की स्वतन्त्रता के बाद ये बाजार काफी सीमा तक भारत से छिन गये हैं। अतएव अपनी स्थिति पूर्ववत् रखने के लिए विवेकीकरण की शरण लेना आवश्यक है।

(३) अप्रचलित व घिसी मशीनरी—युद्धोत्तर काल में चीन, जापान आदि सभी देशों ने लगभग सभी करघों व तकुओं का नवीनीकरण कर लिया है तथा वहाँ स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें

एक मजदूर ४० करघे तक एक साथ देखता है। हमारी मिलों में प्रयोग होने वाली मशीनें बहुत पुरानी हैं। इस सम्बन्ध में सन् १९५२ में सूती उद्योग की वर्किंग कमेटी ने निम्न आंकड़े दिये, जिसके अनुसार सूती वस्त्र उद्योग में ६५% मशीनरी सन् १९२५ से पहले की है, उसमें ३०% तो सन् १९१० से भी पहले की है। बीविंग विभाग में ७५% करघे सन् १९२५ से पहले के हैं, जिसमें ४६% तो सन् १९१० से भी पहले के हैं। सन् १९५८ में कॉटन टेक्सटाइल इन्व्वाइरी कमेटी (जोशी कमेटी) ने भी इन बातों पर बल दिया कि हमारे मिलों की गिरी हुई दशा का एक प्रधान कारण अभिनवीकरण का अभाव है। योजना आयोग का भी इस सम्बन्ध में यही मत है।

(४) घरेलू मांग में कमी—युद्ध के समाप्त होने से आन्तरिक मांग में भी बहुत कमी आ गई है। एक ओर तो खाद्य पदार्थों तथा औद्योगिक कच्चे माल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और दूसरी ओर आर्थिक आयोजन की पूर्ति के लिए सरकार तरह-तरह के कर लगा रही है, इसलिए अन्य उपभोग की वस्तुओं की मांग स्वतः कम हो रही है। मांग में वृद्धि के हेतु किस्म में वृद्धि अनिवार्य है और वह तब तक सम्भव नहीं जब तक कि विवेकीकरण की शरण न ली जाय।

(५) देश का विभाजन—देश की विभाजन-जन्य समस्याओं (जैसे रुई, पट-सन आदि कच्चे माल की कमी) को हल करने के लिए भी विवेकीकरण को अपनाना होगा, जिससे कि उपलब्ध भाषना व अच्चे में अच्चा उपयोग हो सके तथा अपव्यय रोका जा सके।

वर्तमान काल में विवेकीकरण

आवश्यकता की ६ बातें

१. विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा।
२. विदेशी बाजारों को बनाये रखना।
३. अप्रचलित व घिसी मशीनरी का प्रतिस्थापन।
४. घरेलू मांग में कमी को रोकने के लिये।
५. देश के विभाजन की समस्याओं को हल करने के लिये।
६. विदेशी विनिमय कमाने के लिये।

(६) विदेशी विनिमय का अर्जन—पंच वर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए बहुत घड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय की आवश्यकता है, जो तभी संभव हो सकती है जबकि हमारे निर्यात बढ़ें। निर्यात को बढ़ाने के लिए वस्तुओं की किस्म बढ़ानी होगी और इस हेतु वैज्ञानिक प्रणालियों का अनुसरण अनिवार्य है।

भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की आवश्यकता—

भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की प्रगति के एकमात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हमारे देश में खोह एवं स्थात उद्योग के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्योग में वैज्ञानिकता का उपयोग न के बराबर है। अन्य उद्योगों में जो किंचित प्रयत्न किए गए हैं वे या तो सयाग के लाभ को प्राप्त करने अथवा प्रतिस्पर्धा का अन्त करने की दृष्टि से किए गए हैं। उदाहरणार्थ, वस्त्र मिल उद्योग को ही लीजिए। इस उद्योग में वैज्ञानिकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए टाटा क्वाटरों ने लिखा है कि सूती वस्त्र उद्योग में निर्माण क्रियाओं के वैज्ञानिकता की आवश्यकता निम्न दो कारणों से अधिक बलवती हो गई है,—

(१) मशीनों का अप्रचलित हो जाना एवं घिस जाना।

(२) देश के बँटवारे के बाद निर्यात बाजारों का विकास आवश्यक हो जाना।

सन् १९५२ में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में सूती उद्योग की कॅपिटल कमिटी ने बताया था कि स्पिनगिंग विभाग में ६५% मशीनरी सन् १९२५ से पहले लगाई गई थी और ३०% सन् १९१० में पहले। बीविंग विभागों की स्थिति भी धीरे धीरे खराब है। ७५% लूमस सन् १९२५ से पहले लगाये गये थे। ४९% तो सन् १९१० से भी पहले के हैं। साधारणतः एक मशीन २० साल तक काम करता है, इसलिए इसे बदलने का निरन्तर आवश्यकता है। पाकिस्तानी प्रदेश में देश के विभाजन के पूर्व २०% उत्पादन खपता था। आज वह बाजार बन्द सा हो गया है। वे स्वयं बढ़िया मशीनरी लगा रहे हैं। जापान ने भी युद्ध के बाद प्रायः सारी मशीनरी अपटूटेड कर दी है। जापान के सूती वस्त्र उद्योग के ७०% स्पिन्डिल और ५६% लूमस युद्धोत्तर काल में सन् १९५२ के अन्त तक लगाये गये थे और अधिकांश लूमस ओटोमैटिक हैं। अन्य देशों ने भी अपने उद्योगों की मशीनरी अपटूटेड कर ली है, यद्यपि युद्ध-पूर्व के युग में सन् १९५१ के अन्त तक विश्व की उत्पादन क्षमता ३५,००० मिलियन गज से बढ़ कर ३९,००० मिलियन गज हो गई है, किन्तु वस्त्र सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा ६,७५० मिलियन गज घट कर केवल ५,४४० मिलियन गज रह गई है। उनमें प्रतिस्पर्धा के लिये हमारे देश में विवेकीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई भी मांग नहीं है।

वस्त्र-मिल उद्योग की मशीनरी के अभिनवीकरण का प्रश्न केवल विदेशी बाजार की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि घरेलू माँग (Domestic Demand) को स्थिर रखने के लिये भी वाञ्छनीय है। गत कुछ वर्षों से कपड़े की माँग गिरती जा

रही है। मार्च सन् १९५२ की मन्दी के बाद से वस्त्र-उद्योग के लिये परिस्थितियाँ विशेषतः कठिन हो गई हैं। सन् १९५३ के प्रथम ६ महीनों में कपड़े का बिना बिका स्टॉक दुगुना हो गया, जो कि वर्ष के अन्त में लगभग ७६ करोड़ रुपये का था। जब तक उद्योग अपने उत्पादन व्यय व मूल्यों को कम नहीं करता और माल की किस्म में उन्नति नहीं करता तब तक विकास तो दूर, आन्तरिक बाजार को स्थिर रखना भी अत्यन्त कठिन है। वस्त्र मिल उद्योग के अतिरिक्त भारत के अन्य उद्योगों में भी मशीनरी के अभिनवीकरण (Modernisation) का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

चीनी उद्योग में अभी तक मिला ने देव्य पदार्थों (Waste) का उपयोग उप-वस्तुएँ (Bye products) बनाने के लिये नहीं किया, जो निश्चय ही आवश्यक है। इससे मितव्ययिता होकर उत्पादन व्यय गिरेगा। यन्त्रों के आधुनिकीकरण एवं उत्पादन क्रियाओं के प्रमापीकरण का प्रयत्न भी अभी तक नहीं किया गया है, जो बहुत आवश्यक है।

जूट मिल उद्योग में विवेकीकरण के अवलम्बन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना न तो हम अन्य देशों की प्रतिस्पर्द्धा में टिक सकते हैं और न विदेशी माँग को पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। सीमेन्ट उद्योग में भी अभी तक मानवीय श्रम एवं यन्त्रों का निरर्थक व्यय करने की दृष्टि से तथा उत्पादनशीलता बढ़ाने एवं यन्त्रों के आधुनिकीकरण की ओर कुछ भी नहीं किया गया है।

भारतीय प्रभाष सस्सा ने अभी तक जो कुछ किया है वह सन्तोषजनक अवश्य है, किन्तु औद्योगिक विकास में अभी प्रमापों को महत्त्व नहीं दिया जा रहा है। उद्योग-पतियों की शिकायत है कि खरीदार देशी माल का विश्वास नहीं करते और विदेशी माल को मँहगा होते हुए भी खुशी से खरीदते हैं।

अतः भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की बड़ी आवश्यकता है। इसी के आधार पर हमारे उद्योग केवल देशी बाजार में ही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी टकर लेने के लिए समर्थ हो सकते हैं, परन्तु विवेकीकरण का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय उद्योग वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से समुचित शिलान्यास कर विवेकीकरण की नींव को सुदृढ़ करें।

रोजगार पर विवेकीकरण के प्रभाव—

श्रम संचालक-यन्त्रों के द्वारा विवेकीकरण के प्रचलन का सबसे बड़ा विरोध यह बताया जाता है कि इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है और रोजगार की समस्या, जो पहले से ही जटिल है, और भी भीषण हो जाती है। इसी समस्या पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे।

विवेकीकरण के परिणामस्वरूप जो बेरोजगारी पैदा होती है, उसके दो रूप हो सकते हैं—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से, उद्योगों में बेरोजगारी होने की सम्भावना है, जहाँ औद्योगिक मशीनरी का प्रयोग किया जाय और अप्रत्यक्ष

रूप से उन उद्योगों में भी बेरोजगारी की सम्भावना है जो वैज्ञानीकृत इकाइयों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती और फलस्वरूप अपना कार्य बन्द करने में लिये विवश हो जायें। वसी प्रकार छोटे पैमाने के उद्योग तथा हौण्डलूम उद्योग में भी बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि वैज्ञानीकृत मण्डित उद्योगों के मामले उनके टिकने की सम्भावना कम हो जाती है।

विवेकीकरण की योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इस दिशा में जो कार्य किया जाय वह दोनों पक्षकारों—श्रम तथा पूँजी के सहयोग में हो। सबसे पहले नो सम्पूर्ण नीति श्रमिकों को भली प्रकार समझा दी जाय और यदि उचित हो तो आदर्शकृतानुसार उसमें संशोधन भी कर दिये जायें। योजना को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाय कि यदि श्रमिकों पर इसके कुछ बुरे प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो वे एक विस्तृत अवधि पर फैला दिये जायें, जिसमें कि उनका भार सहनीय न हो। बेरोजगारी रोक्ने तथा निकाले हुए श्रमिकों को पुनः कार्य देने का भी आयोजन होना चाहिये। इसके लिये निम्न कार्य किये जा सकते हैं—नवीन पद्धतियाँ के अनुसार कार्य करने की ट्रेनिंग का आयोजन करना, साम्यिक शिक्षा की सुविधा देना, कार्य की पालियाँ (Shifts) बढ़ाना तथा एक विभाग में दूसरे विभाग को श्रमिकों का स्थानान्तरण। इन ढंगों से रोजगार पर पड़ने वाले विवेकीकरण के कुप्रभावों को कम किया जा सकता है।

वास्तविक बात तो यह है कि यदि विवेकीकरण के लिये खुली आशा भी दी जाय तो भी बड़ी भाना में बेरोजगारी होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि एक तो देश की समस्त औद्योगिक इकाइयाँ विवेकीकरण की योजना को धन की कमी के कारण अपनाते में असमर्थ हैं और जो किंचित उद्योग इसका प्रयोग भी करेंगे उनके उपलब्ध कोषों का अधिकांश भाग तो मशीनरी के आधुनिकीकरण में ही खप जायगा और शेष, जो श्रम सचय यन्त्रों में स्तेमाल होगा, बहुत थोड़ा होगा। एक अनुमान के अनुसार बम्बई तथा अहमदाबाद की केवल २० वस्त्र मिल औटोमैटिक मशीनरी लगाने की कल्पना कर सकती है। सन् १९४६ से सन् १९५३ तक ७ वर्ष की अवधि में केवल ४,६०५ औटोमैटिक लूम लगाय गये अथवा दूसरे शब्दों में प्रतिवर्ष ६५८ लूम लगाये गये। इसने स्पष्ट है कि वैज्ञानिकों के प्रचलन में रोजगार की स्थिति पर कोई भीषण प्रभाव पड़ने की आशका नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि औटोमैटिक मशीनरी के द्वारा जितने श्रमजीवियों की छूटनी करनी पड़गी उनकी संख्या अधिक न होगी, अतएव कुछ समय के उपरान्त उन निकाले हुये श्रमिकों को उद्योगों में पुनः काम देना कोई कठिन बात नहीं। यदि निकाले हुए श्रमिकों को दुबारा रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने औद्योगिक संघर्ष (संशोधित) अधिनियम सन् १९५३ में निकाले हुए श्रमिकों की क्षति पूर्ति करने की व्यवस्था की है।

यही नहीं, विवेकीकरण के प्रचलन में उत्पादन व्यय तथा मूल्यों में कमी होगी और वस्तुओं की किस्म सुधर जायेगी। फलस्वरूप माँग बढ़ेगी, जिससे नवीन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इन नवीन उद्योगों में श्रमिका को कार्य दिया जा सकता है।

यदि विवेकीकरण स्थगित कर दिया जाय ?—

यदि विवेकीकरण की योजना को कार्यान्वित न कर तो इस बात की गारन्टी नहीं है कि भविष्य में रोजगार की दशा सुधर जावेगी। सच तो यह है कि इसको स्थगित करने से वस्तुओं की किस्म एवं उनके मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप देशी तथा विदेशी माँग भी कुप्रभावित होगी। उदाहरण के लिए, वस्त्र मिल उत्पादन का २०% भाग, जो आज़कल विदेशों को जाता है, जाना बन्द हो जावेगा और इससे मिलों को अपना उत्पादन कम करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, अतएव हमारे सम्मुख बचल दो मार्ग हैं—प्रथम, विवेकीकरण का प्रचलन जिसके परिणामस्वरूप यद्यपि थोड़ी तत्कालिक बेरोजगारी होने की सम्भावना है किन्तु उद्योग की कार्यक्षमता निस्सन्देह बढ़ेगी और स्थिति सुदृढ़ होगी तथा दूसरा मार्ग यह है कि विवेकीकरण की योजना को स्थगित कर दिया जाय, जिसमें यद्यपि तत्कालिक बेरोजगारी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन निम्न भविष्य में बाजारों के छिन्न जाने पर बेरोजगारी एक रौद्र रूप धारण कर लेगी।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Explain the urgency of introducing rationalisation in Indian Industries. What repercussions will it have on the employment situation in the country? What are the advantages of rationalisation?
- 2 What is 'Rationalisation'? Discuss the problems of its application to Indian Industries.
- 3 Write an essay on 'Rationalisation' in the Cotton Textile Industry of India.
- 4 Discuss the reasons for the slow growth of Rationalisation in Indian Industries.
- 5 Attempt an essay on 'Industrial Productivity Movement in India,' undertaken by the Govt. of India.

राज्य एवं विवेकीकरण

(State & Rationalisation)

प्रारम्भिक—

जबकि विश्व के औद्योगिक रूप से उन्नत देश अणु शक्ति एवं स्वचालन द्वारा प्रसारित द्वितीय औद्योगिक क्रांति के मोड़ पर खड़े हैं, तब भारत में स्टीम एवं विद्युत शक्ति पर आधारित प्रथम औद्योगिक क्रांति भी अपने पूर्ण निखार पर नहीं आ पाई है। हमारी अत्यधिक दरिद्रता, हमारे भूतपूर्व शासकों की उपेक्षा और हमारी जनता की रुढ़िवादिता ने बंगलादेशी युग की अवधि का बढ़ा दिया है तथा हम अब भी औद्योगिकरण की शक्तियों का हथौड़ी से ही सामना कर रहे हैं। इस खेदजनक स्थिति के होने पर भी विवेकीकरण के प्रति सरकार का रुख अस्पष्ट एवं सकोचपूर्ण है, यद्यपि वह छुले रूप से विवेकीकरण के विरुद्ध नहीं कही जा सकती। भारत सरकार ने विवेकीकरण की दिशा में अब तक जो प्रयास किये हैं उन्हें निम्न शीपको के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है —

(१) अन्-पूँजी सहयोग—

सन् १९५१ में योजना मंत्री श्री नन्दा की अध्यक्षता में उद्योग विकास समिति की एक उप समिति ने भारतीय उद्योगों के विवेकीकरण की समस्या पर विचार किया और निम्न निराग किये :—

(१) भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण किया जाय, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाय कि कम से कम मजदूरों की छूटनी हो। इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये गये—(i) मृत्यु अथवा रिटायर होने के कारण जो स्थान खाली हो उन्हें भरा नहीं जाय, (ii) अतिरिक्त (Surplus) श्रमिकों को अन्य विभागों में काम दिया जाय और इससे उनकी सेवा की अवधि तथा पुरुस्कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिये, (iii) अपनी इच्छा से रिटायर होने वाले श्रमिकों को अर्धुइटी दी जाय, और (iv) टेक्नोलॉजिकल सुधारों के कारण जो मजदूर बेकार हो गये हैं उनमें से कुछ को काम देने के लिये मशीन का विस्तार किया जाय।

(२) कार्य-भार (Work-load) का एक आदर्श निश्चित कर देना चाहिये।

- (३) टेक्नीकल परिवर्तनों को कुछ समय तक अजमाया जाय, ताकि उद्योगों को उसका प्रारम्भिक अनुभव हो सके ।
- (४) विवेकीकरण से होने वाले लाभ में श्रमिकों को भी उचित भाग दिया जाय ।
- (५) निकाले हुये श्रमिकों के पुनर्वास के लिये सरकार को उपयुक्त योजना बनानी चाहिये ।

इसी प्रकार के कुछ सुझाव प्रथम पंच-वर्षीय योजना के निर्माताओं ने दिये, जिससे विवेकीकरण देश में प्रगति करे और श्रमिकों एवं सेवायोजकों के बीच सघर्ष न हो । द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में योजना आयोग ने औद्योगिक ट्रेड्यूनलों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि वे अवार्ड देते समय समझौते द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था को उचित महत्त्व दें ।

अभी हाल में, भारत सरकार ने विवेकीकरण से सम्बन्धित एक आदर्श ठहराव बनाया है, जो कि जुलाई सन् १९५७ में भारतीय श्रम सम्मेलन के सन्मुख रखा गया था । इस ठहराव में यह स्वीकार किया गया है कि विवेकीकरण की योजनाओं को कार्यान्वित करने की सुविधा के लिये श्रमिकों एवं सेवायोजकों में पारस्परिक परामर्श व सहयोग की आवश्यकता है । इस ठहराव में यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन करने में पहले, जिसके कारण श्रमिकों की संख्या में कमी होने की आशंका है, प्रबन्धकों वा चाहिये कि अपने इस इरादे की सूचना श्रम सघ को ३ सप्ताह से लेकर ३ माह पूर्व ही दें । यदि टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन करने के फलस्वरूप कुछ श्रमिक बेकार हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः काम देने के लिये कारखाने के कार्यक्षेत्रों का यथासंभव विस्तार किया जाय । यदि श्रमिकों और सेवायोजकों में कोई मतभेद हो तो उसे मध्यस्थ को सौंपा जाय ।

सुझाव—

‘मौजू रहित विवेकीकरण’ (Rationalisation without tears) वह वाक्य है जिसके द्वारा भारत में जनता की इस आशा और माँग को व्यक्त किया जाता है कि बड़ी हुई उत्पादकता के कारण बेरोजगारी की समस्या में, जो कि देश में पहले ही व्यापक रूप से विद्यमान है, और अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए । बेरोजगारी के भय से विवेकीकरण करने के लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :—

- (१) साधारणतः बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों को काम देने वाले उद्योगों में स्वचालन का प्रचलन करना अबुद्धिमत्तापूर्ण है, जब तक कि उद्योगों में योजनाबद्ध विकास की व्यवस्था न हो ।
- (२) विवेकीकरण द्वारा संभव की गई बचत में श्रमिकों, सेवायोजकों एवं उपभोक्तृओं तीनों को हिस्सा मिलना चाहिए ।
- (३) यदि विद्यमान इकाइयाँ अथवा उद्योग विस्थापित होने वाले श्रमिकों को काम देने के लिये अपने प्लान्ट का विस्तार करने में असमर्थ हो, तो

उनमें व्यवस्था करने की आवश्यकता है तब तक रोकना बुद्धिमाना होगा जब कि आर्थिक विस्तार — कार्यक्रम अथवा उद्योगों में अतिरिक्त श्रमिका का काम मिलने की सुविधा उपलब्ध न कर दे।

(२) उद्योग का नियन्त्रण—

उद्योग (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम सन् १९५१ ने भारत सरकार को इस शक्ति का अधिकार दिया है कि वह अनुसूचित उद्योगों में विचार कराने के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये विकास परिषद नियुक्त कर दे। इन विकास परिषदों के निम्न कार्य हैं —

- (१) उत्पादन में लक्ष्य की सिफारिश करना उत्पादन के कार्यक्रमों का समन्वय करना और समय-समय पर प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (२) प्रपञ्च्य को समाप्त करने अधिकतम उत्पादन करने किम्में में सुधार करने और लागत घटाने की दृष्टि से निपुणता के प्रमाण निश्चित करना।
- (३) स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने तथा उद्योग के कार्यकरण का सुधार करने के लिये उपाय सूचना।
- (४) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान की व्यवस्था करना।
- (५) उद्योग में चलाने श्रमिका की देखभाल करने की दृष्टि से दत्त तथा विस्थापित श्रमिकों को अन्य कार्यों की दृष्टि से दत्त।
- (६) भारत सरकार को परामर्श देने के लिये विभिन्न विषयों या सामग्री का संकलन करना।

अब तक तेरह उद्योगों के लिये विकास परिषदों की स्थापना की जा चुकी है।

(३) वित्तीय सहायता—

कर जाँच आयोग सन् १९५४ की सिफारिशों पर भारत सरकार ने औद्योगिक

राज्य द्वारा वित्तकीकरण की
दिशा में किये गये प्रयत्न

- १ धर्म-पूजी सहयोग
- २ उद्योग का नियंत्रण।
- ३ वित्तीय सहायता।
- ४ औद्योगिक अनुसंधान।
- ५ भारतीय प्रमाण सस्था।
- ६ भारतीय उत्पादकता आन्दोलन।

संस्थाओं को कुछ-कुछ कर सम्बन्धी रियासतें द्या है जैसे विकास छूट और अतिरिक्त घिसाई का अलाउन्स। आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में रुचि रखने वाली औद्योगिक इकाइयों में प्लांट एवं मशीनरी के अतिरिक्त प्रतिस्थापना एवं नवकरण के लिये वित्तीय सहायता देने को सन् १९४८ में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई प्रथम पंच वर्षीय योजना में प्रस्तापन एवम् आधुनिकीकरण के

कार्यक्रमों के लिये २६० करोड़ के धन की व्यवस्था की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट क्षेत्र के लिये इन कार्यों पर १५० करोड़ के व्यय की व्यवस्था की गई है।

(४) औद्योगिक अनुसन्धान—

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत में औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान की समस्या पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। उद्योग मुख्यतः विदेशी टेक्नीकों पर ही निर्भर करते थे तथा अपनी ही टेक्नीकों के विकास का प्रयास नहीं करते थे। युद्ध काल में आयात की जाने वाली सामग्रियों की स्थानापन्न वस्तुओं का विकास करना आवश्यक हो गया और साथ ही इन स्थानापन्न वस्तुओं को, आयात की सामग्रियों के स्थान में प्रयोग करने के लिये नई विधियाँ खोजना भी आवश्यक था। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने सन् १९४० में बोर्ड आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की। काउन्सिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना सन् १९४२ में हुई। स्वतन्त्रता के बाद से तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान की प्रगति के लिये अतिरिक्त सुविधायें देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण बात है देश के विभिन्न भागों में नेशनल लैबोरेटोरियों की स्थापना होना, जिनमें से मुख्य-मुख्य लैबोरेटोरियाँ इस प्रकार हैं —

- (i) National Physical Laboratory, New Delhi.
- (ii) National Chemical Laboratory, Poona
- (iii) Central Fuel Research Institute, Jealgora (Bihar).
- (iv) Central Food Technological Research Institute, Mysore.
- (v) Central Glass and Ceramic Research Institute, Jadhavpur.
- (vi) Central Drug Research Institute, Lucknow.
- (vii) Central Road Research Institute, New Delhi.
- (viii) Central Electro-Chemical Institute, Karaikudi Madras.
- (ix) Central Leather Research Institute, Madras.
- (x) Central Building Research Institute, Roorkee
- (xi) Central Electric Engineering Research Institute, Pilani (Rajasthan).
- (xii) National Botanical Gardens, Lucknow
- (xiii) Central Salt Research Institute, Bhawnagar.
- (xiv) Central Mining Research Station, Dhanbad.

इन सब समस्याओं का मुख्य कर्त्तव्य नये मौलिक ज्ञान की खोज करना है। वे विद्यमान औद्योगिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हैं और निर्माण कार्य की तकनीक में सुधार करने के सुभाव देते हैं।

(५) भारतीय प्रमाण सस्था—

भारतीय उद्योगपतियों ने सर्वप्रथम सन् १९४० के बारहवें उद्योग सम्मेलन में भारतीय प्रमाण 'निश्चित करने के लिये 'भारतीय प्रमाण सस्था' (Indian Standards' Institute) खोलने का प्रस्ताव सरकार व सम्मुख रखा, किन्तु युद्ध की परिस्थितियों के कारण उस समय भारत सरकार ने प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया। सन् १९४६ में औद्योगिक योजना के अन्तर्गत प्रमापीकरण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए भारत सरकार ने एक प्रमाण सस्था खोलने का निश्चय कर लिया। सस्था खोली गई और उसका केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में रखा गया है। इस सस्था का प्रबन्ध एक साधारण परिषद् (General Council) द्वारा होता है, जिसके सनापति उद्योग सचिव हैं और इसमें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्यों, अनुसन्धान सस्थाओं, बैंबर आफ कामर्स इत्यादि के कुल ६४ प्रतिनिधि हैं।

भारतीय प्रमाण सस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर विभिन्न वस्तुओं एवं क्रियाओं के प्रमाण निर्धारित करना तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करना औद्योगिक आंकड़ों एवं सूचनायें एकत्रित एवं प्रकाशित करना तथा प्रमापीकरण की उन्नति के लिये पुस्तकालय, म्यूजियम तथा प्रयोगशालायें स्थापित करना और विभिन्न वस्तुओं के प्रमापीकृत चिन्हा का रजिस्ट्रेशन करना है। भारतीय प्रमाण सस्था अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापीकरण संगठन की सदस्य है। इस दान में ही इसकी यशस्विता का परिचय मिलता है। भारतीय प्रमाण सस्था का कार्य अब राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त कर चुका है। यह सस्था ७ साल पहले सरकार और जनता के समर्थन में प्रारम्भ की गई थी और यह भारत में खपने और बनने वाली चीजों के ताप, विस्म और काम के प्रमाण निर्धारण करती है। सस्था को केन्द्रीय सरकार सहायता देती है। इसके अलावा राज्य सरकारें, औद्योगिक एवं व्यापारिक सस्थाएँ, कारखाने, औद्योगिक-शालाएँ, नगरपालिकाएँ और निगम आदि भी सस्था के सदस्य हैं तथा इसके लिए चन्दा देते हैं। इस काम की लोकप्रियता और महत्त्व इसी दान में प्रकट होता है कि अब कारखानों के मालिक अपनी चीजों के प्रमाण निर्धारित करने के लिए स्वयं ही माँग करने लगे हैं।

भारतीय प्रमाण सस्था के विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम सन् १९५२ का भारतीय प्रमाण अधिनियम है। इस अधिनियम के बन जाने से प्रमाण सस्था के अधिकार बढ गये हैं। अब सस्था को प्रमाण चिह्न देना और कम्पनियों को भारतीय प्रमाणों के अनुसार माल तैयार करने के लाइसेन्स देने का अधिकार मिला है। इससे उचित किस्म का माल निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा सन्तुष्ट और धटिया

माल के रकाविले का डर कम हो जायगा। केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि जहाँ तक हो नियत प्रमाण का वस्तुएँ ही खरादी जाए। ज्यों-ज्यों उपभोक्ता प्रमाण वाली वस्तुओं पर भरोसा करण त्यों-त्यों औद्योगिक विकास की गति भी तीव्र होती जायगी। हमारे जैसे निधन देश में तो कच्चे माल की बचत का महत्त्व युद्ध और शान्ति-काल दोनों में एकसा है।

(६) भारतीय उत्पादकता आन्दोलन—

फरवरी सन् १९५८ में एक स्थायित्व सस्था के रूप में भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना की गई थी जिसका काम उत्पादकता आन्दोलन चलाना है। इस उत्पादकता आन्दोलन का आधार नीचे लिखे पांच सिद्धांत हैं —

- (१) उत्पादकता आन्दोलन का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और सुधरी उत्पादन विधियों द्वारा माल की किस्म उत्तम करना है। इसका लक्ष्य मानव मशीनों माल बिजली और पूँजी के उपलब्ध साधना का कुशल तथा उपयुक्त प्रयोग करना, जनता के रहन सहन का स्तर ऊँचा करना और मजदूरों की काम करने तथा कल्याण की स्थितियों में सुधार करना है। ऐसा करते समय इन पारवर्तना के सामाजिक परिणामों का भी ध्यान रखा जाता है।
- (२) निरन्तर विकासशील अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता बढ़ने का अर्थ होता है कि अन्ततः उद्योगों का विकास होकर इससे रोजगार बढ़ने में सहायता मिलेगी।
- (३) उत्पादकता बढ़ने से होने वाले फायदे को समुचित रूप से मालिक मजदूर और उपभोक्त्यों में वितरित किया जाना चाहिए और इनका परिणाम यह होना चाहिए कि सयन्त मशीनों और उपकरणों का विस्तार तथा नवीकरण हो।
- (४) राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता में समान रूप से सुधार किये जाएँ। उद्योगों के क्षेत्र में यह आन्दोलन सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के विभाग मध्यमवर्गीय तथा उद्योगों तथा हल्के उद्योगों में किया जायगा।
- (५) मिल मालिकों तथा श्रमिकों के पूरे-पूरे सहयोग के बिना उत्पादकता बढ़ाई नहीं जा सकती।

STANDARD QUESTIONS

1. What steps have been taken by the Government of India for the Rationalisation of Indian Industries?
2. Write an essay on State & Rationalisation

औद्योगिक उत्पादकता आन्दोलन

(Industrial Productivity Movement)

प्रारम्भिक—

उत्पादकता आन्दोलन से आशय—

किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम पूँजी, भूमि और संगठन चारों साधनों का सहयोग होता है। इनमें से किसी एक साधन का उत्पत्ति में जो अनुपातिक भाग रहता हो उसे ही उस साधन की 'उत्पादकता' कहा जाता है। सबसे अधिक शक्ति श्रम के सम्बन्ध में ली जाती है, अतः 'उत्पादकता' शब्द का अभिप्राय प्रायः श्रम के सापेक्षिक सहयोग से लगाया जाता है। श्रम की उत्पादकता को प्रति व्यक्ति या प्रति घंटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस परिभाषा की लोकप्रियता का आधार यह तथ्य है कि श्रम में बचन होने का लागत मूल्य लाभ, मजदूरी और यहाँ तक कि राष्ट्र की सामाजिक सुरक्षा तथा जीवन स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है।

लेकिन उत्पादकता को केवल श्रम के दृष्टिकोण से मापना गलत परिणाम प्रस्तुत करेगा क्योंकि श्रम का उत्पादन के कई साधनों में से एक है। वास्तव में उत्पादकता का आशय सब साधनों के सम्मिलित प्रयास से है और उत्पादकता की वृद्धि के लिये प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार के अपव्यय पर रोक लगाना और उपलब्ध श्रम, यन्त्र, सामग्री पूँजी शक्ति, भूमि इत्यादि का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है।

अधिको में 'उत्पादकता' शब्द का एक गलत एक श्रमपूर्ण अर्थ प्रचलित है, जिससे प्रभावित होकर वे उत्पादकता आन्दोलन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। 'उत्पादकता' में वे अपने 'लघे अधिक कार्य-भार एक घण्टे परिश्रम का आशय लते हैं जिसका उद्देश्य मिल मालिकों के लाभ में वृद्धि करना है। अधिको को अपने मन में इस भ्रांतिपूर्ण धारणा को निजाल देना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि उत्पादकता अर्थशास्त्र की उन्नति का उद्देश्य अधिक उत्पादन के रूप का सम्बलन करना है जिससे उन्हें कम बर्बाद हो उनके काम की दशाओं में सुधार हो और उनकी कार्य-विधि सरल हो जाय। यह सोचना भी गलत है कि उत्पादकता आन्दोलन से केवल प्रबन्धकों को ही लाभ होता है। वास्तव में इसका लाभ श्रमिकों, उपभोक्ताओं, सेवायोजकों, सरकार व माधारण समाज सभी को होता है।

भारत के लिये उत्पादकता आन्दोलन का महत्त्व—

(1) उत्पादकता सम्बन्धी सूचनाका को देश की आर्थिक और औद्योगिक सफलताओं का मापक यन्त्र (Barometer) माना जाता है। इसकी सहायता से आर्थिक परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। (ii) योजनाकरण के दृष्टिकोण से उत्पादकता सम्बन्धी आंकड़े बहुत ही महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसके आधार पर एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों में एक देश की औद्योगिक इकाइयों की दूसरे देश की औद्योगिक इकाइयों से तुलना की जा सकती है तथा सम्पूर्ण उद्योग की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। (iii) उत्पादकता सम्बन्धी अध्ययन के आधार पर सरकार को यह निर्दिष्ट करने में सुविधा होती है कि गन्तव्य उद्योग को किस सीमा तक संरक्षण दिया जाय। (iv) करारोपण व प्रशुल्क नीतियों के संचालन एवं सामाजिक बीमा व भ्रम कल्याण की योजनाओं के विस्तार में भी सहायता मिलती है। (v) टेक्नोलॉजीकल परिवर्तनों का उत्पादन और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है और विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रवन्ध की योजनाओं ने उत्पादन की वृद्धि में किस सीमा तक योग दिया है इसका निरन्तर करने में भी बड़ी सुविधा हाँ जाती है। (vi) उत्पादकता सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर ही दुबल एवं दोषयुक्त अथ व्यवस्था के पुनर्वास की योजना बनाई जाती है। संक्षेप में उत्पादकता निर्देशांक अनेक उपयोगों में लिये जाते हैं और राजनीतिज्ञों व्यापारियों उद्योगपतियों व श्रमिक नेताओं की नीतियों के निर्धारण में बड़ी महायत्ता देते हैं। भारत में उत्पादकता आन्दोलन का विशेष महत्त्व है जो इस प्रकार बताया जा सकता है—

(1) विद्यमान उत्पादकों से सफल प्रतियोगिता करने के लिये—उत्पादक को भावी शर्तें व्यवस्था का एक महान आधार बताया जाता है भारतीय अर्थ व्यवस्था में उत्पादकता की वृद्धि का एक विशेष महत्त्व है क्योंकि अतमान प्रतिस्पर्धात्मक विश्व अर्थ-व्यवस्था में भारतीय उद्योगों के लिये उत्पादन की पुरानी तकनीक के सहारे टिकना कठिन है। देश के भीतर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी बाजारों का विकास करना है। यह तभी सम्भव है जब उत्पादकता में वृद्धि हो जिसमें उत्पादकता की सामान्य कम होकर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य रखे जा सकें।

(2) विद्यमान कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिये—भारत में औद्योगीकरण बहुत कम हो पाया है। परिणामतः उसे अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं और भाज-सामान के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। नवीन औद्योगिक विकास के लिये उपलब्ध पूँजी की मात्रा बहुत अपर्याप्त है अतः नए कारखाने स्थापित करना सुगम नहीं है। ऐसी दशा में विद्यमान कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का महत्त्व स्पष्ट है। यह आवश्यक है कि उत्पादन की नई तकनीक एवं विधियाँ का प्रयोग करके सभी साधनों का मानव श्रम का, भूमि का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय जिससे निर्माण की आवश्यकता न्यूनतम रखी जा सके।

(3) निम्नलिखित कारणों के लिये—उत्पादन में वृद्धि करके

हर प्रकार का उत्पादन साज सामान अधिक द्रुत गति में बनाया जा सकता है, अथ रहन सहन के स्तर में भावी प्रगतियों की बुनियाद डाली जा सकेगी। विद्यमान साधनों से ही अधिक वस्तुएं उपान करने में उत्पादन की लागत कम किया जा सकता है और वस्तुएं पहले से कम कीमत पर बेची जा सकती हैं। इसका लाभ उपभोक्ता को तो मिलेगा ही, साथ में मजदूरों के पारिश्रमिक में थोड़ी वृद्धि करने का अवसर भी मिलता है।

नवम्बर सन् १९६७ में उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय उद्योग मंत्री ने इस बात पर बल दिया था कि उत्पादन की प्रति इकाई पर श्रमिक द्वारा व्यय की जाने वाली शक्ति में बचत करके उत्पादन करना संभव है जिसका लाभ श्रमिक को प्रतिरिक्त मजदूरी के रूप में मिलेगा। उत्पादकता में वृद्धि होने से नये कारखाना की स्थापना के लिये अधिक पूंजी मिलना सरल होता है और अतः रोजगार की वृद्धि आती है।

‘औद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले घटक—

ये तो औद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले विविध प्रकार के घटक हैं तथापि उन्हें टेक्नोलोजिकल, वित्तीय, प्राकृतिक, सामाजिक, प्रावधिक एवं राजकीय वर्गों में इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है —

(१) **टेक्नोलोजिकल घटक**—टेक्नोलोजिकल प्रगति का औद्योगिक उत्पादन की तीव्र वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। भाप शक्ति और यांत्रिक आविष्कारों का उत्पादन की क्रियाओं में प्रयोग करने में औद्योगीकरण की गति बहुत ही तेज हो गई है और विज्ञान एवं टेक्नालोजी के क्षेत्र में विस्तृत एवं उपयोगी संभावनाएँ दिखाई पड़ने लगी हैं। औद्योगिक प्रगति पर जिन टेक्नोलोजिकल परिवर्तनों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वे निम्न हैं—(i) यांत्रिक शक्ति का प्रयोग (ii) विशिष्ट एवं स्वचालित मशीना का प्रचलन (iii) सप्लाय एवं मशीनों का उच्च कोटि का समन्वय, (iv) उत्पादन एवं काय दोनों का विशेषोपयोजन और (v) उत्पादक प्रक्रियाओं का समन्वय।

(२) **वित्तीय घटक**—नवीन टेक्नीकल सुधारों को प्रचलित करने के लिये पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होना अति आवश्यक होता है। टेक्नीकल अनुसंधानों पर, मजदूरों को उन्नत सुख सुविधाय प्रदान करने के लिये और एक माल का स्टॉक रखने इमारतों व साज सामान का आधुनिकीकरण करने एवं प्लांट व मशीनरी का काय योग्य दशा में बनाय रखने के लिये अपार धन राशि व्यय करनी पड़ती है। अतः जिन देशों में पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ उत्पादकता आयोजन में बड़ी उन्नति कर ली है।

(३) **प्राकृतिक घटक**—प्राकृतिक घटकों में भौतिक, जलवायु, भौतिक एवं जलवायु सम्बन्धी अन्तरो का सम्बन्ध दिया जाता है जोकि औद्योगिक प्रगति की उत्पादकता

पर एक व्यापक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिये (i) कोयला खानों की गहराई, (ii) सम्बन्धित क्षेत्र की रचना, (iii) कोयले की किस्म, (iv) कोयले की तहों की मोटाई का कोयला उद्योग की उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता पर जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, प्रमथ्यरेखीय एवं उष्ण जलवायु में श्रमिक काम करते हुए जल्दी थक जाते हैं।

(४) सामाजिक घटक—सामा-

जिक रहन-सहन एवं दृष्टिकोण का औद्योगिक प्रणाली के सुचारु संचालन से प्रायः उचित प्रकार समायोजन नहीं होने पाता। नगरों में स्थित उद्योगों में भूमि-रहित कुबक या पूरा काम न पाने वाले किसान या शहरों में बेकार निवासी ही आकर्षित होते हैं और उनमें यह आशा की जाती है कि वे कारखाने के अनुशासन को मानेंगे। यह ग्रामीण जनो के लिये, जो कि

‘औद्योगिक उत्पादकता’ पर प्रभाव डालने वाले ६ घटक	
१	टेक्नोलोजिकल।
२	वित्तीय घटक।
३	प्राकृतिक घटक।
४	सामाजिक घटक।
५	प्रबन्ध सम्बन्धी घटक।
६	सरकारी नीतियाँ।

स्वच्छन्द धातावरण में जन्मे और बड़े हैं तथा अनेक रुढ़ियों व प्रथाओं से जकड़े रहते हैं, एक क्रांति परीक्षा सिद्ध होती है। बहुत से सेवायोजकों का अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति का रुख नहीं होता वे उनकी स्वतन्त्र समिति को महत्व नहीं देते। इन सब बातों का औद्योगिक उत्पादकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

(५) प्रबन्ध सम्बन्धी घटक—यह मस्य ही कहा जाता है कि औद्योगिक विकास के इतिहास में सजग, साहसी, दूरदर्शी, प्रबन्ध कला में चतुर, कल्पना शक्ति में श्रोत-श्रोत प्रबन्धकों के लिए इतनी अधिक आवश्यकता पहले कभी भी अनुभव नहीं हुई जितनी कि आज अनुभव की जाती है, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों की सफलता एवं असफलता बहुत कुछ उन लोगों पर निर्भर होती है जो कि ^{गो की वृद्धि के परिणाम-} यह आवश्यक है कि प्रबन्धकों में संगठन की अपूर्व क्षमता, क्योंकि सयुक्त-स्कन्ध वाली उठाने की तत्परता हो, अपने अधीन कर्मचारियों एवं अधिकार व्यापारिक संगठनों का सम्मानजनक व सहानुभूतिपूर्ण हो। इन गुणों के प्रमन्डलों के निर्माण के परिणाम-दुर्लभ अस्तर पड़ता है। इतने प्रबन्ध कमान धीय रहता है न सयोग का निर्माण सरल हो का कुशल मंजेजर होना भी आज को मूल्य की कमी से कुर्बानियाँ होते हैं, उन्हें सधारी के क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है। मे क्षणिक होता है, क्योंकि कमजोर उ।

(६) सरकारी

सम्बन्धी नीति तथा ^{निकाल देने के उपरान्त, वे शक्तिशाली उत्पादक तथा नजाने के} ^{एव माने दाम माँगने लगते हैं और इस प्रकार जनता को निन्द्य-}

सकती है। जैसे, विशाल कारखानों एवं मशीनों की स्थापना के लिये कर सम्बन्धी छूट दी जा सकती है। इसके विपरीत, अत्यधिक सुरक्षण देने की नीति के कारण घरेलू बाजार में एकाधिकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा यह भी संभव है कि सरकारी सहायता के आधार पर अकुशल एवं अनाधिक इकाइयों का पालन भी होता रहे। दोनों ही दशाओं में औद्योगिक उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बड़े औद्योगिक संयोगों की उत्पत्ति पर रोक लगा कर सरकार ऐसी दशायें उत्पन्न कर सकती है जिनमें प्रतिस्पर्धा करने वाली विभिन्न इकाइयाँ अपनी उत्पादकता की वृद्धि के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। सरकार की प्रशासन एवं वित्त-नीतियाँ, विनियोग, वचन एवं एवं उद्योग से दूसरे उद्योग में पूँजी के प्रवाह को उत्साहित या निरसाहित कर सकती हैं।

भारत में उत्पादकता वृद्धि-आन्दोलन की प्रगति—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम की उत्पादकता बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया गया। उन कारणों की वैज्ञानिक जाँच कराई गई, जिनके लिए सेवायोजक और श्रमिकों का आरोप एवं प्रत्यारोप था कि वे उत्पादकता को घटाते हैं। उत्पादकता की वृद्धि के उपायों पर विचार करने के लिये अध्ययन गौष्ठियों का आयोजन भी किया गया और 'टेक्नीकल सहायता कार्यक्रम' के अन्तर्गत विदेशों से टेक्नीकल विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया गया तथा अपने शिष्ट मंडल भी विदेशों में अध्ययन के लिये भेजे गए।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के प्रथम शिष्टमण्डल का आगमन भारत में दिसम्बर सन् १९५२ में हुआ। इसमें प्रबन्ध एवं औद्योगिक इन्जीनियरिंग से सम्बन्धित चार विशेषज्ञ सम्मिलित थे। इनकी सहायता के लिये हैडक्वार्टर स्टाफ के अनेक कर्मचारी भी साथ आये थे। सरकार, उद्योगपतियों एवं श्रमिक सचों के परामर्श पर यह दल दो भागों में बँट गया और उन्होंने कसकत्ता में औद्योगिक इन्जीनियरिंग तथा बम्बई व अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल उद्योग के सम्बन्ध में अनेक प्रदर्शनों का आयोजन किया। बलकत्ता में पाँच फर्म (जिनमें एक सरकारी कारखाना भी शामिल था) चुनी गई और दल ने 'मैथड स्टडी' की टेक्नीक का अनुसरण करते हुए यह उत्पादन एवं कार्य दोनों समन्वय। द्रुतगामी ढंगों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता

(२) वित्तीय घटक—नवी उत्पादकता सम्बन्धी रिकार्डें उचित रूप से रखकर ही पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होना तयार किया जा सकता है। अधिकतर सुभाव कार्य पर, मजदूरों को उन्नत सुख, सुविधायें प्रदान करने, बच्चे स्थान और कार्यशील पूँजी से रखने, इमारतों व साज सामान का आधुनिकीकरण करना कार्य दो मिलों में आरम्भ कार्य योग्य दशा में बनाये रखने के लिये अपार धन-राशि तब विस्म, घटे हुए कार्यभार जिन देशों में पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ उत्पादकता उन्नति कर ली है। सरकार ने दिसम्बर

(३) प्राकृतिक घटक—प्राकृतिक घटकों में भौतिक, मोतिवद्वय कर लिया कि सम्बन्धी अन्तरे प्राकृतिक घटकों में भौतिक, मोतिवद्वय कर लिया कि

वेह सन् १९५४ में राष्ट्रीय उत्पादकता केन्द्र की स्थापना करने में टेक्नीकल सहायता दे। सन् १९५४ में एक दूसरा मिशन भारत आया और अनेक कारखानों में अपना कार्य फैलाया।

मार्च सन् १९५७ में एक दल डा० विक्रम सारभाई की अध्यक्षता में जापान की उत्पादकता बढ़ाने की प्रचलित विधियों का गहन अध्ययन करने के लिये भेजा गया। इस दल ने लौटकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी और उसमें इस बात पर बल दिया कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में उत्पादन सम्बन्धी जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनकी पूर्ति में विद्यमान उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये उत्पादन विधियों में सुधार करने तथा श्रमिक वर्ग में अधिक और अच्छा मान पैदा करने की भावना जागृत करना आवश्यक है। दल ने जापान की भाँति एक 'राष्ट्रीय उत्पादकता-वृद्धि काउन्सिल' (National Productivity Council) की स्थापना करने का सुझाव दिया, जिसके निम्न कार्य हो—(१) उत्पादकता की वृद्धि के लिये उपयुक्त वातावरण पैदा करना, (२) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, (३) विशिष्ट टेक्नीकल सहायता प्रदान करना एवं (४) क्षेत्रीय काउन्सिलों की स्थापना करना।

उत्पादकता वृद्धि से सम्बन्धित सेमिनार—

भारतीय मण्डल की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में पहला कदम सन् १९५७ में उठाया गया, जबकि केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्रालय ने उत्पादकता बढ़ाने के सम्बन्ध में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय उत्पादकता आन्दोलन के सिद्धान्तों और कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। सेमिनार द्वारा यह निश्चय किया गया कि कार्य का अत्यधिक केन्द्रीकरण न किया जाय और राष्ट्रीय एवं स्थानीय काउन्सिलों का कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर विस्तृत होना चाहिये अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिगत साधन से और उत्पादन की प्रत्येक इकाई में उसका सम्पर्क रहे। काउन्सिलें स्वतन्त्र रूप में संचालित हों। उत्पादकता आन्दोलन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सेमिनार ने निम्नलिखित सिद्धांतों की वृद्धि के परिणाम-

(१) उद्देश्य यह होना चाहिये कि सुधरी हो, क्योंकि समुक्त-स्कन्ध वाली दल बढ़ाया जाय और किस्म में सुधार किया जाय, अधिकतम व्यापारिक संगठनों का जाय, श्रमिकों के काम करने की दशाओं में सुधार, प्रमण्डलों के निर्माण के परिणाम-को जाय तथा इन परिवर्तनों के प्रभाव को मूल्य की कमी से कुर्छित होते हैं, उन्हें सघारी का उद्देश्य श्रमिकों के कार्य-शुद्धता को मूल्य की कमी से कुर्छित होते हैं, उन्हें सघारी

(२) एक वृद्धिशील में क्षणिक होता है, क्योंकि कमजोर का प्रोत्साहित कर अन्तिम निकाल देने के उपरान्त, वे क्षत्तिशाली उत्पादक से चलाने के

(३) उत्पन्न-माने दाम माँगने लगते हैं और इस प्रकार जनत्व की आवश्यक-के मध्य न्यायोचित f

(४) उत्पादक आन्दोलन के क्षेत्र में बड़े, छोटे और हल्के (सांख्यिक क्षेत्र में प्रथम प्राइवेट) सभी उद्योगों को सम्मिलित किया जाय ।

(५) उत्पादकता की वृद्धि के लिये उपयुक्त वातावरण पैदा करने के हेतु सयुक्त विचार-विमर्श, प्रबन्ध में भूमिकों के भाग और प्रत्येक उद्योग एवं प्रत्येक इकाई में पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

राष्ट्रीय एवं स्थानीय उत्पादकता काउन्सिलें—

राष्ट्रीय उत्पादकता काउन्सिल की स्थापना सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत सन् १९५८ में हुई । काउन्सिल में ११ प्रतिनिधि हैं, जो कि सरकारी विभागों, सेवायोजकों के सभी तथा थम सभी से लिये गये । उपभोक्ताओं, टेक्नीशियनों, लघु उद्योगों आदि के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है । कुल सदस्य संख्या ६० है । मूलनियम उद्योग मन्त्री इस काउन्सिल के अध्यक्ष हैं । काउन्सिल की एक प्रशासन समिति भी है, जिसमें १४ सदस्य हैं, जिनका निर्वाचन काउन्सिल करती है । इस समिति के चैयरमैन डाक्टर लोकनाथन हैं ।

सन् १९५८-५९ की अवधि में क्षेत्रिक, प्रांतीय एवं स्थानीय आधार पर १५ उत्पादकता काउन्सिलें संगठित करने का प्रस्ताव था । स्थानीय काउन्सिलों का संगठन राष्ट्रीय काउन्सिल के समान ही किया जाना था । प्रांतीय सरकार का प्रतिनिधि इन काउन्सिलों में रखा गया और इन काउन्सिलों को राष्ट्रीय काउन्सिल में प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

आठ-सूत्री कार्यक्रम—

अपनी पहली बैठक में राष्ट्रीय काउन्सिल ने निम्नलिखित आठ सूत्री कार्यक्रम स्वीकार किया है :—

(१) उत्पादकता से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करके उत्पादकता बढ़ाने की चेतना को बढ़ावा देना ।

(२) प्रबन्ध के सभी स्तरों पर उत्पादकता की टेक्नीक व प्रक्रियाओं की समन्वय ।

(२) वित्तीय घटक—नवीनतम आवश्यक समझे सब विशेषताओं की सेवायें पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होना ।

पर, मजदूरों को उन्नत सुख, सुविधायें प्रदान की जान, प्रोत्साहन देना, जिससे सामान्य रखने, इमारतों व साज-सामान का आधुनिकीकरण करना जैसे-जैसे ।

कार्य योग्य दशा में बनाये रखने के लिये अपार धन-राशि का प्रसन्धान कराना ।

जिन देशों में पूर्ण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ उत्पन्न लिये अपनाये गये साधनों उन्नति कर ली है ।

(३) प्राकृतिक घटक—प्राकृतिक घटकों में भौतिक, मानवीय, प्रकृतिक, सामंजस्यपूर्ण प्रयोगों का प्रयोग किया जाता है, जाव प्रयोगों का प्रयोग ।

अप्रैल सन् १९५८ में राष्ट्रीय काउन्सिल ने एक 'प्रोडक्टिविटी सर्वे कमेटी' का संगठन किया, जिसका उद्देश्य टेक्नीकल कर्मचारियों की उपलब्धता और भावी आवश्यकता के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करना था। फ़ैक्टरियों का चीफ एडवाइजर इस कमेटी का चेयरमैन है। सर्वे के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबन्ध मानवीय सम्बन्ध, औद्योगिक इंजीनियरिंग आदि को सम्मिलित किया गया। जहाँ तक प्रबन्ध का प्रश्न है, सभी थ्योरियों के प्रबन्धकों को प्रोडक्टिविटी की टेक्नीक का जो प्रशिक्षण दिया जायगा उसमें वैज्ञानिक प्रबन्ध, मानवीय सम्बन्ध, कार्य-मूल्यांकन, भूति-प्रेरणायें, औद्योगिक डिजायन, विधि विश्लेषण इत्यादि भी शामिल है। विभिन्न केन्द्रों में विशेषज्ञों की रीजनल प्रोडक्टिविटी यूनिटें स्थापित की जायेंगी, जिनकी सेवायें लोकल प्रोडक्टिविटी काउन्सिलों के द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी। बम्बई, मद्रास कलकत्ता, कानपुर और दिल्ली में ऐसी यूनिटें कायम की गई हैं।

सूचना के प्रसार के लिए एक टेक्नीकल इन्वाइरी सर्विस संगठित की जायेगी, जो कि उद्योगों द्वारा पूछे गये टेक्नीकल प्रश्नों का उत्तर देगी तथा रिपोर्टें, पुस्तिकायें, व्याख्यान, सेमिनार प्रदर्शनियों के संगठन आदि के द्वारा उत्पादकता सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करेगी।

राष्ट्रीय काउन्सिल ने आठ सदस्यों का एक दल पश्चिमी जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के कारखानों का अध्ययन करने के लिये सितम्बर सन् १९५८ में भेजा था। ऐसे ही अनेक दल अभी और भेजे जाने को हैं।

उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम में भाग लेने वाली एजेंसियाँ—

निम्न सस्यायें उत्पादकता आन्दोलन के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता कर रही हैं—

(१) दी इण्डियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट कलकत्ता ने कुछ वर्ष पहले भारतीय उद्योगों में क्वालिटी कंट्रोल की टेक्नीक को प्रोत्साहन देने के लिये सेमिनार आयोजित किये और बम्बई व बंगलौर में इसने क्वालिटी कंट्रोल यूनिटें स्थापित की हैं। दी ग्रहमदाबाद टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन्स की वृद्धि के परिणाम-क्वालिटी कंट्रोल की टेक्नीक का विस्तार करने के लिये, क्योंकि समुक्त-स्कन्ध वाली हाल में ही इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन अधिकांश व्यापारिक संगठनों का किया है।

प्रमन्दलो के निर्माण के परिणाम-

(२) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम एकमात्र ध्येय रहता है "समय का निर्माण सरल हो की है, जिन्होंने भारत के विज्ञान को मूल्य की कमी से वृद्धि-पूर्ण होते हैं, उन्हें संचारी किये हैं।

व में क्षणिक होता है, क्योंकि कमजोर उ।

(३) भारत के विकास देने के उपरान्त, वे शक्तिशाली उत्पादक से चलाने के हैं और मैनेजमेंट एसोसियेशन दाम माँगने लगते हैं और इस प्रकार जनत्व की आवश्यक-विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

(४) इण्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में बुद्ध प्राइवेट परामर्शदाता फर्म भी कार्य कर रही हैं। दी इण्डियन इस्टैब्लिश्मेंट आफ टेक्नोलॉजी सडमपुर में भी इण्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग का बेशर्त चलाया जाता है। बम्बई का प्रोडक्टिविटी सेंटर भी इस दशा में काफी प्रयत्नशील है।

(५) भारत सरकार द्वारा स्थापित स्माल इण्डस्ट्रीज इन्स्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रदान करते हैं और टेक्निक में सुधार कराने का प्रयत्न करते हैं।

(६) नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल के अन्तर्गत प्लान प्रोजेक्ट कमेटी व प्लानिंग की इण्डस्ट्रियल मैनेजमेंट रिसर्च यूनिट और अन्य कई औद्योगिक अनुसंधान एसोसियेशन भी अनुसंधान और औद्योगिक इकाइयों व प्रोजेक्टों के अधिक उन्नत संचालक संचालन की विधियों के सम्बन्ध में छानबीन कर रहे हैं।

(७) अमेरिका का टेक्नीकल कोऑपरेटिव मिशन भी प्रोडक्टिविटी आन्दोलन में बहुत कुछ सहयोग दे रहा है। उसे मैनेजमेंट लाइब्रेरियों के लिये बहुमूल्य पुस्तकें भेंट देना, विशेषज्ञों के लेक्चर आयोजित करना इत्यादि।

उपसंहार—

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में उत्पादकता आन्दोलन के प्रति लोगो का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित होता जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश कार्य का समन्वय नहीं हो पाया है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि एक ऐसा पत्र प्रकाशित किया जाय करे जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का विस्तृत व्यौरा हो। इससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता आन्दोलन का सही मूल्यांकन करने में बड़ी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को चाहिए कि वह विभिन्न एजेंसियों के कार्य में उचित समन्वय स्थापित करे और उन्हें उचित सहायता दे।

(१४) उत्पादन एवं कीय दान।

समन्वय।

(२) द्वितीय घटक—नवा^{द्रु}त^{उत्} **SECOND QUESTIONS**

पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होना^{1b} पर, मजदूरों को उन्नत सुख, सुविधाय प्रदान करने, व ^{1c} **Importance of Productivity** रखने, इमारतों व साज सामान का आधुनिकीकरण करना। कार्य योग्य दशा में बनाय रखने व लिये अपार धन राशि ^{1d} **Importance of Productivity** जिन देशों में पूर्णजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहां उत्प ^{1e} **Importance of India to in-** उन्नति कर ली है।

(३) प्राकृतिक घटक—प्राकृतिक घटकों में भौतिक, ^{1f} **Importance of India,** सम्बन्धी प्रश्नों का समावेश किया जाता है, जो कि औद्योगिक



औद्योगिक संयोगों के प्ररूप एवं उनका विकास

(Growth & Forms Of Industrial Combinations)

प्रारम्भिक विवेचन

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में इङ्ग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के बाद समस्त औद्योगिक जगत में पूँजीवाद का बोलबाला था। वह 'यथेच्छकारिता' (Laissez Faire) का युग था। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय व उद्योग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। उद्योग अथवा व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र में राज्य का लक्ष्मण भी हस्तक्षेप न था। आर्थिक क्षेत्र में भी किसी प्रकार का राजकीय नियन्त्रण न था। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में 'जिसकी साठी उसकी भैंस' यह कहावत पूर्णतः लागू होती थी। स्पर्धा पूर्णतया स्वतन्त्र व खुली हुई थी। प्रत्येक अपनी व्यवसायी जो योग्य अथवा चालाक था, वह अन्य साधियों को उस व्यवसाय क्षेत्र से स्वतन्त्र स्पर्धा की आड़ में बड़ी सरलता से निकाल सकता था। इस प्रकार विशेष नीति का आविष्कर्ता एडम स्मिथ था, परन्तु क्रमशः

लोगों को प्रतीत होने लगे। यह प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे प्रचलित हुई प्रचलित नीति ने भी लगी कि कमजोरा का गला निरर्थक ही काटा जाने लगा-काट-प्रतिस्पर्धा से बचने तथा को वेतन कम देना प्रारम्भ कर दिया तथा न्यूनतमभन्ने राष्ट्रीय शासनों ने ऐसी नीति पूँजीवाद के अन्य दोषों को भी अनुभव करने लगे। कीमती हो गया अथवा उस माल जब तक सम्पूर्ण देश में आधिक समानता एवं स्वतन्त्रता (a System) के अन्तर्गत वह की नीति यथास्वी नहीं हो सकती। जिस देश में एक दिया जाता था।

और ऐश्वर्यशाली अमीरी विराजमान हो वहाँ में उद्योगों की वृद्धि के परिणाम-नीति कदापि भ्रमल नहीं हो सकती। सीमित मितली, क्योंकि सयुक्त-स्वतन्त्र वाली नहीं है, किन्तु जहाँ वह उन विषम परिस्थितियों में अधिकांश व्यापारिक संगठनों का काट स्पर्धा (Cut throat Competition) प्रमण्डलों के निर्माण के परिणाम-क्षेत्र से बाहर निकालना ही एकमात्र ध्येय रहता है। सयोग का निर्माण सरल हो कहा जा सकता। उससे जनता को मूल्य की कमी से कुछ लाभ होते हैं, उन्हें सघारी प्रतीत होता है, वह वास्तव में दारिद्र्य होता है, क्योंकि कमजोर उद्योग

क्षेत्र व विषय क्षेत्र से निकाल देने के उपरान्त, वे शक्तिशाली उत्पादक से चलाने के अपनी वस्तुओं के मन-माने दाम माँगने लगते हैं और इस प्रकार जनत्व की आवश्यक-

से लूटते हैं। अन्त में, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सम्पूर्ण व्यवसाय किंचित उत्पादकों के हाथ में आ जाता है और आर्थिक स्वतन्त्रता के जो स्वप्न यथेच्छवारिता नीति के अतर्गत देखन की कल्पना की थी, वह सब उलट जाती है और उसके स्थान पर विदोहन (Exploitation) का नग्न नृत्य होने लगता है।

अतः १९वीं शताब्दी के अन्त में इस गला काट प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गईं, जिनमें आवागमन के सुधार, संयुक्त कम्पनियों का विस्तार तथा नवीन व्यापारिक संस्थाओं का निर्माण प्रमुख हैं। इन प्रयत्नों से भी पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिली तब व्यापारिक जगत् का ध्यान इस नियम की ओर आकर्षित हुआ कि—‘प्रतिस्पर्धा से संयोग का जन्म मिलता है’ (Competition begets Combination) अर्थात् उस समय की समस्त योजनाओं की विभिन्न प्रकार के संयोगों का रूप देने का प्रयत्न किया गया। यही नहीं, व्यापारिक संगठन तथा औद्योगिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये विभिन्न व्यापार-संस्थाओं में

एक ही उद्योग की विभिन्न शाखाओं में संघीय (Guild) पद्धति पर समझौते लगे, जिन्होंने आगे चलकर संयोगों को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार की प्राथमिक विक्रय नियन्त्रण (Limitation of vend) के लिए ब्यूकेसल (इङ्ग्लैण्ड) में बनाई गई, जिसमें कोयले का विक्रय निश्चित मूल्यों पर किया जाता था।

अंग्रेज आन्दोलन क्यों?—

अधिकांश कार्य को उत्पन्न करने वाले कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं — कि एक ऐसा पत्र प्रकाशित किया गया था जिसमें प्राचीन विस्तृत व्यापारों को हटाने का प्रयत्न किया गया था। इससे राष्ट्रीय रूप से कोई प्रवृत्ति नहीं बनी। शोषण भी क्रमशः करने में बड़ी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय अधिक भजवूरी तथा लाभ कमाने की विभिन्न एजेंसियों के कार्य में आती। उन्होंने स्वयं उद्योगों का नियन्त्रण सहायता दी।

के लगभग प्रतिस्पर्धा ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रायः छोटी मात्रा में किया जाता था, जिसमें तु बाजारों के विस्तार के साथ बड़ी मात्रा में प्रतिस्पर्धा के दोषों का भी लाभ अनुभव करने के व्यापार से किसी को भी लाभ नहीं होता था, या उत्पादक व्यापारिक क्षेत्र में एक-दूसरे का यह प्रतिस्पर्धा इङ्ग्लैण्ड में सन् १८७५-६५ की अवधि में कार्य योग्य बंश में बनाया, जबकि व्यापार में लाभ की अपेक्षा होने होना है एक जिन देशों में पूर्ण रूप से इस प्रकार की विषम परिस्थितियों से किसी को लाभ नहीं होता उन्नति कर ली है—

(२) वित्तीय घटक—नवीन वित्तीय साधन उपलब्ध होना पर, मजदूरों को उन्नत सुविधाएँ रखने, इमारतों व साज सामान कार्य योग्य बंश में बनाया, जबकि व्यापार में लाभ की अपेक्षा होने होना है एक जिन देशों में पूर्ण रूप से इस प्रकार की विषम परिस्थितियों से किसी को लाभ नहीं होता उन्नति कर ली है—

(३) प्राकृतिक व्यवस्था—Haney.
“Business Organisation”—Shields, page 80
सम्बन्धी प्रश्नों का

देख कुछ योग्य व अनुभवी व्यक्तियों ने अपना ध्यान 'संयोग' की ओर आकर्षित किया, अर्थात् प्रतिस्पर्धा ने संयोग को जन्म दिया।

(३) आवागमन के साधनों में वृद्धि तथा सुधार—आवागमन के साधनों में वृद्धि एवं सुधार के कारण बाजार का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया। व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें मिलने लगी, जिससे बड़ी मात्रा में वस्तुओं का संग्रह तथा विक्रय होने लगा। यही नहीं, उत्पादन के क्षेत्र में भी अनेक आविष्कार हुए, जिसके लिए पूँजी तथा सुदृढ़ व्यापारिक संगठन की आवश्यकता थी, अतः विस्तृत व्यापार क्षेत्र के नियन्त्रण के लिए व्यापारिक पाषण्डों (Business Associations) का निर्माण होने लगा एवं उद्योगों के परस्पर संयोग के लिए प्रस्ताव आने लगे, जिससे विभिन्न उत्पादकों एवं व्यापारियों की व्यवस्था तथा निर्देशन से लाभ उठाया जा सके।

(४) बड़ी मात्रा में उत्पादन से लाभ का आकर्षण—परिकल्पित लाभ के आकर्षण तथा आवागमन के साधनों में वृद्धि ने बड़ी मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। एक से अधिक उत्पादक मिलकर सामूहिक रूप में संयोग निर्माण करके बड़ी मात्रा में उत्पादन कार्य करने से होने वाली मितव्ययिता (Economies) का लाभ उठाने की चेष्टा करने लगे। मुख्यतया उत्पादन क्षेत्र में अर्थशास्त्र का क्रमागत वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) प्रचलित होता है, अतः सदैव बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में उत्पादन परिधाय कम रहतर्हता और उत्पादकों को विशेष लाभ मिलने की सम्भावना रहती है।

(५) प्रशुल्क नीति—विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई प्रशुल्क नीति ने भी संयोग आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया। पारस्परिक गला-काट-प्रतिस्पर्धा से बचने तथा राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक राष्ट्रीय शासनों ने ऐसी नीति अपनाई कि जिससे विदेशी माला, उनके देश में अधिक कीमती हो गया अथवा उस माल की मात्रा संकुचित हो गई, नही क कोटा पद्धति (Quota System) के अन्तर्गत वह माल केवल सीमित मात्रा में ही देश के अन्दर आने दिया जाता था।

(६) समुक्त-स्कन्ध व्यवसाय—समुक्त स्कन्ध उद्योगों की वृद्धि के परिणाम-स्वरूप भी संयोग आन्दोलन को अनेक सुविधायें मिली, क्योंकि समुक्त-स्कन्ध वाली अभिकर्तृत्व संस्थाओं द्वारा केवल थोड़े से व्यक्ति ही अधिकांश व्यापारिक संगठनों का नियन्त्रण कर सकते थे। इस प्रकार समुक्त-स्कन्ध संस्थानों के निर्माण के परिणाम-स्वरूप औद्योगिक समन्वय सम्भव हुआ, जिसके द्वारा संयोग का निर्माण सरल हो गया। इस प्रकार औद्योगिक समन्वय के हेतु जो संयोग निर्माण होते हैं, उन्हें सघारी मण्डल कहते हैं।

(७) पूँजी की आवश्यकता—बड़े-बड़े व्यवसायों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अधिक पूँजी, असामान्य योग्यता, महत्वाकांक्षा तथा प्रभावी व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है। इसी पूँजी एकत्रित करना प्रत्येक उपक्रम के लिए सम्भव नहीं

होता । फिर उक्त आवश्यकताएँ व्यापारिक एवं औद्योगिक विस्तार के साथ सीमित हो जाती हैं जिसकी पूर्ति के लिए भी व्यापारिक तथा औद्योगिक संयोगों का निर्माण किया जाता है । तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण वैयक्तिक प्रमुख व्यापार के विस्तार के साथ कम हो जाता है अतः उस विषय प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए यह उचित समझा जाता है कि उन सब उपकरणों व चीजों ऐसा कोई पारस्परिक सम्झौता हो, जिसके द्वारा वे अपने अपने क्षेत्र में किसी दूसरे के हस्तक्षेप के बिना सुचारु रूप से कार्य करते रहें । इस प्रकार 'शथिल संयोग' (Loose Combinations) हमारे यहाँ भी अधिकता से पाये जाते हैं ।

(८) औद्योगिक एवं तार्किक परिस्थिति—औद्योगिक एवं तार्किक परिस्थितियों कारण भी संयोग आंदोलन को काफी बल मिला । आधुनिक व्यापारिक विश्व की वृद्धि विभिन्न है उनकी मांग की पूर्ति करने के लिए बड़ी बड़ी निर्माण शालाओं व उत्पादन शालाओं की आवश्यकता पड़ता है । यातायात तथा संचार साधनों के उन्नत साधनों ने इन उत्पादनशालाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत बना दिया है । इस परिस्थिति ने वैज्ञानिकों को ऐसे-ऐसे नूतन अनुसंधान करने के लिए विवश कर दिया जिनकी सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हो गया । इस प्रकार औद्योगिक एवं तार्किक परिस्थितियों के कारण भी औद्योगिक संयोगों का निर्माण हुआ तथा विश्व-व्यापक विपणन अस्तित्व के कारण यह सम्भव हो गया कि कोई भी एक उद्योग अपना व्यापार क्षेत्र में अन्य विभिन्न व्यापारों को परस्पर संयोगों में आना अनिवार्य हो गया ।

(९) व्यापार चक्रों का प्रभाव—तीव्र मंदी (Boom and Depression) वर्तमान अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है । व्यापार चक्रों व कारण भी बड़े बड़े संयोगों का निर्माण हुआ । व्यापार चक्रों के कारण मंदी के समय उद्योग आर्थिक संकट में फँस जाते हैं और कभी कभी उनका अस्तित्व खतरे में हो जाता है । इनके विपरीत तेजी के युग में नूतन उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है । इस समय सभी प्रकार के व्यापार क्षेत्र में आते हैं चाहे वे व्यापारिक कार्य करते हों अथवा नहीं । मंदी के युग में ऐसे नूतन उद्योगों को या तो अपना व्यापार बन्द करना पड़ता है अथवा सीमित करना पड़ता है । उनकी नौका व्यवधार में फँस जाते हैं जिसकी पार लगाने के लिए संयोग की शरण ग्रहण करते हैं । इस प्रकार से पारस्परिक विरोध और स्पर्धा को दूर करके पारस्परिक लाभ और समृद्धि के हेतु विभिन्न प्रकार के संयोग निर्माण कर लेते हैं ।

(१०) युद्ध-कालीन प्रभाव—युद्ध-काल में वस्तुओं की मांग दो विभिन्न दिशाओं में आती है—सैनिक आवश्यकताएँ और जन साधारण की आवश्यकताएँ, जो पूर्ण रहती हैं । बड़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है, किन्तु उत्पादन का भौतिक शक्ति एक साथ नहीं हो सकती ।

मुद्रा-संसार के कारण वस्तुओं के मूल्य भी चढ़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय सरकार संयोग-निर्माण करने के लिये उत्तेजना देती है, जिससे मजदूरी, उत्पादन, माग एवं पूर्ति का नियमन हो सके तथा काम करने की परिस्थितियों पर नियन्त्रण रख सकें। इसका अपने देश में उपयुक्त उदाहरण उत्तर-प्रदेश का सुपर सिन्डीकेट लिमिटेड है।

(११) वैज्ञानिकरण की आवश्यकता—छोटे-छोटे उद्योगों में वैज्ञानिकरण के प्रयोग भी सम्भव नहीं है अतः औद्योगिक वैज्ञानिकरण करने के लिए तथा उसकी मितव्ययिता का साधन उठाने की दृष्टि से संयोग का निर्माण होने लगा।

(१२) युद्धोपरान्त-परिस्थिति—युद्ध के बाद प्रायः वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं, उद्योग नष्ट प्रायः हो जाते हैं अथवा उनका विवेकीकरण हो जाता है, बेकारी को प्रोत्साहन मिलता है तथा विभिन्न राष्ट्र औद्योगिक प्रगति के लिए अधिक मात्रा में संरक्षण कर लगाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी उद्योगों को संयोग की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिससे वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। विस्थापित विपणियों को पुनः प्रस्थापित कर सकें एवं श्रेणीगत क्लेवर को मजबूत बनाकर नष्ट प्रायः उद्योगों को जीवन दान दें।

संयोग की परिभाषा—

जब किसी उद्योग या व्यवसाय में विभिन्न इकाइयाँ किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ अंशों में अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करते हुए एक सूत्र में बँधती हैं तो इस प्रकार के बने संगठन को 'संयोग' (Combination) कहते हैं। औद्योगिक संयोग प्रायस में लड़ने, छूटने बचने की भाँति की तरह होता है। इसमें भिन्न-भिन्न छोटे-बड़े तथा प्रायस में परिस्थिति करने वाले व्यापारियों अथवा उत्पादन-कर्ताओं को एकत्रित किया जाता है तथा एक-दूसरे के सहयोग और सहायता से एक-दूसरे को हानि पहुँचा कर नहीं, परन्तु एक-दूसरे के कार्य को बढ़ाते हुए सबके हित में काम किया जाता है। यदि संयोग के सदस्य स्वेच्छा एवं ईमानदारी से कार्य करते हैं तो वह संयोग स्वार्थ तथा सुदृढ़ होता है और अपने सदस्यों की प्रगति के लिए अनन्तकारिक कार्य करता है, अन्यथा ऐसा न होने पर प्रारम्भ में ही नष्ट हो जाता है।

संयोग के उद्देश्य—

संयोग का निर्माण प्रधानतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु किया जाता है—

- (१) विषम प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करना तथा संयोग में समाविष्ट (Merged) उद्योगों में परस्पर सहायता एवं सहकार्य की आवश्यकता का निर्माण करना।
- (२) सदस्य उद्योगों में उत्पादन, वितरण, क्रय तथा विक्रय पद्धतियों के केन्द्रीकरण से उनमें व्यय में कमी करना तथा उनको पर्याप्त लाभ प्रदान करना।

- (३) प्रत्येक सदस्य उद्योग के आर्थिक एवं औद्योगिक माधनो के केन्द्रीयकरण में सम्पूर्ण उद्योग का आर्थिक क्लेवर सुदृढ़ बनाना ।
- (४) प्रत्येक सदस्य उद्योग के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के केन्द्रीयकरण से न्यूनतम व्यय में कार्यक्षम एवं समुचित प्रबन्ध तथा नियन्त्रण सुविधायें प्रदान करना ।
- (५) बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं औद्योगिक विवेकीकरण के लाभ प्रदान करना ।
- (६) प्रत्येक सदस्य की विनियोगित पूँजी पर समुचित प्रत्याय (Return) देना ।

संयोग के प्रकार एवं प्ररूप

संयोग तीन प्रकार के होते हैं —

- (I) क्षैतिज अथवा समतल संयोग (Horizontal Combination) ।
- (II) उदग्र अथवा लम्ब रूप संयोग (Vertical Combination) ।
- (III) चक्रीय संयोग (Circular Combination) ।

(I) क्षैतिज अथवा समतल संयोग

परिभाषा एवं हेतु—

इन्हें 'व्यापारिक संयोग' भी कहते हैं, क्योंकि ये विशेषतः व्यापारिक क्षेत्र में ही पाये जाते हैं । क्षैतिज संयोग का निर्माण अधिकतर विभिन्न उत्पादको व निर्माण-कर्त्ताओं द्वारा बनाई हुई एक ही वस्तु को बाजार में उचित मूल्य में बेचने के हेतु किया जाता है । प्रत्येक औद्योगिक इकाई का उत्पादन कार्य व संगठन पूर्ववत् ही चलता रहता है । उनके बीच केवल एक ऐसा समझौता हो जाता है कि उनका प्रबन्ध-व्यय कम हो जाय और उत्पादित वस्तु सरलतापूर्वक बेची जा सके । इस संयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करके अप्रबन्ध को बचाया जाय । कभी-कभी ऐसे संयोग अन्य संयोग के साथ भी इस प्रकार का समझौता कर लेते हैं, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ बना लेते हैं तथा बाजार पर अपना एकाधिकार जमा लेते हैं । विपणि पर एकाधिकार के कारण ये उत्पादन पर नियन्त्रण कर सकते हैं तथा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में भी समर्थ हो जाते हैं ।

विशेषता तथा लाभ—

क्षैतिज संयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पारस्परिक-विरोधी-स्पर्धा को जड़ में उखाड़ देते हैं । जो भी स्पर्धा शेष रह जाती है, उसे हम उचित व लाभप्रद (Healthy) कह सकते हैं और उनसे जनता को विशेषतया लाभ ही पहुँचता है । संयोग में सम्मिलित विभिन्न इकाइयाँ आवश्यकतानुसार उत्पादन शक्ति

को घटा या बड़ा सकती है। कारखाने में काम के घंटे घटाकर व वस्तुओं का मूल्य समान निश्चित करके तथा सबके माल के विक्रय के हेतु विक्रय संगठन (Mutual Sales Organisation) स्थापित कर बड़ी सरलता से आवश्यकता नुसार परिवर्तन व संशोधन करके बाजार में उत्पादित वस्तु विशेष को माँग से अधिक नहीं होने देते। शैतिज संयोग की दूसरी विशेषता यह है कि ये उन तान्त्रिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें साधारणतः प्रत्येक इकाई पृथक् रूप से नियुक्त नहीं कर सकती थी। तीसरे, प्रत्येक इकाई अनुसन्धान का भी प्रबन्ध कर सकती है।

अवगुण—

इतने गुणों के होते हुए भी इस प्रकार के संयोगों में कुछ अवगुण भी हैं। सबसे बड़ा दोष, जो भारतवर्ष में प्रधानतः देखने में आता है, वह यह है कि उत्पादित वस्तुओं को निश्चित रूप से बेचने का उत्तरदायित्व कोई नहीं लेता। दूसरे, सामूहिक शक्ति के एकीकरण के कारण वे इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि जनता से मनमाने दाम लेकर असहाय जनता का बलिष्ठ हाथों से खूब शोषण करते हैं, किन्तु ये दोष उसी दशा में होते हैं जब वे उत्पादन एवं उपभोग विपणन पर अपना एकाधिकार प्रस्थापित कर अन्य उत्पादकों को (जो संयोग के सदस्य नहीं होते) उद्योग क्षेत्र से उन्मूलन करने में सफल हो जाते हैं।

उदाहरण—

शैतिज संयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'दी एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड' है। वास्तव में 'दी इण्डियन सीमेन्ट मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन' तथा 'एसोसियेटेड सीमेन्ट मार्केटिंग ऑरगेनाइजेशन' का सम्मिलित रूप है। अन्य उद्योगों ने अभी शैतिज संयोग की ओर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि युद्धकालीन परिस्थिति के कारण उत्पादन के विक्रय में उन्हें असुविधाएँ अभी अनुभव नहीं हुई हैं। दूसरे, अभी भारत में उद्योगों का उत्पादन भी इतना अधिक नहीं हुआ है कि जिसमें नवीन विपणनों की खोज की जा सके।

(II) उद्यम या सम्बन्ध संयोग

परिभाषा —

इन्हें 'औद्योगिक संयोग' भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिकांशतः औद्योगिक जगत में पाये जाते हैं। इस प्रकार के संयोग में अनेक प्रकार के उद्योगों का समावेश होता है। इनमें विभिन्न उद्योगों का समावेश इस प्रकार होता है कि जिसमें उत्पादन के प्रारम्भ की सीढ़ी से अन्तिम सीढ़ी तक के सभी उद्योग आ जायें। उदाहरण के लिये, अगर मोटर गाड़ियों के उत्पादन का काम है तो उसमें निम्न अवस्थाएँ हो सकती हैं— (अ) इंजन का निर्माण, (ब) डिब्बे का निर्माण, (स) रबड़ के ट्यूब-टायर व पहियों का निर्माण, (द) काँच का सानान, (इ) गह्वियों का निर्माण इत्यादि। यदि मोटर-गाड़ियों के उत्पादन की इन विभिन्न अवस्थाओं का सम्बन्ध हो जाय तो ऐसे संयोग

को लम्ब रूप संयोग कहेंगे, अतः यह स्पष्ट है कि उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में अन्तिम अवस्था तक पहुँचने के लिए जितने भी मध्यस्थ उद्योग होंगे, उन सब उद्योगों का यह एक सगठन होता है, इसलिए ऐसे संयोग को उदग्र सन्नि-ययन (Vertical Integration) भी कहते हैं।

लम्बरूप संयोग के हेतु—

लम्बरूप संयोग निम्न उद्देश्यों में बनाए जाते हैं :—

- (१) विभिन्न अवस्था वाले उद्योगों के एकसूत्रीकरण से उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में होने वाले अपव्यय को कम करना।
- (२) ऋय-विक्रय, यातायात एवं विज्ञापन में होने वाले व्यय को कम करना।
- (३) संयोग में आने वाले विभिन्न उद्योगों की क्रियाओं के सुव्यवस्थित एकसूत्रीकरण से प्रत्येक सदस्य उद्योग के लाभ बढ़ना।
- (४) उद्योगों के उत्पादन सम्बन्धी एकसूत्रीकरण से प्रत्येक कम्पनी के आन्तरिक व्यवस्था सम्बन्धी व्यय को कम करना।

लम्बरूप संयोग के लाभ—

- (१) इस प्रकार के संयोग से प्रबन्ध व्यय में भिन्नव्ययिता होती है और सग्रह विक्रय, अर्निमित वस्तुओं के ऋय तथा यातायात इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में बचन होती है।
- (२) उपयोग में आने वाली आर्थिक तैजी अथवा मन्दी का परिणाम संयोग से सम्बन्धित इकाइयों के उत्तरोत्तर विकास पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता।
- (३) प्रत्येक सदस्य उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल भी उसे अपनी निचली अवस्था के उद्योग से मिलता रहेगा। केवल सबसे निचली अवस्था वाले उद्योग को ही कच्चा माल प्राप्त करना पड़ेगा।
- (४) संयोग में आने वाले सभी कारखाने एक उद्योग की विभिन्न क्रिया करते हैं, जिससे क्रियाओं का विशेषीकरण हो कर उद्योग की कार्य क्षमता एवं उत्पादनशीलता बढ़ जाती है।
- (५) कच्चे माल की खरीद, निर्मित माल की बिक्री, विज्ञापन आदि उपयुक्त मितव्ययिताओं की वजह से उद्योग का लाभ बढ़ जाता है।

लम्बरूप संयोग के दोष—

- (१) क्षैतिज अथवा समतल संयोगों की भांति इनमें औद्योगिक अनुसन्धान के लिए कम अवसर होता है, जिसे औद्योगिक कार्यक्षमता बढ़ाने का अवसर इस संयोग में नहीं मिलता।
- (२) सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि इन विभिन्न अंगों में से एक भी अंग यदि किसी प्रकार भी स्थित पड़ जाय या विस्थापित (Dislocate)

हो जाये तो उस उद्योग सयोग की सम्पूर्णा अर्थ-व्यवस्था शिथिल तथा छिन्न-भिन्न हो जाती है । यह बात सैतिज सयोग में नहीं होती ।

(३) उद्योग सयोगों के बहु-परिमाण उत्पादन से होने वाले लाभ भी उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि इनमें सदस्य उद्योग का स्वरूप समान न होते हुए भिन्न होता है ।

(४) ऐसे सयोग पूर्ण होते हुए भी अन्य उद्योगों से होने वाली प्रतिस्पर्धा को टाल नहीं सकते ।

उदाहरणार्थ, पुस्तक प्रकाशन मण्डल के लिए मुद्रणालय, कागज के कारखाने, लुग्दी बनाने के कारखाने आदि का सयोग अथवा ऐसा शक्कर व्यवसाय जिसमें कच्चे माल की पूर्ति, गुड का शुद्धिकरण, रैक्टीफाइड स्प्रिट बनाने का कारखाना, आदि सभी का समावेश हो ।

(III) चक्रित संयोग

परिभाषा—

चक्रित सयोग आरम्भ निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा बड़े-बड़े उद्योगों को नियन्त्रण में रखने की लालसा में निर्मित किए जाते हैं । इन्हें पूरक (Complementary) सयोग भी कहते हैं और इनके निर्माण में उपर्युक्त नियमों में से कोई भी मान्य नहीं है । भारतवर्ष में ऐय सयोग अधिकता से पाये जाते हैं, क्योंकि यहाँ के औद्योगिक विकास में प्रबन्ध अभिकर्तारों का विशेष हाथ रहा है एवं उन्होंने विभिन्न व्यवसायों को अपने नियन्त्रण में कर लिया है । इस प्रकार अगर एक ही प्रबन्ध अभिकर्ता की देख-रेख में कुछ वस्त्राद्योग, शक्कर-उद्योग, सूट-मिलें इत्यादि कारखाने हो तो ऐसे सयोग को 'चक्रित सयोग' कहेंगे ।

विशेषता —

चक्रित सयोग मुख्यतया आकस्मिक होते हैं अथवा वे व्यापारिक जगत में प्रबन्ध-अभिकर्तारों की शक्ति प्राप्ति की लालसा के प्रतीक होते हैं । बड़े-बड़े पूँजीपतियों को विभिन्न उद्योगों पर नियन्त्रण रखने की लालसा होती है और इसी लालसा से प्रेरित होकर वे अपना हाथ विभिन्न उद्योगों में फैसाते चले जाते हैं । भारतवर्ष में चक्रित सयोग के निम्न उदाहरण हैं — बिरला ब्रादर्स लिमिटेड, जे० के० ग्रुप माटिन एण्ड कम्पनी, बग सदरलेड, एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी इत्यादि ।

सयोगों के प्ररूप

(Forms of Combinations)

सयोगों का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । भिन्न-भिन्न देशों में सयोगों का विकास विभिन्न परिस्थितियों में हुआ है । मिश्र देश के जोसिफ नामक एक अन्न-नियन्त्रणकर्ता ने साध सामग्री का एक ऐसा शक्तिशाली सयोग स्थापित किया था, जो बाद में विश्व

के अनेक भागो में प्रभावशाली सिद्ध हुआ। १८वीं शताब्दी में विक्रय नियन्त्रण के द्वारा विक्रय एवं मूल्यों का परस्पर समझौते द्वारा निर्धारण किया जाता था। तत्पश्चात् जसत औद्योगिक राष्ट्रा में देश, काल एवं आर्थिक परिस्थिति के अनुसार तथा औद्योगिक आवश्यकतानुसार समझौते की ओर प्रवृत्ति बढ़ी और इन आवश्यकताओं के अनुसार ही विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के समझौते का निर्माण हुआ। समझौते को उनके आधार-प्रकार की दृष्टि से अनेक नाम दिये जाते हैं, जैसे—

- (I) व्यापारिक पार्षद (Trade Associations),
- (II) उत्पादक पार्षद (The Cartels),
- (III) प्रत्यास (Trusts),
- (IV) पूँजीपति-सम (Rings),
- (V) गोष्ठियाँ (Conventions),
- (VI) कोण (Corners),
- (VII) सम (Pool),
- (VIII) सधारो प्रमण्डल (Holding Company),
- (IX) संयोग (Combinations)।

अब हम संयोग के प्रमुख रूपों का विवेचन करेंगे :—

(i) व्यापारिक पार्षद (Trade Associations)

निर्माण विधि—

इस प्रकार के पार्षद विशेषतः व्यापारिक क्षेत्र में मिलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र प्रयत्ना जाति के व्यवसायी मिलकर अपनी इच्छा से पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सरल तथा ढीली प्रकृति का संयोग बना लेते हैं। इस प्रकार के पार्षद का निर्माण करने के लिए किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं करनी पड़ती। ये मुख्यतया व्यक्तिगत विश्वास तथा बचन-बद्धता (Gentlemen's Promises) पर निर्भर रहते हैं।

पार्षद की नियमित रूप से चालू रखने के लिए उस सदस्यता के हितु सदस्यों को प्रवेश के समय प्रवेश-शुल्क एवं प्रति वर्ष वार्षिक शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क समान रूप से प्रत्येक सदस्य से लिया जाता है अथवा प्रत्येक सदस्य साधन प्रथम उद्योग की पूँजी के अनुसार अथवा उनकी वार्षिक विशिष्ट के अनुपात में निर्दिष्ट किया जाता है।

पार्षद का निर्माण जाति अथवा प्रदेश के आधार पर हो सकता है। जातिगत आधार का मुख्य उदाहरण है, 'मारवाडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स' और प्रादेशिक आधार का उदाहरण है, 'बोम्बे मिल ट्राई एंजोसियेशन'।

पार्षदों के उद्देश्य—

- (अ) आवश्यकतानुसार उत्पादन पर नियन्त्रण रखना, अर्थात् असाधारण व युद्धकालीन परिस्थितियों में उत्पादन को सीमित करना ।
- (ब) मन्दी के समय में, जब सदस्य सार्थों की उत्पादन शक्ति जनसाधारण की माँग से अधिक हो तो प्रत्येक सदस्य सार्थ को उत्पादन कम करने के लिए निश्चिन्त योजना के अन्तर्गत विवश करना ।
- (स) विज्ञापन व्यय में मितव्ययिता लाने की दृष्टि में सामूहिक-विज्ञापन आन्दोलन करना ।
- (द) औद्योगिक प्रगति के लिए एवं उत्पादन में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से अनुसन्धानशालाओं का सामूहिक व्यय से आयोजन करना ।
- (इ) स्वस्थ-प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना ।
- (फ) सूचना-विभाग स्थापित करना और उसके द्वारा सभी सदस्यों को लाभ पहुँचाना ।
- (ज) विक्रय की शर्तों, व्यापारिक साख एवं अपहार देने की शर्तों, अम प्रदाय अथवा माल के पैकिंग एवं इस सम्बन्धी सदस्यों में किसी प्रकार का र मझौता करना एवं इस सम्बन्ध में उन्हें विशेष सुविधाएँ प्रदान करना ।

इन पार्षदों के कार्य संचालन के लिए एक कार्यवाह (Secretary) होता है । सदस्य-सार्थों के प्रवन्धकों में से एक कार्यकारिणी (Executive) बनाई जाती है, जिसके सदस्य लगभग २, ३ अथवा ५ वर्ष के लिए साधारण सदस्यों में से चुने जाते हैं । कार्यकारिणी का एक सभापति (President) भी होता है और वह तांत्रिक सलाहकार तथा कार्यवाहक की सहायता से पार्षद का कार्य करता है ।

भारतवर्ष में पार्षदों का अभाव नहीं है । अनेक पार्षद विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, जैसे—‘ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसिएशन’, ‘दी इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन’ इत्यादि । यहाँ दो केन्द्रीय चैम्बर भी हैं :—

- (क) एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स, जो मुख्यतया विदेशी व्यापारियों द्वारा संचालित व नियन्त्रित है ।
- (ख) दी फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बरस ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज । ये दोनों केन्द्रीय चैम्बर भारतवर्ष के प्रायः सभी छोटे-बड़े चैम्बरों को अपनी सदस्यता में ले चुके हैं । इनका प्रधान उद्देश्य भारतीय व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग को उचित संरक्षण प्रदान करना तथा देश के उद्योगों का विकास उचित मात्रा में करने के लिए सहायता देना है ।

(II) उत्पादक संघ (Cartels)

परिभाषा—

समान व्यवसाय में सगे हुए विभिन्न स्वतन्त्र व्यवसायी जब अपनी इच्छा से तथा विपणि पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पारस्परिक अनुबन्ध में बंध जाते हैं तो उत्पादक संघ अथवा 'कार्टेल' बन जाता है। डाक्टर इसे क अनुसार "उत्पादक संघ स्वतन्त्र व्यवसायियों का एक पापंद है, जो उत्पादन, विपणन-क्रय, मूल्य-निर्धारण अथवा व्यापारिक शर्तों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का भार सदस्यों पर रखता है तथा स्वतन्त्र-प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध विपणि को प्रभावित करता है।" जब ये संघ साधारण विक्रय संगठन स्थापित करते हैं, तो इन्हें 'व्यापारी संघ' (Syndicates) कहते हैं। उत्पादक संघ बहुधा राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय होते हैं। जर्मनी उत्पादक-संघों की जन्म-भूमि है। जर्मनी, आस्ट्रिया, बेल्जियम इत्यादि योरोपीय देशों में ही ये अधिकता से मिलते हैं। जर्मनी तथा आस्ट्रिया में तो लोहा, इस्पात तथा अन्य धातुओं की निर्मित वस्तुओं का संगठन करने वाले शक्तिशाली उत्पादक-संघ भी मिलते हैं। कार्टेल उत्पादकों का एक सिविल संयोग होता है। इसकी सिविलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह बड़ी शीघ्रता से स्थापित हो जाता है और शीघ्रता से टूट भी जाता है। इनमें न तो किसी व्यवसाय के ऊपर संघ का नियन्त्रण ही रहता है और न प्रत्येक प्रमण्डल के लाभ की कोई मर्यादा ही निश्चित की जाती है, किन्तु केवल इतना प्रतिबन्ध रहता है कि कोई सदस्य संघ द्वारा निश्चित मूल्यों से कम पर अपनी वस्तुएँ नहीं बेचेगा।

मुख्य लक्षण—

उत्पादक-संघ के तीन प्रमुख लक्षण हैं:—

- (अ) एक ही व्यवसाय में सगे हुए विभिन्न व्यवसायी कार्टेल बना सकते हैं।
- (ब) उत्पादन एवं विक्रय के सम्बन्ध में ये परस्पर स्वेच्छा से अनुबन्ध करते हैं।
- (स) उनका संयोग बनाने का मुख्य लक्ष्य 'विपणि एकाधिकार' प्राप्त करना होता है।

1 "An association of independent undertaking which enforces obligations as to the treatment of output, market-purchase, price calculations of trade terms and, therefore, serves to influence the market against the working of free competition"—Dr Issai—Combines and Rationalization in Germany—D. Warriner

निर्माण क्यों हुआ ? —

कार्टेल प्रायः 'सकट के उत्पाद' (Children of Distress) कहलाते हैं, क्योंकि जब उन्मुक्त रूप से प्रतिस्पर्धा चारा और फैलने लगती है, तब समस्त औद्योगिक व्यवसायो का विनाश होना प्रारम्भ हो जाना है। प्रतिस्पर्धा केवल मूल्य तक ही सीमित नहीं रहती, किन्तु कभी-कभी वस्तुओं के गुण एवं रूप पर भी प्रभाव डालती है। परिणामस्वरूप, अत्यधिक उत्पादन होने लगता है, यहाँ तक कि उन समस्त वस्तुओं का बाजार में बिकना असम्भव हो जाता है। इस मनोवृत्ति पर नियन्त्रण करने के अभिप्राय में उत्पादक-सघों का निर्माण किया गया है।

उत्पादक-सघों की अर्थ-पूर्ति—

उत्पादक-सघों के लिए आवश्यक पूँजी सदस्या से ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक सदस्य प्रमण्डल को उसके उत्पादन के अनुसार कुछ निश्चित कोटा सघ की पूर्ति के लिए दना होता है। सदस्यों को कार्टेल द्वारा निर्धारित नियमों को स्वेच्छा से मानना पड़ता है, किन्तु वह उत्पादन एवं विक्रय के अतिरिक्त अपने व्यवसाय की अन्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र रहता है। उत्पादन कोटा निश्चित करने व समान मूल्य निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार कार्टेल को होता है। सघ के नियमों का पूर्णतः पालन हो रहा है अथवा नहीं, इस बात को देखने के लिए कार्टेल निरीक्षकों (Inspectors) की नियुक्ति करता है।

कार्टेल के रूप—

उत्पादक सघों के प्रमुख प्रारूप इस प्रकार हैं:—

(१) मूल्य निर्धारण कार्टेल— इनका मुख्य लक्ष्य यह होता है कि कोई भी सदस्य-प्रमण्डल कार्टेल के द्वारा निर्धारित मूल्य में कम मूल्य पर अपनी वस्तुएँ न बेचे। आवश्यकतानुसार समय-समय पर मूल्य में परिवर्तन भी किये जाते हैं, किन्तु सब आवश्यक आदेश कार्टेल द्वारा ही सदस्यों को दिये जाते हैं।

(२) शर्त निर्धारण कार्टेल— इस प्रकार के सघ साधारणतः विक्रय सम्बन्धी शर्तें निर्धारित करते हैं, जैसे—ग्रहण की दर, साख की मर्यादा एवं अवधि, वस्तुओं के पैकिंग व बीमा कराने सम्बन्धी शर्तें इत्यादि।

(३) प्रदेश निर्धारक कार्टेल— इससे द्वारा प्रत्येक सदस्य प्रमण्डल के लिए निश्चित विपणि निर्धारित कर दिये जाते हैं और कोई भी सदस्य अन्य किसी सदस्य के निर्धारित किये हुए विपणि-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिये कभी-कभी इन्हें 'विपणि पूल' भी कहते हैं।

(४) कोटा निर्धारक कार्टेल— जब उत्पादन अधिक और माग कम होती है, तब वस्तुओं का उत्पादन सीमित करने के लिए उत्पादन-कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य-प्रमण्डल की उत्पादन शक्ति के अनुपातानुसार उत्पादन कोटा निर्धारित किया जाता है।

(५) गुण निर्धारक काटेल—इस प्रकार के सघ अपने सदस्यों को प्रत्येक वस्तु के उत्पादन का प्रमाण निश्चित कर देते हैं और उसी प्रमाण के अनुसार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं ।

(६) अभिषद्—कुछ जमन लेखकों के अनुसार काटेल और अभिषद् (Syndicates) में अन्तर है । उनके अनुसार जब कि प्रथम प्रकार का संयोग मूल्य निर्धारण उत्पादन नियमन विपणि नियोजन करता है तो अभिषद् केवल सदस्यों के विपणन के हेतु एक विक्रय संगठन का निर्माण करता है जिससे उनकी वस्तुओं का मितव्ययिता से क्रय हो सके किन्तु अधिकांश लेखकों के मतानुसार अभिषद् काटेल का एक ही प्ररूप है । अभिषद् का निर्माण बहुधा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है —

(अ) भाग का प्रत्येक सदस्य को समुचित वितरण ।

(ब) पूर्ति का प्रत्येक सदस्य को समान एवं समुचित वितरण ।

(स) वस्तु विशेष से प्राप्त लाभ से प्रत्येक सदस्य प्रमण्ड को समुचित लाभदा देना ।

उत्पादक सघों के लाभ—

(१) प्रतिस्पर्द्धा का उन्मूलन—किसी भी प्रकार के बाहरी एवं अनिर्णायक नियंत्रण की पर्येक्षा स्वयं नियमित तथा ऐच्छक नियमों से सदैव प्रभावशाली होता है । इस दृष्टि से काटेल निर्माणकर्त्ताओं का विषम प्रतिस्पर्द्धा को उन्मूलन करने में सफल हुए हैं । नये उत्पादनकर्त्ताओं में परस्पर सहयोग तथा मेल की भावना बढ़ती है ।

(२) उपभोक्ताओं को लाभ—उत्पादक सघ जन साधारण की मांगों का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि इनके द्वारा निश्चित किये हुए मूल्य प्रायः सामाजिक व व्यापक होते हैं ।

(३) मध्यस्थों का विलोपन—निर्माणकर्त्ताओं तथा उपभोक्ताओं के बीच जो मध्यस्थों की कड़ी होती है उसे काटेल अलग करने का प्रयत्न करते हैं । यही नहीं वे निजी विक्रयशालाय खोलकर जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार जनता को वस्तुय सस्ते दामों पर उपलब्ध होने लगती है ।

(४) उत्पादन तंत्र में विकास—समान उत्पादकों का संयोग होने से उत्पादनतंत्र (Technique of Production) में भी सुधार होता है । उत्पादक वस्तुओं के प्रमापीकरण की ओर ध्यान देते हैं अतः नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है ।

उत्पादक-सघ से हानियाँ—

(१) शोषण—उत्पादक-सघ पूँजीपतियों का समूह होता है अतः यह पूँजीवादी नीति अपनाता है तथा जनता के शोषण से अपना पैट भरना चाहता है । जिन

क्षेत्रों में उन्हें एकाधिकार मिल जाता है, वहाँ वे उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूल करते हैं।

(२) उत्पादक-संघों को विदेशी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा से भय बना रहता है, परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों का निर्माण होता है, जो राजनैतिक दृष्टि से अवाञ्छनीय होते हैं, क्योंकि उनके निर्माण से यह सम्भव होता है कि आर्थिक अशक्त राष्ट्र के उत्पादन पर आर्थिक सुदृढ राष्ट्र नियन्त्रण करे।

कार्टेल्स की वर्तमान नीति —

उत्पादक-संघों ने राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन किया है, जिसमें उन्हें जो शक्ति मिली उसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्टेल्स का निर्माण करने को प्रोत्साहन दिया। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्टेल्स के निर्माण की प्रवृत्ति का बोलबाला है। अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स की संख्या, जो प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व ११४ थी, वह द्वितीय युद्ध पूर्वकाल तक १७५ हो गई है। ये संघ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय पर नियन्त्रण कर रहे हैं तथा अधिकाधिक नियन्त्रण एवं लाभ प्राप्त करने की लालसा से १९४५ के बाद से अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

गत कुछ वर्षों से उत्पादक संघों की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति में बहुत सुधार हुआ है। अब ये केवल निजी लाभ की ओर ही ध्यान न देकर जनता के सार्वजनिक हितों का भी ध्यान रखते हैं। वस्तुओं की विस्म में उन्नति तथा उचित मूल्य के निर्धारण में उन्होंने अच्छी शक्ति पाई है। बहुत सा माल जो पहले व्यर्थ चला जाता था अब नष्ट नहीं होने दिया जाता है। मध्यस्थों की कड़ी भी छोटी होती जा रही है। उत्पादन पद्धति में भी अनेक सुधार हुए हैं तथा अन्वेषण हो रहे हैं।

उत्पादक संघों की कठिनाइयाँ—

कार्टेल्स को निम्नलिखित कारणों से आपत्तियों का सामना करना पड़ा है :—

(१) सदस्यों का विश्वासघात—उत्पादक-संघों का अस्तित्व केवल सदस्यों के परस्पर विश्वास पर निर्भर रहता है, अतः यदि कोई सदस्य संघ से विश्वासघात करता है तो संघ उसके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकता और जब ऐसे विश्वासघाती सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो संघ का ही अस्तित्व डावाडोल होने लगता है। व्यवहार में ऐसे अनेक सदस्य होते हैं जो संघ के नियमों का अक्षरशः पालन नहीं करते। परिणामस्वरूप संघों का विनाश हो जाता है।

(२) अस्तित्व की अवधि के कारण—ऐसे संघों का निर्माण बहुधा विशेष परिस्थिति में तथा निश्चित अवधि के लिए होता है, जिसके व्यतीत होने पर संघ का अस्तित्व रहेगा अथवा नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(३) बाहरी लोगों के कारण—उत्पादक संघों को चिरस्थायी बनाने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन एवं मूल्यों का उचित स्तर स्थापित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें एक वस्तु के अधिक से अधिक निर्माता सदस्यता प्राप्त करें,

परन्तु यदि ऐसा न हो तो सध कमजोर हो जाता है तथा उसका अस्तित्व भी खतरा में पड़ जाता है ।

(४) नवीन विकास के कारण—उत्पादक-सधो में बहुधा इतनी शक्ति नहीं होती कि वे नए उद्योगों के विकास को रोक सकें । जब नए-नए उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो वे इन सधो को ही समाप्त कर डालते हैं ।

(५) असन्तुष्ट सदस्यों के कारण—उत्पादक सधो के अधिकांश कार्य सदस्य प्रमण्डलों की व्यक्तिगत रुचि पर अंकुश रखते हैं, यतः प्रत्येक सदस्य अपने वैयक्तिक के विकास में इन्हे बाधक समझता है । जब कोई औद्योगिक व्यवसाय अपनी मुख्यवस्तु करके उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो ये सध अपने नियमों के कारण उन्हें उन्नति नहीं करने देते, जिसके कारण वे प्रायः इनसे असन्तुष्ट रहते हैं ।

उपयुक्त पाँच कारणों में ही उत्पादन सधों का अस्तित्व विशेषतः चिरकालीन नहीं रहता ।

(III) ग्रन्थास (Trusts)

व्युत्पत्ति—

व्यापारिक संयोग का यह रूप सर्व प्रथम सन् १८७६ में स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी द्वारा स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट के रूप में सम्मुख आया । संयुक्त राज् अमेरिका ट्रस्ट्स की जन्मभूमि है । १९वीं शताब्दी के अन्त में जब अमेरिका की अनेक रियासतों में संयोग ग्रान्दोलन के विषय कदम उठाये जा रहे थे, उस समय वहाँ की 'मैसाचुसेट्स' (Massachusetts) नाम्नी रियासत में ट्रस्ट नामक संयोग की नींव पड़ी और इसी के आधार पर उन ग्रन्थासों को 'मैसाचुसेट्स' ग्रन्थास कहते हैं ।

परिभाषा—

'ट्रस्ट' शब्द का मूल अर्थ है 'विश्वास' (Confidence), अतएव जब कभी कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के हाथों यह विश्वास करके सौंप दी जाती है कि वह उसका किसी अन्य निश्चित व्यक्ति के लिए अथवा किसी ऐसे उद्देश्य विशेष के लिए जो धर्मार्थ ही, प्रयोग करेगा तो इस प्रकार संरक्षण में रखी हुई सम्पत्ति को ट्रस्ट ग्रन्थास में रखी कहेंगे । इस प्रकार के धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा धर्मार्थ (Charitable) ग्रन्थास भारतवर्ष में भी अनेक हैं । आजकल 'ग्रन्थास' का प्रयोग 'संयोग' के अर्थ में भी किया जाता है, जिसका अग्रिप्राय पूँजी का संगठन तथा वस्तुभा की पूर्ति एवं उनके मूल्य पर शक्तिशाली नियंत्रण करना होता है । इन्हें 'संयोग ग्रन्थास' भी कहते हैं और वे किसी निश्चित हेतु की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं । श्री रॉबर्टसन^१ के अनुसार इस प्रकार के संयोग-ग्रन्थास में—“विभिन्न कम्पनियों के स्कन्वधारी अपने

स्कन्ध प्रत्यासियो (Trustees) को हस्तान्तरित करते हैं, जिसके बदले में उन्हें प्रत्यास-प्रमाण-पत्र (Trust Certificate) दिया जाता है, जिस पर मूल अश-धारियों को लाभार्थ प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा प्रत्यासियो को उन कम्प-नियों के प्रबन्ध का अधिकार मिलता है ।" ये प्रत्यास प्रमण्डलो की सम्पूर्ण व्यापारिक एवं औद्योगिक नीति का नियोजन करते हैं । जो व्यक्ति प्रत्यास नियन्त्रण के लिए विश्वास-पात्र समझे जाते हैं एवं जिन्हें उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, उस व्यक्ति समूह को प्रत्यास सभा (Board of Trustees) कहते हैं ।

प्रत्यासों के रूप—

प्रत्यासों के ट्रस्टीज को जो विभिन्न प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं, उनके अनुसार ही प्रत्यासों के विभिन्न प्ररूप होते हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—

(१) **संसाधन-प्रत्यास** इसका जन्म अमेरिका की नान्नी रियासत में हुआ था । यह अपूर्ण मधनन का एक नया प्ररूप था । इसमें प्रत्येक प्रमण्डल का पृथक् अस्तित्व रहते हुए अशधारियों के सम्पूर्ण अश का हस्तांतरण कुछ घुने हुए प्रत्यासों को दे दिया जाता था, जो विभिन्न प्रत्यास-प्रमण्डलों की व्यवस्था का नियन्त्रण करते थे ।

(२) **स्थायी या इकाई-प्रत्यास**—इनका उदय सर्वप्रथम सन् १९३१-३२ में अमेरिका में हुआ । उस समय मन्दी की परिस्थिति में विवक्षित होकर लगभग ६० करोड़ डॉलरों की पूँजी के स्थायी-प्रत्यास स्थापित किये गये । इनमें प्रत्यास की पूँजी केवल कुछ निर्धारित विशेष उद्योगों में ही विनियोजित की जाती है । इनकी अवधि निश्चित रहती है और अवधि के उपरान्त इनको बेच दिया जाता है । इस प्रकार स्थायी प्रत्यास स्वयं स्थायी नहीं होते । उनको स्थायी केवल इस अर्थ में कहते हैं कि जो कुछ रुपया विनियोजित किया जाता है, वह कुछ निश्चित प्रमण्डलों का ही किया जाता है और जब तक वह प्रत्यास अपना काराबार करता रहता है, उस समय तक विनियोजन में कोई रूपान्तर नहीं किया जाता ।

(३) **भूतधिकारी प्रत्यास**—इस प्रकार के प्रत्यासों में किसी भी प्रमण्डल के बहुसंख्यक अशधारी अपने अशों का हस्तांतरण प्रत्यासियों को करते हैं और यह हस्तांतरण केवल भूतदान तक ही सीमित रहता है । अशों का भूतधिकार हस्तांतरण केवल कुछ निश्चित अवधि के लिए ही किया जाता है और अवधि समाप्त होने पर अश पुनः मूल अशधारियों को प्राप्त हो जाते हैं ।

(४) **विनियोग प्रत्यास**—ऐसे प्रत्यास प्रमण्डल अधिनियम के अन्तर्गत बनाए जाते हैं तथा अपने अशों एवं ऋण-पत्रों के निर्गमन से प्राप्त पूँजी को विभिन्न उद्योगों के अश आदि खरीदने में विनियोग करते हैं । इस प्रकार विभिन्न उद्योगों के अश तथा ऋण-पत्रों का क्रय-विक्रय करते रहते हैं और इससे जो व्याज तथा लाभार्थ मिलता रहता है, उसमें से अपने अशधारियों को लाभार्थ तथा ऋण-पत्र-

पारियो को ध्याज देते हैं। इन्हें प्रबंध-द्रव्यास (Management Trust) भी कहते हैं।

(IV) संघ

(Pool)

परिभाषा—

श्री हैने के अनुसार—‘पूल’ “व्यापारिक संगठन का वह प्ररूप है, जो विभिन्न व्यापारिक इकाइयों के साधन से बनाया जाता है। इसके सदस्य ‘मूल्य’ के ऊपर कुछ सीमा तक नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं तथा निर्धारित मूल्य में पारस्परिक संगठन के लिए कुछ अंश सम्मिलित करके उस समूह का अभिभाजन इकाइयों में करते हैं।” यह संयोगो का सबसे विकसित प्ररूप है। संघ और उत्पादक संघ में मुख्य अन्तर यह है कि संघ में उत्पादक संघ की भाँति विक्रय संगठन का निर्माण नहीं किया जाता।

संघ-निर्माणकर्ता का प्रधान लक्ष्य विपणन पर एकाधिकार स्थापित करना नहीं होता। य तो केवल वस्तु के निर्धारण में कुछ सीमा तक नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। मूल्य नियंत्रण की दो मुख्य रीतियाँ हैं—(१) भाग बढ़ा कर अथवा (२) पूर्ति घटा कर।

संघों का स्वरूप स्थायी भी हो सकता है और अल्पकालीन भी। अल्पकालीन संघों का निर्माण विशेषतः परिकल्पनिक व्यवहारों के लिये किया जाता है और उनसे होने वाले हानि-लाभ का वितरण सदस्यों में समानता अथवा समझौते के अनुसार किया जाता है। इसी आधार पर औद्योगिक जगत में औद्योगिक संघ बनाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादक संघों की भाँति विपणन पर एकाधिकार स्थापित करना नहीं, बरन् मूल्य-नियंत्रण होता है। निश्चित मूल्य पर प्रत्येक सदस्य अपनी निर्मित वस्तुएँ बेच सकता है। कभी-कभी प्रत्येक सदस्य का विपणन-क्षेत्र भी निश्चित कर दिया जाता है, फिर उस क्षेत्र में अन्य सदस्य अपने माल को नहीं बेच सकते। प्रत्येक औद्योगिक इकाई, जो एक संघ की सदस्य है, कुछ विषयों को छोड़कर, दोष सब विषयों में पूर्ण स्वतन्त्र होती है। जिन विषयों पर प्रत्येक सदस्य को संघ के नियमों का प्रसरण पालन करना पड़ता है, वे ये हैं :—

1 ‘Pool’ has been defined by Sri Haney as “A form of business organisation established through federation of business units whose members seek a degree of control over prices by combining some factors in the price making process in a common aggregate and apportioning the aggregate among the units”—Business Organisation and Combination by Haney

- (अ) मूल्य-निर्धारण ।
- (ब) विक्रय सम्बन्धी नियम ।
- (स) विज्ञापन विधियाँ ।
- (द) अपहार ।
- (इ) माल की सुपुर्दगी इत्यादि ।

मूल के प्ररूप—

समझीते की शर्तों के अनुसार सघ के विभिन्न प्ररूप होते हैं, जो विशेषतः निम्न हैं :—

(१) मूल्य सघ—इस प्रकार के सघ समान मूल्य निर्धारण पर विद्येय जोर देने हैं और बिज्जी व्यवस्था, विज्ञापन, अपहार, साख की अवधि आदि सम्बन्धी आयोजन में भी एक्ता लाने का प्रयत्न करते हैं । कभी-कभी निर्भिन्न विपणि-क्षेत्रों के अनुसार एक ही वस्तु के विभिन्न मूल्य निश्चित किये जाते हैं ।

(२) प्रादेशिक सघ—इस प्रकार के सघ भिन्न-भिन्न उत्पादकों के लिए भिन्न-भिन्न प्रदेश निश्चित कर देते हैं और फिर अन्य उत्पादक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकत । वे अपने-अपने क्षेत्र में उचित मूल्य पर सङ्घ द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तु विव्य करत रहते हैं ।

(३) उत्पादन सघ—इनका मुख्य लक्ष्य उत्पादन को सीमित करना होता है । अत्यधिक उत्पादन की दशा में ऐसा किया जाता है । ये सघ प्रत्येक इकाई के लिए उत्पादन कोटा निश्चिन कर देते हैं तथा उस माल के विक्रय हेतु मूल्य भी निश्चित कर देत हैं । समय-समय पर सघ जनता की माँग का अनुमान लगाना है और उसी माँग के आधार पर प्रत्येक सदस्य प्रमण्डल की उत्पादन-शक्ति तथा उसकी कार्यशील पूँजी को ध्यान में रखते हुए उन सबके लिए उचित कोटा निश्चिन करता है ।

(४) आय अथवा लाभ संघ—आय सघ में सम्पूर्ण सदस्य-प्रमण्डलों की उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त हुई पूर्ण धन-राशि एक ही विक्रय सगठन के लेखे में जमा कर ली जाती है अर्थात् उन सब सदस्यों का विव्य केवन एक ही विक्रय संस्था द्वारा किया जाता है । प्रत्येक सदस्य अपने निश्चित कोटे के अनुसार उत्पादित माल विक्रय सगठन को बेचने के लिए देता है । माल के विक्रय के पश्चात् जो आय बचती है उसमें से विव्य-व्यय तथा सघ के अन्य आवश्यक व्यय निकाल कर घटाकर जो लाभ शेष रहे, उसको निश्चिन अनुपात में बाँट दिया जाता है ।

(५) पेटेन्ट संघ—इस प्रकार के सघ विभिन्न सुस्थाओं में उनके पेटेन्ट अधिकार प्राप्त करके धीरे-धीरे अधिक से अधिक क्षेत्र अपने नियन्त्रण में लेने का प्रयत्न करते हैं । अमेरिका में जी० ई० सी० (General Electric Co) ने एक नई सस्था 'रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका' खोल कर लगभग ४,००० पेटेन्ट अधिकार अनेक कम्पनियों से प्राप्त किये हैं ।

(६) निर्यात सघ इस प्रकार के सघ केवल विदेशी बाजार में विदेशियों के साथ सफल प्रतिस्पर्धा करने की दृष्टि में एव तथा का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए निर्माण किये जाते हैं ।

(७) कृषि सघ इस प्रकार के सघ का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं का लाभ बढ़ाने के लिए नवीन आवश्यकताओं के अनुसार कृषि उत्पादन का विपणन करना होता है । कृषि की प्रगति का दृष्टि में इस प्रकार के सघ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । भारतवर्ष में भी इनको बढ़ावा देना चाहिये ।

(५) सघारी धनदायी प्रमण्डल (Holding Company)

सघारी प्रमण्डल की परिभाषा हम पीछे देखेंगे । इनके निम्न विभिन्न रूप होते हैं

(१) प्रमुख सघारी प्रमण्डल (Primary Holding Company) — बहु प्रमण्डल सहायक प्रमण्डलों में प्रमुख होता है और किसी भी अन्य प्रमण्डल के नियंत्रण में नहीं होता ।

(२) मध्यस्थ सघारी प्रमण्डल (Intermediate or Subholding Company) — इसका प्रबंध एक अन्य बड़ा प्रमुख सघारी प्रमण्डल द्वारा होता है । इसलिए यह प्रमुख सघारी प्रमण्डल के सम्मुख यह प्रमण्डल तथा केवल मध्यस्थ प्रमण्डल कहलाने का अधिकारी है ।

(३) सम्पत्ति सघारी प्रमण्डल (Offspring Holding Company) — इसका निर्माण उस समय से होता है जब अन्य सहायक प्रमण्डल बन जाते हैं ।

(४) धन सघारी प्रमण्डल (Finance Holding Company) — यह सहायक प्रमण्डलों के लिए धन उपलब्ध करता रहता है और इस दृष्टि में यह एक विनियोग प्रयास है । यह सघारी प्रमण्डल का नाम मुख्यतः धन और सहायक प्रमण्डलों के लाभों में से प्राप्त लाभों पर अवलम्बित होता है ।

(५) जनक सघारी प्रमण्डल (Parent Holding Company) — यह बहु प्रमण्डल है जिसका निर्माण पहले होता है और बाद में वह अपना अपने सहायक प्रमण्डलों का निर्माण करता है ।

(६) स्वामित्व सघारी प्रमण्डल (Proprietary Holding Company) — यह प्रमण्डल अपने सहायक प्रमण्डलों की सम्पूरा पूंजी के अपने अधिकार में रखता है ।

(७) संचालक सघारी प्रमण्डल (Operative Holding Company) — इसके संचालक अपने सहायक प्रमण्डलों में विशेष रुचि रखते हैं एवं उनकी व्यवस्था का संचालन करते हैं तथा उत्पादन आदि पर नियंत्रण रखते हैं ।

(८) शुद्ध संधारी प्रमण्डल (Pure Holding Company)—इस प्रकार के संधारी प्रमण्डल विभिन्न सहायक प्रमण्डलों के स्कन्ध का कुछ न कुछ भाग क्रय कर लेता है, किन्तु उनके प्रबन्धक उन प्रत्येक सहायक प्रमण्डलों के आन्तरिक प्रबन्ध में कोई विशेष भाग नहीं लेते ।

बारकपुर कोल कम्पनी लिमिटेड तथा एसोसियेटेड सीमेण्ट कम्पनी लिमिटेड संधारी प्रमण्डलों के उदाहरण हैं ।

संधारी प्रमण्डलों के लाभ—

- (१) सर्व प्रथम लाभ तो यह है कि इनका निर्माण प्रमण्डल अधिनियम के अन्तर्गत होता है, अतः इनका अस्तित्व स्थायी एवं वैधानिक हो जाता है । अन्य संयोगों में यह बात नहीं है, क्योंकि उनका निर्माण मौखिक अधवा अनुबन्धात्मक होता है ।
- (२) अनेक प्रमण्डलों के सम्मेलन से संधारी प्रमण्डल के आन्तरिक व्ययों में बहुत कमी हो जाती है । निरर्थक व्यय नहीं करने पड़ते । विज्ञापन आदि में भी मितव्ययिता हो जाती है ।
- (३) संधारी प्रमण्डलों के निर्माण से प्रत्येक सहायक प्रमण्डल का वैधानिक अस्तित्व पृथक् रहता है, जिसमें आय-कर सम्बन्धी मिलने वाले लाभ मिलते रहते हैं ।
- (४) संधारी प्रमण्डलों को साधारण प्रमण्डलों की अपेक्षा पूर्णतः एकत्र करने में काफी सरलता होती है ।
- (५) संधारी प्रमण्डल का निर्माण अत्यन्त सरल होता है । इसके लिये सदस्य प्रमण्डलों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रायः सभी कम्पनियों के अंश खुले बाजार में बिकते हैं, जो सरलता से खरीदे जा सकते हैं ।
- (६) प्रबन्ध विषयक व्यय में भी काफी मितव्ययिता हो जाती है । केन्द्रीय नियन्त्रण अनेक स्थलों पर व्यय में बचन करा देता है ।
- (७) प्रत्येक सदस्य-प्रमण्डल को सुयोग्य विशेषज्ञ मिल जाते हैं, अतः उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है ।
- (८) प्रत्यास अधवा कार्टेल्स की अपेक्षा संधारी प्रमण्डलों का महत्व इसलिये भी है, क्योंकि ये अपने सहायक नियन्त्रित प्रमण्डलों को अनेक कार्यों के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर देते हैं । इस प्रकार बहुत में विक्रेताओं के चंगुल से बच जाते हैं तथा उन सबकी नीति पर एक ही केन्द्रीय नियन्त्रण रहने से लगभग सबकी बाह्य दृष्टि समान रहती है ।

संधारी प्रमण्डलों की हानियाँ—

- (१) संधारी प्रमण्डलों के विरुद्ध पहला आरोप यह है कि वर्तमान औद्योगिक विकास साहसी व्यक्तियों के नियन्त्रण में न रहते हुए केवल कतिपय

पूँजीपतियों के समूह के नियन्त्रण में चला जाता है। इनसे नियन्त्रण का केन्द्रीयकरण हो जाता है जो अनेक दृष्टि से हानिकारक भी है तभी राष्ट्रीय हित के सर्वथा विरुद्ध है।

- (२) सघारी प्रमण्डलो के संचालकमण अधिकतर निजी लाभ की दृष्टि से पूँजीवाद के सिद्धान्तों एवं तर्कों के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे देश में दो या विभिन्न वर्गों का निर्माण होकर समाज क्षान्ति की ओर अग्रसर हो जाता है।
- (३) सघारी प्रमण्डल अपने सहायक प्रमण्डलों के बीच इस चालाकी से छल-साधन (Manipulation) करते हैं कि जिससे विनियोगों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है।
- (४) सहायक प्रमण्डलों से होने वाले लाभ का अगिकाश भाग (Lion's share of profit) असधारियों की अपेक्षा प्रबन्धकों की जेब में जाता है, क्योंकि वे तरलित स्क्वो (Watered stocks) की बिक्री से अधिक लाभ कमाते हैं।

बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन के अनुसन्धान के अनुसार छुट्ट लाभ का

वितरण इस प्रकार से होता है—

प्रमण्डल सदस्य	उद्योग	प्रबन्ध अधिकर्ताओं का लाभाना	असधारियों का लाभाना
३६	सूती वस्त्र उद्योग, बम्बई	३८.८%	४६.२७%
२०	„ „ „, अहमदाबाद	७०.५%	३१.००%
१६	जूट उद्योग	३६.९%	७६.००%
१४	कलकत्ता	५४.२%	७३.२०%

- (५) सघारी प्रमण्डलों के पूँजी-आधिकार में भी विनियोगों का शोषण होने की सम्भावना रहती है।
- (६) सघारी प्रमण्डल प्रायः असामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि एक ही सघारी कम्पनी के नियन्त्रण में अनेक सहायक कम्पनियाँ रहती हैं जो अपने सुदृढ़ आर्थिक साधनों से उस क्षेत्र में स्वतन्त्र प्रतियोगिता करने वाले व्यक्ति या व्यवसाय को कुचल डालती हैं तथा अपनी वस्तुओं को मनमाने मूल्य पर बेचती हैं।

(VI) समावेशन, सम्मिश्रण एवं सविलोयन

Merger, Amalgamation & Absorption)

समावेशन, सम्मिश्रण एवं सविलोयन के लिये एक शब्द है 'प्रणालीय संघनन'

(Complete consolidation), जिसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। संघनन के निम्न लाभ हैं :—

संघनन के लाभ—

- (१) संघनित प्रमण्डलों में पारस्परिक वैमनस्य की भावना नहीं रहती, अपितु उनमें समानता तथा एकरूपता आ जाती है, जिससे नियन्त्रण सुदृढ़ हो जाता है।
- (२) प्रबन्ध एवं व्यवस्था का केन्द्रीयकरण हो जाता है, जिससे प्रबन्ध व्यवस्था में मितव्ययिता आ जाती है, प्रमण्डल के लाभों में वृद्धि होती है।
- (३) संघनित प्रमण्डलों को बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ मिलते हैं एवं क्रय-विक्रय आदि संगठन के केन्द्रीयकरण होने से मितव्ययिता होती है।
- (४) अनुसन्धान तथा अन्वेषण के लिए क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
- (५) तात्त्विक विशेषज्ञों की सेवाएँ सुविधा तथा सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं।

संघनन की हानियाँ—

- (१) प्रमण्डलों का अस्तित्व न रहने के कारण उनकी पृथक् ख्याति, स्थान, बिपणन क्षेत्र आदि का लाभ संघनन से प्राप्त नहीं होता है।
- (२) इनको निर्माण करने के लिये वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इनका संगठन गोपनीय रह सकता है।
- (३) संघनन बड़ा होने की दशा में नियन्त्रण एवं प्रबन्ध अक्षम होने की सम्भावना रहती है और उत्पादन व्यय में भी मितव्ययिता नहीं रहती।

STANDARD QUESTIONS

1. (a) Discuss the nature, objects and economies of vertical and horizontal combinations in industry.
(b) How do you account for the slow appearance of combinations in Indian Industry?
2. "Combination by giving rise to monopoly harm the interests of consumers". "Combinations by reducing costs offer goods and services at lower prices to consumers". Reconcile these views.
3. What are the chief causes that lead to combination in industry and trade? Illustrate your answer from Indian conditions.

4. Give the main classification of business combinations. Illustrate your answer from Indian conditions
5. Discriminate clearly between Trusts and Cartels and explain the conditions which favoured the growth of trusts in the U S A and cartels in Germany
6. Define clearly 'Vertical' and 'Horizontal' combination, with reference to their existence in two principal Indian industries. Distinguish between a 'Cartel' and a 'Trust' bringing out their main features
7. What is a Trust? How many kinds of trusts are there? How does trust differ from a holding company?
8. What do you understand by a 'Cartel'? Explain its functions and objects. How does it differ from a trust?

अध्याय २६

भारतीय उद्योगों में संयोग आन्दोलन

(Combinations in Indian Industry)

भारत में आन्दोलन धीमा क्यों ?—

पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में संयोग आन्दोलन अत्यन्त मन्द गति से बढ़ा है। इसकी धीमी प्रगति के निम्न कारण हैं —

(१) भारतीय उद्योगपतियों की वैयक्तिक भावना—भारतीय व्यापारी प्रारम्भ से ही वैयक्तिक भादना को अपनाते चले आ रहे हैं, अतः संयोग की दिशा में अभी तक उन्होंने जो भी प्रयत्न किये हैं उनमें सफलता नहीं मिली। भारतीय उद्योगपति अधिकतर निजी लाभ की दृष्टि में कार्य करते हैं। उनके हृदय में सामाजिक तथा सामूहिक हित के लिए कोई स्थान नहीं है। लाभ होने की दशा में वे समस्त लाभ का उपयोग स्वयं करना चाहते हैं। ऐसी भावना संयोग के सम्बन्ध में विच्छेद है। हाँ, गत कुछ दिनों से वे सहकारिता का पाठ अवश्य पढ़ने लगे हैं और औद्योगिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना भी हुई है।

(२) प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति—भारतवर्ष में मुख्यतः प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति ने संयोग आन्दोलन को जड़ नहीं पकड़ने दिया । उनकी आर्थिक तथा व्यापारिक स्थिति के सुदृढ़ होने के कारण, वे जिन व्यापारों को प्रारम्भ करते हैं उनके संयोग करने में वे आत्म-सम्मान का हनन समझते हैं । पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा तथा वैमनस्य के कारण भी वे दूसरों के साथ सम्मिलित होना हेय समझते हैं । प्रबन्ध-अभिकर्त्ता पद्धति द्वारा भी सामूहिक प्रबन्ध होने के कारण संयोग के समान मितव्ययिता उद्योगपतियों को प्राप्त हो जाती है, अतः वे संयोग की आवश्यकता नहीं समझते ।

(३) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होना—औद्योगिक विकास की दृष्टि से अन्य उन्नतिशील देशों की अपेक्षा भारत अभी बहुत पिछड़ा हुआ है । प्रथम विश्व युद्ध ने हमारे यहाँ की ब्रिटिश सरकार को भारत के औद्योगिक विकास के लिए प्रेरित किया और द्वितीय महायुद्ध में हमारे उद्योगों का विशेष प्रोत्साहन मिला, किन्तु अभी तक देश की प्राकृतिक सम्पदा को दृष्टि में रखते हुए किंचित उद्योगों को छोड़ कर समस्त उद्योग अभी परिवर्तन की स्थिति में ही हैं । कुछ अपवादों को छोड़ कर भारत में उद्योगों को अभी वह अवस्था प्राप्त नहीं हुई, जिससे कि उनको संयोग में सम्मिलित किया जाय तथा प्रभावशाली नियन्त्रण में रखा जाय ।

(४) कुछ उद्योगों का वृहत् आकार—भारत में कुछ उद्योग, जैसे—चीह एव स्पात उद्योग, कुछ राजकीय उद्योग आदि पहले से ही इतने बड़े आकार पर प्रारम्भ किये गये हैं कि अब नवीन संस्थाओं को उनमें मिलाना अत्यन्त कठिन है । दूसरे, उनसे प्रतिद्वन्द्विता करने वाली संस्थाएँ भी भारत में नहीं हैं ।

(५) विदेशी प्रतिस्पर्द्धा—विदेशी प्रतिस्पर्द्धा ने भी संयोग आन्दोलन की गति को रोक रखा है । सन् १९२१ के पूर्व भारत सरकार की प्रशुल्क नीति भी असन्तोषजनक थी, जिसने प्रोत्साहन की अपेक्षा संयोग के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी ।

(६) राष्ट्र की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति—छठवें, भारत सरकार की आर्थिक नीति भी संयोग प्रवृत्तियों की ओर उदासीन रही है । जर्मनी में राज्य ने संयोग आन्दोलन को सक्रिय प्रोत्साहन दिया तथा वहाँ कुछ संयोग राजकीय प्रभाव डालकर स्थापित किये गये, किन्तु इसके विरुद्ध अमेरिका में संयोगों को रोकने के लिए नियम बनाये गये । ब्रिटन तथा भारत की सरकारें अभी तक किसी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध रही हैं । हाँ, गत कुछ वर्षों में अवश्य संयोगों के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है एवं उद्योगों में नियन्त्रण के केन्द्रीयकरण के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है । कुछ लोगों का मन है कि प्रबन्ध-अभिकर्त्तृत्व-प्रणाली, जिसके आधार पर भी कुछ संयोग स्थापित हुए हैं तथा हो सकते हैं, को जड़ से उखाड़ देना चाहिए । इस विचारधारा ने भी संयोग आन्दोलन की गति को धीमा कर दिया है ।

आन्दोलन की वर्तमान स्थिति—

वर्तमान समय में संयोग आन्दोलन की गति कुछ प्रबल हो गई है किंतु संयोग निर्माण की प्रवृत्ति बड़ी मात्रा में उत्पादन की अपेक्षा वृहत संगठना की ओर विशेष पार्श्व जाती है। अब हम भारतीय उद्योगों में होने वाले संयोग आन्दोलन का विवेचन करेंगे—

सीमेन्ट उद्योग—

क्षैतिज पद्धति का सबन बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण संयोग सीमेन्ट व्यवसाय में हुआ, जिसमें अनेक सीमेन्ट कंपनियों का संविनीयन हुआ। भारताय सीमेन्ट उद्योग में संयोग की दिशा में प्रयत्न सर्वप्रथम सन् १९२५ में किया गया जब इस उद्योग को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। वास्तव में सरकार का इस उद्योग के प्रति अनन्तोपप्रद व्यवहार तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा ही संयोग का कारण बना। प्रतिद्वन्द्विता के युग में एक सीमेन्ट कारखाने नष्ट हो रहे थे और शेष का जीवन भी संकटमय था। पारणामस्वरूप सन् १९२६ में इण्डियन सीमेन्ट मेन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन का निर्माण किया गया। इसके बाद सन् १९३० में सीमेन्ट का विनरण एवं विनियमन करने के हेतु 'सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी' का निर्माण किया गया। इसको कार्टेल्स अथवा सिण्डिकेट भी कह सकते हैं किंतु दुर्भाग्यवश वह प्रयत्न असफल रहा अतः सन् १९३७ में इन दोनों के सम्मिश्रण से एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी (A. C. C.) का निर्माण किया गया। इनमें ११ सीमेन्ट कंपनियों का संविनीयन हुआ जिनमें कटनी सीमेन्ट कम्पनी लि० इण्डियन सीमेन्ट क० लि० बी० सी० पी० सीमेन्ट क० लि० कोयम्बटूर सीमेन्ट क० लि० इत्यादि प्रमुख थीं। नतीजस्वरूप इस बड़े संयोग के भी प्रतिस्पर्धी (Competition) के रूप में डालमिया सम्मुख आये और पुनः वयम प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई। सन् १९४१ में एक दूसरा कदम उठाया गया और डालमिया कम्पनियों के समूह तथा ए० सी० सी० के समूह में एक समझौता हुआ जिससे आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पर और भी अधिक नियन्त्रण लगा दिया गया। समझौते के अनुसार बाजार बांट दिए गये। फिर द्वितीय महायुद्ध ने सीमेन्ट उद्योग का रूप बदल दिया। अत्यधिक उत्पादन के स्थान पर सीमेन्ट की कमी हो गई। आज भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना सीमेन्ट उद्योग के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या है। २० जनवरी सन् १९५० को ए० सी० सी० की १३वीं वार्षिक मीटिंग में कम्पनी के समापति के माध्याम में यह बात स्पष्ट है।^१

शक्कर उद्योग—

भारतीय शक्कर उद्योग में तम्बरूप संयोग के दशन होते हैं। गत २०-२२ वर्षों में इस उद्योग की उन्नति बड़ी शीघ्रता से हुई है और तभी में शक्कर के उत्पादन पर नियन्त्रण के हेतु एक केन्द्रीय संस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई। सन् १९३५ में यह

सन् १३० तक पहुँच गई। इसका प्रधान कारण उद्योग को संरक्षण मिलना था, किन्तु इस शोध विकास से उद्योग की उन्नति में कुछ कमजोरियाँ आ गई। सन् १९३० में भारत में केवल २७ शक्कर के कारखाने थे। स्पर्धा को रोकने के लिए 'सुगर मार्केटिंग बोर्ड' का निर्माण किया गया, किन्तु व्यक्तिगत कारखानों की उदामीना और उपेक्षा के कारण यह संगठन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। जुलाई सन् १९३७ में 'सुगर सिन्डीकेट' का निर्माण किया गया, जिसके प्रयत्नस्वरूप मूल्य निर्धारण में काफी सफलता मिली। सन् १९३९ तक इस सिन्डीकेट ने बड़ी सफलतापूर्वक कार्य किया, किन्तु फिर द्वितीय महासमर आरम्भ होने से शक्कर का उत्पादन अत्यधिक होने लगा। सिन्डीकेट ने अधिक ऊँचे मूल्य निर्धारित किये थे, अतएव उसे विवश होकर सन् १९४० में मूल्य घटाने पड़े। सन् १९४२ में समस्त भारतीय शक्कर उद्योग पर नियन्त्रण के हेतु सद्प्रयत्न किये गये। केन्द्रीय शक्कर सलाहकार बोर्ड की दिल्ली में एक सभा की गई। सन् १९४३ के बाद 'कंट्रोल' के कारण सुगर सिन्डीकेट अपने कार्य से विरत रहा और उत्पादन तथा वितरण पर सरकार का अपेक्षाकृत अधिक कड़ा नियन्त्रण रहा। सन् १९४७ के बाद पुनः सुगर सिन्डीकेट सक्रिय कार्य करने लगा। सन् १९४९ में भारतीय संसद में सुगर सिन्डीकेट तथा शक्कर उद्योग के विषय में राजकीय नीति की कड़ी आलोचना की गई और सुगर सिन्डीकेट को समाप्त करने का भी निश्चय कर लिया गया।

जूट उद्योग—

भारत के सभी उद्योगों में जूट उद्योग सबसे अधिक संगठित उद्योग है और इस उद्योग के अन्तर्गत जितनी भी कम्पनियाँ हैं, वे प्रायः सभी सहयोग से कार्य करती हैं। सन् १८८६ में ही भारतीय जूट मिल्स एसोसियेशन का निर्माण किया गया था। इसको हम यदि उत्पादन-संघ (Output Pool) अथवा 'कार्टेल' कहें तो अनुचित न होगा। तान्त्रिक विकास तथा अनुसन्धान को इस संघ ने विशेष प्रोत्साहन दिया। यही नहीं, शोध कार्य के हेतु इसने आर्थिक सहायता प्रदान की। जूट उद्योग की उत्पादन क्षमता का ९५% भाग इसी संघ के अन्तर्गत है, जिसने अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। गिरते हुए मूल्यों और माँग का सामना करने के लिए सन् १९२९ में मिलें ५४ घण्टे कार्य करने के लिए राजी हो गईं, सन् १९३० में तीन सप्ताह तक कार्य की पूर्ण रोक रहीं। द्वितीय महायुद्ध के समय जूट मिलों ने ४५ घण्टे प्रति सप्ताह कार्य किया। कभी-कभी माह में एक सप्ताह तक मिलें बन्द रही। मई सन् १९५२ में १०% करघों को सील बन्द कर दिया गया। भारत के वेटवारे के बाद इस उद्योग के बुरे दिन आये। अनेक मिलों को हानि उठानी पड़ी, किन्तु पारस्परिक सहयोग के कारण उद्योग अपने पैरों पर खड़ा रहा। इस आपत्ति के समय में भी जूट मिल एसोसियेशन ने उद्योग की बड़ी सेवा की।

सूती उद्योग—

भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में औद्योगिक इकाइयों की संख्या इतनी अधिक (४०० मिलों से भी ज्यादा) है कि संयोग एक कठिन समस्या है, किन्तु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण संयोग स्थापित हुए हैं। उदाहरण के लिये, बर्किशम बर्नाटक मिल्स वास्तव में तीन वस्त्र-मिलों का संयोग है। बम्बई तथा अहमदाबाद में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के प्रयत्नस्वरूप अनेक आर्थिक संयोग स्थापित हुए हैं। लकाशायर कॉटन कॉरपोरेशन के आधार पर सन् १९३० में ३४ वस्त्र मिलों के संयोग का एक प्रस्ताव रखा गया था, किन्तु यह प्रयत्न असफल रहा। अपने देश में कुछ व्यापारिक संघ हैं, जैसे—बॉम्बे मिल-मालिक संघ इत्यादि, किन्तु वे किसी का नियन्त्रण नहीं करते। गत वर्षों में जितने भी सम्मिश्रण या संविलीयन हुए वे प्रायः सभी प्रबन्ध-अभिकर्ताओं द्वारा किए गए और उनका स्वरूप स्पष्ट रूप से न तो क्षैतिज है और न लम्ब ही, अपितु उन्हें चकित या मिश्रित संयोग कह सकते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रमण्डलों का सम्मिश्रण हुआ है। उदाहरण के लिए, सन् १९२० में निम्नलिखित ६ कंपनियों को लेने के लिए ब्रिटिश कॉरपोरेशन की स्थापना की गई—कानपुर वूलन मिल्स, कानपुर कॉटन मिल्स, न्यू ईगटन वूलन मिल्स, नार्थ-वेस्ट टेनरी, कूपर एलन एण्ड कम्पनी तथा एम्पायर इंजीनियरिंग कम्पनी। बी० आई० सी० (B I C.) के अन्तर्गत फ्लेक्स, लाख इमली तथा काकोशी भी हैं। सन् १९४८ के बाद से तो इसका क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है, क्योंकि वेग सदरलैण्ड कम्पनी में भी अब बी० आई० सी० का काफी हाथ है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रमण्डल इस कॉरपोरेशन के अन्तर्गत हैं।

लौह एवं स्पात उद्योग—

लौह एवं स्पात उद्योग के क्षेत्र में अथवा यों कहें कि भारत के औद्योगिक इतिहास के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संयोग इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड तथा स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल लिमिटेड का है, जो 'IISC Co SCOB Merger' के नाम से विख्यात है। यह संयुक्तीकरण कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं बरन् प्रेसीडेंट के एक विशेष अध्यादेश द्वारा जनवरी सन् १९५३ में हुआ। इस संयुक्तीकरण के कारण इस प्रकार हैं :—

दिसम्बर सन् १९३६ में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने बंगाल आयरन कम्पनी का व्यापार खरीद लिया और इसमें बंगाल आयरन कम्पनी को अपनी तीन-चौथाई पूँजी व इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी को एक-चौथाई पूँजी उपलब्ध करनी पड़ी थी। स्टील विभाग खोलने के लिए यह उचित नहीं समझा गया कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शेयरहोल्डरों से पुनः पूँजी देने के लिए कहा जाय, जिसकी आवश्यकता लगभग ५ करोड़ रु० की थी, अतः सन् १९३७ में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से एक नई इकाई स्थापित की गई, जिसमें

इण्डियन प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के पास आधी इक्विटी केपिटल थी। विचार यह था कि किसी दिन दोनों कम्पनियों को एक इकाई में गठित कर दिया जायगा। युद्धोत्तर काल में जब युद्धकालीन मूल्य नियन्त्रण हटा लिए गए और प्रशुल्क बोर्ड ने नये मूल्य निर्धारित कर दिये तो यह अनुभव किया गया कि यदि उक्त दोनों कम्पनियों का एकीकरण हो जाय तो दोनों ही संस्थायें लाभान्वित होगी। तत्पश्चात् प्रत्येक टैरिफ बोर्ड ने भी यही सिफारिश की और सरकार ने भी दोनों कम्पनियों को इस दिशा में विचार करने के लिए कहा। टैरिफ कमीशन एवं इसमें पूर्व टैरिफ बोर्ड ने लौह एवं स्पात के लिए मूल्य (Retention prices) की गणना करने के लिए जो ढग अपनाये थे उनके कारण दोनों कम्पनियों को एक सम्मिश्रित इकाई की तुलना में हानि उठानी पड़ती थी, किन्तु दोनों कम्पनियों के एकीकरण से यह हानि नहीं होती।

इसके अतिरिक्त जब उत्पादन के विस्तार के लिए भारी मात्रा में प्लाण्ट आयात करने के हेतु विदेशी विनिमय की आवश्यकता हुई तो सरकार ने इन्टरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलेपमेंट के समक्ष प्रार्थना की। बैंक ने प्रत्युत्तर में देश की औद्योगिक सभावनाओं की जाँच के लिए टेक्नीकल मिशन भेजा, जिसने उक्त दोनों इकाइयों का निरीक्षण किया और यह सिफारिश की कि भारत में लौह एवं स्पात का उत्पादन बढ़ाने का सस्ता और शीघ्रगामी साधन इन दोनों कम्पनियों को सम्मिश्रित करके विकास करना है। बैंक ने भारत सरकार को सूचित किया कि वह इण्डियन प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को विकास के लिए १५ करोड़ २० लक्ष रुपये देने के लिए तैयार है, बशर्ते इन दोनों कम्पनियों का एकीकरण हो जाय, अतः भारत सरकार ने परिस्थिति की आवश्यकता को अनुभव करते हुए आर्डिनेन्स द्वारा एकीकरण की घोषणा की। यदि सामान्य ढग से एकीकरण कराया जाता तो उसमें आवश्यक देर लगती, जिससे आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती और विकास कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाता।

सम्मिश्रित कम्पनी का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। टैरिफ कमीशन द्वारा मूल्य गणना की विधि ने फलस्वरूप होने वाली हानि तो दूर हो ही जावेगी, साथ ही सम्मिश्रित कम्पनी अधिक निपुणता एवं मितव्ययिता से कार्य कर सकेगी। उदाहरण के लिए, अब प्रबन्ध अधिकर्ताओं को दुहरा पारिश्रमिक नहीं देना पड़ेगा। सम्मिश्रित कम्पनी ने जो विकास कार्यक्रम बनाया है उसके लिए उसे बैंक से एवं सरकार से सुविधाजनक शर्तों पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

कोयला उद्योग—

कोयले के उद्योग में अनेक संयोग हुए। दी न्यू बीरभूम कोल कम्पनी ने अनेक कोयला-खान-उद्योगों का सम्मिश्रण किया। सन् १९३७ में कोल जाँच-समिति ने भी सम्मिश्रण पर जोर दिया। इस प्रकार सम्मिश्रणोत्पन्न संयोग की आवश्यकता कोयले

के खान-व्यवसाय में अधिक है, जिसमें वे प्रमण्डलों के लघु परिमाण होने के कारण उत्पादन की दृष्टि से अक्षम हैं।

भारत में सघ (Pool) प्रणाली संयोग—

‘सघ’ प्रणाली के संयोग का सबसे अच्छा भारतीय उदाहरण हमारा कागज उद्योग है जो एक प्रबल संगठन है। इण्डियन पेपर मेकर्स एसोसिएशन के अन्तर्गत अनेक कागज मिलें सम्मिलित हैं। यह सघ कागज का मूल्य निर्धारित करता है तथा प्रांतीय एवं केन्द्रीय सरकारों से कागज के सम्बन्ध में अनुबन्ध करता है कि कौनसी मिल किससे कितना कागज देगी। इस प्रकार मूल्य सघ (Price pool) का उदाहरण हमारा यहाँ के तेल व्यवसाय में मिलता है जिसमें ब्रिटिश-बर्मा पेट्रोलियम क०, आसाम ऑयल क०, दी रायल डबल्लस ग्रुप तथा बर्मा ऑयल कम्पनी सदस्य हैं और मिट्टी के तेल का सदस्यों द्वारा विक्रय एवं सदस्य प्रमण्डलों से क्रय किस प्रकार होगा, यह निर्धारण करता है। इण्डियन जूट मिल एसोसिएशन ने उत्पादन सघ (Production pool) का रूप ले लिया है। सन् १९२६ से यह एसोसिएशन जूट के उत्पादन, काम के घण्टों की बर्मी कुछ मिला की तालाबन्दी पासियों पर नियन्त्रण आदि का कार्य सफलता से कर रहा है। बाजार सघ (Marketing pool) डालमिया तथा एसोसियेटेड सीमट कम्पनी के समझौते के बाद स्पष्ट हुआ है जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में व्यापार नहीं करेगा। इससे उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन होगा।

सघारी कम्पनियाँ (Holding Companies)—

सघारी कम्पनियों का निर्माण भारत में विशेषतः सन् १९१३ से प्रारम्भ हुआ। ऐसे प्रमण्डल विभिन्न प्रमण्डलों की व्यापारिक नीति एवं प्रबन्ध पर नियन्त्रण के हेतु उनके अंश खरीद लेते हैं। यह कार्य उस समय विशेष रूप में पाया जाता है, जब विभिन्न कम्पनियाँ एक ही प्रबन्ध अधिकर्ता के अन्तर्गत कार्य करती हैं। भारत के विभिन्न व्यवसायों में धन लगाने के लिए उन पर नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में विनियोग प्रत्यास स्थापित हुए हैं, किन्तु शक्तिशाली प्रबन्ध अधिकर्ताओं के कारण उनका नियन्त्रण अधिक प्रभावशाली नहीं दिखाई देता है।

बीमा तथा बैंकिंग के क्षेत्र में बैंकिंग की अपेक्षा बीमा कम्पनियों की स्थिति अच्छी है, विशेषकर निम्न कम्पनियों की। फ्री इण्डिया जनरल इन्श्योरेंस क० लि० कानपुर, आयन इन्श्योरेंस क० लि० कलकत्ता, फेडरल इण्डिया इन्श्योरेंस क० लि० दिल्ली आदि। बैंकिंग कम्पनियों के सम्मिश्रण के लिए पर्याप्त क्षेत्र है इसमें उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा मितव्ययिता होगी। अभी देश में ऐसी अनेक छोटी बैंकिंग कम्पनियाँ हैं, जिनका सम्मिश्रण या सविलीयन राष्ट्र के हित में अनिवार्य है, जिससे वे अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों के साथ विशेषतः विदेशी विनिमय बैंकों से टक्कर ले सकें।

व्यापारिक पार्षद एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स (Trade Associations & Chambers of Commerce)—

यहाँ व्यापारिक पार्षदों के विषय में दो शब्द लिखना अनावश्यक न होंगे । इन पार्षदों का प्रधान उद्देश्य किसी व्यापार विशेष के हितों की रक्षा करना तथा उसकी उन्नति करना है । चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी व्यापारिक पार्षद ही है, जो व्यापारियों की, निर्माताओं की तथा अर्थ-प्रदायकों की स्वेच्छा से सीमित प्रमण्डल के रूप में संगठित किये जाते हैं । इनका भी मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए समान सिद्धान्तों का अवलम्बन तथा सदस्यों को व्यापारिक सुविधायें देने के लिए नियम बनाना होता है । इसके अनिरीक्त ये अपने सदस्यों का व्यापारिक सूचनार्थ तथा आवश्यक सलाह भी देते रहते हैं, परस्पर भगडों का निर्णय भी देते हैं एवं आवश्यकतानुसार वैधानिक एवं माहिती भी प्रदान करते हैं । सदस्यों को व्यापारिक सुविधायें देने के लिये ये सरकार के पास व्यापारियों की ओर से प्रतिनिधि मण्डल भी भेजते हैं । उक्त उद्देश्य का प्रथम भारतीय संगठन कलकत्ते में मन् १८८७ में 'कलकत्ता नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स' के नाम से स्थापित किया गया था । भारत के प्रायः प्रत्येक बड़े औद्योगिक नगर में अब पार्षद स्थापित हो गये हैं, जिनमें मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बम्बई, इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता, इण्डियन मर्चेंट चैम्बर ब्यूरो ऑफ बाम्बे तथा दी उ० प्र० चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमुख हैं ।

नौवहन चक्र तथा सम्मेलन (Shipping Rings and Conferences)—

इनके अनिरीक्त भारत में बाजार का विभाजन कुछ अन्य क्षेत्रों में भी किया गया है । ये क्षेत्र नौवहन-चक्र तथा सम्मेलन (Shipping Rings and Conferences) कहलाते हैं । ये चक्र पारस्परिक समझौते के आधार पर किये जाते हैं । ऐसा ही समझौता ब्रिटिश इण्डिया स्टील नेवीगेशन क० लि० तथा सिंधिया स्टीम नेवीगेशन क० लि० में हुआ है । इस प्रकार के समझौते अन्तर्देशीय नौवहन क्षेत्र में भी विभिन्न नौवहन प्रमण्डलों के बीच हुए हैं । ये समस्त चक्र प्रायः देश के आन्तरिक भागों से जूट को तटवर्ती बाजारों तक ले जाने के लिये स्थापित किये गए हैं । ये कम्पनियाँ समझौते के अनुसार इण्डियन जूट मिस्ट एसोसियेशन तथा कलकत्ता बेस्ट जूट एसोसियेशन के सदस्यों के लिए जलमार्ग से जूट लाने की पूर्णतया अधिकारिणी हैं ।

भारतीय उद्योगों में आर्थिक तथा प्रबन्ध संयोग (Community Interest or Managerial Integration in Indian Industries)—

'सामुदायिक हित संयोग' (Community Interest Combinations) से अभिप्राय उस संस्था का है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक कम्पनियों में, जिनके शेयरों का स्वामित्व सीमित व्यक्ति के हाथों में हो, सुखद सम्बन्धों की स्थापना की जाती है । इन संस्थाओं के जुने हुए व्यक्ति परस्पर प्रतिद्वन्द्विता मिटाने तथा

सामान्य हितों की रक्षा के लिए एक संचालक मण्डल के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे संयोगों को साधारणतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है—पारिवारिक, नागरिक एवं अधिकांशिक। पारिवारिक समुदाय (Family Community Interest) का प्रचलन पाश्चात्य देशों में पाया जाता है, जैसे अमेरिका में रॉक फेलर, मैलन, ड्यूपोन्ट आदि। कुछ कम्पनियों के स्वन्ध दूसरी कम्पनियों को बेच देना या हस्तान्तरित कर देने से या उपहार स्वरूप दे देने से इनका विकास हुआ। नागरिक समुदायों (Local Community Interest) का नगरों में बड़े-बड़े बैंक, उद्योग धन्य तथा व्यापारिक संस्थाओं के एक ही संचालकों के होने से सामुदायिक हित रक्षक संस्थाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार इन अलग-अलग कम्पनियों के संचालक एवं दूसरी कम्पनी के संचालन में योग देते हैं। अधिकोषों के सामुदायिक संगठन (Banking Community Interest) परस्पर प्रतियोगिता को मिटाने के उद्देश्य से स्थापित किए गये हैं। इन संगठनों के द्वारा नई प्रतिभूतियों के निर्गमन तथा प्रत्येक क्षेत्र में व्यापार करने में प्रतिद्वन्द्विता न करने का समझौता करते हैं। कोई भी प्रतिभूति इन संस्थाओं के बाहर नहीं बेची जा सकती। सरकार भी अपनी प्रतिभूतियाँ इन्हीं संघों को बेती है। ये संस्थाएँ अंश निर्गमन करने वाली संस्थाओं के संचालकों का चुनाव करके उनकी आर्थिक गतिविधि पर नियन्त्रण करती हैं।

भारतवर्ष में जो भी क्षैतिज अथवा उद्यम संयोग हैं, उन्हें औद्योगिक संयोग की अपेक्षा आर्थिक संयोग कहना ही अधिक उचित होगा क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने संयोग को अपनाया है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि एक प्रबन्ध अभिकर्त्ता के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की अनेक इकाइयाँ हैं और परिणामस्वरूप हमारे उद्योगों का केन्द्रीयकरण निश्चिन् व्यक्तियों के हाथों में हो गया है। फण्डा उद्योग के ४१८ मिलों का १/२ भाग लगभग ३० प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में है। भ्रमदाबाद की कुल मिलों का ३/४ केवल १८ परिवारों के हाथ में है। इसी प्रकार सन् १९४६ में जूट की ८५ मिलों में ३३ मिलें ४ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में थी तथा १९६६ चीनी मिलों में से ५१ का प्रबन्ध १६ प्रबन्ध अभिकर्त्ता करते हैं, जिनमें से डालमिया, नारायण बाबापर ३१ मिलों का नियन्त्रण करते हैं। कोयले की ६० कम्पनियों का प्रबन्ध १४ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में है, जिनमें से ३० का प्रबन्ध केवल ४ प्रबन्ध अभिकर्त्ता करते हैं। इसी प्रकार चाय की १२० कम्पनियाँ ११ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के अधीन हैं, जिनमें से १६ केवल ६ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में हैं तथा ३ प्रबन्ध अभिकर्त्ता क्रमशः २५, १६ और १८ कम्पनियों का प्रबन्ध करते हैं। ऐसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज आज प्रायः देश के अधिकांश सीमेन्ट उत्पादन का नियन्त्रण करती है। लोहे में ५०% उत्पादन केवल दो संस्थाओं के अधीन है—मार्टिन यूरॉ एण्ड कम्पनी तथा टाटा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड। माचिस के उद्योग में 'स्वेडिस ट्रस्ट' एकाधिकार प्राप्त किये हुए हैं और उसने बेस्टर्न इन्डिया मंच

फैक्टरी के अन्तर्गत बम्बई, मद्रास, कलकत्ता उत्तर-प्रदेश तथा पंजाब में अपनी फैक्टरियाँ खोली हुई है।

भारतवर्ष में प्रबन्ध अभिकर्ता लगभग ७०० औद्योगिक कम्पनियों का नियन्त्रण करते हैं, जिनमें से ५० कम्पनियाँ वेबल एण्डगूल तथा मैकलॉड के आधीन हैं। डालमिया लगभग ५० कम्पनियों का नियन्त्रण करते हैं। जुगमीमल कमलापति ४५ कम्पनियों का, थापस २२, बर्ड एण्ड कम्पनी २३, जे० पी० श्रीवास्तव १० प्रकार के उद्योगों का। किल्लिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड पटियाला सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड तथा ए० सी० सी० के सैनेजिग एजेन्ट होने के साथ-साथ १० प्रकार के उद्योगों का भी नियन्त्रण करती है। रामकुमार अग्रवाल एण्ड ब्रादर्स लगभग १५ प्रकार के उद्योगों का नियन्त्रण करते हैं। ए० बी० थापस एण्ड कम्पनी लिमिटेड लगभग १५ कम्पनियों का नियन्त्रण करती है। इसी प्रकार टाटा एण्ड सन्स लिमिटेड ने लौह एवं स्पात बिजली, तेल के कारखाने, साबुन के कारखाने, कपड़ों की मिलें, इन्जीनियरिंग कारखाने, होटल, वनस्पति कारखाने, बीमा कम्पनियाँ, बैंक, एयरवेज आदि उद्योगों का नियन्त्रण किया है। इसी प्रकार बिडला ब्रादर्स ने कपड़ा, चीनी, कागज, साइकिल, मोटर, जहाज आदि उद्योगों के नियन्त्रण के साथ-साथ बैंक, बीमा, एयरवेज आदि ३३ कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। जे० के० तथा डालमिया आटा, साबुन, तेल, इन्जीनियरिंग, रासायनिक, कपास, जूट, ऊन, चीनी, एयरवेज आदि उद्योगों का नियन्त्रण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीमा कम्पनियाँ, विनियोग सच, बैंक तथा विनियोग कम्पनियों का निर्माण भी किया है।

एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि औद्योगिक तथा आर्थिक प्रमण्डलों पर नियन्त्रण के अतिरिक्त भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ताओं का प्रेस (Press) पर भी अधिकार है। प्रायः प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्ता के नियन्त्रण में एक न एक प्रमुख समाचार पत्र भी है, जिसके द्वारा जनता पर भी वे अपना नियन्त्रण रखते हैं। उदाहरण के लिए, बिरला का 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'सीडर', डालमिया का 'नवभारत टाइम्स', जे० के० का 'जे० के० रिव्यू', टाटा का 'टाटा रिव्यू' इत्यादि।

यही नहीं, कम्पनियों के संचालन में भी घोर केन्द्रीयकरण (Interlocking of Directorates) है। देश के समस्त उद्योगों के संचालन की बागडोर वास्तव में चोटी के २० व्यक्तियों के हाथों में है। ऐसा अनुमान है कि भारत की ५०० प्रमुख औद्योगिक इकाइयों पर २,००० संचालकों का प्रबन्ध है, किन्तु इन २,००० संचालकों

1 'The effective Directors of one trust holds directorships in many a concern managed by other trusts And that 'courtsey' is reciprocated In the world of capital, the captains themselves are ambassadors at one another's courts' . The top twenty men hold in their hands the significant threads of power "

"Who Owns India"—Ashoka Mehta, Page 36-37.

के पद पर केवल ८५० व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इनमें से १,००० पदों पर केवल ७० व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और शेष १,००० पर ७८० व्यक्ति। चोटी पर केवल १० व्यक्ति हैं, जो ३०० सचालक-पदों का भार अपने ऊपर लिए हुए हैं। निम्न तालिका^१ से यह स्पष्ट है —

८५० व्यक्ति	२,००० सचालक पद ग्रहण किए हैं—औमत	२ ३३
७० व्यक्ति	१,००० " " " " — "	१४ २८
१० व्यक्ति	३०० " " " " — "	३०

वर्तमान युग में यह भी प्रवृत्ति देखने में आती है कि भारतीय उद्योगपति विदेशी सस्थाओं तथा हितों का दाय कर रहे हैं, भले ही भारतीय सचालकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति विशेषतः स्वतन्त्रता के उपरान्त राष्ट्रीय भावनाओं की प्रवृत्तियों के कारण हुई।^२ इस तालिका^३ में यह प्रवृत्ति स्पष्ट है।

कम्पनियों की संख्या तथा प्रकार	सन् १९३६ में सचालकों की संख्या		सन् १९४६ में सचालकों की संख्या	
	भारतीय	यूरोपियन	भारतीय	यूरोपियन
१० कोल कम्पनीज		३४	१७	२८
११ " "	१६	२६	३२	२५
१३ लूड " "	-	४६	११	४४
२१ " "	३५	५२	६३	३५
३ इंजीनियरिंग " "		६	३	११
४ " "	८	११	१५	८
१४ अन्य " "		५३	३०	३७
६ " "	६	१६	१८	१६

^१ Who Owns India by Ashoka Mehta, page 17

^२ The Daily Express wrote in 1945—"Indians recently grown rich and powerful due to inflationary conditions and profits from war contracts are attempting to buy out British interests" See the Eastern Economist, dated August 24, 1945.

^३ Capital Annual No. 1949.

ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं, जहाँ एक व्यक्ति ४०-४० कम्पनियों का संचालक है। उदाहरण के लिए, श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ५१ विभिन्न कम्पनियों के संचालक हैं।

कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ ने प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा अन्तर्बद्ध विदेश-नालयों और अन्तर्बद्ध स्वहितों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने का यत्न किया है। भविष्य में व्यक्ति को ही संचालक बनने दिया जायेगा और उसे २० से अधिक लोक कम्पनियों का संचालक नहीं बनने दिया जायेगा। इसी प्रकार कोई प्रबन्ध अभिकर्त्ता १० से अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध अभिकर्त्ता नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्रबन्ध अभिकर्त्ता संचालकों की कुल संख्या ५ से अधिक होने पर एक और अधिक संचालक नियुक्त कर सकेगा।

विदेशी सम्बन्ध एवं बड़े व्यापार की प्रवृत्ति—

एक ओर तो हमने देखा कि संचालकों का भारतीयकरण हो रहा है, किन्तु दूसरी ओर ऐसा भी देखने में आता है कि भारतीय उद्योगपति विदेशी उद्योगपतियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। सन् १९४५ में भारतीय उद्योगपतियों का जब से एक मिशन ब्रिटेन गया, तब से यह प्रवृत्ति विशेष दिखलाई पड़ती है। सन् १९४५ में सर्व प्रथम भारत तथा ब्रिटिश की साझेदारी में 'नफील्ड बिरला' (मोटर्स लि०) के नाम से सामने आई। ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट (४ जनवरी सन् १९४६) ने इस साझेदारी को 'आर्थिक संयोग' का नाम दिया। इसके बाद और भी ऐसी अनेक साझेदारियाँ स्थापित हुईं। कारो तथा ट्रवस के निर्माण के हेतु अशोक मोटर्स लि० ने ऑक्सिडेंट मोटर्स के साथ साझेदारी की। वस्त्र-निर्माण-मशीनरी के निर्माण के हेतु बिरला ब्रदर्स ने ब्रिटेन की वेवकाँफ एण्ड विलकाक्स नामक फर्म के साथ एक समझौता किया है। २५ लाख रु० अश पूंजी के साथ बी० एस० ए० साइकिल कम्पनी की भी एक शाखा भारत में खोली गई है। इसमें १,००,००० रु० की विदेशी पूंजी लगी हुई है। हरकुलिस कम्पनी तथा रैले कम्पनी की भी ऐसी योजनाएँ हैं। रासायन उद्योग के क्षेत्र में भी आई० सी० आई० तथा टाटा के बीच एक समझौता हुआ है। I. C. I. एक शक्तिशाली ब्रिटिश एकाधिकृत संस्था है। सिल्क उद्योग के क्षेत्र में भी सिर सिल्क लि० तथा लैन्सिल की कुछ ब्रिटिश फर्मों के बीच समझौता हुआ है। हैदराबाद कन्स्ट्रक्शन लि० उसके प्रबन्ध अभिकर्त्ता हैं। बम्बई की किरलोस्कर नामक इन्जीनियरिंग संस्था ने ब्रिटिश ऑयल इन्जिन्स लि० के साथ तथा ब्रिटिश इलेक्ट्रोकेल इन्जीनियरिंग कम्पनी एव पैरी एण्ड कम्पनी के साथ गठबन्धन कर लिया है। इसी प्रकार भारत-अमेरिका के बीच भी कुछ समझौते हुए हैं। उदाहरण के लिए, बालचन्द्र हीराचन्द ने क्रिसलर कॉरपोरेशन के साथ समझौता करके सन् १९४५ में प्रीमियर ऑटोमोबायल वर्क्स की स्थापना की। श्री ठाकुरदास तथा श्रोफ द्वारा स्थापित 'नेशनल रियल कॉरपोरेशन लि०' का भी 'स्कन्दा रियल कॉरपोरेशन' तथा 'लॉकवुर्ड ग्रीन एण्ड

व० अमेरिका' के साथ सम्बन्ध है। इनके प्रतिरिक्त और भी अनेक विदेशी मस्थाओं की 'Rupee Subsidiaries' स्थापित की गई है।

उपरोक्त विवेचन में स्पष्ट है कि भारत में कम्पनियों के नियन्त्रण तथा अर्थ व्यवस्था का एक बड़ी सीमा तक केन्द्रीयकरण हो रहा है। इसके कारण साधारण अशक्तारियों तथा उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। इनके उद्योगों में श्रमिका को भी यथोचित लाभ नहीं होता, क्योंकि लाभ का अधिकांश भाग इनकी जेब में चला जाता है। प्रबन्ध अभिकर्त्तागण कम्पनियों की अर्थ व्यवस्था को इस प्रकार निर्वहण कर देते हैं कि उनको हमेशा इनकी ओर ताकना पड़ता है। प्रबन्ध अभिकर्त्तागण तथा बड़ी कम्पनियाँ के आर्थिक लाभ का अनुमान उनके द्वारा दिये जाने वाले आय-कर से लगाया जा सकता है। सरकार के वार्षिक राजस्व का ५०% इन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाता है। इन्होंने बड़ी सीमा तक हमारे राजनैतिक वातावरण को भी अपने शिकजे में बस लिया है।

यह सच है कि भारत का विशाल क्षेत्र, कच्चे माल की बहुतायत और आर्थिक पिछड़पन को देखते हुए औद्योगिक एकाधिकार या आर्थिक एकीकरण से अभी भय-कर रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है। देश में अभी तक प्रायः सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता के लिये पूर्ण सुविधा है, क्योंकि मध्यम श्रेणी के उद्योग भी देश में प्रचलित हैं और विशाल उद्योगों में श्रमिका की समस्या इतनी अधिक नहीं है जितनी कि इन छोटे-छोटे उद्योगों में है। देश में बेकारी की समस्या भी अभी तक पूर्ण रूप से नहीं सुलभ पाई है। एकाधिकार की अन्य बुराइयों का, जैसे छोटे उद्योगपतियों पर दबाव, ऊँची दरें, कानून का दुरुपयोग, क्रेताग्रा की स्वतन्त्रता का अपहरण, नवीन विकसित साधनों पर रोक आदि नहीं आ पाई है, किन्तु यदि मान लिया जाय कि देश में एकाधिकार की भयकर स्थिति नहीं है तो भी यह मानना पड़गा कि उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट है, इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकना जनतन्त्रवादी सिद्धान्तों की रक्षा के लिए आवश्यक है। नया कम्पनी अधिनियम इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

STANDARD QUESTIONS

1. How do you account for the slow appearance of Combination in Indian Industries.
2. Examine the trend towards amalgamation and mergers in India and discuss the causes of such combinations.

3. Write a short essay on Combination Movement in Indian industries
4. Trace briefly the growth of combination of Indian Industries. What do you know about Big Business Deals negotiated with foreign industrialists after 1945
5. What do you understand by 'Community Interests'? What are its various forms? Write a note on Community Interest in India
6. Give a detailed account of the IISCO SCOB Merger which was effected in India on 1st January 1953
7. Write a lucid essay on Managerial Integration in India. What are the provisions of the Indian Companies Act, 1956 for preventing the concentration of economic power in the hands of a few persons?

अध्याय २७

राज्य एवं औद्योगिक संयोग

(State & Industrial Combinations)

प्रस्तावना—

औद्योगिक संयोगों के सम्बन्ध में दो विरोधी विचारधाराएँ प्रचलित हैं। एक विचारधारा के अनुसार औद्योगिक संयोग कोई 'संगठन' ही नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यवस्था का एक खेदजनक उत्त्वघन है, जिसे केवल अप्रोत्साहित करने के लिये ही कोई कदम नहीं उठाना चाहिए बल्कि उन्हें दबाने के लिए प्रत्यक्ष उपाय भी किए जायें। इसके विपरीत, दूसरी विचारधारा यह है कि औद्योगिक संयोग, औद्योगिक संगठन का उच्चतर एवं विकसित रूप है तथा इसे सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में लागू करना चाहिए। वास्तव में हमें औद्योगिक संयोगों के सम्बन्ध में उचित नीति अपनाने के लिए इन दोनों विचारधाराओं से बचना चाहिए तथा थोड़ा भी ध्यान रखना चाहिए कि उद्योग की रचना में गहरे परिवर्तन हो रहे हैं और एकाधिकारिक संगठनों को स्वतन्त्र निर्माता की अपेक्षा विशेष प्रबन्ध-समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सरकारी नीति के उचित लक्ष्य—

सरकारी नीति के दो परस्पर विरोधी लक्ष्य सामने आते हैं। पहला लक्ष्य उपभोक्ताओं के कारण रखा गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें व्यापारिक सयोगों के दुष्प्रभावों से रक्षा मिलना चाहिए। अतः प्रथम लक्ष्य ऐसे विशाल सयोगों की शक्ति को नष्ट या सीमित करने से सम्बन्धित है। दूसरा लक्ष्य छोटी छोटी प्रतियोगिता करने वाली फर्मों को बड़े पैमाने के संगठनों में परिणत होने के लिए विवश या प्रोत्साहित करके औद्योगिक कृदालता में सुधार करना है।

औद्योगिक सयोगों का नियमन करने के लिए सरकार जो उपाय करती है वह भिन्न-भिन्न होते हैं। असामाजिक एवं हानिप्रद औद्योगिक सयोगों के विरुद्ध प्रायः कड़ी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है। सरकारी हस्तक्षेप विभेदात्मक मूल्य-नीतियों और व्यापारिक प्रथाओं तथा घाति पूर्णोत्पत्ति के कारण आवश्यक हो जाता है। इन परिस्थितियों में सरकार क्या करेगी, इसका कोई निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता। सामान्यतः असामाजिक मूल्य नीति से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए औद्योगिक सयोगों से मर्षण कर सकती है। लेकिन समन्वित औद्योगिक संगठन की यातिर वह प्रतिस्पर्धा के बजाय सयोगीकरण को बढ़ावा भी दे सकती है। वह इनमें से कौनसा मार्ग अपनाएगी, यह सयोग के आधिक प्रभावों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यही नहीं, परिस्थितियों के बदलने पर आर्थिक प्रभावों का स्वभाव भी बदल जाता है। अतः सरकार को औद्योगिक सयोगों के सम्बन्ध में कोई स्थिर (Static) नीति न अपना कर एक प्रगतिशील (Dynamic) नीति अपनानी चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि कभी-कभी सयोगिक प्रवृत्तियों का विरोध करने का अर्थ दुर्बलता की निपुणता के विरुद्ध संरक्षण देना है। अतः सरकार को सयोगों के सम्बन्ध में एक रचनात्मक नीति अपनानी चाहिये, क्योंकि 'अनुमति दो' या 'अनुमति न दो' इन दो मार्गों में से किसी एक मार्ग पर चलना ही सदा लाभप्रद नहीं होगा। उन्ने सयोगों का समर्थक अथवा विरोधी मार्ग अपनाने के बजाय उद्योग के उचित मार्ग-दर्शन का कार्य करना चाहिये। अमेरिका की भाँति भारत में भी 'व्यापारिक स्वशासन' के सिद्धान्त को सरकारी समर्थन मिलना चाहिए। सन् १९३८ में नेशनल रिकवरी एक्ट निस्ट्रिक्शन के चेयरमैन ने कहा था कि, 'हमारे सामने दो ही विकल्प हैं—या तो हम संगठित हो जायें अथवा बरबाद हो जायें। प्रतिस्पर्धी व्यवस्था के दोषों से बचने के लिये या तो हम जनतान्त्रिक एवं सहकारिक नियन्त्रण अपना लेंगे अथवा मुसीबत में पड़ जायेंगे और तानाशाही नियन्त्रण के द्वारा मुक्ति का प्रयास करेंगे।'^१

1 "We have only two choices—we will get together or get nowhere. Either we will establish democratic, cooperative controls in time to avoid the collapse of an anarchistic competitive system or we will drift into disaster and then seek salvation through accepted dictatorial control."

औद्योगिक संगठन के व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर यह प्रतीत होता है कि उद्योग में संयोगों के निर्माण से प्राइवेट हितों को सार्वजनिक जिम्मेदारी की भावना का अनुभव होना चाहिए। जर्मनी की भाँति उनमें संयोग सम्बन्धी एक आचार संहिता का विकास हो सकता है। बड़े संयोगों को चाहिये कि वे समय को पहचानें और उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में अपना नैतिक दायित्व अनुभव करें। यदि वे श्रमिकों, उपभोक्ताओं और समाज के प्रति अपना दायित्व अनुभव करने लगें तो उन पर प्रतिबन्धों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।^१

सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कितनी भी कानूनी व्यवस्था, दबाव एवं प्रतारणा उद्योगों के सहयोग को प्राप्त नहीं कर पायेगी। सहयोग तभी मिल सकता है जबकि देश की प्रत्येक औद्योगिक इकाई के हृदय में उनके प्रति भावना उत्पन्न हो।

भारत में सरकारी नीति—

भारतीय संविधान में सरकारों नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार भौतिक प्रसाधनों के स्वामित्व एवं नियन्त्रण का वितरण इस प्रकार बनायेगी जिससे कि सामान्य हितों की पूर्ति हो और आर्थिक प्रणाली के कार्य-वाहन द्वारा कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण न हो सके। दिसम्बर सन् १९४५ में जब संसद ने सामाजिक एवं आर्थिक नीति के लक्ष्य में समाजवादी नमूने के समाज की स्थापना को स्वीकार कर लिया, तो उक्त सिद्धान्तों को अधिक ठोस रूप प्राप्त हो गया। इसका अर्थ यह है कि प्राइवेट लाभ के बजाय सामाजिक लाभ को महत्व दिया जायगा। विकास की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जायेगी कि न केवल राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में वृद्धि हो बल्कि आय और सम्पत्ति के वितरण में अधिक समानता आवे। यह तब ही सम्भव है जबकि आर्थिक विकास का लाभ निम्न वर्ग को अधिक मात्रा में दिया जाय। समाजवादी समाज की स्थापना के अन्तर्गत निम्न तीन बातों को महत्व दिया गया है—जीवन-स्तर में सुधार, उसके लिये उपयोगी कार्य के अवसरों में वृद्धि तथा समाज के सब वर्गों में समभावना, सहयोग एवं सहानुभूति का विस्तार।

सन् १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी आय और सम्पत्ति की असमानता को कम करने तथा एकाधिकारों के निर्माण व आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने पर बल दिया गया था। इसके अनुसार सरकार नये औद्योगिक उपक्रमों की

1 "If we can condition industry to act responsible to the workers, consumers and community, we shall have gone a long way to preparing it for the willing acceptance of directives, when directives are needed, from Government, and thereby will have done some thing to minimize the need for direct Government intervention."

—G. Gosder "the Future of Private Enterprise", p. 38.

स्थापना में एक बढ़ता हुआ एवं प्रत्यक्ष दायित्व स्वीकार करेगी। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का एक लक्ष्य आय और सम्पत्ति की असमानता को कम करना तथा आर्थिक सत्ता के अधिक समान वितरण का उपाय करना है। योजना में कहा गया है कि विकास कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिये जो असमानता को और भी बढ़ा दे। असमानता को कम करने के उपायों से उत्पादन व्यवस्था का कोई हानि पहुँचाने का भय नहीं है। जनतन्त्रीय मिद्धान्त असमानता की विद्यमानता के लिये आवार नहीं हो सकते हैं। असमानता को कम करने के लिये दोहरी नीति अपनानी चाहिए—उच्च स्तर पर धन के अत्यधिक केन्द्रीयकरण को रोका जाय और निम्न स्तर पर आयों में वृद्धि की जाय। इस नीति के प्रशासन में सहकारी क्रियाओं का संगठन करने, प्राइवेट मोनोपोली पर नियन्त्रण रखने तथा सरकारी क्षेत्र का विस्तार करने से बहुत मदद मिलेगी। योजना के अन्तर्गत असमानता को दूर करने के लिये निम्न विशेष उपाय किये गये हैं,—

- (१) सरकारी क्षेत्र में विशाल विनियोग का कार्यक्रम बनाया गया है।
- (२) सरकार आर्थिक क्रिया का नियमन करेगी।
- (३) योजना के लिये धन जुटाने के हेतु विशेष प्राशुल्किक उपाय।
- (४) सम्पत्ति स्वामित्व एवं प्रबन्धक क्षेत्र में संस्थागत परिवर्तन किये गये हैं।
- (५) प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर प्रतिबन्ध लगाये गए हैं।
- (६) सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कम्पनी अधिनियम, १९५६ की व्यवस्थायें—

भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ में सरकार को प्राबन्धक, प्रशासनिक एवं वित्तीय सयोग के निर्माण का नियमन करने के कुछ अधिकार प्रदान किये गए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं —

(१) प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी प्रतिबन्ध—धारा ३२४ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकती है कि औद्योगिक व्यापार के अग्रमुक-अग्रमुक वर्गों से सम्बन्धित कम्पनियों में मैनेजिंग एजेंट नहीं रख सकती। धारा ३३२ के अन्तर्गत कोई व्यक्ति १० से अधिक कम्पनियों का मैनेजिंग एजेंट नहीं बन सकता। इन धाराओं के कारण इने गिन व्यक्तियों के पास आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण होना रुकेगा। वित्तीय सयोगों का रोकने की दृष्टि से कम्पनियाँ द्वारा पारस्परिक विनियोग करने पर भी अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं।

(२) संचालकों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध—प्रशासनिक सयोगों के निर्माण की रोकथाम के लिए यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम का आरम्भ होने के समय से २० से अधिक कम्पनियों में संचालक नहीं बन सकता (धारा २७५) और यदि वह ऐसा करता है तो उस पर प्रत्यक्ष अतिरिक्त कम्पनी के

लिए ५,०००) तक जुमाना किया जा सकता है। कम्पनियों की सख्या की गणना करते समय प्राइवेट कम्पनियों, अनलिमिटेड कम्पनियाँ और अ-लाभ परिवदों को नहीं गिना जायगा।

(३) सदस्यता सम्बन्धी जाँच पड़ताल—धारा २४७ के अन्तर्गत (जोकि इंगलिश कम्पनीज एक्ट, १९४८ के आधार पर बनाई गई है) केन्द्रीय सरकार किसी भी कम्पनी की सदस्यता एवं अन्य मामला की जाँच पड़ताल करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, ताकि यह भालूम हो सके कि कौन लोग वास्तव में कम्पनी में वित्तीय हित रखते हैं या कम्पनी की नीति पर प्रभाव डालते हैं।

(४) सम्मिलन सम्बन्धी अधिकार—धारा ३९६ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह दो या अधिक कम्पनियों के सम्मिलन (amalgamation) का आदेश दे दे, बशर्ते ऐसा करना राष्ट्रीय हित में हो।

सन् १९५८ में राज्य सभा के एक कम्युनिस्ट सदस्य ने देश की एकाधिकारिक सस्याओं के कार्य-संचालन की जाँच करने के हेतु एक ससदीय कमेटी स्थापित करने का सुझाव दिया था, जिसे सभा ने ठुकरा दिया, क्योंकि, जैसा कि उद्योग मंत्री ने कहा था, सरकार को आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण रोकने से सम्बन्धित व्यापक अधिकार पहले से ही काफी प्राप्त हैं।

[यह उल्लेखनीय है कि सरकारी नीति के दृष्टिकोण से भारत में औद्योगिक संयोगों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—(१) वह वर्ग जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए (जैसे—सन् १९५२ में सरकार ने इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी और स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल का मिश्रण होने पर जोर दिया था) और (२) वह वर्ग जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। (जैसे सन् १९५० में अ-सामाजिक कार्यवाहियों करने के अपराध में सुगर सिन्डीकेट से अपनी मान्यता वापिस ले ली थी।)

STANDARD QUESTIONS

1. Indicate the chief reasons for the modern tendency towards amalgamation of business undertakings. Point out the effects of such amalgamation.
2. What is big business and why do business tend to become big?
3. Discuss carefully the merits and demerits of business combinations?
4. What should be the policy of a State towards Industrial combinations? Describe in brief the policy adopted by the Government of India.

भारतीय श्रमिकों की विशेषतायें एवं उनकी कार्यक्षमता, आदि

(Characteristics & Efficiency of Indian Labour)

भारत में श्रम समस्याओं का उदय—

भारत में श्रम समस्याएँ अपेक्षाकृत कुछ नवीन ही हैं। प्राचीन काल में श्रमिकों की क्या स्थिति थी, उनकी काम करने की दशायें कैसी थी और उनका जीवन स्तर कैसा था, इस विषय में कोई व्यवस्थित विवरण नहीं मिलता। हाँ, तत्कालीन ग्रन्थों, साहित्य तथा रीतिरिवाजों के आधार पर अनुमान में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन श्रमिक असंगठित, अरक्षित किन्तु कार्य-कुशल थे। पुस्तकी कलाकारों तथा दस्तकारों द्वारा ब गाँवों व नगरों में बसा व दस्तकारी के उद्योग धन्धे किये जाते थे। ये लग गाँव के सेवक भी होते थे तथा नगरों में दस्तकारी संघों (Craft Guilds) में संगठित होते थे। प्रवीण दस्तकारों (Master craftsmen) के यहाँ कुछ लोग (Apprentices) दस्तकारी का काम सीखते थे। काम सीखने के बाद व स्वयं पृथक् व्यवसाय करने लगते थे। श्रमिक का जो आधुनिक अर्थ लिया जाता है, वह १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही प्रारम्भ हुआ। सन् १८५७ के उपरान्त देश में नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई और आधुनिक उद्योगों व यातायात तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास होना प्रारम्भ हुआ। जैसे-जैसे देश में उद्योगों का विकास हुआ और नए कारखानों की स्थापना हुई, रेल, तार, डाक, चाय, रबड़ सूत, जूट, लौह इत्यादि सभी प्रकार के उद्योगों का विकास होने लगा। औद्योगिक क्रान्ति तथा मन्त्रों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के आधुनिक कारखानों की पद्धति ने ही श्रम की समस्याओं को जन्म दिया। २०वीं शताब्दी में इन समस्याओं का रूप उपरान्त होता गया। एक ओर तो आधुनिक उद्योगों के विकास और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विनाश तथा कृषि भूमि पर जन-संख्या के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले भार ने कारण, गाँवों से भुण्ड के भुण्ड कारीगर व किसान नगरों में जाकर श्रमिकों के रूप में आबाद होने लगे। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और देश में बम्बई, ब्रह्मपुत्र, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास और आदि-नगर जैसे श्रमिक प्रधान नगर विकसित हुए।

इस प्रकार जो एक नया श्रमिक वर्ग उत्पन्न हुआ उसकी कुछ अपनी विशेषतायें थीं। उसके पास न धन था, न भूमि और न कोई अन्य सम्पत्ति। उनके निवास की

भी जटिल समस्या थी। पर्याप्त व उपयुक्त घरो के अभाव में भारतीय श्रमिक वर्ग को नगरो की तंग, अदेरी और दुर्गन्धपूर्ण गलियो में नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता पडा। प्रारम्भ में उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। उनके काम करने के स्थान की दृशाये बड़ी अनुपयुक्त व स्वास्थ्य के प्रतिकूल थी। उमे १२ मे १५ घण्टे तक काम करना पडता था। उसके स्वास्थ्य व चिकित्सा तथा दुर्घटनाओं से रक्षा करने के लिये कोई प्रबन्ध न था। उद्योगपति श्रमिको का निर्दयतापूर्वक शोषण करते थे और श्रमिक अपने स्वामी की दया पर निर्भर एक बेवश व असहाय शोषित प्राणी था।

किन्तु समय बदला। प्रथम विश्व युद्ध ने श्रम-समस्याओं को ऊपर लाकर रख दिया। श्रम तथा पूँजी के बीच खाई, वर्गीय भेदभाव तथा घन व भ्राय की बढ़ती असमानता के कारण श्रमिको और मिल मालिको के बीच वैमनस्य तथा द्वेष की आग भडक उठी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में भारतीय उद्योगपतियो ने भारी लाभ कमाये और श्रमिको से शक्ति में भी अधिक काम लिया। इससे मजदूरो में कुछ जागृति हुई और उन्होंने अपनी दशा सुधारने के लिए आवाज उठाई, यद्यपि इस आवाज में बल न था। युद्ध तथा युद्धोत्तर तेजी में मूल्यों में असाधारण वृद्धि के कारण जीवनयापन की लागत बढ गई थी और इसमें श्रमजीवियो में बडा असन्तोष छाया हुआ था। मंहगाई, भत्तो, बोनसो या लाभशो और अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिये हड़तालो की देश में एक बाढ आ गई थी। श्रम-सघो का सघटन हुआ, जिससे श्रमिको को अपने महत्व तथा अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ। यही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघो व सम्मेलनो में भी भारतीय श्रम सघो के प्रतिनिधि भाग लेने लगे। समुक्त राष्ट्र सघ ने भारत को विश्व का आठवाँ औद्योगिक देश घोषित किया तथा भारतवर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम नियमों को स्वीकार कर लागू करना पडा।

कुछ श्रम कल्याणकारी कानूनों का भी निर्माण किया गया, किन्तु श्रमिको में सगठन का अभाव होने के कारण उनके हितो की उचित रक्षा न हो सकी। सन् १९२६ में श्रम-सघ अधिनियम के पास होने से उनकी दशा में सुधार की आशा बधी। सन् १९२९ में भारत सरकार ने रॉयल श्रम कमीशन की नियुक्ति की, जिसने अपना प्रतिवेदन सन् १९३१ में प्रस्तुत किया। उसके आधार पर श्रमिको के निवास, कार्य दशाओं, कार्य अवधि, नौकरी की सुरक्षा तथा उनके हितकारी कार्यों के सम्बन्ध में नन्द्रीय तथा राज्य सरकारो ने अनेक अधिनियम पास किए। तत्पश्चात् सन् १९३७ में कार्प्रेस मन्त्रिमण्डलो ने श्रम-हित की एक प्रगतिशील नीति को कार्यान्वित कर न्यूनतम भृत्ति, नौकरी की सुरक्षा, क्षतिपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था की।

देश की स्वन्त्रता के उपरान्त श्रम आन्दोलन को एक नया बल मिला है। आज देश में औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रो में श्रमिका के अनेक सगठन कार्य कर

रहे हैं। औद्योगिक श्रमिकों की मर्यादा लगभग ६० लाख है जो अधिकतर मिलों या कारखानों, खानों, वामानों, रेलों, जहाजों बन्दरगाहों या निजी दूकानों या व्यापारिक संस्थाओं में काम करते हैं। इनमें से लगभग ३० लाख श्रमिक देश के विभिन्न राज्यों के उन कारखानों में काम करते हैं जो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, १० लाख श्रमिक रेल-उद्योग में काम करते हैं तथा लगभग ७ लाख श्रमिक केन्द्रीय सरकार के संस्थाओं में लगे हुए हैं। आज का श्रमिक दिन प्रति दिन अपनी अवस्था में महत्त्व से परिचित होना आ रहा है। इस चेतना के परिणामस्वरूप श्रमिकों की स्थिति सुधरती जा रही है तथापि कायस्थमता की दृष्टि से अन्य उन्नत देशों के समक्ष आने में हमारे श्रमिकों को अनवरत परिश्रम की आवश्यकता है। उनकी दशा में सुधार तथा जीवन-स्तर को उठाने में श्रम-संगठनों, उद्योगपतियों तथा सरकार तीनों ही का सहयोग करके उचित दिशा में प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए एक पूर्ण सन्तुष्ट व सुखी वर्ग की आवश्यकता है। यदि भारत को अपने औद्योगिक विकास की प्रगति में अन्य देशों से कदम मिला कर चलना है, तो उसे अवश्य ही श्रम-समस्याओं को अविलम्ब हल करना पड़ेगा।

भारतीय श्रमिकों की विशेषतायें

(Characteristics of Industrial Labour)

(१) भारतीय कारखाना मजदूरों की प्रवासी प्रवृत्ति—

भारतीय औद्योगिक श्रम की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, जिसके गम्भीर आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम हुए हैं, यह है कि वे अधिकतर गाँवों से आते हैं और यथा-शीघ्र अवसर मिलने पर पुनः गाँवों को वापिस लौट जाते हैं। यही कारण है कि भारत में अभी तक स्थायी श्रमिक वर्ग का उदय नहीं हो पाया है।

भारतीय श्रमिकों की प्रमुख

विशेषतायें

१. भारतीय कारखाना मजदूरों की प्रवासी प्रवृत्ति।
२. एकता का अभाव।
३. अनियमित उपस्थिति।
४. अज्ञानता एवं शिक्षा का अभाव।
५. श्रमिकों की पूर्ण उद्योगों की आवश्यकतानुसार न होना।
६. रहन-सहन का निम्न स्तर।
७. श्रमिकों की अक्षमता।
८. भाग्यवादिता।

पाश्चात्य देशों में कारखानों में काम करने वाले व्यावसायिक मजदूरों के स्थायी वर्ग होने हैं तथा वे खेती से एकदम सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं। वहाँ प्रायः अधिकांश मजदूरों का पालन पोषण शहरों में ही होता है तथा कुछ तो गाँवों में अपना नाता पूर्णतः तोड़कर शहर के निवासी बन जाते हैं। कारखानों के क्षेत्र का पालन-पोषण पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तो श्रेष्ठता के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी है, परन्तु इस देश के कारखाना का श्रमिक तो प्रायः प्रवासी होता है और शायद ही कभी गाँव

में सम्बन्ध विच्छेद करता है। अधिकांश मजदूरों का शीघ्र ही गाँव को लौटना तथा एक कारखाने में अधिक दिन न टिकना अवश्य ही इस बात का द्योतक है कि वे कृषि कार्य अल्पकाल के लिये ही छोड़ते हैं। औद्योगिक केन्द्रों के अधिकांश श्रमिक असल में तो ग्रामीण ही होते हैं, जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँवों में ही होती है और ग्रामीण रीति रिवाजों में ही उनकी आस्था होती है। उनका अभीष्ट गाँव लौटना ही होता है तथा ऐसा करने में वे प्रायः सफल ही होते हैं।

प्रवासी प्रवृत्ति के कारण—

श्रमिका के गाँव से शहर आने के कारणों पर दृष्टिपात करने पर हम देखेंगे कि (i) कृषि पर पड़ने वाली विपत्ति का पहला असर भूमिहीन खेतियार मजदूरों पर ही पड़ता है, अतः उन्हें गाँव छोड़कर कारखानों, नौका-निर्माण स्थानों, बगीचों तथा रेल, सिंचाई आदि सरकारी निर्माण-कार्य वाले स्थानों में अधिक वेतन के लिए काम ढूँढ़ने जाना पड़ता है। (ii) उन्नत आवागमन के साधन होने इस प्रवास में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों तथा बम्बई के रतनगिरि आदि कुछ जिलों में जन-घनत्व तथा भूभार इतना अधिक है और अनाधिक जोतें इतना भयानक रूप धारण कर चुकी हैं कि साधारण कृषक जीविकोपार्जन के हेतु शहर में जाने को बाध्य हो जाते हैं। (iii) इस प्रवास कार्य में समुक्त परिवार पणाली भी सहायक होती है। परिवार के कुछ सदस्य अपने घर तथा खेत से सम्बन्ध विच्छेद किए बिना ही उसे परिवार के अन्य व्यक्तियों की देख-रेख में छोड़कर गाँव से चले जाते हैं। (iv) कमी-कमी कृषक गाँव के साहूकार से बचने या भूमि और पशु खरीदने के लिए पर्याप्त धन कमाने के उद्देश्य से शहरों में नौकरी तलाश करते हैं। (v) फिर कभी अपनी जीविका और भावी जीवन को उत्तम बनाने की आशा से निम्न श्रेणी के ग्रामीण श्रमिक (जो कि दलित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं) शहरों और कस्बों को चले जाते हैं। चूँकि उनके नगर जाने का प्रधान कारण कष्ट है, न कि महत्वा-कांक्षा, अतः हम यह कह सकते हैं कि गाँवों से नगरों को प्रवास करने वाले सबसे कम कुशल और अत्यन्त निरुपेय ग्रामीण होते हैं। अतः कमीशन के शब्दों में :—

“प्रवास की प्रेरक शक्ति एक मिरे से आती है, अर्थात् गाँवों में। औद्योगिक श्रमिक नागरिक जीवन के आकर्षण में शहरों में नहीं जाता और न उसके प्रवास का कारण महत्वाकांक्षा ही होती है। शहर स्वयं उसके लिए कोई आकर्षण की वस्तु नहीं है और अपना गाँव छोड़ने के समय उसके मन में जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं रहती। वह न ही कम औद्योगिक-श्रमिक शहर में रहना चाहेंगे, यदि उन्हें गाँव में जीवनयापन के लिए पर्याप्त भूत और वस्त्र मिल जाय। वे नगर की ओर आकर्षित नहीं होते, वरन् ढकेले जाते हैं।”

प्रवासी प्रवृत्ति के आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम—

(i) प्रवासी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप कारखानों में काम करने वालों के

कितने ही वर्ग अपने की एकदम अपरिचित रीति-रिवाजा और परम्पराओं के मध्य पाते हैं। यह भी हो सकता है कि वहाँ भाषा भी दूसरी हो।

11. (ii) पुरानी प्रथाओं और मान्यताओं व वन्यन ढीले पड़ जाते हैं, नवीन सम्बन्ध शीघ्रता से नहीं स्थापित हो पाते। फलतः जीवन अधिकाधिक व्यक्ति हो जाता है।

(iii) जलवायु के अत्यधिक परिवर्तन, दायपूर्ण भोजन स्थानाभाव के कारण अत्यधिक भीड़-भाड़, सफाई का अभाव तथा पारिवारिक जीवन से विच्छेद होने के बाद पुनः मिलने का प्रलोभन इन सबका संयुक्त प्रभाव श्रमिक के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है।

(iv) कुछ दुर्व्यसनो के कारण श्रमिक के नैतिक जीवन का और भी पतन होता है। शराब और जुआ इन दुर्व्यसनो के उदाहरण हैं जो कि गाँवों में अपेक्षाकृत अज्ञात हैं।

(v) चूँकि श्रमिक के मन में गाँव लौटने की इच्छा सदैव बनी रहती है, अतः वह अपनी नागरिक कृति में स्थायी रुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। यही कारण है कि वह उच्चकोटि की प्राविधिक कुशलता प्राप्त नहीं कर पाता।

(vi) उसके बार-बार गाँव लौटने तथा अन्य कारणों से मालिक और श्रमिक के बीच सम्पर्क की घनिष्टता नष्ट हो जाती है और उनमें प्रभावपूर्ण संगठन का भी प्रभाव हो जाता है।

(vii) श्रमिक जब लम्बी अनुपस्थिति के बाद लौटता है तो वह निश्चित नहीं होता कि उसे काम मिलेगा ही। पुनः काम मिलने की कठिनाइयाँ उसे साहूकार, मजदूरों के ठकेदार, शराब बेचने वाले आदि की दया पर आश्रित कर देती हैं।

क्या श्रमिकों का गाँवों से सम्पर्क उचित है ?

जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं श्रमिकों का अभी गाँव लौटना ही होता है। अधिकांश श्रमिक अपना परिवार गाँवों में ही रखते हैं। शहर में अपने पति के साथ आन वाली पत्नी भी प्रसव के समय प्रायः गाँव ही चली जाती है। शहर में रहते हुए उनका सम्बन्ध गाँव में इसलिए भी नहीं टूट पाता कि वहाँ उनको अपने परिवार, किसी सम्बन्धी या अपने साहूकार को कुछ रकम भेजनी ही होती है।

अम आयोग के मतानुसार श्रमिकों का गाँवों से सम्पर्क लाभहीन नहीं है।

(i) शहरों की अपेक्षा गाँवों के अधिक स्वास्थ्यप्रद वातावरण में पापित होने के कारण ग्रामीण श्रमिकों का स्वास्थ्य अधिक उत्तम होता है। (ii) समय-समय पर गाँव जाने से खोई हुई मानसिक और शारीरिक शक्ति फिर से लौट आती है। (iii) बीमारी और वृत्तिहीनता व अवसर पर गाँव का घर एक शरण-स्थल का काम देता है। जिस प्रकार गाँवों के आश्रित भाग को नगर प्रवास हल्का कर देता है उसी प्रकार गाँव नगरों

की वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। (iv) ग्रामीण और नागरिक जीवन का संयोग दोनों (नगरी और गाँवों) के लिए हितकर होता है। इससे ग्रामीण जीवन में बाहरी दुनियाँ का थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तथा पुरानी जर्जर प्रथाओं की शृङ्खला को तोड़ने में सहायता मिलती है। (v) इसी प्रकार, नागरिकों को भारतीय जीवन की वास्तविकताओं का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है, अतः हमारा मत है कि इस समय गाँवों से सम्बन्ध की कड़ी को बनाये रखना लाभदायक है। हाँ, यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सुनिश्चित और स्वास्थ्यप्रद हो।

(२) एकता का अभाव—

भारतीय उद्योगों में श्रमजीवी प्रायः बहुत दूर-दूर से काम करने आते हैं। ऐसे विरले ही औद्योगिक नगर हैं जिन्हें निकटवर्ती क्षेत्रों से ही समस्त श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, मजदूरों का वर्ग एक ऐसा विचित्र समुदाय बन गया है, जिसमें भिन्न-भिन्न धर्मों के, भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न-भिन्न रहन-सहन एवं रीति रिवाज के लोग होते हैं। मजदूर वर्ग में इन अनेक भिन्नताओं के कारण सगठन नहीं है। सगठन तो दूर रहा, पारस्परिक मेल-जोल भी उनमें बहुत कम है।

जै. (३) श्रमियमित उपस्थिति—

जैसा हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, भारतीय श्रमिक कारखानों के निकटवर्ती गाँवों अथवा अन्य राज्यों में काम करने के लिए नगरों में आते हैं, अतः अपने गाँवों के प्रति उनका आकर्षण घना रहता है। वे समय-समय पर गाँव जाते रहते हैं। कृषि क्षेत्रों से आने वाले श्रमिक कृषि मौसम में अथवा फसल पर, जब गाँवों में अधिक काम होता है, अपना काम छोड़ कर चले जाते हैं, इससे उनकी उपस्थिति कारखानों में अनियमित रहती है। निकटवर्ती गाँवों से आने वाले श्रमिक तो प्रायः प्रति मास ही अपने गाँव जाया करते हैं, जिससे कारखानों के काम में बड़ी बाधा पड़ती है।

(४) अज्ञानता एवं शिक्षा का अभाव—

भारत की सम्पूर्ण जन-संख्या में से केवल १७% व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं। इन पढ़े-लिखे व्यक्तियों में से औद्योगिक श्रमिकों का भाग तो नाममात्र को ही होगा। सामान्य शिक्षा का अभाव होने के कारण श्रमजीवी पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ अपने कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर पाते। साथ ही, भारतीय श्रमजीवियों में जब सामान्य शिक्षा का अभाव है तो औद्योगिक शिक्षा का अभाव हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। यहाँ कारण है कि हमारे श्रमजीवी सापरवाही के साथ यन्त्र-प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तथा अपने काम का महत्त्व नहीं समझते।

(५) श्रमिकों की पूर्ति उद्योगों की आवश्यकतानुसार नहीं—

भारतीय श्रमिकों में कुशल श्रमिकों की अपेक्षा अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी अधिकांश जन-संख्या कृषि उद्योग में लगी हुई है। सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार, भारत की २५ करोड़

जन मर्या कृपि पर प्रयत्न अथवा परोक्ष रूप से निर्भर है तथा शेष जन मर्या मर्गटिन उद्योग खान उद्योग यातायात व्यापार एवं वाणिज्य पर निर्भर है ।

(६) रहन सहन का निम्न स्तर—

भारतीय श्रम जीवियों के रहन-सहन का स्तर अत्यंत गिरा हुआ है । इसका प्रधान कारण यह है कि उनको पारितोषण बहुत कम मिलता है । कोई भी व्यक्ति जब तक उसके पास अपनी समस्त आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के हेतु साधन न हो अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं कर सकता । अतः यह दोष श्रमिकों का नहीं वरन् उन परिस्थितियों एवं वातावरण का है जिनके अन्तर्गत वे पले हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं ।

(७) श्रमिकों की अक्षमता—

भारतीय श्रमिकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे श्रमिकों की कार्यक्षमता बहुत कम है । श्री एनेक्जेडर मकरावट के अनुसार भारतीय श्रमिक की अपेक्षा एक अग्रज श्रमिक ४ गुना काम करता है परन्तु भारतीय श्रमिक की अक्षमता का विचार करते हुए हम यह भी स्मरण रखना चाहिये कि श्रमिकों की कुशलता निम्न बातों पर निर्भर करती है—जलवायु, भूति पद्धति करने की परिस्थिति, रहन-सहन का स्तर तथा श्रम प्रबंध । इन घटकों के विवेक से ही किसी देश के श्रमिकों की अक्षमता के विषय में समुचित निष्कर्ष किया जा सकता है । काम करने की परिस्थिति काम के घट यंत्र सामग्री औद्योगिक शिक्षा एवं श्रम प्रबंध आदि कुछ ऐसा बात है जो श्रमिकों के ऊपर निर्भर न रहते हुए उद्योग पतियों और निर्माताओं के ऊपर निर्भर रहती है तथा जिनकी समुचित व्यवस्था कर्ण पूर्ण जिम्मेदारी उनके ही ऊपर होती है इसलिए यह कहना यथाप्य है कि किसी भी देश की औद्योगिक क्षमता की जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर निर्भर होनी है । इस दृष्टि से यदि इस कसौटी पर भारतीय श्रमिकों की तुलना अन्य देशों के श्रमिकों के साथ कार्यक्षमता में की जाय तो यह स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों की काम करने की परिस्थिति तथा उनको दी जाने वाली सुविधाय अन्य देशों की तुलना में नहीं के बराबर है अतः श्रमिकों की अक्षमता उनका व्यक्तिगत दोष न होते हुए उस परिस्थिति का दोष है जिसमें भारतीय श्रमिक रहता है एवं जिस परिस्थिति में उसे काम करना पड़ता है ।

(८) भाग्यवादिता—

भारतवासी (विशेषतः गृह का श्रमिक वर्ग) बड़ा भाग्यवादी है । अपने जीवन के सुख-दुख को वे भाग्य की देन समझते हैं । हुई है सोई जो राम रवि राखा में उनका इतना विश्वास है कि वे अपनी उन्नति के लिए पुण्याथ करने को प्रयत्नशील भी नहीं होते । भाग्य में हाया तो मिल जायगा ऐसा सोच कर वे हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं ।

भारतीय श्रमिकों की कुशलता (Efficiency of Indian Industrial Labour)

क्या भारतीय श्रमिक वास्तव में अकुशल हैं ?—

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता उनकी लोकप्रिय विशेषता है। साधारणतः यही कहा जाता है कि भारतीय श्रमिक अक्षय एवं अकुशल हैं। औद्योगिक कमीशन के मम्मुल सर अलेक्जेंडर मैक राबर्ट (Sir Alexander Mac Robert) ने अपनी साक्षी में यह कहा कि एक अंग्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक से चौगुना कुशल होता है। सर क्लेमेंट सिम्पसन (Sir Clement Simpson) के अनुसार लङ्काशायर की सूती मिल का एक श्रमिक भारतीय सूती कपड़ों की मिल में काम करने वाले २६७ श्रमिकों की योग्यता के बराबर है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की ओर से की गई जांच इस धारणा को गलत मिट्ट कर देती है। इस जांच से यह प्रकट है कि योरोप की तुलना में हमारे श्रमिकों की अक्षमता निर्विवाद सत्य नहीं है। कुछ उद्योगों में तो वह अन्य देशों के श्रमिकों के बराबर कुशल है। अन्य उद्योगों में भी वह पूरी तरह अक्षम नहीं कहा जा सकता। यदि योरोपीय श्रमिक भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा अधिक उत्पादन करते हैं तो वे अधिक शिक्षा प्राप्त भी होते हैं, उनको अधिक भुक्ति एवं अन्य सुविधायें भी मिलनी हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय श्रमिक यदि अक्षम हैं तो अपने दोषों के कारण नहीं, अपितु उन परिस्थितियों के कारण हैं जिनमें वह रह रहा है। अक्षमता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

भारतीय श्रम की अक्षमता के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय—

(१) प्रवासी प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति के कारण श्रमिक फल के समय तथा अन्य विशेष उत्सवों पर अपने गाँव आते-जाते रहते हैं जिसमें भारत में अभी तक स्थायी श्रमिक वर्ग का उदय नहीं हो पाया है। इनकी इस प्रवृत्ति का यह परिणाम होता है कि वे प्रायः कारखानों में अनुपस्थित रहते हैं। इससे उत्पादन बड़ा अनिश्चित हो जाता है।

इन दोषों को दूर करने एवं औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों को स्थायी रूप से रहने का प्रोत्साहन देने के लिए शहरी जीवन का सुधार कर उसे श्रमिक आकर्षक बनाना चाहिए।

भारतीय श्रमिकों की अक्षमता

के प्रमुख १२ कारण

१. प्रवासी प्रवृत्ति।
२. शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव।
३. निर्धनता और निम्न जीवन स्तर।
४. अल्प वेतन।
५. शारीरिक दुर्बलता।
६. जलवायु।
७. स्वतन्त्रता एवं आशा का अभाव।
८. ऋणग्रस्तता।
९. कार्य के दीर्घ घण्टे।
१०. काम करने की दशायें।
११. भरती की दोषपूर्ण पद्धति।
१२. दोषपूर्ण प्रवृत्ति।

(२) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव—सामान्य ज्ञान का स्तर हमारे श्रमिकों में बहुत नीचा है। माता-पिता की अशिक्षा के कारण घर का वातावरण शिक्षाप्रद नहीं होता। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षा-प्रणाली बहुत सकुचित है। अभी प्रारम्भिक शिक्षा भी सब जगह निःशुल्क तथा अनिवार्य नहीं हुई है। शिक्षा न मिलने से वे कट्टर, अन्धविश्वासी, भाग्यवादी और साहसहीन हो गये हैं। इन सब बातों से श्रम की कुशलता बढ़ती है। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त हमारे श्रम-जोड़ियों के लिये 'शिल्प' प्रशिक्षण का सुघनसर भी नहीं मिलता। अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों में, जहाँ श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, श्रमिक जटिल से जटिल मशीन का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं, किन्तु भारत में ऐसा नहीं है। हमारे श्रमिकों को मशीनों का उपयोग जानने तथा अन्य देशों में होने वाली श्रमिकों की गतिविधियों को समझने में अधिक समय लगता है। उनकी इस अज्ञानता के कारण उत्पादन क्षमता गिर जाती है।

अन्य प्रगतिशील देशों की भाँति भारत में भी प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम अनिवार्य होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक शिक्षण सस्थायें खोलकर शैल्पिक प्रशिक्षण की सुविधायें सुगम एवं सुलभ करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा से श्रमिकों का मानसिक विकास होगा और औद्योगिक शिक्षा से व्यावसायिक अज्ञानता दूर होकर कार्यक्षमता बढ़ेगी।

(३) निर्धनता और निम्न जीवन स्तर—भारतीय श्रमिक की दरिद्रता सर्व-विदित है। दरिद्रता के कारण उसे भर पेट भोजन एवं पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में दूध, फल आदि निपुणतावद्धक वस्तुओं की वह कल्पना भी कैसे कर सकता है ? परिणामस्वरूप कार्यक्षमता गिर जाती है।

अस्तु, श्रमिकों की निर्धनता को दूर करके उनका जीवन स्तर ऊँचा करने के उपाय सोचना चाहिए। कुटीर उद्योगों की प्रगति से यह समस्या काफी सीमा तक हल की जा सकती है।

(४) अल्प वेतन—इसका भी भारतीय श्रमिकों की कुशलता पर बुरा प्रभाव हुआ है। दरिद्रता के कारण वे भली प्रकार अपना पेट भी नहीं भर सकते। परिस्थितिवश उनकी आय का काफी भाग श्रम चुकाने एवं नशा करने में निकल जाता है और जो शेष रहता है वह उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होता। अपना स्वास्थ्य बढाना तो दूर रहा, पेट भरने को पर्याप्त रोटी भी उन्हें नहीं मिल पाती। इस प्रकार कार्यक्षमता दिनो दिन कम होती जाती है।

इस दोष को दूर करने के लिये श्रमिकों को कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य दी जाय, जिससे कि वे अपना तथा अपने परिवार का उचित भरण-पोषण कर सकें।

(५) शारीरिक दुर्बलता—निर्धनता एवं अल्प वेतन के कारण श्रमिकों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है। अधिक समय तक वे निरन्तर कठिन

परिश्रम करने के लिए अपने को असमर्थ पाने हैं। एक बार रोगी होने पर वे अच्छी तरह अपना इलाज भी नहीं करा सकते। भारत के अनेक क्षेत्रों में मलेरिया आदि रोगों से अधिकांश श्रमिक पीड़ित रहते हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता गिरती है और उत्पादन को भी क्षति पहुँचती है। सन् १९५१ में बम्बई के एक कारखाने में हिसाब लगा कर देखा गया था कि वहाँ २५.१% श्रमिकों को जुकाम तथा फेफड़े सम्बन्धी रोग, २६.०% श्रमिका को दस्त, पेचिस व हैजा आदि, ५.३% को गठिया या वात सम्बन्धी रोग, ०.८% को मलेरिया, ७.८% को चोट (काम करते समय नहीं), ०.८% को छूत के तथा ३४.२% श्रमिकों को विविध प्रकार के रोग हुए। निम्न-लिखित तालिका से हम कारखाने में इस प्रकार हुई समय की क्षति का अनुमान लगा सकते हैं। यही स्थिति प्रायः भारत के सभी कारखाने और उद्योगों में है। —

रोग	प्रत्येक रोग के कारण समय के विनाश का प्रतिशत	प्रत्येक रोग के कारण अनुपातिक दिनों की क्षति
(१) फेफड़ा सम्बन्धी रोग	४०.१	६.२
(२) पाचन सम्बन्धी रोग	२६.९	६.०
(३) मलेरिया	५.४	७.८
(४) मूत्र सम्बन्धी रोग	०.२	६.०
(५) छूत के रोग	१.१	११.७
(६) चोट (काम पर नहीं)	२.७	६.४
(७) विविध	२३.४	७.४

इसके अतिरिक्त गाँव के स्वतन्त्र और स्वच्छ वातावरण से आकर नगरों की गन्दगी व मकीयाँ बलियों में रहने, नगरों की विचित्र परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की नैतिक बुराइयों का आसेट होने, मदिरा, जुआ और अश्लीलता में पँस जाने तथा अन्य नस्लसम्बन्धी विषमताओं के परिणामस्वरूप श्रमिकों की श्रमात्मक शक्तियों का पतन हो जाता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के इस प्रकार नष्ट हो जाने से उनकी कार्यक्षमता पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है।

इस दोष को दूर करने के लिए श्रमिक के लिए विविधता सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करना चाहिये और मनोरंजन के स्वस्थ साधन उपलब्ध कर उनका मद्यपान एवं जुए का व्यसन छुड़ाना चाहिये।

(६) जलवायु— इसका भी कार्यक्षमता पर निर्णयात्मक प्रभाव पड़ता है। परिश्रम के कार्य के लिये शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन हमारे देश की

जलवायु गर्म प्रदेश की है। गर्मी के मौसम में निलमिलाती धूप में देर तक बड़ा परिश्रम करना सम्भव नहीं होता। दङ्गल तथा तराई प्रदेशों की जलवायु तो यही खराब है।

बिजली के पखे एवं नमीकरण यन्त्र (Humidifiers) आदि कृत्रिम साधनों की सहायता से यह कठिनाई भी कुछ सीमा तक दूर की जा सकती है।

(७) स्वतन्त्रता और आशा का अभाव—इसका भी श्रमिकों की कार्यक्षमता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बड़ निरीक्षण और आशा के अभाव में श्रमिक की कार्यक्षमता में कमी होना स्वाभाविक है।

इस दोष के निवारण के लिये प्रेरणात्मक भुत्ति-पद्धति (Progressive Wage System) का अनुकरण करना चाहिये।

(८) श्रृणप्रसूता—ग्रन्थ-शास्त्री डॉलिङ्ग के अनुसार भारतीय श्रमिक ऋण में ही जन्मता है, नशा में ही उसका पालन पोषण होना है और तब ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऋण प्रगति में बाधक होते हैं।

अतः, श्रमिकों की शीघ्र से शीघ्र ऋण मुक्त किया जाय और सहकारी आन्दोलन द्वारा उन्हें मिलव्ययिता का पाठ पढ़ाया जाय।

(९) काम के दीर्घ घण्टे—यद्यपि कारखाना अधिनियम द्वारा काम के घण्टों का अधिकतम निश्चय कर दिया गया है, किन्तु भारत के गर्म जलवायु को देखते हुए वे अब भी अधिक हैं। वर्तमान समय में सदा चलन वाले कारखानों में ४८ घण्टों का सप्ताह और मौसमी कारखाना में ५४ घण्टों का सप्ताह होना है। लेकिन यह अधिनियम अनेक छोटे कारखाना में लागू नहीं होता। असंगठित उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा कृषि में श्रमिकों के काम करने के घण्टे दीर्घ अनियमित तथा मालिक की इच्छा पर निर्भर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता कम होना स्वाभाविक है।

अतः उचित सन्नियम द्वारा इस दोष का निवारण किया जाय।

(१०) काम करने की दशाएँ—भारतीय कारखानों की दशाएँ, जहाँ हमारे श्रमजीवी काम करते हैं, सन्तोषजनक नहीं हैं।

कार्य-कुशलता को स्थिर रखने के लिये स्वच्छ जल, वायु विश्राम आदि की पूर्ण व्यवस्था होना आवश्यक है।

(११) भरती की दोषपूर्ण पद्धति—इसके कारण भी श्रमिकों की कार्यक्षमता गिरी हुई है। श्रमिकों की भरती जाँबर करते हैं, जो प्रत्येक भरती होने वाले से दस्तूरी लेते हैं। श्रमिकों की नियुक्ति, उन्नति एवं एक विभाग से दूसरे विभाग को स्थानान्तर सब कुछ इस जाँबर पर ही निर्भर है, अतः श्रमजीवियों को नाना प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहना पड़ता है। जाँबरों की आय नई निश्चितियों पर ही निर्भर होती है, अतः वे तरह-तरह के बहाने बनाकर पुरानों को निकालते और नवों को भरती

करते रहते है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिक की कार्यक्षमता कम हो जाती है और उद्योग का उत्पादन व्यय बढ़ जाता है।

इस दोष को दूर करने के लिये जाँवर पद्धति का अन्त करके श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिये।

(१२) दोषपूर्ण प्रबन्ध—बहुत सीमा तक यह भी श्रमिकों की अक्षमता के लिये दायी है। प्रबन्धकों का दुर्व्यवहार, काम का दोषपूर्ण विभाजन घिसी हुई यन्त्र सामग्री आदि ऐसे दोष हैं, जिनसे काम में जी नहीं लगता।

अस्तु, भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए उत्तम मशीनों और अच्छे माल का प्रयोग आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कुशल प्रबन्ध के निरीक्षण में उनसे कार्य लिया जाय।

भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की गृह-समस्या

श्रमिकों के निवास की गम्भीर समस्या—

भोजन और वस्त्र के उपरान्त 'मकान' मनुष्य की तृतीय प्रमुख आवश्यकता है। यो तो हमारी ये तीनों ही समस्याएँ गम्भीर हैं, किन्तु मकानों की समस्या, मुख्यतः औद्योगिक नगरों में, बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है। नगरों की बढ़ती हुई जन संख्या तथा गृह निर्माण की मन्द गति इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। अत्येक बड़े औद्योगिक नगर में एक इंच भी भूमि कहीं खाली नहीं और आबादी बहुत घनी है। नगर निवासियों में कारखानों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग सबसे बुरे मकानों में रहता है। अनेक नगरों में जो उनके निवास स्थानों का 'मकान' की सजा देना ही लज्जा की बात है। उन्हें मानव के योग्य नहीं कहा जा सकता। कानपुर में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने २ दिसम्बर सन् १९५२ को श्रमिकों के निवास स्थान का निरीक्षण करते हुए उन्हें 'मरक कुण्ड' कह डाला। पंडित नेहरू ने कहा कि भारतीय श्रमिकों की निवास समस्या बहुत ही जटिल है और उनके रहने के स्थान में ली-कुचेली गली (Slums) से अच्छे नहीं कह जा सकते। अन्य औद्योगिक केन्द्रों में भी उनकी गंदी वस्तियाँ होती हैं, जहाँ सफाई का नाम नहीं। कोठरी में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, पछों में नमी रहती है, रोशनदान का पता नहीं तथा स्वच्छ वायु भी नहीं सकती। अधिकांश श्रमिक ऐसे गन्दे वातावरण में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे मकानों में रहने वाले श्रमिकों से कार्यक्षमता की कैसे आशा की जा सकती है? ऐसे स्थानों को बम्बई में (Chawl), मद्रास में चेरी (Cherry), कलकत्ता में बस्ती (Basti) तथा कानपुर में अहाता (Ahata) कहते हैं। अब हम श्रम जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत के प्रमुख औद्योगिक नगरों की औद्योगिक बस्तियों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

(१) बम्बई में श्रमिकों की चॉल्स (Chawls) अत्यन्त ही अस्वास्थ्यकर हैं, जहाँ एक ही कमरे में ६-७ श्रमजीवी रहते हैं। उन्हें न तो कीटप्रतिक वातावरण ही

मिलता है और न स्वच्छ वायु तथा प्रकाश हो। श्री हर्स्ट (Hurst) ने इस प्रकार मजदूरों के बसाने का मोदाम म माल भरने के समान बताया है। बम्बई में ७०१ में अधिक श्रमिक एक कमरे वाले मकान में रहते हैं, जबकि लन्दन के केवल ६^० श्रमिक १ कमरे वाले मकान में निवास करते हैं। बम्बई के श्रमिकों में मकानों को पुनः किराये पर देने की प्रथा है, जिससे धनी आमादी की समस्या और भी बढ़ जाती है। किराये में वृद्धि करने के विचार से ४ या ६ श्रमिक एक कोठरी किराए पर ले लेते हैं। उसी के अन्दर चारों कोना में खाना पकाया जाता है। श्री शिवागम ने लिखा है कि जब बम्बई में मजदूरों की बस्ती में एक लेडी डाक्टर मरीज देखन गई तो उसने देखा कि एक कमरे में ४ गृहस्थियाँ रहती थी, उनके सदस्यों की संख्या २४ थी। चारों कमरों में चूल्हे बने हुए थे, सारा कमरा धुँये में काला हो रहा था। बम्बई के औद्योगिक श्रम-जीवियों के रहने की दशा के सम्बन्ध में श्रीयुक्त हर्स्ट का निम्न वर्णन बड़ा हृदय-स्पर्शी है—“रहने की दशाएँ यहाँ सबसे खराब हैं। एक मकरी गली में जिसमें कि दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते (लेखक के) घुसने के पश्चात् इतना अश्वेरा था कि हाथ से दटोलने पर कमरे का दरवाजा मिला। उस कमरे में सूर्य का शमात्र भी प्रकाश न था। ऐसी दशा दिन के १२ बजे थी। एक दियामलाई जलाने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि ऐसे कमरे में भी अनेक श्रमिक रहते हैं।” श्रम के शर्ही कमिशन ने तो बम्बई की खाला के सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा है कि इनको पूर्णतया तोड़ने के प्रतिरिक्त इनमें सुधार के लिए लेशमात्र भी प्रयास नहीं है।

(२) ग्रहमदावाद के श्रम-निगम स्थान भी अधिक सन्तोषजनक नहीं कह जा सकते। यहाँ की नगरपालिका ने हरिजनो तथा अन्य श्रमिकों के लिए कुछ मकानों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त ग्रहमदावाद मिल्स हाउसिंग कम्पनी एवं सूती वस्त्र मिल श्रम-संघ की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई है। श्रम-संघ द्वारा निर्मित कॉलोनी में रहने वाले श्रमजीवियों से १०) मासिक किराया लिया जाता है और २० वर्ष के उपरान्त जिस मकान में वे रहते हैं वह उनका हो जाता है। प्रत्येक मकान में दो कमरे, एक रसोईघर तथा एक बरामदा है। ग्रहमदावाद में श्रमिकों की गृहनिर्माण सहकारी समितियाँ भी हैं।

(३) बलफोर्ते की दशा भी बम्बई में अच्छी नहीं है। यहाँ बम्बई की अपेक्षा कम दाम पर भूमि मिल जाती है। यहाँ मजदूरों के घर भोपड़ियों की कतार हैं, जिन्हें ‘बस्ती’ कहा जाता है। ये भोपड़े मिल-मालिकों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वरन् सरदार (Sirdar) एवं कुछ मकान मालिकों ने बनवाए हैं। कलकत्ता नगर निगम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इन भोपड़ियों का निर्माण विना किसी योजना के हुआ है। प्रायः सभी निवास-स्थान कच्चे हैं और श्री केसे (Casey) के शब्दों में “कोई भी मानव वहाँ रहना पसन्द न करेगा।” चारों ओर गन्दगी का साम्राज्य है। मलेरिया और तपेदिक का काफी जोर रहता है। घरों में न नल है न सण्डास। पूरे मुहल्ले के लिए

एक या दो नल तथा एक सण्डास होगा, जिस पर बिचारे श्रमजीवी लाइन लगाकर लड़े रहने हैं। छोटी-छोटी बातों पर, जैसे—पानी के लिए, नित्य भगड़े-फसाद होते रहते हैं। सड़कें और गलियाँ सराब, गन्दी, पतली तथा प्रकाशहीन हैं, जिन पर रात्रि में चलना खतरनाक है। गत कुछ वर्षों में सवथ्री बिडला जी न सदप्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप जूट मिल कर्मचारियों के लिये अच्छे घरा की व्यवस्था की गई है, जिनमें लगभग ५०% जूट-मिल-श्रमिक रहते हैं, किन्तु शेष 'बस्तियों' में ही निवास करते हैं, जिनकी दशा अत्यन्त दयनीय है।

(४) कानपुर उत्तरी भारत का 'मैनचेस्टर' कहलाता है, अतएव यहाँ श्रमिकों के निवास के लिये समुचित व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। यद्यपि कानपुर में नगरपालिका, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं कुछ सेवायोजकों ने श्रमिकों के निवास के लिए आदर्श व्यवस्था की है, किन्तु फिर भी आज यहाँ 'अहाते' तथा 'बस्तियाँ' दृष्टिगोचर होती हैं, जिनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। उत्तर-प्रदेश की सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से गृह समस्या के निवारणार्थ यहाँ कुछ भी नहीं किया। हाँ, सन् १९४३-४४ में राज्य सरकार ने २,४०० परिवारों के लिये क्वार्टर बनवाने के हेतु इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को ३०३ लाख रुपए का ऋण दिया। तब में प्रति वर्ष यह सस्था कुछ न कुछ मकान बनवाती रही है, जिनका किराया ४) प्रति माह है। सन् १९३८ की कानपुर श्रम जाँच समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ सेवायोजकों की ओर से केवल ३,००० मकान बनाए गए, जिनमें १०,००० श्रमिक रहते हैं। सन् १९३८ से सन् १९४३ तक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सन् १९४३ में यहाँ श्रमिकों की संख्या १,०३,००० थी। इसमें से केवल १०% श्रमजीवियों के रहने के लिये सेवायोजकों ने व्यवस्था की। यहाँ के सेवायोजकों में से ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिसने मैक रोहटगज तथा अलेनगज में १,६६० श्रम-क्वार्टर्स बनवाए। इन क्वार्टरों में जल, प्रकाश, स्वच्छ वायु आदि की तो सुव्यवस्था है ही, इसके अतिरिक्त प्रत्येक कॉलोनी के लिये एक शिक्षण संस्था एवं डिस्पेंसरी भी है। सर्वे श्री वेग सुदरलैंड एण्ड कम्पनी लि० के प्रबन्ध के अन्तर्गत एलगिन मिल्स ने भी अपने श्रम-जीवियों के लिये सुन्दर मकानों का निर्माण करवाया है। एलगिन मिल्स से क्वार्टरों में अन्य सुविधाओं के साथ साथ बिजली की रोशनी का भी प्रबन्ध है। इसी प्रकार सर्वथ्री जुर्मीनल कमलापति की ओर में भी उनके श्रमिकों के निवास के लिए एक पृथक कॉलोनी का निर्माण किया गया, जिसमें प्रायः सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कानपुर की नगरपालिका ने भी निम्न कोर्ट के श्रमिकों के लिये (जैसे भगी एवं पार्क तथा सार्वजनिक उद्यान में काम करने वाले कर्मचारी) निवास की अच्छी व्यवस्था की है।

इतना होते हुए भी कानपुर की श्रम-बस्तियों एवं अहातों में सहस्रो श्रमिक रहते हैं। श्रम के साही कमीशन ने अहातों का वर्णन इस प्रकार किया है—“प्रायः

प्रत्येक मकान एक-एक कमरे का है, जिसकी लम्बाई चौड़ाई = फीट \times १० फीट है। किसी भी कमरे के आगे बरामदा नहीं है और प्रत्येक कमरे में ३-४ परिवार रहते हैं। फर्श बच्चा है तथा नमी रहती है। कच्ची भी स्वच्छ वायु प्रकाश आदि का प्रबन्ध नहीं है। पण्डित नेहरू ने तो इन अहातों को 'गरक कुरड' की मज्जा दी है।

(५) टाटानगर—यहाँ सब श्री टाटा की ओर में लोहे एवं स्थापन उद्योग में काम करने वाले श्रमजीवियों के लिये लगभग ८,१०० मकान बनवाये गये हैं। प्रत्येक मकान में दो कमरे, रसाईघर तथा एक बरामदा है। इसके अतिरिक्त स्नानागार एवं पल्ल-सडाम भी है। सभी मकान पक्के हैं तथा कुछ में बिजली के पत्ते भी हैं। यह सब व्यवस्था दक्ष बारीगरो के लिये अनुकूल श्रमजीवियों के निवास-स्थान बड़े गन्दे एवं असन्तोषजनक है।

(६) मद्रास में भी श्रमिकों के निवास स्थान बड़े असन्तोषजनक हैं। कुछ मिल मालिकों ने श्रमिकों के लिये क्वार्टर बनवाये हैं, परन्तु उनमें अनिवार्य श्रमिक रहना पसन्द नहीं करते क्योंकि उनके ब्रिड्ड खुफिया जाँच होती रहती है और यदि कभी हड़ताल में भाग लगे तो वे क्वार्टर में निवास दिया जायेगा। ऐसे वातावरण में वे रहना पसन्द नहीं करते।

(७) कोलापुर में श्रमिकों की गृह व्यवस्था सन्तोषजनक है। इसी प्रकार मदुरा में भी श्रमिकों के लिये सुन्दर मकान बने हैं, जिनमें प्रायः सभी बनमान सुविधाएँ उपलब्ध हैं। नागपुर की एम्प्रेस मिल तथा बगनोर की मृती जूनी तथा रेसमी वुल मिल के श्रमजीवियों के लिए बड़ी सुन्दर गृह-व्यवस्था है। रानीगंज तथा भरिया की कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो मकान बनवाये गये हैं वे Mines Board of India के मादेशानुसार बनवाये गए हैं अतः सन्तोषजनक कहे जा सकते हैं। ग्रामों के बाह्य के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों की गृह-दशा प्रत्यन्त शोचनीय है। वहाँ नहीं भी स्वच्छता नहीं तथा मले रखा का बड़ा बोझाला है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किंचित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी नगरों में औद्योगिक श्रमिकों की गृह-समस्या अत्यन्त जटिल है। श्रमिकों के निवास स्थानों को देखकर कभी-कभी मसानो (Masano) के शब्द स्मरण हो आते हैं—'विश्व की खूबता ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने और श्रम बस्तियों की शोचन ने।'

बुरी गृह व्यवस्था के दुष्परिणाम—

अच्छे घरों का अर्थ है गृह-जीवन की सम्भावना सुख और स्वास्थ्य तथा बुरे घरों का अर्थ है, गन्दगी, क्षयबलहीनता, बीमारियाँ, आचारहीनता, व्यभिचार और अपराध—इनके लिए अस्पताल, जेल और पागलखानों की आवश्यकता होती है, जहाँ समाज के भ्रष्ट एवं पतित लोगों को छिपाया जाता है, जो स्वयं समाज की लापरवाही के ही परिणाम हैं। (१) उपरोक्त एवं सुविधाहीन घरों के कारण श्रमिकों का घरेलू जीवन

नीरस एवं गंदा दरहिन हो जाता है। (11) गंदगी के कारण मोगिया और तपदिक जैसी नयनक वामारियों का होर रहता है श्रमिकों का वास्थ्य विगड़ जाता है उनके मस्तिष्क सकुचिन हो जाते हैं तथा मानसिक विकास का कोई अवसर नहीं रहता। (111) अपूर्ण और गंदे मकान औद्योगिक अशांति के भी कारण हैं। (115) एक सबसे बड़ी वृत्ताइ अधिक सख्या में शिशु मृत्यु है जो बम्बई की गंदी बस्तियों में पाई जाती है। मृत्यु सरया निवाम के कमरे के विपरीत अनुपात में है। उदाहरण के लिए सन् १९३६ में एक कमरे वाले निवाम स्थानों में मृत्यु सख्या ७८ % थी। सबसे गंदे स्थानों में मृत्यु दर २६८ प्रति हजार था जबकि साधारण दर २०० से ५० प्रति हजार ही था। (12) अतः मकान चालक जीवन की भयंकर दशाय तथा गोपनीयता के अभाव के कारण लोग अपने कुटुम्ब को नहीं ला पाते जिसमें श्रम की स्थिरता तथा कायक्षमता पर कुभाव पड़ता है। (13) एकाकी जीवन व्यतीत होने के कारण उनमें वैश्वागमन जसा बुरा आदत पदा हो जाती। जो श्रमिक परिवार सहित रहते व भी एक कमरे ही के कारण गोपनीयता नहीं रख सकते। एक ही कमरे में पुरुष स्त्रियों के साथ रहने के कारण समय में जीवन व्यतीत नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में महिला श्रमिकों के नैतिक पतन की बड़ी आशंका रहती है।

डा० राधाकमल मुकर्जी के शब्दों में भारतीय औद्योगिक केन्द्रों की श्रम बस्तियों की दशा इतनी भयंकर है कि जहाँ मानवता का विध्वंस होता है महिलाओं के सतीस्व का नाश होता है एवं देश के भावी आधार स्तम्भ—शिशुओं का गला घोट जाता है।

अतः श्रम जाव भूमिनिर्माण की है कि शिक्षा और औपधि सम्बन्धी सहायता की भाँति सरकार को औद्योगिक आवास का भी उत्तरदायित्व सभालना चाहिये।

गृह समस्या को हल करने के लिए किए गए प्रयत्न

(1) सुधार प्रयासों के पोट टस्टों के प्रयत्न—

यद्यपि भारत में घर सम्पत्ति सुविधाय गून है और इस सम्बन्ध में दशा बड़ी गंभीर है किन्तु ऐसी भा सस्थाय तथा सेवायोजक न जिहाने बड़ी सुदर व्यवस्थाय की हैं। बम्बई में गृह समस्या के निवारणार्थ सुधार प्रयास (Improvement Trusts) की स्थापना हुई। इसका काम नई भवित्ता का निर्माण घन क्षया का विस्तार समुद्र में भूमि को निम्नानना जिससे प्रसार पाय में सुविधा हो तथा गरीबों के लिये स्वच्छ मकानों का निर्माण करना था किन्तु ट्रस्ट का सीमित दक्षि नगर निगम सहयोग का कमा तथा भूमिपतियों के विरोध के कारण इसे कुछ विशेष सफलता नहीं मिली। फिर भा ट्रस्ट ने कुछ सीमा तक प्रशंसनीय कार्य किया। सन् १९६० तक नगरपालिका ने भा अपने कमचारियों के लिए २६०० मकान बनवाये तथा २२०० के लिए स्वीकृति दी। पोट टस्ट ने ५००० व्यक्तियों के लिए मकान बनवाये। इधर नगर का जन सख्या बड़ा तजा से बढ़ रहा था कि सेवायोजक ने अपने श्रमजाविधों के रहने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सन् १९१४-१८ के युद्ध

के उपरान्त बम्बई सरकार द्वारा इस समस्या का मुलभूतन के लिए सुविस्तृत योजना तैयार की गई। इसने सिधे ६ करोड़ रुपये के विकास ऋण तथा बम्बई आने वाली सभी कपास पर १) प्रति गाँव की दर से नगर कर लगाकर आवश्यक धन एकत्रित किया गया, किन्तु इस प्रकार निर्मित चाल (मुख्यतः वोरली की चाल) दस वर्ष तक खाली पड़ी रही। इतम रहन के लिये श्रमिका के आकर्षित न होने व निम्न कारण थे — वहाँ तक पहुँचने की कठिनाई, बाजार सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव, उनका सीमेण्ट से बना होना—जिसका कारण वे गर्मी में अधिक गर्म तथा जाड़ में अत्यन्त सर्द रहती है, किराये की ऊँची दर तथा प्रकाश सम्बन्धी व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा का अभाव। इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किये गये हैं। नगर निगम तथा पोर्ट ट्रस्ट भी अरबों विकास योजनाएँ कार्यान्वित करने में प्रयत्नशील हैं। मई सन् १९४७ में बम्बई सरकार ने वारली पर भवन निर्माण योजना प्रारम्भ की, जिसमें काम करने वाले एक व्यक्ति तथा परिवार दाना के रहने के लिए मकान बनवाये गये हैं। अब बम्बई में एक कमरे वाले मकान न रहेगे।

(II) मिल मालिकों द्वारा किये गये प्रयत्न—

जहाँ तक मिल मालिकों का प्रश्न है कुछ मिला न जैमे—जैकब सासन मिल ने, अपने श्रमजीवियों के लिये मकान देने की व्यवस्था की है। उचित दर पर कारखानों के समीप स्थान मिलने की कठिनाई, इस बात की सुरक्षा का अभाव कि मकान मिलने पर श्रमिक मकान देने वाली मिल में ही काम करेंगे तथा स्वयं कर्मचारियों की उन मकानों में रहने की अनिच्छा—इन सब कारणों में काम के प्रसार में काफी शिथिलता आ गई है। कमचारों डरत है कि उनकी स्वतन्त्रता में गांधी पड़गी तथा हुकूमत व समय वे ज़िवाल दिये जायेंगे। वे स्वच्छता और अनुशासन के नियमों को भी पसन्द नहीं करते क्योंकि वे उनका महत्त्व ही नहीं समझते। कानपुर नागपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद, मद्रास आदि नगरों में 'मिल मालिकों ने श्रमजीवियों के हितों पर अधिक ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में एम्प्रेस मिल नागपुर, जीवाजीराव वाटन मिल ग्वालियर तथा टाटा के जमशेदपुर के छोटे और स्थान के कारखानों के प्रबन्धकों द्वारा किये गये आवास सम्बन्धी प्रयत्न प्रशंसनीय हैं। दक्षिणी भारत में सहकारी-गृह निर्माण समितियों ने भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है।

(III) औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए राजकीय प्रयत्न —

बहुत अधिक समय तक भारत सरकार ने गृह समस्या की ओर लक्ष्मात्र भी ध्यान नहीं दिया। परन्तु स्वतन्त्रता के उपरान्त, राष्ट्रीय सरकार के लिए अधिक समय तक मोन रखना सम्भव न था। सन् १९४८ का आद्यमिक नीति सम्बन्धी घोषणा में, औद्योगिक श्रमजीवियों के लिए गृह निर्माण पर प्रथम बार बल दिया गया। अप्रैल सन् १९४८ में सरकार ने यह घोषित किया कि वह ३०० करोड़ रुपये की लागत पर अगले १० वर्षों में १० लाख घर बनवाएगी, जिसका विवरण इस प्रकार होगा—

कारखानों के लिए ७॥ लाख, बागानों के लिए २ लाख और जहाजी कम्पनियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ३ लाख । यद्यपि राज्य सरकारों ने इस योजना का स्वागत किया, परन्तु घनाभाव के कारण कोई प्रगति न हो सकी । सन् १९४६ में एक नई योजना—औद्योगिक आवास योजना—घोषित की गई, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को ऋण दिए गए ।

पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत गृह निर्माण की प्रगति—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना की अवधि में एक राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम के विकास की प्रारम्भिक व्यवस्थाओं के संगठन का प्रयास किया गया । दो नगर आवास योजनायें—'आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना' (Subsidised Industrial Housing Scheme) और 'कम आय वाले वर्ग के आवास की योजना' (Low Income Group Housing Scheme)—१,२०,००० आवास इकाइयों के निर्माणार्थ ३८ ५ करोड़ रु० के व्यय से प्रारम्भ की गई । इसके साथ-साथ जन-संख्या के कुछ विशेष वर्गों जैसे विस्थापित व्यक्तियों एवं सरकारी नौकरों के लिये गृह योजनाओं पर भी काम जारी रहा । यह अनुमान लगाया गया है कि सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा पहली योजना अवधि में ७,४२,००० घर बनाये गये ।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में १२६ करोड़ रु० विभिन्न गृह-योजनाओं के लिये स्वीकार किये गये । योजना को सन् १९५८ में संशोधित करने पर यह आयोजन घटाकर ८४ करोड़ रहने दिया गया । किन्तु यह घटोत्तरी वास्तविक व्यय की सीमा को लागू होनी थी, अधिकतम सीमा को नहीं ।

(१) आर्थिक सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना—

राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद भारत सरकार ने सन् १९५२ में 'आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना' को अन्तिम रूप दिया ।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रारम्भ में राज्य सरकार को सम्पूर्ण लागत देगी, जिसका ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में होगा तथा शेष ५०% ऋण के रूप में होगा, जिसे ५ वर्ष में वापिस करना होगा । श्रमिक के आवास की स्वीकृत योजनाओं के लिए नियोक्ताओं का लागत का २५% आर्थिक सहायता तथा ३७.३% ऋण के रूप में देने की व्यवस्था है । यह योजना सर्व प्रथम औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वीकृत हुई थी, किन्तु अब सन् १९५२ के खान अधिनियम के अनुसार कोयला तथा अभ्रम खानों के श्रमिकों को छोड़कर शेष कुछ अन्य खान मजदूरों के लिए भी लागू होती है । इन योजना के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान केन्द्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों, वैधानिक गृह बार्ड, औद्योगिक नियोक्ताओं तथा रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं को दिए जाते हैं । अक्टूबर सन् १९६० के अन्त तक राज्य सरकारों,

कारखाना मालिकों तथा मजदूरों की सहकारी संस्थाओं को ऋण के रूप में ₹२.६५ करोड़ रुपये तथा सहायता के रूप में २०.८३ करोड़ रुपये दिये गये और १,३६,४६६ मकानों के लिए स्वीकृति दी गई। दिसम्बर सन् १९६० के अन्त तक ६८,००० मकान बनाए जा चुके थे।

(२) कम आय वाले वर्ग के लिये भूह योजना—

सन् १९५४ में कम आय वालों के लिए सरकारी आर्थिक व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लोगों को एक सम्बन्धी अवधि के लिए बहुत कम व्याज पर ऋण देने का प्रबन्ध किया गया। केवल उन्हीं लोगों को इस योजना के अन्तर्गत ऋण मिल सकता है जिनकी वार्षिक आय (६,०००) में अधिक नहीं हो। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को दीर्घकालीन व्याज रहित ऋण देती है। अधिक से अधिक ५ वर्ष की अवधि के अल्पकालीन ऋण भी केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भूमि का अधिग्रहण एवं विकास करने तथा इसके बाद उसको प्लॉटों के रूप में अ-लाभ आधार पर आय वाले व्यक्तियों को बेचने के लिये उपलब्ध करती है। ११ मार्च सन् १९६१ तक राज्य सरकारों ने इस योजना के अन्तर्गत ४२.७६ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार से लिया। इस अवधि में ८२,८४८ घर बनाने के लिये स्वीकृति दी गई, ५०,६५६ घर बनकर तैयार हो गये तथा २०,०६४ घर बनने की प्रगति में थे।

(३) बागान मजदूर आवास योजना—

सन् १९५१ के 'बागान मजदूर अधिनियम' ने प्रत्येक बागान-मालिक के लिये अपने श्रमिकों के आवास हेतु व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। अप्रैल सन् १९५६ में एक योजना भी उनकी सहायता के लिये (विशेषतः छोटे बागान मालिकों के लिये) बनाई गई। इस योजना के अन्तर्गत बागान मालिकों को राज्य-सरकारों के माध्यम से मकानों की लागत के ८०% तक व्याज मुक्त ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता देना तय हुआ। सन् १९६० के अन्त तक राज्य सरकारों ने ६८३ घरों के निर्माण के लिये १२.५७ लाख रु० स्वीकार किये। इनमें से २६८ घर बन गये हैं।

ऋणों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रतिभूति देने में असमर्थ होने के कारण बागान मालिक योजना का लाभ उठाने में कठिनाइयाँ अनुभव कर रहे हैं। अतः प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक 'पूल गारन्टी फण्ड' की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखे गये हैं। 'पूल गारन्टी फण्ड' (Pool Guarantee Fund) का उद्देश्य राज्य सरकारों को घुरे ऋणों के कारण (जो कि प्रतिभूति सम्बन्धी नियम ढीला करने के फलस्वरूप डूब जायें) होने वाली हानि से बचाना है। यह फण्ड उस धन से बनाया जायेगा जो कि ऋणों पर ३% वार्षिक व्याज अधिक लगाकर प्राप्त होगा। यदि फण्ड की सीमा से अधिक हानि हो, तो वह भारत सरकार, राज्य सरकार एवं कमोडिटी बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बट जायेगी।

(४) गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना—

गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना (Slum Clearance Scheme) मई सन् १९५६ में अमल में लाई गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को एवं इनके द्वारा म्युनिस्पल एवं स्थानीय सस्थाओं को गन्दी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के पुनः आवास के लिये, जिनकी आय वम्बई व कलकत्ता में २५० रु० प्रति माह एवं अन्य स्थानों में १७५ रु० प्रति माह से अधिक नहीं है, वित्तीय सहायता देने का प्रबन्ध है। अभी यह योजना मुख्यतः बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और ग्रहमदाबाद में, जहाँ कि गृह दशायें बुरी हैं और अविलम्ब सुधार चाहती हैं, सीमित है। यदि आवश्यकता हो, तो अन्य क्षेत्रों भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दिसम्बर सन् १९६० तक राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई १७० योजनाओं पर स्वीकृत मिल चुकी थी, जिनके अन्तर्गत १६*०७ करोड़ रु० के व्यय से ४८८४१ गृह-इकाइयाँ (Housing Units) बनाने का प्रस्ताव था। सन् १९६० के अन्त तक १०,०६५ गृह-इकाइयों का निर्माण हो चुका था तथा ७,७०१ गृह-इकाइयों पर काम जारी था। ४,६२७ घर एवं १०५ दुकानें सन् १९६० तक बन कर तैयार हो गईं।

अम बस्तियों में मकानों के निर्माणार्थ योजना टोली सन् १९५८ के सुझाव—

गन्दी बस्तियों में सुधार कर मकान बनाने के विषय में राष्ट्रीय विकास परिषद् की योजना समिति ने जो योजना टोली बनाई थी, उसके सुझाव निम्न हैं—

(१) गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस काम के लिये कानून द्वारा निगम मण्डल बनाये जायें, जो स्वायत्त हो और जिनके ऊपर कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व हो। वे अपने क्षेत्रों में योजनाओं के लिये नीति निर्धारित कर।

(२) आयोजन में मकान बनाने के लिये जो राशि रखी गई है वह केन्द्रीय मकान निगम को दे दी जाय, जिससे वह उसे राज्य के मकान निगमों को बाँट सके। केन्द्रीय निगम, राष्ट्रीय भवन निर्माण सङ्गठन और केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान-शाला के साथ भी निकट सम्पर्क रहे।

(३) गन्दी बस्तियों की बाढ को रोकने के लिये गाँवों से नगरों की ओर जाने की प्रवृत्ति को रोका जाय तथा केन्द्रीय सरकार नगर में नये उद्योग खोलने या किसी उद्योग को बढ़ाने की अनुमति तभी दे, जब स्थानीय सस्थाएँ भी इसे स्वीकार कर ल।

(४) जहाँ आबादी बहुत घनी है, वहाँ अधिक रोजगार न दिये जायें। प्रत्येक नगर में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए वृहत योजना बनाई जाय।

(५) मकानों के लिए न्यूनतम स्तर स्थापित किया जाय और गन्दी बस्तियों में सभी मकानों की जाँच की जाय।

(६) मकानों के निर्माण का व्यय कम होना चाहिए।

(५) ग्राम आवास योजना (Village Housing Projects Scheme)—

यह योजना सन् १९५७ में प्रारम्भ की गई। इससे ग्रन्थगत सामुदायिक विकास खंडों में लगभग ५,००० चुन दिये गाँवाँ में तृतीय योजनावधि में ग्रन्थर हाउसिंग प्रोजेक्ट स्थापित करने थे। यह योजना महायन्त्र प्राप्त आत्म-महायन्त्र तथा मिद्वान्त (Principle of aided self help) पर बनाई गई है। निर्माण लागत की है या २,०००-२० (दोला में जो भी कम हो) की वित्तीय महायन्त्र तथा वे हथ में दो जाती है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित Rural Housing Cells तथा सह-विकास अधिकांशों द्वारा तकनीक महायन्त्र निशुल्क दान की व्यवस्था है। Rural Housing Cells लगभग सभी राज्यों में (गुजरात व जम्मू-काश्मीर को छोड़ कर) बन गये हैं। लगभग ३,७०० गाँव चुने गये, जिनमें से १,६०० गाँवों का सर्वे व योजनाकरण दिसम्बर सन् १९६० तक पूर्ण हो गया है। राज्य सरकारों ने १५,२०० करोड़ के निर्माण के लिये २१८ लाख रु० से अधिक रु० तथा स्वीकृत किया है। इसमें १२८ लाख रु० वास्तव में दिया जा चुका है ३,७०० घर बन कर तैयार हो गये हैं तथा ८,००० घर बनाने की प्रगति में है।

(६) भूमि-अधिग्रहण एवं विकास योजना—

अक्टूबर सन् १९५६ में प्रचलित की गई यह योजना वर्तमान पर भूमि का अधिग्रहण और विकास करके प्लॉट बनाकर उचित कीमता पर गृह निमाताओं को (विशेषतः कम आय वाले वर्गों के) बेचने में राज्य सरकारों की विशेष सुविधा हेतु उन्हें ऋण देने के लिये बनाई गई है। इस योजना के अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे भूमि के मूल्यों में स्थायित्व लाना, नगर विकास का विस्तार करना आदि आत्मनिर्भर मिश्रित उपनिवेशों को प्रोत्साहन देना।

इस योजना के अन्तर्गत १५ करोड़ रु० की सीमा तक महायन्त्र का वापस किया गया, जबकि वास्तविक आय द्वितीय योजना अवधि में २६० करोड़ रु० तक सीमित रखा गया। इसमें से राज्य सरकारों ने ३८ लाख रु० सन् १९५६-६० में तथा १८३ करोड़ रु० १९६०-६१ में लिया है।

मध्यवर्गीय जनता के लिये आवास योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत ६,००१ रु० से १२,००० रु० तक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को या उनकी सहकारी समितियों का गृह निर्माण सम्पन्धी ऋण दिये जाते हैं। जीवन बीमा निगम ने इस उद्देश्य के लिये १० करोड़ रु० दिये हैं। दिसम्बर सन् १९६० तक ३,५८६ घरों के निर्माण हेतु ४८७ करोड़ रु० की सीमा तक ऋण सहायता स्वीकृत की गई। वास्तविक ऋण २४३ करोड़ रु० दिया गया। ४७७ मकान बन कर तैयार हुये।

राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को पर्याप्त आवास सुविधा प्रदान करने में सहायता करने के लिये एक किराया-गृह-योजना (Rental Housing Scheme) बनाई गई है। इस उद्देश्य के लिये जीवन बीमा निगम ने ७ करोड़ रु० उपलब्ध

किये हैं। दिसम्बर सन् १९६० तक २,४६० घरों के लिये २०८ करोड़ रु० स्वीकृत किया गया और ७३४ मकान बनाये गये।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (National Building Organisation)—

जुलाई सन् १९५४ में एक राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन बनाया गया, जिसका उद्देश्य भवन-निर्माण की लागत को कम करने के उपायों की खोज-प्राप्ति करना है। यह संस्था निर्माण सामग्री का विकास करता है तथा अपने अनुसन्धान परिणामों का प्रचार करता है। इसके अन्तर्गत कुछ प्रादेशिक अनुसन्धान संगठन भी कार्य कर रहे हैं।

तृतीय पंच-वर्षीय योजना में आवास व्यवस्था—

निजी क्षेत्र में आवास की व्यवस्था के प्रतिरक्त, भारत सरकार की गृह-निर्माण सम्बन्धी योजना निम्न ६ वर्गों से सम्बन्धित है—(i) औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करना, (ii) निम्न-आय-वर्गीय व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था करना (low-income-group housing), (iii) गन्दी बस्तियों की सफाई करना; (iv) गृह निर्माण के हेतु भूमि की प्राप्ति करना, (v) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था करना, और (vi) वागान-श्रमिकों के हेतु आवास की व्यवस्था करना। आवास सम्बन्धी इन सुविधाओं के लिए तृतीय पंच-वर्षीय योजना में १२० करोड़ रुपये पृथक् रखा गया है। इसके अतिरिक्त रेल, डाक व तार एवं सुरक्षा विभागों की प्रलग-प्रलग गृह-निर्माण सम्बन्धी योजनाएँ हैं।

यद्यपि गृह समस्या पर अब उचित ध्यान दिया जा रहा है तथापि जो कुछ हो रहा है उससे समस्या कम भले ही हो जाय, किन्तु पूर्णतः नहीं सुलभ सकती। ग्रामीण आवास और मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास के हेतु बहुत कम अर्थ-व्यवस्था की गई है। औद्योगिक गृहों के किराये भी इतने अधिक हैं कि साधारण श्रमिक उनको वहन नहीं कर सकता है, अतः कार्यक्रम में उपयुक्त सुधार करने आवश्यक हैं।

भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता

(Indebtedness of Indian Industrial Labour)

भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की अक्षता एवं उनके निम्न जीवन स्तर का एक प्रधान कारण उनकी ऋणग्रस्तता है। हमारे अधिकांश श्रमजीवी किसी न किसी ऋणदाता के जगल में फँसे रहते हैं। अम के शाही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर लिखा है कि—“भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर का प्रधान कारण उनकी ऋणग्रस्तता है। भारतीय श्रमिक ऋण में ही जन्म लेता है, ऋणों के रूप में ही जीवन व्यतीत करता है तथा ऋण के भार से दबा हुआ ही वह इस संसार से फूँच कर जाता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के उपरान्त भी वह ऋण का उत्तरदायित्व वसीयत के रूप में अपने उत्तराधिकारियों के कंधों पर छोड़ जाता है।” यह कथन भारतीय श्रमजीवियों के लिए पहले जितना सत्य था, उतना ही आज भी

सत्य बना हुआ है। सम्भव है कि द्वितीय विश्व-युद्ध में भजदूरी एवं मँहगाई की वृद्धि के कारण औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता में कुछ कमी हो गई हो, किन्तु छोटे श्रमिकों की दशा में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

औद्योगिक ऋण का अनुमाप—

भारत में कुल औद्योगिक ऋण कितना है, इससे बारे में विश्वनीय एवं ठीक आँकड़े नहीं मिलते। कारण यह है कि औद्योगिक साख प्रणाली असंगठित है और ८०% साख ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाती है, जिन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक ऋण के सम्बन्ध में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। समय-समय पर इसके सम्बन्ध में अनुमान लगाया गया है। निम्न तालिका औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता पर शकाक्ष डालती है—

केन्द्र	ऋणग्रस्त परिवारों का प्रतिशत	प्रति कुटुम्ब ऋण का औसत (रु०)
I. बम्बई राज्य		
(१) बम्बई ...	६४.१	१२४
(२) जलगाव .	६०.७	२२७
(३) शोलापुर	८५.७	२३४
II. पश्चिमी बंगाल		
(१) कलकत्ता	४१.५	११७
III बिहार		
(१) देहरी ग्रौन्-सोन	५८.०	१५७
(२) टाटनगर	६२.२	२३५
(३) झरिया	२२.६	२६
(४) मुंगेर तथा जमालपुर	७३.७	२०४
IV आसाम		
(१) गौहाटी	१३.३	१६७
V. पंजाब		
(१) लुधियाना ...	३२.४	१५१
VI. उड़ीसा		
(१) बरहमपुर ...	५६.४	१६७
(२) कटक	३१.०	१६६

उपयुक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत के लगभग २/३ श्रमजीवी ऋणग्रस्त हैं और उनके ऋण की मात्रा सामान्यतः उनकी तीन माह की भजदूरी से भी अधिक है। श्रम जाच समिति सन् १९४६ ने भारतीय औद्योगिक ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उससे प्रगत है कि बम्बई नगर में श्रमिकों के ऋण की मात्रा १०) से ७००) तक है। अहमदाबाद में लगभग ५७ प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त हैं और

प्रति परिवार ऋण का औसत २६६) है। नागपुर में राज्य सरकार द्वारा कार की जाँच से यह प्रगत है कि वहाँ लगभग ८२% परिवार ऋणग्रस्त है और प्रति परिवार ऋण का औसत १२६) है। मिर्जापुर के दरी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों में ७०% ऋणग्रस्त हैं एवं प्रति परिवार ऋण का औसत ११४) है। इसी प्रकार धीनगर एवं अमृतसर के दरी उद्योग के कर्मचारियों में क्रमशः ८९% एवं ६०% श्रमिक ऋणग्रस्त हैं। बलकता, कानपुर एवं मद्रास के चमड़ा उद्योग में सलग्न श्रम-जीवियों में क्रमशः १००%, ६६% तथा ६४% ऋणग्रस्त हैं। बीड़ी उद्योग में काम करने वाला प्रायः प्रत्येक श्रमिक ऋणग्रस्त है। मेरठ के शक्कर-उद्योग में ऋणग्रस्त श्रमिकों की संख्या ७८% है और ऋण की मात्रा ३६०) प्रति ऋणी है। देश के अन्य उद्योगों एवं अन्य केन्द्रों में भी ऋणग्रस्तता की यही दशा है।

ऋणग्रस्तता के कारण—

(१) पैतृक ऋण—बहुधा देखा जाता है कि श्रमिक परिवारों में पूर्वजों द्वारा लिए हुए ऋण का भुगतान करना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। पूर्वजों की गलती या मजबूरी के कारण परिवार के सदस्यों को यह उत्तरदायित्व प्राप्त होता है एवं चक्रवृद्धि व्याज के कारण ऋण की राशि बढ़ती चली जाती है तथा परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस परम्परागत देनदारों को चुकाने के प्रयत्न में उत्तराधिकारी जीवन व्यतीत कर देते हैं। कदाचित् उन्हें इस कानून का ज्ञान नहीं होता कि मृतक द्वारा लिए हुये ऋणों के लिए उत्तराधिकारी उसी सीमा तक उत्तरदायी होते हैं जितनी कि सम्पत्ति मृतक द्वारा उत्तराधिकार के रूप में छोड़ी जाती है। यदि मृतक ने कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ी तो उसके द्वारा लिए गये ऋण के लिये उसके उत्तराधिकारियों को किसी भी न्यायालय में उत्तराधिकारी नहीं ठहराया जा सकता है।

(२) सामाजिक अवसरों पर अग्रव्ययता—भारतीय श्रम-समाज में विभिन्न अवसरों पर सम्पन्न होने वाले समारोहों में बड़ी ही अदूरदर्शिता से काम लिया जाता है। श्रम-जाच-समिति के शब्दों में—“भारतवर्ष में रीति रिवाज अत्यन्त कठोर शासक हैं, क्योंकि उनके पासनाथ—श्रम-जीवियों को अपना सब कुछ न्योछा र करना पड़ता है।” उदाहरण के लिये, विवाह के अवसरों पर सामाजिक भोज एवं दहेज की प्रथा के कारण श्रम-जीवियों को अपनी हैसियत से अधिक

भारतीय श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के ६ कारण

- (१) पैतृक ऋण।
- (२) सामाजिक अवसरों पर अग्र-व्यय।
- (३) जुया, नशा आदि पर फिक्कल-खर्च।
- (४) दोषपूर्ण भरती पद्धति।
- (५) ऋण प्राप्ति की सुविधा।
- (६) अत्यधिक व्याज-दर।
- (७) अशिक्षा।
- (८) ऋणदानाओं की दूषित कार्य-प्रणाली।
- (९) बीमारी।

नए लेकर इन सामाजिक उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर प्रायः श्रमिक अपनी वास्तविक आर्थिक दशा को भूल जाता है और उसके समुदाय के अग्र लोभ भी इसका विचार न करके उसे नए देकर हम उत्तरदायित्व को सम्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मकारियोजक (Jobber) मिस्त्री अथवा पठान लोग प्रति क्षण ऐसे ही अवसरों की ताक म रहते हैं और सक्षम नए प्रदान करने की तयारी हो जाती है। इसी प्रकार जन्म एवम् मृत्यु के अवसरों पर भी अदृष्टदृष्टि से काम लिया जाता है। श्रमिक की अणुप्रस्तुता का यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक अनुमान के अनुसार अणु का लगभग ३५% भाग सामाजिक अवसरों पर व्यय करने का कारण ही लिया जाता है।

(३) जुआ नशा आदि पर किङ्कलसर्चों—जुआ खेलना एवम् नशा करना भारतीय श्रमजीवियों की बहुत बुरी आदत है। भले ही पेट-भर भोजन करने के लिए उनके पास पैसा न हो किन्तु दिन भर की थकान दूर करने के लिए नए लेकर वे मदिरापान अवश्य करेंगे। विवेकहीन होने के कारण श्रमिक अपनी आय का सदुपयोग नहीं कर पाते। यदि उनकी जेब में चार पैसे पड़ें तो मनोरंजन की अपेक्षा वे शराब अथवा जुआ को अधिक प्राथमिकता देंगे। इस दुर्गुण के कारण भी उन्हें नए रहना पड़ता है।

(४) होशपूर्ण भरती पड़ती—श्रमिकों की भरती कर्मकारियोजकों द्वारा होती है। प्रत्येक भरती होने वाले को दस्तूरी देनी पड़ती है। श्रमिकों की नयुक्ति उनकी उर्ध्व अथवा एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना सब कुछ इन्हीं थाजों पर निर्भर करता है। इन थाजों की आय नई भरती पर ही निर्भर करती है अतः वे तरह-तरह के बहाने बताकर पुरानों को निकालते तथा नयों को भरती करते हैं। परिणामतः भारत में घूस लेने की प्रथा प्रचलित है। अपनी नौकरी को सदैव स्थिर रखने के लिए श्रमजीवियों को नए लेकर कर्मकारियोजकों की हथेली सदैव गर्म रखनी पड़ती है।

(५) नए प्राप्ति की सुविधा—औद्योगिक श्रमिकों की अणुप्रस्तुता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उनको नए बड़ी सुविधा से मिल जाता है। नगर का महाजन—मारवाड़ी अथवा पठान उनको नए चमड़े में पसाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी मिस्त्री तथा कर्मकारियोजक भी नएदाता का कार्य करते हैं। यही नहीं, मदिरा विक्रेता तथा परचूनी वाले भी प्रायः श्रमिकों को उधार मास बेचकर उनकी अणुप्रस्तुता को बढ़ाते हैं। जिस किसी व्यक्ति के पास भी थोड़ा आधिक्य धन है (जैसे क्लर्क, प्रबन्धक आदि) वह अधिक व्याज के लालच से श्रमिकों को नए दे देता है। कभी-कभी वेश्याएँ एवं विधवाएँ भी अपने लाभ की दृष्टि से इन्हे नए प्रदान करती हैं।

(६) अत्यधिक व्याज की दर—यद्यपि श्रमजीवियों को नए मिलने में बड़ी सुविधा होती है, किन्तु नए की शर्त सरल नहीं होती। व्याज की दर बहुत अधिक

ऊँची होती है, क्योंकि बिचारे श्रमजीवी सम्पत्तिहीन होने के कारण किसी प्रकार की प्रतिभूति देने में असमर्थ होते हैं। उनकी प्रवासी प्रवृत्ति होने के कारण ऋणदाताओं को अधिक जोखिम उठानी पड़ती है, अतएव वे व्याज की दर और भी अधिक कर देते हैं। एक प्रोनोट पर अशिक्षित श्रमिक का निशानी अँगूठा ले लिया जाता है। इसमें कपट की आशंका अधिक रहती है। लिखित कार्यवाही न होने की दशा में भी ऋणदाता के डंडे के जोर के कारण बिचारे श्रमजीवी प्रति माह एक बहुत बड़ी राशि व्याज के रूप में देते हैं।

(७) अशिक्षा—हमारे अधिकांश श्रमजीवी पढ़े लिखे नहीं हैं अतः ऋणदाता उनके लोभ का दुरुपयोग करते हैं। काला अक्षर भेस बराबर होने के कारण वे स्वयं तो व्याज का हिसाब लगा नहीं पाते। ऋण की जो भी घटी बड़ी राशि ऋणदाता उन्हें बताते हैं उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी तो माह की पहली तारीख पर श्रमिक को जो कुछ भी मजदूरी मिलती है उसे वे ऋणदाता तुरन्त ले लेते हैं तथा बिचारा श्रमिक ऋण की ज्वाला में सुलगता रहता है।

(८) ऋणदाताओं की दूषित कार्य प्रणाली—प्रायः ऋणदाता व्याज से प्राप्त होने वाली नियमित आय पर ही निर्भर करते हैं और इसलिए मूलधन की चिन्ता नहीं करते। वे अनुत्पादक कार्यों के लिये भी सह्य ऋण दे सकते हैं। ऋण प्राप्ति की सरलता एवं महाजन की तत्परता के आकर्षण के कारण बहुधा श्रमजीवी आवश्यकता एवं अपनी प्रदेय समता से अधिक ऋण लेते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आता है कि ऋणदाता व्याज या मूलधन के भुगतान के समय प्राप्ति की रसीद नहीं देते तथा हिसाब-किताब की पुस्तकों में भी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ कर देते हैं।

(९) बीमारी—जन-संख्या के आधिक्य के कारण नगरों में माय दिन मलेरिया एवं महामारियों के प्रकोप के कारण भी श्रमजीवियों को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है।

इनके अतिरिक्त ऋण लेने के और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जो भिन्न-भिन्न श्रमिकों की परिस्थितियों एवं सामाजिक वानावरण के ऊपर निर्भर करते हैं।

ऋण के दुष्परिणाम—

(१) निम्न जीवन स्तर—श्रम जाच समिति के अनुसार श्रमिकों की निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर का प्रधान कारण उनकी भारी ऋणग्रस्तता है। श्रमजीवियों की अधिकांश आय भारी व्याज चुकाने में ही व्यय हो जाती है और वह अपने परिवार के उपभोग के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का भी प्रबन्ध नहीं कर पाता। फलतः अनुचित एवं अपर्याप्त आहार के कारण उसका व उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

(२) कार्य कुशलता में कमी—ऋणग्रस्तता के कारण चिन्ता की चिन्ता पर

बिचारे श्रमर्ज विद्या का बल भस्म हो जाता है और वे दक्षता से नार्थ करने में असमर्थ होते हैं ।

(३) श्रमिकों के स्वाभिमान को ठेस—आधे दिन ऋणदाता श्रमिक को मूलधन अथवा व्याज की अदायगी का स्मरण दिखाता रहता है । यदि राशि अधिक बढ़ जाती है और श्रमिक ऋणदाता की इच्छा के विरुद्ध काम करता है तो वे उसे न्यायालय की धमकी देते हैं । कभी-नभी व्याज न चुकाने के कारण प्रतिफल के रूप में ऋणी से ऋणदाता घर का काम भी लेता है । ये सब एसी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण स्वच्छन्द व स्वाभिमानी श्रमिक लाचार होकर ऋणदाता के दास बन जाते हैं । ऋणप्रस्तता क्योंकर दूर हो ?—

औद्योगिक श्रमजीवियों की ऋणप्रस्तता को दूर करने के लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं .—

(१) शिक्षा का प्रसार—शिक्षा के प्रसार में हमारा श्रमिक जागरूक हो जायेगा एवं उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण में अन्तर समझ जायेगा । वह फिर कभी भी विवेकहीन होकर ऋण न लेगा और यदि लेगा भी तो उसका इतना शोषण न हो सकेगा जितना आजकल होता है । देश के प्रचलित कानूनों का भी उस ज्ञान हो जायेगा, अतः ऋणदाताओं के जाल में न फँसेगा ।

(२) शराबखोरी पर प्रतिबन्ध—शराबखोरी को कम करने के लिये चाय तथा केसरिया दूध की दुकानों, सिनेमागृहों, क्लबों तथा अन्य प्रकार के मनोरंजन के साधनों का निर्माण होना चाहिए । कुछ सेवायोजकों ने इस दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं । मदिरापान को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा बम्बई, मद्रास तथा अन्य राज्यों में मद्य निषेध की नीति अपनाई गई है । वास्तव में मद्य-निषेध के अधिक प्रसार की आवश्यकता है ।

(३) भरती पद्धति में सुधार—श्रमिक की भरती एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि कर्मकारियाजका द्वारा धूम सेने की प्रथा का उन्मूलन हो सके । कर्मकारियों को की सदैव अपने पक्ष में रखने के लिए बेचारे श्रमिकों को ऋण लेकर उनकी हथेली गमं रखनी पड़ती है, अतएव जब दोषपूर्ण भरती की प्रणाली ही वैज्ञानिक आधार पर नियाजिन हो जायेगी तो श्रमिकों की ऋणप्रस्तता बहुत कुछ कम हो सकती है ।

(४) सहकारी साख समितियों की स्थापना—श्रम वस्तियों में सहकारी साख समितियों की स्थापना करनी चाहिये, जहाँ श्रम-जीवियों का सरलता से एवं कम व्याज की दर पर ऋण मिल सके । इसके लिए यह भी अनिवार्य आवश्यक है कि श्रमजीवियों में परस्पर सहकारिता की भावना भी हो । आजकल सहकारी साख समितियाँ श्रमिकों के मध्य अधिक लोकप्रिय नहीं हैं । इसका प्रधान कारण श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति है । संयुक्त पूँजी वाले बैंक श्रमजीवियों को थोड़ी राशि के ऋण

देने में विश्वास नहीं रखते, इसीलिये यह आवश्यक है कि सहकारिता का प्रचार एवं प्रसार करके सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय। मगरों के महाजब, पठान आदि ऋणदाता इस आन्दोलन की सफलता में बाधक सिद्ध होते हैं। अतएव उनके नियन्त्रण के हेतु सुन्दर सन्निधिम का निर्माण होना चाहिये। बम्बई एवं मद्रास राज्यों में सहकारी साख आन्दोलन बड़ा सफल हुआ है। वहाँ सहकारी साख का संगठन इटली के लूजेटी मॉडल (Luzatti Model) पर हुआ है, जिसका दायित्व विभिन्न सदस्यों द्वारा धारण किये हुये अंशों की सीमा तक होता है। वे प्रतिभूति पर भी ऋण देते हैं। नगरी जनता के लिये सहकारी साख का कार्य अन्य प्रान्तों में लगभग नगण्य हुआ है। सन् १९४६ की सहकारी नियोजन समिति ने निम्न सिफारिशों की थीं—

(१) यद्यपि साख समितियाँ ऋणग्रस्तता की समस्या का पूर्ण हल प्रदान नहीं करती, तथापि प्रत्येक मिल या कारखाने में उसके कारीगरों की आवश्यकतायें पूरी करने तथा मितव्ययिता की आदत डालने के लिए भी इनकी स्थापना अवश्य करनी चाहिए।

(११) इन समितियों को सेवायोजकों से सहायता मिले, जो कि निम्न रूप में दी जा सकती है:—

(अ) प्रबन्ध कार्य के लिए आवश्यक स्टाफ देकर।

(आ) उनके व्यय स्वयं भुगत कर।

(इ) बिना व्याज या कम व्याज पर ऋण देकर।

(ई) कर्मचारियों की मजदूरी एवं वेतन में से ऋण की रकमे वसूल करने की अनुमति प्रदान कर।

(उ) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को चाहिए कि वे अम-अफसरों के साथ अमिकों के कल्याण के लिए समितियाँ संगठित करने में सहयोग दें।

(ऊ) उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स स्थापित किए जायें।

भारत में औद्योगिक अम को भरती

अम की भरती के लिये प्रचलित पद्धतियाँ—

दुर्भाग्य से भारत में भरती की व्यवस्था बड़े उल्टे-सीधे ढंग में विकसित हुई है अतः अम-प्रशासन और अम प्रबन्ध के वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग नहीं हो पाया है आवश्यक अमिक प्राप्त करने के लिए प्रायः मध्यस्थों द्वारा भरती करनी पड़ती है। संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के उद्योगों में अधिकांशतः मध्यस्थों पर निर्भर रह जाता है। ये मध्यस्थ विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, यथा—जावर सरदार, चौधरी, मुकद्दम, मिस्त्री, फोरमैन या ठेकेदार। इन मध्यस्थों द्वारा अमिक की भरती अनेक दोषों से पूर्ण है। अमिकों को निकालना व रखना, प्रमोशन देना, छुट्टी दिलाना आदि इन्हीं मध्यस्थों के हाथ में होना है, अतः ये अमिकों पर अपने इस प्रभा

का दुरुपयोग करने में नहीं झुकते। उनसे धूस लेते हैं और अनैतिक कार्यवाहियों में विवश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से नांवगी दिलान में इन्हें 'भट मिलती है, अतः अपने लाभ बढ़ाने के लिए ये पुराने श्रमिका को निकालते व नए श्रमिकों को भरती करते रहते हैं। इससे उद्योग का भी सतुष्ट और अनुभवी श्रमिका का अभाव हो जाता है।

कुछ कारखानों में प्रत्यक्ष रूप से भी श्रमिकों की भरती की जाती है। यह पद्धति बम्बई मद्रास और पंजाब में अधिक देखी जाती है। सामान्य विधि इन प्रकार है—कारखाने के दरवाजे पर इस आशय की सूचना चिपकी दी जाती है कि इतने श्रमिकों की आवश्यकता है और अमुक तिथि को कारखाना मैनेजर या थ्रम-सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा इनाम दिया जाये। श्रमिकों के लिये आवश्यकता की घोषणा कभी-कभी विद्यमान श्रमिकों के समक्ष कर दी जाती है जिन्हें वे अपने मित्रों और सम्बन्धियों में इसका प्रचार कर दें। इस प्रकार अनेक प्रार्थी निर्दिष्ट तिथि को कारखाने के दरवाजे पर उपस्थित हो जाते हैं। यह विधि अकुशल समचारियों की भरती के लिये उपयुक्त हो सकती है। कुशल वर्तमान रखा की भरती के लिए तो प्रार्थना-पत्र निमन्त्रित किये जाते हैं और एक आवश्यक परीक्षा लेने के बाद चुनाव किया जाता है।

भारत के अनेक उद्योगों में श्रमिकों की भरती के लिये उनके घर श्रम की भरती की पद्धति भी प्रचलित है। अहमदाबाद में कुल श्रमिकों का लगभग १०% ठेकेदार के द्वारा काम पर लिया जाता है। इस प्रकार की भरती के समथन में कई कारण दिये जाते हैं, जैसे—कार्य के शीघ्र सम्पादन के लिए अल्प-सूचना पर बड़ी मात्रा में श्रमिकों की उपलब्ध होना, पर्याप्त सुपरवाइजरी स्टाफ का अभाव, रोजगार केन्द्रों का शिथिल संगठन आदि किन्तु कई विद्वानों की सम्मति में यह प्रथा ठीक नहीं है। इसके अन्तर्गत सेवायोजकों को श्रम अधिनियमों के अनेक प्रावधानों की अवहेलना करने का अवसर मिल जाता है।

कुछ औद्योगिक संस्थाओं में लेबर आफसरों के द्वारा भरती की पद्धति प्रचलित की है। कभी-कभी यह अफसर भरती के लिये गाँवा में जाते हैं और श्रमिकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं लेकिन उनको अधिक सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि अपरिचित होने के कारण वे मजदूरों में वह विश्वास प्रेरित नहीं कर पाते जो कि स्थानीय व्यक्ति कर सकते हैं। फल यह होता है कि लेबर आफसर वास्तव में एक स्त्रीन का कार्य करते हैं, जिसके पास सरकारी टाइट भरती पद्धति चलती है। कुछ मिल ट्रेड-यू नयनों द्वारा श्रमिक प्राप्त करते हैं। यूनियन के पास मिल में काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्धियों की सूची होती है, जो कि काम की तलाश में है। सूचना मिलते ही यूनियन वेकेन्सी के लिये नाम भेज देती है। अन्तिम निर्णय प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है।

उक्त सब भरती-पद्धतियाँ दोषपूर्ण हैं। भरती का सबसे अच्छा ढङ्ग रोजगार केन्द्रों की सहायता लेना है।

श्रम विनिमयो का महत्त्व—

श्रम-विनिमयो का दूसरा नाम रोजगार विनिमय केन्द्र अथवा रोजगार केन्द्र है। यह एक विशेष कार्यालय है, जिसकी स्थापना काम की तलाश करने वाले श्रमिकों को श्रमिकों की तलाश करने वाले सेवायोजकों से मिलाने के लिए की गई है। ये रोजगार केन्द्र श्रम की गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। आजकल इनकी स्थापना का समर्थन बढ़ता जा रहा है और अधिकांश सेवायोजक व उनके मध्य एवं मजदूरों के संगठन भी सभी औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार केन्द्रों की स्थापना चाहते हैं। इतना तो निःसन्देह कह सकते हैं कि वे यदि रोजगार नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम सेवायोजकों को सक्रिय भरती के स्वच व परिश्रम से अवश्य वचा सकेंगे।

रोजगार केन्द्रों को अब केवल सेवायोजकों की सुविधा का साधन भर नहीं माना जाता। उनके प्रमुख कर्तव्य आजकल निम्न प्रकार हैं :—

- (१) मानव शक्ति और कार्यों के सम्बन्ध में सूचना का वितरण करना।
- (२) काम दिलाना।
- (३) ट्रेनिंग की आवश्यकताओं को समझना व उपयुक्त योजनाएँ संचालित करना।
- (४) व्यवसायिक सूचना देना।
- (५) रोजगार सम्बन्धी साधारण सूचनाएँ सरकारी एजेंसियों, सेवायोजकों व सामान्य जनता को देना।
- (६) श्रमिका और सेवायोजकों व साथ घनिष्ट सहयोग करना।

यदि इन कार्यों को रोजगार केन्द्र उचित रूप से करे तो ये रोजगार में तेजी ला सकते हैं। विश्व के सभी प्रमुख औद्योगिक देशों में, जैसे—ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और जापान में ये श्रमिकों की भरती में महान सेवाएँ कर रहे हैं।

भारत में भी रोजगार केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इनका प्रारम्भिक उद्देश्य युद्ध-पेवा में निकाले हुए लोगों को काम दिलाना था, किन्तु अब इसका प्रयोग पूर्ण रोजगार की दशाएँ उपलब्ध करने में सहायता देना है। ये श्रमिकों को अपने लिए अधिक उपयुक्त काम तलाशने में और सेवायोजकों को सबसे उपयुक्त श्रमिक प्राप्त करने में सहायता देते हैं। उनमें यह भी आशा की जाती है कि विभिन्न राज्यों में उपलब्ध योग्यता का उचित वितरण करायेग और उत्पादन की सभी ज़ाखाओं का उपयुक्त व्यक्ति दिलावेगें। मजदूर व कार्यों में असन्तुलन का एक कारण प्रायः यह पाया गया है कि मजदूरों को उपलब्ध कार्यों के विषय में और सेवायोजकों का उपलब्ध श्रमिकों के विषय में जानकारी नहीं होती, अतः कभी तो बेरोजगारी फैली रहती है और कभी श्रमिकों का अभाव रहता है। ऐसी दशा में रोजगार केन्द्र सूचनाएँ प्रदान कर बड़ी सहायता कर सकता है और आवश्यक ट्रेनिंग देकर नये श्रमिक तैयार कर सकता है। रोजगार केन्द्र दूरस्थ भागों में, जहाँ रोजगार उपलब्ध हो, पान के लिए श्रमिकों को आवश्यक वन पेशगी दे सकता है।

प्रवर्द्धन सन् १९६० के अन्त में २७६ अम धिनियम के द्र थे । ४ धिविविधानय विनिमय के द्र इस सख्या में सम्मिलित नहीं है । इनके कायों का व्योरा निम्न तानिका से समझा जा सकता है —

अम धिनियम के द्रो के कायवाहन सम्ब धी आकड

वर्ष	विनिमय के द्र ता सख्या	रजिस्ट्र प्रार्थियो की सरया	काम दिलाये गये प्रार्थियो की सख्या	चाहू रजिस्ट्र पर प्रार्थियो की सरया	विनिमयो का प्रयोग करन वाले गवा योगको की औसत मार्सिक सख्या	सूचित रिक्त स्थानों की सख्या	विचाराधीन रिक्त स्थानों की सरया
१९५६	१५३	१६६६८६५	१८६८५५	७५८५०३	५ ४६	२६६६८६	४६८०५
१९५७	१८१	१७७४६६८	१६२८३१	६२२०६६	५ ६३२	२६७१८८	४५१५६
१९५८	२१२	२२०३८८८	२३३३२०	११८३२६६	६४८५	३६४८८४	६४६८०
१९५९	२४४	२४७१५६६	२७११३१	१४२०६०१	७४७०	४२४३६३	८४६०३
१९६० (अप्रैल)	२७६	२२५४६८०	२५१५१३	१५६४३४७	८६२१	४१४४८२	१२२४८५

औद्योगिक सस्थागो मे श्रमिको की अनुपस्थितता

अनुपस्थितता से आशय—

एक संगठित उद्योग की सफलता बहुत कुछ उसके श्रमिको की कुशलता और अनुभव पर निर्भर रहती है अतः इस दृष्टि से श्रमिक की अनुपस्थितता एक विचार-रणीय समस्या है। भारत सरकार ने श्रम-विभाग द्वारा एक रकुंलर कुछ वष पहले प्रांतीय सरकारो को भेजा गया था जिसमे अनुपस्थितता (Absenteeism) की परिभाषा इस प्रकार की गई थी जो श्रमिक कार्यकाल के किसी भाग के लिए काम पर आता है उसे 'उपस्थित' मानना चाहिए। यदि सेवायोजक के पास कार्य कराने के लिए श्रमिक को इस बात का पता है तथा विचाराधीन बिबस एक अवकाश का दिन भी नहीं है तो श्रमिक को चाहिए कि वह अपने को काम पर उपस्थित करे। यदि वह इस बिबस की छुट्टी लेता है या बिना सूचना दिए काम पर नहीं आता तो वह 'अनुपस्थित' मानी जायगी। हाँ, उसको ऐसी अनुपस्थिति इतनी लम्बी न होनी चाहिए कि उसकी नौकरी ही समाप्त हो जाय। घोषित अवकाश के दिनों पर श्रमिको को 'अनुपस्थित' नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार जो श्रमिक हड़ताल पर हो, वे भी अनुपस्थित नहीं कहे जायेंगे। भारत के विभिन्न उद्योगों में श्रमिको की उपस्थितता का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है—

वष	मूल (वर्ग)	ऊन		इन्जीनियरी		लोहा व स्पात	युद्ध सामग्री	सीमेंट	दियासलाई	चमड़ा
		रानपुर	वारीवाल	बम्बई	प० बंगाल					
१९५१	१२*७	८३	—	१३६	१०१	११०	८६	११८	१०५	७८
१९५२	१२७	८४	६३	१३४	१०३	१०६	८४	११६	१०६	८२
१९५३	१२६	११०	५०	१३७	१०८	१०६	८६	११६	१०१	८२
१९५४	१४*६	८५	३२	१६६	१५६	१६*६	१६६	१६०	१३६	६७
मई										

श्रमिको की अनुपस्थितता के परिणाम—

उपरोक्त आँकड़ो से स्पष्ट है कि हमारे देश के संगठित उद्योगों में अनुपस्थितता बहुत साधारण बात हो गई है। इस अनियमित उपस्थिति के दोष निम्न लिखित हैं—

(१) स्वयं श्रमिको को हानि उठानी पड़ती है क्योंकि अनियमित उपस्थिति के कारण उनकी आय कम हो जाती है जबकि सामान्य नियम यह है कि "कोई काम नहीं तो कोई पारितोषण भी नहीं।"

(२) सेवायोजकों की हानि तो और भी अधिक है क्योंकि अनुशासन और कुशलता दोनों ही पर आघात आती है। उधे या तो अतिरिक्त श्रमिक रखने पड़ते हैं या कारखाने व फाटक पर काम की तलाश में खान श्रमिकों से आकस्मिक भरती करती पड़ती है। यह आकस्मिक भरता दोषपूर्ण है क्योंकि प्रायः श्रमिक ढग क नहीं मिल पाते। इसी प्रकार अतिरिक्त श्रमिकों के रखन में भी दोष है। अतिरिक्त श्रमिकों को पूरा काम देने के लिए सेवायोजक बुद्ध श्रमिकों को अनिवार्य छुट्टी लेने के लिए विवश करते हैं। इस प्रवृत्ति का श्रमकगण विराध करते हैं क्योंकि उह इस बात का जर होना है कि इस प्रकार हड़ताल का परिस्थितियों में मुकाबला करने के लिए एक दूसरी रक्षा पक्ति (Second Line of Defence) तयार की जा रही है।

अनुपस्थितता के कारण—

हमारे औद्योगिक संस्थानों में अनुपस्थितता का कई कारण हैं जो कि इस प्रकार दिने जाते हैं—

श्रमिकों की अनुपस्थितता के प्रमुख कारण

- (१) बीमारी।
- (२) रात्रिपालिया।
- (३) गांव लौटने की इच्छा। ✓
- (४) नगरों की घर सम्बन्ध काठिनाइयाँ।
- (५) दुःखसन।
- (६) जादू का दुष्प्रवहार।
- (७) पञ्चम महाजन के चंगुल से बचने के लिए।

(१) बीमारी—जराब और अपर्याप्त भोजन दोषपूर्ण यह व्यवस्था बढ़ती काम करने की श्रम पोषण के वशाय गरीब श्रमिकों को अनेक महा माग्या जैसे मलेरिया हैजा चेचक आदि का सरलता से शिकार बना देती है। जब श्रमिक बीमार पड़ जाय ता फिर कारखाने में काम पर जाना उसके लिए कैसे सम्भव हो सकता है? कमी कभी परिवार के सदस्य भा साथ ही बीमार पड़ जाते हैं और ऐसी दशा में सेवायोजकों को सूचना दन लिए भी कोई व्यक्ति नहीं बचता।

(२) रात्रिपालिया—रात्रिपालियों में दिन की पालियों की अपक्षा अधिक अनुपस्थितता होती है क्योंकि रात्रि में काम करने में अधिक तबलीफ होना है। कुछ नवयुवक श्रमिक केवल घर रहने के लिए ही रात्रिपाली में अनुपस्थित रहते हैं। कुछ कारखानों में पाली परिवर्तन (Change over of Shifts) का व्यवस्था हो गई है। इससे उनमें रात्रिपालियों की अनुपस्थितता घट रही है।

(३) गांव लौटने की इच्छा—अत्यधिक अनुपस्थितता का सबसे प्रधान कारण श्रमिकों के हृदय में जल से जल अपने गांव को लौटन की इच्छा है। उह

नागरिक जीवन से कोई प्रेम तो होता नहीं, क्योंकि वे ग्रामीण-वातावरण में पले होते हैं और गाँव से अपनी आर्थिक कठिनाइयों द्वारा ढकेले हुए शहर को आते हैं, अतः जैसे ही आर्थिक कठिनाइयों से तनिक भी छुटकारा मिला कि वे गाँव लौटने की सोचते हैं। गाँव में उनका परिवार है, खेतीबारी है, बन्धु-बान्धव हैं, इन सबका आकर्षण उन्हें गाँव लौटने के लिए विवश करता है।

(४) नगरो की 'घर' सम्बन्धी कठिनाइयाँ—नगरो में सरलता से रहने के लिये घर नहीं मिलते और जो मिलते हैं वे बहुत तग, महंगे किराये के और अस्वास्थ्य-मय होते हैं, अतः वे प्रायः अपना परिवार गाँव में ही छोड़ देते हैं, अतः उनसे सम्पर्क रखने के लिये समय-समय पर छुट्टी लेकर गाँव जाना पड़ता है।

(५) दुर्व्यसन—जिस दिन वेनन श्रैष्टता है उस दिन श्रमिक शराब पी लेते हैं और मौज उड़ाते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने कर्त्तव्य का ध्यान नहीं रहना और कई दिनों तक कारखाने में अनुपस्थित रहते हैं। जो श्रमिक इन दुर्व्यसनो से बचे हुए हैं वे भी आवश्यक वस्तुयें खरीदने या अपने परिवार के सदस्यों से मिलने मिलाने गाँव चले जाते हैं।

(६) जाँवर का दुर्व्यवहार—जाँवर का दुर्व्यवहार भी श्रमिकों को कारखाने में अनुपस्थित रहने के लिए विवश कर देता है।

(७) पठान महाजन के खंगुल से बचने के लिए—प्रायः श्रमिक कर्जदार होते हैं। पठान महाजन उनसे तकाजा करने के लिये कारखाने पर आ धमकते हैं। उनकी निर्दयता में बचने के लिए भी किसी-किसी दिन श्रमिक छिपे रहते हैं।

अनुपस्थितता के उपचार—

बम्बई वस्त्र-श्रम जाँच समिति के अनुसार अनुपस्थितता को घटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

- ✓ (१) कारखाने में काम करने की दशायें सुधारी जायें।
- ✓ (२) श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाये।
- ✓ (३) बीमारी एवं दुर्घटना से बचाव की व्यवस्था की जावे।
- ✓ (४) आराम के लिये अवकाश लेने की सुविधा दी जाये।

यदि काम की दशायें कठोर और अस्वास्थ्यप्रद रहती तो स्वभावतः श्रमिक काम से बचने की कोशिश करेगा, अतः सर्वोत्तम उपाय तो यही होगा कि श्रमिक के कार्य एवं जीवन की दशायें सुधारी जायें, जिससे वे प्रसन्न रहे। उन्हें सबेरा या वेनन बिना अवकाश दिवस दिये जायें, जिससे वे अपने प्राइवेट कार्यों के लिए अवसर पा सकें। प्रौद्योगिक नगरो में सुविधाजनक घरों की व्यवस्था की जाये, जाँवर का व्यवहार सज्जनता का होना चाहिए, पठान-महाजन के विरुद्ध श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा दिलाया जाए। यदि श्रमिकों को शिक्षा दी जा सके तो इससे इन्हें अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान हो सकेगा और अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति घटेगी।

भारत में बाल और स्त्री-श्रम का उपयोग

विभिन्न उद्योगों में बाल व स्त्री श्रम—

उत्पादन की कारखाना प्रणाली में कई गम्भीर दोष हैं। उत्पादक कम लागत पर शीघ्र लाभ अर्जन करके बहुत अमीर बन जाना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे एक बड़ी सख्या में बालक और स्त्रियों को काम पर रख लेते हैं और इन्हें कम मजदूरी देते हैं तथा अत्यधिक काम कराते हैं। संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के उद्योगों में अनेक बाल और महिला श्रमिक काम करते हैं। ऐसे उद्योग विशेषतः निम्नलिखित हैं,—

(१) बागवानी—उद्यान उद्योग सम्पूर्ण परिवार के लिए काम प्रदान करता है। आसाम के चाय बागानों में ही सन् १९४६—४७ में औसत दैनिक रोजगार के घण्टे इस प्रकार थे—पुरुष—१,६४,६८६, स्त्रियाँ—१,२४,३६३ और बालक—५४,६०६। इससे हमें यह पता लगता है कि विभिन्न व्यवसायों में कितनी बड़ी सख्या में स्त्री और बालक श्रमिक काम पर रखे गये। चाय उद्यानों में स्त्री और बाल-श्रमिकों के लिए नियमित रोजगार उपलब्ध है, जो कि एक खान या कारखाने में सम्भव नहीं है।

(२) बीड़ी-निर्माण उद्योग—बीड़ी-निर्माण एक अन्य उद्योग है, जिसमें बच्चे और स्त्रियाँ बड़ी सख्या में काम करते हैं। यह उद्योग बंगाल, बिहार व मध्य-प्रदेश में केन्द्रित है। काम भीसमी होना है। और काफी देर तक सँकड़ों बालक काम पर लगे देखे जा सकते हैं। मजदूरी के अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक को कुछ बीड़ियाँ दे दी जाती हैं, जिससे स्त्रियाँ और विशेषतः बालकों को बीड़ी पीने की आदत पड़ जाती है। स्त्रियाँ प्रायः अपने घरों में काम करती हैं। यदि कुछ बीड़ियाँ अस्वीकृत कर दी जाती हैं तो उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका भुगतान नहीं मिलता। दान-पुष्प के बहाने भी कुछ कटौती कर ली जाती है।

(३) अन्नक उद्योग—अन्नक उद्योग में काम करने वाले स्त्री और बाल श्रमिकों की सख्या बहुत अधिक है। अधिकांश कारखाने भारतीय कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि वे बहुत छोटे हैं और शक्ति का प्रयोग नहीं करते अथवा छोटी छोटी दुकानों में चलाय जाते हैं। सन् १९३० में बिहार के अन्नक के १२७ कारखानों में केवल १ कारखाना रजिस्टर्ड था और इनमें काम करने वाले पुरुष, स्त्री और बच्चों का अनुपात क्रमशः ५७, १७ व २७% था। यह अनुमान किया जाता है कि स्त्री और बाल श्रमिकों की वास्तविक सख्या सरकारी अंकों से कहीं अधिक होगी। इन स्त्री और बाल श्रमिकों को उपरोक्त कारण से सरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। इन कारखानों में जो दोष देखे जाते हैं उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—भुगतान मुद्रा में नहीं किया जाता, देर में आने, खराब काम, कम तोल आदि के लिये मनमानी कटौती कर लेना।

(४) कोयला खान—कोयला खानों में भी स्त्री श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। खान में काम करने वाले श्रमिकों की रक्षार्थ बनाए गए सन्धियम धीरे-धीरे प्रगति कर पाये हैं। प्रथम खान अधिनियम सन् १९०१ ने केवल खनिकों की सुरक्षा और निरीक्षण के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति का ही आयोजन किया था। खनिकों की संख्या में वृद्धि होने पर तथा वाशिंगटन-श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सन् १९३३ में दूसरा खान अधिनियम बनाया गया, जिसने खान के ऊपर ६० और खान के अन्दर ४४ घण्टे का सप्ताह निर्धारित किया। एक साप्ताहिक अवकाश की भी व्यवस्था की गई और १३ वर्ष से कम आयु के बालकों में खान में नीचे काम कराने का निषेध कर दिया गया। सन् १९२९ के बाद इस उद्योग में स्त्री श्रमिकों की संख्या घटने लगी और सन् १९३७—४३ से स्त्रियों को खान के अन्दर काम करने से रोक दिया गया है।

(५) धान कमाना—यह उद्योग (Rice milling) मद्रास, बंगाल और बिहार में अधिक पाया जाता है। सन् १९४६ में लगभग ६०० मिल थे, जिनमें लगभग ४०,००० व्यक्तियों को काम मिला हुआ था। इन मिलों में जो स्त्री श्रमिक काम कर रही हैं उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है और कार्य करने की दशाएँ बड़ी असन्तोषजनक हैं। खुले मैदान में सूरज की तेज धूप में चावल सुखाना, फँलाना और पलटना पड़ता है। इस कार्य में बराबर चलते रहना पड़ता है।

(६) शिलाक उद्योग—इन कारखानों (Shellac Factories) में स्त्री-श्रमिकों की संख्या बाल श्रमिकों से बहुत अधिक है। यह अनुमान किया जाता है कि ये संख्याएँ क्रमशः ३० व १०% हैं। यह उद्योग अधिकांशतः कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जाता है। स्टोर के कमरे में दिन का कार्य, विशेषतः गरम मौसम में विशेष कठिन होता है। धोने के स्थान, नालियाँ, टकियाँ अच्छी तरह साफ नहीं की जाती हैं, जिससे उनमें से बड़ी दुर्गन्ध निकलती रहती है। शिलाक बनाने के स्थान में और इसके चारों तरफ खराब निकला हुआ पानी इकट्ठा होकर सड़ता रहता है, क्योंकि वहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं होती। इसकी अपेक्षा सुधार की व्यवस्था अधिक चाहने वाला कदाचित् ही कोई अन्य सगठित उद्योग होगा।

और बाल श्रमिकों की विशेष समस्याएँ—

सामान्यतः स्त्री और बाल श्रमिकों को काम देने वाले उद्योग, केवल उद्यान-उद्योग को छोड़ कर, भारतीय कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते बड़े-बड़े उद्योगों में भी, जो कि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, जब दशाएँ बड़ी खराब हैं तो इन अनियंत्रित उद्योगों में अवस्था कितनी भयंकर होगी, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। स्त्री और बाल श्रमिकों को काम देने वाले कारखानों में सामान्य समस्याएँ तो हैं ही, किन्तु निम्नलिखित विशिष्ट समस्याएँ भी हैं:—

(I) बाल श्रमिकों की समस्याएँ—

(१) उनके काम करने की दशाये बड़ी असन्तोषजनक है । उन्हें गन्दे वायु-मण्डल में ग्रन्थकारपूर्ण और भीड़-भाड़ के स्थानों में काम करना पड़ता है ।

(२) बाल श्रमिकों की मजदूरी भी बहुत कम है, जो कि वयस्क श्रमिकों की मजदूरी की १० से २०% तक होनी है ।

(३) भारतीय कारखाना अधिनियम ने बाल श्रमिकों के लिये कार्य के घंटे, मध्याह्न, अवकाश आदि के सम्बन्ध में नियम बनाये हैं, लेकिन कारखाना निरीक्षण स्टाफ की शिथिलता से इनका लाभ नहीं उठाया जा सका है ।

(४) बाल-श्रमिकों के स्वास्थ्य पर अत्यधिक कार्य का बुरा प्रभाव पड़ता है ।

(५) यद्यपि कुछ उद्योगों में सामान्यतः एक निर्दिष्ट आयु से कम के बालकों का काम पर रखने का निषेध है, फिर भी झूठे प्रमाण-पत्र बनवाकर अनियमितता बरती जा रही है । इस अनियमितता में माता पिता भी भाग लेते हैं ।

(II) स्त्री श्रमिकों की समस्याएँ—

(१) स्त्री श्रमिका को दी जाने वाली मजदूरी पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा कम है, भले ही उनका कार्य पुरुषों जैसा हो । औद्योगिक ट्रिब्युनल के अनुसार यह भेद-भाव बड़ा अनुचित है । कोई कारण नहीं है कि एक ही काम के लिए पुरुष और स्त्री श्रमिकों को भिन्न-भिन्न मजदूरी दी जाय ।

(२) कारखाना अधिनियम ने अन्तर्गत स्त्री-श्रमिका के लिए (और बाल श्रमिकों का भी) रात्रि-कार्य का निषेध है । वे बवल सुबह ६ से संध्या के ७ बने तक कार्य कर सकती हैं । इससे अनिश्चित कार्य के घंटा मध्याह्न आदि के सम्बन्ध में उन्हें कोई विशेष सुविधा प्राप्त नहीं है जबकि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि स्त्री और पुरुष की सहनशीलता समान नहीं होती ।

(३) कारखाना अधिनियम ने स्त्री श्रमिकों के लिए प्रसूति लाभ और शिशु सदन की व्यवस्था की है । अनेक कारखानों में स्त्री श्रमिक प्रसूत लाभ से, समय रहते काम में अलग कर दिये जाने के कारण, वंचित रहती हैं और स्त्री-श्रमिकों की संध्या ५० से कम दिखलकर शिशु गृह की व्यवस्था करण का दायित्व भी बर्त्ता लिया जाता है । जहाँ शिशु-गृह हैं भी वहाँ उनको ठीक हालत में नहीं रखा जाता । उनमें प्रशिक्षित नर्सों का अत्यन्त अभाव है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाती ।

(४) हमारे देश में स्त्रियों को पुरुषों से निम्न समझा जाता है । परिणामतः स्त्रियों में अभी वह सामाजिक घेतना, आत्म विद्वान और आत्म सम्मान की भावना नहीं हो पाई है जो कि परिवर्ती स्त्री-जगत् में देली जाननी है । स्त्री श्रमिकों को बाँव में हेय दृष्टि से देला जाता है । औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली अधिकांश स्त्रियों का नैतिक पतन हो गया है, जिसमें जाबर की बड़ी जिम्मेदारी है । कभी-कभी सवा योजकों की भी साजिश होनी है । गांव के सामाजिक और धार्मिक वजन सहारा में

अनुपस्थित है। कुछ विधवा या एकाकी स्त्रियाँ दिन में कारखाने में काम करके अपनी आय अर्जन करती हैं और रात में अनैतिक जीवन व्यतीत करती हैं। यह सामाजिक-आर्थिक समस्या उत्पन्न होनी जा रही है, किन्तु इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

बुधवार के उपाय—

(१) पुरुषों की आय में वृद्धि—ऐसे प्रयास किए जायें कि परिवार के पुरुष सदस्य की आय इतनी पर्याप्त बढ़ जाये कि उसे अपनी स्त्री और बच्चों में कारखानों में जाकर काम करने के लिए कहने की विवशता न होना पड़े।

(२) अधिनियम द्वारा संरक्षण—केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तुरन्त ही ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए, जिससे स्त्री और बाल श्रमिकों को संरक्षण मिले। न केवल कारखानों में जाकर उनके लिए काम करने का निषेध हो अपितु उन्हें अपने ही घरों पर करने के लिए सम्मानपूर्ण कार्य प्रदान करना चाहिए। बालकों के लिए शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए।

(३) निरीक्षण में कड़ाई—निरीक्षण स्टाफ पर कर्तव्यपरायण इन्स्पेक्टरों की संख्या बढ़ाई जाय, जो कार्य करने के स्थानों पर कभी निगरानी रहें। जब कभी कोई दोष पाया जाय तो कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे शिथिलता दूर हो।

(४) शिशु सदनों व शिक्षालयों की व्यवस्था—राज्य को चाहिए कि बाल-श्रमिक रखे जाना कनई बन्द कर दे। कुछ सेवा-योजकों का कहना है कि बालकों को काम पर रखने से पारिवारिक आय बढ़ जाती है तथा बालक भी शिक्षा-सुविधाओं के अभाव में सुस्त तथा आचारा फिरने नहीं पावेंगे, लेकिन ये सब खोखले तर्क हैं। आज के बालक कल के सेना हैं। इन्हीं पर देश के शासन का भार पड़ने वाला है, अतः सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि मजदूरों की भावी पीढ़ियों का वचन कारखानों के गन्दे वातावरण में बर्बाद न हो। उनके लिए शिशुसदन और शिक्षालयों की व्यवस्था भी कदा आवश्यक है।

(५) स्त्री श्रमिकों को विशेष सुविधाएँ—अब भारतीय संविधान स्त्री और पुरुषों को बराबरी का दर्जा प्रदान करता है, अतः राज्य को चाहिए कि स्त्री और पुरुषों को बराबर के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार मिलें—जैसे दोनों को जीविकोपार्जन के बराबर अवसर मिलें, समान कार्य के लिए समान मजदूरी हो। माताओं के स्वास्थ्य पर भावी पीढ़ियों का स्वास्थ्य निर्भर होता है, अतः श्रमिकों को विशेष सुविधाएँ देनी चाहिए।

(६) प्रचार—शैक्षणिक क्षेत्रों में यह प्रचार करना चाहिए कि स्त्रियाँ समाज में सर्वाधिक सम्मान की अधिकारिणी हैं और उनकी शारीरिक व नैतिक उन्नति पर राष्ट्र का भाग्य निर्भर है।

भारतीय उद्योगों में कार्य करने की दशायें

कार्य सम्बन्धी दशायें श्रमिकों की कुशलता पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। यदि कार्य सम्बन्धी दशायें सन्तोषजनक हो तो श्रमिक के शरीर और दिमाग पर सुन्दर एवं स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ जायगी। इसके विपरीत यदि कार्य की दशायें असन्तोषजनक हुईं तो श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जावेगी, अतः यह आवश्यक है कि कार्य सम्बन्धी दशाओं पर उचित ध्यान दिया जाए। भारतीय उद्योगों में कार्य सम्बन्धी दशाओं का अध्ययन निम्न शीर्षक के अन्तर्गत करेंगे :—

(१) हवा आने-जाने की व्यवस्था,

(२) तापक्रम, और

(३) प्रकाश।

हवा आने-जाने की व्यवस्था प्राकृतिक हो सकती है, जबकि वह खिड़कियों और वायु-भरोखों की सहायता से हो। वह कृत्रिम भी हो सकती है, जबकि पखों द्वारा हवा बाहर निकाली जाती हो या यांत्रिक उपकरणों द्वारा अन्दर पहुँचाई जाती हो। भारतीय उद्योगों में कृत्रिम व्यवस्था पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। कार्य करने के कमरों में उचित तापक्रम रखना आवश्यक है। भारत के कुछ ही सेवायोजकों ने अभी इस बात पर ध्यान दिया है। बम्बई व अहमदाबाद की अनेक कपास मिलों में वायु-प्रतिकूलित यन्त्रों की स्थापना हो गई है, किन्तु बम्बई इस दिशा में अहमदाबाद से पीछे रह गया है। अथ औद्योगिक क्षेत्रों में दशायें बड़ी खराब हैं। कार्य करने के स्थानों में पर्याप्त एवं उपयुक्त रोशनी होनी चाहिए, जिससे श्रमिकों की आँखों पर जोर न पड़े और उत्पादन बढ़ जाये। दुर्भाग्य से इस अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति भी सन्तोषजनक नहीं है।

बड़ी इकाइयों में कार्य की दशायें सामान्यतः सन्तोषजनक हैं। छोटी और अनियन्त्रित इकाइयों में, विशेषतः वे जो कि पुरानी इमारतों में चल रही हैं, प्रकाश और हवा के बारे में बड़ी असन्तोषजनक व्यवस्था पाई जाती है। दुर्भाग्य से अधिकांश सेवायोजक उदासीन रहते हैं और केवल कानून के अक्षर पालन से, न कि उसकी भावना की पूर्ति से, असन्तुष्ट हो जाते हैं। परिणाम यह है कि कानून द्वारा निर्दिष्ट सीमा के अन्दर भी मशीनों में सुरक्षा आदि के नियमों की अवहेलना की जाती है। हाँ, कुछ ऐसे उदार हृदय सेवायोजक भी हैं जिन्होंने न केवल मशीनों के गतिशील भागों से श्रमिक की सुरक्षा की व्यवस्था की है, अपितु श्रमिकों में 'सुरक्षा प्रथम' समितियाँ संगठित की हैं, ताकि श्रमिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों से परिचित हो जायें। यदि एक विशेष श्रमिक समूह में कोई दुर्घटना न हो तो बोनस भी दिए जाते हैं।

कुछ उद्योगों के उदाहरण—

(१) बस्त्र मिलों में सामान्यतः कारखानों की इमारतें भली प्रकार प्रकाशित हैं और उनमें वायु आने-जाने की अच्छी व्यवस्था है। मशीनों को इस प्रकार जमाया गया है कि श्रमिक स्वतन्त्रतापूर्वक आस-पास घूम सकते हैं।

(२) इजीनियरिंग कारखानों में हवा और प्रकाश की व्यवस्था अधिकांश दशाओं में बड़ी सन्तोषजनक है। कुछ दशाओं में फाउन्ड्री, वर्कशॉप जैसे भाग बड़े अन्धकारपूर्ण और भीड़भाड़ के हैं।

(३) पॉटरीज में, विशेषतः कलकत्ता और ग्वालियर में प्रकाश और हवा की व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुधार आवश्यक है।

(४) प्रिंटिंग प्रेसों में सामान्यतः दशाएँ बड़ी खराब हैं। प्रायः ही श्रमिक अस्तबलो, टीन के शेडों और अपर्याप्त वायु भरोखे वाले अंधेरे कमरों में काम करते देखे जाते हैं।

(५) काँच के कारखानों में घाव लगना, जल जाना आदि घटनाएँ बहुत होती हैं। इस उद्योग की कार्य सम्बन्धी दशाएँ इतनी असन्तोषजनक हैं कि बहुत से काँच का काम करने वाले श्रमिक व्यावसायिक बीमारियों के शिकार हो गये हैं।

(६) शक्कर उद्योग का जहाँ तक सम्बन्ध है, मद्रास और बम्बई के कारखानों में काम की दशाएँ उत्तर-प्रदेश और बिहार के कारखानों में उपलब्ध दशाओं से अधिक अच्छी हैं। उत्तर-प्रदेश और बिहार के शक्करखानों में जो दुर्गन्ध उड़ती है वह अहमदनगर के कारखानों में नहीं मिलेगी। हाँ, सफाई की दशाएँ बेवपूर्ण हैं।

(७) धान के मिल, विशेषतः जो कि मद्रास राज्य में हैं, अधिकांश छोटे और प्राचीन हैं तथा अनुपयुक्त इमारतों में स्थित हैं। कुछ तो इतने अन्धकारपूर्ण हैं कि दिन के समय भी वाम गैस की लालटेनों के प्रकाश में करना पड़ता है। सफाई सम्बन्धी नियमों का केवल इतना ही पालन किया जाता है, जिससे अधिनिषेध के अन्धकार का पालन हो जाय।

(८) अन्न के कारखानों में कम से कम बड़ी संस्थाओं में कार्य सम्बन्धी दशाएँ सन्तोषजनक हैं, लेकिन छोटी इकाइयों में वे असन्तोषजनक हैं। ऐसी इकाइयों में श्रमिकों को अन्धकारपूर्ण और वायु के अने-जाने की अपर्याप्त व्यवस्था वाले कमरों में काम करना पड़ता है। शिलॉक कारखाना में शक्ति प्रयोग करने वाले कुछ कारखानों को छोड़कर किसी भी श्रम सन्धियम का आदर नहीं किया जाता।

(९) मद्रास की सिप्रेट फ़ैक्ट्री गली-कुचो, अस्वास्थ्यप्रद और अर्द्ध प्रकाशित गोशामों में अवस्थित है। वहाँ बड़ी भीड़-भाड़ है, पीने का पानी, पेशाबघर व सण्डास की कोई व्यवस्था नहीं है। गलीचो के कारखानों में भी सफाई सम्बन्धी आयोजन सन्तोषजनक नहीं है।

(१०) चमड़ा कमाने के कारखानों में कार्य की दशाएँ बड़ी भयंकर हैं, चाहे वे नियन्त्रित इकाइयों में हों या अनियन्त्रित इकाइयों में। सफाई और नालियों का तो अभाव है ही, टुकड़े इधर-उधर बिखेर दिए जाते हैं और चारों तरफ दुर्गन्ध उड़ती रहती है। भूमिगत नालियों की व्यवस्था बहुत कम पाई जाती है। कारखाने का काम कच्ची इमारतों में चलता है।

(११) मध्य-प्रदेश की मैदानीय खानों में कठिनाता से कुछ आश्रम मजदूरों के आराम करने के हेतु होंगे। सदास और पेशाबघर अधिकांश खानों में नहीं है। कहीं-कहीं तो नीचे काम करने के स्थानों में पर्याप्त मौसम-सुविधाएँ भी नहीं दी जाती। अश्रम की खानों में दशायें अधिक बुरी हैं। बड़ी फर्मों के स्वामित्व में जो खानें हैं उनके ऊपरी भागों में तो अच्छी वायु-व्यवस्था है, परन्तु जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे-वैसे दशायें खराब होती जाती हैं।

(१२) उद्यानों में आसाम और बंगाल के चाय उद्यान बड़े मनोरंजक पीछित क्षेत्रों में स्थित हैं और प्रायः चाय उद्यानों में खाद्य सामग्री का राशन प्रपूर्यप्त होता है, जिससे श्रमिक प्रसन्न रहते हैं। स्त्री और बच्चों को मित्रों द्वारा प्रसन्न करने के अन्तर्गत काम पर रखा जाता है। इन्हें सम्बन्धित तक काम करना पड़ता है। मित्रों द्वारा बच्चों को शारीरिक दण्ड दिये जाने के भी अनेक उदाहरण हैं। अनेक चाय बागानों पर बड़े खराब विस्म की शिष्टशालाएँ हैं। कहने के उद्यानों में तो ऐसी भी नहीं हैं। खेतों में काम करते समय पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांश भारतीय उद्योगों में कार्य की दशायें बड़ी खराब हैं और उनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss the social and economic effects of the migration of Indian Factory Workers. Would you advocate continuance of the factory worker's connection with his village?
2. Briefly point out the principal characteristics of Indian industrial labour.
3. It has often been remarked that Indian labour is cheap and inefficient. Trace some of the causes of low efficiency and suggest ways and means to stimulate production and to improve efficiency.
4. "The tyranny of debt degrades the employee and impairs his efficiency." Discuss the above statement with special reference to the causes of indebtedness among the industrial workers in India and the means suggested to remove the evil.
5. "Modern industry demands scientific methods of recruitment." Comment with reference to the methods employed in our industries and indicate the part played by labour exchange in the matter.
6. Analyse the causes of, and suggest the cure for absenteeism in our industrial establishments.
7. What are the chief industries in India in which women and children are employed? What special problems have arisen on account of this employment? Suggest suitable remedies.
8. Discuss the housing problem of industrial workers in India with special reference to the industrial towns of the country. What are the consequences of bad housing?

औद्योगिक संघर्ष एवं उनका निबटारा

(Industrial Disputes & Their Settlement)

औद्योगिक संघर्ष के कारण

औद्योगिक संघर्षों के सम्बन्ध में जो आँकड़े प्रकाशित होते रहते हैं, उनसे इनके कारण स्पष्ट प्रगट हो जाते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन कारणों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—(I) आर्थिक कारण, (II) प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी कारण, और (III) राजनैतिक कारण।

(I) आर्थिक कारण—

औद्योगिक संघर्ष के आर्थिक कारणों के अन्तर्गत निम्न वा समावेश किया जा सकता है :—

(१) मजदूरी, बोनस, मंहगाई आदि—औद्योगिक संघर्षों का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि लगभग ५७ प्रतिशत आँकड़े मजदूरी एवं बोनस के प्रश्न को लेकर हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक अशान्ति का मूल कारण यही था कि वस्तुओं का मूल्य-स्तर गगन-चुम्बी होता जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बिचारे श्रमिकों ने अधिक मजदूरी तथा मंहगाई भत्ते की माँग की। सेवायोजक इस माँग को पूरी करने में असमर्थ थे। उन्होंने कुछ सीमा तक मजदूरी में वृद्धि की तथा काम की दशाओं में भी सुधार किये गये, परन्तु सन् १९२६-३० की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी ने व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की कमर तोड़ दी, अब वे श्रमिकों की माँग को पूर्ण करने में पूर्णतः असमर्थ हो गये। श्रमिकों की छुट्टी की गई तथा मजदूरी भी घटा दी गई। फलतः हड़तालों की एक बाढ़-सी आई, जिससे औद्योगिक अशान्ति के बाढ़ल छा गये। यही दशा सन् १९३६-४५ के द्वितीय महासमर के बाद हुई। सन् १९४० तथा सन् १९४८ के बीच जितनी भी हड़ताले हुई, उनका मूल कारण मजदूरी तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि कराना था। सन् १९४० में ३० प्रतिशत तथा सन् १९५१ से ३० प्रतिशत औद्योगिक संघर्ष प्रायः मजदूरी और बोनस के प्रश्न को लेकर ही हुए। वर्तमान स्वतन्त्रता की अवधि में भी अनेक उद्योगों तथा राजकीय विभागों में संघर्ष हुए, जिनके पीछे अधिक मजदूरी अथवा मंहगाई भत्ते का ही प्रश्न था। ६ अगस्त सन् १९५७ से होने वाली डाक व तार घर के कर्मचारियों की हड़ताल का मूल कारण भी अधिक वेतन पाना था।

भारत में औद्योगिक संघर्षों के मुख्य

१० कारण

१. मजदूरी, बोनस, महगाई आदि ।
२. काम करने की दशायें ।
३. भरती पद्धति ।
४. श्रमिक संघ आन्दोलन ।
५. श्रम व पूँजी का पारस्परिक सम्बन्ध ।
६. श्रमिकों की शिक्षा ।
७. छुट्टी व नौकरी की अन्य शर्तें ।
८. शान्तिपूर्ण समझौते की व्यवस्था का अभाव ।
९. विवेकीकरण की योजना ।
१०. राजनैतिक या अनाधिकार ।

बुरी-गृह-व्यवस्था, दोषपूर्ण यन्त्र, काम करने के अधिक घण्टे, आदि बातों को लेकर भी हुए हैं, परन्तु इनका प्रतिफल कम ही रहा है ।

(३) भरती पद्धति—भारत में श्रमिकों की भरती प्रायः कर्मकारियोंजको (Jobbers) द्वारा होती है । कर्मकारियोंजका का अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है । जब किसी कारण उन्हें अलग कर दिया जाता है तो कभी-कभी सहानुभूतिवश, परन्तु अधिकतर भय से, (अर्थात् श्रमजीवी) उस समय तक काम करना बन्द कर देते हैं, जब तक कि वह ठेकेदार या कर्मकारियोंजक काम पर वापिस न ले लिया जाय ।

(४) श्रमिक संघ के आन्दोलन ये भी गत वर्षों में भगडों के लिए उत्तरदायी हैं । यह संघ आन्दोलन सेवायोजकों के लिए अभी नया-सा है वे इसे अपने अधिकारों के लिए चुनौती समझते हैं ।

(II) प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी कारण—

(५) श्रम एवं पूँजी का पारस्परिक सम्बन्ध—ये महत्वानुसार दूसरी श्रेणी के कारण हैं । मजदूरों को भाँति-भाँति से परेशान करना, श्रमिक संघों से सम्बन्धित मजदूरों को निकाल देना, श्रमिक संघों को मान्यता न देना, काम दिलाने वाले ठेकेदार की बेईमानी और भ्रष्टाचार, कुछ ऐसे ही इस वर्ग के कारण हैं, जिन्होंने प्रति पाँच में एक भगडे को जन्म दिया ।

(६) श्रमिकों की शिक्षा—अधिकतर श्रमजीवी अल्प तथा अनभिज्ञ हैं और वे श्रम भी बाहरी पथ-प्रदर्शन पर निर्भर रहते हैं । उनकी इस दशा का कुछ स्वार्थी लोगो ने लाभ उठाकर उनमें पारस्परिक वैमनस्य व कटुता के बीज बो दिए हैं ।

भारत में रहन-सहन का स्तर बहुत कुछ मजदूरी पर निर्भर करता है, परन्तु दुर्भाग्य से इसको निश्चित करने का कोई विशेष आधार नहीं है । पक्षों के पारस्परिक सौदा ठहराने की शक्ति ही एवमान मजदूरी ठहराने की कसौटी है । उचित आधार के अभाव में भगडों की उत्पत्ति को बड़ा प्रवर्धन मिला । आजकल तो हड़तालों का एक अकेला महत्वपूर्ण कारण श्रमिक, अर्थात् कम मजदूरी एवं बढ़ती हुई रहन सहन की कीमत में अन्तर होना है ।

(२) काम करने की दशायें—हमारे

देश में अनेक संघर्ष अस्वस्थ वातावरण,

(७) छुट्टी, अवकाश दिवस व नौकरी की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में नियमों का अभाव, बिना पूर्ण सूचना के काम से हटा देना, काम करने की दशाओं में उनकी सम्मति के बिना परिवर्तन कर देना, जुर्माना करना या उनकी मजदूरियों में से गैर-कानूनी कटौतियाँ कर देना आदि कार्यवाहियाँ मजदूरों को भडका देती हैं और वे काम रोक देते हैं तथा हड़ताल उस समय तक जारी रहती है जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो जाती ।

(८) ऐसी व्यवस्था का अभी तक अभाव था जिससे सेवायोजकों और मजदूरों में परस्पर शान्तिपूर्ण वार्ता हो सके । कभी-कभी तो छोटी सी बात पर तूल दे दिया जाता है, जो कि सरलता से ठीक की जा सकती थी । उदाहरण के लिए, २ मार्च सन् १९५० को हावडा की 'फोर्ट ग्लोस्टर जूट मिल्स' के ८,००० श्रमजीवियों ने होली के त्यौहार पर एक दिन की छुट्टी न मिलने पर हड़ताल कर दी थी और इसके परिणाम इतने गम्भीर हुए कि पुलिस को विवश होकर गोली चलानी पड़ी और मिल मालिकों को तालाबन्दी करनी पड़ी, जो बाद में ५४ दिन पश्चात् समाप्त हुई । इसके फलस्वरूप तीन लाख कार्य-दिनों (Man-days) की हानि हुई । बहुधा मजदूर नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, किन्तु हड़ताल कर देते हैं, बाद में भाँगों की सूची तैयार होती है । यदि मजदूरों का शक्तिशाली सघ हो तो ऐसी अनुत्तरदायित्वपूर्ण घटनाएँ बन्द हो सकती हैं । पहले तो मजदूर अपनी कठिनाइयों को समझ-बूझ लें, फिर सेवा-योजकों को मार्गें भेजें और जब वे उनको धस्वीवार कर दें तब ही कोई अन्य कदम उठावें ।

(९) विवेकीकरण की योजना—विवेकीकरण की किसी भी योजना का तत्काशीन परिणाम श्रमिकों की छटनी होता है; अतः श्रमजीवी इसका विरोध करते हैं । उदाहरण के लिए, बम्बई के निपोत्ताओं द्वारा विवेकीकरण की योजना लागू करने के विरुद्ध वहाँ के वल्ल उद्योग के कर्मचारियों ने सामान्य हड़ताल घोषित कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर चार्ल्स फॉसेट की अध्यक्षता में एक समिति (फॉसेट समिति) नियुक्त करनी पड़ी थी । इसी प्रकार टाटाशहर के लौह एवं स्पात के कारखाने में भी विवेकीकरण के विरोध में पाँच महीने तक हड़ताल रही, जिससे २५ लाख कार्य-दिनों (Man-Days) की हानि हुई । अप्रैल, मई सन् १९५५ में कानपुर की सूती वस्त्र मिलों में विवेकीकरण की योजना लागू करने पर ४६,००० श्रमजीवियों ने अनिश्चित हड़ताल की थी, जो ८० दिन तक चलती रही । इससे राष्ट्रीय उत्पादन को बड़ी क्षति पहुँची ।

(III) राजनैतिक कारण—

राजनैतिक कारणों के अन्तर्गत उन कारणों का समावेश किया जाता है जो कि देश की स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित थे ।

(१०) राजनैतिक अथवा अनाधिक कारण—जैम किसी राजनैतिक नेता का आगमन किसी दलगत की धरगैठ मनाना आदि अवसरों पर एक दो दिन के लिए काम रोक घटनाय न जानी है परंतु वह छोड़े नहीं चला है। जब कुछ अद्वितीय सेवायोजक एष्य दमगो पर जर्मन आदि कर द ता अवश्य स्थिति विगड जाती है। ब्रिटिश नामन काल में तब जब हमारे राष्ट्र के नया पकड कर कात्तार में डाल दिए गए सहानुमति स्वरूप हमारे धर्म जीवियों न हडताल की। अमनयोग आंदोलन के काल में ऐसी अनेक हडताल हुई थी।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक सघर्ष के विविध कारणों में प्रायः आर्थिक कारणों का हो सदैव श्रेष्ठवाला रहा। औद्योगिक सघर्ष के कारणों के सम्बन्ध में धर्म के गहरी समीक्षण का भा यहा मन है कि अधिकांश भगनों के मूल में एक न एक आर्थिक तत्व ही छिपा रहना है।

भारत में औद्योगिक सघर्षों का इतिहास

प्रारम्भिक—

ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि सम्पूर्ण श्रमिक दल की सबसे प्रथम सामूहिक हडताल कब हुई। या काम रोक घटनाय तो असंगठित रूप में प्रारम्भ से होती रही है और प्रायः इसलिए हुई कि सेवायोजक न श्रमिकों को ठीक काम न करने पर रथ घण्ट दिया अथवा उन्होंने उनका काम का घटाना का प्रयत्न किया परंतु वह कुछ घण्टे ही चल पायी और सदा गान्ति से निवृत्त जाती थी। धारे धारे श्रमिकों में जागृति उत्पन्न हुई और वे सामूहिक कार्यवाही के महत्त्व को समझने लग। सामूहिक रूप से श्रमिकों की पहली हडताल सन् १८७७ में मायपुर के एम्प्रेस मिल में हुई। तत्पश्चात् तो बहूतरी घटनाय हुई जो श्रमिकों के किसी एक दल में ही सीमित नहीं रही। मेहतर से कर स्थल अध्यापकों तक न हडताल का डाँडा उठा दिया। कारखाने स्कूल तक बीमा कम्पनी देव नगरपालिका पुलिस फौज आदि कोई विभाग अछूता न रहा।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व औद्योगिक सघर्ष—

१९वीं शताब्दी तक श्रमजोबो बड़ा असंगठित तथा पूँजीपति संगठित व शक्तिमान थे अतः ऐसी परिस्थितियों में विचारे श्रमिक चुपचाप पूँजीपतियों द्वारा किये गये अत्याचारों को सहन कर लिया करते थे किंतु प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में इस वातावरण की बदल बिया और श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिये लड़ना सीख लिया। संगठित होकर सन् १९१८ में उन्होंने एक भाषण हडताल की। इसका बाद सन् १९२० के प्रथम छ माह में लगभग २०० हडताल हुईं जिनमें ११ लाख श्रमिकों ने भाग लिया। सन् १९२१ में ग्रामाम के चाय बगानों में सन् १९२२ में इस्ट इंडिया रेलवे में सन् १९२३ में अहमदाबाद में तथा सन् १९२४ में बम्बई की बल्ल मिला में मयदूर हडताल हुई। इसके बाद कुछ दिना स्थिति सन्तोषजनक रही परन्तु विश्व

व्यापी आर्थिक मन्दी के झोके से विवश होकर सन् १९२८ में पुनः हड़तालों की बाढ़ आई। इस समय तक श्रमिक सघों पर साम्यवादियों का पूरा अधिकार हो चुका था। परिणामस्वरूप सन् १९२८ में बम्बई में एक भीषण हड़ताल हुई और फिर सन् १९२९ में सहानुभूति प्रदर्शक एक लम्बी हड़ताल की गई, जो कि छ महीने तक जारी रही। परिस्थितियों को सुधारने के लिए सन् १९२९ में श्रमिक सघ अधिनियम (Trade-Disputes Act) पास किया गया। इसके बाद सन् १९३७ तक पूर्व समय की अपेक्षा कुछ औद्योगिक शान्ति रही। सन् १९३७ में हड़तालों का तृप पुनः बढ़ा लग्न हो गया। इसका प्रधान कारण यह था कि यद्यपि भारत के विभिन्न राज्यों में कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हो गयी थी, किन्तु फिर भी श्रमिकों की स्थिति में कोई आशाजनक सुधार नहीं हुआ। इस वातावरण से लाभ उठा कर साम्यवादियों ने श्रमिकों को और भी भड़का दिया, फलतः इन दोनों वर्गों (सन् १९३७ व १९३८) में क्रमशः ३७९ व ३९९ हड़ताल हुई।

द्वितीय महायुद्ध काल में औद्योगिक सघर्ष—

सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और पूँजीपतियों ने मनमाने लाभ कमाय, इसके विपरीत ऊँचे मूल्य-स्तर के कारण श्रमिकों की दशा और भी मिर गई। परिणामस्वरूप सन् १९४० में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ३२२ हड़ताल हुई, जिनकी संख्या सन् १९४२ में बढ़कर ६९४ हो गई। इन हड़तालों के विभिन्न कारणों में महंगाई का प्रश्न मुख्य था।

स्वतन्त्र भारत में औद्योगिक सघर्ष—

सन् १९४७ में औद्योगिक भगड़ा अधिनियम पास हुआ, जिसने श्रम एवं पूँजी के सघर्ष को शान्तिपूर्ण साधनों से सुलभान के बड़ सुन्दर नियम बनाय, किन्तु देश के विभाजन, जन-संख्या का पारवर्तन तथा बिगड़ती हुई राजनीतिक स्थिति के कारण श्रमिका की दशा में कोई सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ। साम्यवादियों ने इस अवसर का पुनः लाभ उठाया और श्रमिकों की भावनाओं का भड़काने में अग्नि में घी डालने का काम किया। फलतः चारा और हड़ताल का ताना बँध गया। उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बम्बई तथा मद्रास की वस्त्र मिला में प्रत्येक भीषण हड़ताल हुई। बंगाल में ३ जूट मिलों ने भी तालाबन्दी कर दी। सन् १९४८ में कलकत्ते में १० दिन तक ट्राम-गाड़ियों ने पूरी हड़ताल रखी। फानपुर में भी भीषण हड़ताल हुई। अगस्त सन् १९५० में बम्बई की वस्त्र मिला में एक बहुत अव्यवस्थित हड़ताल हुई, जिसमें लगभग दो लाख मजदूरों ने भाग लिया और इस लगभग ६ करोड़ कार्य दिना की क्षति हुई। सन् १९५१ में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी, किन्तु सौभाग्य से समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण व रेल मन्त्री के सुप्रयत्नों से यह टल गई। इसी वर्ष बैंक कर्मचारियों ने मुमूरी कोट के निष्पक्ष के विरुद्ध एक देशव्यापी हड़ताल की। सन् १९५२ व ५३ में स्थिति सन्तोषजनक रही। हाँ सन् १९५३ में कलकत्ते की ट्राम हड़ताल में

बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया, जिससे विवश होकर सरकार को गोली चलानी पड़ी। २३ सितम्बर सन् १९५४ को भारत के बैंक कर्मचारियों ने भारत सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन करने के प्रति रोष प्रकट करने के लिये एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। इसी प्रकार बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों ने भी सितम्बर सन् १९५४ में सरकार को यह नोटिस दिया था कि उनके लिये अखिल भारतीय औद्योगिक-ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाय, नहीं तो वे हड़ताल कर देंगे। फिर भी सन् १९५४ में औद्योगिक शान्ति का वातावरण रहा। अप्रैल-मई सन् १९५५ में १६ वर्ष की औद्योगिक शान्ति के उपरान्त कानपुर में वस्त्र-उद्योग के ४६,००० श्रमिकों ने सूती मिल मजदूर सभा के नेतृत्व में विवेकीकरण की योजनाओं का विरोध करते हुए एक भीषण हड़ताल की, जिससे उद्योग को बड़ी हानि हुई।

औद्योगिक संघर्षों की वर्तमान स्थिति—

निम्नलिखित आँकड़ों से गत वर्षों में हुए औद्योगिक झगड़ों की संख्या तथा इनसे हुई क्षति का आभास मिलता है :—

वर्ष	झगड़ों की संख्या	भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या	नष्ट होने वाले कार्य-दिनों की संख्या
१९४७	१,८११	१८,५०,७८५	१,६५,६२,९६६
१९४८	१,२५६	१०,५६,१२०	७८,३७,१७३
१९४९	६२०	६,८५,४५७	६६,००,५६५
१९५०	८१४	७,१६,८८३	१,२८,०६,७०४
१९५१	१,०७१	६,६६,३२१	३८,१८,६२४
१९५२	६६३	८,०६,२४२	३३,३६,६६१
१९५३	७७२	४,६६,६०७	३३,८२,६०८
१९५४	८४०	४,७७,१३८	३३,७२,६३०
१९५५	१,१६४	५,२२,७६७	५६,६७,८४८
१९५६	१,२०३	७,१५,१३०	६६,६२,०४०
१९५७	१,६३०	८,८६,३७१	६४,२६,३१६
१९५८	१५,२४	६,२६,०००	७७,६८,०००
१९५९	१,५३१	६,६४,०००	५६,३३,०००
१९६०	८२२	५,०८,०००	३५,०४,०००
(मक्दूर तक)			

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान युग में श्रमिक अत्यन्त जागरूक हो गया है, अतः श्रम और पूँजी के बीच सुन्दर सम्बन्ध रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इन दोनों पक्षों के ही साथ न्याय का बर्ताव किया जाय और देश में स्थायी औद्योगिक शान्ति की स्थापना की जाय। यह सचमुच बड़े ही सन्तोष की बात है कि सन् १९५६ से स्थिति में क्रमशः सुधार होता जा रहा है। राजकीय प्रयत्नों का इस स्थिति पर बड़ा स्वस्थ प्रभाव पड़ा है।

राज्य एवं औद्योगिक शान्ति

प्रारम्भिक प्रयास—

औद्योगिक झगड़े रोकने व उनको तय कराने के लिए सर्व प्रथम कानूनी व्यवस्था सन् १९२६ में व्यापारिक सघर्ष अधिनियम (Trade Disputes Act) द्वारा हुई। इस अधिनियम के अनुसार जब झगड़ा करने वाला कोई पक्षकार सरकार को झगड़ा सुलझाने के लिए प्रार्थना पत्र देता था, तो एक जीव अदालत तथा सम-भौता समिति की नियुक्ति कर दी जाती थी। किन्तु इसके निर्णय को मानना किसी भी पक्ष के लिए अनिवार्य न था, अतः इससे कोई विशेष लाभ न हुआ। इसी कारण सन् १९३८ में बम्बई में एक अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार हड़ताल तथा तालाबन्दी घोषित करने से पूर्व झगड़े की जाँच की जानी अनिवार्य थी। कुछ राज्यों में श्रम और पूँजी के सम्बन्धों की अच्छा बनाने के लिए समभौता अधिकारी नियुक्त किये गये। युद्ध काल में आवश्यक सेवाओं वाले उद्योगों में झगड़ों को अनिवार्य रूप से सुलझाने का प्रबन्ध किया गया।

औद्योगिक सघर्ष अधिनियम—

युद्धोपरान्त काल में औद्योगिक सघर्षों की समस्या बहुत बढ गई। ऐसी दशा में भारत सरकार ने सन् १९४७ में औद्योगिक सघर्ष अधिनियम बनाया, जिसमें सन् १९४६, १९५०, १९५१, व १९५२ में क्रमशः संशोधन किये गये। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) प्रत्येक उद्योग, जिसमें १०० या अधिक व्यक्ति काम करते हैं, में एक कार्य समिति (Works Committee) बनाना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें श्रमिकों तथा अधिकारियों के प्रतिनिधि होंगे। यह समिति दोनों पक्षकारों के मध्य सद्भावना और अच्छे सम्बन्ध रखने के लिये है।

(२) अनेक समभौता अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे, जो झगड़ों की जाँच करके उनको निपटाने का प्रयत्न करेंगे।

(३) झगड़ा प्रारम्भ होने पर सरकार एक समभौता बोर्ड नियुक्त कर सकती है, जिसमें कि एक स्वतन्त्र अध्यक्ष तथा प्रत्येक पक्ष के एव या दो प्रतिनिधि होंगे।

(४) सरकार झगड़े की जाँच कराने के लिये ए- जाँच अदालत भी नियुक्त कर सकती है, जिसमें स्वतन्त्र व्यक्ति होंगे।

(५) अनिवार्य रूप से भगडे का निबटारा कराने के लिए सरकार एक औद्योगिक न्यायालय भी स्थापित कर सकती है, जिसमें एक या दो हाईकोर्ट या जिला अदालत के जज होंगे।

(६) यदि समझौता बोर्ड अथवा समझौता अफसर द्वारा कोई भगडा तय हो जाता है, तो वह दोनों पक्षों पर लागू होगा। जांच अदालत की रिपोर्ट मानना किसी पक्ष के लिये अनिवार्य नहीं है, किन्तु इस रिपोर्ट को सरकार जनता की सूचनायें प्रकाशित करेगी। हाँ, औद्योगिक न्यायालय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(७) निम्न हड़ताले व सालाबन्दी अबैध घोषित कर दी गई हैं :— (अ) शोक हित सैवागो वाले उद्योगों में यदि ६ सप्ताह का नाटिस न दिया गया हो। (आ) उस समय जबकि कोई भगडा समझौता बोर्ड अथवा औद्योगिक न्यायालय के सामने पेश हो। (इ) यदि सरकार ने किसी भगडे को बोर्ड, अदालत अथवा न्यायालय को सौंप रखा हो और सरकार ने उस समय के लिये हड़ताल को अबैध घोषित कर दिया हो जब तक मामले की जांच चले।

(८) वे लोग जो अबैध हड़तालों में सम्मिलित होंगे अथवा ऐसी हड़तालों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, उनको दण्ड दिया जायगा। किसी भी श्रमिक को उस समय तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि मामला समझौता बोर्ड के पास है।

श्रमिक अपील न्यायालय—

सन् १९५० में एक नये अधिनियम द्वारा एक श्रमिक अपील न्यायालय नियुक्त करने का प्रवन्ध किया गया। इस न्यायालय के सामने औद्योगिक न्यायालयों, जांच अदालतों तथा मजदूरी बोर्ड के फंसलों की अपील होगी। इस न्यायालय का फैसला अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों के लिये मान्य होगा।

सन् १९५१ में सरकार ने एक श्रम सम्बन्ध-विधेयक पास किया, जिसने इस बात पर जोर डाला गया कि भगडे को सुलझाने के लिये आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार की मशीनरी होनी चाहिए। इसके अनुसार सरकार कई प्रकार के अफसर व न्यायालय स्थापित कर सकती है। इस विधेयक के अनुसार रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारी नियुक्त किए जायेंगे, जिनके पास मिल मालिक अपनी आज्ञाओं की प्रतिलिपियाँ भेजेंगे। श्रमिकों की बाते सुनने के बाद उन आज्ञाओं में परिवर्तन किया जा सकता है।

भगडों के निपटारे की व्यवस्था—

जब कोई भगडा हो अथवा होने की सम्भावना हो, तो कोई भी पक्ष दूसरे को भगडा निबटाने के लिए एक नोटिस दे सकता है। साधारण उद्योगों में यह भगडा ७ दिन में तथा लोकहित उद्योगों में १४ दिन में निबट जाना चाहिये। अन्यथा सरकार इसे बोर्ड को अथवा न्यायालय को सौंप सकती है। यदि फिर भी कोई समझौता न हो, तो इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जायगी। अपील करने के लिए सबसे ऊँचा न्यायालय 'अपीलेट ट्रिब्यूनल' है, किन्तु सरकार इस न्यायालय के निर्णय को भी बदल

सकती है। नियम विरुद्ध हड़ताल करने या तालाबन्दी करने के लिए भगडना एक अपराध बना दिया गया है। जो मजदूर नियम विरुद्ध हड़तालों में भाग लेंगे उनको हड़ताल के समय अपनी मजदूरी, छुट्टी, बोनस आदि नहीं मिलेंगे। नियम विरुद्ध मिल बन्द करने वाले मालिकों को सामान्य मजदूरी के दुगुने तक देने के लिए कहा जा सकता है। यदि कोई श्रम सभ समझौते की शर्तों को न मानेगा, तो उसको मान्यता रोकी जा सकती है। स्थायी श्रमिकों को काम पर ले हटाने के पूर्व उसको अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जायगा। फालतू मजदूरों को हटाने के लिए भी एक माह के नोटिस की आवश्यकता है। जब कोई मामला विवाग्योन हो तो श्रमजीवी हड़ताल न कर सकेंगे। 'धीरे-धीरे काम करने' की नीति, सहानुभूति की हड़ताल तथा लोक-हित व्यवसायो में हड़ताल नियम के विरुद्ध घोषित कर दी गई है। यदि हड़ताल नियम के विरुद्ध न हो, तो श्रमिकों को औसत मजदूरी का ३ मिलेगा। आपसी समझौता करने को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकृत मोदा करने वाले एजेंट (Certified bargaining agents) की व्यवस्था की गई है। आपसी समझौता न होने पर मध्यस्थ निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा। उचित कारणों से छूटनी करने पर मजदूरों को प्रति एक वर्ष नौकरी के पीछे आधे माह की मजदूरी उपहार के रूप में मिलेगी, जिसमें भत्ता भी सम्मिलित होगा।

औद्योगिक संघर्ष (संशोधन) अधिनियम सन् १९५६

सन् १९४७ के औद्योगिक संघर्ष अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी, परन्तु विभिन्न न्यायानयों द्वारा विभिन्न निष्पत्तियों के कारण बड़ी कठिनाइयों व असुविधाओं का अनुभव होने लगा। अतः सन् १९५० में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस व अन्य श्रम सभों ने इसका विरोध किया। सेवायोजक भी इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि सन् १९५० के (संशोधन) अधिनियम के अनुसार वे श्रमिकों से बदला लेने का कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। अतः श्रमिकों व सेवायोजकों के लगातार विरोध के कारण लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिया गया। सन् १९५६ के औद्योगिक संघर्ष (संशोधन) अधिनियम के अनुसार तीन नए प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई।

सन् १९५६ के संशोधित अधिनियम की विशेषताएँ—

इस अधिनियम की दो प्रधान विशेषताएँ हैं—

(I) अब श्रमिक लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील न कर सकेंगे; परन्तु अगर कोई निर्णय अतिकार के परे तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध दिया गया है, तो ऐसी दशा में श्रमिक सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

(II) अब तीन प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गये हैं :—

(१) श्रम न्यायालय (Labour Courts)

(२) औद्योगिक ट्रिब्यूनल (Industrial Tribunals)

(३) राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल (National Tribunals)

(१) श्रम न्यायालय—सन १९४६ के संशोधित औद्योगिक संघर्ष अधिनियम के अन्तर्गत सरनार औद्योगिक भगडों को तय करने के लिए एक या इससे अधिक श्रम-न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इस न्यायालय में कम से कम एक जज होगा, जो भारत के किसी न्यायालय में कम से कम ७ साल तक जज के पद पर कार्य कर चुका हो अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित श्रम न्यायालय में ५ वर्ष तक सम्पादित रह चुका हो। इन श्रम न्यायालयों में नीचे दिए हुए भगड (जिनका संकेत अधिनियम की तालिका २ में है) तय किए जायें —

(i) स्थायी आदेशों का प्रयोग तथा उनका स्पष्टीकरण,

(ii) किसी श्रमजीवी का निकालना तथा माली से निकाले हुए श्रमिक को फिर रखना उसकी क्षतिपूर्ति तय करना

(iii) स्थायी आदेशों के आधार पर सेवायोजकों के किसी आदेश की वैधानिकता प्रमाणित करना।

(iv) किसी प्रचलित रियायत या सुविधा को वापिस लेना।

(v) हड़तालों व तालेबन्दियों की वैधानिकता या अवैधानिकता को प्रमाणित करना।

(vi) तीसरी तालिका में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय।

यदि किसी संघर्ष का सम्बन्ध में श्रमिकों की संख्या १०० से कम है, तो तीसरी तालिका में सम्बन्धित निम्नलिखित विषय भी श्रम न्यायालय द्वारा तय होंगे,—

(i) वतन जिसमें समय तथा पदवि सम्मिलित है।

(ii) क्षतिपूर्ति तथा अन्य भुगतान।

(iii) काम के घन्टे तथा बकाश का समय।

(iv) सवेतन छुट्टी व छुट्टियाँ।

(v) पारितोषण, लाभ का विभाजन व प्रावदेन्ट फण्ड।

(vi) स्थायी आदेश के अतिरिक्त पाली (Shift) में काम कराना।

(vii) श्रेणी अनुसार वर्गीकरण।

(viii) अनुशासन सम्बन्धी नियम।

(ix) विवादोंकरण।

(x) श्रमिकों की छठनी तथा फूम को समाप्ति।

(xi) अन्य सम्बन्धित विषय।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि श्रम-न्यायालय में किसी भी संघर्ष को

भेजने का अधिकार सरकार को है। प्रत्येक राज्य सरकार के अपने पुष्क अम-न्यायालय होंगे।

(२) औद्योगिक ट्रिब्यूनल—इस ट्रिब्यूनल की स्थापना सन् १९४७ के औद्योगिक सघर्ष अधिनियम के अनुसार की गई है। यदि उक्त लिखित तालिकाओं में दिए हुए सघर्षों में १०० से अधिक श्रमजीवी सम्मिलित हैं, तो वह मामला औद्योगिक ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा। इस ट्रिब्यूनल का सम्भाषति केवल वही व्यक्ति हो सकेगा जो किसी उच्च न्यायालय का जज रहा हो अथवा कम से कम २ वर्ष तक लेबर प्रपीलेट ट्रिब्यूनल अथवा अन्य ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष रहा हो। आजकल हमारे देश में ऐसे दो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं—प्रथम घनबाद में और दूसरा नागपुर में। इनके अतिरिक्त दिल्ली में भी एक 'एड हॉक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल' है।

(३) राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल—यह ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय महत्व के झगड़ों को सुलझाएगा। 'एड हॉक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल' लखनऊ में काम कर रहा है। तालिका २ व ३ में वर्णित विषय भी इस ट्रिब्यूनल में भेजे जा सकते हैं, यदि वे राष्ट्रीय महत्व के हैं। इसका सम्भाषति केवल वही व्यक्ति हो सकता है, जो औद्योगिक ट्रिब्यूनल का सम्भाषति होने की योग्यता रखता हो।

वर्तमान राजकीय प्रयत्नों का संक्षिप्त व्यौरा—

वर्तमान काल में औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए हुए प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(१) औद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी आदेश—सन् १९४६ के 'औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम' के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम (Model Rules) बनाये, जिनमें १०० अथवा उससे अधिक मजदूर काम करने थे। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल तथा बम्बई के उन सभी औद्योगिक संस्थानों के लिए लागू कर दिया गया है जिनमें से प्रत्येक में ५० अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अधिनियम उत्तरी भारत के करीबाना मालिक सघ, उत्तर-प्रदेश तेल मिल-म लिंक सघ, बिजली कंपनियों तथा सभी कॉच के उद्योगों के लिए लागू कर

औद्योगिक शान्ति की स्थापना के वर्तमान राजकीय प्रयत्न

१. औद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी आदेश।
२. मजदूर सघों के लिये आचार महिता।
३. कार्य समितियों का निर्माण।
४. त्रिदलीय तंत्र।
५. समझौता तंत्र।
६. उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों का योग।
७. मजदूरों की शिक्षा।

मिल-म लिंक सघ, बिजली कंपनियों तथा सभी कॉच के उद्योगों के लिए लागू कर

दिया है। आसाम में यह नियम ऐस सब उद्योगा जिनमें १० या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, लागू होता है, परन्तु आसाम के इन उद्योगों में खान, क्वार्टीज (Quarties), तेल-मुये तथा रेलवेज सम्मिलित नहीं हैं।

(२) मजदूर-सङ्घों के लिए आचार संहिता—विविध औद्योगिक संस्थानों में आजकल संघर्ष के बढ़ते हुए समाचार जो पढ़ने को मिलते हैं, उसका एक कारण मजदूर संगठनों की प्रतिद्वन्द्विता भी है। मजदूर-संगठनों की प्रतिद्वन्द्विता हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में जितने मजदूर-संगठन हैं वे अपनी अपनी पृथक् विचारधारा रखते हैं। कोई कार्यसो विचारधारा का पक्षपाती है तो कोई साम्यवादी प्रभाव में है। इसी तरह और भी विचारधारा हो सकती है। एक खराबी यह भी है कि मजदूर एक श्रमिकों के विद्युद्द हित की ही दृष्टि की अपेक्षा राजनीति का भी विविध संगठनों में समावेश है। वास्तव में हाथ में आजकल सत्ता है, इसलिए कौन सी विचारधारा के संगठन को समय और मर्यादा से काम लेना ही पड़ता है, जबकि विरोधी पक्ष की विचारधारा वाले संगठनों का लक्ष्य ऐसी स्थितियाँ पैदा करना हो सकता है जिससे सरकार को अग्रिय हस्तक्षेप करना पड़े और उन्ह सत्ताधीन दल को बदनाम करके लोगों को अपने पक्ष के अनुकूल करने का असर मिले। फिर यह भी ध्यान रखने की बात है कि सभी मजदूर ऊँचे नीचे साचन वाले नहीं होते अतः जो सुनहल स्वप्न प्रस्तुत करके उन्हें भडका सके, उसी को अपना हितैषी मान कर वे उसके अनुवर्ती हो जाते हैं। विविध मजदूर संघ मजदूरों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए यही तरीके अपनाते हैं और जो इस काम में जितना बड़ा चढ़ा होता है वह उतनी ही सफलता पाता है चाहे मजदूरों या श्रमिकों को अन्ततोगत्वा लाभ हो या नहीं।

यह स्थिति निरसन्देह अच्छी नहीं है। प्रारम्भिक बात तो यही है कि मजदूर संगठन राजनीति की अपेक्षा मजदूरों के ही हित की दृष्टि से संचालित हो जिसके लिए मजदूरों की मांगों की ही प्रोत्साहित करने की अपेक्षा मजदूरों को सदाचारी और मितव्ययी तथा विवेकशील बनाने की ज़िम्मेदारी भी उन्हें सम्भली और सम्हालनी चाहिए, पर साथ ही, यह भी बहुत जरूरी है कि मजदूर संगठनों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता समाप्त की जाय। हम हर्ष है कि कम से कम दूसरी बात की ओर हमारे मजदूर नेताओं का ध्यान गया है और नीतिशास्त्र में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के बाद केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में चारों बड़े मजदूर संगठनों ने विविध मजदूर संघों के बीच सद्भाव बनाए रखने को एक आचार संहिता स्वीकार की है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इटक) भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) हिन्दू मजदूर महा और युनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटक) आज हमारे देश के चार बड़े मजदूर संगठन हैं। केन्द्रीय श्रममंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा की अध्यक्षता में उन्होंने आपसी सद्भाव के लिए आचार संहिता बनाई है और यह तय किया है कि एक तटस्थ व्यक्ति की अध्यक्षता में इन चारों के प्रतिनिधियों का एक संगठन बनाया जायगा, जो उस

आचार संहिता को कार्य रूप देगा। इसके फलस्वरूप न केवल विविध मजदूर संगठनों में अच्छे सम्बन्धों की, बल्कि इससे औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरी जगह सचपों में तीव्रता कम होने की सम्भावना है।

आचार-संहिता का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह सप्तमूर्ती है। उसके निर्माणात्मक उद्देश्य हैं कि (१) किसी भी औद्योगिक संस्था या दूसरी जगह हर एक कर्मचारी अपनी पसन्द के मजदूर सच में शामिल हो सकेगा, (२) दो सचों का एक साथ कोई सदस्य नहीं होगा, (३) मजदूर सचों के जनतन्त्रीय रूप में काम करने में रुकावट नहीं डाली जायेगी, (४) मजदूरों के अज्ञान और संगठन में पिछड़ेपन का कोई संगठन फायदा नहीं उठायेगा, (५) कोई संगठन ऐसा भाग नहीं करेगा जो औचित्य से मेल न खाने हो और अत्यधिक भासूम पड़े, (६) जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा प्रांतीयता को कोई संगठन प्रोत्साहन नहीं देगा, और (७) विविध मजदूर संगठन आपसी व्यवहार में हिंसा दबाव, धमकियों या वैयक्तिक दोषारोपों का सहारा नहीं लेंगे। इनमें कुछ विषय अभी और साफ होने हैं तथा व्यवहार से ऐसी नई बातें भी सामने आयेगी, जिनका और समावेश किया जा सकता है। यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि विविध संगठनों का अपने सम्बन्धों को अच्छा बनाने का इरादा। श्रम सम्मेलन ने उद्योगों में मजदूर, संगठनों को मान्यता देने के सिद्धान्त भी निश्चित किये हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त करने के लिए होने वाली बशमकश कम होने की सम्भावना है। यदि ऐसा हो तो एक बड़ी सिरदर्दी कम हो सकती है और नैनीताल के निर्णयों के फलस्वरूप ऐसा हो तो उसे एक बड़ी सफलता मानना चाहिए। हम आशा करेंगे कि आचार संहिता तथा हमारे नियम केवल कागज पर लिखे नहीं रहेगे, बल्कि उन पर सचाई और सद्भावना के माध्यम से प्रमत्त किया जायेगा।

हर्ष का विषय है कि आचार संहिता के निर्माण में औद्योगिक शक्ति की स्थापना के ऐच्छिक प्रयत्नों को बहुत बड़ा मिला है। केन्द्र एवं राज्यों में कार्यान्वित करने वाली कमेटियों (implementation committees) ने अनेक जटिल एवं दीर्घकालीन भगड़े सुलभय हैं। जब से आचार संहिता को स्वीकार किया गया है तब से नष्ट होने वाले कार्य दिवसों की संख्या सन् १९५८ में ६३६ लाख व सन् १९५९ में ४६.५ लाख से घटकर सन् १९६० में ३६.५ लाख रह गई है।

(३) कार्य समितियों का निर्माण—सन् १९४७ के औद्योगिक संघर्ष अधिनियम के अन्तर्गत अक्टूबर सन् १९६० तक केन्द्रीय संस्थाओं में ८०९ कार्य समितियाँ (Works Committees) स्थापित की गईं, जबकि सन् १९५९ में केवल ७४५ थी।

(४) त्रिदलीय तन्त्र—केन्द्रीय तन्त्र में गठित भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति, औद्योगिक समितियाँ तथा कुछ अन्य समितियाँ आती हैं। सन् १९५८ में इन संस्थाओं के वार्षिक अधिवेशन में उद्योग सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर (जैसे मजदूरों

नीति, उद्योगों में अनुशासन, शिक्कीकरण, श्रमिकों की शिक्षा तथा श्रमिकों द्वारा उद्योगों के प्रदूषण में भाग लेना) विचार विमर्श किया गया। बागानों की औद्योगिक समिति (Industrial Committee on Plantations) की ८वीं वार्षिक बैठक शिलोंग में १ जनवरी सन् १९५८ को हुई। लौह तथा स्पाट एंव रासायनिक उद्योगों के लिए भी नई औद्योगिक समितियाँ स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इसी प्रकार धातु-खाना व कोयला खाना के लिए भी ऐसी समितियाँ बनाने का विचार है व बुद्ध बनाई भी गई है।

सन् १९६० में भारतीय श्रम सम्मेलन ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा हड़ताल किए जाने पर विचार विमर्श किया। तीन लगातार बैठकों में स्ट्रिडिंग लबर कमेटी ने तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम नीति प्रस्ताव पर विचार किया। सन् १९६० में कोयला खनिज, बागान व सीमेन्ट से सम्बन्धित औद्योगिक कमेटियाँ की जा बैठकें हुईं उनमें बागान उद्योगों के लिये मजदूरी बोर्ड स्थापित करना, अधिनियम में संशोधन करना व कुछ चुने हुए सीमेन्ट उद्योगों में कार्य भार की समस्याओं पर विचार किया गया।

(५) समझौता सन्त्र—केन्द्र के क्षेत्र में आने वाली औद्योगिक संस्थाओं में औद्योगिक मन्त्रालय के प्रशासन के काम का उत्तरदायित्व मुख्य श्रम आयुक्त पर है। इसकी महत्त्वता के लिए एक मण्डल स्थापित किया जा चुका है, जिनमें प्रादेशिक श्रम आयुक्त, समझौता अधिकारी तथा श्रम निरीक्षक होते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारों के भी अपने अपने समझौता सन्त्र हैं, जिनके प्रधान अधिकारी श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) होते हैं।

(६) उद्योगों के प्रदूषण में मजदूरों का योग—भारतीय श्रम सम्मेलन में जुलाई सन् १९५७ में उस अध्ययन-मण्डल की सिफारिशों पर विचार किया गया, जिसने कुछ पश्चिमी देशों से इस योजना को कार्यान्वित करने की अवस्थाओं का प्रारम्भिक अध्ययन किया था। जनवरी-फरवरी सन् १९५८ में आयोजित इसी प्रकार की एक अन्य गोष्ठी में ऐसी परिषद स्थापित करना स्वीकार किया गया। सन् १९५९ में २४ औद्योगिक संस्थाओं में इस योजना पर काम जारी है, ऐसी परिषद स्थापित हो गई हैं, जबकि अन्य संस्थाओं ने भी इस परीक्षण के लिए अपना स्वीकार कर लिया है। श्रम सम्मेलन की सब कमेटी का पुनर्गठन करके उसका नाम Committee on Labour Management Cooperation रखा गया है।

(७) मजदूरों की शिक्षा—केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, कारखाना मालिकों के मण्डलों तथा शिक्षाशास्त्री मण्डलों के प्रतिनिधियों ने युक्त 'केन्द्रीय मजदूर शिक्षा मण्डल' एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया। नवम्बर सन् १९५८-५९ में ६७ अध्यापक प्रशासकों के प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण किया। मंडल ने श्रमिकों की शिक्षा के लिये भी

१२ केन्द्र स्थापित किये हैं, जिन्होंने ७७७ श्रमिक शिक्षक तैयार किये, सन् १९६० में २१८ यूनिट स्तर कक्षाएं चल रही थी।

पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक शान्ति

प्रथम पंच-वर्षीय योजना एवं औद्योगिक शान्ति—

'इन्डस्ट्रियल टुस' के प्रस्तावनानुसार, प्रथम पंच-वर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि श्रम और पूँजी के अच्छे सम्बन्धों के बिना अधिक उन्नति नहीं हो सकती, अतः यह आवश्यक है कि मालिक व मजदूर म हर स्तर पर घनिष्ट सम्बन्ध हो। श्रमिकों के संगठन करने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। भगडों को सुलभाने के लिए कार्य समितियों के निर्माण के लिये भी कहा गया है, जो प्रत्येक मिल में होगी। उद्योग की सारी मिलों के भगडों को सुलभान के लिए सामूहिक समितियाँ होगी। यदि कोई भगडा समझौते से तय न होगा, तो वह मध्यस्थ के द्वारा तय कराया जावेगा।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना—

इस योजना के अन्तर्गत, योजना आयोग ने सन् १९५५ में Representative Panel on Labour की स्थापना की है। इसके अलावा प्रत्येक उद्योग में Council of Management की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जिसमें श्रम व नियोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व रहेगा।

कुछ विशेष सुझाव—

भारत की वर्तमान आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों में कड़े निरीक्षण, मजदूरी और काम की दशाओं के समुचित नियन्त्रण तथा कल्याण-कार्यों के विकास द्वारा ही औद्योगिक शान्ति की वृद्धि की आशा की जा सकती है। सभी लोगों के लिये जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए, मकानों तथा सामाजिक सुरक्षा के विषय में भी काफी सुधार की आवश्यकता है। मूल्यों में स्थानित्व होना चाहिये तथा श्रम एवं पूँजी में पारस्परिक सहयोग।

उपसंहार—

अन्त में, गाँधी जी के निम्न शब्दों को लिखना अनावश्यक न होगा—“नौकर और मालिक के सम्बन्ध को स्वार्थ की भावना से आवद्ध न होकर एक दूसरे की सुख की भावना पर निर्भर होना चाहिये। लेन-देन की नीति पर स्थिर न होकर पारस्परिक सहानुभूति पर स्थिर रहना चाहिये।” मजदूर और उद्योगपति दोनों ही एक मांग के दो राही हैं, एक रथ के दो चक्र हैं, एक जीवन की दो धाँसे हैं तथा एक साधन के दो साधक हैं। दोनों को ही एक दूसरे का हित सोचना चाहिए। उद्योगपतियों को अपनी पूँजी द्वारा मजदूरों को सुविधाओं को प्राप्त कराना चाहिए तथा मजदूरों का अपने श्रम के बल पर पूँजीपतियों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए।

STANDARD QUESTIONS

- 1 What are the more frequent causes of trade disputes in India ?
- 2 Briefly summarise the history of industrial disputes in India.
- 3 What measures have been taken by the Government of India for the establishment of industrial peace in this country,
- 4 Describe the circumstances which led to the adoption of "the Industrial Truce Resolution" What steps have been taken by the central and the state governments to ensure the proper implementation of this resolution.

अध्याय ३०

श्रमिक-संघ

(Trade Unions)

प्रारम्भिक—

सेवायौन्व की तुलना में श्रमिक की स्थिति बड़ी दुर्बल होती है। वह प्रकृति अपनी आवश्यकताओं का अपन स्वामियों के सम्मुख रखने में हिचकता है। इसका कारण उसकी आर्थिक अवस्था का खराब व शिक्षा का अभाव होना है। परिणामस्वरूप उसे बड़ी हानि सहनी पड़ती है। श्रमिक के हित की रक्षा के लिए ही श्रमिक संघ का जन्म हुआ। वे मांग एवं पूर्ति के एकांगी प्रस्ताव को सामूहिक रूप देते हैं।

श्रम-संघ का अर्थ

सर्व श्री सिडनी तथा बीट्रिस वेब (Sidney and Beatrice Webb) के शब्दों में "श्रमिक संघ वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के उनके काम की दशाएँ ब्रिगडन न देने तथा उन्हें सुधारने के लिए बनाये गये स्थायी संगठन है।" इस प्रकार इनके दो प्रमुख उद्देश्य हैं—प्रथम, जो कुछ प्राप्त हो चुका है, उसे बनाये रखना और दूसरे, अधिक सुधार के लिए प्रयत्न करना।

फ्रैंक टनेनबॉम (Frank Tannen Baum) के मतानुसार—“श्रम-आन्दोलन परिणाम है और मशीनों का आविष्कार इसका प्रधान कारण है।” मशीनों के आविष्कार से एक व्यक्तिगत श्रमिक की सुरक्षा को बड़ा भारी आघात पहुँचा है, अतएव अपने बचाव के उद्देश्य से उसने सघ का निर्माण किया। श्रम-सघ द्वारा वह मशीनों के दुष्परिणामों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। श्रम-सघों का प्रमुख उद्देश्य पूँजीवादो व्यवस्था के स्थान पर ‘औद्योगिक जननम्बवाद’ की स्थापना करना होता है।

राबर्ट एफ० हॉक्स्ली (Robert F. Hoxley) के विचारानुसार, “श्रम-सघ वास्तव में वर्ग मनोवृत्ति (Group Psychology) के उत्पाद है।” प्रायः सभी श्रमिक-सघों का अन्तिम उद्देश्य सामान्य होता है—अर्थात् वे श्रमजीवियों की मौद्रिक करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे कि वे मिलकर अपनी समस्याओं का स्वयं हल करने में समर्थ हों सकें।

सेलिग पलमैन (Selig Pearlman) ने एव स्थान पर लिखा है कि किसी देश के श्रम-आन्दोलन की शक्ति वहाँ के रहने वाले श्रमिकों की जागरूकता पर निर्भर करती है।

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के शब्दों में, “श्रमिक सघ वास्तव में श्रम-जीवियों में सगठन का केन्द्र बिन्दु है।” सघ-शक्ति से श्रमिकों में परस्पर बन्धुत्व एव सहयोग की भावना का विकास होता है। सगठन के अभाव में श्रमजीवियों में स्वयं विषम-प्रतियोगिता की भावना पैदा हो सकती है, अतः पारस्परिक प्रतियोगिता की भावना का उन्मूलन करने एव बन्धुत्व की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही श्रमिक सघों का जन्म हुआ।

कुछ लोग श्रमिक-सघों को ‘लडाका-सगठन’ (Militant Organisations) समझते हैं, जो सदैव औद्योगिक युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, किन्तु यह धारणा सही नहीं है। श्रमिक सघ वास्तव में सामाजिक अशान्ति नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति के प्रतीक हैं।

श्रमिक-सङ्घ के उद्देश्य

(१) श्रमिकों में परस्पर बन्धुत्व एव सहयोग की भावनाओं का विकास करना एव उन्हें सगठित करना।

(२) उनके काम एवं भजदूरी के सम्बन्ध में उनकी विभिन्न शिकायतों पर सोच-विचार करना तथा उन्हें वैधानिक रूप से दूर करने का प्रयत्न करना।

(३) श्रमिक एवं उनके अधिकारियों में सहयोग की भावना उत्पन्न करना।

(४) अपने सदस्यों की बीमारी तथा अन्य मुसीबत के समय में निःशर्क राहत देना।

(५) रोग-बीमा, प्रोविडेंट फण्ड, सहकारी-साख, डाक्टरी मदद आदि लाभदायक योजनाओं की व्यवस्था करना।

(६) हड़ताल घोषित करना, संगठित करना तथा उन्हें चलाना, सेवायोजनों से वार्ता करना और भगड़ो को शान्ति से तय करना ।

(७) आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता देना ।

(८) अन्य ऐसे कार्य करना जो श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा सम्बन्धी दशाओं के सुधार के लिए हो ।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्रमिक सघों का प्रारम्भिक उद्देश्य अपने सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक हित साधना है । इस उद्देश्य से ही वे समस्त कार्य करते हैं ।

श्रमिक सङ्घों के कार्य

श्रमिक-सङ्घ के कार्यों को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—
(१) श्रमिकों की काम की दशाओं से सम्बन्धित कार्य, (२) काम की दशाओं से असम्बन्धित, किन्तु उनके सामान्य जीवन-स्तर में सम्बन्धित कार्य, और (३) राज-नैतिक कार्य ।

(१) काम की दशाओं से सम्बन्धित कार्य—(Intra-mural Functions)—श्रमजीवियों की काम की दशाओं से सम्बन्धित कोई भी कार्य इस शीर्षक के अन्तर्गत आता है, जैसे—पर्याप्त मजदूरी दिलाने के लिए प्रयत्न करना, कारखाने के अन्दर काम करने की दशाओं में सुधार करना, काम के घंटों में कमी करना, सेवा-योजकों से उचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना आदि । लाभ-अशभागिता एवं सह-भागिता की दिशा में किए गए प्रयत्न भी इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किये जा सकते हैं । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए श्रमिक सघ सामूहिक रूप से अपने सेवा-योजकों से व्यवहार करते हैं और माँग की अस्वीकृति की दशा में हड़ताल तथा असहयोग करते हैं । यही कारण है कि कभी-कभी श्रमिक सघ के इन कार्यों को 'लड़ाकू कार्य' (Militant or Fighting functions) कहते हैं ।

(२) सामान्य जीवन-स्तर से सम्बन्धित कार्य (Extra-mural activities)—इस शीर्षक के अन्तर्गत उन कार्यों का समावेश किया जा सकता है, जिनसे कि श्रमिकों के सामान्य जीवन-स्तर में वृद्धि हो, जैसे—श्रमजीवियों में परस्पर-बन्धुत्व एवं सहयोग की भावना प्रोत्साहित करना, उनका दैहिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, बीमारी, बेकारी अथवा हड़ताल आदि की अवधि में श्रमिकों की रक्षा तथा सहायता करना, कानूनी परामर्श देना, श्रमजीवियों के लिए कल्याण-कार्य की व्यवस्था करना, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजनालय आदि का प्रवर्धन करना, सस्ते भ्रमण, सस्ते अनाज एवं गृह आदि की व्यवस्था करना । इन कार्यों को 'अन्धुत्व-प्रेरक-कार्य' (Fraternal functions) भी कहा जा सकता है और ये सदस्यों के सहयोग तथा उनकी आर्थिक दशा पर निर्भर करते हैं । आर्थिक दृष्टि से श्रमिक सघ जितने ही बल-शाली होंगे, ऐसे कार्यों की मात्रा उतनी ही अधिक होगी ।

(३) राजनैतिक कार्य (Political activities)—देश के शासन प्रबन्ध में भाग लेने के उद्देश्य से निर्वाचन आदि में श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों को खड़ा करना राजनैतिक कार्यों की श्रेणी में आता है।

श्रमिक संघों के लाभ व हानियाँ

श्रमिक संगठन के लाभ—

श्रमिक संगठन के निम्नलिखित लाभ होते हैं—

- (१) श्रमिक संगठन से श्रमजीवियों में परस्पर बन्धुत्व एवं सहयोग की भावना का विकास होता है और इससे उनकी सामूहिक सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप पूँजीपति शक्तिशाली होते हुए भी श्रमजीवियों का शोषण नहीं कर पाते।
- (२) श्रमिक संगठन श्रमिकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं प्राथमिक दशा को सुधारने का सदैव प्रयत्न करते हैं। इन प्रयत्नों का फलस्वरूप श्रमिकों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता है एवं उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है।

(३) श्रम संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ कर श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलवाने का प्रयत्न करते हैं। जब श्रमिकों को उचित पारितोषिक मिलता है तो वे मन लगाकर कार्य करते हैं एवं भरण-पेट भोजन पर सदैव सन्तुष्ट रहते हैं।

(४) श्रमिक संगठन श्रमजीवियों में शिक्षा का भी प्रचार करते हैं और उनको अनुशासन में रहने का आदेश देते हैं। ऐसी स्वस्थ शिक्षा से केवल श्रमिका को ही नहीं बल्कि देश को भी बड़ा लाभ होता है।

(५) श्रमिक संगठन देश में औद्योगिक शान्ति भी रखने का

श्रम-संघों के लाभ व दोष

लाभ—

- (१) सहयोग की भावना का विकास।
- (२) रहन-सहन का ऊँचा स्तर।
- (३) शिक्षा का प्रचार।
- (४) औद्योगिक शक्ति को बढ़ावा।
- (५) उचित मजदूरी दिलाना।
- (६) कल्याण कार्य की व्यवस्था।
- (७) राजनैतिक प्रतिनिधित्व।

दोष—

- (१) श्रम नेताओं द्वारा श्रमिकों को उकसाना।
- (२) राजनैतिक अधिकार प्राप्ति के लिए इनका नेतृत्व।
- (३) साम्यवाद को बढ़ाना।
- (४) पदसौलुब्धता के कारण भगड़े।
- (५) पारस्परिक मतभेदों के कारण श्रम योजनायें बेकार होना।

प्रयत्न करते हैं, फलतः औद्योगिक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती है और देश उन्नति करता है ।

- (६) धर्मिक संगठन धर्मियों के लिये कल्याण कार्य की व्यवस्था भी करते हैं, जिससे मानसिक दृष्टिकोण विकसित होता है ।
- (७) राजनैतिक क्षेत्र में धर्म-संघ लोक सभा में अपने प्रतिनिधि भेजकर सरकार तक धर्मियों की आवाज पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं । परिणामस्वरूप, सरकार भी सनियम बनकर धर्मियों को सुविधायें देने का प्रयत्न करती है, जिससे उनका जीवन उन्नत हो और वे देश के आदर्श नागरिक बन सकें ।

धर्मिक संगठनों से हानियाँ—

इतना लाभ होते हुए भी धर्मिक संगठन से कुछ हानियाँ भी हैं, जो इस प्रकार हैं :—

- (१) धर्म संघों के नेता धर्मियों को अपना स्वायत्त सिद्ध करने के लिए भुलावा देकर उनको हड़ताल करने के लिये विवश करते हैं । औद्योगिक प्रगति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन की क्षति पहुँचती है और धर्म संघों में पूर्णतः एक दूसरे से बहुत दूर होते चले जाते हैं ।
- (२) धर्म-संघों के नेता केवल राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इनका नेतृत्व करते हैं, परन्तु वास्तव में इनको धर्मियों से अधिक सहानुभूति नहीं होती ।
- (३) धर्मिक संगठन से साम्यवाद एवं समाजवाद को अधिक दहावा मिलता है ।
- (४) धर्म-संघों के विभिन्न नेताओं में प्राद. पदलोचुपता के लिए झगड़े होते रहते हैं जिससे धर्म संघ-ग्रामदोहन की जड़ें कमजोर होती हैं तथा धर्मिक वर्ग का अहित होता है । उदाहरण के लिए ओ० टी० रेल्वे मूनिग्रन की कार्यकारणी सभा के निर्माण के सम्बन्ध में नेताओं में आपस में भगड़ा हुआ जो दो वर्ष तक चलता रहा । इस बीच मूनिग्रन की समस्त क्रियायें स्थगित रही तथा मुकदमेबाजी में विचारे धर्मियों की घन राशि बरबाद हो गई । अन्त में, संघ का रजिस्ट्रेशन सरकार को निरस्त करना पड़ा ।
- (५) कभी-कभी धर्म-संघ के नेताओं के पारस्परिक मतभेद के कारण सरकार की धर्म सम्बन्धी योजनायें बेकार व निष्प्रिय हो जाती हैं । उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के कुछ औद्योगिक केन्द्रों में कार्य समितियाँ (Work Committees) में प्रतिनिधित्व के लिए धर्म-संघ के नेताओं में भगड़ा

हुआ । अतः 'समिति' राजनीति का अखाड़ा बन गई । परिणामस्वरूप सन् १९५० में श्रमिकों तथा उद्योगों के हिा में 'कार्य समिति सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई ।

निष्कर्ष—

उपर्युक्त लाभ-हानियों के सन्तुलन से यह स्पष्ट है कि श्रम-संघ वास्तव में श्रम-समाज एवं देश के लिए एक कल्याणकारी संस्था है । जो भी दोष ऊपर बतलाये गये हैं वे श्रमिक संगठन की वृद्धियों न होते हुए उनके नेताओं के दोष हैं, जो अपने संगठन के उद्देश्यों से विचलित होकर स्वार्थ-साधक बन जाते हैं ।

भारत में सङ्घ आन्दोलन

श्रम-संगठन के प्रारम्भिक प्रयास—

पारस्परिक सामान्य लाभ के लिए श्रमिकों का संगठन होना भारत में अभी थोड़े समय से ही प्रारम्भ हुआ है । सबसे प्रथम बार सन् १८८४ में सामूहिक प्रतिनिधित्व किया गया, जबकि फैक्टरी कमीशन को प्रस्तुत किये जाने वाले स्मरण पत्र को तैयार करने के लिए श्रमिकों का एक सम्मेलन बुलाया गया, परन्तु संगठित कार्य-क्रम का विचार श्रमिकों में देर से आया । सन् १८९० में श्री लीखण्डे ने श्रमिकों को संगठित किया । इस संगठन का नाम बम्बई मिल हैण्ड्स एसोसियेशन था, जो सरकार की कारखाना अधिनियम के संशोधन के विषय में स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आयोजित किया गया था, परन्तु यह बड़ा ढीला-ढाला संगठन था । इसका न तो कोई निश्चित विधान था और न निश्चित बन्दा देने वाले सदस्य हों । सन् १८९७ में अमल-गेमेटेड सोसायटी ऑफ रेल्वेमैन ऑफ इण्डिया एण्ड ऑफ बर्मा की स्थापना हुई, जो अब भी वर्तमान है, परन्तु इसका कार्यक्रम भाई-चारे का कम था एवं लड़ाका अधिक ।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में कुछ सघ, जैसे—सी.मैन यूनियन कलकत्ता एवं पोस्टल यूनियन बम्बई स्थापित हुए । एक मुहम्मदन एसोसियेशन बंगाल में थी, परन्तु उसे कठिनता से एक श्रमिक संघ कहा जा सकता है । इसी प्रकार इण्डियन लेबर यूनियन, यद्यपि नाम से बड़ा उचित संगठन जान पड़ता है, बहुत क्रियात्मक नहीं रहा । सन् १९१० में श्रमिकों के कल्याण की वृद्धि के लिए कामगार हितवर्द्धक सभा स्थापित हुई, जो सन् १९५२ तक बनी रही, परन्तु इसने भी अधिक काम नहीं किया ।

श्रम-संघ आन्दोलन का वास्तविक शुभारम्भ—

वास्तव में श्रमिक संघ आन्दोलन भारत में सन् १९१८ से प्रारम्भ होता है, जबकि अनाप-सनाप कीमतेँ बढ़ने से उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ, सामान्य राजनैतिक वशमकस एवं श्रमिकों की बढ़ती हुई विद्रव्यापी चेतना ने श्रमिकों के दिमाग में अपने हितों के लिए संगठित होने की आवश्यकता की बात भर दी । पहली यूनियन मद्रास में

स्थापित हुई। इनके बाद अन्य स्थानों में भी यूनियन स्थापित हुई। इनमें अधिकतर तो केवल हड़ताल समिति मात्र थी, जिनका जन्म समस्या को जीतने या हारने पर या उसमें पूर्व ही समाप्त हो जाने के लिए हुआ था। वे एक दूसरे से असम्बन्धित थी, परन्तु जब उनकी एकीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई, क्योंकि इन्हीं दिनों विश्व श्रमिक संघ के लिए किसी केन्द्रीय एवं प्रतिनिधि संघ से प्रतिनिधि जाने को थे, अस्तु स्थानीय यूनियन संघ में परिवर्तन हो गई और फिर प्रान्तीय संघ की स्थापना हुई। सन् १९२० में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो समस्त यूनियनों का राष्ट्रीय फंक्शन थी, बुलाई गई। सन् १९२२ में केन्द्रीय श्रमिक समिति की स्थापना हुई और उसी वर्ष आल इण्डिया रेलवेमैन फंक्शन, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ यूनियन स्थापित हुई। इस अवधि की विशेषता यह थी कि उपयुक्त नेता श्रमिकों में से ही सुलभ न थे, अस्तु अनेक बाह्य व्यक्तियों के नेतृत्व पर निर्भर रहना पड़ता था।

सेवायोजकों का विरोध—

सेवायोजकों ने इन यूनियनों को मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया। श्रमिकों को मनाया जाने लगा। भारतीय अपराध दण्ड सत्रियम संशोधित किया गया और श्रमिक संघों के कार्य अवधि कोपित कर दिये गये। सन् १९२० में बकिंजम मिल्स के मामले में मद्रास यूनियन के विरुद्ध आदेश जारी किये गये और तब श्रमिक नेताओं ने देखा कि वे सच्च श्रमिक संघ कार्यों के लिये भी उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं। श्री एम० एस० जोशी ने श्रमिकों के लिए संरक्षण प्राप्त करने का उद्योग किया, परन्तु उनकी यह परिश्रम पाँच साल बाद उस समय सफल हुआ जबकि सन् १९२६ में व्यापार संघ अधिनियम पास किया गया। तब से संघों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

कम्यूनिस्टों का आन्दोलन पर प्रभाव—

सन् १९२६-२९ में आन्दोलन बड़ी तेजी पर था। कम्यूनिस्टों का संघों पर प्रभाव बढ़ गया। एम संघों में बिरनी कामगार यूनियन (सदस्य संख्या ५०,००० से अधिक) प्रमुख थी। इन्होंने बम्बई में सन् १९२८ में हड़ताल संगठित की और सफलता भी प्राप्त की, परन्तु बम्बई सिटी सदस्यों की कुछ कार्यवाहियों से मुसीबत पैदा हो गई। शहर में दहला हो गया, कई प्रमुख नेता पकड़ लिए गये और उन्हें सजायें दी गई। सन् १९२९ में उन्होंने फिर दूसरी हड़ताल की और वह काफी समय तक जारी रही। तब एक और अदालत बठी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार कामगार यूनियन ही हड़ताल

के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी थी। एक प्रमुख सघ के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट न आन्दोलन को बदनाम कर दिया और उसे बहुत धक्का पहुँचा। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सन् १९२६ के अधिवेशन में उसकी कार्य समिति पर कम्युनिस्टों ने अधिकार कर लिया तथा उग्र कार्यवाही की और विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन से सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया।

आन्दोलन में फूट पड़ना—

इस पर नम्र दलील सघों ने श्री एम० एम० जोशी की अध्यक्षता में इस कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और इण्डियन ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन बनाया। रेल्वे मैन्स फ़ेडरेशन ने भी उस कांग्रेस से सम्बन्ध तोड़ लिया। सन् १९३१ में तो उग्रदलियों ने स्वयं अपनी अलग आल इण्डिया रैड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना ली। सन् १९३१ के विश्व श्रमिक सघ को इण्डियन ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन से ही प्रतिनिधि भेजे गये थे। इस फूट से आन्दोलन में बड़ी कमी आ गई। एकता लाने के प्रयत्न एक बार फिर किये गए। सन् १९३३ में नेशनल ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन बना, जिसमें कम्युनिस्टों को छोड़कर और सब सघ सम्मिलित थे। सन् १९३५ में एकता का अन्तिम आधार भी निश्चित हो गया और सन् १९४० में तो काम चलाऊ समझौता भी हो गया था, परन्तु अभाव्यवश उसी समय युद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्ध में सहायता दी जाये या नहीं, इस प्रश्न पर फिर तीव्र मतभेद पैदा हो गया, फलस्वरूप कई सघ अलग हो गये।

वर्तमान स्थिति—

वर्तमान समय में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस देश के श्रमिक सघों की सबसे अधिक प्रतिनिधिक सस्था है। इसमें लगभग ८०० सघ सम्मिलित हैं, जो लगभग १२ लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जो किसी समय श्रमिकों की प्रतिनिधि सस्था थी, परन्तु कम्युनिस्टों के घुस आने पर जबसे भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सघ कांग्रेस उससे अलग हो गई तब से उसकी सदस्य सस्था घटती जा रही है। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अतिरिक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित हिन्द मजदूर सभा भी है तथा सन् १९४६ में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की और स्थापना हुई। इस प्रकार भारत में आज ४ प्रमुख अखिल भारतीय-श्रम संगठन हैं, जिनके सदस्यों की संख्या अग्रलिखित तालिका से ज्ञात की जा सकती है :—

तालिका I

रजिस्टर्ड श्रम संघ तथा उनको सदस्यता

	केन्द्रीय मण		राजकीय मण	
	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५६-५७	१९५७-५८
रजिस्टर में लिखित सघों की संख्या	१७३	२२३	८,१८०	९,८८२
रिट्स फाइल करने वाले सघों की संख्या	१०२	१३६	४,२६७	५,३८४
रिट्स फाइल करने वाले सघों की सदस्यता	१,८७,२९५	३,४२,१६६	२१,८६,४६७	२६,७२,८८३
				८,४२१ ५,८७६ ३३,४८८,३३७

तालिका II

	एफीलियेटेड सघों की सदस्यता		सदस्यता	
	१९५७	१९५८	१९५७	१९५८
१. इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस	६७२	७२७	६,३५,३८५	९,१०,२२१
२. हिन्दू मजदूर संघ	१३८	१५१	२,३३,६६०	१,६२,६४८
३. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस	—	८०७	—	५,३७,५६७
४. यूनियन ट्रेड यूनियन काँग्रेस	—	१८२	—	८२,००१
योग	—	१,८७६	—	१७,२२,७३७
				१८,६३,२६०

भारत में श्रमिक सघ की सफलताएँ

भारत में श्रमिक सघों का इतिहास नया है, इसलिए व्यवहार में उनका वास्तविक महत्व आँकना ठीक नहीं तो कठिन अवश्य है। यह तो निस्संकोच कहा जा सकता है कि उन्हें पर्याप्त सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिए, (i) अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष में ही वे मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटे कम करवाने में सफल हुए। (ii) सन् १९२६ में उन्होंने मजदूरी में कटौती होने से रोकी। (iii) इसके अतिरिक्त वे मालिकों का श्रमिकों के प्रति व्यवहार बदलने में भी सफल हुए हैं। वे अब पहले की तरह उनके प्रति उदासीन एवं विरुद्ध नहीं रहे। (iv) कर्मचारी सघ ने सन् १९२५ में बी० एन० आर० की हड़ताल एवं सन् १९२७ में खडगपुर वर्कशॉप की 'तालाबन्दी' में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया।

दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश के श्रमिक सघों की प्रगति लगभग नगण्य है। कठिनता से ५०% श्रमिक इन सघों के सदस्य होंगे। दुर्भाग्यवश हमारे अधिकतर संगठन केवल खोखले आयोजन मात्र हैं, जिन्हें अपर्याप्त कोष एवं जाली सदस्य सख्या और बाहरी लोगों के उत्साह द्वारा ही जीवित रखा जा सकता है। बहुत कम श्रमिक-सघों ने बरोजगारी, बीमारी व बुढ़ापे के लाभ दिये हैं। उनमें 'पारस्परिक सहायता' की प्रवृत्ति तो लगभग अविकसित है और उन्होंने अपने को केवल लड़ाकू कार्यों तक ही सीमित रखा है। अहमदाबाद का वस्त्र सघ अवश्य ही श्रमिका के लिए कई कल्याण कार्य—अस्पताल, शिक्षा, सस्ते अनाज सत्कारी ऋण एवं मनोरंजन की सुविधाओं के रूप में कर रहा है। प्रति सप्ताह वह एक पत्र भी प्रकाशित करता है।

यह आशा की जाती है कि शिक्षा के फैलने पर दशा और सुधरेगी, श्रमिक अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझेंगे, अनुशासन अवेगा संगठन के महत्व का उन्हें ज्ञान होगा व श्रमिक सघों के सदस्यों की सख्या भी बढ़ेगी, वे स्वयं अपने धर्म में से ही नेता प्रकट कर सकेंगे, बाहरी लोगों की स्वार्थपूर्ण चालों से छुटकारा पावेंगे और अपना कार्य अधिक चतुरता एवं बुद्धिमत्ता से चला सकेंगे। वह दिन दूर नहीं है, जब कि भारत इस बात पर गव कर सकेगा कि उसके श्रमिक सघ भी अब अन्य देशों से किसी भाँति पीछे नहीं ह।

भारतीय श्रमिक-सघ के मार्ग में बाधाएँ

भारत में श्रमिक-सघ आन्दोलन की प्रगति बहुत-सी बाधाओं के कारण धीमी रही है। कुछ महत्वपूर्ण बाधाएँ ये हैं—

(१) अनिष्ठा व अज्ञानता—भारतीय श्रमिक प्रायः अल्प है, अस्तु व अनुशासन के महत्व को नहीं समझने और न सघ को बुद्धिमानी और चतुरता से चला सकते हैं।

भारतीय श्रमिक सघों की घीमी

प्रगति के १२ कारण

१. शिक्षा और अज्ञानता ।
२. विचित्र समुदाय ।
३. प्रवासी प्रवृत्ति ।
४. कम वेतन ।
५. न्यून शुल्क ।
६. कम अवकाश ।
७. नियोक्ताओं व ठेकेदारों की विरोधी प्रवृत्ति ।
८. विज्ञान क्षेत्र ।
९. सुनेशुत्व का अभाव ।
१०. श्रमिक नेताओं के प्रति द्वेष ।
११. श्रमिका में अनुशासनहीनता ।
१२. नियोक्ताओं का असहानुभूति-पूर्ण वातावरण ।

(२) विचित्र समुदाय—भारतीय श्रमिक वर्ग विभिन्न प्रकार के घमों, विचारधाराओं, रीति-रिवाजों और आदतों के मजदूरों का मिश्रण है, इसलिए उनके संगठित होने में देर लगती है ।

(३) प्रवासी प्रवृत्ति—वे दूर-दूर के गाँवों से नौकरी की खोज में पाते हैं और चले जाते हैं, अतः वे अपना काम प्रयत्न उद्योग पारितोषिक करते रहते हैं, इस कारण वे किसी सघ में स्थायी उत्साह नहीं लेते ।

(४) कम वेतन—भारत में मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता है, इस कारण बहुत से तो चन्दा नहीं दे पाते । यदि कुछ दे भी सकें तो ऐसा शुल्क इतना न्यून होता है कि उससे सघ को यथेष्ट द्रव्य प्राप्त नहीं हो

सकता, अतः वे फिर थकड़ा कार्य, जिसकी उनमें आशा की जाती है, नहीं कर पाते । यही नहीं, भारतीय मजदूर के मूल समस्यात्मक लाभ के लिए शुल्क देने में सकोच करता है और अपने शुल्क के बदले में अपनी सब आपत्तियों में बचाव प्रयत्न थोड़ी अवधि ही में वेतन वृद्धि की आशा रखता है ।

(५) न्यून शुल्क—न्यूनतम शुल्क भी वसूल करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उसे मिल मालिक तनखाह बांटते समय उगाहने नहीं देते । बाद में वह या तो सरलता से कौषाध्यक्ष तक पहुँचना नहीं और यदि पहुँचना भी है तो बीच में ही उसका कुछ भाग इधर उधर कर दिया जाता है ।

(६) कम अवकाश—मजदूरों को अवकाश इतना कम रहता है कि वे अन्य बातों, जैसे—सघ आदि के विषय में सोच नहीं पाते ।

(७) नियोक्ताओं व ठेकेदारों की विरोधी प्रवृत्ति—सेवायोजकों एवं कम-कारियोजकों का विरोध सघ आन्दोलन की प्रगति में एक अन्य बाधा है । उन मजदूरों को जो सघ के प्रति कुछ सहानुभूति रखते हैं, तरह-तरह का परेशान किया जाता है । वे मजदूर-सघ को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं और यदि करते हैं तो ऐसी शर्तों के साथ कि फिर संगठन व्यर्थ रहता है । कभी-कभी सन्धे सघों के विरोध में सेवायोजकों द्वारा भूटे सघ स्थापित कर दिये जाते हैं और इनकी महायत्ना में उनकी कार्यवाहियों

में विघ्न डालने का प्रयत्न किया जाता है। सघ के कार्यकर्त्ताओं को घूस देकर फोड़ लेना तो एक साधारण सी बात है।

(८) विशाल क्षेत्र—हमारे देश में मजदूर एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और कुछ दशाओं में तो उन तक पहुँच भी नहीं हो पाती, जैसे—आसाम के चाय बागान आदि, अस्तु इनमें सम्बन्धित सूचनाएँ देवाई जा सकती हैं और बाहर वालों को उनकी जानकारी नहीं हो पाती। यह दशा सघों की प्रगति में बाधक है।

(९) सु-नेतृत्व का अभाव—सबसे बड़ी बाधाओं में एक बाधा अच्छे नेतृत्व का अभाव होना भी है। श्रमिक प्रपञ्च है, वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों से अपरिचित हैं, इसलिए उन्हें बाहरी नेतृत्व पर निर्भर रहना पड़ता है। यह उनकी बड़ी दुर्बलता है, क्योंकि ऐसी दशा में प्रायः अपने राजनैतिक प्रथवा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वार्थी लोग नेतृत्व संभाल लेते हैं। इन्हें श्रमिकों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्हें कभी कारखानों में काम नहीं करना पड़ा। वे उद्योग की आवश्यकताओं से अपरिचित होते हैं। उन्हें श्रमिकों से सच्ची सहानुभूति भी नहीं होती। कुछ पढ़े लिखे वकील आदि, जिन्हें काम नहीं मिलता, बैठे ठाले इस कार्य को संभाल लेते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयत्न में सलग्न रहते हैं। कहीं-कहीं तो ऐसे लोगो ने मजदूरों के चन्दे भी हजम कर लिए। कुछ नेता कई सघों का काम संभालते रहते हैं, इसलिए प्रत्येक सघ को पर्याप्त समय भी नहीं दे पाते। रॉयल कमीशन ने यह स्पष्ट कहा है कि जब तक ये सघ इस विषय में आत्म-निर्भर नहीं हो जाते, तब तक किसी विशेष प्रगति की आशा करना व्यर्थ है।

(१०) श्रमिक नेताओं के प्रति द्वेष—अधिकांश श्रमजीवियों में अपने नेताओं के प्रति सद्भावना नहीं होती। जनसाधारण भी उन्हें प्रायः विप्लवकारी, आग जगलने वाला कहकर बदनाम करते हैं।

(११) श्रमिकों में अनुशासनहीनता—अशिक्षा, अज्ञानता एवं रुढ़िवादिता के कारण भारतीय श्रमिक नियन्त्रण व शासन के अन्तर्गत रहने का आदी नहीं होता, अतः श्रम सघ की ओर से प्रायः लापरवाह रहता है।

(१२) नियोक्ताओं का असहानुभूतिपूर्ण वातावरण—मिल मालिकों का असहानुभूतिपूर्ण वातावरण भी श्रम-सघ आन्दोलन की एक बड़ी बाधनाई है। भारतीय नियोक्तागण यह नहीं समझते कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ सघवाद हड़तालों के विरुद्ध बीमा का कार्य करता है। इसके फलस्वरूप अनिर्णयित, अनाधिकृत तथा बिजली की तरह क्षणिक हड़ताले नहीं हो पाती।

राष्ट्र-निर्माण में संघों का भाग

किसी भी देश को कल्याणकारी राज्य बनाने में श्रमिक सघ बहुत लाभकारी हो सकते हैं। श्रमिक संघों को मजदूरों में यह भावना व प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए कि

वे राष्ट्र हित की दृष्टि से उत्पादन को बहुत बढ़ावें। मिल मालिकों का भी यह कर्तव्य है कि वे उत्पादन बढ़ाने के उपायों को श्रमिक (अर्थात् श्रमिक सघ के प्रतिनिधियों) के सामने रखें और उनका सहयोग प्राप्त करें। श्रमिक प्रतिनिधि उन्हें राष्ट्रीय समृद्धि में जहाँ अपने सहयोग का विश्वास दिलायेगे वहाँ अपने लिए भी मिल मालिकों से निम्न-लिखित आश्वासन चाहेंगे—

- (१) उत्पादनक्षमता में हुई वृद्धि के कारण जो लाभ होगा उसमें मजदूर भी वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं के रूप में भागीदार होंगे।
- (२) नये उपायों का अर्थ मजदूर पर कार्य का अनुचित भार डालना नहीं होगा।
- (३) नये उपायों का परिणाम मजदूरों की छुट्टी और बेकारी भी नहीं होनी चाहिए।

इसके बाद श्रमिक सघ मजदूरों को राष्ट्रीय उत्पादन में अधिकाधिक हादिक सहयोग देने के लिए सम्भाव्य, मजदूरों को मशीनों का काम अधिक कुशलता से करने की ट्रेनिंग भी देंगे और शिक्षण की व्यवस्था भी करेंगे। श्रमिकों के प्रतिनिधि मिल इन्जीनियरों के साथ बैठ कर उत्पादन की नई योजनाओं पर विचार करेंगे और उपयुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सहयोग देंगे। इस तरह श्रमिक सघ राष्ट्रीय समृद्धि में महत्वपूर्ण भाग ले सकते हैं।

शिक्षा प्रचार देश की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आज श्रमिक सघ ४५% व्यय अपने कार्यक्रमों के वेतन पर करते हैं और केवल ५% शिक्षा प्रसार पर व्यय करते हैं। यह बहुत असन्तोषजनक स्थिति है। शिक्षा की और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निम्नलिखित अन्य विशाखों में काम करके भी श्रमिक सघ राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकते हैं :—

- (१) श्रमिक सघ सहकारी समितियाँ बना कर मजदूरों के लिए घर बनवा सकते हैं।
- (२) मजदूरों में बचत की आदत पैदा की जा सकती है और विभिन्न कार्यों के लिए सहकारी समितियों का संगठन किया जा सकता है।
- (३) मजदूर परिवारों में तथा घयोवृद्ध पुरुषों में ग्रामोद्योग का प्रसार करके आमदनी बढ़ाई जा सकती है।
- (४) शारीरिक व्यायाम, खेल-कूद आदि का प्रचार करके मजदूरों को स्वस्थ बनाने में श्रमिक सघ सहयोग दे सकते हैं।

संक्षेप में, श्रमिक सघ विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य करके राष्ट्र-निर्माण में सहायक हो सकते हैं। इसमें मजदूरों का शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर भी

ऊँचा उठेगा, वे अच्छे नागरिक बनेंगे और जो सामाजिक व्यवस्था वे लाता चाहते हैं, उसमें भी इससे सफलता मिलेगी।

श्रम-संघ-अधिनियम

(Trade Union Act)

श्रम संघ अधिनियम सर्व प्रथम सन् १८२६ में बनाया गया था, जो कि १ जून सन् १८२७ से लागू किया गया। इसके बाद सन् १८२८ व सन् १८४२ में कुछ संशोधन किये गये। सन् १८४७ ने द्वारा श्रम संघ अधिनियम बनाया गया।

(1) सन् १८२६ का श्रम संघ अधिनियम—

इस अधिनियम के द्वारा श्रम-संघों को वैधानिक मान्यता प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हुई है। यद्यपि श्रम-संघों की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है, परन्तु रजिस्टर्ड श्रम-संघों को कुछ विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं। सन् १८२६ के अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) श्रम संघों की रजिस्ट्री कराना—

अधिनियमानुसार श्रम-संघ वे सात या इससे अधिक सदस्य, अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार को संघ के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। आवेदन पत्र श्रम संघों के प्रांतीय रजिस्ट्रार को भेजना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ श्रम संघ के नियमों की प्रति तथा नीचे लिखी बातों का एक विवरण पत्र भेजना चाहिये—

(1) आवेदन पत्र देने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय तथा पते।

(11) श्रम संघ का नाम व उससे प्रधान कार्यालय का पता।

(111) श्रम संघ के पदाधिकारियों की उपाधियाँ, नाम, आयु, पते व व्यवसाय।

यदि कोई श्रम-संघ रजिस्ट्री के लिये आवेदन पत्र दिये जाने के एक वर्ष से अधिक पहले से विद्यमान हो, तो रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र के साथ-साथ श्रम संघ की सम्पत्ति एवं दायित्वों का एक व्यापक विवरण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिसमें कि नियत विवरण हो तथा वह नियत रूप के अनुसार तैयार किया गया हो।

आवेदन पत्र और नियत शुल्क के पाने पर रजिस्ट्रार ऐसी जाँच करेगा, जो वह उचित समझे और यदि उसे विश्वास हो जाय कि संघ ने अधिनियम की सारी शर्तों को पूरा कर दिया है और संघ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री के लिये अपेक्षित निर्धारित नहीं किया गया है, तो वह उस श्रम-संघ का नाम 'श्रम-संघों के रजिस्टर' में लिख लेगा और रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र जारी कर देगा। यदि रजिस्ट्रार को यह विश्वास हो जाय कि रजिस्ट्री के लिये आवेदन पत्र काम करने वालों के हितों में सम्भव से नहीं किया गया है, परन्तु सेवायोजकों के हितों में किया गया है, तो वह रजिस्ट्री नहीं करेगा। दूसरे, रजिस्ट्रार किसी एक कारखाने के एक से अधिक श्रम-संघों की रजिस्ट्री नहीं करेगा।

(२) श्रम-संघ की रजिस्ट्री का निरसन—

नीचे लिखी हुई दशाओं में रजिस्ट्रार किसी श्रम-संघ की रजिस्ट्री को निरस्त (Cancel) कर देगा—

- (i) यदि रजिस्ट्री होने के समय श्रम-संघ की रजिस्ट्री के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा न किया हो, अथवा उसकी रजिस्ट्री किसी गलती, मिथ्या-बयान अथवा कपट के कारण हुई हो ।
- (ii) यदि आवेदन पत्र देने की तारीख पर श्रम-संघ रजिस्ट्री के लिये आवश्यक न्यूनतम सदस्यता (Minimum Membership) सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहा हो ।
- (iii) यदि श्रम-संघ काम करने वालों के हितों में सद्भाव से संचालित नहीं किया जाता है, परन्तु काम कराने वालों के हितों में संचालित किया जाता है ।
- (iv) यदि श्रम-संघ ने इस अधिनियम के किसी नियम का उल्लंघन किया हो—
- (v) यदि श्रम-संघों की कार्यवाहियाँ उद्योग के हितों को हानिकर हैं ।

(३) रजिस्ट्री किये हुए एवं योग्य ट्रेड यूनियनों का स्वत्व तथा दायित्व—

प्रत्येक रजिस्ट्री की हुई ट्रेड यूनियन को एक साधारण कोष (General Fund) रखना चाहिए । साधारण कोष नीचे लिखी हुई बातों के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य पर व्यय नहीं किया जायगा :—

- (1) ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और अन्य व्यय के चुकाने के लिए ।
- (ii) ट्रेड यूनियन के प्रबन्ध के लिये व्यय के चुकाने के हेतु, जिसमें यूनियन के साधारण कोष के हिसाब की जाँच सम्मिलित है ।
- (iii) किसी ऐसी राजनियम सम्बन्धी कार्यवाही के चलाने या प्रतिवाद करने के लिये जिसमें ट्रेड यूनियन या उसका कोई सदस्य पक्षकार हो ।
- (iv) ट्रेड यूनियन या उसके किसी सदस्य की ओर से श्रम-सम्बन्धी-भगडों के संचालन के हेतु ।
- (v) श्रम सम्बन्धी भगडों से उत्पन्न हुई हानि के लिए सदस्यों की क्षति-पूर्ति के हेतु ।
- (vi) ऐसे सदस्यों की मृत्यु एवं वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटनाओं या बेकारी के कारण सदस्यों या उनके आश्रितों के उप-वेतन के हेतु ।
- (vii) सदस्यों की मृत्यु या दुर्घटना के कारण उनके आश्रितों की सहायता के लिये ।
- (viii) सदस्यों की या उनके आश्रितों की शिक्षा सम्बन्धी या सामाजिक कार्य-वाहियों के लिए ।

(1X) सरकार द्वारा शासकीय गजट में विज्ञापित किसी अन्य उद्देश्य के लिए, किन्हीं ऐसी शर्तों का पालन करते हुए जो उसमें लिखी हो ।

एक रजिस्ट्री की हुई टेंडर यूनिशन साधारण कोष से भिन्न भी एक कोष कुछ विशेष कार्यों के लिए रख सकती है । ऐसे पृथक् कोष के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) किसी ऐसे व्यय का चुकारा जो किसी पदाभिलाषी द्वारा, अधिनियम द्वारा किसी धारा सभा में भ्रमजीवियों के लिए नियत स्थान के लिए अपने पदाभिलाषी होने या निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन से पूर्व, उसके होने के काल में या उसके पश्चात् प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, या

(11) ऐसे किसी पदाभिलाषी या भावी पदाभिलाषी को सहायता के लिए किसी मोटिंग का करना अथवा कोई साहित्य या लेख पत्रों का वितरण करना, या

(111) इस प्रकार निर्वाचित हुए ऐसे व्यक्ति का प्रतिपालन (Maintenance) करना ।

इस प्रकार स्थापित किए गए कोष में चन्दा देने के लिए किसी सदस्य को विवश नहीं किया जायगा तथा जो सदस्य उक्त कोष में चन्दा न देगा, उसे भ्रम-संघ के किसी लाभ से वंचित न रखा जायगा ।

(४) भ्रम-संघ के रजिस्ट्रेशन से लाभ—

(1) भ्रम-संघ के वैध (legal) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हुए भ्रम-संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अपराध सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनको बढ्यन्त्र के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

(11) रजिस्टर्ड संघ के किसी भी सदस्य एवं पदाधिकारी के द्वारा दिए गये किसी भी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो उन्होंने संघ के वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है, कोई भी दावा इस आधार पर कि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति को कार्य का अनुबन्ध तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, किसी भी दीवानी अदालत में स्वीकार नहीं किया जायगा ।

(111) रजिस्टर्ड भ्रम-संघ के विरुद्ध किसी भी दीवानी अदालत में ऐसे किसी कार्य के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जायगा, जिसको कि किसी व्यक्ति ने संघ की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करते हुए किया है ।

(1४) अधिनियम द्वारा संघ के सामान्य कोष को व्यय करने की दृष्टि से सीमाएँ बाँध दी गई हैं ।

(४) भ्रमिक संघ ऐच्छिक रूप से अपने सदस्यों के राजनैतिक एवं सामाजिक हितों के लिए अतिरिक्त कोष निर्माण कर सकते हैं ।

(VI) रजिस्टर्ड भ्रम-संघों को अपना नाम तथा उद्देश्य निश्चित करने पड़ते हैं तथा प्रति वर्ष अन्वेषण (Audit) के लिए अपना बैलान्स तैयार रखना पड़ता है ।

(II) सन् १९४७ का श्रम-संघ अधिनियम—

सन् १९४७ में, सन् १९२६ के श्रम-संघ अधिनियम में कुछ संशोधन कर दिये गये। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(१) मान्यता की शर्तें—सेवायोजको द्वारा प्रतिनिधि संघ की मान्यता प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया तथा इस दृष्टि से उत्पन्न हुए संघर्षों को निवटाने के लिए श्रम न्यायालय (Labour Courts) की स्थापना की गई है। किसी भी श्रम-संघ को श्रम-न्यायालय द्वारा उस समय तक मान्यता प्राप्त न होगी, जब तक कि—

- (१) उसे अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त न हो।
- (II) उसके सभी सदस्य उसी या उससे सम्बन्धित उद्योग में कर्मचारी होने चाहिए।
- (III) वह सेवायोजको द्वारा उस उद्योग में नियुक्त किये हुये कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करे।
- (IV) उसके नियम उद्योग के किसी कर्मचारी की सदस्य न बनने के लिये छूट न दें।
- (V) उसके नियमों में हड़ताल घोषित करने की पूर्ण विधि होनी चाहिए।
- (VI) उसकी कार्यकारिणी की सभा कम से कम ६ माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

(२) कुछ संघ कार्यवाहियों को अनुचित घोषित करना—सन् १९४७ के संशोधनानुसार कुछ कार्यवाहियों को मान्यता प्राप्त संघों के लिये अनुचित घोषित कर दिया गया है, जैसे—

- (१) उसके अधिकांश सदस्यों द्वारा अनियमित हड़तालों में भाग लेना।
- (II) कार्यकारिणी द्वारा अनियमित हड़ताल के लिए सुझाव अथवा सहायता प्रदान करना।
- (III) सभ के किसी पदाधिकारी द्वारा झूठे विवरण-पत्र (Returns) भिजवाना।

(३) कुछ कार्य सेवायोजकों के लिये अनुचित ठहराना—नीचे लिखे हुये कार्य सेवायोजकों के लिये अनुचित ठहरा दिये गये हैं—

- (१) अपने कर्मचारियों द्वारा श्रम-संघ संगठित करने के किसी अधिकार में हस्तक्षेप करना अथवा सुरक्षा या पारस्परिक सहायता के लिये गति-विधियां जारी करना।
- (II) श्रम-संघ के विरुद्ध एवं उसके प्रबन्ध में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करना अथवा उसको आर्थिक एवं अन्य दूसरी प्रकार की सहायता प्रदान करना।

(iii) मान्यता प्राप्त संघ के किसी पदाधिकारी अथवा किसी कर्मचारी को (यदि उसने अधिनियम के अन्तर्गत किसी जाँच में गवाही दी है) निकालना या उससे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना ।

(iv) मान्यता प्राप्त संघों से सम्पर्क रखने के लिए इन्कार करना अथवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सुविधायें प्रदान न करना ।

(४) दण्ड की व्यवस्था—कोई भी सेवायोजक जो अनुचित कार्य करता है, अर्थात्-दण्ड का भागी होगा, जो ₹,०००) तक हो सकता है । यदि कोई मान्यता प्राप्त संघ अनुचित कार्यवाही करता है, तो उसकी मान्यता वापिस ले ली जायगी । यदि कोई संघ, श्रम न्यायालय द्वारा मान्य किया गया है, तो भी सेवा-योजक तथा रजिस्ट्रार उसकी मान्यता वापिस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं । हाँ, ऐसी दशा में यह अनिवार्य है कि उसने कोई अनुचित कार्य किया हो या वह श्रमजीवियों का प्रतिनिधि संघ नहीं रहा है अथवा वह अधिनियम के अन्तर्गत विवरण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा हो ।

(५) श्रम संघ के विधान में अनिवार्य नियम—सशोधित अधिनियमानुसार, अधिष्ठ में प्रत्येक श्रम-संघ के नियम में नीचे दी हुई बातें अवश्य होनी चाहिए :—

(i) सदस्यों के चन्दे की दर ।

(ii) वे परिस्थितियाँ जिनके अनुसार सदस्य का नाम सदस्यता से काट दिया जायगा । इसमें चन्दे का भुगतान न करना भी शामिल है ।

(iii) सदस्यों की सूची ।

(iv) कार्यकारिणी एवं अन्य पदाधिकारी की आज्ञा का उल्लंघन कर हड़ताल या तालेबन्दी में भाग लेने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की विधि ।

(६) मान्यता का रद्द होना—यदि किसी श्रम संघ ने ऐच्छिक रूप से अथवा रजिस्ट्रार की सूचना प्राप्त होने के बाद अधिनियम की किसी धारा या संघ के नियमों का उल्लंघन किया हो अथवा बाध्य होने वाले किसी समझौते या निर्णय के अनुसार काम करने में असफल रहा हो, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है ।

(७) राजकीय कर्मचारियों पर रोक—राजकीय कर्मचारी, चाहे वे नागरिक सेवक ही क्यों न हों, राजनैतिक कोषों में चन्दा नहीं दे सकेंगे ।

(८) बाहरी सदस्यों के पदाधिकारी होने पर रोक—बाहरी सदस्य उस श्रम-संघ के पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे जिसमें समस्त अथवा कुछ अंशों में नागरिक सेवक हैं । यदि श्रम संघ जिनके पदाधिकारी बाहरी व्यक्ति हैं, कोई अनुचित कार्य करता है, तो वे पदाधिकारी किसी भी श्रम संघ में तीन वर्ष तक कोई पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे ।

(९) अधिक संख्या वाले संघ की मान्यता—यदि दो या अधिक श्रम-संघ

मान्यता के अधिकारी हो तो सत्था में अधिक सदस्यों वाले सच को मान्यता प्रदान की जायगी।

श्रमिक-सङ्घ अधिनियम के कुछ दोष एवं

उनके सुधार के लिए सुझाव

केवल सन् १९२८ एवं सन् १९४७ के कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को छोड़ कर दोष अधिनियम बंसा ही बना है, जैसा कि सन् १९२६ में स्वीकृत किया गया था, परन्तु सन् १९२६ और सन् १९६० की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है और श्रमिक आन्दोलन आज एक नये और ऊँचे स्तर पर है, इसलिए यह आवश्यक है कि श्रमिक-सच अधिनियम में निम्न संशोधन कर दिये जाय —

श्रमिक सच अधिनियमों में विशेष सुधार के लिये मुख्य ७ सुझाव

१. अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर जोर देना।
२. सामान्य व राजनैतिक कोषों के अन्तर की समाप्ति।
३. चन्दे की अनिवार्यता।
४. आडिट की निशुल्क व्यवस्था।
५. नैवाभोजकों के विरुद्ध मरक्षण।
६. बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक।
७. अनिवार्य मान्यता की उचित शर्तें।

(१) अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर जोर देना—इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक सच की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य नहीं है। रजिस्ट्री अनिवार्य न करने के भले ही तब कुछ कारण रहे हों, लेकिन अब तो परिस्थिति बदल गई है। रजिस्ट्री कराना एक सीधा-सादा कार्य है। रजिस्ट्री करा लेने से कोई विशेष उत्तरदायित्व भी नहीं आता, जिसे कि एक सच पूरा न कर सकता हो और फिर रजिस्टर्ड होने पर लाभ बहुत होते हैं। वास्तव में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर जोर न देना एक बड़ी अनुचित बात है। धारा २८ (डी) के अन्तर्गत श्रमिक न्यायालय की

आज्ञानुसार सच को मान्यता देने की एक शर्त उसका रजिस्टर्ड होना है। इस दृष्टि से भी रजिस्ट्री कराना आवश्यक है। इससे सचों को वह उचित स्तर प्राप्त होगा जिसकी उन्हें बड़ी आवश्यकता है।

(२) सामान्य व राजनैतिक कोषों के अन्तर की समाप्ति—सच के कोष को दो भागों में रखा गया है—सामान्य कोष और राजनैतिक कोष। सामान्य कोष के लिये चन्दा देना अनिवार्य है। अधिनियम के अन्तर्गत इस कोष के जो प्रयोग बताये गये हैं वे बहुत संकुचित हैं, अस्तु सच द्वारा किये जाने वाले कई उपयोगी कार्यों के सम्पादन में बाधा पड़ती है। हमारा सुझाव तो यह है कि सामान्य कोष एवं राजनैतिक कोष में अन्तर ही समाप्त कर दिया जाय, क्योंकि विगत अनुभव यह बताता है कि

सघो ने राजनैतिक क्षेत्र में अधिकाधिक भाग लेते हुये भी अपने प्रारम्भिक कार्यों को नहीं छोड़ा। भविष्य में उन्हें देश के राजनैतिक निर्माण में और भी अधिक भाग लेना है और इस कार्य में उनकी अधिक द्रव्य की आवश्यकता होगी।

(३) चन्दे की अनिवार्यता—कोष (कुल-कोष) के लिये चन्दा लेना अनिवार्य कर दिया जाय। सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख पेश किये गये बिलों में भी चन्दा अनिवार्य रखा गया है, परन्तु हमारा सुझाव यह है कि चन्दे की अनिवार्य रकम ६ आना और ८ आना के मध्य हो, क्योंकि अब श्रमिक पहले की तरह निर्धन नहीं है, रोजगार भी बढ़ रहा है, अधिनियम द्वारा उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जा रही है और फिर जब मजदूर अधिक चन्दा देंगे तो वे राजनैतिक दृष्टि में अधिक जागृत भी होंगे।

(४) ब्राडिट की निरुक्त आवश्यकता—इस समय श्रमिक सघ की आय का एक बड़ा भाग (४४%) ब्राडिट भावि में व्यय हो जाता है। यदि सरकारी अफसरों द्वारा ब्राडिट निःशुल्क करने की व्यवस्था हो जाये तो इस प्रकार व्यय होने वाली धन-राशि अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए सुलभ हो जायगी।

(५) सेवाभोजनों के विरुद्ध संरक्षण—श्रमिक सघ के पदाधिकारियों को सेवा-भोजन सर्वद्व ही परेशान करते रहते हैं। यह भी श्रमिक आन्दोलन की प्रगति में बाधा है। अधिनियम में इसे रोकने के लिए आवश्यक धारारें जोड़ना आवश्यक है।

(६) बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक—अधिनियम में ऐसी भी धारारें हो जो कि बाहरी व्यक्तियों को श्रमिक सघ में प्रवेश करने से रोके। प्रायः स्वार्थी व्यक्ति अनभिज्ञ श्रमिकों को उकसा कर अपना काम बनाते रहते हैं, अस्तु श्रमिक वर्ग में से ही पदाधिकारी नियुक्त करने को प्रोत्साहन दिया जाय।

(७) अनिवार्य मान्यता की शर्त—सन् १९४७ के संशोधित अधिनियम में किसी सघ को अनिवार्य मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में एक शर्त यह है कि वह एक 'प्रतिनिधि' सस्था हो, परन्तु प्रतिनिधि सस्था की कसौटी क्या है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अच्छा हो यदि 'प्रतिनिधि' सस्था की परिभाषा समान रूप में सब जगह समझी जाये। इसी प्रकार अनिवार्य मान्यता पाने के लिए दूसरी शर्त यह है कि सघ के नियम हड़ताल घोषित करने की व्यवस्था करें। यह शर्त वास्तव में ब्रेकार है, क्योंकि यदि संघ के नियमों में हड़ताल घोषित करने का अधिकार प्रेसीडेण्ट को सौंप दिया जाय तो भी वह पूरी समझी जायगी और मान्यता पाने की अधिकारी होगी, यद्यपि यह स्पष्ट है कि हड़ताल घोषित करने की ऐसी व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है। यदि उपरोक्त आधार पर उचित संशोधन कर लिया जाय तो निश्चित ही यह अधिनियम श्रमिक सघ आन्दोलन को ठोस सहायता पहुँचा सकता है।

श्रम संघ एवं भारतीय श्रम सम्मेलन—

भारतीय श्रम-सम्मेलन सन् १९५८ ने मजदूर सघों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्न सिद्धान्त निर्धारित किये—

(१) जहाँ एक से अधिक मजदूर सघ हैं, वहाँ यदि कोई सघ मान्यता के लिए दावा करे तो वह रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम १ वर्ष तक सक्रिय होना आवश्यक है। जहाँ केवल एक ही सघ ठन है वहाँ यह शर्त लागू नहीं होती।

(२) सम्बद्ध उद्योग में इसकी सदस्य संख्या कम से कम २५ प्रतिशत अवश्य होनी चाहिए।

(३) यदि किसी मजदूर सघ के सदस्यों की संख्या सम्बद्ध स्थानीय उद्योग के मजदूरों की संख्या का २५ प्रतिशत है, तो वह उस क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त करने का दावा कर सकता है।

(४) जब किसी मजदूर सघ को मान्यता मिल जाय तब इस स्थिति में दो वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

(५) जहाँ किसी उद्योग या संस्थान में कई मजदूर सघ ठन हो वहाँ जो सबसे बड़ा सघ हो उसे मान्यता प्रदान की जाय।

(६) किसी क्षेत्र के उद्योग की प्रतिनिधि मजदूर यूनियन उस क्षेत्र के उस उद्योग के सभी कामगारों का प्रतिनिधित्व करेगी, परन्तु यदि किसी विशेष उद्योग की यूनियन की सदस्य संख्या ५० प्रतिशत है, तो वह उस उद्योग की सीमा तक प्रतिनिधित्व कर सकती है।

(७) प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप के निश्चय के लिए प्रक्रिया और अधिक सम्पूर्ण होनी चाहिये। जहाँ पर विभागीय तंत्र के विनिश्चयात्मक निर्णय अन्य पक्षों को स्वीकार न हो वहाँ सभी केन्द्रीय मजदूर संघठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाय, जो मामले पर विचार करे तथा निर्णय दे। इसके लिए केन्द्रीय सरकार मजदूर संघठन, जो स्थायी तन्त्र के रूप में कार्य करेगा, स्थानीय आधार पर व्यक्ति और धन प्रदान करेगा।

(८) केवल उन्ही मजदूर सघों को मान्यता दी जायगी जो अनुशासन की संहिता का पालन करेंगे।

(९) ऐसे मामले में, जहाँ कोई मजदूर सघ केन्द्रीय सरकार के संघठन में से किसी से भी सम्बद्ध न हो, मामले को अलग रूप से ही तय किया जायगा।

श्रम-सघ तथा द्वितीय पक्ष-वर्तीय योजना—

श्रम-सघों के दोष को दूर करने के लिए द्वितीय योजना अवधि में निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं—

(i) श्रम सघों में बाहरी व्यक्तियों को शामिल न होने देना,

(ii) आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर उन्हें मान्यता प्रदान करना,

(iii) श्रम-सघों के कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न (Victimization) से रक्षा करना, और

(iv) श्रम सघों की व्यक्तिगत साधनों द्वारा उन्नति करना।

STANDARD QUESTIONS

1. Define a 'Trade Union' and briefly enumerate its aims, objects and functions
2. Summarise carefully the advantages and disadvantages of trade unions
3. Sketch the growth of trade unionism in India pointing out its defects and suggesting remedies
5. What are the main provisions of the Trade Unions Act, 1926 and 1947 ? Do you suggest any improvements in the existing legislation
5. Briefly summarise the main provisions of the Indian Trade Union Act.

अध्याय ३१

श्रम कल्याण

(Labour Welfare)

प्रारम्भिक—

'श्रम कल्याण कार्य' का अभिप्राय उन समस्त कार्यों से होता है, जो कि कानून द्वारा दी गई वेतन इत्यादि अनेक सुविधाओं के अतिरिक्त श्रमिक की सुविधा तथा उसके शारीरिक, मानसिक व सामाजिक हित के विकास की दृष्टि से किये जाते हैं। 'श्रमिक-कल्याण-कार्य' के क्षेत्र की व्याख्या करते हुये श्रम जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि श्रम-कल्याण कार्यों के अन्तर्गत श्रमिक की बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास के कार्यों का समावेश होना चाहिये। ये कार्य चाहे नियोक्ता, सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा किए जायें तथा साधारण अनुबन्धात्मक सम्बन्ध अथवा विधान के अन्तर्गत श्रमिकों को जो मिलना चाहिए उसके अलावा किये गये हों। इस प्रकार इस परिभाषा के अन्तर्गत हम आवास-व्यवस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधायें, प्रच्छा भोजन (केन्टीन के आयोजन सहित), आराम एवं मनोरंजन की सुविधायें, सहकारी समितियाँ, छात्र घर एवं शिशु-गृह, शौचालय की व्यवस्था, सवेतन छुट्टियाँ,

सामाजिक बीमा, प्रॉवीडेंट फण्ड, सेवा-निवृत्ति वेतन आदि सुविधाओं का समावेश कर सकते हैं।

भारत में श्रम-कल्याण-कार्य की आवश्यकता—

भारतवर्ष में श्रमिकों के हेतु कल्याण-कार्य की बहुत आवश्यकता है। यहाँ का श्रमिक अकुशल है और अन्य देशों की तुलना में उसकी कार्यक्षमता न्यून है। श्रमिकों को सन्तुष्ट और सुखी करने के लिए उनकी परिस्थिति में सुधार करना चाहिए। हमारी दृष्टि में श्रमिकों की वेतन नकद भ्रष्टदूरी बढ़ाने ही से कोई विशेष लाभ न होगा, क्योंकि इससे उनकी नार्थ-निपुणता पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ता। सम्भव है कि नकद राशि को वे जुए और नशे में उड़ा दें। इससे विपरीत यदि कल्याण कार्य के द्वारा उनको लाभ पहुँचाया जायगा तो हमें विश्वास है कि उनकी कार्यक्षमता अवश्य बढ़ेगी।

भारत में श्रम-कल्याण कार्य की आवश्यकता के सम्बन्ध में निम्नलिखित दलीलें दी जा सकती हैं :—

(१) औद्योगिक शान्ति की स्थापना—इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि कल्याण कार्य की विस्तृत व्यवस्था में श्रम एवं पूँजी के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। जब श्रमिक को इस बात का अनुभव होने लगता है कि सेवा-योजक तथा राज्य उनके ही कल्याण के लिए प्रयत्न योजनाएँ कार्यान्वित कर रहे हैं, तो उनके मन में एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो जाता है, जिससे औद्योगिक शान्ति की स्थापना में बड़ा योग मिलता है।

(२) श्रमिकों के उत्तरदायित्व में वृद्धि—श्रम-कल्याण-कार्य की व्यवस्था से श्रमिक यह अनुभव करने लगते हैं कि वे उद्योग के एक अनुयायी हैं। अतः वे संस्था के विकास में विशेष रुचि लेने लगते हैं, उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि की भावना से सेवायोजकों को भी बड़ा लाभ होता है।

(३) सेवाओं का आकर्षक बनना—जिस औद्योगिक संस्था में कल्याण कार्य की योजनाएँ लागू होती हैं, वहाँ की सेवाएँ अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो

भारत में श्रम कल्याण की आवश्यकता

से सम्बन्धित ७ बातें

१. औद्योगिक शान्ति की स्थापना।
२. श्रमिकों के उत्तरदायित्व में वृद्धि।
३. सेवाओं का आकर्षक बनना।
४. औद्योगिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग।
५. मानसिक शान्ति।
६. कार्यक्षमता में वृद्धि।
७. सामाजिक गुण।

जाती है और अधिकांश श्रमिक वही कार्य करना पसन्द करते हैं। इससे स्थायी श्रम शक्ति की वृद्धि होती है।

(४) औद्योगिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग—आज प्रायः सभी विवेकशील सेवायोजक इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि कल्याण कार्य औद्योगिक व्यवस्था का

एक अनिवार्य अंग है। यह श्रमिकों के हृदय में आत्म गौरव की भावना प्रेरित करता है।

(५) मानसिक क्रान्ति—कल्याण कार्य की व्यवस्था श्रम एवं पूँजी की मानसिक क्रान्ति के द्वारा उनके हृदय-परिवर्तन का एक श्रेष्ठ साधन है।

(६) कार्यक्षमता में वृद्धि—कल्याण-कार्य से श्रमिकों की कार्यक्षमता में निश्चय ही वृद्धि होती है।

(७) सामाजिक गुण—अन्त में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि कल्याण कार्य की व्यवस्था से अनेक सामाजिक कुरीतियों का भी निवारण होता है और इस प्रकार समाज भी लाभान्वित होता है। श्रमिक समाज के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। कैंटीन में सस्ते व मनुजित भोजन की सुविधा से श्रमिकों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, स्वस्थ मनोरंजन के द्वारा उनकी अनेक बुरी आदतें (जैसे मदिरापान, जुधा खेलना आदि) दूर हो जाती हैं, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं से श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, इत्यादि।

इन लाभों से ही प्रेरित होकर टेंक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी ने कहा था — “कार्यक्षमता का उन्नत स्तर केवल वही हो सकता है, जहाँ श्रमिक शारीरिक दृष्टि में स्वस्थ तथा मानसिक दृष्टि से सन्तुष्ट हो। इसका तात्पर्य यह है कि केवल वही श्रमिक कुशल हो सकते हैं जिनके लिये शिक्षा, आवास भोजन तथा वस्त्रादि का उचित प्रबन्ध हो। इसी दृष्टि से हमारे देश में बम्बई विश्वविद्यालय ने श्रम समस्याओं एवं कल्याण कार्य के अध्ययन तथा शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किया। श्री टाटा ने भी दान्ते स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एवं सोशल साइन्सेज की स्थापना इसी उद्देश्य से ही की है।

भारत में श्रम कल्याण कार्यों का विकास—

कल्याण-कार्य की भावना वास्तव में एक नवीन स्फूर्ति है, जिसने प्रथम महायुद्ध के पश्चात् से अधिक जोर पकड़ा। प्रथम महायुद्ध युग में जब निर्मित वस्तुओं की माँग बढ़ी, आवश्यक वस्तुओं के दाम चढ़ गए। नगरों में गृह समस्या जटिल हो गई, श्रमिकों की कार्य-क्षमता में कमी आ गई तो ऐसी परिस्थितियों में उद्योगपतियों का ध्यान श्रम-कल्याण की ओर आकर्षित हुआ। सन् १९२२ में बम्बई में एक ग्रहिल भारतीय श्रम कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया था, किन्तु प्रस्ताव पास करने के अतिरिक्त इसने कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया। सचमुच में द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। सर्व-प्रथम उन कारखानों में श्रम-कल्याण-कार्य आरम्भ किये गए जिनमें युद्ध सम्बन्धी सामग्री का निर्माण किया जाता था। सन् १९४२ में, केन्द्रीय सरकार ने एक श्रम कल्याण सलाहकार (Labour Welfare Adviser) नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिये कुछ अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। सन् १९४४ में कोयले की

खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याणार्थ सन्धियम बनाये गये । इस कार्य के लिये एक कल्याण-कोष (Labour Welfare Fund) भी स्थापित किया गया । इन श्रमिकों के लिये टी० बी० अस्पताल में ६ स्थान सुरक्षित कर दिये गये । सन् १९४३ में एक अन्व-अधिनियम अम्रक की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये पास किया गया । सन् १९४७ में उनके ही लाभार्थ एक कल्याण कोष स्थापित किया गया । अन्य अधिनियमों द्वारा सरकार ने काम के घण्टे कम कराये एवं शिशुगृह, मकान, जल इत्यादि का प्रबन्ध कराया । उन कारखानों में जहाँ ५०० से अधिक श्रम-जीवी कार्य करते हैं, श्रम-कल्याण अधिवारी (Labour Welfare Officer) की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है ।

सन् १९४८-४९ में सरकार ने एक श्रम कल्याण कोष स्थापित किया, जिसमें उसकी ओर से १ लाख रुपये का अनुदान दिया गया । इस कोष से उन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जो श्रम-कल्याण-कार्य करती थी ।

कारखाना अधिनियम सन् १९४८ के अनुसार ऐसे प्रत्येक कारखाने में जहाँ २५० से अधिक श्रमजीवी कार्य करते हैं, वंटीन का होना अनिवार्य है ।

सन् १९५२-५३ में मध्य-प्रदेश के चादा नगर में १० स्त्रियों के लिए एक प्रसूतालय बनाया गया । कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ७ बहु-उद्देशीय-कल्याण-केन्द्र और विध्य-प्रदेश में ३ बहु-उद्देशीय कल्याण-केन्द्रों की स्थापना की गई । सन् १९५२-५३ में ही प्रांकीडेण्ट पण्ड योजना चलाई गई, जो पहले बिजली, लोहा व स्पात, इंजीनियरिंग, कागज, कपड़ा, सीमेंट तथा सिगरेट उद्योगों पर लागू की गई । ३१ जुलाई सन् १९५६ को यह योजना १३ अन्य उद्योगों पर लागू की गई और सितम्बर सन् १९५६ को ७ अतिरिक्त उद्योगों पर लागू की गई, जिनमें दिया-सलाई, चीनी, चाय, प्रेस, सीसा, भारी रसायन तथा तेल सम्मिलित हैं । ३१ दिसम्बर सन् १९५६ को समाचार-पत्रों पर तथा १३ जनवरी सन् १९५७ से खनिज तेलों पर भी यह योजना लागू कर दी गई है । अब यह योजना उन सभी उद्योगों पर लागू होती है जिनमें ५० से अधिक श्रमजीवी कार्य करते हैं और जिन्हें स्थापित हुए ३ वर्ष हो चुके हैं ।

सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय-कल्याण मण्डल (Central Welfare Board) स्थापित किया, जो सारे देश में कल्याण-कार्यों का समन्वय करता है । सन् १९५३-५४ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने श्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण के हेतु एक नया विभाग स्थापित किया ।

श्रम कल्याण की दिशा में प्राधुनिक प्रयत्न—

भारतवर्ष में अभी तक जितना भी श्रम-कल्याण किया गया है उसका श्रेय सहायतः तीन संस्थाओं को है :—(I) केन्द्रीय सरकार, (II) राज्य सरकार, (III)

उद्योगपति और (IV) श्रमिक सघ । अब हम इन सस्थाओं द्वारा किये गये कार्य का विशद विवेचन करेंगे ।

(I) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित कल्याण कार्य—

युद्धोपरान्त (सन् १९३९-४५) केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों की ओर ध्यान दिया । उसके पूर्व सन् १९२२ में बम्बई में एक अखिल भारतीय श्रम-हितकारी सम्मेलन के बुलाने के अनिर्दिष्ट कोई महत्वपूर्ण प्रयत्न उसने नहीं किया था, लेकिन अब उसने कुछ ठोस कदम उठाये हैं । सन् १९४२ में एक श्रम हितकारी सलाहकार और उसकी सहायता के अन्य श्रम-हितकारी नियुक्त किए । सन् १९४४ में कोयला खानों के श्रमिकों के लिए एक हितकारी कोष खोला, जिसके द्वारा श्रमिकों के मनोरंजन, चिकित्सा और शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । सन् १९४६ में अभ्रक खान श्रमिक हितकारी कोष अधिनियम पास कर दिया गया । साथ ही, सरकार ने अन्य कानूनों का निर्माण किया, जिनके आधार पर कारखानों के श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था, काम के घंटे, रोशनदान, मशीनों को ढक कर रखना, चिकित्सा, उपहार-गृह और शिशु गृहों की व्यवस्था की गई । देखभाल के लिए निरीक्षक रखे गए । ५०० या इससे अधिक श्रमिक वाले कारखानों में श्रमिक हितकारी अफसर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई । सरकार अपने कारखानों में श्रम हितकारी कोष स्थापित करने के साथ-साथ व्यक्तिगत औद्योगिक कारखानों में कोष स्थापित कराने के प्रयत्न कर रही है । यह कोष श्रमिकों के लिए हितकारी सेवाएँ जुटाने में व्यय किया जाता है । सन् १९५४ में स्थायी श्रम समिति ने भी श्रम-हितकारी कोष की स्थापना पर बल दिया । यह कोष केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित करना चाहिए । इसके अन्तर्गत कारखाने, ट्रामवे, मोटर बस सेवाएँ, आन्तरिक स्टीम जलयान, कोयला व अभ्रक की खानों के अतिरिक्त सब खानें, तेल कूप, उद्यान, जन कार्य, सिंचाई तथा विद्युत सम्मिलित किन्ने गए पावनालय, रेलवे कर्मचारियों तथा बन्दरगाहों पर काम करने वाले श्रमिकों के भी विभिन्न प्रकार की हितकारी सुविधायें कर दी गई हैं ।

योजना कमिशन ने भी श्रम-कल्याण-कार्यों के महत्व को भली भाँति समझा है, अतः उन्होंने पंच-वर्षीय योजना में इन कार्यों के लिए ७ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया था । द्वितीय आयोजन में केवल श्रमिकों के कल्याणार्थ २९ करोड़ रुपये की राशि प. की गई है । प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में १२ लाख घर बनवाये गये । युद्धोत्तर काल में सरकार ने श्रमिकों के लिये सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों, सहकारी गृह निर्माण समितियों, उद्योगपतियों तथा गृह निर्माण बोर्डों को आर्थिक सहायता देकर गृह बनवाये । प्रथम आयोजन काल में कुल ३८५ करोड़ रुपये गृह निर्माण पर व्यय किया गया और द्वितीय आयोजन में १२० करोड़ की व्यवस्था की गई है । उद्यानों तथा अभ्रक व

कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं। ये घर श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत बन रहे हैं। इसी प्रकार ग्राम की ग्रामीय तथा राज्य मंत्रालय अपने अपने विभागों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए घर बनवाने की योजनाएँ चला रहे हैं। द्वितीय आयोजन काल में देश में कुल १६ लाख घर बनवाए जायेंगे।

(II) राज्य सरकारों द्वारा किये श्रम कल्याण कार्य—

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। इस दिशा में कार्य का श्रीगणेश तो प्रथम विश्व युद्ध बाद ही हो गया था और सन् १९३७ में भी कांग्रेसी सरकारों ने इन कार्यों के प्रति बड़ी रुचि दिखाई थी किन्तु कोई सराहनीय कार्य नहीं हो सका। हाँ युद्धोत्तर काल में प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इस ओर गया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तो राज्य सरकारों ने इस दिशा में बड़ा प्रयत्नशील कार्य किया है। अब हम भारत के कुछ औद्योगिक राज्यों में होने वाले श्रम-कल्याण कार्यों पर प्रकाश डालेंगे।

बम्बई राज्य—बम्बई राज्य में श्रम कल्याण के लिये सबसे पहले सन् १९३६-४० के बजट में १२० ००० रु० का आयोजन किया गया था जिससे कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये। सन् १९४६-५० के बजट में इसी कार्य के लिये १० ६० ००० रु० स्वीकार किये गये। सन् १९५१-५२ में इस राज्य में ५४ कल्याण केन्द्र थे—५ क श्रमिकों के ११ ल श्रमिकों के ३६ ग श्रमिकों के और २ व श्रमिकों के। ये चार श्रेणियाँ सुविधाओं के आधार पर बनाई गई हैं। क श्रमिकों के कल्याण केन्द्रों में निम्न सुविधायें प्रदान की जाती हैं—पुण्या के लिए मद्यानी तथा भीतरी खेल स्त्रियाँ की सिलाई तथा कढ़ाई बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल स्त्री-पुरुषों के लिए अलग अलग स्नानागार श्रमिकों के पुस्तकालय वाचनालय तथा माह में १ बार फ़िज दिखाने का प्रबन्ध। ग्राम श्रमिकों के केन्द्रों में सुविधायें कम होती हैं। बम्बई नगर में १८ केन्द्र हैं गोलापुर और अहमदाबाद में ६६ केन्द्र हैं। सन् १९५३-५४ में बम्बई राज्य ने श्रम कल्याण कोष अधिनियम पार कर दिया। श्रम कल्याण के कार्य संचालन के लिए १४ सदस्यों की एक समिति बनाई गई। सन् १९५७ के बजट में ३८ ७८ लाख रुपये का अनुदान देना स्वीकार किया गया जिसमें से २७ ६७ लाख रुपये औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए दिए गए। एक सराहनीय कार्य बम्बई राज्य ने यह किया है कि श्रमिकों में से ही नेताओं का निर्माण किया जाये और इसके लिए उन्हें बम्बई अहमदाबाद तथा गोलापुर में शिक्षा दी जाती है। इसी वर्ष में राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत ५ २७ ४१७ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा इत्यादि की सुविधा प्रदान की गई। श्रम कल्याण कार्यों द्वारा इस प्रदेश के श्रमिकों को काफी लाभ पहुँचा है और उनकी क्षमता में यथेष्ट वृद्धि हुई है।

उत्तर-प्रदेश—इस प्रदेश में सन् १९३७ में प्रथम बार दायर स मजिस्ट्रेट की स्थापना हुई तथा कानपुर में ४ कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये। सन् १९४७ के बाद

इस दिशा में सराहनीय प्रगति हुई है। सन् १९५५ में इस राज्य में श्रम-कल्याण केन्द्रों की संख्या ४४ थी। सुविधाओं के विचार से उनकी ३ श्रेणियाँ की गई हैं— अ, ब और स। प्रथम श्रेणी के केन्द्रों में एक एलोपैथी का चिकित्सालय, पुस्तकालय व वाचनालय, स्त्रियों के लिये सिलाई व कढ़ाई की कक्षाएँ, भीतरी और बाहरी खेल सगीत, रेडियो, प्रसूति-गृह इत्यादि की व्यवस्था होनी है। द्वितीय श्रेणी के केन्द्रों में भी लगभग यही सुविधायें होती हैं। यहाँ होम्योपैथी का चिकित्सालय होता है। तृतीय श्रेणी के केन्द्रों में पुस्तकालय व वाचनालय, खेलकूद तथा रेडियो इत्यादि होते हैं। श्रम-हितकारी केन्द्रों पर मुफ्त में सिनेमा भी दिखाये जाते हैं। कभी-कभी श्रमिकों का कार्यक्रम ग़ज़िल भारतीय रेडियो लखनऊ व इलाहाबाद पर भी होता है। हर्नमेन्ट व दगल आयोजित किये जाते हैं, जिनमें विजेता श्रमिकों को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाता है। चर्खा कक्षायें, प्रौढ शिक्षा कक्षायें तथा स्त्रियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा की कक्षाएँ भी इन केन्द्रों द्वारा चलाई जाती हैं।

सन् १९५४ में कानपुर में श्रमिकों के हितार्थ एक टी० बी० का अस्पताल खोला गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के एक सचल दल का भी निर्माण किया गया है। जुलाई सन् १९५४ में केन्द्रीय सामाजिक हितकारी बोर्ड के आधार पर U P Social Welfare State Advisory Board की भी स्थापना कर दी गई है। यही नहीं, श्रमिकों के रहने के लिए हजारों घरों का भी निर्माण किया गया है। गृह निर्माण कार्य को उत्तर-प्रदेश में तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी के श्रमिकों के लिए कानपुर तथा लखनऊ में क्रमशः २,२१६ व ५६० घर सन् १९५५-५६ में बने, जो श्रमिकों को भी दिए गए हैं। द्वितीय श्रेणी में कानपुर में २,७५० गृहों का निर्माण किया गया है। तृतीय श्रेणी में कानपुर, आगरा, फिरोज़ाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर तथा बनारस में ७,४०० मकान बनाने की योजना है, जिनमें से पाँच हजार घरों का निर्माण हो चुका है। श्रमिक-राज्य-स्त्रीमा योजना, जो सन् १९५० में कानपुर में लागू की गई थी, अब उस नगर के लाखों श्रमिकों को लाभ पहुँचा रही है। सन् १९५५-५६ में आगरा, लखनऊ तथा सहारनपुर में २० हजार श्रमिकों का भी इसके अन्तर्गत ल लिया गया है। स्त्रियों की देखभाल के लिये एक महिला अधिकारी (Women Labour Welfare Superintendent) की नियुक्ति की गई है। उत्तर-प्रदेश की द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत २५३१ करोड़ रुपये की निर्धारित धन राशि में स श्रम-कल्याण पर १४२५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

पश्चिमी बंगाल—सन् १९४० में बंगाल राज्य में १० श्रम कल्याण केन्द्र खोले गये, जिनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते सन् १९४५ में ४१ हो गई। विभाजन के बाद इनकी संख्या ३० रह गई। इन केन्द्रों पर भी चिकित्सा, मनोरंजन, खेल-कूद, शिक्षा और सिलाई आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं। लगभग ४५ हजार व्यक्ति प्रतिदिन इन

केन्द्रों पर जाते हैं तथा लगभग १६,६६४ बच्चे और ६,४४८ प्रौढ प्रात तथा सन्ध्या-कालीन कक्षाओं में शिक्षा पाते हैं। कलकत्ता, हावड़ा तथा सीरामपुर में श्रमिकों के लिये क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं। राज्य में इस समय १५ चिकित्सालय श्रमिकों के लिये कार्य कर रहे हैं। चाय के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये केन्द्रीय चाय बोर्ड ने सन् १९५५-५६ में एक लाख रुपया कल्याण कार्यों के लिये दिया था। इससे मुख्यतः रित्रियों तथा बच्चों का कल्याण होगा। सन १९५७ में पुखरियावाग तथा बाग डामरा में कल्याण केन्द्र और खोले गए हैं, जूट मिला के श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा में काफी सुधार हो गया और उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है।

अन्य राज्य—भारत के अन्य राज्यों में भी श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पंजाब के तमरा (श्रमृतसर, लुधियाना, भम्बाला, बटाला, जालन्धर तथा ग्रन्डुल्ला-पुर) में इनकी स्थापना हुई है। मध्य-प्रदेश में हिंगनघाट, जबलपुर, रवालिपर, उज्जैन, इन्दौर, रतलाम में—भद्रास में नीलगिरि, कोयम्बटूर तथा करियार रोड (उडीसा), राजस्थान में गगानगर, जोधपुर और वृष्णागढ़ में भी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रम कल्याण कार्यों की ओर केन्द्रीय व राज्य सरकार का ध्यान बढ़ता ही जा रहा है। भारत का प्रत्येक राज्य अपने को कल्याणकारी राज्य (Welfare State) कहता है, किन्तु समस्या की गुरुता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

(III) उद्योगपतियों द्वारा कल्याण कार्य—

सन्धे भरसे की उदासीनता के बाद उद्योगपतियों ने श्रमिकों के प्रति कुछ विशेष जागरूकता दिखाया है, लेकिन उनके श्रम कल्याणकारी प्रयत्न अधिकांश में श्रमिकों के हित के प्रति दया भावना पर आधारित हैं। जहाँ तक उद्योगपतियों के दृष्टि कोण का प्रश्न है, वे अब तक कल्याण-कार्य को श्रमजीवियों को फसाने के लिये एक 'भूग मारीचिका व जाल' के रूप में उपयोग करते रहते हैं। इन कार्यों को करते हुए वे एक प्रकार से श्रमिकों के ऊपर मानो अहसान सा करते हैं। यद्यपि अधिकांश में उद्योग-पति प्राज में बड़े अनुदार हैं और वे कल्याण कार्यों में होने वाले व्यय को अधिक लागत नहीं मानते, किन्तु कुछ उद्योगपति उदार व प्रगतिशील भी हैं, जो इस व्यय को विनियोग समझ कर करते हैं, जो आवश्यक में उनकी बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के रूप में उन्हें पुनः मिल जाता है। अब हम ऐसे ही उद्योगपतियों द्वारा किए हुए कल्याण कार्य की झंकी करेंगे।

सूती वस्त्र मिल उद्योग—

दम्बई में सूती मिलों में चिकित्सालय जलपानगृह स्थापित किये गये हैं। कुछ मिलों में आधुनिकतम अस्पताल भी हैं। इनके अतिरिक्त बाहरी भीतर खेलों की सुविधा, सहकारी समितियाँ, बाल एवं प्रौढ शिक्षालय, प्रावीडेंट फण्ड की योजना आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी देश के लगभग सभी मिलों में की गई है। इस दृष्टि से

नागपुर का एम्प्रेस मिल, दिल्ली का देहली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स व बिडला कॉटन मिल्स, ग्वालियर का जीवाजी राव कॉटन मिल्स, मद्रास के बकिंगहम एण्ड नार्नाटिक मिल्स, बगलौर का बगलौर बुलियन कॉटन एण्ड सिल्क मिल्स तथा मदुरा मिल्स कम्पनी न अत्यन्त सराहनीय कार्य किये हैं।

जूट-उद्योग—

जूट उद्योग श्रम हितकारी कार्यों को करने वाली एक मात्र सस्था भारतीय जूट मिल सघ है, जिसने हजारीबाग, कनकीनाडा, मीरामपुर, टीटागढ और भद्रेश्वर में श्रम-हितकारी केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों पर बाहरी-भीतरी खेल-कूदों की व्यवस्था की जाती है। सघ की ओर से पाँच प्राथमिक पाठशालायें भी चल रही हैं। जूट मिलों ने व्यक्तिगत रूप में भी हितकारी कार्यों में योग दिया है। सभी जूट मिलों में एक चिकित्सालय है। सात मिलों में प्रसूताओं के लिये क्लिनिक है। ५१ मिलों में शिशुगृह एवं ४५ जूट मिलों में जलपान गृह खोले गये हैं।

ऊनी मिलों में बड़े कारखानों में सभी उत्तम व्यवस्थायें उपलब्ध हैं और छोटी मिलों में न्यूनतम कानूनी सुविधाओं का प्रबन्ध है।

इजीनियरिंग उद्योग में १,००० या इससे अधिक श्रमिक वाले सभी कारखानों में चिकित्सालय हैं। जहाँ-जहाँ स्त्री श्रमिक हैं वहाँ शिशु गृह भी बने हैं। जलपान-गृह तो सभी कारखानों में मिलेंगे। १०० से ऊपर श्रमिक वाले कारखानों में प्रॉवीडेंट फण्ड योजना लागू है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर विशेष उल्लेखनीय है। इसमें ४०० पलङ्ग वाला अस्पताल, प्रसूतागृह एवं ६ प्रसूति क्लिनिक है। कम्पनी की ओर से ३ हाईस्कूल, १० मिडिल स्कूल और २५ प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं। २ बड़े जलपान-गृह हैं। विशाल क्रीडा-स्थल, भुफ्न सिनेमा, सहकारी उपभोक्ता भण्डार व डाकखाने आदि की आदर्श व्यवस्था है। अन्य कारखानों में भी इसी प्रकार व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कोयला तथा श्रमिक की खानों में श्रमिक हितकारी कोय कानून द्वारा बनाये जा चुके हैं, जिनके अन्तर्गत अनेक श्रम हितकारी कार्य किये जा रहे हैं। कोलार की सोना खानों में भी श्रम हितकारी कार्य हो रहे हैं। आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के अधिकांश बड़े चाय उद्योगों में बड़े-बड़े अस्पताल बने हैं। इनमें अभी जो व्यवस्थायें की गई हैं, वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं। इसी प्रकार की न्यूनाधिक व्यवस्थायें अन्य उद्योगों में भी की गई हैं, परन्तु श्रमिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए ये अत्यन्त अपर्याप्त हैं।

(IV) श्रम-सघों द्वारा किये हुये कल्याण-कार्य—

भारतीय श्रम सघों की शक्ति अभी तक अधिकांशतः अपने धैर्य तथा काम करने की दशाओं के सम्बन्ध में उद्योगपतियों से सघर्ष करने में ही खी रही, अतएव कल्याण कार्य की दिशा में रचनात्मक कार्य करने के लिए उन्हें कम सुअवसर मिला। यही नहीं, दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी वे इस दिशा में कुछ करने में

असमर्थ रहे। जब श्रमिक स्वयं अपना पैट नहीं भर सकता तो उससे सघ किस प्रकार सम्पन्न हो सकते हैं? कल्याण-कार्य की व्यवस्था के लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी कुछ श्रम-सघों ने इस दिशा में अनुकरणीय कार्य किये हैं, जिनमें से अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल श्रम-सघ, मजदूर-सभा कानपुर एवं मिल मजदूर सघ इन्दौर के नाम उल्लेखनीय हैं।

अहमदाबाद टेक्स्टायल श्रम-सघ—

इस सघ की लगभग ७५% आय कल्याण-कार्यों पर ही व्यय होती है। इस सघ के तत्त्वावधान में २५ ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहाँ श्रमिक एकत्रित होकर सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक पुस्तकालय तथा वाचनालय है। इसके अतिरिक्त यह ७५ सहायता-अनुदान प्राप्त वाचनालयों एवं सचल पुस्तकालयों का भी संचालन करता है। अहमदाबाद की प्रमुख श्रम बस्तियों में क्रीडास्थल भी सघ की ओर से स्थापित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत श्रम-सदस्यों की धिक्रिस्ता के लिए एक एलोपैथिक, एक होमियोपैथिक तथा एक आयुर्वेदिक औषधालय है। सघ द्वारा संगठित ६ शिक्षा संस्थायें भी नगर में चल रही हैं, जिनमें से ६ स्कूल, २ अध्ययन भवन (Study Homes) तथा एक बालिकाओं के लिए छात्रावास है। प्रति वर्ष श्रमिकों के बच्चों को सहायता देकर उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सघ द्वारा संगठित चार व्यावसायिक प्रशिक्षणशालाएँ भी हैं। सन् १९५२ में इस सघ ने एक बैंक तथा एक सहकारी उपभोक्ता भण्डार भी खोला। इस निर्वरण से स्पष्ट है कि अहमदाबाद श्रम-सघ ने कल्याण-कार्य की दिशा में सराहनीय कार्य किया है।

कानपुर मजदूर-सभा ने भी मजदूरों के कल्याणार्थ पुस्तकालय, वाचनालय तथा चिकित्सालय की स्थापना की है। इन्दौर मिल मजदूर सघ ने श्रम कल्याण केन्द्र की स्थापना की है। इस केन्द्र की तीन शाखाएँ हैं—बाल मन्दिर, महिला मन्दिर तथा कन्या मन्दिर। बाल मन्दिर में श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, उनके लिए स्वास्थ्य, खेल-कूद व क्रीडास्थल आदि तथा सांस्कृतिक विकास के लिए संगीत, नृत्य तथा अभिनय इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। कन्या मन्दिर में श्रमिक बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा, खेल-कूद व स्वास्थ्य, सिलाई-कढ़ाई तथा अन्य गृह-विज्ञान सम्बन्धी बातों के पढ़ाये जाने, आदि की व्यवस्था है। महिला मन्दिर में महिलाओं के हेतु प्रौढ-शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

उपयुक्त श्रम-सघों के अतिरिक्त देश के रेल कर्मचारी सघ भी अपने सदस्यों के लिए कल्याण-कार्य की व्यवस्था करते हैं—जैसे, क्लब खोलना, सहकारी समितियों की स्थापना करना, मुकद्दमों की पैरवी करना इत्यादि। उत्तर-प्रदेश में भारतीय श्रम सघ (Indian Federation of Labour) ने अनेक श्रम कल्याण-केन्द्रों की

स्थापना की है। आसाम के चाय के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार की सह्यता से 'श्रविल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस' ने कुछ श्रम-कल्याण-कार्यों का आयोजन किया है। अन्त में, हम यह कह सकते हैं कि अब श्रमिक वर्ग काफी जागरूक हो गया है और वह स्वयं सघीय शक्ति से अपने पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा है, किन्तु अभी तक श्रमिक-सघों ने जो कुछ भी किया है, उसे सन्तोषजनक एवं पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र-संघ एवं भारत में श्रम-कल्याण-कार्य—

संयुक्त राष्ट्र-संघ विश्व के सभी देशों के श्रमिकों के कार्यों में रुचि रखता है। इस संस्था ने भारत तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के श्रमजीवियों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए सराहनीय कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय बालकों के कल्याणार्थ मार्च सन् १९५४ तक लगभग ६० लाख डालर व्यय किया। भारत की प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याण-कार्यों का संयुक्त राष्ट्र संघ के मातृ तथा कल्याण-कार्यों से सम्बन्धित एक योजना से समन्वय कर दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५५-५६ में स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा दाइयों के प्रशिक्षण तथा उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सज्जा से सुसज्जित करने में २० लाख डालर व्यय किये गये।

संयुक्त राष्ट्र सघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सङ्कट कोष (U. N. I. C. E. F. —United Nations International Children's Emergency Fund) भारत में माताओं तथा बच्चों को दूध वितरित करने तथा प्रसूतिपूर्व एवं बात कल्याण-केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। इसमें से १० लाख डालर दूध-निर्धारण, मलेरिया-नियंत्रण एवं दुर्भिक्ष निवारण पर व्यय किया जा चुका है। इस धन का अधिकांश भाग भारतीय गाँवों तथा श्रमिक बस्तियों में व्यय हो रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को कोष-राशि में से उनका भाग देती है। इसमें से पश्चिमी बंगाल को १.२५ लाख डालर, केरल को १.१० लाख डालर, बिहार को २ लाख डालर तथा उत्तर-प्रदेश को भी २ लाख डालर दिये जा चुके हैं। ये राज्य सरकारें पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्यों की अपनी योजनाओं पर इस धन का उपयोग माताओं तथा बच्चों के कल्याण-कार्यों पर कर रही है। गाँवों के लिए दाइयों को प्रशिक्षित करके उन्हें सज्जा (Kit) प्रदान करना, योजना का मूल उद्देश्य है। इस सज्जा में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित होंगी, जिनकी कि प्रसव के समय आवश्यकता पड़ सकती है। उक्त संस्था ने ऐसी १४,००० सज्जाएँ विश्व के २७ राष्ट्रों को देने की योजना बनाई है, जिसमें अबले भारत को ६,००० सज्जाएँ मिलेंगी। आशा ही नहीं, वरन् पूर्ण विश्वास है कि इन प्रयत्नों से भारतीय श्रमिकों को बड़ा लाभ होगा। इस समय श्रमिक-बस्तियों में मातृ-

मृत्यु तथा बाल-मृत्यु के ऊँचा होने के कारण अपार मानव सहार हो रहा है, अतएव इस योजना के परिणामस्वरूप सहार न होकर मानवीय कल्याण की वृद्धि होगी ।

पञ्च-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत श्रम कल्याण

(I) प्रथम पञ्च वर्षीय योजना में श्रम-कल्याण—

प्रथम पञ्च वर्षीय योजना में श्रम कल्याण के लिये ६२१ करोड़ रुपये आयोजित किए गये थे । चाय बागाना के श्रमिकों के हितार्थ के द्रीय चाय मण्डल (Central Tea Board) को ४ लाख रुपये दिये गये थे । ७६,६७६ क्वार्टर बनवाने की योजना स्वीकार की गई थी, जिनमें से १६,१६५ बम्बई में, २१,७०६ उत्तर-प्रदेश में, ५,६२६ हैदराबाद में ५,१८१ मध्य-प्रदेश में और ३,४४४ मध्य भारत व अन्य राज्यों में बनाये जाने थे । प्रथम योजना के अन्त तक ४०,००० मकान बन कर तैयार हो चुके थे ।

मई सन् १९५४ में सरकार ने १२८ घरों के निर्माण के लिए १,६७,६५० रुपये का अनुदान दिया था । इसमें से १८,६०० रुपये बम्बई राज्य को दिये गये और इसमें प्रतिरिक्त ३७,८०० रुपये ऋण के रूप में दिय गये थे । जुलाई सन् १९५४ में आंध्र प्रदेश की चीनी मिल को १०१,०५० रुपये का अनुदान और १,५८ ३४२ रुपये का ऋण दिया गया । इसी योजना के अन्तर्गत अगस्त सन् १९५४ में केन्द्रीय सरकार ने १०,२२६ मकानों के निर्माण के लिए ३,१४,३५,२६७ रुपये की आर्थिक सहायता दी, जिसमें से उत्तर प्रदेश को लगभग २ करोड़ रुपये मिले थे । निम्न तालिका से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने मकानों का निर्माण किया गया —

नगर	मकानों की संख्या
कानपुर	३,४००
आगरा	१,२६६
फिरोजाबाद	१,०००
सहारनपुर	६०४
इलाहाबाद	५०४
बनारस	५००
मिर्जापुर	६६

योग ७४००

बम्बई राज्य को श्रमिकों के क्वार्टर बनवाने के हेतु १,०७,४६००० रुपये दिये गये थे, जिनसे २,३८८ क्वार्टर बनवाये गये हैं ।

प्रथम पञ्च-वर्षीय योजना के अन्तर्गत ३५२ कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गई ।

(II) द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याण-कार्य—

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत थ्रम कल्याण कार्यों के लिये २६.१६ करोड़ रु० का आयोजन किया गया था—केन्द्रीय सरकार के लिये १८ करोड़ रु० व क्षेत्र प्रदेशीय सरकारों के लिये। थ्रमिकों के क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये ५० करोड़ रु० पृथक् में आयोजित थे और चाय बागानों के थ्रमिकों के लिये ११,००० मकान बनाने के हेतु २ करोड़ रु० भी उक्त राशियों से अलग थे। 'खान थ्रम कल्याण कोष' (Coal Mines Labour Welfare Fund) में ८ करोड़ रु० गृह निर्माण पर व्यय किये जाने थे।

थ्रमिकों का जीवन स्तर ऊँचा करने, एकता और सफाई की ओर उनकी रुचि बढ़ाने के लिये एक नई शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। जुम्मा खेलने, शराब, ताड़ी तथा अन्य मादक वस्तुओं की लत छुड़ाने के लिये फिल्मों द्वारा शिक्षा देना अधिक हितकारी होगा। इस हेतु सन् १९६०-६१ तक १०० फिल्म (Audio Visual Films) तैयार होने की आशा है। कारखानों के थ्रम कल्याण विभाग और राजकीय थ्रम कल्याण केन्द्र ऐसे फिल्मों के दिखाने का प्रबन्ध करते हैं।

सन् १९५६ में औद्योगिक शिक्षा के लिये १०,३०० व्यक्तियों को सुविधायें प्राप्त थीं। द्वितीय योजना अवधि में १६,७०० व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये अधिक प्रबन्ध किया गया। प्रशिक्षण की अवधि भी बढ़ा दी गई है। काम सीखने की 'शिप्यत्व योजना' (Apprenticeship Scheme) चलाई गई। इसके अन्तर्गत सन् १९६०-६१ तक लगभग ५,००० व्यक्ति भरती किय गये। यह ट्रेनिंग उद्योगों की आवश्यकतानुसार २ से ५ वर्ष तक चलेगी। ट्रेन्ड व्यक्तियों द्वारा कारखानों में कार्य करने पर उत्पादन स्वभावतः बढ़ जावेगा।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत १,३२० थ्रम कल्याण केन्द्र खोले गये।

(III) तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत—

तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत मैंगेनीज एब लोहा खानों के लिये विशेष कोष स्थापित किये गये हैं। ऐसे ही कोष कौयला व अभ्रक खानों के लिये पहले ही संगठित किये जा चुके हैं। ये थ्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी कार्य करने के लिये धन की व्यवस्था करते हैं।

उपसंहार—

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में थ्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने तथा उनके लिये कल्याण कार्यों की व्यवस्था के बहुत कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं। किन्तु समस्या की गम्भीरता व गुरुता को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में अभी तक जो कुछ भी किया गया है वह बहुत ही थोड़ा है। सच बात तो यह है कि विभिन्न थ्रमिक सनियमों में दी गई कल्याण सुविधाओं का न्यूनतम भी आज थ्रमिकों को अधिकांश में नहीं मिल पाता। अतः सर्व प्रथम तो पूर्व-स्थित सनियम

को ही सच्चे अर्थ में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । दूसरे, श्रमिकों की समस्या को सुलभाने के लिए यह भी निरन्तर आवश्यक है कि एक मानवीय दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाय । तभी भारतीय श्रमिक विद्व के अन्य देशों के श्रमिकों के समान निपुण न घलिष्ट होकर देश का आर्थिक उत्थान कर सकेंगे ।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Define the scope of 'Labour Welfare Work' and discuss its importance in India
- 2 State briefly how welfare work has developed in India Describe briefly the welfare activities undertaken by the various agencies in India for labouring classes
- 3 How far has the United Nations' Organisation promoted labour welfare in India ?
- 4 Briefly summarize the welfare work done by the trade union organisations in India
- 5 Please try a short note on labour welfare under the First and Second Five Year Plans in India

— — —

अध्याय ३२

सामाजिक सुरक्षा

(Social Security)

सामाजिक सुरक्षा क्या है ?—

सामाजिक सुरक्षा वर्तमान युग की एक नवीन विचारधारा है । आज कोई भी स्वतन्त्र देश अपनी उन्नति की किसी भी योजना में सामाजिक सुरक्षा का समावेश किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि इसके बिना बेकारी, बीमारी एवं रोग का उन्मूलन सम्भव नहीं है । वैसे तो सामाजिक सुरक्षा का आयोजन मूलतः औद्योगिक श्रम-जीवियों के

लिए किया जाता है, किन्तु अब सर्वमंगलकारी राज्य (Welfare State) का निर्माण करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा में केवल श्रमजीवियों को ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे सम्पूर्ण समाज को लाभ हो सके।

साधारण शब्दों में, सामाजिक सुरक्षा से आशय ऐसी पद्धतिमुक्त योजना से है जिसके द्वारा 'आवश्यकता', बीमारी 'इज्जानता' 'पिजूषर' और 'बेकारी' इन पाँचो दानवों पर विजय मिले।^१ श्री जी० डी० एच० कोल के विचारानुसार सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य है कि सरकार जो समाज का प्रतीक एवं प्रतिनिधि है, अपने समस्त नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन-स्तर स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। यह स्तर इस आधार पर हो कि उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी व्यक्ति के जीवन की सब मुख्य आवश्यकताएँ (Contingencies) सम्मिलित हों।^२ सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र सचमुच बड़ा व्यापक है।^३ वास्तव में आवश्यकता है 'गर्भ से मरण तक' (From womb to the tomb) सुरक्षा की। गर्भ में शब्दों को प्रसूति सम्बन्धी सुविधाय और गर्भ से बाहर आने पर उसके पालन-पोषण एवं भोजन की सुविधा होनी चाहिये, इसके बाद शिक्षण की सुविधा, फिर काम आदि की। इसमें उस समय की सुरक्षा भी सम्मिलित होती है जबकि मनुष्य काम पर न लगा हो अथवा वह बेकार या विस्थापित हो।

अन्य देशों में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति —

सामाजिक सुरक्षा की विचारधारा का विकास सर्वप्रथम जर्मनी में सन् १८८१ में हुआ, जबकि इस विचार चक्र को विलियम प्रथम ने प्रारम्भ किया तथा प्रिंस ऑफ विस्मार्क ने प्रोत्साहन दिया। फलस्वरूप सन् १८८३ में बीमारी के बीमे का सन्धियम (Sickness Insurance Act) बना तथा क्रमशः श्रमजीवी क्षति पूर्ति, वृद्धावस्था एवं अपंग आश्रय का आयोजन करने के लिये सन् १८८४, १८८६ और सन् १९२५ में अधिनियम बनाये गये। इसके उपरान्त इस विचारधारा का विकास अन्य उन्नत एवं औद्योगिक राज्यों (जैसे, इंग्लैण्ड, अमेरिका, रूस आदि) में भी हुआ। वहाँ औद्यो-

1 "Social Security in simple terms means the elimination of the five evil giants, viz, want, disease, ignorance, squalor and idleness"

2 "The idea of social security put broadly is that the State shall make itself responsible for ensuring a minimum standard of material welfare to all its citizens on a basis wide enough to cover all the main contingencies of life"—G D H Cole

3 "Sir William Beveridge in his famous report on Social Security emphasizes the wide scope of 'social security' measures when he says 'What is only one of the five giants on the road of reconstruction and in some way the easiest to attack.'"

श्रमिक श्रमिक के लिये सुविधाओं का पर्याप्त आयोजन है, विशेषकर इंग्लैण्ड में तो बीवरिज योजना के अन्तर्गत मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक उसकी सुरक्षा का भार सरकार ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया है। बीवरिज योजना सामाजिक सुरक्षा की एक पूर्ण तथा आदर्श योजना है। इसमें सम्पूर्ण जनता के लिये प्रसूति सुविधाओं से लेकर शव सस्कार की सहायता तक का आयोजन किया गया है। यह समाज के प्रत्येक मनुष्य, स्त्री और बच्चे के लिए आभारनी की सुरक्षा व हेतु एक योजना है और जीवन की सभी घटनाओं—जन्म, बचपन, शादी, बुढ़ापा, मृत्यु बेकारी, दुर्घटना, बीमारी आदि से साबन्धित है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक मनुष्य देता है और प्रत्येक मनुष्य प्राप्त भी करता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा

भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता—

भारत में सामाजिक सुरक्षा की महिमा के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाय, कम ही होगा। भारतीय श्रमिकों की दशा अत्यन्त खोचनीय है। औद्योगीकरण के सभी खतरों का उन्हें भागना करना पड़ रहा है, जैसे—बीमारी, बेकारी आदि। हमारे श्रमजीवियों में संगठन की भी बहुत कमी है, वे अशिक्षित, अज्ञाना एवं दरिद्र हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना उन्हें नहीं आता। इस दृष्टि में अन्य उद्योगशील देशों की अपेक्षा भारतीय श्रमिकों की दशा अधिक खराब है अतएव सामाजिक सुरक्षा का आयोजन अनिवार्य हो जाता है।

भारत में अभी तक क्या हुआ ?—

भारत में स्वास्थ्य बीमे की आवश्यकता सर्वप्रथम सन् १९२७ में अनुभव की गई, जबकि लगभग २ वर्ष पूर्व सन् १९२५ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय में औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, किन्तु फिर भी कोई वास्तविक कार्यवाही उस समय नहीं की गई। तत्पश्चात् सन १९३०-३१ में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पर रायल कमीशन ऑफ लेबर ने जोर दिया एवं स्वास्थ्य बीमे पर एक योजना की रूपरेखा भी तैयार की। दुर्भाग्यवश उस समय वह योजना साफ़ में रख दी गई। सन १९४० में अनिवार्य चन्दे द्वारा बीमारी आगोप की योजना बनाने का निश्चय किया गया। तृतीय श्रम-मन्त्री सम्मेलन ने इस योजना के सम्बन्ध में यह निश्चय किया कि बस्त्र व्यवसाय तथा इजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों को बीमारी सम्बन्धी बीमे की सुविधा दी जायें। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए बी० पी० अद्वारकर की नियुक्ति की गई। प्रोफेसर अद्वारकर ने अपनी रिपोर्ट सन १९४४ में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 'कर्मचारी राजकीय बीमा सन्निधय' बनाया गया, जो सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिये एक ठोस कदम है।

सामाजिक सुरक्षा के लिये वर्तमान समय में निम्नलिखित आयोजन है :—

(I) श्रमिक क्षति-पूर्ति अधिनियम ।

(II) कोल माइन्स प्रॉवोडेन्ट फण्ड एण्ड बोनस स्कीम एक्ट ।

(III) मातृत्व लाभ अधिनियम ।

(IV) प्रॉवोडेन्ट फण्ड एक्ट सन् १९५२ ।

(V) श्रमिक राज्य बीमा अधिनियम ।

(I) श्रमिक क्षति पूर्ति अधिनियम सन् १९२३—

यह अधिनियम (संशोधनों सहित) अब जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत में लागू होता है । जिन कर्मचारियों का वेतन ४००) मासिक से अधिक है अथवा जो क्लर्क है, उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता । वास्तव में रेल, कारखाने, खाने, नाविक व समुद्र पर काम करने वाले कुछ अन्य श्रमिकों, डाक या तार, नहर, चाय, रबड़, कच्चा तथा मिनकोना के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों, विद्युत, स्टेशनों, गोशालों, वेतन पाने वाले, मोटर ड्राइवरों आदि तथा ऐसे सभी कारखानों जहाँ १० या इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं तथा शक्ति का भी प्रयोग होना है एवं ऐसे कारखानों में जहाँ शक्ति का प्रयोग तो नहीं होता, किन्तु ५० या अधिक श्रमिक काम करते हैं, यह अधिनियम लागू होगा है । राज्य सरकारें इसे किसी भी क्षेत्र के श्रमिकों पर, यदि वे इनके काम का स्तरनाक सम्भरना है, लागू कर सकती हैं । मद्रास एवं उत्तर-प्रदेश सरकारों ने इस भगोन से चलन वाली गाड़ियों, माल लादने तथा उतारने वाले श्रमिकों और विद्युत प्रयोग करने वाले सभी कारखानों पर लागू कर दिया है । जो श्रमिक राज्य बीमा अधिनियम या श्रमिकों के राज्य बीमा कॉरपोरेशन की ओर से मुआविजा पाने का अधिकारी है, वह इस अधिनियम का लाभ नहीं उठा सक्ता ।

यदि श्रमिकों को काम करते समय किसी दुर्घटना से कोई चोट लग जाये तो मालिक द्वारा हर्जाना दिया जायगा । यदि चोट ७ दिन से पहले ठीक होने वाली हो या जिनमें श्रमिक का दोष हो और मृत्यु न होने पावे तो मालिक कोई हर्जाना देने के लिए बाध्य नहीं । अधिनियम की सूची नं० ३ में दिया हुआ कोई व्यावसायिक रोग हो जाने पर भी हर्जाना दिलाया जायगा, हजाने की मात्रा चोट के प्रकार एवं श्रमिक की मासिक मजदूरी पर निर्भर होती है ।

यह अधिनियम बड़ा संशोधन की वस्तु है । आवश्यकता इस बात की है कि उसे अधिक से अधिक श्रमिकों पर लागू किया जाय और हजाने की रकम नियमित रूप से दिलाई जाय । इस अधिनियम के आधार पर श्रमिकों के हर्जाना सनियम कुछ राज्यों में भी पास किये गये हैं ।

(II) कोयला खान प्रॉवोडेन्ट फण्ड योजनाएँ—

इन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों को अपनी वार्षिक मजदूरी के ६ १/४% की

दर से चम्दा देना पड़ता है। इस आशय ने लिए बेसिक मजदूरी में महगार्ह भत्ता, नगद व वस्तुओं के रूप में अन्य रियायतें भी सम्मिलित की जाती हैं। मेवायोजकों को भी श्रमिकों के बराबर चम्दा देना पड़ता है। यह योजना आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, म प्र०, उड़ीसा, राजस्थान व प० बंगाल को लागू होती है। पन्ड की कुल राशि अबतक सन् १९६० में २३ करोड़ थी।

(III) मातृत्व लाभ अधिनियम—

भारत में एक बड़ी सख्या में स्त्रियाँ मजदूरी करती हैं। प्रसव-काल से पहले और बाद में विश्राम एवं पीष्टिक भोजन न मिलने के कारण उनकी बड़ी सख्या में मृत्यु होती है। बच्चों की मृत्यु सख्या बढ़ने का कारण भी यही है। मातृत्व लाभ की समस्या मानवता एवं सामाजिक पहलू से ही नहीं, अपितु आर्थिक पहलू में भी महत्वपूर्ण है। इतने पर भी भारत में अभी तक कोई ऐसा अधिनियम अखिल भारतीय स्तर पर नहीं बनाया गया है जो मातृत्व लाभ की सुविधायें प्रदान करता हो। भारत में अभी तक जो प्रयत्न हुये हैं वे व्यक्तिगत राज्यों में ही हुए। सर्व प्रथम बम्बई में मातृत्व लाभ अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद रायल श्रम कमीशन के सुझावों पर अन्य प्रान्तों ने भी जैसे, मद्रास (सन् १९३४), उत्तर-प्रदेश (सन् १९३८), बंगाल (सन् १९३९), पंजाब (सन् १९४३), आसाम (सन् १९४४), बिहार (सन् १९४५) ने भी इन अधिनियमों को बनाया। केन्द्रीय सरकार ने (सन् १९४१ में) काम करने वाली स्त्रियों के लिये मातृत्व लाभ अधिनियम बनाया। अब लगभग सभी राज्यों में ये अधिनियम बन चुके हैं।

मातृत्व लाभ अधिनियमों के अन्तर्गत स्त्रियों को प्रसव के पहले और बाद में लाभ दिया जाना लगा है। लाभ की दर और समय की अवधि भिन्न भिन्न प्रान्तों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिये, आसाम में १५० दिन काम करने पर, बिहार और उत्तर-प्रदेश में ६ महीने काम करने पर, महाराष्ट्र व गुजरात, बंगाल, पंजाब और मध्य-प्रदेश में ६ महीने काम करने पर तथा मद्रास में २४० दिन काम करने पर ही कोई स्त्री लाभ प्राप्त कर सकती है। लाभ की दर भी भिन्न भिन्न है। आसाम के साथ उद्योगों में प्रसव के पहले १) तथा बाद में १।) प्रति सप्ताह है, जिसकी कुल धन राशि १४) से अधिक नहीं होनी चाहिये। बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र व गुजरात, बिहार तथा उत्तर-प्रदेश में न्यूनतम १।) प्रति दिन है। पंजाब में १२ आना प्रति दिन या अनुपातिक दैनिक आय रखी गई है।

रूपे तथा विश्राम के अलावा बीमर और डाक्टरों महायता के रूप में अन्य लाभ भी स्त्री श्रमिकों को दिये जाते हैं। काम करते समय शिशुओं को रखने के लिए शिशु-गृहों की भी व्यवस्था है। उत्तर-प्रदेश का अधिनियम स्त्रियों के गर्भपात होने पर ३ सप्ताह सैवतनिक छुट्टी की आज्ञा देता है।

इन अधिनियमों का पालन कराने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। मालिकों को प्रति वर्ष इन लाभों की रिपोर्ट सरकार को भेजनी पड़ती है। फिर भी

यह कहना पड़ेगा कि इन अधिनियमों में कुछ दोष हैं। मालिकों पर ही लाभ देने का उत्तरदायित्व होने से ये लोग इसमें अनियमितता करते हैं। लाभ का रूप रुपये में होने में स्त्रियाँ दूष, औषधि आदि से वंचित रह जाती हैं। गर्भवती होमों का बर्माचार मिलने पर मालिक स्त्री को अलग कर देते हैं या कुमारियों को ही नौकरी पर रखते हैं। बहुत सी स्त्रियों के नाम ही रजिस्टर में नहीं लिखते। इन शोषों को दूर करना स्वतन्त्र भारत की चहुँमुखी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है।

प्रसूति संरक्षण के लिये एक समान स्तर निर्धारित करने के उद्देश्य से लोक-सभा में प्रसूति लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Bill), १९६० रखा गया था। यह उन सभी कारखानों, खानों व बागानों को लागू होगा जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता।

(IV) कर्मचारी प्रॉवीडेंट फंड—

कर्मचारी प्रॉवीडेंट बीमा फंड अधिनियम, १९५२, जो पहले मूलतः ६ प्रमुख उद्योगों को लागू होता था, अब ४१ अन्य उद्योगों को भी लागू होता है, जिनमें बागान (आसाम के चाय बागानों को छोड़कर), खाने, अखबार, बियासमाई के कारखाने, सड़क मोटर यातायात संप्रदान आदि मुख्य हैं। अधिनियम उन्हीं कारखानों व संस्थानों को लागू होता है जो कि अनुसूचित उद्योगों में कार्य-सलग हैं और जिनमें ५० या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तथा जो ३ वर्षों से अधिक पुराने हो गये हैं। जो श्रमिक १ वर्ष तक लगातार काम करते रहे हैं या एक वर्ष में कम से कम २४० दिन कार्य किया है और जिनकी मासिक मजदूरी (मंहगाई भत्ता व राशन का नक्द मूल्य सहित) ५०० रु० प्रति माह न, अधिक नहीं है, उनको अनिवार्य रूप से फंड में अपनी वार्षिक मजदूरी के ६.३% की दर से चन्दा देना पड़ता है। सेवायोजक को भी इतनी ही रकम ऐम श्रमिकों के सम्बन्ध में देनी पड़ती है। नवम्बर सन् १९६० तक उक्त अधिनियम ८,००० संस्थाओं में लागू हो रहा था। फंड में चन्दा देने वाले श्रमिकों की संख्या २८ लाख थी तथा प्रॉवीडेंट फंड चन्दों की रकम २५० ३५ करोड़ रु० थी। ६३.६६ करोड़ रु० फंड से ऋण रूप में या दावों के भुगतान में दिया गया। इस प्रकार १८६ ६६ करोड़ रु० (व्याज सहित) शेष रहा। एक विशेष रिजर्व फंड भी बनाया गया है, जिसमें से मृत्यु व स्थायी असमर्थता की दशा में लाभ दिया जायेगा।

उक्त अधिनियम को सन् १९६० में संशोधित किया गया। इस संशोधन के निम्न उद्देश्य थे :—(1) एकट को २० या अधिक कर्मचारी रखने वाली छोटी इकाइयों को लागू करना, (ii) १ वर्ष तक संस्थाओं पर एकट लागू रखने की अवधि बढ़ाना जबकि न्यूनतम कर्मचारी संख्या १५ तक गिर जाय, (iii) किसी संस्थान की शाखाओं व विभागों को एक ही संस्थान मानना, (iv) श्रमिकों के चन्दों की गणना के लिये मौसमी कारखानों में Retaining allowances को भी सम्मिलित करना,

(v) ५० से कम कर्मचारी रखन वाली सहकारी मस्थानों का मुक्त रखना, और
(vi) २० से ५० तक थमिक रखने वाले छोटे कारखानों को अधिनियम के दायित्व से मुक्त करना ५ वर्ष तक ।

(V) श्रमिकों का राज्य बीमा अधिनियम —

यह अधिनियम भारत के सब राज्यों पर लागू होता है । यह सन्निधम ऐसे स्थायी कारखाना क उन श्रमिकों एवं बलकों पर लागू होता है जिनकी मासिक आय ४००) तक है और जो फैक्टरी एक्ट क अन्तगत आते हैं । इसमें लगभग २० लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ पहुँच रहा है । इसमें राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे चाह तो इसे अपने राज्य में औद्योगिक, व्यापारिक कृषि एवं अन्य सस्थाओं पर भी लागू कर सकती है । हा इसके लिए उन्हें पहले केन्द्रीय सरकार की मान्यता लेना अनिवार्य होगा । इस स त्रयम के आसार ही दिल्ली में कमचारी राजकीय बीमा प्रमण्डल (Employee's State Insurance Corporation) की स्थापना सन् १९४८ में की गई ।

शासन प्रबन्ध—

यह प्रमण्डल एक शासकीय प्रमण्डल है जिसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नियुक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधि भी होंगे । इसी प्रकार इसमें केन्द्रीय समद एवं डाक्टर पेशे के प्रतिनिधि होंगे । प्रमण्डल का शासन प्रबन्ध एक स्थायी समिति (Standing Committee) के हाथ में है । इसमें भी मालिकों और श्रमिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि हैं । औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में सलाह देने के लिए भा एक डाक्टर परिषद (Medical Benefit Council) बनाई गई है । बड़ अधिकारी वग की नियुक्ति, हिसाब एवं उनकी जाच पादि का अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है ।

प्रमण्डल की अथ व्यवस्था के हेतु एक कर्मचारी राज्य बीमा फंड खोला गया है, जो मालिकों और श्रमिकों के चन्दे से बनेगा तथा इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकार भी सहायता के रूप में कुछ धन राशि दगी । श्रमिकों एवं मालिकों के चन्दे की दर उनकी आय के अनुसार निश्चय की गई है । इस हेतु श्रमिकों को उनकी आय के अनुसार ८ शणियों में बाँटा गया है ।

आगोषित व्यक्तियों को सुविधाएँ—

सामाजिक बीमा की इस योजना क अन्तगत आगोषित व्यक्तियों को पाँच प्रकार की सुविधाय दी जायँगी —

(१) औद्योगिक सम्बन्धी सुविधायें—इस काय के लिए उन स्थानों में जहाँ भी यह योजना लागू होगी, आगोष प्रमण्डल द्वारा औद्योगिकों का आयोजन होगा तथा कुछ चलते-फिरते औद्योगिक रखे जायँगे, जो आगोषित व्यक्तियों के घर जाकर उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी देख भाल करेगे ।

(२) मातृत्व सम्बन्धी लाभ—ये सुविधायें स्त्री-श्रमिकों को प्रसूत सम्बन्धी बीमारी में दी जायेंगी । ऐसी दशा में स्त्री श्रमिकों को १० आना प्रति दिन की दर से अथवा औपधोपचार सम्बन्धी सुविधाओं की दर से (जो भी दर ऊँची हो) १२ सप्ताह तक प्रसूति लाभ मिलता रहेगा तथा गर्भावस्था में औपधोपचार सुविधाएँ दी जायेंगी ।

(३) आरोग्यता लाभ—कारखाने में काम करते समय होने वाली दुर्घटना की वजह से अथवा उस कारखाने से सम्बन्धित किसी रोग का शिकार हो जाने से यदि कोई श्रमिक काम करने के अयोग्य हो जाता है तो उसे आगोप प्रमण्डल द्वारा श्रमजीवी क्षति-पूर्ति सन्नियम के अनुसार सुविधायें प्रदान की जायगी ।

(४) श्रमिकों पर आश्रित व्यक्तियों के लिए लाभ—यदि किसी कारखाने के आगोपित व्यक्ति को कारखाना में होने वाली किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उन आश्रितों को (अथवा उसकी विधवा एवं बच्चों को) वार्षिक वृत्ति (Annuity) के रूप में कुछ राशि दी जायगी ।

(५) बीमारी सम्बन्धी लाभ—इसके अनुसार जिस श्रमिक का बीमा है उसे डाक्टरों प्रमाण-पत्र के आधार पर समय के अनुसार नकद रकमा मिलता है । प्रथम दो दिन तक कुछ नहीं मिलता और उसके बाद यदि १५ दिन तक रोग चलता रहे तो आर्थिक सहायता मिलनी प्रारम्भ हो जाती है । ३६५ दिन के निरन्तर काल में अधिक से अधिक ५६ दिन तक यह लाभ मिल सकता है । इस लाभ की दर श्रमिक के दैनिक वेतन का ३ होगी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अधिनियम बड़ा विस्तृत है । ३१ दिसम्बर सन् १९५२ को कानपुर तथा दिल्ली में इस योजना से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या क्रमशः १,०६,४२२ और ५३,४२४ थी । कानपुर की जन-संख्या के आधार पर श्रमिकों के लिए १३ डिस्पेंसरियाँ इस प्रकार स्थापित की गई हैं कि प्रत्येक श्रमिक को कोई न कोई डिस्पेंसरी पाम पड़े । इनके अतिरिक्त कानपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए दो चलते-फिरते अस्पताल भी हैं, जहाँ पर कुशल चिकित्सक कार्य करते हैं । ११ जुलाई सन् १९५४ से नागपुर में भी योजना कार्यान्वित की गई है । इससे नागपुर में लगभग २५,००० श्रमिक लाभान्वित होंगे । ६ अक्टूबर सन् १९५४ को भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने श्रमिक राज्य बीमा योजना का उद्घाटन सम्बन्ध में किया । इससे ४३ लाख औद्योगिक श्रमिक लाभ उठावेंगे इसी प्रकार मध्य-भारत में इन्दौर, खालियन तथा रतलाम नगरों में भी औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना १४ अक्टूबर सन् १९५४ में लागू की गई है । उत्तर-प्रदेश में प्रागरा, लखनऊ तथा सहायनपुर नगरों में भी राज्य योजना जनवरी सन् १९५६ में लागू कर दी गई है । भारत सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि यह योजना शेष भारत पर भी

लागू कर दी जाय। वास्तव में यह योजना एशिया भर में अपने प्रकार की प्रथम है और देश में पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक शुभ प्रयत्न है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रगति—

सन् १९५८-५९ से इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएँ उनके परिवारों का भी मिलनी शुरू हो गई। सबसे पहले यह निर्णय मैसूर राज्य ने किया। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी उसका अनुकरण किया। सभी राज्यों में (गुजरात और दिल्ली के नव दोष को छोड़कर) लगभग १५ लाख ७० हजार व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सन् १९५९-६० के अन्त में कर्मचारियों का अक्ष दान ४०८ करोड़ ६० और मालिकों का अक्षदान ३१९ करोड़ ६० था। बीमित व्यक्तियों को विभिन्न लाभों के रूप में २६८ करोड़ ६० दिया गया बीमारी लाभ २२२ करोड़, प्रसूति लाभ १३५९ लाख ६०, २९८५ लाख ६० असमर्थता लाभ और २७८ लाख आश्रित लाभ। बीमित कम्पनियों के ४८८ लाख परिवारों को आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य-प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और दिल्ली के सद्यः क्षण में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ दी जा रही हैं।

भारत में रोग बीमा की योजना—

यहाँ श्री अदारकर की रिपोर्ट पर सन् १९४८ में श्रमिक राजकीय बीमा अधिनियम पास किया गया था, जिसका उद्देश्य अन्य लाभों के अलावा बीमारी और प्रसूति के लिये भी श्रमिकों को कुछ लाभ प्रदान करना था। यह सभी कारखानों को लागू होता है। यह उन सब लोगों पर लागू होती है जो मजदूरी पर किसी कारखाने में काम करते हों और जिनकी आमदनी ४००) से अधिक नहीं है। योजना के प्रशासन के लिये एक कारपोरेशन कायम कर दिया गया है। श्रमिक राजकीय बीमा फण्ड में सेवायुक्तों के चन्दों और कन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों स्थानीय सत्ताओं, व्यक्तियों द्वारा दी गई घाट, दान व भेंट की रकमें शामिल की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार कारपोरेशन को प्रथम पाँच वर्षों तक कारपोरेशन के प्रशासन व्ययों के दो-तिहाई के बराबर रकम की वार्षिक ग्रांट देगी। अपना और अपने सेवायुक्तों के चन्दों की रकम चुकाने का भार अधिनियम में यवा-नोजको पर डाल दिया है। हाँ, उस अवधि के लिये कोई चन्दा नहीं लिया जायगा, जिसमें कि कोई सेवा नहीं की गई है और न मजदूरी देनी पड़ी है। बीमिन व्यक्ति को, अधिकतम भुगतान के रूप में, चिकित्सा लाभ पान का अधिकार होगा, यदि एक उचित रूप से नियुक्त चिकित्सक उसकी बीमारी के लिए प्रमाण पत्र दे दे। बीमारी के लाभ की दैनिक दर उसकी औसत दैनिक मजदूरी के आधे के बराबर है। इस लाभ की अधिकतम अवधि २६५ दिन में ५६ दिन है। पहले दो दिनों के लिये कोई लाभ नहीं दिया जाता। हाँ, उस दस्ता में मिल सकता है जबकि श्रमिक १५ दिन के भीतर ही दुबारा बीमार पड़ जाता है।

परन्तु इससे एक बीमित श्रमी श्रमिक को १२ घण्टे प्रतिदिन की दर से

प्रसूति-लाभ दिया जाता है। प्रसूति लाभ की अवधि १२ हफ्ते है। एक बीमित व्यक्ति को, जिसे रोजगार सम्बन्धी चोट के कारण स्थायी या अस्थायी असमर्थता हो गई है, असमर्थता लाभ पाने के अधिकार है।

एक बीमित व्यक्ति को किसी भी सप्ताह के लिये, जिसमें उसने चन्दे दिया है, रोग, प्रसूति या असमर्थता सम्बन्धी लाभ पाने का अधिकार है, चिकित्सा लाभ में निशुल्क चिकित्सा शामिल है, जो कि बीमा डिस्पेन्सरी में इलाज की सुविधा के रूप में या बीमा डॉक्टर को घर पर जाकर देखने की सुविधा या किसी अस्पताल या अन्य संस्था में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा के रूप में हो सकती है। कॉरपोरेशन चाहे तो चिकित्सा लाभ बीमित व्यक्ति के परिवार को भी विस्तृत कर सकता है।

प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों को देखते हुए अभी यह बीमा-योजना देश के प्रमुख-प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में ही लागू की गई है।
भारत के लिए स्वास्थ्य बीमे की योजना—

इस आशय के लिए एक कारपोरेशन बनाया जायेगा, जो कि बीमे के आशय के लिए एक अधिक राजकीय बीमा निधि संचय करेगा, जिसमें सेवायोजकों व सेवा-युक्तों के चन्दे और राष्ट्रीय व प्रान्तीय सरकारों, स्थानीय सत्ताओं, व्यक्तियों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये अनुदान, दान और भेंट शामिल की जायेंगी। प्रथम पाँच वर्षों तक केन्द्रीय सरकार प्रशासन व्यय के दो-तिहाई के बराबर रकम की ग्रांट प्रति वर्ष कारपोरेशन को दिया करेगी। सभी कारखानों व संस्थाओं को यह बीमा योजना लागू होगी। सेवायोजकों पर अपने व अपने अधिकों के चन्दे कारपोरेशन में जमा कराने का भार होगा। हाँ, अधिकों का चन्दा वे उनकी मजदूरी में से काट सकेंगे। जो अधिक १) प्रति दिन से कम मजदूरी पाने हैं उनको चन्दा नहीं पड़ेगा। चन्दा उस अवधि के लिये देय होगा, जिसमें कि मजदूर काम पर लगा हो या छुट्टी पर हो या तालाबन्दी अथवा हड़ताल के कारण काम में असमर्थ था।

बीमित व्यक्ति को बीमारी-लाभ किसी भी लाभ की अवधि में तभी माँगने का अधिकार होगा जब कि उसी चन्दा अवधि में, उसके साप्ताहिक चन्दे रोजगार की अवधि के कम से कम दो तिहाई हफ्ता के लिए देय हो। न्यूनतम १२ चन्दों की सीमा है। बीमारी की अवधि में बीमारी लाभ निधारित दरों से दिये जायेंगे। बीमारी के पहले दो दिनों के लिये कोई लाभ नहीं दिया जायेगा। हाँ, उस दशा में दिया सकता है जबकि १५ दिन के अन्दर वह दुबारा बीमार पड़ जाये। यह लाभ १ वर्ष में अधिक से अधिक ५६ दिन तक लिया जा सकता है। एक बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को जिसकी दशा ऐसी है कि चिकित्सा और देख-भाल आवश्यक है, चिकित्सा-लाभ (Medical benefit) पाने का अधिकार होगा। यह

विक्रित-लाभ या तो बाहरी मरीज (Out patient) के रूप में या डॉक्टर द्वारा घर जाकर अथवा अन्दर-मरीज (In patient) के रूप में इलाज कराने की सुविधा के रूप में दिया जायगा। इसके लिये केन्द्रीय सरकार योग्य डॉक्टर, सर्जन, विशेषज्ञ, विशेष अस्पताल आदि की व्यवस्था करेगी। संयोजक किसी सेवायुक्त को लाभ पाने की अवधि में नौकरी से नहीं निकाल सकेंगे और न सजा दे सकेंगे।

STANDARD QUESTIONS

1. What do you understand by the term "Social Security." ? Discuss its importance with special reference to India
2. Write a critical note on the organisation and working of the Employee's State Insurance Corporation.
3. Briefly describe the principal measures taken by the Government of India in the sphere of social security

अध्याय ३३

श्रम संनियम तथा श्रम नीति

(Labour Legislation & Labour Policy)

श्रम नीति (Labour Legislation)

प्रारम्भिक—

श्रम संनियम वास्तव में २०वीं शताब्दी की देव है। १९वीं शताब्दी में इस सम्बन्ध में जो भी वैधानिक नियम बनाये गये थे वे अधिकांशतः सेवायोजकों के हित में थे, श्रमिकों को उनसे कोई लाभ न था। दृष्टान्त के लिये, आसाम में श्रम सम्बन्धी अधिनियम इस दृष्टि से बनाये गये थे कि सेवायोजकों को पर्याप्त श्रमिक सरलता से मिल सकें, किन्तु बाद में परिस्थितियोंवश श्रमिकों के हित में भी कुछ नियम बनाये

गए। सन् १८६० के पश्चात् बम्बई का वस्त्र व्युत्पत्ति बड़ी तेजी से बढ़ने लगा, जिससे लङ्काशायर के व्यवसायी बड़े घबड़ाये। भारतीय उद्योगपतियों को प्राप्त श्रम-सम्बन्धी सुविधाओं (जैसे, भारत में इंग्लैण्ड की अपेक्षा श्रमिकों से अधिक काम लिया जा सकता था, आदि) से लङ्काशायर के उद्योगपतियों को ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्यावश (परन्तु प्रगटित श्रमिकों के प्रति होने वाले निर्दय व्यवहार के नाम पर) उन्होंने भारतीय श्रमिकों में आन्दोलन प्रारम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम बार सन् १८८१ में श्रमिकों के हित में कारखाना अधिनियम (Factory Act) बनाया गया। तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार इस अधिनियम में अनेक प्रत्यावर्तन हुए तथा अन्य अधिनियम भी बनाये गये, जिनका विवरण इस प्रकार है :—

(I) कारखाना अधिनियम

(१) सन् १८८१ का कारखाना अधिनियम—

- (I) १०० से अधिक श्रमिक एवं शक्ति का उपयोग करने वाले कारखाने पर लागू होना था।
- (II) काम के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु ७ वर्ष रखी गई। सात और बारह वर्ष के मध्य की आयु वाले बच्चों के लिए काम के घंटे (१ घण्टा विश्राम सम्मिलित करते हुए) ६ थे। प्रति माह चार अवकाश दिवसों की भी व्यवस्था थी।

(२) सन् १८९१ का कारखाना अधिनियम—

- (I) ५० अथवा अधिक श्रमिक एवं शक्ति का प्रयोग करने वाले कारखानों पर यह लागू होता था।
- (II) बच्चों की कार्यवस्था ६ से १४ कर दी गई और कार्यवाहक घण्टे ६ से घटाकर ७ प्रति दिन कर दिये गये।
- (III) स्त्री श्रमिकों से कार्य लिए जाने के अधिकतम घण्टे ११ प्रति दिन निश्चित कर दिये गये।
- (IV) स्त्रियों तथा बच्चों के लिये कार्यवाहक घण्टे ६ प्रति दिन निश्चित किये गये।

(३) सन् १९११ का कारखाना अधिनियम—

- (I) पुरुष श्रमिकों के लिये १२ घण्टा प्रति दिन अधिकतम कार्यकाल नियुक्त कर दिया गया।
- (II) सूती कपड़े के कारखानों में बच्चों के लिए कार्यवाहक घण्टे ६ प्रति दिन निश्चित कर दिए गए।
- (III) मौसमी कारखानों को नियन्त्रण में लाया गया।

(४) सन् १९२२ का कारखाना अधिनियम—

- (1) यह शक्ति प्रयोग करने वाले समस्त कारखानों, जिनमें कि २० अथवा अधिक श्रमिक काम करते हो, में लागू था ।
- (11) वयस्क श्रमिकों के लिए अधिकतम कार्यवाहक घण्टे ११ प्रति दिन तथा ६० घण्टे प्रति सप्ताह निश्चित किए गए ।
- (111) बच्चों की कार्यवस्था १२ से १५ वर्ष निश्चित की गई ।
- (1V) श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी रक्षा, सफाई तथा निरीक्षण की व्यवस्था की गई ।

(५) सन् १९३४ का कारखाना अधिनियम—

- (1) वयस्क श्रमिकों के कार्यवाहक घण्टे ५० प्रति सप्ताह अथवा १० प्रति दिन तक सीमित कर दिए गए । प्रति सप्ताह एक अवकाश दिवस एवं विश्रांति-काल की भी व्यवस्था की गई ।
- (11) बच्चों के लिये कार्यवाहक घण्टे ५ प्रति दिन ही रह गये । इन्हें शारीरिक योग्यता का प्रमाण-पत्र देना आवश्यक हो गया ।
- (111) कृत्रिम नमी बनाये रखने की योजनायें विकसित की गई तथा श्रमिकों के कल्याण एवं अतिरिक्त कार्य के लिए भी प्रबन्ध विद्या गया ।
- (1V) स्प्रेड ओवर (Spread over) का सिद्धान्त पहले-पहल लागू किया गया ।

(६) सन् १९४६ का संशोधित कारखाना अधिनियम—

- (1) वर्ष भर चलने वाले कारखानों में श्रमिकों के लिए अधिकतम कार्यवाहक घण्टे ५४ से घटाकर ४८ प्रति सप्ताह कर दिये गए तथा मौसमी कारखानों के वयस्क श्रमिकों के लिए ६० से घटा कर ५० प्रति सप्ताह कर दिए गए ।
- (11) स्प्रेड ओवर वर्ष भर चलने वाले कारखानों में १३ घण्टे से घटा कर १० घण्टे और मौसमी कारखानों में ११ घण्टे निर्धारित कर दिए गए ।
- (111) अतिरिक्त कार्य के लिए (दोनों प्रकार के कारखानों में) मजदूरी साधारण से दुगुनी कर दी गई । उसका उद्देश्य अतिरिक्त कार्य को निरस्तहित करना था ।

(७) सन् १९४८ का वर्तमान कारखाना अधिनियम—

इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) यह अधिनियम समस्त भारत पर लागू होता है ।

(२) यह अधिनियम शक्ति-प्रयोग करने वाले कारखानों में, जिनमें १० या इससे अधिक श्रमिक काम करते हो, जहाँ तक कि शक्ति का प्रयोग तो नहीं होता, परन्तु २० या इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, लागू होता है ।

(३) वर्ष भर चलने वाले मौसमी कारखानों में कोई अन्तर नहीं रखा गया है ।

(४) कारखाना अधिनियम का क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से इस अधिनियम में यह भी आदेश दिया गया है कि जहाँ कहीं भी निर्माण कार्य हो रहा है (भल ही उसमें कितने भी श्रमजीवी कार्य करते हों), यह सनियम लागू होगा । शक्ति का प्रयोग करना अथवा न करना महत्त्वहीन है । हाँ, यदि केवल परिवार के सदस्यों की सहायता से ही कोई निर्माण किया जा रहा है तो ऐसी दशा में कारखाना अधिनियम लागू न होगा ।

काम के घण्टों के सम्बन्ध में आदेश—

(५) नए अधिनियम में यह स्वीकार किया गया कि यदि श्रमिकों के काम के घण्टे कम होंगे तो उनकी आयक्षमता में अवश्य वृद्धि होनी चाहिए । अतएव व्यवस्था श्रमिकों के लिए अधिवर्तमान काम के घण्टे प्रति सप्ताह ४८ और प्रति दिन ९ नियत किए गये । कम से कम २ घण्टे का मध्याह्नतर दिए बिना ही उनमें ५ घण्टे में अधिक काम न लिया जाय, इस बात की व्यवस्था की गई । स्ट्रैंड ओवर मध्याह्नतरों को सम्मिलित करते हुए १०३ घण्टे से अधिक न होगा । कारखाना अधिनियम सन् १९४८ के अन्तर्गत राज्य-सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कुछ व्यक्तियों को काम के घण्टे, साप्ताहिक छुट्टी आदि नियमों के पालन करने के सम्बन्ध में छूट (exemption) दे सकती हैं, किन्तु ऐसी छूट-प्राप्त-व्यक्ति भी निम्न नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते :— (अ) किसी भी दिन कुल काम के घण्टे १० से अधिक न होने चाहिए । (आ) ३ माह की अवधि में कुल अतिरिक्त कार्य के घण्टे ५० से अधिक न होने चाहिए । (इ) किसी भी दिन स्ट्रेड ओवर १२ घण्टे से अधिक न होगा । (ई) अतिरिक्त कार्य के लिए दूनी दर से वेतन देने एवं पूरे सप्ताह में एक दिन की छुट्टी रखने की व्यवस्था भी की गई ।

सवेतन छुट्टी—

(६) प्रत्येक श्रमिक को सप्ताह में एक सवेतन छुट्टी तो मिलेगी ही, इससे अतिरिक्त निम्न दर पर निरन्तर बारह माह की सेवा होने पर उसे अतिरिक्त सवेतन छुट्टियों का अधिकार होगा । यथा :—

(अ) एक प्रौढ श्रमिक २० दिन काम करने के बाद १ दिन सवेतन छुट्टी का अधिकारी है, परन्तु वह एक वर्ष में न्यूनतम १० दिन की सवेतन छुट्टी ले सकेगा ।

(आ) एक बालक १५ दिन काम करने के बाद १ दिन सवेतन छुट्टी का अधिकारी है, किन्तु वह एक वर्ष में न्यूनतम १४ दिन की सवेतन छुट्टी ले सकेगा ।

(स) यदि कोई श्रमिक अपनी अर्जित छुट्टियों का लाभ लिए बिना सेवा से

मुक्त कर दिया जाता है या स्वयं निकल जाता है तो ऐसी दशा में सेवायोजक का कर्तव्य होगा कि उन दिनों का वेतन उनको दे ।

नवयुवकों की नियुक्ति से सम्बन्धित आदेश—

(७) १४ वर्ष से कम आयु का कोई भी युवक नियुक्त नहीं किया जा सकता । १८ वर्ष की आयु के बाद एक युवक को प्रौढ (Adolescent) माना जायगा । नियुक्ति के पहले आयु सम्बन्धी डाक्टरों प्रमाण-पत्र देना भी आवश्यक कर दिया गया और यह भी आदेश दिया गया कि ऐसे प्रमाण-पत्र केवल १२ महीने तक ही वैध रहेंगे ।

महिला श्रमिकों की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश—

(८) महिला श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्न आदेश बनाये गए :—

(अ) किसी भी महिला श्रमिक को मशीन चालू रहने की दशा में मशीन की सफाई करने, उसमें तेल डालने अथवा मशीन को सुधारने आदि के लिये नियुक्त न किया जायेगा ।

(आ) जिन कारखानों में कपास की धुलाई करने वाले यन्त्र का उपयोग किया जाता है, उनमें कपास प्रस करने के लिये महिला श्रमिक नियुक्त न की जा सकेंगी । हा, यदि धुलाई का कमरा प्रेस के कमरे से अलग हो तो उनकी नियुक्ति की जा सकती है ।

(इ) यदि किसी कारखाने में ५० से अधिक महिलाएँ कार्य करती हैं तो उनके ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक शिक्षु-सदन होना चाहिये । इसके अतिरिक्त आवश्यक मध्यान्तर के उपरान्त माताओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी सुविधा देनी चाहिए ।

(ई) किसी भी महिला श्रमिक से सप्ताह में ४८ घण्टे अथवा ६ घण्टे प्रति दिन से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा ।

(उ) स्त्री एवं बाल श्रमिक से ७ बजे शाम से प्रातः ६ बजे तक काम नहीं लिया जा सकता ।

(ऊ) यदि राज्य सरकार की सम्मति में किसी कारखाने को कोई भी खतरनाक है तो उस कार्य को करने के लिए महिला श्रमिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती ।

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण कार्य सम्बन्धी आदेश—

(६) स्वास्थ्य—सन् १९४६ के अधिनियम के विपरीत, इस अधिनियम में श्रमिकों के स्वास्थ्य रक्षण एवं सामान्य आराम के लिए कुछ अधिक व्यवस्था स्वयं ही कर दी । राज्य सरकार के जिम्मे केवल व्यावहारिक नियम बनाने का कम महत्वपूर्ण कार्य ही रह गया ।

- (अ) प्रत्येक कारखाना पूर्णतः साफ रहना चाहिए और किसी भी श्रेत से आने वाली गन्दगी अथवा कूड़ा-बर्त कारखाने के किसी भी भाग में एकत्र न हो । निर्माण क्रिया के द्वारा किसी भी स्थान पर निरर्थक अथवा क्षेप्य पदार्थ गिरते हैं तो उनकी सफाई के लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (आ) प्रत्येक कारखाने में शुद्ध वायु के आने के लिये एवं गन्दी वायु के जाने के लिए पर्याप्त झरोखे होने चाहिए । झरोखे इनमें हो कि शुद्ध एवं शीतल वायु पर्याप्त मात्रा में आ सके और तापक्रम ऐसा रहे कि जिसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े । यदि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि पुताई कराने, स्ररे कराने, झरोखे निकलवाने अथवा दोबाले तथा छत ऊँची कराने में कारखाने के अन्दर तापक्रम को ठीक रखा जा सकता है तो वह कारखाना अधिकारियों को इस सम्बन्ध में उचित आदेश दे सकती है ।
- (इ) यदि कारखाने की कोई निर्माण क्रिया ऐसी है, जिसके परिणामस्वरूप धूल इत्यादि सड़ कर इधर-उधर जमा होती है तो उसकी सफाई के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े ।
- (ई) कारखानों के अन्दर अत्यधिक शुष्कता या अत्यधिक नमी भी हानिकारक होती है । हमारी वस्त्र मिलों में कृत्रिम साधनों द्वारा नमी पैदा की जाती है । इस सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तापक्रम में जो अन्तर किया जाये वह श्रमिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक न हो ।
- (उ) नए कारखाना अधिनियम के प्रचलन के बाद प्रत्येक कारखाने में प्रत्येक श्रमजीवी के लिए ५०० क्यू० फीट का स्थान होना चाहिए और अधिनियम के प्रचलन के पूर्व विद्यमान कारखानों के लिए भी प्रति श्रमजीवी कम से कम ३५० क्यू० फीट का स्थान होना चाहिए । इस आदेश का प्रमुख उद्देश्य कारखानों में अत्यधिक भीड़-भाड़ को कम करना है ।
- (ऊ) कारखाने में जहाँ भी श्रमजीवी कार्य करते हों, अथवा जिस मार्ग से गुजरते हों वहाँ पर्याप्त प्राकृतिक अथवा कृत्रिम प्रकाश आने की व्यवस्था होनी चाहिए । बहुत तेज प्रकाश, जो कि आँखों को हानिकारक है, को रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (ए) प्रत्येक कारखाने में पीने के लिए पानी की भी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए । जहाँ २५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हों, वहाँ ठंडे पानी के लिए रेफीजरेटर होने चाहिए ।

- (ए) प्रत्येक कारखाने में पुरुष एवं महिलाओं के लिए पृथक्-पृथक् पेशाबघर एवं शौचालय होने चाहिए । पलश सिस्टम न होने की दशा में भगियों की अच्छी व्यवस्था हो, जो वि मन्दगी को साफ करते रहे । शौचालय एवं पेशाबघर के अतिरिक्त कारखाने के अन्य भाग एवं दीवारों आदि की भी सप्ताह में कम से कम एक बार भली प्रकार सफाई होनी चाहिए ।
- (भो) प्रत्येक कारखाने में झूकने के लिए पीवदानों की भी व्यवस्था होनी चाहिए एवं उनकी सफाई भी होती रहनी चाहिए ।

(१०) सुरक्षा —

(ङ) ट्रान्समिशन मशीनरी का प्रत्येक भाग एवं अन्य मशीनों का प्रत्येक खतरनाक भाग चारों तरफ से ग्राउ (Fencing) लगाकर रखा जाना चाहिए । जबकि कोई खतरनाक मशीनरी चल रही हो तो उसकी देखभाल का काम केवल विशेष रूप में प्रशिक्षित प्रौढ पुरुष श्रमिक ही कर सकता है, जिसका कि नाम कारखाने के रजिस्टर में उस कार्य विशेष को करने के लिए लिखा हो ।

(ब) बाल अथवा महिला श्रमिक खतरनाक मशीनों पर कार्य नहीं करेंगे ।

(स) कोई भी नई मशीन, जो कि यांत्रिक शक्ति द्वारा चलाई जाती हो, भली प्रकार फिट होनी चाहिए । ऐसी मशीन को बेचते समय उत्तरदायित्व विक्रेता पर होगा और खरीदने के बाद क्रेता पर । अतः सेवायाजक को बड़ी सावधानी में देखभाल करने के बाद मशीन फिट करवानी चाहिए । प्रत्येक होइस्ट तथा लिफ्ट (Hoist and lift) भली प्रकार निर्मित होने चाहिए, जिससे कि प्रयोग के समय कोई दुर्घटना होने की आशका न रहे । इसी प्रकार बोझा उठाने वाली मशीनों तथा क्रेन आदि का पूर्णरूपेण ठीक होना अनिवार्य है । क्रेन ड्राइवर को केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त न होगा, वरन् 'स्टॉप ब्लाक', डिटोनेटर्स अथवा 'वट आउट्स' का प्रयोग होना चाहिए तथा यह भी आवश्यक है कि ड्राइवर क्रेन के पहिए से २० फीट दूर रहे ।

(द) कोई भी व्यक्ति इतना बोझा उठाकर चलने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, जिससे कि उससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े ।

(य) यदि किसी कार्य विशेष से आँखों पर कुप्रभाव पड़ने की आशका हो तो उसकी रोक के लिये सेवायोजकों को विशेष प्रकार के चश्मे आदि का प्रबन्ध करना चाहिए । धूल आदि से बचने के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । आग लग जाने की दशा में श्रमिकों के बचाव

एवं आग बुझाने की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । (जैसे, दरवाजे में ताला कुंजी न होना, आग लगने पर बाहर जाने का मार्ग (Fire exits) होना, खतरे की घंटों की व्यवस्था आदि) ।

(११) कल्याण कार्य सम्बन्धी—

श्रमिकों के लिए उपहार गृहो, विश्रामालयों, श्री श्रमिकों के छोटे बच्चों के दिन में रखने के लिये शिशु गृहो, बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, वस्त्र धोने के स्थान की सुविधा भी दी गई । ५०० से अधिक श्रमिक वाले कारखानों के लिए राज्य सरकारों की सहायता से 'हितकारी अफसर' (Welfare Officers) रखना अनिवार्य कर दिया गया । व्यावसायिक रोगों आदि के विषय में सभी कारखाना मालिकों के लिये यह आवश्यक है कि वे दुर्घटना या बीमारी होने पर तत्काल सूचना दें । इन कारखानों के लिए नियुक्त किए गए चिकित्सकों को भी जो कि इन श्रमिकों की चिकित्सा कर रहे हों, यह समाचार सीधे ही चीफ पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर को पहुँचाना होगा । राज्य सरकार जाँच के लिए उचित व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है । इस अधिनियम का पालन कराने के लिए पर्याप्त निरीक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गई है । आदेशों के अनुसार आवरण हो, इसका उत्तरदायित्व निरीक्षकों पर न रहकर कारखाना व्यवस्थापकों पर है ।

(II) खान सम्बन्धी सश्रियम

खान सम्बन्धी सश्रियम का विकास—

खानों के श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम सश्रियम काफी धीरे-धीरे प्रारम्भ हुआ । सर्वप्रथम सन् १९०१ में भारत में खान सम्बन्धी अधिनियम का सूनपात हुआ था । इसके अनुसार खानों की कार्य-दशाओं को नियमित कर दिया गया एवं निरीक्षकों की नियुक्ति के लिये व्यवस्था की गई, किन्तु कार्य के घण्टे नियमित नहीं किये गये । वार्शिंगटन सम्मेलन की सिफारिशों तथा सीधेता से विकसित होते हुये खान उद्योग में अधिक सख्या में काम करने वालों को दृष्टि में रखते हुये सन् १९२३ में सशोधित अधिनियम पास किया गया । इससे 'खान की परिभाषा विस्तृत हो गई । ऊपर काम करने वाले श्रमिकों के लिये सप्ताह में ६० घण्टे तथा खानों में भीतर काम करने वालों के लिये ४४ घण्टे एवं एक दिन विश्राम के लिये भी नियत कर दिया गया । १३ वर्ष तक के बच्चों के लिये खानों में भीतर काम करने के लिये वर्जित कर दिया गया । भूमि के अन्दर महिलाओं की नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, क्योंकि खानों में काम करने वाले श्रमिकों में लगभग ४५% महिलाएँ थी, अतः यदि उन पर रोक लगाई जाती तो उद्योग को आघात पहुँचने की आशंका थी । इसके विपरीत, सुधार की भी आवश्यकता अत्यन्त तीव्रता के साथ अनुभव की जा रही थी ।

समय की प्रगति के साथ ही साथ सन् १९२३ का अधिनियम अपर्याप्त हो गया और इसमें क्रमशः सन् १९२८, १९३१, १९३६, १९३७, १९४० तथा १९४६ में

सशोधन हुये। सन् १९२८ में रैनिय कार्य-अवधि १२ घण्टे कर दी गई। सन् १९२९ में बंगाल, बिहार व उड़ीसा, मध्य-प्रदेश की कयला खानों तथा पंजाब की नमक की खानों को छोड़कर अन्य सभी खाना के भीतर महिलाओं का कार्य करना वर्जित कर दिया गया।

सन् १९२५ में पुनः सशोधन हुये। एक तो श्रम के साही कमीशन की सिफारिशों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा काम के घण्टों के नियत किये जाने और भारत द्वारा इस सिफारिश को मान लेने के पक्षस्वरूप निम्न सशोधन करना अनिवार्य हो गया था। कोर्ट भी व्यक्ति खान में १ सप्ताह में ६ दिन से अधिक काम नहीं कर सकता। खान के ऊपर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति सप्ताह में ५४ घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकता। एक दिन में १० घण्टे से अधिक कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। वायेंवास इस प्रकार होगा कि विश्राम-काल को सम्मिलित करने हुये वह एक दिन में १२ घण्टे से अधिक न होगा। ६ घण्ट लगातार काम करने के बाद १ घण्टा विश्राम अवश्य मिलेगा। खानों के अन्दर काम करने वाले व्यक्तियों को १ दिन में ६ घण्टे से अधिक काम नहीं करना होगा। खान के अन्दर एक ही प्रकार का काम ६ घण्टे से अधिक नहीं किया जायगा। यदि बारी-बारी से काम करने की पद्धति हो तो उसे उपवाद माना जा सकता है, किन्तु इसमें भी एक बार में ६ घण्टे से अधिक काम नहीं होगा। १५ वर्ष में नीचे की आयु वाले बच्चों को खानों में काम करने से रोक दिया गया। १७ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए डाक्टरों प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही इस सशोधन के अनुसार श्रमिकों के लिए पानी, चिकित्सा तथा अन्य स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी गई। सन् १९४५ में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को दिन में काम करते समय रखने के लिए शिशु गृहों की व्यवस्था कर दी गई। सन् १९४६ में स्त्री व पुरुष श्रमिकों के लिए बन्द स्नानागारों की अलग अलग सुविधा कर दी गई। श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के हेतु 'माइनिंग बोर्ड' की स्थापना भी कर दी गई, जिसमें श्रमिक, सेवाधोजक तथा सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकेंगे—

भारतीय खान अधिनियम सन् १९५२—

सन् १९४८ के कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा में तो पर्याप्त सुधार हो गया था, किन्तु खानों में हुई अनेक भयंकर दुर्घटनाओं से यह अनुभव किया गया कि खान में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना है। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने ८ दिसम्बर सन् १९४९ को भारतीय पालिमेंट में एक बिल रखा, जो कि १५ मार्च सन् १९५२ को भारतीय खान अधिनियम सन् १९५२ के रूप में सामने आया। यह अधिनियम १ जुलाई सन् १९५२ में जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत पर लागू हो गया है।

(१) स्वास्थ्य व दुर्घटनाएँ—इस अधिनियम ने खानों की परिभाषा को

अत्यन्त व्यापक स्वरूप दिया। श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। ऊपर और नीचे काम करने वाले श्रमिकों के लिए शीतल जल, शौचालय तथा श्रौषधियों की पेट्टी की व्यवस्था बरनी होगी। जिन खानों में ५०० से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, वहाँ एम्बुलेन्स गाड़ियों तथा स्ट्रेचरों की अनिवार्य व्यवस्था करनी होगी। यदि मुरय निरीक्षक अथवा उसके द्वाग नियुक्त किसी अन्य निरीक्षक को यह विश्वास हो जाए कि खान में काम करने वाले श्रमिकों की जान को खतरा है तो वह कुछ समय तक नए श्रमिकों को भरती और वर्तमान श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना बन्द कर सकता है। सभी भयंकर अथवा प्राणघातक घटनाओं की सूचना खानों के प्रबन्धकों को अनिवार्य रूप से सरकार के पास पहुँचानी होगी। खानों सम्बन्धी व्यावसायिक रोगों के विषय में भी ऐसा करना होगा। केन्द्रीय सरकार का इस अधिनियम के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन दुर्घटनाओं तथा रोगों की जाँच कराके उनके कारणों का प्रकाशन कर सकती है।

(२) विशेष सुविधायें—इस अधिनियम में बच्चों तथा स्त्रियों के लिए शिशु-गृहों, खानों के मुहाने पर महिनाओं तथा पुष्पों के हनु अलग-प्रलग भरनेदार स्नानागार, १५० श्रमिकों वाली खानों में विश्रामालय, उपहार गृह तथा ५०० श्रमिकों वाली खानों में कल्याण अधिशारिया की नियुक्ति आदि की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार दे दिए गये हैं।

(३) बाल श्रमिक—बच्चों के सम्बन्ध में यह आदेश है कि १८ वर्ष से कम आयु के बच्चे खानों में नीचे काम नहीं कर सकते। १५ व १८ वर्ष की आयु वाले व्यक्ति किशोर कलार्यों में और बिना उचित डाक्टरों प्रमाण-पत्र के उनकी नियुक्ति न होगी। काम करते समय उनको यह प्रमाण-पत्र हर समय पास रखना होगा। इन्हें ४½ घण्टे निरन्तर काम करने के उपरान्त ३ घण्टे का विश्राम मिलेगा। प्रमाण-पत्र की अवधि १ वर्ष होगी।

(४) कार्य के घण्टे व अवकाश—सन् १९५२ के खान अधिनियम ने श्रमिकों की साप्ताहिक कार्यावधि ४८ घण्टे तथा दैनिक कार्यावधि ८ घण्ट कर दी है। खानों के भीतर काम करने वाला का कार्यावधि क्रमशः ४८ घण्ट साप्ताहिक और ८ घण्ट दैनिक कर दी गई। नीचे काम करने वाला की सम्पूर्ण कार्य-विस्तार अवधि (Spread Over) नौ घण्टे से घटा कर ८ घण्टे कर दी गई। बिना ३ घण्टे का विश्राम दिए कोई भी प्रौढ श्रमिक ५ घण्टे से अधिक लगातार काम नहीं कर सकेगा। खानों के भीतर स्त्रियाँ द्वारा काम करना तो वर्जित था ही, किन्तु इस अधिनियम ने धरातल के ऊपर काम करने वाली स्त्रियों को भी सायंकाल ७ बजे से प्रातः ६ बजे तक काम करने से रोक दिया। अनिश्चित कार्य के लिए, भीतर काम करने वाले श्रमिकों को सामान्य मजदूरी का दो गुना और ऊपर कार्य करने वालों को १½ गुना वेतन दिया जावेगा। नए अधिनियम ने १ दिन के साप्ताहिक अवकाश के अलावा छुट्टी के अन्य नियम

भी बना दिए, जिनके अनुसार १ वर्ष की नौकरी पूरी होने पर श्रमिकों को १४ दिन का सैवतनिक अवकाश दिया जायेगा। यह अवकाश २८ दिन तक समग्र भी किया जा सकेगा।

(५) निरीक्षण—अधिनियम के आदेशों का पालन कराने के लिए एक मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। इसका सहायता के लिए उप-निरीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट भी होंगे। उपरान्त वर्णन से स्पष्ट है कि सन् १९१२ के अधिनियम ने खानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा में प्रशंसनीय सुधार किया।

(III) उद्यानों से सम्बन्धित अधिनियम

उद्यानों (Plantations) में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति बहुत समय तक अत्यन्त बरणाजनक रही। वे बिचारे दास के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी अधिनियम न था। आसाम में बाघ के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम सन् १८६३ में सन् १९०१ तक अनेक प्रयत्न किये गए, किन्तु इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप उद्यानों में बंधक श्रमिकों (Indentured Labours) का सूत्रपात हुआ। ये श्रमजीवी कठपुतली की भाँति अपने सेवामोर्चकों की इच्छानुसार नाचते थे और नौकरी छोड़ने पर बंद किए जा सकते थे। अतः सन् १९०१ में आसाम श्रमिक तथा प्रवास अधिनियम (The Assam Labour and Emigration Act) पारित किया गया, जिसके अनुसार श्रमिकों की कार्य दशाओं का नियमन किया गया।

तत्पश्चात् सन् १९०८ तथा सन् १९१५ में इस अधिनियम में संशोधन किये गये, जिनके अनुसार श्रमिकों का बंधन से मुक्त कर दिया गया और व्यक्तिगत बगीचों के मालिकों का श्रमिकों का नौकरी छोड़ने पर बंद कराने के अधिकार से बन्धित कर दिया गया, किन्तु इतना होते हुए भी श्रमिकों की स्थिति में सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ। सन् १९३१ में श्रम के शाही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा का हृदयस्पर्शी चित्रण किया और उसके सुधार हेतु अनेक सिफारिशों की, जिनके आधार पर सन् १९३२ का The Tea Districts Emigrant Labour Act बनाया गया।

यह अधिनियम मुख्यतः आसाम के श्रमिकों की भरती में सम्बन्धित था। इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र को श्रमिकों की भरती के लिए नियन्त्रित करके किसी भी व्यक्ति को किसी मालिक या मालिकों के लिए स्थानीय एजेंट बनाने के लिए लाइसेंस दे। सरकार वहाँ भेजे जाने वाले श्रमिकों के रहन-सहन व खान-पान की सुविधाओं का भी उचित ध्यान रखेगी। प्रत्येक १६ वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति आसाम में श्रमिक के रूप में जाने के लिए रोका जा सकता है। केवल माँ-बाप या ऐसे सरक्षक या सम्बन्धी के साथ ही वह आसाम जा सकता है जिनपर वह विश्वास है। इसी प्रकार बिना पति की आज्ञा

के कोई भी विवाहिब स्त्री को वहाँ भेजने में सहायता नहीं कर सकता। ३ वर्ष आत्मा में रहने के बाद कोई भी श्रमिक मालिक के व्यय से स्वदेश लौटने का अधिकारी है। अन्त में, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिए एक 'प्रवासी श्रमिक अधिकारी' (Controller of Emigrant Labour) की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई, जिसका कर्तव्य यह होगा कि वह श्रमिकों की भरती तथा उनके स्वदेशगमन इत्यादि बातों का प्रबन्ध करे।

उद्यान सम्बन्धी अधिनियम सन् १९५१

यह अधिनियम जम्मू व काश्मीर को छोड़ कर समस्त भारत के चाय, कहवा, रबड़ तथा सिनकोना के उन सब बगीचों पर लागू होता है, जिनका कम से कम क्षेत्रफल ६५ एकड़ हो और जहाँ कम से कम ३० श्रमिक काम करते हों।

इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा सामाजिक हितों, कार्य के घन्टा, छुट्टी के नियमों, बच्चों के रोजगार तथा श्रमिकों के लिए बीमारियों इत्यादि से बचने और उनकी चिकित्सा सम्बन्धी नियमों की पूर्ण व्यवस्था की गई। उद्यान स्वामियों को श्रमिकों के लिए स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय, भूतलाय तथा पर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करनी होंगी। राज्य सरकारों के आदेशों पर श्रमिकों के मनोरंजन के साधन जुटाने, १५० में अधिक श्रमिकों वाले बगीचों में उपहार गृहों की व्यवस्था, ६ से १२ वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा सुविधायें तथा ऐसे बगीचों में जहाँ कम से कम ५० महिलायें काम करती हों, शिशुगृहों की व्यवस्था इत्यादि का प्रबन्ध भी किया गया है।

श्रमिकों के निवास के लिये सेवायोजक को उद्यानों पर ही गृहों का निर्माण करना होगा। इन घरों का स्थान, निर्माण, किराया, स्वास्थ्यवर्द्धक अवस्थायें, आकार तथा भोजनालय इत्यादि सभी बातें राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों से नियमित होंगी। जिन बगीचों में ३०० से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं उनमें एक कल्याण-कार्य अधिकारी भी रहेगा। नए अधिनियम के अनुसार १२ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। १५ वर्ष से १८ वर्ष की आयु के व्यक्ति किशोर माने जायेंगे। बच्चों और किशोरों को आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देना होगा, जो कि उनके काम करते समय सदैव रहना चाहिए।

फ्रीडो को सप्ताह में ५४ घन्टे तथा बच्चों व किशोरों को ४० घन्टे काम करना होगा। दिन में काम करने के घन्टे नियत नहीं किए गए हैं, किन्तु ऐसे घन्टे विश्राम के समय को सम्मिलित करते हुए १२ घन्टे की सम्पूर्ण कार्यावधि से अधिक नहीं हो सकते। संध्या के ७ बजे से प्रातः ६ बजे तक बच्चों तथा स्त्रियों के लिए कार्य का निषेध है। ३ घन्टा या अधिक देर से काम पर आने वाले श्रमिकों को उस दिन काम पर रखने से मालिक द्वारा रोका जा सकता है। आधी, तूफान, अग्नि तथा अन्य किसी प्राकृतिक बाधा से काम पर न आ सकने वाले श्रमिकों के लिए वह दिन अवकाश का दिन गिना जा सकता है।

प्रत्येक श्रमिक को निम्न रीति से मजदूरी अवकाश मिलेगा —

(अ) प्रौढों को २० दिन काम करने पर १ दिन और (ब) बच्चे या किशोर को १५ दिन काम करने पर १ दिन । ये लोग अपनी छुट्टी को ० दिन तक संग्रह कर सकते हैं । बीमार होने पर प्रत्येक श्रमिक का चिकित्सक के प्रमाण-पत्र देन पर बीमारी का भत्ता भी दिया जाएगा । महिला श्रमिका को भी प्रसूतकाल के लिए भत्ता दिया जायेगा ।

(III) यथायात सम्बन्धी सन्निधय

यातायात श्रमिकों के सम्बन्ध में अधिनियम सुविधाएँ दे देने के कमचारियों के लिए सन् १८६० के भारतीय रेलवे अधिनियम द्वारा दी गई । यह अधिनियम सन् १९३० में संशोधित होकर रेलवे कर्मचारियों का छाड़ कर समस्त कमचारियों पर लागू हो गया और उनके विश्राम तथा काम करने के घंटों का नियमन करने लगा । इससे अनुसार अनुपातत माह में प्रति सप्ताह निरन्तर छुट्टी पर रहने वाले कमचारियों के काम के घंटे ६० तथा बीच बीच में रुक रुक कर छुट्टी पर जाने वाले कमचारियों के लिए ८४ घंटे प्रति सप्ताह रखे गये । साथ ही प्रति सप्ताह २४ घंटे के लगाने पर विश्राम की भी व्यवस्था की गई । सन् १९३१ में भाग्स सर ने काम के घंटों का नियमन करने के लिए कुछ और नियम बनाए

सन् १९४६ में मखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ ने भारत सरकार के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व भेजा और कर्मचारियों के काम के घंटे तथा अवकाश प्राप्ति विषयों की जांच करने के लिए एक निर्णायक नियुक्त करने की मांग की । फलतः जस्टिस राजाध्याय को इस पर नियुक्त किया गया । उन्होंने मई सन् १९४७ में अपना निर्णय दिया जिसके अनुसार काम के घंटे छुट्टी के नियम साप्ताहिक अवकाश इत्यादि के विषय में उन्होंने अपना निर्दिष्ट मत दिया जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया । परिणामस्वरूप ३१ मार्च सन् १९५१ से भारत की सभी रेलों में ये नियम लागू कर दिए गए हैं । लोको कर्मचारियों तथा टिकट रतियों स्टाफ के लिए भी इसी प्रकार के नियम बनाए गए हैं । इन लोगों को महीने में ३० ३० घंटे के ४ विश्राम मिलेंगे । रेल भाग पर काम करने वाले भेटों (V.L. ३) की मनो तथा गम मनो को भी सप्ताह में एक दिन विश्राम मिलेगा

रेलों के अतिरिक्त शिपिंग उद्योग के कर्मचारियों के लिए भी सन् १९३२ में दो इण्डियन मच ट शिपिंग एक्ट बनाया गया जिसमें क्रमशः सन् १९४६ तथा सन् १९५१ में संशोधन किए गए । संशोधित अधिनियम के अनुसार कोई भी नाविक भारतीय ब्रिटिश या विदेशी जलयान पर उसके स्वामी के द्वारा निर्धारित नियमानुसार नौकर रखा जा सकता है । उपर्युक्त व्यवस्थाओं पर सरकार बाह्य तो राजगार के दफ्तर भी खोल सकती है । पहले तो १८ वर्ष के कम आयु वाले श्रमिकों का डाक्टरी परीक्षा की जाती थी किन्तु अब सभी की डाक्टरी जांच होती है । राज पर कार्य प्रारम्भ

करने के समय से ही नाविक को वेतन लेने का अधिकार हो जाता है। वेतन के भुगतान तथा समय पर वेतन न मिलने पर अनिश्चित रूपया मिलने की भी अधिनियम में व्यवस्था की गई है। यदि किसी नाविक को अनुचित प्रकार से नौकरी में हटा दिया जाता है तो उसे १ माह के अतिरिक्त वेतन का अधिकार है। नाविकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी नियम बनाए गए हैं। उनके लिये जलयान पर स्वच्छ पानी, पर्याप्त घोषधि तथा यात्रा पर होने के समय अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था होनी चाहिये। उनकी चिकित्सा निःशुल्क होगी। जलयान पर रहते समय प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम ७२ क्यूबिक फुट का निवास-स्थान मिलना चाहिए। साथ ही, नाविकों पर अनुशासन रखने तथा उनके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए भी अधिनियम में व्यवस्था की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके लिए दण्ड की भी व्यवस्था है।

इसी प्रकार डॉक पर माल लादने या उतारने वाले श्रमिकों के लिए भी कानूनों का निर्माण हुआ है। प्रारम्भ में ये लोग पूर्णतः अनिश्चित थे। सन् १९१८ में 'इण्डियन पोर्ट्स एक्ट' पास किया गया, जिसका मन् १९२२ व मन् १९३१ में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों की भरती का नियमन किया गया। १२ वर्ष में कम आयु वाले बच्चों को माल लादने से रोक दिया गया। सन् १९२९ में अन्तर्गट्टीय श्रमिक सचिवों ने 'डापट कन्वेंशन' तथा रायल कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप मन् १९३४ में 'भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम' पास किया गया, किन्तु इसे सन् १९४८ तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस अधिनियम के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि वह डॉक पर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा तथा उनकी नौकरी के निश्चयन के सम्बन्ध में विधान निर्माण करे। मार्च सन् १९४८ में भारत सरकार ने डॉक कर्मचारियों की कठिनाइयों का निवारण करने के हेतु 'डाक-कर्मचारी (रोजगार का नियमन) अधिनियम' पास कर दिया। इससे सभी बन्दरगाहों पर काम करने वाले डॉक-कर्मचारियों का नाम अनुमूर्चित किया जा सके। इससे इनके भर्ती तथा नौकरी सम्बन्धी नियमों का नियमन हो जायगा। अधिनियम में इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण, शारीरिक सुरक्षा, हितकारी कार्य तथा उनके वेतनों को नियमित रूप से दिलाए इत्यादि की व्यवस्था की गई है। इन नियमों का पालन करने के सम्बन्ध में पलाह देने के लिए अधिनियम में एक मलाहकार समिति स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इस समिति में श्रमिका, मालिकों तथा सरकार के १५ प्रतिनिधि होंगे। सरकारी प्रतिनिधियों में समिति का अध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत होगा।

इस समिति की रचना इत्यादि के सम्बन्ध में जून मन् १९४९ में नियम बना दिये गये थे और फरवरी सन् १९५० में एक समिति भी बना दी गई। २७ जनवरी सन् १९५१ को भारत सरकार ने बम्बई डॉक-कर्मचारियों की नौकरी के नियमों को

बनाने के उद्देश्य से एक योजना भी प्रकाशित की, जिसके अनुसार श्रमिक तथा मालिकों दोनों का नाम रजिस्टर्ड किया जायगा। कोई भी रजिस्टर्ड श्रमिक किसी भी मालिक के यहाँ बिना अधिकारियों की आज्ञा क नौकरी नहीं कर सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि श्रमिक काम करने को उद्यत हो और उसे काम न मिल तो साह में कम से कम १२ दिन तक उसे सचित कोप में से मजदूरी तथा महंगाई मिल सकेगी। सभी रजिस्टर्ड डॉक-कर्मचारियों की मजदूरी दर, महंगाई भत्ता, काम के घण्टे विधायक व अवकाश तथा उनकी अन्य दशाओं का निर्धारण उस बोर्ड के द्वारा किया जायेगा, जो कि योजना के प्रशासन के लिए बनाया जायगा।

कलकत्ता तथा मद्रास के डॉक-कर्मचारियों की दशाओं का नियमन करने के लिए भी सरकार ने अक्टूबर सन् १९५१ व मार्च सन् १९५२ में योजनाएँ बना दी हैं। इनके प्रवन्ध के लिए बोर्ड भी बन चुके हैं और योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

(v) न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी सन्निधय

‘न्यूनतम मजदूरी’ से आशय—

‘न्यूनतम मजदूरी’ से आशय उस मजदूरी से है, जिससे कम मजदूरी देना जुर्म होता है। आजकल प्रायः सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि श्रमिका को उचित मजदूरी साधारणतया नहीं मिल पाती है। कुछ व्यवसायों तथा कुछ क्षेत्रों में श्रमिका की पूर्ति अत्यधिक होने के कारण मजदूरी काफी नीचे गिर जाने की सम्भावना रहती है। इस नीची मजदूरी के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। इस देश की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन की शान्ति भंग हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक संपर्कों को प्रोत्साहन मिलता है। यही नहीं, राज्य सरकार का भी जीवन सफट में पड़ सकता है, इत इन् दोषों के निवारणार्थ सरकार कुछ व्यवसायों में अथवा देश के भीतर सभी व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी नियत कर देती है। अभी तक लोगों की यह धारणा थी कि राज्य को मजदूरी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सेवायोजका का यह अधिकार होना चाहिए कि वे पारस्परिक वार्तालाप के फलस्वरूप जो मजदूरी उनके तथा श्रमिकों के बीच तय हो वही देते रहे, किन्तु श्रमजीवियों की हीन दशा तथा उनके सौदे करने की निर्वलता को देखते हुए राज्य की ओर से हस्तक्षेप उचित समझा जान लगा है। इस नवीन विचारधारा ने न्यूनतम भृत्ति प्रणाली को जन्म दिया। निर्धारित मजदूरी का देना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है, परन्तु इस प्रकार नियत की हुई मजदूरी से अधिक मजदूरी देने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता।

न्यूनतम मजदूरी की समस्या के दो अलग-अलग रूप हो सकते हैं— प्रथम, जबकि इस प्रकार की मजदूरी किसी विशेष उद्योग अथवा कुछ विशय उद्योगों के लिए

नियत की जाती है और दूसरे, जबकि सारे देश के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी जाती है। इन दोनों नीतियों के अलग-अलग परिणाम होते हैं। न्यूनतम भुत्त सन्तियम का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि श्रमजीवी संतुष्ट रह और देश में आर्थिक शान्ति रह।

न्यूनतम भुत्ति निश्चित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए —

- (१) मजदूरी इतनी हो कि श्रमिक सरलता से अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।
- (२) न्यूनतम भुत्ति निश्चित करते समय उद्योग विशेष की आर्थिक दशा का भी विचार रख।
- (३) यह भी सम्भव है कि श्रमिक कुछ दिनों के लिए बेकार हो जावें, अतएव मजदूरी निर्धारित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्रम आयोग का यह सुझाव है कि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारक यन्त्र की स्थापना के पूर्व ऐसे उद्योगों को चुनना होगा, जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित धारणा है कि उनमें वेतन की दशा शोचनीय है और विस्तृत गवेषणा वाछनीय है। इन गवेषणाओं के आधार पर यह निश्चित किया जाये कि क्या न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण व्यावहारिक एवं वाछनीय है। इस प्रकार के निर्णय के बाद व्यय पर विशय रूप में ध्यान रखनी पड़गी, क्योंकि नियोजकों की उदासीनता और कर्मचारियों के अज्ञान के कारण इन नियमों का पालन में बड़ी असुविधा और शिथिलता होती है। यदि बिना भयंकर परिणामों के वाछनीय उद्देश्य प्राप्त करता है तो गति को धीमा करना होगा।

भारतीय न्यूनतम भुत्ति अधिनियम की प्रमुख बातें —

भारतीय श्रम सन्तियम के इतिहास में सन् १९४८ का न्यूनतम भुत्ति अधिनियम सचमुच एक आदर्श है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को आदेश द दिया गया है कि वे न्यूनतम भुत्ति निश्चित करें। यही नहीं, यदि वे चाहें तो समय-समय पर कुछ अनुसूचित कर्मचारियों की मजदूरियों पर पुनः विचार भी कर सकती हैं। न्यूनतम भुत्ति निश्चित करने के लिए राज्य सरकार सलाहकार समितियाँ एवं उप समितियाँ नियुक्त करेंगी। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार भी मजदूरी निश्चित करने के मामले में एकीकरण के उद्देश्य से राज्य सलाहकार बोर्डों को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड नियुक्त करेगी। जो लोग निश्चित न्यूनतम भुत्ति से कम मजदूरी देंगे उन्हें श्रम सन्तियम के अनुसार उचित दण्ड मिलेगा।

कानपुर श्रम जांच समिति ने एवं आवाराधन न्यूनतम मजदूरी का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह सुझाव रखा है कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति महीने में २६ दिन काम करके (१५) न वम वेतन नहीं पायगा। उनकी सख्या को अब तिगुना करना होगा, अर्थात् (१५) के स्थान पर ४५) न्यूनतम वेतन श्रमिकों को

मिलना चाहिए । सन् १९२८ में नियुक्त विहार ग्राम जॉब समिति ने जून सन् १९४० में अपनी रिपोर्ट दी तथा अतः म श्रमिका की दशा सुधारन के लिए अनेक सिफारिशों की, जिनमें से एक 'न्यूनतम भृति के सम्बन्ध में भी थी । सन् १९४७ व कन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऊँची श्रेणी से लेकर नीची श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का एक नया ढाँचा स्वीकार करने की सिफारिश की गई है जिसके अनुसार न्यूनतम वेतन ३०) माहवार और अधिकतम वेतन २०००) होना चाहिए ।

•न्यूनतम मजदूरी के लाभ—

आधुनिक युग में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की प्रथा बड़ी लोकप्रिय हो गई है । न्यूनतम मजदूरी का नियन करना निम्न दृष्टिकोणों से उपयुक्त समझा जाता है—

(१) श्रमिकों का एक जीवन-स्तर निश्चित हो जाता है । मजदूरी की नीची से नीची सीमा के निर्धारित हो जाने के कारण जीवन स्तर की भी न्यूनतम सीमा निश्चित हो जाती है ।

(२) साधारणतः मजदूरी बढ़ जाती है जिसके कारण कायव्यवसाय में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है ।

(३) अकुशल उत्पादक जो केवल श्रमिका के शायद पर ही जीवित रहते हैं धीरे धीरे बाजार से गायब हो जाते हैं । राष्ट्र की आर्थिक कुशलता के दृष्टिकोण से यह अच्छा ही होता है ।

(४) श्रमजीवी से तृप्त हो जाना है और परिणामतः आन्वेषिक तत्त्व बम हो जाते हैं तथा काम भी अधिक अच्छा होता है ।

न्यूनतम मजदूरी की हानियाँ—

(१) जब कुछ ही व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाती है तो उत्पत्ति के साधनों का उन व्यवसायों में दूसरे व्यवसायों को हस्तांतरण होने लगता है और बेरोजगारी के बढ़न का भय उत्पन्न हो जाता है इसलिए जबल ऐसी ही व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी ठीक रहनी जिनमें वर्तमान मजदूरी बहुत ही नीची है ।

(२) न्यूनतम मजदूरी अधिकतम मजदूरी बनने की प्रवृत्ति रखती है । तथा योजक निश्चित से कम मजदूरी तो दे ही नहीं सकता है परन्तु वह इससे अधिक भी यथासम्भव नहीं देगा । इसका अन्तः म श्रमिका की कार्य कुशलता पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है ।

(३) व्यावहारिक जीवन में न्यूनतम मजदूरी के दर का नियत करना भी कठिन होता है । यदि प्रतियोगी दर से ऊँची दर रखी जाती है तो बेरोजगारी फैलने का भय रहता है और यदि न्यूनतम मजदूरी प्रतियोगी मजदूरी से कम रखी जाती है, तो वह अलाभकारी होती है ।

(४) न्यूनतम मजदूरी की दर को लागू करना कठिन होता है। जिन धेनो एवं व्यवसायो में श्रम की पूर्ति अधिक होती है, वहाँ मालिक के लिए केवल कागज पर ही न्यूनतम मजदूरी रहती है। वास्तविक जीवन में इससे बचने के लिए मिल मालिक कम वेतन देकर अधिक पर हस्ताक्षर करा लेते हैं।

श्रम-नीति (Labour Policy)

प्रारम्भिक—

भारत में श्रम नीति का विकास उद्योग और श्रमिक वर्गों की विशेष आवश्यकताओं और आयोजित अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए किया गया है। मालिकों, मजदूरों और सरकार—तीनों दलों की राय विचार-विनिमय से जान ली जानी है। इस त्रिदलीय व्यवस्था के सर्वोच्च स्तर पर भारतीय श्रम-सम्मेलन है।

श्रम नीति सम्बन्धी आधुनिक विकास—

औद्योगिक सम्बन्धों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उद्योगों में शान्ति का बनावरण रहे तथा मजदूरों को उचित न्याय मिले। इस बात पर जोर दिया जाता है कि जैसे ही औद्योगिक सम्बन्धों में विगाड़ आरम्भ हो, वैसे ही उसे रोकने के लिए समुचित उपाय किये जायें। इसके लिये पक्षकारों के हितोंको एवं विचारों में एक आधारभूत परिधर्तन तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों में नवीन ढंग का समायोजन होना आवश्यक है। उद्योग के लिये एक आचार संहिता स्वीकार की गई है, जो सार्वजनिक व प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में लागू होती है। आचार-संहिता में प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के विशेष कर्तव्य निश्चित किये गये, ताकि उनमें सहयोग व सहभावना का विकास हो। आचार संहिता की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसको धैर्य व ईमानदारी के साथ पर्याप्त अवधि तक कार्यान्वित किया जाय। वैसे इनके सुप्रभाव अभी से नजर आने लगे हैं। दोनों पक्षों की यह शिकायत रही है कि अग्राडों व समझौतों का पालन नहीं किया जाता। यदि ऐसी स्थिति जारी रहे, तो आचार संहिता का कोई अर्थ ही नहीं रहता। अतः अग्राडों व समझौतों का पालन कराने के लिए केन्द्र एवं राज्यों में एक कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन मशीनरी बनाई गई है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत दो विशेष विभाग हुए, जिनसे भविष्य में बहुत लाभ होने की आशा है। प्रथम, श्रमिकों को अपनत्व का एवं उत्पादकता बढ़ाने में लाभ का अनुभव कराने के लिए उनको प्रबन्ध में भाग देने की योजना विकसित की गई। प्रयोग रूप में २३ इकाइयों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें स्थापित कर दी गई हैं। दूसरे, श्रमिकों की शिक्षा के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत अध्यापक-प्रशासक (Teacher Administrators) एवं श्रमिक-शिक्षक (Workers Teachers) प्रशिक्षित किये जायेंगे। श्रम समस्याओं पर जाँच पड़ताल करने के लिए स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाओं को सरकारी सहायता देने का प्रबन्ध भी किया गया है।

तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम नीति

श्रम नीति का दृष्टिकोण अथवा लक्ष्य—

अगल वर्षा में उन विचारों का प्रभाव पूर्ण रूप में दिखाई पड़न लगेगा जिन्हें द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में अपनाया गया था। तीसरी योजना को भी श्रम-नीति का विकास करने तथा इसके आधारभूत उद्देश्य की पूर्ति में अपना महत्वाग देना है। जो भी कदम उठाया जाय वह आयाजित आर्थिक विकास की न केवल तात्कालिक वरन् दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। प्रगति के सामने सभी पक्षों को व्याप-पूर्ण भाग मिल तथा आर्थिक व सामाजिक संगठन का विकास समाजवादी समाज के आदर्शानुसार है। पंच वर्षीय योजना के उद्देश्य की पूर्ति में श्रमिक वग एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है और औद्योगीकरण की गति के साथ इसमें अधिक वृद्धि होती जायेगी। अधिक सफलताओं का अनुमान केवल उत्पादन और आय के आँकड़ों से ही नहीं वरन् आर्थिक क्रिया के सभी पक्षों की मलाई में लगाना चाहिए। एक ऐसे समाज का विकास होना चाहिए, जिसमें लोग अपने-अपने अधिक लाभ के लिए नहीं, वरन् सामान्य लाभ के लिए पारस्परिक दायित्व का अनुभव करते हुए कार्य करेंगे।

श्रम नीति के लक्ष्य की पूर्ति के लिए विविध आयोजन—

श्रम-नीति का जो लक्ष्य निश्चित किया गया है उसकी पूर्ति के लिए निम्न आयोजन किये गये हैं—

(१) औद्योगिक सम्बन्ध—

(१) तृतीय पंच वर्षीय योजना में औद्योगिक सम्बन्धों का विकास उस आधार पर होगा जो कि गत तीन वर्षों में आचार संहिताओं के कार्यान्वित होने में विकसित हुआ है। आचार संहिता सम्बन्धी दायित्वों का ज्ञान श्रमिकों एवं सेवायोजकों के सभी संगठनों को कराना होगा, ताकि औद्योगिक सम्बन्धों में अधिक सुधार हो। आचार संहिता की सत्ता पक्षकारों की सहमति पर निर्भर है। इस सत्ता को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

(२) श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य उठने वाले मतभेदों को हल करने के लिए ऐच्छिक मध्यस्थता के मिशनरों का प्रयोग बढ़ाने के उपाय करने होंगे। ऐच्छिक मध्यस्थता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा। सरकार को चाहिये कि क्षेत्रीय एवं उद्योग वार आचार पर मध्यस्था के पैनल बनाने में पहल करे।

(३) सेवायोजकों एवं श्रमिकों के बीच मधुर सम्बन्धों का विकास करने के उद्देश्य से प्लान्ट स्तर पर वर्क्स कमेटियों की स्थापना की कानूनी व्यवस्था की गई है। यह आवश्यक है कि वर्क्स कमेटियों के कर्तव्यों को ट्रेड यूनियनों के कर्तव्यों से पृथक् रखा जाय, जिसमें उन्हें श्रम सम्बन्धी मामलों के जनतन्त्रीय प्रशासन की एक सहाय्य एजेंसी बनाया जा सके।

(४) तृतीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि के लिये एक मुख्य कार्यक्रम नवीन उद्योगों एवं इकाइयों में संयुक्त प्रबन्ध परिपक्वों की योजना को अधिकारिक बढ़ाना है। जन-तंत्रीय आधार पर आर्थिक व्यवस्था के शान्तिपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है। प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग देना एक मौलिक सिद्धान्त व गम्भीर आवश्यकता के रूप में स्वीकृत कर ली जाय। कालान्तर में इससे श्रम व प्रबन्ध के बीच खाई के भरन में सहायता मिलेगी। उन सभी सस्यानों में, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में, जहाँ अनुकूल दशाय उपलब्ध हो, संयुक्त प्रबन्ध परिपक्व स्थापित कर देनी चाहिए। जिन सस्यानों में संयुक्त प्रबन्ध परिपक्व कायम हो गई है वहाँ श्रमिकों की शिक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम अपनाया जायेगा।

(५) श्रमिकों की शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम सरकार एक अर्द्ध स्वशासित बॉर्ड के द्वारा चला रही है उसमें सभी सेवायोजकों व श्रमिकों के संज्ञानों का सहयोग लिया जाना है। तृतीय योजना में इस योजना को बड़ पैमाने पर चलाया जायगा। जब तक श्रमिक साक्षर नहीं होंगे तब तक विभिन्न कार्यक्रमों को सफलता नहीं मिल सकती, अगले वर्षों में अधिक से अधिक श्रमिकों को साक्षर करने का प्रयास होना चाहिए।

(६) श्रम संधि के दृष्टिकोण, कार्यों व प्रयासों में बहुत परिवर्तन होना चाहिए, ताकि वे नवीन विकासशील परिस्थितियों में फिट हो सकें। उन्हें औद्योगिक एवं आर्थिक प्रशासन का एक अनिवार्य अंग मान लेना चाहिये, इनको भी चाहिये कि अपने दायित्वों को सच्चाई से निभायें, ट्रेड यूनियन के नेता स्वयं श्रमिक वर्ग से उपलब्ध होने चाहिए। आचार संहिता में यूनियनों को मान्यता देने का जो आधार स्वीकृत किया गया है वह देश में एक सुदृढ़ एवं स्वस्थ ट्रेड यूनियन आन्दोलन का विकास कर सकेगा, ऐसा विश्वास है।

(७) औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके चुनाव व प्रशिक्षण में अधिक सावधानी रखनी होगी। ट्रेड यूनियन के सदस्यों व समझौता कराने वाले समुचित योग्यता स्तर के होने चाहिये, ताकि वे अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। इस आशय के लिये एक उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है।

(II) मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा—

•यूनितेड मजदूरी विधेयक को पहले से अधिक अच्छी तरह लागू करने के लिए हमें निरीक्षण व्यवस्था को और अच्छा बनाना होगा। जैसे-जैसे सम्भव हो, वेतन मण्डलों को और उद्योगों में भी स्थापित करना चाहिए। बीएस सम्बन्धी दावों और बीएस की अदायगी के लिए निर्देशक सिद्धान्त और आदर्श निर्धारित करने की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। जहाँ जहाँ ५०० या इससे अधिक औद्योगिक कर्मचारी हैं उन सभी कन्ट्रा में कर्मचारी राज्य बीमा

योजना लागू की जायगी। इसके फलस्वरूप कुल मिलाकर लगभग ३० लाख श्रमिक इस योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे। कर्मचारी प्राविष्टेष्ट पड़ योजना का जो इस समय ५८ टोनों पर लागू है विस्तार किया जाएगा।

अब तक केवल संगठित उद्योगों के मजदूरों को ही सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाभ पहुँचा है। मजदूरों के ऐसे वर्ग भी हैं, जिनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी ओर समाज को अधिक ध्यान देना चाहिए। इनमें विशेष तौर पर वे विप्लवांग व्यक्ति, काम के अयोग्य वृद्ध व्यक्ति और स्त्रियाँ और बच्चे शामिल हैं, जिनकी आय का कोई उपयुक्त मापन नहीं है। स्वयंसेवी और खैरानी संस्थाएँ, नगरपालिकाएँ, पंचायतों और पंचायत समितियाँ को स्थानीय समुदायों की सहायता से अपनी कार्य-वाहियाँ चलाने योग्य बनान और उन्हें छोटी सहायता देने के लिए एक छाटा सहायता कोष स्थापित करने का सुझाव विचाराधीन है।

(III) काम करने की दशाय सुरक्षा एवं कल्याण—

काम करने की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण सम्बन्धी जो कानूनी व्यवस्थायें हैं, उनको और प्रबलतर तरह कार्यान्वित करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस संबंध में काम करने की व्यवस्था और दक्षता सुधारण में केन्द्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों को विशेष गौरव देना है। कारखाना दुर्घटनाय कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एक श्रमिक मनाहकार समिति की नियुक्ति की जायगी। खान उद्योग में सुरक्षा-शिक्षा और प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी।

(IV) रोजगार और प्रशिक्षण सुविधायें—

कारीगरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत ५८ ००० नई जगहों की व्यवस्था की जायगी। इस वृद्धि का फलस्वरूप कुल प्रशिक्षण क्षमता बढ़ कर लगभग १ लाख हो जाएगी, ताकि उनकी रोजगार की सम्भावनाएँ व्यापक हो जाएँ। दस्तकारी प्रशिक्षकों के लिए जो तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनका उन्नयन होगा और योजना की अवधि में तीन और केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अप्रगटित शिक्षण योजना को अनिवार्य रूप देने का विचार है और इस सम्बन्ध में एक विधायक सदन में पेश किया जाएगा। हर जिले में कम से कम एक रोजगार दफ्तर खोलने के लक्ष्य को सामने रखते हुए तीसरी योजना की अवधि में लगभग १०० नए रोजगार दफ्तर खोले जाएँगे। छुट्टी किए गए कर्मचारियों की सहायता के लिए, छोटे पैमाने पर एक कोष की स्थापना करने का विचार है।

(V) उत्पादकता—

प्रबंधकों को चाहिए कि वे श्रमिकों के लिए मशीन, काम करने के उपयुक्त स्थिति और तरीके, पर्याप्त प्रशिक्षण और उद्युक्त मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रेरणाएँ

प्रदान करने की कोशिश करें। काम में लगे श्रमिकों की योग्यता और दक्षता में वृद्धि करने के लिए उद्योग, मजदूर मधो और सरकार को मिलजुल कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिए। हम देश में जब तक उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि नहीं होती, तब तक श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता। श्रमिकों को अपने तथा देश के हित में वैज्ञानिकन के रास्ते में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उन्हें इसकी मांग करनी चाहिए। वैज्ञानिकन का अधिक में अधिक विस्तार हो सना है, यशसे कि वैज्ञानिकन के फलस्वरूप निवाल हुए लोगो की श्रमिकों की महमनि में नौकरी में रखने और दूसरे कामों में लगाने की ठीक व्यवस्था हो। भारतीय श्रमिक सम्मेलन प्रब कार्यकुशलता और कल्याण-महिता बनाने के काम का अपन हाथ में लेगा। विभिन्न स्तरो पर काम करने वाले प्रबन्धकों को मालिक-मजदूर सम्बन्धों के बारे में प्रशिक्षण इन पर और अधिक ध्यान दना हागा।

(VI) अनुसधान—

मन् १९६० में धम-अनुसधान पर हुय एक सम्मेलन में धम मामलो में सम्बन्धित आँकडा व अभाव की चर्चा हुई थी। इसे दूर करने के लिय एक केन्द्रीय समिति बनाई जायगी, जिसमें सरकार, मेवायोजका व श्रमिकों के संगठनों, विश्व-विद्याल। आदि क प्रतिनिधि हों। यह समिति धम अनुसधान कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss briefly the broad features of existing factory legislation in India. How far does it safeguard effectively interests of the workers?
2. Give a brief history of mining legislation in India during the last sixty years
3. Give a brief history of the Plantation Legislation in India, pointing out the important changes made in recent years.
5. Briefly summarize the history of Transport legislation in India with special reference to changes made in recent years.
5. Define 'Minimum Wage', and discuss the main provisions of the Minimum Wage Legislation in India. Briefly summarize the merits and demerits of a minimum wage.
6. Briefly summarize the Labour Policy of the Govt of India.

लाभ अंश भागिता एवं औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग

(Profit Sharing & Workers' Participation In Management)

(1) लाभ अंश भागिता (Profit Sharing)

प्रारम्भिक—

वर्तमान औद्योगिक प्रणाली के अन्तर्गत श्रम का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। वे दिन चले गये जबकि श्रम को उत्पादन का एक सामान्य घटक नमूना जाना था। दिलाहैलफिया घोषणा में इस सिद्धान्त की पुष्टि की गई थी कि श्रम केवल एक वस्तु नहीं है, जिसका विनिमय-मूल्य मजदूरी हो, बल्कि वह एक मनुष्य (Human being) है और इस नाते एक मानव की भाँति 'श्रम' को अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति का पूर्ण अवसर मिलना चाहिये। इस परिवर्तित धारणा के आधार पर आज विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में लाभ अंश भागिता (Profit Sharing) एवं सहभागिता (Co-partnership) की योजनाएँ कार्यान्वित की गईं। कुछ देशों में तो लाभ अंश भागिता एवं सहभागिता दोनों को ही साथ-साथ लागू किया गया है। इस अध्याय में औद्योगिक श्रमिकों में प्रेरणा पैदा करने की इन दो योजनाओं पर ही विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

‘लाभ अंश भागिता’ से आशय—

‘लाभ अंश भागिता’ से आशय ऐसी व्यवस्था का है जिसके अन्तर्गत सेवायोजक अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त अपने होने वाले लाभ में एक पूर्व निश्चित अंश देने के लिये प्रस्तुत होते हैं। हेनरी सीजर के अनुसार, “लाभ अंश भागिता स्वतन्त्र इच्छा से किया गया एक ठहराव है, जिसके द्वारा कर्मचारियों को लाभ में से एक पूर्व निश्चित भाग मिलता है।”¹ ब्रिटेन में लाभ अंश भागिता एवं सहभागिता सम्बन्धी जो रिपोर्ट सन् १९२० में प्रकाशित की गई थी उसमें लाभ अंश भागिता का प्रयोग उन दशाओं के लिये किया गया है जिनमें एक सेवायोजक अपने श्रमिकों से, उनके श्रम के आंशिक पुरस्कार के रूप में तथा उनकी मजदूरी के अतिरिक्त, सस्था के लाभ में से एक पूर्व निश्चित भाग देना तय कर लेता है।²

1 Henry R Seager—Principles of Economics, p 581

2 U. K Profit Sharing and Copartnership Report, 1920.

लाभ अंश भागिता की ४ मुख्य विशेषतायें हैं :—(१) लाभ का वह भाग जो श्रमिकों को वितरित किया जाता है, सस्या के असली लाभ अथवा अशधारियों को दिये गये लाभानुश पर निर्भर करता है एवं उसी के अनुसार घटता-बढ़ता भी है; (२) श्रमिक को लाभ का कितना प्रतिशत दिया जाय, यह पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। तत्पश्चात् सेवाभोजक उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, (३) लाभ अंश भागिता की व्यवस्था का लाभ कुछ विद्योप कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होना, वरन् इसका लाभ सस्या के प्रत्येक श्रमिक का मिलता है, और (४) वैयक्तिक लाभ अंश निर्धारण करने की मोटी रूप-रेखा सब श्रमिकों को पहले से ही ज्ञात होती है।

‘लाभ अंश भागिता’ योजना की वाछनीयता—

इस योजना के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व सामाजिक न्याय का है। आज प्रायः सभी यह स्वीकार करने लगे हैं कि श्रम का उत्पादन मूल साधन है। यदि श्रमिक कार्य न करे, तो मनवाछित लाभ मिलना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव हो सकता है। सस्या को जो लाभ होना है उसका प्रमुख श्रेय श्रमिकों को ही प्राप्त है, उन्हीं के परिश्रम व पसीने के परिणामस्वरूप उच्चतर व श्रेष्ठतर उत्पादन सम्भव हो पाता है। अतः यह अन्यायपूर्ण होगा यदि सस्या के लाभ में उनको कोई भी भाग न दिया जाय। पूँजीपति वर्ग प्रायः समस्त लाभ पर अपना एकाधिकार सम्भत्ता है। उसकी इस भावना से श्रम एवं पूँजी के बीच की खाई गहरी हो जाती है, जिसका परिणाम औद्योगिक सघर्ष, उत्पादन में कमी और उत्पादन के साधनों का अप-व्यय होता है। अतः यह न्यायसंगत प्रतीत होता है कि औद्योगिक शालि की स्थापना के हेतु लाभ-अंश भागिता की योजना को कार्यान्वित किया जाय। इस योजना के परिणामस्वरूप श्रम व पूँजी के हित परस्पर वध जाते हैं, सघर्ष की आशंका कम हो जाती है एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। इससे श्रमिकों में स्थाई रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति भी प्रोत्साहित होती है। इसके अतिरिक्त वे श्रमिक जिन्हें लाभ में भाग प्राप्त होता है, बहुत सावधानी एवं परिश्रम से अपना कार्य करते हैं। परिणामतः श्रमिक माल का अप-व्यय कम करते हैं तथा मशीन व उत्पादन के यन्त्रों का विशेष ध्यान रखते हैं। यही नहीं, उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती है। रोबर्ट ओवन के शब्द इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं, जो कि उन्होंने एक मिल मालिक से कहे। इस मिल मालिक ने ओवन से कहा था कि यदि मेरे श्रमिक चाहें, तो अच्छा कार्य करके १०,००० पौंड प्रति वर्ष बचा सकते हैं। इस पर ओवन ने कहा कि “तब आप उनको ५,००० पौंड प्रति वर्ष इस कार्य के लिये वश नहीं दे देते हैं”। लाभ अंश भागिता का एक अन्य लाभ यह होता है कि ऊँची योग्यता वाले श्रमिक लाभ अंश भागिता वाली संस्थाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। इससे उत्पादन क्षमता और भी बढ़ जाती है।

भारत में लाभ अंशभागिता की योजनायें (Profit Sharing Schemes in India)

विचार का विकास—

सन् १९४६ एव सन् १९४७ की औद्योगिक अनादित से विवश होकर दिसम्बर सन् १९४७ में भारत के तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री सन्मुखम चट्टी ने अन्तरिम बजट बहस के समय इस बात की घोषणा की कि श्रमिकों में अधिक उत्पादन के हेतु प्रेरणा पैदा करने के लिये सरकार लाभ अंश भागिता की योजनाओं की सम्भावना पर विचार कर रही है। उसी समय भारत सरकार ने एक उद्योग-सम्मेलन (Industries Conference) बुलाया, जिसमें प्रान्तीय और देशी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, अनेक महत्त्वपूर्ण व्यापारी तथा उद्योगपति एक संगठित श्रम के नेतागण ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 'औद्योगिक शांति का प्रस्ताव' (Industrial Truce Resolution) रखा गया। उस प्रस्ताव में इस बात का दर्शन था कि श्रमजीवी और पूँजीपति दोनों अपने सम्मिलित प्रयत्नों से हुई उत्पत्ति को आपस में बाँट लेंगे, किन्तु यह तभी सम्भव होगा, जबकि—(अ) श्रमिकों को उचित भूतियाँ दी जाय, (ब) पूँजीपतियों को उद्योग में लगी हुई पूँजी का एक उचित प्रतिफल दिया जाय और (स) उद्योग को स्थिर रखने तथा बढ़ाने के लिये भी उचित राशि रखी जाय। इसके बाद जो शेष बचे उसे पूँजीपति और श्रमिक दोनों बाँट ल।

सन् १९४८ में भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घण्टा में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कुछ समय उपरान्त नई दिल्ली में श्री जगजीवनराम की अध्यक्षता में प्रान्तीय श्रम मन्त्रियों का एक सम्मेलन यह सलाह देने के लिये बुलाया गया कि पूँजी का क्या उचित पारिश्रमिक होना चाहिए तथा श्रम और पूँजी के बीच लाभ का वितरण किस प्रकार हो। इस सम्मेलन के निष्पत्तिसार २५ मई सन् १९४८ को भारत सरकार ने 'लाभ अंश भागिता' पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति के सभापति श्री एस० ए० बेंकटारमन थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट १ दिसम्बर सन् १९४८ को पेश की।

सन् १९४८ की लाभ अंश भागिता समिति—

लाभ अंश भागिता समिति, १९४८ के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं—बेंकटारमन समिति ने सम्बन्धित अनेक बहुसुओं की विस्तृत जाँच के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि लाभ अंश भागिता की ऐसी प्रणाली का निर्धारण करना सम्भव नहीं है, जिसमें 'श्रमिकों के लाभ और श्रम उत्पादन के अनुपातानुसार निर्दिष्ट किया जा सके'। इस समिति ने निम्नलिखित ६ उद्योगों में सर्वप्रथम ५ वर्षों की अवधि के लिये लाभ अंश भागिता की योजना पर प्रयोग करने की सिफारिश की—(१) मूली वस्त्र उद्योग, (२) लूट उद्योग, (३) स्टील (मुख्य उत्पादन), (४) सीमेंट उद्योग, (५) टायरों का निर्माण व (६) मिमरेटो का निर्माण।

समिति ने बताया कि उद्योग के द्वारा प्राप्त किया गया लाभ श्रम के प्रतिरिक्त और भी कनेव साधनों पर निर्भर करता है। श्रम क्या करता है, क्या नहीं करता, इसकी लाभ से कोई सापेक्षिक माप नहीं की जा सकती। इसका प्रतिरिक्त उत्पादन, उद्योग-उद्योग में और प्रत्येक उद्योग की इकाई-इकाई में भिन्न होता है। सामान किम तरह का है, संगठन व निर्देशन का कैसा स्तर है, इन बातों पर भी श्रम की उत्पादकता निर्भर होती है। अतः प्रतिरिक्त लाभ में श्रमिक का भाग एक स्वच्छन्द ढंग में (Arbitrarily) ही निर्दिष्ट किया जा सकता है। यदि एक बार श्रमिका का कुल भाग प्रतिरिक्त लाभ में से निर्दिष्ट हो जाय तो उसे व्यक्तिगत श्रमिकों के मध्य किसी एक पिछले समय में उनकी प्राप्त कुल आय के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिये। इस प्रकार की पद्धति से व्यक्तिगत पारिवारिक व्यक्तिगत प्रयत्ना के अनुसार कुछ सीमा तक सम्बन्धित हो जायेगा।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया कि लाभ ग्रह भागिता की योजना पर विचार करते समय निम्न तीन दृष्टिकोणों को सामने रखना चाहिये—(१) 'लाभ ग्रह भागिता' उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जानी चाहिये अथवा (२) लाभ ग्रह भागिता का उद्देश्य औद्योगिक क्षान्ति प्राप्त करना होना चाहिये अथवा (३) लाभ ग्रह भागिता श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग देना व उद्देश्य से की जानी चाहिये। प्रथम दृष्टिकोण के सम्बन्ध में समिति का यह मत था कि यदि पिछली अवधि की कुल आय के अनुपात में श्रम के उत्पादन का भाग व्यक्तिगत रूप से वितरित कर दिया जाय तो उत्पादन अधिक करने में इससे व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। समिति ने जिस उद्देश्य में लाभ ग्रह भागिता की योजना को कार्यान्वित करने की सिफारिश की वह यह था कि इससे औद्योगिक क्षान्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये समिति ने यह सुझाव दिया कि किसी ऐसे वर्ष में जब श्रमिक या श्रमिका के वष उपयुक्त प्राधिकारियाँ द्वारा घोषित अवधि हड़ताल में भाग लेते हैं, तो लाभ का भाग पूरा अथवा आंशिक रूप में रोक लगा चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई अवधि तालाबन्दी है, तो प्रतिरिक्त लाभ की गणना लाभ ग्रह भागिता के लिये इस प्रकार की जानी चाहिये जैसे कि मानो कोई तालाबन्दी न हुई हो।

पूँजी पर उचित प्रतिफल क्या होना चाहिये, इस प्रश्न को लेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में पूँजी की पूर्ण व्याख्या की है। पूँजी को चुकना पूँजी (Paid-up Capital) माना है और इसके साथ समस्त सेवाओं के भुगतान के लिये उस रिजर्व फण्ड को भी ले लिया है जो व्यवसाय में रखा जाता है। रिजर्व फण्ड में विसाई फण्ड की रकम को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, वरन् केवल उसी सुरक्षित राशि को लिया जावेगा जोकि लाभ में से ली जाती है तथा जिस पर करों का भुगतान किया जाता है। समिति ने इस बात की सिफारिश की कि कुल लाभ में सबसे पहले तो विसाई फण्ड के लिए निधि निकाल लेनी चाहिये और शुद्ध लाभ में से मई प्रथम

रिजर्व फण्ड की राशि निकाल लेनी चाहिये। 'शुद्ध लाभ' से आशय यह है कि कुल लाभ में से घिसाई कोष, प्रबन्ध व्यय एवं करों का भुगतान निकालने के बाद जो शेष रह जाना है वही शुद्ध लाभ है।

पूँजी की व्याख्या करने के बाद समिति ने इस पर उचित प्रतफल के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकाला कि संग्रामों में (जिनके लिये लाभ अक्ष भागता की योजना का लागू करने का भुभाव दिया गया था) पूँजी का प्रतिफल कम से कम इतना होना चाहिए कि प्रोत्साहन मिल और विनियोग बढ़ें। सब पर स्थितियों को देखते हुए प्रतिफल की उचित दर पूँजी पर ६% होनी चाहिये। यदि अतिरिक्त लाभ में ५०% और मिल जाय, तो उद्योग उचित लाभार्थ घोषित कर सकेगा।

अतिरिक्त लाभ में से श्रम का भाग कितना हो, इस विषय में समिति ने यह निष्कर्ष दिया कि यह व्यवसायिक अतिरिक्त लाभ का ५०% होना चाहिये। प्रत्येक श्रमिक का भाग उसकी पिछले १२ महीनों की कुल आय के अनुपात में होना चाहिए। परन्तु इस आय में भँहाई भत्ता अथवा आय कोई बोनस जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया हो, सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी श्रमिक का भाग उसकी मूल मजदूरी के २५% से बढ़ जाता है तो नगद भुगतान उसकी मूल मजदूरी के २५% तक सीमित होना चाहिये तथा शेष राशि उसके प्रावीदेन्ट फण्ड या अन्य किसी हिसाब में रखी जानी चाहिये। सावधानी से विचार करने के उपरान्त सभिनि ने यह भी सिफारिश की है कि श्रमिकों का लाभ प्रत्येक औद्योगिक इकाई के आधार पर होना चाहिये कि नु सूनी वस्तु उद्योग के विषय में यह अफवाह रखा गया कि बम्बई, प्रह-मदाबाद और शोलापुर में लाभ का विभाजन उद्योग और स्थानीय क्षेत्र के समुक्त आधार पर किया जा सकता है।

योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन—

लाभ अक्ष भागिता सन् १९४८ की प्रस्तुत रिपोर्ट में सभी सदस्य एक मत नहीं थे। मिल मालिकों तथा श्रमजीवियों दोनों के ही द्वारा विभिन्न आधारों पर अनेक आपत्तियाँ उठाई गईं। केन्द्रीय सलाहकार परिषद् जिमने इस रिपोर्ट पर विचार किया, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकी। अगस्त व सितम्बर मन् १९५१ तथा जून १९५२ में यह मामला बार बार समुक्त सलाहकार मण्डल की सभाया में विचाराय प्रस्तुत किया गया। औद्योगिक विकास समिति द्वारा स्थापित समुक्त सलाहकार मण्डल के प्रधान श्री गुनजारीलाल नन्दा ने अपने विचार इस प्रकार प्रगट किये —“लाभ अक्ष भागिता तथा वानम जैसी समस्याओं की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि अमेरिका, इङ्ग्लैंड जैसी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संधि एवं भारत के विद्यमानों की सहायता से सिद्धान्तों आदर्शों का स्वरूप की स्थापना की जाय। प्रथम पंच वर्षीय योजना में भी कहा गया है कि लाभ अक्ष भागिता और बोनस के प्रश्नों के लिए विशाल अध्ययन की आवश्यकता है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना ने भी इन सिद्धान्तों के विशेष अध्ययन पर बल दिया।

इस प्रकार लगभग १२ वर्षों से योजना को विकसित करने का प्रश्न लगानार सरकार के विचाराधीन है। अधिकांश मिल मालिकों ने इस योजना का विरोध किया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि योजना को कार्यान्वित करना बिल्कुल असम्भव है। इस सम्बन्ध में वे यह तक प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान समय में, जबकि हमको पूँजी का निर्माण करना है एवं विदेशी बाजारों में अपने देश के प्रति विद्वान् पैदा करना है, ऐसी योजनाओं से सम्बन्धित परीक्षण जोखिमपूर्ण ही सिद्ध होंगे। यह भी कहा गया है कि श्रमिकों को कार्यक्षमता बोनस, उपस्थिति बोनस आदि योजनाओं से कहीं अधिक लाभ हो सकता है। इसके विपरीत लाभ प्रश भागिता वी योजनाओं के प्रस्पष्ट स्वरूप के कारण न तो इससे श्रमिकों को ही लाभ होगा और न मिल मालिक ही लाभान्वित हो सकेंगे। 'टिस्को' का उदाहरण इस सम्बन्ध में भुलाया नहीं जा सकता। इस सन्ध्या में अधिकांशतः बोनस के रूप में श्रमजीवियों को असली लाभ का २२½% भाग दिया गया, परन्तु प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। उत्पादन में इस कमी के अनेक कारण हो सकते हैं, परन्तु कुछ भी हो, यह योजना असफल रही।

निष्कर्ष—

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लाभ प्रश भागिता की योजना को कार्यान्वित करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। अन्य देशों में भी इस योजना से सम्बन्धित प्रयोग विशेष उत्साहवर्द्धक सिद्ध नहीं हुए हैं। इसके विपरीत, मिलमालिकों एवं श्रमिकों के बीच अविश्वास पैदा हो गया है। हमारी सम्मति में भारत की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अन्तर्गत लाभ प्रश भागिता की योजना का प्रयोग श्रेष्ठकर ही होगा। आज हमारा देश एक विशेष प्रकार की क्रांति से गुजर रहा है। औद्योगिक शान्ति के बादल मटार रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रम बर्बाद करने के लिये एवं उसके साथ मानवीय व्यवहार करने के उद्देश्य से तथा औद्योगिक शान्ति की स्थापना के हेतु इस योजना का कार्यान्वयन वाछनीय है। इससे देश में औद्योगिक शान्ति बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होगी। हमारी पञ्च-वर्षीय योजना के अन्तर्गत देश की सबसे बड़ी मांग है "उत्पादन में वृद्धि"। हमें अधिक उत्पादन के हित में श्रमिकों को संतुष्ट रखना पड़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सबसे सुगम उपाय यही है कि श्रमिकों को भी उद्योग के लाभ में भागीदार बनाया जाय।

(II) औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग

(Workers' Participation in Management)

प्रारम्भिक—

औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने के विभिन्न उपायों के अन्तर्गत उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। फिलोसोफिकल घोषणा में इस सिद्धान्त की पुष्टि की गई थी कि श्रम वस्तु नहीं है, जिसका विनिमय मूल्य मजदूरी

हो, वरन् वह एक मनुष्य है और इस लए एक मानव का भावि उो अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति का पूर्ण अवसर मिलना चाहिये। उद्योग के प्रबन्ध में श्रमिकों के भग दाली योजना की तीन प्रधान विशेषतायें हैं—(१) श्रमिक निर्धारित वेतन के प्रतिरिक्त सस्था व श्रमली लाभ का भी कुछ अंश पाते हैं (२) श्रमका के वयक्ति लाभ का कुछ अंश सस्था की पूँजी में सम्मिलित कर लिया जाता है और (३) अंश पूँजी क सथायी ढान व न त श्रमिका का सस्था के प्रबन्ध एवं उसी व्यवस्था में भी अधिनार मिल जात है। इस प्रकार उद्योग के भविष्य का निर्माण करने का उद्देश्य भी सुगमसर मिलता है।

योजना के लाभ—

कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि में तो यह योजना बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है। मवप्रथम, यह एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है और श्रमिक का सामाजिक स्तर ऊँचा करती है। ऐसी योजना के अभाव में, श्रमिक प्रायः यही समझते हैं कि वे एक बड़ी मशीन के बस पुर्जे मात्र हैं और सारी बात उन पर बरबस लादी जाती हैं, परन्तु उद्योग के प्रबन्ध में श्रमिका के भाग की योजना में इस समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि उनके प्रतिनिधियों को मिल मालिकों से आमने सामने बैठकर बात करने का मौका मिलता है दूसरे यह योजना श्रमिकों के हृदय में परिश्रम एवं प्रसन्नता से कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। उनके परिश्रम के फलस्वरूप ही सस्था को अधिक लाभ हो सकता है और श्रमिक में अधिक लाभ में ही उनका भी सामाजिक बढता है। यही प्रेरणा का साधन है। प्रबन्ध में भाग लेने से श्रमिकों को विश्वास उत्पन्न होता है जिससे उनकी कार्यक्षमता बढती है। बढी हुई कार्य क्षमता से केवल मिल मालिकों को ही लाभ नहीं होना वरन् मजदूरों को आय में भी वृद्ध होती है। तीसरे, सेवा-यानक एवं सवायुक्त एक दूसरे व काफी निकट आ जात है, क्योंकि उनके हित परस्पर बंध जाते हैं। इसमें उनमें सहयोग का भावना बढती है और औद्योगिक संघर्ष की संभावना कम हो जाता है। इससे औद्योगिक जननन्व स्थापित हो जाता है एवं अपने भाग्य का स्वयं निर्णायक होने व कारण श्रमिक उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं।

योजना की कठिनाइयाँ—

भिन भा लक इस योजना का पार विरोध करते हैं। इनके मतानुसार, औद्योगिक सस्था के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार केवल उन्हें ही है और इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि श्रमजीवी भा प्रबन्ध में भाग लगे तो सवा-योजना का वह शक्ति, जिसमें व उद्योग उो गवटकाल में सफलतापूर्वक चला ले जाते हैं। नष्ट हो जायगी। सेवायोजक प्रायः यह भी दलील देते हैं कि एक पहिय में दो ड्राइ-वर होने से जिस प्रकार पहिया अग्रं नहीं बढ़ सकता उन्ही प्रकार उद्योग भी नहीं चल सकता। तीसरे, वे यह भी तक प्रस्तुत करते हैं कि श्रमिका के प्रतिनिधियों के पास

म तो पर्याप्त ज्ञान ही होना है और न टेक्नीकल अनुभव ही, अतः वे सही दशा में उद्योग का मार्ग-दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। सहभागिता की योजना की एक अतिरिक्त कठिनाई यह है कि यह योजना संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डलो में ही लागू की जा सकती है, अन्य समस्याओं में नहीं। श्री फिर्ले ने विचार में सहभागिता से विशेष लाभ की आशा नहीं है।

उपयुक्त तर्क देखने में सार्थक भले ही प्रतीत हो, परन्तु इसमें हमें यह न सोच लेना चाहिये कि सहभागिता की योजना पूर्णतः व्यर्थ है। स्वार्थी वर्ग ने सदैव प्रत्येक नई विचारधारा का विरोध किया है, चाहे वह प्रजातन्त्र हो, राष्ट्रीयकरण या सहकारिता।

विदेशों में योजना की प्रगति—

कुछ देशों में औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग की योजना ने पर्याप्त उन्नति की है। इङ्ग्लैण्ड में निजी एवं राजकीय दोनों क्षेत्रों के उद्योगों में कर्मचारियों को भाग देने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समितियों का संगठन किया गया है। इन समितियों में मिल मालिक तथा मजदूर दोनों के प्रतिनिधि होते हैं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त वोट द्वारा होता है। इन समितियों के प्रमुख कार्य निम्न हैं :—

(१) कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण का प्रबन्ध करना।

(२) मजदूरों की ट्रेनिंग, शिक्षा एवं अनुशासन सम्बन्धी नियमों तथा वैयक्तिक समस्याओं की देखभाल करना।

(३) उत्पादन पद्धति में सुधार करना तथा समय और मशीनों का अधिकतम उपयोग करना।

(४) उद्योगों में सुधार के लिये सुझाव देना।

फ्रान्स में श्रमजीवियों को उद्योगों के प्रबन्ध में भाग देने की प्रथा का श्रीगणेश सन् १९४५ में हुआ। एक अधिनियम द्वारा गैर सरकारी उद्योगों में, यदि ५० से अधिक श्रमजीवी कार्य करते हैं, तो कार्य समितियाँ का संगठन अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक राजकीय उद्योग में कार्य समितियों का निर्माण किया गया है और कर्मचारियों का परामर्श प्रत्येक पक्ष पर किया जाता है।

जर्मनी में ऐंगी योजना का नाम 'मह-निर्धारण' (Co-determination) है। इसके तीन मुख्य पहलू हैं—आर्थिक, वैयक्तिक तथा सामाजिक। श्रम-जीवियों की सहमति प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले पर जैसे उनकी भर्ती, ट्रान्सफर, पदोन्नति, काम के घण्टे, मजदूरी की दर, छुट्टी इत्यादि में ली जाती है। इस योजना के परिणामस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा अथवा नहीं, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा

सकता, परन्तु यह सत्य है कि श्रमिकों में इससे काफी सन्तोष पैदा हो गया है। यूगो-स्लाविया, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैण्ड, बेल्जियम आदि अन्य देशों में भी उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमजीवियों को भाग देने की योजनाएँ कार्यान्वित हो चुकी हैं एवं परिणाम-स्वरूप उसमें अधिक सन्तोष के वातावरण का निर्माण हुआ है।

भारत में उक्त योजना का स्थान—

भारतवर्ष में औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग की योजना अभी भली प्रकार नहीं पनपी है। यत्र-तत्र द्वि-दलीय समितियों का निर्माण हुआ है, किन्तु उन्हें कमचारियों के भाग देने की व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। हाँ, भारत सरकार ने सन् १९४८ एवं सन् १९५६ की नीतियाँ पे इस ओर सकेत किया। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में भी इसका उल्लेख है। योजनानुसार एक समाजवादी समाज की रचना लाभकारी सिद्धान्तों पर नहीं की जा सकती उसके लिये ना समाज सेवा के सिद्धान्त को अपनाना पड़गा। यह आवश्यक है कि यजदूर मर्मभे कि वह प्रगतिवान् राष्ट्र का निर्माण में अपना योग दे रहा है। प्रजानात्रक समाज को संगठित करने के पहले औद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापना अति आवश्यक है। द्वितीय योजना के सफल संचालन के लिये कमचारियों का प्रबन्ध में अधिकाधिक सहयोग आवश्यक है। इससे उत्पादन बढ़ेगा, मजदूर उद्योग के तार में अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें अपने विचार प्रगट करने का मौका मिलेगा। इन सबका अन्तिम परिणाम होगा—औद्योगिक शान्ति की वृद्धि। प्रबन्ध में श्रमजीवियों को भाग देने की योजना को वास्तविक रूप प्रदान करना तथा इससे उत्पन्न होने वाला समस्याओं के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने १० सदस्य वाले एक मण्डल की स्थापना की, जिसने अक्टूबर सन् १९५६ में भारत से बाहर ग्रेट ब्रिटेन फ्रान्स जर्मनी स्वीडन यूगोस्लाविया और बेल्जियम का दौरा किया।

अध्ययन मण्डल की सिफारिशें—

इस अध्ययन मण्डल की रिपोर्ट जून सन् १९५७ में प्रकाशित हुई। अपनी रिपोर्ट में मण्डल ने तो विभिन्न देशों में प्रचलित व्यवस्था का विवरण दिया है और अन्त में उनमें भारतवर्ष में इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में निम्न सिफारिशें की हैं—

(१) श्रमजीवियों को प्रबन्ध में भाग देने का अधिनियम किन् उद्योगों पर लागू हो, यह निर्णय करने का अधिकार सरकार को होना चाहिये। अध्ययन मण्डल के मतानुसार छोटे उद्योगों को छोड़ देना उचित होगा। यह प्रणाली उन्हीं उद्योगों में लागू की जाय, जिनकी प्रबन्ध-व्यवस्था सवश्रेष्ठ हो।

(२) अध्ययन मण्डल का मत है कि यदि उद्योग या कारखाने की कई शाखायें न हों, तो उनके लिए एक ही संयुक्त परिषद होनी चाहिये। जो उद्योग विभिन्न स्थानों

में फैले हुए हैं उनमें अलग-अलग स्थानीय, प्रादेशिक या राष्ट्रीय परिपदें होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार इन परिपदों की उप-समितियाँ, प्राविधिक समितियाँ और अध्ययन गोष्ठियाँ होनी चाहिए, जो विभिन्न विषयों की देखभाल कर सकें।

(३) अध्ययन मण्डल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अनेक देशों में प्रबन्ध परिषदा में कर्मचारियों एवं मालिकों की समस्या बग़ावर रखी जाती है, किन्तु यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि निर्णय तो आपस के सहयोग व समझौते से होना चाहिए, न कि बोट से। अध्ययन मण्डल ने इस बात की विशेष रूप से सिफारिश की है कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदा में शिल्पिकों या टेक्नीकल कर्मचारियों को भी अवश्य स्थान दिया जाय।

(४) अध्ययन मण्डल का मत है कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदों और श्रम सघों का काम स्पष्ट रूप से नियत कर देना चाहिये। सेवायोजकों में नौकरी के नियमा आदि के सम्बन्ध में सौदा करने का काम श्रम सघों के हाथ में होना चाहिए। कारण, श्रम सघों की संयुक्त प्रबन्ध परिषद से सहयोग करना चाहिए।

(५) रिपोर्ट में कहा गया है कि कारखानों में काम के नियम (Standing Orders), छुट्टी, रेशनलाइजेशन, कारखाने की बन्दी, नये तरीके अपनाते तथा दण्ड आदि में प्रबन्ध परिषद से परामर्श किया जा सकता है।

(६) प्रबन्ध परिषद को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे उद्योग की आर्थिक स्थिति, बाजार की हालत, उत्पादन और बिजली के कार्यक्रम, कारखाने के संचालन, आश-व्यय और हानि लाभ तथा वार्षिक चिट्ठों आदि की जानकारी प्राप्त करें और उनके बारे में अपने सुझाव दें।

(७) प्रतिवेदनानुसार संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि श्रम एवं पूँजी में सम्पर्क रहे, श्रम-जीविका क रहन सहन के स्तर में सन्तोषजनक सुधार हो, श्रमिका को काम के सम्बन्ध में नये सुझाव देने के लिए प्रेरणा मिले और कारखाने में सम्बन्धित अधिनियमों और अनुबन्धों को पालन करने में सहायता मिले।

(८) प्रबन्ध-परिषदों में निस्स्माह पैदा न हो, इस उद्देश्य से उन्हें संचालन तथा प्रशासन का कुछ काम सौंपना चाहिए, जैसे श्रमिका के लिए कटगण-कार्य की व्यवस्था, काम सिखाने की व्यवस्था, काम के घण्टों और छुट्टियों को तय करने तथा उपयोगी सुझावों के लिए इनाम देने आदि के काम उन्हें सौंपे जा सकते हैं।

(९) अध्ययन मण्डल ने कहा है कि हम जिन देशों में गए वहाँ सक्त्र श्रमिका के लिए कॉलेज, रात्रि कक्षाएँ, शिक्षा गोष्ठियाँ तथा पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था है और ये सारे कार्य श्रम सघों द्वारा संचालित किये जाते हैं, किन्तु भारतवर्ष में धनमाव के कारण श्रम सघ ये कार्य नहीं कर सकते, अतः सरकार को मागे बढ़ाना चाहिए।

(१०) अध्ययन मण्डल ने यह भी संकेत किया है कि विदेशों में श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग देने की योजनाओं में उनकी शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। श्रम-संघ और वही-कहीं कारखाने, श्रमिका को तकनीक एवं आर्थिक विषयों की शिक्षा देने का प्रबन्ध करते हैं।

(११) अध्ययन मण्डल ने यह सिफारिश की है कि श्रमजीवियों की शिक्षा के प्रबन्ध के लिये त्रिदलीय संगठन हों और इस काम के लिये उदायोगिक और श्रम-जीवियों के संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं गैर सरकारी संस्थाओं से मदद ली जाय।

(१२) प्रतिवेदना में कहा गया है कि श्रमिकों के शिक्षित होने और कारखाने के प्रबन्ध का अनुभव प्राप्त होने के बाद उन्हें राजकीय उद्योगों में प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जाय।

संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के कार्य

अध्ययन मंडल की रिपोर्ट में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि 'संयुक्त परामर्श का आशय केवल दानों पक्षों को मिलाकर बैठाना ही नहीं होना चाहिये, वरन् इसका तात्पर्य यह होना चाहिये कि सभी विषयों में संयुक्त रूप में परामर्श हो। टक्कीकल विशेषज्ञों और सुपरवाइजरो को भी परामर्श व्यवस्था में सम्मिलित करना चाहिये। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि संयुक्त प्रबन्ध परिषद् श्रम संघों की स्थाना-तही होनी चाहिये। अर्थात् मजदूरों, बानस और निजी शिकायतों आदि पर ऐसी संयुक्त परिषदों द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिये।'

संयुक्त प्रबन्ध परिषदों को निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना चाहिये
(१) स्थाई आदेशों में परिवर्तन, (२) श्रमिका की छुट्टी, (३) विवेकीकरण एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव, (४) संस्थान को बन्द करना या उत्पादन क्रियाओं को कम करना या बन्द करना, (५) संस्थान में नई उत्पादन प्रणालियाँ लागू करना, (६) भरती एवं दण्ड की कार्य-विधि।

संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का निम्न विषयों में सूचना प्राप्त करने तथा सुझाव देने का अधिकार होना चाहिये :—(१) संस्थान की सामान्य आर्थिक अवस्था, बाजार की प्रवृत्ति, उत्पादन तथा बिक्री कार्यक्रम, (२) संस्थान का संगठन तथा सामान्य संचालन, (३) संस्थान की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाली दशावधि, (४) निर्माण कार्य की प्रणालियाँ, (५) वार्षिक स्थितिविवरण व लाभ-हानि खाता तथा अन्य सम्बन्धित लेख पत्र आदि।

इस भय को दूर करने के लिये कि परिषदों के कार्य के प्रति उदासीनता न आ जाय, इन परिषदों को कुछ प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं, जैसे—(१) कल्याण कार्यों का प्रशासन, (२) सुरक्षा-उपायों की देखभाल, (३) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षार्थी योजनाओं का संचालन, (४) कार्यों के घन्टे और आराम के लिये

अनुसूची तैयार करना, (५) छुट्टियों की अनुसूची बनाना तथा (६) महत्वपूर्ण सुभावों के लिये पारितोषण की व्यवस्था करना ।

अध्ययन मंडल परिषदों के निर्माण में किसी भी बंधन अथवा अनिवार्यता के विरुद्ध था । वह केवल ऐसे कानून बनाने के पक्ष में था, जिसके अन्तर्गत ऐसी परिषदों के निर्माण की अनुमति मात्र मिल जाय । यदि किसी संस्थान की विभिन्न स्थानों पर विभिन्न इकाइयाँ न हों, तो एक संस्थान के लिये केवल एक ही परिषद बनाने की सिफारिश की गई थी ।

भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृति—

अध्ययन मंडल की प्रमुख सिफारिशें जुलाई सन् १९५७ में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार कर ली गई । इस सम्मेलन के निर्णयानुसार १२ सदस्यों की एक उपसमिति बनाई गई, जिसका काम यह था कि इस विषय में अधिक गम्भीरता से जाच पड़ताल की जाय और इस बात का विचार किया जाय कि प्रारम्भ में ऐच्छिक आधार पर कुछ चुनी हुई संस्थाओं में “औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजना” लागू हो सकती है या नहीं । इस उपसमिति ने यह सिफारिश की कि पहले यह योजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के चुने हुये ५० औद्योगिक संस्थानों में चलाई जानी चाहिये । परिणामतः ऐसी औद्योगिक संस्थाओं की सूची तैयार की गई । यह निर्णय किया गया कि परीक्षण हेतु जो इकाई छाँटी जायें उनको निम्नलिखित आधार पर चुना जाय :—

- (१) उनमें सुदृढ़ एवं शक्तिशाली श्रम संघ हों ।
- (२) उनमें कम से कम ५०० श्रमिक काम करते हों ।
- (३) सालिक और श्रम संघ दोनों ही केन्द्रीय संघठनों के सदस्य हों ।
- (४) संस्थान की इस बात में कुछ साख हो कि उसमें औद्योगिक मन्वन्ध सौहार्दपूर्ण रहे है, और
- (५) श्रम व पूँजी दोनों ही पक्ष इस योजना को सहयोग की भावना से लागू करने के हेतु तैयार हों ।

उप-समिति ने यह भी निर्णय किया कि एक पूरे संस्थान के लिये केवल एक परिषद् होनी चाहिये । श्रमिकों के प्रतिनिधियों के, श्रम-सदों द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिये तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों में बाहरी व्यक्तियों की संख्या २५% से अधिक नहीं होनी चाहिये । संयुक्त परिषद में सदस्यों की संख्या १२ से अधिक न हो तथा परिषद की बैठकें भी काम के घंटों के दौरान में ही होनी चाहिये ।

श्रम प्रबन्ध सहयोग सेमिनार—

३१ जनवरी एवं १ फरवरी सन् १९५८ को नई दिल्ली में हुये श्रम-प्रबन्ध सहयोग सेमिनार (Labour Management Co-operation Seminar) में भी

उपसमिति की सिफारिशों पर विचार किया गया। इस सेमिनार की अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्रालय रोजगार मंत्री श्री गुलजारीसाल नन्दा ने की। इसमें मिला मालिकों, श्रम-जीवियों व सरकार के लगभग १०० से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों में से कुछ प्रतिनिधि उन समस्याओं से सम्बन्धित थे, जिनमें योजना पहले से नार्गान्वित की जा रही थी अर्थात् जिन्होंने योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था। सेमिनार में प्रायः सभी लोग इस बात पर एक मत थे कि समुक्त परिषदों में मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर-बराबर होनी चाहिये तथा यह संख्या १२ में अधिक भी नहीं होनी चाहिये जिससे कि परिषदों का कार्य प्रभावशाली रूप से किया जा सके एवं उनका प्रबंध भी स्वतन्त्रतापूर्वक हो सके। छोटी संस्थाओं में सदस्यों की संख्या ६ से कम नहीं होनी चाहिये। सनियम में इस बात पर भी सब सहमत थे कि जो भी नियम लिये जाय वे सर्वसम्मति से स्वीकृत हों। इस बात पर भी सब सहमत थे कि श्रमिकों के प्रतिनिधि स्वयं श्रमिक ही होने चाहिये, परन्तु जहाँ श्रम सब यह अनुभव करे कि वाहरी व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये, तो ऐसी दशा में बाहरी सदस्यों की संख्या एक (२५% से अधिक नहीं) या, पारस्परिक समझौते से २ तक सीमित होनी चाहिये। समुक्त परिषदें इकाई के आधार पर स्थापित की जानी चाहिये। जहाँ एक संस्थान में अनेक विभाग हैं, वहाँ के लिये सेमिनार में यह निर्णय किया गया कि समुक्त परिषदों में प्रतिनिधित्व का प्रश्न एक ही संस्थान पर ही छोड़ देना चाहिये। एक ही क्षेत्र तथा एक ही प्रबंध के अन्तर्गत यदि विभिन्न संस्थान हों, तो उनके सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि योजना को पहले तो इकाई के आधार पर प्रारम्भ करना चाहिये और बाद में जब कुछ अनुभव हो जाय, तो एक केन्द्रीय परिषद की स्थापना की जा सकती है।

अन्त में यह निर्णय किया गया कि प्रबंध में श्रमिकों का जो भी भाग हो वह समुक्त प्रबंध परिषदों के रूप में हो। इन परिषदों के तीन पृथक् कार्य होंगे—

(I) ऐसे कार्य जिनके अन्तर्गत परिषद का उत्तरदायित्व परामर्श देना होगा, उदाहरणतः निम्न विषयों में—

(1) स्थायी आदेशों का प्रस्तावन।

(II) उनमें संशोधन।

(III) उत्पादन की नई विधियाँ लागू करना।

(IV) कुछ प्रक्रियाओं में कमी करना, उन्हें कुछ समय के लिये रोकना अथवा पूर्णतः बन्द करना, इत्यादि।

(II) ऐसे कार्य जिनके अन्तर्गत परिषदों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा, उदाहरणतः निम्न विषयों में—

- (१) सस्थान की सामान्य चालू रहने की योग्यता,
- (11) बाजार की दशा, उत्पादन तथा बिक्री कार्यक्रम,
- (111) सस्थान का संगठन तथा सामान्य संचालन,
- (1४) उत्पादन और कार्य विधियाँ,
- (५) विस्तार तथा इसी प्रकार के कार्यक्रमों की योजना इत्यादि ।

(III) ऐसे कार्य जिनके अन्तर्गत परिषद् का दायित्व प्रशासनात्मक होगा, उदाहरणतः निम्न विषयो मे :—

- (१) कल्याण कार्य,
- (11) सुरक्षा कार्यक्रम,
- (111) व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षार्थी योजनाये,
- (1४) कार्य सूची तैयार करना, तथा
- (५) फारितोपण की व्यवस्था, इत्यादि ।

इसके पश्चात् १० इकाइयों मे उपरोक्त निर्णयों को लागू करने तथा समुक्त प्रबन्ध परिषदों के स्थापित करने के प्रयत्न किये गये । निम्नलिखित ३ निजी सस्थानों एवं राजकीय यातायात (State Transport) मद्रास ने अपने श्रमिकों को प्रबन्ध मे भाग देने की योजनाय कार्यान्वित की हैं :—(१) टाटा लोहा एवं स्पात कम्पनी जमशेदपुर , (२) सिम्पसन ग्रुप इन्डस्ट्रीज मद्रास , (३) मोदी बुनाई व कताई मिल्स, मोदीनगर । निम्नलिखित ३ सस्थाओं मे विभागीय उत्पादन समितियों की भी स्थापना की गई :—(१) टाटा लोहा व स्पात कम्पनी, (२) मोदी बुनाई व कताई मिल्स, (३) इंडियन अल्यूमिनियम वर्क्स लि० बँलूर (५० बगाल) । टाटा लोहा व स्पात कम्पनी जमशेदपुर तथा इंडियन अल्यूमिनियम वर्क्स बँलूर मे योजना के विषय मे त्रिदलीय दलों द्वारा २ अध्ययनों की रिपोर्टें भी प्रकाशित की गई, जिनमे इस क्षेत्र मे हुई प्रगति का उल्लेख है ।

सन् १९६० का द्वितीय सेमिनार—

आठ व नौ मार्च सन् १९६० को नई दिल्ली मे श्रमिकों के प्रबन्ध मे भाग लेने के विषय पर दूसरा सेमिनार हुआ । इस सेमिनार की प्रमुख सिफारिशें निम्न-लिखित थी :—

- (१) केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर एक उचित व्यवस्था की जाय, जो यह देखे कि समुक्त प्रबन्ध परिषदें प्रभावात्मक रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं ।
- (२) इस योजना को और अधिक सस्थाओं तक शीघ्रता से विस्तृत करना चाहिये ।

- (२) केन्द्र में एव त्रिदलीय समिति की स्थापना की जानी चाहिये, जिससे समय समय पर इस योजना की प्रगति का प्रवक्तृत्व किया जा सके और परिषदों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का पता चल सके ।
- (४) एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये, जो इन संस्थानों से सूचनाओं को एकत्र कर सके जहाँ कि योजना लागू है ।
- (५) योजना को लागू कराने के लिये अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

मालोचनात्मक मूल्यांकन—

सितम्बर सन् १९५८ में केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति में कहा गया कि श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने के सम्बन्ध में जो भी प्रगति हुई है वह निराशाजनक है । मार्च सन् १९६० में श्री गुलजारीलाल नन्दा ने भी कहा था कि वे इस योजना की प्रगति से विशेष स्तुष्ट नहीं हैं । मार्च सन् १९६० तक ५० में से केवल २३ इकाइयों ने योजना को लागू किया था, जिनमें से १५ तो सरकारी क्षेत्र में थी और शेष = निजी क्षेत्र में । योजना को लागू करने वाली इकाइयों ने न तो सयुक्त परिषदों की कार्यवाहियों के विषय में कोई ठोस सूचना प्रदान की है और न ही ऐसे विशेषज्ञों से परामर्श लिया है जिनकी नियुक्ति श्रम मन्त्रालय ने इन परिषदों को सहायता देने के लिये की है । इस मन्द प्रगति का कारण दोनों पक्षों में सदेह और भय की भावना है । अधिकतर श्रमिक अशिक्षित होते हैं । परिणामतः प्रबन्ध में भाग लेने के सम्बन्ध में उनके विचार अस्पष्ट होते हैं । आधुनिक औद्योगिक संस्थाओं में प्रबन्ध के लिये टेक्नीकल, प्रशासनात्मक तथा वित्तीय क्षेत्रों में कुशल ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जिनका श्रमिकों में इस समय अभाव है । इसके अतिरिक्त अनेक मालिक अपने अधिकारों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं । अहाँ कहीं भी ये योजनाएँ लागू की गई हैं, वहाँ मालिकों की विशेष रुचि इसका कारण नहीं है, वरन् अनेक स्थानों पर श्रमिकों को केवल बहकाने के लिये यह योजना कार्यान्वित की गई है ।

यह सत्य है कि विश्व के कुछ उन्नतिशील राष्ट्रों में औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग की योजनाएँ सफल हुई हैं, परन्तु हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि भारत की परिस्थितियाँ इनसे भिन्न हैं । हमको ऐसी योजनाएँ कार्यान्वित करनी चाहिये, जो हमारी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुरूप हों । यदि इस योजना में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें इसे धीरे-धीरे करना होगा और अगला चरण उठाने से पूर्व पहले कदम को ठीक प्रकार से जमा लेना चाहिये । श्री बी० बी० गिरि ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि श्रमिकों का औद्योगिक प्रबन्ध में भाग लेना वास्तविक अर्थ में उसी दशा में सार्थक सिद्ध होगा, जब श्रमिक और प्रबन्धक दोनों में यह भावना पैदा जाय कि उन्हें कच्चे से कच्चा मिलकर कार्य करना है और अपने-अपने

उत्तरदायित्वों को ठीक-ठीक समझना है। दोनों पक्षों को यह समझना चाहिये कि वे एक ऐसी औद्योगिक प्रणाली में सहभागी हैं, जो समाज को आवश्यक वस्तुओं का प्रदान करती है और इसलिए जनता के हितों की रक्षा करना उनका 'धर्म' है।

STANDARD QUESTIONS

1. Define the term 'Profit Sharing' How far is it a panacea for Industrial ills ?
2. Attempt a lucid essay on "Profit sharing Schemes in India."
3. Write an essay on 'Workers Participation in Management'

अध्याय ३५

पूँजी निर्माण एवं बाजार

(Capital Formation & Capital Market)

पूँजी-निर्माण (Capital Formation)

'पूँजी-निर्माण' से आशय —

पूँजी का निर्माण तब होता है जब कि बचाई हुई आय का कुछ भाग उत्पादक प्रयोगों में लगा दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग उपभोग न करे, तो केवल इतना ही पूँजी का निर्माण नहीं हो जायेगा। पूँजी का निर्माण होने के लिये उपभोग को स्थगित रखने की क्रिया के साथ उत्पादों के साधनों की वृद्धि होना भी आवश्यक है। अर्थात् पूँजी निर्माण की क्रिया तब शक्तिशाली होती है जब कि उपभोग से बचाई हुई आय उत्पादन के लिये प्रयोग की जाय। यह आवश्यक नहीं है कि बचत करने वाला स्वयं ही साहसी हो वरन् वह अपनी क्रय शक्ति या मुद्रा अन्य लोगों के सुपुर्द कर सकता है, जो कि अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से उसका प्रयोग कर सकते हैं। बचतों के हस्तांतरण का कार्य बैंक आदि संस्थाओं द्वारा ऋण लेने की क्रियाओं

द्वारा अथवा पूँजी बाजार के द्वारा सम्पन्न होता है। यह उल्लेखनीय है कि पूँजी के निर्माण पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—(१) भौतिक दृष्टिकोण ने पूँजी निर्माण व्यक्तियों या संस्थाओं में वृद्धि करने की क्रिया है, और (२) भौतिक दृष्टिकोण से पूँजी निर्माण का अर्थ है नया निर्माण तथा वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन। भौतिक दृष्टिकोण ही पूँजी निर्माण का सही अर्थ प्रस्तुत करता है। अतः हम कह सकते हैं कि नये निर्माण, उत्पादकों की स्थाई माज-मजा के विस्तार, स्टॉक की वृद्धि एवं विदेशी विनियोगों में वृद्धि के प्रयोग करने की क्रिया ही 'पूँजी का निर्माण' है।

पूँजी निर्माण का महत्त्व—

'मुद्रा' वह धुरी है जिस पर आर्थिक क्रियाओं का चक्र घूमता है। अतः पूँजी ही वह आधार है जिस पर किसी राष्ट्र की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का विशाल ढाँचा खड़ा होता है। यदि हम उत्पादकता में वृद्धि करना चाहते हैं तथा यदि आय और रोजगार के स्तरों में वृद्धि करने के इच्छुक हैं, तो यह तभी सम्भव है जबकि पूँजी के निर्माण की दर बढ़ी जाय।

आज विश्वव्यापियों के निरुद्ध देशों में पूँजी निर्माण की गति का बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है, जिसमें लिया है कि प्रारंभिक के कुचक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान दुर्घटनाओं की है। इस मत में लगाया जा सकता है कि एशिया, दक्षिणी-पूर्वी यूरोप व लेटिन अमेरिका में अर्थिक विकास के लिए निम्न आय वर्ग की ६६% जन-संख्या के पास विश्व उनके विचार अस्पष्ट होते हैं। आधुनिक है, जबकि अमेरिका, कनाडा व यूरोप और कुल, प्रशासनात्मक तथा वित्तीय क्षेत्रों में समस्या के पास विश्व की ६७% आय है। इस प्रकार अर्थिकी में इस समय अभाव अभाव तभी हो सकती है जबकि अर्थिकी में अधिकारों को छोड़ने के लिये तैयार

विश्व, वहाँ मालिकों की दृष्टि से स्थितियों में हुआ है। उदाहरण के लिये, ब्रिटेन में को केवल बहुकाली आय का १०% और तेजी के काल में १५% शुद्ध आय है कि विश्व है। यद्यपि विनियोग की दर १० में १५% के बीच परिवर्तित होने की योजना पिछले सन् १८७० और १९१३ के मध्य अपनी राष्ट्रीय आय में १५% वृद्धि स्थिति थी। इसी प्रकार, अमेरिका में सन् १८६६-१९१३ के बीच शुद्ध विनियोग (अर्थात् पूँजी के निर्माण) की दर १३ से १६% के मध्य रही और वहाँ इस अवधि में राष्ट्रीय आय ५ गुनी बढ़ गई। जापान में नई पूँजी का निर्माण सन् १९०० व सन् १९०६ के मध्य औसतन राष्ट्रीय आय का १२% रहा, जबकि उसकी जन-संख्या वार्षिक औसत वृद्धि १.३% थी। इस अवधि में वहाँ प्रति व्यक्ति आय दूनी हो गई। रूस में सन् १९२८-३८ के मध्य शुद्ध विनियोग की दर राष्ट्रीय आय का २०% थी इस अवधि में वहाँ राष्ट्रीय आय में १३% वृद्धि हो गई।

उपरोक्त सम्बन्धों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक पीढ़ी या दो पीढ़ी में प्रति व्यक्ति आय को दूना करने के लिये अधिकांश देशों में शुद्ध विनियोग राष्ट्रीय आय के १२ से १५% तक की दर में हुआ है। अधिकसित देशों में जहाँ रहन-महन स्तर बहुत नीचे है तथा जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहाँ समुचित आर्थिक विकास (जो कि आनन्द्यकताओं के अनुरूप हो) तभी सम्भव है जबकि पूँजी के निर्माण की दर राष्ट्रीय आय के २०% के बराबर हो। पूँजी के निर्माण की दर जितना अधिक होगी, उतना ही अधिक आर्थिक विकास होगा।

भारत में पूँजी निर्माण की दर के सम्बन्ध में योजना समीक्षण के अनुमान—

भारत में योजना आयोग ने निम्न मान्यताओं के आधार पर अगले कुछ दशकों में विकास की सम्भावित दरों में सम्बन्धित अनुमान लगाये हैं :—(i) जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि बराबर ही १.३% की दर से होनी रहेगी, (ii) राष्ट्रीय उत्पत्ति और आय में एक इकाई वृद्धि के लिये पूँजी के स्टॉक में ३ गुनी वृद्धि करनी होगी तथा विनियोग की तिथि से तीसरे वर्ष में उत्पादन की वृद्धि दृष्टिकोण से होगी; और (iii) प्रत्येक अवधि में जो अतिरिक्त आय हो उसे पुनः विनियोग करने के सम्बन्ध में वांछित विकास की दर के अनुसार अनुपात चुनने की सुविधा है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सन् १९५०-५१ के लिये ६,००० करोड़ रु० का था। इस आधार पर, समीक्षण ने गणना द्वारा यह बताया कि २० वर्षों में राष्ट्रीय आय में १६०% वृद्धि की जा सकती है तथा प्रति व्यक्ति आय को दूना किया जा सकता है, बशर्ते प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय के ३ के बराबर वृद्धि पूँजी-निर्माण में कर दी जाय। लेकिन विकास की यह दर समाज के उपलब्ध साधनों पर अत्यधिक भार डालने वाली समझी गई। मंगठानामक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने का भय भी था।

द्वितीय पद-वर्षीय योजना में उद्देश्य राष्ट्रीय आय में २५% की वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों का इतना विस्तार करना कि जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप श्रम-शक्ति की जो वृद्धि हो उसे भी काम मिल जाय तथा औद्योगीकरण की दशा में साहसिक कदम उठाना, जिससे अगली योजनावधियों में अधिक तीव्र विकास के लिये भूमि तैयार हो सके। यह अनुमान लगाया गया था कि राष्ट्रीय आय सन् १९५५-५६ में १०,८०० करोड़ रु० से सन् १९६०-६१ में १३,४८० करोड़ रु० (अर्थात् २५% वृद्धि, हो जायेगी)। इसका अर्थ प्रति व्यक्ति आय सन् १९५५-५६ में २८१ से सन् १९६०-६१ में ३३१ रु० (अर्थात् १८% वृद्धि) होना और प्रथम योजना काल में २५३ रु० में २८१ रु० (अर्थात् ११% वृद्धि होना)। इस सम्बन्ध में निम्न तालिका पर्याप्त प्रकाश डाल सकती है :—

राष्ट्रीय आय, विनियोग एवं बचत

(करोड़ रु० में)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१. राष्ट्रीय आय	६,११०	१०,८००	१३,४८०
२. शुद्ध विनियोग	४४८	७६०	१,४४०
३. शुद्ध प्रवाह विदेशी प्रसाधनों से	(-) ७	३४	१३०
४. शुद्ध घरेलू बचत	४४१	७२६	१,३१०
५. राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में विनियोग	४०.६४	७.३१	१०.६८
६. राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत	४.६८	७.००	९.७

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में ६,२०० करोड़ रु० का विनियोग करने का प्रोग्राम था, जिसके लिये घरेलू बचत की दर को सन् १९५५-५६ में ७% से सन् १९६०-६१ में लगभग १०% तक बढ़ाना आवश्यक हो गया। ६,२०० करोड़ के विनियोग से राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि होना तब ही सम्भव बताया गया, जबकि १,१०० करोड़ रु० विदेशी साधनों से घरेलू बचत के पूरक के रूप में उपलब्ध हो जायें, योजना में बरबादी को रोकने के लिये समन्वय पर बल दिया जाय, उन्नत विधियाँ अपनाने में लोगों का सहयोग मिले व उपभोग के औसत स्तर में कोई प्रसाधारण वृद्धि न हो।

पूँजी निर्माण के स्वरूप—

पूँजी के निर्माण का अध्ययन करने के लिये उस पर दो शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है :—सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी निर्माण और प्राइवेट क्षेत्र में पूँजी निर्माण। सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दो पृथक् इकाइयाँ नहीं हैं, वरन् वे एक ही देह के दो अंग हैं, जो विकास के लिए एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले नियोजन के अन्तर्गत तो मावजनिक एवं प्राइवेट क्षेत्रों में अधिक सहयोग होना अनिवार्य है, क्योंकि एक क्षेत्र की नीतियाँ व कार्यक्रम दूसरे क्षेत्र की नीतियों और कार्यक्रमों को सुप्रभावित या कुप्रभावित कर सकते हैं। स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों की नीतियों व कार्यक्रमों में उचित समन्वय होना चाहिये। यही बात पूँजी निर्माण को भी लागू होती है। अधिकसिद्ध एवं अर्द्ध विकसित देशों में अधिकतर नई पूँजी सरकार द्वारा उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिये, उत्पादन की तुलना में बचत को सीमित करने सरकार बहुत सीमा तक घरेलू बचत बढ़ा सकती है,

प्रथवा लाभो पर कर लगा कर बचत को सरकारी सजाने में ले सकती है। इसी प्रकार विदेशी पूँजी भी अन्तर सरकार ऋणों (inter governmental loans) के रूप में हो सकती है। इससे अनिश्चित, जब सरकार बड़े पैमाने पर कोष एकत्र करने के लिये पूँजी बाजार में प्रवेश करती है, तो प्राइवेट क्षेत्र के विनियोगों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऋण-पूँजी शेयरों में हट कर सरकारी प्रतिभूतियों में जाने लगती है। ऐसी दशा में प्राइवेट उद्योगों को पूँजी का अभाव खटकने लगेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार को सार्वजनिक एवं प्राइवेट क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कोषों का वितरण करना चाहिये।

(I) सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी निमार्ण—

अद्यव्यवस्था की विनियोग सम्बन्धी क्रिया में सरकार को सक्रिय रुचि लेनी पड़ेगी, क्योंकि (1) भारत में पूँजी बाजार असंगठित है, जिससे व्याज की ऊँची दरें वहाँ प्रचलित हैं और भावी अनिश्चितताओं के कारण दीर्घकालीन विनियोग की सीमान्त कृशालता कम है, (2) अनेक विकासवात्मक एवं दीर्घकालीन प्रोजेक्टों में प्राइवेट विनियोगता भाग लेने से जोखिम की गंधिक्ता के कारण हिचकते हैं, (3) सरकार चालू प्राइवेट लाभों और भावी सामाजिक लाभों के बीच की खाई का भरने में दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपना सकती है, (4) ऐच्छिक वचन पर ही विनियोग के लिए निर्भर रहने में आय की असमानता बनी रहने का डर है, क्योंकि धनान्ध लोगों द्वारा जो वचन उपलब्ध की जायेगी वह काफी विद्वान हो सकती है।

किन्तु सरकार द्वारा विनियोग में अधिकधिक भाग लेना और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण एक बात नहीं है। सरकार का विद्यमान सस्याओं का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय सार्वजनिक कोषों का प्रयोग नई सस्यायें व उद्योग खोलने में लगाना चाहिये। सभी उपलब्ध सीमित साधनों का अधिकतम प्रयोग करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है। यदि विद्यमान सस्याओं का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो प्राइवेट क्षेत्र के विनियोग पर बुरा असर पड़ने की सम्भावना भी है।

सरकार के लिये आन्तरिक ग्रंथ प्रबन्धन (Domestic financing) के कई तरीके उपलब्ध हैं, जैसे—करारोपण, ऋण, घाटे की अर्थ-व्यवस्था और श्रम के रूप में विनियोग (Invest man, in kind)। इन तरीकों का चक्रवर्ती नमूने (Cyclical Pattern) पर अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिये, मन्दी की अवधि में मुद्रा प्रसार द्वारा विकास-कार्यक्रमों का ग्रंथ प्रबन्धन किया जा सकता है। साथ में वरा में व व्याज दर में कमी की जा सकती है। लाकन समृद्धि के काल में करारोपण व ऋणों में वृद्धि करनी होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक पूँजी को गतिशील करने की सफलता कई बातों पर निर्भर है—(1) देश में सम्पत्ति-उत्पादन क्रियाय होनी चाहिये, जो कि इतनी

पर्याप्त आय उपलब्ध करें जिस पर टैक्स लगाया जा सके या जिससे से भ्रष्टा लिया जा सके । (ii) सरकारी मशीनरी में पर्याप्त कुशलता व र्वमानदारी हो ताकि सरकार कोष अधिक प्रभावपूर्ण ढंग में एकत्र व खर्च कर सक । (iii) सरकारी आय का काफी बड़ा भाग राष्ट्र निर्माण कार्यों में खर्च चाहिये न कि चालू कार्यों की पूर्ति प्रतिरक्षा अथवा मावजनिक स्मारका क निर्माण कार्यों में ।

नीचे हमने मावजनिक क्षय के दृष्टिकोण से आन्तरिक अर्थ प्रबंधन क आता पर विचार किया है—

(१) करारोपण—विकास वाधकता का अर्थ प्रबंधन करने में करारोपण का बहुत महत्व है क्योंकि इसका द्वारा राशय प्रवाधनों का वाछित योजना में खवाया जा सकता है । लेकिन इस प्रभावशील बनान क लिये चतुरता एवं बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है ताकि इसके कारण समाज के सामान्य हिता को कोई ठेस न लगन पाये । कर व्यवस्था का प्रयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकता है—
(i) विकास अर्थ के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के कुछ भाग को पुन विनियोग क हेतु प्राप्त करने क लिये (ii) आय व वितरण में असमानता कम करने के लिये और (iii) वाछित कार्यों में ही विनियोग को प्ररित करने के लिये । यह प्ररणा कई रूप ले सकती है—अर्थक्ष आर्थिक सहायता स्वीकार करना करारोपण की दर में कमी पूजा माल के आयात पर कर घटना आदि ।

करों द्वारा समाज के उस बचन-कोष का उपयोग किया जाता है जो कि उपभोग करने के बाद आधिक्य के रूप में उपलब्ध होता है कर प्रणाली द्वारा बचतों को प्राइवट प्रयोग से सावजनिक प्रयोग में मोड़ना आसान है लेकिन विनियोग के लिये उपलब्ध बचत की कुल मात्रा में वृद्धि करना अपेक्षित कठिन है । किंतु इस तथ्य का कि करारोपण प्राइवट क्षय व लिय उपलब्ध कोषों से आहरण (Draw ing) करके सावजनिक क्षय के लिये उपलब्ध कोषों की वद्धि करता है यह आशय नहीं लगाना चाहिये कि करारोपण कुन पर र्नि नियोग कम कर देता है क्योंकि करारोपण साव जनिक विनियोग की मात्रा को प्राइवट विनियोग में कमी करके नहीं बरन् उपभोग में कमी करके बढ़ा सकता है । मच तो यह है कि एक अद्ध विकसन देश में जहाँ उपभोग वृत्ति (Propensity to Consume) सामान्यत ऊंची हुआ करती है पूँजी निर्माण को बढ़ाने का एक मात्र प्रभावशाली तरीका करारोपण ही है, जिसके द्वारा सरकार प्रसाधनों को प्राइवट उपभोग से हटकर सावजनिक विनियोग में खवा सकती है ।

यह आवश्यक है कि कर प्रणाली गहराई और क्षत्र दोनों ही दृष्टियों से पर्याप्त हो । लेकिन इसे सम्बन्ध में बरदान क्षमता को नहू भुलाना चाहिये । इस हतु यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय आय के साथ कुल कर आय का क्या अनुपात रखा जाय । भारतय कर आगम राष्ट्रीय आय का केवन ७ या ८% है ।

यह प्रतिष्ठित अन्य अनेक देशों की तुलना में कम है। इससे पता चलता है कि भारत में कर-वृद्धि के लिये पर्याप्त क्षेत्र है। कर-दान क्षमता कर के उद्देश्य से सीमित होती है। इस सीमा पर जनता की मनोवैज्ञानिक दशा का भी प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार को कर से सम्बन्धित उद्देश्य के लिये प्रचार द्वारा जन समर्थन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये।

(२) ऋण—ऋण दो तरह प्राप्त किये जाते हैं—वास्तविक ऋण (genuine borrowing), जो ऐच्छिक बचत के द्वारा प्राप्त हो और मुद्रा प्रसारिक ऋण (inflationary borrowing), जो अनिवार्य बचत के द्वारा प्राप्त हो। प्र-मुद्रा प्रसारिक ऋणों का आर्थिक विकास के अर्थ-प्रबन्धन में विशेष महत्त्व है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि एक आन्तरिक ऋण देश के लिये एक विदेशी ऋण की तरह भार नहीं होता। फिर भी एक सीमा में अधिक आन्तरिक ऋण लेने पर व्याज और पूँजी का शोधन गम्भीर प्राशुस्तिक समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऋणों द्वारा जिन विकास कार्यक्रमों के अर्थ प्रबन्धन को अच्छा समझा जाता है वे निम्नलिखित हैं :—सार्वजनिक सम्पत्तियों के उत्पादन वाले कार्यक्रम, लाभ देने वाले विशेष प्रोजेक्ट एवं विकास कार्यक्रम, जिनके लिये लाभ उठाने वाले व्यक्तियों पर फीस या विहिष्ट कर लगाये जा सकते हैं। उत्पादन व्यय में ऋणों के प्रयोग की प्रवृत्ति का विकास कुछ तो प्रथा के रूप में, कुछ सीमा तक बचतों को आकर्षित करने के लिये और अन्ततः अनु-त्पादक व्यय पर नियंत्रण रखने के लिये हुआ है। भारत में पञ्च-वर्षीय योजनाओं के अर्थ प्रबन्धन में ऋणों द्वारा अर्थ प्रबन्धन को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

(३) घाटे की अर्थ व्यवस्था—घाटे की अर्थ-व्यवस्था या मुद्रा प्रसारिक अर्थ प्रबन्धन पर विचार करते समय प्रश्न यह उठता है कि इसे मुद्रा प्रसार बढ़ाये बिना किस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है अथवा यों कहिये कि करो में वृद्धि करने के एक विवक्षित रूप में घाटे की अर्थ-व्यवस्था किस सीमा तक पसन्द की जानी चाहिये। सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्थिक विकास कम से कम मुद्रा प्रसार द्वारा सुलभ किया जाय। यदि ऐच्छिक बचत पर्याप्त न हो, तो करारोपण के रूप में अनिवार्य बचत के द्वारा कोष इकट्ठे किये जा सकते हैं। यदि तब भी कमी रहे, तो विभिन्न नियन्त्रणों एवं विदेशी ऋणों का सहारा लेना चाहिये। इन सब विकल्पों को अपना कर भी कुछ कमी रह जाये और विकास कार्यक्रम का पूरा करना अति आवश्यक समझा जाय, तो मुद्रा छाप कर कमी को पूरा किया जा सकता है। किन्तु यह अन्तिम विकल्प बहुत खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरीके का प्रयोग तब ही करना चाहिये जब कि अन्य साधन अपूर्ण रह जायें। मुद्रा प्रसार औद्योगिक प्रगतिशील देशों की अपेक्षा अर्द्ध विकसित देशों के लिये अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इन देशों की उत्पत्ति क्रय शक्ति के अनुपात में नहीं बढ़ पायी। मुद्रा प्रसार विभिन्न प्रकार

के उपक्रमों की लाभदायकता को समाप्त कर देना है, श्रमों को परिकल्पी उपक्रमों में अत्यधिक पूँजी लगान के लिये प्रोत्साहन देता है, स्वयं के रूप में पूँजी का संचय होने लगता है। एवं विदेशों विनियोगों का प्रममन को निरस्तार्हित करता है। एक बार धारम्भ होने पर मुद्रा प्रसार की वृद्धिमूलक प्रक्रिया स्थापित हो जाती है।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि सभी घाटे की अर्थ-व्यवस्था मुद्रा प्रसार उपपन्न करती है, चाहे इसकी मात्रा या परिस्थितियाँ कुछ भी हों। किन्तु परिस्थितियों में एवं किस सीमा तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था उचित रूप से की जा सकती है, यह एक विषय की बात है। जिस सीमा तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था मुद्रा प्रसारक होवे उसी सीमा तक उसे अपनाता खतरनाक तो है ही, इसमें सदेह नहीं किया जा सकता। जब घाटे की अर्थ-व्यवस्था से मुद्रा प्रसार का खतरा पैदा हो, तो प्रतिरिक्त करारोपण द्वारा उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

(४) धन के रूप में विनियोग (Investment in kind) —मौद्रिक पूँजी की कमी को पूरा करने के लिये उस विशाल बचत का उपयोग किया जा सकता है जो बेकारी एवं मौसमी बेकारी के रूप में पाई जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों में बहुत ही पाई जाती है। इन देशों में, अत्यधिक पूँजी विनियोग द्वारा धन को प्रति-स्थापित करने के प्रयास अवास्तविक है। आवश्यकता इस बात की है कि पूँजी में वृद्धि करने के साथ-साथ 'पूँजी बचत-युक्तियों' (Capital Saving Methods) का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिये। जब किसी देश को सड़का, सिंचाई की नहरों, ग्रामीण स्कूल-भवनो व डिस्पेन्सरियों, कुँओ आदि की आवश्यकता है तथा वहाँ जनसङ्ख्या में बेकारी एवं मौसमी बेकारी का बोलबाला है (जैसे कि भारत के समान कृषि प्रधान देश में), तो मौद्रिक बचतों और मौद्रिक विनियोगों की जटिल मशीनरी का आश्रय लिये बिना पर्याप्त मात्राओं में पूँजी का निर्माण किया जा सकता है। वास्तव यह है कि जनता से विकास योजनाओं के लिये अथवान कराया जा सकता है। भारतीय पञ्च-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अर्थ-प्रबन्धन का पहलू को विचार में लिया गया है। सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत ऐच्छिक अथवान की महिषा छिपी नहीं है। गांव वालों ने अपने लिये अनेक सड़के, स्कूल व कुये बनाए हैं, बनारोपण किया है और भूमि कटाव को रोकने की योजनाओं में ऐच्छिक अथवान करके मौद्रिक पूँजी की भारी बचत की है। ऐच्छिक अथवान से सम्बन्धित योजनाओं का संचालन जब नेताओं द्वारा किया जाना चाहिये। अथवान से जनता में योजनाओं के प्रति रुचि भी जागृति होती है।

(II) प्राइवेट क्षेत्र में पूँजी का निर्माण—

प्राइवेट क्षेत्र में पूँजी के निर्माण के सम्बन्ध में सराफ कमेट्री ने जो बातें अपनी रिपोर्ट में बताई हैं, वे यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। कमेट्री ने यह अनुभव किया कि भारत

की वर्तमान परिस्थितियों में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में विनियोजन क्रिया की प्रगति में बाधा डालती हैं :—(1) प्राइवेट विनियोग की सामान्य कठिनाइयों व अनिश्चितताओं में वृद्धि तथा साम-भावना के प्रति समाज की भालोचनात्मक प्रवृत्ति । (11) प्राइवेट क्षेत्र के लिये उपलब्ध बचतों में कमी एवं विनियोग करने की क्षमता में कमी । सरकारी विनियोग की वृद्धि के कारण प्राइवेट क्षेत्र में लिये उपलब्ध साधन कम हो गये और कुल विनियोग में वृद्धि होना तभी संभव है जबकि आन्तरिक बचतें बढ़ें या विदेशी बचतें आयात की जायें । अतः सरकार को चाहिये कि विनियोग के लिये वातावरण सुवारे तथा प्राइवेट उपक्रम में विश्वास प्रेरित करे ।

प्राइवेट विनियोगों पर कुप्रभाव डालने वाली निम्न बातों का भी कमेटी ने सकेन किया ।—

(१) राष्ट्रीयकरण का डर होने से उपक्रमियों में उन उद्योगों की स्थापना के प्रति कम उमाह पाया जाता है जिनमें प्रारम्भिक विनियोग बहुत अधिक करना पड़ता है तथा लाभ भी काफी लम्बी अवधि के बाद उदय होते हैं । विदेशों से प्राइवेट पूँजी के आगमन पर भी राष्ट्रीयकरण का भय बुरा असर डालता है । कमेटी की राय थी कि यदि सरकारी प्रवक्ता राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी सरकार के अधिकार का बारम्बार हवाला देना बन्द कर दें तो प्राइवेट विनियोजकों के डर बहुत कुछ समाप्त हो जायें । इसके प्रतिरिक्त, सरकार को दीघवालीन विवास के उद्योगों की राष्ट्रीयकरण से कम से कम कुछ अवधि के लिये मुक्त रखने का आश्वासन दे देना चाहिये । सरकारी उपक्रमों को ऐसी अनुचित सुविधायें न दी जायें, जिसे उन्नी क्षेत्र में सलग्न प्राइवेट उपक्रमों को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े । हर्ष का विषय है कि औद्योगिक नीति, जो सन् १९४६ में घोषित की गई थी उक्त आश्वासन देती है । उसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से प्राइवेट क्षेत्र में सहयोग की कामना की है तथा सुविधाय देने के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों व प्राइवेट उपक्रमों के मध्य कोई भेद भाव न करने का निश्चय प्रकट किया है ।

(२) उद्योग (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम, कन्ट्रोल आफ केपीटल इश्यू आदि के अन्तर्गत सरकार की जो नियन्त्रणात्मक शक्तियाँ हैं उनके कारण कार्यविधियाँ बड़ी अनिश्चित एवं कठिन हो गई हैं । वैसे इन शक्तियों का उद्देश्य आन्तरिक एवं विदेशी विनियम साधना का भित्तिव्ययिता के साथ प्रयोग करना तथा वाञ्छित क्रियाओं में सहायता है, किन्तु उन्होंने प्राइवेट विनियोजन में बाधा डाली है, इसे भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः कमेटी का मत है कि उक्त अधिनियमों की कार्यविधि का विवेकीकरण किया जाय, ताकि उनकी पूर्ति में अनावश्यक देरी न लगे और विनियोग समय पर सुलभ हो जाय । आशा है कि कम्पनी ला प्रशासन-विभाग लाइसेन्स व

रजिस्ट्रेशन आदि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की क्रियाओं में सम्चित समन्वय स्थापित कर सकेगा, जिससे वार्षिक पूँजी हानि में कम से कम समय लगे।

(३) श्रम सम्बन्धी दशाओं में भारी परिवर्तनों को भी कमेटी ने प्राइवेट विनियोजन के लिये निम्नसाध्य बनाया है, क्योंकि उद्योगों एवं कारखानों में तरह-तरह के कानूनों के अन्तर्गत उद्योगपतियों पर अनेक जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अब वे बाजार की परिस्थितियों के साथ उत्पादन को समायोजित करने के उद्देश्य से श्रयवा विवेकीकरण के हेतु श्रमिकों को हटाने में अग्रसर हैं। इसके फलस्वरूप कुछ उद्योगों में तो पर्याप्त कोष उपलब्ध होते हुये भी विवेकीकरण एवं आधुनिकीकरण की गति को धीमा करने के लिये विवश होना पड़ा है। इस सम्बन्ध में यह धाशा की जाती है कि प्राइवेट उपक्रम श्रम के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलेगा और उन्हें उत्पादन का एक मूल साधन न मानकर एक चरन एवं अनुभवशील साधन समझेगा। कई बार विवेकीकरण के पक्ष में श्रमिकों पर अधिक कार्य भार लादने का प्रयास किया गया है। ऐसी योजना से श्रमिकों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिय प्रेरणा नहीं मिलती।

(४) मूल्य नियंत्रण, सामाजिक वितरण की सीमा व उत्पादन सम्बन्धी नियंत्रण न भी आन्तरिक साधनों की अधिकतम र्गतशीलता में नया उद्योग के विस्तार के लिये नई पूँजी को आकर्षित करने में बाधा डाली है। एतत् यहाँ यह न भुलाना चाहिये कि एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नियन्त्रणों का मज़बूत स्थान होता है।

(५) सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन जो गत दशक में हुये हैं उनके कारण परम्परागत विनियोगता बग, जैसे जमींदार, जागीरदार, राजा, नवाब आदि समाप्त हो गया, जिससे औद्योगिक विनियोजन में बड़ी कमी आ गई है। इसके विपरीत, जिन वर्गों की आय में वृद्धि हुई है उनमें वचन-वृत्ति (Propensity to Save) कम होती है। अर्थात् बड़ी हुई आय का प्रयोग उपभोग पर व्यय बढ़ाने में किया गया है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में विशेषतः कृषकों एवं मजदूरों का जीवन स्तर बहुत नीचा रहा है।

(६) सरकारी प्रतिभूतियों में ठन्डक वचन बहुत सीमा तक विनियोग की जाने लगी है, क्योंकि जनता को औद्योगिक कंपनियों में अविश्वास है। यही नहीं, बल्कि के लिये भी यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे एक निश्चित सीमा तक अपना कोष सरकारी प्रतिभूतियों में लगावें। इन परिस्थितियों में प्राइवेट क्षेत्र के लिये विनियोग-धन का कम हो जाना स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में सरकारी कमेटी ने प्राइवेट उपक्रमियों को उन त्रुटियों का संकेत किया है, जिनके कारण विनियोगक उनकी ओर सरलता से आकर्षित नहीं हो पाते—(i) प्रबन्ध व्यवस्था में बार-बार परिवर्तन, (ii) व्यापार के संचालन में अकुशलता एवं बेईमानी, (iii) सट्टे के व्यवहारों में धन का प्रयोग, (iv) अवसरवादिता एवं कुप्रबन्ध, आदि। इन अनुचित प्रवृत्तियों ने विनियोगताओं को प्राइवेट उपक्रमियों के प्रति अविश्वासी बना दिया है। यहाँ तक

कि वे एक देशी प्राइवेट उपक्रमी के बजाय विदेशी प्राइवेट उपक्रमी द्वारा संचालित व्यवसाय में अधिक विश्वास करते हैं।

पूँजी बाजार (Capital Market)

‘पूँजी बाजार’ से आशय —

पूँजी बाजार का सम्बन्ध दीर्घकालीन अर्थ प्रवर्धन से है। पूँजी बाजार उन्हीं से उस श्रुतला का बोध होता है जिसके द्वारा समाज की वृद्धि प्रौद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक सत्ता को उपलब्ध होनी हैं। इसका सम्बन्ध उन प्राइवेट (व्यक्तिगत एवं सस्थागत) बचनों से है जो कि सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा नवीन पूँजी निगमनो एवं नवीन सार्वजनिक ऋणों के निगमन द्वारा विनियोगों में परिणित की जाती हैं। पूँजी बाजार में मांग कृषि, उद्योग, व्यापार एवं सरकार में उदय होनी है तथा सप्लाई व्यक्तियों व संस्थाओं की बचनों तथा सरकारों के आधिकारों से घाती है। इसमें वृद्धिकर्ता और वृद्धि को गतिशील बनाने वाली संस्थाएँ सम्मिलित होती हैं। वृद्धि करने वाली संस्थाएँ जैसे सेविंग बैंक, विनियोग प्रणालि, विनियोग कम्पनियाँ, विशिष्ट वित्त निगम एवं स्टॉक विपणन पूँजी बाजार के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं।

पूँजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में भेद—

‘पूँजी बाजार’ ‘मुद्रा बाजार’ से भिन्न होता है। संकुचित अर्थ में ‘मुद्रा बाजार’ (Money Market) का सम्बन्ध चल या तरल साधनों में है, जो कि बैंकिंग प्रणाली के द्वारा व्यापार एवं उद्योग में अल्पकाल के लिये विनियोग किये जाते हैं। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से, मुद्रा बाजार भी उन क्रियाओं से सम्बन्ध रखता है जिनके द्वारा दीर्घकालीन पूँजी का निर्माण होता है। वास्तव में पूँजी बाजार एवं मुद्रा बाजार एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि मुद्रा बाजार में व्याज दर बढ़ जाये, तो पूँजी बाजार में मांग बढ़ेगी और यदि पूँजी बाजार में व्याज दर बढ़ जाय, तो इसका मुद्रा बाजार की मांग पर प्रभाव पड़ेगा।

भारत में पूँजी बाजार का वर्गीकरण—

भारत में पूँजी बाजार को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—संगठित एवं असंगठित। दुर्भाग्य से देश में संगठित बाजार का भी उचित विकास नहीं हुआ है, क्योंकि (i) कृषि जो कि भारतीय जनता का मुख्य व्यवसाय है, प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिये उपयुक्त नहीं है, (ii) विदेशी व्यवसाय, जिनकी भारत में प्रमुखता रही है, भारतीय मुद्रा बाजार की अपेक्षा लन्दन मुद्रा बाजार पर निर्भर रहते थे, जिससे उद्योगों के लिये भी प्रतिभूतियों का बाजार पूर्ण रूप में विकसित नहीं हो पाया है, (iii) प्रबन्ध अभिकर्ता गृह उद्योगों का प्रवर्धन करने के माध्यम-माध्यम उनके लिये

अर्थ की व्यवस्था भी कर देते थे, जिससे विशिष्ट वित्त संस्थाओं के विकास की प्रोत्साहन नहीं मिला। (१४) पूँजी बाजार संकुचित है और निर्गमित प्रतिभूतियों की किस्मे थोड़ी हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ ही पूँजी बाजार में कुल निर्गमन के आधे के बराबर हैं, (१५) व्यक्तियों की विनियोग रुचि तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के विनियोगों पर लगाये गये प्रतिबन्ध भी पूँजी बाजार के कम विकास के लिये उत्तरदायी हैं।

पूँजी बाजार के असमंजसित वर्ग में नगरों के देशी बैंकर और गाँवों के साहूकार सम्मिलित हैं। इस वर्ग के विभिन्न अंगों में कोई निकट सम्पर्क नहीं है। यह क्षेत्र समंजसित क्षेत्र से कटा हुआ है। इसमें उपसन्ध कोष भाग की अपेक्षा बहुत कम होती है। ये संस्थाएँ प्रायः उपभोग के लिये अधिव्यय देती हैं, उत्पादक कार्यों के लिये कम। उनकी व्याज दरें भी बहुत ऊँची होती हैं।

यह निम्नान्न आवश्यक है कि पूँजी बाजार में दशावें सुधरे। सभी वह उद्योग की अधिक सेवा कर सकेगा। एक आदर्श पूँजी बाजार में वित्त-व्यवस्था उचित व्याज पर सम्भव होती है।

पूँजी बाजार में उतार-चढ़ाव—

भारतीय पूँजी बाजार में समय-समय पर जो उतार-चढ़ाव होते रहते हैं उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(१) द्वितीय महायुद्ध काल—सन् १९४० में फ्रांस की हार के बाद बम्बई के वायदा व्यापार (Forward Trading) को बड़ा धक्का लगा और उसे बन्द करना पड़ा। कलकत्ता में भी वायदा व्यापार बन्द कर दिया गया। सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिये न्यूनतम मूल्य निर्दिष्ट कर दिये। सन् १९४३ में दशा कुछ सुधरी, जबकि युद्ध के कुछ अनुकूल समाचार प्राप्त हुए तथा सरकार ने सस्ती मुद्रा नीति अपनाई। सरकार ने वस्तु बाजार (Commodity Market) में कपास पर तथा बुलियन बाजार में भी सट्टा बन्द कर दिया। इससे सट्टे का खल स्टॉक एक्सचेंज की ओर हो गया। सरकार ने सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत सितम्बर सन् १९४३ से सभी वायदा व्यवहार एवं बदला व्यवहार बन्द कर दिये, लेकिन प्रशासनिक त्रुटियों के कारण स्टॉक बाजार के बाहर भी शेयरों में व्यवहार होता रहा।

(२) युद्धोत्तर काल—सन् १९४४-४६ समृद्धि का काल था, जो अगस्त सन् १९४६ में पराकाष्ठा पर पहुँच गया। इसके बाद मूल्यों में गिरावट आई, जो सन् १९४९ के मध्य तक जारी रही। इस गिरावट के कई कारण थे—वर्किंग सफ्ट, साम्प्रदायिक उपद्रव, राजनैतिक सघर्ष, हैदराबाद व काश्मीर की पुलिस कार्यवाहियाँ, साम्यवाद के विस्तार का भय, विनियोग-कोषों की कमी तथा सरकार की अनिर्दिष्ट उद्योग नीति। पूँजी बाजार पर जो बुरा प्रभाव पड़ा उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सन् १९४६-१९४८ की अवधि में ७४७ संयुक्त स्वयं कंपनियों की दस पूँजी

१६० करोड़ से १६२ करोड़ ८० हो गई, किन्तु उसका बाजार मूल्य ६२२ ६ करोड़ ८० से घट कर ३३५*५ करोड़ ८० रह गया। इस प्रकार अशधारियों को ३५७ १ करोड़ ८० की हानि हुई।

जुलाई सन् १९४९ से धीरे-धीरे बाजार की दशा में सुधार हुआ तथा पिछले तीन वर्ष में शेयरों के मूल्य में जो कमी आई वह पूरी हो गई। इस सुधार के कई कारण थे—उद्योग को ह्रास सम्बन्धी छूट देने की घोषणा, अधिक उत्पादन होने की रिपोर्टें मिलना, करारोपण व्यवस्था में सुधार, वस्त्र उद्योग के सफ्ट को दूर करने का १२ सूत्री सरकारी कार्यक्रम, अवमूल्यन, कम्पनी ला सुधार, उद्योग के नियंत्रण एवं विदेशी विनिमय को उचित व्यवस्था के बारे में सरकार का आश्वासन।

सन् १९४९ के बाद भी, यद्यपि कई कुप्रभावकारी घटक विद्यमान थे (जैसे कि काश्मीर पर पाकिस्तान से विवाद, पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आगमन, खाद्य सफ्ट, प्रमुख औद्योगिक कच्चे मालों की कमी) तथापि दशा में सुधार जारी रहा, क्योंकि कई सुप्रभावकारी घटक भी विद्यमान थे (जैसे—निर्यात बाजार का विस्तार, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रेलवे यातायात में उन्नति, योजना आयोग की नियुक्ति, सरकार की समृद्धित आर्थिक नीति)। परिणाम यह हुआ कि लाभांश-प्रतिभूतियाँ व।सम्पादक सूचनांक ७ जनवरी सन् १९५० को ११८ ८ से २ दिसम्बर सन् १९५० को १२५*४ हो गया।

सन् १९५१-५२ में कोरिया युद्ध का पूर्वी बाजार पर प्रभाव पड़ा। अन्य प्रभावशील घटक थे—भारतीय व।संपत्ति अधिनियम में मशोधन, रेलवे हड़ताल की आशंका, उद्योग (विवास एवं नियमन) अधिनियम की स्वीकृति, बैंक दर, प्रतिवार्य प्रॉवीडेंट फण्ड योजना, दस्त्र निर्माण पर प्रतिबन्ध। कोरिया युद्ध के प्रारम्भ होने पर मूल्यों में कुछ चढ़ाव हुआ और उसकी समाप्ति पर उक्त अन्य घटकों के कारण गिरावट आई।

सन् १९५२-५३ में भी औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति रही। मुख्य प्रभावशील घटक था चालू लाभ एवं आगामी लाभ अनुमानों में कमी होना। सन् १९५३ ५४ में केन्द्रीय बजट के प्रकाशन पर स्थिति में पुनः सुधार हुआ। यह वृद्धि सन् १९५४-५५ तक जारी रही। सन् १९५५-५६ भी चढ़ाव का वर्ष प्रमाणित हुआ। सन् १९५५-५६ में प्रारम्भिक स्थिरता के बाद बाजार ने चढ़ाव की प्रवृत्ति पुनः अपनाई। इसके प्रमुख कारण निम्न थे—प्रथम पंच-वर्षीय योजना अवधि के अन्तिम वर्ष में घाटे का अधिक अर्थ-प्रबन्धन, कम्पनी-लाभ व लाभांशों में वृद्धि, समाजवादी समाज में प्राइवेट क्षेत्र की उचित सुविधाओं का आश्वासन, कम्पनी लाँ सुधार, सरकार की समृद्धित औद्योगिक नीति का अनुकूल प्रभाव, द्वितीय याजना की अपेक्षा विस्तृत कार्यक्रम, औद्योगिक कच्चे माल व मशीनों के आयात के लिये विशेष सुविधा मिलना आदि।

किन्तु सितम्बर १९५६ के बाद पुनः गिरावट आरम्भ हुई और सन् १९५७ ५८ के बजट प्रस्ताव पेश होने तक जारी रही। इस प्रवृत्ति के कारण ये—वस्त्र पर

उत्पादन कर बढ़ना, पूँजी लाभों पर कर लगना, लाभालाभ पर मुपर टैक्स की वृद्धि, कम्पनियों की अनिवार्य डिपॉजिट स्कीम कच्चे मानों की कीमतों तथा मजदूरी लागतों में वृद्धि ।

सन् १९५८ व प्रारम्भ से विश्वास पुन बढन के आसार दिखाई पडे तथा शेयरों का मूल्य गिरन की प्रवृत्ति रूख गई । इसके निम्न कारण थे—विदेशी सहायता मिलने की संभावना कुछ प्रमुख मस्याप्रा द्वारा बोमम शेयरों के निर्गमन की आशा, सीमेन्ट और कोयन के मूल्यों में वृद्धि, वस्त्र पर उत्पादन करा म कमी, अनिवार्य डिपॉजिट योजना का संगठन । जुलाई सन् १९५८ से एक वृद्धिमूलक प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई और लाभालाभ प्रतिभूतियों का सूचनाक १८-२० वढ गया ।

उपसंहार—

उपरांत विवेचन में यह स्पष्ट है कि भारत में पूँजी बाजार में बड़ी उथल-पुथल होती रहती है । यदि पूँजी बाजार संगठित हो, तो वह प्रतिभूतियों के सफल निर्गमन में बहुत सहायक हो सकता है । अन्य देशों में संगठित पूँजी बाजार का आदाय न केवल मस्यागत विनियामकों की उपस्थिति में वरन् उन प्रोत्साहन देने वाली सरकारी नीति से भी है । केवल एक जीवन बीमा निगम जैसी एक इकाई की स्थापना से कार्य न चलगा वरन् अनक सस्थागत विनियोजक होने चाहिये । इनके निर्माण को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है । किन्तु इसके साथ ही व्यक्तिगत विनियोगकों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । उन्हें भी अधिक बचत एवं अधिक निनियोग करने के अवसर दिये जाने चाहिये, क्योंकि अब भी वे पूँजी बाजार का मुख्य आधार बने हुये हैं । १,००१ कम्पनियों के अर्थ प्रवर्धन के माधना की चर्चा करने हुए अक्टूबर सन् १९५८ की रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने बताया था कि नवीन शेयर निर्गमनों से सन् १९५६ में भी केवल २२ करोड ६० (कुल कोषों के १०% के बराबर) प्राप्त हुआ, जबकि सन् १९५५ में यह प्रतिशत ८०% था ।" फडरेसन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एंव इण्डस्ट्री ने यह परामर्श दिया है कि पूँजी बाजार एवं स्टॉक विपणियों के अधिक सक्रिय कार्य-वाहन के हेतु एक समुचित विनियोग वातावरण पैदा करने के लिए सरकार को सम्पत्ति कर, व्यय कर, लाभालाभ कर आदि की समाप्त करके २० करोड ६० की आय खोन में सर्वाध नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभ इस हानि की अपेक्षा कहीं अधिक होगा ।

STANDARD QUESTIONS

1. What do you understand by the term 'Capital Formation' ? 'The key to higher productivity and expanding levels of income and employment lies really in stepping up the rate of Capital formation'. Discuss.
2. Briefly describe the process of capital formation in the public and private sectors of an economy with special reference to India.

भारत में औद्योगिक प्रतिभूतियों का स्वरूप

(Security Pattern in Indian Industries)

प्रारम्भिक—

भारत में औद्योगिक प्रतिभूतियों के स्वरूप से सम्बन्धित निम्न विवेचन श्री मुल्की, करारोपण जाँच आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अनुमन्त्रान एव सांख्यिकी विभाग द्वारा एकत्र किये गये घाँवड़ों पर आधारित है। ये आंकड़े क्रमशः सन् १९४५ के पूर्व की अवधि, सन् १९५१ का वर्ष एव सन् १९५०-५६ की अवधि से सम्बन्धित हैं।

साधारण शेयर—

(१) भारत में पूँजी एकत्र करने के लिए साधारण शेयर सबसे अधिक लोक-प्रिय साधन हैं—दत्त पूँजी में इनका अनुपात उद्योग-उद्योग में भिन्न-भिन्न है, किन्तु लौह एव स्पात उद्योग में सबसे कम और दियासलाई उद्योग में सबसे अधिक है। यह बात तालिका I में दिखाई गई है। श्री मुल्की के अध्ययन में भी डमी प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। दत्त पूँजी का ८०% भाग साधारण शेयरों में रखने वाली कम्पनियाँ सूची वस्त्र एव अन्य वस्त्र मिल, इन्जीनियरिंग शक्कर, रसायन, वनस्पति तेल, बागान, कोयला, व बिजली कम्पनियाँ हैं, जबकि सीमेन्ट, चाय, गिपिंग एव दियासलाई कम्पनियाँ में ६०% से भी अधिक दत्त पूँजी साधारण शेयरों के रूप में है। जूट, कागज, लौह एव स्पात तथा अन्य निर्माणी उद्योगों की ७५% से कम दत्त पूँजी साधारण शेयरों के रूप में है। लौह एव स्पात उद्योग में तो यह प्रतिशत केवल ४५% था।

(२) भारत में १० रु० और १०० रु० वाले साधारण शेयर बहुत लोकप्रिय हैं—श्री मुल्की ने जिन ५६७ कम्पनियों का अध्ययन किया था उनके ६१० साधारण शेयर निगमनों में से १६५ निगमन १०० रु० के शेयरों के तथा २८५ निगमन १० रु० के शेयरों के थे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित कम्पनियों में १० रु० वाले शेयर अधिक लोकप्रिय हैं, जबकि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्ध रखने वाली कम्पनियों में १०० रु० के शेयर अधिक पसन्द किये गये हैं।

(३) साधारण लाभांशों की औसत दरें लौह एव स्पात, दियासलाई, बागान, कागज, शक्कर एव चाय कम्पनियों में सन् १९५१-५५ के मध्य काफी ऊँची १०% में ऊपर थी। किन्तु जूट, सूत रीपेट, वस्त्र एव कोयला कम्पनियों में लाभांश दर कुछ कम ऊँची (अर्थात् ७ और १०% के मध्य) रही है। वनस्पति तेल, रसायन आदि उद्योगों में औसत लाभांश दर ३% से कम थी। (दख्ये तालिका २)

(४) भविष्य की कमी की दर अधिक नहीं है—विशेषतः तब जबकि हम इस बात को विचार में लें कि यहाँ पूँजी बाजार का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। आधुनिक कम्पनी निगमनों के अध्ययन से मालूम होता है कि उचित दर १ और ५% के बीच परिवर्तित होती रही है, जबकि इंग्लैंड में यह दर २ से ६% तक रहती है।

डिविडेंड व प्रिफरेंस शेयरों की तुलना में माघारण शेयरों पर कमीशन की दर अधिक है क्योंकि इन पर अभिमापका को अधिक बोझिम उठानी पड़ती है।

TABLE 2

Showing the dividends as average percentage of paid up capital in various industries during 1951-55

	Industry	Ordinary	Preference	Deferred
1	Cotton Textiles	8.7	4.0	6.4
2	Jute	10.0	6.3	2.7
3	Other Textiles	3.0	4.7	
4	Iron and Steel	13.4	6.7	373.3
5	Engineering	3.8	3.7	10.2
6	Cement	9.2	6.2	4.5
7	Sugar	11.3	5.4	30.7
8	Paper	10.8	5.2	
9	Vegetable Oil	2.7	2.8	1.0
10	Chemicals	2.6	6.7	1.7
11	Minerals	10.8		
12	Coal	7.1	5.4	4.6
13	Electricity Generation and Supply	6.9	6.8	
14	Shipping	3.5	6.3	
15	Tea	17.4	5.9	
16	Other Plantations	16.0	6.6	
17	Trading	6.7	3.0	12.8
18	Land and Estate	1.8	4.1	3.3
	Total (including others)	8.1	5.2	19.7

Source: Reserve Bank of India Bulletin September 1957

प्रिफरेंस शेयर—

(१) दत्त पूँजी में प्रिफरेंस शेयरों का प्रतिशत औसतन दत्त है। दियासलाई उद्योग में यह लगभग शून्य है जबकि लौह एवं स्पात में सबसे अधिक अर्थात् ५५ है। २०% से अधिक प्रिफरेंस शेयर रखने वाले उद्योग पूँट कागज एवं निर्माणियाँ हैं। काटन इंजीनियरिंग कमीकल्स वनस्पति तेल १५ से २०% के वर्ग में आते हैं। निपिन चाय सीमेंट और दियासलाई उद्योग में १०% कम दत्त पूँजी प्रिफरेंस शेयरों के रूप में था। (अभिय तालिका १)।

(२) कर मुक्त सचयी एवं पूँजी की वापसी का अधिकार वाले प्रिफरेंस शेयर विशेष पसंद किये जाते हैं। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित २१५ कम्पनियाँ द्वारा जो २४० नियमन किये गये थे उनमें से २३४ को सचयी नामांश पाने का २०१ को करमुक्त लाभान् पाने का २२८ को कम्पनी के समापन का दशा में पूँजी की वापसी का १७ को अनिश्चित लाभ में भाग लाने का तथा ६ का समापन पर कम्पनी की आधिक्य सम्पत्तियों में भाग लाने का विशेष अधिकार था।

Showing the analysis of paid up capital, mortgages and debentures of 407 selected companies

Paid up Capital

Industry	No of Cos	Ordinary		Preference		Deferred		Total Amount	A	%
		A	%	A	%	A	%			
1 Cotton	90	380	82	73	16	53	1	458	11	24
2 Jute	42	160	74	56	26	(a)		216	17	79
3 Other Textiles	9	18	86	3	14	(a)		21		
4 Iron and Steel	3	85	447	104	548	1	5	190	16	84
5 Engineering	41	193	82	43	18	(a)		216	32	136
6 Sugar	25	63	85	10	135	1	14	74	10	135
7 Chemicals	23	78	81	18	19	(a)		96	6	63
8 Paper	7	31	69	14	31			45	11	244
9 Vegetable oil	4	13	81	3	19			16		
10 Matches	4	25	100	(a)		(a)		25	10	69
11 Cement	5	137	96	6	4			143	1	22
12 Tea	45	43	93	3	7			46	(a)	
13 Other plantations	10	8	89	1	11			9		
14 Coal	16	48	86	8	14			56	10	179
15 Electricity	21	176	86	29	14			205	66	322
16 Shipping	8	119	97	4	3			123	73	593
17 Other Manufacturing	54	199	73	72	27	1		272	2	118
Total	407	1776	795	447	20	11	1	2234	297	133

* Source Report of the Taxation Enquiry Commission

(a) Negligible amount

A Amount in crores of rupees

% Percentage to total paid up capital

भारत में औद्योगिक प्रतिभूतियों के स्वरूप से सम्बन्धित मुख्य बातें

(I) साधारण शेयर—

- (१) ये भारत में पूँजी एकत्र करने का सबसे लोकप्रिय साधन हैं।
- (२) १० रु० और १०० रु० मूल्य के साधारण शेयर अधिक प्रचलित हैं।
- (३) लाभांश की दर लौह एवं स्पात उद्योग में सबसे ऊँची, जूट व सूती वस्त्र उद्योग में मध्यम तथा रसायन आदि उद्योगों में सबसे कम है।
- (४) अभिपोषक कमीशन की दरें अधिक नहीं हैं।

(II) प्रिफरेंस शेयर—

- (१) दत्त पूँजी में इनका प्रतिशत औसतन १० है।
- (२) कर मुक्त, सचयी एवं पूँजी की वापसी का अधिकार प्राप्त प्रि० शेयर बहुत लोकप्रिय है।
- (३) शोध प्रि० शेयर विशेष प्रचलित नहीं हैं।
- (४) १०० रु० मूल्य के शेयर बहुत लोकप्रिय हैं।

(III) डेफर्ड शेयर—

- (१) अत्यन्त कम मूल्य रखते हैं।
- (२) विशेष वर्गों द्वारा ही खरीदे जाते हैं।
- (३) सबसे अन्त में लाभ पाते हैं।
- (४) नियन्त्रण हथियाने का साधन हैं।

(IV) डिबेन्चर—

- (१) दत्त पूँजी में इनका अनुपात औसतन १३.३ है।
- (२) इनका मूल्य प्रायः अधिक होता है।
- (३) ब्याज की औसत दर ५.५% रही है।

(३) शोध प्रिफरेंस शेयर भारतीय कम्पनियों में विशेष पसन्द नहीं किये जाते, यद्यपि उनके निर्गमन के लिये कम्पनी कानून में उपयुक्त व्यवस्था कर दी गई थी। २४० प्रिफरेंस शेयर-निर्गमनों में से केवल ३६ निर्गमन ही शोध प्रिफरेंस शेयरों वाले थे। अब कुछ पुरानी कम्पनियों ने शोध प्रिफरेंस शेयरों का निर्गमन करने में रुचि लेना आरम्भ किया है।

(४) १०० रु० मूल्य के प्रिफरेंस शेयर अधिक प्रचलित हैं—२४० निर्गमनों में से १७५ निर्गमन १०० रु० वाले शेयरों के थे। वैसे ये शेयर ३ रु० से लेकर १,००० तक के मूल्यों में होते हैं।

(५) लाभांश की दर के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा प्रकाशित किये गये आँकड़ों से यह पता चलता है कि सन् १९५१-५२ के मध्य ६% से अधिक लाभांश घोषित करने वाली कम्पनियाँ लौह एवं स्पात, बिजली उत्पादन एवं पूर्ति, जूट टेक्स्टाइल्स, सीमेंट, कैमीकल्स, सिपिंग व वागानों से सम्बन्धित थीं। ५ और ६% के मध्य लाभांश घोषित करने वाले उद्योग कागज, शक्कर, फोस्फाट एवं चाय हैं। ४ और ५ प्रतिशत के मध्य घोषणा करने वाले उद्योगों में सूती वस्त्र व अन्य टेक्स्टाइल्स सम्मिलित हैं। किसी भी उद्योग ने २८% से कम लाभांश नहीं बाँटा।

डेफर्ड शेयर —

इन शेयरों की कम्पनी के लाभों में साधारण शेयरों पर एक निर्दिष्ट दर से लाभांश देने के पश्चात् भाग मिलता है। जब ये कम्पनी के मूल प्रवर्तकों को या बंडरों (Vendors) को दिये जाते हैं तो इन्हें 'स्थापना अंश' (Founders' Shares) भी कहते हैं। कम्पनी की अर्थ-प्रबन्धन योजना में इन्हें सम्मिलित कर लेने से प्रबन्धकों को कम विनियोग करके ही कम्पनी पर नियंत्रण रखने का अवसर मिलता है, क्योंकि इनका मूल्य प्रायः बहुत कम होता है। प्रबन्ध को हथियाने का अवसर देने के अतिरिक्त ये शेयर सट्टे को भी बढ़ावा देते हैं। जब कभी कोई कम्पनी अधिक लाभ कमाती है, तो इन शेयरों पर बहुत लाभ बँटता है। इससे इनका बाजार मूल्य बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के लिये, टाटा कम्पनी के डेफर्ड शेयरों का अंकित मूल्य केवल ३० रु० प्रति शेयर, जो सन् १९४६ में ३,६४० रु० तक पहुँच गया, सन् १९४९ में घटकर १,१४२ रु० रह गया और सन् १९५४ में फिर २,०६७ रु० हो गया। सन् १९५४ में इन शेयरों को साधारण शेयरों में परिणत कर लिया गया।

डेफर्ड शेयरों का दुरुपयोग कुछ विख्यात प्रबन्ध अभिकर्त्ता पहले तक ने किया है। वास्तव में कन्ट्रोल को कुछ व्यक्तियों तक सीमित रखने की यह एक कानूनी चाल है। यही कारण था कि बम्बई शेयर होल्डर एसोसिएशन ने भारत सरकार से इस सम्बन्ध में उपयुक्त कानून बना कर इन शेयरों के निगमन की प्रथा को समाप्त करने का अनुरोध किया। डेफर्ड शेयरों के सम्बन्ध में दिया गया यह तर्क कि इन शेयरों से कुछ जोखिमपूर्ण उद्योगों में विनियोग आकर्षित होते हैं, अनुभव से सिद्ध नहीं होता। भाभा कमेटी ने बताया है कि इस प्रकार के शेयरों का निर्गमन वस्तुतः पूँजी के निर्माण में बाधक होता है।^१ हर्ष का विषय है कि डेफर्ड शेयर कम्पनी अधिनियम १९५६ द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं।

डिवेन्चर —

(१) सभी उद्योगों में इतनी पूँजी से डिवेन्चरों का प्रतिशत औसतन १३ ३ था। तालिका १ को देखने से यह मालूम होगा कि विपिग में डिवेन्चरों का प्रतिशत सबसे ऊँचा

1. "The history underlying most recent issues of deferred shares, however, belies this theory and even if in some exceptional cases, additional inducements to investors are considered necessary, it is difficult to justify such differential treatments to certain classes of investors as a matter of general policy. On the contrary, the issue of deferred shares with disproportionate voting rights has often resulted in the control of an undertaking by a minority of shareholders and by the undesirable repercussions which they produce on investment markets more often than not impede capital formation" (Report of the Company Law Committee, p. 35-36)

अर्थात् ५६.३% था, जबकि बिजली में ३२.२% था। निर्माणी उद्योगों में कागज उद्योग की दत्त पूँजी में डिबेन्चरों का प्रतिशत २४.४ था। कॉटन, जूट, लौह एवं स्पात रसायन, सीमेंट व चाय में १०% से कम था। वनस्पति तेल, दियासलाई आदि में डिबेन्चरों का प्रतिशत बहुत मामूली तथा इंजीनियरिंग व शक्कर उद्योगों में १० से १५ के बीच था।

(२) डिबेन्चरों का मूल्य बहुत अधिक रखा जाता है, जिससे इनका बाजार सस्यागत विनियोगको एक घनाडय विनियोक्तधो तक सीमित रहता है। औद्योगिक कम्पनियों के ६६ डिबेन्चर निर्गमनों में से ४७ में डिबेन्चरों का मूल्य ५०० रु० तथा ३२ में उनका मूल्य १,००० था।

(३) डिबेन्चरों पर औसत ब्याज दर ५.५% थी, जो प्रीफरेन्स शेयरों की मिलने वाली दर से कुछ अधिक नहीं है। १०५ निर्गमनों में से ५६ निर्गमनों पर, श्री मुल्की के विश्लेषणानुसार ५% या इससे कम ब्याज दर थी। डिबेन्चरों के वर्तमान निर्गमन भी उचित दर पर हुये हैं।

भारत में डिबेन्चरों की कम लोकप्रियता—

इन्डियन बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी ने अनुमान लगाया है कि भारतीय उद्योगों में पूँजी की १०० इकाइयों में ७५ साधारण शेयर, १९ प्रीफरेन्स शेयर तथा डिबेन्चर केवल ६ होते हैं, जबकि ब्रिटिश उद्योगों में ये अनुपात क्रमशः ४७, ३३ व २० थे। श्री मुल्की के अध्ययन से भी यह मान्य होता है कि नई पूँजी प्राप्त करने के हेतु ५६७ कम्पनियों में से ६६ कम्पनियों ने डिबेन्चर निकाले और डिबेन्चरों का कुल पूँजी से प्रतिशत केवल ७.५% था। कर आँच आयोग ने भी ४०७ चुनी हुई कम्पनियों के ग्रंथ प्रबन्धन का विश्लेषण करके बताया है कि डिबेन्चरों का दत्त-पूँजी से प्रतिशत १३.३ था, जबकि प्रीफरेन्स शेयर व साधारण शेयरों का दत्त पूँजी से अनुपात क्रमशः २० एवं ७६.५ था। कन्ट्रोलर आफ कंपीटल इश्यू द्वारा प्रकाशित आकड़ों के आधार पर बनाई गई निम्न तालिका से भी यह बात प्रगट होती है :—

वर्ष	कुल स्वीकृत रकम		डिबेन्चर		कुल स्वीकृत रकम के साथ डिबेन्चरों का प्रतिशत
	कम्पनियों की संख्या	करोड़ रु०	कम्पनियों की संख्या	करोड़ रु०	
१९५०	२६३	७५	२५	११	१५
१९५१	३४३	६०	१६	४	७
१९५२	२५४	४०	६	२	५
१९५३	२३२	८१	२०	१४	१७
१९५४	२२०	१११	२४	२०	१८
१९५५	२८६	१२५	२३	१७	१४
१९५६	२६७	२३०	१२	११	५
१९५७	३४५	१५३	२२	६	६

डिबेन्चरों की कम लोकप्रियता के कारण—

डिबेन्चरों की कम लोकप्रियता के कारणों पर निम्न शीर्षको के अन्तर्गत विचार किया जा सकता सकता है :—

(१) इश्यू करने वाली सस्था का दृष्टिकोण (*Attitude of the Issuing enterprise*)—(i) डिबेन्चरों पर स्टाम्प कर लगाना पड़ता है, जिससे अर्थ-प्रबन्धन का व्यय बढ़ जाता है, (ii) कम्पनियों को बैंक की निगाहों में अपनी साख कम होने का भय रहता है, (iii) प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा ही उनकी मध्यमकालीन आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं तथा प्रबन्ध-अभिकर्ता उन्हें डिबेन्चरों का निर्गमन करने के लिये निरुत्साहित करते हैं।

(२) विनियोजकों की मनोवृत्ति—जैसा कि सर मॅकडोनाल्ड ने भारतीय बैंकिंग जाँच समिति के समक्ष बताया था, भारतीय विनियोजक ऐसी प्रतिभूतियों को पसन्द करते हैं जिनके बाजार मूल्यों में ऊँचे परिवर्तन होते रहे, जिससे उनको पूँजी लाभ की आशा रहे। कम जोखिम किन्तु निश्चित आय वाले डिबेन्चर उन्हें पसन्द नहीं आते। लेकिन यह बात आधुनिक अनुभव से मिट नहीं होनी। आजकल सरकारी प्रतिभूतियों में जनता निसर्कोच कापी धन लगा रही है। (ii) कम जोखिम व निश्चित आय वाले डिबेन्चर सस्थागत विनियोजकों को विशेष पसन्द आते हैं, लेकिन ऐसी सस्थाओं का भारत में नितान्त अभाव है। (iii) डिबेन्चरों का अधिक मूल्य होना भी उनकी लोकप्रियता का एक कारण है। (iv) अमेरिका की भाँति भारत में डिबेन्चरों पर आकर्षक छूटें नहीं दी जाती हैं। अमेरिका में बान्डों को शेयरों में परिणत कराया जा सकता है। इस तरह बान्डहोल्डर प्रारम्भिक अवस्थाओं में जोखिम में बच जाते हैं, किन्तु जब कम्पनी सफल हो जाती है तो वे अपने बांडों को शेयरों में परिणत करके अधिक लाभ के भागी भी बन जाते हैं।

(३) सामान्य कारण—(i) ट्रस्टी व्यवस्था जो डिबेन्चरों को अधिक लोकप्रिय बना सकती है, भारत में नहीं पाई जाती है। (ii) औद्योगिक प्रतिभूतियों के लिये पूँजी बाजार इतना सर्गठित नहीं है कि डिबेन्चरों के लिये नियमित माग और पूर्ति हो। (iii) भारत में कम्पनियों की अभिगोपन गृहों की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। ये गृह बाजार मन्दा होने पर भी कृत्रिम माग पैदा करके डिबेन्चर निर्गमन को सहारा दे सकते थे। (iv) पूँजी बाजार में प्रतिद्वन्दी प्रतिभूतियों का बाहुल्य है, जैसे (*Gift edged Securities*) एव डिफरेंस शेयर आदि। इनमें सुरक्षा तत्त्व होने से उन्हें अधिक पसन्द किया जाता है।

डिबेन्चरों को लोकप्रिय बनाने के उपाय—

विनियोजकों में डिबेन्चरों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिये निम्न उपाय किये जा सकते हैं—

- (१) इन पर अधिक आनर्सेक शर्तें दी जाय ।
- (२) मुख्य कम रखा जाय ।
- (३) स्टाम्प ड्यूटी कम की जाय ।
- (४) बका को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये ।
- (५) एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत जो कम्पनियाँ हैं उन्हें मिल कर डिबेन्चरा का निगमन करना चाहिये ताकि वे विनियोजकों को श्रेष्ठ प्रतिभूति दे सकें व निगमन लागत एक बड़ पैमाने पर बच जाय ।
- (६) सम्पागत विनियोजकों जैसे बैंकों बीमा कम्पनियों को काबूनी ढील दकर डिबेन्चरो में अधिक विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।
- (७) डिबेन्चरधारियों को नुस्त सेबाय उपानय की जायें ।
- (८) प्रतिगोपन सुविधाय बड़ाई जायें ।

उपसंहार—

मार्च १९५६ में रिणव बक ने कैपिटल इश्यू के स्वरूप का जो विश्लेषण दिया है उससे यह मालूम पड़ता है कि साधारण शेयरों का महत्त्व बढ़ रहा है तथा अन्य प्रतिभूतियाँ विशेषतः डिबेन्चरा का महत्त्व घट रहा है । १००१ कम्पनियों के शेयर व डिबेन्चर सम्बन्धी नये निगमन की कुल रकम २४ करोड़ ६० थी जिसमें साधारण शेयर ३६% थे प्रिफरेंस शेयर १८% तथा डिबेन्चर केवल ६% ही थे ।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Discuss the important features of security pattern as obtained in Indian industries
- 2 Account for the unpopularity of debentures in Indian industries Suggest measures to make them more popular

आन्तरिक वित्त व्यवस्था

(Internal Financing)

आन्तरिक वित्त व्यवस्था से आशय—

अधिकांशतः देखा जाता है कि किसी भी औद्योगिक संस्था को जितना लाभ होता है, उस संस्था के प्रबन्धक समस्त लाभ को अशुधारियों के बीच वितरित नहीं कर देते। वे कुल लाभ में से कुछ भाग बचा कर रख लेते हैं। किसी औद्योगिक कम्पनी के जीवन में इस प्रकार से जो बचत की जाती है, वह कभी-कभी भविष्य में बहुत काम देती है। संस्था को जब अनिर्वित्त पूँजी की आवश्यकता होती है, तो यह 'बचत' काम में लाई जा सकती है। किसी भी औद्योगिक संस्था के अनिर्वित्त अथवा उक्त रीति से बचाये गये लाभों को यदि स्थायी या कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयोग किया जाय, तो ऐसे प्रयोग को वाणिज्य की भाषा में 'आन्तरिक साधनों के द्वारा वित्त प्रबन्धन' (Internal Financing) अथवा 'आन्तरिक साधनों के वित्त प्रबन्धन' (Financing from Internal resources) कहेंगे। कभी-कभी इस प्रणाली को 'आय का पृष्ठ विनियोग' (Ploughing Back of Profits) भी कहते हैं।

'आय के पृष्ठ विनियोग' के अनुसार कम्पनी अपनी सम्पूर्ण आय का वितरण लाभांश देने में न करती हुई उसका एक अथ विभिन्न निधियों (Funds) में रखती जाती है, जैसे—संचित प्रणोद, नवकरण प्रणोद, पुन. संस्थापन प्रणोद आदि। इसी प्रकार अशुधारियों की जानकारी के बिना वह गुप्त-कोष (Secret Reserve) भी बना सकती है, जिसके अनुसार यन्त्र आदि की मरम्मत पर अधिक प्रबलत्व दिया जाता है। इन विभिन्न विधियों की राशि से वे अपनी विकास योजनाओं की आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी करती हैं। यह प्रमण्डल की आर्थिक दृढ़ता के लिए अधिक लाभकर है, क्योंकि ऋण से कर विकास योजनाओं की पूर्ति करने से प्रमाण पर व्याज का बोझ बढ़ता है और यदि ऋणों का मुग्तान अकल्पित समय माँगा जाय तो कम्पनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, अतः अच्छी एवं पूर्व स्थापित कम्पनियों के लिए यह पद्धति अत्यन्त उपयोगी है।

आन्तरिक वित्त प्रबन्धन के प्रभाव (Effects of Internal Financing)—

आन्तरिक वित्त प्रबन्धन के प्रभावों का अध्ययन निम्नलिखित तीन दृष्टिकोणों से किया जाता है :—

- (I) औद्योगिक संस्था पर प्रभाव,
(II) अशधारियों पर प्रभाव;
(III) समाज पर प्रभाव ।

‘आय के पृष्ठ विनियोग’ के लाभ

(I) औद्योगिक संस्था पर प्रभाव—

१. व्यावसायिक उपलब्ध-पुण्य के विस्तार शस्त्र ।
२. स्थाई लाभदायक नीति एवं संस्था की उच्चतर साध ।
३. संस्था के विस्तार में सुविधा ।
४. मृत्यु हानि आदि की कमी की पूर्ति ।
५. ऋण पत्रों, बांड्स आदि के विमोचन की सुविधा ।

(II) अशधारियों पर प्रभाव—

१. विनियोग की सुरक्षा ।
२. प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में वृद्धि ।
३. सुपर टैक्स से बचत में सुविधा ।

(III) समाज पर प्रभाव—

१. पूँजी के निर्माण में वृद्धि ।
२. वित्तीय स्थायित्व एवं लचक ।
३. औद्योगीकरण का विकास ।
४. विवेकीकरण व आधुनिकीकरण की योजनाओं का अर्थ-प्रबन्धन ।

(I) औद्योगिक संस्था पर प्रभाव—

(१) व्यावसायिक उपलब्ध-पुण्य के विस्तार शस्त्र—यदि कोई औद्योगिक संस्था अपनी आय की कुल राशि का अशधारियों के मध्य वितरण न करके, कुछ बचाकर रख ले, तो कम्पनी की बचत (Corporate Savings) का यह भाग भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है । किसी भी औद्योगिक संस्था के जीवन में आर्थिक उपलब्ध-पुण्य अर्थात् तेजी व मन्दी, प्राप्ति ही रहती है । इसके अतिरिक्त संस्था के लिए ३६५ दिन सदा समान नहीं होते । वर्ष के कुछ दिन समृद्धि के दिन कहे जा सकते हैं तथा कुछ काल ऐसा भी हो सकता है जबकि संस्था को नेकमात्र भी लाभ न हो । इन मौसमी परिवर्तनों एवं व्यापार चक्रों के विरुद्ध एक सफल शस्त्र है—‘आय का पृष्ठ विनियोग’ । आय का पृष्ठ विनियोग संस्था को दुर्दिनों में धैर्य बँधाता है एवं सफलतापूर्वक स्थिति का सामना करने के लिए साहस प्रदान करता है ।

(२) स्थायी लाभदायक नीति एवं संस्था की उच्चतर साध—लाभों को

बचाकर रखने का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे संस्था की लाभदायक नीति में स्थायित्व आता है । यदि दुर्भाग्य से किसी वर्ष पर्याप्त लाभ न हुआ हो अथवा बिलकुल ही लाभ न हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में संस्था के प्रबन्धकों व संचालकों को अधिक चिन्तित नहीं होना पड़ता, क्योंकि ‘बचत’ की राशि से सामाज्य दिये जा सकते हैं । इस प्रकार अशधारियों के मध्य भी सदैव शान्ति का वातावरण रहता है एवं वे पूर्णतः सन्तुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनको प्रति वर्ष नियमित रूप से लाभान्वित मिलता रहता है ।

यदि सस्था अपनी आय का कुछ भाग बचाकर न रखे एवं लाभ न होने वाले वर्ष में लाभान्ध को घोषणा न करे, तो अशधारियों के मध्य असन्तोष की भावना पैदा हो सकती है। उनके असन्तोष से सस्था की साख गिरने का भी डर रहता है। परन्तु आय का पृष्ठ विनियोग कम्पनी की साख पर ग्राँच नहीं आने देता।

(३) संस्था के विस्तार में सुविधा—जब कभी किसी विद्यमान संस्था का विस्तार होना है और विस्तार हेतु अनिश्चित पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी है, तो कम्पनी द्वारा बचाई गई राशि (Corporate Savings) का प्रयोग इस काम के लिए किया जा सकता है। ऐसा करने से एक दूसरा लाभ यह होता है कि कम्पनी को अपनी सम्पत्तियों पर प्रभार पैदा करने का नहीं लेना पड़ता। आन्तरिक साधनों के द्वारा ही समस्यायें हल होती हैं। विकास योजनाओं के अर्थ प्रबन्धन की यह प्रत्यक्ष श्रेष्ठ रीति है।

(४) मूल्य ह्रास आदि की कमी की पूर्ति—कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि घटौती कोष अथवा इस प्रकार के अन्य संचित कोषों में घन की कमी (Deficiency) पड़ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आय का पृष्ठ विनियोग शीघ्रक साधन की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार कम्पनी की संचालन क्षमता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने पाती।

(५) ऋण पत्रों, बाइंड आदि के विमोचन की सुविधा—कम्पनी की अविनिश्चित आय (Undistributed Income) का प्रयोग ऋण-पत्रों आदि के विमोचन के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार सिंकिंग फंड (Sinking Fund) की व्यवस्था बड़ी सरलता से हो जाती है एवं सस्था को ऋण-पत्रों के विमोचन के सम्बन्ध में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, उद्योग पर ऋण-पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज आदि का जो भार होना है, वह बहुत कुछ हल्का हो जाता है।

(II) अशधारियों पर प्रभाव —

आय के पृष्ठ विनियोग की योजना अशधारियों की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होती है। आन्तरिक वित्त प्रबन्धन का अशधारी वय पर निम्नलिखित गुणकारी प्रभाव पड़ता है—

(१) विनियोग की सुरक्षा—अशधारियों की दृष्टि से आय के पृष्ठ विनियोग की योजना से उन्हें विनियोग अत्यन्त सुरक्षित रहते हैं, जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, आय का पृष्ठ विनियोग मौसमी परिवर्तनों एवं व्यापारिक चक्रों के विषय में एक शक्ति है, अतः अशधारियों के लिए यह बहुत लाभप्रद सिद्ध होना है। आय के पृष्ठ विनियोग से सस्था की साख भी स्थिर रहती है एवं उसकी लाभान्ध नीति में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने। यह बात भी अशधारियों की दृष्टि से हितकारी ही होती है।

(२) प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में वृद्धि—संस्था की सुदृढ़ साख एवं स्थायी लाभदायक नीति का उभरती प्रतिभूतियों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ जाता है। इस मूल्य वृद्धि से अशायरी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि ऐसी प्रतिभूतियों को वे ऊँचे मूल्य पर बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। यदि अशायरी ऐसी औद्योगिक प्रतिभूतियों पर स्वामित्व बनाए रखते हैं तो कम्पनी की बड़ी हुई आय कमाने की क्षमता में वे लाभान्वित होते हैं।

(३) सुपर टैंक्स से बचत में सुविधा—जिन कम्पनियों में अशायरियों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, उनमें आय के पृष्ठ विनियोग की पद्धति के द्वारा वे सुपर टैंक्स से बच सकते हैं। यह लाभ अब विशेष लाभ नहीं रहता, क्योंकि एक तो नैतिक दृष्टि से टैंक्स न देना वांछनीय नहीं है और दूसरे आय कर अधिनियम की धारा २३-A के प्रादेशों के अन्तर्गत टैंक्स से बचना कठिन हो गया है।

(III) समाज पर प्रभाव

आय के पृष्ठ विनियोग की योजना केवल कम्पनियों या अशायरियों की दृष्टि से ही लाभप्रद नहीं होती, बल्कि समाज पर भी इसका पुणकारी प्रभाव पड़ते हैं। नीचे हम ऐसे कुछ प्रभावों की विवेचना कर रहे हैं—

(१) पूँजी के निर्माण में वृद्धि—कम्पनी की बचत पूँजी के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। पूँजी का निर्माण आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक होता है। यदि किसी दश में पूँजी का निर्माण मन्द गति से होता है तो वहाँ औद्योगीकरण की समस्त योजनाएँ भी बहुत धीमी गति से तथा बहुत सम्झी अवधि में पूरी हो सकेंगी। इसके विपरीत जिस दश में पूँजी का निर्माण तेज गति से होता है, वहाँ औद्योगीकरण भी सरलता व क्षीघ्रता के साथ हाता है। औद्योगीकरण से समाज भी लाभान्वित होता है, क्योंकि इससे समाज के सदस्यों को अधिक मात्रा में उच्च क्वालिटी की वस्तुएँ उपलब्ध होने लगती हैं।

(२) वित्तीय स्थायित्व एवं बचत—प्रत्येक समाज अपनी विद्यमान संस्थाओं के कुशल व निरन्तर संचालन एवं नई-नई समस्याओं की स्थापना में रुचि रखता है। कम्पनी की बचत इसको सम्भव बनाती है। आन्तरिक अर्थ-प्रवन्धन की व्यवस्था से संस्था को किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई नहीं होने पानी एवं सभी भावी योजनाएँ आसानी के साथ पूरी हो जाती हैं। यदि कम्पनियाँ बचत न करें, तो उनकी स्थिति कभी भी ठाँवाटोल हो सकती है।

(३) औद्योगीकरण का विकास—आय के पृष्ठ विनियोग से औद्योगीकरण भी प्रोत्साहित होता है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है और यह धन कम्पनियों की बचत से प्राप्त किया जा सकता है।

(४) विवेकीकरण व आधुनिकीकरण की योजनाओं का अर्थ-प्रवन्धन—विवेकीकरण व आधुनिकीकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा

मे वन की आवश्यकता होती है। आय का पृष्ठ विनियोग द्वारा यह समस्या काफी सीमा तक हल हो जाती है। बचत की राशि का बन्धीकरण, स्वचालन, आधुनिकीकरण आदि की योजनाओं में विनियोग करके सस्या की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे समाज को लाभ पहुँचता है।

भ्रान्तरिक वित्त प्रबन्धन का महत्त्व—

पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय योजना आयोग (Planning Commission) ने भी 'भ्रान्तरिक प्रचं प्रबन्धन' के महत्त्व को स्वीकार किया है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के विकासार्थ कुल ६१३ करोड़ रु० की राशि में से २०० करोड़ रु० अथवा ३२.६% भ्रान्तरिक साधनों के द्वारा प्राप्त किए गए। सन् १९५०-५१ में औद्योगिक लाभों की मात्रा ६८ करोड़ रु० थी, जिसमें से ३४ करोड़ रु० अथवा ३४.७% आय का पृष्ठ विनियोग किया गया। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत भी निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कुल विनियोग (६२० करोड़ रु० में से ३०० करोड़ रु० अथवा ४८% भ्रान्तरिक साधनों द्वारा प्राप्त किया गया। इसी प्रकार तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत भी, उद्योगों के विकास के लिए भ्रान्तरिक साधनों पर काफी सीमा तक निर्भरता दिखाई गई है। सन् १९५४ में श्रोफ (Shroff) कमिटी ने भी प्लान्ट व मशीनरी के आधुनिकीकरण व नवकरण के हेतु 'आय के पृष्ठ विनियोग' का सुझाव दिया था।

इस बात पर पुनः बल देना अनावश्यक न होगा कि विद्यमान उद्योगों के विकास व विस्तार के लिए दो ही रास्ते होते हैं—(i) अतिरिक्त समता अंश पूँजी आमंत्रित करना और अथवा (ii) संचित लाभों का उपयोग करना। इन दोनों साधनों में से कर जाँच समिति (Taxation Enquiry Commission) ने दूसरे साधन को ही अधिक श्रेष्ठ बताया।¹

भारतीय उद्योग एवं अवितरित लाभ

करारोपण जाँच आयोग के अध्ययन के निष्कर्ष—

करारोपण जाँच आयोग (Taxation Enquiry Commission) ने ४६२ कंपनियों ने सन् १९४६ से ५१ की अवधि के लिये लाभ और इसके विवरण का अध्ययन किया था, जिससे अनेक महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं :—

1 "It appears that corporate savings provided a larger source than new subscriptions, on the whole, in the financing of industrial expansion during the post war period, including new companies, in respect of the other companies corporate savings were even more important."

(१) इस सम्पूर्ण अवधि के लिये करो, लाभानो एवं अविवरित लाभो में अनुपात ४,३ और २ का था। करो का लाभ में भाग सबसे अधिक रहा। इस आधार पर उद्योगधनियो न वृत्त आलोचना भी की थी। जैसे-जैसे करो में कमी जा गई, वैसे वैसे लाभ में उनका भाग भी कम होना गया है। मन् १९४६ में करो का भाग ४०% था, किन्तु मन् १९५१ में ३६ हो गई मया।

(२) करो देने के पञ्चान प्रितरण के लिये उपलब्ध वाषिष श्रीमत् शुद्ध लाभ की मात्रा ०६ करोड ८० ली, जिसमें से १६३ करोड ८० (अर्थात् ४८%) वितरित किया गया और श्रोमन् ११५ करोड ८० (अर्थात् ४०%) अविवरित लाभ था। वितरण के लिये उपलब्ध लाभ की मात्रा उक्त अवधि में कम या अधिक होनी रही है, लेकिन वितरित लाभ की मात्रा प्रायः स्थिर रही है। अन् वितरित लाभ का प्रतिशत घटता-बढ़ता रहा है। अविवरित लाभ का प्रतिशत भी अधिक लाभ के वर्ष में अधिक और कम लाभ के वर्ष में कम रहा। यह बात निम्न तालिका में स्पष्ट हो जाती है :—

चुनी हुई कम्पनियों के लाभ एवं इसका प्रयोग

(१९४६-५१)

(करोड ८० में)

वर्ष	कर देने के पश्चात् लाभ	वितरित लाभ	श्रिजवा या ट्रान्स्फर	अवितरित लाभ	वितरित लाभ का प्रतिशत	अवितरित लाभ का प्रतिशत
	१	२	३	४	५	६
१९४६	२७.८०	१५.५१	६.६७	१०.७८	५५.८	३८.८
१९४७	२४.३६	१५.१२	८.३२	८.५७	६२.०	३५.०
१९४८	३१.३०	१५.२८	१६.३३	१५.७१	४८.८	५०.०
१९४९	१६.६२	१५.१०	६.६२	४.२४	७७.०	२१.६
१९५०	३०.३६	१७.८६	११.६६	१०.११	५८.६	३६.६
१९५१	३६.०२	२०.६१	१६.७१	१७.६३	५२.८	४६.६
कुल	१७०.४८	६६.४६	६६.५४	६६.२८	५७.७	४०.१

(३) लूट, बिजली, जहाज, चाय एवं अन्य वगैरा उद्योगों में वितरित लाभ का अनुपात सब उद्योगों के औसत अनुपात (५७.७) अधिक था और तदनुसार इनके अवितरित लाभ का अनुपात भी सब उद्योगों के औसत अनुपात (४०.१%) से कम रहा। इसके विपरीत, मशीन, कागज व सूती वस्त्र उद्योगों में अवितरित लाभ का अनुपात सब उद्योगों के औसत अनुपात से अधिक है। इसका कारण यह है कि इन उद्योगों में कोषों का पूँजीकरण अधिक मात्रा में किया जाना है। यह बात निम्न-तालिका में दिखाई गई है :—

विशेष उद्योगों में वितरित एवं अवितरित लाभ

(१९४६-५१)

	वितरित लाभ (कर काटने के बाद शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में)	अवितरित लाभ (कर काटने के बाद शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में)
सूती वस्त्र	४६.२	४६.७
लूट का सामान	७३.१	२६.८
अन्य वस्त्र	५७.४	४१.८
लौह एवं स्पात	५२.६	४०.४
इजीनिपरिंग	५६.२	४३.७
चीनी	५६.०	४२.७
रसायन	६४.६	३३.३
कागज	४७.३	५२.७
वनस्पति तेल	६१.५	३६.५
दियासलाई	४८.८	५१.२
सीमेन्ट	६०.१	२७.३
चाय बागान	६८.७	३१.३
अन्य बागान	६६.७	३२.३
कोयला	६४.२	३५.४
बिजली	७६.७	२२.०
जहाज	७०.५	२९.५
अन्य	५५.५	४३.५
सब उद्योगों के लिये	५७.७	४०.१

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्ययन के निष्कर्ष—

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग ने सन् १९५०-५५ की अवधि के लिये ७५० सयुक्त स्कन्ध कम्पनियों की वित्तीय दशा का अध्ययन किया था। इस अध्ययन के परिणाम नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किये गये हैं :

(१) कुल लाभ (२८२ करोड़ रु०) में कर, लाभांश व अविनरित लाभ का अनुपात क्रमशः ४१, ३६ व २३ था।

(२) कर देने के बाद वितरण के लिये उपलब्ध लाभ २२७ करोड़ रु० था। इसमें से कम्पनियों ने १:६ करोड़ रु० (अर्थात् ६१%) लाभांश के रूप में वितरित किया और ८८ करोड़ रु० (अर्थात् ३९%) रोक लिया या अवितरित लाभ था।

(३) वार्षिक लाभ में परिवर्तन होने का सबसे अधिक प्रभाव अवितरित लाभों पर हुआ। उदाहरण के लिये, कर देने के बाद लाभ सन् १९५२ में ३१ करोड़ रु० रह गया, जब कि पिछले वर्ष ५१.५ करोड़ रु० था। इसके फलस्वरूप लाभ में केवल २.५ करोड़ रु० की कमी हुई, जबकि अवितरित लाभ में १८ करोड़ रु० की कमी आई। (देखिये तालिका)

कम्पनियों द्वारा लाभ का प्रयोग (१९५१-५५)

वर्ष	कर काटने के बाद लाभ	वितरित लाभ (लाभांश)	अवितरित लाभ	वितरित लाभ का अनुपात	अवितरित लाभ
१९५१	५१.५	२७.०	२४.६	५२.०	४८
१९५२	३१.०	२४.५	६.६	७६	२१
१९५३	३८.६	२६.१	२.५	६८	३२
१९५४	४५.८	२६.२	१९.६	६४	३६
१९५५	५६.५	३२.२	२७.३	५४	४६

(४) अधिकांश उद्योगों में अवितरित लाभ अर्थ प्रवर्धन का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोह एवं स्पात, इंजीनियरिंग, शिपिंग एवं कागज उद्योगों ने अपना आधे से अधिक लाभ (कर काटने के पश्चात्) रोक लिया था। सीमेंट, चाय, अन्य बगीचा उद्योग व वीथला कम्पनियां न ३ या ३ से

अधिक लाभ रोका था। वनस्पति तेल, भूमि एवं जायदाद कम्पनियो ने लाभार्थ तो बाँटे किन्तु इस हेतु उन्हें अपने रिजर्व से लाभ निकालना पड़ा (देखिये निम्न तालिका)।

विशेष उद्योगों में लाभ का प्रयोग (१९५१-५५)

उद्योग	वितरित लाभ का प्रतिशत	अवितरित लाभ का प्रतिशत
सूती वस्त्र	७७	२३
जूट वस्त्र	८३	१७
अन्य वस्त्र	६८	२
लौह एवं स्थात	३५	६५
इंजीनियरिंग	४७	५३
सीमेन्ट	६१	३९
चीनी	५६	४१
कागज	४५	५५
वनस्पति तेल		.
रसायन	६६	१
दियासलाई	७२	२८
कोयला	६७	३३
बिजली	७८	२२
जहाज	४७	५३
चाय	६३	३७
अन्य वगैरे	६३	३७
व्यापारिक कम्पनी	८६	११
भूमि एवं जायदाद	११६	...
(कुल अन्य कम्पनियो सहित)	६१	३९

आन्तरिक बचत को प्रभावित करने वाले मुख्य-मुख्य घटक—

किसी कम्पनी में आन्तरिक बचत की मात्रा कितनी होगी, यह निम्न मुख्य घटकों पर निर्भर है :—

कम्पनियों की दहत की प्रभावित करने वाले घटक

- (I) कम्पनिया की आय,
- (II) सरकार की कर नीति, एवं
- (III) उद्योग की लाभांश सम्बन्धी नीति ।

(I) कम्पनियों की आय—

कुछ लाभ बांटने और कुछ लाभ रोक्ने का प्रश्न तब ही उदय होता है जबकि कम्पनी को पर्याप्त लाभ हो । लाभ की मात्रा को प्रभावित करने वाले निम्न घटक हैं :—(i) माँग एवं पूर्ति सम्बन्धी दशाएँ, (ii) उत्पादन एवं विक्री लागत, (iii) सामान्य मूल्य

स्तर, (iv) सस्था का आकार (v) सम्मेलन का स्तर एवं स्वरूप, (vi) पूँजी का अनुपात (Gearing of Capital) आदि । ये घटक कम्पनी की आय को निर्धारित करते हैं । आय का कितना भाग कम्पनी पुनः राक कर विनियोग करेगी, यह भी अनेक घटकों पर निर्भर है जैसे—(i) व्यापार में उतार-चढ़ाव की सम्भावना, (ii) विकास की आवश्यकताएँ, (iii) घिसाई की मात्रा, (iv) ऋण परिशोधन कोष की आवश्यकता, एवं (v) लाभांश की दर में स्थायित्व लाने की इच्छा । प्रत्येक प्रगतिशील व्यवस्थापक का यह मुख्य लक्ष्य होता है कि वह अपने व्यापार व उद्योग को सहज गति, सफलता सहित एवं स्थायी ढंग से चलावे । इस उद्देश्य की पूर्ति में सचित आय से बड़ी सहायता मिलती है ।

(II) करारोपण—

गत कुछ वर्षों में विभिन्न उद्योगपतियों, संगठनकर्ताओं एवं व्यापारिक व औद्योगिक पापदों द्वारा सशस्त्री कर नीति को कड़ी आलोचना की गई है, क्योंकि (i) कर की अत्यधिक ऊँची दर ने कम्पनियों में पूँजी निर्माण को कुप्रभावित किया है, (ii) करारोपण की वर्तमान दरें प्रति व्यक्ति आय के इतने न्यून स्तर पर भारतीय अर्थ-व्यवस्था की सहनशक्ति के परे हैं, (iii) क्रेता के बाजार की दशाएँ लौटने के सन्दर्भ में करों की इतनी ऊँची दर न्यायसंगत नहीं है, (iv) कर की ऊँची दरों का प्राधुनिकीकरण एवं विकास योजनाओं पर प्रभाव पड़ रहा है व (v) विदेशी पूँजी के आयात में भी बाधा हो रही है । इसके विपरीत सरकार का मत था कि (i) भारत में कुल कर आय का राष्ट्रीय आय से अनुपात विश्व में सबसे कम है । यह भारत में सन् १९५०-५१ में ७% था, जबकि ब्रिटेन में ३५, जापान में २३, आस्ट्रेलिया में २२ और लवा में २०% है । यदि कर अनुपात इतना ही कम रहा, तो विनियोग-स्तर में विशेष वृद्धि होने की आशा छोड़ देनी पड़ती, (ii) प्राइवेट उपक्रमों ने स्वयं ही एक उचित लाभ-नीति नहीं अपनाई है तथा रिजर्व भी नहीं बनाये गये हैं, (iii) कर की दर इतनी ऊँची नहीं है कि उपक्रमों को विशेष निरुत्साहित करने वाली हो, और (iv) सरकार ने परिस्थितियों को देख कर कर भार में कमी करने का प्रयास भी किया है, ताकि उद्योगों को अनावश्यक भार न उठाना पड़े ।

केर समस्या पर विचार करते समय करारोपण-जाँच-आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखना आवश्यक है। ४६२ कम्पनियों की लाभ-नीति का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से यह मालूम हुआ है कि वितरित लाभ की मात्रा और लाभ से इसका अनुपात करो की मात्रा व दरो से इतना प्रभावित नहीं होते जितना कि लाभ की मात्रा व दर से। एक अन्य आधुनिक अध्ययन से भी यह पता चला है कि यद्यपि उद्योग पर कुल करो का भार बढ़ रहा है तथापि उसे उद्योगपतियों ने उपभोक्ताओं पर डाल दिया है, जिससे उनके लाभों और उत्पादन की मात्रा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भारत सरकार की करारोपण नीति में कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। कर नीति में उचित मशौघन करके कम्पनियों की वचत को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, भारत में भी जापान की भाँति वितरित लाभों पर कर कम दर से लगाया जा सकता है।

(III) लाभाला सम्बन्धी नीति

कम्पनियों की वचत को प्रभावित करने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण बात उनकी लाभाला-नीति है। करारोपण जाँच आयोग की रिपोर्ट से पता लगता है कि कम्पनियाँ अपने शुद्ध लाभों का काफी बड़ा भाग वितरित कर देती हैं। सन् १९४६ में कुल उद्योगों के लिये, शुद्ध लाभों का ७७% भाग वितरित किया गया था। कुछ लोगों ने यह सम्मति दी है कि उद्योग के आन्तरिक साधनों को सुदृढ़ बनाने के लिये लाभाला पर वैधानिक सीमा लगा देनी चाहिये। किन्तु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसके पक्ष में नहीं हैं। लाभाला पर वैधानिक सीमा लगाने के सम्बन्ध में सूती वस्त्र उद्योग के लिये नियुक्त कार्यकारी दल (Working Party for Cotton Textile Industry) ने कहा है कि, “यद्यपि विशाल लाभाला वितरित करके लाभों को बिखेर देना अनुचित है तथापि किसी भी उद्योग में लाभाला को सीमाबद्ध करने का बुरा प्रभाव न केवल उस विशेष उद्योग पर बल्कि सभी उद्योगों पर पड़ेगा। जब निर्धारित न्यूनतम लाभाला के लिये गारन्टी नहीं है, तो अधिकतम लाभाला (जो कि बँने ही बहुत नीचा है) सम्बन्धी प्रश्न खड़ा करने से विनियोगकों में यह भावना पैदा होगी कि शेयरों में विनियोग करना आवश्यक है। आज देश में पूँजी निर्माण की बहुत आवश्यकता है। यदि लाभाला पर सीमा लगाई गई, तो इसका पूँजों के प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा है।”^१

1. “While it deprecates the frittering away of unexpected profits by the distribution of large dividends—a statutory provision for limitation of dividends in any industry will have an unhealthy effect not merely on the industry concerned but on the flow of capital to indus-

लाभांशों को सीमाबद्ध करने के विषय में प्रायः निम्न तब दिये जाते हैं —
(i) इसमें पूँजी बाजार अस्त-व्यस्त हो जाता है तथा प्राइवेट धन के लिए अर्थ प्रबन्धन सम्बन्धी कुप्रवृत्तियाँ का प्रोत्साहन मिलता है । (ii) यह धन को व्यर्थ कामों में खर्च करने को प्रोत्साहन देता है । (iii) इसमें कम्पनियों की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है एवं (iv) औसत की अवधि सदा विवादास्पद है ।

सन् १९५५ में राज्य मन्त्रालय ने इस प्रश्न का प्रस्ताव रखा गया था कि सरकार देश की सभी औद्योगिक संस्थाओं के लाभों पर सीमा (Ceiling) लगा दे और सीमा से ऊपर होने वाले लाभ को आर्थिक सहायता चाहने वाले उद्योगों को देना देना स्वीकार करे । यह सीमा बैंक दर से २ या ३% अधिक लगाई जाय । प्रोफसर राज्जा ने इसका पार विरोध किया था और कहा कि इसमें प्राइवेट धन में घाटा की लहर दौड़ जायगी । हाँ, ऐसे उपाय करना आवश्यक है जिनसे लाभ को संस्था में कम से कम मात्रा में निकालने की प्रेरणा मिले । एवं सदस्य ने बताया है कि यदि सरकार ने ऐसा कदम उठाया तो यह सारे के अण्ड दान वाली मुर्गी को ही मार डालने के समान होगा । जैसे भी यदि विचार करें तो उक्त प्रस्ताव की अमल में लाजाना निरर्थक प्रतीत होगा । वर्तमान बैंक दर पर २ या ३% अधिक का सीमा लगभग ६५% होती है जबकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा १००१ कम्पनियों की जाँच में पता चला है कि लाभों की दर ५२% रही है । अतः ऊँचे लाभों पर रोक लगाने का एक अच्छा तरीका करारोपण ही है । अस्थायी रूप से प्रतिरिक्त लाभ कर लगाया जा सकता है । यदि लाभों पर सीमा लगाई गई तो शेयर बाजार पर बुरा असर पड़ेगा तथा प्राइवेट क्षेत्र निरुत्साहित होगा ।

लाभों के अन्तर्विनियोग की हानियाँ—

यदि लाभों का अविवेकपूर्ण ढंग से अन्तर्विनियोग किया गया तो निम्न हानियाँ होने की सम्भावना है —

(१) **एकाधिकारों का निर्माण**—लाभों के अन्तर्विनियोग ने विद्यमान फर्मों का अधिकधिकार विस्तार होता जायगा जबकि नई फर्मा को पूँजी मिलने में कठिनाई अनुभव होगी । इस प्रकार एकाधिकार बनने की प्रोत्साहन मिलता है ।

tries generally Where there is no guarantee of a minimum dividend prescribe, the question of a maximum—and too at a low level would certainly create feeling in the investor that equity investment is not attractive At a time when capital formation is still the greatest need of the country it will be taking a great risk if an actual definite limitation was put on the dividends

(२) शेयरों के मूल्यों में गड़बड़ी—सम्पत्ति में बहुत अधिक एकत्रित आय होने से व्यवस्थापकों को शेयरों के मूल्य में गड़बड़ियाँ करने का अवसर मिल जाता है। सामान्य दर कम रख कर तथा अधिक अनुपात में लाभ रोक कर वे शेयर बाजार में शेयरों का मूल्य नीचा लाने में सफल हो जाते हैं और फिर घटे हुये मूल्य पर स्वयं खरीद कर लेते हैं। बाद में एकत्रित लाभ को सहायता से वे ऊँचे सामान्य होने लगते हैं, जिससे शेयरों का मूल्य बढ जाता है। अब वे अपने घटे हुये मूल्य पर खरीदे गये शेयर बेच कर लाभ उठाते हैं। उनको इन भावबाजियों में निर्दोष व अनभिज्ञ विनियोजकों को बड़ी हानि सहनी पड़ती है।

(३) कर दायित्व से बचना—कर-दायित्व से बचने के लिये कम्पनी की बचत में घुड़ि की जा सकती है। (आय कर अधिनियम में इतने बोप को दूर करने का उपाय कर दिया गया है।)

(४) बचत का दुरुपयोग—यह भी सम्भव है कि सम्पत्ति की बचत को शेयर होल्डरों के व्यापक हित में प्रयोग न किया जाय। प्रबन्धक एक कम्पनी की बचत को अपने ही स्वार्थ वाली कम्पनियों में विनियोग कर सकते हैं।

(५) अत्यधिक पूँजीकरण—प्रबन्धक शेरों को खरीद करके एकत्रित लाभ का पूँजीकरण करते रहते हैं। इससे अत्यधिक पूँजीकरण हो जाने का भय है। शेजी के दिनों में ऐसा अधिक पूँजीकरण ठीक होता है, लेकिन 'संतोष का बाजार' लौटने पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा।

(६) विनियोजक की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप—साधारणतः विनियोजक को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह पुराने उद्योग के विकास में सहयोग दे अथवा नई सम्पत्ति स्थापना में सहायता करे। किन्तु सामान्य-विवरण की उपरोक्त नीति उसकी इन स्वतन्त्रता में बाधा आसती है।

(७) पूँजी बाजार के प्रवाह पर रोक—यह भी कहा जाता है कि लाभ को सम्पत्ति में रोक रखना पूँजी बाजार के स्वाभाविक कार्यवाहन पर प्रतिबन्ध लगाने के समान है।

उपसंहार—

ब्रिटेन में ब्रिटिश उद्योग द्वारा लाभों के अन्तर्विनियोग की नीति को अपनाते के विरोध में सशक्ति प्रयास चले रहे हैं। लेकिन यह स्मरण रहे कि भारतीय परि-

लाभों के अन्तर्विनियोग

की ॥ हानियाँ

१. एकाधिकारी का निर्माण।
२. शेयरों के मूल्यों में गड़बड़ी।
३. कर-दायित्व से बचाव।
४. बचत का दुरुपयोग।
५. अत्यधिक पूँजीकरण।
६. विनियोजक की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप।
७. पूँजी बाजार के प्रवाह पर रोक।

स्थितियाँ ब्रिटेन की परिस्थितियों में विस्तृत भिन्न ? । अत्यधिक विकास हो जाने के कारण ब्रिटिश उद्योग के लिये लाभ के अन्तर्विनियोजन की नीति भले ही अनुपयोगी जैचे किन्तु भारत में लाभ के अन्तर्विनियोजन की उपेक्षा करने में औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था करना कठिन होगा । आशा है कि नव स्थापित बम्पनी लॉ प्रशासन विभाग की नीति अपनायेगा कि बम्पनियों के एकत्रित लाभ को शेयर होल्डरों के देश के व उद्योग के सामान्य हित में अन्तर्विनियोग किया जा सके ।

STANDARD QUESTIONS

- 1 What do you mean by the term 'Internal Financing' ? How does it affect the interest of the Share holder, industry and society ?
- 2 Write a note on 'Retained Profits in Indian Industries.'
- 3 Discuss the factors which affect the amount of savings in a company. What are the dangers of ploughing back of profits ?

अध्याय ३८

बैंक एवं औद्योगिक वित्त

(Banks & Industrial Finance)

भारत में औद्योगिक वित्त की समस्या—

भारत में औद्योगिक समस्याओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की एक बड़ी समस्या है । सन् १९०६-१३ के स्वदेशी आन्दोलन के समय में व्यापारिक बैंकों ने (विशेषतः पंजाब के व्यापारिक बैंकों ने) औद्योगिक वित्त व्यवस्था में प्रथम बार भाग लेना आरम्भ किया । स्वदेशी आन्दोलन की प्रेरणा प्राप्त उद्योगों को इन तथाकथित औद्योगिक बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन सन् १९१३-१५ के वित्तीय संकट ने ऐसे अनेक बैंकों को फेल कर दिया । प्रथम युद्ध काल में व इसके पश्चात् तेजी की दशाओं से उत्साहित होकर अनेक कम्पनियों का निर्माण हुआ । जापान व जर्मनी

ने औद्योगिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक उन्नति की और वहाँ औद्योगिक और बैंकिंग प्रणालियों में जो समन्वय था उससे प्रेरणा लेकर हमारे देशवासियों ने भी वंसा ही नमूना अपनाए जाने का प्रयास किया। अतः औद्योगिक बैंकिंग के क्षेत्र में हमारा दूसरा प्रयोग सन् १९१७ टाटा इन्डस्ट्रियल बैंक की स्थापना से आरम्भ हुआ। इस बैंक ने इतनी तेजी से उन्नति की थी कि स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयरों का मूल्य बहुत बढ़ गया। औद्योगिक वित्त प्रबन्ध करने के उद्देश्य को लेकर कई बैंक टाटा बैंक के नमूने पर आरम्भ हुये, किन्तु अगले कुछ वर्षों में ये सब बंद होने के लिये विवश हो गये। इनकी असफलता के कई कारण थे।

प्रारम्भिक औद्योगिक बैंकों की असफलता के कारण—

इन बैंकों की असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे—

(१) जर्मन नमूने के बैंकों के सफल संचालन के लिये आवश्यक ज्ञान व योग्यता का अभाव—हमारे देशवासियों ने भारतीय परिस्थितियों में जर्मन नमूने के बैंकों की स्थापना करने का उत्साहपूर्ण प्रयास तो किया, लेकिन उनके उत्साह में आवश्यक ज्ञान और योग्यता का अभाव तो पूरा नहीं हो सकता था, जो कि ऐसी विशिष्ट समस्याओं के संचालन के लिये अनिवार्य है। जर्मन बैंकों के संगठन, कार्य प्रणाली व कार्यों के बारे में बड़ा धर्म प्रचलित था। जर्मन बैंकों में प्रत्येक

भारत में औद्योगिक बैंकों की असफलता के कारण

१. जर्मन नमूने के बैंकों के सफल संचालन के लिये आवश्यक ज्ञान व योग्यता का अभाव।
२. ऋणियों की पर्याप्त जांच पड़ताल न करना।
३. विनियोग का विविधीकरण न होना।
४. संचालकों की अकुशलता।

विभाग आत्म निर्भर होता था। उनकी इस विशेषता को भारतीय प्रवर्तकों ने नहीं समझा, जबकि जर्मन बैंकों के पास विशाल निजी पूंजी थी, वे डिबेंचर बेच कर भी प्रतिरिक्त कोष जुटा लेते थे तथा औद्योगिक प्रतिभूतियों में सदा के लिये धन फँसाने की नीति कभी स्वीकार नहीं करते थे तब भारतीय औद्योगिक बैंकों के पास निजी कोष बहुत कम थे, ऋण वह उनमें लोकप्रिय न था तथा उनके कोष स्थायी रूप से औद्योगिक शेयरों में लग चुके थे। व मुख्यतः डिपॉजिट बैंक थे, किन्तु उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कार्य भी अपने को उलझा लिया।

(२) ऋणियों की आर्थिक अवस्था के विषय में पर्याप्त जांच पड़ताल न करना—बैंकों ने ऋण लेने की इच्छुक समस्याओं की आर्थिक अवस्था के विषय में पर्याप्त जांच पड़ताल नहीं की। फल यह हुआ कि बिल्कुल ही अयोग्य समस्याओं को पर्याप्त प्रतिभूति के बिना ऋण दे दिये गये, जो कि वसूल न हो सके।

(३) विनियोगों के विविधोत्तरण का अभाव—विनियोगों का चुनाव उचित प्रकार नहीं हुआ, उनके विविधोत्तरण की उपेक्षा की गई, विनियोग की सुरक्षा को अधिक ध्यान के साथ बलबलान कर दिया गया, प्रतिभूति का वैधानिक ढंग में मूल्यांकन नहीं कराया जाता था सट्टे के लिये प्रतिभूतियों का श्रम विप्रेषण किया जाता था ।

(४) संचालकों की अनुकूलता—अनेक दशाओं में संचालकों की अनुकूलता के कारण भी बंको को बड़ी हानि सहनी पड़ी । शेयर होल्डरों व बाहरी व्यक्तियों में सच्ची दशा छिपाने के लिये पूँजी में से लाभान्न बाटे जाते थे । संचालकों की हित वाली संस्थाओं की दिना पर्याप्त जाच-पड़ताल के बिना रकमें उधार दे दी गईं । प्रत्येक प्रकार का बैंकिंग कार्य किया जाता था, किन्तु साख या मिश्रित बैंकिंग को फल बनाने के लिये आवश्यक उपाय नहीं किए गये । अल्पकालीन बैंकिंग एवं दीर्घकालीन साख व्यापार का उचित समन्वय न होने से बंको के ऋण बढ़क गये । हमारे बंको की अज्ञानता एवं अकुशलता ने स्थिति को अधिक भयावह बना दिया ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय परिस्थितियाँ जर्मन नमूने के बंको की स्थापना के लिये अनुकूल नहीं थीं और साथ ही उनके संचालन की आवश्यक टेक्नीक का भी पालन नहीं किया गया ।

सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक बैंक—

प्राइवेट उपक्रम के अतिरिक्त सरकारी सहायता से एक विशिष्ट संस्था की स्थापना पर भी विभिन्न समितियों द्वारा जोर दिया गया है, क्योंकि उनके मतानुसार इससे देश में औद्योगिक वित्त की समस्या बहुत सीमा तक हल हो सकती है । सन् १९१८ में ही औद्योगिक कमिशन ने भारत में औद्योगिक बंको की स्थापना करने का सुझाव दिया था और कहा था कि उनकी पूँजी (शेयर या डिबेन्चर पूँजी) कुल व्यापार के अनुपात में काफी अधिक होनी चाहिये, किन्तु भी एक संस्था या एक उद्योग में बहू अपनी रकम न फमावें, प्लान्ट, इमारत व भूमि पर ऋण देते समय पर्याप्त सावधानी रखें, अधिकतर कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करे, स्वयं ही कंपनियों के प्रवर्तन की चेष्टा न करे, नई कंपनियों की दिशा में उचित सावधानी बरतें आदि । औद्योगिक बैंक में सुरक्षा को प्रभावित करने वाली मुख्य बात यह है कि प्रत्येक प्रकार के व्यापार को उचित सीमा के अन्दर रखा जाय । औद्योगिक कमिशन ने जापान के औद्योगिक बैंको के नमूने को भारत में अपनाने का परामर्श दिया । मुख्यतः कार्यशील पूँजी में भाग लेने का परामर्श देकर कमिशन ने औद्योगिक बैंको की उपयोगिता को ही कम कर दिया ।

सरकारी सहायता से औद्योगिक बैंको की स्थापना के प्रश्न पर भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिती ने विचार किया । इसके समक्ष अधिकांश अर्थशास्त्रियों, देशी बैंको, व्यापारिक बैंको, चेम्बर आफ कॉमर्स आदि ने दीर्घकालीन अर्थ प्रवर्ध के लिये

विशिष्ट सस्या की स्थापना पर जोर दिया। इसके विपरीत, विदेशी विशेषज्ञों ने यह मत प्रगट किया कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में मैनेजिंग एजेन्ट्स ही दीर्घकालीन अर्थ प्रबन्ध का उत्तम साधन है। कुल पर प्रचलित सामान्य धारणा यही थी कि औद्योगिक बैंकों की स्थापना की जानी चाहिये और सरकार को उनकी पूंजी में भाग लेना चाहिये। अब औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों की स्थापना में भारत की यह दीर्घकालीन आवश्यकता पूर्ण हो गई है।

मिश्रित बैंकिंग

मिश्रित बैंकिंग के कुछ अनुभव—

‘मिश्रित बैंकिंग’ (Mixed Banking) से आशय डिपॉजिट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का समन्वय करने से है। इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा उद्योगों के लिये अल्प कालीन, मध्यम-कालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध की जाती है। यूरोप व अमेरिका में सन् १९३१—३३ के बैंकिंग संकट में जो अनुभव हुआ उसके प्रकाश में डिपॉजिट बैंकिंग व इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को सम्मिलित करने के विरुद्ध कानूनी प्रतिबन्ध लगाये गये। भारत में भी द्वितीय महायुद्ध के समय में ५० बंगाल के अधिकांश बैंकों की असफलता का मुख्य कारण उन दीर्घकालीन ऋणों को बनाया जाता है जो कि बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये थे।

विभिन्न कमेटीयों के मत—

(१) उद्योगों को व्यापारिक बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण देने के प्रश्न पर भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने सन् १९३०—३१ में विचार किया था और इस नतीजे पर पहुँची थी कि सुस्थापित बैंक (जैसे उस समय इम्पीरियल बैंक और नौ अन्य बड़े संयुक्त पूंजी वाले बैंक) अपनी कुल पूंजी व कोषों का १०% भाग, जर्मन क्रेडिट बैंकों की भाँति, औद्योगिक कम्पनियों के शेयरों व डिबेन्चरों में विनियोग कर सकते हैं। लेकिन कमेटी को सिफारिशों पर कोई कार्य नहीं किया गया।

(२) संवित्तमिलन कमेटी ने कहा था कि जो देश आर्थिक प्रगति की राह पर बढ़ना चाहता है उसे वित्तीय एवं औद्योगिक क्षेत्र को एक उच्च संगठन द्वारा समन्वित करना चाहिये। आर्थिक इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण मिलना कठिन है जहाँ बैंकों का (अल्पकालीन व दीर्घकालीन वित्त में) पृथक्करण किया गया है। इसके विपरीत, मिश्रित बैंकिंग अपनाते वाले देशों के कई उदाहरण मिल जायेंगे।

(३) सराफ कमेटी ने भी बैंकों द्वारा उद्योगों को दीर्घकालीन सुविधायें देने की सभावनाओं पर गम्भीरता से विचार किया। उसके समक्ष विभिन्न मत प्रस्तुत हुये। उद्योगों के प्रतिनिधियों ने सामान्यतः इस बात पर जोर दिया कि बैंकों को चाहिये उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक मात्रा में वित्त व्यवस्था करें। इससे विपरीत, बैंकरों ने इस बात पर बल दिया कि उनका प्रारम्भिक एवं मुख्य कार्य अल्पकालीन वित्त व्यवस्था तक ही सीमित है। हाँ, कुछ बैंकों ने स्थायी

सम्पत्तियों के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देने को अपनी तत्परता प्रगट की, वरतें ऐम एडवान्सो के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भी उन्हें (बैंको को) उधार की सुविधा दे। कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि व्यापारिक बैंक अपने उपलब्ध साधना की सीमा के भातर उद्योगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे रहे हैं। उन्होंने दीर्घकालीन वित्त भा देन का प्रयास किया है। जिन उद्योगों व वार में उन्हें यह संतोष हो गया कि उनका ऋण देने से सुरक्षा व तरलता पर असर नहीं पड़गा, उनको उन्होंने दीर्घकालीन ऋण भी दिये हैं।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कष का जो दल भारत में सन् १९५३ में प्राया था उसने यह बताया कि भारतीय उद्योगों को पर्याप्त साख प्राप्त करने में जो कठिनाई अनुभव हो रही है उसका कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली की ऋद्धिवादी प्रवृत्ति है। भारतीय बैंक दीर्घकालीन ऋण दैनिक कार्यों के लिये देते हैं किन्तु मशीनों के क्रय व प्रतिस्थापन के लिये पर्याप्त साख नहीं देते। परिणामस्वरूप उपलब्ध बैंक साख का अधिकांश भाग स्टॉक रखने की वित्त व्यवस्था में लगा हुआ था। उत्पादन के विस्तार का अथ प्रबन्धन करने में बहुत थोड़ा ही भाग लगा था।

(५) प्लानिंग कमिशन ने भी वहाँ को परामर्श दिया है कि वे उचित साख सृजन का कार्यक्रम तैयार कर उपलब्ध बचन एवं उत्पादन वृद्धि का अनुमान लगावें तथा ऋद्धिवादी दृष्टिकोण बदलें।

दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का सहत्व—

व्यापारिक बैंकों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि वे दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भाग ले सकते हैं। उनकी अनुकूल स्थिति में सम्बन्धित बातें निम्नलिखित हैं — (१) अनेक शाखाय होने व पूँजी एवं द्रव्य बाजार से घनिष्ट सम्बन्ध रहने के कारण वे किसी भी व्यापारिक उपक्रम के भविष्य का विश्वस्त अनुमान लगा सकते हैं। (२) दीर्घकालीन वित्तीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उनके बढकर सहाय मागेशन व ठोस सहायता देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि वापार का दीर्घकालीन अथ प्रबन्ध करने के दौरान में वे न केवल उनकी वित्तीय समस्याओं के साथ वरन् अन्य श्रेणीगत समस्याओं के सम्पर्क में भी आते हैं। (३) वित्त प्रबन्ध की एक शाखा व सम्बन्ध में हुये अनुभव का लाभ दूसरी शाखा में भी उठाया जा सकता है। (४) उद्योगों की वित्तीय नीतियों और समस्याओं के घनिष्ट परिचय होने के कारण वे विनियोजन करने वाली वित्त के हिता की रक्षा कर सकते हैं तथा उनको उपयोगी सलाह दे सकते हैं।

दीर्घकालीन वित्त प्रबन्ध में बैंकों को अधिक सहायक बनाने के सुझाव—

उद्योगों की दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था में बैंकों को अधिक उपयोगी बनाने के लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं —

(१) शेयरों व डिबेन्चरों में विनियोग—अभी व्यापारिक बैंकों द्वारा बहुत कम औद्योगिक विनियोग किया गया है। ३१ दिसम्बर सन् १९५५ को अनुसूचित एवं असूचित बैंकों का कुल विनियोग ४८३.६ करोड़ था, जिसमें से कम्पनियों के शेयरों व डिबेन्चरों में केवल (१३ करोड़ ४० अर्थात् २.६%) ही लगाया। इस दशा का कारण यह है कि बैंकों के दायित्व प्रायः माग पर शोधनीय होने हैं। साथ ही औद्योगिक विनियोजन में कुछ स्वाभाविक खतरा भी होता है। बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसिएशन ने सराफ कमेटी को अपन स्मरण पत्र में कुछ उपयोगी सुझाव दिये थे। उसने सुझाव दिया कि नियमा में इस प्रकार सशोधन किया जाय कि सरकार द्वारा स्वीकृत चुने हुए प्राइवेट पूंजी निर्गमनों में बैंक रुपया लगा सके। जब सरकार कम्पनियों का पूंजी निर्गमन करने की आज्ञा दे, तो, सत्था की विस्तृत जाच करके, वह बैंक को उचित सलाह दे सकती है कि वे चाहे तो उसके शेयरों और डिबेन्चरों में विनियोग कर सकते हैं। विनियोक्त बैंकों को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि वे ऐसे विनियोगों के आधार पर स्वयं भी रिजर्व बैंक से ऋण ले सकें। यह तभी संभव है जबकि ऐसे विनियोगों को रिजर्व बैंक ऋण देने के लिये स्वीकृत सम्पत्ति धातित कर दे।

(२) दीर्घकालीन ऋण देना—

बहुत कम बैंक भारत में उद्योगों को म्यादी सम्पत्ति पर ऋण देते हैं। इस प्रकार के ऋणों से सम्बन्धित आकड़ उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु हम सब जानते हैं कि अल्पकालीन ऋण के रूप में दिए गये एडवान्स का प्रायः नबकरणा कर दिया जाता है। इस प्रकार यह विधि कुछ सीमा तक उद्योगों की दीर्घ कालीन ऋणों की आवश्यकता पूरी करती है। यदि बैंक कम्पनियों के शेयरों में रुपया लगावें तो दीर्घकालीन ऋण देने की अपेक्षा अधिक खतरा

उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था में व्यापारिक बैंकों को अधिक उपयोगी

धनाने के सुभाव

१. शेयरों एवं डिबेन्चरों में विनियोग करना।

२. दीर्घकालीन ऋण देना।

३. प्रतिभूतियों का अभियोग करना।

४. निगमों में विनियोग।

५. कम्पनी प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण।

नोटे केवल अक्षत है, क्योंकि दीर्घकालीन ऋण तो एक निश्चित समय के अन्दर कम्पनी के जीवन काल में वापिस होने की सम्भावना रखते हैं, जबकि शेयरों में लगाया गया धन कम्पनी के जीवन काल में नगद नहीं मिल सकता। हाँ, उसे अन्य विनियोगों को देखा जा सकता है। इस प्रकार शेयरों में विनियोग करने का मुख्य खतरा 'हानि' है, जबकि दीर्घकालीन ऋणों का खतरा 'अन्तरलता' है। यही नहीं, ऋणों की अपेक्षा शेयरों में विनियोग करने पर बैंक की सुरक्षा कम हो जाती है, क्योंकि जब बैंक ऋण

दता है ता शेरर कैपीटल वक न नियम का नाम करनी है । इसका अनिर्दिष्ट, जब वैक कृषी औद्योगिक मस्या को स्पर्द्धा सम्पत्ति की दृष्टि पर करण दना है ता सम्पत्ति का मूल्य इनकी उत्पादकता व क्षमता निर्दिष्ट किया जाता है किन्तु जब वह सस्या व शेरर मान नना है शेरर का मूल्य एमी गस्तिया द्वारा निर्धारित जाता है जा नि उत्पादन एवं उपभाग मे सम्पत्ति ननी न । एम प्रकार बका व दृष्टिकोण से शेरर म विनियोग करन की अपेक्षा दीषकालीन करण दना अधिक लाभप्रद है । वैक प्रपन माग-दायित्वा को बचन अल्पकालीन करण दन म समय डिपार्जिट विधि निपार्जिट एवं रिजर्व ना उद्योग का दीषकालीन करण दन म प्रयोग करना चाहिए । वे इस काय क लिय मध्यमकालीन डिबन्चन का नियमन करव न घन कोष जुटा सकते है ।

() प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना—मराफ कमटी न यह सुभाव दिया है कि देश व व व बका को दामा सम्पत्तिया व माय मित्रकर एवं मिन्डीकट बना लेना चाहिए । एम मिन्डीकट का नाम औद्योगिक सम्पत्तिया व शेरर व डिबेन्चर के नवीन नियमना का अभिगोपन करना ययवा उनम विनियोग करना हो । य द वर अपन निपार्जिट का ५० एन शेरर व डिबेचर म नमी व तो वे बिना गपनी तरनता की मुकमान पदुचाय प्रादृष्ट क्षम व उगागो र दिए ३० करोड २० दीष कालीन करण की प्रतिरक्त व्याख्या कर सकन ह । बल्त यह मिन्डीकट प्रभावशाली ढंग म तमा काय कर सकता है जबकि व खुल बाजार की क्रियाश्रम म भाग ल अधवा किमी विषय सम्पनी या सम्पत्तिया म अनिश्चित अवधि तक निगमन रखन का मह मत हा जाय । दोनों म म को वात तम ही सम्भव ह जरकि व-द्रीय मादक अधिकारी (ग्रोव् रिजर्व वक) का सक्रिय सहयोग मिले

(४) निगम मे विनियोग—आगारिक प्रतभूतियों म प्रत्यक्ष विनियोग करन व बजाय वक विशिष्ट वित्त निगम व माध्यम म भी उगागो र दिए कोष उपनब्ध कर सकते ह । औद्योगिक वित्त निगम गज वित्त निगम आर्थोर्गिक साख एवं विनियोग निगम आदि का स्थापना होने पर वका न इनकी शेरर पूंजी म भाग लिया है और य निगम स्वयं उगागो का करण दन ह । मराफ कमटी की सिफारिश पर रिजर्व वक न व-द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त उक्त निगमो क शेरर को करण योग्य प्रतभूति धारित कर लिया है यवान वक चाह तो निगम म गरीदे हुए अपने शेरर के आधार पर रजव वक म न ग न सकते ह । एम प्रकार बका व लिए उद्योगो को दीषकालीन करण दने का प्रयत्न नर ता बहुत सुविधाजनक हो गया है । सराफ कमटी न यह सुभाव दिया कि उक्त निगमो म विभिन्न विनियोगका द्वारा लिये जाने वाल अंश की मात्रा का सीमित करन वाला नियम समाप्त कर देना चाहिय, क्योंकि इसम विनियोगो की तरनता बढ जायगा । कुछ दायका कहना है कि उक्त नियम समाप्त करने से शेरर का कुछ गोमो क पास इन्दीयकरण हा जान का र है । फिर नियम को समाप्त करना इस कारण भा आवश्यक है कि य शेरर एक विशेष यूप क विनियोजका म तो परस्पर बदले जा सकने है । अतः उक्त नियम नरना तो पहले मे ही काफी है ।

(५) औद्योगिक प्रतिभूतियों पर करण—कई व्यापार एवं उद्योग चम्बरो न यह सुभाव दिया है कि औद्योगिक प्रतिभूतियों (कल्प नय क शेरर) की गमानत पर वको द्वारा दिए गए करण का ६ माह या १२ महीन व मुमे म बिना म परिणित कर दिया जाय तथा फिर इन विनो को गजव बँडु से राडिस्काउट करन योग्य धारित

कर दिया जाय। दूसरे शब्दों में, रिजर्व बैंड को चाहिए कि औद्योगिक कम्पनी को शेयरों व डिबेन्चरों को अपने ऋणों के लिए म्यागक प्रतिभूति स्वीकार कर ले, तो ध्या-
पारिक बैंड औद्योगिक अर्थ प्रवर्धन में आघक भाग ले सकेंगे। यदि आवश्यकता हो,
तो ऐसे शेयरों व डिबेन्चरों की एक स्वीकृत सूची प्रणाली प्रचलित की जा सकती है।

उपसंहार—

भारतीय बैंडिंग की वर्तमान व्यवस्था में बड़े पैमाने पर मिश्रित बैंडिंग को
अपनाना भले ही सम्भव न हो, लेकिन उम से कम बैंडों और उद्योगों के घनिष्ठ
सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। बैंडों के सहयोग में ही औद्योगिक विकास
तीव्र प्रगति से किया जा सकता है। मिश्रित बैंडिंग को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए
अनुभवी बनकर एक प्रशिक्षित कमचारियों की आवश्यकता है, जिनका दुर्भाग्य से अभी
देश में अभाव है। कहा जाता है कि बैंकों के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए
उद्योगों को मध्यमकालीन साख देने का विनाश क्षेत्र है। परन्तु इसका लिए बैंडों के
कोषों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य में ही
री-फाइनेन्स कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है।

पुनर्वित्त निगम (Refinance Corporation)

पुनर्वित्त निगम का महत्त्व—

पुनर्वित्त निगम की स्थापना में देश की तरफ बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी हो
गई है। वास्तव में बहुत पहले से ऐसे निगम की आवश्यकता अनुभव हो रही थी,
शक्ति केवल मध्यमकालीन साख की पूर्ति करे। दीर्घकालीन साख देने वाले बैंक निगम
इसमें पूर्व स्थापित हो चुके थे, किन्तु मध्यमकालीन साख देने वाली समस्या का अभाव
बहुत खटक रहा था। जैसा कि सब जानते हैं, अनेक बैंडों अपने आह्वानों का ऐम अणु
दिया करते हैं जो कि टेक्नीकल दृष्टि में तो अल्पकालीन सूचना पर लीटायें जाने वाले
होते हैं, लेकिन व्यावहारिक में उनका प्रायः मध्यमकालीन पर नजर रख कर दिया जाता है।
इस प्रकार में अणु वास्तव में मध्यमकालीन ऋण होते हैं। पुनर्वित्त निगम का उद्देश्य
ऐसे ही ऋणों के आधार पर पुनः ऋण लेने की सुविधा प्रदान करना है।

पुनर्वित्त निगम की स्थापना व कार्य प्रणाली—

देश के १५ बड़े बैंडों व जीवन बीमा निगम व निगम की पूँजी में भाग लिया
है, जो कि १२५ करोड़ रु० है। निगमित पूँजी की यह मात्रा बाद की बढ़ाई जा
सकती है। रिजर्व बैंड ने ५ करोड़ रु०, जीवन बीमा निगम ने २५ करोड़ रु०, स्टेट बैंक
ने २५ करोड़ रु० व अनुसूचित बैंक ने २५ करोड़ रु० व शेषर लिए हैं। अमेरिका
का सहयोग २६ करोड़ रु० तक सीमित है। यह निर्दिष्ट किया गया कि प्रत्येक सदस्य
अनुसूचित बैंक को निगम व कुल काया की सीमा में से एक कोटा नियत कर दिया
जाएगा। इस कटे के भीतर वह कुछ निश्चित प्रकार के ऋणों के आधार पर निगम
में पूनः अणु की सुविधा प्राप्त कर सकगा। ये ऋण ३ से ७ वर्षों तक की अवधि के
हों तथा प्रत्येक व्यापकगत ऋण की राशि ५० लाख रु० में अधिक न होनी चाहिए।
इन योजना के अन्तर्गत बैंक ६-१०% की प्राय दर, अणु दे सकेंगे और राज्य निगम
से ५% की व्याज पर ऋण ले सकते हैं। निगम में भाग लेने वाले बड़े बड़े बैंक की
निगम व प्रति प्रस्तुत किये गये ऋणों की आस्थि का उत्तरयोग। निगम स्वयं
की साख या प्रतिभूतियों की पर्याप्तता के कारण में चिन्ता नहीं करेगा। यह

यह ध्यान रखेगा कि प्रस्ताविन ऋण पत्र योजना वे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा या नहीं। यह आशा की जाती है कि वारपारिंग से पुनः ऋण मिलने की सुविधाओं (re-financing facilities) के कारण व्यापारिक बैंक उद्योग का अधिक मात्रा में मध्यमकालीन ऋण दे सकेंगे।

पुनर्वित्त निगम की कठिनाइयाँ—

पुनर्वित्त निगम व भाग में कठिनाइयाँ आने की सम्भावना है, जो कि निम्न-लिखित हैं:—

- (१) बैंकों को उन ग्राहकों की मास सम्बन्धी सब जोखिम उठानी पड़ेगी, जिन्हें व मध्यमकालीन ऋण दे। किन्तु मध्यमकालीन मास देने के क्षमता में हमारे बैंकों का अनुभव सीमित है और नविक सी अभावधानी से उन्हें भारी हानि हो सकती है।
- (२) १५% का जो माजिन व्याज के सम्बन्ध में रखा गया है वह बहुत थोड़ा है, विशेषतः इस सम्बन्ध में कि सम्पूर्ण जोखिम बैंकों को ही उठानी पड़ती है।
- (३) इस क्षेत्र में बैंकों को सफल प्रयोग करने के लिए एक सतृप्तजनक आधार प्राप्त नहीं है। इसके लिए पहले जनता में दीर्घकालीन डिपॉजिटों का विकास करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह प्राया गया कि यदि भारतीय बैंक ३ से ५ वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड जारी करें, तो उद्योग को मध्यमकालीन साख देने का अच्छा आधार तैयार हो सकता है।

यह योजना तब ही सफल हो सकती है जबकि सरकार ऐसी प्रशुल्क एवं आर्थिक नीतियाँ अपनाये जिनमें औद्योगिक संस्थाओं को विस्तार के लिए ऋण लेने और फिर बायद के अनुसार जल्दी लौटाने का प्रोत्साहन मिले। यह हर्ष का विषय है कि सरकार में कारपोरेशन में व्यावहारिक बैंकों का सहयोग लिया है, जिससे पक्षपात आदि की शिकायतें न उठें।

अल्पकालीन अर्थ प्रबन्धन—

व्यापारिक बैंक कम्पनियों की अल्पकालीन वित्त-आवश्यकताएँ एडवांस, ऋण ओवर ड्राफ्ट और कॅश क्रेडिट स्वीकृत करके तथा विलो ट्रेण्डिंग और अन्य व्यापारिक पत्रों को भुना कर पूर्ण करते हैं। कम्पनियों को बाहिये कि अपने बैंकर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करे। इसे टेक्नीकल भाषा में 'साख बनाना' (A Line of Credit) कहते हैं। Line of Credit का अर्थ है निर्धारित परिस्थितियों में बैंक से किसी विशेष संस्था को मिलने वाली साख की मात्रा। इस व्यवस्था के कारण ऋण मिलने में देर नहीं लगती। बैंक कभी भी ठहरी हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत ऋण देने में चूक नहीं करते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो ग्राहकों के असन्तुष्ट होने का भय रहता है। परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर साख व्यवस्था में संशोधन भी किया जा सकता है।

किसी विशेष व्यापारिक संस्था को किन्तु एडवांस दिया जा सकता है यह मुख्यतः बैंक की ऋण दान क्षमता पर निर्भर होता है। बैंक की ऋण दान क्षमता निम्न बातों द्वारा प्रभावित होती है —

(१) कानूनी आदेश—बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ में बैंकों के लिये ऋण सम्बन्धी कुछ विशेष आदेश दिये गये हैं, जिनका पालन करना बैंकों के लिये आवश्यक

है। ये आदेश विम्बन्धित है — बैंकिंग कम्पनी अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकती, अपने संचालकों को या उनके हित वाली फर्मों या कम्पनियों की असुरक्षित ऋण नहीं दे सकती, प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अपने समय और माँग दायित्वों का कम से कम २०% नगदी में, स्वर्ण या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना होगा। इन नूतनी आदेशों का लक्ष्य यह है कि बैंक तरसता का बहिर्दान करके अत्यधिक ऋण न दे द और माँग दायित्वों की पूर्ति के लिये उचित बोध रखने के लिये प्रेरित हो।

(२) वित्तीय सिद्धान्त—कानूनी आदेशों के अतिरिक्त बैंकों को वित्तीय सिद्धान्तों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे ऋणों का किसी एक उद्योग में देकर विभिन्न उद्योगों पर फैलाना, जोखिम का वितरण करना, ऋण की मियादों का क्रम ऐसा रखना कि नगद धन का नियमित प्रवाह बना रहे, उचित नगद अनुपात (Cash ratio) रखना आदि।

भारत में बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये अल्पकालीन ऋणों का अध्ययन करने से कई रोचक बातों पर प्रकाश पड़ता है :—

(१) कार्यशील पूँजी प्रदान करने के सम्बन्ध में बैंकों का महत्त्व विभिन्न उद्योगों के लिये अलग-अलग है। हमारे बड़े पैमाने के व सुसंगठित उद्योगों की विक्षपत्, इंजीनियरिंग, कैंमीकल, फूट, काँटन टैक्सटाइल एवं सुगर उद्योगों को व्यापारिक बैंकों ने काफी आर्थिक सहायता दी है।

(२) लौह एवं स्पाइन तथा सीमेन्ट उद्योग बैंकों पर कम निर्भर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने व्यापक मात्रा में लाभों के अन्तर्विनियोजन की नीति अपनाई है। देखिये तालिका)

बैंकों द्वारा उद्योगों की कार्यशील पूँजी में भाग

उद्योग	कार्यशील पूँजी (करोड़ रु०)	बैंक का एडवांस (करोड़ रु०)	कार्यशील पूँजी से एड- वांस का अनुपात
सूती वस्त्र	१५७४	६१०	३८.७
फूट	३३६	१३.४	३.६५
लौह एवं स्पाइन	३४३	५.६	१.७०६
इंजीनियरिंग	३६३	२२.३	५.६७
सीमेन्ट	८.८	१.२	१.०६
सुगर	४६.६	१३.५	२८.६
कैंमीकल्स	२४४	६.२	३७.७

(३) सन् १९१७ में बैंकों की कुल दत्त पूँजी कोष का कुल डिपॉजिटों से अनुपात केवल ६ था, जिसमें सातुम होता है कि बैंकों के पास निजी साधन बहुत थोड़े थे।

(४) चूँकि १०% डिपॉजिट 'मॉर डिपॉजिट' है, इसलिए वे दीर्घकालीन विनियोग करने की स्थिति में नहीं हैं।

- (५) कुल विनियोगों का कुल डिपाजिटों में अनुपात ३॥ था तथा लगभग नारी रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित थी ।
- (६) बैंकों का बैंक अनुपात मन् १९४६ में १४३ में घट कर मन् १९५७ में केवल ८ रह गया है ।
- (७) एडवांन्स की राशि कुल डिपाजिटों की ६३% है ।

बैंकिंग कम्पनियों की पूँजी, डिपाजिट, विनियोग आदि के महत्त्वपूर्ण अनुपात (१९५७)

क्रम संख्या	शीर्षक	अनुपात
१.	कुल पूँजी व फोण का डिपाजिटों में अनुपात	६
२.	रिजर्वों का दत्त पूँजी में अनुपात	८३
३.	माँग डिपाजिट का कुल डिपाजिटों से अनुपात	५०
४.	समय डिपाजिटों का कुल डिपाजिटों से अनुपात	५०
५.	कैश बैलेन्सेज का कुल डिपाजिटों से अनुपात	=
६.	सरकारी प्रतिभूतियों वाल विनियोगों का कुल डिपाजिटों से अनुपात	३३
७.	कुल विनियोगों का कुल डिपाजिटों में अनुपात	६३
८.	एडवांन्स का कुल डिपाजिटों में अनुपात	३७

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमें चाहिए कि उद्योगों को मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं के बढ़ाने का प्रयास करे । प्रथम, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करना चाहिये । दूसरे, बैंक अनुपात को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है, यद्यपि उसे अत्र और घटाना जोखिमपूर्ण ही है । तीसरे, विद्यमान बैंकों के साधनों को बढ़ाया जाय ।

सराफ कमेटी की सिफारिशें—

सराफ कमेटी ने बैंकों के प्रसाधनों में वृद्धि करने और प्राइवेट सेक्टर के लिए अधिक वित्त उपलब्ध करने की समस्या पर विचार किया तथा निम्न सुझाव दिये—

(1) बैंकिंग प्रणाली का विकास करने के सुझाव—

बैंकिंग प्रणाली के विकास के लिए कमेटी ने निम्न सुझाव दिये थे —

(१) बैंकिंग आदत को प्रोत्साहन—भारत में प्रति व्यक्ति औसत डिपाजिट २५ रु० है, जबकि ब्रिटेन में १,६३६ रु० और अमेरिका में ४,४६३ रु० है । चलन से बैंक डिपाजिटों का अनुपात भारत में ७६ है, जबकि ब्रिटेन में ४२५, कनाडा में ५७६, अमेरिका में ५१७ और जापान में ३६३ । इन आँकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में बैंकिंग-आदत का विकास अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हुआ है । इसकी उन्नति के लिए कमेटी ने उन बाधाओं को हटाने पर जोर दिया जो कि भारत में बैंकिंग की प्रगति को रोकती हैं । बैंक में जन-विवश्राम बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने पर भी कमेटी ने बल दिया ।

बैंकिंग को अधिक प्रगति के लिए
सराफ कमेटी के सुझाव

(I) बैंकिंग प्रणाली का विकास—

१ बैंकिंग आदत को प्रोत्साहन ।

२ बैंका के परिचालन व्यय में कमी ।

३ औद्योगिक ट्रिब्यूनलों के अवाड में सरोधन ।

४ आयकर एवं बिक्रीकर विभागों की जांच पड़ताल ।

५ शाखाओं का नियोजित विस्तार ।

६ परास्ति सुरक्षा प्रबंध ।

७ चल बैंकों की व्यवस्था ।

(II) बैंकों के साधनों में वृद्धि

१ सामाजिक क्षेत्र से प्रतियोगिता का नियमन ।

२ द्रव्य हस्तान्तरण की सुविधा ।

३ डिपॉजिट बैंकिंग का नियमन ।

४ डिपॉजिट बीमा ।

५ स्थानीय समस्याओं से डिपॉजिट मिलना ।

६ सरकार से सुरक्षित भुगतान की सुविधा ।

(२) बैंकों के परिचालन व्ययों में कमी—बैंकों के परिचालन व्यय (Operating costs) अधिक होने से आधुनिक वर्षों में बैंकिंग के विकास को विशेषतः ग्रहण शहरी क्षेत्रों में बड़ी ठस पहुँची है। सन् १९४८ में १९४२ तक का अवधि में डिपॉजिटों से स्थापन व्यय (Establishment cost) का अनुपात में ६५% वृद्धि हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि बैंकों को कमचारियों के वेतन के सम्बन्ध में औद्योगिक ट्रिब्यूनलों के अवाड को सार्यान्विन करना पड़ा। जब तक परिवारन व्ययों में मितव्ययता नहीं होगा तब तक कोई बैंकिंग विकास सम्भव नहीं है। अतः बैंकों के परिचालन व्यय में कमी लाने का प्रत्येक उचित प्रयास करना चाहिए।

(३) औद्योगिक ट्रिब्यूनलों के अवाड में सरोधन—कुत्र बानों में औद्योगिक ट्रिब्यूनलों के अवाड बैंकों के लिए हानि व प्रमाणित हुए हैं, जैसे—
(1) बैंक कमचारियों में अनुशासन की कमी हो गई है, जिससे काम की प्रकृति सलता वृद्धियाँ थोड़ा घड़ी व जनता के प्रति सेवा स्तर में भी कमी आ गई है। (11) बैंकों के कार्यशील घट कम

हो गए हैं, जिससे बैंकों के मुनाफे की सुविधाय घट गई है तथा व्यापारी समाज को कठिनाइयाँ होनी हैं। (111) ग्रामीण क्षेत्रों को भी अवाड लागू होने से गाँवों में बैंकिंग के विकास में बाधा पड़ी है। कमेटी ने इन दोषों के लिए तत्कालिक कदम उठाने पर बल दिया। उसने एक विशेषज्ञ कमेटी की नियुक्ति का सुझाव दिया, जो बतन क्रमों के विवेकीकरण तथा परिचालन व्ययों में कमी करने के उपाय सुझावे।

(४) ग्राय कर एवं विक्री कर विभागों की पूछताछ सम्बन्धी जांच पड़तालें— श्री ग्राहक के मध्य गोपनीयता का नाता है। ग्राहक आगा करते हैं कि बैंक की ग्राहिक दशा सम्बन्धी बातों का गुन रहेगा। लेकिन आजकल ग्राय कर एवं वी कर विभाग व्यापारियों के द्वार में बैंक का बड़ी पूछताछ करने लग हैं। इन रसिदों तथा मध्य पारिया व अन्य चीजों में शका पैदा हो गई है। अतः वे बैंक में गया रखने के बजाय अपनी वचन करे-सी नाटो और घातु के रूप में अपने ही पास दना इच्छित समझने लग हैं। निमन्देह वरों ने वचन की प्रवृत्ति बहुत प्रमामाजिक। फिर भी बैंक और ग्राहक के सम्बन्ध की गोपनीयता को बनाय रखने के लिये सम्भव प्रयास करना चाहिये और वैकिंग घादन से बचावा देना चाहिये।

(५) शाखाओं का नियोजित विस्तार—गत कुछ वर्षों में बैंकों के शाखा-पालियों की संख्या में कुछ कमी हो गई है। अतः इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता। अखिल भारतीय ग्रामीण जांच सर्वे की सिफारिश के अनुसार स्टेट बैंक की स्थापना गई है और उसने अपने ज़िम्मे डाले गये ६०० शाखाएँ खोलने का कार्य भी शुरु कर लिया है। किन्तु यह भी आवश्यक है कि अन्य व्यापारिक बैंकों को भी अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिये प्रेरित करना चाहिये। सराफ कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि भारत सरकार में परामर्श करके रिजर्व बैंक को सार्वजनिक प्रात अनुमोचित बैंकों को वित्तीय सहायता देने की एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए और इन बैंकों में यह कहा जाय कि वे एक विशेष योजना के अनुसार, जिस पर पटन रिजर्व बैंक की अनुमति ले ली जाय, शाखा विस्तार करें।

(६) सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था—सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि ट्रेजरी एव मंत्र ट्रेजरीयों द्वारा बैंकों को सुरक्षित क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा-सुविधाय प्रदान की जायें।

(७) चल बैंक - छोटे-छोटे गाँवों में बैंकिंग की आदतों का विकास करने के लिये चल बैंक (Mobile Bank) बहुत उपयोगी हो सकते हैं। सरकार एवं जनता दोनों को ही इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये।

(II) बैंकों के साधनों में वृद्धि -

बैंकों के साधनों में वृद्धि करने के लिये कमेटी के निम्न सुझाव हैं—

(१) सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का नियन्त्रण—द्रव्य बाजार में उपलब्ध सीमित साधनों के लिये केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों, व विभिन्न सरकारी एजन्सियों (जैसे डाकखाना) द्वारा तीव्र प्रतिस्पर्धा की जा रही है, जिसमें बैंकों के डिपॉजिटों में कमी आ गई है। यद्यपि मिश्रित अवस्था में कुछ सीमा तक सरकार व प्राइवेट एजन्सियों में प्रतिस्पर्धा होनी स्वाभाविक है, किन्तु इसमें प्राइवेट क्षेत्र के लिये वित्त का अकाल नहीं पड़ने देना चाहिये।

(२) द्रव्य हस्तांतरण की सुविधायें—द्रव्य व हस्तांतरण की अपर्याप्त सुविधायों के कारण हमारे बैंकों को अपनी ग्राहकों के पास अधिक मात्रा में कैश व बैंक

बैलेन्स रखने पड़ते हैं, जो उनकी व्यापारिक आवश्यकताओं से अधिक होते हैं। यही नहीं, उन्हें अपना काफी धन सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना पड़ता है, ताकि स्टेट बैंक से लिये गये ओवरड्राफ्ट का माँग करने पर तत्काल भुगतान करने की गारन्टी हो। यदि द्रव्य के हस्तांतरण की सुविधाओं में सुधार हो जाय, तो हमारे बैंकों की धन-दान शक्ति बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें अपने पास अथवा शाखाओं के पास अधिक कंश बैंक बैलेन्स न रखने पड़ा करेगा। इस सम्बन्ध में सराफ कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं :—(1) सवादवाहन के साधनों में सुधार, जैसे रिजर्व बैंक के कार्यालय व एजेंसियों के बीच टेलीग्रैफ़र एव विशेष तार सेवा की व्यवस्था, (11) बैंकों की शाखाओं से उनके प्रधान कार्यालयों व एजेंसियों पर टेलीग्राफ़िक ट्रान्सफर खरीदना। बैंक की प्रत्येक शाखा के लिये उचित सीमा निर्धारित की जा सकती है। (111) रिजर्व बैंक द्रव्य हस्तान्तरण सम्बन्धी सुविधाय देने की अपनी योजना को विस्तृत करें, ताकि बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं की और शाखाओं द्वारा अपने प्रधान कार्यालयों को द्रव्य भेजने की सुविधायें निशुल्क मिलने लगे। बैंकों को इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ समय-समय पर हो उन्हें दूर करने के लिये एक प्रतिनिधि कमेटी का गठन भी करना चाहिये।

(3) नियन्त्रित डिपाजिट बैंकिंग—बैंक दर में वृद्धि होने से डिपाजिटों पर व्याज-दरों में एक सामान्य वृद्धि हो गई है। विनियम बैंकों ने व्याज दर में वृद्धि करके अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी है, क्योंकि बैंक दर बढ़ जाने से लन्दन मुद्रा बाजार का आकर्षण उन्हें कम हो गया है। सराफ कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि बैंकों के हितों की रक्षार्थ एक अखिल भारतीय बैंक एसोसियेशन बनाना चाहिए।

(4) डिपाजिट बीमा—अमेरिका की भाँति भारत में भी डिपाजिटों की बीमा प्रणाली चालू करने की आवश्यकता है। इससे बैंकिंग प्रणाली में जनना का विश्वास बढ़ेगा। बैंक इस योजना को तो उचित बताते हैं, किन्तु इसके चालू करने में जो अधिक व्यय होगा उसके कारण सकोच करते हैं। अखिल भारतीय बैंकिंग जाँच कमेटी का मत था कि डिपाजिट बीमा की योजना को बैंकों का सघनन पूर्ण होने तक स्थगित रखा जाय। सराफ कमेटी ने एक डिपाजिट बीमा निगम स्थापित करने का सुझाव दिया।

(5) स्थानीय संस्थाओं से डिपाजिट लेना—भारत सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि कोई भी स्थानीय संस्था या अर्द्ध सरकारी संस्था व्यापारिक बैंकों के पास अपने कोष तब तक नहीं रख सकेगी जब तक कि वह व्यापारिक बैंक अपनी ही रकम की सरकारी प्रतिभूतियाँ जमानत के रूप में डिपाजिट न कराये। संभवतः यह प्रतिबन्ध इस कारण लगाया था कि कुछ बैंकों के फंस हो जाने से सरकारी विभागों को कुछ हानियाँ उठानी पड़ी थी। किन्तु अब समय बदल गया है। सरकार को चाहिए कि इस प्रतिबन्ध को ढीला कर दे। ऐसा करने से हमारे व्यापारिक बैंक के प्रसाधन बढ़ जायेंगे। सराफ कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति-प्राप्त बैंकों को ऐसे डिपाजिट लेने का अधिकार होना चाहिये।

(६) सरकार द्वारा तात्कालिक भुगतान—प्रायः देखा गया है कि सरकार ज। माल सप्लाई किया जाता है उसका बिलों का भुगतान होने में बहुत देर लगती जिससे फलस्वरूप लघु एवं मध्यम उद्योगों की काफी पूँजी अटक जाती है। अनुमान के अनुसार, एमोबिलिटीड चेम्बर आफ कामस एंव इन्डस्ट्रीज के कुछ सदस्यों सरकार की आग १-२५ कराड रुपया रुका हुआ था। यदि सरकार पर निकलने में सम्पूर्ण अदस्त धन का भरोसा कराया जाय तो बकाया राशि बहुत अधिक निवलेगी यदि सरकार अपने बिलों का भुगतान करने में जल्दी करे, तो उद्योगों की पूँजी अटक नहीं तथा बैंकों के डिपॉजिट पर भी सुप्रभाव होगा।

बैंकों के ऋणों की आधुनिक प्रवृत्तियाँ—

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में यह देखा गया कि बैंक की साख विस्तार होने के साथ साथ उद्योगों को मिलने वाली साख के अनुपात में वृद्धि हुई जबकि व्यापार, व्यक्तिगत एवं प्रोफेशनल तथा अन्य क्षेत्रों में साख का अनुपात का कम हो गया है। यदि हम यह स्मरण रखें कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में ही औद्योगीकरण पर बल दिया गया था, हम उक्त प्रवृत्ति स्वाभाविक ही प्रतीत हो सकती है। इस अवधि में उद्योगों का अधिक विकास होने से उनकी आवश्यकता भी बढ़ उठी है।

औद्योगिक साख में जो वृद्धि हुई है उसका लाभ सभी बड़े उद्योगों ने लिया है फिर भी सीमेंट लौह एवं स्पात और इंजीनियरिंग उद्योगों को अधिक साख दी गई क्योंकि इनको द्वितीय योजना के अन्तर्गत एक विशेष भूमिका अदा करनी थी। पुराने उद्योगों जैसे सूती वस्त्रों को भी ऋण की मात्रा बढ़ी, किन्तु इसकी गति धीरी थी। लौह एवं स्पात तथा इंजीनियरिंग उद्योगों की साख के अनुपात में सा अधिक वृद्धि हुई। उद्योगों की कुल साख का अनुपात ३४ से बढ़ कर ४५% हो गया जब कि व्यापार आदि का अनुपात ४६ से घटकर ४२ रह गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट प्रगट होता है कि व्यापारिक वक उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पटल की अपेक्षा अधिक तत्पर है।

तृतीय पंच-वर्षीय योजना-अवधि में बैंकिंग प्रणाली का सहान् दायित्व

बैंकों द्वारा शाखा विस्तार—एक सामयिक आवश्यकता—

तृतीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में ग्राइवेट सेक्टर में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना अवधि की अपेक्षा लगभग दो गुना विनियोज किया जायगा। अतः स्पष्ट है कि बैंकिंग प्रणाली पर कायशील पूँजी की पूर्ति के लिये भारी माँग होगी। साथ ही उसमें यह भी आशा की जायगी कि अल्पकालीन पूँजी के अतिरिक्त वह मध्यकालीन कोषों की भी पर्याप्त पूर्ति करे। यही पर बैंकों के प्रसाधनों की पर्याप्तता का प्रश्न उठता है। इसका मुख्य हल यह है कि बैंक व्यापक पैमाने पर शाखाएँ खोलने में

नीति अपनाये । इसका फल यह होगा कि जिन स्थानों में अभी तक बैंकिंग सुविधायें न थी वहाँ वे अब उपलब्ध होने से डिपाजिट सुविधा द्वारा बचते गतिशील हो सकेंगी । अभी तक शाखा विस्तार की गति धीमी रही है । स्टेट बैंक के शाखा विस्तार के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक बैंकों को भी शाखा विस्तार का एक साहसिक कार्यक्रम अपनाना होगा । यह उनके लिये समभव भी है, क्योंकि उनके लाभों में आजकल वृद्धि हो रही है । यदि प्रारम्भिक वर्षों में शाखा-विस्तार से उन्हें कुछ हानि भी उठानी पड़ती है, तो उसकी पूर्ति कालान्तर में शाखाओं के कार्य की मात्रा बढ़ जाने से हो आयेगी ।

बैंकों की सामान्य वित्तीय दशा में सुधार करना जरूरी है—

नये और अर्द्ध विकसित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें बढ़ाने के अतिरिक्त बैंकों की सामान्य वित्तीय दशा में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है । रिजर्व बैंक ने निरीक्षण की जो व्यवस्था लागू की है उसमें काफी सुधार हुआ है । किन्तु बैंकों के कार्यवाहन में अब भी सुधार करने के लिये क्षेत्र है । अधिकांश बैंकों की यह कठिनाई है कि उनको पर्याप्त बिजनेस नहीं मिलता । जहाँ तक हम दुर्बलता का प्रश्न है, छोटे-छोटे बैंक अपेक्षाकृत बड़े-एव सुदृढ़ बैंकों के साथ विलीन होने की संभावनाओं पर विचार करें । यह न केवल उनके लिये वरन् देश के व्यापक हित के लिये भी उचित होगा । जो दुर्बलतायें सामयिक निरीक्षणों द्वारा उनके सामने लाई जायें व वित्तीय-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये जो सुझाव दिये जायें, उन पर उचित कार्यवाही करने से बैंकिंग प्रणाली में स्थायित्व व दृढ़ता आवेगी ।

कोषों की कमी का हल साख-नियंत्रण नहीं—

स्टेट बैंक के निर्माण एव बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण से प्राइवेट सेक्टर के हाथ से वित्तीय श्रोन का एक महत्त्वपूर्ण साधन निकल गया । अतः व्यापारिक बैंकों पर अब पहले से भी अधिक जिम्मेदारी आ गई है । उन पर ऋण लेने की जिननी भारी मांग की जाने लगी है उतनी वृद्धि उनके डिपाजिटों में नहीं हो पायी है । डिपाजिटों और एडवान्सों की इस अनमान दौड़ ने बैंकों के कार्यवाहन पर गम्भीर प्रभाव डाला है । डिपाजिट प्राप्त करने की होड़ में डिपाजिटों और ऋणों दोनों पर ही ब्याज दरें बढ़ गई हैं । चूँकि डिपाजिटों की मात्रा अपर्याप्त प्रमाणित हुई है, इसलिये वित्तियोगों और नगद कोष को कम करने की युक्तियाँ अपनाई गई हैं । यही नहीं, जब बैंक अपने डिपाजिटों से अनुपातातीत ऋण देने लगते हैं, तो उनकी तरलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है । लेकिन विकास की अवधि में साख का विस्तार होना अनिवार्य है तथा साख पर नियंत्रण लगाना ऐसे समय में भलाई के बजाय हानि अधिक पहुँचा सकता है । अतः कोषों की कमी का हल साख नियंत्रण में नहीं है, वरन् उचित आवश्यकता पूर्ति के लिये अधिक सावा में देने में निहित है ।

बैंकिंग प्रणाली के भावी विकास के सम्बन्ध में कुछ सुझाव—

बैंकिंग प्रणाली का भावी स्वरूप क्या होगा, इस सम्बन्ध में बहुत मोच विचार की आवश्यकता है। भारतीय बैंक एसोसियेशन के सहयोग से एक विस्तृत योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य व्यापारिक बैंकों का विकास करने के साथ-साथ उनका विवेकीकरण करना भी है, ताकि उनके हानिप्रद कार्यों पर रोक लगे। सराफ बमेटी में घेड़ू डिपाजिटों का बीमा कराने का प्रस्ताव रखा था। इससे डिपाजिट बैंकिंग की उन्नति हो सकेगी। बैंकों के कार्यवाहन में कुशलता की वृद्धि के लिए एप बैंकिंग सेवा (Banking Service Cadre) स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें विदेश के अन्य देशों में बैंकों की आधुनिक प्रवृत्तियों की जानकारी होगी और जो देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रवृत्तियों को अपनायेगी। इस बात की भी आवश्यकता है कि विभिन्न व्यापारिक बैंकों में आपस में तथा व्यापारिक बैंकों और अन्य बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं (जैसे सहकारी बैंक व स्टेट बैंक) में समन्वय हो। बड़ा अनुसूचित बैंकों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वे ग्रैंड-सर्वजनिक संस्थाओं को बैंकिंग सुविधायें प्रदान करें जिससे उनके कोषों की वृद्धि हो। व्यापारिक बैंकों को इस योग्य बनाना चाहिये कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा कार्यालय खोल कर वहाँ की बचत को गतिशील बनाये। इसके लिये यह जरूरी है कि उनको स्टाफ के वेतन सम्बन्धी बैंक अवाढ के नियमों से कुछ छूट दी जाय।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss the importance of Industrial Banks in India. Why did the earlier industrial banks fail?
2. How far can the commercial banks be of use in providing long term finance to industries? Give your suggestions for increasing their participation in long term financing of Indian industry.
3. Write a note on Refinance Corporation of India.
4. How do the Commercial banks meet the short term requirements of companies? Give the recommendations of the Shroff Committee to expand the resources of banks and make more finance available to the private sector.
5. Analyse the recent trends in bank advances, and outline the task before the banking system in the coming years.

अध्याय ३६

औद्योगिक अर्थ-निगम

(Industrial Finance Corporation)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—

भारत में औद्योगिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं का अभाव बहुत दिनों से रहा है। इस अभाव का अनुभव सबसे पहले सन् १९१८ के औद्योगिक आयोग ने किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में देश के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया था। तत्पश्चात् सन् १९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी देश में बढ़ते हुए औद्योगीकरण के लिए पूंजी की आवश्यकता पर अधिक बल दिया। किन्तु दुर्भाग्यवश भयवा यो कहे कि विदेशी शासन की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण उन प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त, सन् १९४५ में भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रलेख में इस बात का संकेत किया था कि औद्योगिक विनियोग निगमों की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कुछ समय बाद इस पर विचार विमर्श हेतु वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से परामर्श मांगा। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक मिल बनाया, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख सुविधाएँ प्रदान करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) की स्थापना के लिए सुझाव दिया। यह बिल पहले विधान सभा में सन् १९४६ के बजट अधिवेशन में सर आर्चीडेल रोलेन्डस ((Sir Archibald Rowland) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला था, परन्तु अन्य विधान सम्बन्धी अविवेकता के कारण ऐसा सम्भव न हो सका। कुछ समय बाद माननीय आर० के० शर्मा मुखर्जी ने भारतीय ससद में कुछ संशोधन करके औद्योगिक अर्थ निगम की स्थापना सम्बन्धी बिल को प्रस्तुत किया। २४ मार्च सन् १९४८ को गवर्नर जनरल से इस बिल पर स्वीकृति मिली और एक जुलाई सन् १९४८ से इस निगम का कार्य प्रारम्भ हुआ।

निगम के उद्देश्य—

निगम का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को दीर्घ एवं मध्यकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हमारे देश के अधिकांश भी इस प्रकार की सहायता प्रदान करते

है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि निगम अधिकोषो से प्रतियोगिता करना चाहता है अथवा उनको इस कार्य से विचलित करना चाहता है। निगम का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में अधिकोषो की सहायता करना है, जिससे ये दोनों संस्थाएँ मिलकर देश में पूँजी की कमी को दूर कर उद्योगों की उन्नति में सहायक हों। अधिकोषो का मुख्य कार्य तो उद्योग को अल्पकालीन सहायता और निगम का कार्य लम्बी अवधि के लिए या मध्यम समय के लिए आर्थिक सहायता देना है। विवास का अर्थ केवल नवीन उद्योगशालाएँ खोलना नहीं है। नई उद्योगशालाओं के स्थापन के साथ-साथ प्राज भारत में चालू उद्योगों के पुनर्संगत विवेकीकरण की आवश्यकता भी है। औद्योगिक संस्थाओं की प्राप्त पूँजी का लगभग सारा भाग मशीन, भूमि व अन्य औजारों के खरीदने में ही चला जाता है और समय पर कार्यशील पूँजी की बड़ी भारी कमी पड़ जाती है, जिसका परिणाम उद्योग की सफलता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए निगम का प्रधान उद्देश्य चालू व नवीन सार्वजनिक कम्पनियों को अल्पकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना है। किन्तु वे उद्योग जो बुनियादी उद्योगों की श्रेणी में हैं अथवा जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, इस साख-सहायता के भागीदार नहीं बन सकते। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि निगम केवल उन्हीं उद्योगों को आर्थिक सहायता देगा, जो सार्वजनिक अथवा लोक सीमित होंगे अथवा जो सहकारिता के सिद्धान्तानुसार कार्य कर रहे हैं। यह आर्थिक सहायता केवल उन क्षेत्रों तक सीमित रहेगी, जिनमें औद्योगिक अर्थ निगम लागू होता है, यतएव स्पष्ट है कि अलोक सीमित प्रमण्डल तथा सांकेदारी की संस्थाएँ निगम द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ न उठा सकेंगी।

औद्योगिक अर्थ-निगम अधिनियम (I. F. C. Act) १९४८ का सबसे बड़ा दोष यह था कि निगम केवल उही औद्योगिक संस्थाओं को ऋण दे सकता था, जो पहले से ही व्यापार कर रही हों, अर्थात् यह उन सार्वजनिक को ऋण नहीं दे सकता था जो व्यापार प्रारम्भ करने वाले थे। इन दोषों को दूर करने के लिए अधिनियम में सन् १९५५ में कुछ संशोधन किए गए, जिनके अनुसार अब निगम नव निर्मित कम्पनियों को सहायता दे सकता है।

निगम के कार्य—

औद्योगिक अर्थ निगम अधिनियम, १९४८ की धारा २३ के अनुसार, यह निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है :—

(१) गारन्टी देना—औद्योगिक संस्थाओं के ऋणों पर जिसे उन्होंने सार्वजनिक बाजार से लिया है और जिसके अग्रत न की अवधि अधिक से अधिक २५ वर्ष है, गारन्टी दे सकता है।

(२) अभिगोपन करना—औद्योगिक संस्थाओं द्वारा निगमित स्टाक, बॉन्ड या ऋण पत्रों का अभिगोपन करना, यदि इन प्रतिभूतियों का विव्रय सात वर्ष की अवधि के भीतर कर दिया जाता है।

(३) ऋण व अग्रिम देना—औद्योगिक मस्याओं को अधिक से अधिक २५ वर्ष की अवधि के लिए ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना और उसके द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों को (जिनकी अवधि २५ वर्ष से अधिक नहीं है) क्रय करना ।

वर्जित कार्य—

अधिनियम के अनुसार औद्योगिक अर्थ निगम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है :—

- (१) अधिनियम की शर्तों के विरुद्ध जमा (Deposits) स्वीकार करना ।
- (II) किसी भी सीमित दायित्व वाले अंतो अथवा स्टॉक को प्रदर्श रूप से क्रय करना ,
- (III) सात वर्ष की अवधि के अंतो अथवा ऋण पत्रों का अभिगोपन करना ,
- (IV) एक करोड़ से अधिक का ऋण देना ।

ऋण देने में सावधानी—

(१) निगम उस समय तक किसी भी ऋण की स्वीकृति अथवा अभिगोपन नहीं करता है जब तक कि उस पर प्रत्याभूति न हो ।

(२) किसी भी एक औद्योगिक सार्थ को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि ५० लाख रुपये में सन् १९५२ में एक करोड़ रुपये कर दो गई है । एक करोड़ से अधिक का ऋण बवल उसी दशा में दिया जाता है जब कि भारत सरकार ने उस पर गारंटी दी हो ।

(३) यदि ऋण लेने वाली कम्पनी ऋण का भुगतान करने में अथवा निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन करने में कोई त्रुटि करती है, तो नियम को कम्पनी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने, उस कम्पनी की संचालन सभा में संचालक नियुक्त करने अथवा उसके प्रबन्ध की अपने हाथ में लेने का अधिकार है । निगम को ऐसी ऋण लेने वाली कम्पनियों से भुगतान की तिथि से पूर्व भी भुगतान मागने का अधिकार प्राप्त है ।

ऋण देने की शर्तें—

अपने उद्देश्यानुसार अर्थ निगम किसी सीमित पब्लिक कम्पनी तथा सहकारी समिति को निम्न शर्तों पर ऋण दे सकता है :—

(१) ऋण मुख्यतः स्थायी एवं अचल सम्पत्ति खरीदने के लिये अचल सम्पत्ति, जैसे—भू-शुद्धि, यन्त्र औजार आदि, की प्रथम रहन (First Mortgage) पर दिया जाता है । यह कम्पनी कार्यशील पूँजी के लिए कच्चे-पक्के माल के आधोन ऋण न देगी, क्योंकि यह काम व्यापारिक बैंकों का है । अर्थ निगम उनके साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहता ।

(२) दिये हुए ऋण का समुचित प्रबन्ध एक ध्येय हो रहा है या नहीं, इस बात को निश्चित करने के लिये ऋण लेने वाली कम्पनी के सचालका से उनकी व्यक्तिगत स्थिति में वैयक्तिक तथा सामूहिक जमानत ली जाती है, जिसमें उद्योग का प्रबन्ध समुचित रीति से हो सके ।

(३) अर्थ निगम को उद्योग की सचालक समा में दो सचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार है, जिससे वे सचालक उद्योग के प्रबन्ध का निरीक्षण करते हैं तथा यह भी देखते हैं कि उसका प्रबन्ध अर्थ निगम के हित में हो रहा या नहीं ।

(४) औद्योगिक कम्पनी को उद्घाटनश्रीस वर्षों में होने वाला लाभ लाभांश देने में ही न बाँटा जाय, इसलिए जब तक ऋण का भुगतान न हो तब तक वह उद्योग ६०% से अधिक लाभांश न दे सकेगा । हाँ, दोनों की सहमति से इस दर में परिवर्तन सम्भव है ।

(५) ऋण भुगतान की अवधि साधारणतः १२ वर्ष है, परन्तु अभी तक जो अधिकतम अवधि दी गई है वह १५ वर्ष है । इस शर्त के अतिरिक्त ऋण भुगतान की अवधि ऋण लेने वाली कम्पनी के व्यापारिक स्वरूप और उसके भविष्य के अनुसार निश्चित की जाती है ।

(६) ऋण का भुगतान सामान्यतः समान प्रभागों (Equal Installments) में होना चाहिये, परन्तु ये प्रभाग कितने होंगे, यह दोनों की सहमति से निश्चित होता है ।

(७) अर्थ निगम के पास रहन रखी हुई सम्पत्ति का भाग, साम्प्रदायिक कलह, विद्रोह आदि की सुरक्षा के लिये किसी अच्छे बीमा प्रमण्डल से बीमा कराना अनिवार्य है ।

(८) जब उद्योग को ऋण दे दिया जाता है तो उसका उपयोग जिस कार्य के लिये ऋण लिया गया है उसी कार्य के लिये हो रहा है अथवा नहीं, यह देखने के लिये अर्थ निगम आवश्यक कदम उठाता है ।

निगम का प्रबन्ध—

निगम का प्रबन्ध एक सचालक समिति द्वारा होता है, जिसकी सहायता के लिये एक केन्द्रीय समिति और एक जनरल मैनजर भी होता है । सचालक समिति में चेयरमैन सहित कुल १३ सदस्य हैं । ये सदस्य निम्नलिखित पद्धति से निर्वाचित अथवा मनोनीत होते हैं :—

औद्योगिक वित्त निगम की संचालक समिति (३० जून, १९६० को)

क्रम संख्या	नाम	पदवि
१.	श्री के० आर० के० मैनन	चेयरमैन
२.	श्री एस० सी० राय	बोमा कम्पनियो, विनियोग प्रग्यासो तथा प्रय वित्तीय संस्थाओ द्वारा निर्वाचित
३.	श्री सी० सी० देसाई	
४.	श्री बी० पी० वादे	
५.	श्री आर० एम० देवमुख	सहकारी संस्थाओ द्वारा निर्वाचित
६.	श्री एस० बी० राममूर्ती	
७.	श्री एम० सी० मुथिया	ग्रनुसूचित बंको द्वारा निर्वाचित
८.	श्री डा० बी० के० मदन	
९.	श्री एस० पी० वीरमणी	रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मनोनीत
१०.	श्री जी० डी० अम्बेकर	
११.	प्रो० एस० के वसु	केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत
१२.	श्री रगनाथन	
१३.	श्री ए० बक्शी	

३० जून सन् १९६० को निगम की केन्द्रीय समिति में नीचे दिये हुए पाच
व्यक्ति थे :—

क्रम संख्या	नाम	निर्वाचन पद्धति
१.	श्री के० आर० के० मैनन	चेयरमैन
२.	श्री एस० सी० राय	निर्वाचन मंचालको द्वारा निर्वाचित
३.	श्री एम० सी० मुथिया	
४.	श्री एस० पी० वीरमणी	मनोनीत संचालको द्वारा निर्वाचित
५.	रित्त	

माजकल निगम के जनरल मैनेजर है श्री एच० बी० वेन्कटा मुन्निय्या । श्री डी०
आर० मंडोक इसके सेक्रेटरी हैं । श्री ज्वालाप्रसाद चोपडा इसके वैधानिक सलाहकार
एव रिजर्व बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इनके बैंकर्स है ।

निगम का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में एव शाखा कार्यालय बम्बई, कलकत्ता
व मद्रास में है । औद्योगिक अर्थ नियम अधिनियम संचालक-सभा के सदस्यों से यह
आशा करता है कि वे उद्योग, व्यापार व जनहित के सिद्धान्तों को सामने रखते हुये
व्यापारिक सिद्धान्तों का पालन करेंगे । यदि संचालक समिति उचित समझे, तो विभिन्न
बातों के विचारार्थ सलाहकार समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं । निगम की सामान्य
नीति का संचालन केन्द्रीय सरकार करेगी ।

निगम की पूँजी का कलेवर—

(अ) ग्रश पूँजी—निगम की अधिकृत पूँजी १० करोड़ रुपये है, जो ५,००० रु० के २०,००० अंशों में विभाजित है। अंशों की मूल राशि तथा २½% लाभांश की गारन्टी केन्द्रीय सरकार ने दी है। इस समय ५ करोड़ रुपये के मूल्य के केवल १० हजार अंशों का निर्गमन किया गया है और शेष अंशों का निर्गमन समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा। इन अंशों को क्रय करने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनी, विनियोग प्रत्यास तथा इसी प्रकार की वित्त संस्थाओं को है। अतएव यह स्पष्ट है कि निगम के अंश खरीदने व पूँजी में योग देने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। प्रारम्भ में इन संस्थाओं को एक निश्चित अनुपात में अंशों का आवंटन किया गया था, किन्तु कालान्तर में इस आवंटित संस्था में कुछ परिवर्तन हो गया है। इसका आभास निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :—

क्रमांक	संस्थाएँ	पूर्व निर्धारित अंशों की संख्या	क्रय किए गए अंशों की संख्या	धन राशि (रुपये)
१	केन्द्रीय सरकार	२,०००	२,०००	१,००,००,०००
२	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	२,०००	२,०५४	१,०२,७०,०००
३	अनुसूचित बैंक	२,५००	२,४०५	१,२६,६०,०००
४	बीमा कम्पनी, विनियोग प्रत्यास	२,५००	२,५६८	१,२६,६०,०००
५	ग्रन्थ वित्तीय संस्थाएँ			
	सहकारी संस्थाएँ	१,०००	६४३	४७,१५,०००
	योग	१०,०००	१०,०००	५,००,००,०००

(ब) ऋण पत्र पूँजी—निगम ऋण पत्रों का निर्गमन करके तथा बाइंड का विक्रय करके वार्षिकी पूँजी प्राप्त कर सकता है परन्तु ऋण पत्रों, बाइंड तथा

इसी प्रकार से प्राप्त की हुई पूँजी निगम की शुद्धता पूँजी तथा सचिव कोष के पांच गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(स) रिजर्व बैंक से ऋण—निगम केन्द्रीय सरकार को प्रतिभूतियों के विह्वल ६० दिन की अवधि के लिये रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकती है । धारा २१ (३) (ब) के अन्तर्गत निगम अपने ऋण-पत्रों का प्रतिभूति के आधार पर अधिक से अधिक ३ करोड़ ६० का धन १८ माह की अवधि के लिये उधार ले सकता है ।

(द) जमा—निगम जनता से कम से कम पाब वर्ष के लिए तथा अधिक से अधिक १० करोड़ ६० की धन राशि तक जमा स्वीकार कर सकता है ।

(य) विदेशी मुद्रा में ऋण—सन् १९५६ के संशोधित अधिनियम के अनुसार निगम विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकता है और भारतीय सरकार ऐसे ऋणों पर गारन्टी देगी ।

(र) केन्द्रीय सरकार से ऋण—सन् १९५२ के संशोधित अधिनियम के अनुसार निगम केन्द्रीय सरकार से ऋण ले सकती है ।

निगम की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिये एक विशेष सचय कोष स्थापित किया गया है । इस कोष में केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के आदेशों पर प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण लाभों उस समय तक जमा किये जायेंगे जब तक कि इसकी राशि ५० लाख रुपये न हो जाय ।

लाभ का वितरण—

निगम के नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निगम एक बचत कोष रखेगा । सन्निवृत्ति के लिये, सम्पत्ति का मूल्य ह्रास तथा इस प्रकार के अन्य व्यापारिक घाटों के लिए आयोजन करने के उपरान्त, यदि कुछ लाभ शेष बचे, तो निगम उसे आशोधितियों में बाँट देगा । किन्तु इस लाभ की दर उन समय तक सरकारी गारन्टी से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि उक्त बचत कोष का धन निगम की प्राप्त पूँजी के बराबर न हो जाय ।

निगम की कार्य विधि—

निगम द्वारा किसी भी औद्योगिक संस्था को ऋण प्रदान करने की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है :—

(१) ऋण लेने वाली कम्पनी की प्रकृति, माल आदि की जाँच—
निगम किसी भी उद्योग को ऋण देने के पूर्व, ऋण लेने वाली कम्पनी से निमित्त किये

जाने वाले माल की प्रकृति, कारखाने की स्थिति का स्थापन (Location), भूमि पर अधिकार, भवन, विद्युत शक्ति की उपलब्धता, तान्त्रिक स्टाफ, बाजार की स्थिति, उत्पादन की अनुमानित लागत, मशीनों की किस्मे, दी जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य, सहायता लेने का उद्देश्य तथा लाभ कमाने व ऋण चुकाने की क्षमता, आदि के विषय में सूचना प्राप्त कर लेता है।

(२) निगम के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण—सत्परचास् निगम के अधिकारियों द्वारा ऋण लेने वाली कम्पनी का निरीक्षण किया जाता है। वे निगम की कम्पनी का लेखा (A/c Books), सम्पत्ति की वास्तविक स्थिति, प्रबन्ध की कार्यक्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता तथा निर्मित माल के बाजार की स्थिति के विषय में सूचना देते हैं। औद्योगिक संस्थाएँ अपने कुशल तान्त्रिक पदाधिकारियों को इस विषय में वार्तालाप के हेतु भेज सकती हैं।

(३) सामयिक रिपोर्ट—निगम, ऋण लेने वाली संस्थाओं से सामयिक रिपोर्ट भी माँगती है, जिससे कि ऋण के सदुपयोग के विषय में उसे जानकारी रहे।

(४) ऋण देते समय स्मरणीय घटक—ऋण प्रदान करते समय निगम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है —

- (1) उद्योग का राष्ट्रीय महत्व,
- (II) उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की देश में मांग,
- (III) तान्त्रिक व्यक्तियों एवं कच्चे माल की उपलब्धता,
- (IV) प्रबन्ध की योग्यता,
- (V) दी गई प्रतिभूति की प्रकृति;
- (VI) निर्मित वस्तुओं के गुण, और
- (VII) प्रस्तावित योजना की सम्भावना तथा लागत।

निगम द्वारा किए गए कामों का व्यौरा—

औद्योगिक अर्थ निगम ने ३० जून सन् १९६० को १२ वर्ष पूर्ण किए और इन १२ वर्षों में निगम ने अनेक प्रकार की औद्योगिक संस्थाओं को ऋण दिए हैं। निगम के पास इन १२ वर्षों में जितने आवेदन पत्र आए एवं जिन्हें ऋण स्वीकृत किए गए तथा जिन आवेदनपत्रों को अस्वीकार किया गया, उनका व्यौरा इस प्रकार है :—

तालिका १

(हजार रुपये में)

क्रमांक	विवरण	सख्या	३० जून सन् १९५७ लक	सख्या	३० जून सन् १९५८ लक	सख्या	३० जून सन् १९५९ लक	सख्या	३० जून सन् १९६० लक
१.	प्राप्त भावेदन पत्र	६७	२१,३६,३५	४८	१४,८८,५०	२६	११,१६,५७	३८	१७,५२,१०
२.	स्वीकृत भावेदन पत्र	५१	११,६०,७५	२३	७,७८,५०	१९	३,७९,००	२९	१७,६१,७४
३.	मुग्तान किये गये ऋण	—	६,७७,५०	—	८,३३,३५	—	७,४७,७१	—	८,४०,८१
४.	अस्वीकृत प्रार्थना-पत्र	१४	४,८७,५०	१	१०,००	३	३१,५०	१	४०,००
५.	वापिस लिए हुए अथवा संप्रद (Ispeed) प्रार्थना-पत्र	१०	२,७३,१०	१०	२,११,५०	२२	६,७९,५०	६	८,५०,००
६.	वर्ष के अन्त में विचाराधीन प्रार्थना-पत्र	२६	११,३७,००	४१	१२,६८,५०	२३	११,७०,६७	२५	७,८८,१०

३० जून सन् १९६० तक निगम ने ८४'६१ करोड़ रु० के कुल ऋण १८५ कम्पनियों को स्वीकृत किए और जिनमे से कुल ५०'७३ करोड़ रुपए वास्तव में वितरित कर दिए गए। इसका स्पष्टीकरण निम्न तालिका में हो जाता है :—

३० जून को अन्त होने वाला वर्ष	ऋण की कुल स्वीकृत धनराशि (करोड़ रु०)	वास्तव में दी गई धनराशि (करोड़ रु.)	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रार्थना पत्रों का संख्या
१९४९	३'४२	१'३३	६५	२१
१९५०	७'१९	३'४१	१६०	४६
१९५१	९'५८	५'७९	२०५	६१
१९५२	१४'०३	७'५७	२५९	९४
१९५३	१५'४७	१०'०७	३३३	१०८
१९५४	२०'७४	१२'८९	३७६	१३७
१९५५	२८'०८	१४'५३	४२२	१६४
१९५६	४३'२१	१६'७३	५०८	२०८
१९५७	५५'८२	२६'५१	५७१	२५९
१९५८	६२'९०	३४'८४	६२३	२८१
१९५९	६६'६९	४२'३२	६४९	३००
१९६०	८४'६१	५०'७३	९८७	३२९

स्थगित धुकारों की गारन्टी—

औद्योगिक अर्थ निगम (संशोधन) अधिनियम सन् १९५७ के अन्तर्गत निगम को स्थगित धुकारों (Deferred Payments) की गारन्टी करने का भी अधिकार मिल गया है। औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विदेशों से पूँजीकृत माल (Capital Goods) आयात करने के सम्बन्ध में जो स्थगित भुगतान थे, उनकी गारन्टी अर्थ निगम ने दी। इसका संक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है :—

तालिका २

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विवरण	संख्या	२१ जून सन् १९५७ से ३० जून सन् १९५८ तक	संख्या	३० जून सन् १९५८ तक	संख्या	३० जून सन् १९६० तक
१.	स्वमित्त भुगतान के हेतु गारंटी के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्र	६	५,२४,००,०००	११	१६,५०,८०,५००	५	३,७२,४५,०००
२.	स्वीकृत प्रार्थनापत्र	३	३,८६,००,०००	२	३५,००,०००	६	७,८७,०६,८००
३.	मस्वीकृत प्रार्थना पत्र	—	—	—	—	—	—
४.	वापिस ले लिये गये प्रार्थनापत्र	—	—	५	५,१४,१७,७००	३	३,४५,१७,०००
५.	विचाराधीन प्रार्थनापत्र	३	१,२८,००,०००	७	१२,२६,६२,८००	३	३,६२,१३,०००

गत वर्षों में अर्थ निगम द्वारा जो प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये गये उनकी अस्वीकृति के कारणों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार वर्गित किया जा सकता है :—

- (१) प्रार्थी द्वारा योजना का त्याग देना या स्थगित करना,
- (२) प्रार्थी द्वारा योजना में संशोधन करना,
- (३) प्रार्थी की आर्थिक स्थिति में सुधार,
- (४) अन्य स्रोतों से ऋण उपलब्ध हो जाना,
- (५) निगम की शर्तों को पूरी न कर पाना ।

औद्योगिक अर्थ निगम द्वारा गत १२ वर्षों में भारत के जिन विभिन्न उद्योगों को ऋण स्वीकार किये गये, उनका संक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है :—

उद्योगों का प्रकार	३० जून १९५६ तक स्वीकृत ऋण	३० जून १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	योग
	रु०	रु०	रु०
वस्त्र मशीनरी	८३,००,०००	—	८३,००,०००
मैकेनिकल इन्जीनियरिंग	२,२८,००,०००	६५,००,०००	३,२३,००,०००
एलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग	१,८१,७०,०००	१५,००,०००	१,९६,७०,०००
सूती वस्त्र	६,३७,७५,०००	२५,००,०००	६,६२,७५,०००
ऊनी वस्त्र	३५,००,०००	—	३५,००,०००
रेमन उद्योग	१,१०,००,०००	३,००,००,०००	४,१०,००,०००
रासायनिक	८,५३,२५,०००	८४,५०,०००	९,३७,७५,०००
सीमेन्ट	६,१७,००,०००	—	६,१७,००,०००
सेरेमिक व ग्लास	१,६१,७५,०००	६५,००,०००	२,८६,७५,०००
तेल मिल	११,००,०००	—	११,००,०००
विद्युत शक्ति	८२,७५,०००	—	८२,७५,०००
मेटलर्जिकल उद्योग	४५,५०,०००	६,००,०००	५१,५०,०००
लौह व स्पात	२,६०,५०,०००	३०,००,०००	२,९०,५०,०००
अल्यूमीनियम	५०,००,०००	८०,००,०००	१,३०,००,०००
बीनी उद्योग	२०,६२,००,०००	५,००,००,०००	२५,६२,००,०००
खनिज	३७,००,०००	—	३७,००,०००
कागज	५,७१,५०,०००	४,०२,२४,०००	९,७३,७४,०००
ग्रांटामोबायल व ट्रेक्टर	१,६४,५०,०००	६,००,०००	१,७३,५०,०००
प्लाईवुड	३०,००,०००	—	३०,००,०००
होटल उद्योग	—	१,५०,००,०००	१,५०,००,०००
अवर्गित	१,१६,८०,०००	—	१,१६,८०,०००
योग	६६,६६,००,०००	१७,६१,७४,०००	८४,६०,७४,०००

गत वर्ष अन्तरिम ऋण (Interim Loan) के प्रदान करने में भी निगम ने बड़ी नमी दिखलाई ।

औद्योगिक अर्थनिगम संशोधन अधिनियम सन् १९५३—

औद्योगिक अर्थनिगम का कार्यक्षेत्र तथा आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए उपर्युक्त अधिनियम बनाया गया, जिससे दीर्घकालीन ऋण देने में वह अधिक उपयोगी हो सके । इस संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत निगम को निम्नलिखित अधिकार मिल गए हैं :—

(१) औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा के अन्तर्गत जहाजी कंपनियों का भी समावेश होगा, जिन्हें अर्थनिगम ऋण दे सकेगा ।

(२) प्रत्येक उद्योग मण्डल को अर्थनिगम १ करोड़ रुपया अधिकतम ऋण दे सकेगा ।

(३) सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा भारतीय उद्योगों को जो ऋण दिए गए हैं, उनका निरीक्षण सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि के नाते अर्थनिगम स्वयं करेगा ।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से अर्थनिगम जो ऋण लेगा, उसकी जमानत भारत सरकार देगी तथा इस प्रकार के विनिमय व्यवहारों में निगम को जो हानि होगी उसकी क्षति पूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी ।

(५) केन्द्रीय सरकार की जमानत पर अर्थनिगम किसी एक उद्योग प्रमण्डल को एक करोड़ रुपये से अधिक ऋण दे सकेगा, परन्तु ऐसी जमानत के लिए अर्थनिगम द्वारा ऋण की स्वीकृति की सिफारिश आवश्यक है ।

(६) अर्थनिगम अपनी राशि रिजर्व बैंक की सलाह से किसी भी सूचीबद्ध बैंक अथवा प्रांतीय सहकारी बैंक के पास निक्षेप (Deposit) में रख सकेगा । इस संशोधन में यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी राशि का विनियोग सरकारी प्रतिष्ठानों में ही करे । इसमें अर्थनिगम को ब्याज की हानि नहीं होगी ।

(७) अर्थनिगम अपनी कार्यशील पूँजी के लिए १८ माह से अधिकतम अवधि के लिए ३ करोड़ रुपये का ऋण दे सकेगा । इससे निगम को स्वीकार करते ही बच अवधि के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन की आवश्यकता नहीं रहेगी । जब तक अर्थनिगम का संचित कोष ५० लाख रुपये तक नहीं हो जाता, तब तक रिजर्व बैंक एवं केन्द्रीय सरकार को मिलने वाले लाभार्थ इसी में जमा होंगे ।

(८) किसी ऋण लेने वाले उद्योग का नियन्त्रण अर्थनिगम ले सकेगा । इस सम्बन्ध में ३० A से ३० E तक नई धाराएँ जोड़ दी गई हैं । इससे नियन्त्रित उद्योग में वह अपने संचालकों की नियुक्ति करेगा, जिसके बाद पूर्व संचालक अपना पद छोड़ देंगे । दूसरे, मैनेजिंग एजेंट्स का उद्योग प्रमण्डल के साथ जो अनुबन्ध होगा उसका बिना किसी क्षति पूर्ति के अन्त हो जायगा । तीसरे, अशुधारियों के मनोनीत संचालकों की नियुक्ति निरस्त होगी और बिना अर्थनिगम की अनुमति के अशुधारियों द्वारा

स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सकेगा। चौथे, ग्रथनिगम की अनुमति के बिना किसी उद्योग प्रमण्डल का समापन भी नहीं हो सकेगा।

(६) ग्रथनिगम की सचालक सभा पर केन्द्रीय सरकार के मनोनीत ४ सचालक होने तथा उप प्रबन्ध सचालक (Deputy Managing Director) सचालक सभा में बैठ सकेगा, किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा। इसी प्रकार प्रबन्ध सचालक को किसी भी समय निकाला जा सकता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में प्रबन्ध सचालक को स्पष्टीकरण करने के लिए समुचित अवसर दिया जायगा, किन्तु दो-तिहाई बहुमत से सचालक सभा चाहे तो उसे कर सकती है।

प्रमण्डल की कठिनाइयाँ—

गत वर्षों में कॉरपोरेशन में बरोड़ो खर्चों ने ऋण औद्योगिक संस्थाओं को प्रदान किये, किन्तु फिर भी प्रमण्डल पूर्णरूपेण सहायता नहीं पहुँचा सका। कॉरपोरेशन का तो अनुभव यह है कि भारतीय औद्योगिक क्लेवर की नाड़ी कमजोर है। प्रमण्डल के मार्ग में मुख्य दो बाधाएँ निम्न हैं —

(१) योजना का अभाव—अनेक उदाहरणों में ऐसी योजनाएँ कॉरपोरेशन के पास भेजी गईं, जिनमें तात्त्विक पहलुओं व वित्त समस्याओं पर पूर्ण विचार नहीं किया गया था। कुछ में तो यह भी नहीं बताया गया कि भूमि, इमारत, मशीनरी आदि अन्य विभागों पर अलग अलग कुल कितनी राशि व्यय होगी। ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ मशीन आदि इसलिए खरीद ली गई हैं क्योंकि वे सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। ऐसी धपूरी कसगजी योजनाओं में वास्तविक योजना के मूल सत्वों का अभाव होना स्वाभाविक ही है। मांग और पूर्ति की समस्याओं पर अधिकांश संस्थायें पर्याप्त रूप से सोचने में असमर्थ रही हैं, अतः ऐसी दशा में कॉरपोरेशन के लिए अन्वेषण करना कठिन सम्भव हो सकता है ?

(२) अपर्याप्त साधन—अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें पूँजी आवश्यकता से बहुत कम है। ऐसी संस्थाओं को ऋण देकर उनका ग्रहित करना है।

(३) कुछ उदाहरणों में यद्यपि प्राप्त पूँजी पर्याप्त थी, किन्तु संस्था की अधिकांश सम्पत्ति गिरवी रखी जा चुकी थी। ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ संस्था के सारे अंश प्रवर्तकों को उनसे ली गई सम्पत्ति के बदले में दे दिए गए हैं और ऐसी सम्पत्ति बहुत अधिक मूल्य पर प्राप्त की गई है।

(४) ऐसे भी प्रमण्डल हैं जो ऋणस्वीकृत हो जाने पर वैधानिक कार्यवाही पूरी नहीं करते और न इस दिशा में प्रयत्न ही करते हैं।

अतः औद्योगिक अर्थ प्रमण्डलों को चाहिए कि वे उक्त कठिनाइयों को दूर करने में तथा अधिकाधिक सहायता प्रदान करने में औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल को सहयोग दें, तभी विकास सम्भव है।

औद्योगिक अर्थ निगम की आलोचना—

जिस समय लोक सभा में औद्योगिक अर्थ निगम (संशोधन) अधिनियम, सन्

१९५२ तथा औद्योगिक एवं राज्य अर्थ निगमो (संशोधन) अधिनियम, १९५५ पर बहस हो रही थी, उस समय इस निगम की बड़ी कठोर आलोचना की गई। आलोचनाओं के प्रमुख आधार निम्नलिखित थे :—

(१) पक्षपात वरतना—निगम कम्पनियों को ऋण देते समय पक्षपात व भेदभाव की भावना रखता है, दूसरे शब्दों में निगम केवल संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है, जिनमें उसके संचालक अथवा अन्य पदाधिकारी हित रखते हो।

(२) अनिकसित क्षेत्रों की उपेक्षा—निगम उन राज्यों अथवा क्षेत्रों में, जो अपेक्षाकृत कम विकसित हैं, औद्योगिक उद्योग धंधे स्थापित करने में असफल रहा है।

(३) किंचित व्यक्तियों का प्रभुत्व—निगम पूर्णतया सरकार के स्वामित्व व नियन्त्रण में नहीं है, अतएव किंचित महारथियों की चतुरता सम्पूर्ण देश की आर्थिक स्थिति को अपने अधिकार में ले सकती है।

(४) लघु व कुटीर उद्योगों की उपेक्षा—निगम की सबसे कठोर आलोचना यह है कि इसने केवल बड़े पैमाने के उद्योगों की वित्तीय समस्याओं की ओर ही अधिक ध्यान दिया है, मध्य-स्तरीय, लघु एवं कुटीर उद्योग इसकी सहायता से वंचित हो गए हैं।

(५) आधारभूत उद्योगों के प्रति उपेक्षा—निगम ने ऐसी औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता दी है, जो पंच-वर्षीय योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती हैं। अन्य शब्दों में, निगम ने आधारभूत तथा पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों को बहुत कम सहायता प्रदान की है, जबकि उपभोक्ता सम्बन्धी उद्योगों को पर्याप्त सहायता दी गई है।

(६) ऋण लेने वाली कम्पनियों पर नियन्त्रण का अभाव—निगम ऋण लेने वाली कम्पनियों के द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की देखरेख करने में असफल रहा है। परिणामतः वस्तुओं के उत्पादन तथा उत्पादन-शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(७) सामान्य पूँजी प्रदान करने में असमर्थता—निगम कम्पनियों को सामान्य पूँजी नहीं प्रदान करता है, अतः उनको अन्य संस्थाओं का मुँह ताकना पड़ता है।

(८) ख्याति प्राप्त कम्पनियों को ऋण देना—निगम ने ऐसी कम्पनियों को भी ऋण दिया है जो खूब लाभ कमा रही थी तथा अपनी ख्याति के कारण मुद्रा बाजार से ऋण प्राप्त कर सकती थी।

(९) फिजूलखर्ची—यह भी कहा गया है कि निगम अपने स्थापन व्यय तथा अन्य व्ययों में मितव्ययिता नहीं कर सका है।

उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर निगम की ग़्रियाओं का पर्यवेक्षण कराने के लिए भारतीय सरकार ने श्रीमती सुचेता कृपसानी एम० पी० की अध्यक्षता में

दिसम्बर सन् १९५२ में एक समिति नियुक्त की। इस समिति के अन्य सदस्य- श्री वी० बी० गांधी, श्री श्रीनारायण मेहता, श्री पी० ए० नारियलवाला, श्री आर०००० सूर्यनारायण राव तथा श्री जी० बासु थे। इस समिति को निम्न बातों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देनी थी :—

- (१) लोक सभा में औद्योगिक अर्थ निगम (सञ्चोधक) बिल पर बहस के समय निगम के द्वारा दिये गये ऋणों पर लगाने गये दोष की छान-बीन करना ।
- (२) यह पता लगाना कि ऋण देते समय साधारण रूप से उचित सावधानी रखी जाती है अथवा नहीं ।
- (३) निगम की ऋण देने की नीति को इस विचार से देखना कि वह निगम के अधिनियम के उद्देश्यों तथा सरकार द्वारा निर्गमित आदेशों का पालन करती है अथवा नहीं ।
- (४) निगम की क्रियाओं में सुधार करने के लिए उचित सुझाव देना ।

कृपलानी समिति के सुझाव—

श्रीमती सुचेता कृपलानी समिति ने अपनी रिपोर्ट ७ मई सन् १९५३ को प्रस्तुत की। इस समिति ने बहुत से साधारण सुझाव दिये तथा 'सौदेपुर ग्लास वर्क्स' को दिये गये ऋण के बारे में भी विस्तारपूर्वक रिपोर्ट दी ।

जहाँ तक प्रथम दोष का सम्बन्ध है, समिति की राय में यह आधार रहित है। समिति ने इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसे उद्योगों, जिनमें निगम के संचालक या अध्यक्ष नेकमान भी हित रखते थे, उनको ऋण सुगमता व शीघ्रता से मिल गया है। समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि निगम ऋण देते समय सुस्थापित व व्यातिप्राप्त उद्योगों को अन्य उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता देता है। समिति ने किस आधार पर ऐसा निर्णय दिया, रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। फिर भी भारतीय सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट की विवेचना करते हुए कहा है कि "समिति ने जो कुछ भी रिपोर्ट दी है, सही तथ्यों पर आधारित है।"

कृपलानी समिति के सुझाव—

समिति द्वारा दिये गये सुझावों को अध्ययन की दृष्टि से हम तीन भागों में बाँट सकते हैं :—

- (1) शासन तथा संगठन सम्बन्धी,
- (II) कार्य विधि सम्बन्धी तथा
- (III) नीति सम्बन्धी ।

(I) शासन तथा संगठन सम्बन्धी सुझाव—

इस सम्बन्ध में समिति ने निम्न सुझाव दिए हैं :—

- (1) निगम के वर्तमान अर्वाचनिक अध्यक्ष तथा वैतनिक प्रबन्ध संचालक के

स्थान पर पूर्ण वैतनिक अग्र्यक्ष तथा एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति होनी चाहिए ।

- (11) प्रत्येक उप कार्यालय के लिए एक क्षेत्रीय परामशदाता पारपद होना चाहिए जिनमे से कुछ सदस्य ऋण आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए चुन लेना चाहिए, इसके अतिरिक्त कभी कभी निगम की संचालक सभा को बम्बई, कलकत्ता, मद्रास इत्यादि में अपनी सभा करनी चाहिए ।
- (111) समिति की राय में प्रबन्ध संचालक के हाथ अधिक अधिकारों का केन्द्रीयकरण उचित नहीं । प्रबन्ध संचालक तथा उप प्रबन्ध संचालक के कर्तव्य तथा अधिकारों को स्पष्ट रूप में परिभाषित कर देना चाहिए ।
- (11V) निगम को ऋण लेने वाली कम्पनिया की संचालक सभा में अपने पदाधिकारियों को संचालक नियुक्त करने के अधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए । इन संचालकों को ऋण देने वाली कम्पनी के स्थिति विवरण तथा हानि लाभ के खाता पर रूपाक्षर करने का अधिकार होना चाहिए ।
- (V) ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें निगम की संचालक सभा पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों का आधिपत्य न हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को चाहिए कि वह निगम की संचालक सभा में एक अर्थशास्त्री एक प्रबन्धकीय विशेषज्ञ तथा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को मनोनीत करें । मनोनीत किये गये संचालकों में एक ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए जो लघु उद्योगों के विकास में हित रखता हो ।

उपरोक्त सुझावों को सरकार ने लगभग मान लिया है तथा तदनुसार व्यवस्था हो जा चुकी है ।

(II) कार्य विधि सम्बन्धी सुझाव—

- (1) निगम का कोई भी संचालक जो किसी भी ऋण लेने वाली कम्पनी में हित रखा हो तो उस अपने हित को प्रकट कर देना चाहिए । ऐसी कोई भी पद जिसमें निगम का कोई भी संचालक, प्रबन्ध संचालक, या साफ़दार या प्रबन्ध अधिकर्ता हो तो उस कम्पनी को ऋण नहीं दिया जायगा । यदि निगम का कोई संचालक किसी ऋण लेने वाली कम्पनी का केवल साधारण संचालक या असहारी हो तो कम्पनी को ऋण उसी अवस्था में मिलेगा जब निगम की संचालक सभा के सचालक, जो मत देने के अधिकारी है, एकमत से ऋण देने के लिए प्रस्ताव पास कर दें । ऐसा संचालक जो किसी कम्पनी को ऋण

दिलाने में हिा रखता हो, तो सचालक सभा की शासकीय जिसमें इस ऋण पर विचार किया जा रहा हो, उपस्थित न चाहिए ।

(11) ऋणों को स्वीकृत करने में सचालकों की सभा को अन्तिम : होना चाहिए तथा शासकीय समिति को चाहिए कि वह कर्क मुरय ऋणों वाले प्राथना पत्रों को सचालक सभा की अनुमति बाद में प्रस्तुत करे ।

(111) निगम को अपनी वार्षिक रिपोर्टें जिसमें अधिक से अधिक सू तथा पच-वर्षीय रिपोर्टें जिसमें ऋण लेने वाली कम्पनियों प्रत्येक ऋण लेने वाली कम्पनी की क्रियाओं एवं सफलताओं में तथा उद्योगों के विकास की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना : करने चाहिए । स्थिति विवरण तथा लाभ-हानि के खातों : भी संशोधित कर देना चाहिये ।

(1 IV) ऋण देते समय कम से कम ५०% का अन्तर रलना चाहिये अनिश्चित यह भी ध्यात रखना चाहिये कि ऋण लेने वाली अपनी सम्पत्ति का अतिमूल्यन न कर दे । ऋण लेने वाली की लाभोपाजन शक्ति तथा दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यक सम्बन्ध में ऋण स्वीकृत करने से पहले ठीक ठीक अनुमान ल चाहिये । ऋण लेने वाली कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं : अशों को बिना नियम की आज्ञा के बेचने का अधिकार न चाहिये ।

(V) ऋणों के स्वीकृत करने में तथा उनका चुकाने में जो देर लगन कम से कम कर देना चाहिये ।

(VI) निगम के पास तात्त्रिक विशेषज्ञों का दल होना चाहिये ।

(VII) निगम यदि किसी कम्पनी को खरीद लेता है तो उसका विभागीय प्रबन्ध या प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के द्वारा होने की सिद्धान्तगत मनोनीत सचालकों की सभा को दे देना चाहिए ।

अभी तक निगम ने केवल एक ही कम्पनी (सोदेपुर ग्राम बक्स) क किया है, जिसका प्रबन्ध मनोनीत सचालकों के द्वारा किया जा रहा है ।

(III) नीति सम्बन्धी सुझाव

इस सम्बन्ध में समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं —

(1) निगम को पच वर्षीय योजना में दी गई प्राथमिकताओं के 5 तथा योजना आयोग के द्वारा ४२ उद्योगों के अनुमूचित क का पालन करना चाहिए । निगम को ऐसी कम्पनी को स्वीकृत नहीं करना चाहिए जो स्वयं काफी विकसित हो चुकी है

- (११) औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन अधिनियम की धारा ६—(३) के अनुसार सरकार को निगम को सिद्धान्त अपनाने के सम्बन्ध में आदेश देने चाहिए । सरकार को निगम को ऐसे आदेश देना चाहिए जिसमें अवसिक्त तथा विकसित क्षेत्रों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए । निगम को ५० लाख से अधिक राशि वाले आवेदन पत्रों को तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के सामने रखना चाहिए ।
- (३) इस समय तक निगम के राष्ट्रीयकरण के लिए सुझाव नहीं दिया गया है । लोक सभा के सदस्यों को निगम के दैनिक शासन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । परन्तु लोकसभा को इसकी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में समिति ने सुझाव दिया कि लोक सभा की एक पब्लिक कॉरपोरेशन कमेटी' बना दी जाय ।
- (४) निगम को सामान्य पूँजी या जोखिम पूँजी में भाग नहीं लेना चाहिए ।
- (५) निगम के संचित कोष के ५ करोड़ रुपये से अधिक हो जाने पर सामान्य पूँजी में भाग लेने पर विचार किया जा सकता है ।
- (६) निजी सीमित कम्पनियों को निगम अंश नहीं दे सकता है ।
- (७) निगम किसी कम्पनी के अस्थायी अंशों, जिनको वह किसी बैंक से प्राप्त करता है, पर गारंटी दे सकता है ।
- (८) किसी नई कम्पनी के लिए प्रारम्भिक वर्षों में व्याज की राशि को स्थगित कर सकता है ।
- (९) उन कम्पनियों के सम्बन्ध में जिनका निर्माण व पंजीयन भारतवर्ष में हुआ है परन्तु असधारियों की सख्या विदेशियों की अधिक है तो यह निश्चित करना कि ऐसी कम्पनी भाग लेने की अधिकारी है । अथवा नहीं ।
- (१०) जहाँ पर कोई राज्य विशेष पृथक रूप से राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम स्थापित करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में दो राज्य निगम की स्थापना कर सकते हैं । औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन निगम की क्रियाओं का स्पष्ट विवेचन होना चाहिए ।

उपरोक्त सुझावों को भारत सरकार ने सगंमय पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है ।

ऑफ समिति के सुझाव—

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा नियुक्त ऑफ कमेटी ने निजी क्षेत्र को अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक अर्थ निगम की क्रियाओं का पर्यवेक्षण भी किया । समिति ने इस सम्बन्ध में निम्न दोष व सुझाव प्रेषित किए :—

(१) ऋणों की स्वीकृति में विलम्ब—समिति ने यह अनुभव किया कि ऋणों की स्वीकृति में बहुत समय लगता है। विलम्ब का कारण प्रावेदन पत्रों में वैधानिक उपचारों की कमी थी। इस दोष को दूर करने के लिए समिति ने सुझाव दिया कि मुख्य शहरों में वैधानिक परामशदाताओं का दल रखा जाय।

(२) ऋण देने की शर्तें—निगम को ऋण देने की शर्तें बहुत ही अनाकर्षक हैं। उदाहरणार्थ, निगम ५०% का मार्जिन रखने के अतिरिक्त उस कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की प्रत्याभूति पर भी जोर देते हैं। समिति ने सुझाव दिया कि निगम को ऋण देने वाली कम्पनी की मुहठना के आधार पर ऋण देना चाहिए, प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की प्रत्याभूति पर नहीं।

(३) अधिक व्याज दर—निगम ऋण सेने वाली कम्पनियों से जो व्याज लेता है वह अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। यह व्याज की ऊँची दर मधुनिर्मित औद्योगिक कम्पनियों के विकास में बाधा डाल सकती है। समिति के विचार में निगम को नवीन कम्पनियों के प्रारम्भिक काल में नीची दर से व्याज लगाना चाहिए और बाद में कम्पनी की लाभ वर्जन शक्ति बढ़ने पर व्याज की दर बढ़ाई जा सकती है।

राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम

(State Financial Corporation)

मलिन भारतीय औद्योगिक ग्रंथ प्रमण्डल का क्षेत्र सीमित है, अतः औद्योगिक क्षेत्र के लिये ऐसे प्रांतीय अर्थ प्रमण्डलों की आवश्यकता है, जो सामेदारी सन्धियों, अलोक प्रमण्डलों तथा व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान कर। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि प्रांतीय अर्थ प्रमण्डल तथा औद्योगिक ग्रंथ प्रमण्डल परस्पर सहयोग से कार्य करें, जिसमें वे एक दूसरे के पूरक हों, क्योंकि मध्यम एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का कार्य क्षेत्र विस्तृत होने से औद्योगिक ग्रंथ निगम को यह क्षेत्र अपने आप में कठिनाइयाँ भी होगी। इसी हेतु समद ने २८ मितम्बर सन् १९५१ का 'प्रांतीय प्राधिक अर्थ प्रमण्डल सन्धियम' पास किया, जो सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

इस विधान के अनुसार प्रत्येक प्रांतीय सरकार अपने प्रांत में प्रांतीय अर्थ-प्रमण्डल स्थापित कर सकती है। इस सन्धियम की अधिकांश धाराएँ औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल सन्धियम सन् १९४९ से मिलती जुलती हैं। केवल तीन बातों में भिन्नता है—

(१) 'औद्योगिक सन्धियों' की परिभाषा इस प्रकार विस्तृत की गई है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सामेदारियों एवं यहाँ तक कि एकाकी स्वामित्व वाली सन्धियों भी इसके क्षेत्र में आ जाते हैं। (२) जन साधारण और अनुभूचित बैंक भी राज्य निगमों की अंश धूर्तों में भाग ले सकती हैं। (३) ऋण की अवधि केवल २० वर्ष रखी गई है।

सन् १९५१ का अधिनियम पास होने से अब तक कुल १३ अर्थ निगम बन चुके हैं। इनका कार्य कुछ अधिक सतोपजनक नहीं रहा है और वे लघु एवं मध्यम

उद्योगों की विशेष सहायता नहीं कर पाये हैं। इस अमफनना के लिए कुछ तो अधि-
नियम की दुर्बलताएँ दायी थी। कुछ सीमा तक लघु उद्योगों का स्वभाव एवं संगठन
भी बाधक हुआ। ये उद्योग भली प्रकार संगठित नहीं थे, अतः वे निगम से सहायता
मांगने में समर्थ नहीं हुये। फलतः सन् १९५६ में सन् १९५१ के राज्य-वित्त निगम
अधिनियम में संशोधन किए गए, जिनके उद्देश्य निम्न थे :—

(१) अधिनियम के कार्यान्विन करने में जो कनिष्ठ कठिनाइयाँ गन कुछ वर्षों
में अनुभव हुईं उन्हें दूर करना।

(२) दो या दो से अधिक राज्यों को पारस्परिक समझौते द्वारा एक संयुक्त
वित्त निगम की स्थापना करने के लिए अनुमति देना।

(३) एक राज्य के विद्यमान वित्त निगम का क्षेत्र दूसरे राज्य पर, एक पार-
स्परिक ठहराव के अन्तर्गत, विस्तृत करना।

(४) राज्य वित्त निगम को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या अखिल भार-
तीय वित्त निगम की ओर से ऐजेंसी कार्य लेने की अनुमति देना।

(५) रिजर्व बैंक से लघुकालीन ऋण लेने की अनुमति देना।

(६) लघु एवं कुटीर उद्योगों को, जिनके पास यथेष्ट सम्पत्ति नहीं है, किसी
राज्य सरकार या अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक की प्रत्याभूति देने पर आर्थिक सहा-
यता देने की अनुमति प्रदान करना।

(७) निगमों को अपने अधिकार में की गई औद्योगिक संस्थाओं के कुशल
प्रबन्ध संचालन के लिए अधिकार प्रदान करना।

(८) रिजर्व बैंक को, केन्द्रीय सरकार की आज्ञा पर, राज्य वित्त निगमों की
कार्य प्रणाली का जाँचने की अनुमति प्रदान करना।

यह अनुभव किया गया है कि लघु उद्योगों के विकास से रोजगार में विशेष
वृद्धि होगी और आय में असमानता घटेगी, अतः इनकी उन्नति पर सरकार बड़ा ध्यान
दे रही है। लघु उद्योगों की उन्नति के लिए वित्तीय सहायता बड़ी आवश्यक है, जो
केवल राज्यों के वित्त निगम ही दे सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इनको अधिक
सहायता नहीं दे सकता, क्योंकि लघु उद्योग सारे देश में बिखरे हुए हैं।

प्रबन्ध—

प्रत्येक प्रांतीय संस्था के प्रबन्ध के लिये १० सदस्यों की एक सभा होगी,
जिसके सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार की जायगी :—

(क) प्रांतीय सरकार द्वारा मनोनीत संचालक	३
(ख) रिजर्व बैंक	१
(ग) औद्योगिक अधिनियम " "	१
(घ) प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्ध-संचालक	१
(ङ) अनुसूचित बैंको, सहकारी बैंको, शेष आर्थिक व्यवसायों तथा अशधारियों में से प्रत्येक का अलग अलग प्रतिनिधि संचालक	४

राज्य वित्त निगमों के कार्य—

राज्य वित्त निगम को निम्न के लिये अधिकार दिये गये हैं :—

- (१) औद्योगिक सस्थाओं को ऋण देना या उनसे ऋण-पत्र खरीदना, जो कि २० वर्ष में वापिस लिये जा सकते हैं ।
- (२) औद्योगिक सस्थाओं द्वारा खुले बाजार में (५० वर्ष की अवधि में चुकता किये जाने वाले) ऋण निर्गमनों की प्रत्याभूति देना ।
- (३) औद्योगिक सस्थाओं के अशो, ऋण-पत्रों, बॉन्ड आदि का अभिगोपन करना, वशतें जो अश आदि निगम को लेने पड़ उन्हें ७ वर्ष के अन्दर बाजार में बेच दिया जाय ।

निगम के निश्चित कार्य—

(१) अधिक से अधिक उद्योगों को सहायता करने के बिनार से निगम किसी एक औद्योगिक सस्था को अपनी प्रदत्त पूँजी के १०% भाग अथवा दस लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं दे सकता ।

(२) निगम किसी भी औद्योगिक सस्था के अशों अथवा स्कन्धों को प्रत्यक्ष रूप से क्रय नहीं कर सकता ।

(३) निगम जनता से पाँच वर्ष से कम अवधि की जमा (Deposits) स्वीकार नहीं कर सकता ।

(४) निगम अपने अशों की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकता ।

(५) निगम अपनी प्रदत्त पूँजी से अधिक राशि की जमा स्वीकार नहीं कर सकता ।

विभिन्न राज्यों के अर्थ-निगम

(I) महाराष्ट्र राज्य का अर्थ-निगम

महाराष्ट्र राज्य में अर्थ-निगम की स्थापना ३० नवम्बर सन् १९५३ को हुई । इसकी अधिकृत पूँजी ५ करोड़ रुपये है । इस पूँजी का क्रय महाराष्ट्र राज्य की सरकार, संयुक्त स्कन्ध बैंको, बीमा कम्पनियों, सहकारी बैंको विनियोग प्रयास तथा अन्य आर्थिक सस्थाओं ने किया है । इस निगम का मुख्य कार्यालय बम्बई में है ।

उद्देश्य—

महाराष्ट्र राज्य के अर्थ-निगम का उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुविधायें प्रदान करना है ।

कार्य—

(१) औद्योगिक इकाइयों से ऋण पत्रों का क्रय करना तथा उन्हें ऋण देना ।

(२) औद्योगिक सस्थाओं द्वारा स्कन्ध विपणन में लिए गए ऋण की गारण्टी देना ।

(३) औद्योगिक संस्थाओं के ऋण-पत्रों, बंधों एवं स्क्रिप्सों के निर्गमन का अभियोगन करना ।

(४) औद्योगिक संस्थाओं को कम से कम दस हजार तथा अधिक से अधिक ५ लाख रुपये का ऋण देना ।

ऋण देने की शर्तें—

(१) स्थायी सम्पत्ति के शुद्ध मूल्य के १% राशि तक ऐसी सम्पत्ति की प्रथम वैधानिक प्राप्ति पर ऋण दिया जा सकेगा ।

(११) ऋण अधिक से अधिक दस से बारह वर्ष की अवधि के लिए दिया जा सकेगा और इसका भुगतान किस्तों में होगा । इन किस्तों की राशि एवं ऋण की अवधि प्रत्येक उद्योग की योग्यता एवं उसकी स्थिति के अनुसार निर्धारित होगी ।

(१११) ब्याज की दर ६% सालाना होगी ।

(१११) ऋण के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर ऋण की स्वीकृति देने के पूर्व नीचे दी हुई बातों पर विचार किया जायगा .—

(१) उद्योग की आर्थिक स्थिति, (२) प्रतिभूतियों की पर्याप्तता, (३) लाभार्जन शक्ति, (४) ब्याज तथा प्रमाणों में मूलधन के भुगतान करने की योग्यता, (५) तान्त्रिक विशेषज्ञों एवं प्रबन्धकों की योग्यता एवं अनुभव, (६) साधुनिकीकरण, विस्तार एवं विभाग योजना की तान्त्रिकता, (७) सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार । तथा (८) ऋण लेने वाले उद्योग की साख योग्यता ।

(II) उत्तर-प्रदेशीय अर्थ-निगम

२५ अगस्त सन् १९५४ को उत्तर-प्रदेशीय अर्थ-निगम की स्थापना हुई । इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में है । इसकी अधिकृत पूँजी ३ करोड़ रुपये है । प्रारम्भ में केवल ५० लाख रुपये के ५०,००० अंशों का निर्गमन किया गया है । इन अंशों का क्रय निम्न संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार किया गया है—राज्य सरकार ३६%, अनुसूचित बैंक बीमा कम्पनी आदि ३६%, रिजर्व बैंक १५%, अन्य संस्थाएँ १०% ।

उद्देश्य—

इस निगम का प्रमुख उद्देश्य लघु तथा माध्यमिक उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ।

ऋण देने की शर्तें—

इस निगम को पंजाब राज्य के अर्थ-निगम की शर्तों के आधार पर वन्च तथा ऋण पत्र बेचने का अधिकार है । निगम का संचालक मंडल इस बात का निर्णय करता है कि किन उद्योगों को सहायता मिलनी चाहिये । संचालक मंडल ही ऋण की अधिकतम व न्यूनतम राशि निर्धारित करता है । निगम द्वारा नवीन तथा विद्यमान दोनों प्रकार की संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । निगम द्वारा

१४]
 दिए गए ऋण पर ६% की दर से व्याज लिया जाता है और नियत समय पर ऋण की किस्तों तथा व्याज के भुगतान करने पर १२% छूट दी जाती है।

प्रबन्ध—

उत्तर प्रदेशीय अर्थ निगम का प्रबन्ध एक संचालक सभा के द्वारा होता है। इसका प्रबन्ध संचालक (Managing director) रिजर्व बैंक की सम्मति के अनुसार नियुक्त किया जाता है। निगम की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से परामर्शदाता समितियाँ भी नियुक्त की जा सकती हैं।

(III) मध्य-प्रदेश राज्य वित्त-निगम

मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना सन् १९५५ में हुई। इसका प्रधान कार्यालय इन्दौर में है। श्री दुर्गाप्रसाद जी महेलिया इसके चेयरमैन हैं तथा श्री० बी० गुप्ता इसके प्रबन्ध संचालक हैं। इस निगम के गत पाँच वर्षों के कार्यों का अनुमान नीचे दी हुई तालिका से लगाया जा सकता है :—

वर्ष	प्रदान किए गए ऋणों का योग	प्रदत्त ऋणों की मात्रा	दस्त पूँजी के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त ऋणों की मात्रा
	₹०	₹०	
३१-३-१९५६			
३१-३-१९५७	५,५०,०००	५,५०,०००	५.५०%
३१-३-१९५८	४०,८६,०००	४०,६१,०००	४०.६१%
३१-३-१९५९	४८,१५,०००	४३,२६,५००	४१.२७%
३१-३-१९६०	६०,०२,५००	४६,१०,४४६	४६.१०%

राज्य वित्त निगमों के कार्यों की आलोचना

यद्यपि कई राज्यों में अभी वित्त निगम भली प्रकार स्थापित नहीं हो पाये हैं, तथापि कुछ वित्त निगमों के कार्यों से यह प्रगट होना है कि यदि उनकी संरचना एवं काम प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर दिए जायें तो वे अधिक उपयुक्त बन सकते हैं। निगमों की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं :—

(१) इन निगमों की रचना ऐसी है कि उद्योगों को अपने विस्तार के लिए अतिरिक्त स्थाई सम्पत्तियाँ (मशीनों, इमारतों आदि के रूप में) खरीदने के हेतु पूँजी की सहायता मिल सकती है, किंतु अधिकांश लघु उद्योगों को कायशील पूँजी चाहिए, जिसे देने में राज्य निगम सक्षम करते हैं।

(२) अधिकांश लघु उद्योगों का संगठन छोटे पैमाने पर हुआ है। उनकी वित्तीय आवश्यकताएँ नियम के कार्य क्षेत्र से परे रह जाती हैं, क्योंकि राज्य निगम एक न्यूनतम राशि से कम आर्थिक सहायता नहीं देते।

(३) लघु उद्योगों द्वारा उचित रूप में हिसाब किताब नहीं रखा जाता। ये

उद्योग प्रायः एकल स्वामित्व या सामेदारी के आधार पर संगठित किये गये हैं, अतः इन पर हिसाब-किताब सम्बन्धी कोई वैधानिक प्रतिबन्ध भी नहीं है। जब निगम किसी उद्योग को सहायता स्वीकार करता है तो वह यह आशा करता है कि उचित हिमाब-किताब रखा जायेगा। छोटे छोटे उद्योग इसके लिए अपने को असमर्थ पाते हैं।

(४) लघु उद्योगों के पाम प्रतिभूति के रूप में देने के लिये पर्याप्त स्थाई सम्पत्ति (Block assets) नहीं है। भूमि और गवन प्रायः निराये का होता है, मशीनें भी कम होती हैं। यही नहीं, निगम स्थाई सम्पत्ति का ५०% मार्जिन भी छोड़ता है। फलस्वरूप उद्योग निगम को पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे पाते हैं।

(५) अधिकांश राज्य-वित्त निगमों ने कर मुक्त २३% ग्यूनरम लाभांश की गारंटी के आधार पर पूँजी प्राप्त की है, जिसके कारण वे स्वयं उद्योगों से ६% या ७% ब्याज लेने के लिये विवश हो जाते हैं, किन्तु यही अन्त नहीं है। उद्योग को ऋण लेने में कुछ व्यय करना पड़ता है, जिसको मिलाकर कुल ब्याज लगभग ६-१०% पड़ जाता है।

राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम (संशोधन) अधिनियम सन् १९५६—

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण राज्य निगमों को अधिक सफलता नहीं मिल रही थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया और ३० अगस्त सन् १९५६ को राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम (संशोधन) अधिनियम पास हो गया। इसके निम्न उद्देश्य थे :—

(१) पिछले वर्ष में अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करना।

(२) जो राज्य वित्तीय नियम की स्थापना करने में असमर्थ हैं उनके हित के लिए संयुक्त अर्थ-प्रबन्धक निगम की स्थापना करना।

(३) जिन लघु तथा कुटीर उद्योगों के पास प्रत्याभूति (Guarantee) देने के लिये उचित प्रतिभूतियाँ नहीं हैं उनको राज्य, सरकार, अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक की प्रत्याभूति पर ऋण देना।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट, १९३४ को ३० अप्रैल सन् १९६० में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक, स्टेट फाइनेन्स कॉरपोरेशन को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की प्रतिभूति (Security) पर ऋण अथवा अग्रिम १ = मास तक की अवधि के लिए दे सकती है। स्वीकृत की गई ऋण अथवा अग्रिम की कुल धनराशि किसी भी समय निगम की कुल पूँजी के ६०% से अधिक नहीं होगी।*

STANDARD QUESTIONS

- 1 How far do you think the establishment of the Industrial Finance Corporation has been able to remove the drawbacks of Indian industrial finance and has helped in the growth of large scale industries in the Indian Union? Examine critically in the light of its working for the last year
- 2 Review the working of State Finance Corporations during the past few years and offer suggestions for their better working

— — —

अध्याय ४०

अन्य विशिष्ट अर्थ-संस्थायें

(Other Special Finance Institution)

(I) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

(National Industrial Development Corporation)

स्थापना—

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (N I D C) की स्थापना २० अक्टूबर सन् १९५४ को एक करोड़ रुपये की दत्त पूँजी से की गई है। यह समस्त पूँजी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक निगम पूर्णतया राजकीय संस्था है। इसका पूर्ण स्वामित्व तथा नियंत्रण सरकार के हाथों में है। इस निगम की स्थापना देश में शीघ्रातिशीघ्र औद्योगीकरण करने के उद्देश्य से की गई है। उपरोक्त उद्योगों के क्षेत्र में निजी साहस यादों से ही बाहरी सहायता से सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता किन्तु जहाँ तक आधारभूत व तालिका उद्योगों की स्थापना व विकास का प्रश्न है निजी क्षेत्र के लिए यह अत्यन्त दुर्लभ काम है। अतः सरकार को इस क्षेत्र में स्वयं अग्रगण्य बनना पड़गा।

उदगम—

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की बात तत्कालीन व्यापार एवं उद्योगमन्त्री श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी के मस्तिष्क में आई थी। अक्टूबर सन् १९५३ में योजना आयोग के उप-अध्यक्ष श्री बी० टी० कृष्णमाचारी ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस बात की घोषणा की थी कि पंच वर्षीय योजना के एक अंग के रूप में एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की जायगी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य अन्य निगमों की भाँति उद्योगों का अर्थ-प्रबन्धन करके, उनके विकास एवं स्थापना के साधनों को जुटाना होगा। निजी साहस को यद्यपि करने में अधिक सफलता मिलने की आशा नहीं है, परन्तु वह अपने विनियोगों, अनुभव एवं योग्यता के द्वारा सहायता पहुँचा सकता है। यह निगम अपने उद्देश्य की पूर्ति में निजी साहस को सहर्ष स्वीकार करेगा और उसका सदुपयोग करेगा।

पूँजी—

‘राष्ट्रीय औद्योगिक विकास’ निगम की पूँजी १ करोड़ रुपये है, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था में केवल १० लाख रुपये की दत्त पूँजी होगी, जो सरकार देगी। इस निगम का रजिस्ट्रेशन भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। इस निगम को जो अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी वह केन्द्रीय सरकार निम्न रीति से प्रदान करेगी :—

- (१) औद्योगिक योजनाओं के अध्ययन, अनुसन्धान एवं औद्योगिक निर्माण के लिए तथा ऐसी ही अन्य औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए देश में आवश्यक तान्त्रिक एवं श्रमिकीय कर्मचारियों का दल तैयार करने के लिए वार्षिक अनुदान द्वारा। अनुदान की इस राशि का आयोजन वार्षिक बजट में किया जायगा।
- (२) औद्योगिक विकास निगम की प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता के समय देकर।

प्रबन्ध—

औद्योगिक विकास निगम का प्रबन्ध एक सचालक सभा द्वारा होगा, जिसमें २० सदस्य हैं। वाणिज्य एवं उद्योगमन्त्री इसके सभापति हैं। इन सचालकों को केन्द्रीय सरकार ने मनोनीत किया है। औद्योगिक अनुभव तथा तान्त्रिक एवं इन्जीनियरी कार्यक्षमता की दृष्टि से सचालक सभा में १० उद्योगपति, ५ अधिकारी तथा ४ इन्जीनियर हैं।

उद्देश्य—

- (१) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य देश की औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक मशीनरी एवं यन्त्र प्रदान करना तथा आधार-भूत उद्योगों का प्रवर्तन एवं उनकी स्थापना करना।
- (२) देश के औद्योगिक विकास में सहायक वर्तमान व्यक्तिगत उद्योगों को

तान्त्रिक एवं इन्जीनियरिंग सेवाओं की सुविधा देना तथा यदि आवश्यक हो तो पूँजी देना ।

(३) व्यक्तिगत उपक्रमियों को सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक तान्त्रिक, इन्जीनियरिंग, आर्थिक अथवा अन्य सुविधायें प्रदान करना ।

(४) प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक अध्ययन करना, उनको तान्त्रिक, इन्जीनियरिंग तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना तथा उनकी पूर्ति के लिए धन देना ।

इस प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का उद्देश्य लाभार्जन न होते हुए देश के सुदृढ़ औद्योगिक कलेवर के निर्माण में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना है, ताकि जल्दी से देश का औद्योगिक विकास हो सके ।

इस उद्देश्य से निगम के बोर्ड ने २३ अक्टूबर सन् १९५४ को हुई अपनी पहली मीटिंग में उद्योगों की अस्थायी सूची तैयार की, जिसके अध्ययन से निगम को इस बात का पता लग जाय कि नया औद्योगिक विकास किस सीमा तक आवश्यक है और विद्यमान उद्योगों को किस सीमा तक बढ़ाना चाहिये ? चुने गये उद्योग इस प्रकार हैं :—

(१) कुछ उद्योगों के लिये (जैसे—जूट, कपास, वस्त्र, चीनी, कागज, सीमेंट रासायनिक, छपाई, खान, निर्माण एवं यान्त्रिक आवागमन आदि उद्योग) मशीनरी और साज-सज्जा (Machinery and Equipment) का निर्माण ।

(२) लौह मिश्रण और मैंगनीज फेरोक्रीम ।

(३) अलूमिनियम ।

(४) ताँबा, जस्ता और अलौह धातुयें ।

(५) डीजल इंजिन और जेनरेटर ।

(६) भारी रासायनिक द्रव्य ।

(७) खाद और उर्वरक ।

(८) कोयले और कोलतार का सामान ।

(९) मेथेनॉल, फॉरमेलडिहाइड ।

(१०) काजल ।

(११) कामज, अख्तवारी कामज आदि बनाने के लिए लकड़ी की लुगदी ।

(१२) कृत्रिम दवायें, विटामिन और हार्मोन ।

(१३) एक्सरे और डाक्टरी औजार आदि ।

(१४) हाइड्रोड और इन्सुलेशन बोर्ड आदि ।

लेकिन यह स्पष्ट है कि मशीनरी और साज-सज्जा के निर्माण पर काफी जोर दिया गया है, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास के विशाल कार्यक्रम पूरे

करने पड़ेगे। स्थूल मशीनरी एवं उद्योग की स्थापना के अलावा निगम कुछ विद्यमान उद्योगों को उनके विशाल पैमाने पर उनके विकास के हेतु भी सहायता करेगा। उदाहरण के लिए, भारत सरकार देश में ३० नये चीनी मिल स्थापित करके चीनी का उत्पादन १२ लाख टन से बढ़ाकर १८ लाख टन करने का विचार कर रही है, अतः नये चीनी कारखानों की स्थापना के लिए उदारनापूर्वक लाइसेंस दिये जा रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग की क्षमता में भी १०० गुनाई मिलों के बराबर वृद्धि करना आवश्यक है। सीमेंट का उत्पादन भी सन् १९६१ तक ४५ मिलियन टन से १० मिलियन टन तक बढ़ाना चाहिए, अतः निगम इन क्षेत्रों में अनिरिक्त इकाइयाँ स्थापित करना चाहता है।

कुछ उद्योगों में, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक प्रयत्नों द्वारा कुछ उन्नति दिखाई गई, जैसे—अल्फूमीनियम और फर्टिलाइजर उद्योगों में, निगम कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह केवल तब ही सामने आवेगा जब अधिक सहायता या कार्य की आवश्यकता हो। फेरोमेनगैज उद्योगों में भी यदि प्राइवेट प्रयत्नों द्वारा प्रस्तावित और सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएँ पूरी हो जाती हैं तो निगम कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, क्षेप्य पदार्थों के उपयोग और बच्चे माल के विकास में काफी टेक्नीकल छानबीन तथा सहायता की आवश्यकता है, अतः निगम ने अपने उद्योगों की सूची में रेयोन, कागज, अखबारी कागज आदि के उत्पादन में काम करने वाले बोयला, कोलतार, लकड़ी की लुग्दी आदि शामिल कर लिये हैं। इस कार्य के लिए एक जर्मन विशेषज्ञ भी आमन्त्रित किया गया है।

निगम के बोर्ड ने अनुभव किया है कि देश के शीघ्र औद्योगीकरण के लिए सबसे पहली बात उद्योगों को ठोस टेक्नीकल सहायता प्रदान करना है, अतः उसने परामर्शदाता इञ्जीनियरों की एक संस्था स्थापित करने पर जोर दिया है। योग्य कार्यकर्त्ताओं का देश में मिलना कठिन होन के कारण उसने यह सुझाव दिया कि प्रारम्भिक अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय स्याति प्राप्त किसी फर्म को भारत में अपना कार्यालय खोलने के लिए आमन्त्रित किया जाय और यदि आवश्यक हो तो उसे कुछ फीस भी दी जाय। इस फर्म की सेवाएँ प्राइवेट उद्योगों के लिए भी सुलभ की जावेंगी। इनके अनिरिक्त बोर्ड ने यह भी निश्चय किया है कि व्यापक अनुभव वाले ३ या ४ इञ्जीनियर भी रखे जावें, जो निगम को उसके सामने आने वाली टेक्नीकल समस्याओं को हल करने और निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए उपयुक्त सलाह देंगे। इन प्रारम्भिक निर्णयों में यह प्रष्ट होता है कि निगम का दृष्टिकोण बड़ा व्यावहारिक है और वह अपने कार्यों को वास्तविक रूप से हल करना चाहता है।

निगम की क्रियाएँ—

औद्योगिक विकास निगम की संचालक समिति की प्रथम बैठक मितम्बर सन् १९५५ में हुई। इस बैठक में कुछ औद्योगिक विकास की योजनाएँ स्वीकृत की गईं

तथा उन योजनाओं का पर्यवेक्षण भी प्रारम्भ कर दिया गया। निगम ने भारतीय जूट उद्योग के पुनर्स्थापन तथा आधुनीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक माधन जुटाने का निश्चय भी कर लिया। इसने एक समिति, जिसके सदस्य अधिकतर उद्योगों से सम्बन्धित थे, की स्थापना की और निश्चय किया कि इस समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत मिलों को केवल ४॥% व्याज पर दीर्घकालीन ऋण दिया जायगा।

जूट उद्योग की मान मिलों को आधुनीकरण के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने १*३६ करोड़ रुपये का ऋण दे दिया है और ८ अन्य मिलों के लिए १*५८ रुपये का ऋण निगम के विचाराधीन है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उपरोक्त ऋणों के द्वारा तथा जूट उद्योग के आन्तरिक माधनों के द्वारा सम्पूर्ण जूट उद्योग की लगभग आधी पुरानी मशीनों का आधुनीकरण हो जायगा।*

निगम ने कुछ अन्य उद्योगों की स्थापना करने का भी निश्चय किया है। ये उद्योग स्टील फाउण्ड्रीज फोर्जेज, प्रिंटिंग मशीनरी, एयर कम्प्रेसर्स (Air Compressors), कागज की लुग्दी, बार्बन इत्यादि हैं।

निगम के सचालकों ने २३ मार्च सन् १९५२ को दिल्ली में हुई बैठक में सरकार के सम्मुख कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे। इन सुझावों में से एक सुझाव 'सिन्थेटिक रबर प्लांट', (Synthetic Rubber Plant) के सम्बन्ध में भी था। निगम ने भारतीय सरकार के सामने तीन योजनाओं के पर्यवेक्षण कराने का सुझाव रखा। ये योजनाएँ निम्न चीजों के निर्माण से सम्बन्धित थीं—

(अ) औद्योगिक मशीनरी तथा प्लांट,

(ब) एल्यूमिनियम, तथा

(स) एलिमेंटल फास्फोरस (Elemental Phosphorus)

निगम ने यह भी निश्चय किया है कि 'स्ट्रक्चरल-कम मशीनशाप' (Structural-Cum-Machinestop) मिलाई में तथा 'स्ट्रक्चरल शाप' दुर्गापुर में स्थापित किए जायेंगे। निगम ने सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्स्थापन तथा आधुनीकरण करने के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता को समस्या पर विचार किया। सचालक सभा की एक समिति वस्त्र उद्योग से प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए स्थापित की गई। यह उपसमिति 'टेक्सटाइल कमिश्नर' के कार्यालय के पर्यवेक्षण दल की सहायता से कार्य करेगी।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में कार्य क्रम—

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत निगम की क्रियाओं के लिए ५५ करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया था। इस धनराशि का एक भाग (लगभग २० या २५ करोड़ ६०) सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग के आधुनीकरण की

योजनाओं को सफल बनाने में खर्च किया गया। शेष धनराशि नवीन आधारभूत तथा मुख्य उद्योगों के निर्माण तथा प्रवर्तन में व्यय की गई।

आलोचना—

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की तख्तीना समिति की राय में निगम से वित्तीय व्यवस्था का काम छीन लिया जाना चाहिए, जोकि उसका इस समय मुख्य दाय है। समिति का कहना है कि यदि ऐसा हो जाय, तो निगम का विकास सम्बन्धी कार्य अन्य संस्थाएँ कर सकती हैं। इस दशा में निफारिश की गई है कि सरकार को विचार करना चाहिए कि निगम को बनाये रखना कहाँ तक उचित है। तख्तीना समिति की १२२वीं रिपोर्ट आज लोकसभा में रख दी गई। समिति की राय में निगम निजी व सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का सन्तुलित विकास करने में भी असमर्थ है। क्योंकि हिस्टुस्तान स्टील, हिस्टुस्तान मशीन टूल्स आदि उद्योग उसकी सहायता के बगैर ही स्थापित कर लिये गये और इसके अलावा उसके पास टैक्निकल स्टाफ भी नहीं है।

(II) औद्योगिक ऋण एवं अर्थ निगम

(Industrial Credit and Finance Corporation)

यह एक विशुद्ध गैर सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना जनवरी सन् १९५५ में २५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य नये उद्योगों के प्रवर्तन को प्रोत्साहित करना, विद्यमान उद्योगों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करना एवं तात्त्विक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता देना है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन 'दिन दूनी रात चौगुनी' उन्नति करे और रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो।

उद्गम—

सन् १९५३ में भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों के मण्डल ने इंग्लैण्ड के औद्योगिक तथा व्यापारिक वित्त निगम के आधार पर उपरोक्त निगम को स्थापित करने का निश्चय किया था, क्योंकि भारतीय औद्योगिक अर्थ निगम अर्द्ध सरकारी होने के कारण उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति उतनी कुशलता से नहीं कर सका जैसी कि इसको करना चाहिये था। फरवरी सन् १९५४ में विश्व बैंक का एक प्रतिनिधि एवं अमेरिका के वित्त निगमों के दो प्रतिनिधि भारतवर्ष में आये। निगम की स्थापना के ध्येय से भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली के उद्योगपतियों की सलाह में, 'स्टीयरिंग समिति' नियुक्त की गई। इस समिति में ५ सदस्य थे, जिनमें से २ सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा संयुक्त राज्य विदेशी विनियोक्तों तथा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिये गये। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप निगम का रजिस्ट्रेशन जनवरी सन् १९५५ में भारतीय कम्पनी अधिनियम (Indian Companies Act) के अन्तर्गत हुआ। इसका प्रमुख कार्यालय बम्बई में है।

पूँजी का ढाँचा—

निगम की अधिष्ठित पूँजी २५ करोड़ रु० है, जो सौ-सौ रुपये के ५ लाख साधारण अंशों तथा सौ-सौ रुपये के २० लाख अवर्गीय अंशों (Unclassified Shares) में विभाजित है। निगम की चुकना पूँजी ५ करोड़ रुपये है, जो सौ-सौ रुपये वाले ५ लाख साधारण अंशों में विभाजित है। अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया और उनके धारियों को प्रति अंश पर एक भत (वोट) देने का अधिकार है। निर्गमित पूँजी का क्रय विभिन्न सस्थाओं के द्वारा इस प्रकार किया गया है :—

(१) भारतीय बैंक, बीमा कम्पनियाँ तथा विनियोक्ता वगैरह	३½ करोड़ रु०
(२) ब्रिटिश इस्टर्न एक्सचेंज बैंक तथा अन्य औद्योगिक समूहों आदि	१ करोड़ रु०
(३) अमरीकी विनियोक्ता-गण	५० लाख रु०
योग	५ करोड़ रुपये

अमेरिकन विनियोक्तागणों में 'रौकफ़ेल्ड ब्रदर्स' 'वेस्टिंग हाउस', 'इलेक्ट्रिकल इंटरनेशनल कम्पनी' तथा 'मेसर्स आलिन मैथीसन केमिकल कॉरपोरेशन' सम्मिलित हैं।

भारत सरकार ने निगम को ७½ करोड़ रुपय का ऋण बिना व्याज के दिया है, जिसका भुगतान १५ वार्षिक किस्तों में ऋण देने की तिथि के १५ वर्ष पश्चात् होगा। विश्व बैंक ने भी निगम का समय समय पर विविध मुद्राओं में १ = मि० डालर के बराबर ऋण देना स्वीकार किया है। ऋण के मूलधन, व्याज तथा अन्य व्यय की गारंटी भारत सरकार ने मार्च सन् १९५५ में दी है। ऋण की अवधि ५ वर्ष तथा व्याज की दर ४½% है। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकृत हो जाने के कारण भारतीय सरकार के स्वामित्व व अधिकार में पूँजी का लगभग १८% भाग आ गया है। परन्तु सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहती है।

उद्देश्य—

औद्योगिक ऋण एवं अर्थ निगम का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों को सहायता प्रदान करना है। यह सहायता निम्न रीति से दी जावेगी :—

- (१) ऐसे उपक्रमों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में वार्षिक सहायता देना।
- (२) ऐसे उपक्रमों में देशी एवं विदेशी व्यक्तिगत पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन देना।
- (३) विनियोग विपणन को विस्तृत करना एवं औद्योगिक विनियोगों के व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।

- (४) व्यक्तिगत उपक्रमियों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन आर्थिक सुविध में देना अथवा उनके निर्गमन साधारण अशो को खरीद कर आर्थिक सुविधाये देना ।
- (५) नई कम्पनिया के अशो एवं प्रतिभूतिया का अभिगोपन करना ।
- (६) व्यक्तिगत उपक्रमों के लिए व्यक्तिगत विनियोग स्रोतों से प्राप्त ऋणों की जमानत देना ।
- (७) चद्रिन विनियोग द्वारा पुन विनियोग के लिय व्यक्तिगत उपक्रमा का राशि प्रदान करना ।
- (८) व्यक्तिगत उपक्रमा को प्रबन्ध सम्बन्धी तांत्रिक एवं शासकीय सहायता देना एवं उनके उद्योगों को इस हेतु आवश्यक विशेषज्ञ प्रदान करना ।

प्रबन्ध—

इस निगम का प्रबन्ध संचालक सभा द्वारा होगा, जिसमें ११ सदस्य तथा १ जनरल मैनेजर होगा। इन संचालकों में ७ भारतीय, २ ब्रिटिश, १ अमरीकी तथा १ संचालक वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय की ओर से हों। इसमें जनरल मैनेजर वेंकट राव अह्लूवाल्ल के प्रमुख कोषाध्यक्ष पी० एस० वीरू हैं तथा चैयरमैन श्री रामास्वामी मुदालियर हैं।

भारत सरकार ने कम्पनी को ७५ करोड़ रुपये की राशि देना स्वीकार कर लिया है, जिस पर कोई व्याज न होगा। यह राशि कम्पनी को धन मिलने की तिथि से १५ वर्ष बीत जाने के बाद से शुरू होने वाली १५ वार्षिक किश्तों में चुकाई जावेगी। सरकार को एक संचालक नामांकित करने का अधिकार है। विश्व बैंक ने कम्पनी को समय समय पर विभिन्न मुद्राओं में १ करोड़ डालर की राशि उधार देना स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निगम को १७५ करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी मिल गई है। यह भी आशा है कि इस निगम के माध्यम से विदेशी पूँजी या ऋणों के रूप में मदद मिलेगी और कुछ ही समय में निगम के पास ५० करोड़ रुपये हो जायेंगे।

निगम ने अशुधारी दूर-दूर तक फैले हुये हैं और इससे कार्यों तथा पूँजी नियोजन के अन्तर्गत छोटे बड़े सब तरह के उद्योग घटने आ जायेंगे। निगम दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण देगा, अशु पूँजी में भाग लया और प्रतिभूतियों के तब निगमन का अभिगोपन करेगा। निगम का प्रारम्भिक धन और वह धन जो इसको विश्व बैंक से मिलता है, यदि विवेक से काम में लाया जाय तो वह देश में व्यक्तिगत पूँजी बाजार के साधनों को और भी बढ़ा सकता है तथा भविष्य में उपलब्ध सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी सुविधाओं को प्रोत्साहित कर सकता है।

निगम के कार्य और उनकी आलोचना—

सन् १९५६ के अन्त में कम्पनी ने २४ योजनाओं के सम्बन्ध में सहायता देना

स्वीकार किया था और शेष विचाराधीन थी। बाद में कुछ और योजनायें स्वीकृत गईं। इस प्रकार कुल २८ योजनाओं के लिए ८ करोड़ से अधिक रुपया स्वीकृत जा चुका है। निगम के लिए यह कोई बड़ी सफलता नहीं कही जा सकती। यह दोष बताया जाता है कि निगम का कार्य बहुत धीमा है और अपनी गहरा एव विनि नीति में वह अत्यधिक कृपणता से काम ले रहा है।

इस सम्बन्ध में कम्पनी की द्वितीय वार्षिक व्यापक सभा में, जोकि २२ दिसम्बर १९५७ को बम्बई में हुई, अध्यक्ष पद से अपने भाषण में श्री रामास्वामी मुकादर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि निगम के विरुद्ध आरोपों जांच कराई गई है और वे सही नहीं लगे। उन्होंने बताया कि कम्पनी को प्रारम्भ अभी थोड़ा समय हुआ है, अतः सगठित होने व अनुभव प्राप्त करने में कुछ संलग्नता अनिवार्य है। ऐसा ही कारोबार करने वाली भारत और विदेशों की अन्य कंपनियों का भी रिकार्ड उनकी प्रारम्भिक अवस्थाओं में बहुत कुछ इस निगम के ही साक्षात्कारों का भी पर्याप्त विस्तृत है। वह कुछ ऐसी कार्यों को भी कर रहा है, जो कि अन्य कंपनियों ने भारत में नहीं किये। निगम कोई पूर्णतः न देने वाला कम्पनी मात्र नहीं है, जिसका सम्बन्ध बस उस प्रतिभूति से हो जोकि वह उसे दी जा रही है। अपने असा के अभिगणन का कार्य भी किया और अस्तुत कम्पनियों की असा पूँजी में भाग लिया है। इस सबके लिए यह स्वाभाविक है कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन-पत्रों की निष्पत्ति से जांच की जाय।

श्री मुदालियर ने कहा कि कम्पनी के पास न केवल अगधारियों का, बल्कि सरकार का भी काफी धन ऋण के रूप में है। कम्पनी के उद्देश्य स्पष्ट रूप से सोच धृष्ट कर दिए गए हैं और इन्हें अति सावधानी से ही पूरा किया जा सकता है। निगम ही ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ खतरा तो लेना ही पड़गा, परन्तु यह खतरा अ हाकर नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर उठाना है। कुछ उद्योगपतियों को इस ध की शिवायत है कि प्रस्तावों पर व्यर्थ इतना सच विचार किया जाता है। वे ऐसा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने योजनाओं की अपने सतर्पण लिए परीक्षा कर ली है, पर इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि निगम जांच न करे या दिवाई करते। यदि निगम ऐसा करे तो वह अपने वस्तुव्यपालन में भ्रष्ट का दोषी होगा।

निगम के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वह विश्व बैंक द्वारा दिए गये ६० मिलियन डॉलर के ऋण का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। इस स्थिति में श्री मुदालियर ने बताया कि कम्पनी स्वयं यह चाहती थी कि इसका प्रयोग किया जाये, परन्तु दुर्भाग्य से कम्पनी के पास विदेशी मुद्रा की सुविधा देने के लिए एक आवेदन पत्र नहीं आया, क्योंकि औद्योगिक और प्रवक्तव्य को सामान्य ढङ्ग से परिपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती थी अतः ऐसी स्थिति में विश्व बैंक से सहायता लेना वा प्रश्न नहीं उठा। कम्पनी वेकान में ही क्या एक साधन से हाथ धोये। ह

अब विदेशी मुद्रा का अभाव अनुभव किया जा रहा है और विदेशी मुद्रा के ऋणों के आवेदन भी आने लगे हैं ।

कम्पनी की स्थापना प्राइवेट क्षेत्र में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, किन्तु श्री मुदालियर ने कहा कि सन् १९५४ से प्राइवेट क्षेत्र की स्थिति बिगड़ गई है । यदि प्राइवेट क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित करना है और पुरानों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करना है तो यह आवश्यक था कि इस क्षेत्र में विनियोग करने वाली जनता को भवका न पहुँचे । दुर्भाग्य से अभी हाल में ऊँचे दर लगा दिये गये हैं । आय-कर, कॉरपोरेशन टैक्स और सुपर टैक्स में वृद्धि हो गई है, पूँजी लाभ पर कर लग गया है और पिछले एक साल लाभों के सम्बन्ध में डिपोजिट सिस्टम बालू कर दिया गया है । इन सबका प्राइवेट क्षेत्र के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है । जो थोड़ा बहुत विकास आज प्राइवेट क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है वह पूर्व योजनाओं का परिणाम है । नई योजनाओं पर तो बड़ा कुठाराघात हुआ है । निश्चय ही सरकार को कुछ अधिक धामदनी हो गई है । वह पब्लिक क्षेत्र में अधिक विकास कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर प्राइवेट क्षेत्र का विकास खतरे में पड़ गया है और भारतीय एवं विदेशी, दोनों ही पूँजियों का अभाव हो गया है । सम्भवतः इसलिए सरकार ने अभी हाल में विदेशी पूँजी को कुछ अधिक सुविधाएँ दी हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार कर नीति के परिणामों को समझ रही है ।

निगम के प्रारम्भ सन् १९५५ से लेकर सन् १९५६ के अन्त तक ५६ कम्पनियों के लिये स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता २०*४० करोड़ रुपये थी । सन् १९५८, सन् १९५७ और सन् १९५६ के अन्त तक यही सहायता क्रमशः १३३७ करोड़ रुपये, ११६५ करोड़ रुपये तथा ६*०१ करोड़ रुपये थी और कम्पनियों की संख्या क्रमशः ४४, २८ तथा ११ थी ।

सन् १९५६ के अन्त तक स्वीकृत किए गये २०*४० करोड़ रुपये में से १०*२४ करोड़ रुपये (लगभग ५०%) ऋण और गारंटी के रूप में थे । ८*३० करोड़ रुपये साधारण तथा पूर्वाधिकारी अंशों के अभिगोपन (Under writing) कार्य के लिए थे । शेष १*८६ करोड़ रुपये साधारण तथा पूर्वाधिकार अंशों का व्यय करके दिये गये ।

निगम ने अपनी क्रियाओं में और अधिक प्रसार किया है और पहली बार सन् १९५८ में विदेशी मुद्रा में ऋणों को बाँटा है । सन् १९५६ के अन्त तक स्वीकृत किए गए ऋणों में से ६*७४ करोड़ रुपये (कुल ऋण का ६६%) विदेशी मुद्रा में तथा ३५५ करोड़ रुपये (कुल का ३४%) के ऋण देशी मुद्रा में दिये गये ।

कॉरपोरेशन की कुल आय सन् १९५६ में ५७ लाख रुपये थी । यही आय सन् १९५८, १९५७ और १९५६ में क्रमशः ५७ लाख, ५४ लाख और ४७ लाख रुपये थी । संस्थापन तथा अन्य व्यय (७*२६ लाख रुपये) तथा करो के लिये प्रावधान (२२*४३ लाख रुपये) करने के पश्चात् कॉरपोरेशन को २८*३३ लाख रुपये का शुद्ध

लाभ (Net Profit) हुआ, जो कि पिछले वर्ष (२५*२२ लाख रुपये) की अपेक्षा में ३५१ लाख रुपये अधिक था ।*

(III) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राइवेट लिमिटेड

(National Small Industries Corporation Private Limited)

स्थापना—

सरकारी आदेशों की पूर्ति के लिए लघु उद्योगों के उत्पादन का संगठन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक नियम की स्थापना की है । निगम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड कराया गया है ।

निगम की पूँजी—

निगम की स्थापना २० लाख रुपये की अधिकृत पूँजी से निजी सीमित कम्पनी के रूप में हुई है । इसे केन्द्रीय सरकार से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती रहेगी । इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में रखा गया है ।

निगम के उद्देश्य—

(१) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समय समय पर निकलने वाले सप्ताह सम्बन्धी टेन्डरों को दिलाना ।

(२) निगम उन उद्योगों की तात्त्विक एवं आर्थिक सहायता करेगा जो कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की आवश्यकता का सामान तैयार करते हैं, ताकि उनका उत्पादन प्रमाण के अनुसार हो ।

(३) निगम का मुख्य कर्तव्य लघु एवं विशाल उद्योगों के बीच सामंजस्य लाना भी है, ताकि लघु उद्योग विशाल उद्योगों के पूरक बन सकें । यह आशा भी की जाती है कि निगम द्वारा छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से छोटे मोटे पुर्जों के लिए आदेश प्राप्त हो जाया करेगा ।

निगम की क्रियायें—

निगम ने राज्य सरकारों की सिफारिश पर 'डाइरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एण्ड डिस्पोजिशन' की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने द्वारा रजिस्टर्ड लघु उद्योगों को आदेश दिये हैं । प्रारम्भ में २०० वस्तुओं से अधिक के आदेश कुटीर तथा उद्योगों के लिए सुरक्षित किए गये थे । सन् १९५५-५६ में निगम ने छोटे उद्योगों के लिए ४,६८,५६५ रु० के आदेश प्राप्त किए ।

निगम ने तीन 'चल विक्रय गाडियाँ' दिल्ली क्षेत्र की ३०० वस्तुओं का क्रय करने के लिए चालू कर दी हैं । इसके अतिरिक्त आगरा के लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय करने के लिए आगरा में एक होल सेल डिपो भी खोला गया है । इसी प्रकार अलीगढ़ के तालों और खुर्जा की पॉटरों के लिए अलीगढ़ में एक होल-मेल डिपो

खोली जा रही है। लघु उद्योगों को मशीनें भी निराया खरीद आधार पर सपनाई करने की व्यवस्था की जा रही है।

निगम की क्रियाओं को और विस्तृत करने के लिए चार और शाखाएँ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में खोली जावगी। सब राज्यों में कार्यक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से 'उद्योग सेवा संस्थाया' की संख्या ४ से बढ़ाकर २० कर दी जावेगी।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों पर कुल व्यय इस प्रकार किया गया है, जिसका व्यौरा निम्न प्रकार है :—

सन् १९५१-५६

विवरण	करोड़ रुपये
हाथ कर्षा	११.१
खादी	७.४
ग्राम उद्योग	४.१
लघु उद्योग	५.३
हस्त शिल्प	१.०
सिल्क एवं सेरीकल्चर	१.३
योग	३०.२ करोड़ रुपये

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास के लिये २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसका व्यौरा निम्न प्रकार है :—

(१) हाथ कर्षा	५६.५ करोड़ रुपये
(२) खादी	१६.७ " "
(३) ग्राम उद्योग	३८.८ " "
(४) हस्तकारियाँ	६.० " "
(५) लघु उद्योग	५५.० " "
(६) अन्य उद्योग	६.० " "
(७) सामान्य योजनाएँ, प्रशासन, शोध आदि	१५.० " "
	२००.० करोड़ रुपये

तृतीय पंच-वर्षीय योजना में ५८६ करोड़ रुपये कुटीर, लघु एवं मध्यम वर्गों के उद्योगों के विकास के हेतु आवंटित किए गये हैं।

अभी हाल में ही हमारी केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए १० मिलियन डॉलर की धन राशि प्राप्त करने के उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 'विकास-ऋण कोष' (Development Loan Fund of U.S.) से एक अनुदान किया है। इस राशि का प्रयोग मुख्यतः लघु उद्योगों के हितार्थ मशीनरी को

आयाज करने के लिए किया जाएगा। यह मशीनरी लघु उद्योगों को किराया खरीद के आधार पर प्रदान की जाएगी।*

(IV) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation)

स्थापना—

निजी व्यवसाय को विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जुलाई, सन् १९५६ में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation) की स्थापना की गई। यह एक सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है तथा इसको अनेक देशों का सहयोग प्राप्त है। इस अन्तर्राष्ट्रीय निगम के सदस्य केवल वे ही देश हो सकते हैं, जो विश्व बैंक के सदस्य हैं। आज तक ३२ देश इसके सदस्य हो चुके हैं।

उद्देश्य—

निगम का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय सहायता द्वारा अपने सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति करना है। निम्न ढङ्गों से यह निगम इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा :—

(१) यदि पर्याप्त मात्रा व उचित शर्तों पर निजी पूँजी उपलब्ध नहीं हो रही है, तो उसकी व्यवस्था करना।

(२) विकास सम्बन्धी सुषमसूत्री, निजी पूँजी (देशी एवं विदेशी) तथा कुशलता को एकत्रित करके निकास गृह (Clearing house) के रूप में कार्य करना।

(३) देशी तथा विदेशी निजी पूँजी के उत्पादनशील विनियोग को प्रोत्साहित करना।

पूँजी—

इस निगम की अधिकृत पूँजी १०० मिलियन डालर है। प्रमुख देशों द्वारा, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की पूँजी, इस प्रकार क्रय की गई है :—

क्रम संख्या	देश	राशि (००० डालरों में)
१.	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	३५,१६८
२.	इंग्लैण्ड	१४,४००
३.	फ्रांस	५,८१५
४.	भारत	४,४३०
५.	जर्मनी	३,६५५
६.	कनाडा	३,६००
७.	जापान	२,७६८
८.	ऑस्ट्रेलिया	२,२१५
९.	पाकिस्तान	१,१०८
१०.	स्वीडन	१,१०८

* See Economic Times dated 10 March, 1956.

निगम को अपने बान्ड इत्यादि बेचकर रुपये जुटाने का अधिकार है, किन्तु सम्भवतः प्रारम्भिक वर्षों में इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अतः विनियोग के लिए उपलब्ध कोष इसकी प्राप्ति पूँजी तक ही सीमित है ।

निगम का प्रबन्ध—

निगम अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के साथ मिल कर काम करेगा, यद्यपि उसका एक पृथक् वैधानिक अस्तित्व है और उसके कोष भी बैंक से बिल्कुल पृथक् हैं । जो सरकारें बैंक की सदस्य हैं वे ही निगम की सदस्य बन सकती हैं । बैंक के ये एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर जो कम से कम एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, निगम के डाइरेक्टर का भी काम करेंगे । बैंक का प्रेसीडेंट इम बोर्ड का चेयरमैन होगा । निगम का प्रेसीडेंट बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा चेयरमैन की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है और निगम का अपना स्टॉफ है ।

विनियोग-प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए योग्यता-गुण—

(१) निगम विनियोग सम्बन्धी उन्ही प्रस्तावों पर विचार करेगा जिनका उद्देश्य किसी उत्पादक प्राइवेट उपक्रम (Productive Private Enterprise) की स्थापना, विस्तार या सुधार करना है ।

(२) निगम से वित्तीय सहायता पाने वाले उपक्रम किसी सदस्य देश में ही स्थापित होने चाहिए । प्रारम्भिक वर्षों में निगम केवल अधिकवित्त देशों के विषय में ही अपना ध्यान केन्द्रित करेगा ।

(३) निगम यह आशा करना है कि प्राइवेट विनियोग भी आवश्यक पूँजी का कम से कम आधा होगा । वस्तुतः निगम वित्तीय सहायता के लिए तभी हाथ बँट एगा जबकि प्राइवेट विनियोग यथासम्भव पूँजी दे चुके हो और शेष पूँजी समुचित शर्तों पर प्राप्त करना असम्भव हो ।

(४) प्रारम्भिक वर्षों में निगम ऐसे ही विनियोग प्रस्तावों पर विचार करेगा :—

(१) जिनमें उपक्रम का नया विनियोग कम से कम पाँच लाख अमेरिकन डालर हो, और

(११) निगम से कम से कम १,००,००० डालर की सहायता माँगी गई हो ।

(५) सहायता की अधिकतम मात्रा तो अभी निर्धारित नहीं की गई, किन्तु सामान्य नीति यह होगी कि इन्ने विने उपक्रमों में बड़ी राशियाँ लगाने की अपेक्षा पर्याप्त सख्या में समुचित मात्रा के विनियोग किय जायें ।

(६) यों तो कार्पोरेशन में औद्योगिक, कृषि, वित्तीय, व्यापारिक एवं अन्य प्राइवेट उपक्रम सभी सहायता ले सकते हैं, बशर्ते उनका कार्य उत्पादन से सम्बन्ध रखना है, तथापि प्रारम्भिक वर्षों में कार्पोरेशन उन्ही उपक्रमों को चुनेगा जो कि औद्योगिक प्रकृति के हों । वह गृह-निर्माण, अस्पताल, स्कूल आदि सामाजिक उपक्रमों

या सार्वजनिक उपयोगिता के उपक्रमों में विनियोग नहीं करेगा। निगम किसी ऐसे वित्त प्रबन्ध में भी भाग न लेगा जो कि पुनर्प्रबन्धन (re-financing) के लिये है।

(७) निगम केवल प्राइवेट उपक्रमों को सहायता देगा, सरकारी उपक्रमों को नहीं। किसी उपक्रम में सरकारी कोष लम्बे होने से ही वह निगम की सहायता से वंचित नहीं होगा, बसतैं उसका स्वभाव एक प्राइवेट उपक्रम जैसा हो।

विभिन्न विचार-योग्य प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय देते समय कॉरपोरेशन निम्न बातों का ध्यान रखेगा :—

(१) निगम की सहायता से अन्य विनियोगकों द्वारा प्राइवेट पूँजी का विनियोग कितना बढ़ जायेगा ?

(२) निगम में उसके सहयोगियों को विनियोग से लाभ की क्या सम्भावनाएँ हैं ?

(३) निगम के विनियोग करने से उत्पादन को कितना प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्तीय प्रबन्ध के रूप एवं ढंग—

निगम को यह अधिकार है कि वह किसी भी रूप में विनियोग करे, किन्तु केवल एक अपवाद यह रखा गया है कि वह पूँजी अंशों में विनियोग नहीं कर सकता, अतः निगम के विनियोग ऋण के समान होंगे, किन्तु साधारण ऋणों की भाँति नहीं होंगे। कॉरपोरेशन अपनी विनियोग निरन्तर बदलता रहता चाहता है, अतः प्रत्येक दशा में उसका प्रमुख उद्देश्य विनियोग के सम्बन्ध में ऐसा अधिकार प्राप्त करना होगा कि ऋण को अंशों में बदला जा सके। कॉरपोरेशन स्वयं इस अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, किन्तु जिसे वह अपने ऋण बेच देगा वह ऐसा कर सकेगा। इस प्रकार निगम अपने सफल विनियोगों को लाभ पर बेच सकेगा। कॉरपोरेशन यह भी चाहेगा कि रथाई ब्याज के अलावा उसे लाभों में भी कुछ भाग दिया जाय, जिससे उपयुक्त क़ौता मिलने तक वह लाभ ग्रहण कर सके।

ब्याज की दर—

ब्याज की दर प्रत्येक दशा में विशिष्ट परिस्थितियों एवं जोखिम के अनुसार निर्दिष्ट की जायेगी। निगम द्वारा दिये गये ऋणों की अवधि प्रायः ५ से १५ वर्ष तक होगी। किन्तु में भी विनियोग के भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है। निगम ऋण जमानत पर या बिना जमानत के दे सकते हैं। यदि वह जमानत लेगा तो उसका क्या रूप होगा, यह प्रार्थी की हैसियत एवं विनियोग की शर्तों पर निर्भर है।

ऋण देने की शर्तें—

वित्तीय सहायता की रकम इकट्ठी की जा सकती है या किस्तों में। इस रकम का प्रयोग प्रार्थी उपक्रम अपने सामान्य व्यापारिक कार्यों में कर सकता है, किसी विशिष्ट सेवा या माल के भुगतान में उसका प्रयोग किया जाय, ऐसा कोई प्रतिबन्ध

नहीं है। साधारणतः ऋण का भ्रमरीकी ढालरो में मूल्यांकन किया जायेगा, किन्तु उपयुक्त दशा में वह करैन्धी में भी किया जा सकता है।

निगम तब ही विनियोग करेगा जब उसे यह सन्तोष हो जाय कि प्रार्थी उपक्रम का प्रबन्धक-वर्ग योग्य एवं अनुमती है। किन्हीं आवश्यक दशाओं में निगम उपयुक्त प्रबन्धक खोजने में सहायता दे सकता है, किन्तु वह स्वयं प्रबन्ध का उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं कर सकता है। निगम सामान्यतः अपने प्राइवेट सहयोगियों से ही प्रबन्धक उपलब्ध करने की अपेक्षा रखता है। हाँ, इतना वह अवश्य चाहेगा कि प्रबन्ध में कोई बड़ा परिवर्तन करने से पूर्व उनकी राय ले ली जायेगी। वह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में अपने प्रतिनिधि भी रख सकता है।

निगम इस बात का सन्तोष प्राप्त करना चाहेगा कि उपक्रमों को वास्तव में उस ऋण की आवश्यकता है और प्रबन्धकों ने एक उपयुक्त कार्यक्रम भी तैयार कर लिया है। वह संस्था द्वारा पूँजीयत सामान और सेवाओं के खरीदने का ढग भी जीव सकता है, जिससे उसके विनियोग सुरक्षित रहे। यह भी आवश्यक है कि उपक्रम के हिसाब-किताब का सरकारी अकैसको से निरीक्षण कराया जाय तथा वे निगम के प्रतिनिधियों के लिये खुले रहे। निगम को वार्षिक खाते, प्रगति-विवरण एवं अन्य सूचनाएँ भेजी जाये। निगम के प्रतिनिधियों को सहायता लेने वाले उपक्रम के प्लान्ट, कारखाने आदि को देखने का भी अधिकार होगा।

निगम का सरकार से सम्बन्ध—

कॉरपोरेशन सरकार की गारन्टी नहीं मागेगा। हाँ, यदि देश की सरकार को आपत्ति है तो कॉरपोरेशन विनियोग नहीं करेगा। सम्बन्धित देश की सरकार को आपत्ति करने के लिये उचित अवसर प्रदान किया जाय। यदि किसी सदस्य देश की सरकार ने विदेशी विनियम पर प्रतिबन्ध लगा रखा हो तो एक साधारण विनियोगिक रूप में निगम अपने विनियोग एवं तत्सम्बन्धी लाभ के ट्रान्सफर के लिये सरकार के साथ उचित समझौता करेगा। इन सब मामलों में निगम कोई विशेष अधिकार नहीं चाहेगा।

पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम (Re Finance Corporation)

स्थापना—

यद्यपि दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में अनेक संस्थाएँ थी, किन्तु ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो कि केवल मध्यकालीन साख की व्यवस्था करती हो। अतः औद्योगिक संस्थाओं के लिए मध्यकालीन साख सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य में ५ जून, सन् १९५८ को पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना की गई। यह निगम एक स्वतंत्र अर्द्ध सरकारी संस्था है। यह निजी उद्योगपतियों की तीन में सात वर्ष के लिए ऋण प्रदान करती है।

उद्देश्य—

इस निगम का प्रमुख उद्देश्य मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसी भी एक संस्था को १० लाख रु० से अधिक ऋण नहीं मिलेगा। यह निगम इन उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से उधार नहीं देगा, बल्कि वेकों को उधार देने में सहायता पहुँचायेगा। इस निगम से केवल ऐसी ही औद्योगिक संस्थाएँ ऋण प्राप्त कर सकती हैं जिनकी दत्त और सचिन पूँजी २३ करोड़ रु० से अधिक न हो।

पूँजी—

पुनः प्रथम निगम की अधिकृत पूँजी २५ करोड़ रु० तथा निर्गमित पूँजी १२३ करोड़ रुपए है। निर्गमित पूँजी १,२५० अंश पत्रों (प्रति अंश १ लाख रुपया) में विभाजित है, जिसमें से १०% प्रावेदन पत्र और १०% आवंटन पर देना प्रावश्यक है। इस पूँजी का क्रय निम्न संस्थाओं द्वारा किया गया है :—

(१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	५० करोड़ रुपये
(२) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	२५ " "
(३) राज्य जीवन बीमा निगम (L. I. C of India)	२५ " "
(४) अन्य बैंक	२५ " "

योग १२५ करोड़ रुपये

अन्य बैंक के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ोदा, नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, युनाइटेड कॉमर्सियल बैंक, लापड्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, चार्टर्ड बैंक, इण्डियन बैंक, युनाइटेड बैंक, मरकेन्टाइल बैंक ऑफ इण्डिया, डेना बैंक (Dena Bank), तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सम्मिलित हैं।

प्रगस्त मनु १९५६ में भारतवर्ष तथा अमेरिका के बीच 'भारत प्रमरीकी कृपि' सम्बन्धी वस्तुओं का समझौता हुआ था, जिसके अनुसार भारतवर्ष को अपने निजी व्यवसाय वाली संस्थाओं को पुनः उधार देने के लिए ५५ मि० डालर या ३६ करोड़ रुपये का कोष रखा गया था। यह राशि इस निगम को दे दी गई है। २९ जुलाई मनु १९५६ का भारतीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त मन्त्री एन० सी० सेन गुप्ता तथा अमेरिका के टैक्नीकल कोऑपरेशन मिशन (T. C. M.) के सचालक श्री हावर्ड हौस्टन (Howard Houston) के मध्य हुए समझौते के अनुसार यह ५५ मिलियन डालर का ऋण अमेरिका की भारतवर्ष भारतीय मुद्रा (रुपये) में ३० वर्ष के अन्दर ध्याज सहित वापस कर देगा।

भारत सरकार समय समय पर निगम को व्याज पर ऋण देकर सहायता

करेगी और उस कोष में से उचित समय पर ऋण के पुनर्मुनान का प्रबन्ध करेगी । इस प्रकार से प्रारम्भ में निगम के पास कुल ३८'५ करोड़ रुपये (१२'५ करोड़ २० + २६ करोड़ ६०) की पूँजी होगी, जिसमें से १५ अनुसूचित बैंक में से प्रत्येक का कोटा निश्चित होगा और उसी सीमा के अन्तर्गत निगम से उस बैंक को पुनः अर्थ-प्रबन्ध की सुविधाएँ मिलेंगी ।

निगम का प्रबन्ध—

पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम का प्रबन्ध एक संचालक समिति के द्वारा होगा । इस समिति के सान सदस्य होंगे, जिसमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का गवर्नर उसका चेयरमैन होगा । शेष छः सदस्य इस प्रकार होंगे .—

- (१) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का डिप्टी गवर्नर
- (२) स्टेट बैंक आफ इण्डिया का चेयरमैन
- (३) जीवन बीमा निगम (L. I. C.) का चेयरमैन
- (४) अन्य बैंकों के तीन प्रतिनिधि ।

पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम पूर्व स्थापित औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation) की क्रियाओं में सहायता पहुँचाता है । वास्तव में आधारभूत तथा मध्यवर्गीय उद्योगों को अपनी जीर्ण मशीनों तथा साज-सज्जाओं के परिवर्तन के लिए तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होनी थी, जिसकी पूर्ति अब पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम से होने लगेगी । इस प्रकार इस निगम का औद्योगिक क्षेत्र में विशेष महत्त्व है ।

निगम की क्रियाओं का व्यौरा—

३१ दिसम्बर सन् १९६० को अन्त होने वाले वर्ष तक पुनर्वित्त निगम की क्रियाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगम का कार्य क्षेत्र दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है । आलोच्य वर्ष में पुनर्वित्त के हेतु ८ बैंकों से ४५६'५० लाख रुपये के लिए निगम के पास २५ आवेदन पत्र आये, जबकि गत वर्ष केवल ३ बैंकों ने २२३ लाख ६० के लिए ही प्रार्थना पत्र दिए थे । इस प्रकार सदस्य बैंकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली पुनर्वित्त की राशि लगभग दुगुनी हो गई । १४ प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में निगम ने १७५ लाख ६० की राशि स्वीकार की, किन्तु वास्तव में १४१ लाख ६० ही प्रदान किया गया किन्तु यह राशि भी गत दो वर्षों में प्रदान की हुई राशि (जो ८५ लाख ६० थी) से कहीं अधिक है ।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक निगम ने कुल २२६ लाख ६० की राशि (Total Disbursement) प्रदान की, जिसमें से २१६ लाख ६० की राशि अदत्त (Out Standing) थी । निगम के कार्यों के व्यौरे के अवलोकन से इन बात का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि पुनर्वित्त (Refinance) की माँग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । जवाहरराज के लिये अनेक जनवरी, फरवरी सन् १९६१ में ही ८८'४५ लाख ६० के पुनर्वित्त की माँग निगम के सम्मुख आई । जैसा कि निगम के

चेयरमेन श्री एच० वी० आर० आयरर (H. V R. Iengar) ने कहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में निगम का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जायेगा ।

इस वर्ष भी निगम द्वारा ऋण देने की दर ५% प्रति वर्ष ही है । अभी हाल में निगम ने अपने ऋण लेने वाला पर दो शर्तें लगा दी हैं—(१) ऋण लेने वाली सस्थाओं (अर्थात् बैंकों) को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिस दर पर वे निगम से ऋण लें और जिस पर औद्योगिक सस्थाओं को ऋण दें, उनके बीच बम से कम १½ % का अन्तर हो । (२) यदि स्थानीय वित्तीय सस्थाओं द्वारा औद्योगिक सौधों को सुगम ढर्रे पर ऋण मिल जाता है और पुनर्वित्त की दशा में उनको वे सुविधायें नहीं मिलती, तो ऐसी परिस्थिति में पुनर्वित्त की मांग करने वाली सस्थाओं को ऋण नहीं प्रदान किया जायेगा ।

आलोच्य वर्ष में निगम को २८-८६ लाख रु० की कुल आय हुई । गत वर्ष यह राशि २६-५७ लाख रु० थी । आय में कमी होने के कारण निगम को लाभ इस वर्ष केवल १६-३६ लाख रु० ही हुआ । गत वर्ष लाभ की राशि २०-०२ लाख रु० थी ।

प्राप्ति—

निगम के अध्यक्ष के अनुसार पुनर्वित्त निगम का क्षेत्र औद्योगिक अर्थ निगम तथा औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम की अपेक्षा अधिक संकुचित है । यह निगम केवल मध्यकालीन ऋण (अर्थात् तीन वर्ष से सात वर्ष के लिये) दे सकता है । अतः इस निगम की सुविधायें केवल उन निगमों के लिये उपयुक्त हैं जो सात वर्ष के अंदर ऋण का भुगतान कर सकें ।

सुझाव—

निगम के संचालक ने इसके क्रिया क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये निम्न-लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं —

(१) अधिक से अधिक बैंकों को चाहे वे निगम में सदस्य हों अथवा न हों पुनर्वित्त निगम की सुविधायें प्रदान करना है ।

(२) उन समस्त उद्योगों को जो विकास योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, सुविधायें प्रदान करना है ।

(३) निगम द्वारा लिये गये ऋण और इस ऋण को पुनः देने पर व्याज की दर में अन्तर कम से कम १½% प्रतिशत का हो, इस प्रतिबंध को दूर करना ।

ये सुझाव केन्द्रीय सरकार तथा भारता स्थित संयुक्त राष्ट्र तांत्रिक सहयोग आंदोलन (U. S Technical Cooperation Mission) के विचाराधीन हैं ।

भविष्य—

निगम का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होता है, क्योंकि उपरोक्त सुझाव लगभग स्वीकार कर लिये गये हैं। इन सुझावों के अनुसार कार्य करने के लिये निगम ने ४३ व्यापारिक बैंको, १४ राज्य अर्थ निगमों और ३ राज्य सहकारी बैंको के मध्य पुनर्वित्त की योजना का विस्तार करने का निश्चय कर लिया है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उसके संबंध में भी वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधायें प्रदान की जायेंगी। लेकिन इसके लिये गारंटी संगठन द्वारा प्रत्याभूति की आवश्यकता है।

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि निगम का कार्य क्षेत्र अवश्य बड़ेगा।

विनियोग प्रत्यास

(Investment Trusts)

विनियोग प्रत्यास वे वित्तीय संस्थायें हैं जो व्यक्ति विनियोक्ता को, चाहे उसके साधन कितने भी कम क्या न हो, इस योग्य बनाने के उद्देश्य से गठित की जाती हैं कि वह एक ही विनियोग में विविधता (Diversification) के लाभ प्राप्त कर सके। प्रत्यास विभिन्न कोटि के स्कन्धों, अथवा तथा ऋण-पत्रों में अपने कोष का विनियोग करते हैं, अतः विनियोग प्रत्यास के असहारी विनियोक्ताओं का जोखिम कई जगह बँट जाता है। यह उल्लेखनीय है कि विनियोग प्रत्यास प्रतिभूतियों को नियन्त्रण के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, बल्कि विनियोग के उद्देश्य से खरीदते हैं। इसी बात में वे सूत्रधारी कंपनियों से भिन्न हैं। प्रास ध्याज और लाभश में से वे अपनी प्रतिभूति पर ध्याज तथा लाभश चुकाते हैं।

विनियोग कंपनी या प्रबन्ध प्रत्यास (Discretionary Trust) में सचालकों को प्रतिभूतियों के मौलिक चुनाव तथा बाद में उसमें विनियोग के समय परिवर्तन की पर्याप्त छूट देना है। चूंकि समय-समय पर प्रतिभूतियों का चुनाव करना प्रबन्धकों का काम है, इसलिए प्रबन्ध-प्रत्यास को विवेकाधीन प्रत्यास भी कहा जाता है। यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को उक्त विवेकाधिकार दिया जाये, वे सदा चौकन्ने तथा सावधान रहें। उन्हें अपने विशेष क्षेत्र में व्यापारी, उसाही, सत्यवादी, उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखने वाला होना चाहिए।

लाभ—

(१) इकाई प्रत्यास के सामान्य लाभ, जैसे—वैविध्यकरण (Diversification), विशिष्ट ज्ञान तथा सतत निरीक्षण प्राप्त होते हैं।

(२) विनियोक्ता को अपनी पूँजी पर अधिक लाभ अर्जन करने में समर्थ करता है।

- (३) सभी प्रकार के लोगो को अपनी बचतें निरापद तथा लाभप्रद सरणि में विनियोग करने की योग्यता प्रदान करता है ।
- (४) प्रबन्ध व्यय कम होता है, क्योंकि हजारों व्यक्तियों के विनियोग का थोड़े विशेषज्ञ लोग प्रबन्ध कर सकते हैं ।
- (५) यह विनियोग प्रत्यास साधारण विनियोक्ता को सट्टेबाजी से दूर रखता है तथा हद कम्पनियों के अनुपात को बढ़ाता है ।
- (६) जो जोखिम उठाता है वही नियन्त्रण करता है ।

श्रुटियाँ—

- (१) प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आ सकता है जो अयोग्य हों ।
- (२) चूंकि प्रबन्ध को प्रतिभूतियों के चुनाव का सोलहो आने अधिकार दे दिया जाता है, इसलिए निरर्थक सम्बन्धी भूखों का जोखिम भी रहता है ।

सीमित प्रबन्ध प्रत्यास (Flexible Trusts)—

पहला दो वर्गों के प्रत्यासों के बीच का मार्ग है । इस प्रकार का प्रत्यास एक ओर तो नियत प्रत्यास की अनम्यता को दूर करता है और दूसरी ओर प्रबन्ध प्रत्यास के प्रबन्धाधिकारियों के विवेकाधीन अधिकार में कटौती करता है, अर्थात् सीमित विवेकाधिकार देता है ।

विनियोग को निरुत्साहित करने वाले कारण—

(१) राष्ट्रीयकरण का भय—यह सही है कि योजना में प्राइवेट विनियोजन का महत्त्व दिया गया है तथापि देश में ऐसी व्यापक धारणा फैली हुई है कि प्राइवेट उपक्रम विकास के साधन के रूप में 'सहन' किया जा सकता है, 'स्वीकार' नहीं । औद्योगिक नीति की घोषणा से भी यह प्रकट होता है कि सरकार किसी भी समस्या को, सामाजिक हित में या प्राइवेट उपक्रम द्वारा असन्तोष द आश्चर्य दिए जाने की दशा में, अपने अधिकार में ले सकती है । इसी प्रकार उद्योग (विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम भी सरकार को यह अधिकार देता है कि किसी भी अनुसूचित उद्योग या संस्था की जाँच पड़ताल के लिए आदेश दे । इस प्रकार हर समय प्राइवेट उपक्रम के ऊपर राष्ट्रीयकरण का डर मँडराया करता है, अतः जिन उद्योगों में विशाल पूँजी लगती है और लाभों का अर्जन कुछ वर्षों के पश्चात् आरम्भ होता है उनमें प्राइवेट विनियोगक हिचकते हैं । विदेशों से भी प्राइवेट पूँजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है । कम से कम सरकार ऐसे उद्योगों में, जिनका जल्दसे ऊपर किया गया है, राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कुछ आश्वासन दे सकती है ।

(२) उद्योगों का नियन्त्रण—सरकार ने नियन्त्रण सम्बन्धी जो अधिकार प्राप्त किये हैं उनके कार्यान्वित होने में कुछ अनिश्चिन्नाय एवं कठिनाइयाँ हैं । जैसे, एक नई इकाई की स्थापना या विद्यमान इकाइयों में विस्तार अथवा किसी नए प्रकार की वस्तु बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, नये पूँजी निगमन के लिए

कन्ट्रोल ऑफ कंपीटल इश्यूज से आज्ञा लेनी पड़ती है, मशीनों व अन्य सामान के आयात के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करनी पड़ती है। जहाँ एक ओर इन आदेशों का उद्देश्य आर्थिक विकास को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करना है, वहाँ यह दोष भी है कि इन कार्यों में देरी बहुत लग जाती है। प्रत्येक कदम पर अधिकारियों को सन्तुष्ट करना पड़ता है, अतः यह आवश्यक है कि इस कार्य विधि को सरल बनाया जाय, जिससे अनावश्यक देरी न लगे।

(३) सरकार की श्रम नीति—जिन परिस्थितियों में आज श्रम की निपुणता की जाती है वे पहले की अपेक्षा बहुत बदल गई हैं। मजदूरी के सामान्य स्तर में तो वृद्धि हुई है, किन्तु साथ में उनको अनेक प्रकार से सतिपूर्ण भी देनी पड़ती है। इन सब बातों से श्रम-लागत बहुत बढ़ गई है और उद्योगपतियों को अनुशासन रखने में भी कठिनाई हो रही है। वह उद्योग की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की संख्या में घटा-बढ़ी नहीं कर सकता। उसे यह भी सुविधा नहीं है कि वैज्ञानिकों की योजनाओं उद्योग में लागू कर सके।

(४) विशेष नियन्त्रण—कुछ उद्योगों पर विशेष नियन्त्रण लगाये गये हैं। जैसे, लोह एवं स्पाय, बोयला व सीमेंट उद्योग। इनके मूल्य नियंत्रित कर दिये गये हैं और उत्पादन के विवरण पर भी नियन्त्रण लगा दिया गया है। मिलों द्वारा धोतियों का उत्पादन भी सीमित कर दिया गया है। इन नियन्त्रणों के फलस्वरूप आन्तरिक प्रसाधनों का उद्योग के विस्तार के लिए अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता।

(५) बचत की प्रवृत्तियाँ—युद्ध युग और युद्ध के बाद वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि हो गई है। कर भी बढ़ते जा रहे हैं। अतः स्थायी आय वालों की बचत-क्षमता बहुत घट गई। यही नहीं, सामाजिक एवं राजनैतिक परिघटनो के फलस्वरूप राजे महाराजे, जमींदार आदि समस्त हो गये हैं, जिसमें विनियोग बाजार को बड़ा झटका लगा है। अनाज का मूल्य बढ़ने से ग्रामीण जनता की आमदनी में अक्षय्य वृद्धि हुई है, किन्तु उसकी बचत क्षमता पर, जो कि पहले नहीं के बराबर थी, बहुत कम प्रभाव पड़ सका है। वास्तव में देश में आय का पुनर्वितरण हो रहा है। जिनकी बचत क्षमता नहीं थी, उनकी बचत-क्षमता किंचित बढ़ गई है, जबकि अधिक बचत-क्षमता वाले व्यक्ति कम होते जा रहे हैं। यह ऐसी प्रवृत्ति है जो विनियोग के लिए प्रतिकूल है।

(६) प्रबन्ध की दुर्बलतायें—बाहरी वारणों के अलावा स्वयं प्राइवेट साहस की कुछ ऐसी बुराईयाँ हैं जिनके कारण विनियोग सुविधा से उपलब्ध नहीं होते। प्रबन्ध अभिवर्तनों में बार-बार परिवर्तन होना, व्यापार के संचालन में दूषित कार्य-वाहियाँ करना, इन्होंने विनियोगको के मन में शङ्का का बीज बो दिया है, अतः हमारे प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने कार्यों में जनता में विश्वास उत्पन्न करें। इस दिशा में व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों से बड़ी सहायता मिल सकती है।

मध्यम वित्त निगम

(Medium Finance Corporation)

जून सन् १९५८ मे मध्यम वित्त निगम की स्थापना की गई। इस निगम का प्रधान कार्यालय बम्बई मे है। यह निगम पंच-वर्षीय योजना मे सम्मिलित निजी क्षेत्र के मध्यम कारखानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस निगम की पूँजी ३१ करोड़ रु० है, जिसमे से ५ करोड़ रुपया १५ बैंको से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित बैंको के प्रतिनिधि निगम के सचालक मण्डल मे है — (१) स्टेट बैंक, (२) सेंट्रल बैंक, (३) पञ्जाब नेशनल बैंक (४) इलाहाबाद बैंक, (५) बैंक ऑफ इण्डिया, (६) हैदराबाद बैंक, (७) बैंक ऑफ बड़ोदा, (८) नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, (९) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, (१०) चारटर्ड बैंक, (११) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया तथा देना बैंक। इन बैंको के प्रतिनिधि विशेष प्रशिक्षण के हेतु अमेरिका भेजे गये हैं।

निगम की शेष २६ करोड़ रु० की पूँजी भारत सरकार ने इसे ऋण स्वरूप प्रदान की है। आशा ही नहीं, वरन् पूर्ण विश्वास है कि मध्यम वर्गीय उद्योगों को निगम से बड़ी सहायता मिलेगी।

STANDARD QUESTIONS

1. Describe the functions of (a) National Industrial Development Corporation and (b) National Small Industries Corporation
2. Attempt a lucid note on the International Finance Corporation
3. What do you know about Refinance Corporation ?
4. What is Industrial Credit and Investment Corporation of India ? What part is it expected to play in the provision of Industrial Finance in India ?
5. Describe briefly the principal factors which inhibit private investment in industries at the present time in India.
6. What do you mean by 'Investment Trusts' ? Describe its classifications

अध्याय ४१

पूँजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम

(Capital Issues Control Act)

भूमिका—

पूँजी निर्गमन पर नियन्त्रण द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियों की उपज है। १७ मई सन् १९४३ को भारत सरकार ने डिफेंस ऑफ इन्डिया एक्ट के अन्तर्गत पूँजी के निर्गमन पर नियन्त्रण लगाया, जिसका उद्देश्य पूँजी बाजार के उपलब्ध न्यून साधनों को सरकारी प्रतिभूतियाँ में आकर्षित करना था, जिससे कि सरकार को फौजी कार्यों में सुविधा हो जाय। अप्रैल सन् १९४७ में इसका स्थान 'पूँजी-निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम' में ले लिया। इस अधिनियम की भूमिका में पूँजी के निर्गमन पर नियन्त्रण जारी रखने का उद्देश्य अनभिज्ञ विनियोगिका का कम्पनी प्रवर्तकों की स्वायत्तपूर्ण कार्य-वाहियों से बचाना (जो कि औद्योगिक संगठन के सामान्य सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए युद्ध अनिष्ट तेजों के समय में एक के बाद एक अनगिनती कम्पनियाँ खड़ी करते जा रहे थे) और देश के उपलब्ध साधनों का उद्योग, कृषि और सामाजिक सेवाओं के मध्य समुचित विनियोग का अवसर देना था। प्रारम्भ में इस अधिनियम के प्रभावशील रहने की अवधि तीन वर्ष रखी गई थी, किन्तु बीच-बीच में इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है। सन् १९५६ से बजट अधिवेशन में इसे स्थाई रूप दे दिया गया। इस अवसर पर भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने उक्त अधिनियम को जारी रखने की आवश्यकता को निम्न शब्दों में बतलाया, "यह (कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज) योजना की आवश्यकतानुसार पूँजी के प्रवाह का नियन्त्रण एवं नियमन करने के लिए प्रशासन के हाथों में एक महत्वपूर्ण हथियार है।"

पूँजी निर्गमन अधिनियम की मुख्य बातें—

पूँजी निर्गमन अधिनियम का प्रशासन कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(I) पूँजी निर्गमन के लिए सरकारी स्वीकृति—

(१) विदेशों में पूँजी के निर्गमन पर प्रतिबन्ध—भारत में समामेलित कोई भी कम्पनी केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना भारत के बाहर पूँजी का निर्गमन नहीं कर सकेगी।

पूँजी निर्गमन अधिनियम की प्रमुख बातें

(I) पूँजी निगमन पर प्रतिबन्ध—

(१) सरकार की स्वीकृति के बिना विदेशों में पूँजी का निगमन नहीं।

(२) भारत में भी पूँजी का निगमन नहीं।

(३) प्रविवरण के निगमन पर रोक।

(४) विदेशों में अनाधिकृत निगमन में विनियोग करने पर रोक।

(५) भारत में अनाधिकृत निगमन में विनियोजन पर रोक।

(II) सरकारी स्वीकृति के लिए आवश्यक बातें—

(१) प्रवक्तृ व सचालको द्वारा २०% भाग लेना।

(२) मतदान अधिकार पूँजी के अनुपात में।

(३) मूल्यांकन विवेचन की रिपोर्ट।

भी व्यक्ति भारत में या भारत से बाहर पूँजी के उम निगमन के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिभूति के लिए न तो धन लेगा और न देगा।

(५) अनाधिकृत निर्गमन की प्रतिभूतियों के व्यवहारों पर रोक—कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत निगमन वाली प्रतिभूतियाँ का क्रय-विक्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकता।

(II) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए आवश्यक बातें—

केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति या अनुमति मिलना निम्न बातों पर निर्भर है—

(१) प्रवक्तृ व सचालको द्वारा २०% भाग लेना—प्रवक्तृ, सचालको उनके मित्रों एवं सम्बन्धियों को प्रविवरण का निगमन करने के पूर्व प्रस्तावित पूँजी निगमन का कम से कम २०% भाग स्वयं ही लेना चाहिये।

(२) मतदान अधिकार पूँजी के अनुपात में—इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एवं फाइनेंस कंपनियों की दशा में विभिन्न प्रकार के शेयरहोल्डरों के मतदान सम्बन्धी अधिकार पूँजी अभिदान (Capital contribution) के अनुपात में होने चाहिए।

(२) भारत में पूँजी के निर्गमन पर प्रतिबन्ध—कोई भी कंपनी, चाहे उसका सम्मेलन भारत में हुआ है या भारत से बाहर, केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना भारत में (१) पूँजी का निर्गमन नहीं करेगी, (११) प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव (Public Offer) नहीं करेगी और (१११) भारत में भुगतान होने वाली किसी भी प्रतिभूति के भुगतान की तिथि स्पष्टित नहीं करेगी।

(३) प्रविवरण के निर्गमन पर रोक—जब तक पूँजी-निर्गमन के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति न मिल जाय, तब तक कोई व्यक्ति भारत में प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए कोई प्रविवरण या प्रलेख जारी नहीं कर सकता।

(४) विदेशों में धन के विनियोजन पर रोक—जब तक केन्द्रीय सरकार ने पूँजी निगमन के लिए मान्यता या सहमति प्रदान न कर दी हो तब तक कोई

ऐसी कम्पनियों को मैनेजिंग एजेंट न रखने चाहिए, पूँजीगत साम शेयरहोल्डरों में न बाँटना चाहिए और पूँजी का विनियोग भी कुछ शर्तों के अन्तर्गत ही करना चाहिये ।

(३) विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट—जब कोई कम्पनी किसी जायदाद या व्यापार को बड़े बड़े मूल्य (Inflated Price) पर खरीद रही है या गुडविल का सही-सही मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ से मूल्यांकन रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करना चाहिए ।

(III) नियंत्रण का अपवाद—

अधिनियम ने उक्त नियंत्रण से उन कम्पनियों को मुक्त रखा है जो किसी १२ महिने की अवधि में १ लाख रुपया से अधिक की प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं करती हैं । यह अपवाद बैंकिंग और धोमा कम्पनियों के लिए नहीं है ।

अधिनियम की आलोचना—

पूँजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम की बड़ी आलोचना हुई है, जिनका सारांश यह है—

(i) नियंत्रण का दृष्टिकोण ऋणात्मक (Negative approach) है, अर्थात् जबकि नियंत्रण को यह व्यवस्था प्रवाहिन दिशाओं में प्रसाधनों के प्रवाह को रोकने में प्रभावशाली है, बाह्य दिशाओं में पूँजी को प्रभावित करने में वह इतनी प्रभावशाली नहीं है ।

(ii) औद्योगिक विकास एवं नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जो लाइसेन्सिंग बमेट्री बनाई गई है उसके कार्यों के साथ इसका कर्तव्य टकराता है ।

(iii) यह नई कम्पनियों के निर्माण में बाधा डालता है ।

(iv) १ लाख से कम की प्रतिभूतियों के निर्गमन की भी छूट नहीं मिलनी चाहिये ।

(v) अधिनियम के प्रादेशों का उचित पालन कराने के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था (Machinery) नहीं है ।

यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय, तो हमें प्रतीत होगा कि उक्त आलोचनाएँ पूर्णतः सत्य नहीं हैं ।

(१) नियंत्रण का दृष्टिकोण—नियंत्रण का ऋणात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ के लिये पूँजी बाजार का सही-सही अनुमान होना अति आवश्यक है । जब

पूँजी निगमन नियन्त्रण अधिनियम की पाँच आलोचनाये

- (१) नियन्त्रण का अणुात्मक दृष्टि-
कोण ।
- (२) लाइसेन्सिंग कमेटी के कार्य के
साथ इसके कर्त्तव्यों का टकराव ।
- (३) नई कम्पनियों के निर्माण में
बाधा ।
- (४) छोटे निगमनों की छूट अनुचित ।
- (५) प्रादेशा का पालन कराने के
लिये उचित व्यवस्था का अभाव ।

तक विनियोग के लिये किसी अवधि
विशेष में उपबन्ध हो सकने वाली पूँजी
की मात्रा का सही-सही अनुमान न होगा
तब तक विनियोग को वांछित दिशाओं
में मोड़ा नहीं जा सकता । दुर्भाग्य से
भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान
संरचना में प्राइवेट पूँजी की मात्रा का,
जो कि उरसब्ध हो सकती है, सही
अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(२) लाइसेन्सिंग कमेटी के कार्य
के साथ इसके कर्त्तव्यों का मेल—यह
आलोचना मलत है कि औद्योगिक विकास
एवं नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत

लाइसेन्सिंग कमेटी के होते हुये पूँजी निगमन पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता नहीं
है । यह विचार वास्तव में उक्त औद्योगिक अधिनियम के सम्बन्ध में अधूरे ज्ञान के
कारण उत्पन्न होता है । औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स लेने की आव-
श्यकता तब पड़ती है जबकि एक नई औद्योगिक संस्था की स्थापना की जा रही हो,
किसी विद्यमान उद्योग का व्यापक विस्तार किया जाना हो और नई वस्तुओं का
निर्माण करना हो । यह अधिनियम ७३ उद्योगों को लागू होता है । प्लांटेशन,
बैंकिंग, बीमा कम्पनियों एवं अनेक अ-औद्योगिक कम्पनियों का इस अधिनियम में कोई
उल्लेख नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उक्त ७३ उद्योगों में जो
विस्तार किया जाना है वह 'व्यापक' (substantial) न हो । ऐसी दशा में औद्यो-
गिक अधिनियम लागू नहीं होगा । इसी प्रकार, औद्योगिक विकास अधिनियम में
क्षेत्रीय क्षेत्रों के नियमन का भी कोई उल्लेख नहीं है, यद्यपि ये क्षेत्रीय कॉरपोरेशनों के
वित्तीय ढाँचे का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं । यही नहीं, ऐसी कई बातें हैं जो कि
औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आती,
जैसे—पूँजी निगमन की शर्तें, अभियोपन की रकम, क्षेत्रीय पर दलाली, विदेशी
विनियोगों का नियमन आदि । इन बातों पर पूँजी नियन्त्रण अधिनियम के द्वारा ही
शासन रखा जा सकता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि कंपोर्टल इश्यूज कंट्रोल एक्ट का
औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम से घृष्क एक निश्चित स्थान है । हाँ,
यह आवश्यक है कि लाइसेन्सिंग कमेटी और कंट्रोल आफ् मेसिट्स इश्यूज के मध्य
पारस्परिक सहयोग होना चाहिये, जिससे प्रशंसा पत्रों को शीघ्रता से निपटाया जा सके ।

(३) नई कम्पनियों के निर्माण में बाधा—कुछ सीमा तक यह आक्षेप
सही है कि कंपोर्टल इश्यूज कंट्रोल नई कम्पनियों की स्थापना में बाधक सिद्ध हुआ है ।
वास्तव में इसे बाधक न होकर उचित मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होना चाहिये ।

(४) छोटे निर्गमनो की छूट अनुचित—इसी प्रकार ५ लाख ६० तक पूँजी के निर्गमन के लिये जो छूट दी गई है उसे काफी घटाकर १ लाख ६० कर देना चाहिये, तभी नियन्त्रण अधिक प्रभावशाली हो सकेगा । इससे नियन्त्रण का क्षेत्र बढ जायेगा, किन्तु, दूसरी ओर, छोटे-छोटे अनेक प्रार्थना पत्रों पर विचार करने में अधिक श्रम व व्यय होने की सम्भावना है ।

(५) आदेशों का पालन कराने के लिये उपयुक्त सस्था होना—कंपीटल इश्यू कन्ट्रोल सम्बन्धी आदेशों का पालन कराने के लिए किसी उपयुक्त व्यवस्था का न होना इस अधिनियम की एक बड़ी दुर्बलता है । प्रार्थियों को यह अनिवार्य नहीं है कि वे कन्ट्रोल अधिकारियों को वास्तविक विनियोगों की, यह सूचना देने रहें । कन्ट्रोल ऑफ कंपीटल इश्यूज द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं वे स्वीकृत आदेशों के अनुसार किए गये वास्तविक विनियोगों की मात्रा प्रकट नहीं करते । जो रिटर्न कंपनियों से मगाई जाते हैं, वे भी कन्ट्रोलर के पास समय पर नहीं पहुँचती । अतः इस दिशा में कठोर उपाय करना चाहिए । सौभाग्य से अब एवाइन्ट स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रारों के कार्यालयों में इस कार्य के लिए पृथक विभाग बना दिये गये हैं । आशा है कि अब ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त करना सरल हो जायगा ।

कन्ट्रोल ऑफ कंपीटल इश्यूज का महत्व—

भारत में औद्योगिक विकास के लिए पूँजी की बड़ी कमी है । अतः इस दृष्टि से कन्ट्रोल ऑफ कंपीटल इश्यूज का महत्व भली प्रकार समझ में आ जाना चाहिए । उचित दशाओं में न्यून पूँजी साधनों का विनियोग केवल कन्ट्रोल द्वारा ही सम्भव है । इस प्रकार यह अधिनियम हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं की पूर्ति में बड़ा सहयोग देगा, वह अनावश्यक या कम आवश्यक कार्यों में पूँजी का विनियोग रोकता है । वह नई एवं पुरानी दोनों ही सस्थाओं की पूँजी संरचनाओं का नियमन करते हुए अवांछित कार्यवाहियों को (जैसे अनुचित मताधिकार वाले शेयर जारी करना) रोकता है, वह कॉरपोरेशनों की वित्तीय योजनाओं में असंतुलन होने से बचाता है, वह इस बात की जाँच रखता है कि निर्गमन के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, वह अनभिज्ञ विनियोगों को चालाक प्रवर्तकों के चंगुल से बचाता है और उनकी कार्यवाहियों पर शंकुश रखता है, शेयरहोल्डर्स एवं लेनदारों के लाभार्थ कंपनियों की पुनर्गठन सम्बन्धी योजनाओं की सावधानी से जाँच करता है, ग्राइवेट एवं पब्लिक क्षेत्र में पूँजी साधनों का संतुलन रखना है और विदेशी विनियोगों का नियमन करता है ।

कन्ट्रोल ऑफ कंपीटल इश्यूज की प्रगति—

नीचे दी हुई तालिका १ में यह दिखाया गया है कि प्रति वर्ष कितनी मात्रा में पूँजी निर्गमन के लिये स्वीकृति मिली थी और मांगी हुई स्वीकृति की मात्रा का कितना प्रतिशत है । मांगी हुई स्वीकृति से मिली हुई स्वीकृति का प्रतिशत (percentage) प्रति वर्ष बदलता रहा है । सन् १९४० के बाद, केवल सन् १९५२

को छाड़ कर जब कि ५०-५० करोड रु० के दो प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिये गये थे, मांगी हुई स्वीकृति की मात्रा से मिली हुई स्वीकृति की मात्रा का प्रतिशत सदा ८०% से अधिक रहा है। इससे स्पष्ट है कि नियन्त्रण अधिनियम ने प्राइवेट क्षेत्र में वित्तियोग के स्वीकृत स्वरूप में कोई बाधा नहीं डाली है।

तालिका १

वर्ष	स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या	स्वीकृत पूँजी निर्गमनों की मात्रा (करोड रुपये में)	स्वीकृति मांगी हुई मात्रा से स्वीकृति मिली मात्रा का प्रतिशत
१९४७ (प्रग० से दिस०)	१५५	५४२	..
१९४८	३७५	१२५७	७५.०
१९४९	३२६	६३०	८६.७
१९५०	२६३	७४८	८७.९
१९५१	३४३	५९६	८७.२
१९५२	२५४	३९८	२६.१
१९५३	२३२	८१४	९०.५
१९५४	२२०	११०६	९४.४
१९५५	२८९	१२५४	८२.७
१९५६	२९७	२३०.१	९०.४
१९५७	३४५	१५३३	८३.९

यह उल्लेखनीय है कि सन् १९४५ और सन् १९४९ के मध्य स्वीकृत औद्योगिक निर्गमनों का प्रतिशत ५० से ६० तक था, जब कि सन् १९४९ से सन् १९५१ के मध्य यह ७०-८० रहा और सन् १९५१ से १९५४ के मध्य ८०-९० हो गया। इस प्रकार औद्योगिक निर्गमनों को अ औद्योगिक निर्गमनों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई थी। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक निर्गमनों का प्रतिशत कुछ घट गया है। नई कम्पनियों के प्रारम्भिक पूँजी निर्गमनों और विद्यमान कम्पनियों के अतिरिक्त निर्गमनों के आँकड़ों से यह प्रगट होता है कि प्रारम्भिक निर्गमनों की अपेक्षा अतिरिक्त निर्गमनों के लिए अधिक स्वीकृति मिली है।

तालिका २

वर्ष	नई कम्पनियों के प्रारम्भिक निर्गमन		विद्यमान कम्पनियों के प्रतिरिक्त निर्गमन		
	रकम	स्वीकृत कुल निर्गमनो का प्रतिशत	रकम (करोड़ रु० में)	बोनस शेयर	अन्य
	(करोड़ रु० में)				निर्गमनो का प्रतिशत
१९४८	६३४	५०४	२३४	३८९	४९६
१९४९	७४७	४०६	१०१	२७२	५८७
१९५०	१३७	१८३	८५	५२६	८१७
१९५१	२१६	३६२	१०८	२७२	६३८
१९५२	१२७	३१९	७८	१९३	६८१
१९५३	१८३	२२६	१४७	४८३	७७४
१९५४	५७९	५२३	९९	४२८	४७७
१९५५	४६९	३८३	६५	७२०	६१७
१९५६	८०३	२८६	८५	१४१३	७१४
१९५७	४३३	२८२	१५४	९४६	७१८

उक्त तालिका के आँकड़ों पर ध्यान देने से निम्न महत्वपूर्ण बातों का भी पता चलता है — (१) कुल स्वीकृत निर्गमनो के साथ प्रारम्भिक निर्गमनो के प्रतिशतों का औसत सन् १९४८ व सन् १९५५ के मध्य ३६ था, जबकि अतिरिक्त निर्गमनो के प्रतिशतों का औसत इही आठ वर्षों के लिए ६४ था। सन् १९५७ में ये औसत क्रमशः २८ और ७२ हो गये। इससे स्पष्ट है कि विद्यमान इकाइयों के विकास के लिए पूँजी निर्गमनो को नई कम्पनियों की स्थापना के लिए पूँजी निर्गमनो की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। (२) स्वीकृत किये गये अतिरिक्त निर्गमनो (Further Issues) का लगभग पाँचवाँ भाग बोनस शेयरों का है। इससे स्पष्ट है कि बोनस शेयरों का पूँजी संरचना में कितना महत्व है। सन् १९४८ के अंत में सरकार ने उम छूट को समाप्त कर दिया जो कि ५ लाख रु० की सीमा तक बोनस शेयरों का निर्गमन करने के सम्बन्ध में उपलब्ध थी। सरकार ने यह नीति अपनाई कि कम्पनियों के पास न तो बहुत बड़ा रिजर्व हो और न बहुत अधिक मुक्ता-पूँजी। बोनस शेयरों के निर्गमन पर भी नियन्त्रण लगा कर सरकार न चालू बाजार मूल्यों के आधार पर स्थाई संपत्ति का मूल्य अपलिखित करने की परिपाटी पर अंकुश लगाया है। सन् १९४९ में सरकार ने बोनस शेयरों के निर्गमन के सम्बन्ध में कुछ उदार नीति अपनाई। किन्तु सन् १९५४ तक उसकी यह नीति दिलमिल ही रही थी। अन्त में, सन् १९५५ में सरकार ने अधिक स्पष्ट नीति ग्रहण की और सन् १९५६ में उसने बोनस शेयरों के निर्गमन पर २ भा० प्रति हफ्ता की दर से सुपर टैक्स लगाया। सन् १९५७ में पूँजी निर्गमन

नियन्त्रण अधिनियम का सशोधन किया गया। इसने यह स्पष्ट कर दिया गया कि अपूर्ण दत्त शेयरों को पूर्ण दत्त बनाने के लिए अथवा विद्यमान शेयरों का अंकित मूल्य बढ़ाने के लिये कोषों के पूँजीकरण के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है।

पूँजी निर्गमन के लिये स्वीकृति प्राप्त करने की विधि—

यह अनुभव किया जाना है कि प्रार्थियों को पूँजी निर्गमन के लिए स्वीकृति माँगने वाले प्रार्थना-पत्र में दी जाने वाली आवश्यक बातों का ज्ञान होने से प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृति देने में देर हो जाती है। श्री केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यविधि पर पूर्ण प्रकाश डाला है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

पूँजी निर्गमन के लिये स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यविधि

- (१) कंट्रोलर को संशुद्ध प्रार्थना पत्र देना।
- (२) प्रार्थना पत्र में सब आवश्यक बातें देना।
- (३) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रकाशित अन्तिम खाने-ब प्रास्पेक्टस की प्रतिलिपियाँ भेजना।

(१) कंट्रोलर को संशुद्ध प्रार्थना-पत्र देना—पूँजी निर्गमन के लिये स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु सर्व प्रथम एक प्रार्थना-पत्र (पाँच प्रतियों में) कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इस्यू को देना होगा। यह प्रार्थना पत्र उस फॉर्म में होना चाहिए, जिसकी विस्तृत बातें कंट्रोलर के ऑफिस से पत्र भेज कर माजूम की जा सकती है। प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी रसीद भी नरथी कर देनी चाहिए। यह ५० रु० के बारे में है, जो कि शुल्क के रूप में केन्द्रीय सरकार के खाते में XLVI शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराने पड़ते हैं।

(२) प्रार्थना पत्र में दी जाने वाली आवश्यक बातें—प्रार्थना-पत्र में निम्न बातें देना आवश्यक है, अन्यथा बारम्बार लिखा-पढ़ी होने से उसकी स्वीकृति में देर होने की संभावना है—

- (i) प्रार्थना-पत्र देने वाली कम्पनी का नाम, उसकी हैसियत (प्रभात वह प्राइवेट कम्पनी है या पब्लिक कम्पनी), उसके रजिस्ट्रेशन का स्थान और उसके प्रधान कार्यालय का पता।
- (ii) विद्यमान एवं प्रस्तावित अधिकृत, याचित एवं दत्त पूँजी की रकम एवं उसका स्वभाव।
- (iii) यदि पहले भी कोई प्रार्थना-पत्र दिये गये हो, तो उनकी सूचना।
- (iv) प्रस्तावित व्यापार का स्वभाव।
- (v) कम्पनी के संचालकों एवं मैनेजिंग एजेंटों के नाम, पते आदि तथा कम्पनी में उनके हित का विवरण।
- (vi) प्रस्तावित पूँजी निर्गमन की रकम, प्रकृति एवं शर्तों के बारे में सूचना।

अर्थात्, इन्विटी, प्रीफेरन्स, डिबेन्चर, अथवा बोनस शेयर, शेयरों का वितरण (पब्लिक को प्रास्पेक्टस के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शेयरों की मात्रा स्पष्ट करते हुये) ।

(१११) ऋण प्रस्तावों की सूचना, जिनके लिये कंपोस्ट इश्यू की स्वीकृति जरूरी हो ।

(११११) यदि प्रस्तावित योग्यता में विदेशी सहयोग लिया जाता है, तो उसकी सूचना, जैसे—विदेशी सहयोग कर्ता कितना धन लगायेगा, बदले में क्या लेंगे, सरकार से इस सहयोग के लिये स्वीकृति मिल चुकी है या नहीं, देशी एवं विदेशी मुद्रा में अनुमानित व्यय आदि ।

(११२) क्या उद्योग (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेना जरूरी है ? यदि जरूरी है, तो क्या लाइसेंस ले लिया गया है या प्रार्थना-पत्र दे दिया गया है । यदि लाइसेंस मिल गया है तो उसकी प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी कर देनी चाहिये । यदि लाइसेंस नहीं मिला है, तो प्रार्थना-पत्र का हवाला दे देना चाहिये । यदि पूँजी की आवश्यकता सम्बन्धी अनुमानों का भी, जिनके आधार पर लाइसेंस मिला है या मांगा गया है, विवरण प्रार्थना-पत्र में देना चाहिये ।

(३) प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी किये जाने वाले प्रलेख—यदि पूँजी या ऋण लेने वाली कंपनी पहले से ही कार्य सलग्न है, तो प्रार्थना-पत्र के साथ उसके अन्तिम प्रकाशित वार्षिक खाते सलग्न करना आवश्यक है । यदि इन वार्षिक खातों से सम्बन्धित भवधि के बाद १ वर्ष या इससे अधिक समय गुजर गया हो, तो अन्तिम वित्तीय वर्ष के परिणाम दिखाने वाला एक कच्चा विवरण (Proforma Statement) भी प्रार्थना पत्र के साथ फाइल करना होगा । यदि प्रास्पेक्टस के द्वारा जनता को पूँजी प्रस्तावित की जा रही है, तो प्रार्थी को चाहिये कि प्रास्पेक्टस का ड्राफ्ट बना कर सरकार की समीक्षा व सुझाव के लिये भेजे । यदि कोई अन्य सूचना सम्बन्धित विषय पर प्रकाश डालने वाली हो, तो उसे भी प्रार्थना-पत्र में दे देनी चाहिये ।

(४) कंट्रोल आफिम दिल्ली से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं परामर्श—प्रवक्तृक, संचालक एवं उनके प्रतिनिधि समय समय पर कंपोस्ट इश्यूज कंट्रोल अधिकारियों से नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और प्रारम्भिक एवं औपचारिक बातों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं । इससे उन्हें यह मालूम हो जाना है कि प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम या वैकल्पिक ढङ्ग क्या हो सकता है, जिससे उस पर सरकार स्वीकृति दे दे । इस प्रकार का व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही पक्षों के लिए लाभदायक होता है ।

(५) प्रार्थना-पत्र पर निर्यात—जब कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता है, तो उस पर तत्काल ही कार्यवाही की जाती है । प्रार्थना पत्र की सूचना को सावधानी

से जाँचा जाता है। यदि पूँजी सरचना उचित एवं पर्याप्त है, यदि प्रस्ताव कम्पनी अधिनियम के प्रादेशों के विपरीत नहीं है, यदि प्रार्थना पत्र की बातें औद्योगिक लाइसेन्स की शर्तों से संगत रखती है, तो निर्गमन पर स्वीकृति दे दी जाती है।

यदि कोई सन्देह की बात प्रनीत होती है तो अन्य मन्त्रालय या मन्त्रालयों से परामर्श लिया जा सकता है। यदि प्रार्थना-पत्र में दी गई सूचना अपूर्ण या अस्पष्ट है, तो प्रार्थी को स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना देने के लिए लिखा जाता है। यदि प्रार्थना-पत्र का कोई प्रस्ताव कन्ट्रोल व्यवस्था के किसी सिद्धान्त से टकराना है, तो उसमें उपयुक्त परिवर्तन करने के सुझाव प्रार्थी को दिये जाते हैं। यदि स्पष्टीकरण के लिए व्यक्तिगत वार्तालाप आवश्यक समझा जाय, तो कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि को दिल्ली बुलवाया जाता है। उसके साथ हुए विचार-विमर्श के सन्दर्भ में कोई निर्णय होता है।

उपसंहार—

एकदम ही अस्वीकार किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। जब कम्पनी को औद्योगिक लाइसेन्स मिलने का आश्वासन तो है, लेकिन अभी वह मिला न हो या जब उसे विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों पर सरकार की सामान्य स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन विस्तृत बातों पर स्वीकृति नहीं मिली हो अथवा जब कम्पनी सम्मिश्रण की किसी विशेष योजना पर स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देना चाहती हो, तभी पूँजी निर्गमन सम्बन्धी स्वीकृति दे दी जाती है।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss the objects and important provisions of the Capital Issues Control Act. How far do you think its working to be satisfactory?
2. Outline the procedure for getting consent to capital issue

अध्याय ४२

विदेशी पूंजी

(Foreign Capital)

भूमिका—

किसी भी देश के आर्थिक विकास में पूंजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजी 'बचत' का परिणाम है और बचत तब होती है जबकि चालू उपभोग से आय अधिक हो। एक पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था में बचते अपर्याप्त होती हैं। परिणामतः वहाँ पूंजी की कमी देखी जाती है। यही नहीं, पूंजीगत माल की कमी टेक्नीकल साज सामान व ज्ञान एवं योग्यता की कमियाँ भी एक पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था की विशेषतामें हैं। इस सन्दर्भ में विदेशी पूंजी के महत्व को सहज ही समझा जा सकता है। वास्तव में "विदेशी पूंजी ने पिछले कुछ वर्षों में हुये विकासो में एक चमत्कारिक भूमिका प्रस्तुत की है तथा विदेशी सहायता ने अर्द्ध विकसित देशों में उन आकस्मिकताओं की पूर्ति की है जो उन देशों के घरेलू साधनों की शक्ति के बाहर की बात थी। भारत-ऐसा ही एक देश है जिसने विदेशी पूंजी की सहायता से वर्तमान प्रगति की है। प्रस्तुत अध्याय में भारत में विदेशी पूंजी की समस्या पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

भारत में विदेशी पूंजी का इतिहास

मोटे तौर पर, विदेशी पूंजी ने भारत में तीन रूपों में प्रवेश किया, अर्थात् इनसे सम्बन्धित तीन प्रावश्यकतायें दृष्टिगोचर होती हैं—प्रथम, व्यापारिक पूंजी (Merchant Capital), जिसकी अवधि अठारहवीं शताब्दी तक है, द्वितीय, औद्योगिक पूंजी (Industrial Capital), जिसने १९वीं शताब्दी में अपना प्रभाव दिखाया, जो अभी तक जारी है; और तिसरा, वित्तीय एवं ऋण पूंजी (Finance and Loan Capital), जिसका विकास हाल में ही हुआ है।

(१) व्यापारिक पूंजी की अवस्था—

इस देश में पुर्तगाली सर्व प्रथम विदेशी पूंजी लाये। इन्होंने भारतीय बाजारों में भारतीय माल खरीदने तथा युरोपियन बाजारों में बेचने के लिये एक व्यापारिक

कम्पनी बनाई। यह समय ऐसा था जबकि हमारे कुटीर एवं सधु उद्योग देश में उन्नति के शिखर पर थे। अपने व्यापार के लिये माल की नियमित पूर्ति बनाये रखने के लिये उन्होंने भारतीय कारीगरों को ऋण व पेसगी रकम देने प्रारम्भ की। बाद में डच एवं ब्रिटिश व्यापारियों ने भी यही नीति अपनाई। इन व्यापारिक कम्पनियों द्वारा दी गई पूँजी को 'व्यापारिक पूँजी' कहा जा सकता है। एक सन्धे सघर्ष के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने धीरे-धीरे एकाधिकार प्राप्त कर लिया। किन्तु यह एकाधिकार बहुत समय तक नहीं चला। औद्योगिक क्रान्ति का जोर बढ़ने पर इङ्ग्लैण्ड में भारत से आयात किये हुये निमित्त माल के विरुद्ध कटु विरोध होने लगा। इङ्ग्लैण्ड निमित्त माल नहीं बरन् कच्चा माल अपने तेजी से विकसित होने वाले उद्योगों के लिये खरीदना चाहता था। उसे निमित्त माल के बेचने में दिलचस्पी थी, न कि खरीदने में। अतः 'व्यापारी पूँजीपतियों' को व्यापार का स्वरूप बदलना पड़ा। वे भारत को निमित्त माल लाने लगे और देशी उद्योगों का प्रोत्साहन देने के बजाय दवाने लगे। इसी अवधि में ब्रिटिश सरकार ने सन् १७७३ के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी में छीन लिया। इस प्रकार भारत में विदेशी पूँजी की प्रथम अवस्था का अन्त हो गया।

(२) औद्योगिक पूँजी की अवस्था—

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में, भारतीय बाजार ब्रिटिश सरकार की स्वतन्त्र व्यापार नीति के फलस्वरूप विदेशी साहसियों के लिये खोल दिया गया। स्थानीय व्यापारी दुर्बल थे और पूँजी बर्माही थी। ब्रिटिश पूँजीपतियों ने भारत में अपने कोष लगाने प्रारम्भ कर दिये। प्रारम्भ में तो यह पूँजी कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उद्योगों में लगाई गई। धीरे-धीरे निमित्त माल के लिये अधिकाधिक बड़े बाजार और अधिकाधिक कच्चे माल की आवश्यकता के होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था की उन्नति करना भी जरूरी हो गया, ताकि निर्यात व आयातों के प्रवाह में रुकावट न आ जाय। सन् १८५७ में प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के कारण राजनैतिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से भी यातायात की व्यवस्था को विकसित करना आवश्यक हो गया था। अतः व्यापार के समय में एकत्र हुई सम्पत्ति अब रेलों, सड़कों, सिंचाई व कोयला खानों के विकास के लिये 'औद्योगिक पूँजी' के रूप में भारत में आने लगी। पूँजीपतियों ने यह अनुभव किया कि भारत से इङ्ग्लैण्ड को कच्चे माल के आयात में और इङ्ग्लैण्ड से भारत को निमित्त माल के यातायात में दुहरा व्यय होता है। भारत में ही उद्योग प्रारम्भ कर दिये जायें, तो इस दुहरे व्यय से बचा जा सकता है। इस प्रकार भारत में जूट एवं सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई। उसी अवधि में तीन प्रेसीडेन्सी बैंक एवं कुछ विनिमय बैंक भी स्थापित हुये। वे विदेशी पूँजीपतियों के लिये शक्ति का एक महान् साधन बन गये। लेकिन इस युग में औद्योगिक पूँजी मुख्यतः यातायात एवं कच्चे माल के उत्पादन में सभी तथा उद्योगों के विकास में काम नहीं आ सकी।

(३) ऋण पूंजी का प्रारम्भ—

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में, ब्रिटिश पूंजी का भारत में सही अर्थानुसार औद्योगिक पूंजी के रूप में आगमन हुआ। कई घटकों ने इस पूंजी के आगमन को प्रोत्साहित किया। प्रथम, यातायात एवं बगीचा उद्योग में लाभदायक विनियोग पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। दूसरे, भारत में ब्रिटिश बाजार संकुचित होने लगे थे; अतः इस हानि को भारत में उद्योगों में विनियोजन करके प्राय की वृद्धि द्वारा पूरा करने की कोशिश की गई। तीसरे, विश्व युद्ध ने भारत में ही उद्योगों के विकास की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि युद्ध काल में आयात रुक जाने से अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की कमी का कटु अनुभव हुआ था। सामरिक एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी भारत में उद्योगों की स्थापना होनी आवश्यक समझी गई। कुछ उद्योगों को सन् १९२३ में संरक्षण मिलने से भारतीय पूंजी भी सचय में से निकल कर उद्योगों में विनियोजन के लिए आनी प्रारम्भ हुई है।

विदेशी पूंजी की तीसरी अवस्था अभी हाल ही में प्रारम्भ हुई है। व्यापार सतुलन के घाटे को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने विदेशों से ऋण लेने प्रारम्भ किये। भारतीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को भी अपने विदेशी सहयोगियों से आर्थिक सहायता मिलने लगी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से भी ऋण लिये गये हैं। ये सभी ऋण एडवान्स के रूप में हैं। इनकी विशेषता यह है कि विदेशी ऋणदाता केवल इस बात में रुचि रखते हैं कि उनका मूल धन तथा निर्धारित व्याज नियमित रूप से मिलता रहे। वे उद्योग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं। भविष्य में ऐसी पूंजी हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भूदा करेगी।

भारत में विदेशी पूंजी की समस्या

देश के सामने एक बड़ी समस्या विदेशी पूंजी की है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इसके विरुद्ध शक्तिशाली आवाजें उठाई गई हैं। प्रायः कहा जाता है कि इसके कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर बहुत तनाव पड़ता है, जो इसे पनपने नहीं देता। देश की राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ भी उसका मेल नहीं बैठता। सीमाव्य से हम विदेशियों की राजनैतिक दासता का बंधन तोड़ने में तो सफल हुये हैं लेकिन सभी प्रकार के व्यापारों व उद्योगों में विनियोजित विशाल पूंजी के रूप में विदेशी प्रभुत्व अभी तक जारी है। लेकिन, इसके विपरीत, अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। वह विदेशी विनियोजक को सकटकाल में अपना अमूल्य सहायक समझते हैं। इसके अतिरिक्त, अब तो विदेशी पूंजीपतियों की कार्यवाहियों का नियंत्रण करना भी सम्भव हो गया है। अतः विदेशी पूंजी को क्यों न स्वीकार किया जाय, जबकि हमारी निजी पूंजी अपर्याप्त है। इस प्रकार भारत में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में दो विरोधी विचारधारायें प्रचलित हैं।

किन्तु यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि विदेशी पूँजी का विरोध मुख्यतः इसके विनियोजन स्वरूप से है। विदेशी पूँजी कई रूपों में विद्यमान है। विनियोग या साहसी पूँजी देश के प्राकृतिक साधनों का शोषण करती है। अतः इस परिस्थिति में विदेशियों के स्थाई हित विकसित होने लगते हैं और इसकी रक्षा के लिये राजनैतिक दम उठाये जाते हैं। किन्तु ऋण एवं एडवान्स पूँजी की दृष्टि में, विदेशी ऋणदा कोई जोखिम अपने ऊपर नहीं लेते। वे तो अपने व्याज व मूलधन की वापिसी हित रखते हैं। अतः पहली प्रकार की पूँजी ही शरारत कर सकती है। इसका विरोध करना उचित ही है।

भारत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता—

विदेशी पूँजी भारत को निम्न प्रकार से लाभदायक हुई है और भविष्य में होगी :—

(१) औद्योगीकरण की गति बढ़ाने के लिये—भारत में विदेशी पूँजी ने औद्योगीकरण की प्रगति में सहायता पहुँचाई है तथा देश की पञ्च-वर्षीय योजना

भारत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता क्यों ?

- (१) औद्योगीकरण की गति बढ़ाने के लिये।
- (२) आवश्यक वस्तुओं व सेवायें आयात करने के लिये।
- (३) उद्योगों के विकास की प्रारम्भिक जोखिम उठाने के लिये।
- (४) टेक्नीकल ज्ञान की प्राप्ति के लिए।
- (५) देश में रोजगार बढ़ाने के लिये।
- (६) देश के उत्पादकों के समक्ष स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करने के लिये।

के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के वर्तमान एवं भावी प्रयासों में सहायता दे रही एवं देगी। अनेक कारणों से देश में उद्योगों के लिये धन की कमी रही है। साथ गरीब हैं, उनकी बचत क्षमता सीमित है, भारतीय पूँजी परम्परा से लजीली है, भारतीय व्यवसाई व्यापारी पृष्ठे उद्योगपति बाद में। इन सब कारणों पूँजी की माँग एवं पूर्ति में भारी अन्तर है, जिसे विदेशी पूँजी की सहायता से वर्य किया जा सकता है।

(२) आवश्यक वस्तुयें व सेवा आयात करने के लिये—भारत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता इसलिये और अधिक अनुभव की गई है कि हमारे निर्यात बेलोच स्वभाव के हैं, जबकि हमें विदेश

से खाद्यान्न, कच्चा माल, मशीनरी व टेक्नीशियनों की सेवायें आयात करनी पड़ती हैं स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा की अधिक माँग होगी, जिसे एक लम्बी अवधि तक विदेशी ऋणों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

(३) उद्योगों के विकास की प्रारम्भिक जोखिम उठाने के लिये—उद्योगों के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में प्रवर्तन का कार्य बहुत जोखिमपूर्ण

होता है तथा प्रायः हानि उठानी पड़ती है। विदेशियों को, विदेशी पूँजी ग्रहण करके, प्रारम्भिक जोखिम उठाने के लिये प्रेरित किया जा सकता है और बाद में जबकि उद्योग सुस्थापित हो जायें, तब स्वदेशी पूँजीपति या सरकार उनके हितों को क्रय कर सकती है।

(४) टेक्नीकल ज्ञान की प्राप्ति के लिये—विदेशी पूँजी के साथ-साथ हमें टेक्नीकल ज्ञान भी प्राप्त होता है। घरेलू उत्पादक इस सम्बन्ध में विदेशी पूँजीपतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

(५) देश में रोजगार बढ़ाने के लिये—विदेशी पूँजी के कारण देश में रोजगार के प्रषस्तर बढ़ जायेंगे, क्योंकि केवल उच्च अधिकारी ही विदेश से आते हैं और अधिकांश बलकों व मजदूरों की नियुक्ति तो विदेशी पूँजी मँगाने वाले देश के निवासियों में से ही की जाती है।

(६) देश के उत्पादकों के समक्ष स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करने के लिये—विदेशी पूँजी का आगमन स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करता है। विदेशियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये देशी उत्पादकों को भी अपनी उत्पादन की टैक्नीक में सुधार करना पड़ता है। इससे उनकी कुशलता बढ़ जायेगी।

विदेशी पूँजी की आलोचनाएँ—

भारत में विदेशी पूँजी के आयात की निम्न प्रमुख आलोचनाएँ हैं :—

(१) प्रसाधनों का दोषपूर्ण शोषण—सर जार्ज पैश (Sir George Paish) के अनुसार भारत में ६७% विदेशी पूँजी सन् १९१४ के पूर्व सरकारी कार्यों में, यातायात, बगीचा उद्योग एवं वित्त व्यवस्था में लगी हुई थी। इस प्रकार विदेशी पूँजी का प्रयोग भारत के व्यापारिक शोषण के लिये हो रहा था, देश के औद्योगिक विकास से उसका कोई सम्बन्ध न था। इससे देश के असन्तुलित विकास को प्रोत्साहन मिला और उसके साधनों का समुचित शोषण नहीं होने पाया।

(२) सरक्षण नीति का अनुचित आश्रय—विदेशियों ने अपनी शाखाएँ व पहायक कम्पनियाँ भारत में रजिस्टर्ड राई और इस प्रकार उन्हें भारतीय आर्थी का रूप देकर प्रत्येक सरक्षण का लाभ उठाया।

भारत में विदेशी पूँजी का विरोध क्यों ?

- (१) प्रसाधनों का दोषपूर्ण शोषण।
- (२) सरक्षण नीति का अनुचित आश्रय।
- (३) औद्योगिक शक्ति का केन्द्रीयकरण।
- (४) भेदभाव की मनोवृत्ति।
- (५) स्वदेशी सस्थाओं से प्रतिस्पर्धा।
- (६) ऊँची लागत एवं अधिक लाभ।
- (७) जुने हुये क्षेत्र।
- (८) अस्थाई अवधि।
- (९) राजनैतिक शक्तें।

(३) औद्योगिक शक्ति का केन्द्रीयकरण—प्रबन्ध अधिकर्ता प्रणाली पूर्ण

रूप से विदेशी कार्यान्वितियों की भेंट है। इसी प्रणाली के कारण एक ही नियंत्रण के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थाओं का वित्तीय, प्राबन्धिक एवं प्रशासनिक गठबन्धन सम्भव हुआ। अन्य देशों के असमान, भारत में स्वामित्व एवं नियंत्रण का केन्द्रीयकरण मुख्यतः विस्तार के द्वारा हुआ है, न कि सम्मिश्रण या विलियन द्वारा, क्योंकि प्रबन्ध अभिकर्ता ही नवीन संस्थाओं के जन्मदाता, पालक एवं संचालक रहे हैं।

(४) भेदभाव की मनोवृत्ति—वर्तमान छाताब्दी के प्रारम्भ में, विशेषतः द्वितीय महायुद्ध के पूर्व, विदेशी व्यापारिक इकाइयों ने साख, बीमा और यातायात के मामले में जातीय एवं राजनैतिक भेदभाव की नीति अपनाई थी। कर्मचारियों को रोजगार देने, विशेषतः उच्च पदस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करने के विषय में भारतीयों के साथ भेदभाव करता जाता था।

(५) स्वदेशी संस्थाओं से प्रतिस्पर्द्धा—विदेशी पूँजी के प्रवेश का विरोध इस आधार पर भी किया गया है कि स्वदेशी संस्थाओं की प्रतिस्पर्द्धा कुशलता विदेशी संस्थाओं की अपेक्षा कम होती है, जिससे देशी व्यवसायों को हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार, रिवर्स (Rivers) के शब्दों में, 'विदेशी फर्मों की आलोचना उनकी दुर्बलताओं या दावा के कारण नहीं बल्कि गुणा के कारण की गई है। स्वदेशी उद्योग-पतियों ने विदेशी फर्मों का इस कारण विरोध किया, क्योंकि वे उनकी अपेक्षा अधिक कुशल थी तथा कठिनाइयों का भली प्रकार सामना कर सकती थी।'

(६) विदेशी पूँजी की ऊँची लागत—विदेशी प्राइवेट पूँजी के प्रयोग की लागत बहुत अधिक पड़ती है। भारत में अमेरिकी विनियोगों पर १६ २% और कनेडियन विनियोगों पर ३३ ३% पुरस्कार दिया गया था, जबकि ब्रिटिश विनियोगों पर बहुत ही उचित केवल ६ ५% लाभ दिया गया। इस प्रकार अमेरिकी एवं कनेडियन पूँजी बहुत ही महंगी है। इसका हमारे सीमित साधनों पर बहुत बोझ पड़ता है। अतः भारत विदेशी पूँजी का स्वीकार नहीं कर सकता।

(७) चुने हुए क्षेत्र—प्राइवेट विदेशी विनियोगों के सम्बन्ध में यह बात देखी जाती है कि विदेशी पूँजी उन उद्योगों में लग रही है जिन पर पूँजी निर्यातक देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, विदेशी कोष कुछ चुने हुए क्षेत्रों में एवं निष्कर्ष उद्योगों में लग रहे हैं, स्थानीय उपभोग की वस्तुओं उत्पादन करने वाले उद्योगों में नहीं। उदाहरण के लिये, एक अनुमान के अनुसार सन् १९४७-४९ के मध्य अमेरिका की प्राइवेट पूँजी का ७८% भाग अर्द्ध विकसित देशों में गया और इसका भी ६०% भाग निष्कर्षण उद्योगों में लगा, जो औद्योगिक प्रगतिशील देशों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्यात करते थे।

1. What brought foreign business in for criticism was not its fault but its virtues. Foreign firms were resented by domestic industrialists because they were more efficient and could stand up better in hard times." (W. F. Rivers "The Position of Foreign Business in India Today," p. 27.)

(८) अस्थाई अवधि—विदेशी पूँजी कभी भी वापिस ली जा सकती है और वह उद्योगों का स्थायी साधन नहीं होती । अतः इस पर निर्भर रहना खतरनाक होता है । मौलिक एवं आधारभूत उद्योगों में तो विदेशी पूँजी का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिये । युद्ध काल में इन उद्योगों के सम्बन्ध में विदेशी पूँजीपतियों पर निर्भर होना अ-नूतनीतिक है ।

(९) राजनैतिक शर्तें—पूँजी की सहायता के साथ-साथ राजनैतिक शर्तों के जुड़ा होने का भी कटु अनुभव है । विश्व नेता विश्व-बन्धुत्व, समानता व न्याय की बातचीत तो करते हैं लेकिन उनके कार्यक्रमों से अपना ही प्रभुत्व जमाने की भावना प्रगट होती है । उदाहरण के लिये, अमेरिका अर्द्ध-विकसित देशों को बहुत आर्थिक सहायता दे रहा है, लेकिन ऐसा मुख्यतः उन देशों को कम्युनिस्ट कैम्प में जाने से रोकने के लिये है । ईरान, मिस्र, मलाया व इन्डोचीन से संघर्ष इस बात के प्रमाण है कि विदेशी सहायता किस प्रकार देश को दासता के बन्धन में जकड़ देती है, जिससे छुटकारा पाना फिर सहज नहीं होना ।

विदेशी पूँजी के लिये उचित क्षेत्र—

ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उससे यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि भारत में विदेशी पूँजी का इतिहास उसकी सेवाओं और कुमेवाओं के दृष्टान्तों से भरा पड़ा है । नये उद्योगों का प्रवर्तन (जैसे जूट, कोयला, चाय, व कहवा प्लांटेशन पहली बीमा कम्पनी व जहाजी कम्पनी) सफल विनियोजन एवं आश्चर्यजनक दूरदर्शिता के लिये विदेशी पूँजी को जहाँ सराहना की जावेगी वहाँ अत्यधिक शोषण, आर्थिक प्रभुत्व एवं राजनैतिक दासता के लिये उसकी बुराई भी करनी होगी । भूतकाल में विदेशी पूँजी की भूमिका कौसी भी रही हो, उसे हमारे नियोजित आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भवा करनी है । देश में पंच-वर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है । औद्योगीकरण हमारा एक निश्चिन एवं प्रमुख लक्ष्य है । इसकी पूर्ति के लिये प्लांट एवं मशीनरी के रूप में विशाल मात्रा में स्थाई पूँजी तथा बच्चा माल खरीदने व आवृत्तक व्ययों को चुकाने के हेतु कार्यशील पूँजी की आवश्यकता है । किन्तु हमारे आन्तरिक साधन इस आवश्यकता के लिये पर्याप्त नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, विदेशी टेक्नीशियनों की सेवाओं से भी वंचित रहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ टेक्नीकल ज्ञान का प्रसार बहुत सीमित है । अभी हमें अधिकाधिक पूँजीगत माल आयात करना है । इन सब बातों के कारण विदेशी पूँजी की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप ऐसी पूँजी के प्रयोग के विरुद्ध जन विरोध कुछ नर्म हो गया है । विदेशी पूँजी की हानियों का सावधानी से विश्लेषण करने पर हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि अधिकांश हानियाँ विदेशी 'पूँजी' से नहीं बरन् 'विदेशी नियन्त्रण' से सम्बन्धित हैं । अतः यदि हानियों के सम्बन्ध में उचित सावधानी रखी जाय और यदि विदेशी पूँजी को विदेशी नियन्त्रण और प्रभाव से मुक्त रखा जा सके,

तो बहुत लाभ उठाया जा सकता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, यह विनियोग या साहस पूँजी (Investment or Entrepreneurial Capital) ही है, जिसको सीमित करने की हमें आवश्यकता है। देश में आजकल इसकी इतनी विशाल मात्रा है कि देशी पूँजी साधन इसे खरीदने में असमर्थ हैं। अतः विदेशी साहस को धीरे-धीरे समाप्त करना ही उचित होगा। यह भी उचित होगा कि भारतीयों को वर्तमान एवं भावी विदेशी सस्यानों से सम्बन्धित किया जाय, ताकि वे टेक्नीक सीख सकें, आवश्यक ट्रेनिङ्ग पा सकें और प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव भी प्राप्त कर लें। विदेशियों को भयभीत करना ठीक न होगा। भारत को चाहिए कि विदेशी पूँजी के दौलतानी करने वाले पहले में धीरे-धीरे किंतु निश्चित रूप से चतुरतापूर्वक कमी करे।

इस सम्बन्ध में एक अन्य आवश्यक एवं ध्यान देने योग्य बात यह है कि भूतकाल में तो विदेशी पूँजी सरलता से प्राप्त होती रही थी, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो सकेगा। युद्ध काल में, लगभग प्रत्येक देश में विदेशी पूँजी की बापसी पर प्रतिबन्ध लगा दिये। परिणामतः अनेक दशकों में विदेशियों को उचित न्याय नहीं मिला। अतः हम देखते हैं कि विशाल मात्रा में विदेशी पूँजी एवं अथवा एक देश से दूसरे देश को अधिक सुरक्षा की खोज में भटक रही है। इससे यह प्रगट होता है कि अब हम अपनी ही शर्तों पर विदेशी पूँजी पर्याप्त न मिल सकेगी। आज के ससार में, जबकि पूँजी की कमी विश्वव्यापी है, कोई देश विदेशी पूँजी पर प्रतिबन्ध लगा कर विदेशी पूँजी-पतियों को देश से भागने पर ही विवश कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि जब एक बार हमने विदेशी पूँजी की आवश्यकता अनुभव कर ली है, तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण नर्म होना चाहिए।

विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति

स्वतन्त्रता के पूर्व नीति—

बहुत समय तक भारत में विदेशी पूँजी स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवाहित होती रही और ग्रेट ब्रिटेन की पूँजी का बाहुल्य रहा। ब्रिटिश पूँजी विशेषतः उन उद्योगों में विनियोग की गई जिनके द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का प्रभावशाली नियन्त्रण रह सके और अत्यधिक लाभ हो। इसी प्रकार, आर्थिक जीवन के उन्हीं अंशों का विकास किया गया जो कि ब्रिटिश माल के आयात को आवश्यक बनावें। विदेशी पूँजी ने कभी भी भारत में नियोजित और संगठित आर्थिक विकास का विचार नहीं किया। ब्रिटिश पूँजीपति असहाय भारतीयों के हितों का बलिदान करके अनाप-शनाप लाभ कमा रहे थे। भारतीयों को विदेशी सस्यानों में काम करने व कमाने के बहुत कम अवसर प्राप्त थे।

बहुत समय तक विदेशी पूँजी के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण सक्रिय प्रोत्साहन एवं प्रत्यक्ष सहायता देने का रहा। भारतीय प्रशुल्क आयोग सन् १९२२ ने

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विदेशी पूँजी के महत्त्व की विवेचना की थी। अधिकांश सदस्यों की यह सिफारिश थी की विदेशी पूँजी के प्रवेश पर कोई रोक न लगाई जाय, लेकिन आयोग का अल्पमत कुछ प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में था। सरकार ने बहुमत के सुझाव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने भेदात्मक सरक्षण का सिद्धान्त अपनाया। अनेक दशाओं में यह नीति विदेशी पूँजी को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने के स्तर तक उदार कर दी गई।

विदेशी पूँजी समिति सन् १९२५ में पुनः सम्पूर्ण स्थिति पर विचार किया। वह विदेशी पूँजी के आयात को प्रोत्साहित करने के पक्ष में थी। लेकिन उसने इस बात पर बल दिया कि विदेशी पूँजीपति को प्रोत्साहन देने की प्रत्येक योजना में मुख्य लाभ भारत को दिलाना चाहिए। उसने यह भी सिफारिश की थी कि एक सर्वसाधारण रियायत योजना में (जैसे कि सरक्षण में) भारतीयों और विदेशियों के मध्य कोई भेद भाव न किया जाय। समिति के मत में विदेशी कम्पनी को रियायतें तब ही देनी चाहिए जबकि वह भारतीयों को ट्रेनिङ्ग की सुविधायें व अवसर देने को तैयार हो जाय। किन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जनता समय-समय पर सरकार की उपेक्षा के विरुद्ध आवाज उठाती रही।

स्वतन्त्रता के पश्चात् विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति—

स्वतन्त्रता के पश्चात् विदेशी पूँजी के प्रति भारतीय अर्थशास्त्रियों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुत बदल गया है, क्योंकि (१) हमारी प्रगति के लिये देशी बचतों की क्षमता से कहीं अधिक साधनों की आवश्यकता है, (२) अरुणी देशों के श्रमकरदार भुगतान-संतुलनों की समस्याओं का अधिक अच्छा अन्तर्राष्ट्रीय समाधान हो सकता है, (३) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना ने विदेशी पूँजी को एक सुपरनेशनल रूप प्रदान कर दिया है, और (४) स्वतन्त्रता की प्राप्ति से देश की विदेशी पूँजी के अवांछित प्रभावों से बचाने की सरकार की क्षमता में बिश्वास बढ़ गया है। अतः यह समझा जाने लगा है कि यदि उपयुक्त शर्तों पर विदेशी पूँजी मिल सके, तो उसका स्वागत किया जाय।

६ अप्रैल सन् १९४८ को जारी किये गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सरकार ने भारत में विदेशी पूँजी के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट किया। इस प्रस्ताव में सहयोग से सम्बन्धित निम्न शर्तों को स्पष्ट किया गया था :—

- (१) विद्यमान विदेशी स्वार्थों से यह आशा कि वे भारत की औद्योगिक नीति की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। भविष्य में विदेशी पूँजी के आयात के लिए उसे भारतीय पूँजी के समान सुविधा मिलेगी तथा पारस्परिक लाभ के आधारे की खोज की जायेगी।
- (२) विदेशी पूँजी के लिये द्रव्य स्थानान्तरण की विद्यमान सुविधायें मिलती रहेंगी और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें खरीदा जा सकता

है। किन्तु विद्यय राशि के स्थानान्तरण की पूर्ण सुविधा देकर ही ऐसा किया जावेगा।

- (३) खरीदे जाने की दशा में, विदेशी हितों को उचित एवं न्यायसंगत क्षति पूर्ति दी जावेगी।
- (४) जब उपयुक्त भारतीय उपलब्ध न हो, तो टेक्निकल योग्यता एवं अनुभव वाले पदों पर अभारतीयों की नियुक्ति के प्रति सरकार को कुछ आपत्ति न होगी, लेकिन ऐसे पदों के लिये विदेशी सस्था भारतीयों की दृष्टि के लिये व्यवस्था करेगी।
- (५) सरकार किसी भी तरह से भारत में ब्रिटिश या अन्य अ-भारतीय हितों को नुकसान नहीं पहुँचावेगी, बसतों वे अर्थ व्यवस्था के विकास में सहकारक एवं सहकारिक भूमिका चुलाते रहे।

तत्पश्चात् अनेक अवसरों पर भारतीय प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा इस नीति को पुनः दोहराया गया है। भारतीय योजना आयोग ने भी इस नीति को स्वीकार किया। बाद में विदेशी पूँजी के आयात को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने ऐसे सब विदेशी पूँजीपतियों को लाभ के भुगतान की विशेष सुविधा प्रदान की है जो अपनी पूँजी सन् १९५० से सरकार द्वारा स्वीकृत उद्योगों में लगावेगी। किन्तु यह एक आवश्यक शर्त बना दी गई है कि भारत में विदेशियों द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले प्रत्येक भागी उद्योग में प्रबन्ध एवं स्वामित्व में मुख्य हिस्सा भारतीयों का होगा। विद्यमान विदेशी पूँजी कंपनियों की दशा में विद्यमान सुविधायें केवल दो शर्तों पर ही जारी रखी जायेंगी — (i) वे भारतीय हितों के प्रति भेदभाव की नीति नहीं अपनावेगी, और (ii) वे भारतीय कर्मचारियों को सभी प्रकार के कामों के लिये प्रशिक्षित करने के हेतु सभी समव सुविधायें देगी।

1. "The stress on the need to regulate, in the national interest, the scope and manner of foreign capital arose from past association of foreign capital and control with domination of the economy of the country. But circumstances to day are quite different. The object of our regulation should, therefore, be the utilisation of foreign capital in a manner most advantageous to the country. Indian capital needs to be supplemented by foreign capital, not only because our national savings will not be enough for the rapid development of the country on the scale we wish, but also because in many cases scientific, technical and industrial knowledge and capital equipment can best be secured along with foreign capital" (Prime Minister Nehru in a statement in Parliament on April 6, 1948).

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ पर विदेशी पूँजी के विरुद्ध पुनः वाद-विवाद छिड़ गया। संभवतः यह विचार प्रथम पंच-वर्षीय योजना के काल में पर्याप्त विदेशी सहायता न मिलने के कारण उत्पन्न हुआ था। सरकारी प्रवक्ताओं व नेताओं ने भी जो बयान दिये हैं उनसे यह प्रगट होता है कि उनका भी विश्वास विदेशी पूँजी में कम हो गया था। दिसम्बर सन् १९५५ में प्रधान मन्त्री ने कांग्रेस की ससदीय पार्टी के समक्ष कहा था कि भविष्य में भारत अपनी विकास योजनाओं के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रह सकता। दिसम्बर १२ सन् १९५५ को वित्त मन्त्री कृष्णमाचारी ने ऐनोसियेटेड चेम्बर ऑफ कामर्स को सम्बोधित करते हुये कहा था कि "मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के बहुत विरुद्ध हूँ कि विदेशी सहायता के लिये हाथ फेंकाया जाय। मैं भीख लेने से घृणा करता हूँ, क्योंकि स्वभावतः जो व्यक्ति हमें सहायता देगा वह अपनी शर्तों हमें ममबायेगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये जो सघर्ष हमें करना है उसकी याद हमारे हृदयों में अब तक नई है तथा किसी भी दशा में हम अपनी स्वतंत्रता का जरा सा भी अंश न छोड़ेंगे।" १ श्री गुजजारीलाल ने भी कांग्रेस के सरदारनगर अधिवेशन में १० फरवरी सन् १९५६ को आर्थिक प्रस्ताव पर भाषण देते हुये कहा था कि "हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। हमें अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये अन्य देशों की ओर नहीं ताकना चाहिये। निसन्देह राष्ट्रों को एक दूसरे पर कई बातों के लिये निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु किसी के दान पर निर्भर होना सम्मानजनक नहीं है।" २ मोटे तौर पर सन् १९५६ की औद्योगिक नीति में भी विदेशी पूँजी का सहयोग सम्मानजनक शर्तों पर लेना स्वीकार किया गया है।

विदेशी पूँजी की वर्तमान स्थिति—

किसी उद्योग में विदेशी पूँजी के विनियोग के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते समय निम्न नियमों का ध्यान रखा जाता है :—

- (1) प्रार्थना पत्र किसी निर्माणी कार्यक्रम से सम्बन्धित होना चाहिये ;
- (11) विदेशी विनियोग उस क्षेत्र में होना चाहिये जहाँ स्वदेशी पूँजी पर्याप्त नहीं है या भारत में टैक्नीकल जानकारी उपलब्ध नहीं है।

1. "I am personally very much against going and asking for foreign aid. I hate to beg, though I am a born Brahmin and mendicant. For, naturally a man who gives us aid lays down his terms. The fight that we had to put up for the attainment of liberty is still fresh in our mind and we shall not barter an inch of that liberty—not for a mess of pottage."

2 "We have to stand on our own legs. We should not look to others for meeting our needs. Nations, of course, had to depend upon each other for a number of things. But to place reliance on some body else's charity is not honourable."

(11) उस विनियोजन के द्वारा, आयात में कटौती होकर, विदेशी मुद्रा की वृद्धि होती है । या विदेशी को निर्यात में वृद्धि होकर, विदेशी मुद्रा की भाव बढ़ती हो ।

(1२) सम्बन्धित कार्यक्रम उत्पादकता में वृद्धि करने वाला हो ।

विदेशी विनियोगों के लिये कोई पूर्व निर्धारित क्षेत्र नहीं है । प्रत्येक प्रस्ताव पर राष्ट्रीय भयं व्यवस्था के लिये उसकी उपयोगिता के आधार पर विचार किया जाता है । हाँ, उन विनिर्दिष्ट उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें एक उच्चकोटि की टेक्नीकल कुशलता एवं जानकारी की आवश्यकता पड़ती है । जिन उद्योगों में भारतीय पूँजी अभी बढ़ने से हिचकिचाती है, शर्माती है उनको भी प्राथमिकता दी जाती है । इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन उद्योगों में भारतीय पूँजी ने कुछ पैर जमा लिये हैं उनमें विदेशी विनियोग को अनुमति नहीं मिलेगी । यदि टेक्नीक एव किस्म की दृष्टि से आन्तरिक क्षमता अपर्याप्त हो तो अनुमति दी जा सकती है । सरकार को उपभोक्ताओं के हित का भी ध्यान रखना पड़ता है । जब तक प्रतिस्पर्धा उचित है तथा देश के हितों के लिये प्रोत्साहित करने लायक नहीं है, तब तक उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में भी विदेशी पूँजी का स्वागत होगा । इस श्रेणी में साइकिलों, बटनों, ड्रगो, खेलकूद का सामान, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रेडियो, इलेक्ट्रिक सैम्प, ब्लेड, आवश्यक तेल आदि आते हैं । सरकार उन विदेशी योजनाओं को निरस्त नहीं करती है जो कि देश को स्थायी लाभ प्रदान नहीं कर सकें, जैसे कि वित्तीय, व्यापारिक या वाणिज्यिक संस्थाओं में विनियोग । कुछ व्यापारिक संस्थाओं में भी विदेशी पूँजी को स्वीकृति दी गई है, लेकिन ऐसा उन्हीं मामलों में किया गया है जहाँ टेक्नीकल ज्ञान क्रय विक्रय के लिये आवश्यक था, जैसे स्थूल मिट्टी हटाने वाली मशीन, खानों के साज-सामान आदि का क्रय विक्रय ।

अभी हाल में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सरकार की नीति को निम्न प्रकार स्पष्ट किया था —“यदि इस देश में बिना विदेशी टेक्नीकल जानकारी के कुछ उद्योगों की स्थापना करना असम्भव है, तो विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाता है । यदि कोई विदेशी व्यापारी उन्हें स्थापित कर रहा है, तो हम उसे सब तरह का प्रोत्साहन देते हैं । इसके विपरीत, यदि ये उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं और कोई विदेशी उनकी स्थापना के लिये आता है तो उससे हम कह देते हैं कि उसे भारतीय सहयोग प्राप्त करना चाहिये, भारतीय सहयोग प्राप्त किये बिना उसे हम प्रोत्साहन नहीं देंगे । यह भारतीय सहयोग सामान्यतः ७०% होना चाहिये । कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं जिनमें उद्योग की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु भारत में सहयोग नहीं मिल रहा है । ऐसी दशाओं में हम विदेशी को इस देश में उद्योग की स्थापना करने की अनुमति दे देते हैं । मोटे तौर पर सरकार इसी नीति का अनुसरण कर रही है तथा रोजगार की संभावनाओं को एवं सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के

ध्यान में रखते हुये वह उद्योगों की स्थापना परे राय देती है।" सामान्यतः निम्न विशेषताओं वाले विदेशी उपक्रमों को अनुमति मिल गई है :—

(१) जो कि भारत के आर्थिक विकास के लिये अत्यावश्यक हो और जिनमें बहुत अधिक पूँजी या उच्च कोटि के टेक्नीकल ज्ञान की आवश्यकता पड़ती हो ।

(२) जो भारतीय व्यापारियों, टेक्नीशियनों और श्रमिकों को उद्योग में अधिक प्रशिक्षण देते हो,

(३) जो भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में सुधार करते हो ।

किन्तु, निम्न विदेशी उपक्रमों को अनुमति नहीं दी गई है .—

(१) जो विलासिता से सम्बन्धित उपक्रम हो अर्थात् जो कि भारत के वर्तमान आर्थिक विकास कार्यक्रम या वर्तमान उपभोग आवश्यकताओं के लिये जरूरी नहीं ।

(२) जो भारतीय उद्योगों (विशेषतः कुटीर उद्योगों) से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जबकि ये भारतीय उद्योग वर्तमान माग को अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं ।

(३) जो सरकार की राय में पैकिंग या अमेम्बलिंग का कार्य ही करते हैं, निर्माण कार्य नहीं ।

(४) जो व्यापार एवं वित्त क्षेत्र में सम्बन्धित हैं, जिनमें भारतीय व्यवसायी पर्याप्त सेवा कर रहे हैं ।

विदेशी व्यावसायिक विनियोग

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की परिभाषा के अनुसार विदेशी व्यावसायिक विनियोग (Foreign Business Investments) में सरकारी क्षेत्र द्वारा प्राप्त विदेशी पूँजी सम्मिलित है । सरकारी क्षेत्र में निम्न का समावेश किया जाता है— केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्टेटुटरी कॉर्पोरेशन्स, पोर्ट ट्रस्ट व म्यूनिसिपैलिटियाँ । सरकारी स्वामित्व वाली संयुक्त सन्ध कम्पनियों को अ-सरकारी क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है । सन् १९५६ के अन्त में कुल विदेशी व्यावसायिक विनियोग ५०६३ करोड़ था । विभिन्न व्यवसायों में इसका वितरण इस प्रकार था :—

विदेशी व्यावसायिक विनियोग

(व्यवसाय क्रम से)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	व्यवसाय	१९४८	१९५६
१.	निर्माण	७१'६	१८६'०
२.	वाणिज्य	६४'३	१०६'६
३.	लोकोपयोगी सेवाएँ व पानायात	३१'२	५६'५
४.	खाने	११'५	१०'८
५.	वित्त	६'६	२८'१
६.	कमीषा	५२'२	८८'२
७.	प्रबंध अभिकर्ता	१४'४	२२'६
८.	अन्य	३'३	१'१
		२५५'८	५०६'३

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विदेशी विनियोग सन् १९४८ की अपेक्षा सन् १९५६ में दूने हो गये, निर्माण व्यवसाय, वाणिज्यिक उपक्रमों, लोकोपयोगी सेवाओं, प्रबंध अभिकर्तात्व श्रुही व वित्तीय व्यवसायों में विदेशी विनियोग बढ़ा है, किन्तु खानों में कम हो गया है। निम्न तालिका में विनियोग करने वाले देश दिखाये गये हैं :—

विदेशी व्यावसायिक विनियोग

(देश-क्रम से)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	देश का नाम	१९४८	१९५६
१.	ब्रिटेन	२०६'०२	४०६'०८
२.	अमेरिका	११'१७	४६'८४
३.	जर्मनी	'०८	२'७६
४.	जापान	१७	'१६
५.	स्विटजरलैण्ड	५'३५	८'२२
६.	पाकिस्तान	८'४१	४'१७
७.	विश्व बैंक		१४'८२
८.	अन्य देश	२४'६३	२३'२५
		२५५'८३	५०६'३०

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विदेशी विनियोगको मे ब्रिटेन का प्रमुख स्थान है। अमेरिका के भी विनियोग इस देश में काफी है। अब विश्व बैंक का योगदान बढ़ता जा रहा है।

पंच-वर्षीय योजनाएँ एवं विदेशी पूँजी—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में देश के सम्मुख विदेशी पूँजी का प्रश्न 'संकट' के रूप में नहीं, धाया, क्योंकि इस अवधि में विकास कार्यों को गति अपेक्षाकृत काफी मन्द रही। स्वर्णीय रफी अहमद कदवाई के परिश्रम से देश की खाद्यान्न स्थिति भी काफी सुधर गई थी। साथ ही औद्योगिक विकास-कार्य जिनके लिए विदेशी विनिमय एक 'अवश्य' है, नाम मात्र के लिए ही प्रारम्भ हुए थे। इस प्रकार से विदेशी मुद्रा की मांग करने वाले उक्त दोनों क्षेत्रों में आवश्यक व्ययों के बाद भी निश्चित धन में से २०० करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय-अवशेष दूसरी योजनावधि के लिए प्राप्त हुआ।

दूसरी योजनावधि में औद्योगिक विकास पर बहुत बल दिया गया और दैव-योग से हमारी लगभग आत्मनिर्भर खाद्यान्न स्थिति भी बिगड़ गई। फिर तो देश को पेट और पीठ दोनों के लिए विदेशों में धूमना पड़ा। पेट और पीठ दोनों एक दूसरे के पूरक न होकर प्रतिस्पर्द्धी बन गए। दोनों के बीच समन्वय एवं सन्तुलन की समस्या खड़ी हो गई। परिणाम यह हुआ कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों में अपेक्षित विदेशी विनिमय 'संकट' प्रथम दो वर्षों के बाद ही देश के सामने आ गया। किन्तु देश के पास एक सम्बल था, वह था ७४८ करोड़ रुपये का पौड-पावना, जो आज घटकर केवल ११३.८७ करोड़ रुपये रह गया है।

अपने प्रचुर प्राकृतिक उपहारों एवं मानव साधनों के उपयोग से समृद्ध समाज के निर्माण के लिए देश ने उत्तरोत्तर बढ़ते हुए विदेशी पूँजी के आयात को रोकना उचित नहीं समझा और खाद्यान्नो के लिए सार्वजनिक विनिमय ४८० का आश्रय लिया। झुषा की शान्ति हुई और पीठ पर मित्र राष्ट्रीयों की सहानुभूति। सत्ताधारियों के गुट के प्रति हमारी तटस्थ विदेशी नीति के बावजूद दूसरी योजना की अवधि में विदेशी वित्तीय सहायता ८०० करोड़ रुपये से, २५ प्रतिशत बढ़कर, १,००० करोड़ रुपये हो गई, इसका वार्षिक विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

द्वितीय योजना में विदेशी सहायता

वित्तीय वर्ष	योजना लागत	विदेशी सहायता (करोड़ रु० में)	स्तम्भ (३) (२) के प्रतिशत के रूप में
(१)	(२)	(३)	(४)
१९५६-५७	६३४	४२	६.६२
१९५७-५८	८८२	६५	१०.७७
१९५८-५९	९९८	२१७	२१.७४
१९५९-६०	१,००६	२७०	२६.९४
१९६०-६१	१,०८०	३७६	३४.८१
(सम्भाव्य)			
पंचवर्षीय योग	४,६००	१,०००	२१.७४

यही नहीं, रिजर्व बैंक की मई सन् १९६१ की बुलेटिन के अनुसार भारत के निजी क्षेत्र में सन् १९५६-६० तक के ५ वर्षों में विदेशी पूँजी (शुद्ध) लगभग २०० करोड़ रुपए या ४० करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से लगाई गई है।

तृतीय पंच-वर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सार्वजनिक क्षेत्र में ७,५०० करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकार किया है। ५,७५० करोड़ रुपए की विदेशी विनिमय की आवश्यकता सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है। तीसरी योजना से सम्बन्धित विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में दो बातें यहां उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह कि दो योजनाओं के विपरीत, तीसरी योजना का प्रारम्भ ऐसे समय हो रहा है जब हमारा पौड-पावना बहुत कम रह गया है। दूसरा यह कि यह निर्णय लिया जा चुका है कि इस क्षेत्र से अब आहरण बिल्कुल ही नहीं होगा। इसलिए आगामी पांच वर्षों में हमें अपने आयात-निर्यात पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी है, ताकि आयात के विपरीत हमारा निर्यात-वर्द्धन अभियान अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके। निर्यात का पुनर्निरीक्षित सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के लिए अन्तिम रूप में ३,७०० करोड़ रुपए, (३,४५० करोड़ रुपए के स्थान पर) निर्धारित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों, पांच वर्षों के होने वाले विदेशी मुद्रा के व्यय का, अंतिम अनुमान ४५,००० लाख डालर या २,६०० करोड़ रुपए है, जिसमें सार्वजनिक विनिमय ४८० के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली १३,००० लाख डालर या ६०८ करोड़ रुपए की सहायता शामिल नहीं है। इस विषय में भारतीय वित्त मन्त्रालय का अनुमान निम्न प्रकार है—

तीसरी योजना में विदेशी सहायता

क्रमांक	देशापक्ष का नाम	सहायता की राशि
१	भारत सहायता संघ	३१,००० लाख डालर
२	सोवियन संघ तथा अन्य साम्यवादी राष्ट्र	८,००० " "
३	व्यक्तिगत (विदेशी) विनियोजक	३,००० " "
४	विश्व बैंक एव अन्य संस्थाएँ	१३,००० " "
योग	(२,६०० करोड़ रुपए)	५५,००० लाख डालर

अभी हाल ही में भारत सहायता संघ, जिसके सौभाग्यवश अब फ्रांस और विश्व बैंक भी कर्मण्य सदस्य बन गए हैं, के वाशिंगटन में हुए निर्णय के अनुसार अगले दो वर्षों (सन् १९६१-६२ और सन् १९६२-६३) में निम्न प्रकार में सहायता प्राप्त होगी :—

भारत सहायता संघ द्वारा विदेशी सहायता के वाड़े (लाख डालर में)

क्रमांक	सदस्य देशों के नाम	सहायता की राशि		योग (३) (४)
		१९६१-६२	१९६२-६३	
१.	२.	३.	४.	५.
१.	कनाडा	२८०	२८	५६
२.	फ्रांस	१५०	१५	३०
३.	पश्चिमी जर्मनी	२,२५०	१३६	३६४
४.	ब्रिटेन	१,८२०	६८	२५०
५.	जापान	५००	३०	८०
६.	संयुक्तराष्ट्र अमेरिका	५,४५०	५००	१,०४५
७.	विश्व बैंक एव अन्य	३,१००	१५०	४००
योग		१,२६५	६३०	२,२२५

कहना न होगा कि विदेशी मुद्रा बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है और विक्रेता पूर्ववत् ही हैं। ऐसी दशा में भी मित्र राष्ट्रों, विशेषकर भारत सहायता संघ, के उत्साहपूर्ण प्रोत्साहन से हमें अपने आयोजित विकास के लिए आवश्यक विदेशी सहायता समय-समय से मिलती जा रही है। मुख्यतः अमेरिका ने

हमें सर्वाधिक सहायता दी है और राष्ट्रपति कनेडी की भारत एवं अन्य अल्प-विकसित राष्ट्रों के प्रति सम्प्रति घोषित उदार ऋण नीति हमारे साहस को बढ़ावा देती है। राष्ट्रपति के अनुसार भारत ने संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से प्राप्त सहायता का बहुत ही बुद्धिमत्ता और उचित प्रकार से उपयोग किया है। विद्वद्वैव का प्रयत्न भी कम सराहनीय नहीं। यह विदेशी सहायता के शुभ लक्षण हमें आशावादी रहने को विवश करते हैं। यह भी आशा है कि इटली, नीदरलैण्ड, आस्ट्रेलिया आदि देश भी भारत सहायता क्लब के निकट भविष्य में सदस्य बन जायेंगे।

विदेशी पूँजी प्राप्त करने में बाधाएँ—

जिन घटकों में विदेशी पूँजी के विश्वास को हिला दिया है वे प्रायः वही हैं जिन्होंने प्राइवेट उपक्रम (भारतीय या विदेशी) की भावना को कुप्रभावित किया है। ये घटक मुख्यतः निम्नलिखित हैं :—

विदेशी पूँजी प्राप्त करने में बाधाएँ

- (१) प्रतिकूल विनियोग वातावरण का अभाव।
- (२) अपरिवर्तनीयता की जोखिम।
- (३) सम्पत्ति का अधिग्रहण।
- (४) सीमित आय।
- (५) भारी कराारपण।
- (६) विनियोग के अदमरो की अनभिज्ञता।
- (७) कर्मचारियों का भारतीयकरण।
- (८) भारतीय व्यवसायियों का विरोध।

(१) प्रतिकूल विनियोग वातावरण—स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद से यह देखा गया है कि विनियोजक में उत्साह का बहुत अभाव हो गया है। इसका प्रमुख कारण सरकार की कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करना असहानुभूतिपूर्ण वातावरण है। सम्पूर्ण बौद्धिक वातावरण वचन, उपक्रम एवं विनियोग के लिये अनुकूल प्रतिकूल है। सविधान में सशोधन करके प्राइवेट सम्पत्ति के अधिग्रहण पर पुनर्विचार करने के न्यायिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ में उचित औद्योगिक क्रियाओं पर अधिक नियन्त्रण व प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। 'समाज की समाजवादी रूपरेखा' (Socialistic pattern of society) से हटकर 'समाजवादी समाज' (Socialist Society) पर बल दिये जाने से अग्नि में घी पड़ गया है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९५६ में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने से भी विनियोजकों के उत्साह पर पाला पड़ गया है।

यदि हम गम्भीरता से विचार करें तो, मान्य होगा कि उपरोक्त दृष्टिकोण सही नहीं है। समाजवादी समाज का लक्ष्य अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि प्राइवेट उपक्रम को समाप्त कर दिया जायेगा। सच तो यह है कि प्राइवेट उपक्रम के लिये बहुत व्यापक क्षेत्र छोड़ दिया गया है। गत वर्षों में जो औद्योगिक प्रगति हुई है उससे साफ जाहिर है कि प्राइवेट उपक्रम को मोहित या दबाया नहीं गया है। सम्पत्ति के

अधिग्रहण के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य किया गया है, लेकिन साथ साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी को भी उसकी सम्पत्ति से कानूनी उपायो के अलावा अन्य तरीकों से वंचित नहीं किया जायेगा। हाल में ही इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के अवसर पर शेयरहोल्डरों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना उक्त भावना का प्रमाण है। कम्पनी अधिनियम के नियन्त्रणों का उद्देश्य भी प्राइवेट उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करना है, ताकि विनियोजकों का विश्वास कोरपोरेट उपक्रमों में पुनः स्थापित हो जाय।

(२) अपरिवर्तनीयता की जोखिम—विदेशी विनियोजकों को लाभ, ब्याज एवं पूँजी के स्थानान्तरण के लिये विदेशी मुद्रा की सुविधायें मिलना अति आवश्यक है। भारत में विदेशी विनियम पर सन् १९३६ से कंट्रोल है, जिसे सन् १९४७ के विदेशी विनियम नियन्त्रण अधिनियम सन् १९४७ द्वारा बढ़ा दिया गया है। दुर्लभ मुद्रा देशों के सम्बन्ध में ये नियन्त्रण सुलभ मुद्रा देशों की तुलना में अधिक बड़े हैं। इन नियन्त्रणों का उद्देश्य विदेशी मुद्रा का अपव्यय होने से रोकना है। चूँकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का सदस्य है, इसलिये ये नियन्त्रण उसे धीरे-धीरे हटा लेने होंगे। वैसे भी भारत में विदेशी फर्मों की सामान्यतः लाभ अपने देश को भेजने की स्वतन्त्रता है। हाँ, विदेशी मुद्रा के लिये प्रार्थना-पत्र देते समय उन्हें अपना अकेलित हिसाब फायल करना पड़ता है।

(३) सम्पत्ति का अधिग्रहण—सौध व पर्याप्त हर्जाना दिए बिना सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लेना भी एक गम्भीर बाधा है। यह तर्क दिया गया है कि जब तक राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रमों में अनिश्चितता रहेगी तब तक भावी विनियोगक के उत्साह पर प्रकुच लगा रहेगा। सीमान्त से भारत सरकार ने इस प्रश्न पर अपनी नीति घोषित कर दी है। स्टर्लिंग क्षेत्र, नार्वे, स्वीडन और डेन्मार्क के निवासियों की पूँजी का स्वतन्त्रतापूर्वक पुनर्भुगतान किया जाता है। अन्य देशों के निवासियों की पूँजी भी, जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट में १ जनवरी सन् १९५० के बाद विनियोग की गई हो, किसी भी समय मूल विनियोग एवं पुनर्विनियोग की सीमा तक लौटा दी जावेगी, लेकिन अमेरिकी पूँजी के सम्बन्ध में अभी ऐसी सुविधाओं का अभाव है। अब सरकार अमेरिका की एक गारण्टी योजना पर विचार कर रही है।

(४) सीमित आय.—रिजर्व बैंक द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार यू० के० एवं यू० एस० ए० कम्पनियों को विनियोगों पर हाने वाली आय सन् १९५५ में १०% थी, जबकि सन् १९५३ में इससे अधिक अर्थात् १२% थी। अमेरिकी कम्पनियों की ब्रिटिश कम्पनियों की अपेक्षा अधिक लाभ हुआ है। कहा जाता है कि विदेशी कम्पनियों की आय में कमी होना विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के मार्ग में एक बाधा है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह नहीं भूना चाहिए कि भारतीय कम्पनियों की अपेक्षा विदेशी कम्पनियों की आय अधिक है (क्रमशः ६४ एवं ६६% सन् १९५५ में एवं ६८% एवं १२१% सन् १९५३ में)। यही नहीं, विदेशी कम्पनियों का कार्य

पेट्रोल, प्लान्टेशन, सिग्रेट व तम्बाकू तथा अन्य चुने हुये क्षेत्रों तक सीमित था, जबकि भारतीय कम्पनियों को एक विस्तृत क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है। स्वदेश में भी विदेशी कम्पनियाँ इनकी आय नहीं प्राप्त करती जितनी कि वे अपने विनियोगों पर भारत में प्राप्त करती हैं।

(५) भारी करारोपण—यह तर्क दिया जाता है कि अर्द्धविकसित देशों में करारोपण का ऊँचा स्तर होने से वहाँ विदेशी पूँजी के आगमन में बाधा पड़ती है। लेकिन यह तर्क गलत है। अमेरिका के प्राइवेट विनियोजक विकसित देशों में अपनी आय का ४०% भाग करा के रूप में देते हैं, जबकि अर्द्धविकसित देशों में उन्हें २५% भाग ही देना पड़ता है। यह भी कहा गया है कि दुहरे कर की व्यवस्था भी पूँजी के आवागमन में बाधक है। पूँजी निर्यात करने वाले देश में कर-अधिकारी अपने कर-क्षेत्र में निवासी व्यक्तियों व कम्पनियों की कुल विश्व आय पर कर लगाते व वसूल करते हैं। पूँजी आयात करने वाले देश में वहाँ के कर-अधिकारी भी विदेशी कम्पनियों की आय पर कर लगाते हैं। यह दुहरा करारोपण व्यापार व विनियोग दोनों पर ही बुरा प्रभाव डालती है। दुहरे करारोपण की समस्या सौभाग्य से अब लगभग सुलभ गई है, क्योंकि प्रमुख पूँजी निर्यात करने वाले देशों ने अपनी ओर से करारोपण में छूट देना आरम्भ कर दिया है। यू० के०, लका, भदन, युगान्डा व अन्य कुछ देशों में जिस आय पर कर लगता है उस पर भारत में भी कर लगाने की दशा में सरकार विशेष राहत देती है। अभी हाल में भारत सरकार के कुछ अधिकारी यूरोपीय देशों के भ्रमण पर गये थे। उनके प्रयासों से प० जर्मनी और स्वीडन की सरकारों से कर समझौते हो गये हैं। अन्य देशों से भी वार्ता जारी है। इस प्रकार दुहरे कर की समस्या बहुत कुछ हल की जा चुकी है।

(६) विनियोग के अवसरों की अनभिज्ञता—भारत में विनियोग के अवसरों के बारे में सूचना के अभाव तथा गलत सूचना होने के कारण विदेशी पूँजी का प्रवाह धीमा रहा है। विदेशी विनियोजकों को विनियोग के विभिन्न क्षेत्रों की केवल सूचना देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसको रुचि को भी जागृत करना चाहिये। इसके लिये 'भारत में विनियोग पथ प्रदर्शिका' जैसी पुस्तकों के प्रकाशन की आवश्यकता है। यह कार्य वित्त मन्त्रालय या कोई प्राइवेट संस्था भी भारत सरकार के सहयोग से कर सकती है। पूँजी निर्यात करने वाले देशों का भी अपने विनियोजकों के प्रति यह कर्तव्य है कि वे विनियोग सम्बन्धी सुखवसलों की सूचना का संग्रह करें। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने तो एक विदेशी विनियोग कार्यालय पृथक् ही स्थापित कर दिया है।

(७) कर्मचारियों का भारतीयकरण—विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना भी एक बाधक घटक माना जाता है। सन् १९५२ से सरकार समय समय पर विदेशी पूँजी और विदेशी सम्बन्ध रखने वाली सभी फर्मों में काम करने वाले उच्च कर्मचारियों की गणना कराती रहती है। इससे पता चला है कि कर्मचारियों के भारतीयकरण की प्रवृत्ति तेजी पर है। उच्च पदों पर भारतीयों की संख्या विशेष

रूप से बढ़ रही है। विदेश नियंत्रित फर्मों में १,००० रु० या इससे अधिक वेतन पाने वाले भारतीय नमंकारियों का प्रतिशत सन् १९४७ में ७.६ से बढ़ कर सन् १९५६ में ४२% हो गया था, जबकि निम्न वेतन वर्ग (३०० रु० से ४०० रु० तक) सभी कर्मचारी भारतीय थे। विदेशी स्वार्थ भारतीयकरण की प्रवृत्ति को पसन्द नहीं करते। अतः यह सुझाव दिया गया है कि विदेशी कम्पनी को अपना राष्ट्रीय स्वभाव रखने की अनुमति होनी चाहिये, उच्च प्रबन्ध पदों पर अपने ही देशवासी नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये और उचित प्रमोशन देने की सुविधा होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि विदेशी फर्म भारतीयों को सरल प्रमोशन तो न दें किन्तु उनकी ट्रेनिंग की पूर्ण व्यवस्था कर तथा उच्च प्रबन्ध-पदों पर अपने ही देशवासियों का एकाधिकार रखने की मनोवृत्ति छोड़ दें।

(न) भारतीय व्यवसायों द्वारा विरोध—विदेशी विनियोजक यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय व्यवसायों का दृष्टिकोण विदेशी पूँजी के आगमन के प्रति हिचकिचाहट पूर्ण है। उदाहरण के लिये, अब एक साबुन बनाने वाली विदेशी कम्पनी ने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशों से मशीनें मगानी चाही या अपने मूल्य कम करने चाहे तो देशी साबुन निर्माताओं ने सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने को कहा। इस आरोप का उत्तर यह है कि सरकार ने अपने हक में देशी उत्पादकों के दबाव पर कोई परिवर्तन नहीं किया। वह अपने विदेशी सहयोग की नीति पर पुनर्वत कायम है। अतः विदेशी विनियोजकों का उक्त तर्क निराधार है।

उपसंहार—विदेशी पूँजी का भविष्य—

यदि हम विदेशी पूँजी के प्रयोग से लाभ उठाना चाहते हैं, तो उपर्युक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी होंगी, ऐसी शर्तों पर विदेशी पूँजी प्राप्त करनी होगी जोकि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक न हो और साथ ही विदेशी विनियोजकों को आकर्षण भी रहे। विदेशियों को ध्यानसायिक सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिये, जिसके लिये देश में एव सर्वप्रधानिक, ईमानदार तथा स्थाई सरकार की आवश्यकता है। विदेशी पूँजी का निर्यात करने वाले देशों का भी चाहिये कि अर्द्ध-विकसित देशों के प्रति वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक उदारता से निभावे। उनको स्वेज नहर व ईरान तेल कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की घटनाओं से व्यर्थ आतंकित नहीं होना चाहिये, क्योंकि इन घटनाओं के पीछे ता साम्राज्यवादी शोषण का लम्बा इतिहास है। इन घटनाओं में आर्थिक घटकों की अपेक्षा राजनैतिक घटकों का प्रमुख प्रभाव था। औद्योगिक देशों का चाहिये कि आर्थिक उद्देश्यों के लिये सहायता कार्यक्रमों एवं सामरिक तथा अनाथिक सहायता कार्यक्रमों में मदद करें।

यह भी आवश्यक है कि सहायता देने वाले देश सहायता के उद्देश्यों पर पुनर्विचार करें। अभी तक विकास कार्यक्रमों को लाभ का साधन माना जाता है और यह आशा की जाती है कि सहायता देने वाले देश अधिक सम्पन्न हो सकेंगे। परन्तु

वास्तविकता यह है कि सम्पन्नता अविभाज्य है एवं किसी देश में दरिद्रता होना शेष संसार के लिये खतरा है। अतः यदि विकसित देश पिछड़े हुये देशों को आर्थिक सहायता देते हैं और उनके विकास में सहायक होते हैं, तो इससे उनकी अपनी सम्पन्नता का वर्तमान स्तर बच्यम रह सकेगा, अन्यथा सम्पन्नता बढ़ना तो दूर उसके घटने की ही संभावना है।

विदेशी सहायता की संभावनाओं का पता लगाने के लिये भारत के जो प्रतिनिधि एवं शिष्ट मंडल विदेशों में गये हैं उन्हें वहाँ से अच्छा प्रत्युत्तर मिला है। उनकी रिपोर्टों से पता चलता है कि यदि अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर दिया जाय, तो अपार मात्रा में विदेशी पूँजी प्राप्त हो सकती है। विदेशी व्यवसायों व फाइनेंसरों से हुई वार्ता के दौरान में शिष्ट मंडल को उनकी अनेक शकाओं का ज्ञान हुआ। हमारी नवीन प्रशुल्क एवं कर नीतियों से उन्हें हमारी आर्थिक नीति के सम्बन्ध में बहुत भ्रम हो गया है, जैसे प्राइवेट क्षेत्र की गतिविधि में क्या भूमिका होगी, राष्ट्रीयकरण कैसे होगा। अनिवार्य डिपॉजिट योजना व अत्यधिक करों की भी बहुत आलोचना की गई है। समाजवाद के बारे में हमारे असावधानों से दिये गये वक्तव्यों से उनको बहुत भय उत्पन्न हो गया है। अतः, विदेशी पूँजी जिस भीमा तक उपलब्ध हो सकती है, यह बहुत कुछ भारत सरकार की नीतियों एवं विदेशी विनियोजकों की दूरदर्शिता पर निर्भर है। यह नितान्त आवश्यक है कि हम विदेशी सहायता प्राप्त करें किन्तु ऐसा करते समय अपनी प्रमूल्य स्वतन्त्रता व सम्मान को न खो दें तथा यह भी ध्यान रखें कि विदेशी पूँजी को प्राप्त करने की लागत भी उचित हो।

STANDARD QUESTIONS

1. What is the role of foreign capital in the economic development of a country? Describe it with special reference to India?
2. Briefly discuss the various forms in which foreign capital entered India. What is the present policy of the Government towards foreign capital.
3. Examine the role of foreign capital under our Five Year Plans.
4. What are the factors which have shaken the confidence of foreign capital in India? How are they being set right?
5. Examine the measures which are proposed to be taken for creating appropriate conditions for the use of foreign capital.



अध्याय ४३

औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धान्त

(Principles of Industrial Location)

प्रारम्भिक—

किसी भी औद्योगिक इकाई की सफलता काफी सीमा तक उसके स्थानीयकरण (Location) पर निर्भर करती है। अर्थशास्त्रिक अथवा अनियोजित औद्योगिकरण केवल सस्था विशेष के लिए नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र के लिए अनेक सामाजिक व आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न कर देता है। यदि किसी सस्था के कार्य-स्थान का चुनाव उपयुक्त ढङ्ग से अथवा यों कहें कि औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं किया गया है, तो एक अच्छी सस्था की सफलता भी खटाई में पड़ सकती है। स्थान के चुनाव की समस्या नई सस्थाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पुरानी विद्यमान सस्थाओं के लिये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार व यातायात एवं सदेशवाहन सम्बन्धी दशायें नित्य-प्रति तेजी से बदल रही हैं।

सहस्र—

अध्यक्षस्थित औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक, समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है। किसी स्थान विशेष पर ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों के केन्द्रीयकरण से श्रमिकों के प्रवास, उनमें स्वास्थ्य, नैतिक पतन आदि सम्बन्धी अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। इन समस्याओं के समाधान के हेतु सरकार पर भी व्यय का बहुत बोझ बढ़ जाता है। राजनैतिक दृष्टि से भी उद्योगों का केन्द्रीयकरण देश के लिये घातक हो सकता है। विदेशी शक्तियाँ प्रायः उन स्थानों पर ही आक्रमण करती हैं जहाँ उद्योग अन्धे केन्द्रित होते हैं, जिससे कि सम्पूर्ण राष्ट्र का आर्थिक ढाँचा क्षिप्त-भिन्न हो जाय। ऐसी परिस्थिति में हमें उन आर्थिक सिद्धान्तों व घटकों का पूर्ण विचार करना चाहिए जो कि औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं।

स्थानीयकरण के सिद्धान्त

(Theories of Localisation)

(I) एल्फ्रेड वेबर का निगमनात्मक सिद्धान्त (Weber's Deductive Theory)—

जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान एल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के सम्बन्ध

में विवाद व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने उद्योगों के स्थानीयकरण सम्बन्धी कारणों को दो भागों में विभाजित किया है :—

- (१) वे कारण जो उद्योगों के प्रादेशिक वितरण पर प्रभाव डालते हैं; और
- (२) वे कारण जो किसी विशेष प्रदेश के भीतर ही उद्योगों के वितरण पर केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीयकरण की रीतियों द्वारा प्रभाव डालते हैं।

चूँकि स्थान की समस्या उत्पादन की न्यूनतम लागत से सम्बन्धित है। इसलिये उद्योग का प्रादेशिक वितरण पूर्णतः लागत विचार से प्रभावित होता है। वेबर के विचार में यातायात व्यय एवं श्रम सम्बन्धी व्यय लागत के ऐसे दो तत्त्व हैं जो कि औद्योगिक इकाइयों के स्थान-निर्धारण से महत्वपूर्ण रूप में सम्बन्धित हैं।

यातायात व्यय—उस स्थान का ही चुनाव करना उपयुक्त होगा जहाँ कच्चा माल औद्योगिक केन्द्रों में लाने व तैयार माल बाहर भेजने में न्यूनतम यातायात व्यय हो। तैयार माल के बाजार और कच्चे माल के स्रोतों का जहाँ तक परस्पर सम्बन्ध है, इनमें से किस का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, यह कच्चे माल के स्वभाव और उनके निर्माण की रीतियों पर निर्भर है। कच्चे माल का उन्होंने दो तरह से वर्गीकरण किया है —(अ) साधारण कच्चा माल (Ubiquities), जो कि प्रत्येक स्थान पर मिल सकता है, और विशेष कच्चा माल (Localised Materials), जो कि कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलता है। ईट मिट्टी, बालू, पानी आदि की गणना साधारण कच्चे माल में की जा सकती है। सभी जगह मुलभ होने के कारण इनका उद्योगों के स्थान-चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत, लोहा, कोयला, लकड़ी, चूने का पत्थर आदि 'विशेष कच्चे माल' की श्रेणी में आते हैं। चूँकि ये कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलते हैं, इसलिए उद्योग इन्हीं क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। (ब) स्थानान्तरण में भार खोने वाला कच्चा माल (Gross Materials) एवं स्थानांतरण में भार न खाने वाला कच्चा माल (Pure Materials)। शुद्ध माल (Pure Materials) प्रयोग करने वाले उद्योग प्रायः बाजार की ओर आकर्षित होते हैं और मिश्रित माल (Gross Materials) संचालन करने वाले उद्योग उस माल के स्रोतों की ओर खिंचते हैं।

श्रम-लागत—सस्ता श्रम भी, जो कुछ क्षेत्रों में ही उपलब्ध होता है, कुछ सीमा तक औद्योगिक स्थानीयकरण पर प्रभाव डालता है। वेबर का विचार है कि कुछ ऐसे निश्चित श्रम-केन्द्र हैं जहाँ से श्रम अन्य केन्द्रों में नहीं जा सकता। इस गति-हीनता के कारण उद्योग श्रम व निश्चित केन्द्रों (Fixed Centres of Labour) की ओर आकर्षित होते हैं, जिसमें कि वे सस्ती-श्रम लागत का लाभ उठा सकें।

एक विशेष क्षेत्र में ही उद्योगों के पुनर्वितरण के बारे में, कुछ कारण (Agglomerative factors) ऐसे होते हैं जो कि उद्योगों को उस क्षेत्र के कुछ भागों में ही केन्द्रित या एकत्र कर देते हैं, जबकि कुछ कारण (Deglomerative factors)

ऐसे भी होते हैं जो उद्योगों को उस क्षेत्र में सब ओर फैला सा देते हैं। बेंकिंग, बीमा और विपणन सेवाओं की सुविधायें तथा बाहरी बचत प्राप्त करने की सम्भावनायें भी उद्योगों को एक विशेष क्षेत्र में एकाग्र करने की प्रवृत्ति रखती हैं। लेकिन उद्योगों का बिखरना किराये व करों की अधिकता तथा आवास सम्बन्धी समस्याओं का परिणाम होता है।

वेबर के सिद्धान्त की आलोचना—

वेबर का सिद्धान्त तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण के कारणों का एक अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। किन्तु यह सिद्धान्त स्थानीयकरण की प्रवृत्ति पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाल सका है। सार्जेन्ट प्लोरेंस, डेनो-सन् एव विन्सन द्वारा विभिन्न आधारों पर इस सिद्धान्त की कटु आलोचनायें की गई हैं। प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं :—

(१) वास्तविक आवश्यकता से अधिक सरल एवं काल्पनिक—वेबर का सिद्धान्त प्रवास्तविक, आवश्यकता से अधिक सरल एवं कुछ काल्पनिक घटकों तक सीमित होने के कारण स्थानीयकरण को अनेक विषम परिस्थितियों पर प्रकाश नहीं डालता। वेबर ने अपना सिद्धान्त यानायात व्यय और श्रम लागन पर ही विशेष रूप से आधारित किया है। इसमें भी उन्होंने यातायात व्यय में वस्तु का भार और दूरी को ही ध्यान में लिया है, जबकि यानायात व्यय में वस्तुओं के मूल्य, वस्तुओं के वर्गीकरण व उनके लाने से जाने के प्रदेशों की भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर है।

वेबर के सिद्धान्त की ४ आलोचनायें

- (१) प्रवास्तविक, आवश्यकता से अधिक सरल एवं काल्पनिक।
- (२) श्रम-लागन का स्थानीयकरण पर अधिक प्रभाव नहीं।
- (३) ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारणों की उपेक्षा।
- (४) वास्तविक वस्तुस्थिति पर पूर्ण प्रकाश नहीं।

(२) श्रम लागत का स्थानीयकरण पर अधिक प्रभाव नहीं—वेबर ने कुछ निश्चित श्रम-केन्द्रों की कल्पना की है, जहाँ से श्रम की पूर्ति असीमित मात्रा में हो सकती है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके अनिश्चित, समय के परिवर्तन तथा उद्योगों के विकास में श्रमिकों के पारिश्रमिक में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः श्रम-लागन ही स्थानीयकरण को अधिक प्रभावित और निर्धारित नहीं कर सकती।

(३) ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की उपेक्षा—उद्योग-धन्धों का स्थानीयकरण केवल प्राथमिक और अनिश्चित कारणों से ही निर्धारित नहीं होता। वरन् ऐतिहासिक और सामाजिक कारण भी उसे प्रभावित करते हैं। किन्तु वेबर ने इन कारणों का कोई संकेत नहीं किया है। इसके अनिश्चित वेबर का वर्गीकरण भी अन्तः विचारकों को स्वीकार नहीं है।

(४) वस्तु स्थिति पर पूर्ण प्रकाश नहीं—वेबर न अपनी व्याख्या में गुणक (Multiplier) और निर्देशांक (Index Number-) का प्रयोग किया है। इनसे एक शुद्ध सिद्धांत (Pure Theory) की रचना तो अवश्य हो गई है, लेकिन वह वास्तविक बात पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाल सका है।

वेबर के सिद्धान्त में आवश्यक सुधार—

यदि वेबर के सिद्धान्त में निम्न सुधार कर दिये जाय तो उसे एक व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है—

वेबर के सिद्धान्त को व्यावहारिक बनाने के ४ सुझाव

- (१) यातायात व्यय सम्बन्धी मान्यता में सुधार।
- (२) स्थिर श्रम केन्द्रों सम्बन्धी मान्यता में सशोधन।
- (३) उपभोग केन्द्रों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण।
- (४) लागतों व कीमतों के सदम में गणनायें।

(१) यातायात व्यय सम्बन्धी मान्यता में सुधार—यातायात व्यय को केवल तैल एवं दूरी के सदम में ही नहीं देखना चाहिये बल्कि यातायात के विभिन्न साधनों की वास्तविक दर अनुसूचियों (rate schedules) को विचार में लेना अधिक उचित होगा।

(२) स्थिर श्रम केन्द्रों सम्बन्धी मान्यता में सशोधन—श्रम केन्द्रों सम्बन्धी मान्यता में भी सशोधन करना चाहिये क्योंकि श्रम की प्रवासी प्रवृत्ति में

वृद्धि होने के साथ साथ विशेष श्रम केन्द्रों का महत्त्व अनुपातन कम होता जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी असत्य है कि किसी क्षेत्र में श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध हो सकती है। श्रम केन्द्रों में मजदूरी स्तर भी स्थिर नहीं होता, क्योंकि वह औद्योगिकरण की प्रगति के साथ परिवर्तित होता है।

(३) उपभोग केन्द्रों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण—उपभोग केन्द्रों पर संकुचित क्षेत्रों के सदम में विचार न करके विस्तृत क्षेत्रों के सदम में विचार करना चाहिये। यह भी संभव है कि किसी उद्योग के क्षेत्रीयकरण पर उपभोग केन्द्रों का कोई प्रभाव न पड़े क्योंकि देश भर में वस्तु का एक ही मूल्य रखने के आशय से सरकार यातायात व्यय की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता दे सकती है।

(४) लागतों व कीमतों के सदम में गणनायें—यदि लागतों एवं कीमतों के सदम में गणनायें प्रचलित कर दी जायें, तो इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह आरोप समाप्त हो जायगा कि वह केवल Technical Coefficients के सदम में ही विचार करता है।

(II) सार्जेंट फ्लोरेन्स का आगमन-विश्लेषण

(Sargent Florence's Inductive Analysis)

आधुनिक युग में सार्जेंट फ्लोरेन्स का आगमन-विश्लेषण बहुत लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि वह औद्योगिक वितरण की प्रवृत्तियों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता

है। सार्जेंट पचोरेन्स ने उत्पादन-गणना (Census of Production) से विभिन्न उद्योगों के लिये स्थानीयकरण की सीमा का सांख्यिकी माप निकाला है। वे स्थानीयकरण के प्रचलित अर्थ को (जो यह है कि उद्योग और भौगोलिक क्षेत्र के मध्य सम्बन्ध को प्रगट करने वाला विचार ही 'उद्योगों का स्थानीयकरण' है) स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि किसी क्षेत्र से उद्योग का सम्बन्ध इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सम्पूर्ण जन-संख्या के वितरण से उद्योग का सम्बन्ध होता है। उन्होंने दो नये विचार दिये हैं, जो कि निम्न हैं—

(१) स्थापन भाज्य (Location Factor)—यह किसी विशेष स्थान में किसी उद्योग के केन्द्रीयकरण की मात्रा का सूचक होता है। यह सूचक (Index) किसी विशेष क्षेत्र में पाये जाने वाले किसी विशेष उद्योग में काम करने वाले सभी श्रमिकों का प्रतिशत लेकर और फिर उसे देश में कुल औद्योगिक श्रमिकों के उस विशेष क्षेत्र में अनुपात से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। चुने गये क्षेत्र देश के राजनैतिक विभाग होने चाहिये, औद्योगिक विभाग नहीं। इस सूचक अंश की सहायता से स्थानीयकरण को देश की जन-संख्या एवं उद्योग के भौगोलिक वितरण के मध्य असमानता की मात्रा के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। यदि कोई उद्योग सारे देश में समान रूप से फैला हुआ है, तो प्रत्येक क्षेत्र का 'स्थानिक घटक यूनिटी' के बराबर होगा, क्योंकि क्षेत्र के कुल औद्योगिक श्रमिकों का अनुपात उस विशेष उद्योगों में श्रमिकों के अनुपात के बराबर होता है। यदि स्थानिक घटक यूनिटी से कम या अधिक है तो इसका आशय है कि उद्योग देश में असमान रूप से वितरित है। जब वह यूनिटी से अधिक हो, तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र का उद्योग में उचित से अधिक भाग है और यदि स्थानिक घटक यूनिटी से कम है, तो इसका आशय है कि उद्योग में उस क्षेत्र का उचित से कम भाग है।

(२) स्थानीयकरण सहगमक (Co-efficient of Localisation)—यह किसी उद्योग के केन्द्रित होने की प्रवृत्ति को सूचित करना है। यद्यपि इसका आशय किसी विशेष उद्योग से है तथापि वह किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं होता। वह देश के किसी भी क्षेत्र में उद्योगों की केन्द्रीयकरण प्रवृत्ति से सम्बन्धित होता है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है—

When workers are divided up region by region as percentages of the total in all regions, the coefficient is the sum (divided by 100) of the plus deviations of the regional percentages of workers in the particular industry from the corresponding regional percentages of workers in all industry.

स्थानीयकरण सहगमक के आधार पर किसी देश के सभी उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—(१) उच्च सहगमक वाले उद्योग (जैसे कोयला खान उद्योग), जो विशेष क्षेत्रों में ही केन्द्रित होने हैं; (२) निम्न सहगमक वाले उद्योग, जो

विभिन्न क्षेत्रों में विवक्षित हो सकते हैं और इस प्रकार विवेन्द्रित हो जाते हैं, तथा (३) मध्यम सहगमक वाले उद्योग ।

फ्लोरेन्स के सिद्धांत की आलोचना—

सार्जेंट फ्लोरेन्स का दृष्टिकोण वेबर के दृष्टिकोण से अधिक वास्तविक और व्यापक है । औद्योगिक आविष्कार एवं निरन्तर होने वाला आर्थिक विकास उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते रहते हैं । इस तथ्य पर वेबर ने ध्यान नहीं दिया था । इसके अतिरिक्त ऋतु परिवर्तन, राज्य परिवर्तन समय परिवर्तन एवं टेक्नालाजी-कल परिवर्तन भी उद्योगों के स्थानीयकरण पर प्रभाव डालते हैं । वर्तमान युग में तो राष्ट्र की सुरक्षा व प्रादेशिक एवं वैयक्तिक भावनाओं भी अपना महत्व रखती हैं । जहाँ सार्जेन्ट फ्लोरेन्स ने वेबर के सिद्धांत की अनेक त्रुटियों को दूर किया है वहाँ उनका अपना सिद्धान्त भी त्रुटियों से मुक्त नहीं है । कुछ त्रुटियाँ इस प्रकार हैं—

सार्जेन्ट फ्लोरेन्स के सिद्धान्त के मुख्य ३ दोष

- (१) विद्यमान औद्योगिक वितरण पर ही प्रकाश डालने में समर्थ ।
- (२) केवल सहगमक के आधार पर उद्योग की केन्द्रीयकरण प्रवृत्ति का पता लगाना कठिन ।
- (३) स्थानिक भाज्य उद्योग के केन्द्रीयकरण की मात्रा का विश्वस्त सूचक नहीं ।

(१) विद्यमान औद्योगिक वितरण पर प्रकाश डालने में समर्थ—सार्जेन्ट का सिद्धान्त किसी विशेष देश में उद्योगों के वितरण की वर्तमान दशा पर ही प्रकाश डालने में समर्थ है । वह किसी विशेष प्रकार के केन्द्रीयकरण के कारणों को नहीं समझा सकता । इसके अतिरिक्त, वह विभिन्न प्रदेशों में उद्योगों के सही वितरण की समस्या पर भी कोई उपयोगी प्रकाश नहीं डालता । इस तरह वह किसी देश में उद्योगों के भावी स्थानीयकरण से सम्बंधित नीति निर्माण करने में पथ प्रदर्शन नहीं कर पाता ।

(२) केवल सहगमक के आधार पर उद्योग की केन्द्रीयकरण प्रवृत्ति का पता लगाना कठिन—स्थानीयकरण का सहगमक (Coefficient of Localization) आवश्यक रूप से प्रत्येक देश में वितरण के स्वरूप पर निर्भर है । अतः वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार देश-देश में भिन्न भिन्न होता है । यही कारण है कि केवल सहगमक के आधार पर ही उद्योगों की केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति का पता लगाना कठिन है । अधिक से अधिक वह सत्यता की पुष्टि कर सकता है । अतः केन्द्रीयकरण के लिये किसी उद्योग की सहज प्रवृत्तियों की भी परीक्षा की जानी चाहिये ।

(३) स्थानिक भाज्य उद्योग के केन्द्रीयकरण की मात्रा का सूचक नहीं है—क्योंकि वह प्रत्येक क्षेत्र में कार्य सलग्न औद्योगिक शक्तियों की सहायता पर आधारित होता है । तुलना का एक अधिक अच्छा आधार विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा हो सकती है ।

निष्कर्ष—

यह उल्लेखनीय है कि फ्लोरेन्स व वेबर के सिद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं। वेबर के विरुद्ध सिद्धान्त को फ्लोरेन्स के सूचक अंकों के साथ प्रयोग करके किसी देश के लिये उद्योगों के वैज्ञानिक स्थापन की एक नीति बनाई जा सकती है। किन्तु उक्त दोनों ही सिद्धान्त समाज की पूँजीवादी रचना पर आधारित हैं। अतः भारत के लिये उनकी सहायता से बनाई गई नीति उपयोगी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने समाजवादी समाज का लक्ष्य अपनाया हुआ है और ऐसे समाज में लागत सम्बन्धी विचार वस्तुस्थिति सम्बन्धी विचारों के आवीन रहे जाने हैं।

STANDARD QUESTIONS

1. Critically examine the Weber's Theory of Industrial location.
2. Write a note on Sargant Florence's Inductive Analysis of Industrial location.

अध्याय ४४

औद्योगिक स्थानीयकरण के घटक

(Factors Affecting Industrial Location)

‘स्थानीयकरण’ से आशय—

किञ्चित् सुविधाओं के परिणामस्वरूप किसी उद्योग के विशिष्ट केन्द्र या स्थान में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति को ही ‘औद्योगिक स्थानीयकरण’ कहने हैं। क्लकर्स में जूट मिल उद्योग, बम्बई में सूती वस्त्र मिल उद्योग, टाटागर में स्थापन उद्योग, आदि औद्योगिक स्थानीयकरण के ज्वलन्त उदाहरण हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में जिन प्रकार कुछ उद्योग सम्बन्धित हो गए हैं, उससे स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले घटकों के महत्त्व का आभास होता है। इनमें कई सन्देह नहीं है कि अब स्थानीय असमानताओं का समान करने की दशा में काफी प्रगति की गई है। मशीनों व इमारतों के प्रमाणीकरण, मजदूरी एवं व्याज की दरों का समानीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं के प्रमाणीकरण द्वारा स्थानीय असमानताएँ बहुत कुछ कम हो गई हैं, तथापि यह मानना होगा कि निर्माणी सस्थाओं के सामंदायिक संचालन पर ‘स्थान’ का अब भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह बात छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में अधिक सही है। एक छोटी सस्था के पास मुख्यतः स्थानीय बाजार होना है और वह निकटवर्तीय विनियोगकों से ही पूँजी प्राप्त कर पाती है। जब एक बार उद्योग किसी स्थान में स्थापित हो जाता है, तो वहाँ से फिर उसे हटाने में बहुत असुविधा होती है।

स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारण—

किसी सस्था के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारण तो अनेक हैं, परन्तु मुख्य एवं सार सिद्धान्त यह है कि किसी कारखाने का स्थान इस प्रकार निश्चित किया जाय कि वह कम से कम मूल्य पर माल का निर्माण करके अधिक से अधिक मूल्य पर बेच सके। किसी कारखाने के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक अनेक प्रकार वर्णित किये जा सकते हैं :—

श्रौद्योगिक स्थानीयकरण के

प्रमु ४ घटक

(I) क्रय सम्बन्धी घटक—

- (१) कच्चे माल का सामोप्य
- (२) कच्चे माल की उपलब्धता ।

(II) निर्माण सम्बन्धी घटक—

- (१) भ्रम की सुविधा ।
- (२) श्रौद्योगिक शक्ति की सुविधा ।
- (३) मरम्मत आदि की सुविधा ।
- (४) साख व बैंकिंग सुविधा ।
- (५) यातायात व सन्देश वाहन की सुविधा ।
- (६) प्लान्ट के निर्माण व विकास की सुविधाएँ ।
- (७) राजकीय नियमन व सहायता ।
- (८) अग्नि से सुरक्षा ।
- (९) अनुसन्धान की सुविधा ।
- (१०) उपयुक्त प्राकृतिक रचना व जलवायु ।

(III) अन्य उद्योगों से सम्बन्धित घटक—

- (१) पूरक उद्योग ।
- (२) प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग ।
- (३) भौगोलिक प्रादुर्भाव ।

(IV) विक्रय सम्बन्धी घटक—

- (१) बाजार की निकटता ।
- (२) जन संख्या का घनत्व ।
- (३) पैशन व स्टाइल ।

(I) क्रय सम्बन्धी घटक—

(१) कच्चे माल का सामोप्य— उद्योग घटो की प्रगति बहुधा उहां स्थानों में देखी जाती है जहां कच्चा माल पाया जाता है, विशेषकर उस दशा में जबकि कच्चा माल अचल हो अथवा अपने बोझ के अनुपात में सस्ता हो । उदाहरण के लिए, खान खोदने का काम खानों के निकट ही पाया जाता है, लकड़ी का काम जङ्गलों के समीप ही होता है और कपड़े के कारखाने भी प्रायः उन्हीं स्थानों में होते हैं जहां कपास पर्याप्त परिमाण में सुलभ है ।

(२) कच्चे माल की उपलब्धता—किसी कच्चे माल का निकट में अपरिमित मात्रा में उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन् उस तक पहुँच होना भी आवश्यक है । यदि कच्चे माल के खोद तक पहुँच सम्भव नहीं है, तो उसका शोषण नहीं किया जा सकेगा । कच्चे माल के स्रोत तक पहुँच न होने का एक प्रधान कारण यह होता है कि काम करने वाले श्रमिकों को जीवन निर्वाह के साधन वहाँ उपलब्ध नहीं होते या बहुत कठिनाता से उपलब्ध होते हैं । यदि कच्चे माल के साधनों का शोषण करने की लागत बहुत अधिक बैठती है, तो कहा जायगा कि कच्चे माल तक पहुँच नहीं है । इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में कच्चे माल के उपलब्ध होने का महत्त्व पर्याप्त यातायात सुविधाओं, उपजाऊ मिट्टी व उपयुक्त जलवायु आदि पर निर्भर होता है ।

(II) निर्माण सम्बन्धी घटक—

(१) भ्रम की सुविधा—प्रत्येक

उद्योग में श्रम की आवश्यकता होती है। किसी किसी उद्योग में तो श्रमिक माना एवं विशेष ज्ञान से सम्पन्न कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि रेशम-उद्योग में। अस्तु, ये उद्योग वही स्थापित होने का प्रयत्न करेंगे जहाँ कुशल श्रम सरलता और कम दामों पर मिल सके। फलस्वाभाव में रंगाई और छपाई का उद्योग श्रम की सुलभता के कारण केन्द्रित हो गया है। वास्तव में श्रम की पूर्ति किसी स्थापित उद्योग को शक्ति प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग का निर्माण होने में कुछ समय लगता है और एक बार निर्मित हो जाता है तो उसे यातायात करना सरल नहीं होता। उदाहरण के लिये, भारतीय औद्योगिक श्रमिक मुख्यतः गाँवों से प्राप्त होते हैं। यद्यपि वे बहुत प्रवासी प्रकृति के होते हैं तथापि बम्बई, जमशेदपुर, मद्रास, नागपुर, और अहमदाबाद जैसे शहरों में औद्योगिक जन सन्ध्या स्थायी होती जा रही है। इस नये औद्योगिक वर्ग में औद्योगिक कुशलता का विकास हो गया है और स्थानीयकरण को प्रभावित करता है।

(२) औद्योगिक शक्ति की सुलभता—औद्योगिक शक्ति की निकटता स्थानीयकरण को बड़ा प्रभावित करती है। कल कारखाने उन्हीं स्थानों में उत्पत्ति कर सकते हैं जहाँ कि उनको चलाने की शक्ति सुलभ हो। शीघ्रता औद्योगिक शक्ति का सबसे प्रमुख साधन है। अतएव ऐसा देखा गया है कि उद्योग अधिकतर कोयले की खानों के समीप में ही केन्द्रित हैं। परन्तु कोयले में औद्योगिक शक्ति के साधन की दृष्टि से जो एक बड़ा दोष है, वह यह है कि अपने भार के अनुपात में यह सस्ता है और इस कारण दूर के स्थानों में इसे लाया नहीं जा सकता। अतः औद्योगिक शक्ति के क्षेत्र में अनेक अनुसन्धान हुए और नवीन साधन निकाले गये। तेल बड़ी सुविधा से पाइपों द्वारा दूर-दूर तक ले जाया जा सकता है। अतः इस अनुसन्धान के फलस्वरूप उद्योगों में विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुआ, अर्थात् उद्योग एक जगह केन्द्रित न रहकर बिखरने लगे, जिससे ग्रन्थ सुविधाओं का, जो ऐसा करने से मिल सकती हो, लाभ उठाया जा सके। विद्युत-शक्ति के आविष्कार (विशेषकर जन-विद्युत) से विकेन्द्रीयकरण की यह प्रवृत्ति और भी बढ़ रही है।

(३) मरम्मत आदि की सुविधा—यह घटक छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए विशेष महत्व रखता है। जहाँ अधिक आदेश प्राप्त होते रहते हैं वहाँ किसी भी स्तर पर मशीन में टूट-फूट हो जाने से फर्म को व्यापार में हानि होती है और उसकी प्रतिष्ठा को घटका पहुँचता है। अतः यह आवश्यक है कि मरम्मत कार्य तत्काल किया जाय। एक बड़ी संस्था में मरम्मत कार्य कारखाने में ही कराया जा सकता है, क्योंकि वह अपने यहाँ एक मरम्मत वर्कशॉप खोल लेती है।

(४) औद्योगिक साख व बैकिंग की पर्याप्त सुविधायें—प्राधुनिक युग में यह स्थानीयकरण का महत्वपूर्ण कारण है। पूँजी उत्पत्ति का एक ऐसा साधन बन गई है जिसे अलग करके या जिसके बिना कोई उद्योग या धन्धा पनपने की आशा नहीं कर सकता। अतः जहाँ पूँजी प्राप्त करने की सुविधायें हैं वहाँ उद्योग विशेष रूप

से स्थापित होंगे, जैसे कि वे स्थान जहाँ जन सख्या बचत कर सकती है और जहाँ औद्योगिक अधिकोप इत्यादि हो।^{*}

(५) यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों की पर्याप्तता—प्रायः ऐसा देखा गया है कि उद्योग-धन्धे उस स्थान पर ही केन्द्रित होते हैं, जहाँ माल साने-ले जाने व समाचार शीघ्र भगाने व भेजने की विशेष सुविधायें हो। यातायात तथा सन्देश-वाहन के सस्ते, सरल तथा शीघ्रगामी साधनों ने बाजार की दूरी की हानियाँ कम हो जाती हैं। यहाँ पर यह कहना अनावश्यक न होगा कि ऐसे साधनों की उन्नति से केन्द्रीयकरण भी हो सकता है।

(६) प्लान्ट के निर्माण व विकास की सुविधायें—प्लान्ट (Plant) को इस तरह स्थापित करना चाहिए जिसमें समय एवं सामग्री का न्यूनतम व्यय करते हुए निर्माण क्रिया सम्बल की जा सके। साथ ही विस्तार एवं पुनर्गठन के लिये चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़ देना चाहिए, जिससे कि कार्य चलते हुए ही विस्तार सम्भव हो सके।

(७) राजकीय नियम व सहायता—राजकल केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें सभी प्रकार के व्यापार में अधिकाधिक भाग लेने लगी हैं और उनके नियन्त्रण में बहुत वृद्धि हो गई है। निर्माणी उद्योगों पर उन नियमों का अधिक प्रभाव पड़ा है जो कि कर्मचारियों की सुरक्षा, क्षतिपूर्ति व अन्य कर्तव्यों में, इमारतों के प्रयोग करने, अग्नि निरोधक उपायों, लाइसेंस, पेटेंट, कायस्थान धष्टे आदि से सम्बन्ध रखते हैं। जब ये प्रतिबन्ध अधिक भार युक्त हो जाते हैं, अर्थात् उद्योगों को लाभ की दृष्टि से चलाना कठिन हो जाता है, तो निर्माता किसी अन्य अधिक अनुकूल क्षेत्र में जाने की योजना बनाता है। नये उद्योगों की स्थापना करते समय उद्योगपति पहले उपरोक्त तत्त्वों को ही विचार में लेते हैं। सरकार अधिक सहायता देकर भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती है। प्रशुल्क प्रतिबन्ध विदेशी स्पर्धा से देशी उद्योगों को बचाते हैं।

(८) अग्नि से सुरक्षा—आग बाहर से लग सकती है और अन्दर से भी। अग्निरोधी आग पर अग्नि निरोधक यंत्रों से काबू पाया जा सकता है, लेकिन बाहर से लगने वाली आग पर नियन्त्रण पाना प्रायः कठिन होता है। भारत के अधिकांश नगरों में अग्नि निरोधक व्यवस्था बहुत दुर्बल दशा में है। गाँवों में तो ये सुविधायें बिल्कुल भी नहीं हैं। परिणामस्वरूप अग्नि बीमों की प्रीमियम की दर बहुत ऊँची है। अग

* 'In Great Britain during the nineteen thirties the opportunities provided for financing new industries through the special Areas Reconstruction Association and the Nuffield Trust induced many entrepreneurs to choose a site in the distressed areas.'

उद्योग की स्थापना के लिए वह स्थान विशेष उपयुक्त है जहाँ कि अग्नि से अधिक सुरक्षा हो ।

(६) अनुसन्धान की सुविधाये—नये व पुराने सभी उद्योगों की उन्नति निर्माण क्रियाओं से सम्बन्धित अनुसन्धानों की प्रगति पर निर्भर होती है । साथ ही, यह भी आवश्यक है कि शिक्षित एवं ट्रेन्ड कर्मचारी यथेष्ट संख्या में बराबर मिलते रहें । अतः अनुसन्धान की प्रगति एवं ट्रेन्ड कर्मचारियों की उपलब्धि के लिए शैक्षिक एवं अनुसन्धान संस्थाओं का होना आवश्यक है ।

(१०) उपयुक्त रचना एवं जलवायु—किसी स्थान विशेष की प्राकृतिक रचना एवं जलवायु का भी स्थानीयकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है । उदाहरण के लिए, एक पहाड़ी, ऊबड़-खाबड़ एवं चट्टानी प्रदेश में कृषि काम बहुत कठिनाता से हो पाता है । अतः वहाँ औद्योगिक प्रगति भी प्रायः कम ही होती है । हाँ, यदि वहाँ खनिज पदार्थ मिलते हों, तो किसी उद्योग विशेष की प्रगति होना संभव है । पहाड़, पठार व तूफानी नदियाँ औद्योगिक विकास में बाधा डालती हैं, क्योंकि इनके कारण यातायात कठिन हो जाता है । जन संख्या की वृद्धि पर भी इनका कुप्रभाव पड़ता है, जिससे स्थानीय बाजार विकसित नहीं होने पाते ।

इसी प्रकार जलवायु का भी औद्योगिक स्थानीयकरण पर प्रभाव पड़ना है । उदाहरण के लिए, सूती कपड़ों के मिलों के लिए नम जलवायु उपयुक्त होती है, क्योंकि नम जलवायु में कपास से पतला और सुन्दर सूत काता जाता है । यही कारण है कि सूती कपड़ों का उद्योग मम्बई में ही विशेष रूप से केन्द्रित है ।

(III) अन्य उद्योगों से सम्बन्धित घटक—

(१) पूरक एवं (२) प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग—कुछ निर्मातागण अपने कारखानों की स्थापना के लिए ऐसे स्थान चुनते हैं जहाँ पूरक अथवा सहायक उद्योगों का (जहाँ कि उनके निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री बनती हो) बाहुल्य हो । इस प्रकार पूरक उद्योगों की उपस्थिति उद्योगों के केन्द्रीयकरण का बड़ावा देती है । किन्तु, इसके विपरीत, प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों की उपस्थिति विकेन्द्रीयकरण को बड़ावा देती है । एक कारखाने का श्रम सघर्ष अन्य कारखानों में भी फैलना, श्रमिकों के प्राप्त करने में होड़, नवीन रीति का उपयोग करने में प्रथा का बाधक होना आदि बातें हानिकारक हैं । तथापि, जैसा कि श्री जोन्स ने अपनी पुस्तक *Administration of Industrial Enterprises* में बताया है, उद्योग प्रायः 'समूह' में ही विशेष उन्नति करते हैं, क्योंकि (1) एक ही स्थान में स्थापित समान उद्योगों को सामग्री सुविधा से व सस्ती मिल जाती है, (11) एक विशिष्ट श्रम बाजार विकसित हो जाता है, जिससे देश के बौने-बौने से उस लाइन में कुशल श्रमिक खिंचे चले आते हैं । यह बात श्रम व उद्योग दोनों के लिए लाभकारी है । (111) बैंक भी विशिष्ट केन्द्रों के प्रमुख उद्योगों की आवश्यकताओं से परिचित हो जाते हैं । उन्हें इस उद्योग में सलग्न विभिन्न फर्मों की आर्थिक दशा की जानकारी हो जाती है तथा वे उनके बिलों को अधिक

तत्परता से भुना लेते हैं। (iv) कुछ कारखाने मिल कर ऐसी माँग उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी पूर्ति के लिए औद्योगिक सेवा उद्योग निकटवर्ती क्षेत्र में कायम होने लगते हैं, जैसे—ढलाई के कारखाने, मशीन, औजार व मिल स्टोर सप्लाय करने वाली सस्थाएँ आदि। (v) एक विशिष्टीकृत औद्योगिक केन्द्र की रयाति का लाभ वहाँ की कुशल एवं कम कुशल सभी प्रकार की सस्थाओं को मिलता है, जिसमें वस्तु विक्रेता में ग्रामासी हो जाती है। (vi) विशिष्ट औद्योगिक केन्द्रों में पैकरो, बीमको, प्रपको, श्रेणी विभाजन करने वालों, विज्ञापन सस्थाओं, सार्वजनिक भण्डारगृहों आदि की सुविधाओं का भी बाहुल्य हो जाता है।

(३) शीघ्र प्रारम्भ का भावेग अथवा पूर्वारम्भ (Geographical Inertia or Momentum of an Early Start)—कभी-कभी उद्योगों की उन्नति एक विशिष्ट स्थान पर इसलिए भी हुई है कि सबसे पहले वह उद्योग वही पर प्रारम्भ किया गया था। कालान्तर में वहाँ उस उद्योग की सभी सुविधायें एकत्र हो जाती हैं, यहाँ तक कि भविष्य में इन उद्योगों की वही स्थापित होने की प्रवृत्ति हो जाती है।* ये लाभ इस प्रकार हैं :—विशिष्ट भ्रम की उन्नति, अनुपूरक उद्योगों का जन्म तथा उनका विकास, अन्वेषण तथा उन्नति की विशेष सुविधायें, आदि। दृष्टान्त के लिए, फ़िरोजाबाद में चूड़ी उद्योग का केन्द्रित होना प्रमुख रूप से 'शीघ्र प्रारम्भ के भावेग' के कारण है।

(IV) विक्रय सम्बन्धी घटक—

(१) बाजारों की निकटता—बाजारों की निकटता उद्योगों के स्थानीयकरण में एक महत्वपूर्ण कारण है। बाजार की निकटता से हमारा तात्पर्य यह है कि उन स्थानों के क्रेता माल की माग कर, वहाँ पर स्पर्धा इतनी तीक्ष्ण न हो कि माल का भ्राना ही असम्भव हो जाय और न वहाँ माल का भावागमन रोकने वाले ऊँचे भायाग व निर्यात कर या चुङ्गी हो। ऐसी सुविधा के स्थानों पर ही प्रायः उद्योगों का कन्दित होना देखा जा सकता है।

(२) जन-संख्या का घनत्व एवं लोगों का स्वभाव—यभी निर्माणी उद्योगों का सक्षम ऐसी वस्तुयें उत्पन्न करना है जो कि लोग खरीद ले। किन्तु किसी वस्तु का बाजार कैसा होगा, यह जन संख्या के घनत्व, उसकी सम्पन्नता एवं जीवन-यापन के ढङ्ग पर निर्भर होता है। जिस वस्तु को लोग उपयोगी नहीं समझते हैं उसे बनाना निरर्थक है। उपभोग-वस्तुओं की विक्री तभी हो सकती है जबकि लोगों को उनका उपभोग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता हो।

(३) फैशन एवं स्टाइल—लोग पुराने फैशन की वस्तुओं को खरीदना पसन्द नहीं करते। एन स्थान जहाँ से नये फैशन की वस्तुयें जनता में शीघ्र फैल सकती हैं, वस्तुओं के लिए अच्छे बाजार प्रमाणित होते हैं। इस सम्बन्ध में यह देखा गया है कि फैशन बड़े नगरों से छोटे नगरों में और घनाढ्य क्षेत्रों से कम घनाढ्य क्षेत्रों में फैलता है।

* When an industry is known to have concentrated in a particular area it is always easy to discover natural advantages attaching to the site." (A Beaucham Economics of Industrial

Organisation, p. 136)

औद्योगिक स्थानीयकरण के गुण-दोष

भारत में औद्योगिक स्थानीयकरण के आलोचनात्मक अध्ययन के पूर्व स्थानीयकरण के गुण व दोषों की विवेचना अनावश्यक न होगी। स्थानीयकरण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं :—

स्थानीयकरण के लाभ—

(१) श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि—जब कोई उद्योग किसी स्थान विशेष में ही केन्द्रित हो जाता है, तब स्वभावतया उस स्थान के श्रमिक उस उद्योग की कला में निपुण हो जाते हैं। श्रमिक ही नहीं धरन् कारीगरों की सन्तान भी अपने पूर्वजों के धन्वे में कुशल हो जाती है, क्योंकि प्रति दिन वे अपने चारों ओर उसी का वातावरण देखते हैं।

स्थानीयकरण के लाभ हैं पांच

- (१) श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि।
- (२) श्रम विभाजन से अनुसन्धान तथा उन्नति।
- (३) स्थान की प्रसिद्धि।
- (४) अन्य उद्योगों का जन्म।
- (५) व्यापारिक मशीनरी की उन्नति।

(२) श्रम-विभाजन से अनुसन्धान तथा उन्नति—स्थानीयकरण से श्रम का अधिक विभाजन सम्भव हो जाता है तथा नई-नई खोज करना भी सरल हो जाता है।

(३) स्थान की प्रसिद्धि—जब किसी स्थान विशेष में ही उद्योग केन्द्रित हो जाता है तब जनता में माल किसी विशेष मिल के नाम से न होकर केन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जैसे फ़िरोजाबाद काँच-उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फर्रुखाबाद छपाई के लिए। एक केन्द्र में बड़े-छोटे, अच्छे-बुरे सभी प्रकार के कारखाने होने हैं, किन्तु माल किसी विशेष मिल के नाम में नहीं धरन् केन्द्र के नाम से बिकता है। इस प्रकार घटिया मिलों का माल भी बढ़िया मिलों के माल के साथ बिक जाता है।

(४) अन्य उद्योगों का जन्म—उद्योग के किसी क्षेत्र में केन्द्रित हो जाने पर वहाँ अन्य अनेक गौण उद्योग भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे शक्कर के कारखानों के पास दोरे आदि का काम प्रारम्भ होता है। इन अन्य उद्योगों की उन्नति से अनेक मनुष्यों को काम मिल जाता है और प्रधान उद्योग का निरर्थक पदार्थ भी प्रयोग में आ जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विभिन्न घटकों का सापेक्षिक महत्त्व समय के साथ बदलता रहता है और विशेष परिस्थितियों में या स्थान किसी उद्योग के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त या बड़ी उत्पादन की टेक्नीक, यातायात के साधन आदि में परिवर्तन हो जाने के कारण उपयुक्त नहीं रहता। सरल शब्दों में, किसी विशेष अवधि में और किसी विशेष क्षेत्र में औद्योगिक स्थानीयकरण उस विशेष समय के आर्थिक विकास की विशेष अवस्था पर निर्भर होता है। अतः विभिन्न घटकों में परिवर्तन होने में औद्योगिक क्रिया के स्थानीयकरण में परिवर्तन हो सकता है। इन परिवर्तनों को परिवर्तन-

शील लागत सम्बन्धी घटका (Cost factors) की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। स्थानिक सन्तुलन (Locational Equilibrium) कभी भी प्राप्त नहीं होता और समायोजन की प्रक्रिया में कठिनाइयों के कारण अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। स्थानिक परिवर्तन (Locational Changes) के मूल कारणों को हूवर (E. M. Hoover) ने निम्न चार वर्गों में बाँटा है—(१) मौसमी (seasonal) चार्किक (cyclical) (२) दीर्घकालीन (secular) एवं (४) संरचनात्मक (structural)।

(५) व्यापारिक मशीनरी की उत्पत्ति—उद्योगों के स्थानीयकरण से उन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में सामान आता तथा जाता है और इस वृद्धि काय के लिए कुशल यातायात मशीनरी की आवश्यकता होती है। अतः उन क्षेत्रों में यातायात तथा संचार वाहन के साधनों की वृद्धि हो जाती है व अनेक व्यापारिक समस्याएँ भी खुल जाती हैं, जैसे अधिकोप आगोप प्रमण्डल आदि।

स्थानीयकरण से हानियाँ—

केन्द्रीयकरण में नाचे लिखे दोष हैं —

(१) धर्मिक की सीमांत उत्पत्ति—केन्द्रीयकरण से केन्द्र स्थान के धर्मिक केवल उस उद्योग सम्बन्धी कला में निपुण होते हैं अनएव यदि वह उद्योग दुर्भाग्य से कहीं समाप्त हो जाय तो व धर्मिक बेकार हो जाते हैं। दूसरे केन्द्रीयकरण से धर्म जोबिया के एक स्थान में दूसरे स्थान पर जान की क्षति भी कम हो जाती है।

(२) आर्थिक तथा सामाजिक हानियाँ—धर्मिक तथा सामाजिक दृष्टि कोण से भी केन्द्रीयकरण हानिकारक है। एक ही स्थान पर उद्योगों के बढ़ने से उस स्थान की जन संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है इससे स्थान की समस्या तथा अनेक अन्य आर्थिक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।

(३) राजनैतिक दृष्टिकोण—इससे भी उदाहरण है एक स्थान पर केन्द्रित होना वांछित नहीं क्योंकि यदि कभी अभावग्रस्त उस क्षेत्र पर ही बम वर्षा हुई तो समस्त उद्योग नष्ट प्रायः हो जायगा और इससे सम्पूर्ण राष्ट्र को क्षति पहुँचेगी।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Discuss carefully the factors which affect the location of industries
- 2 Briefly summarise the merits and demerits of centralisation

अध्याय ४५

भारतीय उद्योगों के स्थानीयकरण का स्वरूप

(Form of Localisation of Indian Industries)

भूमिका—

प्रारम्भ में भारतवर्ष में उद्योग-धन्धे कुछ उही चुने हुये स्थानों में थे जहां केन्द्रीयकरण के लिये विशेष सुविधायें थी, विशेषकर समुद्रतट के निकट के नगरों में, जैसे कि बम्बई और कलकत्ता के आस-पास। भौगोलिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से ये स्थान बड़े उपयुक्त हैं। निर्मित तथा अनिर्मित माल के लाने तथा ले जाने के साधनों की सुविधायें तो यहाँ हैं ही, इससे अतिरिक्त यहाँ औद्योगिक शक्ति के भी भण्डार हैं। पूँजी की यहाँ सदैव सुविधा रही और अब भी है। इन स्थानों में ही देशी-विदेशी प्रबन्ध अभिवृत्तियों के प्रधान कार्यालय रहे और अब भी हैं। अंग्रेज प्रवर्तकों ने सर्वप्रथम कलकत्ते में आकर अपने व्यापार के जाल को विरोना प्रारम्भ किया था। बम्बई में भारतीय पूँजीपतियों ने उद्योग प्राप्त किये थे। संक्षेप में, यो कह सकते हैं कि वहाँ उत्पत्ति के सम्पूर्ण साधनों की सुविधा थी। बम्बई में सूत की मिलें और कलकत्ता में जूट के मिल दिन पर दिन बढ़ने लगे। इन दो क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ स्थान घाड़े से और हैं जहाँ कि उद्योग केन्द्रित हुए, जैसे कानपुर नागपुर, अहमदाबाद, मद्रास, टाटानगर व इन्दौर। इन नगरों के बाद भारत के औद्योगिक नगरों की नामावली समाप्त हो जाती है। उद्योगों के इन इन-चुने स्थानों पर ही केन्द्रित होने का एक कारण अंग्रेजों का अपना स्वार्थ भी था। ये विदेशी कभी भी यह नहीं चाहते थे कि भारत में उद्योग किसी वैज्ञानिक योजना के अनुसार बनयें। उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। यदि भारत में उचित ढंग से उद्योग विकसित होते, तो फिर उनके देश के कारखानों का कार्य कैसे चलता ? वे तो भारत से कच्चा माल ले जाते और उससे अपने देश के उद्योगों को चलाते थे। देश के किंचित स्थानों पर अवश्य कुछ साहसी विदेशी व्यक्तियों ने अपने निजी लाभ की दृष्टि से उद्योग प्रारम्भ किये थे। आइये, अब हम अपने देश के विचित्र औद्योगिक केन्द्रीयकरण की भाँकी करें।

(१) सूती वस्त्र उद्योग—

सूती कपड़े की अधिकतर मिलें बम्बई तथा अहमदाबाद में ही हैं। यह सत्य

है कि इन नगरों के आस-पास की भूमि कपास की उपज के लिये बड़ी उपयुक्त है। यातायात के साधन भी यहां पर सबसे अधिक हैं। अनाएव कपड़े की मिलें यहीं पर केन्द्रित हुईं, परन्तु कपास एक हल्का पदार्थ है और कम खर्च में भी काफी दूर तक सरलता से भेजा जा सकता है, इसलिये औद्योगिक शक्ति (विशेषकर जल-विद्युत) की उन्नति के साथ कपड़े की मिलें भी इधर-उधर बिखरने लगी, जैसे—नागपुर, वानपुर, इन्दौर, मद्रास आदि में कपड़ा मिल खोले गये। किन्तु यह विवेन्द्रीयकरण किन्हीं वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं हुआ और न आज ही है। उदाहरण के लिये, ब्वालियर में कपड़े का एक बहुत बड़ा मिल है (जीवाजी रॉब कॉटन मिल्स), यद्यपि वहां कपास पैदा नहीं होती। वास्को में यहां पर इस मिल की स्थापना किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर नहीं, अपितु 'कर' को बचत करने के लिये हुई। कानपुर, नागपुर आदि नगरों में कपड़े का उद्योग यातायात के साधनों की उन्नति के कारण ही बढ़ गया है। बम्बई तथा अहमदाबाद के नगरों में सूती कपड़े के उद्योग के विकेन्द्रीयकरण के कुछ और भी कारण हैं। बम्बई व अहमदाबाद में उद्योगपतियों को अधिक किराये, अधिक मजदूरियां तथा जल एवं अन्य सेवाओं के लिये अधिक दाम देने पड़ते हैं, अतः विकेन्द्रीयकरण की ओर उद्योगों का विशेष झुकाव है। जल-विद्युत के विकास के साथ-साथ कपड़े की मिल दक्षिण-भारत के अनेक नगरों में फैल गई हैं, जैसे मदुरा, सूतीकोरन तथा कोयम्बटूर में।

(२) जूट उद्योग—

जूट उद्योग अधिकतर बंगाल प्रांत तक ही सीमित है और वह भी कलकत्ता तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में ही। जूट की कुल २५ मिलों में से ६० कलकत्ता तथा इसके इधर केन्द्रित हैं। जूट उद्योग में विवेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति (अर्थात् कि कपड़े के उद्योग में है) नहीं देखी जाती। इसका मुख्य कारण यह है कि इस उद्योग में स्थानीयकरण का एक विशेष नियम लागू होता है। कच्चा जूट बहुत सस्ता होता है, अतएव जूट का उद्योग कहीं अन्य स्थान पर स्थापित किया जाय तो कच्चा माल वहां पर ले जाने में खर्चा बहुत बढ़ जायगा। 'जितने की बुद्धिया नहीं, उससे अधिक कटोराई' वाली कहावत यहां चरिताथ होती है, अर्थात् कच्चा माल वैसे अधिक सस्ता है, पर भाड़े के कारण उसका कुल दाम बहुत बढ़ जायगा। इस कारण जूट-उद्योग जूट की पैदावार के क्षेत्र में केन्द्रित है। बंगाल में गंगा की अनेक सहायक शाखाओं द्वारा बहुत कम खर्च में कच्चा माल जूट के कारखानों तक भेजा जा सकता है। किन्तु बंगाल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कच्चा माल भेजने के लिये ऐसी सुविधायें नहीं हैं, जिनके फलस्वरूप जूट उद्योग बंगाल में ही केन्द्रित है।

जूट की भाँत कोयला भी भारी होन के कारण दूर-दूर के स्थानों पर केवल अधिक भाड़ा देने पर ही भेजा जा सकता है। अतः कोयला उद्योग भी कोयले की खानों के निकट ही केन्द्रित हो गया है। उसके विकेन्द्रीयकरण की भी कोई सम्भावना

नहीं है। उद्योग के मुख्य केन्द्र रानीगंज, भरिया तथा बकारो हैं; इन केन्द्रों से ६०% कोयला मिलता है। कोयला औद्योगिक शक्ति का एक प्रमुख साधन है, अतः अन्य उद्योग भी प्रायः कोयले की खानों के आस-पास ही केन्द्रित हुए और होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ सुविधा से कोयला प्राप्त हो जाता है, परन्तु वर्तमान युग में जब से जल-विद्युत का आविष्कार हो गया है, ऐसी बात नहीं रही। अब औद्योगिक शक्ति तार की लाइन द्वारा बहुत दूर तक भी सरलता से पहुँचाई जा सकती है।

(३) लौह उद्योग—

लौह उद्योग भी वही सम्भव है जहाँ कच्चा लोहा, कोयला तथा पत्थर का चूना विद्यमान हो। ये चीजें अन्य स्थानों में अधिक व्यय करने पर ही भेजी जा सकती हैं, अतः लौह उद्योग सिंधभूमि जिले से उशीसा तक ही केन्द्रित है, क्योंकि यहाँ पर ही ये मद्दार्थ प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं।

(४) शक्कर उद्योग—

शक्कर उद्योग भारत में केवल उत्तर-प्रदेश तथा बिहार के प्रान्तों में ही सीमित है, क्योंकि ये गन्ने के प्रदेश हैं। परन्तु अब सिंचाई के साधनों की उन्नति के साथ शक्कर-उद्योग बम्बई तथा मद्रास में भी बढ़ रहा है। इस उद्योग का विकेन्द्रीयकरण केवल उन्हीं भागों में सम्भव है जहाँ पर गन्ना पैदा होता हो मयबा हो सकता हो, क्योंकि यह बड़ा आवश्यक है कि शक्कर के कारखानों के अधिक से अधिक १६ मील के दूर-गिर्द गन्ना निकलता हो, नहीं तो अधिक दूर से असग करके लाये हुए गन्ने कारखाने तक भाते भाते सूखकर खराब हो जाते हैं।

(५) कागज उद्योग—

कागज उद्योग भी अभी तक बंगाल तथा रानीगंज में ही केन्द्रित है। बम्बई, पंजाब, मद्रास तथा ससनरु में भी कागज की कुछ मिलें हैं। यह उद्योग सवाई घास (मयबा कागज की लुग्दी या बाँस) तथा सस्ती औद्योगिक शक्ति पर निर्भर है। शक्ति की सुलभता के कारण ही यह उद्योग अभी तक बंगाल तथा रानीगंज के निकट ही केन्द्रित है। किन्तु अब प्राप्ता की जानी है कि शक्ति के साधनों की उन्नति के साथ-साथ इस उद्योग का भी विकास तथा विकेन्द्रीयकरण होगा।

(६) सीमेन्ट उद्योग—

सीमेन्ट उद्योग भारत में गिने-चुने स्थानों पर ही केन्द्रित है, जैसे—डालमियाँ नगर, कटनी, जबलपुर, काठियावाड़ तथा ग्वासियर में। यद्यपि पत्थर का चूना इस देश में अधिकता से अन्य अनेक स्थानों पर भी पाया जाता है।

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly describe the locational pattern in Indian Industries.

उद्योगों का प्रादेशिक वितरण

(Regional Distribution of Industries)

भूमिका—

उद्योगों का प्रादेशिक या विकेन्द्रित विकास आधुनिक युग की एक प्रमुख आवश्यकता बन गया है। विशाल क्षेत्रफल वाले देशों के लिए इस दृष्टिकोण का विशेष महत्व है। औद्योगिक विकास की प्रादेशिक प्रणाली विवेकपूर्ण आर्थिक नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है। श्री बेलरबी (Bellerby) अपनी पुस्तक *Economic Reconstruction* में लिखते हैं कि, “औद्योगिक क्रिया के अत्यधिक केन्द्रीकृत स्वभाव के कारण एक राष्ट्रीय योजना के सहज निष्पादन में बड़ी रुकावट पड़ती है। अतः आर्थिक योजना के एक भाग के रूप में प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक प्रादेशिक विकास योजना भी होनी चाहिये।”

प्रादेशिक आधार पर विकास के सम्बन्ध में मतभेद—

यह देखते हुए कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये एक ही सुविधायें नहीं हैं, प्रादेशिक आधार पर उद्योगों का वितरण करना सरल नहीं जान पड़ता। इस आधार पर वितरण हो भी या नहीं, यह स्वयं विवाद का प्रश्न है। एक ओर तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय आर्थिक हित और औद्योगिक निपुणता सदा ध्यान में रखनी चाहिये और साधारणतया उद्योग के वहाँ स्थापित होने में, जहाँ लागत मुख्य न्यूनतम पड़े, कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये, क्योंकि बँसा करना माजकल की प्रतिद्वन्द्विता के युग में औद्योगिक विकास के लिये बड़ा अहितकर सिद्ध होगा। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि राज्य ही प्रत्येक प्रदेश के लिए आर्थिक हितों के अधिक

* The extremely localised character of industrial activity presents a serious stumbling block to the smooth performance of a national plan. Super imposed on the national plan and becoming part of it there must be a regional plan in each area for dealing specifically with the large local residue of unemployment.” (J. R. Bellerby :—*Economic Reconstruction*, p. 287.)

उचित वितरण का प्रयत्न करे। वितरण एवं उत्पादन व्यय की दृष्टि से जहाँ केन्द्रीय-करण सस्ता पड़ता हो वहाँ भी अधिकतर दशाओं में यह देखा जायेगा कि अन्त में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के उद्योगों का विकेन्द्रित किया जाना ही राष्ट्रीय हित में है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मत उल्लेखनीय है—

(१) 'राष्ट्रीय आर्थिक नीति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक विकास का यथासम्भव उचित सन्तुलन हो एवं सम्पूर्ण देश के प्रत्येक भाग में उचित रीति से सब प्रकार के उद्योग फैलें।'

(भारती कमीशन)

(२) 'राजनैतिक तथा आर्थिक योजना समुदाय ने भी उद्योगों के लिये अवांछित सामाजिक, आर्थिक और रक्षात्मक परिणामों एवं कुछ शहरी क्षेत्रों के प्रति औद्योगिक हो जाना का रोकने के लिए नये-नए प्रादेशिक विकास पर जोर दिया है। इससे न केवल बहुमुखी आर्थिक व्यवस्था के लाभ प्राप्त होंगे, वरन् गाँव की पिछड़ी हुई दशा भी सुसंगठित हो जायेगी।

यदि इस व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो 'आर्थिक' और 'सामाजिक' आधारों में कोई अन्तर मालूम नहीं होगा। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कम से कम व्यय पर प्राप्त करना है, अर्थात् राज्य को न केवल आय प्राप्त करने की शक्ति बढ़ानी है, वरन् औद्योगिकरण की सामाजिक कीमत भी कम करनी है। वास्तविक समस्या तो यह है कि किन केन्द्रों का विकास समस्त राष्ट्र के दृष्टिकोण से अधिक हितकर है। अतः देश के आर्थिक हित के विचार से यह आवश्यक है कि उद्योगों का प्रादेशिक आधार पर पुनः संगठन हो।

उद्योगों के प्रादेशिक वितरण के लक्ष्य—

उद्योगों का प्रादेशिक वितरण करने के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

(१) देश के स्थानीय प्रसाधनों का अधिक विकास करने के लिये—

इस प्रकार के औद्योगिक वितरण के अन्तर्गत स्थानीय उद्योगों में विविधता आती है और उनका सन्तुलित विकास होता है। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलित जीवन संभव हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक विकास का लक्ष्य, आत्म निर्भरता नहीं होना, क्योंकि कोई भी प्रदेश इतना सम्पन्न नहीं होता कि वह एक समुचित सभ्य जीवन के लिए आवश्यक सभी औद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति कर सके। वस्तुतः एक प्रदेश की आवश्यक वस्तुएँ दूसरे प्रदेशों में आती जाती हैं

उद्योगों का प्रादेशिक वितरण क्यों ?

- (१) देश के स्थानीय प्रसाधनों का अधिक समान विकास करने के लिये।
- (२) अनुकूलतम औद्योगिक क्रिया के लिये।
- (३) सीमित साधनों का मितव्ययिता से प्रयोग करने के लिये।
- (४) रोजगार के अवसरों का न्यायोचित वितरण करने के लिये।
- (५) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये।

और प्रादेशिक वितरण के फलस्वरूप अन्तर्प्रदेशिक व्यापार के स्वभाव एवं सामग्री में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है।

(२) अनुकूलतम औद्योगिक क्रिया के लिये—उद्योगों के प्रादेशिक वितरण के अन्तर्गत प्रादेशिक सघर्षों को प्राप्ति देने के बजाय राष्ट्रीय प्रगति के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए समन्वित (harmonize) किया जाता है। श्री बालकृष्ण के शब्दों में, “प्रादेशिक विकास का उद्देश्य उपलब्ध प्रसाधनों के उपयोग में अधिक म कुशलता प्राप्त करना है, न कि अपने-अपने उद्देश्यों एवं स्वप्नों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतियोगी दावों का समायोजन करना” ।^४

(३) सीमित साधनों का मितव्ययिता से प्रयोग करने के लिए—भावी पीढ़ी के लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत सीमित एवं समाप्त होने वाले प्रसाधनों का मितव्ययिता से प्रयोग किया जाता है।

(४) रोजगार के अवसरों का न्यायोचित वितरण करने के लिए—प्रादेशिक विकास इस सत्य पर आधारित है कि सम्पन्नता एवं निर्धनता अविभाज्य है। उद्योगों का न्यायपूर्ण प्रादेशिक वितरण होने से रोजगार के अवसर कुछ ही प्रदेशों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सम्पूर्ण देश में व्यापक रूप से सुलभ हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय में असमानता कम हो जाती है। इस प्रकार सभी प्रदेशों के विकास का प्रयत्न किया जाता है।

(५) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये—प्रादेशिक विकास कुछ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है, जैसे—श्रम के प्रवास को रोकना, पिछड़े हुए प्रदेशों को उन्नत करना, प्रति व्यक्ति आय में समता लाना, कुछ बड़े औद्योगिक केंद्रों में जन-संख्या के केन्द्रीयकरण को रोकना।

भारत में उद्योगों के प्रादेशिक वितरण की आवश्यकता—

भारत में औद्योगिक स्थानीयकरण के स्वरूप का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ उद्योगों की स्थापना बड़ी बेतुकी हुई है। कुछ चुने हुये क्षेत्रों में कुछ वृहत उद्योगों का अनुपातशील विकास हो गया है, जबकि शेष क्षेत्रों में इनका नितान्त अभाव है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित “भारतवर्ष में उद्योगों का स्थानीयकरण” शीर्षक पुस्तिका से निम्न उदाहरण बहुत रोचक प्रतीत होगा :—

* ‘The aim of a regional development should be to secure maximum efficiency in the utilisation of available resources rather than the adjustment of rival claims of different areas to achieve their own aims and ambitions.’ (Regional Planning in India 1, p. 73)

“भारतवर्ष में उद्योगों का वितरण बड़ा अनुचित और बिना किसी सिद्धान्त के अनुसार है। जन-संख्या के वितरण से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल बड़े नगर (विशेषतः समुद्र के निकट वाले) ही उद्योगों के केन्द्र हैं, गाँवों में उद्योग कहीं भी उन्नति पर नहीं हैं। विकेन्द्रीयकरण भी केवल अन्दर के बड़े शहरों में ही है, गाँवों की ओर यह प्रवृत्ति लेना मात्र भी नहीं।”

निम्न तालिका से यह प्रगट होता है कि उद्योगों का प्रादेशिक वितरण बहुत असमान है। अधिकांश बृहत् उद्योग बम्बई व कलकत्ता में ही केन्द्रित हैं।

बम्बई व कलकत्ता में उद्योगों का केन्द्रीयकरण (१९५१)

	बम्बई व कलकत्ता	कुल भारत	%
रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या	२,१२१	६,६७८	४२
घट पूँजी १० लाख रुपये में,	५,१८७	७,७५४	६७
स्पाई पूँजी १० लाख रुपये में	१,५१६	२,७५२	५५
शुद्ध उत्पादन (मूल्य १० लाख रु० में)	२,२७६	३,४७२	५६
मजदूरी १० लाख रु० में	१,०३३	१,५३५	६७
मजदूरों की संख्या हजारों में	६३३	१,४७८	६३

सन् १९५१ में बम्बई व कलकत्ता में कुल भारत के ४२% कारखाने थे, जिनमें कुल पूँजी का ६०% लगा था, जिन्होंने ६६% उत्पादन किया व जिनमें ६३% मजदूर लगे हुये थे। उद्योगों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण के फलस्वरूप बम्बई व कलकत्ता की जन-संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। वहाँ गृह समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है, जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं, श्रमिकों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा उनकी कुशलता बहुत घट गई है।

अतः स्पष्ट है कि भारत में उद्योगों का वितरण उचित होना परमावश्यक है। डाक्टर राधाकमल मुर्जी के शब्दों में, “स्वतन्त्र भारत में समस्त देश के हित के लिये एक राष्ट्रीय आर्थिक योजना होनी चाहिए और विकेन्द्रीयकरण यातायात के साधनों की उन्नति तथा जन विद्युत के विकास के साथ-साथ एक वैज्ञानिक ढङ्ग पर होना चाहिये, जिससे समस्त राष्ट्र उन्नति करे।

प्रादेशिक आधार पर औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक उपाय—

भारत की औद्योगिक योजना में उद्योगों के मुक्तिसंगत वितरण को उचित स्थान मिल गया है, किन्तु प्रादेशिक आधार पर औद्योगिक विकास की सफलता के लिए निम्न उपाय करना आवश्यक है :—

भारत में प्रादेशिक आधार पर औद्योगिक विकास के लिए ६ उपाय

- (१) देश के राजनैतिक विभागों का आर्थिक आधार पर पुनर्गठन ।
- (२) उद्योगों के स्थानिक स्वरूप का क्षेत्रक्रम से अध्ययन ।
- (३) लघु एवं मध्यम भाकार के उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका ।
- (४) यातायात प्रणाली की संरचना एवं भाड़ा नीतियों में उचित संशोधन ।
- (५) विद्युत शक्ति के उत्पादन का विकास ।
- (६) विभिन्न उद्योगों की विवेकपूर्ण प्रवृत्तियों का विश्लेषण ।

उपलब्ध, शक्ति, यातायात सुविधा तथा बेरोजगार श्रम शक्ति के सम्बन्ध में प्रदेश के समुचित विकास की संभावनाओं का अध्ययन करना । (ii) नगर नियोजकों (Town planners) के सहयोग से, अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आवास, अस्पताल, स्कूल और पार्क आदि की योजनाएँ बनाना । (iii) योजना आयोग को समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं से अवगत करना । (iv) अपने क्षेत्र के उद्योगपतियों को उद्योगों की स्थापना के लिये स्थान सम्बन्धी परामर्श व सूचना देना । (v) जिला एवं स्थानीय बोर्डों के द्वारा प्रत्येक स्तर पर जनता से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन में सहयोग प्राप्त करना ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उद्योगों की स्थापना के प्रश्न पर बोर्डों को राजनैतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जो सम्भव है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक हित में न हो। उदाहरण के लिये, जब कभी सरकारी क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना का प्रश्न बोर्ड के समक्ष आता है, तो विभिन्न राजनैतिक दल अपने राजनैतिक स्वार्थ को दृष्टि में रख कर उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में रखवाने का प्रयास करते हैं। ऐसे अस्वास्थ्यकर प्रभाव को कम से कम करने का प्रयास आवश्यक है।

(२) उद्योगों के स्थानिक स्वरूप का क्षेत्र क्रम से अध्ययन—प्रत्येक

(१) देश के राजनैतिक विभागों का आर्थिक आधार पर पुनर्गठन—देश के राजनैतिक विभागों का पुनर्गठित करना चाहिए, जिसमें काफी बड़े आर्थिक क्षेत्र बन सकें। प्रत्येक क्षेत्र को एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई माना जाय, जो अपने प्रसाधनों का उस क्षेत्र की विभिन्न राजनैतिक इकाइयों के समुक्त प्रयत्न द्वारा उचित शोषण कर सके। प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक 'क्षेत्रीय योजना बोर्ड' (Regional Planning Board) गठित किया जाय। ये बोर्ड नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में योजना आयोग को भूमूल्य परामर्श दे सकते हैं। इन बाड़ों में विभिन्न राज्यों के (जो कि उस क्षेत्र में आते हैं) प्रतिनिधि सम्मिलित होने चाहिये। बोर्ड निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं :—(1) स्थान, हलके एवं लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से बच्चे माल की

उद्योग की केन्द्रीयकरण के लिये प्रवृत्ति का पता लगाने के हेतु विभिन्न उद्योगों के स्थानिक स्वरूप (Locational Pattern) का क्षेत्रक्रम में अध्ययन करना चाहिए। प्रो० सान्जेट पनोरेन्स ने इस अध्ययन की एक सुन्दर देखनीक बनाई है, जिसके आधार पर उद्योगों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है :—(i) उच्च सहगमक वाले उद्योग (High Coefficient industries) जो विशेष क्षेत्र में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, (ii) निम्न सहगमक वाले उद्योग (Low Coefficient industries) जो विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति रखती हैं, एवं (iii) मध्यम सहगमक वाले उद्योग (Medium Coefficient industries)। इस वर्गीकरण के आधार पर अन्तर-प्रादेशिक समायोजनों की समस्या सरलता से हल की जा सकती है। औद्योगिक वितरण में प्रादेशिक असमानता को कम करने के लिये केवल विद्यमान उद्योगों के सम्बन्ध में ही नहीं, बल्कि नये उद्योगों के सम्बन्ध में भी (जो कि प्रत्येक क्षेत्र में विकसित किए जा सकते हैं) सम्भावनाओं का अध्ययन करना चाहिये।

(३) लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका—लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों में बड़े उद्योगों की अपेक्षा विकेन्द्रीयकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः वे विकेन्द्रीयकरण के लिए अधिक उपयुक्त हैं। प्रादेशिक वितरण की योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों का औद्योगिक पुनर्निर्माण करते समय इनकी सहायता से आवश्यक है कि इन उद्योगों के स्थायी रहने की क्षमता का अध्ययन किया जाय और केवल उन्हीं उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय, जो काफी समय तक स्थायी रह सकते हों।

(४) यातायात प्रणाली की संरचना एवं भाड़ा नीतियों में उचित संशोधन—चूँकि उद्योगों के स्थान-निर्णय में 'यातायात सम्बन्ध' (Transport Relations) एक महत्वपूर्ण भाग लेते हैं, इसलिये यह भी जरूरी है कि यातायात प्रणाली की विद्यमान रचना एवं भाड़ा नीतियों में उचित संशोधन किये जायें, ताकि उद्योगों की स्थानिक प्रवृत्तियों (Locational Trends) में आवश्यक परिवर्तन लाये जा सकें। प्रादेशिक आधार पर संतुलित औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के लिये आधुनिक सड़क यातायात की सहायता ली जा सकती है। यातायात के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित किया जाय। एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा उनके कार्य-क्षेत्र बाँट दिये जायें और उनके कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें।

(५) विद्युत शक्ति के उत्पादन का विकास—प्रादेशिक वितरण का आधार विद्युत शक्ति का विकास है। प्रादेशिक अर्थव्यवस्था प्रसाधनों की मितव्ययिता एवं विविध तथा विवेन्द्रित उद्योगों के विकास के सिद्धान्तों पर निर्भर होती है। मितव्ययिता का प्रारम्भ जल-धारा के उपयोग से किया जाता है, जो कि शक्ति का अनन्त एवं निरन्तर साधन है। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ-साथ शक्ति का

प्रयोग भी बढ़ जायेगा। अतः शक्ति उत्पादन की योजनायें निर्वाह रूप से बनती रहनी चाहिए।*

(६) विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रदर्शित विवेन्द्रीयकरण प्रवृत्तियों पर अनुसंधान—उद्योगों का अधिक अच्छा प्रादेशिक विवरण समझ बनाने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न उद्योगों द्वारा विवेन्द्रीयकरण की जो प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित की जाये उनका सावधानी से विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाय।

अन्त में, यह कहना अनावश्यक न होगा कि प्रादेशिक विकास किसी भी तरह से केन्द्रीय योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का विरोधी नहीं है, बल्कि इसके द्वारा एक राष्ट्रीय प्रकार पर उद्योगों का समुचित विकास सम्भव होगा।

STANDARD QUESTIONS

- 1 What do you mean by 'Regional Development of Industries'? Discuss its aims and objectives
- 2 Make out a case for Regional Development of Industries in India. What are its essential requisites?

* "In the nature of things a target such as this cannot be regarded as being rigid, adjustments will certainly be needed from time to time or as to take account of changes in the scope of industrial programmes, location of industrial units and the growth and pattern of consumption." (Second Five Year Plan, p 325)

राज्य एवं औद्योगिक स्थानीयकरण

(State & Industrial Location)

सरकार द्वारा औद्योगिक नियंत्रण के उपाय—

सरकार द्वारा औद्योगिक स्थानीयकरण का नियमन करने के लिए जो नीति अपनाई जाय उसमें निम्न उपायों का समावेश किया जा सकता है :—

(१) प्रेरणात्मक उपाय—

औद्योगिक स्थानीयकरण का नियमन करने में सरकार को प्रेरणात्मक उपायों से बड़ी सहायता मिल सकती है। इन उपायों का उद्देश्य उद्योगपतियों में कुछ विशेष क्षेत्रों में अपने उद्योगों की स्थापना करने को प्रेरित करना है। इन उपायों की प्रकृति स्थानीय परिस्थितियों एवं उद्योग के स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। मोटे तौर पर प्रेरणात्मक उपायों को इस प्रकार वर्गित किया जा सकता है :—

(१) सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था करना—सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं (जैसे यातायात, भूमि-विकास, जल एवं बिजली) की स्थापना करने को दूर करना है, जिनके कारण उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। सरकार को इन सेवाओं की स्थापना के साथ-साथ इनके प्रचार की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इनका ज्ञान सम्भावित उद्योगपतियों को हो सके।

(२) चुने हुये औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक सुविधायें देना—मनोरंजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक आर्थिक सुविधाओं का आयोजन करके भी सरकार कुछ क्षेत्रों के विकास में सहायता कर सकती है। बड़े-बड़े नगरों के बाहर इन सुविधाओं की उपलब्धि न होने से उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में बाधा पड़ती है, क्योंकि कुछ उद्योगपति अपने कारखानों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव करते समय इन बातों पर भी ध्यान देते हैं। इन सामाजिक सुविधाओं के अतिरिक्त कुछ पूरक आर्थिक सुविधाओं का भी आयोजन किया जा सकता है, जैसे—श्रमिकों को टेक्नीकल ज्ञान प्रदान करना, स्थानीयवृत उद्योगों के लाभार्थ विपणन सम्बन्धी संगठन स्थापित करना आदि।

(३) भावी उपक्रमियों की आर्थिक सहायता करना—आर्थिक सहायता

औद्योगिक नियंत्रण के ढंग

(१) प्रेरणात्मक उपाय—

(१) सावजनिक जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था करना ।

(२) चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक सुविधायें देना ।

(३) भावी उपक्रमियों की आर्थिक सहायता करना ।

(४) पर्याप्त एवं सस्ती वित्त सुविधाओं का आयोजन करना ।

(५) स्टोर्स क्रय नीति ।

(६) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना

(२) निषेधात्मक उपाय—

(१) स्थानीय करो में वृद्धि ।

(२) औद्योगिक विकास कर ।

(३) स्थानीयकरण पर प्रतिबन्ध ।

(४) औद्योगिक लाइसेन्स देने की प्रथा ।

दो प्रकार से दी जा सकती है—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से । प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता तभी दी जानी चाहिए जबकि यह स्पष्टतः विदिन हो जाय कि अमुक आवश्यक उद्योग का विकास ऐसी वित्तीय सहायता के बिना ही हो ही नहीं सकेगा । अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता कुछ सेवाओं की लागत कम करने अथवा प्रतिफूल तत्वों के कुप्रभावों का सामना करने के लिये दी जा सकती है ।

(५) पर्याप्त एवं सस्ती वित्त सुविधाओं का आयोजन—कुछ क्षेत्रों में रियायती दरों पर औद्योगिक विकास के लिये ऋण देने की व्यवस्था की जा सकती है । इन क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्त सम्बन्धी सुविधायें भी बढ़ानी चाहिये । प्रायः और अन्य स्थानीय करो के सम्बन्ध में भौदात्मक व्यवहार द्वारा भी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता कर सकती है ।

(५) स्टोर्स क्रय नीति—सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित होंगे उनमें ही सरकार अपनी स्टोर्स सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएँ खरीदेगी । सरकार इन उद्योगों के उत्पादन को अपने ही विभागों के काम में ला सकती है अथवा उनके लिए बाजार का संगठन भी कर सकती है । मैदानल स्माल इन्डस्ट्रीज वॉरपारेक्षण ऐसा कार्य कर रहा है । इसने लघु उद्योगों के उत्पादन के लिये विदेशों से आर्डर भी प्राप्त किये हैं ।

(६) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना—यू० के० की भाँति भारत में भी औद्योगिक बस्तियों का आयोजन किया जा सकता है । औद्योगिक बस्तियों की योजना के अन्तर्गत सरकार उन क्षेत्रों में, जिनका वह विकास करना उचित समझती है, विशाल भू-भाग लेकर वहाँ सम्स्त औद्योगिक सुविधायें जुटाती है तथा भावी उद्योग-पतियों की भूमि व बिजली आदि के रूप में भारी विनियोग नड़ी करना पड़ता और न औद्योगिक सम्भावनाओं की खोज में अपना धन लगाना पड़ता है । इस प्रकार, औद्योगिक बस्तियों की योजना के द्वारा औद्योगिक विवेन्द्रीयकरण में बहुत सहायता मिल सकती है ।

(२) निषेधात्मक उपाय—

इन उपायों के अन्तर्गत उन विधियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि सरकार द्वारा अनुचित औद्योगिक केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए अपनाया जाता है। किन्तु यह स्मरणीय है कि इन निषेधात्मक विधियों की अपेक्षा प्रेरणात्मक विधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि उद्योगपतियों को कुछ करने की प्रेरणा देना उन्हें कुछ करने से रोकने की अपेक्षा प्रायः सरल होता है। अतः सरकार को निषेधात्मक उपायों पर बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

(१) स्थानीय करो में वृद्धि—कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक केन्द्रीयकरण की रोकथाम के लिए सरकार कुछ सामान्य राकें लगा सकती है, जैसे कि वह स्थानीयकरण करो में वृद्धि कर दे।

(२) औद्योगिक विकास कर—छुने हुए क्षेत्रों में नये औद्योगिक संस्थाओं के सामर्थ्य सरकार स्थापित उद्योगों पर औद्योगिक विकास कर लगा सकती है।

(३) स्थानीयकरण पर प्रतिबन्ध—कुछ दशाओं में सरकार यह आदेश जारी कर सकती है कि अब से अमुक क्षेत्र या क्षेत्रों में कोई नये औद्योगिक कारखाने स्थापित नहीं होने दिये जायेंगे।

(४) औद्योगिक लाइसेन्सिंग—विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक क्रिया का अधिक सन्तुलित वितरण करने के लिये सरकार औद्योगिक लाइसेन्सिंग की प्रथा का प्रचलन कर सकती है। इस योजना के अन्तर्गत देश को तीन क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है—स्वतंत्र क्षेत्र (Free Zones), निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Zones) एवं निष्पक्ष क्षेत्र (Neutral Zones)। प्रत्येक क्षेत्र में नियन्त्रण की मात्रा भिन्न-भिन्न होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाय कि जब तक उपक्रमों की इच्छा राष्ट्रीय नीति के व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक हितों के विरुद्ध न हो तब तक उस पर अधिक प्रतिबन्ध न लगाया जाय।

सरकारी नीति का मूल्यांकन—

अप्रैल सन् १९४५ की औद्योगिक नीति सम्बन्धी घोषणा में भारत सरकार ने औद्योगिक संस्थाओं के लाइसेन्सिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया था, क्योंकि औद्योगिक उपक्रमों के प्रवर्तन की निर्बाध स्वतन्त्रता होने के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में उद्योगों का बहुत केन्द्रीयकरण हो गया, जबकि अन्य क्षेत्र उनसे वंचित रह गये। कुछ दशाओं में निस्संदेह केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहित करने वाले उचित कारण थे, किन्तु ऐसी भी दशाएँ आई गईं जिनमें कोई विशेष प्रोत्साहन न होने पर उद्योगों का केन्द्रीयकरण हो गया। इसके अतिरिक्त देश में अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें औद्योगिक विकास के अवसर उपलब्ध हैं, किन्तु उसका कुछ लाभ नहीं उठाया गया है। इन विषयनाओं की जाँच करके सिफारिशें देने के हेतु सरकार ने कई औद्योगिक पैनल बनाये। अक्टूबर सन् १९४६ में एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं का तुरन्त सर्वे करना और समन्वय व कार्य-

वाहन के सम्बन्ध में उचित परामर्श देना था। इस बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव दिए, जैसे—विद्युत-विकास, रेलवे, कृषि अनुसन्धान, उद्योग आदि। किन्तु देश के विभाजन के फलस्वरूप १५ अगस्त सन् १९४७ से पूर्व तैयार की गई योजनाओं की कोई उपयोगिता नहीं रही।

अप्रैल सन् १९४८ में औद्योगिक नीति सम्बन्धी दूसरी घोषणा हुई, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार ने यह जाँच-पड़ताल करने का निश्चय किया कि जिन उद्योगों का अधिक केन्द्रीयकरण हो गया है उन्हें किम प्रकार एवं किस सीमा तक विकेंद्रित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये उसने औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम सन् १९५१ में पास किया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक नियोजन के सम्बन्ध में दोनों ही प्रकार के (प्रेरणात्मक एवं निषेधात्मक) उपाय बनाये गये हैं। निषेधात्मक उपाय लाइसेन्सिंग प्रणाली का है। जिन औद्योगिक इकाइयों की पूँजी १ लाख रुपये से अधिक है तथा जो अधिनियम में दी हुई अनुसूची में अन्तर्गणित दिखाये गये हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स लिये बिना प्रारम्भ अथवा विस्तार नहीं किया जा सकता। लाइसेन्स में कुछ शर्तों का भी उल्लेख होता है, जो कि लाइसेन्स पाने वालों को पूरी करनी पड़ती है। लाइसेन्स देने या न देने का निर्णय करने वाली कमेटी में वाणिज्य एवं उद्योग, रेलवे, वित्त व उत्पादन मन्त्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यह कमेटी लाइसेन्स देने के पूर्व जाँच करती है और फिर अपनी रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय को देती है। सेंट्रल एडवाइजरी बॉर्डर्स की एक उप-समिति भी इसमें नियुक्त की गयी, अस्वीकृत, बदले गये व रद्द किये गये लाइसेन्सों पर पुनर्विचार करने तथा नये उपक्रमों की स्थापना एवं पुराने उपक्रमों के विस्तार के लिए लाइसेन्स इसमें करने के सम्बन्ध में सरकार को सामान्य निष्ठाओं के सुझाव देने के हेतु नियुक्त की गई है।

जहाँ तक अधिनियम के प्रेरणात्मक आयोजनाओं का सम्बन्ध है, अधिनियम ने सेंट्रल एडवाइजरी बॉर्डर्स और डेवलपमेंट बॉर्डर्स की स्थापना की व्यवस्था की है। सेंट्रल एडवाइजरी बॉर्डर्स में कमचारियों, सेवायोजकों, उपभोक्ताओं एवं वृत्ते माल के उत्पादकों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में इस बॉर्डर्स से परामर्श लेती है। विकास परिषदों की स्थापना किसी उद्योग विशेष के लिये अथवा कई उद्योगों के लिये (जिनके नाम अधिनियम से सलग्न सूची में दिये गये हैं) सम्मिलित रूप से की जाती है। इन्हें 'प्राइवेट उद्योग की धारा' (Nurses for the private industry) की सहायता दी गई है। इन परिषदों में सम्बन्धित उद्योग में सलग्न इकाइयों के सेवायोजकों, कमचारियों, उपभोक्ताओं एवं अन्य हित रखने वाले वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाते हैं। इन विभाग परिषदों के कार्यों की सूची बहुत लम्बी है, मुख्यतः यह (१) लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की दृष्टि में उत्पादन विधाओं के विकेंद्रीयकरण

सम्बन्धी सम्भावनाओं की जाँच करती है ; (ii) अपव्यय को समाप्त करने और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये कुशलता के प्रमाण लिखित करती है ; (iii) स्थापित क्षमता (installed capacity) का पूर्ण उपयोग करने से सम्बन्धित सुझाव देती है । अब तक १३ विकास परिषदें सगठित की जा चुकी हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि एक्ट में प्रेरणात्मक उपायों की अपेक्षा निषेधात्मक उपायों पर ही अधिक धन दिया गया है । इस बात की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट कॉन्सिलों को उद्योग के स्थानीयकरण की समस्या के अध्ययन का भी कार्य सौंपा जाय और यह सम्बन्धित उद्योगों के लिये सही प्रकार के स्थान का चुनाव करने में भी सहायता दे । केन्द्रीय एडवाइजरी कॉन्सिल का भी केवल एक परामर्शदाता सस्था की तरह काम न करके मन्त्रय करने वाली सस्था के रूप में कार्य करना चाहिए । विभिन्न उद्योगों के एक उचित क्षेत्रिक वितरण, लघु एवं बृहत उद्योगों के सतुलित विकास तथा देश के प्रसाधनों का उचित उपयोग करना उसके प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए ।

पञ्च-वर्षीय योजनाएँ एवं औद्योगिक स्थानीयकरण—

पञ्च-वर्षीय योजना आयोग ने यह स्वीकार किया था कि एक अलग काल में ही देश के औद्योगिक स्थानीयकरण का ढाँचा अधिक नहीं बदला जा सकता । बहु-मुखी योजनाओं के द्वारा विद्युत-ऊर्जा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के कारण पंजाब, बिहार एवं उड़ीसा में औद्योगिक विकास की विशाल सम्भावनाएँ पैदा हो गई हैं । नये उपक्रमों की स्थापना के सम्बन्ध में अर्द्ध-विकसित देशों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

द्वितीय एवं तृतीय पञ्च-वर्षीय योजनाओं में क्षेत्रिक विषमताओं पर अधिक विस्तार से विचार किया गया है । यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि विकास की एक राष्ट्रीय योजना में अर्द्ध-विकसित राज्यों को प्राथमिकता दी जाय । विनियोग की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि देश का सतुलित औद्योगिक विकास हो । ऐसा विकास प्रारम्भिक अवस्थाओं में, जबकि कुछ उपलब्ध प्रसाधन आवश्यकता की दृष्टि से कम हैं, कठिन होता है । लेकिन जैसे-जैसे विकास होना जाय और अधिक साधन उपलब्ध होने लगेँ वैसे वैसे अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों को विनियोग का अधिक लाभ दिया जाना चाहिए ।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव (सन् १९५६) में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास के स्तरों में अन्तर को कम करते जाना चाहिए । सभी देश का जीवन-स्तर ऊँचा उठ सकता है । औद्योगिक विवेन्द्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिये प्रभाव में औद्योगिक वस्तियों की स्थापना पर जोर दिया गया है ।

अभी हाल में नेशनल डेवलपमेंट कॉन्सिल ने भी उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण की समस्या पर विचार किया था और यह भी स्वीकार किया है कि उपलब्ध साधनों

की सीमा तक देश के विभिन्न भागों के समुचित विकास का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमने निम्नलिखित सुझाव भी दिये—

- (१) विकेन्द्रित औद्योगिक उत्पादन के लिये उचित कार्यक्रम बनाये जायें ।
- (२) नये उपक्रमों (सरकारी एवं प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में) की स्थापना करते समय समुचित अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य सामने रखना चाहिये ।
- (३) श्रम की गतिशीलता बढ़ाने के लिये कदम उठाये जायें और कम घने वसे प्रदेशों में उनके आवास को प्रोत्साहन दिया जाय ।
- (४) क्षेत्रिक विषमताओं का गम्भीरता से अध्ययन किया जाय तथा क्षेत्रिक विकास के उपयुक्त प्रमाण निर्धारित किये जायें ।

STANDARD QUESTIONS

1. What are the various measures which may be adopted by the Government for the proper and scientific location of industries Please mention the positive and negative approaches

अध्याय ४८

अनुकूलतम परिमाण का सिद्धान्त

(Theory of Optimum Size)

प्रारम्भिक—

अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक इकाइयों का परिमाण 'अनुकूलतम' होना आवश्यक है । यों तो औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न साइज हो सकते हैं । परन्तु 'अनुकूलतम परिमाण' (Optimum size) ही एक ऐसा साइज है, जिसमें उत्पादन व्यय न्यूनतम होते हैं । अब प्रश्न यह है कि किसी औद्योगिक इकाई के अनुकूलतम परिमाण से क्या अभिप्राय है । वास्तव में इसका उत्तर देना जिनना महत्वपूर्ण है

उतना ही कहने में कठिन और अनिश्चित भी है। जब औद्योगिक इकाई के परिमाण की चर्चा की जाती है, तो प्रायः 'इकाई' (Unit) शब्द का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। 'अनुकूलतम परिमाण' की परिभाषा के पहले 'इकाई' शब्द का स्पष्ट अर्थ समझ लेना चाहिए, जिसमें 'परिमाण' और 'निपुणता' में सम्बन्ध स्थापित करने में सरलता हो।

'इकाई' शब्द से आशय—

'इकाई' शब्द को प्रायः तीन प्रकार से प्रयोग किया जाता है—'प्लान्ट', 'फर्म' या 'उद्योग' के रूप में। प्रोफेसर सार्जेंट फ्लोरेन्स के शब्दों में, 'प्लान्ट' (Plant) से आशय उस व्यक्ति-समूह से है जो कि एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्र होता है। इस प्रकार 'प्लान्ट' शब्द एक कारखाना, एक मिल, एक बकशाँप, एक खान, एक गोदाम या एक खेरीज की दुकान का पर्यायवाची है। एक 'फर्म' (Firm) से अभिप्राय उस इकाई का है जो कि प्लान्ट या प्लान्टों का स्वामित्व, नियन्त्रण एवं प्रबन्ध करती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति (या कम्पनी) दो या अधिक मिलों या कारखानों का स्वामी है, तो उसे वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक 'फर्म' या एक औद्योगिक इकाई माना जायगा। कभी-कभी एक 'प्लान्ट' और 'फर्म' समान अर्थ वाले शब्द जान पड़ते हैं, जैसे कि तब, जब एक फर्म केवल एक ही मिल या कारखाना चलाती हो। लेकिन अधिकांश फर्म एक से अधिक कारखाने चलाती हैं, अतः आकार, लाभ, उत्पादनशीलता एवं व्ययों के विचार से सम्पूर्ण विभिन्न कारखाने, जो एक ही स्वामित्व में हो, एक ही 'फर्म' माने जायेंगे। यह फर्म या केन्द्रीय सत्ता अपने अधीनस्थ प्लान्टों की वित्तीय, विपणन एवं लेखाकर्म सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित करती है। इसके विपरीत 'उद्योग' (Industry) शब्द से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो कि प्लान्टों या फर्मों में कार्य करते हो या उनसे सम्बन्धित हो। दूसरे शब्दों में, एक सा माल बनाने वाले कारखानों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध करने वाली सभी फर्मों को मिला कर 'उद्योग' कहा जाता है।

हमारे देश में उद्योगों के प्रबन्ध की दृष्टि से एक विशेषता पाई जाती है और वह है प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली। बहुत से छोटे-बड़े कारखानों पर समुक्त पूँजी वाली कम्पनियों का ही स्वामित्व विद्यमान है। इनमें से पब्लिक कम्पनियों का प्रबन्ध सामान्यतः अभिकर्ताओं द्वारा किया जाता है। ये प्रबन्ध अभिकर्ता अधिकांश दशाओं में, एक ही या कई केन्द्रों में, और एक समान या अलग-अलग प्रकार का उत्पादन करने वाली कई संस्थाओं का प्रबन्ध करते हैं। जब एक प्रबन्ध अभिकर्ता गृह दो या अधिक कारखानों का प्रबन्ध करता है, तो सामान्यतः सामूहिक क्रय एवं विक्रय द्वारा व्यय में कमी कर प्रत्येक कारखाने को लाभ दवश्य हो पहुँकता है और इसी तरह छोटी संस्थाएँ या कारखाने भी बड़ी संस्थाओं या कारखानों की तुलना में अपनी वस्तुओं के विक्रय करने में नुकसान में नहीं रहते। ये प्रबन्ध अभिकर्ता (जो विभिन्न प्रकार के यन्त्रों के निर्माताओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं) सब (छोटी एवं बड़ी) संस्थाओं को यन्त्रादिक एक

ही मूल्य पर देने में समर्थ होने हैं। फिर उनका संगठन प्रत्येक संस्था अथवा इकाई के संगठन का भाग हो जाता है और इस प्रकार उनमें से प्रत्येक को विनियम सम्बन्धी सब मितव्ययिताएं प्राप्त हो जाती हैं। भारत में उद्योगों की इस विशेष रचना को ध्यान में रखते हुये यह कहा जा सकता है कि 'इकाई' का अभिप्राय एक औद्योगिक केन्द्र में उत्पादन की उन समस्त मिलों या कारखानों के समूह से है, जिनका प्रबन्ध कोई एक ही प्रबन्ध अभिकर्तृत्व संस्था करती हो।

यों तो उपर्युक्त परिभाषाओं के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है फिर भी अधिक लाभ इसी में रहेगा कि हम इकाई से अपना अभिप्राय उन मिलों अथवा कारखानों तक ही सीमित रखें जो कि एक ही स्वामित्व में हों। एक ही स्वामित्व की आधार मानना विद्येय रूप में उचित इसलिए है कि भिन्न भिन्न कारखानों से होने वाले आर्थिक परिणामों का उत्तरदायित्व, चाहे वह लाभ के रूप में मिले अथवा हानि के रूप में भुगतना पड़े, उनके स्वामियों पर ही रहता है।

अनुकूलतम परिमाण का आशय—

बहुत समय से यह माना जाता रहा है कि प्रत्येक उद्योग में इकाइयों का एक ऐसा न्यूनतम परिमाण होता है जिसमें कि उत्पादन की निपुणता बनी रहे और इस परिमाण से कम परिमाण वाली कठिनाइयाँ न तो कम व्यय पर उत्पादन कर सकती हैं और न ही वे पतियोगिता करने में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकती हैं। किन्तु अभी तक कुछ वर्षों से न्यूनतम परिमाण के विचार का स्थान 'अनुकूलतम परिमाण' में प्राप्त कर लिया है। यदि औद्योगिक इकाई इस परिमाण से छोटी या बड़ी होगी, तो वह अथवा ही आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं हो सकती। यह परिवर्तन स्वाभाविक एवं सम-योजित ही है। संसार परिवर्तनशील है। अतः यदि परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार परिमाण सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन हा गया है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। जब उद्योग छोटी-छोटी इकाइयों के रूप में चलाया जाता था तब यह प्रश्न, कि 'क्या' इकाइयाँ इतनी बड़ी हैं कि वे कार्य मितव्ययिता से कर सकें, महत्त्वपूर्ण था, किन्तु आधुनिक काल में औद्योगिक क्रान्ति के बाद, जब से उत्पादन, यन्त्रों की सहायता से बड़ी मात्रा में होने लगा है और उद्योगों की इकाइयाँ भी परिमाण में बढ़ती जा रही हैं, तब से यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो गया है कि क्या यह इकाइयाँ उचित परिमाण की हैं, अथवा वे इतनी अधिक बड़ी तो नहीं हैं कि निपुणता से संचालित न की जा सकती हो? हम यह कहावत जानते हैं कि 'प्रति सबत्र वजयेत' यानी प्रति सबकी बुरी होती है। इसी आधार पर हमारा उपर्युक्त प्रश्न उठता है कि कहीं उद्योगों की इकाई का परिमाण आवश्यकता से अधिक तो बड़ा नहीं हो गया, नहीं तो लाभ की जगह हानि पहुँचेगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सबसे उचित परिमाण का नाम 'अनुकूलतम परिमाण' रखा है। राबिन्सन ने अनुकूलतम फर्म की परिभाषा निम्न प्रकार की है — "अनुकूलतम फर्म की परिमाण वाली फर्म वह है जो विद्यमान टेक्नीक एवं संगठन योग्यता की दृष्टि से प्रति इकाई सबसे कम औसत उत्पादन लागत

रखनी हो जबकि सभी दीर्घकालीन लाभों को भी विचार में लिया जाय।^{11*} यही परिमाण ही औद्योगिक इकाइयों के लिए वांछनीय माना गया है और निपुणता की यही सबसे ऊँची सीढ़ी है। इस सीढ़ी से आगे बढ़ने या नीचे उतरने पर निपुणता में कमी आवेगी।

इस परिमाण की स्थापना व्यापारियों की सूझबूझ और निर्णय का फल है, जो बराबर यह विचार करते रहते हैं कि अपने साधनों का किस प्रकार अधिकतम विनियोग किया जाय। प्रतिस्पर्द्धा भी, अकुशल फर्मों को हतोत्साहित एवं कुशल फर्मों को प्रोत्साहित करके, अनुकूलतम परिमाण की फर्मों की स्थापना में योग देती है।

विस्तृत अनुकूलतम फर्म की तीन दृष्टियाँ हैं :—(१) पूर्ण प्रतियोगिता की दृष्टि से व्यवहार में नहीं देखी जाती तथा पूर्ण प्रतियोगिता की माप करना भी कठिन है; (२) यद्यपि पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्मों का अनुकूलतम परिमाण होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की अनुपस्थिति में फर्म अनुकूलतम परिमाण से बहुत भिन्न हो जायेंगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और (३) तथ्यों के अवलोकन द्वारा प्रायः यह पता लगाना कठिन है कि विभिन्न उद्योगों में फर्मों का अनुकूलतम आकार क्या है।

‘अनुकूलतम परिमाण’ को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(Factors Affecting Optimum Size)

रोबिन्सन के अनुसार एक औद्योगिक इकाई के सर्वोत्तम परिमाण को प्रभावित करने वाले कारणों को पाँच श्रेणियों में बाँटा जा सकता है, यथा—टेक्नीकल कारण, प्रबन्ध सम्बन्धी कारण, वित्तीय कारण, विपणन सम्बन्धी कारण एवं जोखिम से सम्बन्धित कारण। कारणों की प्रत्येक श्रेणी से सम्बन्ध रखती हुई एक अनुकूलतम इकाई होती है। इन्हें क्रमशः अनुकूलतम टेक्नीकल इकाई (Optimum Technical Unit), अनुकूलतम प्रबन्ध इकाई (Optimum Managerial Unit), अनुकूलतम वित्तीय इकाई (Optimum Financial Unit), अनुकूल विपणन इकाई (Optimum Marketing Unit) एवं अनुकूलतम जोखिम इकाई (Optimum Survival Unit) कहते हैं। किसी औद्योगिक इकाई का जो वास्तविक या अन्तिम परिमाण होगा, उसका निर्धारण इन विभिन्न अनुकूलतमों के समन्वय पर निर्भर करता है।

* “The optimum firm is one in which existing condition of technique and organisation ability has the lowest average cost of production per unit, when all those costs which must be covered in the long run are included.”

अनुकूलतम इकाई के स्वरूप हैं पाँच

- (१) अनुकूलतम टेक्नीकल इकाई,
- (२) अनुकूलतम प्रबन्ध इकाई,
- (३) अनुकूलतम वित्तीय इकाई,
- (४) अनुकूलतम विपणन इकाई,
- (५) अनुकूलतम जोखिम इकाई।

(१) अनुकूलतम टेक्नीकल इकाई—एक अनुकूलतम टेक्नीकल इकाई का निर्धारण टेक्नीकल विशेषज्ञ द्वारा होता है और अन्य चार अनुकूलतम वित्तीय छूट जाते हैं। यह श्रम विभाजन और प्रक्रियाओं के समन्वयकरण (Integration of processes)

का परिणाम है। श्रम विभाजन की मुख्य मुख्य मितव्ययियाँ निम्नलिखित हैं—प्रत्येक कारीगर की दक्षता में वृद्धि होना, एक काम से दूसरे काम को बदलने में समय खोने की बचत होना, विद्याल मशीनों का आविष्कार, जो श्रम को दबाती हैं एवं सुविधाजनक बनाती हैं। श्रम विभाजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि फर्म इसका लाभ उठाने के लिए यथेष्ट चढ़ी हो। इसके विपरीत, प्रक्रियाओं के समन्वयीकरण में अमिप्राय एक ऐसी विद्याल मशीन की रचना से है, जो कि उस कार्य को करने लगे जिसे अब तक कई शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा या कई यान्त्रिक क्रियाओं द्वारा किया जाता था। श्रम विभाजन का रूप उलट जाता है अर्थात् किसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले की अपेक्षा कम सख्या में प्रक्रियायें करनी पड़ती हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में इस सयुक्तीकरण या समन्वयीकरण से निम्न लाभ होते हैं—स्थाई परिवर्धनों का कम होना और उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में निर्माण एवं संचालन व्ययों का कम बढ़ना। टेक्नीकल अनुकूलतम इकाई का निर्धारण प्रक्रियाओं के सतुलन (Balance of processes) से होता है। मितव्ययितायें हाना बन्द हो सकता है, लेकिन अमितव्ययितायें होना आरम्भ नहीं होता। इस प्रकार टेक्नीकल अनुकूलतम इकाई एक न्यूनतम आकार नियन कर देती है, अधिकतम आकार नहीं। अधिकतम आकार तो अ्य कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(२) अनुकूलतम प्रबन्ध-इकाई—ऐसी इकाई भी प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों में श्रम-विभाजन एवं प्रक्रियाओं के सयुक्तीकरण की मितव्ययिताओं और अमितव्ययिताओं का परिणाम होती है। इस दशा में श्रम विभाजन की मितव्ययितायें निम्न हैं—विशिष्ट योग्यताओं का पूर्णता तक लाभ उठाया जा सकता है और एक ही कार्य पर ध्यान देने से उस कार्य का अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर को, जिसके जिम्मे कच्चा माल खरीदने का कार्य है, पुगने मैनेजरो की भाँति सैंकड़ों अन्य कामों में व्यस्त नहीं रहना पड़ता। इसी प्रकार एकाउन्टेन्ट को केवल हिस्सा पर ही ध्यान देना पड़ता है, टायपराइटर पर नहीं। प्रक्रियाओं के सयुक्तीकरण का उदाहरण है बुक कीपिङ्ग मशीन। अनुकूलतम प्रबन्ध इकाई की दशा में अमितव्ययितायें, मितव्ययिताओं की समाप्ति के तुरन्त बाद ही आरम्भ हो जाती हैं। (यह बात अनुकूलतम टेक्नीकल इकाइयों में नहीं होती)। एक निश्चित परिमाण के परे सम वय करने की कठिनाइयाँ 'अनुकूलतम प्रबन्ध इकाई' के परिमाण की न्यूनतम एवं अधिक-

तम दोनों ही मात्राएँ निर्धारित कर देती है। अनुकूलतम प्रबन्ध इकाइयों के साइज को बढ़ाने के लिए स्टाफ का संगठन करने की विभिन्न युक्तियों को अपनाया जा सकता है।

(३) अनुकूलतम वित्तीय इकाई—किसी औद्योगिक इकाई की उत्पादन-लागत फर्म द्वारा अपने कार्यों के लिए पूँजी उधार लेने की क्षमता पर भी निर्भर होती है। पूँजी जुटाने की कठिनाइयों का फर्मों की संरचना एवं परिमाण दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। विभिन्न फर्म विभिन्न व्याज दर पर और विभिन्न सीमा तक पूँजी जुटाने में समर्थ होती हैं। एक बड़ी फर्म को यह लाभ है कि जैसे-जैसे उसका परिमाण या आकार बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे वह अधिक मितव्ययिता के साथ पूँजी जुटाने में समर्थ बनती जायेगी। इस प्रकार उत्पादन की मात्रा के बढ़ाने से वित्तीय लागतें (Financial Cost) कम हो जाती हैं। अतः वित्तीय कारण किसी औद्योगिक इकाई का न्यूनतम या अधिकतम कोई भी परिमाण निश्चित नहीं करते।

(४) अनुकूलतम विपणन इकाई—एक संस्था के कुल व्यय में क्रय और विक्रय महत्वपूर्ण भाग रखते हैं। अतः उनका उद्योग की संरचना एवं अनुकूलतम परिमाण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुकूलतम विपणन इकाई बड़े पैमाने के क्रय विक्रय की मितव्ययिताओं एवं अमितव्ययिताओं का फल है। एक बड़ी फर्म विशाल मात्रा में क्रय करती है, अतः उसकी सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है, वह कम दाम पर सामग्री खरीद सकती है। इस कार्य के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी रख सकती है और भातायान व्ययों में भी बचत कर सकती है, लेकिन व्यय में जो वृद्धियाँ हो उन्हें एक बड़ी फर्म सरलता से दूर नहीं कर सकती। बड़े पैमाने के विक्रय से यात्रा व्ययों में, स्टॉक रखने में (अतः व्याज के खर्च में भी) और विविध प्रकार के स्टॉक रखने में मितव्ययिताएँ होने लगती हैं। अतः ही देवनीवल अनुकूलतम या प्रबन्ध अनुकूलतम की सीमा भा गई हो, एक संस्था अपना परिमाण (Size) बढ़ा कर विक्रय सम्बन्धी मितव्ययिताएँ प्राप्त कर सकती है। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाओं में, विक्रय की मितव्ययिताओं और विशाल मात्रा के उत्पादन का प्रबन्ध करने से सम्बन्धित अमितव्ययिताओं के समुत्पन्न के फलस्वरूप अनुकूलतम साइज उदय होता है। किन्तु अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाओं में संस्था विक्रय अनुकूलतम तक नहीं पहुँच सकेगी।

(५) अनुकूलतम जोखिम इकाई—अब तक हमने इस आधार पर विवेचन किया है कि उत्पादन के लिए माग वृद्धिशील है। लेकिन व्यवहार में माग में बहुत परिवर्तन होता रहता है। माग के घटने-बढ़ने की सम्भावना बड़ी अनिश्चितता उत्पन्न कर देती है, जिसे एक उत्पादक को अपनी फर्म का परिमाण निश्चित करते समय विचार में रखना पड़ता है। जब माग स्थायी हो और वृद्धिशील हो तो उत्पादक संस्था के सबसे अधिक निपुणता वाले साइज को प्राप्त करना चाहेगा और अधिक से अधिक विशिष्ट मशीनरी का उपयोग करेगा, लेकिन जब माग परिवर्तनशील होती है तो विशिष्ट मशीनें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य माल के उत्पादन में प्रयोग नहीं की

जा सकती और इसलिए बेकार हो जाती है। इसके विपरीत एक छोटी फर्म जिसमें कम विशिष्ट प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं, मुख्य माल की माँग घटने पर अन्य माल के बनाने में सरलता से जुट सकती है। अतः माँग में परिवर्तन की सम्भावनाएँ एक छोटी, 'अनुकूलतम जाखिम इकाई' को प्ररित करती हैं।

(विभिन्न अनुकूलतमों का समन्वय)

(Reconciliation of Optima)

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई सस्था कारणों के एक वर्ग की दृष्टि से अनुकूलतम परिमाण की हो सकती है, जब कि अन्य कारणों के वर्गों की दृष्टि से वह इस परिमाण से छोटी पड़ सकती है। शायद ही कोई उद्योग ऐसा हो, जिसमें सस्था का परिमाण सभी दृष्टियों से अनुकूलतम हो और जिस उद्योग या सस्था के लिये ऐसा होना सम्भव होना है उसमें साहसी के लिये कोई समस्या नहीं है। परन्तु वास्तविक जगत में टेक्नीकल, वित्तीय, प्रबंध, वित्तीय एवं जोखिम सम्बन्धी विभिन्न दशाएँ कई अनुकूलतम परिमाण स्थापित कर देती हैं, क्योंकि ये कारण प्रायः एक ही दिशा में काम नहीं करते। अतः साहसी के सामने विभिन्न अनुकूलतमों में समन्वय करने की समस्या उत्पन्न होती है। सर्वश्रेष्ठ अनुकूलतम परिमाण की स्थापना विभिन्न अनुकूलतमों के पारस्परिक समायोजन (Mutual adjustment) के फलस्वरूप होती है, जबकि कुल मितव्ययितायें कुल मितव्ययिताओं के बराबर हो जाती हैं। "एक उत्पादक को चाहिये कि वह उत्पादन के मित मिश्र साधनों का इस मात्रा और अनुपात में संयोजन करे कि उसकी उत्पत्ति यथासम्भव अधिकतम हो तथा प्रति इकाई लागत कम से कम रहे। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का दूसरे साधन के साथ इस माना तक एकत्रित करना चाहिये कि वह संयोजन सर्वश्रेष्ठ हो और अन्य किसी भी मात्रा में संयोजन करने से इससे अधिक लाभ न हो सके।" वास्तव में यह संयोजन इतना सर्वश्रेष्ठ होता है कि यदि साधनों के आकारों में कुछ कमी या वृद्धि कर दी जावे, तो उत्पादक का लाभ पहले की अपेक्षा कम हो जावेगा। प्रत्येक उत्पादक अपने आधीन उद्योगों में सामान्य लागत को कम से कम रखने का प्रयत्न करता है, ताकि उसकी सस्था अनुकूलतम परिमाण पर पहुँच सके और ऐसी स्थिति के आने पर उत्पादन की सीमान्त लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है। यही परीक्षा है, जबकि हम कह सकते हैं कि वह सस्था अनुकूलतम परिमाण पर पहुँच चुकी है।

यह नहीं भूल जाना चाहिये कि जिस प्रकार जन सस्था सम्बन्धी ('अनुकूलतम जन सस्था') आधुनिक विचारा के अनुसार उसका वांछनीय अनुकूलतम होना सदा के लिये निश्चित बिन्दु नहीं है, उसी प्रकार व्यावसायिक सस्था का भी अनुकूलतम परिमाण सदैव के लिये निश्चित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार विभिन्न देशों में एवं एक ही देश के विभिन्न भागों में अनुकूलतम फर्म का परिमाण अलग अलग हो सकता है।

श्रीद्योगिक इकाई के परिमाण का मापदण्ड

अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उद्योग एवं उमकी इकाइयों का एक 'अनुकूलनम परिमाण' होना अन्यान्य आवश्यक है। वास्तव में परिमाण का श्रीद्योगिक इकाई की निपुणता पर गहरा प्रभाव पड़ना है। अतः यह देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या उद्योग के प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक इकाई इस परिमाण की है कि उममें अधिकतम निपुणता प्राप्त की जा सके। यहाँ पर श्रीद्योगिक इकाइयों का परिमाण नापने का प्रश्न उदय होता है। इस मापदण्ड के कई आधार हो सकते हैं। इनमें से कौनसा मापदण्ड किस उद्योग के लिये उपयुक्त होगा, यह सम्बन्धित उद्योग की प्रकृति एवं उसलक्ष्य इकाइयों की सत्यता पर निर्भर है। मापदण्ड के मुख्य चार आधार हो सकते हैं :—

मापदण्ड का आधार—

(१) उद्योग की इकाई में लगी हुई पूँजी—मूल्य प्रथम पूँजी के आधार को ही लें। हम देखने हैं कि एक ही उद्योग के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न इकाइयों में लगी हुई पूँजी की मात्रा अलग-अलग होती है। इतना ही नहीं, पूँजी भी कई प्रकार की होती है, क्योंकि भिन्न-भिन्न इकाइयों की आर्थिक आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न साधनों से पूरी की जाती हैं। कोई-कोई सस्या या इकाई केवल स्वयं की पूँजी (चाहे वह कम हो या अधिक) से ही कार्य चलाना चाहती है। कोई इकाई स्वयं की थोड़ी पूँजी लगा कर बाकी आवश्यक ऋण लेकर या सार्वजनिक निक्षेप (Public deposits) द्वारा पूरा कराने में विश्वास करती है। इन विभिन्नताओं के कारण उत्पादन में लगी हुई पूँजी की इकाई का परिमाण नापने के लिए उचित मापदण्ड मानना कठिन सा प्रतीत होता है।

(२) श्रीद्योगिक इकाइयों का बलौक मूल्य—यह भी परिमाण मापने का एक अच्छा आधार माना जा सकता है। लेकिन इसमें एक कठिनाई है—प्रत्येक इकाई की सम्पत्ति (जैसे गृह, सज्जा, उपस्कर, सामग्री इत्यादि) में लगी हुई पूँजी के मूल्यांकन के दग इतने अलग-अलग होते हैं कि प्रत्येक इकाई का मूल्यांकन एक सा महत्त्व नहीं रखता।

(३) प्रति तकुआ या करघा पर लगी हुई औसत पूँजी—कपड़े तथा पटसन के कारखानों की साइज के माप के लिए प्रति तकुआ या करघा पर लगी हुई औसत पूँजी एक उपयोगी माप हो सकती है। किन्तु इसमें कठिनाई यह आती है कि प्रत्येक इकाई में पाये जाने

श्रीद्योगिक इकाई के परिमाण का माप दण्ड

- (१) उद्योग की इकाई में लगी हुई पूँजी।
- (२) श्रीद्योगिक इकाइयों का बलौक मूल्य।
- (३) प्रति तकुआ या करघे पर लगी औसत पूँजी।
- (४) करघों या तकुआ की संख्या।
- (५) काम करने वाले श्रमिकों की संख्या।
- (६) प्रयाग की जाने वाली शक्ति की मात्रा।
- (७) उत्पादन की मात्रा।
- (८) कच्चे माल की मात्रा।

घाले तकुये या करघे पर लगाई हुई पूँजी का निर्धारण कई बातों पर निर्भर है, जैसे—औद्योगिक इकाई की स्थिति, उसमें श्रमिकों की सुलभता, अर्थ-प्रवन्ध के ढङ्ग, श्रमिक कल्याण पर व्यय की जाने वाली राशि, शक्ति के उपलब्ध साधन एवं उन पर किया जाने वाला खर्च, बैंको से प्राप्त सुविधायें, बच्चे मास को लाने तथा पक्के मास को भेजने के उपलब्ध यातायात के साधन, इत्यादि। उदाहरण के लिए, जिस इकाई को बैंको में अधिक सुविधायें प्राप्त होती हैं उसे कम व्याज पर सरलता से ऋण मिल सकता है। इसके विपरीत जिन इकाइयों को इस प्रकार की सुविधा नहीं होती, उनको अपनी कायशील पूँजी पर ही या अन्य स्रोतों से ऊँचे व्याज पर ऋण लेने को बाध्य होना पड़ता है, जो मँहगी पड़ती है, फलतः पूँजी अधिक चाहिये। अतः जिन इकाइयों को उपयुक्त जितनी भी सुविधायें प्राप्त होंगी, पूँजी की आवश्यक मात्रा भी उतनी कम होगी। फलतः प्रति करघा या तकुये पर लगी हुई औसत पूँजी की मात्रा भी कम होगी। विपरीत दशा में औसत पूँजी अधिक होगी। अतः इस आधार को मापदण्ड मानना भी हमारी आवश्यकता को पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं करता।

(४) करघों या तकुओं की सख्या—वस्त्र उद्योगों के लिये उनमें पाये जाने वाले करघों या तकुओं की सख्या पर निर्भर रहना अधिक सुविधाजनक होगा। लौह एवं स्पात उद्योगों में इकाइयों में पाई जाने वाली मट्टियों की सख्या एवं उनकी क्षमता परिमाण के माप का एक विश्वसनीय आधार मानी जा सकती है।

(५) काम करने वाले श्रमिकों की सख्या—परिमाण के माप का एक अन्य आधार विभिन्न इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों की सख्या हो सकती है। इस आधार का उपयोग केवल समान प्रकृति वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जा सकता है, विभिन्न प्रकृति वाली इकाइयों के माप का यह उपयुक्त आधार नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, कुछ औद्योगिक इकाइयों में जो उत्पादन होता है वह श्रमिकों के हस्त-कौशल पर निर्भर रहता है और उनकी सख्या उत्पादन की मात्रा के अनुपात पर निर्भर रहती है। यदि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना हो, तो श्रमिकों की सख्या में तत्काल वृद्धि की जा सकती है और विपरीत स्थिति में जब उत्पादन में कमी करनी हो, तो श्रमिकों की सख्या में मात्रा के अनुपात से आवश्यक कमी की जाती है। अन्य उद्योग स्वयंचालित यन्त्र पर आश्रित रहते हैं। अतः उनमें श्रमिकों की सख्या उत्पादन के अनुपात पर नहीं किन्तु यन्त्रों की सख्या पर निर्भर रहनी है। यन्त्रों की सख्या में कमी या वृद्धि होने पर काम करने वाले श्रमिकों की सख्या में कमी या वृद्धि होती रहती है। अतः यदि उपयुक्त परिस्थितियों तथा औद्योगिक इकाइयों की प्रकृति का विचार न करते हुए केवल उन इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों की सख्या को ही परिमाण का माप माना जावेगा, तो इसमें प्राप्त हुए निष्कर्ष भ्रमात्मक होंगे।

(६) उपयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा—औद्योगिक इकाई में उपयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा का भी एक माप हो सकता है। अतः ऐसी

निर्माण-इकाइयों जहाँ सम्पूर्ण उत्पादन केवल शक्ति की सहायता से ही किया जाता हो, वहाँ शक्ति के परिमाण के अनुसार औद्योगिक इकाई का परिमाण निश्चिन करने में सहायता मिल सकती है ।

(७) उत्पादन की मात्रा — कुछ उद्योगों में, जैसे सीमेंट, चीनी या वीयला उद्योग, जिनका उत्पादन एक छा होना है, उत्पादन की मात्रा को परिमाण का एक उचित मापदण्ड माना जा सकता है, लेकिन सूनी वस्त्र जैसे उद्योग में, जोकि विविध प्रकार का सामान बनाते हैं, उत्पादन की मात्रा उसके परिमाण का उचित माप न होगी ।

(८) वच्चे माल की मात्रा — किसी इकाई द्वारा प्रति वर्ष कच्चे माल का जितना उपयुक्त होता है वह उसके परिमाण का एक उचित माप हो सकता है, बशर्ते इकाइयों आत्म निर्भर हो और उत्पत्ति के स्वभाव में अधिक विविधताएँ न हो ।

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि एक व्यापारिक इकाई का साइज, एक निश्चित मिद्वान्त के अनुसार निकाला जाना चाहिए, क्योंकि फर्म का परिमाण फर्म की निपुणता एवं लाभदायकता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है । परिमाण का माप प्रत्येक उद्योग के स्वभाव को देखकर निश्चिन किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए, जिन उद्योगों में अत्यधिक पूँजी विनियोग की आवश्यकता पड़ती है (जैसे शक्कर साफ करना), जिन उद्योगों को एकाधिकार प्राप्त है या जिनका निस्तुत बाजार होता है । (जैसे कि जलसेवा उद्योग), अथवा वे उद्योग जिनमें उत्पादित वस्तु बड़े जटिल स्वभाव की (जैसे टाइपराइटर) या बड़े आकार की (जैसे रेल क इंजन) होती है, प्रायः बड़े पैमाने पर चलाये जाने योग्य हैं, जैसे—वे उद्योग जिनके माल का प्रमाणीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि उनको विभिन्न दृष्टियों के अनुकूल बनाना पड़ता है (जैसे लकड़ कोटि का फर्निचर, कला का सामान, इत्यादि) या ऐसे उद्योग जिनका स्थानीय बाजार बहुत सीमित होता है और जिनका मालायात व्यय बहुत अधिक है (जैसे ईट) या वे उद्योग जिनमें अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है (जैसे नक्काशी, चित्रकारी) इत्यादि । कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो मध्यम आकार पर निपुणता से चलाये जा सकते हैं, जिन—दूध बनारण, आटा पीसना इत्यादि ।

STANDARD QUESTIONS

1. Critically examine the different standards employed to measure the size of a business unit.
2. Explain the term 'Optimum Size' Examine the factors which determine the size of such a unit. How can the different optima be reconciled ?

भारत में औद्योगिक इकाइयों का परिमाण

(Size of Industrial Units In India)

प्रारम्भिक—

विभिन्न भारतीय उद्योगों में औद्योगिक इकाइयों का परिमाण वहाँ तक अनुकूलतम है, इसका अध्ययन करते समय हमें प्रत्येक उद्योग में 'प्रतिनिधि इकाइया' (Representative firms) के परिमाण पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि उनमें मितव्ययिता एवं अधिकतम निपुणता को कितना प्रोत्साहन मिल रहा है।

(I) सूती वस्त्र मिल उद्योग (Cotton Textile Industry)—

एक सूती वस्त्र मिल का टैक्नीकल अनुकूलतम परिमाण अपेक्षित छोटा होता है, क्योंकि टैक्नीकल विशेषताओं के कारण इस उद्योग में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसे बड़े पैमाने पर चलाया जा सके। उत्पादन के क्षेत्र में बड़े कारखाने खोलने की ओर जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, प्रमुखतः प्रबन्ध एवं अनिर्माणीय क्रियाओं से सम्बन्धित व्ययों को कम करने के प्रयासों का परिणाम है। इसके अतिरिक्त किसी मिल द्वारा जो सामान बनाया जाता है उसका स्वभाव भी किसी संस्था के आर्थिक परिणाम को निर्धारित करने में प्रभाव डालता है। बड़ी मात्रा में प्रमाणित माल के उत्पादन के लिए, एक बड़ा प्लांट निर्माण व्ययों को कम करने में सहायक होता है। लेकिन जहाँ उत्पादन विविधता रखता हो, वहाँ एक छोटी इकाई अधिक उपयुक्त होगी। "भारत में जनता की रुचि, आदतों एवं प्रथाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि एक लघु या मध्यम परिमाण के मिल का संगठन अति उपयुक्त रहेगा।" *

टैरिफ बोर्ड (सन् १९३२) ने यह स्वीकार किया है कि भारत के लिए एक उपयुक्त मिल के लिए 'न्यूनतम आर्थिक परिमाण' निर्दिष्ट करना दो बातों के कारण कठिन है— प्रथम, कई मिलों की सम्मिलित सेवा के लिए एक केन्द्रीय संगठन बना

1. 'The existence of marked preferences and tastes of a local or sectional character which has hitherto characterised the Indian market on the whole, favours the organization of the small or moderate sized mills Report of the Indian Tariff Board on Cotton Industry 1932, p 97).

होने से व्यक्तिगत मिलों का साइज अमहत्वपूर्ण सा हो जाता है और दूसरे, एक छोटा मिल जो कि योग्य एव अनुभवी प्रबन्ध के अन्तर्गत चलाया जा रहा है वह एक बड़े मिल की अपेक्षा, जो कि वृष्टिपूर्ण प्रबन्धन के आधीन है, अधिक अच्छे परिणाम दिखा सकता है।

फिर भी टेरिफ बोर्ड ने यह स्वीकार किया है कि ३५ से ४० हजार तकिये एवं १,००० करघे वाली मिल न्यूनतम लागत मूल्य के विचार से अनुकूलतम इकाई है। बम्बई में एक औसत कताई मिल का यही परिमाण है, जब कि अहमदाबाद के लिए आदर्श परिमाण २५ हजार तकिये और ६०० से ७०० करघे स्वीकार किया। इस स्तर से तुलना की जाय, तो भारत में ५६% कताई मिल और ८२% बुनाई मिल अनुकूलतम परिमाण से छोटे थे।

भारत के सूती वस्त्र मिलों के परिमाण में बहुत सौं प्रतीय अन्तर दृष्टिगोचर होता है। दक्षिण-क्षेत्र (मद्रास, बेंगल और मैसूर) की इकाइयों का परिमाण सबसे छोटा है—१० से १५ हजार तकिये एवं २०० से ४०० करघे। पूर्वी पंजाब और राजस्थान में भी यही दशा है। उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र और बम्बई प्रेसीडेंसी के शेष भाग में मध्यम आकार की मिलें पाई जाती हैं, जिनमें १५ से ३० हजार तकिये और ४०० से ६०० करघे होते हैं। बम्बई शहर एवं द्वीप में इकाइयों का परिमाण काफी बड़ा है, लगभग ३० से ६० हजार तकिये और ७५० से १,५०० करघे। अहमदाबाद की मिलों का साइज औसतन बम्बई मिलों के साइज से छोटा है।

बम्बई के मिलों का बड़ा परिमाण (और अहमदाबाद की मिलों का अपेक्षा-कृत छोटा परिमाण) निम्न कारणों से है—

(१) बम्बई में उद्योग प्रारम्भ से ही सूत निर्यात व्यापार के लिए संगठित हुआ है, इसलिये फर्मों का बड़े परिमाण पर स्थापित होना स्वाभाविक था। इसके विपरीत अहमदाबाद में उद्योग 'घरेलू बाजार' का लाभ उठाने के लिये स्थापित हुआ था, इसलिये वे छोटे पूँजीपति और साधारण योग्यता के पन्तु मेहनती व्यक्तियों के लिये काफी आकर्षक थे।

(२) जिन लोगों ने बम्बई में फर्में स्थापित की, उन व्यापारियों ने कपड़े के व्यापार में बड़ा लाभ कमाया था, इसलिये वे कुछ साहसिक और बड़े परिमाण पर उद्योग स्थापित कर सके।

(३) अहमदाबाद में सूती मिलें अलोक-सीमित (Private limited) उत्तरदायित्व के आधार पर स्थापित हुईं, जबकि बम्बई में लोक-सीमित (Public limited) उत्तरदायित्व के आधार पर। अस्तु अहमदाबाद की मिलों को उनकी अधिकांश पूँजी प्रबन्ध-अधिकर्ता व उनके मित्रों से ही प्राप्त होनी है। प्रबन्ध अधिकर्ताओं के साधन सीमित होते हैं, इसलिये आवश्यक रूप से उनका परिमाण छोटा होगा, क्योंकि विशेष विकास के लिए उन्हें जनता की घरोहरो पर निर्भर रहना होता है। परन्तु बम्बई की मिलें स्कन्ध-विपणि (Stock Exchange) की दलचलो

द्वारा सरलतापूर्वक अतिरिक्त अर्थ निगमन करके पर्याप्त पूँजी प्राप्त कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपना परिमाण विशेष विकसित कर लिया ।

उत्तरी भारत के केन्द्रों में छोटी इकाइयाँ सरलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, क्योंकि कच्चे माल के सामिप्य एवं तैयार माल के बाजार की निकटता के कारण उन्हें बम्बई मिस्री की तुलना में रेल-आड़ों के सम्बन्ध में, जो कि कुल लागत का एक महत्वपूर्ण भाग है, अधिक सुविधा मिल गई है । यही नहीं, उपभोक्ताओं के निकट सम्पर्क में रहने की वजह से वे माँग के अनुसार उत्पादन की सरलता में समायोजित कर सकती हैं । कुछ पुरानी रियासतों में छोटी इकाइयों को भी सफलता मिली, क्योंकि उन्हें निशुल्क भूमि, छुट्टी की छूट, बिजली की सुविधा, घाय-कर से मुक्ति इत्यादि लाभ प्राप्त थे ।

साधारणतः बम्बई एवं अहमदाबाद के केन्द्रों को छोड़ कर अन्य केन्द्रों में इकाइयाँ छोटी हैं, तथापि कानपुर, मद्रास, नागपुर, दिल्ली जैसे केन्द्रों में काफी बड़ी इकाइयाँ स्थापित हैं । इन्हें अनुभवों और घनी थोरोपियनों द्वारा स्थापित किया गया था और यथेष्ट वित्तीय साधन, कच्चे माल की समीपता एवं उपभोग के द्रो की निकटता तथा चतुर एवं सस्ते श्रमिका का पर्याप्त मात्रा में मिल सकना ऐसे कारण थे जिन्होंने इन केन्द्रों में काफी बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना को सम्भव बना दिया था । सन् १९०५ तक इन केन्द्रों में ४०,००० तकियों एवं ५०० करघों से कम परिमाणों का एक भी मिल न था । यह तो सन् १९२१ के पश्चात् ही था, जब कि कुछ साहसी पूँजीपतियों द्वारा छोटी छोटी इकाइयाँ कायम की गई ।

सन् १९५१-५६ के औद्योगिक विकास कार्यक्रम में योजना आयोग ने १५० प्रमुख एवं अनाधिक इकाइयों का विश्लेषण किया था । कुछ समय हुआ, इनमें से २५ इकाइयाँ तो बन्द हो गई हैं, जबकि ३५ इकाइयाँ हानि सहित चलाई जा रही हैं । ९० इकाइयों को बहुत कम या नहीं के बराबर लाभ (भयवा साधारण हानि तक) हो रहा है । इन इकाइयों को अपना परिमाण आर्थिक साक्ष्य तक बढ़ा देने के हेतु सहायता देना बड़ा आवश्यक है । योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि ऐसी इकाइयों का विस्तृत अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जावे, जो फिर अभिनवीकरण एवं संवर्धन का कार्यक्रम बनावे । सन् १९५८ में कॉटन टैक्स-टाइल इन्वामरी कमेटी ने यह सिफारिश की कि बहुत ही अनाधिक इकाइयों को उचित सतुलन द्वारा या अन्य समर्थ संस्थाओं के साथ समुत्कीकरण द्वारा आधिक बनाया जाय । सीमावर्ती इकाइयों (Marginal Units) को आपत्ति से बचाने के लिये कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम में ऐसी संशोधन कर दिया जाय, जिससे सरकार ऐसी मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सके । सरकार द्वारा जिन मिलों को प्रबन्ध के हेतु ले लिया गया हो, उन्हें चलाने के लिये पर्याप्त पूँजी वाला एक स्वतन्त्र निगम बनाया जाय ।

(II) जूट उद्योग (Jute-Industry)

जूट मिल वस्त्र उद्योग में औद्योगिक इकाइयों के अनुकूलतम आकार का निर्धारण बहुत सीमा तक विपणि एवं प्रबन्ध सम्बन्धी घटकों द्वारा प्रभावित होता है। इस उद्योग में टेक्नीकल अनुकूलतम छोटा है और आकार को प्लान्ट को सख्या बढ़ा कर बढ़ा किया जा सकता है।

उद्योग के अन्तर्राष्ट्रीय स्वभाव एवं विश्व व्यापार की बढ़ती हुई माँग के कारण इकाइयाँ प्रारम्भ में काफी बड़े पैमाने पर स्थापित की गई थी, किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद इकाइयों का आकार कुछ छोटा हो गया, क्योंकि प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ अनुभव की गई थी।

स्थानीयकरण के घटक ने भी इस उद्योग में इकाइयों के आकार को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिये, बंगाल में स्थापित होने वाले मिलों का आकार देश के अन्य भागों में स्थापित हुये मिलों से बड़ा है। इसका कारण वहाँ कच्चे जूट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना है। सन् १९५१ में बंगाल के ६२ मिलों में से ४१ मिलों की करघा क्षमता ५०० से १,४०० तक थी, जबकि अन्य भागों में यह क्षमता ५०० से कम है।

भारत के औसत जूट मिल का आकार विदेशी जूट मिलों के आकार से बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिये, ब्रिटेन में मॉडल श्रेणी के मिलों की क्षमता केवल २०० है और किसी भी मिल की क्षमता १,००० करघे से अधिक नहीं है। इसका कारण प्रबन्ध या वित्त सम्बन्धी घटक नहीं है, क्योंकि प्रबन्ध योग्यता एवं वित्तीय सुविधायें इंग्लैण्ड में पर्याप्त हैं। वास्तविक कारण यह है कि वहाँ के मिल केवल स्थानीय बाजार की पूर्ति के लिये उत्पादन करते हैं, जबकि भारतीय मिलें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिये माल बनाते हैं।

भारत में सन् १९५१ में ८५ जूट मिल कंपनियों में से ४० मिल कंपनियों का प्रबन्ध ६ प्रबन्ध अभिकर्ता गृहों के हाथ में है। इनमें से २ प्रबन्ध अभिकर्ता गृहों का २१ मिलों पर नियन्त्रण है। एक प्रबन्ध अभिकर्ता गृह द्वारा कई मिलों का प्रबन्ध होने की प्रणाली से प्रबन्ध एवं निरीक्षण सम्बन्धी, केन्द्रीय क्रय एवं विक्रय की तथा वित्त की मितव्ययितायें प्राप्त होने लगती हैं।

जूट उद्योग से वास्तविक उत्पत्ति आयोजित क्षमता से बहुत कम रहती है। उद्योग का विपणि-अनुकूलतम (Marketing Optimum) बहुत अधिक है और कुछ समय से उद्योग में उत्पादन का नियमन व नियन्त्रण करने की योजनायें चल रही हैं।

अभी हाल में उद्योग के अनुकूलतम आकार की समस्या अरब देशों में स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग बढ़ने, पाकिस्तान में जूट मिल खुलने और विभाजन के बाद कच्चे माल का अभाव होने से अधिक जटिल हो गई है। लेकिन पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कच्चे जूट की पूर्ति बढ़ाने में काफी सफलता हुई है।

सन् १९५८ में वंगाल के चैम्बर ऑफ कामर्स की वार्षिक सभा में अध्यक्ष पद से खोलते हुये श्री मिचेलमोर ने बताया था कि बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये अन्त्यार्थिक छोटी-छोटी इकाइयों को समाप्त करने के लिये कदम उठाये गये हैं। जैसे, सन् १९५७ में ६ मिल बन्द कर दिये गये। उनके करघे अन्य मिलों को हस्तान्तरित कर देने से उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ने पाया है।

(III) शक्कर उद्योग (Sugar Industry)

शक्कर उद्योग में किमी इकाई का आर्थिक आकार कितना हो, यह गन्ने की उपलब्ध यातायात सुविधायें एवं बाजारों की निकटता पर निर्भर है। सन् १९३८ में शक्कर उद्योग सम्बन्धी प्रशुल्क बोर्ड के मतानुसार ५०० टन की क्षमता का कारखाना समस्त भारत के लिए एक उचित आर्थिक इकाई है, यद्यपि यातायात व्यय सम्बन्धी विशेष सुविधा होने से इसमें भी कम क्षमता के छोटे कारखाने स्थानीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकते हैं।

अधिकांश इकाइयाँ सन् १९३० के बाद स्थापित हुई थी। इन्होंने एक मामूली आकार पर कार्य प्रारम्भ किया। इनकी क्षमता केवल ४००-५०० टन थी। छोटा आकार रखने के निम्न कारण थे—(i) इन इकाइयों के स्थापकों के साधन अधिक नहीं थे, यद्यपि उनमें संगठन-योग्यता की कोई कमी न थी। (ii) मदी के मूल्य से उद्योगपति अधिक जोखिम उठाने को तैयार न थे, और (iii) यू०पी० एवं बिहार में प्रौद्योगिक टेक्नीकल का उस समय अधिक विकास न था।

इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश शक्कर मिला की क्षमता ७०० से १,००० टन प्रति दिन है, जबकि अन्य राज्या में अधिकांश मिला की क्षमता ५०० से ८०० टन है। जिन भागों में गन्ने की पर्याप्त पूर्ति उपलब्ध है, वहाँ बड़ा मिल भी लाभ सहित खोला जा सकता है। लेकिन देश के अनेक भागों में गन्ने के खेत छोटे-छोटे हैं और गूठ व सड़सारी की प्रतियोगिता भी बाधक है। पञ्जाब में कारखानों का छोटा आकार अच्छे गन्ने के अभाव के कारण है। मद्रास में कारखानों की कठिनाई यह है कि उन्हें छोटे छोटे उत्पादकों से गन्ना खरीदना पड़ता है जो गन्ने की खेती के लिए सीमित क्षेत्रफल ही प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार बम्बई में गन्ने की कृषि के व्यय ऊँचे होने से कारखानों को असुविधा होती है। फिर भी इन राज्यों के कारखानों को स्थानीय बाजारों में उत्तर-प्रदेश व बिहार के गन्ना मिलों की तुलना में यातायात व्यय सम्बन्धी लाभ रहता है, जिससे वे उन मिलों से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर लेती हैं।

यह उल्लेखनीय है कि भारत में गन्ना मिलों का औसत आकार क्यूबा, हवाई आस्ट्रेलिया और जावा की तुलना में, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, बहुत छोटा है। अभी हात्त में, योजना आयोग ने यह पता लगाया था कि देश में प्रति दिन २०० से ३,२०० टन तक गन्ना पेरने की क्षमता रखने वाले मिल हैं। वर्तमान परिस्थितियों में प्रति दिन ७००-८०० टन गन्ना पेरने की क्षमता वाला

मिल एक आर्थिक इकाई कहा जा सकता है। सन् १९५५-५६ में १४३ गन्ना-मिलों में ३१ मिलों की क्षमता ७०० टन से कम थी। इसमें से ६ मिलों को क्षमता बढ़ाने के लिये लाइसेंस स्वीकृत किये गये। सन् १९५५-५६ में जिन मिलों को बन्द रहना पड़ा था उनमें से अधिकांश मिल वे थे जिनकी क्षमता आर्थिक आकार से कम थी। सन् १९५४ में गन्ना विकास परिषद् की स्थापना हुई थी, जिसने बन्द रहने वाले मिलों के विषय में उपयोगी सुझाव दिये थे।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९६०-६१ तक गन्ना उद्योग की कुल आयोजित क्षमता २५ लाख टन तक बढ़ा देने का प्रस्ताव था। अतः ५६ नये कारखानों की स्थापना के लिये ६८ विद्यमान कारखानों की क्षमता के विस्तार के लिये लाइसेंस स्वीकृत किये गये। ५६ नये कारखानों में से ३६ कारखाने सहकारी आधार पर स्थापित किये गये हैं।

(IV) लौह एवं स्पात उद्योग

लौह एवं स्पात उद्योग में प्लाटो का आकार मुख्यतः बच्चे माल (जैसे खनिज लोहा, कोयला, चूने का पत्थर) की प्लान्ट मात्रा में तथा उचित दूरी के भीतर उपलब्धि से, प्रबंध व्यवस्था एवं वित्तीय सुविधा की विद्यमानता, प्रभावीकरण की सीमा, सरक्षण की मात्रा और बाजारों के स्वभाव, सीमा एवं निश्चिन्ता से प्रभावित होता है। टेक्नीकल अनुकूलतम इस उद्योग में काफी ऊँचा है, क्योंकि प्लान्ट का आकार बढ़ा हाने पर व्यय कम हो जाते हैं।

इस उद्योग की औसत इकाई का आकार देश में भिन्न है। इंग्लैण्ड की इकाइयों का आकार अमेरिका और जर्मनी की इकाइयों के आकार से छोटा है। भारत में एक बड़ी इकाई अधिक आर्थिक प्रमाणित होती, क्योंकि यहाँ भौगोलिक एवं जियोसोसियल घटक एक बड़ आकार की इकाई स्थापित करने के अनुकूल हैं। लेकिन प्रबंध योग्यता की कमी तथा खनिज लोहे के भण्डारों से कोयला दूर मिलने के कारण अधिक इकाइयाँ स्थापित करने में कठिनाई अनुभव की जाती है।

प्रथम योजना के पूर्व देश में तीन प्रमुख उत्पादक थे — टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी, इंडियन आइरन एंड स्टील कम्पनी और सैसू आइरन एवं स्टील वर्क्स। तत्पश्चात् पंच वर्षीय योजनाओं का प्रगति के दौरान में सार्वजनिक क्षेत्र में तीन नये प्लांट स्थापित किये गये हैं—रूरकेला (उड़ीसा), मिलाई (मध्य-प्रदेश), और दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल)। इनमें विदेशी टेक्नीशियनों का सहयोग प्राप्त है।

टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी की प्रारम्भिक क्षमता सन् १९११ में ३५,००० टन कच्चा लोहा व ५०,००० टन तैयार स्पात थी। द्वितीय महायुद्ध काल में इसने १.२४ मि० टन कच्चा लोहा, १.०८ मि० टन स्पात पिण्ड तथा ८,१६,००० टन बिक्री योग्य स्पात तैयार किया। युद्धोत्तर काल में इसने दो विस्तार कार्यक्रम अपनाये। इनका लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना था, ताकि वह प्रति वर्ष २ मि० टन स्पात पिण्ड या १.५ मि० टन बिक्री योग्य स्पात तक पहुँच जाय। इस लक्ष्य की पूर्ति

का अर्थ है उत्पादन क्षमता का लगभग दो गुना हो जाना । यह कार्यक्रम सन् १९५८ तक पूर्ण कर लिया गया है ।

। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी सन् १९१८ में बनी । सन् १९५२ में इसमें स्टील कॉरपोरेशन आफ बंगाल को भी मिला दिया गया । सन् १९५५-५६ के अन्त तक इसकी क्षमता तैयार स्पात के लिये ३,५०,००० टन थी, जबकि सन् १९५०-५१ में वह केवल २,२५,००० टन ही थी । द्वितीय योजना के अन्त तक इसकी क्षमता ८,००,००० टन प्रति वर्ष कर देने की थी ।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ने सन् १९२० में जब उत्पादन आरम्भ किया, तो उसकी क्षमता २८,००० टन बच्चा सोहा थी । धीरे-धीरे इसमें नये-नये प्लांट बढ़ाये गये और विविधमुखी उत्पादन के लिये कई विकास योजनाएँ भी कार्यान्वित की गईं । द्वितीय योजना के अन्तर्गत जो विकास कार्यक्रम बनाया गया था उसके पूरा होने पर इसकी क्षमता १,००,००० टन तैयार स्पात तक पहुँच जायेगी ।

सन् १९५५ में सरकार ने ६ मि० टन हस्पात पिण्डों के उत्पादन का लक्ष्य घोषित किया, जिसकी पूर्ति सन् १९६०-६१ तक होनी थी । इसमें सावजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले प्लांटों का सहयोग भी अपेक्षित था । टाटा कम्पनी का उत्पादन ०.६ मि० टन से बढ़ाकर २.० मि० टन, इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी का उत्पादन ०.०३ मि० टन से बढ़ाकर ०.१ मि० टन हो जाना था । सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्येक प्लांट की क्षमता १ मि० टन रखी जायेगी ।

सन् १९५८ के एक प्रेस नोट में भारत सरकार की एक नवीन योजना का संकेत किया गया है, जिसके अन्तर्गत देश के उन भागों में जहाँ लोहे के सम्पन्न भण्डार हैं, लघु-उद्योगों के रूप में स्टील प्लांटों की स्थापना की जावेगी ।

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly discuss the desirability of the size of industrial units obtainable in India these days with special reference to Cotton Textile Industry
2. What are the factors which affect the size of units in (a) Jute, (b) Sugar and (c) Iron Steel Industry in India ? Account for their present position

अध्याय ५०

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली

(उद्गम एवं विकास)

(Managing Agency System—Origin & Development)

भूमिका—

भारतवर्ष के किसी महत्त्वपूर्ण उद्योग में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का बड़ा भाग रहा है। भारतीय प्रशुल्क मण्डल ने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जा रिपोर्ट सन् १९३१ में प्रकाशित की थी, उसमें यह स्वीकार किया गया था कि “केवल उन बड़े उद्योगों को छोड़ कर जिन्हें भारत में राज्य ने संगठित किया अथवा जो उसकी देख-रेख में स्थापित किये गये, लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण उद्योग इन्हीं प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साहस के कारण जन्म पा सका है।” अब भी अधिकतर औद्योगिक समस्याएँ, विशेषकर सीमित उत्तरदायित्व वाली पब्लिक कम्पनियाँ इन्हीं के हाथ में हैं। उदाहरण के लिए, जमशेदपुर का लोह व इस्पात का उद्योग, बम्बई व अहमदाबाद का सूती वस्त्र उद्योग, बंगाल व बिहार का जूट उद्योग देश के सबसे अधिक संगठित उद्योगों में से हैं, परन्तु इन उद्योगों में ऐसा शायद ही कोई मिल हो जो किसी प्रबन्ध अभिकर्ता के परोक्ष निम्नरण में नहीं है। प्रबन्ध अभिकर्ता देश के औद्योगिक क्षेत्र में यह स्थिति कैसे प्राप्त कर सके, इस प्रश्न का उत्तर हमें उन परिस्थितियों में मिलेगा जो भारत की अपनी अनोखी विशेषता रही है।

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ—

(१) पूँजी की कमी—वास्तव में प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति का उदय भारत के औद्योगिक विकास के साथ-साथ हुआ। यहाँ कुछ उद्योगों के भारतीय मूलक विकासकर्ता अथवा व्यवसायी थे, जो पहले यहाँ कुछ व्यापारिक सस्थाओं के प्रतिनिधियों की भाँति आये। पहले तो इन्होंने सामान्य व्यापार का काम किया, परन्तु बाद में अन्य कामों की ओर भी आकर्षित हुए। इन्होंने देखा कि भारत एक विशाल कृषि देश है, भरपूर प्राकृतिक साधन हैं, जाकि विशाल बाबादी, पर्याप्त श्रम की सुलभता होते हुए भी औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जनता दूसरों को उद्योग में

लगाने के लिये द्रव्य देने में सकोच करती है। पूँजी के अतिरिक्त और साधन यहाँ हैं, जिनका होना औद्योगिक उन्नति के लिये आवश्यक है।

अस्तु अपने लाभ के लिए उन्होंने आवश्यक पूँजी स्वयं प्रदान करने का निश्चय किया एवं अपने भिन्नो को भी इसके लिये तैयार किया। उद्योग स्थापित कर दिए गए, साभेदारी बन गई और उद्योग चलाने के लिये आवश्यक पूँजी दे दी गई। हानि एवं अन्य आपत्तियों के समय में भी उन्होंने उद्योग को बचाने के लिये आर्थिक मदद दी, क्योंकि बाहरी जनता से तब ही पूँजी प्राप्त करने की आशा की जा सकती थी जबकि यह उद्योग स्पष्टतः सफल होता प्रतीत हो। जब यह दशा पहुँच जाती थी तो वे उसे कम्पनी में परिवर्तित कर देते और अपनी पूँजी का बड़ा भाग वापिस लेकर उसे फिर विन्ही अन्य प्रयत्नों में लगा देते थे। कम्पनी के जन्मदाता तथा प्रमुख पूँजी प्रदान करने वाले एवं अनुभवही प्रबन्धकर्त्ता होने के रूप में उनका उस कम्पनी के नियन्त्रण में काफी हाथ रहता था। एक ही प्रबन्ध अभिकर्त्ता गृह के आपीत कई प्रमण्डल नियन्त्रित करते थे। प्रबन्ध अभिकर्त्ता-पद्धति वगाल में शुरू हुई और फिर अन्य भागों में भी फैल गई। कुछ भारतीय पूँजीपतियों ने भी उनकी देखा-देखी उनकी सफलता से प्रेरित हो इस प्रकार का कार्य करना प्रारम्भ किया और इसमें उन्हें विदेशियों से बड़ी सहायता मिली।

(२) बैंको का विचित्र दृष्टिकोण—एक दूसरी बात जो इस पद्धति के जन्म का कारण बनी वह थी बैंको की यह हठ कि प्रमण्डलों को तब ही ऋण दिया जाय (वह भी लम्बे समय के लिए नहीं, थोड़ी ही अवधि के लिये) जबकि उसके प्रबन्ध अभिकर्त्ता इस ऋण की गारन्टी दे। उनका यह आग्रह इस कारण था कि वे प्रमण्डलों की आन्तरिक स्थिति से तो परिचित होते नहीं थे, परन्तु प्रबन्ध अभिकर्त्ता सब कुछ जानते थे, अस्तु यह स्वाभाविक हो था कि बैंक उनकी गारन्टी को माग करें। ऊँची आर्थिक स्थिति के प्रमण्डल भी बैंको से तब ही ऋण प्राप्त कर सकते थे जबकि उनके प्रबन्ध अभिकर्त्ता गारन्टी देने को तैयार हो।

(३) कम्पनी अधिनियम की दुर्बलतायें—तीसरे, उस समय के भारतीय कम्पनी अधिनियम की दुर्बलताओं ने भी प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति को प्रसाहित किया। सन् १८१३ तक कम्पनियों के लिये सञ्चालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य न था, अतः जो भी व्यक्ति किसी कम्पनी के निर्माण में हित रखते थे वे स्वयं उसके प्रबन्ध अभिकर्त्ता बन जाते थे। जब सन् १८१३ के अधिनियम ने पब्लिक कम्पनियों के लिए सञ्चालकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी, फिर भी प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के लिए कोई कठिनाई पैदा न हुई, क्योंकि अपने व्यापारिक सहयोगियों एवं मित्रों में से ही वे कुछ लोगों को चुन कर सञ्चालक नियुक्त कर देते थे और इस प्रकार नियन्त्रण की बागडोर वास्तव में उन्हीं के हाथ में रहती थी।

अस्तु इन परिस्थितियों में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का औद्योगिक संगठन में प्रमुख स्थान का लेना स्वाभाविक ही था।

विध अभिकर्ताओं का संगठन—

प्रबन्ध अभिकर्ताओं का संगठन वैयक्तिक, सामेदारी अथवा कम्पनी के रूप हो सकता था, किन्तु मुख्यतः इनका संगठन सामेदारी की संस्थाओं अथवा प्राइवेट कंपनियों के रूप में ही हुआ है। कुछ ऐसी भी संस्था है जो पब्लिक कम्पनी के रूप में भी गई। अभिकर्ताओं में से कुछ संस्थायें भारतीय हैं और कुछ योरोपीय। योरोपीय संस्थाओं में बड एण्ड कम्पनी का नाम प्रमुख है। इनके संगठन का रूप कुछ भी हो, यह विशेषण कौटुम्बिक व्यवसाय की भाँति होते हैं, जिनमें किसी एक विशेष का ही अधिक महत्त्व रहता है, जैसे—गिरला ब्रादर्स लिमिटेड। ये भी फर्म के सदस्यों में अधिकतर अपने कुटुम्बियों को ही लेते हैं। बाहरी लोगों के ये हममें प्रायः कोई स्थान नहीं होता। यह प्रवृत्ति भारतीय अभिकर्ताओं में भी शेष रूप से देखी जाती है, किन्तु योरोपीय अभिकर्ताओं में अनुभव, विशेष योग्यता तथा अन्य किसी गुण को ध्यान में रखते हुए बाहरी लोगों को भी सदस्यता दी जाती है।

बंध अभिकर्ता के कार्य—

प्रबन्ध अभिकर्ताओं के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—(१) कम्पनी का प्रवर्तन व निर्माण करना, (२) अर्थ पूर्ति करना, और (३) कम्पनी की व्यवस्थापना।

(१) कम्पनी प्रवर्तन एवं निर्माण—किसी भी नई कम्पनी की स्थापना पूर्व कुछ प्रारम्भिक अनुसंधान आवश्यक होता है। प्रबन्ध अभिकर्ता इन प्रारम्भिक कार्यों को करते हैं एवं समस्त अनुविधाओं और उत्तरदायित्व को सहन करते हुये सकी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार जहाँ औद्योगिक विकास की कमी रहती है अथवा यदि कहे कि जहाँ लोग अधिक जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते वहाँ प्रबन्ध अभिकर्ता असाधारण मेहनत कर अपने अधिक परिश्रम एवं कर्तव्यपरायणता द्वारा व्यवसाय की उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा देते हैं। भारतवर्ष में प्रवर्तकों का सर्वथा अभाव नहीं है। ये प्रबन्ध अभिकर्ता भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक अनुभव एवं तात्त्विक योग्यता प्राप्त करते हैं तथा अपने अभिकर्ताओं में कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, जिससे वे भिन्न भिन्न व्यावसायिक कम्पनियों का स्थापन एवं संगठन करने में सफल होते हैं।

भारत में टाटा एण्ड सन्स लिमिटेड, डालमिया जैन लिमिटेड, बड एण्ड कम्पनी, पार्टन एण्ड कम्पनी, जेम्स फिन्ले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, जे० पी० श्रीवास्तव एण्ड सन्स, करमचन्द थापर एण्ड ब्रादर्स लिमिटेड आदि प्रसिद्ध प्रबन्ध अभिकर्ताओं की संस्थाएँ हैं, जिन्होंने अनेक कम्पनियों का प्रवर्तन किया है।

(२) अर्थ पूर्ति करना—प्रबन्ध अभिकर्ताओं का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य

कम्पनी की आर्थिक व्यवस्था करना है। ये लोग घनाभाव की दशा में उसकी पूर्ति के लिये पूर्ण प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि कम्पनी की समस्त आर्थिक समस्याओं को सुलभाना उनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाता है। प्रबन्ध अभिकर्ता न केवल प्रारम्भिक स्थायी पूँजी का ही, किन्तु बाद में पुनर्संज्ञान, विकास तथा आधुनिकीकरण व कार्यक्षील पूँजी के लिये भी अथवा प्रबन्ध करते हैं। यह सच है कि गत कुछ वर्षों में, जबकि जनता के पास काफ़ी मात्रा में द्रव्य था, सहस्र कम्पनियाँ केवल जनता के द्रव्य से स्थापित हुई, परन्तु यह सम्पन्नता अधिक ठहरने वाली नहीं है और अब भी जब से 'बन्दोल ऑफ़ कॅपिटल इश्यूज' लागू हुआ है, इस बात की आवश्यकता होती है कि प्रवर्तक भी कुछ पूँजी प्रदान करें। वे अर्थ प्रबन्ध निम्न ढङ्गों से करते हैं —

- (अ) वे स्वयं कम्पनी के अशा व ऋण पत्रों को लेते हैं और अपने मित्रों तथा नातेदारों को भी खरीदवा देते हैं।
- (आ) जिस समय बैंक से ऋण लेने की चार्ज बसती है तो कम्पनी द्वारा मंजि हुय ऋण के लिए प्रतिभूति प्रदान करते हैं।
- (इ) उनकी ख्याति के चल पर प्रमण्डल अपनी स्थायी पूँजी का बहुत बड़ा भाग जनता से धरोहर के रूप में प्राप्त कर लेता है।
- (ई) सङ्कटावस्था में, जबकि अन्य ढङ्गों से उसे सहायता मिलना सम्भव नहीं, उनका आड़े आना प्रशस्तनीय है। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें प्रमण्डल टूटने से बचल इस कारण बच गये कि उन्होंने उनकी समय पर आर्थिक सहायता दे दी और उनके पुनर्संज्ञान में मदद की।
- (उ) नई कम्पनी जनता को अपने अशा व ऋण पत्र खरीदने के लिए प्रबन्ध-अभिकर्ताओं के नाम के चल पर ही आश्रित कर पाती है। किसी अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त प्रबन्ध अभिकर्ता का नाम जब कम्पनी के प्रवक्ता में दिया होता है तो उससे जनता का कम्पनी के प्रति विदवास बढ़ जाता है।
- (ऊ) वे कम्पनियाँ के अशा और ऋण पत्रों का अभिगोपन करते हैं, इससे कम्पनी निडर होकर कार्य आरम्भ कर सकती है, क्योंकि निश्चित मात्रा में अशा न बिके तो यह अभाव प्रबन्ध अभिकर्ता स्वयं पूरा कर देंगे।

(३) कम्पनी की व्यवस्था—प्रबन्ध अभिकर्ता अपने तान्त्रिक ज्ञान एवं व्यावसायिक अनुभव द्वारा कम्पनी की लाभजन शक्ति बढ़ाते हैं। यह ढङ्के की चोट पर कहा जा सकता है कि भारत में कम्पनियों की यशस्विता तथा व्यवस्थापन एवं प्रबन्ध कार्य की सफलता का सम्पूर्ण श्रेय इसी प्रबन्ध अभिकर्ताओं को है।

प्रबन्ध अभिकर्ता के गुरु-दोष

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रथा के लाभ—

भारत के औद्योगीकरण के इतिहास में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि इनकी विभिन्न सेवाओं द्वारा ही देश की औद्योगिक प्रगति सम्भव हो सकी। इन प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) प्रवर्तन एवं निर्माण—

जैसा हम ऊपर सचेत कर चुके हैं, प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने प्रारम्भिक अनुसंधान करके एवं अनुविधानों तथा असफलताओं का सामना करते हुए अनेक सकल उद्योगों की नींव डाली थी। इनकी पहायता के बिना चाय, जूट, कपास, कोयला आदि बड़े बड़े व्यवसाय न तो स्थापित हो सके होते और न उनकी शीघ्र उन्नति हो होती। प्रबन्ध अभिकर्ताओं का कम्पनियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, अतः वे सुदृढ कम्पनियों की ही स्थापना करते हैं। यही नहीं, कम्पनी की स्थापना के लिए समस्त वैधानिक कार्यवाही करते हैं और मान्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को सञ्चालक पद के लिए चुनते हैं।

(२) आर्थिक सहायता—प्रबन्ध अभिकर्ता विभिन्न रीतियों से, जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं, कम्पनी को आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। इनके व्यावसायिक जीवन और वाणिज्य जगत में सहायता के बल पर जनता को नव निर्मित कम्पनियों से सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा रहती है।

(३) वैज्ञानिकरण एवं सूचीकरण—इन सेवाओं के अतिरिक्त प्रबन्ध अभिकर्ता अपने अन्तर्गत कम्पनियों की व्यवस्था में एकसूत्रता लाते हैं, जिससे उनमें मित-व्ययिता होती है और कार्यक्षमता बढ़ती है। प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक संस्थाएँ होती हैं, जिनके विशिष्टीकरण के लिए वे अपने कार्यालय में अलग-अलग विभाग रखते हैं, जिससे उनके अन्तर्गत जितनी कम्पनियाँ हैं उनकी

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के गुरु दोष

गुण एवं लाभ—

- (१) उद्योगों का प्रवर्तन।
- (२) उद्योगों को आर्थिक सहायता।
- (३) वैज्ञानिकरण एवं सूचीकरण।
- (४) विशेषज्ञों की सेवाओं की सुविधा।
- (५) विनियोगों की सुरक्षा।
- (६) प्रतिभूतियों का अभिगोपन।
- (७) प्रतिस्पर्धा का प्रग्न।

दोष प्रथका श्रानियाँ—

- (१) आर्थिक प्रभुत्व।
- (२) शक्ति का अत्यधिक सट्टा।
- (३) सञ्चालकीय नियन्त्रण की स्थिति-सना।
- (४) अन्तर्विनियोग।
- (५) अयोग्य व्यवस्था।
- (६) शोषण।
- (७) ऋण का ऋण प्रभो में परिवर्तन।
- (८) नये प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सापनों में कथो।

विशेष योग्यता का लाभ हो सके। व्यक्तिगत रूप में कम्पनियों के लिए यह सम्भव नहीं होता कि विशिष्ट योग्यता वाले अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकें, किन्तु प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के माध्यम से न्यूनतम व्यय पर उन्हें विशेषज्ञों की सेवा का लाभ प्राप्त हो जाता है। दूसरे, पूरक व्यवसायों की दशा में एक व्यवसाय का माल दूसरे व्यवसाय में सुविधा से खप जाना है। उदाहरण के लिए, सूती वस्त्र, यातायात तथा कोयला ये तीन उद्योग एक दूसरे के पूरक होने के कारण कोयले की खपत वस्त्र मिल उद्योगों में हो सकती है एवं वस्त्र व्यवसाय को यातायात की सुविधायें मिल जाती हैं तथा यातायात उद्योग को स्याई ग्राहक मिल जाते हैं। यदि ये तीन उद्योग अलग-अलग प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के नियन्त्रण में हैं तो सम्भवन, यह लाभ न होगा। तीसरे, प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपना क्रय-विक्रय विभाग भी रखते हैं, जिससे उनके प्रबन्ध में जो व्यवसाय हैं उनकी आवश्यकताओं का क्रय तथा विक्रय इसी विभाग के द्वारा सुगमता से हो जाता है।

(४) विशेषज्ञों द्वारा सहायता—प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने यहाँ कुशल एवं अनुभवी विशेषज्ञ रखता है। इस प्रकार योद्धे से व्यय में ही सरलतापूर्वक इन विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त हो जाता है, जिससे समय-समय पर व्यवसाय को अत्यन्त लाभ होता है।

(५) विनियोगों की सुरक्षा—प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपनी रूपाति का बड़ा ध्यान रखते हैं और जहाँ तक धन पड़ता है, इस पर बलशुक्ल नहीं लगने देते, इसलिए जनता तथा विनियोगिताओं को यह विश्वास हो जाता है कि प्रतिष्ठित प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के प्रबन्ध में जो कम्पनियाँ हैं उनमें उनका धन सुरक्षित रहेगा।

(६) प्रतिभूतियों का अभिगोपन—ग्रन्थ देशों की भाँति हमारे देश में औद्योगिक प्रतिभूतियों का अभिगोपन करने के लिए विशेष सस्थाओं का अभाव है, अतः परिस्थितिवश यह कार्य विचारे प्रबन्ध अभिकर्त्ता को ही करना पड़ता है; इसलिए इनकी इन सेवाओं के परिणामस्वरूप कम्पनी के अंश, ऋणपत्रादि शीघ्र विक्रय उन्हें पूँजी की प्राप्ति हो जाती है तथा जनता के निष्क्रिय धन का भी उद्योगों में सदुपयोग हो जाता है।

(७) प्रतिस्पर्धा का अन्त—एक ही प्रबन्ध अभिकर्त्ता के नियन्त्रण में रहने से कम्पनियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन हो जाता है, अतः उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे प्रबन्ध एवं व्यवस्था में मितव्ययिता आती है।

प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति के दोष—

उपरोक्त गुणों के होते हुए भी प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति को दोष रहित नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि इसके दोषों का उन्मूलन करने के लिए समय-समय पर कम्पनी अधिनियम में संशोधन किये गये एवं सन् १९५६ के कम्पनी अधिनियम में तो कायापलट ही कर दिया गया है। इस प्रणाली के प्रमुख दोष निम्नांकित हैं :—

(१) आर्थिक प्रभुत्व—प्रबन्ध अभिकर्ता पदवि में प्रायः मनो उद्योगी के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिफल की अपेक्षा आर्थिक प्रभुत्व की ही महत्ता दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि इन सस्याओं में मुख्यतः पूँजीपति ही होते हैं, जो नास्तिक योग्यता उनकी नहीं रखते जितनी कि आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। रोते हुए बच्चे को पुचकाने की भाँति ये लोग सकट की अवस्था में कम्पनी को केवल आर्थिक सहायता देकर उनमें पुनर्जीवन का संचार कर देने हैं, परन्तु उन कम्पनी की सच्ची प्रगति के लिए जिस तात्त्विक एवं व्यापारिक योग्यता की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति ये नहीं कर पाते। फलतः कम्पनी की व्यवस्था में अनेक दोष आ जाते हैं। इस आर्थिक प्रभुत्व का यह परिणाम होता है कि यदि किसी समय कम्पनी अर्थ-सकट के दलदल में फँस जाओ है और इन लोगों के पास भी पर्याप्त धन नहीं होता तो ऐसी कटकापूर्ण परिस्थितियों में प्रबन्ध अभिकर्ता अपने अधिकार दूसरे प्रबन्ध अभिकर्ताओं को, जिनके अच्छे आर्थिक साधन होते हैं, सौंपकर स्वयं अलग हो जाते हैं। ऐसा करते समय वे अशधारियों के हितों की लेशमात्र भी चिन्ता नहीं करते।

(२) अशों की अधिक परिकल्पना—इस प्रणाली के अनुसार अनेक स्कन्ध विपणियों में, विशेषकर बम्बई में कम्पनियों के अशों में अत्यधिक परिकल्पना (Speculation) पाई जाती है। ये लोग प्रायः कम्पनी या अशधारियों के हितों की ओर ध्यान न देते हुए सट्टेबाजी में व्यस्त हो जाते हैं। अपने हित के लिए कम्पनी के धन का बलि बड़ा देते हैं, जिससे कभी-कभी कम्पनी को महान् आर्थिक सङ्कट का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर अशों का मूल्य दिन पर दिन गिरने लगता है। यही नहीं, ये लोग एक प्रकार के अशों को दूसरे प्रकार के अशों में परिणत करके भी उनके मूल्यों को प्रभावित करते हैं। जिन अशों को वे स्वयं खरीदना चाहते हैं उन पर लाभालाभ की दर कम कर देने हैं, जिससे उनका मूल्य गिर जाये तथा गिरे हुए मूल्य पर वे उन्हें खरीद लें। इसके विपरीत जिन अशों को वे बेचना चाहते हैं उन पर लाभालाभ की दर बढ़ा देते हैं। इन दूषित कार्यवाहियों से विनि योक्ताओं को बड़ी हानि होती है।

(३) संचालकीय नियन्त्रण की शिथिलता—अभी तक संचालको की नियुक्ति में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है, अतः यद्यपि कम्पनी की व्यवस्था का समस्त भार संचालको पर ही होता है और उन्हीं को प्रबन्ध नीति का निर्धारण करना चाहिए, किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि संचालकगण कठपुतली की भाँति नाचते हैं और उनको नचाने वाले हैं परदे के पीछे कार्य करने वाले प्रबन्ध अभिकर्ता। नये अधिनियम में इस सम्बन्ध में काफी सुधार कर दिये गये हैं।

(४) अन्तर्विनियोग—प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने अपने नियन्त्रण के अन्तर्गत आधिक्य राशि को दूसरी कम्पनियों को ऋण देने में भी लगाया। यदि दोनों ही कम्पनियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तब तो इसमें कोई हानि नहीं थी, किन्तु विपरीत परिस्थिति में यदि अच्छी स्थिति की कम्पनी का कोष एक दुर्बल कम्पनी को

दे दिया जाय तो इससे अच्छी स्थिति वाली कम्पनी को हानि उठानी पड़ती है। नये अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्विनियोग पर रोक लगा दी गई है।

(५) अयोग्य व्यवस्था—प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के अन्तर्गत कौटुम्बिक अनुशासन के कारण व्यावसायिक सङ्गठन में स्थिरता आ जाती है। व्यवसाय में कार्य-कुशल व्यक्तियों का प्रवेश रुक जाता है। पिता के बाद पुत्र को, पुत्र के बाद प्रपौत्र को तथा इसी प्रकार अनेक प्रबन्ध अभिकर्ताओं को पौत्रिक अधिकार मिलते हैं। इससे यह आशङ्का रहती है कि पुत्र अथवा प्रपौत्र उत्तम कार्य-कुशल न हों जितने कि उनके पूर्वज थे।

(६) शोषण—प्रबन्ध अभिकर्ता विभिन्न ढङ्गों से कम्पनियों का शोषण करते रहते हैं। प्रथम तो, इन लोगों को कम्पनी की व्यवस्था सम्बन्धी समस्त आन्तरिक बातों का ज्ञान रहता है, जो कि अशधारियों को नहीं होता अतः वे आन्तरिक व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि जिससे केवल इनको ही लाभ होता है, अन्य अशधारियों को तो उसकी हवा भी नहीं लगती। अपने स्वार्थ को मिट्ट करके के लिए ही वे लाभांश की दर कम या अधिक करते रहते हैं। दूसरे, प्रबन्ध अभिकर्ता अपने पारिश्रमिक के लिये जो अनुबन्ध करते हैं वे अनुचित एवं न्याय विरुद्ध होने हैं। ये निम्न प्रकार के विभिन्न रूपों में पारिश्रमिक लेते रहते हैं—व्यक्तिगत भत्ता, उत्पादन पर कमीशन, बच्चे माल के क्रय पर कमीशन, निर्मित माल के विक्रय पर कमीशन, लाभ पर कमीशन, अन्य विशेष कमीशन तथा कार्यालय भत्ता आदि। इन प्रकार कम्पनी के लाभ का एक बहुत बड़ा भाग, जिसे 'शेर का भाग' (Lion's Share) कह सकते हैं, प्रबन्ध अभिकर्ताओं की जेब में जाता है एवं झूठ-जाठन बिचारे अशधारियों को जाती है। तीसरे, कभी-कभी ये लोग कम्पनी के धन को व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं। चाल लेखे (Current A/c) की चाल द्वारा ये लोग कम्पनी का धन पर्याप्त मात्रा में ऋण लेकर अपना काम चलाया करते हैं। चौथे, प्रबन्ध अभिकर्ता बहुधा कम्पनी के लाभ को लाभांशों के रूप में वितरण न करके कम्पनी के कार्यों में लगा देते हैं और अन्य लोगों को दिखाने के लिए कम्पनी की कार्यशीलता बढ जाती है। कभी कभी भवन निर्माण और मशीनरी के क्रय में रुपया लगा देते हैं। यह विस्तार चाहे अनुचित भले ही हो, किन्तु ये कार्यक्षमता का आडम्बर करने के लिए ऐसी रचना करते रहते हैं।

(७) ऋण का ऋणपत्रों में परिवर्तन—किन्हीं किन्हीं प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने अपने दिए हुए ऋण को ऋण पत्रों में परिवर्तित कर लिया और इस प्रकार समस्याएँ उनके हाथ में पहुँच गईं। बिचारे अशधारियों की वह पूँजी जो उन्होंने कम्पनी में लगाई थी, उनके हाथ में चली गई।

(८) नए प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साधनों व उनकी योग्यता में कमी—कम्पनियों की सख्या में लगातार वृद्धि से प्रबन्ध अभिकर्ताओं की सख्या में भी बरसानी नदी के पानी की भाँति वृद्धि होने लगी है। नए प्रबन्ध अभिकर्ता यह पुरानो

की भांति अनुभवी, योग्य और साधन सम्पन्न भी नहीं है, जो सुन्दर सेवार्य कर सक, जैसे कि इस पद्धति के अन्तगम अब तक होनी रही है।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Define the term 'Managing Agent' and differentiate between 'Manager' and 'Managing Agent' 'Briefly describe the functions of a managing agent in the running of joint stock company
- 2 Write a lucid note on the origin of Managing Agency system in India, pointing out the circumstances which have given a fillip to this institution in this country
- 3 Discuss the merits and defects of the managing agency system of organisation and control of a joint stock company.

अध्याय ५१

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली

(वर्तमान स्थिति एवं भविष्य)

(Managing Agency System—Present Position & Future)

भूमिका—

प्रबन्ध अभिकर्ताओं की वर्तमान स्थिति का अनुमान कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ के नये आदेशों से लगाया जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय में प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्धित आदेशों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ के आदेश

प्रबन्ध अभिकर्ता की परिभाषा—

‘प्रबन्ध अभिकर्ता’ से आशय उस व्यक्ति, फर्म या समामेलित सस्था से है, जो किसी कम्पनी के साथ हुए ठहराव या उसके पार्यद सीमानियम अथवा अन्तनियमों के अन्तर्गत कम्पनी के सम्पूर्ण या अधिकांश कार्यों के प्रबन्ध करने का इस अधिनियम के प्रादेशों के अधीन अधिकारी है। प्रबन्ध अभिकर्ता संचालक-सभा के प्रशासनिक नियन्त्रण तथा निरीक्षण के अधीन कार्य करता है।

प्रबन्धक तथा प्रबन्ध-अभिकर्ता में अन्तर—

प्रबन्धक तथा प्रबन्ध-अभिकर्ता दोनों ही कम्पनी के सम्पूर्ण अथवा लगभग सम्पूर्ण कार्यों के प्रबन्ध के लिए अधिकृत होते हैं और ये दोनों ही संचालक सभा के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं निरीक्षण के अधीन कार्य करते हैं। फिर भी एक प्रबन्धक निम्नलिखित बातों में प्रबन्ध अभिकर्ता से भिन्न होता है —

क्रम संख्या	अन्तर का आधार	प्रबन्धक	प्रबन्ध अभिकर्ता
(१)	रूप	प्रबन्धक एक व्यक्ति होता है।	प्रबन्ध अभिकर्ता एक व्यक्ति फर्म या कम्पनी भी हो सकती है।
(२)	नियुक्ति	प्रबन्धक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उसकी नियुक्ति किसी सेवा सम्बन्धी अनुबंध के अन्तर्गत ही हो।	प्रबन्ध अभिकर्ता सदैव ही कम्पनी के साथ एक औपचारिक अनुबन्ध के अधीन सेवा करता है।
(३)	पारिश्रमिक	प्रबन्धक का दिया जाने वाला अधिकतम पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के ५% तक सीमित है।	प्रबन्ध अभिकर्ता को कम्पनी के शुद्ध लाभ के १०% तक पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति, पद से हटाना, हस्तांतरण आदि

(I) प्रबन्ध अभिकर्ता को नियुक्ति—

प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं :—

(१) केन्द्रीय सरकार को यह घोषित करने का अधिकार है कि भ्रमुक तिथि से भ्रमुक वर्ग के उद्योग या व्यापार में पूर्णतः या अंशतः संलग्न कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकर्ता न हो सकेंगे तथा उस विशेष श्रेणी के उद्योग अथवा व्यापार में संलग्न किसी कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता का कार्य-काल उक्त निर्दिष्ट तिथि से ३ वर्ष के अन्त होने पर या १५ अप्रैल सन् १९६०, दोनों में से जो भी तिथि बाद में पड़े, समाप्त हो जावेगी और घोषित उद्योग अथवा व्यवसाय में संलग्न कम्पनी द्वारा बाद में किसी प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकेगी ।

(२) कोई भी प्रबन्ध अभिकर्ताओं की कम्पनी स्वयं अपने लिए कोई प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकती । इसी प्रकार एक ऐसी कम्पनी जिसका कोई प्रबन्ध अभिकर्ता है, किसी अन्य कम्पनी की प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं बन सकती ।

(३) अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में, जिनको उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होने प्रबन्ध अभिकर्ता तभी नियुक्त या पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं जबकि कम्पनी साधारण सभा में प्रस्ताव पास करे और केन्द्रीय सरकार ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए सहमति प्रदान करे । केन्द्रीय सरकार तभी अपनी सहमति प्रदान करेगी जबकि वह निम्न विषयों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो जाय :—

(अ) कि कम्पनी को प्रबन्ध-अभिकर्ता रखने की आज्ञा देना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध न होगा ।

(आ) कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता एक उपयुक्त व्यक्ति है और प्रबन्ध अभिकर्तत्त्व को शर्त भी उचित तथा न्यायपूर्ण हैं ।

(इ) कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता उन शर्तों को पूरा करता है जो कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है ।

(४) प्रबन्ध-अभिकर्ता का कार्यक्रम—इस अधिनियम का आरम्भ होने के पश्चात् कोई कम्पनी (यदि वह पहली बार अपना मैनेजिंग एजेंट नियुक्त कर रही है) १५ वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त न कर सकेगी ।* अन्य किसी दशा में मैनेजिंग एजेंट को एक समय पर १० वर्ष से अधिक के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता । नई अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति तभी की जा सकती है जब चातुर्य कार्य काल २ वर्ष से कम रह गया हो । हाँ, यदि केन्द्रीय सरकार कम्पनी के हित में आवश्यक समझे तो इससे पहले भी वह पुनर्नियुक्ति की आज्ञा दे सकती है । यदि इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता तो सम्पूर्ण अवधि के लिए ही वह नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति अवैध होगी ।

(५) केन्द्रीय सरकार को पूर्व अनुमति लेकर मैनेजिंग एजेंटों के अनुबन्ध की शर्तों को साधारण सभा में कम्पनी द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है ।

* कम्पनी कानून सलाहकार आयोग की सलाह पर सरकार ने यह तय किया है कि मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी या खजांची को पहली नियुक्ति १० साल की और पुनर्नियुक्ति ५ साल की होनी चाहिये । (नवभारत टाइम्स, अक्टूबर सन् १९५६)

(६) विद्यमान मैनेजिंग एजेन्सीज के बारे में कम्पनी अधिनियम के निम्न आदेश हैं—

(अ) इस अधिनियम का प्रचलन होने पर यदि किसी कम्पनी के कोई मैनेजिंग एजेन्ट हैं तो उनका कार्य काल (यदि वह पहले ही समाप्त न हो जाय) १५ अगस्त सन् १९६० तक समाप्त हो जायगा । हाँ, इस अधिनियम के अन्तर बताये गये नियमों के अनुसार उनको नई अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है ।

(आ) मैनेजिंग एजेन्ट के कार्य-काल सम्बन्धी आदेशों को छोड़कर इस अधिनियम के अन्य सभी आदेश उनको तत्कालिक रूप से लागू होंगे ।

(II) मैनेजिंग एजेन्सी की सहाय पर प्रतिबन्ध—

१५ अगस्त सन् १९६० के पश्चात् कोई व्यक्ति एक समय में १० से अधिक कम्पनियों का मैनेजिंग एजेन्ट नहीं रह सकता । यदि कोई व्यक्ति इस विधि के पहले सक्त आदेश की पूर्ति नहीं करता तो केन्द्रीय सरकार उसका रजिस्ट्रार उन १० कम्पनियों का मैनेजिंग एजेन्ट रहने दे सकती है जिन्हें वह (केन्द्रीय सरकार) निर्धारित करे । कोई व्यक्ति कितनी कम्पनियों का मैनेजिंग एजेन्ट रह सकता है, इसकी गणना करते समय निम्न को छोड़ दिया जायगा—

(१) एक प्राइवेट कम्पनी, जो किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक या भूतधारि कम्पनी नहीं है ।

(२) एक असंमित दायित्व वाली कम्पनी ।

(३) वह सद्य जो लाभ के लिए व्यापार नहीं करता या लाभार्थ के भुगतान का विषय करता है ।

उपरोक्त आशय के लिए निम्न प्रत्येक व्यक्ति कम्पनी का मैनेजिंग एजेन्ट गिना जायगा :—

(१) जबकि कम्पनी की मैनेजिंग एजेन्ट कोई फर्म है तो फर्म का प्रत्येक साझेदार ।

(२) जबकि कम्पनी की मैनेजिंग एजेन्ट कोई कम्पनी है तो उसका प्रत्येक संचालक, सेक्रेटरी एवं बोधार्थक या मैनेजर तथा प्रत्येक सदस्य, जिसकी २०% मताधिकार या नियन्त्रण प्राप्त है ।

यदि कोई व्यक्ति इस धारा के आदेशों की अवहेलना करता है, अर्थात् १० से अधिक कम्पनियों का मैनेजिंग एजेन्ट बना रहता है तो वह प्रत्येक अधिक कम्पनी के लिए प्रति दिन १,०००) तक के अर्थ दण्ड का भागी होगा ।

(III) प्रबन्ध अधिकर्ता के पद का रिक्त होना—

निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रबन्ध अधिकर्ता का पद खाली (Vacated) समझा जायगा :—

(१) यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता कोई व्यक्ति है तो उसके दिवालिया होने पर अथवा दिवालिया घोषित होने का प्रार्थना-पत्र देने पर ।

(२) यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता कोई फर्म है तो उसके किसी भी कारण से भेग होने पर ।

(३) यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता कोई कम्पनी है तो उसके समापन की कार्यवाही आरम्भ होने पर ।

(४) प्रबन्ध अभिकर्त्ता द्वारा प्रबन्धित कम्पनी के समापन की कार्यवाही आरम्भ होने पर ।

(५) यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता की सम्पत्ति का किसी न्यायालय द्वारा या उसके लेनदारों द्वारा या उनकी ओर से कोई गिस्तीबर नियुक्त कर दिया जाय तो वह कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद से मुश्तल (Suspend) समझा जायेगा । हाँ, यदि न्यायालय उसे कार्य करले रहने की आज्ञा दे दे तो बात दूसरी है, किन्तु न्यायालय किसी भी समय अपनी आज्ञा को बदल सकता है या रह कर सकता है ।

(६) यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता (अथवा मैनेजिंग एजेन्सी फर्म का कोई साझेदार या मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनी का कोई सचालक या पदाधिकारी) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तथा कम से कम ६ माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड दे दिया जाता है तो प्रबन्ध अभिकर्त्ता का पद खाली समझा जायगा । यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने दोषी साझेदार, सचालक या अधिकारी को सजा की तिथि से ३० दिन के भीतर निकाल दे, तो उसकी अव्ययता दूर हो जायगी ।

(IV) प्रबन्ध अभिकर्त्ता को पदच्युत करना—

किसी कम्पनी की साधारण सभा एक साधारण प्रस्ताव द्वारा अपने प्रबन्ध अभिकर्त्ता को निम्न कारणों पर पदच्युत (Remove) कर सकती है :—

(१) कम्पनी अथवा इसकी सहायक या सूत्रधारी कम्पनी के मामलों के सम्बन्ध में कपट या प्रत्यास-भङ्ग (Fraud or Breach of Trust) के लिए ।

(२) किसी दूसरी कम्पनी के मामलों के सम्बन्ध में कपट अथवा प्रत्यास-भङ्ग करने के लिये, जबकि ऐसा आरोप किसी न्यायालय में प्रमाणित कर दिया गया हो ।

(३) यदि प्रबन्ध अभिकर्त्ता कोई फर्म या कम्पनी है तो फर्म के किसी साझेदार, सचालक या गुप्तार-ग्राम का अधिकार रखने वाले किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपने या अपनी सहायक अथवा सूत्रधारी कम्पनी के कार्यों में कपट या प्रत्यास-भङ्ग के लिए ।

(४) साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा एक कम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्त्ता को अपने या अपनी सहायक कम्पनियों के कार्यों में उसकी किसी बड़ी लापरवाही (Gross Negligence) के लिये हटा सकती है । कपट, प्रत्यास-भङ्ग

अथवा अत्यधिक सापरवाही के लिये किसी मैनेजिंग एजेंट को पद से हटाने के हेतु कम्पनी की साधारण सभा (यदि इस अधिनियम अथवा अन्तर्नियमों में कोई विपरीत आदेश नहीं है) कम्पनी के किन्हीं दो सचालकों द्वारा बुलाई जा सकती है । प्रस्ताव की सूचना मिलने पर कम्पनी उसकी एक प्रति मैनेजिंग एजेंट को भेजगी । सचालकों की प्रति मैनेजिंग एजेंट को भी यह अधिकार होगा कि वह कम्पनी को उसका लिखित उत्तर दे, उत्तर को मीटिंग में पढ़वाये तथा अपनी वान समझाये ।

(V) मैनेजिंग एजेंट का पद से त्याग-पत्र देना—

यदि मैनेजिंग एजेंट के ठहराव में विपरीत आशय या कोई नियम न हो तो मैनेजिंग एजेंट सचालक सभा को सूचना देकर उसमें दी गई तिथि से त्याग पत्र दे सकता है । ऐसी दशा में मैनेजिंग एजेंट इस प्रकार निर्दिष्ट की गई तिथि से या किसी अन्य बाद की तिथि से (जो परस्पर ठहर जाये) कार्य करना बन्द कर देगा, किन्तु उसका त्याग पत्र तभी प्रभावपूर्ण होगा जब सचालक सभा कम्पनी के अग्निम खाते बनवा ले उन पर अकेलक की रिपोर्टें प्राप्त कर ले अकेलित अन्तिम खाते साधारण सभा में कम्पनी के सामने रख दे और कम्पनी उन्हें स्वीकार कर ले अथवा उनके सम्बन्ध में किसी अन्य कार्यवाही को करने का निश्चय करे ।

(VI) मैनेजिंग एजेंट द्वारा पद का हस्तांतरण—

कोई मैनेजिंग एजेंट अपने पद का तभी हस्तांतरण कर सकता है जबकि कम्पनी की साधारण सभा और केन्द्रीय सरकार दोनों ही की अनुमति प्राप्त हो जाये ।

(VII) मैनेजिंग एजेंट का पद पैतृक (Heritable) नहीं है—

इस अधिनियम का प्रचलन होने के बाद किसी कम्पनी द्वारा अपने मैनेजिंग एजेंट से किया गया कोई ठहराव, जिसमें पद को विरासत द्वारा हस्तांतरित करने की वान हा, व्यर्थ होगा । यदि अधिनियम का प्रचलन होने पर कोई व्यक्ति किसी कम्पनी के मैनेजिंग एजेंट पद पर आसीन है और मैनेजिंग एजेंटों के ठहराव पद के विरासत द्वारा हस्तान्तरित होने का आयोजन करता हो तो इस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् कोई अन्य व्यक्ति विरासत से पद तभी ग्रहण कर सकता है जब इसके लिये केन्द्रीय सरकार यह आज्ञा दे और केन्द्रीय सरकार आज्ञा तभी देगी जब उसकी सम्मति में वह व्यक्ति कम्पनी के मैनेजिंग एजेंट का पद सभालने के उपयुक्त है । ये बातें एक प्राइवेट कम्पनी को, जो किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक नहीं है, लागू नहीं होंगी ।

(VIII) मैनेजिंग एजेंटों फर्म या कॉरपोरेशन के सङ्गठन से परिवर्तन—

इस अधिनियम में किसी विपरीत आशय वाले नियम के अभाव में जब किसी पब्लिक कम्पनी या इसकी सहायक प्राइवेट कम्पनी का मैनेजिंग एजेंट एक फर्म या कम्पनी है और इसके सङ्गठन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो मैनेजिंग एजेंट अपने पद पर इस परिवर्तन की तिथि से ६ महीने अथवा इस आशय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाई गई प्राप्ति की समाप्ति में कार्य करना बन्द कर देगा, यदि केन्द्रीय सरकार ऐसे परिवर्तन के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करती ।

प्रबन्ध अभिकर्ता के अधिकार

सन्निधिम ने पारिश्रमिक पर प्रतिबन्धों तथा आचरण सम्बन्धी कड़े नियमों के अतिरिक्त प्रबन्ध अभिकर्ता के अधिकारों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। भले ही वर्तमान अधिनियम के प्रभावशाली होने के पहले प्रबन्धित कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रबन्ध अभिकर्ता के अधिकारों की कुछ भी स्थिति रही हो, १ अप्रैल सन् १९५६ के पश्चात् तो वे अपने अधिकारों का प्रयोग केवल सचालक-सभा के नियन्त्रण तथा निर्देशन से और कम्पनी के सीमानियम तथा अन्तर्नियमों के आधीन और कम्पनी अधिनियम में वर्णित प्रतिबन्धों के आधीन ही कर सकेंगे।

कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक प्रबन्ध-अभिकर्ता सचालक-सभा की पूर्ण स्वीकृति के बिना निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता :—

- (१) किसी व्यक्ति को कम्पनी का प्रबन्धक नियुक्त करना।
- (२) अपने किसी सम्बन्धी को कर्मचारी नियुक्त करना।
- (३) किसी कर्मचारी का सभा द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्त करना।
- (४) ऐसी परिस्थितियों के अतिरिक्त जो कि सचालक-सभा द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर है, पूँजीगत सम्पत्ति का क्रय या विक्रय करना।
- (५) अपने विरुद्ध कम्पनी के किसी दावे की रकम को कम करना या इसके भुगतान के लिये अवधि बढ़ाना।
- (६) अपने या अपने सहयोगियों द्वारा कम्पनी के विरुद्ध किये गये किसी दावे में समझौता करना।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं की क्रियाओं पर प्रतिबन्ध

निम्नलिखित कुछ ऐसे आय कार्य हैं जिनके दोषों के कारण प्रबन्ध-अभिकर्ता पद्धति की बड़ी आलोचना की गई है। अब इन कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, जिससे उनमें विद्यमान दुबलापन दूर हो जायें और दोष उत्पन्न होने की सम्भावनायें कम से कम रह जायें।

(I) प्रबन्ध अभिकर्ता को ऋण—

प्रबन्ध अभिकर्ताओं की क्रियाओं पर १० प्रमुख प्रतिबन्ध

- (१) प्रबन्ध अभिकर्ता को ऋण ।
- (२) एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत कम्पनियों को ऋण ।
- (३) अन्य कम्पनियों के शेयर आदि खरीदना ।
- (४) प्रतिस्पर्धी व्यापार करने पर रोक ।
- (५) कम्पनी के पुनर्संज्जटन या संयुक्तिकरण का विरोध ।
- (६) संचालकों की नियुक्ति करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध ।
- (७) विक्रय प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्ति ।
- (८) क्रय प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्ति ।
- (९) अन्य सस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति ।
- (१०) कम्पनी में क्रय विक्रय का अनुबन्ध ।

कोई पब्लिक कम्पनी एवं इसकी सहायक प्राइवेट कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्न की या निम्न के द्वारा दिये गये ऋण, या ऋण की गारन्टी अथवा प्रतिभूति नहीं दे सकती :—

(अ) प्रबन्ध अभिकर्ता या इनका सहयोगी, अथवा ।

(ब) कोई भी समामेलित सस्था, जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक एवदेश द्वारा यह धाखिन कर दिया है कि उसका संचालक मण्डल, प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध संचालक, सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष अथवा मैनेजर, प्रबन्ध अभिकर्ता या इसके सहयोगी के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, भले ही उक्त समामेलित सस्था स्वयं प्रबन्ध अभिकर्ता की सहयोगी न हो । [धारा ३६६(१)]

यह उल्लेखनीय है कि उक्त धारा उस साख पर लागू नहीं होती जो कि कम्पनी द्वारा अपने प्रबन्ध अभिकर्ता को कम्पनी का व्यापार चलाने की सुविधा के लिये दी जाती है तथा ऐसे अभिकर्ता द्वारा अपने ही नाम में खुले हुए एक या कई खातों में रखी जाती है । हाँ, इस प्रकार की साख संचालकों द्वारा पूर्ण स्वीकृत सीमाओं से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा कभी भी वह कुल मिलाकर २०,००० से अधिक नहीं हो सकती । इसी प्रकार यह धारा एक सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक को दिये जाने वाले ऋण पर भी लागू नहीं होती । [धारा ३६६(२)]

(II) एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत कम्पनियों को ऋण—

कोई भी कम्पनी (जिसे इस धारा में ऋणदाता कम्पनी (Lending Company) कहा गया है) किसी समामेलित सस्था (जो कि उसी प्रबन्ध के अन्तर्गत चलाई जा रही है जिसमें कि ऋणदाता कम्पनी चल रही है) को न तो कोई ऋण देगी और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उमे दिये गये ऋण के सम्बन्ध में कोई गारन्टी या प्रतिभूति प्रदान करेगी, जब तक कि ऋणदाता कम्पनी के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा

इसकी पूर्व अनुमति न हो । यदि उक्त समामेलित संस्था किसी अन्य व्यक्ति को कुछ ऋण दे, तो ऋणदाता कम्पनी उसकी प्रतिभूति की गारन्टी भी न दे सकेगी ।

[धारा ३७०(१)]

जब कोई ऋणदाता कम्पनी किसी फर्म को, जिसमें समान प्रबन्ध वाली कोई समामेलित संस्था पार्टनर है, कुछ ऋण देती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस फर्म को अथवा उक्त फर्म द्वारा उस अन्य व्यक्ति को दिये गये ऋण की गारन्टी या प्रतिभूति देती है तो यह ऋण (गारन्टी अथवा प्रतिभूति) समान प्रबन्ध वाली समामेलित संस्था को ही दिया गया माना जावेगा ।

[धारा ३७० I A]

दो समामेलित संस्थाओं को एक ही अथवा समान प्रबन्ध के अन्तर्गत तब समझा जायगा जबकि (१) उनमें से एक संस्था का प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध सचालक या मैनेजर अथवा जबकि प्रबन्ध अभिकर्ता एक फर्म हो तो उस फर्म का कोई पार्टनर अथवा जबकि प्रबन्ध अभिकर्ता एक प्राइवेट कम्पनी हो तो उस कम्पनी का कोई सचालक दूसरी संस्था में (१) प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध सचालक या मैनेजर है, अथवा (११) दूसरी संस्था की प्रबन्ध अभिकर्ता का कार्य करने वाली फर्म में एक पार्टनर है; अथवा (१११) दूसरी संस्था की प्रबन्ध अभिकर्ता का कार्य करने वाली प्राइवेट कम्पनी में एक सचालक है, अथवा (२) एक संस्था के बहुमत सचालक अब या अब से तरकाल ६ माह पूर्व दूसरी संस्था के भी बहुमत सचालक हैं, अथवा (३) दोनों संस्थाओं में किसी भी मामले के सम्बन्ध में कुल मतदान शक्ति का कम से कम ३ भाग एक ही व्यक्ति या समामेलित संस्था के पास या उनके नियंत्रण में है, अथवा (४) यदि एक समामेलित संस्था की सूत्रधारों कम्पनी उस प्रबन्ध में है जिसमें कि दूसरी समामेलित संस्था है ।

[धारा ३७०, स्पष्टीकरण I B]

धारा ३७० उस ऋण, प्रतिभूति या गारन्टी को लागू नहीं होती जो कि किसी सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक को अथवा, प्रबन्ध अभिकर्ता या सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष द्वारा अपने ही प्रबन्ध के अन्तर्गत किसी कम्पनी को या एक बैंकिंग कम्पनी द्वारा अपने कारोबार की समान प्रगति में दिया जाय ।

यदि कोई ऋण (गारन्टी या प्रतिभूति) इस अधिनियम का चलन प्रारम्भ होने के पूर्व ही दिया हुआ था तो उसे इस अधिनियम के लागू होने के ६ माह के अन्दर वापस ले लेना चाहिये, भले ही विपरीत आशय का ठहराव हुआ था । इस अवधि की केन्द्रीय सरकार द्वारा एवं कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा बढ़ाया जा सकता है ।

यदि कोई ऋण, प्रतिभूति या गारन्टी धारा ३६६ अथवा धारा ३७० के आदेशों के विरुद्ध दी गई हो तो दोषी व्यक्ति को (उस व्यक्ति को भी जिसके हित में यह ऋण, गारन्टी या प्रतिभूति दी गई है, ५,०००) तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है अथवा ६ माह तक की सजा भी हो सकती है । यदि उक्त ऋण, गारन्टी या प्रतिभूति का निष्पादन हो गया है, तो उस धारा के अन्तर्गत सजा नहीं दी जा सकती और यदि आशिक निष्पादन हुआ है तो सजा भी अनुपातित कम हो जावेगी । सभी व्यक्ति जिन्होंने

दोष में भाग लिया है, संयुक्त एवं प्रथक रूप से ऋण की वापसी के लिए अथवा गारन्टी या प्रतिभूति देने से हुई हानि की पूर्ति के लिये कम्पनी के प्रति दायी होंगे।

[धारा ३७१]

(III) अन्य कम्पनियों के शेयर आदि खरीदना —

एक कम्पनी (जिसे इस धारा में और अगली धारा ३७३ में विनियोग करने वाली कम्पनी Investing Company कहा गया है) किसी अन्य समामेलित सस्था में शेयरों को केवल उनी सीमा तक तथा उन प्रतिबन्धों व शर्तों के अधीन जो कि नीचे बताई गई है, खरीद सकती है, [धारा ३७१] :—

- (१) विनियोग करने वाली कम्पनी का संचालक मण्डल किसी अन्य समामेलित सस्था के शेयरों में उस अन्य समामेलित सस्था की प्राधिकृत पूंजी (subscribed capital) के १०% तक विनियोग कर सकता है। लेकिन सभी अन्य समामेलित सस्थाओं में इस प्रकार किया गया कुल विनियोग, विनियोग करने वाली कम्पनी के ३०% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (२) यदि उक्त सीमा से अधिक विनियोग करना हो, तो इसके लिए विनियोग करने वाली कम्पनी को साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास करना होगा तथा केन्द्रीय सरकार से भी सहमति लेनी होगी।
- (३) विनियोक्ता कम्पनी किसी भी समय किसी भी रकम तक शेयर खरीद सकती है, जो कि उसे धारा ८१ (१) (a) के अन्तर्गत सौंपे जायें। इन शेयरों को Rights Shares कहा जाता है।
- (४) जब विनियोक्ता कम्पनी किसी समय Rights Shares के अतिरिक्त अन्य शेयरों में कोई विनियोग करना चाहे तो उपरोक्त प्रतिशतों की गणना करने में उस समय तक Rights Shares में यदि कोई हो, किए गये सभी विद्यमान विनियोग सम्मिलित किये जायेंगे।
- (५) संचालक मण्डल सभी विनियोग कर सकता है जबकि सभी संचालकों की सहमति से (जो कि सभा में उपस्थित हो और वोट देने के अधिकारी हों) एक प्रस्ताव पास हो जाय और इस प्रकार का प्रस्ताव रखे जाने की सूचना प्रत्येक संचालक को धारा २८६ में वर्णित विधि से दे दी गई है।

प्रत्येक विनियोक्ता कम्पनी समामेलित सस्थाओं के शेयरों में अपने द्वारा किए गए सभी विनियोगों का रजिस्टर रखेगी और उसमें समामेलित सस्था का नाम, विनियोग करने की तिथि, जहाँ उक्त समामेलित सस्था विनियोक्ता कम्पनी के ही ग्रुप में है, वह तिथि भी जब कि वह ग्रुप में सम्मिलित हुई तथा अन्य सब समामेलित सस्थाओं के नाम जो कि उसी ग्रुप में दिखाने चाहिए। विनियोग का विवरण उनकी तिथि के ७ दिन के अन्दर ही नाट हो जाना चाहिए। यदि विनियोग कम्पनी सहायक अधि-

नियम सन् १९६० के पूर्व किए गए थे, तो इस अधिनियम के लागू होने के ६ माह के प्रन्दर (जिसकी अवधि केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी की प्रार्थना पर बढ़ाई जा सकती है) ही उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज कर लेना चाहिए ।

इस धारा के आदेशों का उल्लङ्घन करने पर कम्पनी तथा कम्पनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को ५०० रु० तक का दण्ड दिया जा सकता है । दोष का सर्वप्रथम पता लगने पर भी यदि वह जारी रहे, तो ५० रु० प्रति दिन तक जुर्माना किया जा सकता है ।

यह धारा एक बैंकिंग प्रयत्न बोमा कम्पनी को, एक प्राइवेट कम्पनी को, जो कि पब्लिक कम्पनी की सहायक नहीं है, फाइनेन्सिंग कम्पनी व सूत्रकारी कम्पनी को (उसकी सहायक कम्पनी के सम्बन्ध में) लागू न होगी ।

(IV) प्रतिस्पर्धी व्यापार करने पर रोक—

कोई प्रबन्ध अभिकर्ता अपने लाभार्थ ऐसे किसी व्यापार में सलग्न नहीं हो सकता जिसकी प्रकृति उसकी कम्पनी के (जिसका वह प्रबन्ध अभिकर्ता है) सहायक ऐसी कम्पनी की किसी सहायक कम्पनी के व्यापार के समान है और उससे प्रतिस्पर्धा करने वाला है । यदि वह ऐसा करता है तो इससे अर्जित समस्त लाभ वह उस कम्पनी के लिए ट्रस्ट में रखेगा ।

— उक्त आशय के लिए निम्नलिखित दशांशों में मैनेजिंग एजेंट की अपने लाभार्थ व्यापार में सलग्न समझा जायगा :—

(१) यदि ऐसा व्यापार किसी फर्म द्वारा, जिसमें वह साझेदार है, चलाया जाता है ।

(२) यदि ऐसा व्यापार एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा चलाया जाता है, जिसकी किसी साधारण सभा में निम्नलिखित एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा (मिला कर) कुल मतधिकार के कम से कम २०% पर नियन्त्रण हो :—

(अ) उक्त प्रबन्ध अभिकर्ता ।

(आ) यदि प्रबन्ध अभिकर्ता एक फर्म है तो उस फर्म का कोई साझेदार ।

(इ) यदि प्रबन्ध अभिकर्ता एक समामेलित संस्था है तो उसका कोई अधिकारी ।

(३) यदि व्यापार एक समामेलित संस्था द्वारा, (जो एक प्राइवेट कम्पनी नहीं है) चलाया जाता है, जिसकी किसी साधारण सभा में निम्नलिखित किसी एक (व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा मिल कर) का कुल मतधिकारों के कम से कम २०% पर नियन्त्रण हो :—

(अ) उक्त प्रबन्ध अभिकर्ता ।

(आ) यदि प्रबन्ध अभिकर्ता एक फर्म है तो उसका कोई साझेदार ।

(३) यदि प्रबन्ध अभिकर्ता एक समामेलित संस्था है तो उसका कोई अधिकारी ।

(V) कम्पनी के पुनर्संज्जठन या संयुक्तीकरण का नियम—

यदि कम्पनी के पाषाण सीमानियम अथवा अन्तनियमों में या कम्पनी द्वारा साधारण अथवा संचालक सभा द्वारा पास किये किसी प्रस्ताव में अथवा कम्पनी और उसके प्रबन्ध अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य हुए किसी ठहराव में कोई ऐसा आयोजन हो कि कम्पनी का पुनर्संज्जठन या संयुक्तीकरण तभी हो सकता है जबकि वह प्रबन्ध अभिकर्ता ही पुनर्संज्जठित कम्पनी या संयुक्तीकरण के परिणामस्वरूप बनी नई कम्पनी का प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त किया जाये तो ऐसा आयोजन इस प्राविनियम का चलन होने के बाद से ध्येय होगा ।

(VI) संचालकों को नियुक्ति करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध—

यदि कम्पनी के अन्तनियम प्राज्ञा दें तो प्रबन्ध अभिकर्ता अधिक से अधिक दो (यदि संचालकों की कुल संख्या ५ से अधिक है) नियुक्त कर सकता है । यदि संचालकों की संख्या ५ से कम है तो वह केवल एक ही संचालक नियुक्त कर सकेगा । अपने नियुक्त किये संचालक को प्रबन्ध अभिकर्ता चाहे जब हटा सकता है या उसका पद खाली होने पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ।

(VII) प्रबन्ध अभिकर्ता की एक विक्रय-प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति—

प्रबन्ध अभिकर्तात्वं प्रणाली का एक दोष यह भी रहा है कि प्रबन्ध अभिकर्ता अपनी कम्पनी के लिए माल के क्रय अथवा विक्रय के एजेंट बन जाया करते थे और इन पर कमीशन वसूल करते थे । अब इस दिशा में भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । अब किसी प्रबन्ध अभिकर्ता या उसके किसी सहयोगी को कम्पनी के माल को बेचने के सम्बन्ध में कोई कमीशन या पुरस्कार पाने का अधिकार नहीं होगा । हाँ, भारत के बाहर किसी स्थान से की गई बिक्री के सम्बन्ध में प्रबन्ध अभिकर्ता या उसके सहयोगी को निम्न दो शर्तों के अधीन विक्रय प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सकता है :—(१) उनका ऐसे स्थान पर निजी व्यापार के लिए कोई कार्यालय हो । (२) उनका बिक्री कमीशन इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा पास किये गये विशेष प्रस्ताव के अनुसार हो । यह नियुक्ति पाँच वर्ष से अधिक के लिए नहीं की जा सकती । हाँ, बाद में उसका नव-करण किया जा सकता है ।

(VIII) क्रय प्रतिनिधि के रूप में मैनेजिंग एजेंट की नियुक्ति—

किसी मैनेजिंग एजेंट या उसके किसी सहयोगी को कम्पनी से उसकी ओर से भारत में खरीद गये माल के सम्बन्ध में कोई कमीशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा । हाँ, कार्यालय भत्ते के बदले में मिलने वाले खर्च तो उनको मिलेंगे ही, किन्तु भारत के बाहर किसी स्थान से मैनेजिंग एजेंट या उसके सहयोगी द्वारा कम्पनी की ओर से खरीदे गये माल के सम्बन्ध में कम्पनी की इच्छा पर मैनेजिंग एजेंट या

सहयोगी को या तो उसके कार्यालय का खरीद सम्बन्धी खर्च या कमोशन दिया जा सकता है। हाँ, शर्त यह है कि उक्त कार्यालय मैनेजिंग एजेंट के व्यक्तिगत व्यापार के लिए होना चाहिए। कम्पनी अपने विशेष प्रस्ताव में इस भुगतान की सीमा निश्चय कर देगी। नियुक्ति का यह विशेष प्रस्ताव तीन वर्ष से अधिक के लिए न होगा। बाद में उसका नवकरण कराया जा सकता है।

(IX) अन्य संस्थाओं के क्रय अथवा बिक्री प्रतिनिधि के रूप में कमोशन—

कभी-कभी यह होना है कि एक ही प्रबन्ध अभिकर्ता के आधीन दो कम्पनियाँ परस्पर सेवा या माल का क्रय-विक्रय करती हैं। ऐसी दशा में एक कम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्ता को दूसरी कम्पनी से उस क्रय-विक्रय के लिए प्राप्त कमोशन को रखने की अनुमति दे सकती है। इसके लिए कम्पनी को अपनी साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। यह आवश्यक है कि उक्त क्रय-विक्रय की दरें कम्पनी के लिए बाजार दरों से या उचित दरों से कम अनुकूल न हों।

(X) प्रबन्ध अभिकर्ता और कम्पनी के मध्य क्रय-विक्रय का अनुबन्ध—

एक कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने प्रबन्ध अभिकर्ता या उसके सहयोगी के साथ किसी अचल या चल जायदाद के खरीदने, बेचने या सप्लाय करने अथवा मैनेजिंग एजेंसी के अतिरिक्त किसी अन्य सेवा की सप्लाय के लिए अथवा कम्पनी द्वारा निर्मित या बेचे गये अशो या गृह-पत्रों के अभिगोपन के लिए किये जाने वाले अनुबन्ध की अनुमति प्रदान कर सकती है। यह आवश्यक है कि किसी कम्पनी द्वारा माल की बिक्री या सप्लाय की गई सेवा का भुगतान कम्पनी को प्रबन्ध अभिकर्ता १ महीने के अन्दर कर दे। यह नियम उस माल या सेवा के सम्बन्ध में लागू नहीं होता जिसमें कम्पनी या प्रबन्ध अभिकर्ता नियमित रूप से व्यापार करते हैं। शर्त यह है कि ऐसी जायदाद का मूल्य और सेवा की लागत अनुबन्ध की अवधि में शामिल किसी भी क्लेन्डर वर्ष के लिए कुल ५,०००) से अधिक न हो।

यदि उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रबन्ध अभिकर्ता कोई पुरस्कार प्राप्त करता है तो वह प्राधिकार कम्पनी में जमा करना पड़ेगा।

पद की हानि के लिए हर्जाना

निम्नलिखित दस्तावेजों में पद की हानि (Loss of office) के लिए कोई कम्पनी अपने मैनेजिंग एजेंट को हर्जाना नहीं देगी :—

(१) जबकि प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी के पुनर्संज्ञा ठन या किसी अन्य समामेलित संस्था के साथ संयुक्तीकरण (Amalgamation) के लिए अपने पद से त्याग पत्र देता है और फिर वही पुनर्संज्ञा ठन कम्पनी या संयुक्तीकरण के फलस्वरूप बनी नई समामेलित संस्था का प्रबन्ध अभिकर्ता, सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष, मैनेजर या अन्य अधिकारी नियुक्त हो जाय।

(२) जब प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी के उक्त पुनर्संज्ञा ठन या संयुक्तीकरण के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से त्याग-पत्र दे।

(३) जब प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने पद को इस कारण छोड़ने के लिए विवश होता है कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार की कम्पनियों में मैनेजिंग एजेण्ट रखने का निषेध कर दिया है, अथवा अधिनियम के आदेशानुसार उसका कार्य-काल १५ अगस्त सन् १९६० तक अवश्य समाप्त हो जाना है, अथवा १० कम्पनियों से अधिक मैनेजिंग एजेण्टों न रखने के नियम का पालन करना पड़ा है ।

(४) जब प्रबन्ध अभिकर्त्ता का पद उसके दिवालिया होने (यदि वह एक व्यक्ति है) या फर्म के भंग होने (यदि वह एक फर्म है) अथवा समापन की कार्यवाही आरम्भ होने (यदि वह एक समामेलित संस्था है) के कारण या प्रबन्ध अभिकर्त्ता को किसी अपराध का दोषी पाये जाने पर उसका पद खाली मान लिया जाता है ।

(५) जबकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता का पद इस कारण खाली समझ लिया जाता है कि उसके द्वारा प्रबन्धित कम्पनी के समापन की कार्यवाही आरम्भ हो गई है और कम्पनी का समापन प्रबन्ध अभिकर्त्ता की लापरवाही या त्रुटि के कारण ही ।

(६) जबकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता को उसके पद से रिसीवर की नियुक्ति हो जाने से मुक्ति मिलाने का आदेश दिया गया है ।

(७) जबकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता को कपट या प्रत्यास भ्रम के लिए अथवा अत्यधिक लापरवाही एवं कुप्रबन्ध के लिए विशेष प्रस्ताव द्वारा पद से हटा दिया गया हो ।

(८) जबकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता ने स्वयं अपने पद की समाप्ति के लिये प्रेरणा दी है या समाप्ति के लिए प्रयत्न किया है ।

कम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्त्ता को पद की हानि के लिये जो हर्जाना दे सकती है वह उतने धन से अधिक नहीं हो सकता जितना उसने अपने दोष कार्य-काल में अथवा तीन वर्षों में (जो कम हो) अर्जित कर लिया होता । हर्जाने की गणना प्रबन्ध अभिकर्त्ता द्वारा पद की समाप्ति के तत्काल पहले तीन वर्षों की अवधि में अर्जित औसत पुरस्कार के आधार पर की जायेगी । प्रबन्ध अभिकर्त्ता का पद समाप्त होने के पहले या बाद में किसी भी समय १२ महीने के अन्दर यदि कम्पनी का समापन आरम्भ हो गया है और कम्पनी की सम्पत्ति, अथवा पूँजी (प्रीमियम सहित) चुकाने के लिये अपर्याप्त है तो प्रबन्ध अभिकर्त्ता कोई हर्जाना पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

पद के समाप्त होने पर प्रबन्ध अभिकर्त्ता के अधिकार—

जब किसी मैनेजिंग एजेण्ट का पद समाप्त हो जाय, तो प्रबन्ध अभिकर्त्ता एवं कम्पनी एक दूसरे से पद की समाप्ति के पहले किये गये या न किये गये कार्य के सम्बन्ध में अपनी माँग या दावे को पूरा कर सकेंगे । किसी अन्य रूप में प्रबन्ध अभिकर्त्ता के जो अधिकार या कर्त्तव्य हों, उन पर पद की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति का समापन—

कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ का उद्देश्य प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति को निम्न-लिखित ढंग से समाप्त करना है—

(१) १५ अगस्त सन् १९६० तक तो इस पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किन्तु तत्पश्चात् इसका महत्त्व कम होने लगेगा । कोई भी प्रबन्ध अभिकर्ता १० से अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध नहीं कर सकेगा । १ अप्रैल सन् १९५६ के बाद किसी भी समय केन्द्रीय सरकार यह सूचित करने का अधिकार रखती है कि एक विशेष उद्योग या व्यापार में सलग्न सभी कम्पनियाँ कोई प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं रख सकेंगी । इस सूचना का प्रभाव यह होगा कि जिन कम्पनियों में सूचना की तिथि पर प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं थे वे भविष्य में प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं रख सकेंगे और जिन कम्पनियों में प्रबन्ध अभिकर्ता है उनका कार्यकाल निर्दिष्ट निधि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या १५ अगस्त सन् १९६० से जो भी तिथि बाद में पड़े, समाप्त हो जायगा ।

(२) वे कम्पनियाँ जो उपरोक्त निग्रम में नहीं आती तब तक प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकेंगी जब तक केन्द्रीय सरकार से विशेष स्वीकृति प्राप्त न हो जाय और केन्द्रीय सरकार ऐसी स्वीकृति निम्न बातों का मन्तोष प्राप्त होने पर ही देगी—

(अ) कि कम्पनी को प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति देने से जन-हित को नुकसान नहीं पहुँचेगा ।

(आ) कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता एक उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति है ।

(इ) कि उनके ठहराव की शर्तें उचित हैं । और

(ई) कि प्रबन्ध अभिकर्ता ने उन तीन शर्तों को पूरा कर दिया है जो केन्द्रीय सरकार ने उनके लिए निर्दिष्ट की हो ।

इस प्रकार सन् १९६० के पश्चात् प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति का भविष्य बड़ा अनिश्चित और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इन पाँच वर्षों की अवधि के भीतर प्रबन्ध अभिकर्ताओं का आचरण कैसा रहना है । यदि उनका आचरण समाज-वादी ढाँचे के अनुकूल रहता है, यदि उन पर लगाये गए प्रतिबन्धों के फलस्वरूप इस पद्धति के सब मुख्य दोष दूर हो जाते हैं और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं होता तो उनके बने रहने की सम्भावनाएँ बढ़ जायेंगी । यद्यपि सिद्धान्त-प्रबन्ध अभिकर्ताओं का उन्मूलन उचित है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनके उन्मूलन की समय सीमा निर्दिष्ट कर देना बुद्धिमानी नहीं होगी ।

प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति का भविष्य

(Future of the Managing Agency System)

१५ अगस्त सन् १९६० की निर्धारित तिथि अब व्यतीत हो चुकी है, अतः अब हमें इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का

पूर्ण समापन होना चाहिये अथवा देश की वर्तमान आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के अन्तर्गत आज भी इसकी आवश्यकता है। यह भाव है कि मन वर्षों में अनेक दोषों व दुर्बलताओं के कारण प्रबन्ध अभिवर्त्ता पद्धति का बड़ा घोर विरोध हुआ है। प्रो० के० टी० शाह (Prof. K. T. Shah) ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रबन्ध अभिवर्त्ता पद्धति जड़ से चीटी तक सब चुकी है और शीघ्रता शीघ्र इस प्रणाली का समापन होना चाहिए।^१ सम्भवतः प्रबन्ध अभिवर्त्ता प्रणाली के दाया ने ही भारत सरकार को कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनेक बार विवश किया। मन् १९१२ के भारतीय कम्पनी अधिनियम में, सन् १९३६, १९४६, १९४८ तथा मन् १९५१ में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और अत्यंत बार संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य प्रबन्ध अभिवर्त्ता प्रणाली के दायों पर विजय पाना ही था। अनेक बार संशोधन किए जाने पर भी भारतीय जनता (विद्योपन विनियोगी वर्ग) सन्तुष्ट न हुआ, अतः मन् १९५६ में पुराने कम्पनी अधिनियम का पूरा न मरने के नया अधिनियम बनाया गया, जिसका नाम है 'भारतीय कम्पनी अधिनियम, मन् १९५६।' यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि मन ३०-३५ वर्ष की अवधि में प्रबन्ध अभिवर्त्ताओं के सम्बन्ध में अनेक नये-नये नियम बनाये गए एवं इस प्रणाली के दाया का दूर करने के उद्देश्य से उन पर प्रतिबन्ध लगाए गए, परन्तु किसी भी बार लोगो को यह भाव नही हुआ कि प्रबन्ध अभिवर्त्ता प्रणाली को जड़ में उखाड़ दिया जाय। इस प्रणाली में सुधार किये गए, इसका समापन नहीं। भारतीय प्रमुख आयोग मन् १९४६-५०, योजना आयोग मन् १९५० तथा कम्पनी लॉ कमेटी मन् १९५२ (जो कि भाभा कमेटी के नाम से प्रचलित है) आदि सभी ने इस सत्यता में सुधारों की ही सकारितों की हैं। भाभा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 'अनेक दोषों व दुर्बलताओं के होते हुए भी, भारत में वर्तमान औद्योगिक संगठन में इस प्रणाली पर निर्भर रहना ही अधिक हितकर होगा, क्योंकि निजी उपकरण की विकास व विस्तार बहुत कुछ इस प्रणाली पर ही अवलम्बित है।'^२

1 "Managing Agency System is rotten root and branch, leaves and bark and blossom and must be abolished at the earliest opportunity, so that no ground remains for retaining them, either on the score of providing finance or managerial talent to the industries." —K T Shah.

2 "Bhabha Committee in its report observes. "It feels that notwithstanding the many abuses and malpractices which have disfigured the working of the system, in the present state of industrial organisation of the country, it may still be on balance an advantage to continue and rely on it. Short of these abuses and mal practices, the committee feels that the system may yet prove to be a potent instrument for taking the springs of private enterprise"

अगस्त सन् १९५५ में लोक सभा में कम्पनी लॉ बिल पर बड़ी बहस हुई और अधिकांश बिलों ने प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति की कड़ी आलोचना की थी। स्वयं कांग्रेस दल के आलोचकों ने इस पद्धति के उन्मूलन की माँग की और इस सम्बन्ध में एक निश्चित समय निर्धारित कराने का प्रयास किया। वे 'सेक्रेटरी एव कोषाध्यक्ष' की नई व्यवस्था से भी सन्तुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके विचार में इसमें अधिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, वे कम्पनियों में प्रबंध पर अधिक नियन्त्रण रखना चाहते थे, किन्तु सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत उपक्रम को धक्का पहुँचता और पंच वर्षीय योजना की सफलता खटाई में पड़ जाती। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वेशमुख ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पक्ष में निम्न बल्लौलें प्रस्तुत कीं—

(१) द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिये व्यक्तिगत उपक्रमों पर बहुत सीमा तक निर्भरता रखी गई है। अब बीच में ही प्रबंध अभिकर्ता पद्धति को किसी उद्योग विशेष में न रखने की घोषणा में व्यक्तिगत उपक्रम को बड़ा धक्का लगेगा और वह अपने दायित्व ठीक तरह से नहीं निभा सकेगा।

(२) स्वतन्त्रता के पूर्व जब प्रबंध अभिकर्ता पद्धति के विरोध में आवाज उठाई गई थी तो अधिकांश व्यापार विदेशियों के हाथ में था, किन्तु अब परिस्थिति बदल गई और व्यापार देशवासियों के हाथ में आ गया है। फिर भी अनेक दाव प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के ऐसे हैं जो कि, उन्हीं परिस्थितियों में, संचालक-मन्त्रा या मैकेटरी एव कोषाध्यक्ष अथवा अन्य प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत भी उत्पन्न हो सकते हैं। यही नहीं, आज अनेक ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता भी हैं जो अपने ज्ञान और अनुभव से देश को लाभ पहुँचाना चाहते हैं।

(३) हमें प्रबन्ध अभिकर्ता के कार्यों का लेखा-जोखा केवल समापित कम्पनियों की सख्या से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि नई रजिस्टर्ड कम्पनियों को भी विचार में लेना चाहिए। युद्धोत्तर काल में कम्पनियों की सख्या दुगुनी से अधिक हो गई है और प्राप्त पूँजी भी पहले से तिगुनी हो गई है, जो कि देश के हित में है।

(४) यह कहना असत्य है कि कम्पनियों के प्रवर्तन और अर्थ-प्रबन्धन में प्रबंध अभिकर्ताओं का अधिक भाग नहीं। १,७२० कम्पनियों की परीक्षा से यह पता लगा है कि लगभग १३.६% अर्थात् पूँजी एव २६.६५% पूँजी एव अग्रिम प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त हुआ था। यदि प्रबंध-अभिकर्ताओं का हटा दिया जाय तो इतने वित्त की व्यवस्था सरकार कहाँ से करेगी ?

(५) जहाँ तक आर्थिक सत्ता के कतिपय हाथों में केन्द्रीयकरण का प्रश्न है, यह दोष केवल प्रबंध अभिकर्ता पद्धति का ही हो, ऐसी बात नहीं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में भी, जहाँ कि ऐसी पद्धति प्रचलित नहीं है, आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण की समस्या पाई जाती है। फिर थोड़ा ही (लगभग ३३) प्रबन्ध-अभिकर्ता देश में ऐसे हैं जिनके पास १० या अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध है।

(६) प्रबन्ध-अभिकर्ता देश की व्यावसायिक वृद्धि के प्रतीक हैं। यदि केवल नियन्त्रण द्वारा इनका सहयोग देश के अधिक आर्थिक विकास में प्राप्त हो सकता है तो फिर इनके उन्मूलन की हिंसात्मक नीति अपनाने से क्या लाभ ?

(७) प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पुरस्कार शुद्ध लाभ का १०% निर्धारित किया गया है, जो कि अधिक नहीं है। प्रबन्ध संचालकों को वेतन के अतिरिक्त शुद्ध लाभ का ५% मिलता है और सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष को ७½% निश्चित किया गया है। इनकी तुलना में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को १०% पुरस्कार अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रबन्ध अभिकर्ता विभिन्न प्रकार का अनुभव रखते हैं और वित्त की व्यवस्था भी करते हैं, जबकि संचालक और सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष इनकी चहुँमुखी योग्यता नहीं रखते और न ही उनको वित्त व्यवस्था का भार उठाना पड़ता है। अभी तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं को मिलने वाला पुरस्कार औसतन शुद्ध लाभ का २७% था, पर पुरस्कार में इतनी बड़ी कमी करना वास्तव में भारी असफलता है, जो कि समाज के समाजवादी ढाँचे में अनुकूल है।

(८) यदि किसी विशेष उद्योग या व्यापार में प्रबन्ध अभिकर्ता रखना उचित न समझा जाय तो भी अन्य क्षेत्रों में, जहाँ प्रवर्तन एवं अर्थ-प्रबंधन की आवश्यकता है, उस पद्धति का लाभ क्यों न उठाया जाय, जो कि भूतकाल में उपयोगी थी और भविष्य में उपयोगी होगी।

उपयुक्त हकीमों के आधार पर तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जितलामणि देशमुख ने कहा था कि, 'अभी प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के समापन के लिये उपयुक्त समय नहीं आया है, क्योंकि यदि इसको समाप्त किया गया तो देश के औद्योगीकरण को गहरी आघात पहुँचेगा। अतएव बुद्धिमता का मार्ग तो यह होगा कि जब तक हम अपने देश का पुनर्निर्माण करें, तब तक के लिये इस प्रणाली में केवल उचित संशोधन कर दिये जाय।'*

यही कारण है कि भारत सरकार ने शास्त्री कमेटी सन् १९५७ की सिफारिशों के आधार पर कम्पनी अधिनियम संशोधन आलेख सन् १९५९ में भी प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली पर कठोर नियन्त्रण करने की ही चेष्टा की है। भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मण्डल के आग्रह पर राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद (National Council of Applied Economic Research) ने प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के विभिन्न पहलुओं एवं उसकी उपयोगिता का अध्ययन करके सम्मति प्रपट की है कि देश के

* 'The time has not come for eliminating Managing Agency System because it would deal a very severe blow to industrialisation in the country. The way of prudence dictates reforming the existing institution, while this process of building up new one proceeds a pace'

—C D Deshmukh

आर्थिक विकास में यह प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका भूँदा कर रही है, अतः इस पद्धति को समाप्त करने के लिये कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं दिखलाई देता। परिषद् का कहना है कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इस पद्धति में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं सुधार किये जा सकते हैं। कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा इस पद्धति का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ उठाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह पद्धति ठोस नहीं है, इसलिये इसे समाप्त कर दिया जाय। परिषद् के महा सचालक डा० पी० एस० लोकनाथन (Dr. P. S. Loknathan) ने कहा है कि यह पद्धति निजी क्षेत्र को विशेषतः दो दिशाओं में सक्रिय योगदान दे रही है—(१) यह अपने आय श्रोतों व बचत से प्रबन्धकृत कंपनियों को पूँजी की व्यवस्था करती है, और (२) अपने प्रबन्ध के उद्योगों का बहुमुखी विस्तार कर रही है।

प्रबंध अभिकर्त्ता प्रणाली का समापन वांछनीय क्यों नहीं है ?—

भारत की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक परिस्थितियों के अन्तर्गत यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि प्रबंध अभिकर्त्ता प्रणाली का पूर्ण समापन हितकर न होगा। इस सम्बन्ध में निम्न दलीलें दी जा सकती हैं :—

(१) प्रवर्तन की भावी आवश्यकताएँ—भारतवर्ष में उद्योग धन्धों के प्रवर्तन के लिए अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र है। हमारा देश प्राकृतिक प्रसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी है, परन्तु अपनी प्राकृतिक सम्पदा का विरोहन करने के लिये उपक्रम (Enterprise) की आवश्यकता है। हमारी सरकार अनेक राजनैतिक व इन्ध वरेलू समस्याओं में व्यस्त है एवं वह आर्थिक क्षेत्र में अधिक ध्यान नहीं दे सकती। अतएव निजी उपक्रम को ही आगे बढ़कर औद्योगीकरण की दिशा में

प्रबंध अभिकर्त्ता प्रणाली का पूर्ण समापन क्यों नहीं ?

- (१) प्रवर्तन की भावी आवश्यकताएँ।
- (२) बचत तथा उसका एकत्रीकरण।
- (३) तृतीय पंच-वर्षीय योजना की सफलता।
- (४) पूँजी की सुविधा।
- (५) अभिगोपन सम्बन्धी समस्याओं का अभाव।
- (६) प्रबन्ध-योग्यता की आवश्यकता।

देश को अग्रसर करना होगा। गत ५-७ वर्षों के आर्थिक व औद्योगिक विकास के आँकड़ों से यह स्पष्ट लगता है कि हमारे देश में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने प्रारम्भिक अनुसन्धान करके अनेक नये उद्योग-धन्धों की स्थापना की है। ओटोमोबाइल्स, लोको-मोटिव्स औद्योगिक यन्त्र व उपकरण, रसायनिक पदार्थ, रेयन व प्लास्टिक पदार्थों से सम्बन्धित उद्योगों के प्रवर्तन व स्थापना का श्रेय प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को ही है। भविष्य में भी अपनी पंच-वर्षीय योजनाओं की सन्तुष्टि के लिए हमें अनेक उद्योग-धन्धों की स्थापना करनी होगी, जिसके लिए प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली को चालू रखना नितान्त आवश्यक है।

(२) वचत तथा उनका एकत्रीकरण—तृतीय पंच-वर्षीय योजना की सफलता काफ़ी सीमा तक घरेलू वचत पर निर्भर करती है।* इस घरेलू वचन की प्रोत्साहित करने एवं औद्योगीकरण हेतु उसको एकत्र करने में प्रबन्ध अभिवर्ती प्रणाली ने बहुत बड़ा योगदान किया है तथा भविष्य में भी इससे बहुत आशा है।

(३) तृतीय पंच-वर्षीय योजना के उद्देश्यों की सफलता के लिए—
 जून सन् १९५६ में उदकमण्ड में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस बमटो ने योजना सम्बन्धी सँमितार में यह निश्चय हुआ था कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना मुख्यतः 'उत्पादन वृद्धि की योजना' होनी चाहिए। वास्तव में निम्नलिखित कारणों से आज हमारा नारा 'उत्पन्न बन करो अथवा नष्ट हो जाओ' (Produce or perish) ही होना चाहिए—(i) उपभोग के स्तर को बढ़ाने के लिये, (ii) यशनी हुई जन-संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, (iii) रहन-सहन के स्तर की वृद्धि के लिए, (iv) अतिरिक्त धन शक्ति व प्राकृतिक प्रसाधनों के समुपयोग के लिए, (v) मुद्रा-प्रसार के दानव पर विजय पाने के लिए, एवं (vi) अन्य प्रगतिशील औद्योगिक राष्ट्रों के साथ कदम-ब-कदम मिलाकर चलने के लिये। यही एक कारण है कि अभी हाल में प्रकाशित हमारी तृतीय पंच-वर्षीय योजना में भी औद्योगीकरण के विकास व विस्तार पर बहुत ध्यान दिया गया है। हमारे देश में आज पूँजीकृत उद्योगों की बहुत कमी है, जो कि ऐसे यन्त्रों का उत्पादन करते हों जिनका उपयोग उपभोक्ता उद्योगों में किया जाता है। परन्तु औद्योगिक विकास व विस्तार की कल्पना कोरी मृग-वृष्णा होगी, यदि प्रबन्ध अभिवर्तीओं का अन्त कर दिया गया है। हमारे प्रबन्ध अभिवर्ती प्राधुनिक उद्योगों के नामक या कॅप्टन हैं। जिस प्रकार बिना कॅप्टन के कोई खेल सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना अभिवर्तीओं के औद्योगीकरण का विस्तार करना कठिन है। अतएव तृतीय पंच-वर्षीय योजना की सफलता के लिए प्रबन्ध अभिवर्ती प्रणाली को चालू रखना ही हितकर होगा।

(४) पूँजी के बाजार का सकुचित होना—यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् हमारे देश में औद्योगिक संस्थाओं की अथ-सम्बन्धी आवश्यकताओं की समुष्टि के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया गया (जैसे औद्योगिक अर्थ निगम, राज्य अर्थ-निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, पुनर्वित्त निगम, इत्यादि)। परन्तु

* According to the Report (1959) of the NCAER, "The Marginal propensity to save, which is a crucial determinant of economic development in under developed countries depends upon —(a) Increase in National Income (b) Restraints on consumption and (c) Incentives for savings... The Managing Agency System not only attracts savings of others, but also provide personal savings and savings of their companies of firms for the use of the companies under their management."

भाज भी पूँजी का बाजार अत्यन्त सकुचित है। हमारी पूँजी बड़ी लज्जेली है। औद्योगिक अंशों व ऋण पत्रों में विनियोग करने की प्रवृत्ति अभी अधिक लोकप्रिय नहीं हुई है। अतएव ऐसी परिस्थिति में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त करना पेड़ की उस छाल को काटने के समान है, जिस पर स्वयं बैठे हैं।

(५) साधारण अंश पूँजी व अभिगोपन सम्बन्धी समस्याओं की कमी—हमारे देश में साधारण अंश पूँजी (Equity Capital) को प्राप्त करने में प्रबन्ध अभिकर्ताओं की 'साख' बहुत सहायता पहुँचाती है। अभिगोपन संस्थाओं (Underwriting Institutions) की भी देश में बड़ी कमी है। प्रबन्ध अभिकर्ता ही इस कार्य को करते आ रहे हैं। अतएव उनके समापन से पूँजी के बहुत बड़े स्रोत पर कुठाराघात हो जायगा।

(६) प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता की आवश्यकता—भारत के औद्योगीकरण को सफल बनाने के लिए योग्य प्रबंधकों की बड़ी आवश्यकता है। 'बल' का भारत इन्हीं पर निर्भर करता है। प्रबंध अभिकर्ताओं को जड़ से समाप्त करना बड़ी भारी मूर्खता हो सकती है। अतएव इस प्रणाली को चालू रखना ही राष्ट्रीय हित में होगा।
निष्कर्ष—

संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि (१) प्रवर्तन, (२) अर्थ और (३) व्यावसायिक प्रबंध व व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रबंध अभिकर्ता प्रणाली चालू रखना ही श्रेष्ठ होगा।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Briefly summarize the principal provisions of the Indian Companies Act 1956 with regard to the appointment of a managing agent
- 2 In what circumstances is the office of a managing agent deemed to have been vacated?
- 3 Can the managing agents of a company be removed from office before the expiry of his term? If so how?
- 4 Can the managing agents of a company resign his office? If so, subject to what conditions?
- 5 (a) Can the managing agents of a company be appointed its selling or buying agents? If so how?
(b) Can a company give loans to (i) its managing agent and (ii) any other company under the same managing agents.
- 6 What restrictions have been imposed by the Indian Companies Act, 1956 on the powers of Managing Agents.
- 7 "In theory managing agencies should go in practice it may not be prudent to set a time limit for their exist. Do you agree with this statement? Please give arguments for your answer."

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र

(Public Sector in Mixed Economy)

प्रस्तावना—ऐतिहासिक विवेचन—

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का विचार न केवल भारत के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए भी नया है। प्राचीन काल में 'निर्वाण व्यापार की नीति' का अनुमान किया जाता था, जिसका अन्तर्गत अतिशय एष आर्थिक सभ्यताओं को आर्थिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। सरकार आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी और न उसने कोई उद्योग ही प्रारम्भ किया। प्रतिष्ठित प्रवृत्ताक्रिया के तत्वा में भी यह पता चलता है कि उन दिनों मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रवर्तक आदम स्मिथ (Adam Smith) का मत था कि, 'आर्थिक दृष्टिकोण ही समस्त आर्थिक प्रगति की कुञ्जी है। सरकार को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति केवल इस कारण ही नहीं अपनानी चाहिए कि उस व्यक्तियों को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करनी है, बल्कि इसलिए भी कि वह कुशल एवं व्यावहारिक रीति से आर्थिक कल्याण का निर्माण की स्थिति में भी नहीं है।' कोई भी दो व्यक्तियुक्त इनमें अन्तर्गत नहीं हैं, जिनमें कि एक व्यापारी और प्राप्तक होते हैं समस्त धारण, बिना कोई अववाद, समान में सबसे अधिक मिश्रित होती हैं।¹ सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं में भाग लेने के विरुद्ध एक मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति व्यय करता है, तो वह अपना ही धन व्यय करता है और जब कोई सरकार व्यय करती है, तो वह किसी विशेष व्यक्ति का धन नहीं बल्कि सबका

* The State should not interfere in economic affairs not only because the State has to offer economic liberalism to the individuals but also because the State is not in a position to perform economic functions in an efficient, economic way. No two characters seem more inconsistent than those of trader and sovereign. Sovereigns are always and without any exception, the greatest spend thrifts in the society.' —Adam Smith.

सम्मिलित धन व्यय करती है, जिससे उसके कार्यों में उत्साह एवं उत्तरदायित्व की वह भावना नहीं होती जो कि एक व्यक्ति के कार्यों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति विशेष की आय बहुत कुछ स्थिर होती है, अतः वह अपने बढ़ते हुए व्यय के अनुसार ही अपनी आय को नहीं बढ़ा सकता, जिससे व्यय करते समय उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। जे० बी० से (J. B Say), डेविड रिकार्डो (David Ricardo) और मिल (Mill) ने इन विचारों को अन्य देशों में फैलाया।

निर्बाध व्यापार की नीति कुछ समय तक विश्व में अपना प्रभुत्व जमाये रही, लेकिन बाद में यह प्रभुत्व जाता रहा, क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने इन विचारों से सम्बन्ध तोड़ लिया, क्योंकि इस नीति के दाप (जैसे मला-काट प्रतियोगिता, अत्यधिक आर्थिक उत्पन्न-बढ़ाव और अधिक सकटों का बार-बार आना) सब पर भत्ती भाँति प्रगट हो हो गये थे। कीन्स और पीगू के नाम इन अर्थशास्त्रियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धीरे धीरे निर्बाध व्यापार की नीति का स्थान समाजीकरण (Socialisation) के सिद्धान्त ने ले लिया। इस सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था पर सरकार का ही स्वामित्व एवं नियन्त्रण होना चाहिए। पीगू ने इस सिद्धान्त का प्रबल समर्थन किया। उसका कहना था कि "उत्पादन के साधनों का समाजीकरण आर्थिक शान्ति की स्थापना के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिनका शीघ्र इसे अपनाया जायगा उतना ही यह श्रेष्ठ होगा।" लेकिन प्रोफेसर कीन्स पूर्ण समाजीकरण के विरुद्ध थे। उनकी सम्मति में सरकार का उद्योगों पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाभ-भावना के अभाव के कारण सरकार में एक व्यक्ति के समान उत्साह और कार्य-कुशलता नहीं आ सकती। अतः एक व्यावहारिक अर्थशास्त्री की भाँति उन्होंने बीच का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया अर्थात् कुछ सीमा तक सरकार का नियन्त्रण हो और कुछ सीमा तक व्यापार की स्वतन्त्रता भी रहे। दूसरे शब्दों में; उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण सरकारी स्वामित्व व नियन्त्रण स्थापित करने तथा पूँजीवाद का जड़ से उन्मूलन कर देने की अपेक्षा सरकार को व्यक्तिवादी उपक्रम के साथ मिल कर आर्थिक कार्यों में भाग लेने का सुझाव दिया।

सर्व प्रथम सोवियत रूस ने निर्बाध व्यापार की नीति का परित्याग किया और पूँजीवाद का उन्मूलन करने तथा सरकारी नियन्त्रण स्थापित करने का कदम उठाया। यह उल्लेखनीय है कि उन दिनों सोवियत सरकार, जिसके अध्यक्ष लेनिन (Lenin) थे, उत्पादन के साधनों का एकदम से समाजीकरण करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि वह अनुभव करती थी कि नियन्त्रित व्यवस्था अभी सफल हो सकती है जबकि मजदूर वर्ग प्रबन्ध करने की कला में निपुण हो जाय। अतः वहाँ सरकारी योजनाओं के द्वारा धीरे-

* "Socialisation of the means of production was Sine qua non of economic peace and that sooner it was adopted the better."

—Pigou.

पीरे ही उत्पादन के साधनों का पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त किया गया। अन्त में फरवरी सन् १९२१ को सरकारी योजना आयोग के विधान की स्वीकृति होने से आर्थिक नियोजन की वह प्रणाली स्थापित हो गई जो आज तक भी उस देश में चालू है। इस प्रणाली के अन्तर्गत जो सफलताएँ उस देश में प्राप्त की गई हैं वे शेष विश्व को भी उस प्रणाली के ग्रहण करने के लिये प्रेरणा प्रदान कर रही है। किन्तु यह तो प्रारम्भ ही है; अन्त तो अभी देखना बाकी है।

सोवियत रूस, चीन व अन्य देशों में सरकारी नियोजन की सफलता को देखते के पश्चात् पूँजीवाद के प्रबल समर्थक भी उस चिन्तोह-भावना की भावना का अनुभव करने लगे हैं जो कि पूँजीवाद के विरुद्ध उमड़ रही है। इस भावना को शान्त करने के लिये पूँजीवादी देश पूँजीवाद को समाप्त करने या उसके स्थान में सरकारी उपक्रम को अपना देने के बजाय पूँजीवादी व्यवस्था में ही उपयुक्त संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में भी इसी मार्ग को ग्रहण किया है। विशेषतः संयुक्त अरब गणराज्य, भारत, पाकिस्तान आदि देशों में सरकारी नियोजन किया जा रहा है, किन्तु उसका उद्देश्य वर्तमान में पूर्ण समाजीकरण करना नहीं बल्कि समाज को एक उत्तम रहन-सहन स्तर प्रदान करना है। परन्तु अन्त में यह स्वीकार करना ही होगा कि समाजीकरण की विचारधारा दिनों दिन जोर पकड़ रही है और पूँजीवादी प्रणाली को बीते हुए समय की वस्तु माना जाता है।

✓ **मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का आशय एवं इसकी विशेषताएँ**

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का अर्थ—

‘मिश्रित अर्थ व्यवस्था’ (Mixed Economy) वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक एवं प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों के लिये स्थान होता है और दोनों ही साथ-साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली दो विरोधी विचारधाराओं का—उत्पादन के समस्त साधनों और सम्पूर्ण अधिक ज़िया का समाजीकरण करने की विचारधारा तथा निर्विधि व्यापार की नीति का अनुसरण करने की विचारधारा—एक समन्वित परिणाम है। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत उपक्रमी एवं सरकार दोनों का उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में संयुक्त दायित्व होता है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था में व्यक्तिगत उपक्रमी को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा करते समय उसे सर्व शक्तिमान सरकार का माग दर्शन प्राप्त होता है, जो समाज के व्यापक हितों की रक्षक होती है। इस प्रकार, मिश्रित व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार प्राइवेट उपक्रम का इस प्रकार नियन्त्रण करने का प्रयास करती है कि अधिकतम सामाजिक हित हो।

विशेषताएँ—

मिश्रित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्यः दो या तीन क्षेत्र कार्यशील होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं :—

(१) सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र—‘सार्वजनिक’ या ‘सरकारी क्षेत्र’

(Public Sector) से उस आर्थिक क्षेत्र का अभिप्राय है, जिसमें उत्पादन और वितरण की सम्पूर्ण प्रणाली का प्रबन्ध, नियन्त्रण एवं अर्थ प्रबन्धन सरकार के हाथ में होता है तथा व्यक्तिगत उपक्रम को इसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता। प्रायः सुरक्षा एवं आधारभूत उद्योग इस क्षेत्र में सम्मिलित किये जाते हैं।

(२) सरकार व व्यक्तिगत उपक्रमियों का संयुक्त क्षेत्र—यह क्षेत्र (Public cum-Private Sector) एक संयुक्त सत्ता के नियन्त्रण व प्रबन्ध में होता है। संयुक्त सत्ता से सरकार व व्यक्तिगत उपक्रम दोनों का ही आशय है। किन्तु अपनी मुख्य स्थिति बनाने के लिए सरकार पूँजी में ५१% भाग ग्रहण करती है तथा व्यक्तिगत उपक्रम के लिये केवल ४९% भाग रहता है। गौण महत्व के उद्योग इस क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं।

(३) व्यक्तिगत उपक्रम का क्षेत्र—व्यक्तिगत उपक्रम का क्षेत्र (Private Sector) प्राइवेट उपक्रमियों के पूर्ण नियन्त्रण, प्रबन्ध व अर्थ प्रबन्धन के अन्तर्गत होता है। मुख्यतः अमहत्वपूर्ण उद्योग ही इस क्षेत्र में रखे जाते हैं जैसे उपभोग वस्तुएँ बनाने वाले कुछ उद्योग, वस्त्रोद्योग इन्डस्ट्रीज आदि।

कौनसा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाय और कौनसा उद्योग किसी अन्य क्षेत्र में रखा जाय इसका निर्णय सरकार करती है। सरकार द्वारा नियुक्त योजना-आयोग विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आवश्यकतानुसार समायोजन करता रहता है।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के प्रचलन के कारण

मिश्रित अर्थ व्यवस्था का प्रचलन होने के अनेक कारण हैं। कुछ मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं —

(१) पर्याप्त पूँजी की प्राप्ति के लिए—पूँजी के रूप में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी का अभाव होता है। विशेषतः अर्थ-विकसित देशों में न तो अकेले सरकार के पास और न अकेले व्यक्तिगत उपक्रमियों के पास ही इतनी पूँजी होती है कि वह सम्पूर्ण राष्ट्र की अधिकतम प्रगति के लिए पर्याप्त हो। ऐसी परिस्थितियों में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अधिक लाभदायक होती है।

(२) ट्रेन्ड स्टाफ की पूर्ति के लिए—अनेक देशों में यह अनुभव किया जाता है कि एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षित श्रम-बर्ग (Trained Personnel) असीमित मात्रा में नहीं होता। यदि कार्यों का प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रों में नहीं बाँटा गया, तो इस अभाव के बढ़ जाने की

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था क्यों ?

- (१) पर्याप्त पूँजी की प्राप्ति के लिए।
- (२) ट्रेन्ड स्टाफ की पूर्ति के लिए।
- (३) प्रशासन-व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए।
- (४) पूँजीवाद के गुणों को प्राप्त करने, किन्तु इसके दोषों को दूर रखने के लिए।

आशा है। किन्तु उन्हें सम्मिलित कर दिया जाय तो कुछ सीमा तक यह प्रभाव पूरा हो सकता है।

(३) प्रशासन-व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए—यदि ग्रामिक क्षेत्र को प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाय, तो प्रशासन-व्यवस्था अधिक कुशलता से चलाई जा सकती है। यह लाभ तब प्राप्त होना कठिन है जबकि पूर्ण समाजीकरण या पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाई जाय।

(४) पूँजीवाद के गुणों को प्राप्त करने किन्तु इसके दोषों को दूर रखने के लिये—इस व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजीवाद के समस्त गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु इसके दोषों को नहीं मुक्तता पड़ता, क्योंकि पूँजीवादी प्रणाली को सशोषित रूप से ही ग्रहण किया जाता है। प्राइवेट उपक्रम इस तरह कार्य करने का प्रयास करता है कि उसे भी लाभ हो और समाज का भी हित हो, क्योंकि यदि उसके कार्य समाज के हित में न हूँ तो उसे सरकार का कोप-भाजन बनना पड़ेगा।

भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था—

भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का विशेष महत्व है। सरकार के सामने जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि करके उनकी आर्थिक दशा में सुधार करने की तत्कालिक समस्या है। इसका हल तभी सम्भव है जबकि नयी दिशाओं में पर्याप्त सीमा तक उत्पादन बढ़ाया जाय। औद्योगिक और कृषिक उत्पादन की भारी वृद्धि के लिए बहुत पूँजी एवं प्रयास की आवश्यकता है, जिसे सरकार अपने साधनों से ही नहीं जुटा सकती। यही कारण है कि भारत सरकार में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाने का निश्चय किया और यह आशा की है कि वह प्राइवेट उपक्रम का इस प्रकार अधिकतम उपयोग कर सकेगी कि सम्पूर्ण समाज के आर्थिक कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो। भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्राइवेट और पब्लिक संक्टरों की चर्चा करते हुए यह कहा था कि “लोग प्रायः प्राइवेट और पब्लिक संक्टरों में विरोध होने की आशंका प्रकट करते हैं। कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि प्राइवेट उपक्रमों को पूर्ण एवं अनियंत्रित रूप से कार्य करने देना चाहिए। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्राइवेट उपक्रमों को इस प्रकार अनियंत्रित रूप से कार्य करने की छूट नहीं दी जा सकती है तथा सरकार को एक व्यापक मात्रा में हस्तक्षेप करना होगा। हमारे साधन सीमित हैं, अतः हम व्यक्तियों को सभी दिशाओं में कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। चाहे पब्लिक संक्टर हो या प्राइवेट संक्टर, दोनों के लिए नियोजन करने की आवश्यकता है। प्राइवेट क्षेत्र को अधिक से अधिक भूमिका प्रदान की जायगी, किन्तु उसे योजना में फिट होकर ही कार्य करना होगा। यदि हमारी योजना सम्पूर्ण क्षेत्र (प्राइवेट व पब्लिक) में विस्तृत न हो सके, तो उपयोगिता कुछ भी नहीं रहेगी। पब्लिक संक्टर को तो विशेष रूप से निश्चित एवं नियमित होना चाहिए।”

यद्यपि अनेक पश्चिमी देशों में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की विचारधारा काफी

समय से प्रचलित थी तथापि भारत में इसका प्रचलन थोड़े समय से ही हुआ है। स्वतन्त्रता के पूर्व सरकारी क्षेत्र विद्यमान नहीं था। हार्, रेल, डाक व तार, कस्टम विभाग पोर्ट ट्रस्ट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, आर्म्ड फोर्स एव एयरक्राफ्ट फैक्टरियाँ तथा कुछ अन्य उद्योग अवश्य सरकारी स्वामित्व व नियंत्रण में थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने कृषि व सम्बन्धित क्रियाओं की उन्नति, उद्योगों के विस्तार तथा अन्य सेवाओं का विकास करने का निश्चय किया। इसके लिए तथा विश्व के औद्योगिक उन्नतिशील देशों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो किसी को असंतोष दिए बिना सबको सन्तोष प्रदान करे। बहुत दिनों से सरकार ऐसी उपयुक्त प्रणाली की खोज में थी। अन्त में देश के प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों की सम्मति से उसने देश में मिश्रित-व्यवस्था का श्रीगणेश किया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है—सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र एवं सरकार व प्राइवेट उपक्रम का सम्मिलित क्षेत्र।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में पब्लिक सेक्टर—

भारत में पब्लिक सेक्टर (सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र) का आरम्भ थोड़े समय पूर्व से ही हुआ है, किन्तु योरोपीय देशों में वह काफी समय से विद्यमान था। चीन और रूसी समूह के देशों में यह अपने पूर्णता को प्राप्त हो गया है। भारत में सन् १९४८ की औद्योगिक नीति की घोषणा से इसे महत्व प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीयकरण के तथा इस सामान्य सिद्धान्त की स्वीकृति से, कि प्राइवेट सेक्टर में चलने वाले उद्योगों का भी सरकार नियमन व नियंत्रण कर सकती है, अब तक अनुसरण की गई विचारधारा व नीतियों में एक महान् परिवर्तन आ गया है और तब से पब्लिक सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है।

सन् १९४८ से पब्लिक सेक्टर में आरम्भ किये गये विभिन्न उपक्रमों को पाँच मुख्य शीर्षकों में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है :—

(१) सुरक्षा उद्योग (Defence & Strategic Establishments)—जैसे, हथियार, गोला-बारूद, हवाई जहाज, अणु-शक्ति बनाने से सम्बन्धित उपक्रम।

(२) जन उपयोगी सेवाएँ (Public Utility Undertakings)—जैसे डाक व तार विभाग, रेलवे व अन्य यातायात उपक्रम, विभिन्न विद्युत योजनाएँ आदि। जन उपयोगी सेवाओं के सहायक उद्योग भी सरकार ने आरम्भ किए, जिनमें निम्न विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—बमलौर का टेलीफोन निर्माण उद्योग, हिन्दुस्थान केबल्स लि० पश्चिमी बंगाल, चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क्स, इन्दोगल कोच फैक्टरी, पैरम्बूर।

(३) उद्योग (Industries)—इस वर्ग के उद्योगों का महत्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इनमें निम्न विशेष महत्वपूर्ण हैं—सिंदरी का खाद कारखाना, असोसि-

ग्रेटेड सीमेन्ट कम्पनी, हिन्दुस्तान मशीन टूलिंग लिमिटेड नेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट फैक्टरी बलकत्ता, जर्गपुरा की सरकारी हाउसिंग फैक्टरी, दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला के लोह एवं इस्पात कारखाने ।

(४) शिपिंग (Shipping)—शिपिंग (विशेषतः तटवर्ती शिपिंग) का विकास करने के लिए सरकार द्वारा शिपिंग टनेज क्षमता बढ़ाने के समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । सन् १९५० में ईस्टन शिपिंग कार्पोरेशन लि० की स्थापना हुई । हिन्दुस्तान शिपयाड जहाजों के निर्माण का कार्य करता है एवं वह और भी यार्ड खोले जाने की प्रगति में है ।

(५) विविध उपक्रम (Other Projects)—इस शीपक में निम्नलिखित विविध प्रकार के औद्योगिक संस्थान सम्मिलित किए जाते हैं—इण्डियन रेयर ग्रथ लिमिटेड (द्राव्यनिकोर्-कोबीन), पिम्परी की पेनिसिलिन फैक्टरी, दिल्ली का डी० डी० टी० कारखाना, मडी का नमक का कारखाना, यू० पी० सरकार की सीमेन्ट फैक्टरी, मध्यप्रदेश का नेपा बागज का कारखाना, बिहार सरकार की सुपरफास्फेट फैक्टरी, आदि । इनमें से अधिकांश संस्थानों का पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के रूप में संगठन किया गया है, जिसमें सरकार ने बहुमत शेयर खरीदे हैं । इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्ध संचालक के हाथ में है, जिसको परामर्श देने के लिए एक बोर्ड होगा है ।

पञ्च-वर्षीय योजनाएँ एवं पब्लिक सेक्टर—

प्रथम पञ्च वर्षीय योजना में पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों पर कुल व्यय ६४ करोड़ ६० लखा गया था । इसके अतिरिक्त रेलों की छोड़कर अन्य आधारभूत उद्योगों व यातायात के लिए ५० करोड़ ६० अलग थे । प्राइवेट सेक्टर में २२३ करोड़ ६० के व्यय की व्यवस्था थी ।

द्वितीय पञ्च-वर्षीय योजना की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए बड़ पैमाने पर उत्पादन करने की तथा कुछ विशेष प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में प्रसाधनों के समन्वित नियन्त्रण एवं वितरण की व्यवस्था करना आवश्यक होता है । ऐसी क्रियाओं में खनिजों एवं आधारभूत तथा पूँजीगत माल बनाने वाले उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है । इन पर ही अर्थ व्यवस्था का विकास मुख्यतः निर्भर होता है । इन क्षेत्रों में विकास करने का दायित्व सरकार को ही ग्रहण करना चाहिए तथा विद्यमान इकाइयों को नए नमूने के अनुसार ढलना होगा । इसी प्रकार, जिन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल घटक इस प्रकार के होते हैं कि आर्थिक शक्ति व सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिले, उनमें सरकारी स्वामित्व (आंशिक के पूर्ण) और सरकारी नियन्त्रण विशेष रूप से आवश्यक होता है । कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट उपक्रम सरकार से सहायता मिले बिना तगवकी नहीं कर सकते । अतएव इसमें स्तम्भान किए गए प्रसाधनों के स्वभाव पर ध्यान देना आवश्यक है । एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के विकास के लिए

विशाल क्षेत्र हैं। किन्तु, व्यापक सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि पब्लिक सैक्टर प्राइवेट सैक्टर की अपेक्षा अधिक विकसित हो।

पब्लिक सैक्टर की समस्याएँ—

पब्लिक सैक्टर की निम्नलिखित समस्याएँ हैं :—

(१) सगठन की समस्या—विभिन्न देशों में राष्ट्रीयकरण की योजनाओं का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सगठन का कौन-सा रूप अपनाया जाय। यह मुख्यतः काम में आने वाले साधनों के स्वभाव पर निर्भर है। विभिन्न सगठन प्रणालियाँ निम्न हैं—सिंडीकेट प्रणाली, मैनेजिंग डाइरेक्टर अथवा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की प्रणाली, आदि। प्रत्येक प्रणाली के अपने-अपने गुण-दोष हैं। इन सब पर विचार करके यह निश्चय किया गया है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों को अर्द्ध-स्वतन्त्र निगमों द्वारा प्रबन्धित किया जाय।

(२) मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता—पब्लिक सैक्टर के लिए सबसे कठिन समस्या उद्योग व सेवाओं के उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने की है। सामान्यतः प्राइवेट उत्पादन का बाजार-मूल्य इतना होने की प्रवृत्ति रखता है कि उत्पादन की लागत निकल आये और साहसी को कुछ लाभ भी बच रहे। पब्लिक सैक्टरों के उद्योग की स्थिति भी इसमें अधिक भिन्न नहीं है। अतः केवल इस बात का है कि प्राइवेट सैक्टर को वस्तुओं का इतना मूल्य रखना पड़ता है जिसमें कि लागत के ऊपर कम से कम पूँजी को आवृत्ति करने लायक लाभ बचे। किन्तु पब्लिक सैक्टर को अन्त्यापारिक घटकों का भी मूल्य निर्धारण में ध्यान रखना पड़ता है। वृद्धि के दायरे में, पब्लिक सैक्टर में मूल्य का निर्धारण सरकार की नीति पर भी निर्भर होता है।

पब्लिक सैक्टर की मुख्य समस्याएँ तीन हैं

(१) सगठन की समस्या।

(२) मूल्य-निर्धारण एवं उपभोक्ता।

(३) श्रम की माँग।

(३) श्रम की माँग—पब्लिक सैक्टर में वास्तविक सघर्ष उपभोक्ता और श्रमिक के बीच में है। श्रमिक कम काम, अच्छी मजदूरी और अपनी सेवा की स्थिरता की माँग करते हैं। लेकिन उपभोक्ता अधिक उत्पादन, अधिक चुनाव का अवसर तथा कम कीमत चाहते हैं। ये दोनों विचारधाराएँ सदैव ही संतुलित नहीं हो पाती हैं।

पब्लिक सैक्टर की आलोचना—

पब्लिक सैक्टर के कार्य के विरुद्ध निम्न आलोचनाएँ की जाती हैं :—

(१) सरकारी पूँजीवाद के पनपने की आशंका—यदि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी उपक्रम का अबाध विकास होता रहा, तो सरकारी अधिकारियों का प्रभाव

बहुत बढ़ जायगा, जिससे पब्लिक सेक्टर के कालान्तर में सरकारी पूँजीवाद में परिणित हो जाने की आशंका है।

(२) करो से होने वाली आय में कमी आने का भय—यदि सरकारी व्यापार को अधिकाधिक बढ़ावा दिया गया, तो इसमें लाभ के उन श्रोतों में कमी आ सकती है, जिनसे सरकार को अब कर की आय हो रही है।

(३) पहलपन, लोच एवम् जोखिम उठाने की क्षमता में कमी—पब्लिक

पब्लिक सेक्टर की चार प्रमुख आलोचनायें

- (१) सरकारी पूँजीवाद के पनपने की आशंका।
- (२) करो से होने वाली आय में कमी आने का भय।
- (३) पहलपन, लोच एवं जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव।
- (४) लोक-कल्याण कार्यों पर सरकारी खर्च में कमी।

सेक्टर के अधिकारियों में पहलपन, लोच एवं जोखिम उठाने की भावना को कार्यान्वित होने का अधिक अवसर नहीं मिलता, जिसमें इन गुणों के लुप्त हो जाने की आशंका है।

(४) लोक-कल्याणकारी कार्यों पर सरकारी व्यय में कमी—सरकार के आर्थिक साधन सरकारी व्यापार में लग जाने पर सरकार को अपना व्यय लोक हितकारी कार्यों पर घटाने के लिए विवश होना पड़ता है।

फिर भी भारत जैसे पिछड़े देशों में सरकारी उपक्रम के इतने अधिक लाभ हैं कि उक्त दोषों को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। भारत ने शीघ्र औद्योगीकरण एवं समाजवादी समाज की स्थापना सम्बन्धी जो नीति अपनाई है उसकी पूर्ति के लिए पब्लिक सेक्टर का धीरे-धीरे बाल विस्तृत होना जरूरी है।

STANDARD QUESTIONS

1. What do you understand by the conception of 'Mixed Economy'? What are the special peculiarities of such an economy?
2. Discuss the causes of the introduction of mixed economy with particular reference to India?
3. Define 'Public Sector' and discuss its problems.
4. Write short notes on :
(a) Public Sector, (b) Private Sector,
(c) Public-cum-Private Sector; and (d) Laissez-faire.



अध्याय ५३

राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था एवं प्रबन्ध (१)

(गोरवाला, गैलब्रेथ, अप्पल बी तथा इकेफी की रिपोर्टों के सद्वर्ग सहित)

(Administration & Management of State Enterprises)

‘राजकीय उपक्रम’ से आशय—

‘राजकीय उपक्रम’ (Public or State Enterprise) से हमारा आशय ऐसी औद्योगिक संस्था से है, जिस पर राज्य का स्वामित्व हो और जिसकी व्यवस्था एवं प्रबन्ध का संचालन राजकीय यंत्र द्वारा किया जाता हो। इसे ‘सरकारी’ अथवा ‘जन-संस्था’ भी कहते हैं। राजकीय उपक्रम की उपर्युक्त परिभाषा स्पष्ट होती हुए भी पूर्णतः ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें लोच का अभाव है। यदि उपर्युक्त परिभाषा को ही हम आधार मानकर चलें तो केवल ऐसी औद्योगिक संस्था ही सरकारी या सार्वजनिक संस्था (State or Public Enterprise) कही जा सकती है, जिस पर—(i) पूर्णतः राज्य का स्वामित्व हो, और (ii) जिसका प्रबन्ध एवं संचालन राजकीय यंत्र द्वारा किया जाता हो। अतएव लोच के तथ्य को मस्तिष्क में रखने हुए राजकीय उपक्रम की परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है—“राजकीय उपक्रम एक ऐसी संस्था है, जिस पर या तो राज्य का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबन्ध-व्यवस्था राजकीय यंत्र द्वारा संचालित की जाती हो अथवा दोनों हो (अर्थात् स्वामित्व एवं प्रबन्ध) राज्य के आधीन हो” यह परिभाषा अधिक लचीली (elastic) प्रतीत होती है। इसके अनुसार ‘राजकीय संस्था’ से आशय केवल ऐसी ही संस्था से नहीं है, जिस पर पूर्णतः राज्य का स्वामित्व हो एवं जिसका प्रबन्ध भी राजकीय कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता हो, वरन् ऐसी संस्थाएँ भी राजकीय संस्थाओं की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं, जिन पर राज्य का केवल स्वामित्व ही हो (और उनका संचालन गैर-सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता हो) अथवा जिनका केवल प्रबन्ध ही राज्य के हाथों में हो (भले ही उनका स्वामित्व व्यक्तिगत उद्योगपतियों के पास हो)।

राजकीय स्वामित्व एवं नियंत्रण के उद्देश्य—

कुछ विशेष प्रवृत्ति की औद्योगिक संस्थाओं पर राजकीय स्वामित्व एवं नियंत्रण (Public Ownership and Control) क्यों हो, इस विषय पर एशिया तथा

सुदूर-पूर्व के आर्थिक आयोग (E. C. A. F. E — Economic Commission for Asia & Far East) के आधीन मार्च सन् १९५४ में रंगून में हुये एक सेमिनार में विचार किया गया एवं राजकीय स्वामित्व नियन्त्रण के निम्न उद्देश्य बताये गये :—*

(१) आधारभूत सेवायें प्रदान करना—राजकीय स्वामित्व एवं नियन्त्रण

राजकीय स्वामित्व एवं नियन्त्रण के उद्देश्य हैं ग्यारह

- (१) आधारभूत सेवायें प्रदान करना ।
- (२) व्यक्तिगत नियन्त्रण के स्थान पर सार्वजनिक नियन्त्रण की स्थापना करना ।
- (३) आयें बढ़ाना ।
- (४) एकाधिकार पर नियन्त्रण करना ।
- (५) धन का पुनर्वितरण करना ।
- (६) एक आवश्यक उद्योग को सह-मत्ता देना ।
- (७) औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना ।
- (८) अन्य उद्योगों के लिए आधार तैयार करना ।
- (९) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ।
- (१०) अकुशल प्राइवेट उपक्रम को हटाना ।
- (११) आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना ।

लिए, यदि किसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी पर केवल व्यक्तिगत नियन्त्रण रहना है, तो ऐसी दशा में सार्वजनिक हित कुप्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत उपक्रमी (Private Entrepreneur) अधिक से अधिक लाभ कमाने की भावना से बिजली की अधिक से अधिक रेट चार्ज करेगा और जनहित में कभी भी उद्योग की मशीनरी आदि का नवकरण नहीं करेगा और न कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह जानता है कि किन्हीं ही सराब मशीनरी एवं कितनी ही कम कार्यक्षमता से बिजली का उत्पादन करे, जनता को विवश हाकर उसकी ही शरण आना पड़ेगा और ऊँचे मूल्य पर भी बिजली का उपयोग करना पड़ेगा । इसी प्रकार, कभी-कभी कुछ

का प्रमुख उद्देश्य जनसाधारण की सेवा करना होता है । इसी हेतु प्रायः सभी आधारभूत सेवाओं पर राज्य का स्वामित्व एवं नियन्त्रण देखा जाता है । आधारभूत सेवाओं (Basic Service) के कुछ उदाहरण ये हैं :—जल-पूर्ति, विद्युत-शक्ति की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, इत्यादि । ये सेवायें जनसाधारण के आर्थिक कल्याण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से निरान्त आवश्यक होती हैं, अतः सरकार राष्ट्रीयकरण द्वारा इन सेवाओं को एक उचित स्तर पर बनाये रखने का प्रयास करती है ।

(२) व्यक्तिगत नियन्त्रण के स्थान पर सार्वजनिक नियन्त्रण की स्थापना करना—ऐसी अनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें व्यक्तिगत नियन्त्रण की अपेक्षा सार्वजनिक नियन्त्रण (Public Control) अधिक वाछनीय कहा जा सकता है । ऐसी परिस्थिति तब कही जा सकती है जबकि निजी एवं सार्वजनिक हितों में संघर्ष होता है । उदाहरण के लिए, यदि किसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी पर केवल व्यक्तिगत नियन्त्रण रहना है, तो ऐसी दशा में सार्वजनिक हित कुप्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत उपक्रमी (Private Entrepreneur) अधिक से अधिक लाभ कमाने की भावना से बिजली की अधिक से अधिक रेट चार्ज करेगा और जनहित में कभी भी उद्योग की मशीनरी आदि का नवकरण नहीं करेगा और न कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह जानता है कि किन्हीं ही सराब मशीनरी एवं कितनी ही कम कार्यक्षमता से बिजली का उत्पादन करे, जनता को विवश हाकर उसकी ही शरण आना पड़ेगा और ऊँचे मूल्य पर भी बिजली का उपयोग करना पड़ेगा । इसी प्रकार, कभी-कभी कुछ

* Vide Report of the Seminar on 'Organisation and Administration of public Enterprises in the Industrial field' held at Rangoon under the auspices of E. C. A. F. E. in the month of March, 1954, pp 28-29.

निजी व्यवसायी सार्वजनिक हित वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेते हैं एवं जनहित का ध्यान रखे बिना कार्य करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान में सार्वजनिक नियंत्रण का प्रतिस्थापन किया जाय।

(३) राजकीय आय बढ़ाना—कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कि आय की दृष्टि से बड़े उत्पादक हैं और यदि उन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाय, तो राजकीय आय में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है एवं जनता पर कर का कम से कम बोझ डालते हुये अनेक सार्वजनिक हित के कार्य किये जा सकते हैं। ऐसे उद्योगों पर राजकीय स्वामित्व एवं नियंत्रण होना ही चाहिए। यदि उनको निजी उपक्रम के लिये छोड़ दिया जाय, तो समाज की आय भुट्टी भर लोभों के हाथों में केन्द्रित हो जायगी। यही नहीं, फिर, निजी उपक्रमों पर अधिक टैक्स लगाकर भी सरकार उसे सरलता से वापिस नहीं ले सकती।

(४) एकाधिकार पर नियंत्रण करना—राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यह सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। ऐसे उद्योगों का स्वामित्व एवं नियंत्रण निश्चय ही सरकार के ही हाथों में रहना चाहिये, जिनसे एकाधिकार (Monopoly) की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले। यदि एकाधिकार की प्रवृत्ति का उन्मूलन नहीं किया गया, तो इससे जनता का अनावश्यक शोषण (exploitation) होने की आशंका रहनी है। प्रायः प्रत्येक समय देश में एकाधिकार के विरोध में सनियम बनाये गए हैं, परन्तु एकाधिकार का रोकने का श्रेष्ठ उपाय राष्ट्रीयकरण ही है।

(५) धन का पुनर्वितरण करना—आज विश्व के सभी देशों में यह आवाज सुनाई देती है कि निजी उपक्रम से धन का असमान वितरण होता है। इससे धनवान अधिक धनी और निधन अधिक दरिद्र होते जा रहे हैं। अतएव आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या धन के समान वितरण की है। इस समस्या के हल में उद्योगों पर राजकीय स्वामित्व एवं नियंत्रण होने से बहुत सुविधा हो जानी है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य 'लाभ कमाना' नहीं बल्कि 'सेवा करना' होता है। सरकार अपने मस्तिष्क में व्यक्तिगत अथवा किसी वर्ग विशेष के हित को नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित को रखनी है। समाज में धन का समान वितरण करना उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है।

(६) एक आवश्यक उद्योग को सहायता देना—कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं, जो लाभ पर नहीं चलाए जा सकते एवं जिनमें या तो हानि होती है अथवा केवल नाममात्र की ही लाभ होता है। उदाहरण के लिए, दो-तीन छोटे से गाँवों में यातायात की व्यवस्था करना। कोई भी व्यक्तिगत उपक्रमी कम जन-संख्या वाले गाँव में यातायात की व्यवस्था नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यदि वह निजी बस चलाए भी, तो पर्याप्त सवारियों और माल के अभाव में या तो उसे हानि होगी अथवा नाम मात्र का लाभ होगा। अतएव ऐसे उद्योगों व सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करके उनको सहायता देनी चाहिए।

(७) औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना—किसी देश में उपयुक्त औद्योगिक वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से यह जरूरी हो जाता है कि राज्य सर्व प्रथम अनुशासन बन कर पथ प्रदर्शन करे, जिससे कि बाद में निजी उपक्रमी भी उसके पीछे औद्योगीकरण की दिशा में प्रयास कर सकें ।

(८) अन्य उद्योगों के लिए आधार तैयार करना—राजकीय स्वामित्व एवं नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त आधार तैयार करना भी हो सकता है । उदाहरण के लिए, यदि सरकार कुछ गूँथगूँथ कच्चे माल का निर्माण करे अथवा औद्योगिक शक्ति प्रदान करे अथवा सस्ते यातायात की सुविधायें प्रदान करे, इत्यादि, तो इन सेवाओं से भविष्य में अनेक नए उद्योग पनप सकते हैं । इसलिए यदि कभी सरकार ऐसा अनुभव करे कि अमुक कच्चे माल के उत्पादन में अथवा अमुक सेवा की पूर्ति में अन्य उद्योगों के विकास का माग खुल सकता है, तो इसे पब्लिक सप्लाय स्वामित्व एवं नियंत्रण में ले लेना चाहिए ।

(९) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना—यदि कभी सरकार को ऐसा अनुभव हो कि कुछ उद्योगों पर राजकीय स्वामित्व एवं नियंत्रण के द्वारा समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धिता को जन्म मिलेगा, उत्पादन अधिक आर्थिक हो सकेगा, एकाधिकार की प्रवृत्ति समाप्त होगी एवं निजी उपक्रम में कार्यक्षमता की वृद्धि होगी, तो निश्चय ही सरकार को ऐसा करना चाहिए ।

(१०) अकुशल प्राइवेट उपक्रमों को हटाना—कभी कभी किंचित परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप किसी उद्योग में अकुशल इकाइयाँ बढ़ने लगती हैं । जनहित एवं राष्ट्रीय प्रगति की दृष्टि से ऐसी इकाइयों की वृद्धि स्थापन नहीं की जा सकती । अतएव यह वांछनीय ही नहीं बरन् अनिवार्य है कि सरकार ऐसे उद्योगों को अपने स्वामित्व एवं नियंत्रण में ले ले जिससे कि उसका विकास उचित प्रकार से हो सके ।

(११) आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना—अन्त में, यह सिखना अनावश्यक न होगा कि देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास का भार मुख्यतः सरकार पर ही होता है । अतः इस दिशा में नेतृत्व करना उसका कर्तव्य है ।

राजकीय उपक्रमों के विरुद्ध आरोप

(Objections against State Enterprises)

सरकारी उपक्रमों के कार्यवाहन की कुशलता के विषय में बहुत वाद विवाद किया जाता है । कुछ लोगों का मत है कि सरकारी उपक्रम प्राइवेट उपक्रमों की भाँति कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते, जबकि अन्य लोगों की सम्मति है कि सरकारी उपक्रम प्राइवेट उपक्रमों से अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं । सत्यता की खोज के लिये हमें प्राइवेट एवं सरकारी उपक्रमों की तुलनात्मक प्रगति

का अध्ययन करना होगा । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्राइवेट उपक्रमों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि सरकारी उपक्रम इने-गिने हैं । अतः एक सबसे अच्छी प्राइवेट संस्था की तुलना एक सबसे बुरी सरकारी संस्था से करके कोई उपयोगी निष्कर्ष नहीं निकल सकता । कुछ प्राइवेट उपक्रमों को छोड़कर शेष प्राइवेट उपक्रमों की दशा भी कुशलता की दृष्टि से आदर्श नहीं है । औद्योगिक वित्त निगम ने अनेक प्राइवेट उपक्रमों के अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि उनके कार्य-वाहन में बड़ी अकुशलता का प्रमाण मिलता है । अप्रैल सन् १९५६ में एक उद्योग-पति श्री जी० डी० सोमानी के गैर सरकारी प्रस्ताव पर (जोकि सरकारी उपक्रमों के संचालन की जाँच पड़ताल करने के हेतु एक कमेटी की नियुक्ति के सम्बन्ध में था) बोलते हुए तत्कालीन वित्तमन्त्री श्री देगमुख ने कहा था कि प्राइवेट उद्योगपति स्वयं काच के घरो में रहते हुए पब्लिक सैंक्टर के लोगों पर पत्थर न फेंकें ।

प्राइवेट उपक्रम के समर्थकों ने भारत में राजकीय उपक्रमों के कार्यवाहन के विरुद्ध निम्न आरोप लगाए हैं :—

(१) राजकीय उपक्रमों को अनेक प्रकार की छूटें—यह कहा जाता है कि राजकीय उपक्रमों को अनेक प्रकार की छूटें प्रदान की गई हैं, जाकि प्राइवेट उपक्रम के प्रति घोर अन्याय है, क्योंकि ये छूटें बहुत असाधारण हैं और उसी प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रजनों के हितों को हानि पहुँचाती हैं । उदाहरण के लिए, भारतीय कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ की धारा ६२० ने सरकार को सरकारी उपक्रमों को अधिनियम की कुछ धाराओं से मुक्त रखने का अधिकार दिया है ।

(२) सरकारी अधिकारियों में स्वतन्त्र विचारशक्ति का अभाव—कुछ सरकारी उपक्रमों के सरकारी अधिकारियों में, जो कि कुछ प्रशासनिक कार्यों में बहुत कुशल हो सकते हैं, स्वतन्त्र विचारशक्ति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक सेक्रेटेरियट द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन कराने मात्र का ही कार्य किया है, स्वयं सोचने का अधिक काम नहीं किया ।

(३) उच्च कर्मचारियों के बार बार ट्रांसफर—उच्च कर्मचारियों के प्रायः ट्रांसफर होते रहते हैं, जिससे न केवल मौद्रिक हानि होती है और नीति के कार्यवाहन में रुकावट पड़ती है वरन् राजकीय उपक्रम से सम्बन्धित व्यक्तियों में अनिश्चितता का वातावरण छा जाता है ।

(४) निहित स्वार्थों की नौकरी देने का साधन—राजकीय उपक्रम निहित स्वार्थ वालों को नौकरी देने के साधन बने हुए हैं । सत्तारूढ़ राजनैतिक दल के भाई भतीजों को नौकरी दे दी जाती है उनकी कुशलता-अकुशलता का कोई विचार नहीं रखा जाता । इस प्रकार राष्ट्र को बहुत हानि उठानी पड़नी है ।

(५) सरकारी विभाग का ही एक सुधरा हुआ रूप—अनेक राजकीय

राजकीय उपक्रमों के विरुद्ध

आठ आरोप

(१) राजकीय उपक्रमों को अनेक प्रकार की छूट दी जाती है ।

(२) सरकारी अधिकारियों में स्वतन्त्र विचारशक्ति का अभाव ।

(३) उच्च वर्गचरियों के बार बार दान्सफर ।

(४) निहित स्वार्थों को नौकरी देने का साधन ।

(५) सरकारी विभाग का ही एक सुधरा हुआ रूप होना ।

(६) कार्य संचालन में अवाछनीय हस्तक्षेप ।

(७) बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की दोषपूर्ण रचना ।

(८) आडिट व्यवस्था की सीमायें ।

की प्रथा है । किंतु इस नीति की कई सीमायें हैं जो कि इस प्रकार हैं—(१) उन्हें सस्था में कोई परामर्श देने में सकोच करते हैं, जिनमें उन्हें यह डर हो कि सरकार में उनका सम्मान कम हो जायगा, (२) ये सरकार को प्रसन्न करने कुछ और सुविधायें प्राप्त करने की भावना रखते हैं और प्रयास भी करते हैं, (३) जब उनके हिना की सरकारी उपक्रमों के हितों से टक्कर होती है, तो वे सरकारी उपक्रम को सही एवं ईमानदारी की राय नहीं दे पाते, (४) इनकी राय भले ही वह कितनी सही एवं राष्ट्रीयता से भरी-भरी हो, हैड क्वार्टर के निर्देशों द्वारा समर्थित सरकारी अधिकारियों की आवाज के सामने दब जाती है ।

(८) आडिट सम्बन्धी दोष—आडिटर जनरल द्वारा सरकारी उपक्रमों का जो वार्षिक आडिट किया जाता है वह ऐसे अफसरों की सहायता से किया जाता है जिन्हें इन उपक्रम के व्यापार से सम्बन्धित टेक्नीकल पहलुओं का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । इसके अतिरिक्त इन अफसरों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की उपेक्षा भी कर दी जाती है ।

उपक्रम सेक्रेटैरियट के आधीन कार्यालय मान बने हुए हैं । उन्हें नाम मात्र की स्वतन्त्रता एवं डील प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उन्हें थोड़े से भी महत्व के सभी मामलों में मंत्रालय की पूर्ण अनुमति लेनी पड़ती है तथा अधिकारियों की अधिवास नियुक्तियाँ मंत्रालय की अनुग्रह नियुक्तियाँ होती हैं ।

(६) कार्य-संचालन में अवाछनीय हस्तक्षेप—सरकारी उपक्रमों के सामान्य कार्य-चलाप में बहुत ही अवाछनीय क्षेत्रों में प्रायः हस्तक्षेप हुआ करता है । क्रय विक्रय और ठेके आदि के सम्बन्ध में तो बहुत ही बुरी तरह से प्रभाव डाला जाता है ।

(७) बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की त्रुटिपूर्ण रचना—सरकारी उपक्रमों के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में कुछ उद्योगपतियों और व्यापारियों को भी सम्मिलित करने

सरकारी उपक्रमों की कठिनाइयाँ—

भारत सरकार ने सन् १९५६ में सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये हार्वार्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैलब्रथ को नियुक्ति की थी। उन्होंने यह बताया है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध की उक्त आलोचनाएँ बहुत सीमा तक उन सीमाओं एवं कठिनाइयों के कारण हैं जो कि सरकारी उपक्रमों के स्वभाव में ही निहित हैं। ये सीमाएँ एवं बाधाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) सरकारी उपक्रमों से ऊँची आशाएँ रखी जाती है—एक प्राइवेट फर्म

में वेतन एवं स्टाफ की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपर्याप्तता एवं असमानता होना कोई असाधारण बात नहीं समझी जाती है। यदि उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई त्रुटि हो भी जाय, तो उसे सुधारने के लिये उस कर्मचारी को अधिक सम्मानपूर्ण किन्तु कम महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। इनमें प्रबन्ध की कठोरता न केवल एक साधारण घटना समझी जाती है वरन् उसका समर्थन भी किया जाता है। प्राइवेट संस्थाओं में अंतिम परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाता है और जनता की ओर से आलोचना का डर भी नहीं होता। लेकिन ये सब बातें एक सरकारी उपक्रम के बारे में उचित नहीं समझी जाती हैं।

सरकारी उपक्रमों की पाँच सीमाएँ

(१) सरकारी उपक्रमों से ऊँची आशाएँ रखी जाती हैं।

(२) प्रबन्धक अफसरों में आलोचनाओं से बचने की प्रवृत्ति होती है।

(३) एक उत्पादक संस्था का प्रबन्ध सरकार के साधारण प्रशासन से भिन्न होता है।

(४) सरकारी उपक्रम की सफलता व्यक्तियों की अपेक्षा सगठन पर अधिक निर्भर है।

(५) प्रतियोगिता का अभाव अकुशलता को बढ़ावा देता है।

(२) प्रबन्धक अफसरों में आलोचनाओं से बचने की प्रवृत्ति होती है—चूँकि सरकारी उपक्रमों के लिए ऊँचे ऊँचे आदर्श निर्धारित होते हैं, इसलिए एक जनतन्त्री सरकार में अधिकारियों एवं मन्त्रियों की प्रवृत्ति आलोचना से बचने की होती है। विकेंद्रीकरण एवं स्वशासन के सिद्धान्त पर कबम व्याख्यानों में ही बल दिया जाता है, लेकिन व्यवहार में इन उपक्रमों में 'सुरक्षा प्रथम' (Safety First) के सिद्धान्त की ही प्रमुखता दी जाती है।

(३) एक उत्पादक संस्था का प्रबन्ध सरकार के साधारण प्रशासन से भिन्न होता है—उसमें प्रायः अधिक टेक्नीकल योग्यता की आवश्यकता पड़ती है।

(४) सरकारी उपक्रम की सफलता व्यक्तियों की अपेक्षा सगठन पर अधिक निर्भर होती है—एक व्यक्ति जितनी सफलता प्राप्त कर सकता है उससे कहीं अधिक सफलता एक सगठन को प्राप्त हो जाती है। 'सगठन' (Organisation) के अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यवाही की अनिश्चितताओं एवं कमियों की पूर्ति हो जाती है। प्रो० गैलब्रथ ने इस बात को जनरल मोटर्स और टी० बी० ए० का उदाहरण देकर स्पष्ट

किया है। ये दोनों सस्थाएँ मिलकर किसी भी उत्पादन कार्य को भली प्रकार कर सकती हैं। लेकिन, यदि इन दोनों में कोई एक व्यक्ति नियत कर दिया जाय, तो वह एक ओटोमोबाइल या डीजल लोकोमोटिव उद्योग का उचित विकास करने में कदापि सफल नहीं हो सकता।

(५) प्रतियोगिता का अभाव अकुशलता को बढ़ावा देता है—चूँकि एक सरकारी उपक्रम की निमित्त वस्तुओं की स्वतन्त्र बाजार में प्रायः प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए उनमें निर्णय की शीघ्रता व कार्य करने की तत्परता उतनी मात्रा में नहीं होती है जितनी वे एक प्राइवेट उपक्रम में होती है। इसके अनिश्चित एक सरकारी उपक्रम में न केवल उपभोक्ता को बरन् राष्ट्रीय संपत्ति होने के नाते एक कर-दाता, नागरिक, सरकार, संसद सभी को रुचि होती है। वे उसके कार्यवाहन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिये उत्सुक रहते हैं। चूँकि सरकारी उपक्रम का उद्देश्य एक उचित मूल्य पर जनता की आवश्यकता को पूरा करना होता है, इसलिए वह प्राइवेट उपक्रम की भाँति ऊँचे लाभ नहीं कमा सकता और न केवल लाभ कमाने से जनता संतुष्ट हो सकती है। इस प्रकार एक सरकारी उपक्रम के माध्य में अनेक कठिनाइयाँ स्वभाव से ही मौजूद होती हैं, जो कि प्राइवेट सस्था की दशा में नहीं पाई जाती हैं।

राजकीय उपक्रमों के विभिन्न रूप*

(Forms of Public Enterprises)

जैसा कि हम राजकीय उपक्रम की परिभाषा देते समय सकेत कर चुके हैं, राजकीय उपक्रम के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रूपों का विस्तृत विवेचन नीचे प्रस्तुत किया गया है :—

(1) संस्थाएँ जिन पर स्वामित्व राज्य का हो एवं प्रबन्ध प्राइवेट एजेंसियों द्वारा किया जाता है (Enterprises Owned by the State but Managed by Private Agencies)—

इस प्रकार के राजकीय उपक्रमों का सबसे ज्वलन्त उदाहरण हरकेला की हिंदुस्तान स्टील कम्पनी है, जिस पर यद्यपि स्वामित्व भारत सरकार का है तथापि प्रबन्ध एक जर्मन फर्म अप-डेमस के हाथ में है। प्रारम्भिक स्थापना के उद्देश्य से सिन्दरी खाद व रसायन कारखाने का प्रबन्ध भी अमेरिका के कैमोकन कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के हाथ में दे दिया गया था। इस प्रकार का राजकीय उपक्रम उन दशाओं के लिये उपयुक्त होता है जिनमें सस्थाओं का सरकारी स्वामित्व जन-हित की रक्षा

* Vide "A Study of Public Enterprise in the State of Madhya Bharat during the last fifty years." —Approved Thesis of S. C. Saxena for the Ph. D. degree of Agra University, pp. 42-61.

के लिये आवश्यक हो, किन्तु पूँजी, व्यापारिक योग्यता एवं टेक्नीकल ज्ञान के अभाव के कारण सरकार उस सस्था का प्रबन्ध करने में असमर्थ हो ।

(II) संस्थाएँ जिनका स्वामित्व एवं प्रबन्ध एक सरकारी विभाग के पास हो (Enterprises Owned and Managed by a Government Department) —

इस प्रकार के उपक्रमों के निम्न उदाहरण हैं—रेलवे, डाक व तार, सुरक्षा

- राजकीय उपक्रम के रूप हैं सात
- (I) सस्थाएँ जिन पर स्वामित्व राज्य का हो एवं प्रबन्ध प्राइवेट एजेंसियों द्वारा किया जाता है ।
 - (II) सस्थाएँ जिनका स्वामित्व एवं प्रबन्ध एक सरकारी विभाग के पास हो ।
 - (III) कमेटी अथवा बोर्ड के अन्तर्गत विभागीय प्रबन्ध वाली राजकीय सस्थाएँ ।
 - (IV) पब्लिक कम्पनियों के रूप में राजकीय सस्थाएँ ।
 - (V) वैधानिक अथवा लोक-नियम ।
 - (VI) मिश्रित स्वामित्व वाले निगम ।
 - (VII) पब्लिक ट्रस्ट ।

उद्योग, राजकीय व्यापार, हीराकुण्ड और भाखरा नामक परियोजनाएँ आदि । चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स, डी० डी० टी० फैक्टरी, पैनिसिलिन फैक्टरी, नेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट्स फैक्टरी एवं सरकारी नमक कारखाना अन्य उदाहरण हैं । यद्यपि भारत में पृथक् एवं स्वशासित एजेंसियों की स्थापना की प्रवृत्ति बढ़ रही है तथापि विभागीय प्रबन्ध अब भी व्यापक रूप से प्रचलित है । इस प्रकार के संगठन की प्रमुख विशेषताये निम्नलिखित हैं :—

विशेषताये—

(१) उपक्रम के अर्थ-प्रबन्धन के लिये वार्षिक रकम ट्रेजरी से प्राप्त होती है और उसकी समस्त आय ट्रेजरी में जमा होती रहती है ।

(२) अन्य सरकारी क्रियाओं के समान इस उपक्रम पर भी बजट व ब्राडिट सम्बन्धी नियम लागू होते हैं ।

(३) उपक्रम का स्थाई स्टाफ सिविल सर्विस से लिया जाता है । उनकी भरती का दाय एवं सेवा सम्बन्धी शर्तें अन्य सरकारी नौकरों के समान होती हैं ।

(४) उपक्रम का संगठन केन्द्रीय सरकार के एक विभाग के ब्यूरो के रूप में किया जाता है और विभागीय प्रमुख के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में होता है ।

(५) उपक्रम पर सरकार की अनुमति के बिना मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है ।

गुण-दोष—

इस प्रकार की संगठन प्रणाली का उपयोग तब किया जाता है जबकि उपक्रम का मुख्य उद्देश्य आय प्रप्त करना या उपभोग पर नियन्त्रण करना हो ।

विभागीय प्रबन्ध की मुख्य दुर्बलता इस बात में है कि यह पट्टन करने की भावना और सचनता के विरुद्ध है। इस समयन-प्रणाली के अन्तर्गत, राजकीय उपक्रम में साल पीठा, विलम्ब, अपर्याप्त सेवा, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति उपेक्षा आदि दोष पाये जाते हैं। विभी कार्य को करने के सम्बन्ध में बहुत से अधिकारियों से परामर्श लेना पड़ता है। अधिकार क्षेत्रों के स्पष्ट रूप में परिभाषित न होने के कारण विभिन्न स्तरों पर अधिकारी गलत निर्णय करते हैं हिचकते हैं, बिम्ब के परिष्कार-स्वरूप कार्य विधि बहुत देर से पूर्ण होती है। विभागीय प्रबन्ध में शोध कार्यवाही करने की क्षमता का अभाव होता है। एक साधारण व्यापारिक सस्या में यातायात या तो टेलीफोन पर अथवा इन्टरव्यू द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात् एक सशुद्ध पत्र पुष्टि के लिए इम्बू होता है। लेकिन विभागीय प्रबन्ध के अन्तर्गत यह कार्यवाही बहुत विलम्बपूर्ण होती है। किसी खास समय में काफी सम्भावना इस अधिकारी की तिला जाता है जिससे परामर्श लेना है। पत्र प्राप्त होने पर वह अधिकारी उस पर विचार करता है तथा सूचित करता है। इसमें यदि महीनों की नही तो कम से कम कई सप्ताह की देर तो लग ही जाती है।

विभागीय प्रबन्ध वाले राजकीय उपक्रम मन्त्री एवं ससद के नियन्त्रण में होते हैं और उनके प्रशासन की छोटी से छोटी बात पर भी ससद में वाद-विवाद किया जाता है। इससे इस प्रकार के समठन में बहुत दुबलता आ गई है। व्यवहार में इसका अभाव यह होता है कि सम्बन्धित मन्त्रि महोदय एवं उनके तत्कालिक परामर्श-दाताओं पर छोटी छोटी बातों का कार्य होना अधिक हो जाता है कि वे नीति एवं योजना सम्बन्धी बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। नीति एवं वित्त सम्बन्धी प्रस्ताव पर विधान सभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय विधान सभा द्वारा माताचना एवं अनुचित हस्तक्षेप का अब कार्य करने की स्वतन्त्रता को कुठिल कर देता है। इन सब दोषों के कारण यह कि उन प्रणाली उन व्यापारिक उपक्रमों के लिये उपयुक्त नहीं है जिनमें शीघ्र विकास की आवश्यकता है।

(III) कमेटो अथवा बोर्ड के अन्तर्गत विभागीय प्रबन्ध वाले राजकीय संस्थाएँ (Departmental Management under Committee or Boards)---

सचक ताने एवं निर्णय का अवसर देने की दृष्टि से कुछ विभागीय प्रबन्ध वाले उपक्रमों के लिये विभिन्न मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की कमेटो या बोर्ड की स्थापना का गई है। उदाहरण के लिए, सिदरी खाद कारखाने की स्थापना एवं निर्माण के लिए तथा सरकारी हार्सिंग फंडरी के लिए अन्तर मन्त्रालय कमेटो (Inter-ministerial Committee) की रचना हुई थी। ऐसी कमेटो बनाने का कारण यह था कि योजना बनाने और उप कार्यान्वित करने के विभिन्न स्तरों पर प्रायः कई मन्त्रालयों की सहमति एवं स्वीकृति की आवश्यकता पड़ा करती थी। धुनि

* "The Government department is a strictly hierarchical institution at whose head is a Minister answerable to cabinet and to Parliament for its activities. The administration of the department naturally is largely in the hands of its senior civil servants and financial control rests with the treasury."

(Hugh Clogg : Industrial Democracy and Nationalism, p 38)

जुटानी पड़ती है, जल-पूर्ति और बिजली की व्यवस्था करनी पड़नी है, रेलवे अथवा अन्य यातायात सुविधाओं का प्रबन्ध करना पड़ता है, स्टॉक खरीदने होते हैं तथा बिल्डिंग इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, अतः कमेटीयों और बोर्डों में फाइनैन्स मिनिस्ट्री के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के कारण व्यय के बारे में तुरन्त निर्णय करना सुविधाजनक हो जाता है।

(IV) पब्लिक कम्पनियों के रूप में राजकीय संस्थाएँ (State Enterprises Managed like a Company) —

राजकीय उपक्रम जो चौपा रूप ग्रहण कर सकते हैं वह हैं एक स्वशासित संस्था का। ऐसी स्वशासित संस्था (autonomous authority) के दो प्रकार हो सकते हैं—(1) एक संयुक्त स्वन्ध कम्पनी, जिसकी रजिस्ट्री कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कराई जाय और (2) एक सार्वजनिक निगम, जिसका जन्म एक विशेष विधान के निर्माण द्वारा होता है।

संयुक्त स्वन्ध कम्पनी और कम्पनी प्रबन्ध के अन्य प्रकारों के सम्बन्ध में सश्रियम के विचार व साथ साथ सरकारों ने राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों का प्रबन्ध करने के हेतु स्वशासित कम्पनियों के संगठन पर अधिकाधिक ध्यान देना आरम्भ कर दिया है। इस प्रकार सरकार उपक्रम में एक शेयर होल्डर बन जाती है और सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा कैबिनेट या राज्य के प्रमुख द्वारा शेयर होल्डर के अधिकारों का प्रयोग करती है।

राज्य उपक्रमों के प्रबन्ध का कम्पनी-प्रारूप व्यापारिक प्रकृति वाले उपक्रमों के लिए, अपने लोचपूर्ण स्वभाव के कारण, विशेष रूप से उपयुक्त होता है। गत कुछ वर्षों में इन सिद्धान्त ने भारत सरकार की नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस प्रकार की प्रबन्ध-व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालिका अधिकारियों को अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है और उन्हें केवल कम्पनी अधिनियम के प्रतिबन्धों का ही ध्यान रखना पड़ता है। वस्तुधा के निर्माण एवं विक्रय से सम्बन्ध रखने वाली अनेक राजकीय संस्थाओं ने इस प्रबन्ध व्यवस्था को अपनाया है, जैसे—सिंदरी खाद व रसायन कारखाना, चिनरखन कोकोमोटिड, हिन्दुस्तान एयर क्लैप्ट फैक्ट्री, हिन्दुस्तान शिम-माई आदि।

यद्यपि इस प्रकार की प्रबन्ध-व्यवस्था के अन्तर्गत स्वशासन के विकसित होने की आशा थी तथापि व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया है। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में विभागीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है और ये अपनी व्यक्तिगत स्थिति में कुछ कार्य करने के लिये प्रयत्न अथवा असमर्थ होते हैं। अतः उन्हें प्रश्नों पर अपने विभागों से विचार-विमर्श करना पड़ना है। अतः भारत में बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की सदस्यता न केवल सदस्य-सदस्यों अथवा मन्त्रियों के लिये खुली रखी गई है वरन् व्यापक अनुभव वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है।

(v) **वैधानिक अथवा लोक निगम द्वारा प्रबन्धित राजकीय सस्थाये (State Enterprises Managed by a Statutory or Public Corporation)**—

साधारणतः वैधानिक अथवा लोक निगम (Public Company) को सार्वजनिक कम्पनी (Public Corporation) का पर्यायवाची समझते हैं। पब्लिक कम्पनी वास्तव में संयुक्त पूँजी वाली एक ऐसी सस्था होती है, जिसका प्रबंध पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपक्रमियों द्वारा होता है तथा सरकार का उसकी क्रियाओं पर विशेष नियंत्रण रहता है। यह नियंत्रण कम्पनी अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत लोकनिगम या पब्लिक कॉर्पोरेशन से आशय एक ऐसी सस्था से है, जिसका हेतु व्यक्तिगत उपक्रमियों की भांति सोच अथवा औद्योगिक कुशलता प्राप्त करना होता है और जिसकी सामान्य नाति पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा जिसके संचालक की नियुक्ति सरकार करती है जो सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं अर्थात् संचालकों की दैनिक क्रियाओं में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। इस प्रकार पब्लिक कॉर्पोरेशन एक स्वतन्त्र अस्तित्व रखने वाली सस्था है, जिस पर बाध प्रस्तुत किया जा सकता है एवं जो स्वयं भी बाध प्रस्तुत कर सकती है तथा जो अपने अथ प्रबंध के लिये उत्तरदायी होती है।^१

जो सथायें व्यापारिक प्रकृति की नहीं हैं उनके प्रबंध एवं नियंत्रण के लिये यह स्वरूप अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि, जैसा कि स्वर्गीय प्रसीडेन्ट रूजवेल्ट ने कहा है कि, "पब्लिक कॉर्पोरेशन को वे समस्त लाभ एवं अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि राजकीय सथा का होने चाहिए और इसके अतिरिक्त इनमें वह सब और स्वतन्त्रता भी होती है जो कि व्यक्तिगत उपक्रम की विशेषता है। हबर्ट मोरिसन ने भी कहा है पब्लिक कॉर्पोरेशन की श्रेष्ठता का कारण यह है कि इसमें सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजकीय स्वामित्व, राजकीय उत्तरदायित्व एवं व्यापारिक प्रबंध तीनों का मिश्रण होता है।"^२

स्वामित्व तथा पूँजी के आधार पर पब्लिक कॉर्पोरेशनों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है —

1. 'The Public Corporation is a body with a separate existence which can sue and be sued and is responsible for its own finances

(Earnest Davies M P The Future of Public Corporations) "

2 Public Corporations are though to be the ideal form of business because in the words of the Late President Roosevelt 'they are clothed with the power of Government but Possessed of the flexibility and initiative enterprise Or again in the words of Herbert Morrison because in them is to be found a combination of public ownership public accountability and business management for public ends'

- (१) ऐसा पब्लिक कारपोरेशन जिसकी कुल पूंजी, केन्द्रीय अथवा राजकीय या केन्द्रीय एवं राज्यीय सरकार द्वारा खरीद ली जाती है। ऐसे लोक नियमों का उदाहरण है दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation) ।
- (२) मिश्रित निगम—मिश्रित निगम (Mixed Corporations) वे निगम हैं, जिनकी पूंजी का अधिकांश भाग केन्द्रीय एवं राज्यीय सरकारों द्वारा तथा कुछ भाग, जो कुल पूंजी के साधारणतः २०% से अधिक नहीं होता, व्यक्तिगत उपक्रमों द्वारा खरीदा जाता है। ऐसे निगम के उदाहरण हैं—औद्योगिक अर्थ निगम (Industrial Finance Corporation), राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) इत्यादि ।

पब्लिक कारपोरेशन की विशेषतायें

पब्लिक कारपोरेशन की कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(१) राज्य का पूर्ण स्वामित्व—पब्लिक कारपोरेशन पर पूर्णतः राज्य का ही स्वामित्व होता है ।

(२) विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण—पब्लिक कारपोरेशन का उद्गम पार्लियामेंट के विशेष अधिनियम (Special Statute of the Parliament) द्वारा होता है, जिसमें उसकी शक्तियाँ, कर्तव्य एवं छूटों का उल्लेख किया जाता है । उसके प्रबन्ध की क्या व्यवस्था होगी तथा सरकारी विभागों एवं मंत्रालय से उसका क्या सम्बन्ध हो, इस पर भी उसमें प्रकाश डाला गया होता है । इस प्रकार एक पब्लिक कारपोरेशन की एक विशेष स्थिति होती है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ एवं कर्तव्यों की स्पष्ट व निश्चित परिभाषा कर दी जाती है । इससे निगम उस स्वशासन का उपभोग कर सकता है जो कि सस्था की कुशलता के लिये बहुत आवश्यक होता है । लेकिन स्वशासन का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि वह साधारण सिविल व क्रिमिनल कानूनों के प्रभाव से मुक्त है । उसे भी देश के कानूनों का उसी तरह पालन करना पड़ता है जिस तरह अन्य संस्थायें करती हैं ।

(३) स्वतन्त्र वैधानिक अस्तित्व—पब्लिक कारपोरेशन एक स्वतन्त्र वैधानिक अस्तित्व वाली संस्था होती है, जिस पर दावा हो सकता है और जो स्वयं भी दावा कर सकती है । यह अनुबन्ध करने की क्षमता रखती है और अपने नाम में सम्पत्ति भी प्राप्त कर सकती है । तामसिन बनाम हन्ताफोर्ड के मामले में लार्ड जस्टिस बेंगिन द्वारा दिये गये निम्न निर्णय से एवं पब्लिक कारपोरेशन की वैधानिक स्थिति मजबूत प्रकार स्पष्ट हो जाती है—“संनियम की दृष्टि में, कारपोरेशन स्वयं अपना स्वामी होता है और अन्य व्यक्तियों व निगमों की भाँति ही पूर्णतः जबाबदेह होता है । किन्तु वह राजा नहीं है और उसे राजा के समान विशेष छूटें भी प्राप्त नहीं होती हैं ।

इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। वह राजा के किसी अन्य प्रजा-जन की भाँति पार्लियामेंट के अधिनियमों से बाधित होता है। निस्संदेह वह एक सार्वजनिक सत्ता है और उसके उद्देश्य भी सार्वजनिक होते हैं, लेकिन वह एक सरकारी विभाग नहीं है और न इसकी शक्तियाँ सरकार के क्षेत्र में आती हैं।^१

(४) निजी स्वार्थ का अभाव—एक पब्लिक कॉरपोरेशन की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता उसमें 'निजी स्वार्थ का अभाव' होना है। रोबसन (Robson) ने इसे 'उदासीनता' (Disinterestedness) की संज्ञा दी है। इसका यह अर्थ है कि पार्लियामेंट के अधिनियम द्वारा उसके लिये जो उद्देश्य या स्वार्थ निश्चित कर दिया गया होता है उसके अतिरिक्त कोई अन्य स्वार्थ कारपोरेशन को नहीं होता। दूसरे शब्दों में, वह अपने वैधानिक उद्देश्य के अनिर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने में रुचि नहीं लेता अथवा उदासीन रहता है। किंतु अपने वैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह बहुत सचेत होता है, क्योंकि उसका जन्म ही इस हेतु हुआ था। उसमें लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। किंतु इसका यह आशय नहीं है कि उसे लाभ पर नहीं चलाया जा सकता। वास्तव में 'लाभ' शब्द का प्रयोग इसके लिये कुछ अनुपयुक्त है। इससे अधिक श्रेष्ठ शब्द 'आधिक्य' (Surplus) है, जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए।

(५) स्वतन्त्र वित्त-व्यवस्था—पब्लिक कारपोरेशन का अर्थ प्रबन्ध स्वतन्त्र रूप से होता है। उसे अपनी पूँजी ट्रेजरी अथवा पब्लिक से ऋण लेकर या वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय की आय से प्राप्त होती है और वह आय का पुनः विनियोग भी कर सकता है।

(६) सार्वजनिक कोषों के व्यय सम्बन्धी नियमों से मुक्ति—साधारणतः एक पब्लिक कारपोरेशन सार्वजनिक कोषों के व्यय सम्बन्धी अनेक नियमों एवं प्रतिबन्धों से मुक्त होता है।

* In the eye of the law the corporation is its own master and is answerable as fully as any other person or corporation. It is not the Crown and has none of the immunities or privileges of the Crown. Its servants are not civil servants and its property is not Crown property. It is as much bound by Acts of Parliaments as any other subject of king. It is, as much bound by Acts of Parliaments as any other subject of king. It is, of course, a public authority, and its purposes, no doubt, are public purposes. But it is not a Government Department, not do its powers fall within the province of Government."

(Judgement of Lord Justice Benning given in the Tamlin Vs Harbaurd cases. Quoted by W. A. Robson in his book "Problems of Nationalised Industry" 1952, pp. 40-41)

(७) वजट सम्बन्धी नियमों से मुक्ति—वजट, लेखा कर्म एवं ग्राडिट सम्बन्धी नियमों तथा कार्य-विधियों से भी जो कि एक असमामेलित (non-corporate) संस्थाओं को लागू होते हैं, पब्लिक कारपोरेशन मुक्त होता है ।

(८) कर्मचारियों की नियुक्ति आदि—अधिकांश दशाओं में पब्लिक कॉरपोरेशनों के कर्मचारी सरकारी नौकर नहीं माने जाते और कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ही उनकी भरती की जाती है व पुरस्कार दिया जाता है ।

पब्लिक कॉरपोरेशन के लाभ—

पब्लिक कॉरपोरेशन के आधीन सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध से निम्नलिखित लाभ होते हैं :

- (अ) सरकार का उद्योग की दैनिक प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं होता, जिससे उसकी कार्यक्षमता में बाधा नहीं पड़ती ।
- (आ) पब्लिक कारपोरेशन की क्रियाओं में अधिकतम लोच तथा औद्योगिक निर्यात की स्वतन्त्रता होती है ।
- (इ) पब्लिक कॉरपोरेशन सरकार के वैधानिक नियन्त्रण में होने के कारण उसकी सामान्य नीति राष्ट्रीय सरकार की नीति के अनुकूल होती है ।
- (ई) पब्लिक कॉरपोरेशन उद्योग के प्रबन्ध सम्बन्धी आन्तरिक मामलों में पूर्ण स्वतन्त्र होता है, फलतः उद्योग का विकास अच्छी तरह होता है ।
- (उ) पब्लिक कॉरपोरेशन में राष्ट्रीयकृत उद्योग की क्रियाओं का दायित्व सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों पर होता है, जिनकी नियुक्ति योग्यता एवं निपुणता के आधार पर होती है ।
- (ऊ) पब्लिक कॉरपोरेशन अपने प्रबन्ध में जन-सेवा का परिचय देते हैं एवं नौकरशाही का अन्त करने के लिए तत्पर रहते हैं तथा अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के हेतु आर्थिक स्वावलम्बता की ओर प्रयत्न करते हैं । इन्हीं लाभों के कारण किसी ने ठीक ही लिखा है कि पब्लिक कॉरपोरेशन का भविष्य अत्यन्त ही उज्ज्वल है और प्रायः सभी प्रगतिशील देशों के निर्माण में इनका अद्वितीय भाग रहेगा ।

पब्लिक कॉरपोरेशन के दोष —

(१) इतने लाभ होने हुए भी पब्लिक कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा दोष यह है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ-साथ इसके सविधान में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है । जब तक कि उस अधिनियम में, जिसके द्वारा कि इसका जन्म हुआ है, संशोधन न कर दिया जाय, तब तक इसके सविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है ।*

* The advantage of the Corporation is that it has a special legislation made for peculiar needs; its disadvantage is that when conditions alter substantially, no change can be made without amending the Legislation."

(A. D. Gorbala Report on Efficient Conduct of State Enterprises, pp. 18-19).

(२) कॉरपोरेशन प्रणाली की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत बिल्कुल नया स्टाफ भरती करना पड़ना है। अतः यह सम्भव है कि पर्याप्त एवं उपयुक्त स्टाफ न मिल सके। दामोदर घाटी निगम को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उसे अपना कार्य आरम्भ करने से ३० माह तक बिना मुख्य इंजीनियर के काम चलाना पड़ा था।

(३) इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेशन की स्थापना करने से सरकारी अधिकारों एवं ससदीय नियंत्रण में कमी हो जाती है। इससे सरकारी क्षेत्रों में द्वेष भावना विसृत होने का भय है। वास्तव में इसी प्रकार की कठिनाई का सामना भी दामोदर घाटी निगम को करना पड़ा था। निगम के इतिहास का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे अपनी स्वशासनता कायम रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा।^१

(४) आजकल इन कॉरपोरेशनों के विरुद्ध यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे जर्जियनहाल और आर्द्धित सम्बंधी सरकारी अधिकारों का उल्लंघन करने का यत्न करते हैं। पब्लिक प्रकाउन्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी भी इस सम्बन्ध में अपने को असमर्थ पाती हैं। यह सुभाव दिया जाता है कि पब्लिक कारपोरेशनों के निरीक्षण के लिये एक पृथक् ससदीय कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये।

इन दोषों के होते हुये भी, दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में नियुक्त की गई राय कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि बहुमुखी योजनाओं के कुशल एवं मितव्ययितापूर्ण संचालन के लिये सर्वोत्तम प्रबन्ध व्यवस्था कारपोरेशन प्रणाली ही है। यह इसलिये ऐसा है कि कॉरपोरेशन प्रणाली के अन्तर्गत विभागीय हस्तक्षेप, वित्त नियंत्रण और लाल फीसाशाही के दोष, जो कि सरकारी प्रशासन की विशेषताएँ हैं और जो कार्य-संचालन की गति एवं कुशलता में बाधक होते हैं, नहीं पाये जाते हैं। वस्तुतः यदि कहीं कारपोरेशन असफल हुये हैं तो कारपोरेशन-प्रणाली के किसी स्वाभाविक दोष के कारण नहीं बल्कि कारपोरेशन के कमबारी वर्षों या सरकारी विभागों की त्रुटि से हुये हैं।^२ अतः यह निश्चित है कि २०वीं शताब्दी में पब्लिक कारपोरेशन वही भूमिका भदा करेंगे जो कि गत १०० वर्षों में पब्लिक कम्पनियों ने की है।^३

1. "The history of D. V. C. appears to have been a series of unedifying episodes in which, so far as one can make out, the corporation has had to use a great deal of its energies in attempting to maintain its autonomy"

(Gorwala A. D. : Report, cited above, p 33)

2. "Where it has failed, the fault lies with the personnel of the corporation or of Government departments or of both, rather than with anything inherent in the corporation concept itself."

(The Statesman, Calcutta, Dated 4-11-1953)

3. There is little doubt, therefore, that the public corporation is destined to play as important a role in the latter part of the 20th Century as the joint stock company has played during the last 100 years."

(Robson : Problems of Nationalised Industry.)

पब्लिक कारपोरेशन क्यों कर सफन हो ?

पब्लिक कॉर्पोरेशन की सफनता के लिये अरनेस्ट डेविस ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(१) सरकारी उपक्रम पर उत्तरदायी मन्त्री के माध्यम से सरकार का अधिकतम नियन्त्रण हो, जिससे कि उद्योग का संचालन राज्य की सामान्य नीति के अनुसार हो सके, परन्तु यह आवश्यक है कि जो भी नियन्त्रण हो वह राष्ट्रीय हित की दृष्टि से होना चाहिये । प्रतिदिन की क्रियाओं में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।

(२) मन्त्री के अधिकारों को इस प्रकार सीमाबद्ध किया जाय कि जिसमें इनका उपयोग स्वच्छन्दता से न होते हुए सद्भावना और सहयोग के साथ हो, इसलिये ऐसा उपयोग करने के पूर्व मन्त्री को नीति सभा (Policy Board) की सलाह लेना अनिवार्य है । यह सभा उद्योग के तात्त्विक संचालन के लिये विशेषज्ञ सभा होती है और उद्योग सम्बन्धी मामलों में मन्त्री की अपेक्षा अधिक जानकारी होगी ।

(३) मन्त्री नीति सभा की सफलता के लिए सम्पूर्ण समाज के प्रति उत्तरदायी होगा, इसलिए उसको समाज का हित भी देखना चाहिये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक त्रिपक्षीय सलाहकार समिति होनी चाहिये, जो उद्योग की जाँच कर सके तथा स्वयं अपनी इच्छा में समाज का प्रतिनिधित्व करे । ऐसी समिति में समाज के सभी वर्गों—धर्म, पूँजी, उपभोक्ता, व्यापार परिषद् आदि के प्रतिनिधि होंगे ।

(४) सरकारी उद्योगों के प्रबन्ध में जन साधारण की रुचि और उसका विश्वास पैदा करने के लिये आवश्यक है कि उनमें स्थानीय निपुणता को स्थान मिले, तथा स्थानीय समस्याओं की दृष्टि में सम्बन्धित उद्योग की स्थानीय नीति अपनाई जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक उद्योग के विभिन्न स्थानीय उपक्रमों के प्रबन्ध की नीति देश-हित में रखी जाय, किन्तु स्थानीय नीति एवं उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण हो ।

(५) सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने के लिये प्रत्येक स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का आयोजन होना चाहिये ।

(६) पब्लिक कारपोरेशन के सम्बन्ध में पार्लियामेंट ही अन्तिम मध्यस्थ रहेगी । सरकारी स्वामित्व के लिये सरकारी उत्तरदायित्व भी आवश्यक है, इसलिये किसी मन्त्री को अपना दायित्व टालना नहीं चाहिए, वरन् ससद में पूछे गये सम्बन्धित सभी प्रश्नों का उत्तर देने की तत्परता होनी चाहिए तथा ऐसी सामयिक चर्चाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन की क्रियाओं का प्रकाशन ही कुशलता के विरुद्ध सुरक्षा का सबसे सुन्दर साधन है ।

इस सम्बन्ध में यह कहना अनावश्यक न होगा कि भारतीय ससद में ऐसी चर्चाएँ नाम मात्र की ही होती हैं । सच बात तो यह है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों

के सम्बन्ध में जनता को विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिये भारत सरकार को समय-समय पर विभिन्न सरकारी उपक्रमों की पूर्ण जानकारी देने वाला साहित्य प्रकाशित करना चाहिए।

(७) नीची समिति के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उपलब्ध व्यक्तियों में से अधिकतम निपुण एवं अनुभवों व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए, जो सस्था की बागडोर भली प्रकार समाल सकें एवं मुबाल प्रबन्ध के हेतु उचित सलाह दे सकें।

इस दिशा में भारत सरकार को चाहिए कि केन्द्रीय औद्योगिक सेवा आयोग (Central Industrial Service Commission) का निर्माण करे और उसे विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का भार सौंप दे। केवल इसी मार्ग द्वारा देश की उपलब्ध औद्योगिक एवं तात्त्विक कुशलता की साम सरकारी उपक्रमों को मिल सकेगा।

(VI) मिश्रित स्वामित्व वाले निगम (Mixed Ownership Corporations)—

कम्पनी नमूने के उपक्रम में अनेक रूपान्तर हो गये हैं, क्योंकि सरकार विनियोग में केवल आंशिक भाग लेना चाहती थी अथवा प्रबन्ध कार्य पूर्णतः आंशिक रूप में प्राइवेट उपक्रम पर ही छोड़ देना चाहती थी। इस प्रकार की मिश्रित कम्पनियों अथवा निगमों को प्राइवेट उपक्रम द्वारा आरम्भ किये गये उद्योगों में सार्वजनिक हितों की अथवा सरकार द्वारा स्थापित उद्योगों में प्राइवेट उपक्रम को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उदाहरण के लिये, भारत सरकार ने कुछ सरकारी औद्योगिक सस्थाओं का प्रबन्ध भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तित की गई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को सौंपने का निश्चय किया था। अब तक सिंदरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमोक्रस लिमिटेड, हिन्दुस्तान शियायर्ड लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबिस्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान हावर्सिंग फैक्टरी लिमिटेड, महान फाउन्ड्री लिमिटेड आदि की इस प्रकार स्थापना की गई है। इन कम्पनियों में, सम्पूर्ण अथवा पूर्ण सरकार द्वारा नहीं ली जाते हैं। बोर्ड प्राफ्ट डाइरेक्टर्स में अन्य पार्टियों के भी कुछ प्रतिनिधि लिये जाते हैं। यहाँ तक कि पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली सस्थाओं के बोर्ड में भी गैर सरकारी डाइरेक्टर रखना अच्छा समझा जाता है। सरकार बड़ को अधिक से अधिक स्वशासन देने का प्रयास करती है। केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारें भी कम्पनी नमूने की प्रबन्ध प्रणाली अपनाकर राजकीय उपक्रमों को अधिक स्वशासन देने का प्रयास कर रही हैं। ये

प्रयाप्त प्रयोग के रूप में है। यदि यह प्रणाली ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो अन्य प्रणालियों को अजमाया जायगा।*

प्रमुख विशेषतायें—

मिश्रित स्वामित्व वाले निगमों की निम्न प्रमुख विशेषतायें हैं—

- (१) कारपोरेशन की पूँजी में सरकार और प्राइवेट व्यक्ति दोनों ही भागी होते हैं।
- (२) सरकार व प्राइवेट शेयर होल्डर दोनों को ही डाइरेक्टर चुनने का अधिकार होता है।
- (३) मिश्रित स्वामित्व वाले निगमों की स्थापना एक विशेष विधान बनाकर अथवा सामान्य सनियमों के आदेशानुसार भी की जा सकती है।
- (४) एक समामेलित सस्था होने के नाते मिश्रित स्वामित्व वाले निगम व'तूनी उद्देश्यों के लिये एक पृथक् अस्तित्व रखते हैं और अपने नाम से दावा कर सकते हैं तथा उन पर दावा हो सकता है। वे अपने ही नाम से अनुबंध कर सकते हैं तथा सम्पत्ति खरीद सकते हैं।
- (५) एक मिश्रित स्वामित्व वाला निगम अपने कोष सरकार एवं जनता को स्टॉक (शेयर) बेच कर, ट्रेजरी या जनता से उधार लेकर और वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय द्वारा प्राप्त हुई आय में से जुटाता है।
- (६) मिश्रित स्वामित्व वाले निगमों को साधारण पब्लिक कारपोरेशनों की अपेक्षा भी अधिक छूटें प्राप्त होती हैं।

ऐसे सगठनों में, सरकारी नियन्त्रण बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की नियुक्ति करके और कारपोरेशन के अन्तर्निगमों में उपयुक्त नियमों का समावेश करके कायम रखा जाता है। इस दूरस्थ नियन्त्रण के अतिरिक्त ससद को इन कम्पनियों के निरीक्षण करने का और कोई अधिकार नहीं होता।

* The adoption of the method of promotion under the Indian Companies Act does not mean that we are wedded to this method of managing our undertakings. What we have now attempted to do is only by way of experiment. We have to see how this system works. If after a time, it is found to be not satisfactorily working, our idea is to try out other methods. There is no finality about these things. We are experimenting and, in course of time, we will evolve a type of management which will be satisfactory from all points of view."

(Minister of Production, Mr. K. C. Reddy, in the Council of States in September, 1953.)

मिश्रित स्वामित्व वाले कारपोरेशन तब अच्छे बहून समझे जाने हैं जबकि उपक्रम का बहून कम राजनैतिक महत्त्व हो जबकि जब अन्तिम उद्देश्य पूर्ण प्राइवेट स्वामित्व की स्थापना करना हो। यह विश्वास किया जाता है कि इस मुक्ति के द्वारा सरकार नये उद्योगों की स्थापना का प्रोत्साहित कर सकती है तथा एक सह-स्वामी के रूप में उद्योग के कार्य संचालन के सम्बन्ध में प्रथम मूलीय भूमिका प्राप्त कर सकती है। अपने मनोनीत संचालकों द्वारा वह कारपोरेशन की नीतियाँ को भी, उन्हीं राजनैतिक विवाद का विषय बनाने बिना, प्रभावित कर सकती है।

ऐसे संगठनों से मुख्य लाभ यह है कि उनका कार्य संचालन, प्रबन्ध, वित्त-व्यवस्था और अवेक्षण एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के समान ही व्यापारिक आधार पर किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप कार्य कुशलता से, शीघ्रता व सुगमता से होने लगता है।

मद्यपि मिश्रित स्वामित्व वाले कारपोरेशन को इस आधार पर बुरा बताया जा सकता है कि वह एक सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट कारपोरेशन की अपेक्षा कुछ ही अधिक काम कर सकता है तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यदि सरकार और प्राइवेट उपक्रम के मध्य विश्वास बना रहे तो वह सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगा। कम से कम एक भारतीय राज्य मैसूर में इस प्रकार के संगठन के साथ सफल प्रयोग किया गया है। चूँकि सरकार के मनोनीत चेयरमैन को सरकार (जो कि एक प्रमुख शेयर-होल्डर है) एक साधारण शेयर-होल्डर वानों के ही प्रति रिपोर्टें देने होती हैं, इसलिए वह इस बात का प्रयत्न करता है कि अपने उपक्रम के संचालन में व्यापारिक ईमानदारी तथा समुचित कुशलता में काम लें। लेकिन बहुत कुछ सरकार अप्रथा संसद या राज्य विधान सभा के ऊपर ही निर्भर है। यदि सरकार या संसद या राज्य विधान-सभा मिश्रित स्वामित्व वाले निगमों के कार्य में बहुत हस्तक्षेप करती है, तो निगम की कार्यवाही में प्राइवेट उपक्रमों जैसी कार्य-गति, पहलपन की भावना एवं साहसिकता नहीं रहेगी तथा वह एक विद्युद्ध सरकारी स्वामित्व वाले कारपोरेशन से किसी भी मात्रा में अच्छा न कहा जा सकेगा, क्योंकि उसके अधिकारी राजनीतिज्ञों की आलोचना से बचने के लिए सदैव अत्यधिक सावधानी की नीति अपनायेंगे। मैसूर के सरकारी उपक्रम को जो सफलता मिली है उसका मुख्य कारण यह है कि तत्कालीन मैसूर सरकार और कम्पनी के प्रशासकों के मध्य सहभागिता का बानावरण था।

-(VII) पब्लिक ट्रस्ट (Public Trust)—

राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध का एक अन्य ठोस पब्लिक ट्रस्ट है। इस ढंग का प्रयोग बन्दरगाहों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अधिक किया गया है, जैसे काचला पोर्ट ट्रस्ट। अन्य उदाहरण हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्युनिस्पल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट ट्रस्ट आदि।

सरकारी कम्पनियाँ

(Government Companies)

कोई भी कम्पनी जिसकी कम से कम ५१ प्रतिशत प्रश पूर्णजी केन्द्रीय अथवा एक राज्य सरकार द्वारा ग्रहण की हुई है, एक सरकारी कम्पनी मानी जाती है। एक सरकारी कम्पनी (Government Company) एक मैनेजिंग एजेंट द्वारा प्रबन्धित नहीं हो सकती है। केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों को उनके सरकारी कम्पनियों पर लागू होने के सम्बन्ध में संशोधित कर सकती है।

एक सरकारी कम्पनी का अन्वेषक केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के कम्पट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है और ऑडिटर जनरल को उस विधि का निर्देश करने का जिसके अनुसार सरकारी कम्पनी के लेखे कम्पनी के अन्वेषक द्वारा अन्वेषित किये जाने चाहिये तथा उसके कर्तव्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में अन्य निर्देश देने का भी अधिकार है। ऑडिटर जनरल को एक सरकारी कम्पनी के लेखों का एक पूरक (Supplementary) अथवा परीक्षण अन्वेषण (Test Audit) करने का भी अधिकार है, और इस उद्देश्य के लिये वह ऐसी कोई भी सूचना माँग सकता है जिसकी उसे आवश्यकता पड़े।

एक सरकारी कम्पनी के अन्वेषक को अपनी अन्वेषण रिपोर्ट की एक प्रति कम्पट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के पास भी भेजनी पड़ती है जिसे रिपोर्ट के सम्बन्ध में समालोचना (Comment) करने तथा पूरक रिपोर्ट देने का भी अधिकार है। रिपोर्ट पर उसकी समालोचना तथा पूरक रिपोर्ट भी अन्वेषक की रिपोर्ट की भाँति ही कम्पनी की वार्षिक व्यापक सभा के सम्मुख रखी जानी चाहिये।

गुण—

इस प्रकार के प्रबन्ध के निम्न गुण हैं :—

- (१) सरकारी उद्योग व्यापारिक ढङ्ग से चलाये जा सकते हैं।
- (२) प्रबन्धकों को इसकी निपुणता बढ़ाने के लिए अधिक उत्साह रहता है।
- (३) राजकीय उद्योग प्राइवेट उद्योगों से तुलना करके अपनी निपुणता की परीक्षा कर सकते हैं।
- (४) कम्पनी प्ररूप प्रबन्ध को सरकार ने सामान्य नियन्त्रण के अधीन समुचित स्वतन्त्रता प्रदान करता है। अतः प्रबन्धक अपने को दायित्व लेने से नहीं बचा सकते।
- (५) चूँकि सरकारी कम्पनी की समस्याएँ पार्लियामेण्ट में प्रस्तुत होती हैं इसलिये प्रबन्धक वर्ग सदैव जागरूक एवं सावधान रहता है।

दोष—

- (१) जब कोई सरकारी कम्पनी पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में हो तो वह अपने उत्तरदायित्व को पब्लिक की आलोचना में बचाने के लिए टाल सकती है।

(२) विभागीय सेक्रेटारियों एवं डिप्टी सेंट्रल सेक्रेटारियों को एनस ऑफिसियो हाइरेटर बना दिया जाता है और वे प्रबन्ध कार्य पर समुचित समय व ध्यान नहीं दे पाते ।

(३) सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण वे अन्य साधारण सचालकों के सामान्य रूप में कार्य करने में बाधा डालने वाले बन जाते हैं और जब-तब उन पर 'रोष' जमाते रहते हैं ।

(४) स्टेटुटरी कॉरपोरेशनों की भाँति वे सुसे-भाग काम नहीं करते, उनके गुप्त सोदे व कमन्वारियों का चुनाव जनता के मन में सन्देह उत्पन्न कर सकता है ।

सरकारी कम्पनी की सफलता बहुत कम इस बात पर निर्भर होगी कि बोर्ड ऑफ़ हाइरेटर 'नीति निर्धारक' होगा या "नीति पालक" । यदि वह राज्य मन्त्रालय की नीतियों को कार्यान्वित कराने वाला मात्र है, तो प्रबन्ध की यह पद्धति 'विभागीय प्रबन्ध पद्धति' (Departmental Form of Management) की प्रतीक्षा भेद्य न होगी । जैसा श्री मोरारजी का सुझाव है बोर्ड एक स्वतन्त्र नीति निर्धारक होना चाहिए, जिससे कि वह राजनैतिक प्रभाव से मुक्त रह सके और प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों के समान लोच के साथ काम कर सके ।

STANDARD QUESTIONS

1. Define the term 'Public Enterprise' Discuss carefully the objectives of State ownership as outlined by E C A F E
2. What objections are usually raised against the State ownership and management of business enterprises ?
3. Discuss carefully the various forms prevalent for the management of public enterprises
4. Discuss in details the merits and demerits of the following forms of management
(a) Departmental management, (b) State enterprises managed like a company
5. Define a Public Corporation Mention its special features, advantages and disadvantages and suggest measures to make it a success
6. What do you understand by a mixed ownership cooperation ? Give your personal observations regarding the utility of such corporations
7. Define a Government Company What are its merits and demerits

राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था एवं प्रबन्ध (२)

(गोरवाला, गालब्रेथ, अप्पल बी तथा इकेफी की रिपोर्टों के संदर्भ सहित)

(Administration & Management of State Enterprises)

राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध से सम्बंधित समस्याओं के प्रति बढ़ती हुई चेतना

उद्योग एवं व्यापार में सरकार का भाग दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। इससे इनके प्रबन्ध से सम्बंधित समस्याओं के अध्ययन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। यदि राजकीय उपक्रमों को सफल बनाना है, तो यह आवश्यक है कि इनके प्रबन्ध की कुशलता बढ़ाई जाय। राजकीय औद्योगिक संस्थाओं का प्रबन्ध करने की किसी उपयुक्त व्यवस्था का विकास करने की समस्या कई वर्षों से हमारे सम्मुख है, किन्तु अभी तक इसका कोई सतोषजनक हल नहीं ढूँढा जा सका है। इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न प्रयासों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

(१) भारत सरकार की उत्पादन समिति, सन् १९५०—नवम्बर सन् १९५० में भारत सरकार की उत्पादन समिति के सम्मुख राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध की सर्वोत्तम व्यवस्था का प्रश्न आया, जिस पर विचार विमर्श के पश्चात् समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्रत्येक औद्योगिक संस्था की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार ही प्रबन्ध की व्यवस्था की जा सकती है। कोई एक प्रबन्ध व्यवस्था सब संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। यह भी स्वीकार किया गया था कि सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के लिए विभागीय प्रबन्ध की व्यवस्था करना अनुपयुक्त है। इसके विपरीत कम्पनी प्रणाली के प्रबन्ध का सुझाव दिया गया।

राजकीय उपक्रमों के प्रबंध की समस्या को हल करने के प्रयास

- (१) भारत सरकार की उत्पादन समिति सन् १९५०।
- (२) गोरवाला रिपोर्ट सन् १९५१।
- (३) योजना आयोग के सुझाव सन् १९५२।
- (४) इकेफी रिपोर्ट सन् १९५४।
- (५) एस्टीमेट कमेटी सन् १९५५-५६।
- (६) कम्पनी अधिनियम सन् १९५६।
- (७) औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९५६।
- (८) द्वितीय योजना का ड्राफ्ट।
- (९) गेलब्रेथ रिपोर्ट।

- (१०) अप्पल नी रिपोर्ट ।
 (११) राजकीय उपक्रमों पर सेमिनार सन् १९५७ ।
 (१२) छागला कमीशन सन् १९५८ ।
 (१३) कृष्णा मेनन कमेटी १९५८ ।
 (१४) इक्वेफी सेमिनार सन् १९५९ ।
 (१५) एस्टीमेट कमेटी सन् १९६० ।

(२) गोरवाला रिपोर्ट, सन् १९५१—योजना आयोग के निर्देश पर श्री ए० डी० गोरवाला ने सरकारी उपक्रमों के कुशल प्रशासन का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट (The Efficient Conduct of State Enterprises) सरकार को दी । हमने उन्हीने

विभिन्न सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के लिए एक स्वशासित प्रवायिटी की स्थापना का सुझाव दिया, क्योंकि इनके प्रशासन सांख्यिक हितों की पूर्ति के लिए तोनी विरोधताएँ—राजकीय स्वामित्व, राजकीय उत्तरदायित्व एवं व्यापारिक प्रबन्ध—संभव हो जाती हैं । उन्होंने प्रशासन सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर भी विचार किया था, जैसे ससदीय एवं मन्त्रिमण्डलीय नियन्त्रण, आन्तरिक प्रबन्ध, प्रबन्ध व्यवस्था की रचना, उपनोत्पादों एवं वरदाताओं के हितों की रक्षा ।

(३) योजना आयोग के सुझाव, सन् १९५२—योजना आयोग ने प्रथम पंच-वर्षीय योजना के ड्राफ्ट में यह कहा कि राजकीय औद्योगिक उपक्रम का विकास एक नवीन घटना है, जिसके वरते हुए महत्त्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार की अधिकांश औद्योगिक संस्थाओं का प्रबन्ध सभालने के लिए एक नृपक मन्त्रालय (Ministry of Production) स्थापित करने का सुझाव दिया गया है । उसने यह स्वीकार किया था कि इन संस्थाओं के कार्यवाहन का इतना पर्याप्त अनुभव नहीं हो पाया है कि उसके आधार पर समुचित निष्कर्ष निकाला जा सके । फिर भी उसने एक संतुल बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया, जो कि प्रबन्ध-समस्याओं पर विस्तृत ध्यान दे सका और सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के लिये सामान्य महत्त्व के प्रश्नों पर सरकार को परामर्श दिया करेगा ।

(४) इक्वेफी रिपोर्ट, सन् १९५४—एशिया और सुदूरपूर्व के लिए समुक्त राष्ट्रीय आर्थिक आयोग (U N. Economic Commission for Asia and Far East or E C. A F E) की भाषं सन् १९५४ की कार्यन्वय म भी औद्योगिक क्षेत्र की राजकीय संस्थाओं के संगठन एवं प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया । भारत ने भी इस कार्यन्वय में भाग लिया था । इक्वेफी कार्यन्वय की राय में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी एक उपयुक्त प्रबन्ध प्रणाली नहीं है । सामान्य धारणा पब्लिक कॉर्पोरेशन का संगठन करने में पक्ष में थी ।

(५) एस्टीमेट कम्पनी सन् (१९५५-५६)—इस कमेटी ने अपनी सोलहवीं रिपोर्ट में विभागीय इकाई के रूप में राजकीय उपक्रमों का प्रबन्ध करने का विरोध किया और समुक्त रकम्पनी की प्रबन्ध प्रणाली का समर्थन किया, किन्तु इसने यह जोर दिया कि जनता की रुचि एवं सहयोग प्राप्त करने के लिये कम से कम २५% पूँजी जनता के विनियोग के लिए सुरक्षित की जाय । मैनेजिंग डाइरेक्टर का विभिन्न

विषयो पर समय समय पर परामर्श देने के लिए उसने एक एडवाइजरी कमेटी बनाने की सिफारिश भी की थी। आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में औद्योगिक उपक्रमों को बहुत सीमा तक स्वशासन का अधिकार देना उचित बताया।

(६) कम्पनी अधिनियम, सन् १९५६—नये कम्पनी अधिनियम में प्रथम बार सरकारी कम्पनियों की चर्चा हुई और इस तरह इस प्रबन्ध प्रणाली की वैधानिक मान्यता दी गई।

(७) औद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन् १९५६—सन् १९५६ की औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में नये उपक्रम स्थापित करने में प्रमुख भूमिका ग्रहण की और शीघ्र निणय दायित्व ग्रहण की सुविधा की दृष्टि से इन उपक्रमों के प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण करने व उनको व्यापारिक आधार पर संचालित करने पर बल दिया।

(८) द्वितीय योजना का ड्राफ्ट—द्वितीय योजना के ड्राफ्ट में भी योजना आयोग ने पर्याप्त अनुभव के अभाव में राजकीय औद्योगिक उपक्रमों के लिये कोई उचित प्रणाली सुझान में असमर्थता प्रगट की थी, किन्तु उसने यह कहा कि हमें अपने मौलिक आदर्श सदैव ध्यान में रखने चाहिए तथा प्राप्त अनुभव के प्रकाश से अपनी समस्याओं के प्रबन्ध को ढालने के लिये तैयार रहना चाहिए।

(९) गालब्रेथ रिपोर्ट—भारत सरकार द्वारा परामर्श देने के हेतु आमंत्रित अमरीकन विशेषज्ञ श्री गैलब्रेथ ने इस बात पर जोर दिया था कि राजकीय उपक्रमों की कुशलता एवं सफलता में हमारा अडिग विश्वास होना आवश्यक है। उन्होंने स्वशासन पब्लिक कॉरपोरेशनों की स्थापना का समर्थन किया। किन्तु प्रत्येक उपक्रम के लिये अलग अलग उपक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है। कई उपक्रमों के लिए एक सम्मिलित कॉरपोरेशन रखा जा सकता है। उन्होंने वित्तीय स्वशासन तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण का भी समर्थन किया।

(१०) अप्पल बी रिपोर्ट—डॉक्टर पाल अप्पल बी को भी भारत सरकार ने सन् १९५६ में अमरीका से परामर्श के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट (Re-examination of India's Administrative System with Special Reference to Administration of Government's Industrial and Commercial Enterprises) में यह बताया कि भारत एक संकटकालीन अवस्था में है, जिसकी सुचना युद्धकालीन राष्ट्र से की जा सकती है। अतः उसकी सफलता शीघ्र गण्य एवं शीघ्र कार्यवाही की क्षमता पर निर्भर है। यह आवश्यकता उस क्षेत्र में सर्वाधिक है जहाँ कि नये नये उपक्रम तेजी से बनते जा रहे हैं।

(११) राजकीय उपक्रमों की प्रबन्ध समस्याओं पर सेमिनार सन् १९५७—इस सेमिनार में संसद, सरकार, जनता एवं प्राइवेट उपक्रम, यूनिवर्सिटी व सार्वजनिक वायव्यार्त्ता एवं प्रनिनिधियां भाग लिया था और बाह्य नियन्त्रण, शिखर प्रशासन तथा आन्तरिक प्रबन्ध की समस्याओं का विवेचन किया था।

(१२) छागला कमीशन, सन् १९५८—जीवन बीमा निगम द्वारा भूदंडा के उपक्रमों में विनियोज करने की जाँच पड़ताल के सम्बन्ध में विचार करते हुये छागला कमीशन ने सरकार एवं ससद द्वारा वैधानिक कॉरपोरेशनों पर किये जाने वाले नियन्त्रण पर भी विचार-विमर्श किया। उसने निम्न सुझाव दिये :—(१) सरकार को चाहिए कि स्वशासित पब्लिक कॉरपोरेशनों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे और यदि हस्तक्षेप करना चाहे तो लिखित निर्देश देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए ; (ii) ऐसे कॉरपोरेशनों का चेयरमैन व्यापारिक एवं वित्तीय अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाय , (iii) मन्त्रियों को चाहिए कि प्रारम्भ में ही ससद को आवश्यक सूचना जुटा दें, ताकि आगे चलकर अन्य ओतों से सूचना मिलने पर ससद विविध स्थितियों में न फँस जाय , (iv) सम्बन्धित मन्त्री को अपने आधीन अधिकारियों के कार्यों का पूर्ण दायित्व ग्रहण करना चाहिए ।

(१३) कृष्ण मेनन कमेटी सन् १९५८—ससद में कांग्रेस पार्टी की इस सब-कमेटी ने प्रबन्ध समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट नवम्बर सन् १९५९ में प्रकाशित की थी। इसने निम्न दो आधारभूत समस्याओं पर मुख्य बल दिया है :—कुशलता एवं दायित्व । इसने यह सुझाव दिया था कि सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में रचना, प्रबन्ध एवं नीति ऐसी होनी चाहिए कि एक ओर जन-भावना और दूसरी ओर श्रमिक एवं प्रबंधकर्ता उन्हें राष्ट्रीयता से भ्रोन-प्रोत उत्साह से आदर दें तथा स्वाभिमान एवं स्वाभिमान की भावना का अनुभव करें ।

(१४) इक्की क्षेत्र की सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध पर नई दिल्ली का सेमिनार सन् १९५९—इस सेमिनार में निम्न बातों पर विचार किया गया था :—(१) सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध का आदर्श राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए । (ii) विशेष दशाओं को छोड़ कर सामान्य सरकारी उपक्रमों को लाभ पर चलना चाहिए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें । (iii) किसी सरकारी उपक्रम की सफलता का अनुमान उपक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति, उत्पादन व्यय के कम करने तथा वस्तुओं व सेवा की किस्म में सुधार होने से लगाया चाहिए । (iv) उपक्रमों की स्थापना के पूर्व एवं बाद में भी पर्याप्त नियोजन (Planning) की आवश्यकता है । (v) सरकार को दैनिक कार्य-कलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यापक नीति सम्बन्धी प्रश्नों तक सीमित रहना चाहिए । (vi) सरकारी उपक्रमों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(१५) एस्टीमेट कमेटी, सन् १९६०—एस्टीमेट कमेटी की नवीन रिपोर्ट में भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं : (१) प्रत्येक नये कार्य के लिए पृथक संगठन नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह विशेष महत्त्व का न हो । स्थापित संगठनों से ही नये उपक्रमों के प्रबन्ध का काम लिया जा सकता है । (ii) कुछ सरकारी उपक्रमों को मिला कर उनकी संख्या में कमी कर देना उपयुक्त होगा । (iii) एक विशेषज्ञ कमेटी

स्थापित की जाय, जो प्रत्येक नये उपक्रम के लिये प्रबन्ध की उपयुक्त प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार को सुझाव दिया करेगी ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याओं में गहरी रुचि ली जा रही है और धीरे-धीरे प्रबन्ध-यवस्था में आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं ।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कुछ मुख्य समस्याएँ

(I) प्रबन्ध का प्रारूप (Pattern of Management)—

एक सरकारी उपक्रम सगठन की कोई भी प्रणाली अपनाये, किन्तु वह तब तक कुशलता से कार्य नहीं कर सकती है जब तक कि उसका उच्च प्रबन्धक वर्ग कुशल एवं क्षमतावान् न हो । श्री गोरवाला (A. D. Gorwala) ने सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध बोर्डों (Board of Management) के बारे में कहा था कि इनकी रचना इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि जिससे चोर द्वार के जरिये नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप प्रचलित हो जाय । मत. बोर्ड की सदस्यता संसद के सदस्यों, मंत्रियों एवं विभागीय प्रतिनिधियों के लिये बढ़ कर देनी चाहिए ।^{*} बोर्ड की मीटिंगों की विभिन्न हितों के मतभेदों को निपटान का स्थान भी नहीं बनने देना चाहिए । वरन् प्रत्येक सदस्य संस्था का प्रबन्ध जनहित की दृष्टि से अच्छी प्रकार चलाने में सहयोग दे । बोर्ड के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि सार्वजनिक हित की भावना और एक प्राइवेट उद्योगी की कुशलता दोनों के गुण प्राप्त हो जायें । कृष्णामेनन कमेटी ने भी यह सुझाव दिया था कि बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स में वित्त-विशेषज्ञ, टेक्नीकल विशेषज्ञ, एडमिनिस्ट्रेटिव कुशलता प्राप्त व्यक्ति एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि होने चाहिए । डाइरेक्टर्स का चुनाव कम्पनी में से ही किया जाय तथा चेयरमैन का पद रिटायर होने वाले सिविल सर्वेंट्स को या राजनैतिक सेवा करने वाले व्यक्तियों को पुरुष्कार स्वरूप नहीं दिया जाना चाहिए । बोर्ड को व उसके चेयरमैन को एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए ।

सन् १९५४-५५ की अपनी सोलहवीं रिपोर्ट में लोक-सभा की एस्टीमेट कमेटी ने बताया था कि सरकारी उपक्रमों के

सरकारी उपक्रमों की प्रमुख

६ प्रबन्ध समस्याएँ

- (I) प्रबन्ध का प्रारूप ।
- (II) प्रबन्ध की स्वतन्त्रता ।
- (III) अन्तरिक प्रशासन ।
- (IV) अक्षेपण ।
- (V) संसदीय नियन्त्रण ।
- (VI) जनता को सूचना ।

बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स अन्ध्रा कार्य नहीं कर

रहे हैं, क्योंकि उनके सदस्यों को सरकार ने विभिन्न मन्त्रालयों के सरकारी अफसरों में से मनोनीत किया है। ये लोग दीर्घकाल के पश्चात् मोटिंग करते हैं और कोई उपयोगी कार्य नहीं कर पाते। हाँ, कम्पनी नमूने के प्रबन्ध का वित्ता जरूर इन संस्थाओं को मिल गया है, अतः कमेटी ने यह राय दी है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स नियुक्त करने की प्रथा को समाप्त करके सरकारी उपक्रमों के लिए एक मैनेजिंग डाइरेक्टर्स या संस्था के आकार के अनुसार कई मैनेजिंग डाइरेक्टर्स का पैनल बनाया जाय। ये लोग व्यापारिक अनुभव वाले व्यक्ति होने चाहिए। कुछ सदस्य टेक्नीकल ज्ञान रखने वाले भी हों। इस पैनल का एक चेयरमैन होना चाहिये, जो अपने साधियों के साथ सामूहिक रूप से और एक कार्य विभाजन आधार पर कार्य करे। बोर्ड चेयरमैन के द्वारा तोति सम्बन्धी व्यापक प्रश्नों के सम्बन्ध में मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत मन्त्री को राष्ट्रीय महत्त्व के सरकारी उपक्रम के कार्यकलापों की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती रहेगी और बोर्ड को भी प्रत्यक्ष रूप से मन्त्री का तथा मन्त्री के द्वारा मंत्रि परिषद के विचारों की सूचना मिलती रहेगी और उसके निर्णयों को वह अधिक दीप्तता से कार्यान्वित कर सकेगा।

एस्टीमेट कमेटी की उक्त सिफारिश को इस आधार पर अनुपयुक्त बताया गया है कि काम विभाजन आधार पर सदस्यगण व्यापक दृष्टि से विचार करने में असमर्थ रहेंगे। सम्बन्ध इस आलोचना का कमेटी को भान था। इसलिए उसने समय-समय पर विभिन्न मामलों में मैनेजिंग डाइरेक्टर को परामर्श देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति का भी सुझाव दिया था। इस एडवाइजरी कमेटी में व्यापारियों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और संसद या स्थानीय विधान सभाओं के प्रतिनिधि होंगे। इस बोर्ड की असीमित आलोचना करने का अधिकार होगा। वह किसी भी विषय पर सूचना माग सकती है। मैनेजिंग डाइरेक्टर खुद भी रिपोर्टें, हिसाब-खाते की नकलें आदि भेजकर दियारि से भिज रखेगा। लेकिन यह भय है कि इस कमेटी के सुझाव केवल परामर्श के रूप में न होने के कारण मैनेजिंग डाइरेक्टर पर बाधित न होंगे और इस प्रकार विशेष उपयोगी प्रमाणित न हो सकेंगे। कमेटी भी परामर्श के कार्य में विशेष रुचि नहीं लेगी।

मैनेजिंग डाइरेक्टर का चुनाव प्राइवेट क्षेत्र से किया जाय या सिविल सर्विस से किया जाय, इस सम्बन्ध में एक आदर्श सिद्धान्त यह होना चाहिये कि योग्य व्यक्ति जहाँ से भी मिल सकें, लिय जाने चाहिये। डाक्टर अप्पल बी का कहना था कि व्यापारिक विश्व से सरकारी उपक्रमों के प्रशासकों का चुनाव करना उपयुक्त नहीं है। उनकी यह धारणा निराधार है। हाँ, उन्होंने उत्तरदायित्व के हस्तान्तरण पर उचित जोर दिया है। बोर्ड को अधिकांश अधिकार मैनेजिंग डाइरेक्टर को, मैनेजिंग डाइरेक्टर द्वारा अधिकांश अधिकार अपने आधीन वमचारियों को सौंप देने चाहिए, ताकि तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

(II) प्रबंध की स्वतंत्रता (Autonomy of Management)—

यह आवश्यक है कि कार्यकारी मन्त्रालयों (Operating Ministries) के हस्तक्षेप को घटाकर सरकारी उपक्रमों के स्वशासन की रक्षा की जाय। एस्टीमेट कमेटी ने यह अनुभव किया था कि जिस प्रकार सेक्रेटेरियल सरकारी विभागों और कार्यालयों का नियन्त्रण रखता है उसी प्रकार सरकारी उपक्रमों को भी मन्त्रालयों का एक विभाग मान कर नियन्त्रण किया जा रहा है। इसका उन सस्थाओं की उत्पादकता पर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि एक सरकारी विभाग के समान ही उनमें भी लाल कीर्ति का जोर बढ़ गया है। इन सरकारी उपक्रमों को व्यापारिक सिद्धान्तों पर ही चलाना चाहिए अर्थात् दैनिक प्रशासन में उनको बहुत स्वतन्त्रता होनी चाहिये। सच तो यह है कि स्वशासन और नियन्त्रण के बीच एक उचित सन्तुलन रखने की समस्या बड़ी नाजुक है। इकेफेसेमिनार (दिसम्बर १९५६) में सरकारी नियन्त्रण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुये यह सुझाव दिया गया था कि सरकारी उपक्रमों में सरकारी नियन्त्रण को दैनिक कार्य संचालन में हस्तक्षेप करने का रूप ग्रहण नहीं करना चाहिये। जहाँ तक व्यापक नीतियों का सम्बन्ध है, उपक्रमों को सरकार के सामान्य नियन्त्रण एवं संचालन में कार्य करना चाहिए, किन्तु इन नीतियों की सीमा के भीतर सरकारी सस्थाओं को कार्य की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। स्वशासन का समर्थन करने का आशय सरकार के उत्तरदायी उच्च अङ्गों को इस बात के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल देना है कि वे समय से काम लें और वास्तविक महत्वपूर्ण बातों में हस्तक्षेप करने तक ही अपने को सीमित रखें। साथ ही यह भी समस्या है कि ऐसी सस्थाओं के मुख्याधिकारियों को सेक्रेटेरियो व मन्त्रियों द्वारा उनको दिए गए परामशों से अभ्यर्तित होने से बचाया जाय।

(III) आन्तरिक प्रशासन (Internal Administration)—

सरकारी उपक्रमों की सफलता के मार्ग का एक रोड़ा उनको प्रबन्ध करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होना है एक उत्पादक सरकारी उपक्रम का प्रशासन काय सरकार के सामान्य प्रशासन से बहुत भिन्न होता है। सरकार के सामान्य प्रशासन के लिए इतने अधिक टेक्नीकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, जितने कि उत्पादक सरकारी उपक्रमों के प्रशासन के सम्बन्ध में आवश्यकता होती है। अतः टेक्नीकल व अनुभव ज्ञान रखने वाले विशिष्ट कर्मचारियों की सेवाएँ प्राप्त करना आवश्यक है। एस्टीमेट कमेटी ने सरकारी उपक्रमों के भव्य तक के अनुभव के आधार पर यह सम्मति प्रगट की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के द्वारा सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध चलाने के लिये उपयुक्त कर्मचारी प्राप्त नहीं हो सकते।* एडमिनिस्ट्रेटिव

* It has been noticed that the managing directors of the State undertaking at present are mostly senior officers of the Administrative Department of the Government and that consequently, managements in these undertakings find themselves unable to adopt business methods as the officers have been accustomed all along to the procedure of business in Government departments quite unsuitable for the running of a commercial enterprise."

सर्विस के लोगो को जहाँ-तहाँ औद्योगिक सेवाओं का प्रबन्ध नियुक्त करके उन्हें ट्रेनिंग देना उनके लिये तो लाभदायक हो सकता है लेकिन इन समस्याओं के लिए नहीं। प्रबन्ध सेवाओं में भरती की उक्त समस्या को दो तरह से हल किया जा सकता है— प्राइवेट सेक्टर में कुशल एवं व्यापारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय अथवा विशेष भरती बोर्डों द्वारा नवयुवकों की प्रत्यक्ष भरती की जाय तथा उन्हें औद्योगिक प्रबन्ध की विशिष्ट ट्रेनिंग दी जाय। हर्ष का विषय है कि उत्पादन, यातायात, संचादवाहन, लोह एवं इस्पात और व्यापार एवं उद्योग मन्त्रालयों के प्राचीन सरकारी उपक्रमों के स्टाफ की पूर्ति के लिए अभी हास में ही एक इण्डस्ट्रियल मैनेजमेन्ट सर्विस स्थापित करने का निश्चय किया गया। इस सर्विस द्वारा सामान्य प्रबन्ध, वित्त एवं खाते, विक्रय, क्रय, स्टोर्स यातायात, श्रम प्रबन्ध एवं कल्याण, नगर प्रशासन आदि के लिए औद्योगिक संस्थाओं को प्रबन्ध कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था की जायगी। इस सेवा में पब्लिक सर्विसेज तथा बाहर दोनों ही से भरती की जायगी। प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिए सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलना चाहिये, ताकि कुशल व्यक्ति सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित हो। भरती के पश्चात् उन्हें विशिष्ट ट्रेनिंग के लिए देश-विदेश भेजना चाहिए।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग देने की समस्या भी महत्वपूर्ण है। इस समस्या पर हमें न केवल काय कुशलता की दृष्टि से बल्कि समाज की स्वीकृत नीति एवं उद्देश्य की दृष्टि से भी विचार करना चाहिये। भारत में समाजवादी नमूने के समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया है, जिसकी व्याख्या करने से यह आशय निकलता है कि श्रमिकों को भी प्रबन्ध में भाग मिलना चाहिये। कुछ देशों में श्रमिकों से केवल परामर्श किया जाता है, कुछ में उनका कल्याण कार्यों के प्रबन्ध में ही भाग दिया गया है और कुछ देशों में उनको ऊपर से नीचे तक प्रबन्ध में भाग मिल गया है। भारत में सरकार ने पब्लिक सेक्टर में श्रमिकों के प्रबन्ध की योजना सर्वप्रथम हिन्दुस्थान मशीन ग्रीजार् कारखाने में सन् १९५८ में प्रारम्भ की थी। सितम्बर सन् १९५९ में डी० डी० टी० के कारखानों में भी योजना प्रारम्भ कर दी गई है।

सभी सरकारी उपक्रमों के लिये भरती करने को एक सम्मिलित प्रबन्ध-सेवा (Common Management Cadre) का आयोजन करने के विषय में एस्टीमेट कमेटी ने निम्न महत्वपूर्ण सिफारिशों की थी —

- (१) अकुशल श्रमिक अधिकांशतः उस स्थानीय क्षेत्र से ही भरती किए जाय जहाँ कि सरकारी उपक्रम स्थापित है।
- (२) अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की भरती मुख्यतः स्थानीय जन-संख्या में से की जाय। कुछ श्रमिकों की भरती देश के विभिन्न भागों से भी की जाय, जिससे कि संस्था का राष्ट्रीय स्वभाव भलके।
- (३) अफसरों व उनके स्टाफ को सम्पूर्ण देश से भौगोलिक अनुपात में स्पेशल रेक्यूटिंग बोर्ड द्वारा भरती किया जाय।

- (४) अगले दो-तीन वर्षों में रिक्त होने वाले एवं सम्भावित नये पदों की सूचना प्रकाशित करा दी जाया करे, जिससे कि इनके लिये विद्यार्थी अध्ययन कर सकें ।
- (५) प्रशासन एवं प्रबन्ध स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति संस्थाओं के ४-५ साल की अवधि के लिये ही की जाय, जिससे वे बहुत समय तक एक ही संस्था में रुकने से अनुश्रुत न हो जायें । एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में उनका ट्रान्सफर करते रहना चाहिये, ताकि एक संस्था के अनुभव का लाभ वे दूसरी संस्थाओं को पहुँचा सकें ।
- (६) नये भरती होने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए सुव्यवस्था की जाय । 'कार्य करते हुए काम सीखने' की योजनायें भी बनानी चाहिए ।

(IV) सरकारी उपक्रमों का अक्रेषण (Audit of Government Enterprises)—

डा० अप्पल बी ने भारत में सरकारी उपक्रमों के अक्रेषण की व्यवस्था की बड़ी आलोचना की है । उनकी सम्मति में ऑडिटर जनरल की कार्य-प्रणाली औपनिवेशिक शासन की एक दूषित विरासत है । आजकल सरकारी अफसरों में नियुक्ति लेने और तदनुसार कार्य करने के सम्बन्ध में जो संकोच व्यापक रूप से विस्तृत है उसका एक मुख्य कारण यह ऑडिटर जनरल ही है । वह सरकारी अफसरों पर अप्रत्यक्ष अथवा सदन के द्वारा प्रभाव डालता है । मन्त्रालयों एवं सम्बद्ध संगठनों के बारे में किसी सामान्य नियम पर पहुँचने में अथवा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपनाये गये ढङ्ग का एक सामान्य मूल्यांकन करने में सहायता देने के बजाय उसकी ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट का ध्यान छोटी-छोटी बातों पर केन्द्रित कर देती है । वास्तव में ऑडिटर जो चीज जानता है वह ऑडिटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं । बहुत अधिक ऑडिट रिपोर्टें उपयुक्त अवसर पर उठाये गये विशिष्ट कदमों की महत्ता की कम कर देती हैं ।

किन्तु डाक्टर अप्पल बी का उक्त तर्क एक ऐसे नुस्खे के रूप में है जो कि रोग का उपचार करने के बजाय रोग को बिगाड़ देता है । उन्होंने ऑडिटर जनरल के विरुद्ध जो अविश्वास प्रगट किया है उससे यह भलबलाता है कि उनके मस्तिष्क में ईर्ष्या मुक्त किन्तु ब्रेक रहित एडमिनिस्ट्रेटिव कार का ही चित्र था । निस्संदेह ऑडिटर्स की कुछ आलोचनायें उस विवेक का उदाहरण हैं जो कि घटना घटित होने के पश्चात् उदय हो और इस कारण उनकी कोई उपयोगिता नहीं होनी है । लेकिन सब ही आलोचनायें

* "Too many of audit reports are mere substitutions of hindsight for the kind of judgment possible and necessary and proper at the time of action. What auditors know is auditing—which is not administration."
(Dr Apple by)

इस वर्ग में नहीं आती है। यदि डाक्टर अम्पन बी ने आडिट रिपोर्टों का आडिट किया होता, तो उन्हें मालूम पड़ जाता कि वित्तीय आलोचना निर्णय की दृष्टि से सम्बन्धित है और वित्तीय आलोचना वास्तव में उचित है। पब्लिक अभी भी इस बात के लिये तैयार न होगी कि आडिट का नियंत्रण सरकारी उपक्रमों से हटा लिया जाय, क्योंकि इससे अधिकारियों और मन्त्रियों की वित्तीय दृष्टियों और अनियमितताओं को बढ़ावा मिलने का डर है। फिर पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत घाटे की व्यापक व्यवस्था की गई है। इससे भी जनता का सरकारी उपक्रमों के खर्चों के बारे में जागरूक रहना स्वाभाविक है। यदि आडिट व्यवस्था को निम्न स्थान दिया गया, तो वित्तीय प्रशासन के स्तर में गिरावट आने का भय है। अतः इस वर्ग की आवश्यकता है कि आडिट के सम्मान को कम करने के बजाय उसमें इन प्रकार का सुधार किया जाय कि वह अधिक व्यापारिक और कल्पनाशील किन्तु कम औपचारिक हो सके। अष्टाचार की दशाओं और निर्णय सम्बन्धी दृष्टि की दशाओं के साथ एक-सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरन् आडिट रिपोर्ट में प्रस्तुत करते समय उचित सावधानी रखनी चाहिये। यह कहना भी गलत है कि आडिट 'पोस्ट-मार्टम' (अर्थात् घटना घटित होने के बाद उसकी आलोचना के रूप में) होने के कारण बेकार होता है। इस सम्बन्ध में सिडनी वेब (Sidney Webb) ने तर्क दिया है कि "यह तथ्य कि पोस्टमार्टम रोगी को जीवित नहीं कर सकता, इस बात का प्रमाण नहीं है कि पोस्टमार्टम परीक्षा हत्याओं का रहस्य बना लगाने में कोई सहायता नहीं करती है।"⁴

माजकल वैधानिक निगमों का अन्वेषण केन्द्रीय सरकार द्वारा आडिटर जनरल के परामर्श से, नियुक्त अन्वेषकों द्वारा किया जाता है। कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ में सरकारी कम्पनियों के अन्वेषण के लिये भी यही व्यवस्था है। अन्वेषण पद्धति के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जाता है कि क्या सरकारी उपक्रमों के खातों के अन्वेषण के लिये किसी बाहरी आडिटर को रखना अच्छा होगा या आडिटर जनरल स्वयं ही इस कार्य को करे (जैसा कि हवाई यातायात निगमों में है) अथवा फास व सोवियत रूस की भाँति किसी अत्यन्त विशिष्ट एवं स्वतंत्र संस्था से वित्तीय एवं कार्य-क्षमता सम्बन्धी अन्वेषण कराना अधिक लाभप्रद रहेगा। रूस में Khozrachyot इस प्रकार की एक विशिष्ट संस्था है। इसके कार्यों को वहाँ बहुत महत्त्व दिया जाता है। भारत में भी ऐसी विशिष्ट संस्था की आवश्यकता है जो सरकारी उपक्रमों की न केवल वित्तीय वरन् कार्य-कुशलता का अन्वेषण भी करे।

* "The fact that post-mortem examination does nothing to keep the patient alive is no proof that the existence of a system of post-mortem examinations does not prevent murders."

(The control of Public Expenditure, p. 196)

(V) संसदीय नियंत्रण की समस्या (Problem of Parliamentary Control)—

विभागीय सस्यामो की अपेक्षा सरकारी उपक्रमों को जनता के धन की एक विशाल मात्रा का अधिकार सौंपा जाना है तथा वे अपने कार्यों में अधिक स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं। इन बातों को देखते हुये यह स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी भी ऐसी सस्यामो के सम्बन्ध में अधिक हो। इसमें किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती है कि सरकारी उपक्रम समद के प्रति और इसके द्वारा जनता के प्रति जबाबदेह हो। किन्तु कठिनाई तो तब उदय होती है जबकि इस सिद्धांत के लागू करने का समय आता है और इसके रूप तथा विस्तार की परिभाषा करनी पड़ती है। सरकारी उपक्रमों पर ससद के नियन्त्रण की सीमा के सम्बन्ध में दो मत हैं—कुछ विद्वानों की राय में पार्लियामेंट ने स्वशासित सस्यामो का निर्माण करके स्वयं अपने विरुद्ध यह प्रतिबन्ध स्वीकार कर लिया है कि वह उनके मामलों में नियंत्रण नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से उसकी कुशलता के कुप्रभावित होने का डर है। इसके विपरीत अन्य विचारकों का मत यह है कि पार्लियामेंट द्वारा स्वशासित सस्यामो पर पर्याप्त नियंत्रण होना उनके कुशल संचालन और सार्वजनिक जिम्मेदारी के उचित निष्पादन के हित में है। लेकिन इन सस्यामो के स्वस्थ विकास, कुशल संचालन एवं कौषो के सदुपयोग की दृष्टि से उक्त दोनों ही मार्ग (यथेच्छाश्रिता एवं अत्यधिक हस्तक्षेप) गलत हैं। वास्तव में इनके बीच का स्वर्णिम मार्ग (Golden Mean) ही अपनाया सर्वोत्तम है। चूँकि पार्लियामेंट ने इन सस्यामो को स्थापना कुछ भिन्न स्तर पर की है, इसलिये यह स्वाभाविक है कि वह इन पर अपने नियंत्रण की मात्रा में कुछ कमी कर। यह कमी कितनी होनी चाहिए, यह उस सरकारी उपक्रम के स्वभाव पर, उसकी प्रगति की अवस्था एवं अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों पर निर्भर होती है। चूँकि इन सस्यामो के लिये व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य करना जरूरी बना दिया गया है, इस कारण भी ससद को इन सिद्धान्तों को मान्यता देनी चाहिए तथा उन पर नियंत्रण करने समय उचित दूर रखनी चाहिए। डाक्टर अप्पल बी ने भारत में ससद द्वारा रखे गये नियंत्रण की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत में ससद-सदस्य सरकार को उसके बढ़ते हुए कार्य-भार के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान करने को तैयार नहीं है। उन्हें सरकारी व्यक्तियों पर घोर अविश्वास है, जिसने वे शीघ्रता से उपयुक्त कदम उठाने की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं होते।¹ उनके मत में एक सबसे सरल तरीका (जिसे अपनाकर ससद प्रशासन के

1 "The sift from an agitational function directed against government to a positive responsibility for the large scale operation of a dynamic government has naturally been slowest here among Parliamentarians, it is a difficult sift to make. The lag in this necessary sift entails a lingering distrust of the bureaucracy, and this is hostile to the achievement of the system of delegation necessary to speedy and magnified action." (Dr. Appelle by)

ऊपर अपना अनुकूल प्रभाव डाल सकती है) यह है कि वह प्रशासन के कार्यों की आलोचना की बातें हूँदने के बजाय प्रशंसा की बातें तलाश किया करें। किन्तु डाक्टर अम्पल बी का यह तरीका हमारी सम्मति में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि साहस, पहलपन व सुभ्र-बुद्धि के कार्यों की प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन यह भूलना ठीक नहीं है कि संसद पर जनता के धन की सुरक्षा का भी भार है। अनेक ऐसे अवसर उदय हो सकते हैं जबकि सरकार के कार्यकारी अंग को नियंत्रित एवं सावधान करने की आवश्यकता हो। अतः सरकारी अफसरों को हर मोके पर हरी भण्डी नहीं दिखाई जा सकती है।

सरकारी उपक्रमों पर संसद का नियन्त्रण चार प्रकार से होता है—

(१) प्रश्नोत्तर, (२) ग्राट की वार्षिक भाग के समय वाद-विवाद, (३) कम्पनी अधिनियम की धारा ६३६ के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्टों के प्रस्तुत करने के अवसर पर वाद-विवाद और (४) पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी तथा ऐस्टीमेट कमेटी की रिपोर्टों का विवेचन। लोक-सभा में कम्पनी नमूने की सरकारी सत्थाओं के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विश्लेषण से यह पता लगता है कि सरकारी उपक्रमों के कार्यवाहन के सम्बन्ध में कितनी दिलचस्पी ली जाती है। संसद के प्रति सरकारी उपक्रमों की जिम्मेदारी को सुधारने के लिए निम्न कदम उठाये जा सकते हैं :—

- (१) इन उपक्रमों के खाते एवं वार्षिक रिपोर्टें काफी विस्तृत बनाई जायें, जिससे उन पर वाद-विवाद करने में सुगमता हो।
- (२) संसद में सरकारी उपक्रमों पर नियमित रूप से वाद-विवाद के आयोजन होने चाहिए, किन्तु उनका मध्यान्तर काफी दीर्घ हो।
- (३) सत्थाओं को व्यापारिक नमूने के बजट तैयार करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय तथा सरकार के मुख्य बजट के साथ सलग्न करके उसे सामान्य रूप में स्वीकार करा लिया जाय।
- (४) पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी एवं ऐस्टीमेट कमेटी उन पर पर्याप्त नियन्त्रण रखे। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी कई वर्षों से उनकी रिपोर्टें एवं खातों की सकलतापूर्वक परीक्षा करती आ रही है। ऐस्टीमेट कमेटी ने भी अपने कर्तव्य को केवल ऐस्टीमेटों की ऊपरी परीक्षा तक सीमित नहीं रखा है वरन् वह वर्तमान, भविष्य एवं भूतकालीन कार्यों के संदर्भ में उनकी विवेचना करती है, ताकि वे वास्तविक परिणाम का प्रतिनिधित्व कर सकें। पाँच-पाँच वर्षों के पश्चात् अथवा इससे पहले यदि ऐसा संभव हो सके, सरकारी उपक्रमों के कार्यवाह की परीक्षा कराते रहने से संसद का उन पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण कायम हो जायगा तथा ऐस्टीमेट कमेटी एक अतिरिक्त सुरक्षा का कार्य करेगी और संसद एवं सरकारी उपक्रमों के बीच एक स्वस्थ सम्बन्ध विकसित करने में सफल होगी।

- (५) प्रत्येक सरकारी उपक्रम के लिये संसदीय नियन्त्रण का रूप एवं उमकी सीमा पृथक् पृथक् रूप से निर्धारित करना चाहिये, क्योंकि सब उपक्रमों के लिए कोई एक तरीका नहीं बनाया जा सकता ।
- (६) संसद का अग्र देशों के अनुभव से भी लाभ उठाना चाहिए और अपनी नियंत्रण पद्धति का निरन्तर पुनर्विचार करते रहना चाहिए, जिसमें वह अधिक से अधिक प्रभावशाली बन सके ।
- (७) ब्रिटेन की भाँति भारत में भी एक ऐसी रूढ़ि (Convention) को जन्म देना आवश्यक है कि संसद में आन्तरिक प्रबन्ध, निगम के व्यक्तित्वगत सदस्यों के वेतन अथवा उनके कर्मचारियों की साम्प्रदायिक आधार पर नियुक्ति तथा क्रय विक्रय की विस्तृत बातों से सम्बन्धित प्रश्न न पूछे जावें । यह भी आवश्यक है कि सरकारी उपक्रमों को राजनैतिक दलबन्दी से बचाया जाय ।
- (८) ब्रिटेन में स्टैंडिंग आर्डर्स के अन्तर्गत एक सिलेक्ट कमेटी हाउस ऑफ कामन्स द्वारा नियुक्त की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी उपक्रमों की देखभाल करना तथा उनके हिसाब-किताब की जाँच करना था, किन्तु उनके कार्यवाहन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वे नहीं कर सकती थी । भारत में भी एक ऐसी स्टैंडिंग कमेटी नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो प्रकाशित खातों और रिपोर्टों का ध्यान करके, सम्बन्धित समस्याओं से अन्य आवश्यक सूचना प्राप्त करके तथा इन निगमों के अधिकारियों से वार्तालाप करके सरकारी उपक्रमों की देखभाल करे । यह स्टैंडिंग कमेटी संसदीय उत्तरदायित्व के निष्पादन में अधिक सुविधा दे सकेगी, क्योंकि ऐस्टीमेट कमेटी व पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी कार्यभार की अधिकता के कारण इस दिशा में अधिक समय नहीं दे सकती हैं ।

कृष्णमैनन कमेटी ने भी सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में संसद की एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया था, जो कि एक दोष ढूँढने वाली संस्था या उच्च स्तरीय प्रबन्ध बोर्ड न होकर एक ऐसी कमेटी होगी जिसे उन परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी है जिनमें कि संस्थाओं को कार्य करना पड़ता है ।

स्टैंडिंग कमेटी की नियुक्ति के द्वारा पार्लियामेंट के अनेक सदस्यों को सरकारी उपक्रमों के कार्यवाहन से परिचित होने का अवसर मिल सकेगा और तब वे संसद में उनकी रिपोर्टों पर अधिक योग्यता से विचार-विमर्श कर सकेंगे ।* दुर्भाग्य से देश में अभी ऐसे जानकारी व्यक्तियों का संसद में अभाव है ।

* But the vast majority feel themselves lost and it is absolutely necessary to provide an opportunity to them to keep themselves fully acquainted so that they can exercise Parliamentary Control in a well-informed and vigilant manner."

(Report on Administrative Problems of State Enterprises in India 1957, p. 9)

(VI) जनता को सरकारी उपक्रमों की प्रगति के बारे में सूचना देना

(Public Accountability)

जनता को सरकारी उपक्रमों की प्रगति के बारे में सूचना देने के स्तर में बहुत सुधार की आवश्यकता है। संसद या जनता के लिये इस सूचना की उपयोगिता इस बात पर निर्भर होती है कि वार्षिक खातों में कितनी सूचना दी गई है। दुर्भाग्य से भारत में सरकारी उपक्रमों के बारे में वित्तीय रिपोर्टें उतनी सुगमता से जनता को उपलब्ध नहीं होती जितनी सुगमता में ब्रिटेन में होती हैं। रिपोर्टें अपूर्ण भी होती हैं और बहुत कम सूचना प्रदान करती हैं। इसके अनिश्चित सरकारी उपक्रमों के हिसाब-किताब भी सरकार के नियमित विभागों की भाँति रखे जाते हैं, व्यापारिक आधार पर नहीं रखे जाते। लागत लेखों (Cost accounts) का महत्त्व भी इन संस्थाओं में अनुभव नहीं किया जाता। ऐसे लेखों के अभाव में व्यय का नियंत्रण और कुशल कार्य संचालन कठिन हो जाता है। मंत्रियों की वार्षिक रिपोर्टों में सरकारी उपक्रमों के बारे में इतनी सक्षिप्त और सामान्य सूचना दी जाती है कि इनसे किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। अतः सरकारी उपक्रमों की प्रगति के बारे में सूचना देने के ढंग में निम्न सुधार किये जायें :—

- (१) सरकारी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्टें एवं खाते व ब्याजिट रिपोर्टें अधिक विस्तार से बनाये जायें, ताकि उनके आधार पर विचार विमर्श सुगमता से हो सके। उपक्रम की प्रत्येक क्रिया—संगठन सम्बन्धी हो या कार्य-वाहन सम्बन्धी, उत्पादन अर्थ-प्रबन्धन अथवा कार्यकारी-वर्ग सम्बन्धी—के बारे में उचित रिपोर्टें होनी चाहिये। प्रत्येक क्रिया के वित्तीय परिमाण को भी स्पष्ट कर देना चाहिये। मंत्रियों द्वारा दिये गये निर्देश विशेष रूप से लिखे जायें।
- (२) लागत लेखे रखे जायें, व्यापारिक नमूने के बजट प्रत्येक उपक्रम के लिये बनाकर राज्य के मुख्य बजट के साथ नत्थी किये जायें और मुख्य बजट के साथ-साथ उनको भी पास कर लेना चाहिये।
- (३) जहाँ-जहाँ सम्भव हो वहाँ परामर्शदाता समितियों एवं उपभोक्ता समितियों की स्थापना की जाय और उनसे कहा जाय कि वे संसद को अपनी सामयिक रिपोर्टें प्रस्तुत करें।
- (४) एस्टीमेट कमेटी का सुझाव है कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम गत वर्ष की अपनी क्रियाओं के बारे में अपनी एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट दे, जिसमें गत वर्ष की प्रगति, व्यय, उत्पादन आदि से सम्बन्धित पिछले वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े, चिट्ठा एवं लाभ-हानि खाता, प्रशासनिक परिवर्तन, वर्ष की महत्वपूर्ण घटनायें एवं अगले वर्ष की सभावित नीति व कार्यक्रम के बारे में उल्लेख हो। ये रिपोर्टें सम्बन्धित मंत्रालय का बजट पेश होने के पूर्व ही संसद को प्रस्तुत कर देनी चाहिये।

एस्टीमेट कमेटी ने कुछ सरकारी कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रकाशन तिथियों का सकलन एवं विश्लेषण करके यह पता लगाया था कि रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में ४ से लेकर ३५ महीने तक की देर हो जाती है। अतः उसका यह सुझाव था कि सभी सरकारी उपक्रमों के खाते एवं रिपोर्टें अगले वर्ष के सामान्य बजट को ससद में प्रस्तुत करने से पहले ही पेश कर दी जानी चाहिए।

- (५) जनता में सरकारी उपक्रमों के बारे में उचित प्रचार करना चाहिए। इस विषय में अनुमान (Estimate) समिति की यह सिफारिश है कि देश में होने वाली सभी मुख्य प्रदर्शनियों में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रगति का प्रचार करने के लिये स्टाल लगाने चाहिए। इस सम्बन्ध में सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय के पब्लिकेशन्स डिवीजन की सहायता भी ली जा सकती है।

मन्त्रियों का दायित्व—सरकारों उपक्रमों की स्थापना करने वाले कानूनों में ससद ने सरकार को कुछ शक्तियाँ प्रदान की हुई हैं, जिनमें बिम्ब को सम्मिलित किया जाता है :—(१) सस्था का प्रशासन मजबूत नियुक्त करना, (११) पूँजी में वृद्धि करने की सम्मति देना, (१११) उधार लेने के अधिकार को सीमित करना, (१४) निश्चित से अधिक व्यय करने की शक्ति देना, (४) सरकारी उपक्रमों को निर्देश देना। इन शक्तियों के देने का उद्देश्य इस बात की व्यवस्था करना है कि ये स्वशासित उपक्रम इस प्रकार से शासित किये जायें कि वे सरकार की एवं राष्ट्र की नीतियों से असंगत हो। व्यवहार में मन्त्रियों के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे अपने को केवल उन शक्तियों के प्रयोग तक ही सीमित रख सकें जो कि उन्हें कानून में दी गई हैं। अतः सम्बन्धित मन्त्री का सस्थाओं की नीतियों का मार्ग-दर्शन एवं नियन्त्रण करने में बहुत हाथ होता है। उसे सस्था की सामान्य सफलता एवं विफलता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उसके दायित्व का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए।

कृष्ण मैनन कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक दशा में मन्त्री को ससद के विरुद्ध दायी होना पड़ेगा और 'निर्देशों द्वारा जिम्मेदारी के हस्तांतरण' (Delegation by Directives) की आड़ में अपने को ससदीय दायित्व से नहीं बचा सकता। किन्तु यह आवश्यक है कि बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स एवं मन्त्री के कार्यों के मध्य एक स्पष्ट अन्तर हो। यदि मन्त्री को कम्पनियों के सामान्य कार्यों पर तथा उन मामलों पर जो कि बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स के अधिकार में हैं, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने क्षेत्र से बाहर दायित्व स्वीकार कर रहा है। यदि ऐसे प्रश्नों पर कोई मन्त्री उत्तर देने में सकोच करे, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वह अपने दायित्व से बच रहा है।

सामन्वय समिति

मितव्ययिता अनुभव-लाभ एवं सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से यह

आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में समन्वय रहे। एस्टीमेट कमेटी ने इस आशय के लिये एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की स्थापना का सुझाव दिया था। लेकिन कृष्ण मेनन कमेटी ने इस सुझाव को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि ऐसी अथॉरिटी ग्राहो के पाँचवें पहिये का कार्य देगी, मन्त्रियों के कार्य में सहायक होने के बजाय बाधक होगी और सस्थाओं के उत्साह एवं पहलपन की भावनाओं पर आघात करेगी। समिति की राय में, समन्वय मन्त्रि-स्तर पर होना चाहिये। यही अपनी अन्तर्गत सस्थाओं को परस्पर परामर्श करने का सुझाव (और निर्देश भी) दे सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के कारण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सितम्बर सन् १९५७ में सार्वजनिक क्षेत्र के लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति (Coordinating-Committee) की स्थापना की थी। इस समिति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्रगति पर निरीक्षण रखना है। यह समिति विभिन्न इकाइयों के सामने आने वाली सभी मुख्य एवं महत्वपूर्ण समस्याओं के एक विनियमित हाथ में (पर्याप्त समाधान गृह) का काम करेगी और सरकार और औद्योगिक इकाइयों के मध्य समन्वय व सम्पर्क रखेगी। इसके विशेष उद्देश्य निम्न-लिखित हैं :—

- (१) सभी उपक्रमों की प्रगति पर विचार करना।
- (२) विभिन्न इकाइयों के मध्य प्रशिक्षण एवं उत्पादन-कार्यक्रमों का समन्वय करना।
- (३) श्रम, वित्त, उत्पादन एवं विकास नीतियों पर विचार-विमर्श करना।
- (४) अनुसंधान कार्यक्रमों का विवेचन करना।

यह समिति विभिन्न बोर्डों को उनके सामान्य कार्य में सहायता करने के प्रतिरूप उन्हें आवश्यकता पड़ने पर टैक्निकल एड प्रदर्शन भी प्रदान करेगी। यह विभिन्न इकाइयों के कार्यक्षेत्रों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के हेतु देश के विशेषज्ञों की सहायता लेगी। समिति की बैठक ३ से ६ महीने की अवधि में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

समिति ने निम्न विभिन्न समस्याओं के हल के लिये उपसमितियों की स्थापना कर दी है—(अ) श्रम एवं अन्य कमचारियों से सम्बन्धित समस्याएँ, (ब) वित्त, क्रय एवं विक्रय संगठन सम्बन्धी समस्याएँ और (स) उत्पादन एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्याएँ। ये समितियाँ विभिन्न इकाइयों के साथ सम्पर्क में रहेंगी और उनके बोर्डों के साथ उनकी विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करके केन्द्रीय समन्वय समिति को अपनी उपयुक्त रिपोर्टें व सिफारिशें दिया करेंगी। समन्वय समिति को सभी सफल कहा जा सकेगा जबकि वह ससदीय नियन्त्रण एवं मन्त्रित्व सम्बन्धी दायित्व की सीमाओं के भीतर कुशलता, निरन्तरता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करती रहे। उसमें कार्य करने की इतनी ही सोच होनी चाहिए जितनी कि एक प्राइवेट उपक्रम में होती है।

STANDARD QUESTIONS

1. The Government of India is highly conscious of the problem pertaining to the management of State owned industrial enterprises." Discuss the various steps taken by the Government of India since independence to evolve a suitable structure for the management of State owned concerns.
 2. Discuss the following problems relating to the management of State enterprises in India :—
 - (a) Autonomy of management
 - (b) Internal Administration
 - (c) Audit.
 - (d) Parliamentary Control.
 - (e) Ministerial Responsibility.
-

अध्याय १५

प्राकृतिक प्रसाधन

(Natural Resources)

भूमिका—

किसी एक प्रसाधन के स्वाभाविक गुण या उसकी विशेषताएँ भकेले ही उसे उत्पादन करने योग्य बनाने के लिये पर्याप्त नहीं है और उसका एकाकी रूप से कोई आर्थिक मूल्य हो सकता है। यह आवश्यक है कि उत्पादन में भाग लेने वाले अन्य पूरक प्रसाधन भी उपलब्ध हो तथा जो वस्तु बन कर तैयार हो उसके लिये समुचित बाजार भी हो। संक्षेप में, किसी एक प्रसाधन का मूल्य अन्य प्रसाधनों के मूल्य पर निर्भर होता है। यही कारण है कि देश के आर्थिक विकास के सदर्भ में हमें किसी विशेष प्रसाधन का एकाकी रूप में नहीं बरन् अन्य प्रसाधनों के साथ-साथ अध्ययन करना चाहिये। यह भी नहीं भुलाना चाहिये कि प्राकृतिक प्रसाधनों पर टेक्नोलॉजी की अवस्था, उत्पादन या संगठन के ढंग, सरकार की कुशलता एवं नीतियों तथा समाज की सामान्य रचना भी प्रभाव डालती है।

प्राकृतिक प्रसाधन ही औद्योगीकरण के लिये सब कुछ नहीं—

प्राकृतिक प्रसाधन ही किसी देश के औद्योगिक विकास के एक मात्र निर्धारक नहीं होते । देशों की सम्पन्नता या विपन्नता उनमें किसी प्राकृतिक साधन के विद्यमान होने या समाप्त होने से सम्बन्धित नहीं है । विश्व के कुछ देशों ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है, किन्तु इसके लिये सम्पूर्ण श्रेय केवल उनके प्राकृतिक साधनों को ही नहीं दिया जा सकता । यह तर्क करना अनुचित है कि प्रगतिशील देशों में प्रचुर प्राकृतिक साधन हैं, जबकि गढ़' विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों की कमी है । वास्तव में, "ईश्वर ने ससार को दो क्षेत्रों में—विकसित एवं गढ़' विकसित, जिनमें से प्रथम में प्रचुर प्राकृतिक साधन हो और दूसरे में कम, नहीं बाँटा है । जिन देशों को आज प्रगतिशील कहा जाता है उन्होंने भी गढ़' विकसित कहे जाने वाले देशों के स्तर से ही अपनी उन्नति की है ।" बहुत दिनों तक वे गढ़' विकसित दशा में ही पड़े रहे । अतः पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक प्रसाधन ही औद्योगीकरण के लिये सब कुछ नहीं हैं । दूसरे, औद्योगिक एवं व्यापारिक नेतृत्व प्रायः एक देश से दूसरे देश को, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को हस्तान्तरित होता रहा, यद्यपि उन क्षेत्रों के प्राकृतिक साधनों में कोई विशेष भेद न था । तीसरे, प्रगतिशील देश किसी विशेष जलवायु-खण्ड में ही पाये जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है । चौथे, जो देश किसी समय प्रगतिशील माने जाने थे वे भी बाद में अपनी शान खो बैठ और गढ़' विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गये । उदाहरण के लिये, दक्षिणी यूरोप एवं भूमध्य रेखीय प्रदेशों के साथ वही दुर्भाग्य हुआ ।

उन्नतिशील देशों ने अपने प्राकृतिक साधनों का, पूर्ण, समतल एवं देवनीनल योग्यताओं तथा श्रम के प्रयोग द्वारा, पता लगाकर और विकसित करके मूल्य बढ़ा लिया है । उनके पास पहले उत्पादन के जिस साधन की कमी थी उसकी पूर्ति करके उन्होंने प्राकृतिक प्रसाधनों की उपयोगिता में वृद्धि कर दी है । उदाहरण के लिये, संयुक्त राज्य अमेरिका को ही लीजिये । इसमें प्रचुर प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन एक सप्ते भरसे तक वे अक्षीय पड़े रहे, क्योंकि वहाँ के आदिवासियों ने उनका प्रयोग नहीं किया । प्राकृतिक साधनों के होते हुये भी वे निर्धनता एवं कष्टों का जीवन व्यतीत करते रहे । इसी प्रकार, यदि किसी देश में प्राकृतिक साधनों का अभाव है, तो केवल इस कारण ही उसका विकास नहीं रुकता, बशर्ते अन्य दृष्टियों से वह देश अभावमय न हो । वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात करके वह देश अन्य देशों से अपनी कमी के प्रसाधन खरीद सकता है । अतः यदि प्राकृतिक प्रसाधन उचित आर्थिक शर्तों पर उपलब्ध हो, तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उन प्राकृतिक साधनों का स्वामी कौन है, अथवा, वे, कहां, पर, स्थित हैं, नई, यह, अथवा, है, जिन विदेशी, प्राकृतिक साधनों, की उपलब्धता में राजनैतिक बाधाएँ द्वारा बाधा पड़ सकती है । ऐसी दशा में प्राकृतिक साधनों के स्वामित्व एवं स्थान का प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है ।

प्राकृतिक प्रसाधनों का मूल्य उनकी आर्थिक उपलब्धता पर निर्भर है—

यह मान लिया कि किसी देश की आर्थिक उन्नति केवल उसके ज्ञात प्राकृतिक

साधनों पर ही निर्भर नहीं होती। अतः यदि किसी देश के प्राकृतिक साधनों से सम्बन्धित आँकड़े एकत्र करके हमारे सामने रखे जायें, तो केवल उनके ही आधार पर हम उस देश की औद्योगिक उन्नति का अनुमान नहीं लगा सकते। फिर आँकड़े एकत्र करने में त्रुटि भी हो सकती है। आँकड़े अप्रचलित या पुराने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं एवं साधनों के बाजार में मूल्य प्रायः घटते-बढ़ते रहते हैं और मूल्यों के घटने-बढ़ने से प्राकृतिक प्रसाधनों की पहुँच बाजारों तक तथा पूरक प्रसाधनों तक अधिक-कम हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक साधनों का मूल्य आर्थिक पहुँच या उपलब्धता (Economic accessibility) और मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर होता है। आर्थिक पहुँच एवं मूल्यों के उतार-चढ़ाव बहुत ही अनिश्चित एवं अस्थायी घटक हैं। आर्थिक उपलब्धता ने अनेक अर्द्ध विकसित देशों को आर्थिक दशा को बहुत प्रभावित किया है। आर्थिक उपलब्धता के अनुकूल हो जाने पर बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने अपना विकास कर लिया। उदाहरण के लिये, स्वेज नहर के खुलने पर इंग्लैंड के लिये आर्थिक उपलब्धता अधिक अनुकूल हो गई और उसका व्यापार व्यवसाय बहुत बढ़ गया। अब हम कुछ प्रमुख प्राकृतिक प्रसाधनों पर विचार करेंगे।

भारत के प्राकृतिक प्रसाधन—

योजना कमीशन की नियुक्ति दो बानों के लिये हुई थी :—प्रथम, देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का अनुमान लगाना और जो साधन देश की आवश्यकताओं को देखते हुये कम प्रतीत हो उनकी वृद्धि की संभावनाओं पर विचार करना, तथा, दूसरे, देश के विभिन्न साधनों के सन्तुलित और प्रभावशाली प्रयोग के लिये एक योजना बनाना। अतः प्रथम पंच-वर्षीय योजना ने उस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर देश के साधनों का विवरण प्रस्तुत किया, उनकी समस्याओं का संकेत किया और सर्वे व अनुसन्धान के लिये कार्यक्रम निश्चित किये। सर्वे संगठनों को विस्तृत एवं सुसज्जित करने के उपयोगी सुझाव भी दिये। आजकल अनेक सर्वे व अनुसन्धान संगठन कार्यशील हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं :—The Indian Council of Agricultural Research, The Central Water and Power Commission, Central Board of Irrigation and Power, Geological Survey of India, Oil and Natural Gas Commission, Indian Bureau of Mines, Survey of India, Forest Research Institute, Atomic Energy Commission, The Council of Scientific Research आदि। इन्होंने कई नये सर्वे व अनुसन्धान

किये हैं जिनसे देश के प्राकृतिक साधनों का अधिक सही अनुमान लग सका है। किन्तु प्राकृतिक साधनों के लिये बढ़ी हुई माँग ने टेक्नोलॉजिकल विकासो को प्रेरित किया है, जिससे कुछ पिछले दोष दूर होकर साधनों की पूर्ति बढ़ गई है। प्राकृतिक साधनों की माँग एवं पूर्ति में परिवर्तन लाने वाले गतिशील घटक यह आवश्यक करते हैं कि प्राकृतिक साधनों का निरन्तर अध्ययन किया जाता रहे तथा तत्सम्बन्धी नीतियों में भी संशोधन किये जावे। प्राकृतिक प्रसाधनों पर एक समन्वित ढंग से विचार करना चाहिये और दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिये उनका अनुसन्धान व प्रयोग नियोजित करना चाहिये। जिस सीमा तक साधनों का अध्ययन किया गया है तथा भावी आवश्यकताओं के सदर्भ में उनके प्रयोग की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है। वह हमारी भविष्य व्यवस्था के भावी विकास की दूर की निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। सतुलित विकास के लिये यह भी आवश्यक है कि देश के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के लिये उपलब्धताओं, आवश्यकताओं एवं सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जाय। अभी हाल में ही योजना समीक्षण के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय संगठन प्राकृतिक साधनों के अध्ययन के लिये स्थापित किया गया है, जो अन्य संगठनों की सहायता करता है तथा उनके कार्यों का समन्वय करता है।

(1) भूमि (Land Resources) —

देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन भूमि (Land) है, जो कि कृषि उत्पादन के लिये आधार का कार्य करता है। जबकि जन संख्या वृद्धिशील है भूमि का क्षेत्रफल स्थिर है तथा उसका एवं निश्चित अनुपात ही कृषि के लिये उपयुक्त है। भूमि से सम्बन्धित कई समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है, — (i) निचोड़ एवं अन्य उपायों द्वारा भूमि की उत्पादकता में काफी वृद्धि की जा सकती है, (ii) कुछ बेकार पड़ी हुई भूमि को भी कृषि के अन्तर्गत लाया जा सकता है, (iii) बढ़ती हुई जन संख्या के लिये मकान आदि बनाने से कृषि भूमि कम हो जायेगी, (iv) यातायात के साधनों के विकास के कारण भी उपजाऊ भूमि कम होने की सम्भावना है, एवं (v) शीघ्र नगरीयकरण एवं बड़े शहरों के विकास के कारण पार्क आदि के लिये भूमि की आवश्यकता होगी। इन सब बातों के सदर्भ में यह प्रयास होना चाहिये कि जो कुछ उर्वरा भूमि बच सके बचाई जाय।

भूमि का उपयोग (Land Utilisation) —

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०६ मि० एकड़ है, जिसमें से रिपोर्ट मिलने वाले क्षेत्रफल की मात्रा ७२१ मि० एकड़ है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ३१८ मि० एकड़ है। भूमि उपयोग के वर्तमान एवं सम्भावित स्वरूप पर निम्न तालिका में प्रकाश डाला गया है :—

Table 1.
Land utilisation in 1965-66

Particulars of Area	(Area in million acres)		
	1955-56	1960-61	1965-66
Total reporting area	720.0	721.0	721.0
Forests	125.6	131.0	132.0
Land under miscellaneous tree crops and groves	13.9	14.0	15.0
Permanent pastures and other grazing lands	28.4	32.0	32.0
Culturable waste	54.8	47.0	40.0
Barren and uncultivated land and land put to non agricultural use	118.7	114.0	114.0
Fallow lands other than current fallows	30.9	28.0	26.0
Current fallows	29.5	28.0	25.5
Net area sown	318.2	327.0	335.0
Area sown more than once	44.4	51.5	67.0
Gross area sown	362.6	378.5	402.0

भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता लगभग ०.८२ एकड़ है, जबकि इंग्लैंड में ०.४२, जर्मनी में ०.४८, जापान में ०.१७, चीन में ०.५०, अमेरिका में २.६८ तथा रूस में २.५६ है।

मिट्टी सम्बन्धी सर्वे (Soil Surveys)—

मिट्टी सम्बन्धी सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण करना तथा स्थान निश्चिन करना, विभिन्न मिट्टियों के अन्नर मापन करना तथा विभिन्न मिट्टियों के ज्ञान का समन्वय करना है, जिससे भूमि के अधिक उत्तम प्रयोग की योजनायें बना सक। सन् १९५५ में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था द्वारा एक अखिल भारतीय मिट्टी सर्वे योजना प्रारम्भ की गई थी। चूंकि एक से अधिक राज्यों की मिट्टी सम्बन्धी सामान्य समस्याएँ हैं तथा प्रत्येक राज्य का अपना मिट्टी-सर्वे-संगठन नहीं है, इसलिये भारत के चार प्रमुख मिट्टी प्रदेशों के लिये प्रादेशिक आधार पर सेवोरेटरियाँ खोलने का निश्चय किया गया—प्रथम दिल्ली में नदी या बाढ़ द्वारा लाकर छोड़ी गई मिट्टी के प्रदेश के लिये, दूसरी पूना (अब नागपुर) में काली मिट्टी के प्रदेश के लिये, तीसरी सडगपुर (अब कलकत्ता) में लाल एवं लेटेराइट मिट्टी के प्रदेश (I) के लिये तथा चौथी बंगलौर में लाल एवं लेटेराइट मिट्टी के प्रदेश (II) के लिये। तीन वर्ष बाद उक्त योजना को केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड द्वारा बनाई गई मिट्टी एवं भूमि

प्रयोग सम्बन्धी योजना से समन्वित कर दिया गया, जिससे छह प्रमुख नदी घाटी योजनाओं (मचकुड, हीराकुड, चम्बल, भाखरा नगल, कोसी एवं दामोदर) के प्रभाव-क्षेत्र में मिट्टी एवं भूमि प्रयोग सम्बन्धी सर्वे करने में सुविधा हो जाय। नदी घाटी योजनाओं के प्रभाव क्षेत्र (Catchment areas) में सर्वे करने का उद्देश्य भूमि संरक्षण के उपाय करने की दृष्टि से विभिन्न मिट्टियों की संरक्षण क्षमता का पता लगाना है। कुल ५,००,००० वर्ग मील का सर्वे करना है। सन् १९६१ तक १८,००० वर्ग मील का अखिल भारतीय योजना के अन्तर्गत सर्वे हो चुका है। इसमें से ३,००० वर्ग मील नदी घाटी योजनाओं के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। राज्यों में मिट्टी सर्वे सगठनों ने लगभग ५०,००० वर्ग मील का सर्वे किया है। तृतीय योजना काल में अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग २३,००० वर्ग मील क्षेत्रफल के सर्वे की योजना है।

बिना जोती भूमि का सर्वे —

बिना जोती हुई भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाकर, एक फसल वाले क्षेत्र में दो फसलें पैदा कर तथा गहन कृषि के अन्य उपायों द्वारा कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि की जा सकती है। दुहरी फसल पैदा करके बोये गये कुल क्षेत्रफल में वृद्धि करने की बहुत गुंजाइश है। यह भाषा की गई है कि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सन् १९६०-६१ में ५२ मि० एकड़ से सन् १९६५-६६ तक ६७ मि० एकड़ हो जायगा। सन् १९५५-५६ में कृषि योग्य अन्न-जोती भूमि का क्षेत्रफल लगभग ५५ मि० एकड़ था। जून सन् १९५६ में भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य भूमि का सर्वे करके उसे 'ऊसर भूमि के अतिरिक्त अन्न-जोती भूमि' एवं 'ऊसर भूमि' की श्रेणियों में वर्गीकृत करना तथा ऐसे क्षेत्र का पता लगाना था जहाँ सुधार एवं पुनर्वास के लिये विशाल भूमि खंड उपलब्ध हो। कमेटी ने ७ राज्यों में सर्वे पूरा कर लिया है। इनमें कृषि के लिये उपलब्ध अन्न-जोती भूमि २५० एकड़ या अधिक के खण्डों में उपलब्ध है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग १ मि० एकड़ है। किन्तु कमेटी ने यह स्वीकार किया है कि ये आकड़े विश्वसनीय हैं। अधिक विश्वसनीय आकड़े प्राप्त करने के लिये reconnaissance surveys करानी चाहिये।

(II) वन सम्बन्धी प्रसाधन (Forest Resources)—

११२६ मि० वर्ग मील के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से लगभग २,७४,००० वर्ग मील अर्थात् २१.८% क्षेत्रफल वनों से ढका है। जलवायु एवं ऊँचाई के अन्तरों के कारण भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। वनों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :—

Table 2.
Classification of forests

Serial No.	Particulars	Percentage
(I)	Temperate forests	
	(a) Coniferous	3
	(b) Broad-leaved	4
(II)	Tropical forests	
	(a) Deciduous	80
	(b) Evergreen	12
(III)	Others	1

भारतीय वनों की उत्पादकता काफी बढ़ाई जा सकती है। वनों की गणना प्रगति के कुछ नवकरण योग्य साधनों में की जाती है। यदि इनका सुप्रबन्ध किया जाय, तो वे बिना घटी हुई दर पर तथा अनिश्चित समय तक उत्पत्ति प्रदान कर सकते हैं। इस समय इमारती लकड़ी एवं ईंधन की लकड़ी तथा दवाईयों, कागज व लुग्दी के लिये कच्चे माल की एवं पशुओं के लिये चारे की कमी अनुभव हो रही है। भूतकाल में स्थानीय वन-प्रसाधनों का कोई अनुमान नहीं लगाया था तथा बाहर से अनेक वन-उत्पत्तियों का आयात स्वतन्त्रतापूर्वक होता रहा था। ऐसे वन-उद्योग देश में ही विकसित करने की दृष्टि से इन कच्चे मालों की स्थिति का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में औद्योगिक लकड़ी का प्रति व्यक्ति उपभोग केवल ०.६ घनफुट है, जबकि फ्रांस में यह १६० घन फुट तथा जापान में १३४ घन फुट है। भारत की औद्योगिक लकड़ी सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकता लगभग ४५ मि० टन है और सन् १९७५ तक ६ मि० टन हो जाने की आशा है। ईंधन सम्बन्धी लकड़ी की माग १०० मि० टन हो जाने की सम्भावना है।

उपरोक्त आवश्यकता को देखते हुये यह आवश्यक हो जाता है कि गहन विकास योजनाओं के प्रति वर्ष उत्पादन में वृद्धि की जाय। गहन विकास योजनाओं (Intensified development schemes) में निम्न का समावेश है—उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों का चुनाव, जल्दी बढ़ने वाली किस्मों को बोना, सुधरी हुई प्रोसेसिंग टेक्नीकों का प्रवर्तन व यातायात के साधनों का विकास। यद्यपि इस समय औद्योगिक लकड़ी की आवश्यकता एवं पूर्ति का ग्लोबल अनुमान है तथापि विशेष उपाय न करने की दशा में अगले १०-१५ वर्षों में बहुत अभाव अनुभव होने लगेगा। अतः उत्पादन की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। पहाड़ी वनों का विकास करना चाहिये, निम्न ब्रेड की इमारती लकड़ी का सुधरे हुये ढग से प्रयोग करना, ईंधन की लकड़ी के उपयोग में

मितव्ययिता करता तथा विशिष्ट उद्योगों के सदर्भ में जल-प्रसाधनो का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराना भी आवश्यक है ।

(III) जल प्रसाधन (Water Resources)—

जल प्रसाधनो का माटे तीर पर दो भागों में विभाजन किया जा सकता है : भूमि की सतह का जल (surface water) एवं भूमि के नीचे का जल (Underground Water) । सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल-निवासी, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग की दृष्टि से भी इनके विकास पर विचार करना आवश्यक है ।

भूमि की सतह का जल—

सम्पूर्ण देश का वार्षिक वर्षाजल ३,००० मि० एकड़ फीट से भी अधिक है । इसमें से लगभग १,००० मि० एकड़ फीट जल वाष्प बन कर तत्काल गड़ हो जाता है और १५० मि० एकड़ फीट जल मिट्टी में चला जाता है । शेष १,३५० मि० एकड़ फीट जल नदियों में प्रवाहित होता है । भूमि की सतह पर बहने वाले सम्पूर्ण जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भूमि की रचना, जलवायु एवं मिट्टी सम्बन्धी दशाएँ पूर्णतः अनुकूल नहीं हैं । यह अनुमान लगाया गया है कि केवल ४५० मि० एकड़ फीट जल ही सिंचाई के लिये प्रयोग किया जा सकता है । सिंचाई के लिये जल प्रयोग की वास्तविक प्रगति निम्न प्रकार हुई है:—

Table 3

Surface water utilisation for irrigation

Period of Utilisation	Million acre feet	As percent of usable flow	As percent of total flow
Up to 1951	76	17	11
Up to 1960-61	120	27	9
Up to 1965-66 (anticipated)	160	36	12

भूमि के अन्दर का जल—

जो ६५० मि० एकड़ फीट जल प्रति वर्ष मिट्टी में चला जाता है उसमें से लगभग ३५० मि० एकड़ फीट जल ठपरी परतों में रह जाता है और जनस्थिति की पैदावार के लिये मिट्टी को आवश्यक नमी प्रदान करता है । शेष ३०० मि० एकड़ पानी गहरी परतों में पहुँचकर भूमि के अन्दर के जल को वार्षिक वृद्धि करता है । किसी विशेष समय पर ऐसे जल का कुल भण्डार उच्च मात्रा से कई गुना हो सकता है । इस समय भूमि के भीतरी जल का प्रयोग वार्षिक वृद्धि का केवल २०% है । पिछले आठ वर्षों में भीतरी जल के अनुसन्धान को कई योजनाओं कार्यान्वित की गई हैं, जिससे तलछूप हटाने के लिये अनुकूल क्षेत्रों का पता लग सके । तीसरी योजना विधि में लगभग

५०० खोजात्मक छेदन (exploratory borings) किये जायेंगे। इनकी सुविधा के लिये भू-भौतिकी अनुसन्धान भी कराये जायेंगे।

जल का प्रयोग—

जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई एवं बिजली-उत्पादन के सम्बन्ध में है, लेकिन सावजनिक जल पूर्ति, औद्योगिक एवं नौवहन कार्यों के लिये भी जल का प्रयोग होता है। सिंचाई के लिये जलपूर्ति भूमि पर बहने वाले और भूमि के अन्दर वाले दोनों ही जल-साधनों से प्राप्त की जा सकती है। वन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग ने सन् १९५४ में देश के विभिन्न भागों में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई-योजनाओं के लिये जल-उपलब्धि का अनुमान लगाने के हेतु एक सर्वे का प्रारम्भ किया था। इसके लिये सम्पूर्ण देश को ५ क्षेत्रों में बांटा गया है और इनमें से चार क्षेत्रों के सम्बन्ध में सर्वे पूर्ण हो गई है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार बड़ी एवं मध्यम योजनाओं से सिंचाई सम्भावनाओं का अनुमान १०० मि० एकड़ रखा गया है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :—

Table 4.

Irrigation potential of major and medium projects

Zone	Particulars	Irrigation potential (million acres)
1	West flowing rivers (covering river basins in Kerala, Mysore and Maharashtra States and the basins of Tapti, Narmada & others)	10
2	East-flowing rivers (covering the basins of Tambraparani, Vaigai, Cauveri, Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar and others)	33
3	Indus basin	13
4	Ganga basin (covering Chambal, Jamuna, Ramganga, Tons, Gomti, Sone, Ganga and its tributaries)	41
5	Brahmaputra basin	3
Total		100

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये सम्भावनाओं का निर्धारण करने के हेतु सन् १९५५ में खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय की छोटी सिंचाई योजना समिति ने प्रथम व्यापक प्रयास किया था। राज्य सरकारों ने भी ऐसे सर्वे कराये हैं। इन सर्वे-परिणामों के अनुसार लघु सिंचाई योजनाओं की कुल सम्भावनाएँ ७५ मि० एकड़ हैं। द्वितीय योजना

के अन्त में बड़ी एत छोटी योजनाओं द्वारा भीजा गया शुद्ध क्षेत्रफल लगभग ३१ मि० एकड़ है। अतः स्पष्ट है कि सीमित क्षेत्रफल की वृद्धि करने के हेतु काफी गुंजायश है। सिंचाई की कुल संभावनाओं (१७५ मि० एकड़) का अगले २०-२५ वर्षों में प्रयोग करने (जब कि जोता गया क्षेत्रफल ३५० मि० एकड़ तक बढ़ जायेगा) सीमित भूमि का अनुपात ५०% हो जायेगा और जल प्रयोग की मात्रा ३५०-४०० मि० एकड़ फीट हो जायेगी, जोकि वार्षिक जल पूर्ति (ऊपरी एवं भीतरी) का ६०% है। इस प्रकार अन्य प्रयोगों के लिये पर्याप्त जल पूर्ति बच जायेगी।

उद्योग में जल का प्रमुख प्रयोग वायलर को ठंडा करने एवं प्रोसेसिंग के लिये होता है। जल सम्बन्धी औद्योगिक आवश्यकताएँ तेजी से बढ़ रही हैं। अतः उद्योगों में जल के संरक्षण एवं पुनर्प्रयोग की समस्या पर ध्यान देना अति आवश्यक है। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि उपलब्ध जल पूर्ति (विशेषतः नदियों का जल) औद्योगिक निष्कासनों से खराब हो जाता है। इसका मछलियों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा पीने का पानी भी दूषित हो जाता है। इस सम्बन्ध में प्रल्लित भारतीय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संस्था, भारतीय चिकित्सा परिषद तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था द्वारा अध्ययन किये जा रहे हैं। इनके सर्वे एवं प्रयोग सम्बन्धी कार्यों में समन्वय लाने की बड़ी आवश्यकता है।

(IV) मत्स्य केन्द्र (Fisheries)—

अन्तर्देशीय मत्स्य केन्द्र—

नदियाँ एवं उनकी शाखाएँ, नहरें, भीरें, जल भंडार व तालाब, जिनमें जल पूर्ति निरन्तर रहती है, अन्तर्देशीय मत्स्य केन्द्रों के समाहित क्षेत्र हैं। प्रति वर्ष पकड़ी जाने वाली मछलियों की कुल १४ मि० टन मात्रा में से लगभग ३,००,००० टन मात्रा अन्तर्देशीय जल (Inland Water) से प्राप्त होती है। प्रथम योजनावधि में अन्तर्देशीय जल के एक मि० एकड़ से भी अधिक का सर्वे किया गया तथा ६८,००० एकड़िय जल क्षेत्र का सुधार किया गया। द्वितीय योजना में लगभग ३,४०,००० एकड़िय जल क्षेत्र का सर्वे किया गया तथा ७,२०,००० एकड़िय जल-क्षेत्र का स्टाक किया गया। तीसरी योजना में ५०,००० एकड़िय जल के क्षेत्र का विकास प्रदर्शन मछली केन्द्रों के रूप में किया जायेगा, १,५०० एकड़िय जल क्षेत्र नदी के मुहाने की मछलियों के पालन के लिये और १,५००-२,००० एकड़ दलदली एवं उसर भूमि को मछली पालन के हेतु सुधारने के लिये रखा गया है। ऐसे सब जल-क्षेत्र का पूर्ण सर्वे कराने की आवश्यकता है, जो गर्मियों में सूखें नहीं और जहाँ मछली स्टाक की जा सके।

सामुद्रिक मछली केन्द्र—

वार्षिक कुल मछली उत्पादन १४ मि० टन है, जिसमें से ११ मि० टन सामु-

द्रिक मछलियों का उत्पादन है। सामुद्रिक मछलियों की प्रमुख फणले मेकेरेल, सार्डिन एवं प्रोन हैं। भारत की कुल आवश्यकता ४ मि० टन के बराबर है, लेकिन उत्पादन की दर आवश्यकता की एक चौथाई है। सामुद्रिक मछलियाँ तट से ६ से १० मील तक पकड़ी जाती हैं। अभी तक भारत के सामुद्रिक मछली केन्द्रों का उचित प्रकार से अनुमान नहीं लगाया है। इस सम्बन्ध में पूर्ण सर्वे की आवश्यकता है, क्योंकि सामुद्रिक प्रसाधन भू-प्रसाधनों का उपयोगी पूरक हो सकते हैं।

(V) खनिज साधन (Mineral Resources)

खनिज पदार्थों का वर्तमान औद्योगिक प्रयोज्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, कुछ खनिज पदार्थ (जैसे कोयला एवं खनिज तेल) शक्ति के स्रोत हैं और कुछ उद्योग के लिये कच्चे माल का काम करते हैं, जब कि कुछ खाँड, कपास आदि प्राकृतिक पदार्थों के लिये स्थानापन्न का कार्य करते हैं।

कोयला—

देश में कोयले के भंडारों का अनुमान ५०,००० मि० टन है, जिसमें से कोकिंग कोयले का कोष २,८०० मि० टन के लगभग है। कोकिंग कोयले के कोष भविष्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। १ टन स्टील के लिये २२ टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। अगले १५ वर्षों में स्टील के उत्पादन की वृद्धि सम्बन्धी जो योजना बनाई गई है उसके कारण कोकिंग कोयले की मांग बहुत बढ़ जायेगी। अतः कोकिंग कोयले के सीमित भंडारों को सावधानी से प्रयोग करना जरूरी है। गैर कोकिंग कोयले की स्थिति प्रसन्नोपजनक नहीं है। किन्तु घटिया कोयले की ही मात्रा अधिक होने से बढ़िया कोयले के उपभोग में मितव्ययिता बरतनी चाहिये।

कुल पर कोयले के भंडार कुछ विशेष क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। कोयले की पूर्ति का लगभग ८०% बिहार एवं ५० बंगाल के २०० मील के क्षेत्र में विस्तृत खान-समूह से प्राप्त होता है और दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत में उपभोग हेतु ले जाने के लिये उसका ४०० से १,४०० मील तक यातायात करना पड़ता है। बिहार व ५० बंगाल से बाहर की कोयला खानों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सन् १९५१ में उनका उत्पादन ५७ मि० टन था (कुल का १६%), जो सन् १९६० में बढ़कर १०२ मि० टन (कुल का २०%) हो गया। तीसरी योजना के अन्त तक यह २८ मि० टन हो जायेगा (कुल का लगभग २१%)।

खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस—

कोयले के बाद व्यापारिक शक्ति के प्रमुख साधन हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। अब तक भारत ने इनका कोई विशेष विकास नहीं किया है। लेकिन तेल के लिये विस्तृत जाँच जारी है। आसाम में नये तेल कूपों से लगभग २७५ मि० टन तेल प्रति वर्ष मिलने का अनुमान है। पेट्रोलियम के सम्बन्ध में आसाम में प्राकृतिक

गैस की विशाल मात्रा पाई जाती है। इसके अनिश्चित सम्बद्ध प्राकृतिक गैस भी काफी मिलती है। सम्बद्ध प्राकृतिक गैस (Associated Natural Gas) का प्रयोग करने के लिये योजनायें बनाई गई हैं। अभी हाल में कैम्बे और अकालेश्वर क्षेत्र में जो ड्रिलिंग अभियान हुआ है उसके उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं और यह आशा की जाती है कि सन् १९६५-६६ के अन्त तक इन क्षेत्रों से उत्पादन की मात्रा २ मि० टन तक पहुँच जायेगी।

पेट्रोलियम उत्पादों की माग में वार्षिक वृद्धि पिछली दशकब्दी में ४५% थी। वर्तमान दशकब्दी में इसके १०-११% हो जाने की सम्भावना है। कुल माग जो सन् १९६० में ७.५ मि० टन थी, सन् १९६५-६६ तक ११ मि० टन हो जाने की आशा है। ५ मि० टन के इस घाटे को आयात द्वारा पूरा करने के लिये ५० करोड़ रु० के लगभग विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ेगी। घरेलू आवश्यकता (रोशनी के लिये मुख्य मिट्टी के तेल की) कुल उपयोग का २५%, यातायात के लिये आवश्यकता (डीजल तेल व गैसोलीन) लगभग ३०%, फनेस सेल के हेतु उद्योग की आवश्यकता लगभग २०% है।

अग्नि खनिज पदार्थ—

यद्यपि प्रमुख खनिज क्षेत्र निश्चित व निर्धारित हो गये थे तथा देश की खनिज सम्पदा का एक मोटा अनुमान लगाया जा चुका था तथापि विस्तृत अनुसन्धान अभी कुछ वर्षों पहले तक नहीं किये गये थे। किन्तु जब से देश का नियोजित विकास प्रारम्भ हुआ तब से Geological Survey of India, Indian Bureau of Mines, National Laboratories एवं Atomic Energy Commission द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत एवं नियमित अनुसन्धान किये जाने लगे हैं। अतः अब खनिज सम्पदा के बारे में सही-सही परिमाणान्तरक एवं गुणान्तरक अनुमान सुलभ हो गये हैं। मैंगनीज का अनुमान २० मि० टन से बढ़ कर अब १८० मि० टन हो गया है। बिहार के भमजोर क्षेत्र में सल्फर युक्त माक्षिक (Sulphur Containing pyrites) मिलने से सल्फर सम्बन्धी माग आन्तरिक उत्पादन द्वारा काफी सीमा तक पूरी हो सकेगी। ताँबा, लोहा, क्रोमाइट, बानसाइट, मैंगनीसाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, जस्ता आदि के भंडारों का भी अनुमान लगा लिया गया है और उपलब्धता तथा भाग का अन्तर मालूम पड़ गया है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने अनुसन्धानों द्वारा खनिजों के गुण को, उनकी उपयोगिता को सुधारने का प्रयास किया है तथा दुर्लभ खनिजों के स्थानापन्न खनिज जायदादों को पट्टे पर उठाने एवं उनके विकास में समानता लाने का प्रयास किया गया है। कोयला खान संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम कोयले के प्रयोग में मितव्ययिता लाने का प्रयास करता है। निम्न तालिका में कुछ प्रमुख खनिजों के ज्ञात भंडार हैं। उनका वर्तमान उत्पादन एवं उनकी वर्तमान माग दिखाई गई है —

Table 5
Production and demand for minerals

Mineral	Unit	Estimated reserves	Pre ent production	Current consumption
Coal (non coking)	Million tons	50000	310	518
Coal (coking)	Million tons	2800	148	
Lignite	Million tons	2073	negligible	negligible
Mineral oil	Million tons	not assessed	02	00
Manganese ore	Million tons	180	12	13
Iron ore	Million tons	21870	105	03
Chromite	Million tons	23	010	80
Vanadium ore	Million tons	267		002
Tungsten (metal)	Tons	not assessed	0	30
Nickel (metal)	Tons	negligible		1020
Ilmenite (titanium ore)	Million tons	350	025	001
Copper (ore)	Million tons	329	044	007 (metal)
Lead ore	Million tons	107	3670 Tons (metal)	003 (metal)
Bauxite (aluminium ore)	Million tons	260	038	010
Zinc ore	Million tons		001	006
Gypsum	Million tons	1117	098	098
Magnesite	Million tons	100	015	014
Limestone	Million tons	15740	125	125
Phosphatic nodules	Million tons	20		
Apatite	Million tons	087	0014	022
Tin (metal)	Tons	negligible		4550
Graphite	Tons	not assessed	1500	2500
Sulphur (element)	Million tons	negligible		018
Pyrites 40 percent s	Million tons	384		
Asbestos	Tons	580000	1683	30000

(VI) शक्ति (Energy)—

औद्योगिकरण के कारण भारत में शक्ति के लिये माँग तेजी से बढ़ रही है। यातायात सुविधाओं की वृद्धि व जीवनयापन के स्तर में सुधार के कारण भी शक्ति के लिये माँग में वृद्धि हो गई है। अभी भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग विद्वत् में सबसे कम है। सन् १९६०-६१ में भारत में शक्ति का कुल उत्पादन १६५ मि० टन कोयले के तुल्य था। शक्ति के व्यापारिक स्रोत कोयला, पेट्रोल एवं गिरता हुआ पानी है। वायु शक्ति, सौर-शक्ति व ज्वार-शक्ति भी भावी साधन हैं। इस समय लगभग ६१% शक्ति अ-व्यापारिक स्रोतों से (जैसे गोबर, कड़ी, कोयला, खेतों का घास फूस आदि) प्राप्त होती है। यह बात निम्नलिखित तालिका से विदित हो जाती है (इसमें पशु शक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो लगभग ७६ मि० टन कोयला तुल्य प्रति वर्ष है) :

Table 6
Consumption of Energy in 1960-61

Source	Energy consumed (million tons of coal equivalent)	As percent of commer- cial energy	As percent of total energy
Coal	54.6	84.0	33.0
Oil	9.5	14.6	5.8
Water	0.9	1.4	0.6
Total Commercial	65.0	100.0	39.4
Cattle dung	46.0		27.9
Fuel wood	35.0		21.2
Agricultural wastes	19.0		11.5
Total non-Commercial	100.0		60.6
Total-all sources	165.0		100.0

विद्युत् शक्ति—

शक्ति के उत्पादन के लिये कोयला खानों पर निम्न श्रेणी के कोयले की विशाल मात्राएँ उपलब्ध हैं। अतः वहाँ कोयले की शक्ति से चलने वाले स्टेशन (Coal fired Stations) सुविधा से कार्य किये जाते हैं। विद्युत् स्टेशनों (Hydel Stations) की स्थापना में बहुत समय लग जाना है, खर्चा भी उन पर अधिक होता है तथा दूरस्थ स्थानों में स्थापित किये जाते हैं, जहाँ से शक्ति को दूर-दूर तक ले जाना पड़ता है। किन्तु ये शक्ति के अत्यन्त सस्ते साधन हैं। विभिन्न प्रकार के प्लान्टों की उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है :—

Table 7
Generating capacity by source

Plants	(Million kilowatts)			
	1951	1956	1961	1966
Hydel plant	0 56	0 94	1 93	5 10
Coal	1 59	2 27	3 46	7 08
Oil	0 15	0 21	0 31	0 36
Nuclear			.	0 15
Total	2 30	3 42	5 70	12 69

आजकल भारत में बिजली की शक्ति का उपभोग लगभग ४५ किलोवाट प्रति व्यक्ति है। सन् १९६५-६६ तक इसके ९५ किलोवाट हो जाने की आशा है। अन्य देशों की तुलना में भारत का उपभोग बहुत कम है। जापान में प्रति व्यक्ति उपभोग ९३० किलोवाट और इटली में ९२८ किलोवाट है।

जल शक्ति—

जल शक्ति की क्षमता ४१ मि० किलोवाट आंकी गई है और इसका विवरण इस प्रकार है —

Table 8
Water power potential

	(Million kW)
West flowing south Indian rivers	4 35
East flowing south Indian rivers	8 63
Central Indian rivers	4 29
Rivers of Ganga basin	4 83
Rivers of Indus basin	6 58
Brahmaputra and others	12 49
Total	41 17

परमाणु शक्ति—

एक आत्मनिर्भर परमाणु शक्ति कार्यक्रम के लिये ईंधन सामग्री की पर्याप्त पूर्ति होना एक पूर्व आवश्यकता है। कई दशब्दों से इस बात की जानकारी है कि केरल और मद्रास के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट बालू में विश्व में थोरियम के सबसे विशाल डिपोजिट उपलब्ध हैं। बिहार राज्य में मोनाजाइट बालू के विस्तृत

डिपाजिटो का पता लगा है। यूरेनियम के भारतीय रिजर्व विश्व के कुल यूरेनियम के बराबर हैं। देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के डिपाजिट भी मिलने की आशा है। बिहार में हजारों टन यूरेनियम वाले डिपाजिट का पता चला है तथा प्रतिदिन एक हजार टन खनिज निकालने के लिये एक खान स्थापित की जा रही है।

उपसंहार—

प्राकृतिक प्रसाधनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। पिछले १० वर्षों में देश के प्राकृतिक प्रसाधनों से सम्बन्धित नई सूचना उपलब्ध हो गई है। अब तो हमारे सब संगठन भी पूर्ण रूप से सुसज्जित हो गये हैं तथा उच्च कोटि के प्रशिक्षित एवं अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। यूनीवर्सिटी एवं प्राइवेट संस्थाएँ भी सर्वे कार्य में सहत्वपूर्ण योग दे रही हैं। प्राकृतिक प्रसाधनों के सही मूल्यांकन के आधार पर देश के आर्थिक विकास की ठोस योजनाएँ बनाई व कार्यान्वित की जा सकती हैं।

STANDARD QUESTIONS

1. "The economic prospects of a country or a region cannot be assessed properly on the sole basis of an enumeration of its known natural resources". Discuss.
2. Write an essay on the natural resources of India under the following heads, —
 - (a) Land Resources.
 - (b) Forest Resources
 - (c) Water Resources.
 - (d) Fisheries
 - (e) Energy, and
 - (f) Mineral Resources

अध्याय ५६

मानवीय प्रसाधन

(Human Resources)

भूमिका—

व्यक्ति एवं राष्ट्रों के गुणों एवं उनकी क्षमताओं में महत्वपूर्ण अन्तर होते हैं और इन अन्तरो का सतही आर्थिक कुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन अन्तरो के लिये बायोलॉजिकल, वातावरणात्मक एवं ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी होते हैं। पर्यवेक्षणों से इन कारणों पर प्रकाश डालने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि आर्थिक सिद्धान्तों का इन कारणों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। प्रस्तुत अध्याय में कुछ जन-संख्या सम्बन्धी कारणों पर प्रकाश डाला गया है, जो कि व्यक्तियों एवं समूहों के आर्थिक व्यवहार से सम्बन्ध रखते हैं।

जन-संख्या एवं वास्तविक आय—

जन-संख्या के आकार एवं वास्तविक आय में घनिष्ठ सम्बन्ध है। जन-संख्या सम्बन्धी स्थिति एवं प्रवृत्तियाँ सभी अर्द्ध-विकसित देशों में समान नहीं हैं। विभिन्न देशों में जन-संख्या के घनत्व, आयु रचना एवं जन-संख्या के परिवर्तन की दर सम्बन्धी अन्तर पाये जाते हैं। अधिक घने बसे हुये देश आवश्यक रूप से वे देश नहीं हैं जिनमें जन-संख्या की वृद्धि की दर सबसे तेज हो। सन् १८०० से भारत में जन-संख्या के बढ़ने की दर उसी अवधि में पश्चिमी यूरोप के कई देशों में जन-संख्या की वृद्धि दर से बहुत भिन्न नहीं थी। आजकल भी भारत में जन-संख्या के बढ़ने की दर अमेरिका की तुलना में कोई विशेष अधिक नहीं है। अन्तर की महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अर्द्ध-विकसित देशों में तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ी हुई कृषि पर अत्यधिक निर्भरता पाई जाती है, जिससे विशाल क्षेत्र उस अर्थ में अति-जन-संख्या वाले माने जाते हैं जिसमें पश्चिम में नहीं माने जाते। 'अति जन संख्या' (Over population) शब्द से अभिप्राय उस स्थिति का है जिसमें एक दो हुई टेक्नीक एवं प्राकृतिक साधनों के आधार पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत अधिक होणे, यदि जन संख्या का आकार कुछ छोटा होता। 'न्यून जन संख्या' (Under Population) का इससे विपरीत अर्थ होता है।

‘अनुकूलतम जन संख्या’ (Optimum Population) का अभिप्राय जन संख्या की उस स्थिति से है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिकतम होती है। लेकिन यह विचार बहुत कल्पनापूर्ण है। यदि उचित हो तो भी इस विचार के आधार पर जन संख्या के आकार का नियंत्रण करना सम्भव नहीं है। दी हुई परिस्थितियों में अनुकूलतम जन संख्या क्या होगी, इसका निर्धारण करना सम्भव है। अनुकूलतम जन संख्या के विचार की सबसे बड़ी दुर्बलता, जिसका अर्थ विकसित देशों के संदर्भ में विशेष महत्त्व है, यह है कि दिये हुये प्राकृतिक प्रसाधनों की दशा में प्रति व्यक्ति उत्पादन केवल संख्याओं का फलनात्मक है (Output per head is a function of numbers alone)। वास्तव में, वास्तविक आय पर न केवल निवासियों की संख्या का बरन् उनके गुणों का भी प्रभाव पड़ता है तथा अनुकूलतम (संख्या के अभाव में) जनता की योग्यता, क्षमता एवं मितव्ययिता पर निर्भर होता है।

अर्ध-विकसित देश का यह सामान्य अनुभव है कि बड़ी हुई उत्पत्ति के साथ जन संख्या की भी वृद्धि हो जाती है। अधिक प्रगतिशील देशों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित होने से जो प्रमुख सुधार हुये हैं उनमें से एक यह है कि मृत्यु दर कम हो जाती है, जबकि कुल उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार जन-संख्या उसी गति से बढ़ती है जिस गति से उत्पादन बढ़ता है। अतः जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो पाता, क्योंकि बड़ी हुई उत्पत्ति बड़ी हुई जन संख्या के काम में आ जाती है। जब निम्न देशों में बहुत घनी आबादी होती है तथा जन संख्या में बहुत निरपेक्ष वृद्धि हो जाती है, तो उनकी स्थिति बड़ी नाजुक होती है। क्योंकि एक भी फसल खराब हो जाने पर उत्पादन व उपभोग में बहुत घाटा हो जाता है, जिसकी पूर्ति विदेशों से करने पड़ती है तथा भुगतान समतुल्य सम्बन्धी समस्याएँ सामने आती हैं।

आर्थिक विकास के साथ मृत्यु दर में कमी आने के अतिरिक्त जन्म दर भी कम हो सकती है, क्योंकि विकास होने पर अनेक प्रकार के मनोरंजन उपलब्ध होने लगते हैं तथा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति भी सुधर जाती है। इस प्रकार जन संख्या के परिवर्तनों का आर्थिक विकास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। अब हम भारत की जन-संख्या सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करेंगे।

भारत में जन-संख्या का वितरण

प्रारम्भिक—

सम्प्रति के आरम्भ और सन् १८७२ ई० के बीच के भारतीय इतिहास की अनेक शताब्दियों तक की जन गणना के विषय में बहुत कम ज्ञान है। भारत में प्रथम जन गणना सन् १८८१ में हुई। इसके पूर्व श्री मोरलेण्ड की जन गणना के आधार पर सन् १६०५ (अकबर की मृत्यु का वर्ष) में भारत की जन-संख्या लगभग १० करोड़ थी, किन्तु श्री शिरान और प्रोफ़ेसर डेविस का मत है कि इस समय भारत की जन संख्या

लगभग १३ करोड़ थी। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में डाक्टर मुकर्जी ने जन-गणना अंक १५ करोड़ निश्चित किया है, अतः इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाता है उसका सार यह है कि योग्य की भाँति भारत में भी अतीत काल में जन-संख्या आज की अपेक्षा कम ही थी, किन्तु ज्ञान-ज्ञान इसमें वृद्धि होनी गई है। सन् १८८१ के बाद प्रत्येक १०वें वर्ष जन-गणना होनी चली आई है। विभिन्न जन-गणनाओं के आधार पर भारत की जन-संख्या अप्रतिष्ठित रही है :—

वर्ष	जन संख्या (दस लाख में)	दशान्दी की वृद्धि (दस लाख में)	वृद्धि का प्रतिशत
१८८१	२३५.५	—	—
१८९१	२३५.६	०.४	— ०.२
१९०१	२४६.०	१०.५	+ ५.६
१९११	२४८.१	०.६	— ०.६
१९२१	२७५.५	२७.४	+ १०.४
१९३१	३१२.८	३७.३	+ १२.७
१९४१	३५६.६	४४.१	+ १३.२
१९५१	४३६.४	७९.५	+ २२.२

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष की जन-संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। सन् १९४१ की अपेक्षा सन् १९५१ में १३.२% और सन् १९५१ की अपेक्षा सन् १९८१ में २२.२% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इस समय भारत की जन-संख्या विश्व की कुल जन-संख्या का १/७ भाग है। अर्थात् विश्व के प्रत्येक ७ व्यक्तियों में एक भारतीय है। चीन की जन-संख्या विश्व में सबसे अधिक है। ३० जून सन् १९५३ को वहाँ की जन-संख्या ६०,१६,१२,३७१ थी। चीन के बाद घनी जन-संख्या वाले देशों में भारत का ही स्थान है। दूसरे शब्दों में, जन-संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा नम्बर है।

राज्यानुसार जन-संख्या—

सन् १९६१ की जन-गणना के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों में जन-संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

सन् १९६१ की जनगणना

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील मे)	कुल आबादी	पुरुष	महिलायें
आंध्र	१,०६,०५२	३,५६,७७,६६६	१,८१,७५,३४६	१,७५,०२,६५०
असम	४७,०६८	१,१८,६०,०५६	६३,१८,२२६	५५,४१,८३०
बिहार	६७,१६८	४,६४,५७,०४२	२,३३,२८,१७८	२,३१,२८,८६४
गुजरात	७२,१५४	२,०६,२१,२८३	२,०६,३६,४७०	६६,८४,८१३
जम्मू-काश्मीर	—	३५,८३,५८५	१६,०२,६०२	१९,८०,९८३
केरल	१५,००३	१,६८,७५,१६६	८३,४५,८६७	८५,२९,३०२
मध्य-प्रदेश	१,७१,२१०	३,२३,६४,३७५	१,६५,६८,८२६	१,५७,९५,५४९
मद्रास	५०,१३२	३,३६,५०,६१७	१,६६,१५,४५४	१,६७,३५,४६३
महाराष्ट्र	१,१८,८८४	३,६५,०४,२६४	२,०४,१६,०५६	१,६०,८८,२०८
मैसूर	७४,१२२	२,३५,४७,०८१	१,२०,२१,२४८	१,१५,२५,८३३
उड़ीसा	६०,१६२	१,७५,६५,६४५	८७,७२,१६४	८७,९३,४८१
पंजाब	४७,०८४	२,०२,६८,१५१	१,०८,६६,६१०	९४,०१,५४१
राजस्थान	१,३२,१५०	२,०१,४६,१७३	१,०५,५८,१३८	९५,८८,०३५
उत्तर-प्रदेश	१,१३,४५४	७,३७,५२,६१४	३,८६,६४,४६३	३,५०,८८,१५१
प० बंगाल	६३,६२८	३,४६,६७,६३४	१,८६,११,०८५	१,६०,५६,५४९
आन्ध्रमान-				
निकोबार	३,२१५	६३,४३८	३६,२५६	२७,१८२
दिल्ली	५७३	२६,४४,०५८	१४,८०,७०८	११,६३,३५०
हिमाचल प्रदेश	१०,८७६	१३,४८,६८२	७,००,७३८	६,४८,९४४
लक्षद्वीप, मिनि-				
काय व अमीन				
द्वीप	११	२४,१०८	११,६२७	१२,४८१
त्रिपुरा	४,०३८	११,४१,०६२	५,६१,२१४	५,८०,२७८
जोड़	११,२७,३४५	४३,६४,२४,४२६	२२,४६,५७,६४८	२१,१७,६६,७७८

भारत में जन-संख्या का घनत्व—

जन-संख्या के घनत्व (Density of Population) से आशय यह है कि किसी देश अथवा किसी राज्य में १ वर्ग मील में कितने व्यक्ति रहते हैं। यदि किसी राज्य का क्षेत्रफल २,००० वर्ग मील और वहाँ की जन-संख्या १ लाख है, तो वहाँ पर १ वर्ग मील में औसतन ५० व्यक्ति रहते हैं और इस प्रकार उस राज्य की

जन-संख्या का घनत्व ५० हुआ। अतः यदि हमको किसी देश की जन-संख्या का घनत्व पता लगाना है, तो पहले यह पता लगाना चाहिये कि उसका क्षेत्रफल कितना है और वहाँ की जन-संख्या कितनी है। तब जन-संख्या को क्षेत्रफल से भाग देना चाहिये और जो भजनफल निकले वही उस जन-संख्या का घनत्व होगा।

हमारे देश में जन-संख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील ३८४ है। यह समस्त देश का औसत घनत्व है, किन्तु देश के विभिन्न भागों की भाँकी करें, तो पता चलता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में जन-संख्या का घनत्व भिन्न है, जैसे—

दिल्ली	***	४,५७३
केरल		१,१२५
बङ्गाल	***	१,०३०
बिहार		६६०
उ० प्र०		६५०
पंजाब	.	४३१
राजस्थान		१५०
अण्डमान व निकोबार द्वीप		२०

जन-संख्या के घनत्व की भिन्नता के कारण—

जन संख्या के घनत्व की इस प्रादेशिक भिन्नता के कारण निम्नलिखित हैं —

(१) प्राकृतिक रचना—जन-संख्या का घनत्व किसी देश की प्राकृतिक रचना पर निर्भर करता है। जो स्थान पहाड़ी अथवा पठारी हैं अथवा जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है वहाँ घनत्व कम होता है और उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में प्रायः जन संख्या का घनत्व अधिक होता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बङ्गाल राज्यों में भूमि की उर्वरता के कारण ही जन संख्या का घनत्व अधिक है एवं राजस्थान के मरुस्थल और दक्षिण के पठारी प्रदेशों में घनत्व कम है।

(२) जलवायु—भूमि की रचना के साथ साथ सुंदर जलवायु का होना भी आवश्यक है। जलवायु पर लोगों का स्वास्थ्य ही नहीं वरन् फसलों का उत्पादन अधिक हो सकता है, यदि भूमि भी उपजाऊ हो। ऐसे प्रदेश अधिक व्यक्तियों के लिये जीवन निर्वाह का साधन प्रस्तुत कर

जन-संख्या के घनत्व की भिन्नता के १४ कारण

- (१) प्राकृतिक रचना
- (२) जलवायु
- (३) चावल की उपज के क्षेत्र
- (४) औद्योगिक उन्नति
- (५) सुरक्षा
- (६) विभाजन के फलस्वरूप आवास
- (७) प्रवासी प्रवृत्ति का प्रभाव
- (८) सिंचाई के साधन
- (९) नदियों के डेल्टे
- (१०) विशेष वस्तुओं के उत्पादन केन्द्र
- (११) खनिज पदार्थों के क्षेत्र
- (१२) यातायात के साधनों की सुविधा
- (१३) अनुकूल स्थिति
- (१४) अन्य कारण

जन-संख्या के घनत्व की भिन्नता के कारणों में से प्रत्येक कारण का प्रभाव जन-संख्या के घनत्व पर अलग-अलग होता है।

सकते हैं। यही कारण है कि भारत के दक्षिणी-पूर्वी भागों में अपेक्षाकृत जन-संख्या अधिक है।

(३) चावल की उपज के क्षेत्र—बङ्गाल तथा बिहार में भी जन-संख्या का घनत्व अधिक है, क्योंकि :—

(अ) अन्य अनाजों की अपेक्षा चावल की उतनी मात्रा से अधिक भ्रादमियों की उदरपूर्ति हो जाती है।

(आ) चावल में भोजन के अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं।

(इ) चावल की प्रति एकड़ पैदावार भी अधिक होती है।

(ई) चावल की फसल तैयार भी बहुत शीघ्र हो जाती है।

(४) औद्योगिक उन्नति—ऐसे प्रदेश जहाँ उद्योग-धंधों की प्रगति के लिये समस्त नैसर्गिक साधन उपलब्ध हो तथा आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो भाग समृद्धिशीली है, वहाँ भी जन-संख्या का घनत्व अधिक देखा जाता है, जैसे—बिहार, उड़ीसा इत्यादि।

(५) सुरक्षा—जिन प्रदेशों में मनुष्य को अपने जान व माल का भय नहीं होता, वहाँ भी घनत्व अधिक होता है। जैसे—मध्य-प्रदेश। इसके विपरीत पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जान व माल का भय होने के कारण जन-संख्या का बहुत कम घनत्व है।

(६) विभाजन के परिणामस्वरूप आवास—भारत के बँटवारे के बाद हमारे देश में अनेक ब्याप्त पाकिस्तान से आये और वे ऐसे प्रदेश में बस गये जहाँ की जलवायु उनके अनुकूल थी, अतः उन प्रदेशों में जन-संख्या का घनत्व बढ़ गया, जैसे—दिल्ली राज्य में।

(७) प्रवासी प्रवृत्ति का अभाव—भारतवर्ष में प्रवासी प्रवृत्ति का अभाव भी अधिक घनत्व के लिए उत्तरदायी है। अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने की अपेक्षा लोग अपने ही क्षेत्र में रहना अधिक पसन्द करते हैं, फलतः उन्हें निम्न जीवनस्तर अपनाना पड़ता है। भाषा, धर्म एवं संस्कृति की विषमता भी प्रवासी प्रवृत्ति में बाधक है।

(८) सिंचाई के साधन—जिन प्रदेशों में वर्षा का अभाव है, परन्तु सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ भी प्रायः जन-संख्या का घनत्व देखा जाता है। उदाहरणार्थ, उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग और दक्षिणी पंजाब में यद्यपि अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, परन्तु सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार इन भागों में अच्छी जन-संख्या है।

(९) नदियों के डेल्टे—नदियों के डेल्टों में भी अनेक सुविधाएँ होने के कारण जन-संख्या के घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जैसे—महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टों में अच्छी आबादी है।

(१०) विशेष वस्तुओं के उत्पादन केन्द्र—कुछ प्रदेशों में किंचित महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिससे आकर्षित होकर लोग वहाँ बस जाते हैं। जैसे असम में चाय के हरे-भरे बगीचों ने अनेक व्यक्तियों को आकर्षित कर लिया है। इसी प्रकार बंगाल में जूट के उत्पादन और काली मिट्टी के क्षेत्र में रुई के उत्पादन के कारण उन क्षेत्रों में जन-संख्या का अधिक घनत्व है।

(११) खनिज पदार्थों के क्षेत्र—जिन भागों में खनिज पदार्थ पाये जाते हैं वहाँ अन्य कठिनाइयों के होते हुए भी लोग जाकर बस गये हैं। उदाहरणार्थ, छोटा नागपुर का पठार खनिज सम्पदा की दृष्टि से अत्यन्त घनी है, अतः वहाँ अनेक लोग आकर बस गये हैं। इसी प्रकार राजस्थान में जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज हो रही है। यदि वहाँ पेट्रोल मिल जायगा, तो जन-संख्या के घनत्व में अवश्य वृद्धि हो जायगी।

(१२) यातायात के साधनों की सुविधा—जिन भागों में यातायात के साधनों का जाल बिछा हुआ है वहाँ भी प्रायः जन-संख्या का केन्द्रीयकरण देखा जाता है। जैसे, गङ्गा एवं सतलज के मैदान में, तटीय मैदान एवं डेल्टा क्षेत्रों में थल एवं जल मार्गों की सुविधा होने के कारण वहाँ घनी आबादी पाई जाती है। इसके विपरीत पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में मरुस्थली भागों एवं घने वनों में यातायात के साधनों की अपर्याप्तता अथवा अभाव के कारण जन-संख्या की मात्रा बहुत ही कम है।

(१३) अनुकूल स्थिति—जिन नगरों अथवा क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति अनुकूल होती है वहाँ भी जन-संख्या का आधिक्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, दिल्ली, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद आदि नगरों की अनुकूल स्थिति होने के कारण ही वहाँ जन-संख्या का अधिक घनत्व है।

(१४) अन्य कारण—प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि जो स्थान सुरक्षा की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ होते हैं, वहाँ भी जन-संख्या का केन्द्रीयकरण हो जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा, काश्मीर व आजाद काश्मीर की सीमा तथा गोघा में सुरक्षा की मात्रा कम होने से आबादी भी कम है। इसी प्रकार घने जङ्गलों में जङ्गली पशुओं के भय से वहाँ मनुष्य नहीं रहते। चम्बल के खण्डहरो में चोर व डाकुओं के भय के कारण लोग रहना पसन्द नहीं करते।

जन-संख्या के घनत्व के अनुसार देश के तीन भाग—

भारत एक विशाल देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा नाना प्रकार की रचना पाई जाती है। खनिज पदार्थों का वितरण भी समान नहीं है। परिणामस्वरूप यहाँ जन-संख्या का घनत्व भी देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग-अलग है। जन-संख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से देश को तीन क्षेत्रों में—ऊँचे, मध्यम तथा कम घनत्व वाले भागों में विभक्त किया गया है :—



जन संख्या के घनत्व के अनुसार देश के भाग हैं पाँच

- (१) घनी जन संख्या के क्षेत्र ।
- (२) अधिक जन संख्या वाले भाग ।
- (३) मध्यम जन संख्या वाले भाग ।
- (४) कम जन-संख्या वाले भाग ।
- (५) अत्यन्त कम जन संख्या वाले भाग ।

(१) घनी जन संख्या के क्षेत्र—इन क्षेत्रों के अंतर्गत ५० बङ्गाल, पू० पंजाब, द० प्रयाग, का दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास का तट सम्मिलित हैं जहाँ प्रति वर्ग मील में ५०० से अधिक व्यक्ति रहते हैं। यह प्रदेश विश्व के सबसे अधिक घने वसे भागों में से है। यहाँ समतल भूमि घनी वर्षा उपयुक्त गर्मी और यातायात के साधनों की सुगमता के कारण ही जन-संख्या का घनत्व अधिक है।

(२) अधिक जन संख्या वाले भाग—यहाँ प्रति वर्ग मील में ३०० से ५०० व्यक्ति तक रहते हैं। ऐसे भागों में दक्षिणी भारत की नदियों के डेल्टे, पूर्वी बिहार, महाराष्ट्र व गुजरात, द० पंजाब, कोकन तथा प० उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और जिन भागों में वर्षा की कमी है वहाँ उन्नत सिंचाई के साधनों द्वारा वह भाग पूरा हो गया है।

(३) मध्यम जन-संख्या वाले भाग—यहाँ प्रति वर्ग मील १५० से ३००

व्यक्ति रहते हैं। इसमें सम्पूर्ण द० प्रायद्वीप एवं उत्तर तथा पूर्वी पहाड़ी जङ्गलों में कम बस्ती के जङ्गलों को छोड़कर आसाम व हिमालय प्रदेश सम्मिलित हैं। मध्य-प्रदेश, बिहार के खनिज क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(४) कम जन-संख्या वाले भाग—यहाँ प्रति वर्ग मील में १०० से १५०

व्यक्ति से भी कम मनुष्य रहते हैं। इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य-प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग तथा आन्ध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। यहाँ की भूमि कम उपजाऊ है तथा जलवायु विषम है एवं यातायात के साधनों का भी प्रभाव है।

(५) अत्यन्त कम जन संख्या वाले भाग—यहाँ प्रति वर्ग मील में १००

से भी कम व्यक्ति रहते हैं। उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, तराई, असम की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश, मर्न पुर, कच्छ राज्य, जम्मू-काश्मीर, सुन्दरवन, छोटा नागपुर का पठार तथा उड़ीसा के सूखे भाग सम्मिलित हैं।

जन-संख्या सम्बन्धी विशेषताये—

भारत की वर्तमान जन संख्या (सन् १९६१ की जन गणना के आधार पर) की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताये अग्रलिखित है :—

भारतीय जन संख्या की प्रमुख

७ विशेषतायें

- (१) प्रादेशिक विभिन्नता।
- (२) निरन्तर वृद्धि।
- (३) ग्रामीण जन-संख्या में कमी।
- (४) साक्षरता में वृद्धि।
- (५) ली-गुरु अनुपात।
- (६) आयु के आधार पर जन-संख्या।
- (७) व्यावसायिक आधार पर विभाजन।

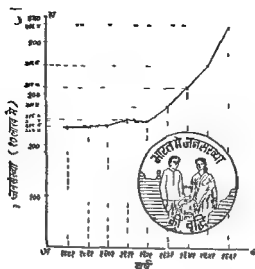
(१) प्रादेशिक विभिन्नता—

सन् १९६१ की जन-गणना के आंकड़ों से यह स्पष्ट प्रगट होता है कि देश के विभिन्न भागों में जन-संख्या का घनत्व अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, दिल्ली राज्य में जन-संख्या का घनत्व ४,५७३ है, जबकि राजस्थान में यह संख्या केवल १५० ही है।

(२) निरन्तर वृद्धि—जन-संख्या

के अनुसार विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा नम्बर है। सन् १९६१ की

जन-संख्या के अनुसार भारत में लगभग ४३½ करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं। यदि हम पिछली शताब्दी के जन-गणना सम्बन्धी आँकड़ों का अध्ययन करें, तो हमको पता लगता है कि सन् १९०१ से सन् १९६१ तक लगभग २० करोड़ व्यक्ति बढ़े। वृद्धि की दर पिछले दशकों की अपेक्षा गत दशकों में अधिक रही है।



(३) ग्रामीण जन संख्या में कमी— सन् १९५१ में २६,०४,५८,५६७ से जन-संख्या सन् १९६१ में ३३,८५,८४,५२६ तक पहुँच गई, जबकि शहरी जन-संख्या (जोकि सन् १९५१ में ६,१८,६५,३६२ थी) में १,५६,७४,५०८ की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि विचारार्थीन अवधि (१९५१-१९६१) में, कुल जन संख्या में ग्रामीण जन-संख्या का अनुपात ०.४६% कम हो गया, जबकि शहरी जन संख्या का अनुपात इतना ही बढ़ गया है। यही नहीं, दस लाख से अधिक जन-संख्या रखने वाले नगरो की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सन् १९५१ में इतनी जन-संख्या के केवल ४ नगर थे। लेकिन सन् १९६१ में यह संख्या ५ हो गई है। (पाँचवाँ शहर भुवनेश्वर है।) इन नगरो की जन-संख्या नीचे दिखाई गई है—

नगर	सन् १९६१	सन् १९५१
हैदराबाद	१२,५२,३३७	१०,८५,७२२
भुवनेश्वर	११,४६,८५२	७,७८,३३३
गुवाहाटी	१७,२५,२१६	१४,१६,०५६
बम्बई	४१,४६,४६१	२६,६४,४४४
कलकत्ता	२६,२६,४६८	२६,६८,४६४

नगरी जन-संख्या के अनुपात में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :—

(प्र) गाँव में व्यक्ति अधिक हैं और भूमि कम है। इसके अतिरिक्त वहाँ सहायक उद्योग धन्धो की भी कमी है। अतः पेट की खातिर गाँव से नगरो की ओर प्रवास बढ़ रहा है।

(ब) आर्थिक नियोजन के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में गाँव की अपेक्षा अधिक औद्योगीकरण हुआ है, जिसमें नगरों की ओर लोग का आकर्षण बढ़ गया है ।

(स) नगरों में गाँवों की अपेक्षा जीवन को सुखमय बनाने के लिये अधिक सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं । यही कारण है कि प्रायः सभी लोगों में नगरीय जीवन के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है ।

(द) जमींदारी व जागीरदारों, उन्मूलन के उतराने जमींदारों व जागीरदारों का गाँवों में नगरों की ओर प्रवास बढ़ रहा है ।

(य) देश के विभाजन के उपरान्त विस्थापितों ने अधिकांशतः नगरों में ही रहना पसन्द किया है, क्योंकि वहाँ उनको जीविकोपार्जन की अधिक सुविधायें मिलती हैं ।

(४) साक्षरता में वृद्धि—सन् १९६१ की जनगणना से पता चलता है कि देश की जन-संख्या का २३.७% भाग साक्षर (literate) हो गया है । सन् १९५१ में यह प्रतिशत केवल १६.६ था । इस प्रकार साक्षरता में ७.१% की वृद्धि हो गई है । लेकिन जब कि ३३.६% पुरुष जन-संख्या साक्षर है तब स्त्री जन-संख्या का केवल १२.८% भाग ही साक्षर है । सन् १९५१ में ये प्रतिशत क्रमशः २४.६% एवं ७.६% थे । इस प्रकार साक्षरता में प्रति वर्ष कुल जन-संख्या के आधार पर ०.७% औसत वृद्धि हुई, पुरुष जन-संख्या में ०.६% एवं स्त्री जन-संख्या में ०.५% औसत प्रति वर्ष वृद्धि है । हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में साक्षरता-प्रतिशत दो गुना नहीं हो पाया है । मध्य-प्रदेश व राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत काफी बड़ा है ।

(५) स्त्री-पुरुष अनुपात—किसी देश की सच्ची प्रगति के लिये स्त्री-पुरुषों का संतुलित अनुपात श्रेष्ठ होता है । कुल जन-संख्या में २२,४६,१७,६४८ पुरुष और २१,१४,६६,४८१ स्त्रियाँ हैं । सन् १९५१ में ये संख्याएँ क्रमशः १८,२८,७१,४२८ और १७,३०,७६,६३१ थीं । सन् १९६१ में प्रति १,००० पुरुषों की तुलना में ६४० स्त्रियाँ हैं, जबकि सन् १९५१ में ६४६ थी । सन् १९०१ के पश्चात् स्त्री-पुरुषों के अनुपात में इस प्रकार की कमी पहली बार हुई है । इस सम्बन्ध में एक अनोखी बात पाई गई है । २२° latitude के उत्तरवर्ती राज्यों में सैक्स अनुपात बहुत कम है, जबकि दक्षिणवर्ती राज्यों में (केवल मध्य प्रदेश व बिहार को छोड़ कर) सैक्स अनुपात अधिक है । गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास, आंध्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उ० प्र० और बिहार के कुछ जिलों में प्रति १०० पुरुष १०० से अधिक स्त्रियाँ हैं । मध्य प्रदेश, पंजाब एवं उत्तर-प्रदेश में कुछ छोटे-छोटे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ स्त्री-पुरुष अनुपात अमाधारण रूप से कम है । ७०-८० आयु वर्ग में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ दुगुनी हैं । सम्भवतः इसका कारण यह है कि पुरुषों का जीवन अधिक जोखिमपूर्ण होता है ।

(६) आयु के आधार पर जन-संख्या—आयु के आधार पर अध्ययन करने से भारतीय जन-संख्या के बारे में निम्न आकड़े प्राप्त होते हैं :—

शिशु व बच्चे	३८ ३%
युवा स्त्री-पुरुष	३३ ०%
प्रौढ स्त्री-पुरुष	२० ०%
वृद्ध स्त्री-पुरुष	८ ३%

इन आँकड़ों के विश्लेषण से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं :—

(अ) भारत में शिशुओं तथा बच्चों की जन-संख्या अधिक है, यद्यपि यह अभी सक्रिय नहीं है, किन्तु वास्तव में देश की प्रगति का कार्य-भार इन्हीं के कंधों पर माना है ।

(आ) भारत में वृद्ध स्त्री पुरुषों की संख्या बहुत थोड़ी है, अर्थात् वृद्ध होने से पहले ही प्रायः लोग मर जाते हैं, इससे देश को बड़ी हानि होती है, क्योंकि एक तो अनुभवी वृद्ध व्यक्तियों के उचित पच-प्रदर्शन का लाभ नहीं मिल पाता । दूसरे, उनके अभाव में उत्पादनशीलता भी घटती है ।

(इ) हमारी घीसत आधु भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है ।

(ई) देश में युवा एवं प्रौढों की जन-संख्या (३३ ० + २० ४) = ५३ ४% है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश के ३६-३७ करोड़ व्यक्तियों में से केवल १८ करोड़ व्यक्ति ही काम करने वाले हैं, अतः जितने व्यक्ति उत्पादन में सलग्न हैं उनके अतिरिक्त लगभग उतने ही व्यक्तियों का पोषण भी उन्हीं को करना पड़ता है ।

(उ) भारत में बच्चों का अनुपात ३८% और वृद्धों का केवल ८% यह संकेत करता है कि देश में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही अधिक हैं ।

(७) व्यावसायिक आधार पर विभाजन—भारत एक कृषि प्रधान देश है और सन् १९६१ की जन गणना में अनुसार कुल जन-संख्या के लगभग ६६% लोग कृषि से आजीविका प्राप्त करते हैं तथा शेष ३४% अन्य व्यवसायों में लगे हैं । सौराष्ट्र, कच्छ, अजमेर व दिल्ली राज्यों को छोड़ कर भारत के अन्य सभी राज्यों में कृषि की प्रधानता है । बंगाल तथा बम्बई जैसे औद्योगिक राज्यों में भी कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या अधिक है । हिमाचल प्रदेश व सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्यों में तो ६०% लोग कृषि द्वारा अपनी आजीविका पालते हैं ।

इङ्गलैण्ड तथा अमेरिका में लगभग आधे लोग कृषि पर और शेष उद्योगों में तथा अन्य कार्यों में लगे हैं अतः यदि इन देशों में कभी कृषि की दशा बिगड़ती भी है तो कोई विशेष चिन्ता नहीं करनी पड़ती, परन्तु हमारे देश में ऐसी परिस्थिति होने पर आर्थिक संतुलन ही बिगड़ जाता है । यही कारण है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना के द्वारा कृषि पर जनता के मार को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण हमारे देश के खेत बहुत छोटे-छोटे हैं एवं प्रति एकड़ उत्पादन भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है,

इसी कारण दरिद्रता एवं बेकारी बढ़ रही है तथा लोगों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। आशा है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा यह समस्या भविष्य में हल हो सकेगी।

क्या भारत में जन-संख्या का आधिक्य है ?—

कुछ लोगों के मतानुसार भारत में जन-संख्या का आधिक्य नहीं है, क्योंकि वहाँ जन-संख्या का घनत्व केवल ३८४ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जबकि हालैण्ड का ८२५३, बेल्जियम का ७३४४, जापान का ५७५४ और इङ्ग्लैण्ड का ५३७८ है। इस विचारधारा के समर्थक यह दलील देते हैं कि भारत के प्राकृतिक प्रसाधनों का अभी पूर्णरूपेण उपयोग नहीं हुआ है, अतः जन-संख्या अधिक प्रतीत होती है। यदि हम अपने नैसर्गिक साधनों का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करें, तो कहीं अधिक जन-संख्या का पालन कर सकते हैं। इसके विपरीत, दूसरी विचारधारा के समर्थक यह कहते हैं कि जन-संख्या के आधिक्य की कोई समस्या न समझना, वास्तव में सत्यता का गला घोटना है। जहाँ तक पहली दलील का सम्बन्ध है, उत्तरी-पश्चिमी भारत व मध्यवर्ती भारत के राज्यों को छोड़कर भारत के शेष राज्यों में जन-संख्या का घनत्व योरोप के घने आबाद देशों की तुलना में कम नहीं है, जैसे—दिल्ली में ४,५७३ व्यक्ति प्रति वर्ग मील, केरल में १,१२५, बंगाल में १,०३०, बिहार में ६६०, उत्तर-प्रदेश में ६५० और पंजाब में ४३१ है। इस द्वितीय विचारधारा के समर्थक निम्न दलीलों के आधार पर ऐसा कहते हैं कि भारत में जन-संख्या का आधिक्य है।

भारत में जन-संख्या का आधिक्य एवं उसके कारण—

(१) मालथस के सिद्धान्तानुसार—मालथस के जन-संख्या के सिद्धान्तानुसार यदि किसी देश में निवारक प्रतिबन्धों, जैसे—ब्रह्मचर्य पालन, कम आयु में विवाह न करना, गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग, जीवन स्तर में सुधार, आदि का अभाव होता है और इनके स्थान पर प्राकृतिक प्रतिबन्ध, जैसे—बीमारी, बेकारी, भूकम्प इत्यादि, क्रियाशील होते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि देश में जन-संख्या का आधिक्य है। भारत में निवारक प्रतिबन्धों का अभाव है। छोटी उम्र में विवाह होने के कारण एवं दूषित पिते वातावरण के कारण लोग ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ होते हैं। यहाँ विवाह एक धार्मिक कर्तव्य और स्वतन्त्रोत्पत्ति एक सामाजिक आवश्यकता समझी जाती है। आजकल देश में केवल बाल-विवाह एवं बहु-विवाह का ही प्रश्न नहीं है, बरन् वृद्ध विवाह का प्रचलन भी हमारे देश का बहुत बड़ा अभिशाप है। फलतः सिद्धान्तानुसार प्राकृतिक प्रतिबन्ध देश में अधिक क्रियाशील रहे हैं, जैसे—महामारियाँ, दुमिख, बाढ़, भूकम्प, दंगे इत्यादि। यहाँ मलेरिया से प्रति वर्ष १५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं। सन् १९४३ के बंगाल दुमिख में ३५ लाख व्यक्तियों की बलि चढ़ी। सन् १९५७ के ग्रीष्म काल में पनू के दानव ने अनेक व्यक्तियों के प्राण लिये। सन् १९५८ में रेल-दुर्घटनाओं एवं बाढ़ की आपत्तियों से भी सहस्रो व्यक्तियों की जानें चली गईं, अतः स्पष्ट है कि निवारक प्रतिबन्धों के अभाव में प्रकृति अपना कार्य तीव्रता से कर रही है। यह जन-संख्या के आधिक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

(२) खाद्य समस्या के आधार पर—हमारे देश में जन संख्या जिस गति से बढ़ी है, भोज्य सामग्री का उत्पादन उम अनुपात में नहीं बढ़ा है। सन् १९३८ में श्री बी० के० वत्तल ने अखिल भारतीय जन संख्या सम्मेलन के समक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया था कि सन् १९१४ और सन् १९४० के बीच की अवधि में भारत में जन-संख्या की वृद्धि १% हुई, परन्तु भोज्य सामग्री में वृद्धि केवल ०.६५% हुई। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त हमारी खाद्य समस्या ने एक उग्र रूप धारण कर लिया और देश के विभाजन ने बड़े पर नमक छिड़कने का कार्य किया। बंटवारे के परिणामस्वरूप यद्यपि भारत को कुल क्षेत्रफल का ७७% भाग मिला, किन्तु जन-संख्या ८१% मिली। भारत से पाकिस्तान में केवल ७५ लाख लोग गये, किन्तु वहाँ से हमारे देश में १ करोड़ से भी अधिक व्यक्ति आये। राष्ट्रीय योजना समिति सन् १९४७, पंच-वर्षीय योजना आयोग सन् १९५३ एवं खाद्यान्न जाँच समिति सन् १९५७ की रिपोर्टों के अनुसार भी इसी मत की पुष्टि होनी है कि जन संख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है।

(३) वृद्धि की अत्यधिक गति—देश में जन संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। परन्तु जहाँ जन संख्या में वृद्धि हो रही है, वहाँ प्रति व्यक्ति बोई गई भूमि निरन्तर घटती जा रही है। यही नहीं हमारे देश में गेहूँ और चावल उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जितनी तेजी से अन्य भोटे अनाजों का उत्पादन। खाद्य सामग्री के अतिरिक्त हमारे देश में चीनी, सब्जी, दूध इत्यादि का उपभोग भी निरन्तर कम होता जा रहा है।

(४) बेकारी की समस्या—यदि जन संख्या अनुकूलतम बिन्दु से कम होती, तो बेकारी की समस्या इतनी भीषण न होती, जितनी कि आज है। योजना आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही वर्गों में बेकारी बढ़ रही है और समस्या इतनी विचाल है कि इसको थोड़े समय में हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सम्बन्ध जन-संख्या के आधिक्य से है।

(५) प्रोफेसर कैनेन का अनुकूलतम जन संख्या का सिद्धान्त—यदि देश की जन-संख्या अनुकूलतम जन संख्या से अधिक है, तो जन-संख्या की अत्यधिक वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय में उसी अनुपात में वृद्धि न होगी, जैसा कि भारत में घटित हो रहा है, अतः कैनेन के सिद्धान्तानुसार भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे देश में अति जन संख्या की समस्या विद्यमान है।

बढ़ती हुई जन संख्या को रोकने की आवश्यकता इसलिये उत्पन्न होती है कि हमारा उपभोग स्तर बहुत नीचा है, जिसे ऊपर उठाने की विशेष आवश्यकता है। जब तक हम इस अनावश्यक वृद्धि को न रोकेंगे, तब तक हमारी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ सकती।

हमारी पंच-वर्षीय योजना में जन संख्या की समस्या को हल करने के उद्देश्य से निम्न कार्य क्रम अपनाया गया है :—

(१) सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में इच्छुक विवाहित व्यक्तियों

के लिए पारिवारिक नियोजन के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उचित परामर्श दिए जाने की व्यवस्था करना ।

(२) जनता के विभिन्न वर्गों में पारिवारिक नियोजन के सिद्धान्तों के प्रभाव, अनुकूलता तथा स्वीकृति के सम्बन्ध में अधिक खोज करके आँकड़े इकट्ठे करना । इस सम्बन्ध में 'रिदमिक प्रणाली' (Rhythmic Method) पर अधिक जोर दिया जाना । इसमें किसी कृत्रिम साधन के अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा यह ग्रामीण जनता के लिए भी उपयुक्त सिद्ध हो सकता है ।

(३) जन-संख्या के विभिन्न वर्गों में प्रजनन दर एवं प्रजनन प्रकार (Reproduction pattern) के सम्बन्ध में आँकड़े इकट्ठे करने एवं पारिवारिक नियोजन के कौन से सिद्धान्त किस क्षेत्र एवं किस वर्ग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, यह जानने के लिए इन आँकड़ों की बड़ी आवश्यकता होती है ।

(४) इनके अतिरिक्त योजना आयोग का सुझाव है कि खोज एवं प्रयोगों के परिणामों का मूल्यांकन करने, जन-संख्या का नियन्त्रण करने तथा सरकार को पारिवारिक नियोजन सम्बन्धी परामर्श देने के लिए एक जन-संख्या आयोग (Population Commission) की नियुक्ति वांछनीय है ।

आयोजन एवं रोजगार—

भारत के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार दिलाना रहा है । विकास की काफी सम्झी अवधि के बाद ही जनशक्ति के उपसब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है । फिर भी, तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह रखा गया है कि योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में जितनी वृद्धि हो उतनी वृद्धि रोजगार के अवसरों में भी होनी चाहिए ।

(१) संस्था की दृष्टि से, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना उन अत्यन्त कठिन कार्यों में से एक है, जिन्हें अगले पाँच वर्षों में करना है । ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी, ये दोनों ही साथ साथ दिखाई पड़ती हैं और उनके बीच कोई स्पष्ट अन्तर नहीं होता । ग्रामों में साधारणतया बेरोजगारी का स्वरूप अर्द्ध-बेरोजगारी है । यह अर्द्ध-बेरोजगारी मन्दी के मौसमों में और अधिक उल्लेखनीय हो जाती है । शहरी क्षेत्रों में व्यापार, यातायात और उद्योग की स्थिति में जो उतार-चढ़ाव होता है, उसी के अनुसार रोजगार में भी उतार-चढ़ाव आता है । इस प्रकार परिस्थितियों में जो अन्तर होता है, उसका रोजगार के आँकड़ों में होने वाली वृद्धि या कमी से पता चलता है । सामान्यतः गांवों में अर्द्ध-बेरोजगारी की जो परेशानी है, वही कस्बों में भी कुछ मात्रा में है ।

(२) रोजगार के बारे में इस समय प्राप्त सामग्री अधूरी है । फिर भी जो सीमित जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक जिन लोगों को रोजगार नहीं दिलाया जा सका, उनकी संख्या लगभग ६० लाख है । दूसरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में ५३ लाख लोगो

के बेरोजगार रह जाने का अन्दाजा था, किन्तु इसकी तुलना में बेरोजगार रहने वाले लोगों में जो वृद्धि हुई उसका यह अर्थ है कि यद्यपि रोजगार की समस्या पर प्रायोजन का प्रभाव पड़ा, किन्तु फिर भी अधिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगों की संख्या में जो निरन्तर वृद्धि हुई, उस हिसाब से लोगों को रोजगार नहीं दिलाया जा सका। पूरा बेरोजगारी के अतिरिक्त, जिन लोगों के पास कुछ काम है, किन्तु जो अतिरिक्त कार्य भी करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि से अर्द्ध-रोजगार वाले लोगों की संख्या लगभग १ करोड़ ५० लाख से १ करोड़ ८० लाख तक है। सन् १९६१ की जनगणना से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में अधिक वर्ग में लगभग १ करोड़ ७० लाख लोगों की वृद्धि होगी, इस वृद्धि की एक तिहाई शहरी क्षेत्रों में होगी। इसके विपरीत यह अनुमान है कि तीसरी योजना में १ करोड़ ४० लाख लोगों को—१ करोड़ ५ लाख लोगों को कृषि-भिन्न कार्यों में और ३५ लाख लोगों को कृषि में अतिरिक्त रोजगार दिलाया जाएगा। नीचे की तालिका में कृषि-भिन्न-कार्यों में रोजगार का विवरण दिया गया है :

अतिरिक्त कृषि-भिन्न रोजगार

(लाखों में)

क्षेत्र	तीसरी योजना में अतिरिक्त रोजगार
१ निर्माण ^१	२३००
२ सिंचाई और बिजली	१००
३ रेल	१४०

१. नू कि निर्माण कार्य से बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है, इसलिए विभिन्न विकास क्षेत्रों में रोजगार का निम्न रूप से दिया गया विवरण उपयोगी होगा :

(लाखों में)

क. कृषि और सामुदायिक विकास	६१०
ख सिंचाई और बिजली	४६०
ग उद्योग और खनिज, जिसमें कुटीर और लघु उद्योग भी सम्मिलित हैं	४६०
घ. यातायात और संचार, (रेल सहित)	३४०
ङ सामाजिक सेवाएं	३५०
च विविध	०५०

कुल योग २३००

४. अन्य यातायात और संचार	८८०
५. उद्योग और खनिज	७५०
६. छोटे उद्योग	६००
७. वन, मछलीपालन और सम्बद्ध सेवाएँ	७२०
८. शिक्षा	५६०
९. स्वास्थ्य	१४०
१०. अन्य सामाजिक सेवाएँ	० ८०
११. सरकारी सेवा	१५०
योग	६७५०
१२ 'अन्य' जिनमें उद्योग और व्यापार सम्मिलित हैं, १ से ११ तक की मजदूरी के कुल योग का ५६ प्रतिशत	३७ ८०
कुल योग १०५३०	

इस प्रकार श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगों को काम दिलाने के लिए ३० लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार होना चाहिए।

(३) रोजगार की समस्या को तीन मुख्य रूपों में सुलझाने का विचार है। पहला, योजना के ढांचे के अन्तर्गत ऐसे प्रयत्न करने होंगे जिनमें पहले की प्रेरणा रोजगार के प्रभावों का फैलाव अधिक व्यापक और सतुलित रूप से हो। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण का एक काफी बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए, जिसमें इन बातों पर विशेष जोर दिया जाए—ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना, ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं का विकास, ग्रामीण उद्योगों की उन्नति, और जनशक्ति को प्रभावशाली रूप में फिर से काम में लगाना। तीसरा लघु उद्योगों द्वारा रोजगार बढ़ाने के अन्य उपायों के अतिरिक्त ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों को संचालित करने का विचार है, जिनसे लगभग २५ लाख और सम्भवतः इससे भी अधिक लोगों को साल में औसतन १०० दिन तक काम मिलेगा।

(४) समूचे देश अथवा बड़े-बड़े प्रदेशों जैसे राज्यों की दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण करना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक जिले के विकास कार्यक्रम हैं, जिनका सम्बन्ध कृषि, सिंचाई, बिजली, ग्राम और लघु उद्योग, संचार और सामाजिक सेवाओं से है और जिनका उद्देश्य अपने क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप के स्तर को ऊँचा उठाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हर स्तर पर—जिला, ग्राम और खण्ड स्तर पर अधिक रूप में सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्थानीय रोजगार के इस प्रकार के विश्लेषण से अधिकारियों को इस बात में सहायता मिलेगी कि वे विशिष्ट वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए साधन जुटा सकें और स्थानीय परिस्थितियों एवं साधनों को ध्यान में

रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में इस समस्या को जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार सुलझा सकें ।

(५) बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी, और तीसरी योजना की अवधि में अधिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगों की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि निर्माण क्षेत्र में हाथ से काम करने वाले लोगों को और कितना अधिक रोजगार दिया जा सकता है, इस बात की फिर से जांच की जाए । श्रम उद्दीपक उपाय बरते जाने चाहिए, किन्तु जहां इनकी आवश्यकता न हो वहां इन्हें नहीं बरतना चाहिए । यदि पूर्वायोजन और आवश्यक संगठन किया जाए तो हाल ही के वर्षों की अपेक्षा जनशक्ति का और बड़ी हद तक उपयोग करना सम्भव है ।

(६) यद्यपि हाल के वर्षों में ग्रामों और लघु उद्योगों की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया गया है, फिर भी इस क्षेत्र में और अधिक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिलाने की संभावनाएँ निकालनी हैं । यह कार्य अभी हो सकता है जबकि मौजूदा उद्योगों के अच्छे साल की मधेष्ठ पूर्ति, प्रामाणिक तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए । इन सुविधाओं में ऋण तथा हाट-व्यवस्था भी सम्मिलित हैं । इस बांध के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए कि छोटे उद्योगों (चाहे वे कारीगरों की सहकारी समितियों द्वारा अथवा वैयक्तिक उपक्रमियों द्वारा चलाए जा रहे हों) को अपना अधिकतम उत्पादन-सामर्थ्य प्राप्त करने में सहायता की जाए । ग्रामीण औद्योगीकरण और गाँवों में बिजली लगाना, ये दोनों सम्बद्ध कार्यक्रम हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इनका सबसे अधिक महत्त्व है । प्रत्येक क्षेत्र में और छोटे-छोटे कस्बा और गाँवों में औद्योगिक विकास के केन्द्र स्थापित करना आवश्यक है और ये सुधरे हुए यातायात एवं अन्य सुविधाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए । प्रत्येक जिले में ग्रामिण आयोजन के द्वारा कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक विकास का कार्यक्रम बिजली की पूर्ति के साथ समन्वित होना चाहिए ।

(७) अर्द्ध-रोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह आवश्यक है कि न केवल सभी लोग कृषि कार्य में विज्ञान का प्रयोग करें, बल्कि ग्रामीण प्राथमिक ढाँचे को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत करना और उसे सुदृढ़ बनाना भी आवश्यक है । ग्राम और लघु उद्योगों तथा प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ाना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने होंगे । इस प्रकार जहाँ ग्रामीण अव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता है । खास तौर पर उन क्षेत्रों में ऐसा होना चाहिए जहाँ अधिकांश लोग भूमि पर निर्भर हैं और जहाँ काफी बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी है । इस कार्यक्रम में खण्ड और ग्राम स्तर पर मुख्यतः स्थायी निर्माण-कार्य किये जाएंगे । विशेषतः कृषि के मन्दे मौसम में कार्यनिवृत्त करने के लिए निर्माण कार्यक्रम बनाए जाएंगे । गाँवों में जो निर्माण कार्य होंगे, उन सभी

मे ग्राम की दूरी पर मजदूरियाँ दी जाएँगी। ऊपर जो बातें बताई गई हैं, मोटे तौर पर उनका अनुसरण करते हुए हाल ही में ३४ प्रारम्भिक परियोजनाएँ चालू की गई हैं। इनमें सिंचाई, वन लगाना, भूमि संरक्षण, नालियाँ बनाना, भूमि का पुनरुद्धार, संचार साधनों में सुधार आदि की पूरक योजनाएँ सम्मिलित हैं। प्रारम्भिक परियोजनाओं के आधार पर अन्य क्षेत्रों में एक बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को विस्तृत करने का विचार है। अस्थायी तौर पर यह अनुमान है कि निर्माण कार्यक्रमों द्वारा पहले वर्ष में १ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए, दूसरे वर्ष में ४ लाख से ५ लाख तक व्यक्तियों को और तीसरे वर्ष में लगभग १० लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए और इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग २५ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल जाना चाहिए। योजना की प्रवृद्धि में इस समूचे कार्यक्रम पर कुल व्यय १५० करोड़ रुपये हो सकता है। कार्यक्रम के आगे बढ़ने के साथ-साथ इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि मजदूरी की अदायगी आर्थिक रूप में हो। निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्यतः राज्यों में और जहाँ तक जरूरी हो वहाँ तक केन्द्र में पर्याप्त संगठन स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

(८) शीघ्रता से औद्योगीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप पड़े-लिखे लोगों के लिए रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ जाएँगे। इसलिए उद्योगों के लिए जिस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा-पद्धति में भी परिवर्तन करने होंगे। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के कारण इस बात की और अधिक ध्यान देना होगा कि पड़े-लिखे लोग लाभदायक रोजगार में लगाए जाएँ। अनुमान है कि इस समय लगभग १० लाख पड़े-लिखे बेरोजगार हैं। तीसरी योजना की प्रवृद्धि में हाई स्कूल तथा इससे ऊपर की शिक्षा-प्राप्त लोगों की संख्या लगभग ३० लाख हो जाने का अनुमान है, जिन्हें रोजगार दिलाना होगा। कृषि, उद्योग और यातायात की उन्नति होने से कुशल और व्यावसायिक अथवा प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की अधिक माँग होगी और उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हाल के वर्षों में हाथ के काम के प्रति पड़े-लिखे लोगों के रुख में परिवर्तन हुआ है और उन्हें विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लेने का विचार है। सहकारी समितियों और वैज्ञानिक खेतों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो जाने से प्राचीण अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत पड़े-लिखे लोगों के लिए नियमित और निरन्तर रोजगार का क्षेत्र काफी बढ़ जाएगा। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में प्राप्त रोजगार से उन्हें सही मायनों में उतनी ही आय होगी, जितनी कि शहरों में होती है। यह भी संभव हो जाएगा कि काफी बड़ी संख्या में पड़े लिखे नवयुवकों को ग्रामीण केन्द्रों में, जहाँ बिजली उपलब्ध की जा सके, छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाए।

(९) इस बात की आवश्यकता है कि जो परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं या

जो पूरी होने वाली हैं, वहाँ से कुशल कर्मचारियों को लेकर उन परियोजनाओं में लगाया जाए जिनका आरम्भ होने वाला है। दूसरी योजना में इस कार्य के लिए बनाए गए समूहों में सन्तोषजनक रूप से कार्य किया है। इस समूहों को बनाए रखते हुए यदि किसी प्रकार की परियोजनाओं की आवश्यकताओं का विभाजन और अधिक अच्छे ढंग से किया जाए तथा पूर्वायोजन किया जाए तो इस समस्या का अधिक आसानी से सामना किया जा सकता है।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss the relationship between population and real income of a country.
2. Why is the density of population so different in different states of India? Analyse its economic effects.
3. Summarize the main features of Indian population.
4. Write a short note on Employment under the Third Five Year Plan.

अध्याय ५७

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व

(Importance of Cottage & Small Scale Industries in India's Economy)

कुटीर उद्योगों से आशय—

कुटीर उद्योग से हमारा आशय उन उद्योगों से है जिनके अन्तर्गत काम करने वाले एक काम लेने वाले प्रायः एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। इनमें विद्युत शक्ति एवं यन्त्रों का प्रयोग होना अथवा न होना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। दूसरे शब्दों में, यह कोई विचार का विषय नहीं है कि कुटीर उद्योगों में बिजली की शक्ति व छोटे मोटे यन्त्रों का उपयोग किया जाय अथवा नहीं। सन् १९४६-५० के प्रशुल्क मण्डल के प्रतिवेदन के अनुसार, "कुटीर उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत केवल ग्राम्य-उद्योग ही नहीं आते, बल्कि ऐसे नगरीय या शहरी उद्योग, जो कुटीर उद्योगों के लक्षणों से मेल खाते हों, इनकी परिभाषा में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

लघु-उद्योगों से आशय—

इसके विपरीत, "लघु उद्योगों" से तात्पर्य उन उद्योगों से है, जिनमें पाँच लाख तक की पूँजी लगी हो एवं इसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या १० व ५० के मध्य हो। लघु उद्योगों की आधुनिक परिभाषा के अनुसार इस द्वितीय लक्षण पर अधिक बल नहीं दिया जाता, अर्थात् यदि किसी उद्योग-धन्धे में ५० से भी अधिक श्रमजीवी कार्य करते हों, परन्तु भूमि, पूँजी, साहस एवं संगठन का आकार बहुत बड़ा नहीं है, तो निश्चय ही ऐसा उद्योग "लघु उद्योग" की श्रेणी में गिना जावेगा। जहाँ तक शक्ति व यन्त्रों के प्रयोग का सम्बन्ध है, लघु उद्योगों में प्रायः इन दोनों का ही उपयोग किया जाता है।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में महत्त्व—

भारतीय अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त्व के विषय में जो कुछ भी कहा जाय, कम ही होगा। ग्राम्य एवं लघु उद्योगों के अत्यधिक महत्त्व

के ही कारण पूँज्य बापू प्रायः कहा करते थे कि, "भारत की आर्थिक समृद्धि कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास में ही निहित है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त्व को भली प्रकार समझने के लिए भारतीय अर्थ व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना अनावश्यक न होगा।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं—

भारत की अर्थ-व्यवस्था का गहन अध्ययन करने से इसकी निम्नलिखित विशेषताओं का आभास मिलता है—

(१) कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार। भारतवर्ष मूलतः कृषि प्रधान देश है। "भारत सम् १९६१" के आँकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट पता लगता है कि यद्यपि आर्थिक नियोजन के गत दस वर्षों से हमारे देश ने औद्योगीकरण की दिशा में सराहनीय प्रगति की है, किन्तु फिर भी आज लगभग ६६% व्यक्ति कृषि व्यवसाय में ही लगे हुए हैं। भारत गावों का देश है और गावों की ९०% जन-संख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है।

(२) वर्ष में ४-६ माह खाली रहना। कृषि के शाही वर्मीशन ने लिखा है कि भारतीय कृषि की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस पर काम करने वाले कृषक को वर्ष भर कृषि कार्य में व्यस्त नहीं रहना पड़ता। साल में कम से कम ४-६ माह वह खाली रहता है। डा० राधा कमल मुखर्जी की खोज के अनुसार 'उत्तरी भारत में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ कृषक वर्ष में लगभग २०० दिन बेकार रहते हैं। कहीं-कहीं, जहाँ सिंचाई के अच्छे और उत्तम साधन प्राप्त हैं, वहाँ इससे भी अधिक समय तक बेकार रहते हैं। जिस कृषक के पास भूमि कम है, उसके सारे परिवार को उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।' अतः जिन दिनों हमारे कृषक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, उन दिनों के लिए उनको व्यस्त रखने तथा खाली समय का सदुपयोग करने एवं उनकी आय का कोई अन्य साधन खोज निकालना, भारतीय अर्थ-व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है।

(३) निम्न जीवन स्तर। उपर्युक्त दो विशेषताओं के परिणामस्वरूप हमारे अधिकांश देशवासियों का जीवन स्तर अत्यन्त निम्न है। अशिक्षा, अज्ञानता एवं कृपमयता के आभाव में पले हुए हमारे अधिकांश ग्राम-बासी दरिद्रता के दानव के शिकार हैं। यदि किसानों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का अवलोकन करें तो सचमुच रोना आ जाता है। आय कम होने के कारण वे जीवन की परम आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध नहीं कर पाते। उनके पास भूमि इतनी कम है कि वे वर्ष भर पूरी महनत भी नहीं कर सकते।

(४) सापेक्षिक पिछड़ापन। विश्व के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों की तुलना में हमारा देश अभी बहुत पिछड़ा है। भारत की गणना अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में की जाती है। जब हम विश्व के अन्य देशों की आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि एक बार जबकि दुनिया के कुछ राष्ट्र चन्द्रलोक की ओर

बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में अभी 'स्वचालन' (Automation) भी पूर्णता की दशा पर नहीं पहुँच सका है। अन्य उन्नतिशील औद्योगिक राष्ट्रों के साथ कदम ब-कदम मिलाकर चलने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना शेष है। इस हेतु हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। (५) राजनैतिक परिस्थितियाँ। अर्थ नीति का राजनीति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होते हुए भी, वर्तमान युग में किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था, राजनैतिक परिस्थितियों से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकती। कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि विश्व के अत्यन्त समृद्ध एवं उन्नत कहे जाने वाले राष्ट्र युद्ध की तैयारियों में सलग्न हैं। भारत भी अपने पड़ोसी देशों की राजनीतिक कार्यों विधियों से सतुष्ट नहीं है। ऐसी अवस्था में अर्थ-व्यवस्था को अत्यन्त सुदृढ़ रखना नितान्त आवश्यक हो जाता है।

अर्थ-व्यवस्था की सुदृढ़ता में कुटीर लघु उद्योगों का योगदान—

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले एवं कृषि प्रधान देश में अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास नितान्त आवश्यक है। औद्योगीकरण की किसी भी देशव्यापी योजना में इनको सम्मिलित करना अनिवार्य हो गया है। अपने एक लेख में डा० बी० सी० नारायण स्वामी नायडू ने एक स्थान पर लिखा है कि, 'कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्त्व भली प्रकार न समझने का एक कारण यह है कि हमको इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं है कि विश्व के अन्य उन्नतशील औद्योगिक राष्ट्रों में कुटीर उद्योगों को क्या स्थान प्राप्त है। गन महायुद्ध के पूर्व जापान का नाम ऐसे एक आदर्श राष्ट्र के रूप में लिया जाता था, जहाँ की औद्योगिक प्रगति का श्रेष्ठ वहाँ के छोटे-मोटे उद्योग धन्धों को ही था। आज भी पश्चिम के अधिक उन्नतिशील देशों, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, में सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत जो छोटे उद्योग धन्धे चलते हैं वे बड़े सफल तथा प्रचलित हैं एवं उनके द्वारा निमित्त पदार्थ कारखानों द्वारा बने हुए माल से अच्छे समझे जाते हैं।' श्री ग्रीन ने भी एक स्थान पर लिखा है कि, 'यदि खराब मौसम तथा शीतकाल में प्राचीन काल की तरह कुछ आय देने वाला काम कृषकों को मिले तो यह एक महत्त्वपूर्ण बरदान होगा।' इसी प्रकार इटली के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि जहाँ मालवरी के वृक्ष हैं वहाँ की कृषक महिलाएँ पूर्ण रूप से कटाई में व्यस्त रहती हैं। अब यह विचारणीय प्रश्न हो जाता है कि जब औद्योगिक दृष्टि से उन्नत एवं कम जन-संख्या वाले देशों में कुटीर-धन्धों का इतना अधिक महत्त्व है, तो भारत में, जहाँ भूमि पर जन-संख्या का प्रभाव अधिक है, चारों ओर समस्याएँ हैं तथा बेकारी फैली हुई है, कुटीर एवं छोटे परिमाण के धन्धों का महत्त्व और भी अधिक हो जाता है। इसी दृष्टि से पूज्य गाँधी जी ने एक स्थान पर लिखा है कि 'यंत्रीकरण तब ही उचित है जबकि कार्य के लिए श्रमिक बहुत ही कम हों। किन्तु यदि काम के लिये आवश्यकता से अधिक श्रमिक हैं, जैसी कि स्थिति भारतवर्ष में है, तो यह एक बुराई है। हमारे सामने समस्या यह नहीं है कि गाँवों में बसने वाले करोड़ों नर-नारियों के लिए कैसे अवकाश प्राप्त करें, अपितु समस्या यह है कि खासी समय का सदुपयोग कैसे किया जाय।' पूज्य महात्माजी धन्यो के उपयोग के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु वे यह नहीं चाहते थे कि मनुष्य उनका दास हो। उन्होंने देखा कि देश में एक ओर तो बेकारी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर पूँजी की कमी है, अतः उन्होंने कुटीर-धन्धों को अपनाने का ही विशेष आदेश दिया है।

पहली और दूसरी योजना में ग्राम और लघु उद्योगों में रोजगार बढ़ाने, उत्पादन में वृद्धि करने और आय के अधिक उचित वितरण के उद्देश्यों की दिशा में काफी योगदान किया। तीसरी योजना में और अधिक बड़े काम करने हैं, इसलिए इनके योगदान का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य लोगों को उत्पादन के नए तरीके अपनाने में मदद करना और इनके संगठनों को अधिक कार्यकुशल बनाना है, ताकि देश में ग्राम आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जो सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हों, उनसे पूरा लाभ उठाया जा सके और कुछ भवधि बाध यह पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बन जाए। लेकिन इसके साथ ही प्राविधिक परिवर्तन पर इस तरह का नियन्त्रण रखना पड़ेगा जिससे बड़े पैमाने की प्राविधिक बेरोजगारी को बचाया जा सके। इसलिए उन उद्योगों की समस्याओं पर बराबर पुनर्विचार करने और आदर्शक उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे ये उद्योग राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के आवश्यक और अभिन्न अंग के रूप में अपना पूरा योगदान कर सकें।

कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्त्व—

अब हम निम्नलिखित दृष्टिकोणों से कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त्व पर प्रकाश डालेंगे :—

कुटीर धन्यो के महत्त्व

के ११ कारण

- (१) कृषि से जन-संख्या का भार घटाना।
- (२) न्यून पूँजी से ही उद्योग का प्रारम्भ।
- (३) पूँजी की कुशलता एवं गतिशीलता में वृद्धि।
- (४) पूर्ण रोजगार की प्राप्ति।
- (५) औद्योगिक उत्पादन का समान वितरण व औद्योगिक विकेन्द्रीकरण।
- (६) आय का समान वितरण।
- (७) श्रम व पूँजी में उत्तम सम्बन्ध।
- (८) युद्ध तथा सुरक्षा।
- (९) उत्पादन व्यय में कमी।
- (१०) उत्पादन की किस्म में श्रेष्ठता।
- (११) समाज के लिये महत्त्व।

(१) कृषि पर जन-संख्या का भार घटाना—अब हम यह संकेत कर चुके हैं कि कृषि पर जन-संख्या का अत्यधिक बोझ होना भारतीय अर्थ-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। आज से लगभग १४-१५ वर्ष पूर्व भारत की ८०% जन-संख्या कृषि पर निर्भर थी और अब भी, औद्योगीकरण की देश-व्यापी योजनाओं के होते हुये भी, लगभग ६६% व्यक्ति कृषि पर अवलम्बित हैं। अतः समस्या यह है कि कृषि से जन-संख्या का अत्यधिक बोझ क्योंकर कम हो। इस समस्या के समाधान के लिये दो ही मार्ग अपनाये जा सकते हैं—एक तो वृहत उद्योगों के विकास द्वारा और दूसरे, कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर। जहाँ तक प्रथम उपाय का सम्बन्ध है, इससे समस्या सुलभ नहीं सकती, हाँ, हो सकता है कि उसपर और भी जलभर्न पैदा हो

जाये। कृषि पर से जन-संख्या का भार कम करने के लिये कुटीर एव लघु उद्योगों को ही विकसित करना होगा। इनके विकास से सतुलित अर्थ-व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

(२) न्यून पूँजी से उद्योगों का प्रारम्भ—बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिये बहुत अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है तथा अनेक वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी पड़नी है, परन्तु भारत एक अविकसित निर्धन देश है। इसके पास पूँजी का अभाव है, जिसमें वृहत आकार के उद्योगों की स्थापना में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कुटीर-उद्योग पूँजी-प्रधान (Capital Intensive) न होकर श्रम-प्रधान (Labour-Intensive) होते हैं। इन्हें प्रारम्भ करने के लिये न तो मूल्यवान् मशीनों एवं बड़ी-बड़ी इमारतों की ही आवश्यकता पड़ती और न जटिल वैधानिक कार्यवाहियाँ ही करनी पड़ती हैं। इनमें तांत्रिक ज्ञान की भी बहुत कम आवश्यकता पड़नी है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में द्रुति गति से औद्योगिक विकास के लिये कुटीर उद्योगों पर अधिक बल देना नितांत आवश्यक है।

(३) पूँजी की कुशलता और गतिशीलता में वृद्धि—कुटीर-उद्योगों के विकास से पूँजी और कुशलता की गतिशीलता में वृद्धि होती है, अन्यथा देश की बहुतसी पूँजी एवं कुशलता बेकार हो जाती है। इस प्रकार कुटीर-उद्योगों की स्थापना से भारत जैसे विशाल जन-संख्या वाले देश में पूँजी एवं कुशलता का पूर्णरूपेण उपयोग संभव हो सकेगा।

(४) पूर्ण रोजगार की प्राप्ति—आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक दृष्टि से किसी भी देश में बेकारों की संख्या अधिक रहना अथवा पूर्ण रोजगार न रहना एक अभिशाप है। सर विलियम बेवरिज एक स्थान पर लिखते हैं कि—“बेकारी का सबसे बड़ा दोष भौतिक नहीं बल्कि नैतिक है। इससे केवल अभाव ही नहीं बल्कि धृष्टता तथा भय को भी जन्म मिलता है।” भारत की वर्तमान परिस्थिति में, जबकि साम्यवाद का प्रसार बड़ी जोर से हो रहा है तथा बेकारी एवं अन्य समस्याओं के कारण साम्यवाद की ओर जनता की प्रवृत्ति हाँती जा रही है, बेकारों की अधिक संख्या राजनैतिक अशांति के लिए बाधक हो सकती है। अतएव बेकार लोगों के लिये पूर्ण रोजगार का आयोजन करना अत्यन्त आवश्यक है। श्रीयुक्त श्रीमन्नारायण अग्रवाल के अनुसार सन् १९४१ में लगभग २ करोड़ श्रमिक बेरोजगार थे। आज की स्थिति तो और भी गम्भीर हो गई। सन् १९२१ की जन-गणना के अनुसार भूमिहीन श्रमिकों की संख्या चार करोड़ है। भारत वास्तव में गाँवों का देश है। अधिकांश लोगों का व्यवसाय भी या तो कृषि है अथवा वे कृषि श्रमिक हैं जिसमें उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं होती। भारतीय कृषक वर्ग वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में कृषि कार्य न करते हुये कुछ मास तक बेकार रहता है, इसलिये कृषि को कार्यक्षम बनाने के लिये पूरक धन्धों की आवश्यकता है। यहाँ प्रश्न है कि क्या बड़ी मात्रा के उद्योग बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सकते? पिछली एक शताब्दी में भारत में संचित उद्योगों का इतना विकास होने पर भी केवल ४७-

४८ लाख मजदूरों को रोजगार मिला है, अतएव यदि बड़े बड़े उद्योगों को ही और अधिक विकसित किया जाय, तो कुछ व्यक्तियों को और रोजगार मिल जायेगा। उनसे बेकारी की समस्या पूर्ण रूप से हल न होगी। इसके अनिर्दिष्ट संगठित उद्योग-धन्धों का विकास होने से श्रमिकों का केन्द्रीयकरण विशेषतः औद्योगिक नगरों में होता है। नई-नई औद्योगिक एवं श्रम सम्बन्धी समस्याएँ उपस्थित होती हैं तथा सरकार एवं उद्योगपतियों को सामाजिक सुरक्षा अथवा सामाजिक बीमा पर अधिक खर्च करना पड़ता है, इसलिये यदि कुटीर-उद्योगों का विकास किया जाय, तो हममें बहुत हद तक बेकारी की समस्या का हल हो सकता है। आज देश के सम्मुख एक और भी समस्या है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, अतएव विस्थापित जमींदारों को रोजगार देना होगा। ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों को कुटीर-धन्धों के विकास में सरकार को सहयोग देना चाहिये और आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए। उद्योग व्यापार पत्रिका फरवरी सन् १९५६ की एक सम्पादकीय टिप्पणी के अनुसार हमारी कुल जन-संख्या का शायद २६ प्रतिशत भाग ही आत्म-निर्भर है जब कि लगभग ११ फीसदी आबादी की कमाई बहुत कम है और वह उनके गुजारे के लिये काफी नहीं। इस तरह आबादी का ६० प्रतिशत भाग ऐसा है जो स्वयं कमाई नहीं करता। इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में एकत्र हैं और भूमि पर बोझ बने हुए हैं जो उनका पोषण नहीं कर सकती। श्रमिक शक्ति के रूप में १५ से लेकर ५५ वर्ष तक की आयु वाले इन लोगों की संख्या १५ करोड़ है। विभिन्न प्रकार की सम्भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि करीब १० करोड़ लोगों के लिए काम खोजना जरूरी है। पूर्ण रूप से बेकार इन लोगों के इस चिन्ताजनक बड़े थक के अलावा अर्द्ध बेकारी का भी पहलू है। कृषि क्षेत्र में लगे करीब ६ करोड़ किसान साल में ४ महीने से अधिक समय बेकार रहते हैं। सन् १९६१ की जन गणना के अनुसार यह अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में लगभग १ करोड़ ७० लाख लोगों की वृद्धि होगी। इस वृद्धि की एक तिहाई शहरी क्षेत्रों में और दो-तिहाई ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। इनमें से १ करोड़ ४० लाख लोगों को काम मिल सकेगा—१ करोड़ ५ लाख लोगों को कृषि-भिन्न कार्यों में और ३५ लाख लोगों को कृषि में। इनके लिए पूरक धन्धे और आमदनी के जरिए खोजने हैं। इस विकट समस्या के साथ साथ गरीबी और लाचारी की मानवीय समस्या की ओर से भी आँखें नहीं मूँदी जा सकती। खादी और ग्रामोद्योग अपना ही ऐसा एक-मात्र तरीका है जिससे इस समस्या को सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है।

(५) औद्योगिक उत्पादन का समान वितरण—देश की बहुमुखी उपज के लिये भी कुटीर धन्धा की शरण लेनी ही पड़ती। बड़े बड़े उद्योगों द्वारा देश का समान औद्योगिक विकास सम्भव नहीं है। वर्तमान समय में संगठित उद्योगों का केन्द्रीयकरण किंचित नगरों में ही है, जैसे—वर्माई, बलकत्ता, बानपुर इत्यादि। इससे उत्पादन का समान वितरण नहीं होना, देश की बहुमुखी उपज नहीं होनी तथा

राज्यों में परस्पर वैमनस्य होता है, जो एकता की दृष्टि में हानिकारक है। इनके अतिरिक्त केवल नगरो वा ही विकास होने न गाँव की ओर ध्यान न देने में देश की आय एवं उद्योग का समान वितरण न होकर देश का आर्थिक विकास एकांगी होता है, अतएव उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण अनिवार्य है, जिससे आधुनिक ढंग पर संचालित-कुटीर धन्यो का विकास होकर वे समर्थित बड़ बड़ उद्योगों के लिये पूरक हो सकें।

(६) आय का समान वितरण—बड़े परिमाण के उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग केवल कुछ भागों में ही केन्द्रित हो जाता है और आय का समान वितरण नहीं होता तथा असमानता बढ़ती है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने में ही यह असमानता काफी सीमा तक दूर की जा सकती है। इस दृष्टि से गांधीजी न अपनी आर्थिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में कहा है कि आधारभूत एवं छोटे परिमाण के उद्योग धन्यो के विकास पर एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर पर्याप्त बल देना चाहिए, जिससे आर्थिक असमानता का अन्त हो।

(७) श्रमजीवी-पूँजीपतियों के सम्बन्ध—वर्तमान औद्योगिक अशान्ति का मुख्य कारण बड़-बड़ उद्योग हैं, अतएव औद्योगिक शान्ति साने के लिये कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना अनिवार्य हो जाता है। कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत प्रत्येक सेवायुक्त ही सेवा-योजक होता है, श्रम एवं पूँजी में अधिक अन्तर नहीं रहता। यदि किसी कुटीर उद्योग में अधिक श्रमिक होते भी हैं तो 'स्वामी और नौकर' की भावना नहीं होती। हड़तालें तथा तालेबंदी नहीं होती। आर्थिक उथल-पुथल भी कम हो जाती है। प्रतिद्वन्द्विता रहती है, लेकिन उसका रूप स्वस्थ होता है और गला घोटने वाली प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इस प्रकार कुटीर-उद्योग द्वारा ही औद्योगिक शान्ति की प्राप्ति की जा सकती है।

(८) युद्ध तथा सुरक्षा—यह कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि कुटीर-उद्योग व्यवस्था के अन्तर्गत युद्ध न होगा, किन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं कि ऐसी अर्थ-व्यवस्था में राजनैतिक अशान्ति की शका कम हो जाती है। यह डके की चोट पर कहा जा सकता है कि यदि आज विश्व महात्मा गांधी की अहिंसात्मक नीति का पालन करे तो युद्ध कभी न हो, किन्तु अहिंसा का सच्चा पुजारी बनना कोई खेल नहीं है। भारत में ही महात्माजी की इस विचारधारा का वह स्वागत नहीं हुआ, जो होना चाहिए था। कुटीर उद्योग पूज्य बापू की अहिंसात्मक नीति का एक प्रधान अंग है।

राजनैतिक सुरक्षा की दृष्टि से भी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना राष्ट्र के हित में होगा। औद्योगिक केन्द्रीयकरण का सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि किसी एक विशेष स्थान पर सैनिक आक्रमण हो जाय, तो उस स्थान के समस्त उद्योग नष्ट हो जायेंगे, अतएव विवेन्द्रीयकरण का महत्त्व स्पष्ट है। विवेन्द्रीयकरण के इस कार्य में कुटीर उद्योगों द्वारा ही सबसे अधिक सहायता मिल सकती है, क्योंकि भारत में गाँवों का वितरण प्रायः समान है और यदि उनमें कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाय, तो केन्द्रीयकरण की समस्या तो हल होगी ही, साथ में समस्त भारत का समान

औद्योगिक विकास होगा। कुटीर धन्यो के विकास की ओर इसीलिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

(६) उत्पादन व्यय—जहाँ तक उत्पादन व्यय का सम्बन्ध है, यह सभी जानते हैं कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से अनेक प्रकार की बचतें होती हैं, जिन्हें अर्थशास्त्री मार्शल ने 'आन्तरिक' एवं 'बाह्य' बचत कहा है। अतः कुटीर उद्योगों की अपेक्षा वृद्ध उद्योगों में उत्पादन का व्यय बहुत कम होता है। एक साधारण उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कल्पना कीजिये कि एक उपभोक्ता को अपने पसन्द के लिये चादर की आवश्यकता है। वह पहले हैन्डलूम की बनी हुई एक चादर देखता है, जिसका मूल्य है १० रु०। अधिक मूल्य के कारण वह उसको क्रय करने में हिचकिचाता है और निकट ही दूसरी दुकान पर वृद्ध उद्योग द्वारा निर्मित एक अन्य चादर को देखता है, जिसका मूल्य है केवल ४ रु०। कम मूल्य के कारण वह मिल-निर्मित चादर को खरीद लेता है। यहाँ, जहाँ तक द्राव्यिक मूल्य का सम्बन्ध है, मिल निर्मित चादर की विजय हुई। परन्तु श्रद्धेय बापू के अनुसार हमें केवल वस्तु के द्राव्यिक मूल्य पर ही ध्यान नहीं देना चाहिये। द्राव्यिक मूल्य की अपेक्षा सामाजिक मूल्य का अधिक महत्त्व है। सामाजिक मूल्य से हमारा तात्पर्य यह है कि हमको यह नहीं देखना चाहिये कि (i) टिकाऊपन की दृष्टि से समाज के लिये कौन सी वस्तु उपयोगी होगी और (ii) रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से समाज के लिये कौन से पदार्थ का क्रय अधिक हितकर होगा। इन दोनों दृष्टिकोणों से कुटीर उद्योगों एवं कुटीर पदार्थों की ही विजय होगी। मिल निर्मित चादर भले ही कुटीर उद्योग-निर्मित चादर से सस्ती हो परन्तु पोथी के घाट की पिटाई उसके लिये असहनीय होगी और इसके विपरीत हैन्डलूम की चादर अधिक टिकाऊ होगी। इसके अतिरिक्त, हस्त-करवा उद्योग एवं अन्य कुटीर उद्योगों में वृद्ध उद्योगों की अपेक्षा कहीं अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अतः सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन करने पर कुटीर उद्योगों की उपादेयता स्पष्ट हो जाती है।

ग्राम उद्योगों के नैतिक मूल्य के विषय में ससद सदस्य श्री ए० सी० शुहा के निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय हैं—“ग्रामोद्योगों में अपने धन्ये से ही अपनी रोजी कमाने में मनुष्य का मनोबल ऊँचा उठता है और उसमें नैतिक विराट या अमानवीय प्रभाव नहीं आने पाते, जो केवल-भोगी रोजगार के साथ आने अनिवार्य हैं, चाहे वह नौकरी सामाजिक नियन्त्रण में चलने वाले कारखाने में ही क्यों न की जाती हो। अपनी कुटिया में काम करते समय कारीगर का अपने पड़ोसियों से सम्पर्क होता है, जो प्रायः उसके बनाये हुए माल के ग्राहक होते हैं। वे एक-दूसरे की बनायी हुई चीजों का आदान-प्रदान करते हैं। वहाँ रुपये का महत्त्व गीण होता है। लेकिन वहाँ मानवीय संस्पर्श का सर्वथा अभाव होता है।

(१०) उत्पादन की किस्म—इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कारखाने में बने हुए माल की अपेक्षा हस्त-निर्मित माल में अधिक कला एवं टिकाऊपन होता है।

कुटीर उद्योगों में अधिक वस्तु के निर्माण में अपनी आत्मा निकाल कर रख देता है। अपनी रूपाति के लिये वह भरसक प्रयत्न करता है, इसलिये कुटीर उद्योग-निर्मित मान की किस्म अच्छी होती है। इस सम्बन्ध में श्री मुहा ने लिखा है कि “राष्ट्रीय जीवन में कला का महत्त्वपूर्ण मूल्य होता है। नगरों में जिस प्रकार की कला के दर्शन होते हैं, वह कभी-कभी अत्यधिक बनावटी हो जाती है और उसमें मनुष्य की नैसर्गिक कलात्मक भावना का अभाव होता है। इन ग्रामोद्योगों के माध्यम से हम अपनी जनता की स्वाभाविक कला-प्रियता तथा कलात्मक भावना के दर्शन कर सकते हैं। देहानों के लोग शहरी लोगों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निवृत्त रहने हैं, इससे उनका प्रकृति के साथ अधिक घनिष्ठ सम्पर्क होता है और वे प्रकृति को अधिक अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक विशेष मूल्य होता है, जिसका पुनरुत्थान किया जाना चाहिए और जिन्हें संजोया जाना चाहिए।

(११) समाज के महत्त्व—बड़े बड़े उद्योगों में यन्त्रों के अधिक प्रयोग होने के कारण मनुष्य, मनुष्य न रह कर यन्त्रों का गुलाम हो जाता है, जिससे उसकी नैतिक एवं आध्यात्मिक शांति का ह्रास होता है और स्वास्थ्य भी गिरता है। यह बुराईयाँ कुटीर उद्योगों में नहीं रहती, क्योंकि उसमें वह अपनी इच्छानुसार कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। कुटीर उद्योग व्यवस्था का प्रधान लक्षण सरलता है और आवश्यकताओं की सरलता में ही मानव जाति की मुक्ति निहित है—“सादा जीवन उच्च विचार, है मानव जीवन का सार”—जीवन की सरलता एवं सार, कुटीर उद्योग व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

क्या कुटीर उद्योग प्रतियोगिता में टिक सकेंगे ?—

कुटीर उद्योगों के महत्त्व सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट कि किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था में उनको उपयुक्त स्थान मिलना ही चाहिये। फिर भारत जैसे विशाल जन-संख्या वाले देश में, जहाँ विस्तृत बेरोजगारी हो, कुटीर एवं लघु उद्योगों का तो और भी अधिक महत्त्व है। परन्तु कभी-कभी उनकी सफलता के सम्बन्ध में मन में आशंकाएँ पैदा होती हैं। जो व्यक्ति इस सम्बन्ध में निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, वे प्रायः यह दलील देते हैं कि यन्त्र निर्मित वस्तुओं की तुलना में कुटीर पदार्थ प्रतिस्पर्धा में टिक न सकेंगे, क्योंकि—

प्रतिस्पर्धा का भय क्यों—

- (I) बृहत उद्योगों के पदार्थों की अपेक्षा कुटीर पदार्थों का द्राव्यिक मूल्य कहीं अधिक होता है और उपरोक्त प्रायः तत्कालीन द्राव्यिक मूल्य पर ही अधिक बल देना है।
- (II) कुटीर उद्योगों में अधिकतर यन्त्रों के प्रयोग का अभाव होता है। फलतः उनके उत्पाद भी एक रूप एवं सस्ते नहीं हो सकते।
- (III) इसी प्रकार विद्युत शक्ति के प्रयोग के अभाव के कारण भी कुटीर

पदार्थों का उत्पादन-व्यय यन्त्र निर्मित पदार्थों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है।

- (1४) हमारे देश में राजकीय प्राशुलिक नीति भी कुटीर उद्योगों को संरक्षण की दृष्टि से कोई विशेष हितकर नहीं है। वृहत, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिये कोई विशेष भेदभाव नहीं बरता जाता। सबको एक घाट उतारने से अर्थात् वृहत उद्योगों के ही समान कर देने के कारण इनका उत्पादन व्यय और भी अधिक होता है।

(१) सामान्य उपभोक्ता भी कुटीर पदार्थों को प्राथमिकता नहीं देता।

कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं—

परन्तु गम्भीरता से उपर्युक्त समस्या पर विचार करने से यह स्पष्ट पता लगता है कि इस सम्बन्ध में हमें निराशावादी नहीं होना चाहिये। जब दूबते हुये व्यक्ति को तिनके का एक सहारा ही काफी होता है, तो कुटीर उद्योगों के विकास के लिये तो आशा की अनेक किरणें हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(१) विद्युत शक्ति का प्रसार—भारत के आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत विद्युत शक्ति के प्रचार एवं प्रसार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कुटीर उद्योगों का साम्राज्य छाया हुआ है, विद्युतीकरण बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अतः छोटे-मोटे उद्योग धन्धों को संचालित करने में अब सस्ती विद्युत शक्ति का सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत शक्ति का प्रसार कुटीर उद्योगों के विकास में निश्चय ही सहायक सिद्ध होगा।

(२) यन्त्रीकरण का प्रसार—द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में हमारे देश में ऐसे अनेक कल-कारखाने खुल गये हैं, जिनमें उन मशीनों का निर्माण किया जाना है, जिनके द्वारा कुटीर एवं लघु-उद्योगों की कार्यक्षमता बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है। तृतीय योजनावधि के अन्तर्गत ऐसे कारखानों का और भी अधिक विकास और विस्तार होगा। इसके विस्तार के साथ-साथ कुटीर उद्योगों की यन्त्र निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता करने की शक्ति बढ़ेगी।

(३) तान्त्रिक प्रशिक्षण का विस्तार—जब से हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है तब से तान्त्रिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय विकास हुये हैं। खडगपुर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास व कानपुर की टेक्नोलॉजीकल इन्स्टीट्यूट्स इस क्षेत्र में हमारी प्रगति के प्रतीक हैं। इनके अतिरिक्त अनेक छोटी-मोटी प्रशिक्षणशालायें स्थापित की गई हैं, जिनसे निश्चित रूप से कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास को प्रेरणा मिलेगी।

(४) सामान्य शिक्षा का प्रसार—तान्त्रिक प्रशिक्षण सुविधाओं के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा का प्रसार भी सतोषजनक गति से हो रहा है। शिक्षा के प्रसार से हमारी अज्ञानता एवं कृप मद्धकता शन-शन- कम होती जा रही है और इससे निश्चय ही कुटीर उद्योग पनपेंगे।

(५) औद्योगिक व प्राशुलिक नीति—स्वतन्त्रता के उपरान्त हमारी जनप्रिय सरकार ने देश की सच्ची प्रगति के लिये एक स्वतन्त्र औद्योगिक व प्राशुलिक नीति का निर्माण किया है, जिसमें कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास के लिये पर्याप्त आयोजन है ।

(६) राजकीय स्टोर्स क्रय-नीति—केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों ने अपनी स्टोर्स क्रय-नीति में इस प्रकार संशोधन कर लिया है जिससे कि कुटीर उद्योगों को लाभ हो । इस संशोधन से कुटीर उद्योगों का आत्म विश्वास बहुत कुछ बढ़ गया है और उनकी प्रतियोगिता शक्ति भी विकसित हो गई है ।

(७) राष्ट्रीय भावना का प्रसार—भले ही कुछ लोग इस बात से सहमत न हों परन्तु मेरा यह अनुभव है कि जबसे हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है तब से प्राज राष्ट्रीय भावनाओं में काफी वृद्धि हो गई है । अब हम 'विदेशी' की अपेक्षा 'स्वदेशी' को अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं । इसी प्रकार बहुत उद्योगों के पदार्थों की अपेक्षा कुटीर एवं लघु उद्योगों के पदार्थों को भी प्राथमिकता मिलने लगी है । जैसे-जैसे इन भावनाओं का प्रसार होगा, कुटीर उद्योगों के पैर भी मजबूत होते जायेंगे तथा उनकी प्रति-योगिता शक्ति भी बढ़ जायेगी ।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss carefully the importance of Cottage Industries in India's economy
2. "Cottage Industries are Labour Intensive and not Capital Intensive, hence they must be developed in India" Comment.
3. Discuss the role of Rural Cottage Industries in the present day economy of the country.
4. Admitting the definite role of cottage industries in India's economy, do you think they can successfully compete with large-scale industries?

कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्यायें

(Problems of Cottage and Small Scale Industries)

प्रारम्भिक—

हमारे कुटीर उद्योगों की कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण कुटीर घरे प्रावश्यक उन्नति नहीं कर पाये हैं। यद्यपि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को विभिन्न भाँति की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किन्तु उनमें से कुछ सबसे विद्यमान हैं। भारतीय कुटीर उद्योगों की कुछ सामान्य समस्यायें इस प्रकार हैं —

कुटीर उद्योगों की समस्यायें

- (१) कच्चे माल की कठिनाई।
- (२) पूँजी का अभाव।
- (३) विक्रय की कठिनाई।
- (४) शिल्पियों की प्रशिक्षण तथा रुढ़िवाद।
- (५) वैज्ञानिक यन्त्रों का अभाव।
- (६) कर की समस्या।
- (७) मिल निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता।
- (८) संगठन का अभाव।
- (९) जनता द्वारा पूर्ण सहयोग का अभाव।

(१) कच्चे माल की कठिनाई—
घरेलू उद्योग घरों की सबसे बड़ी समस्या प्रावश्यक मात्रा में उत्तम कोटि का कच्चा माल प्राप्त करने की है। हमारे कारीगरों को पर्याप्त मात्रा में उन्नत श्रमों का कच्चा माल नहीं मिलता। वे अधिकतर स्थानीय व्यापारियों से कच्चा माल खरीदते हैं। छोटे पैमाने पर खरीद होने के कारण इहे वस्तुओं के लिए बहुधा अधिक मूल्य चुकाना होता है और वस्तु भी अच्छी नहीं मिलती। साथ ही ये खरीदने की कला में भी दक्ष नहीं होते जिसके फल स्वरूप में प्रायः ठगें जाते हैं। दश का अधिकारी कच्चा माल तो बड़-बड़े

कारखानों में ही खप जाता है और जो शेष बचता है, वह कुटीर कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता।

(२) पूँजी का अभाव—पूँजी का अभाव कुटीर उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या है। इन लोगों के पास न तो कच्चा माल खरीदने को पैसा है न वे मशीन खरीद पाते हैं और न इनकी इतनी सामर्थ्य होती है कि माल बनाने के बाद अच्छे

मावो की प्रतीक्षा कर सकें। माल तैयार करते ही उन्हें बेचना पड़ता है, भाव चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल। ये लोग अधिकांश रूप में गाँव के महाजन से अथवा कच्चा माल देने वाले व्यापारी से रुपया उधार लेते हैं, जोकि ऊँची ब्याज की दर पर रुपया देते हैं और अधिकतर तो उन्हें अपना माल ही ऋण देने वाले महाजन अथवा व्यापारी के हाथ सोपना पड़ता है। पूँजी के अभाव में कारीगर कभी-कभी महाजन के यहाँ ही एक निश्चित वेतन पर काम करने लगते हैं। बैंकिंग सुविधाओं का भी उनके लिए अभाव ही है। सरकार का भी इस सम्बन्ध में कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है।

(३) विक्रय की कठिनाई—घरेलू उद्योगों द्वारा निर्मित माल की विक्रय प्रणाली भी दोषपूर्ण है। कुटीर-उद्योगों के सामने सगठित बाजार के अभाव की समस्या सचमुच बड़ी महान है। सगठित बाजार के अभाव में हमारे कारीगरों को अपनी वस्तुओं के विक्रय के लिये स्वयं इधर-उधर घूमना पड़ना है, जिससे समय की हानि होती है। कारीगर अपनी वस्तुओं की बिक्री उचित मूल्य पर नहीं कर सकता। उन्हें कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। वे अपनी वस्तुओं की माँग का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते। वे अपनी वस्तुओं का विज्ञापन भी नहीं कर पाते। विक्रय के लिये अभी तक कोई भी केन्द्रीय संस्था न होने के कारण कारीगरों के लाभ का एक बहुत बड़ा भाग मध्यस्थों की जेब में चला जाता है।

(४) शिक्षा की अशिक्षा तथा रुढ़िवादी एवं प्रशिक्षण का अभाव—अधिकांश कुटीर कारीगर साधारण लिखना-पढ़ना भी नहीं जानते। नवीन तरीकों एवं औजारों को वे व्यवहार में नहीं लाते और न कभी ऐसा ही प्रयत्न करते हैं कि उनके माल में नवीनता आये। उत्पादन व्यय सम्बन्धी आँकड़े लगाने में भी वे अनभिज्ञ ही होते हैं। शिक्षा के कारण वे समरूप तथा उच्च कोटि का माल तैयार नहीं कर पाते। यह बात भी निर्विवाद कही जा सकती है कि कुटीर-उद्योगों की पिछड़ी हुई अवस्था का एक मुख्य कारण उनमें अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण का अभाव है। इसी कारण ये उद्योग वृहत उद्योगों की स्पर्धा में टिक नहीं पाते। सच तो यह है कि आर्थिक कठिनाई के कारण हमारे लघु उद्योगों के लिये यह सम्भव नहीं होता कि वे औद्योगिक विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों की सेवाएँ प्राप्त कर सकें। देश में जितने भी ऐसे विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकते हैं उनकी सेवाओं को वृहत उद्योग ले लेते हैं, अतः लघु-उद्योगों में अनुसन्धानों की सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं।

(५) वैज्ञानिक यन्त्रों का अभाव—बैसे तो कुटीर-उद्योगों में औजारों की अधिक आवश्यकता नहीं होती, किन्तु हमारे कारीगर इतने दरिद्र हैं कि उनको थोड़े से आवश्यक औजार भी दुर्लभ हैं। हमारे अधिकांश कारीगर उत्पादन की पुरातन रीतियों का ही अनुकरण करते हैं। गाँव में चमड़ा पकाने, बर्तन बनाने तथा खट्टर बुनने की विधियाँ इतनी भद्दी, पुरातन, गंवार तथा अवैज्ञानिक होती हैं कि अधिकांश में लोग उनसे निर्मित पदार्थों का उपभोग करना कम पसन्द करते हैं। परम्परागत

विधियों का पालन करने के ही कारण हमारे कुटीर कारीगरों की कार्यक्षमता भी बहुत कम है। परिणामस्वरूप वस्तु की मात्रा के साथ किस्म भी अत्यन्त भरी तथा गैरवास्तविक हो जाती है, जिसके कारण ये पदार्थ अन्य निर्मित पदार्थों की प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते।

(६) कर की समस्या—केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने कुटीर-उद्योगों द्वारा निर्मित पदार्थों पर कर लगाया है। वास्तव में ये उद्योग इस भार को सहन नहीं कर सकते। आवश्यकता तो इस बात की है कि इन्हें कर में मुक्त करके धार्मिक सह्यिता दी जावे, जिससे वे कारखानों द्वारा निर्मित माल से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकें।

(७) मिल-निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता—कुटीर-उद्योगों की मिल की बनी हुई वस्तुओं से घोर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। मिल की बनी हुई वस्तुएँ कुटीर पदार्थों की अपेक्षा प्रायः सस्ती होती हैं। मगर इन्हीं वस्तुओं को खरीदना लोग अधिक पसन्द करते हैं। फलस्वरूप कारीगरों की वस्तुओं की माँग कम हो जाती है।

(८) संगठन का अभाव—प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में कुटीर-उद्योगों में लगे कारीगरों में संगठन का अभाव रहता है। कारीगर स्वयं अपना काम चलाया करता है तथा किसी प्रकार के संगठन का प्रयत्न नहीं करता। उक्ति संगठन के अभाव में इन उद्योगों को तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि संगठन रहता तो इन्हें सुगमतापूर्वक कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। पूँजी तथा बाजार की व्यवस्था में भी सुधार हो जाता तथा सरकार भी इनकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करती है।

(९) जनता द्वारा पूर्ण सहयोग का अभाव—प्राचीन काल में कुटीर-उद्योगों की राजा-महाराजा तथा जागीरदारों द्वारा प्रोत्साहन एवं सहायता मिलती थी। मगरेजों के शासन काल में यह बातें प्रायः लुप्त हो गईं और घोर विरोध के कारण उद्योग भी अवनति हो गई। आज यद्यपि हमारा देश स्वतन्त्र है, परन्तु अधिकतर जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में निर्मित कुटीर पदार्थों की अपेक्षा मिल निर्मित विदेशी पदार्थों को प्राथमिकता देने हैं। फिर, ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जो मुख से तो स्वदेशी कुटीर पदार्थों का प्रचार करते हैं परन्तु स्वयं विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सरकार की क्रय नीति भी विशेष संतोषजनक नहीं है।

इस प्रकार कुटीर-उद्योगों के समस्त उपर्युक्त समस्याएँ हैं, जिनके समाधान के बिना इनका विकास सम्भव नहीं है।

कुटीर-उद्योगों की समस्याओं के समाधान के उपाय—

यद्यपि भारत की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर-उद्योगों की एक महत्वपूर्ण स्थान

प्राप्त है, किन्तु फिर भी इनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः इनकी स्थिति में सुधार करना निम्नलिखित आवश्यक है। इस सम्बन्ध में हमारे निम्नलिखित सुझाव हैं :—

(१) कच्चे माल की समुचित व्यवस्था—कुटीर कारीगरों को प्रायः पर्याप्त मात्रा में एवं उचित मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः उनके विकास के लिए कच्चे माल की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकारों को अधिक सक्रिय सहयोग देना होगा।

इस समस्या का दूर करने के लिए आवश्यक है कि उद्योगपतियों की अपनी सहकारी समितियाँ हो, जो उन्हें कच्चा माल साफ़ करें। ये ही समितियाँ उनके माल को अच्छे भावों पर बेचने का प्रबन्ध करें। उत्तर-प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई में कपड़ा बुनने वाले उद्योगियों की सहकारी समितियाँ हैं, जो सदस्यों को कच्चा माल देती हैं तथा उनके कपड़ों को ऊँचे से ऊँचे भाव पर बेचने का प्रबन्ध करती हैं। ऐसी समितियों के होने से मध्यस्थ लोग उद्योगियों का शोषण न कर सकेंगे। ऐसी समितियाँ प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में होनी चाहिए।

कुटीर उद्योगों की समस्याओं के उपचार

- (१) कच्चे माल की समुचित व्यवस्था।
- (२) पूँजी की समुचित व्यवस्था।
- (३) निष्क्रम की समुचित व्यवस्था।
- (४) शिक्षा की समुचित व्यवस्था।
- (५) कर्मचारियों में संगठन की आवश्यकता।
- (६) करों में कमी।
- (७) मिल निर्मित पदार्थों की प्रति-योगिता से रक्षा।
- (८) प्राथमिक यन्त्रों व नवीनतम उत्पादन प्रणालियों की व्यवस्था।
- (९) जन-सहयोग की आवश्यकता।
- (१०) अन्य सुझाव।

(२) पूँजी की समुचित व्यवस्था—कुटीर कारीगरों की दरिद्रता के कारण इनके समस्त पूँजी की कठिनाई सदैव बनी रहती है। पूँजी के अभाव के कारण इन्हें अनेक प्रकार की सुविधाओं का नुक़ार होना पड़ता है। पूँजी सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय बैंकिङ्ग जाँच समिति ने यह सुझाव दिया कि कारीगरों को अपनी सहकारी समिति स्थापित करनी चाहिए, जो सदस्यों को कम एवं उचित मूल्य पर ऋण देकर उनकी पूँजी की आवश्यकता को पूरी करे। सहकारी समितियों द्वारा इन्हें उचित मूल्य तथा व्याज पर पूँजी प्राप्त हो सके। साथ ही सरकार को भी समय-समय पर इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। कुटीर-उद्योगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न राज्यों में अथनियम (State Finance Corporation) स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि महाजनो धोर साहूकारों को नियन्त्रित किया जाय अथवा राज पूँजी वी इस पद्धति का क्रमशः उन्मूलन कर औद्योगिक सहकारिता (Industrial

Co-operatives) का आयोजन किया जाय। इसी से कुटीर उद्योगों का आर्थिक समर्थन एवं संस्थापन सुदृढ होगा।

(३) विक्रय की समुचित व्यवस्था—कुटीर कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के लिए भी समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है। इसके लिए इनके बीच सहकारी विक्रय समितियों का संगठन होना चाहिए, जिससे उचित मूल्य पर इनकी वस्तुओं का विक्रय सम्भव हो सके। विदेशों में इनके उपयोग को बढ़ाने के लिए विज्ञापन एवं प्रचार भी आवश्यकता है। केन्द्रीय कुटीर-उद्योग इम्पोरियम की स्थापना होने में विक्रय की कठिनाई काफी सीमा तक हल हो गई है, किन्तु जब तक ऐसी सस्था प्रत्येक राज्य में न हो, तब तक इस कठिनाई का निवारण न हो सकेगा। अतः इस दिशा में सुधार करने के लिए इन उद्योगों को अपने मातृ की विस्म में सुधार करना चाहिए, सहकारी समितियों की स्थापना करना चाहिए तथा उत्पादन व्यय में मितव्ययिता करनी चाहिए। योजना आयोग के मतानुसार सरकार को चाहिए कि अपने लिये स्टोर की खरीद करके तथा आयात को समाप्त करके इन उद्योगों को प्रोत्साहित करे और इनको निर्माण विधि में सुधार करे।

(४) शिक्षा की समुचित व्यवस्था—कुटीर कारीगरों की अशिक्षा व अज्ञानता भी इन उद्योगों के विकास के मार्ग में बाधक है। अतः कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए कारीगरों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। देश में विशेष प्रकार की औद्योगिक शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। माजकल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए संस्थाएँ स्थापित की जा रही हैं। सरकार स्वयं इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना कर रही है तथा दिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। साथ ही, विभिन्न संस्थाओं को इस कार्य के लिए अनुदान भी दिया जाता है। इस सम्बन्ध में हमारे अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं :— (अ) प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाय। (ब) तांत्रिक शिक्षा के केन्द्र खोले जायें। जेलों में भी इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाय। (स) आधुनिक प्रणाली से कार्य करने के लिए अनुसन्धान किया जाय। उत्पादन मये ढंग से नवीन मशीनों द्वारा किया जाय। (द) कारीगरों को व्यावसायिक शिक्षा देने के हेतु प्रदर्शन केन्द्र खोले जायें, जिनमें कारीगरों को शिक्षा दी जावे। जेलखानों और सुधार संस्थाओं में भी औद्योगिक दस्तकारी सिखाई जाय, जिनमें बि यहाँ से निकले हुए व्यक्ति सुन्दर नागरिक जीवन व्यतीत कर सकें। (य) कुटीर-कला प्रदर्शन-केन्द्रों की स्थापना की जाय, जहाँ सीखने वाले लोगों को नई-नई डिजायनों, नवीन उत्पादन विधियों, आदि का ज्ञान कराया जाय।

(५) कुटीर कर्मचारियों में संगठन की स्थापना करना—कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि कारीगरों के बीच संगठन हो। अशिक्षा एवं अज्ञानता ने कारण वे प्रायः संगठन की महिमा को नहीं समझते। अतः इनके बीच संगठन को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार द्वारा इनके संगठन को

आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए । कारीगरों का सच्चा संगठन ही औद्योगिक सहकारिता को प्रेरित कर सकता है ।

(६) करो मे कमी—कुटीर पदार्थों को विन्नय-कर, निर्यात-कर आदि से मुक्त कर देना चाहिए तथा इनके लिए रेल-भाड़ा भी कम होना चाहिए । ऐसा करने से इनकी वस्तुओं के विन्नय में सुविधा होगी तथा ये मिल-निर्मित माल से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकेंगे ।

(७) मिल निर्मित पदार्थों की प्रतियोगिता से रक्षा—आजकल भारत सरकार ने उत्पादन के सामान्य कार्यक्रम (Common Production Programme) की नीति को अपनाया है, जिसके अनुसार उत्पादन के क्षेत्रों का विभाजन व धर्मिकरण करके उनको सुरक्षित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । जहाँ तक विदेशी प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, भारत सरकार को इनके आघात पर इस प्रकार नियन्त्रण रखना चाहिए, जिससे कि हमारे कुटीर उद्योगों का माल बड़ी सुगमतापूर्वक खप सके । मिल निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से कुटीर पदार्थों की रक्षार्थ यह उचित होगा कि इन दोनों प्रकार के उद्योगों के उत्पादन क्षेत्र का निग्रह तथा उत्पादन की मात्रा सीमित कर दी जाये । ऐसा करने से प्रतियोगिता की आशंका समाप्त हो सकती है ।

(८) आधुनिक यन्त्रों व नवीनतम उत्पादन प्रणालियों की व्यवस्था—कुटीर-उद्योगों की निरन्तर प्रगति के लिए यही नितान्त आवश्यक है कि इनमें आधुनिकीकरण का प्रवेश हो । हमारे कुटीर कारीगरों को आधुनिक तरीकों से कार्य करने की प्रणालियाँ बतलाई जायें तथा उनको नये-नये यंत्र प्रदान किये जायें । ऐसा करने से उत्पादन अधिकतम व श्रेष्ठतम हो सकेगा । सरकार को कम मूल्य पर या ऋण एवं अनुदान के रूप में आधुनिक औजारों के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए । इस क्षेत्र में औद्योगिक सहकारी समितियाँ भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती हैं । साथ ही, स्थान-स्थान पर विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में नये नये यन्त्रों के प्रदर्शन की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे यह अधिक लोकप्रिय हो सके ।

(९) जन-सहयोग की आवश्यकता—आज हमारा देश स्वतन्त्र है । हमको चाहिए कि 'स्वदेशी वातु उपयोगी आन्दोलन' करें तथा कुटीर निर्मित पदार्थों की मांग बढ़ायें । यह सचमुच बड़े लज्जा का विषय है कि आज भी ऐसे अनेक भारतीय हैं, जो स्वदेशी वस्तुओं की अपेक्षा मिल निर्मित विदेशी पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं । ऐसा करना वास्तव में राष्ट्र के प्रति कुसेवा है । कुटीर उद्योगों के विकास के लिए जनता को अधिक सहयोग देना चाहिए । हमारी राष्ट्रीय सरकार को भी चाहिए कि वह इन वस्तुओं के निर्यात की ओर विशेष ध्यान दे और ऐसे प्रयत्न करे जिससे भारतीय कुटीर निर्मित पदार्थ विश्व के कौने-कौने में पहुँचकर देश की स्वायत्ति को बढ़ाये ।

(१०) अन्य सुझाव—उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जल विद्युत शक्ति का प्रसार, हमारे कुटीर धन्वों की उन्नति एवं उनकी आर्थिक सुदृढता

में सहायक होगा। इनके विकास से बेरोजगारी का निवारण होगा और अधिकांश लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होगा तथा उनमें जीवन के प्रति उत्साह जागृत होगा।

उपयुक्त उपचारों के अध्ययन से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रथम तो यह कि कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए सरकार को बहुत अधिक तत्परता से काम लेना चाहिए। इन उद्योगों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बिना राजकीय सहायता के इनका विकास बिल्कुल सम्भव नहीं है। दूसरे, औद्योगिक सहकारिता (Industrial Co-operatives) के विकास के द्वारा इनकी अधिकांश कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। ये समितियाँ इनके लिए पूँजी, यन्त्र, कच्चे माल आदि की व्यवस्था सुविधा से कर सकती हैं साथ ही, ये इनके द्वारा उत्पादक वस्तुओं के विक्रय का भी उत्तरदायित्व ले सकती हैं।

भारी, लघु एवं कुटीर उद्योगों में समन्वय—

भारत की अर्थ व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का अधिक महत्त्व होते हुए भी यह सुझाव कि बड़े परिमाण के उद्योग बड़े से उखाड़ देने चाहिए, राष्ट्र के लिए हितकर नहीं होगा। देश के औद्योगीकरण के लिए आज बड़े-बड़े उद्योगों की भी आवश्यकता है। सभी हम विश्व के अन्य उन्नतिशील देशों के स्तर तक पहुँच सकते, अतएव यदि हम केवल कुटीर-उद्योगों के आधार पर ही अपने औद्योगिक विकास का स्तम्भ स्थापित करने की चेष्टा करें, तो हमें विश्व के अन्य देशों से पृथक् रहना पड़ेगा, अतः एकाकी जीवन भी व्यतीत करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, किन्तु प्रायः विश्व की स्थिति भिन्न है। हम किसी अन्य देश से असंग होकर रह नहीं सकते, अतएव आवश्यकता है इनके समन्वय की। हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें बड़े पैमाने के उद्योग एवं कुटीर उद्योग दोनों को उचित स्थान मिले। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक प्रकार के उद्योग का क्षेत्र निश्चिन कर देना चाहिए। उदाहरणार्थ, स्थाूल उद्योग और आधारभूत उद्योगों का बड़े पैमाने पर ही विकास होना चाहिए, क्योंकि ये उद्योग कुटीर आधार पर टिक ही नहीं सकते। ऐसे उद्योगों के उदाहरण हैं—लौह एवं स्पात उद्योग, मशीन टूल्स एवं वाहन उद्योग, विद्युत तथा शक्ति उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, रक्षा सम्बन्धी उद्योग इत्यादि। इनके प्रतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग भी, जिनके उत्पादन देश के निर्वात के प्रधान अंग हैं, बड़ी मात्रा पर विकसित होना चाहिये, जैसे—जूट उद्योग, सूती वस्त्र मिल उद्योग आदि। कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो कि बड़े पैमाने एवं कुटीर आधार पर भी चलाये जा सकते हैं, जैसे—बटाई-मुनाई उद्योग, काच का उद्योग, चमड़े का उद्योग, कागज का उद्योग, शक्कर का उद्योग आदि। कुछ उद्योग केवल कुटीर आधार पर ही विकसित होने चाहिये जैसे—मलीचा एवं दरी का बुनना, जर्दोजी, वाम्रदानी और चिकन उद्योग, नूढ़ाई का काम, बर्तन बनाने का उद्योग, होजियरी, सिल्क तथा ऊन उद्योग, दूध-दही से सम्बन्धित उद्योग, साबुन बनाना, गुड़ बनाना, तेल निकालना, खिलौने बनाना,

फर्नीचर उद्योग आदि । इन उद्योगों में कलात्मक वस्तुओं बनाने का विस्तृत क्षेत्र है । दूसरे, इनके लिए अधिक पूँजी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । तीसरे, इन वस्तुओं का उपभोग भी प्रायः स्थानीय होता है और यदि इनका निर्यात भी किया जाय, तो वे सफलतापूर्वक बारखाना निर्मित माल से टक्कर ले सकते हैं । चौथे, कार्य करने वाले श्रमिक के परिवार के अन्य सदस्य भी इन कामों में सहायता पहुँचा सकते हैं । सच बात तो यह है कि कुटीर एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच अन्तर की कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती । उदाहरण के लिए, सूती वस्त्र उद्योग को ही ले लें । यह उद्योग बड़े परिमाण पर भी चलाया जा सकता है एवं कुटीर आधार पर भी, किन्तु इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह है कि बतार्ई का काम मिलों में हो और बुनाई का काम कुटीर कारीगरों को सौंपना चाहिए, क्योंकि मिल का कता हुआ सूत सुन्दर होगा एवं उसमें एकरूपता होगी और फिर ऐसे सूत को यदि कुटीर कारीगरों के द्वारा बुनवाया जाय, तो वे उसमें अपनी सम्पूर्ण कला दिखला सकते हैं । दूसरा सुझाव यह है कि २० अथवा ३० बाउन्ट्स के नीचे कतार्ई तथा बुनाई दोनों का कार्य कुटीर श्रमिकों द्वारा कराया जाय और बढिया किम्म का कपडा बनाने के लिए मिलों से सहायता ली जाय । इसी प्रकार अन्य उद्योगों में भी कार्य विभाजित किया जा सकता है ।

कुटीर एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच अस्वस्थ प्रतिद्वन्द्विता को दूर करने के लिए सरकार को भरमक प्रयत्न करना चाहिये । सुन्दर दक्षियम के द्वारा दोनों प्रकार के उद्योगों में समन्वय सम्भव है । कुटीर-उद्योगों द्वारा निर्मित माल का क्रय करके भी राज्य सरकार कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है । पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थान पर लिखा है—“यह समन्वय राष्ट्रीय योजना द्वारा सम्भव है, किन्तु एक प्रभावशाली योजना राजनैतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना नहीं बन सकती । राज्य नियन्त्रण के बिना भी युक्तिपूर्ण योजना का निर्माण असम्भव है । आधारभूत उद्योग, जन-सेवा उद्योग एवं यातायात उद्योग पर तो राज्य का पूर्ण नियन्त्रण रहना चाहिए । अन्य उद्योगों पर नियन्त्रण की मात्रा कम हो सकती है । कोई भी बड़ा उद्योग जो किसी कुटीर-उद्योग के मार्ग में रोड़ा बने, उस पर तो राज्य का नियन्त्रण अनिवार्य रूप से होना चाहिए । इसी नीति द्वारा सामंजस्य सरल एवं सम्भव होगा ।”

भारतीय पार्लियामेण्ट में बोलते हुये ६ मार्च सन् १९४६ को डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भी एक बार यह कहा—“भारत का भविष्य दोनों प्रकार के उद्योगों के विकास में ही निहित है । यदि हम ग्राम्य जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तथा बकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं, तो यह कार्य केवल बड़े पैमाने के उद्योगों के द्वारा ही सम्भव न होगा, बरन् प्रादेशिक योजना के द्वारा ही

हो सकता है, जिसमें बड़ उद्योग, लघु उद्योग एवं कुटीर-उद्योग सभी को यथोचित स्थान मिले।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Discuss carefully the principal problems of Indian Cottage Industries
- 2 What are your suggestions to solve the problems of Indian Cottage Industry
- 3 The solution to the problems of Indian Cottage Industries lies in Industrial Co-operation Explain
- 4 Heavy Small and Cottage Industries—all need to be developed at the same time in the present economic conditions of India How far do you agree with this statement? Give reasons for your answer and lay a scheme for co-ordination between different types of Industries

अध्याय ५६

सरकार द्वारा कुटीर-उद्योगों के विकास के लिये प्रयत्न

(प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं के विशेष सन्दर्भ सहित)

(Governmental Steps To Encourage Cottage Industries)

स्वतन्त्रता के पूर्व सरकार की नीति—

सन् १९४७ के पूर्व भारत में अंग्रेजी राज्य था और उन विदेशियों ने सद्भावना से कभी भी देश के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे कुटीर उद्योग अवनति की दशा में पड़ रहे। सन् १९२० के बाद देश के विभिन्न प्रांतों में कुटीर उद्योगों को

पुनर्जीवित करने के लिये अवश्य कुछ प्रयत्न किये गये और उनका निरीक्षण करने के लिये सन् १९३३ में भारत के प्रत्येक प्रान्त में उद्योग विभाग की स्थापना की गई। किन्तु इन विभागों ने जितनी तत्परता एवं आत्मीयता से काम करना चाहिए था, नहीं किया। सन् १९३३ में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल की स्थापना के उपरान्त कुटीर-धन्वों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया, जो काँग्रेस का एक राजनैतिक एवं भावनात्मक पहलू है।

आधुनिक काल में किये गए सरकारी प्रयत्नों का विवरण—

कुटीर-उद्योगों के भाग्य का सितारा तो १५ अगस्त सन् १९४७ की अर्द्ध-रात्रि को चमका। हमारी जन-प्रिय सरकार अपने पूर्व वचनानुसार कुटीर-उद्योगों के विकास के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रही है। अप्रैल सन् १९४८ में घोषित अपनी प्रथम औद्योगिक नीति में सरकार ने कुटीर-उद्योगों पर उचित बल दिया। प्रथम पंच-वर्षीय योजना ने भी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर-उद्योगों के महत्त्व को स्वीकार किया है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना ने तो रोजगार को बढ़ाने और उपभोग पदार्थों में वृद्धि करने के लिये ऐसे उद्योगों पर विशेष निर्भरता प्रकट की है।

ऐसे उद्योगों के विकास को प्रासाहित करने की दृष्टि से सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं। सन् १९४८ में कुटीर-उद्योगों का विकास प्रोत्साहित करने के लिये एक कुटीर-उद्योग बोर्ड (Cottage Industries Board) विशेष रूप से स्थापित किया गया। विद्यमान उद्योगों के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए बोर्ड ने एक सर्वे कराने का निर्णय किया, जो कि अब पूर्ण हो गया है। नवम्बर सन् १९५२ में एक अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (The all India Handicrafts Board) का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य कुटीर पदार्थों की किस्म में सुधार करना और भारत में तथा विदेशों में उसका प्रचार एवं बिक्री बढ़ाना था। हैंडलूम उद्योग की, जोकि भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग है, सहायता करने के लिए अखिल भारतीय हैंडलूम बोर्ड (All India Handloom Board) की सन् १९५२ में स्थापना की गई। यह बोर्ड उद्योग में सहकारिताओं के विकास पर और उत्पादन के विपणन पर विशेष जोर दे रहा है। बोर्ड के अन्तर्गत एक केन्द्रीय विपणन संगठन (Central Marketing Organisation) स्थापित किया गया है, जिसकी शाखायें मद्रास, बम्बई और बनारस में रखी गई हैं। यह संगठन देश भर में प्रचार-कार्यक्रम चलाने में बोर्ड की मदद करता है। अखिल भारतीय खादी और ग्राम्य उद्योग बोर्ड (All India Khadi and Village Industries Board), जिसका गठन फरवरी सन् १९५३ में हुआ था, ग्रामीण उद्योगों की प्रधान संस्था है। खादी एवं १० अन्य ग्राम्य उद्योग इसके आधीन कर दिये गये हैं और इनके विकास के लिए यही बोर्ड कार्यक्रम बनायेगा। सन् १९५४ में सरकार ने लघु-उद्योग-बोर्ड (Small-scale Industries Board) की भी स्थापना की। इन बोर्डों का

कर्तव्य लघु उद्योगों को तानिक सहायता प्रदान करने के लिए, विभिन्न केन्द्रों में स्थापित किये गये संगठनों की क्रियाओं में समन्वय करना है।

सरकार तथा बैंकिंग संस्थान छोटे उद्योगों की वित्तीय सहायता देते हैं। सन् १९५७-५८ में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों के लिए ₹ ३० करोड़ रुपये के ऋणों तथा १-१० करोड़ रुपये के अनुदानों की स्वीकृति दी गई। अब तक ७२ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से सितम्बर सन् १९५८ तक ७२ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से सितम्बर सन् १९५८ तक १७ औद्योगिक बस्तियों का निर्माण पूरा हो चुका था और इन पर ₹ ६८ करोड़ रुपये व्यय हुए। इन औद्योगिक बस्तियों के लिए योजना में निर्धारित राशि १० करोड़ रुपये से बढ़ाकर १५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार सेवा' के नाम से छोटे उद्योगों को प्राविधिक सहायता देने का एक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास स्थित ४ प्रादेशिक संस्थाओं, १२ जूनी संस्थाओं, ५ शाखा संस्थाओं तथा ६२ विस्तार केन्द्रों का भी कार्य आरम्भ हो चुका है। प्रत्येक राज्य में भी ऐसी एक संस्था की व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर सन् १९५८ में इस सेवा का पुनर्संरजन किया गया। लघु उद्योगों को प्राविधिक मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं तथा फंड प्रतिष्ठान की सहायता से भारतीय प्राविधिकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है।

फरवरी सन् १९५५ में एक 'राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम' स्थापित किया गया। सन् १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित ₹ ४० करोड़ रुपये की वस्तुएँ खरीदीं। निगम ने मशीनों तथा उपकरणों के क्रय-विक्रय (हायर परपेच) के लिए एक योजना लागू की, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योगों को १-४३ लाख रुपये की मशीन दी जा चुकी है। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए 'सामुदायिक योजना कार्य प्रशासन' ने कई सामुदायिक योजना कार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में खण्ड स्तर के औद्योगिक अधिकारी नियुक्त किये हैं।

दस्तकारी की वस्तु के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके विक्रय की व्यवस्था के लिए सन् १९५२ में स्थापित 'अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल' ने देश तथा विदेश, दोनों स्थानों में विशेष रूप से ध्यान दिया। इस मण्डल के नियति प्रोत्साहन सम्बन्धी कुछ कार्यों के लिए 'भारतीय दस्तकारी विकास निगम' स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में 'दस्तकारी सप्ताह' मनाये जाते हैं। दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रति वर्ष १ अरब रुपये के मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और प्रति वर्ष लगभग ७ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

नारियलजटा उद्योग मुख्यतः एक कुटीर उद्योग है। इसके कुछ कारखानों में

लकड़ी के करघे है, जिन पर हाथ से काम किया जाता है। १*२० लाख टन के अनुमानित वार्षिक उत्पादन में से ६० प्रतिशत उत्पादन केरल में ही होता है। औसतन ५०,००० टन नारियलजटा तथा इससे बनी २१,००० टन वस्तुओं का निर्यात किया जाता। 'नारियलजटा मण्डल' भारत में नारियलजटा से बनने वाली वस्तुओं को लाकप्रिय वस्तु तथा उनको प्रोत्साहन देने के कार्य में लगा हुआ है। नारियलजटा से बनी वस्तु विदेशी विनिमय के अर्जन के महत्वपूर्ण स्रोत होने की दृष्टि से द्वितीय योजना नारियलजटा उद्योग के लिए की गई व्यवस्था अब बढ़ाकर २*३० करोड़ रुपये की गई है।

सन् १९५८ में ३४*०१ लाख पीण्ड कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ, जिसमें लगभग आधे का उत्पादन मैसूर राज्य में ही हुआ। मैसूर के बाद इसके महत्त्व उत्पादन-क्षेत्रों में आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिमी बंगाल तथा मद्रास के र आते हैं। अग्रे सन् १९५८ में पुनर्संरुद्धित 'केन्द्रीय रेशम मण्डल' रेशम उद्योग रेशम-कीड़ा पालन के विकास की देखभाल करता है। सन् १९४३ में बरहान (पश्चिमी-बंगाल) में एक 'केन्द्रीय-रेशम कीड़ा-पालन शोध केन्द्र' स्थापित किया गया। इनकी एक छात्रा कलिम्पोंग में भी स्थापित की गई। द्वितीय योजना में इन केन्द्रों का विस्तार किया जायगा। 'केन्द्रीय रेशम मण्डल' की धार से मैसूर में एक 'आर्य भारतीय रेशम-कीड़ा-पालन प्रशिक्षण संस्था' तथा श्रीनगर में एक 'केन्द्रीय रेशम-न (विदेशी) पालन केन्द्र' स्थापित किया गया।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने इन उद्योगों की सहायता करने के लिए कुछ सिद्धान्त स्वीकार किये हैं। उदाहरण के लिए, कुटीर और लघु उद्योगों की सहायता करने के लिए उनके प्रतियोगी बृहत् उद्योग पर उत्पादन कर लगाया जाता है, जैसे मिल के बने कपड़े पर एक पैसा प्रति गज कर लगाया गया है, जिसमें लगभग ६ क रुपये प्रति वर्ष आय होगी। इस धन का उपयोग हैन्डलूम उद्योग के अधिक विकास के लिए किया जायगा। इसी प्रकार एक अन्य सिद्धान्त यह भी है कि विशेष परिस्थितियों में कुटीर उद्योग को, उत्पादन का कुछ क्षेत्र उसके लिए विशेष रूप से सुरक्षित क व्यवस्थाई सहायता प्रदान की जा सकती है, जैसे—साड़ियों का उत्पादन केवल हैन्ड उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिया गया है।

उपरोक्त वाक्यों के अतिरिक्त सरकार कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए मुविधायी के विस्तार के प्रयत्न भी कर रही है। ऐसे उद्योगों की आर्थिक सहायता करने के हेतु १० राजकीय वित्त निगमों की स्थापना की जा चुकी है। रिजर्व बैंक के एक संशोधन के अनुसार, रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया। वह ऐसे उद्योगों के उत्पादन एवं विपणन के लिए राज्य सहकारी बैंकों और राज निगमों को धन दे। सरकार ने अपनी विभाग-सामग्री क्रय नीति में भी उदारता ली है। कुटीर-उद्योगों के उत्पादकों को एक निश्चित प्रतिशत तक प्राथमिकता दी है। इन्टरनेशनल प्लानिंग टीम की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नि

३, मद्रास और कलकत्ता में चार लघु उद्योग सेवा इन्स्टीट्यूट (Small Industries Service Institutes) स्थापित कर दिये हैं। सरकारी आदर्शों की पूर्ति के लिए उत्पादन का संगठन करने के हेतु दिल्ली में एक लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) की भी स्थापना की गई है। लघु उद्योगों के संगठन का चार्ज संभालने के लिए एच. विकास कमिशनर (Development Commissioner) नियुक्त कर दिया गया है। अम्बर चूर्ण का प्रचलन करने के लिए भी प्रस्ताव है। यह चूर्ण उत्पादन की लागत में बड़ी कमी कर देगा और देश के लाखों व्यक्तियों को अपार लाभ पहुँचायेगा। सन् १९५६-६० में विभिन्न-विकास योजनाओं की प्रगतियों के लिये सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिये १८०३ करोड़ रुपये निर्धारित किये, जिनमें १०७० करोड़ रुपये अनुमान और ७३३ करोड़ रुपये ऋण रूप में थे। इसमें से ३५० करोड़ रुपये पुरानी चाल की खादी, ११२८ करोड़ रुपये अम्बर चूर्ण कार्यक्रम और ३२५ करोड़ रुपये ग्रामोद्योग की योजनाओं के लिये थे।

प्रथम योजना में कुटीर-उद्योगों की प्रवृत्ति—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल (सन् १९५१-५६) में लघु तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये विभिन्न परिपदों द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जो व्यय किया वह इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

विवरण	व्यय की राशि
१. हस्त करघा परिपद	१२.२
२. खादी	१२.३
३. ग्रामोद्योग	२.६
४. लघु उद्योग	४.४
५. हस्तकला	०.८
६. मिल्क	०.७
७. नारियलजट्टा	०.३
कुल योग	३३.६

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत हस्त करघा उद्योग को विशेष रूप में प्रोत्साहन दिया गया, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के कपड़े का उत्पादन सन् १९५१ में ७,४२० लाख गज में बढ़कर सन् १९५४-५५ में १३,५४० लाख गज और सन् १९५५-५६ में १४,५०० लाख गज हो गया। प्रथम योजना काल में खादी उत्पादन का मूल्य सन् १९५०-५१ में १३ करोड़ रुपये से बढ़कर सन् १९५५-५६ में ५४ करोड़ रुपये

के लगभग हो गया। भारत सरकार ने अपनी स्टोर क्रय नीति में भी प्रसशनीय सुधार किया, जिसके अनुसार कुटीर एवं लघु उद्योगों के उत्पादन को सरकार द्वारा खरीद के समय प्राथमिकता दी जाती है। इस नीति के परिणामस्वरूप भारत सरकार को जबकि सन् १९५२-५३ में ६६ लाख रु० का सामान इन उद्योगों से खरीदा गया था, सन् १९५५-५६ में यह राशि बढ़कर ३०४ लाख रुपए हो गई। इसी काल में कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के हेतु उत्पादन के सामान्य कार्यक्रम (Common Production Programme) की नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार लघु उद्योगों की सहायताएं इनके अनुरूप बड़े पैमाने के उद्योगों पर कर लगाने, उत्पादन क्षेत्र के निग्रह (Reservation of Spheres of Production) तथा आर्थिक सहायता द्वारा लघु उद्योगों को अल्पकालीन सुरक्षा प्रदान करने के सिद्धान्त को अपनाया गया है। इन उद्योगों की प्रगति के लिये औद्योगिक सहकारिता के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया। सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में भी इन उद्योगों के विकास के लिये रचनात्मक काम किए गए। योजना में कुल मिलाकर ४३.७ करोड़ रुपया इस मद में खर्च किया गया था। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा १३.६ करोड़ रुपया और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा १०.१ करोड़ रुपया व्यय किया गया।

कर्वे समिति की नियुक्ति—

कुटीर व लघु उद्योगों की समस्या पर गम्भीरता से विचार करने के लिए जून सन् १९५५ में योजना आयोग ने प्रो० डी० जी० कर्वे की अध्यक्षता में एक 'ग्राम एवं लघु उद्योग समिति' की नियुक्ति की। इस समिति ने निम्नलिखित उद्देश्यों को अपने सम्मुख रखा—

- (अ) द्वितीय योजना काल में परम्परागत ग्रामोद्योगों में होने वाली प्राद्योगिक बेकारी को रोकने का यथासम्भव प्रयास करना।
- (ब) इन उद्योगों के द्वारा रोजगार के साधनों में अधिक से अधिक वृद्धि करना।
- (स) विकेंद्रित समाज के ढाँचे पर तीव्र गति से प्रगतिशील आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करना।

कर्वे समिति का यह सुझाव कि गाँव की औद्योगिक इकाई—'प्रजातन्त्रीय ग्रामीण ग्रंथ व्यवस्था पर आधारित उद्योग का पैरामिड' अथवा आधार मानकर औद्योगिक व्यवस्था के निर्माण की आदर्श योजना बनाई जाये। ऐसी योजना निम्नलिखित मान्यताओं पर निर्भर होगी—(क) समान उद्योग की बड़ी एवं छोटी इकाइयों के लिये सामान्य उत्पादन कार्यक्रम, (ख) औद्योगिक उत्पादन के स्थानीय क्षेत्रों को महत्व देना, तथा (ग) छोटी इकाइयों को कच्चे माल, वित्त, प्रशिक्षण आदि के द्वारा सहायता-प्रदान करना। कर्वे समिति ने द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अंतर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया, जिसके अनुसार योजना काल में २६० करोड़ रु० व्यय का आयोजन था।

प्रथम एवं द्वितीय योजना के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा -

(१) पहली योजना में हाथकरघा उद्योग, खादी और ग्रामीणोद्योग, रेशम, नारियल रेशा, दस्तकारी और लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों के बनाने में मदद करने और परामर्श देने के लिए अखिल भारतीय मण्डल नियुक्त करके इन उद्योगों की प्रगति के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। विवास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घग इनमें लगे दस्तकारों को विविध रूप से सहायता पहुँचाने का था, जैसे प्रशिक्षण सुविधाएँ, तकनीकी परामर्श, सुधरे हुए औजार आसान किस्तों पर देने का प्रबन्ध और विक्री की दूकानों की स्थापना। दूसरी योजना में इन सब प्रकार की सहायता बहुत अधिक बढ़ा दी गई। इसके लिए ₹८० करोड़ रुपये से कुछ कम खर्च किया गया, जब कि पहली योजना में केवल ४३ करोड़ रुपये खर्च किया गया था। राज्यों के उद्योग विभागों को भी बढ़ाया गया।

(२) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार हाथकरघे के कपड़े का उत्पादन सन् १९५०-५१ में ७४२ करोड़ गज से बढ़कर सन् १९६०-६१ में लगभग १६० करोड़ गज हो गया। इसमें लगभग ३० लाख बुनकरों को पहले से अधिक रोजगार मिला। सहायकारी समितियों में हाथकरघों की संख्या सन् १९५३ में ७ लाख से बढ़ कर सन् १९६० के मध्य तक १३ लाख हो गई। खादी (सूती, रेशमी और ऊनी) का उत्पादन सन् १९५०-५१ में ७० लाख गज से बढ़कर सन् १९६०-६१ में ४८ करोड़ गज हो गया और अम्बर खादी का उत्पादन सन् १९५६-५७ में १६ लाख गज से बढ़कर सन् १९६०-६१ में लगभग २६० लाख गज हो गया। इन कार्यक्रमों से लगभग १४ लाख कानने वालों को अर्द्ध-रोजगार मिला और लगभग १.६ लाख बुनकरों और बढ़इयों इत्यादि को पूरा रोजगार मिला।

ग्रामीणोद्योगों के कार्यक्रमों से दूसरी योजना में लगभग ५ लाख दस्तकारों और गाँवों की महिला श्रमिकों को कुछ रोजगार मिला। दूसरी योजना में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए खादी और ग्रामीणोद्योगों के सघन विकास के लिए एक सघन क्षेत्र योजना चलाई गई। कच्चे रेशम का उत्पादन सन् १९५१ के २५ लाख पौंड से बढ़कर सन् १९६० में ३६ लाख पौंड हो गया। दूसरी योजना के अन्त में यह अनुमान था कि इस उद्योग में ३५,००० व्यक्तियों को पूरा रोजगार और लगभग २७ लाख व्यक्तियों को आंशिक रोजगार मिला। नारियल के रेशे के धाने और सामान का निर्यात पहली पंच वर्षीय योजना के अन्त के स्तर से नीचे रहा। इस उद्योग में इस समय लगभग ८ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। दस्तकारियों की चीजों की देश और विदेश दोनों में विक्री बढ़ी। यह अनुमान है कि गलोचो समेत लगभग ६ करोड़ रुपये प्रति वर्ष का सामान दूसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों में विदेश भेजा गया।

दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में अनेक छोटे उद्योग जैसे मशीनी औजार, सिलाई की मशीन, बिजली के पंखे और मोटरें, साइक्लें, राजगीरों के औजार तथा लोहे की चीजों का बहुत विकास हुआ और इनमें २५ से ५० प्रतिशत प्रति वर्ष उत्पादन

बढ़ा। छोटे उद्योगपतियों को किस्तों पर मशीन देने के लिए एक औद्योगिक विस्तार सेवा शुरू की गई, जिसमें लगभग ४२ करोड़ रुपए की मशीनें विक्री-खरीद शर्तों पर दी। छोटे कारखानों ने निर्यात के लिए ६ लाख जोड़ी चमड़े के जूते तैयार किए। लगभग ६० औद्योगिक बस्तियां सन् १९६०-६१ में पूरी हो गईं, जिनमें सन् १९५२ में १,०३५ कारखाने थे, जिनमें १३,००० लोग काम करते थे। लघु उद्योगों के कार्यक्रम से अनुमान है कि लगभग ३ लाख लोगों को पूरा रोजगार मिला।

तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण—

तीसरी योजना में ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम चलाने समय निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य सामने रखे जाएंगे :—

- (क) कारीगर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उसे कार्यकुशल बनाने, प्राविधिक परामर्श देने, बढ़िया औजार और ऋण आदि की सहायता देकर उत्पादन-व्यय घटाना।
- (ख) विक्री में सहायता, उत्पादन में सहायता और भाग्य प्राप्त विक्रय आदि को धीरे-धीरे कम करना।
- (ग) गांवों और छोटे कस्बों में उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहन देना।
- (घ) छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में विकास करना।
- (ङ) दस्तकारों की सहकारी समितियां बनाना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति और उपाय किए जाएंगे, वे नीचे दिए जा रहे हैं।

कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार—

प्राविधिक और प्रबन्धकीय कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ तीसरी योजना में बहुत बढ़ाई जाएंगी। ग्रामीण कारीगरों के लिए चुने हुए क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की संस्थाएँ चलाने की योजना बनाई गई है, जो भास-पास के गांवों को लोहारी, बढईगिरी इत्यादि पेशों का प्रशिक्षण देगी। औद्योगिक विस्तार तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था बनाई जाएगी। विभिन्न उद्योगों में लगे हुए कारीगरों और दस्तकारों को सुबरे हुए औजार और मशीनें देने के अलावा उन्हें तकनीकी परामर्श देने की भी व्यवस्था की जाएगी।

ऋण और पूँजी—

तीसरी योजना में ऋण देने की सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाएगा और ऋण उचित शर्तों और न्यूनतम समय में दिया जाएगा। इसके लिए लक्ष्य यह रहेगा कि जिनने ऋण की आवश्यकता पड़नी है, वह साधारण बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिले।

संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम—

पहली और दूसरी योजनाओं में समूह और सहायता के व्यावहारिक उपायों को 'संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम' के तत्त्व कहा गया था। संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम से भाव

यह है कि किसी उद्योग के विभिन्न विभागों के विकास कार्यक्रम को बनाते समय उसमें बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों का योगदान क्या रहेगा, जिसमें समाज की सारी मांग सामाजिक और दूसरे उद्देश्यों के अनुरूप पूरी की जा सके। इस कार्यक्रम के दूसरे तत्त्व थे उत्पादन के क्षेत्र नियंत्रित करना, उद्योग के बड़े अंगों की क्षमता के विस्तार पर रोक लगाना, बड़े कारखानों पर शुल्क लगाना और टैक्सों, बिक्री में छूट, सहायता आदि देकर छोटे कारखानों को मूल्य की दृष्टि से लाभ पहुँचाना। यह महसूस किया गया कि संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम के ग्राम असूक्तों को उद्योग विशेष की समस्याओं का पूरा अध्ययन और छानबीन करने के बाद ही लागू किया जाय।

सरकारी सहायता, बिक्री में छूट आदि की भूमिका—

व्यवहार्य सहायता के कार्यक्रमों के क्रमिक विकास से यह आशा है कि तीसरी योजना में सरकारी सहायता और बिक्री में छूट आदि की आवश्यकता कम हो जाएगी।
 सकता है कि कुछ पारस्परिक उद्योगों के मामले में इस प्रकार की सहायता देने और उनमें बने माल के लिए बाजार ढूँढने आदि के उपायों को अन्य लघु उद्योगों की अपेक्षा अधिक समय तक जारी रखना आवश्यक हो।

ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों का औद्योगिक विकास—

तीसरी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों तथा ऐसे कम विकसित क्षेत्रों में जहाँ उद्योग खोलने की साफ सम्भावनाएँ हो, उद्योगों की और अधिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा। इसलिए जिन क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यक्रमों के कारण विभिन्न मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँगी, उनके मामले पर गौर करना होगा और उन ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में छोटे उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सहायता देनी होगी। इस प्रकार अनेक सफल केन्द्र बनाने होंगे, ताकि वे और अधिक विस्तृत विकास के लिए केन्द्र या भादर्श का काम दे सकें। विशेषकर माल की विविध रूप में तैयार करने वाले उद्योग छोटे पैमाने पर और सहकारी समितियों द्वारा अधिकतम सीमा तक खोले जाने चाहिए। जहाँ बिजली तथा अन्य मूल सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ ग्रामीण कारीगरों को सहकारी समितियों में संगठित करने में मदद करनी चाहिए।

छोटे उद्योगों का सहायक उद्योगों के रूप में विकास—

बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में छोटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के विभिन्न उपायों पर एक विशेष समिति विचार कर रही है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े कारखानों और छोटे-छोटे कारखानों का पारस्परिक सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव है। उद्योग के हर पटलू में समाज की आवश्यकताओं का विस्तृत दृष्टिकोण लेना आवश्यक है जिससे पता चल सके कि बड़े और छोटे उद्योग क्या योगदान कर सकते हैं और उत्पादन का विभिन्न चरणों में किस प्रकार विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। ऐसे समन्वित विकास की दृष्टि से अनेक उद्योगों का अध्ययन किया जा रहा है।

औद्योगिक सहकारी संस्थाएँ—

तीसरी योजना में वर्तमान सहकारी संस्थाओं के संगठन और पूँजी को मजबूत बनाने और अधिकाधिक कारीगरों को उनमें भर्ती करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए जिन प्रमुख उपायों का प्रस्ताव है, वे हैं कुछ समय तक प्रबन्धकीय और निरीक्षक कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था और प्रारम्भिक समितियों से केन्द्रीय सहकारी वित्तीय एजेंसी जो शुरू से, उसने लिए सरकारी सहायता देना। जिन छोटे उद्योगों में एक या कुछ छोड़े मालिक लोग हों, वहाँ संगठनों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए।

समन्वय के लिए प्रबन्ध—

इन कार्यक्रमों को जो विभिन्न मण्डल और एजेंसियाँ विशेष तौर पर क्षेत्रों में चलाएंगी, उनके काम में सामञ्जस्य लाने के उपायों की बड़ी आवश्यकता है। गांधी ने खेती, बिजली, परिवहन आदि का विकास हो जाने से यह आवश्यक हो जाएगा कि प्राणीय औद्योगीकरण की समस्या पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो वर्तमान मण्डल आदि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र अपने विशेष उद्योग तक ही सीमित है। इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों और विभिन्न मण्डलों के साथ मिल कर आगे विचार करने का प्रस्ताव है।

व्यय और व्यय-परिमाण—

तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए २६४ करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। दूसरी योजना में इन पर १८० करोड़ रुपये से कुछ कम व्यय होने का अनुमान है। यह राशि विभिन्न उद्योगों पर निम्नलिखित रूप में व्यय की जायगी :—

(करोड़ रुपये में)

उद्योग	दूसरी योजना (अनुमित व्यय)	तीसरी योजना (व्यय)		
		राज्य और केन्द्रीय प्रदेश	केन्द्र	योग
हथकरघा उद्योग क्षेत्र	२६७	३१०	३०	३४०
हथकरघा क्षेत्र में बिजली के करघे	२०	—	४० ३७०	४०
खादी—पारस्परिक ग्रन्थर ग्रामोद्योग	८२४	३४	३२० २००	६९४

रेशम उद्योग	३१	५५	१५	७०
नारियल रेशा उद्योग	२०	२४	०८	३२
दस्तकारी	४८	६१	२५	८६
सधु उद्योग	४४४	६२६	२२०	८४६
औद्योगिक वस्तियाँ	११६	३०२	—	३०१
योग	१८०.०*	१४१२	१२२८	२६४०

ऊपरलिखित व्यय के अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भी इन उद्योगों के विकास के लिए २० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा विस्थापितों के पुनर्वास कार्यक्रम और समाज कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों में भी इन उद्योगों के लिए कुछ व्यवस्था है। निजी तौर पर जिनमें बैंक भी शामिल हैं लगभग २७५ करोड़ रुपये इन उद्योगों में लगाए जाने का अनुमान है। हर कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि भवन निर्माण और ऊपरी खर्चों को न्यूनतम रखा जाय।

विकास के कार्यक्रम

हथकरघा और बिजली करघा उद्योग—

हथकरघों पर बुनने वाले जुलाहों को पहले से अधिक काम देकर, उन्हें बेयर पूँजी के लिए ऋण देकर और सुधरे हुए तरीकों को प्रचलित किया जाएगा और साथ-साथ बिक्री छूट इत्यादि के महत्व को कम करके अन्य प्रकार की, उद्योग को हट बनाने वाली, सहायता देकर कमजोर सहकारी समितियों को बड़ा और सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। हथकरघे के कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के भी उपाय किए जाएंगे। सहकारी समितियों में शामिल हथकरघा जुलाहों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगले कुछ वर्षों में नी-मादे नी हजार बिजली करघे लगाने का प्रस्ताव है। सन् १९६५-६६ में कपड़े के कुल उत्पादन का लक्ष्य ९३० करोड़ गज है। उसमें से हथकरघा, बिजली करघा और खादी उद्योग का हिस्सा ३५० करोड़ गज रखा गया है। लेकिन इन उद्योगों में अलग-अलग कितना-कितना उत्पादन होगा इसका निश्चय अभी नहीं किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में हुई उन्नति को देखकर समय-समय पर स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।

पारस्परिक और अम्बर खादी—

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सघन क्षेत्रों या ग्राम इकाइयों के रूप में ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम बनाया है उसी के अनुसार तीसरी योजना में खादी के विकास का कार्य चलेगा। इस कार्यक्रम में ३ हजार ग्राम इकाई खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें से हरेक में एक या एक से अधिक गाँव होंगे, जिनकी जन-संख्या लगभग :

सहस्रत और गैर सहस्रत वाली रेशम का उत्पादन सन् १९६० में ३६ लाख पौंड से बढ़कर सन् १९६५-६६ में ५० लाख पौण्ड होने की आशा है ।

नारियल रेशा उद्योग—

तीसरी योजना में इस उद्योग के माल का निर्यात बढ़ाने और उसमें सहकारी संस्थाओं को हद आधार पर सङ्गठित करने पर जोर दिया जाएगा । नारियल रेशे को काटने वालों को मशीनें दी जाएँगी, ताकि काम की किस्म बढ़िया हो सके । इसके साथ ही प्रारम्भिक सहकारी समितियों के कार्यकलाप पर और अधिक देख-रेख रखी जाएगी । इस उद्योग के उत्पादकों और निर्यात करने वालों की सहायता के लिए एक विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाई गई है । इस कार्यक्रम में उत्पादन की नई प्रणालियों को प्रोत्साहन देना नारियल के सार भाग तथा रेशों में से बचे हुए हिस्सों को उपयोग में लाना इसके अन्तर्गत है । गद्दों तथा ब्रश रेशों के कार्य को भी बढ़ाया जाएगा ।

दस्तकारियाँ—

अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल ने १२ चुनी हुई दस्तकारियों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये हैं । पिछले वर्षों में जो विकास कार्य हुआ है उससे विभिन्न दस्तकारियों की मुख्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई । तीसरी योजना में इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कदम उठाये जाएँगे । विकास अधिकतर सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन कुछ छोटे उपक्रमों के सध बनाने का भी प्रस्ताव है, ताकि किस्म पर नियन्त्रण किया जा सके और कारीगरों की दशा में सुधार हो तथा व्यावसायिक स्तर में भी सुधार हो । निर्यात को प्रोत्साहन देने के साथ ही दस्तकारियों के उत्पादन का इस तरह नए ढङ्ग से सङ्गठन करना होगा ताकि देश के विभिन्न भाग-वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही सामान तैयार किया जा सके और ग्रामीण दस्तकारियों का भी विकास हो । तीसरी योजना के अन्तर्गत ये काम भी होंगे : बाहर भेजे जाने से पहले वस्तुओं का निरीक्षण तथा निर्यात करने वालों की ऋण सुविधा, डिजाइन तैयार करने के केन्द्र, अन्तराज्य व्यापार को प्रोत्साहन, कुछ दस्तकारियों में प्रशिक्षण सुविधाएँ, बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान और विक्रय भण्डारों के प्रबंध और बिक्री सम्बन्धी प्रशिक्षण ।

लघु उद्योग—

दूसरी योजना में प्राविधिक परामर्श देने, उधारवित्त और प्रशिक्षण सुविधाएँ, मशीनें देने, बिक्री की व्यवस्था और कच्चे माल की उपलब्धि आदि की व्यवस्था के जो कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे उन्हें तीसरी योजना के बड़े कामों को देखते हुए और अधिक बढ़ाया जाएगा । उत्पादन में वृद्धि और उसके विकेन्द्रीकरण के साथ ही तीसरी योजना के कार्यक्रमों का एक लक्ष्य यह भी रहेगा कि अधिक से अधिक उद्योगों के छोटे और बड़े कारखानों में समन्वय रहे । छोटे कारखाने बड़ों के रूप में बड़े और छोटे उद्योग छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलें तथा उन्हें चलाने वाली सहकारी

समितियों और नए उद्योगपतियों और उपक्रमों को और अधिक सुविधाएँ मिलें। विकास का एक महत्वपूर्ण अङ्ग यह भी है कि कारखाने की क्षमता का पूरा फायदा उठाया जाए, इसके लिए एक से अधिक पालियाँ शुरू की जाएँ और आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध किया जाए। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों की भाँति भी अधिक-तर छोटे उद्योगों से ही पूरी करने की नीति और कड़े ढङ्ग से लागू की जाए। राज्यों के साथ ही केन्द्र में स्टोर की अन्य सम्बन्धी नीतियों तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को और भी विस्तृत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। अन्य विकास कार्यक्रमों में ये हैं : राज्य सरकारों द्वारा मुश्किल से मिलने वाले कच्चे माल के भण्डार स्थापित करना, औद्योगिक बस्तियाँ बनाने, कच्चे माल के भण्डारों का संचालन करने और सर्व सेवा सुविधा क्षेत्र चलाने के लिए लघु उद्योग निगमों को स्थापित करना।

औद्योगिक बस्तियाँ—

तीसरी योजना में लगभग ३०० नई विभिन्न प्रकार की औद्योगिक बस्तियाँ खोलने का विचार है। ये मध्यमवर्ग छोटे और मझोले कस्बों के समीप बसाई जाएँगी। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सकती हैं वहाँ भी अनेक औद्योगिक बस्तियाँ खोलने का विचार है। बड़े शहरी और विकसित कस्बों के पास छोटे उद्योगपतियों को कारखाने बनाने के लिए केवल विकसित स्थान देने का भी प्रयत्न है। छोटे उद्योगों को सहायक के रूप में विकसित करने के लिए यह सुझाव है कि बड़े उद्योगों के पास-पास उनके सहायक के रूप में बन सके वाली एक ही प्रकार के लघु उद्योगों की बस्तियाँ खोली जाएँ। नई बस्तियाँ खोलते समय भवन निर्माण आदि कामों में कम से कम खर्च करने के अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर पूरा प्रयत्न करना आवश्यक होगा।

रोजगार—

तीसरी योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ऊपर लिखित कार्यक्रमों को अपना लगाया जाएगा, यानि है उससे ८० लाख लोगों को मासिक या पहले अधिक रोजगार और लगभग ६ लाख लोगों का पूरा रोजगार मिलेगा।

निर्यात—

नारियल रेशे का सामान, हथकरघे का कपड़ा और इस्करियों का सामान लगभग प्रतिवर्ष २६ करोड़ रुपये का निर्यात होता है। लघु उद्योगों का भी कुछ निर्यात होने लगा है। लघु उद्योगों के माल की किस्म बढ़िया करके, कीमत घट और नए डिजाइन आदि बनाकर उनके और अधिक माल को बाहर भेजना होगा।

किसी कार्यक्रम का क्या प्रभाव होगा, इसको माँकने के लिए देश भर के अत्यन्त आवश्यक होते हैं, लेकिन लघु उद्योगों सम्बन्धी पूरे आँकड़े अभी उपलब्ध हैं। सन् १९६१ की जनगणना से उम्मीद है कि औद्योगिक इकाइयों की एक पूरे तालिका मिल जाए। उसको बाँचा मानकर जो कारखाने दस या उससे अधिक क

रखने हैं या जिनकी पूँजी ५ लाख से अधिक है उन सबका छमाही सर्वेक्षण करने का एक प्रस्ताव है।

लघु उद्योगों के प्रोत्साहन में सरकार का योग

(जापानी प्रतिनिधि मंडल द्वारा विकास के लिए अनेक सुझाव)

देश में छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो विभिन्न कदम उठाए हैं, उनमें लघु उद्योगों सम्बन्धी जापानी प्रतिनिधि मण्डल बहुत ही प्रभावित हुआ है। उसका कहना है कि इन कदमों की जापान में किए गए उपायों से भली प्रकार तुलना की जा सकती है। भारत की अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान चरण में, हाल में उठाए गए ये कदम सर्वथा स्वाभाविक ही हैं। लेकिन प्रतिनिधि मंडल का यह भी कहना है कि "देश के सभी भागों में इन उपायों का प्रभाव फैलना तथा वांछित उद्देश्य प्राप्त करना अभी शेष है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य वित्त निगम तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया जैसी संस्थाओं ने इस दिशा में काम की शुरुआत ही की है। लघु उद्योग सेवा संस्थाओं जैसे संगठन भी जो इस काम के लिए अपेक्षाकृत अधिक ठीक हैं, अभी इसी तरह की स्थिति में हैं।"

सरकारी संरक्षण एवं पोषण—

जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आगे कहा है कि सरकारी कार्यक्रम पर सामान्य रूप से दृष्टिपात करने में हमें यह पता लगा कि सरकार द्वारा किये जा रहे कुछ उपाय, लघु उद्योगों का आवश्यकता से अधिक संरक्षण तथा पोषण करते हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि उनकी उद्यम की भावना को खुल कर प्रयोग होने का अवसर नहीं मिल सकेगा। उदाहरण के तौर पर सहकारी समितियों को अत्यधिक उदारतापूर्ण संरक्षण दिया जाता है। कुछ राज्य तो आदर्श केन्द्र जैसी संस्थाएँ तक स्थापित कर रहे हैं, इससे तो यह भय है कि गैर सरकारी उद्योगों की स्थापना या वृद्धि में बाधा पड़ेगी। पश्चिमी बंगाल में सिरीमिक इन्स्टीट्यूट आफ सेन्ट्रल इन्जीनियरिंग इसका एक उदाहरण है।

"प्रत्येक उद्योगपति की उद्यमशीलता की भावना लघु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक शर्त है, इसलिए सरकारी कार्यक्रम ऐसे ढंग से बनाया जाना चाहिए कि उन्ने सरकार या अन्य लोगों पर निर्भरता बढ़ाने तथा स्वतन्त्रता एवं स्वावलंबन की भावना पैदा करने की ओर प्रवृत्त किया जा सके। अतएव राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि के साथ-साथ सरकारी उपायों का मूल उद्देश्य संरक्षण एवं पोषण से हटकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन होते जाना चाहिए।

प्रतिनिधि मंडल ने लघु उद्योगों को विजली की अधिकाधिक व्यवस्था करने तथा औद्योगिक वस्तुओं की स्थापना पर अधिक धन दिया है। वह यह अनुभव करता है कि कम दर पर ब्याज आदि के रूप में मूल्य विभेदक आर्थिक सहायता देना कार्य-कुशलता, उद्यमशीलता तथा आबिष्कारिणी प्रतिभा आदि की दृष्टि से दीर्घकाल में लाभप्रद न होगा। उसने यह विचार भी प्रकट किया है कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय अर्थतन्त्र

का विकास होगा, वैसे-वैसे भारत में इस समय विद्यमान अधिकांश श्रम-प्रधान उद्योगों में धीरे-धीरे मशीनें आते जाना निश्चित है और इस प्रकार वे आधुनिकीकरण का रास्ता अपनायेंगे ।

औद्योगिक बस्तियाँ—

लघु उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में औद्योगिक बस्तियाँ जो योग दे रही हैं, उसकी जापानी प्रतिनिधिमंडल ने प्रशंसा की है । लघु उद्योगों को बढावा देने की यह प्रद्वितीय प्रणाली है, जो शायद ही किसी अन्य देश में चल रही हो । उसने यह सुझाव दिया है कि औद्योगिक बस्तियों की सख्या और बढायी जाय और देश भर में उन्हें फैला दिया जाय । ये बस्तियाँ उन इलाकों में खास तौर से स्थापित की जाएँ जहाँ कच्चे मालों और बाजार की स्थितियों की दृष्टि से औद्योगिक विकास की उत्कृष्ट संभावनाएँ हों और जहाँ शारीरिक श्रम प्रधान धन्धों के आधुनिकीकरण की सख्त आवश्यकता हो । औद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम बढाने के लिए इस प्रतिनिधिमंडल ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे किसी गैर सरकारी उद्योगों अथवा सहकारी समितियों की इन प्रयोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दें । ये प्रोत्साहन आर्थिक सहायता देकर या अन्य उपयुक्त उपायों के द्वारा दिए जा सकते हैं ।

प्रतिनिधिमंडल की अन्य सिफारिशों में से कुछ ये हैं—जिन क्षेत्रों में विद्युत शक्ति सुलभ नहीं है, वहाँ डीजल शक्ति की व्यवस्था की जाए, एक औद्योगिक बस्ती में अनेक प्रकार के कारखानों का मिश्रण बचाया जाए, औद्योगिक बस्तियों के किराएदारों से धीरे-धीरे किराया बढाया जाए और कारखानों की जगह को आसान किशतों पर बेचा जाय ।

उद्योगों के अनुसार लघु उद्योग सहकारी समितियाँ बनाने के महत्त्व पर प्रतिनिधिमंडल ने जोर दिया है । लघु उद्योगों की परिभाषा में आने वाले लघु उद्योग, मालिक तथा कर्मचारी इन नयी सहकारी समितियों के सदस्य होंगे । ये सहकारी समितियाँ कच्चे माल की सम्मिलित खरीद, सम्मिलित बिक्री, भंडारण, माल की दुलाई तथा तैयार माल की उत्कृष्टता के परीक्षण मिल-जुल कर करावेंगी । सहकारी समितियों की छोटी से छोटी इकाई जिले से कम होगी और बड़ी से बड़ी इकाई राज्य भर के लिए शीर्षस्थ सहकारी समिति या छोटी सहकारी समितियों का सच होगा । यह भी सुझाव दिया गया है कि हर राज्य में प्रत्येक उद्योग के लिए व्यापारिक संघ हों, जिनके मुख्य कामों में सामान्य हित की बातें जैसे निमित्त होने वाली वस्तुओं के बारे में शोध, टैक्नीकल जानकारी जमा करके सदस्यों में वितरण, व्यवसाय-प्रबन्ध में मार्ग दर्शन, जन सम्पर्क कार्य एवं सरकार से सम्पर्क रखना भी होगा ।

वित्तीय सहायता—

वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में इस प्रतिनिधि दल ने यह मत व्यक्त किया कि

भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बाद भी सरकारी वित्तीय संस्थाएँ एवं गैर सरकारी बैंक अब भी सतकतापूर्ण एवं अनुदार नीति अपना रहे हैं। लघु उद्योगों की अनुभव होने वाली दिक्कतों दूर करने के लिए प्रतिनिधि मण्डल ने निम्न उपाय सुझाये हैं —

- (क) ऋण गारंटी योजना अपनाना, जिसके अधीन प्रत्येक राज्यीय वित्त निगम के अंतर्गत एक ऋण गारंटी निधि स्थापित की जाए, जिससे वित्त संस्थानों द्वारा छोटे कारखानों का दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी दी जा सके।
- (ख) एक ऋण बीमा योजना लागू करना, जिसके अनुसार मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त धन से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में एक ऋण बीमा निधि स्थापित की जाए। इस योजना के अनुसार ऋण बीमा योजना का एकमात्र बीमा कर्ता ऋण गारंटी फंड होगा और योजना तभी प्रभाव में आ सकेगी जब ऋण गारंटी फंड कर्जदार लघु उद्योग की तरफ से धन भुका कर चुका हो और कर्जदार से धन न ले सका हो।
- (ग) प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारिता बैंक या शीर्षस्थ सहकारिता बैंक स्थापित की जाए, जो छोटे पैमाने की औद्योगिक सहकारिता समितियों का ऋण दिया करे।
- (घ) सरकारी ऋण राज्यों के वित्त निगमों की माफ़त दिए जाएँ और
- (ङ) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं का राज्यों के वित्त निगमों के एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाए।

प्रतिनिधि मण्डल ने यह सिफारिश भी की है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाय तथा उसका संगठन भी बढ़ाया जाए। उसने हर राज्य में लघु उद्योग निगम स्थापित करने का भी सुझाव दिया है, जो देश में निर्मित मशीनें किराया-खरीद प्रणाली के अधीन दिलाएँगे, राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगों में बने माल की खरीद कराएँगे और लघु उद्योगों के लाभार्थ कच्चे माल के डिपो बसाएँगे। किराया खरीद प्रणाली के नियमों को खूब सुलभ बनाने, कुछ सरकारी विभागों द्वारा केवल लघु उद्योगों से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़वाने और इस तरह की खरीद अन्य विभागों जैसे—रेला, प्रतिरक्षा, छापाखाना आदि तक बढ़वाने की भी सिफारिश की गयी है।

शैल्पिक सुविधाएँ—

शैल्पिक सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल ने यह पाया है कि सरकार लघु उद्योगों का शैल्पिक स्तर ऊँचा करने की दृष्टि से तरह-तरह की सुविधाएँ दे रही है। किन्तु उसके विचार से इनमें से कुछ सुविधाओं के प्रबन्ध में कुछ सुधार किये जाने चाहिए। वर्तमान सुविधाओं के पूरक के रूप में कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की

व्यवस्था की जानी वांछनीय है। प्रतिनिधिमण्डल का विचार है कि यदि ये अतिरिक्त सुविधाएँ और दी जा सकी तो वर्तमान सुविधाओं को और भी अधिक लाभ हो सकेगा। उसने सिफारिश की है कि लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा विस्तार केन्द्रों में अधिकाधिक मशीनें तथा औजार आने चाहिए तथा बढ़िया इन्जीनियर रखे जाने चाहिए। गवेष्टणा प्रयोगशाला तथा परीक्षण की सुविधाओं पर विशेष रूप से बल दिया गया है और अधिक सेवा-संस्थान खासकर हर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में एक-एक संस्थान स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।

प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी सुझाव दिया है कि शैल्पिक ज्ञान के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। उसने अनुरोध किया है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में शिक्षित कर्मचारियों को रखना चाहिए, जिससे वे उन्नत शैल्पिक ज्ञान हासिल कर सकें।

विदेशी विशेषज्ञ--

प्रतिनिधिमण्डल ने इस बात की वकालत की है कि उपयुक्त मामलों में विदेशी विशेषज्ञों को भारत में काम करने के लिये आमन्त्रित किया जाए और भारतीय शिल्पज्ञों को विदेश भेजा जाए, लेकिन यह दोनों काम उचित रूप से योजना बनाकर किए जाएँ, ताकि इनका अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। प्रत्येक राज्य में एक टैक्नीकल समिति स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है, जो स्थानीय प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण करे और उनके विकास तथा उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन करे। उसने प्रत्येक लघु उद्योग सेवा संस्थान में व्यावसायिक शैल्पिक समिति स्थापित करने का भी सुझाव दिया है, जो व्यवसाय सम्बन्धी शैल्पिक समस्याओं को बराबर निबटाती रहे।

सहायक उद्योग

जापानी विशेषज्ञों ने सहायक उद्योगों के विकास के बारे में भी सुझाव दिये हैं, जैसे राष्ट्रव्यापी आधार पर समान पुर्जें, सहायक सामान तथा कच्चे मालों का औद्योगिक मानदण्ड स्थापित किया जाय, सरकारी क्षेत्र के नये कारखानों से कहा जाय कि वे अपनी आवश्यकता के हिस्से तथा सहायक सामान लघु उद्योगों से ही खरीदे; राज्य सरकारें एवं लघु उद्योग सेवा-शालाएँ इन सहयोगी कारखानों का प्रत्यक्ष शैल्पिक मार्ग दर्शन करें; सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के वर्तमान बड़े कारखानों का सहयोग कुशल सहायक कारखाने स्थापित करने में प्राप्त किया जाय और औद्योगिक बस्तियों में कारखानों को स्थान देने में सहयोगी लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए।

लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि लघु उद्योगों को पहले देश के बाजार पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए और उन्हें अपना माल तभी निर्यात करना चाहिए जब माल की किस्म में उत्कृष्टता हासिल हो चुकी हो और उनके माल का मूल्य प्रति-

योगितापूर्ण हो। उसका महत्ता है कि हथकरघो तथा दस्तकारियों की चीजों का निर्यात करने की अच्छी गुंजाइश है। उसने कहा है कि विदेशी बाजारों में जन-सम्पर्क कार्य तथा बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी गतिविधियाँ उसी प्रकार चलानी चाहिए जिस प्रकार 'जापानी निर्यात व्यापार पुनः प्राप्ति संगठन' चलाता है।

औद्योगिक आँकड़े—

प्रतिनिधिमण्डल ने सभी उद्योगों से सम्बन्धित पूरे आँकड़े रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उसने सिफारिश की है कि आयोजन की दृष्टि से एक सकलन की संस्था का पूर्णतः पुनर्गठन किया जाय और औद्योगिक एक सकलन निदेशालय वारिण्ड तथा उद्योग मन्त्रालय में स्थापित किया जाए।

प्रतिनिधिमण्डल ने यह सुझाव दिया है कि इण्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट को चाहिए कि वह योजना निर्माण तथा एक सकलन सम्बन्धी सर्वेक्षणों को तालिकाबद्ध करने में सहायता दे तथा व्यवसायी एवं नोर्सिस्त्रिये प्रकशास्त्रियों को प्रशिक्षण दे।

उत्कृष्टता-मानदण्ड—

सद्यः उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के उत्कृष्टता सम्बन्धी मानदण्ड बनाये रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रतिनिधिमण्डल ने सिफारिश की है कि जहाँ तक सम्भव हो, भारतीय मानक संस्था के प्रतिमान अपनाये जाएँ। सद्यः उद्योग सेवा संस्थान सद्यः उद्योगों को ठीक-ठीक कच्चा माल, परिचासक नियंत्रण, प्रक्रिया नियंत्रण तथा अन्य मानदण्ड सम्बन्धी सलाह दें, जिससे अपेक्षित मानदण्ड हासिल किये जा सकें।

STANDARD QUESTIONS

1. What steps have been taken by the Government of India to encourage our cottage and small scale industries?
2. Discuss carefully the Indian Cottage Industries under (a) First Five year Plan and (b) Second Five-year Plan.
3. Comment upon the suggestions of the Japanese Delegation for the development of Indian Cottage Industries.

अध्याय ६०

अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन मण्डल, कर्वे-समिति की रिपोर्ट आदि

(International Planning Team, Karve Committee Report, Etc.)

(१) अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन मण्डल

प्रारम्भिक—

सन् १९५३ में फोर्ड फाउण्डेशन (Ford Foundation) की सहायता से भारत सरकार ने लघु उद्योगों की उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं एवं उनको रोजगार प्रदान करने की क्षमता के अध्ययन के लिये विदेशी विशेषज्ञों के एक दल को आमन्त्रित किया था। इस अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन मण्डल (International Planning Team) ने देश के समस्त लघु उद्योगों का सर्वेक्षण किया। इस मण्डल की रिपोर्ट सन् १९५४ में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया था कि भारत में लघु उद्योगों की घनी प्रगति का प्रधान कारण कुटिपूर्ण उत्पादन और प्रच-व है। इन उद्योगों के विकास की शिथिलता का मुख्य कारण निजी क्षेत्र में आवश्यक प्रेरणा का अभाव है। इसके अनिर्दिष्ट मण्डन ने यह भी बतलाया कि राजकीय सहायता एवं सरकारी खरीद पर अत्यधिक निर्भरता, उत्पादन की रूढ़िवादी रीतियाँ, विपणन की असुविधाएँ, साज व बैंकिंग की समुचित सुविधाओं का अभाव, आयोजन का अभाव आदि भी इनके लिये कम उत्तरदायी नहीं हैं। "युक्तिकरण एवं प्राधुनिकीकरण की प्रक्रिया को रोकना, केवल तर्कहीन ही नहीं है, वरन् इससे भारतीय लघु उद्योगों में गतिहीनता तथा प्रतिगमिता की आश्रय देना होगा।"^१ अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन मण्डल की समिति में स्थायी औद्योगिक विकास के हेतु निजी प्रेरणा एवं पूँजी को अत्यधिक प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है।

* "To prevent rationalization to stop the process of modernization is not only illogical. it will force stagnation and retrogression of Indian small industries."

—International Planning Team.

सुझाव—

भारतीय लघु उद्योगों के विकास के लिये आयोजन मण्डल ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये :—

(१) देश के विभिन्न भागों में चार बहु उद्देशीय औद्योगिक संस्थायें (Multi-purpose Institutes of Technology) खोली जायें। यह संस्थायें छोटे-छोटे उद्योगों की व्यावसायिक प्रबन्ध, वित्त तथा विक्रय सम्बन्धी परामर्श दिया करेंगी।

(२) नमूना सम्बन्धी एक राष्ट्रीय विद्यालय (National School of Design) की स्थापना की जाय।

(३) लघु उद्योगों की बनायी हुई वस्तुओं की समुचित विक्रय व्यवस्था के हेतु एक विक्रय सेवा निगम (Marketing Service Corporation) की स्थापना की जाय।

(४) एक लघु उद्योग निगम (Small Scale Industries Corporation) की स्थापना की जाय।

(५) उत्पादन एवं प्रशिक्षण के लिए एक कारखाना और प्राथमिक विकास के लिए प्रदर्शनार्थ छोटे-छोटे केन्द्रों की स्थापना की जाय।

(६) दो निर्यात-विकास कार्यालय (Export Promotion Offices) एक उत्तरी अफ्रीका में तथा दूसरा योरोप में खोले जाएँ।

राजकीय कार्यवाही—

भारत सरकार ने ऊपर की सभी सिफारिशों में से चार बहु उद्देशीय औद्योगिक संस्थाएँ, एक विक्रय सेवा निगम तथा एक लघु उद्योग निगम सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सभी संस्थाओं की स्थापना भी की जा चुकी है एवं ये बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

(२) कर्वे समिति की रिपोर्ट**प्रारम्भिक—**

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना प्रारम्भ करने के पूर्व कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करके उसके समाधान के हेतु व विकास की एक योजना प्रस्तुत करने के लिये योजना आयोग ने प्रो० डी० जी० कर्वे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति को 'ग्राम एवं लघु उद्योग' (द्वितीय पंच-वर्षीय योजना) समिति (Village and Small-Scale Committee) कहते हैं। इस समिति से उद्योग-क्रम और जहाँ भी सम्भव हो राज्य क्रम में एक ऐसी योजना बनाने को कहा गया जो कि पूर्ण रूप से द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ग्रामीण एवं लघु-उद्योगों के विकास के साधनों में प्रयुक्त की जा सके।

उद्देश्य—

कर्वे समिति ने अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों को अपने सामने रखा था :—

- (१) द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में जहाँ तक हो सके, प्रौद्योगिक बेरोजगारी (Technological Unemployment) को दूर करना, विशेषकर परम्परागत कुटीर उद्योगों में ।
- (२) द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न ग्रामीण एवं लघु-उद्योगों के माध्यम से अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देना, और
- (३) विकेंद्रित समाज के ढाँचे पर तीव्र गति से आर्थिक उन्नति के लिए आधार का निर्माण करना ।

ग्राम एवं लघु उद्योग अथवा कर्वे कमेटी के अनुसार भारत में कुटीर एवं लघु-उद्योगों की बहुत दिनों से उपेक्षा होती आ रही है । यद्यपि प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में इन उद्योगों के विकास के लिये प्रयत्न किए गए, परन्तु उन्हें अधिक सन्तोषजनक या पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । प्रथम योजनावधि में इनके विकास के लिये ६ विविष्ट मण्डलों की स्थापना की गई थी तथा केन्द्र द्वारा इनके विकास के लिए ३३'६ करोड़ ६० व्यय किये गये । किन्तु समिति के मतानुसार इन उद्योगों की स्थिति को देखते हुए अभी तक जो कुछ किया गया वह सागर में एक बूँद के समान था । अतः कर्वे समिति ने इस बात की जोरदार सिफारिश की कि द्वितीय योजनावधि में उन लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर पूरा जोर दिया जाय जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे सूती व ऊनी कपड़े, हाथ द्वारा कुटे हुए चावल, दलहलियाँ, तेल, गुड़, खाँडमारी, दियासलाई, कूते आदि । इनके अतिरिक्त देश में कीड़े पालना, रेशम बुनना, हस्तकरघा उद्योग, नारियल की जटा काटना तथा बुनना आदि उद्योगों के विकास पर भी समिति ने काफी जोर दिया ।

कर्वे समिति की सिफारिशें—

कर्वे समिति ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिये योजना आयोग के सम्मुख अनेक सुझाव प्रस्तुत किये, इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(१) सहकारी समितियों को प्रोत्साहन—राज्य सरकारों को चाहिए कि सहकारी समितियों को अधिक से अधिक मात्रा में वित्त एवं अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था करें, जिससे ये ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की अधिक से अधिक सहायता कर सकें । समिति के मतानुसार रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक भी इन उद्योगों को अनेक रूपों से सहायता प्रदान कर सकते हैं । समिति ने इस बात की भी सिफारिश की कि जब तक इन उद्योगों के सहायताार्थ सस्थागत रूप में ऋण की व्यवस्था न हो जाय, तब तक अखिल भारतीय प्रमंडलों, राज्य विभागों तथा राज्य वित्त निगमों को इन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करते रहना चाहिए ।

(२) बृहत् उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध—ग्रामीण एवं लघु उद्योग को विस्तार का अवसर प्रदान करने के लिए समिति ने इस बात की भी सिफारिश की कि अनुसूच बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट कर दी जाए, जिससे अधिक होने वाली माँग की पूर्ति लघु उद्योगों द्वारा निमित्त पदार्थों से ही की जाय ।

(३) लघु एवं ग्राम उद्योगों की वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य निर्धारण—सहकारिता के आधार पर संगठित लघु एवं ग्राम उद्योगों की वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कर देना चाहिये तथा इस मूल्य से कम पर बेचने में जो पाटा हो उसे राज्य द्वारा पूरा करना चाहिये ।

(४) बृहत् उद्योगों पर उत्पादन शुल्क—कबे समिति ने यह भी सुझाव दिया कि बृहत् उद्योगों पर एक विशेष प्रकार का उत्पादन शुल्क लगाया जाये, जिससे प्राप्त आय लघु एवं कुटीर उद्योगों के सहामतायं व्यय की जाय । इस प्रकार के शुल्कों के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हो सकते हैं :—

- (अ) लघु उद्योगों के विकास के लिये धन एकत्रित करना ;
- (ब) मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप बड़े उद्योगों को प्राप्त अधिक लाभ को ले लेना, और
- (स) छोटी भाषा में उत्पादन करने वालों के हित में मूल्य में अन्तर निर्दिष्ट करना ।

(५) लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के हेतु पृथक मन्त्रालय—कबे समिति ने केन्द्र में लघु एवं ग्रामीण उद्योग के लिये एक पृथक मन्त्रालय की भी स्थापना का सुझाव दिया था ।

समिति ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण उद्योगों का आधुनिकीकरण और निरन्तर विकास तभी हो सकता है, जबकि छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों का बड़े-बड़े गाँव व छोटे-छोटे कस्बों में देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाल सा बिछा दिया जाये । इनके साथ ही साथ आवश्यक सेवाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिये । उद्देश्य यह है कि समस्त औद्योगिक गतिविधियों का मूल आधार गाँव हो —“प्रगतिशील ग्राम्य अर्थ व्यवस्था के ऊपर आधारित उद्योग का पैरामिड ।” रिपोर्ट में इन उद्योगों के महत्त्व के सम्बन्ध में लिखा है कि दस्तकारी का महत्त्व अपने उत्पादन की मात्रा और मूल्य से कहीं अधिक है, क्योंकि उनसे देश की पुरातन सांस्कृतिक परम्पराओं का ज्ञान होता है और वह निर्माणात्मक तथा कलात्मक रुचि का प्रादुर्भाव है । अतः दर्शन-

कारी का विकास न केवल कुछ दस्तकारा को इनके परम्परागत धन्यो मे पुनर्स्थापित करने का एक विषय है, बरन् लोगो के परम्परागत कला को जीवित रखने तथा निर्माणात्मक सुविधाओ और वशानुगत निपुणताओ को उदार अवसर भी प्रदान करना है ।*

राजकीय कार्यवाही—

कर्वे समिति की सिफारिशो के आधार पर द्वितीय पंच-वर्षीय योजना मे कुटीर एव लघु उद्योगो के विकास के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया तथा योजना काल मे इस मद मे २६० करोड़ रुपये धन्य की सिफारिश की । परन्तु योजना आयोग ने द्वितीय योजना काल मे कुटीर एव लघु उद्योगो के पुनरुत्थान के लिये केवल २०० करोड़ रु० धन्य का आर्योजन किया ।

आलोचना—

लघु एव कुटीर उद्योगो के विकास की दिशा मे कर्वे समिति ने जो सुझाव प्रस्तुत किये वे सचमुच सराहनीय है । किन्तु फिर भी कर्वे समिति की सिफारिशो की तीव्र आलोचना की गई है । यह निश्चय है कि लघु एव ग्रामीण उद्योगो मे लगे हुए लाखो व्यक्तियों की कार्यक्षमता, आय तथा जीवन स्तर मे वृद्धि से राष्ट्रीय हित मे अवश्य वृद्धि होगी, परन्तु परम्परागत उद्योगो मे कार्य करने वाले श्रमिको को उनके घर पर ही काम देने से, (जिसकी सिफारिश समिति ने अपनी रिपोर्ट मे की है) श्रमिको की गतिशीलता न तो कमी होगी ही, साथ ही उनको कुशल प्रविधियो को अपनाने के लिये उचित प्रोत्साहन भी नही मिलेगा । कुटीर एव लघु उद्योगो के विकास के लिये भी कुशल प्रविधियो को अपनाना जरूरी हो जाता है, अन्यथा दीर्घकाल मे इन उद्योगो को कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा । कर्वे समिति ने उपभोक्ता उद्योगो की अधिकतम उत्पादन की सीमा निर्धारित करने की, सिफारिश की है, जिसका उद्देश्य प्रतिरिक्त मांग को लघु उद्योगो की ओर प्रेरित करना है । इसके प्रतिरिक्त लघु एव ग्राम उद्योगो के विकासार्थ विपणन (Marketing), आवश्यक प्रसाधनो की पूर्ति एव वित्तीय सहायता आदि के लिये सिफारिश की गई है । किन्तु प्रो० बी० के० मदन (Prof B. K Madan) के अनुसार इस प्रकार की सिफारिश, निश्चय ही अप्रयोगात्मक एव अव्यवहारिक है, क्योंकि इसको कार्यान्वित करने के लिये बहुत

* 'Handicrafts have far greater importance than is indicated by the volume or value of their production because they embody ancient cultural traditions of the country and are expression of its creative and artistic genius. Development of handicraft is therefore, not merely a matter of rehabilitating a few craftsmen in their ancestral trades but of keeping alive traditional art and giving free scope to the creative faculties and inherited skill of the people' (Para 19 of the Karve Committee Report.)

अधिक धन राशि की भी आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त बड़े उद्योगों के उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर देने से लघु उद्योगों में अकुशल प्रविधि के प्रयोग के अस्थायी बनने की आशंका है। कर्वे समिति ने लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण व वैज्ञानिकों की सिफारिश इसी शत पर की है कि इनके फलस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि न हो। परन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह पता लगता है कि यह तर्क पूर्णतया निराधार है। आधुनिकीकरण का स्वाभाविक परिणाम श्रमिकों की छूटनी होती है। इससे देश के दीर्घकालीन आर्थिक विकास को निश्चय ही आघात पहुँचेगा।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि किञ्चित् आलोचनाओं के होते हुए भी, कर्वे समिति की सिफारिशों ने कुटीर, ग्राम्य एवं लघु उद्योगों की समस्याओं को सुलझाने में अच्छा मार्ग दर्शा दिया है।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Briefly summarise the recommendations of the Karve Committee Report.
- 2 Write a note on the recommendations of International Planning Team

अध्याय ६१

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(National Small Industries Corporation)

प्रारम्भिक—

भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अन्तर्गत यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यदि हम अपने राष्ट्र का सतुलित आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो वृहत, कुटीर एवं लघु सभी प्रकार के उद्योगों की उन्नति होनी चाहिये। उद्योगों की इन तीन श्रेणियों में वृहत उद्योग सबसे अधिक शक्तिशाली है एवं प्रायः पूँजीपतियों एवं कुशल प्रबन्धकों द्वारा उनके प्रचलन के कारण इनको अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। कुटीर उद्योग अत्यन्त निम्न स्तर के होने के कारण भारत सरकार के लाडले पुत्र हो रहे हैं। अब प्रश्न है लघु उद्योगों के विकास का। देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों का कुल महत्वपूर्ण भाग नहीं है। दुर्भाग्यवश, अभी तक इनके विकास के लिए कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं किया गया। हाँ, गत कुछ वर्षों से भारत सरकार का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ है। हमारी जनप्रिय सरकार ने लघु उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए अनेक अध्ययन मण्डल आमन्त्रित किये एवं उनकी सिफारिशों के आधार पर रचनात्मक कदम भी उठाए गए। लघु उद्योगों के विकास के लिये भारत सरकार ने अभी तक जो कार्य किये हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (N. S. S. I. C.) की स्थापना है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना व उद्देश्य—

फोर्ड फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रस्ताव के अनुसार, लघु उद्योगों को विपणन एवं यन्त्र सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी सन् १९५५ में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। यह निगम भारत सरकार का निजी प्रमण्डल (Private Company) है। इस निगम के द्वारा ऐसे लघु उपक्रमों को सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें ५ लाख रु० से कम की पूँजी का विनियोग हुआ हो तथा शक्ति द्वारा प्रचलित उद्योगों में अधिक से अधिक ५० एवं बिना शक्ति द्वारा प्रचलित उद्योगों में अधिक से अधिक १०० व्यक्ति काम करते हो।

इस निगम का समामेलन भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत १० लाख

६० की अधिकृत पूँजी से किया गया। इसकी सम्पूर्ण पूँजी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। अब इसकी पूँजी को ४० लाख ६० तक करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग प्रमण्डल (Small Scale Industries Board) के निकटतम सम्पर्क में कार्य कर रहा है। यह छोटे छोटे उद्योगों को किराया खरीद प्रणाली (Hire Purchase System) के आधार पर यन्त्र प्रदान करता है। हायर परचेज की शर्तें इस प्रकार हैं—साधारण प्रकार के यन्त्रों के लिये प्रारम्भ में मूल्य का २० प्रतिशत तथा विशेष प्रकार के यन्त्रों के लिये मूल्य का ४० प्रतिशत देना पड़ता है। व्याज की दर ४४% से ५% तक होती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भविष्य में लघु उद्योगों की वस्तुओं के बिक्रय की भी व्यवस्था करेगा। यह निगम लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की प्रत्याभूति भी दे सकता है।

प्रबन्ध—

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा मनोनीत (nominated) शासकीय सदस्यों की एक संचालक परिषद द्वारा होता है। संचालकों की इस परिषद का मुख्य कार्य सामान्य नीति का निर्धारण करना एवं धन की योजनाओं पर विचार करना है। आवश्यकतानुसार शासन की आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी प्रस्ताव दिये जाते हैं। प्रबन्ध संचालक, जो कि निगम का प्रमुख अधिकारी है, अपने ४ विभागीय अध्यक्षों की सहायता से उस नीति को कार्यान्वित करता है।

निगम के विभाग—

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पाँच विभाग हैं—(१) स्टोर क्रय विभाग; (२) विपणन विभाग, (३) किराया खरीद विभाग, (४) औद्योगिक क्षेत्र विभाग; तथा (५) प्रशिक्षण एवं लेखा-जोखा विभाग।

निगम के कार्यों का स्पीरा—

प्रारम्भ में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना लघु उद्योगों को शासकीय क्रय संस्थाओं से ऑर्डर दिलवाने के लिये की गई थी। परन्तु आजकल इसका कार्य-क्षेत्र बढ गया है। यह शासकीय अनुबन्ध (Government Contracts) लेकर उनकी पूर्ति लघु उद्योगों से कराता है। यह उनको प्रत्यक्ष अनुबन्ध की प्राप्ति में भी सहायता करता है। नवम्बर सन १९५६ तक इसकी सूची में ५,१५२ ऐसे लघु उद्योग थे जिनको इसने शासकीय ऑर्डर दिलवाया।

शासकीय क्रय विभाग—

शासकीय क्रय विभाग राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यों का प्रमुख केन्द्र है। यह विभाग उन वस्तुओं की सूची तैयार करता है, जिनका निर्माण लघु उद्योगों द्वारा किया जा सकता है। इस निगम की सहायता से अभी तक लघु उद्योगों को जितनी राशि के अनुबन्ध मिले, उसका अनुमान निम्न आँकड़ों से लगाया जा सकता है—

वर्ष	अनुबन्ध की मूल्य राशि रुपये
१९५५-५६	४,६७,७५०
१९५६-५७	११,१६,३५३
१९५७-५८	६२,१४,६६४
१९५८-५९	२,२६,१२,३३७

स्टेट बैंक की सहायता से लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसकी प्रादेशिक सेवा सस्थाएँ तांत्रिक सहायता भी देती हैं।

विपणि विभाग—

लघु उद्योगों को अपने द्वारा निमित्त पदार्थों को बेचने में प्रायः घोर असुविधा का सामना करना पड़ता रहा है। उनके व्यापार चिन्हों (Trade Mark) से भी बहुत कम लोग परिचित हैं। अतएव डा० लिंकन क्लार्क के प्रस्तावानुसार एक बस वाहन (Motor Van) दिल्ली केन्द्र से प्रारम्भ किया गया। कुछ समय पश्चात्, लघु उद्योग पदार्थों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से भी ऐसे ही वाहन चलाये गये। इससे वस्तुओं के प्रचार, प्रसार, विज्ञापन एवं विपणि शोध (Market Research) में बड़ी सहायता मिलती है।

थोक-डिपो—

देश के जिन भागों में बहुत अधिक सख्या में इसी प्रकार के उद्योग होते हैं वहाँ निगम द्वारा थोक डिपो (Whole Sale Depots) खोले गये हैं। उदाहरण के लिये, अलीगढ़ में ताला भंडार, आगरा में जूता भंडार, खुर्जा में मिट्टी बरतन भंडार, बम्बई में रंग भंडार, कलकत्ता में हाँजरी वस्तु भंडार आदि थोक डिपो की स्थापना की गई। इनकी कार्य प्रगति सचमुच बड़ी उत्साहवर्द्धक है।

सहायक निगमों की स्थापना—

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के विपणि एवं अन्य सहायक कार्यों को विकेंद्रित करने के उद्देश्य से ४ सहायक निगमों की स्थापना की गई है—पूर्वी (कलकत्ता में), पश्चिमी (बम्बई में), उत्तरी (दिल्ली में), और दक्षिणी (मद्रास में)। इनकी अधिकृत पूँजी १० लाख रु० तथा निगमित पूँजी २५ लाख रु० है।

सन् १९५६ में निगम ने दिल्ली तथा देश के अन्य औद्योगिक नगरों में एक औद्योगिक डिजाइन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, जिसका नाम था—“Design To-day in America & Europe”

विपणि विभाग का निर्यात कक्ष—

विपणि विभाग का यह कक्ष (Export Section) विदेशों से व्यापार दिलवाने में सक्रिय सहायता करता है। उदाहरण के लिये रूस तथा अनेक अन्य देशों

से जूनों का व्यापार तथा न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया आदि देशों से अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आदेश प्राप्त करने में इसने लघु उद्योगों को बड़ी सहायता दी है।

औद्योगिक बस्तियाँ—

लघु उद्योगों के विकास के लिये सरकार द्वारा चालू की गई विभिन्न योजनाओं में से औद्योगिक बस्तियों की योजना सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है। बहुत से छोटे कारखानों के पास अपनी इमारतें बनाने के लिये पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं हैं और जहाँ वे धन इकट्ठा कर भी लेते हैं वहाँ पानी और शक्ति आदि की सुविधाएँ प्राप्त करने और इमारतों के लक्ष्य मजूर कराने आदि में काफी विलम्ब होता है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटे उद्योगपतियों को इस योग्य बनाने के लिये कि वे इन कठिनाइयों को दूर कर सकें और उनमें सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने देश भर में उपयुक्त डिजाइन वाले कारखानों की इमारतों सहित औद्योगिक बस्तियों का एक जाल सा बिछा दिया है। इन बस्तियों में छोटे कारखानों को अधिक संख्या में एक स्थान पर केन्द्रित कर दिया है और वे अपना उत्पादन उचित कार्य की दशाओं में कर सकते हैं। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में १२ करोड़ रुपये की कुल लागत वाली १२० से अधिक ऐसी औद्योगिक बस्तियों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और उनमें से एक तिहाई से अधिक तैयार हो चुकी हैं, जिनमें कारखाने चलाये जा रहे हैं। अन्य योजनाएँ भी विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जब सब औद्योगिक बस्तियाँ तैयार हो जायेंगी तो भाषा है कि इनमें विभिन्न प्रकार के ४,००० कारखाने चलाये जा सकेंगे, जिनसे करीब १०,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा विपणन सहायता—

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का एक प्रमुख उद्देश्य छोटे औद्योगिक कारखानों को विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करना रहा है। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश में किसी भी एक अकेले संगठन के लिये छोटे कारखानों के उत्पादनों की बिक्री व्यवस्था की जिम्मेदारी लेना न तो सम्भव ही है और न आवश्यक ही। ठीक किस्म की वस्तुएँ बनाने तथा बाजार में उनकी माँग बनाये रखने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत उद्योगपतियों की ही रहती है। परन्तु उद्योगपतियों को उनकी वस्तुओं की बिक्री में सहायता देने के लिये निगम ने कुछ सम्मर्द्धनात्मक उपाय किये हैं। निगम द्वारा चलायी गयी विपणन सहायता सम्बन्धी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना यह है कि सरकार के विभिन्न अधिकरणों द्वारा खरीदे जाने वाले माल का बड़ा भारी भाग छोटे उद्योगपतियों को उपलब्ध कराया जाय। इस देश में उपभोक्ता की वस्तुओं की सबसे बड़ी खरीदार बेल सरकार ही है और छोटे उद्योगपति सरकारी अधिकरणों द्वारा माँग किये जाने वाले विविध प्रकार के माल को तैयार कर सकते हैं। चूँकि सभी प्रकार की सरकारी खरीद प्रतिस्पर्धात्मक भावों के उद्देश्यों पर आधारित है अतः टेण्डरों के द्वारा ठेका देने की प्रक्रिया को छोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी

छोटे कारखानों द्वारा तैयार की जाने वाली लगभग २७ प्रकार की वस्तुयें छोटे कारखानों से ही सरीदे जाने के लिये रक्षित कर दी गयी हैं। छोटे बड़े दोनों प्रकार के कारखानों द्वारा बनायी जाने वाली वस्तुओं के बारे में, सम्भरण और निपटान का महा-निदेशालय बड़े उद्योगों द्वारा स्वीकृत उद्धरण के मुकाबले छोटे उद्योगों के उद्धरण १५ प्रतिशत अधिक होने पर भी उन्हीं को प्राथमिकता देता है। ऐसी वस्तुओं के विशिष्ट विवरण देने वाले टेण्डर फार्म प्रमाणित छोटे कारखानों को निशुल्क दिये जाते हैं। सरकार से आर्डर प्राप्त करने वाले छोटे कारखानों को लघु उद्योग सेवा सङ्घाओं द्वारा प्राविधिक सहाय्य और स्टेट बैंक द्वारा ऋण दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत छोटे कारखानों को स० नि० म० नि० (डी० जी० एस० एण्ड डी०) से ७ ८३ करोड़ रुपये के सविदा मिले हैं।

छोटे उद्योगों के उत्पादनों के निर्यात के लिये निगम को भी काफी आर्डर मिल रहे हैं। जूनो के आर्डर को पूरा करना इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सफलता है। पिछले कुछ वर्षों में निगम द्वारा पूरे किये गये इस प्रकार के आर्डरों का मूल्य लगभग ४० लाख ६० है।

किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर मशीनें—

छोटे कारखानों को किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर मशीनों का सम्भरण करना भी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। भावेदकों की मशीन की कीमत का २० प्रतिशत भाग बचाना के रूप में चुकाना होता है और शेष कीमत आसान किस्तों में ५-७ वर्षों में चुकायी जा सकती है। इस योजना के शुरू होने के समय से अबतक सन् १९६० तक की अवधि में लगभग १४ करोड़ के मूल्य की मशीनों के लिये प्राप्त हुये भावेदन पत्रों की संख्या ३६ ६ थी। अल्प साधन वाले छोटे औद्योगिकों के लिये यह योजना बड़ी ही लाभदायक सिद्ध हुई है।

भारत में छोटे उद्योग विभिन्न किस्म की वस्तुएँ तैयार करते हैं, जैसे, कृषि उपकरण, भवन निर्माण में काम आने वाली चीजें, वैद्युतिकले तथा उनके हिस्से, सिलाई की मशीनें तथा उनके हिस्से, खेल का सामान, साबुन, रंगलेप तथा वार्निश, फाउन्टेनपेन, बीजा-बनियानें, शल्य चिकित्सा के औजार, डीजल तथा तेज से चलने वाले इंजन, चमड़े की वस्तुयें, घरेलू वैद्युत उपकरण, वैज्ञानिक शोध का सामान तथा उपकरण, छोटी मशीन तथा मशीनी औजार आदि। आयात पर प्रतिबन्ध लग जाने से छोटे औद्योगिकों को अधिकाधिक वस्तुयें बनाने के लिये प्रोत्साहन मिला है। वे बड़े क्षेत्र के कारखानों द्वारा काम में लाये जाने वाले कई किस्म के हिस्सों और सहायक वस्तुओं को भी तैयार करते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं की सबसे अधिक उत्साहवर्द्धक बात यह है कि छोटे उद्योग इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिये अग्रसर हैं। इस बात ने सरकार को तीसरी योजना की अवधि में १०७ करोड़ रु० परिचय कराने की व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित किया है, जो कि दूसरी योजना में निर्धारित की गयी राशि से लगभग दुगुनी है।

STANDARD QUESTIONS

1. Write an essay on the National Small Scale Industries Corporation, under the following captions :—

- (a) Its Origin,
- (b) Its Objects,
- (c) Management and sub divisions.
- (d) Progress & present position.

अध्याय ६२

सूती वस्त्र मिल उद्योग

(Cotton Mill Industry)

प्रारम्भिक—

भारत का सूती वस्त्र मिल उद्योग देश के अतीत का गौरव, वर्तमान और भविष्य का सन्देह, परन्तु सदैव आशा की वस्तु रहा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, किन्तु परिमाण एवं गति की दृष्टि से इसके विकास में विशेष रूप से विगत शताब्दी का समय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। आजकल कृषि उद्योग के बाद सूती वस्त्र उद्योग ही देश के सबसे अधिक व्यक्तियों को जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग में ८० लाख अधिक लोग जुड़े हुए हैं तथा १२२ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। सन् १९६१ के प्रारम्भ में, हमारे देश में ४८३ सूती वस्त्र मिलें थी, जिनमें १३५.५ लाख स्पिन्डर तथा लगभग २ लाख लूम (जिनमें १५,००० स्वचालित लूम भी सम्मिलित हैं) जुड़े हुए थे। आज यह उद्योग ४०० करोड़ रु० की उत्पत्ति कर रहा है। सूती वस्त्र के परिमाण की ध्यान में रखते हुए यह विश्व में तीसरे दर्जे का उद्योग है और सूत उद्योग में इसका विश्व में द्वितीय स्थान है। निम्नलिखित विवरण से सूती वस्त्र मिल उद्योग का महत्व स्पष्ट हो जाता है :—

उद्योग का महत्त्व—

- (१) सूती वस्त्र मिल उद्योग देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित लगभग ७५ नगरों में फैला हुआ है।

- (ii) यह राष्ट्र का सबसे अधिक संगठित उद्योग है, जिसकी प्रदत्त पूँजी लगभग १२२ करोड़ रु० है, जो कि देश की कुल कम्पनियों में विनियोगित प्रदत्त पूँजी की १२% है ।
- (iii) देश के समस्त औद्योगिक उत्पादन का ३५% भाग केवल सूती वस्त्र मिल उद्योग से प्राप्त होता है ।
- (iv) करो व चुगी आदि के रूप में सूती वस्त्र मिल उद्योग का अशदान लगभग १०० करोड़ रु० वार्षिक है ।
- (v) कपास, जिसे प्रायः 'सफ़ेद स्वर्ण' (White Gold) की संज्ञा दी जाती है और जो इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, के उत्पादन में देश के अनेक कृषकों व व्यवसायियों को रोजगार मिला हुआ है । इसके अतिरिक्त वस्त्र मिल उद्योग (अर्थात् मिलों व कारखानों में) से भी अनेक श्रमिकों व कर्मचारियों को मजदूरी व वेतन प्राप्त होता है । मिल उद्योग में लगभग ८६ लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है । यह उद्योग मजदूरी के रूप में प्रति वर्ष करीब १०० करोड़ रु० वितरित करता है एवं प्रत्येक श्रमिक को औसतन १,६०० रु० प्रति वर्ष प्राप्त होता है ।
- (vi) गत तीन वर्षों में, भारतीय वस्त्र मिलों ने लगभग ५० लाख देशी व विदेशी गाँठों का प्रति वर्ष उपभोग किया, जिनका मूल्य २०० करोड़ रु० से भी अधिक होता है ।
- (vii) हैण्डलूम उद्योग, जो स्वयं करीब १५ लाख कारीगरों को रोजगार देता है, अपनी सूत सम्बन्धी आवश्यकताओं को मिल उद्योग से ही पूरी करता है । इसमें भी मिल उद्योग का महत्त्व स्पष्ट है ।
- (viii) भारतीय सूती वस्त्र मिलें अनुमानतः १६ करोड़ रु० वार्षिक के मूल्य का कोयला, लकड़ी, तेल व विद्युत शक्ति प्रयोग करती हैं ।
- (ix) सूती वस्त्र मिल उद्योग अनेक सहायक उद्योगों का भी भरण पोषण करता है, जिनमें विविध प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे बाँविन, स्पिण्डल्स, होल्डर्स, रीड, रासायनिक पदार्थ, पैकिंग का सामान, आदि । इन सब पदार्थों का मूल्य लगभग ४१ करोड़ रु० वार्षिक होता है ।
- (x) चाय व जूट को छोड़कर, सूत व सूती माल के निर्यात से देश को सबसे अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय प्राप्त होता है । द्वितीय योजना के अन्त तक इस साधन से हमें लगभग ३७५ करोड़ रु० का विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ ।

(X) यही एक ऐसा उद्योग है जो समष्टि व यांत्रिक उद्योगों में सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मिल उद्योग के प्रतिरिक्त (जिसमें वरीब ८६ लाख थमिक लगे हुए हैं) कपास की कृषि में, कपास, मूत व वस्त्रों में व्यापार में, यातायात सेवाओं में, जिनिंग व वेल्डिंग पॅक्टरीज में, टेलर्स आदि के रूप में अनेक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

उद्योग का अतीत एवं विकास—

हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्राचीन काल से ही उत्तम स्थिति में था। भारतीय सभ्यता के प्राचीन स्मारक मोहनजोदड़ो के भवशेषों में सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स टर्नर और ए० एन० गुलाटी के मतानुसार ये प्राप्त सूती वस्त्र रई से बनाये गये हंगे। ग्रीस के सुप्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडाटस आश्चर्य व्यक्त होकर कहते हैं कि "भारतीय एक ऐसे ऊन के वस्त्र पहनते हैं, जो भेड़-बकरियों के शरीर से प्राप्त नहीं होती, वरन् पेड़ों पर उगाई जाती है। अजन्ता की कला कृतियाँ भी इस उद्योग के गौरवपूर्ण अतीत की कहानी कहती हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग को मुस्लिम काल में बहुत गौरव प्राप्त हुआ। थो डी० एन० मुर्जी के मतानुसार मलमल का एक २० गज लम्बा तथा १ गज चौड़ा सुन्दर टुकड़ा धौंधी के बीच में सुगमतापूर्वक निवस सकता था, इस कपड़े के निर्माण में लगभग ६-७ माह लगते थे। थो टैबनियर के शब्दों में—'भारतीय मलमल इतनी महीन थी कि हाथ से वह अनुभव नहीं की जा सकती थी।'

सूती कपड़े बनाने की मिल यद्यपि भारत में सन् १८१८ में हुगली नदी के किनारे दूसरी नामक स्थान पर स्थापित की गई थी, परन्तु वास्तविक रूप में इस उद्योग की प्रगति का प्रारम्भ सन् १८१४ में उस समय हुआ जब कि एक पारसी उद्योगी थो कावस जी नाना भाई डाबर ने बाम्बे सिपनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी की स्थापना की और इसके बाद एक अग्रज उद्योगपति ने भटोच में दूसरा मिल स्थापित किया। इन दोनों कारखानों की प्राप्त सफलता के परिणामस्वरूप सन् १८७५ तक समस्त देश में ४८ वस्त्र मिलें स्थापित हुई। इन कारखानों की प्रगति से प्रभावित होकर अहमदाबाद, जोलापुर, मद्रास, बालपुर आदि नगरों में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। सन् १८७६ से १९४७ तक की प्रगति का अनुमान निम्न प्रांकों से भी लगाया जा सकता है :—

सूती वस्त्र मिल उद्योग का विकास (१८७६-१९४७)

वर्ष	मिलों की संख्या	स्पिन्डिल्स की संख्या (हजारों में)	लूमों की संख्या (हजारों में)	उत्पादन (लाख पीण्ड)	
				सूत	पीस गुद्द
१८७६-८०	५८	१४,०८	१३३	—	—
१८८१-८०	११४	२६,३५	२२१	—	—
१९०१	१७८	४८,४१	४०५	३७,३०	१७,००
१९११	२३९	६०,९५	८५८	६२५०	२६,७०
१९२१	२४६	७२,७८	१३३५	६६४०	४०,३०
१९३१	३१४	९०,७८	१७५२	८६,६०	६७,२०
१९४१	३६६	१००,२६	२००२	१५७,७०	१०६,३०
१९४७	४२३	१,०३,५४	२०३०	१२६,६०	३७६,२०

(लाख गज)

प्रथम महायुद्ध काल में उद्योग की स्थिति—

देशी सूती कपड़ा मिल की उन्नति और खासकर सन् १९१४ के बाद की प्रगति में, पूणत नहीं तो मुख्य रूप से महायुद्ध, स्वदेशी आन्दोलन एवं इस उद्योग के उत्पादन से विदेशी प्रतियोगिता की समाप्ति, आदि का योग रहा। किन्तु इस उद्योग के विकास की सर्वाधिक रूप से देश में बढ़ी हुई कपड़ की माँग ने प्रभावित किया।

प्रथम महायुद्ध काल में इस उद्योग का विशेष प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इस समय विदेशों से कपड़ का आयात बन्द हो गया और भाव ही भारतीय सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासन ने देश में ही बहुत सा सामान खरीदा। युद्धोपरांत ६ वर्ष तक यह उद्योग निर्बाध रूप से चलता रहा, किन्तु इसके बाद जापान एवं अमरीका से प्रतिस्पर्धा, युद्ध के पश्चात् माँग में कमी, हड़ताल एवं कोयले के मूल्य में वृद्धि होने से, उद्योग को भारी छति उठानी पड़ी। इस समय तक सूती वस्त्र मिलों की संख्या बढ़ कर २७१ होगई थी। इन परिस्थितियों में, जबकि उद्योग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, सरकार की माँग की गई। सन् १९२७ में स्थापित टैरिफ बोर्ड द्वारा आयात मशीनों के कर को सरक्षण दिया गया। सन् १९३० में वस्त्र उद्योग सरक्षण अधिनियम बना इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश आयात पर १५ प्रतिशत तथा अन्य देशों के आयात पर २० प्रतिशत कर लगाया गया। इस कर में सन् १९३४ में ५ प्रतिशत की वृद्धि की गई। सन् १९३४ में एक अधिनियम और पास हुआ, जिसके अनुसार सरक्षण की अवधि सन् १९४७ तक बढ़ा दी गई।

द्वितीय महायुद्ध काल में उद्योग की स्थिति—

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में सूती वस्त्र मिलें थी। युद्ध की शक्ति ध्वनि के साथ ही उद्योग को पुनः प्रोत्साहन मिला। युद्ध के कारण मूल्यो में वृद्धि हुई। साथ ही ब्रिटिश वस्त्र उद्योग युद्ध की आवश्यकताओं के उत्पादन में लग गया एवं जापान से शत्रुता होने के कारण भारत को उपभोक्ताओं एवं मित्र देशों की सेनाओं की आवश्यकता पूर्ति का एकाधिकार प्राप्त हो गया। उद्योग की स्थिति से विवक्षित होकर सरकार को कपड़े पर बण्टाल लगाना पड़ा, इसके लिए सरकार ने चार आदेश जारी किये। प्रथम आदेश Cotton Cloth and Yarn Control Order, 1943 के अनुसार कपड़े का उत्पादन, वितरण एवं कोमन पर सरकार द्वारा नियन्त्रण किया गया। दूसरे आदेश द्वारा कपड़े का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न एवं तीसरे आदेश के अनुसार कपड़े के यातायात पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न किया गया एवं चौथे आदेश का उद्देश्य कपड़े के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा अन्य साधनों के मूल्यों पर नियन्त्रण करना था। इस नियन्त्रण के प्रभाव से सन् १९४६ में उद्योग की स्थिति में प्रभाव हुआ, इत सन् १९४७ में वस्त्र-उद्योग पर से नियन्त्रण सम्बन्धी सभी आदेश हटा लिए गए। नियन्त्रण से पूर्व सन् १९४२ में कपड़े का मूल्य सन् १९३९ की अपेक्षा चार गुना बढ़ गया, साथ ही भारतीय वस्त्रों का निर्यात भी बढ़ता जा रहा था एवं देश में भी कपड़े की माँग में वृद्धि हो रही थी। किन्तु सन् १९४८ तक उद्योग की स्थिति सामान्य हो गई और इस समय तक कपड़ा मिलों की संख्या बढ़कर ४०७ होगई।

देश के विभाजन का वस्त्र-उद्योग पर प्रभाव—

१५ अगस्त सन् १९४७ को देश स्वतन्त्र होने के साथ-साथ भारत एवं पाकिस्तान, दो हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग को गहरा धक्का लगा। ७५ प्रतिशत थ्रेड कपास उत्पन्न करने वाली भूमि तथा १४ सूती घस्त्र कारखाने पाकिस्तान की हस्तांतरित किये गये। इस समय उद्योग के लिए कपास एक समस्या बन गई। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अनेक व्यापारिक समझौते होते हुए भी पाकिस्तान के दुर्व्यवहार से भारत को हानि उठानी पड़ी। अन्त में विवक्षित होकर भारत ने मिल, अफ्रीका आदि देशों से समझौते किये एवं देश में 'अधिक कपास आन्दोलन' चलाया गया, परिणामस्वरूप बल्ल उद्योग पुनः प्रगति के मार्ग पर बढ़ने लगा एवं उत्पादन में वृद्धि हुई।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सूती वस्त्र-उद्योग—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अधीन ४७० करोड़ गज कपड़ा और १६४ करोड़ पीन्ड सूत पैदा करने का लक्ष्य था और उत्पादन के ये लक्ष्य अपनी योजना की प्रवधि ३१ मार्च सन् १९५१ के समाप्त होने के बहुत पूर्व ही पूरे कर लिये गये थे। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग हेतु रखे गये एक निश्चित कार्यक्रम के अनु-

सार लक्ष्य था कि भारत पर्याप्त मात्रा में वस्त्रों का निर्यात करता रहे और देश के आन्तरिक उपभोग के लिए भी आवश्यकता से अधिक कपड़ा प्राप्त हो ।

कर्वे कानूनगो समिति की सिफारिशों के अनुसार योजना काल में हस्त करघा उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कारण वस्त्रों की सहाय में अपेक्षित वृद्धि से कम वृद्धि हुई । समिति की सिफारिशों के अनुसार हस्त-चलित एवं शक्ति-चलित करघों का उद्योग में अधिक उपयोग होना चाहिए, जिससे बेकार बैठे लोग रोजगार पर लग सकें । सरकार ने इस योजना-काल में कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए एक 'सूती वस्त्र निर्यात प्रवर्तक परिषद्' (Cotton Textile Export Promotion Council) की नियुक्ति की, जिसका कार्य वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये हर सम्भव उपाय करना था ।

द्वितीय योजना-वधि में उत्पादन—

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना-वधि में कपड़े का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष	सूत (लाख पौण्ड)	सूती कपड़ा (लाख गज)
१९५६	१६,७१२	५३,०६६
१९५७	१७,८०१	५३,१७४
१९५८	१६,८५४	४९,२७०
१९५९	१७,२२८	४९,२५४
१९६०	१७,७७१	५०,४८३
१९६१		
जनवरी	१,५५१	४,३६६
फरवरी	१,४५५	४,०८३
मार्च	१,५१३	४,३१७

द्वितीय योजना-वधि में भारत सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में अपनी नई नीति घोषित की, जिसके अनुसार मिलों द्वारा ३५*३ करोड़ गज, विद्युत चलित करघों द्वारा २०१ करोड़ गज और हस्तकरघा द्वारा १०० करोड़ गज अतिरिक्त कपड़ा बुना जाना था । सरकार की इस नीति की प्रमुख बातें निम्न हैं —

(अ) नवीन तकलियों के लायसेंस केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जायें जो उन्हें शीघ्र चालू करने का प्रबन्ध कर सक, जिससे बढ़ती हुई मांग को शीघ्र पूरा किया जा सके ।

(ब) सूती वस्त्र मिलों को १४,६०० नवीन करघा को लगाने की अनुमति

इस कारण दी गई कि उनका समस्त उत्पादन, जो लगभग ३५ करोड़ गज है, प्रति वर्ष निर्यात किया जा सके।

(स) ३५ हजार विद्युत चलित करधे महकारी समितियों द्वारा लगाये जाने की व्यवस्था की गई, और

(द) इस नीति के अन्तर्गत अम्बर-बरखो को विशेष महत्त्व दिया गया।

उपरोक्त नीति के अनुसार कुटीर एवं ग्रामोद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अम्बर बरखा एवं नई सूती मिलों के बीच के राजनैतिक भ्रतभेद भी बहुत कुछ समाप्त हो गये हैं। भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात व्यापार पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

तृतीय पंच वर्षीय योजना एवं सूती वस्त्र उद्योग—

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ६३० करोड़ गज कपड़े की आवश्यकता का अनुमान है। इसमें ८५ करोड़ गज निर्यात के लिए होगा। ६३० करोड़ गज के लक्ष्य में से ३५० करोड़ गज हस्त करघा बिजली का करघा और खादी उद्योग में बनेगा। कपड़ की मिलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तृतीय पंच-वर्षीय योजनाबधि में २५ हजार स्थापित करधे लगाये जायेंगे। मिलों में तकुमों की संख्या भी १६५ लाख कर दी जायेगी, जो कि दूसरी योजना के अन्त में १२७ लाख थी।

सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान समस्याएँ—

हमारे सूती वस्त्र-उद्योग के सम्मुख वर्तमान काल में अनेक कठिन समस्याएँ हैं, जिनका निवारण करना इस उद्योग की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। इन समस्याओं में से कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

(१) वस्त्र की मांग में सकुचन—यद्यपि कुछ समय से देश में कपड़े की मांग में बहुत अधिक कमी अनुभव की जा रही है। यहाँ यह स्मरणीय है कि कुछ समय पूर्व लोक सभा में ऐसी घोषणा की गई थी कि जनता की क्रय शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि का एक बहुत बड़ा संकेत यह है कि मिलों में कपड़े का स्टॉक घट कर औसतन २० दिन के उत्पादन के बराबर रह गया है और कुछ मिलों में तो इतना भी नहीं है। किंतु आज मिलों में इतना अधिक जमाव हो गया है कि उत्पादन स्थगित करने की बर्बाद बसने लगी है। इस समस्या के निवारणार्थ विभिन्न विधियों से मांग में वृद्धि करना नितांत आवश्यक है।

(२) करो का भार—उत्पादन करो का उपभोक्ता पर कितना अधिक भार पड़ा है, इसका सामान्य अनुमान इस बात में लगाया जा सकता है कि किसी कपड़े पर उत्पादन कर ३८/३६ प्रतिशत हो जाना है। इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन-कर लगे हुए हैं। उत्पादन-कर की वसुली के लिए कपड़े को मोटे, साधारण, महीन और अति महीन इन चार वर्गों में विभाजित किया गया है और का ११.६% से ३६% तक है। उत्पादन करो के भार का एक अन्य अनुमान इस बात से

लगाया-जा सकता है कि सरकार को इन दशा में प्रति वर्ष ७५ करोड़ रु० प्राप्त होने हैं। उत्पादन करो का यह अमहनीय भार बिचारे उपभोक्ताओं के कंधों पर ही पड़ता है।

(३) पर्याप्त कच्चे माल का अभाव—देश के विभाजन के पूर्व हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में कपास उत्पन्न होती थी। अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के बाद हम विदेशों की भी कपास का निर्यात करने में समर्थ थे, किन्तु देश के दुःखद विभाजन के परिणामस्वरूप कपास की उपज का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, फलतः हमारे देश में कच्चे माल के अभाव की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से अधिक मूल्य देकर कपास का आयात करना पड़ा। यद्यपि आर्थिक नियोजन की गन दशाब्दि में कपास के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, किन्तु फिर भी पर्याप्त मात्रा में अब अब ओणी के कच्चे माल के अभाव की समस्या आज भी विद्यमान है। इस समस्या के समाधान के लिए अच्छे निर्यात की एवं लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुमन्त्रान होना चाहिये, जिससे कच्चे माल के उत्पादन में हम आत्म निर्भर हो सकें। साथ ही वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित अव्यवस्था सस्या की स्थापना की जाय, जिनमें कच्चे माल के उत्पादन एवं मुखों में सुधार हो सके।

(४) अनार्थिक इकाइयों की समस्या—वर्तमान काल में हमारे देश में लगभग १५० मिलें ऐसी हैं जो अपने विस्तार की अपेक्षा कम उत्पादन करती हैं। इनमें से कुछ तो बन्द हो चुकी हैं, किन्तु कुछ अभी विद्यमान हैं। इनके प्रतिरिक्त अनेक मिलें ऐसी भी हैं जिनमें उत्पादन केवल सीमान्त रेखा तक होता है। पूँजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव तथा कुप्रबन्ध की समस्याएँ इसी के कारण हैं, अतः इस बात की आवश्यकता है कि इन मिलों का पुनर्संयोजन करके इनकी अवस्था में सुधार किया जाय।

(५) हस्त करघा एवं मिलों में समन्वय—भारत जैसे विशाल जन-संख्या वाले देश के लिए हस्त करघा उद्योग का महत्व निर्विवाद है। किन्तु यदि मिन उद्योग तथा करघा उद्योग में प्रतिद्विदिता रहे तो इसमें दोनों को ही हानि हो सकती है। अतः आज इस उद्योग के समक्ष यह समस्या उपस्थित है कि इन उद्योगों का किस प्रकार समन्वय किया जाय, जिससे ये दोनों प्रतिद्वन्दी न होकर एक दूसरे के पूरक हो जायें।

(६) विदेशों प्रतिस्पर्धा—विदेशों में भारतीय माल की जापान, ब्रिटेन एवं अन्य देशों के मध्य तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। भारत की वस्त्र मिलें, सरकार की वस्त्र उद्योग सम्बन्धी अनिश्चित नीति के कारण अपने निर्यात के अनुबन्ध पूरे नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही भारतीय माल की किसम एवं पैकिंग भी निर्यात की शर्तों के अनुरूप नहीं होती है, परिणामतः हमारे हाथ में निर्यात बाजार छिनते जा रहे हैं एवं विदेशों में भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति दुर्बल होती जा रही है यह वस्त्र उद्योग की सबसे गहन समस्या है, जिन पर हमारे व्यवसायियों को

तुरत ध्यान देना चाहिये । बदलती हुई माँग को ध्यान में रखते हुये विदेशी बाजारों का गहन अध्ययन ही इस समस्या का उचित हल है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्राहक की इच्छा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । यही नहीं माल की किस्म एवं उसका मूल्य भी ग्राहक को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं । जापान की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हठ स्थिति का कारण उसके द्वारा माल के गुण एवं मूल्य में प्रतियोगिता करने की शक्ति है । अतः भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता में अपना स्थान सर्वोच्च बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ भी नवीनतम साधनों को अपनाया जाये ।

(७) किस्म पर नियन्त्रण—वर्तमान युग में वस्तुओं की किस्म (Quality) पर विशेष ध्यान दिया जाता है । विदेशी बाजारों में आज प्रायः इस बात की चर्चा है कि जहाँ तक “किस्म” का सम्बन्ध है, भारतीय माल अधिक श्रेष्ठ नहीं होता । यही कारण है कि गिरी हुई किस्म का माल निर्यात करने पर, आयातक उसे वापस कर देते हैं, अतः किस्म पर नियन्त्रण करना समय की सबसे बड़ी माँग है । इस समस्या के समाधान के लिए हमें उच्चकोटि का माल निर्माण करने हेतु प्रयास करना चाहिए, उत्पादन-यन्त्रों में सुधार होना चाहिये एवं श्रमिकों की कायक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय करना चाहिये ।

(८) वस्त्र उद्योग के लिये आवश्यक यन्त्रों का निर्माण—विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा होने के कारण, वस्त्र उद्योग देश का प्राचीनतम उद्योग होते हुए भी, उद्योग के लिए आवश्यक यन्त्र सामग्री के लिए विषय १०० वर्षों से विदेशी आयात पर निर्भर था । इसके अलावा विदेशों में, विशेषकर अवमूल्यन के बाद, यन्त्र सामग्री के दाम बहुत ऊँचे हो गये हैं । अतः विदेशी विनिमय की सुरक्षा एवं आत्म-निर्भरता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हमारे देश में आवश्यक यन्त्रों का निर्माण हो, जिससे हम विदेशों पर निर्भर नहीं रहे । हमारे देश में विगत कुछ समय से वस्त्र-उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कई यन्त्र एवं उनके हिस्से बनाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । आज हमारे देश में ठकुर, सादा करधे, रिग फ्रेम इत्यादि का निर्माण पर्याप्त परिमाण में होता है, साथ ही स्वचालित करधो, ड्रा फ्रेम, पलाई फ्रेम, आदि यन्त्रों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है । बहुत शीघ्र ही यन्त्र सामग्री के अन्य कई भागों का निर्माण देश में ही प्रारम्भ किया जायगा । वस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित यन्त्रों के निर्माण के लिए नियुक्त की गई काम चलाऊ समिति द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में वस्त्र-उद्योग मशीनरी के हिस्सों के तैयार करने के सम्बन्ध में शीघ्र उठाये जाने वाले कदमों पर विचार करेगी । इस दिशा में कुछ उद्योग-पतियों द्वारा भी कदम उठाया गया है ।

(९) अभिनवीकरण की समस्या—पिछले दो महायुद्धों में अत्यधिक उत्पादन के कारण यन्त्र सामग्री बहुत घिस गई है । युद्ध का एवं उसके पश्चात् यन्त्रों के मिलने में कठिनाई होने एवं उनका अधिक मूल्य होने के कारण उन यन्त्रों को परिवर्तित नहीं किया गया, अतः इन पुरानी मशीनों में अत्यधिक टूट-फूट एवं

घिसाई हुई है। साथ ही अन्य देशों की अपेक्षा हमारा उत्पादन व्यय भी उपरोक्त कारणों से अधिक हो गया है। वर्तमान समय में इस उद्योग में लगी हुई सभी मशीनें लगभग ४० वर्ष पुरानी हैं। अतः आज इस उद्योग की महत्वपूर्ण समस्या यन्त्र सामग्री के पुनः स्थापन एवं आधुनिकीकरण की है। "समस्त उद्योग में उपयुक्त आधुनिकीकरण के बिना लागत में कमी अथवा क्वालिटी में कोई बड़ा सुधार होना सम्भव नहीं है।" सूती वस्त्र उद्योग में विश्व ने अत्यधिक प्रगति की है। भारत जो कि सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसे प्रगति के साथ चलना होगा, यह विश्व की बढ़ती प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बनाये रखने के लिए भी नितान्त आवश्यक है। आज विश्व के अन्य देशों में स्वचालित करघों का उपयोग होता है, हम पुराने यन्त्रों के प्रयोग में इस उद्योग में सूती वस्त्र के उत्पादन में गुण एवं सख्या में वृद्धि नहीं कर सकते। सूती वस्त्र मिलों में जिस तेजी के साथ पुरानी यन्त्र सामग्री के स्थान पर नवीनतम उपकरणों का प्रतिस्थापन किया जायेगा, वैसे-वैसे सूती वस्त्र के उत्पादन में गुण एवं सख्या में वृद्धि सम्भव होगी। इस समय आधुनिकीकरण की आवश्यकता केवल उद्योग की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु स्वदेश एवं विदेश की निरन्तर बदलती हुई माँग की योग्यता एवं सुविधा से पूरा करने के लिये भी आधुनिकीकरण आज की माँग है।

अभी कुछ दिन हुए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी दल ने कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण एवं अभिनवीकरण के विषय में एक रिपोर्ट दी है। हमारे देश के कपड़ा उद्योग की स्थिति की जाँच तथा उसके विकास के लिए आवश्यक सुझाव देने के वास्ते पहले भी ऐसे ही एक दल को आदेश दिया गया था और श्री ए० रामस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित उस दल ने सन् १९५२ में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। अब तक प्राप्त सकेतों से तो ऐसा ही लगता है कि वह रिपोर्ट 'बुझबुझ' में डाल दी गई। क्योंकि उसकी प्रमुख सिफारिशों पर भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ है। इनका ज़रूर हुआ है कि तब से लेकर अब तक सरकारी नेता बार-बार यह घोषणा करते रहे हैं कि भारतीय मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और अभिनवीकरण की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कहना नहीं होगा कि सन् १९५२ की उस रिपोर्ट और सन् १९६१ की इस रिपोर्ट के बीच की अवधि में भारतीय मिला की स्थिति और भी खराब हो गई है और इस तथ्य को इस नयी रिपोर्ट में जोरदार शब्दों में स्वीकार किया है। सम्भवतः सूती वस्त्र-उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है जो नवीनीकरण एवं अभिनवीकरण के लाभ से वंचित रह गया है। पिछले दो पच-वर्षीय आयोजनाओं की प्रेरणार्थ लहर इस उद्योग को आन्दोलित नहीं कर सकी। पिछले दस वर्षों में अनेक नये उद्योग खुले और पालू उद्योगों का विस्तार हुआ। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा सबसे अधिक कमाऊ "पूत" ही पिछड़ गया। मिला में प्रति व्यक्ति उत्पादन अभी ११.५० गज से अधिक नहीं है, जबकि सन् १९५६ में १४.०६ गज और सन् १९५१ में १२.५० गज था।

विद्यले दस वर्ष सम्पूर्ण सप्ताह के लिए औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। अनेक देशों ने दासता की बेड़ियाँ तोड़ी, आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, तो कई देशों में औद्योगिक और आर्थिक जाबरन का नया अध्याय आरम्भ हुआ। यह सम्भावना सन् १९५० में ही दिखाई पड़ने लगी थी कि यदि भारतीय मिलों ने अपने आपको आधुनिक तकनीक प्रगति के साथे में नहीं ढाला, तो कालान्तर में उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से निकल जाना पड़ेगा। मुद्रालयपर समिति ने भी इन तथ्यात्मक सम्भावनाओं की ओर सचेत किया था, परन्तु अभी मजदूरों की बेकारी, तो अभी विदेशी मुद्रा के प्रभाव के नाम पर अभिनवीकरण और आधुनिकीकरण का मामला टलता रहा।

मोल्दूदा रिपोर्ट में सूनी कपड़ा उद्योग की समस्या के इन्हीं पहलू पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि देशवासियों के लिए कपड़ा पर्याप्त मात्रा में और उचित ढङ्ग से पहुँचाना हमारा ध्येय है, तो कपड़ा उद्योग को इस महान उत्तरदायित्व के वहन के योग्य बनाना ही पड़ेगा। कपड़ा उद्योग को अब भी अन्य देशों की अपेक्षा सस्ती रई तो मिलती ही है, कम पैसे पर मजदूर भी उपलब्ध होते हैं, फिर भी प्रति वन उत्पादन-मात्रा में अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक बैठती है। रिपोर्ट के अनुसार ही—

“यदि समय रहते ही हमारी मिलें आधुनिक मशीनों से सज्जित नहीं की जा सकी, तो प्रागे चलकर वही सङ्कट और बेकारी की स्थिति पैदा हो जायगी जिससे अचने के लिए मजदूर इतने बित्तिय हैं। यह सर्वविदित है कि भारत में कई मिलें बहुत ही पुरानी और जाकड़ मशीनों से काम चला रही हैं। इनमें से कई सकटग्रस्त रही हैं और कई तो बिल्कुल बंद हो गई हैं, फलतः इनमें काम करने वाले मजदूर स्थायी तौर पर बेकार हो गये हैं। यदि अन्य मिलों को इस स्थिति में पहुँचने से बचाना है, तो उनका आधुनिकीकरण एक अपरिहार्य आवश्यकता है।” (जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती)।

रिपोर्ट में यह भी साफ कर दिया गया है कि आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है। आधुनिकीकरण का अभिप्राय सिर्फ यह नहीं कि पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें बैठा दी जाएं। बल्कि इसका अर्थ है ऐसी स्थिति व पद्धतियाँ का निर्माण, जिससे भारतीय मिलें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के प्रतियोगिता उत्तार-चढ़ाव तथा अन्य देशों की प्रतिप्रेषिता में न वेचल ठहर सकें, बल्कि प्रागे बढ़ जाने की भी समर्थ हो जायें।

सम्भावित व्यय—

क्या है कि यदि भारतीय मिलों का आधुनिकीकरण किया जाये, तो इस पर कोई = अरब ६० खर्च होगा, जिसके लिए देश प्रायः कई वर्षों तक तैयार नहीं हो सकता। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि आधुनिकीकरण का काम थोड़ा-थोड़ा करके शुरू किया जाये। इस पर भी कम से कम १ अरब ८० करोड़ ६० लगेगा। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि इस राशि में से कम से कम ८० करोड़ ६० की व्यवस्था स्वयं मिलों की करनी चाहिए।

अपनी वर्तमान परिस्थिति में आगामी पांच वर्षों की अवधि में मिलें ८० करोड़ ६० की अतिरिक्त राशि जुटा सकेंगी, यह सन्देहास्पद दीखता है। यह रकम कैसे जुटायी जाये, इस पर रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। फिर भी वस्तुस्थिति से तो कतराया जा नहीं सकता। जरूरत है अनुकूल वातावरण बनाने की—धीरे इसमें सरकार मत्त्वपूर्वक योगदान कर सकती है। यदि नियोजकों को यह विश्वास हो जाये कि कपड़ा उद्योग का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है, तो वे इस उद्योग में पैसा लगाने को आसानी से तैयार हो सकते हैं।

(१०) वस्त्र उद्योग की अन्य समस्याएँ—उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त हमारे सूनी वस्त्र मिल उद्योग के सम्मुख कुछ अन्य समस्याएँ भी हैं, जिनका सुलझाना अत्यन्त आवश्यक है। इनमें से विकन्दीकरण की समस्या, क्षिति की समस्या, शक्ति के साधन के अभाव की समस्या, अपर्याप्त अनुसन्धान की समस्या, विशेषज्ञों का अभाव, प्रशिक्षणों के साधन का अभाव तथा विपणन की समस्याएँ प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त धम एवं पूँजी के बीच पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास की भावना होना भी अत्यन्त आवश्यक है। धर्मिक वर्गों को सुखी एवं सन्तुष्ट रखने के लिये पर्याप्त भुजगूरी, उत्तम कार्य की दशाएँ, उचित काम के घटे तथा उनकी बेकारी दूर करना अत्यन्त आवश्यक है।

अन्य सुझाव—

वस्त्र मिल उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिये राष्‍ट्रीय योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—(अ) मशीनों की उत्पादन-शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय, (ब) वे मिलें जो घाटे पर काम कर रही हैं, उनका विस्तार करके उन्हें आर्थिक बनाया जाय, (स) ३॥ लाख नये तकिये लगाये जायें, (द) केवल श्रेष्ठ माल का निर्यात करके विदेशी बाजार में अपना स्थान बनाने का प्रयत्न किया जाय, और (प) जहाँ तक संभव हो, घाटे का निर्यात न किया जाय।

उत्पादकता अध्ययन—उद्योग की उन्नति में उत्पादकता अध्ययन का भी अत्यधिक महत्त्व है। इसलिये प्रबन्ध एवं श्रम दोनों वर्गों के हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वे अपनी अधिक शक्ति इस प्रकार के अध्ययन में लगाएँ। निश्चयात्मक रूप से ऐसे अध्ययन प्रबन्ध, श्रम एवं सारे उद्योग के लिए ही लाभप्रद होंगे।

यन्त्र सामग्री की देख-रेख—यन्त्र सामग्री की उचित देख-रेख की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, अभी तक नहीं दिया गया। मिल के उत्पादक यन्त्र को सुचारु एवं सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए, यन्त्रों के हिस्सों की बदलना, उचित निरीक्षण एवं देखभाल बहुत जरूरी है। इस कार्य में तांत्रिकों को मिल के प्रबन्धकों के साथ ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए।

लागत मूल्य में कमी एवं किस्म में सुधार—वस्त्र-उद्योग में लागत मूल्य में

कमी एवं किस्म में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि मिल-उद्योग के उत्पादन, आधुनिकीकरण एवं पुरातन यन्त्रों के स्थान पर नवीनतम यन्त्रों का प्रतिस्थापन किया जाये। इसमें गति लाने के लिए निश्चित कार्य क्रम की आवश्यकता है। उत्पादन कार्यों में दक्ष व्यक्तियों को मिल के प्रबन्धकों को इस बात की सलाह दी जानी चाहिये कि उद्योग में किस प्रकार से शीघ्र आधुनिकीकरण एवं पुनः संस्थापन हो सकता है। इस धोर तान्त्रिकों को भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, क्योंकि वे प्रबन्ध एवं श्रम को मिलाने वाली एक कड़ी हैं। तृतीय पंच वर्षीय योजना में तीव्र औद्योगीकरण पर बल दिया गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि तान्त्रिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हो।

निर्यात करना आवश्यक—भारतीय वस्त्रों का निर्यात न सिर्फ वर्तमान स्तर पर, अपितु उसके बढ़ाये जाने के लिए निरन्तर प्रयत्न अति आवश्यक है। मिल-उद्योग में सामान्य आर्थिक स्थिरता एवं विदेशों से आयात की जाने वाली ४०-५० करोड़ रुपये की रई, आवश्यक यन्त्र सामग्री एवं अन्य माल के आयात के भुगतान के लिए यह आवश्यक है। निर्यात बढ़ाने के लिये हमें जिन बाजारों में भारतीय वस्त्र की माँग है, वहाँ माँग कायम रखने एवं बढ़ाने के लिये तो प्रयत्न करने ही चाहिये, साथ ही साथ उन बाजारों में भी कपड़ा बेचने के प्रयत्न बहुत आवश्यक हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ के कपड़े का विक्रय खास बड़े पैमाने पर नहीं होता। मध्य योरोप के पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों में जहाँ हमारे वस्त्रों की अच्छी खासी बिक्री हो सकती है, बशर्ते कि वहाँ के बाजारों के प्रतिमानों के अनुसार हम माल निर्यात कर सकें। बिक्री बढ़ाने के नये मार्ग निकालने के लिये माल के उत्पादन में विविधता लाना, प्रमाणित माल तैयार करना एवं अधिक निर्यात करना जरूरी है।

STANDARD QUESTIONS

1. Trace the history of Indian Cotton Textile Industry since Independence upto date.
2. What are the present problems of our Cotton Textile Industry? Give suggestions to solve them.

अध्याय ६३

भारतीय जूट-उद्योग

(Indian Jute Industry)

प्रारम्भिक—

जूट-उद्योग भारत का गौरव है। ससार के आर्थिक इतिहास में भारत के जूट-उद्योग को प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार के रेशों में, जो औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं, रुई के बाद केवल जूट को स्थान प्राप्त है। यह उद्योग सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं केन्द्रित उद्योग है। इस उद्योग में ८३४ कराड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है एवं ३ लाख श्रम-जीवियों को कार्य मिला हुआ है। संपूर्ण देश में ११३ जूट की मिलें हैं। देश का जूट-उद्योग वास्तव में निर्यात उद्योग है। भारत में निर्मित जूट के माल का लगभग ८० प्रतिशत विदेशों को निर्यात किया जाता है। अमरीका भारत के जूट निर्मित माल का सबसे बड़ा ग्राहक है, इसलिये यह उद्योग डालर प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

भारतीय जूट उद्योग की महत्त्वपूर्ण दो विशेषतायें हैं—प्रथम, यह उद्योग संगठित उद्योगों में एक आदर्श उद्योग है, जिसमें प्रबन्ध निर्देश एवं श्रम-व्यवस्था सुनिश्चित है। दूसरे, यह उद्योग एक स्थान पर व्यवहारिक रूप में केन्द्रित है। केवल ११ मिलों को छोड़कर जो उत्तर-प्रदेश, बिहार, मद्रास एवं मध्य-प्रदेश में हैं, शेष १०२ मिलें, अनुकूल भौतिक परिस्थितियों, माता-पिता के साधन, पर्याप्त श्रम एवं सस्ती शक्ति के कारण, पश्चिमी बंगाल में स्थित हुगली नदी के किनारे कलकत्ते से ३५ मील ऊपर एवं २५ मील नीचे की ओर लगभग २ मील चौड़े एवं ६० मील लम्बे क्षेत्र में स्थित हैं।

विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने की दृष्टि से जूट के द्वारा निर्मित वस्तुओं का सर्वोच्च स्थान है। देश में निर्मित समस्त जूट के माल का ८० प्रतिशत निर्यात माल के कारण हमें इसके द्वारा कुल विदेशी विनिमय के लगभग २० प्रतिशत की प्राप्ति होती है। यद्यपि माल का अधिकांश उत्पादन देश में ही हो जाता है, किन्तु जो माल निर्यात किया जाता है उससे हमें अमूल्य विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, जिससे हम विदेशों से आयात की हुई खाद्य एवं अन्य वस्तुओं को भुगतान कर सकते हैं।

उद्योग का अतीत एवं विकास—

देश में जूट की खेती अत्यन्त प्राचीन काल से होती है। पूर्व में यह उद्योग यहाँ पर कुटीर-उद्योग के रूप में संगठित था, किन्तु योरोपीय देशों से जूट का व्यापार ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के बाद प्रारम्भ हुआ। पालो से चलने वाले जहाजों के लिए रस्सी की आवश्यकता थी। इसके द्वारा बिछौने एवं बोरो का भी निर्माण होता था। सन् १७६५ से १८३० तक भारत ने भारी मात्रा में टाट के टुकड़ों का निर्यात किया, किन्तु सन् १८३५ में डही चसित करके के आविष्कार से बच्चे जूट की माँग बढ़ गयी। अतः कुटीर-उद्योग नष्ट होने लगा। शनैः-शनैः जूट के उद्योग को प्रोत्साहन मिला, १९वीं शताब्दी के पूर्व ही स्काटलैंड का जूट-उद्योग भारत में स्थापित हुआ। प्रारम्भ में उद्योग की धीमी गति से उद्योग के असफल होने का भय था, किन्तु इसके निरन्तर विकास ने इसे भारत का प्रमुख उद्योग बना दिया। विगत १०० वर्षों से जूट उद्योग में यन्त्रों द्वारा निर्माणी क्रिया प्रारम्भ हुई है।

हमारे देश में सबसे पहला जूट मिल श्रीरामपुर में सन् १८५४ में स्थापित हुआ, परन्तु आर्थिक विपन्न परिस्थितियों के कारण कुछ समय बाद यह मिल बंद हो गई। इसके बाद सन् १८९६ में भारत में एक जूट मिल की और स्थापना हुई और सन् १८८२ तक मिलों की संख्या २२ तक पहुँच गई, जिनमें २०,००० श्रमजीवी कार्य करते थे। इन मिलों को आर्थिक लाभ एवं सफलता प्राप्त हुई, इन सभी मिलों के स्वामी मद्रास थे। मिल उद्योग की उन्नति से इन्डो के जूट मिलों को काफी हानि हुई। मिल-उद्योग की उन्नति के कारण भारत ने अमरीका एवं आस्ट्रेलिया को बड़ी मात्रा में निर्यात प्रारम्भ किया, जिससे जूट-उद्योग को प्रोत्साहन मिला। उपरोक्त २२ जूट कारखानों में से १७ कलकत्ते के ही समीपवर्ती क्षेत्रों में थे। विदेशों की बढ़ती हुई माँग से जूट-उद्योग को प्रोत्साहन मिला। परस्पर मिलों में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मानावरण भी पैदा नहीं हुआ और संगठन भी अच्छा रहा। पटसन का उत्पादन हमारे देश की माँग की अपेक्षा विदेशों की माँग पर अधिक निर्भर करता था, यन्त्रों से दबाया हुआ पटसन विदेशों को निर्यात किया जाने लगा। विदेशों में पटसन से निमित्त माल की माँग की वृद्धि होने से मिलों की संख्या में वृद्धि हुई। इसमें लगे श्रमजीवियों की संख्या लगभग दुगुनी हो गयी, करघों एवं ठकुमों की संख्या भी बढ़कर लगभग ढाई गुनी एवं तीन गुनी हो गयी। उत्पादन वृद्धि ने उत्पादन व्यय में कमी की, साथ ही लाभ की मात्रा में वृद्धि हुई। बच्चे माल की समीपना न उद्योग के विकास में सहयोग दिया।

यद्यपि सन् १८६६ से सन् १९०० के मध्य पड़े दुर्भिक्ष में इस उद्योग को थोड़ी उठानी पड़ी, परन्तु २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वृष्टि की उन्नति ने पाट के धन्ने में गति प्रदान की। जूट-उद्योग की समस्याओं के हल एवं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए सन् १८८४ में जूट निर्माण संघ की स्थापना प्रतिस्पर्धा माल की खपत के लिये नये धातारों की खोज के उद्देश्य से की गई। सन् १९०२ में इस उद्योग का नाम

जूट-मिल सघ रखा गया। सन् १९०५-०६ में विश्वव्यापी मन्दी के कारण पुनः उद्योग में शिथिलता आ गई, इसके साथ ही जर्मनी व अमरीका आदि देशों में पटसन की स्थानापन्न वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, किन्तु इसके कारण उद्योगों को विशेष क्षति नहीं उठानी पड़ी। सन् १९१३-१४ तक जूट मिलों की संख्या बढ़ कर ६४ हो चुकी थी।

प्रथम महायुद्ध काल में उद्योग की दशा—

प्रथम महायुद्ध काल में जूट-उद्योग अत्यंत लाभप्रद स्थिति में रहा। एक तो फौजी आवश्यकताओं के लिए जूट की माँग बढ़ गई, दूसरे यत्र सामग्री का विदेशों से आयात बन्द हो गया, जिससे नई मिला की स्थापना एवं उनसे प्रतिस्पर्धा का डर नहीं रहा, तीसरे विदेशों में भी जूट की माँग बढ़ गई। मिल मालिकों में हठ संगठन था, इसलिए जूट का उत्पादन पूर्ण क्षमता से किया गया। कच्चे माल का निर्यात एकदम रोक दिया एवं कारखाना अधिनियम भी ढोला कर दिया गया। सन् १९१५-१८ की इस अवधि में मिल मालिकों ने खूब लाभ कमाया। जूट की खपत भी ५५ लाख गाँठ प्रति वर्ष हो गयी, जबकि युद्ध के पूर्व ४४ लाख गाँठ प्रति वर्ष की खपत थी। इसी समय मजदूरी की दर एवं पाट के मूल्य में भी विशेष वृद्धि हुई।

मन्दी के समय उद्योग—

युद्ध समाप्ति के पश्चात् मन्दी का एक झोका आया। सरकारी माँग लुप्त हो गयी, किन्तु मजदूरी एवं कच्चे माल के दाम बढ़ गये। युद्धकालीन लाभ से उत्साहित होकर कुछ नई मिलों की स्थापना हुई एवं कुछ पुरानी मिलों ने अपने कार्य-क्षेत्र में वृद्धि की। इस प्रकार उत्पादन वृद्धि तो होने लगी, किन्तु खपत घटने से मन्दी बढ़ती गई। फलतः अछड़ी होने से कच्चे जूट की पूर्ति बढ़ गई, जिससे मूल्य में कमी हुई। कोयले की भी कमी अनुभव हुई। अस्तु, जूट मिल सघ के निर्णयानुसार काम के घंटे घंटा दिये गये एवं किसी भी मिल का और अधिक विस्तार न करने का निश्चय किया गया। सन् १९२१ में काम करने के घंटों की संख्या ४० प्रति सप्ताह कर दी गई एवं १५ प्रतिशत प्रतिनित्त करों में भी बढ़ाव कर दिये। यह निर्णय सन् १९३८ तक चलता रहा। यद्यपि इस नियंत्रण में कुछ मिला ने सहयोग नहीं दिया, फिर भी संगठन अच्छा होने के कारण स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ।

द्वितीय महायुद्ध में उद्योग की दशा—

सन् १९१९ में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के साथ ही देश के जूट-उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला। विदेशी माँग में वृद्धि होने से, बोरे और अन्य जूट निर्मित सामान के लिए सरकार की माँग में वृद्धि होने से, उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, फलतः कार्य अवधि पर से रोक-थाम हटाकर सभी मिलें अपनी पूरी क्षमता से ६० घंटे प्रति सप्ताह कार्य करने लगीं। सन् १९४० तक तो उद्योग की स्थिति ठीक रही, इसके बाद माँग कम हो जाने से उद्योग में संकट की स्थिति दृष्टिगोचर होने लगी, परिणामस्वरूप

कार्यावधि ४५ घंटे प्रति सप्ताह कर दी गई। उद्योग में समय-समय पर इस प्रकार से उतार-चढ़ाव होते रहे। सन् १९४२ में जूट मिल सघ द्वारा उद्योग के विवेकीकरण का सुझाव दिया गया, सन् १९४३ में तो कोयले की कमी के कारण कुछ मिलों को स्वयं ही अपना कार्य बन्द करना पड़ा। यहाँ तक कि जौलाई के अग्निम सप्ताह में तो सभी मिलें कोयले व विद्युत-शक्ति की कमी, यातायात की कठिनाई एवं सन् १९४३ के बंगाल के अकाल के कारण बन्द रही और इसके पश्चात् जूट-उद्योग में विवेकीकरण की नयी योजना लागू की गई, जो सन् १९४४ की जौलाई से सन् १९४६ के मार्च तक लागू रही। इस प्रकार सन् १९४७ तक जूट-उद्योग की ऐसी ही स्थिति रही।

देश के विभाजन का उद्योग पर प्रभाव—

सन् १९४७ में देश का भारत एवं पाकिस्तान के दो हिस्सों में विभाजन होने के बाद उद्योग की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। विभाजन से पूर्व देश में विश्व का १७ प्रतिशत जूट उत्पन्न होता था, किन्तु विभाजन के परिणामस्वरूप जूट उत्पन्न करने वाली ७५ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान को हस्तान्तरित कर दी गई। भारत में प्रायः पाठ प्रतिशत जूट मिलें थी, किन्तु पाकिस्तान द्वारा पाठ के निर्यात पर कर लगा देने के कारण, कच्चे माल के प्रभाव में देश की जूट मिलें कई माह तक बन्द रही। पाकिस्तान भारत को सन् १९४८ के एक समझौते के अनुसार ५० लाख गांठे जूट की देता था, परन्तु यह समझौता सन् १९४९ में टूट गया। सितम्बर सन् १९४९ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो गया, पाकिस्तान द्वारा ऐसा नहीं किया गया, फलनः पाकिस्तान से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ४८ प्रतिशत मूल्य घटिका देना पड़ा और सन् १९४९-५१ के बीच तो भारत-पाक के मध्य व्यापार भी रुक गया, इस कारण देश की कुछ मिलें बन्द हो गईं एवं कुछ की कार्यावधि में कमी करनी पड़ी। उधर पाकिस्तान जूट के निर्यात का विटर्गाव बन्दरगाह को केन्द्र बनाना चाहता है एवं पाक सरकार ने ब्रिटिश विशेषज्ञों को जूट उद्योग के विकसित करने के लिए आमन्त्रित किया है एवं वहाँ नई जूट मिलें खोलने के आदेश भी दिये गये हैं। ऐसी दशा में देश में जूट-उद्योग के विकास एवं कच्चे माल की आरम्भनिर्भरता के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किये गए हैं। जूट-उद्योग की सहायता प्रदान करने के लिए सन् १९५२ में निर्यात शुल्क में कमी की जाना शुरू हुई, जो सन् १९५६ में बिल्कुल उठा सी गई। इस प्रकार सन् १९४५ से सन् १९५५ तक के ये १० वर्ष जूट-उद्योग के लिए बहुत नाजुक थे।

विभाजन के फलस्वरूप जूट-उद्योग पर आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब देश की अपने कारखानों की पूर्ति हेतु स्वयं अत्यधिक मात्रा में कच्चा माल उत्पन्न करना होगा। यह हर्ष का विषय है कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं केरल आदि राज्यों में जूट की खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अब एक पृथक विभाग ने द्वारा गाँव-गाँव जाकर जूट की खेती का प्रचार किया जाता है, उत्तम बीज बाँटता है एवं खागे सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारी देता है एवं कृषकों को विभिन्न सम्बन्धी अनुविधाओं से बचाने के लिए स्थान-स्थान पर उत्पन्न माल का खरीदने

का प्रबन्ध करता है। जूट-उद्योग से सम्बन्धित नवीन अनुसंधान किये जा रहे हैं। इस समय उत्तर-प्रदेश ने जूट उत्पादन क्षेत्र से कई सौ मील दूर होते हुए भी जो प्रगति की है, वह सराहनीय है। यहाँ तीन बड़ी जूट की मिलें हैं। कच्चे माल की पर्याप्तता के लिए यहाँ चार क्षेत्र, लखीमपुर, सीतापुर, बोडा तथा गोरखपुर, "अधिक जूट उत्पादन" के हेतु बनाए हैं। राजकीय प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अब उत्तर-प्रदेश में जूट का उत्पादन ६,००० मन पाट से बढ़कर ६,००,००० मन पाट उत्पन्न होता है। यद्यपि यहाँ का पाट घटिया किस्म का "जंगली पाट" है, किन्तु अच्छे पाट के उत्पादन के लिए प्रयत्न जारी है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी जूट-उद्योग के विकास के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

प्रथम एवं द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में उद्योग की दशा—

योजना आयोग के द्वारा जूट-उद्योग के विकास के लिए भविष्य की कोई योजना नहीं बनाई गई है, अपितु वर्तमान स्थिति को ही ह्रदय और ठोस बनाने का निश्चय किया गया है। आयोग द्वारा कच्चे जूट के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि उसके अनुसार भारतीय जूट मिलों की उत्पादन क्षमता तो अधिक है किन्तु आवश्यकता कच्चे जूट की है। अतः सरकार द्वारा जूट उत्पादन के लिए खेती व फसल के तरीकों में सुधार, सिंचाई की उचित व्यवस्था, उत्तम बीज व खाद के वितरण एवं आर्थिक सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्यों में समुचित प्रयत्न किये जा रहे हैं। विभाजन के समय पटसन का वार्षिक उत्पादन १५ मिलियन गठि था। विभाजन के उपरान्त जूट के माल के उत्पादन का अनुमान निम्न आँकड़ों से लगाया जा सकता है।*

वर्ष	उत्पादन (हजार टनो में)
१९४७	१०,४२
१९४०	८,३६
१९४५	१०,२७
१९४६	१०,६३
१९४७	१०,३०
१९४८	१०,६२
१९४९	१०,५०
१९६०	१०,६७

उद्योग की वर्तमान समस्याएँ एवं हल—

जूट उद्योग की वर्तमान समस्याओं के हल द्वारा ही उद्योग की उन्नति सम्भव है। भारतीय जूट मिल एसोसियेशन के प्रधान वी० डी० आज़ान के मतानुसार

* India 1961, Page 315.

उद्योग की निम्न समस्याये हैं—बढिया विस्म के जूट की कमी, जूट के मूल्य में कमी एवं प्रतियोगिता आदि ।

(१) अच्छी किस्म व सस्ती जूट का अभाव—देश के विभाजन से उद्योग के एकाधिकार की अवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है, आज सबसे जटिल समस्या जूट के उत्पादन की है । पाकिस्तान से आने वाली जूट पर देश की मिलें निर्भर नहीं रह सकती हैं, क्योंकि न मालूम अब पाकिस्तान भारत को जूट देना बन्द कर दे । आवश्यकता इस बात की है कि देश में ही अच्छी किस्म का, सस्ता जूट उत्पन्न किया जाये, इसी उद्योग से 'अधिक जूट उपजाओ आन्दोलन' प्रारम्भ किया गया, फलतः १५'८ लाख एकड़ भूमि पर ४१'४ लाख गाँठें जूट सन् १९५५-५६ में उत्पन्न हुआ, जबकि सन् १९४६-४७ में केवल ५'४ लाख एकड़ भूमि पर १३'२ लाख गाँठों का उत्पादन हुआ था । प्रथम योजना का जूट उत्पादन का लक्ष्य ५३ ६ लाख गाँठें यद्यपि पूरा नहीं हो सका, फिर भी हम अब पाकिस्तान पर अधिक निर्भर नहीं हैं । इस समय देश की अपनी आवश्यकता का केवल १० प्रतिशत कच्चा जूट पाकिस्तान से आयात करना पड़ता है । जूट के उत्पादन के लिये किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सन् १९६०-६१ में जूट की फसल देश में बहुत अच्छी रही, मतः कच्ची जूट तथा जूट निर्मित माल के भाव गिर गये । सरकार द्वारा जूट उत्पादक विभिन्न राज्यों की गतिविधियों का एकीकरण करने के लिये एक केन्द्रीय देख-रेख संगठन स्थापित किया गया है । यह संगठन जूट-उत्पादन के कार्यक्रम को कार्य रूप देता है, प्रति एकड़ अधिक उपज करने एवं फसल की विस्म आदि सुधारने का भी ध्यान रखता है । यह संगठन जूट-उद्योग से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करता है । यदि इस वर्ष किसानों को कच्ची जूट का उचित मूल्य नहीं मिला पाया तो फिर जूट का उत्पादन देश में कम हो सकता है ।

यद्यपि पाट उत्पादन के नवीन क्षेत्रों में जलवायु सम्बन्धी (जैसे—सूखा, बाढ़, आदि) कठिनाइयाँ भी एक प्रधान समस्या है । फिर भी सरकार कृषि वर्षा, बाढ़ नियन्त्रण, उन्नति बीज एवं खाद द्वारा जूट की फसल प्रति एकड़ बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रही है ।

(२) जूट की स्थानापन्न वस्तु का भय—विज्ञान ने आज के युग में बहुत प्रगति की है, मतः विविध देशों ने जूट की स्थानापन्न वस्तुओं का निर्माण किया है । अब उपभोक्ताओं को माल देने के लिये उत्पादन की नई-नई प्रणालियों का विकास हुआ है । जूट के स्थान पर अब एक ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाने लगा है, जो कपड़े में समान है एवं जूट के बोरो की जगह उपयोग में आती है । अन्य देशों में जूट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नये रेशे खोज निकाले गये हैं तथा नवीनतम उपकरणों से पूर्ण जूट मिल पाये जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि ये जूट की स्थानापन्न वस्तुएँ जूट से सस्ती प्राप्त होने लगी, तो इस उद्योग के गूँट हो जाने का भय है । मतः आज इस बात की आवश्यकता है कि जूट निर्मित माल का उत्पादन बढ़ाया जाये,

उसके गुणों में सुधार किया जाये तथा विभिन्न एवं नवीन क्षेत्रों में उसके प्रयोग के लिये अनुसन्धान किये जायें ।

(३) प्रतियोगिता—देश के विभाजन के परिणामस्वरूप जूट उत्पन्न करने वाली ७५ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान को सौंप दी गई और वहाँ की सरकार इस उद्योग को हर प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है, नवीन उपकरणों से सुसज्जित कारखानों का निर्माण किया जा रहा है एवं इस सम्बन्ध में ब्रिटिश विशेषज्ञों द्वारा भी सहायता ली जा रही है । अतः निश्चित है कि वहाँ की मिलें भारत की अपेक्षा अधिक कार्यक्षम होंगी तथा वहाँ जूट की भी अधिकता है । भारत को पाकिस्तान से कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि हानि भी उठानी पड़े । इसलिए सरकार को अधिक मात्रा में जूट उत्पन्न करने के लिये कारखानों में आधुनिकतम उपकरणों के प्रयोग पर बल एवं अच्छी से अच्छी किस्म की जूट उत्पन्न करने के प्रयत्न करना चाहिए ।

(४) आधुनिकीकरण—जूट उद्योग में आधुनिकीकरण के प्रयत्न विगत कई वर्षों से हो रहे हैं । सरकार ने उद्योग में आधुनिकीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया है । इस समय जूट उद्योग की सहायता प्रदान करने से सरकार को ४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है एवं ८ हजार श्रमिकों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, फिर भी ऐसी यन्त्र सामग्री को बदलने की व्यवस्था की गई है, जो या तो उत्पादन के बिलकुल अयोग्य है या जिसके प्रयोग से उत्पादन व्यय अधिक आता है । उद्योग आधुनिकीकरण की ५० प्रतिशत योजना पूरी कर चुका है । सरकार ने उद्योग को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था की है । जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा ३१ मार्च सन् १९५६ तक ४५६ करोड़ ६० लक्ष दिया गया, जिससे जूट मिलों में आधुनिकीकरण का कार्य पूरा करने में बहुत सहायता मिली है तथा कई मिलों ने तो भविष्य की योजनाएँ भी बना ली हैं । माशा है कि दो या तीन वर्षों में उद्योग आधुनिकीकरण योजना का ७५ प्रतिशत पूर्ण कर लेगा । यद्यपि उद्योग में सम्पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, किन्तु मिलों के कतई-बुनाई विभाग में नवीनतम उपकरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे उत्पादन लागत में कमी के साथ काम भी अच्छा होगा ।

(५) जलवायु सम्बन्धी कठिनाई—देश के विभाजन के बाद जूट का उत्पादन अधिक मात्रा में करना बहुत आवश्यक है । उद्योग में कच्चे माल में आत्मनिर्भर होता है, इसके लिये किये गये प्रयत्नों में, जूट उत्पादन के जो नये क्षेत्र बनाये गये हैं, वहाँ जलवायु सम्बन्धी (जैसे—सूखा, बाढ़, अनावृष्टि आदि) कठिनाई की एक प्रधान समस्या है । इसके हल के लिये कृत्रिम वर्षा, बाढ़ नियन्त्रण, उत्तम बीज एवं खाद का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, जिससे प्रति एकड़ फसल अधिक बढ़ाई जा सके ।

(६) पाकिस्तान का असन्तोषजनक व्यवहार—भारत एवं पाकिस्तान के बीच ठीक सम्बन्ध नहीं होना भी, जूट-उद्योग की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के मध्य हुए समझौते को कभी पूरा नहीं किया। ५ अगस्त सन् १९५२ को नई दिल्ली में हुआ एक समझौता भी पूरा न हो सका, जिसमें भारतीय व्यापारियों में निराशा छा गई। समझौते के अनुसार भारत को आशा थी कि २३ ६० प्रति मन् का विवेचनात्मक लाइसेंस शुल्क (Discriminating License Fee) जोकि पाकिस्तान ने लगा रखा था, हटा दिया जायेगा, परन्तु इसके विपरीत पाकिस्तान द्वारा समझौते का तोड़ा गया। यही नहीं, पाकिस्तान अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली जूट की गांठा पर निर्यात कर ३ ६० प्रति मन् प्राप्त करता था और भारत से पीने चार ६० प्रति मन् निर्यात कर वसूल करता था। अतः पाकिस्तान के इस असन्तोषजनक व्यवहार से पाकिस्तानी जूट का निर्यात करने एवं उसके द्वारा वस्तुएं तैयार करने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है।

(७) मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई—२१ सितम्बर सन् १९४६ को भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डालर के सम्बन्ध में अपने रुपये का अवमूल्यन किया। स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, परन्तु पाकिस्तान ने इन सबके विपरीत अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करने का निश्चय किया। परिणामस्वरूप पाकिस्तान को १०० ६० के स्थान पर भारत द्वारा १४४ ६० दिये गये। इस प्रकार भारत द्वारा पाकिस्तानी माल निर्यात करने के लिये ४४ प्रतिशत मूल्य अधिक दिया गया। भारत अपने जूट के मूल के दाम नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ऐसा करने से भारतीय निर्यात व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। विवश होकर पाकिस्तानी जूट का निर्यात भारत की जूट मिल ऐसोसियेशन द्वारा कम कर दिया गया। इससे उद्योग को बड़ी हानि उठानी पड़ी और आज भी हानि उठानी पड़ रही है।

निसर्वेह इस अभाव को पूरा करने के लिये जूट टेक्नालॉजिकल इंस्टीट्यूट ने केन्द्रीय जूट समिति के सकेत पर अलसी के छिलके से रेशा निकालने की कला में विकास किया है, इस रेशे को जूट से मिलाते हैं। किंतु इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि स्थापनापत्र रेशे का मूल्य अधिक है।

(८) विदेशी प्रतिस्पर्धा का भय—भारतीय जूट-उद्योग की एक बहुत बड़ी समस्या विदेशी माल, विशेषकर जूट की स्थापनापत्र वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा की है। विश्व के विभिन्न देशों में जूट की स्थापनापत्र वस्तुओं के निर्माण में काफी प्रगति हुई है एवं देश के विभाजन के बाद तो इन देशों को और भी प्रोत्साहन मिला है। भारतीय मिलों की उत्पादन-क्षमता भी कम हो गई है, अतएव अपेक्षाकृत अन्य देशों का जूट मिल उद्योग काफी उन्नति कर रहा है। पाकिस्तान भी जूट निर्माण के लिये प्रयत्न कर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में भारत को सावधान होकर कार्य करना चाहिये।

(६) पाट के मूल्य का प्रश्न—जूट के दामों में अन्य स्वानाम्न वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा जो अत्यधिक वृद्धि हुई है, उसका एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान से आयात किये गये पाट के मूल्य में वृद्धि हो गई है। सन् १९४७ में अन्तिम दिनों में पाकिस्तान की सीमा से बाहर जाने वाले पाट पर वहाँ की सरकार द्वारा जूट पर शुल्क लगा दिया गया तथा पाकिस्तान से आयात की गई जूट में मौसम के कारण नमी अधिक होने से १६४ लाख रु० की हानि हुई। दूसरे श्रम लागतों में भी बड़ी-सारी हुई। भारतीय मजदूरों की कार्य करने की शक्ति कम होने के कारण १ मजदूर का कार्य ४ मजदूर करते हैं। इन इन सब कारणों का उद्योग पर कुप्रभाव पड़ा। अन्य देशों में आधुनिकीकरण की तीव्र गति की अपेक्षा भारत में यह गति बहुत कम हो गई, क्योंकि उपरोक्त कारणों से उद्योग की आय पर बुरा प्रभाव पड़ा था। अतः यदि हमने उद्योग के वैज्ञानिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये उचित प्रयत्न नहीं किये तो लागत मूल्य में कमी नहीं हो सकती, इसके लिये सरकार द्वारा जूट के माल पर निर्यात वर की दरें भी कम करनी आवश्यक है, जो भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद बहुत बड़ गई है। साथ ही, सरकार निर्यात की कोटा पद्धति को समाप्त करे। हाँ, वह प्रशंसा बना रहे जो विदेशों में हुए द्विपक्षीय समझौतों की पूर्ति के लिये आवश्यक हो।

भारतीय जूट उद्योग पर संकट—*

भारतीय जूट उद्योग की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सरकारी तथा गैर-सरकारी पक्ष से गत कुछ समय में इतने अधिक वक्तव्य जारी किये गये हैं कि सही स्थिति का पता लगाना कठिन है, किन्तु सहजार्थ से विचार करने पर यह पता चलता है कि आजकल मूल समस्या कच्चे जूट की उपलब्धि अथवा कम या ऊँचे भावों की नहीं, वरन् जूट उद्योग तथा जूट माल-बाजार की स्थायित्व देने की है। इन्डियन जूट मिल एसोसियेशन ('इजमा') का कहना है कि कच्चे जूट की सप्लाई स्थिति जटिल बनी हुई है और मिलें अपना उत्पादन घटाकर कच्चा माल बचा कर रखने के लिए बाध्य हो गई है। कुछ बड़ी बड़ी जूट मिलों ने १९% तक करछे बन्द कर दिये हैं। इस प्रकार कुल ३०% तक करछे बन्द हैं। कई मिलों में ४२½ घंटे की जगह ४० घंटे काम हो रहा है। एक मिल ने तालाबन्दी घोषित कर दी है। मिलों द्वारा माल न उठाये जाने के कारण भाव गिरते जा रहे हैं और यदि इस गिरावट की गति की रोकथाम के लिए कोई पग न उठाया गया, तो भाव और गिर जायेंगे। जूट उद्योग की वर्तमान स्थिति कितनी चिन्तनीय है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह प्रश्न राज्य सरकार की सीमा को लाघ कर केन्द्र तक पहुँच गया है। केन्द्रीय श्रम-मन्त्री के सन्मुख दो मुद्दाव आये हैं—(१) जूट का संकट-कालीन भण्डार बनाया जाय, जिसकी व्यवस्था के लिए राज्य सरकार तथा 'इजमा' के

प्रतिनिधियों की एक समिति गठित हो, और (२) जूट का न्यूनतम भाव निर्धारित किया जाय ।

जूट उद्योग की वर्तमान स्थिति से श्रमिक भी बहुत चिन्तित हो गये हैं । यदि मिलों में पूरे पैमाने पर काम शीघ्र ही चावू नहीं हुआ, तो उनके सम्मुख पूर्ण बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जायेगी । श्रमिकों ने माँग की है कि जूट उद्योग के वर्तमान गतिरोध को दूर करने के लिए अघ्यादेश जारी किया जाय । उनका कहना है कि इजमा न केवल विदेशी व्यापार में रूकावट डाल रहा है वरन् उसकी नीति से जूट उत्पादकों और जूट उद्योग में लगे श्रमजीवियों की आजीविका भी छिनी जा रही है । इस समस्या के समाधान के लिए अल्पकालीन उपाय कारगर न होंगे, इसके लिए तो स्थायी उपाय करना होगा । वर्तमान समस्या के एक समाधान के रूप में कच्चे जूट का निम्नतम भाव निश्चित कर देना चाहिये । यदि भारत व पाकिस्तान दोनों ही देश मिल कर जूट-भावों के नियमन के लिए कोई सहयोग सगठन बनाय तो श्रेष्ठकर होगा ।

उपसंहार—

सचमुच ही यह सन्तोष का विषय है कि हमारे जूट उद्योग के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों के प्रति जूट उद्योगपति तथा सरकार दोनों जागरूक हैं । इण्डियन जूट मिल एसोसियेशन ने जूट की माँग में वृद्धि करने के उद्देश्य से अमेरिका व इंग्लैण्ड में अपने कार्यालय खोल रखे हैं तथा अन्य देशों में भी प्रतिनिधि मण्डल भेजे जा रहे हैं । इजमा नई नई वस्तुओं के निकालने के अनुसन्धान कर रहा है । हमारी जूट मिलों ने परदे, दरियाँ, मोटे कपड़े तथा छोटे-छोटे बोरे आदि बनाने प्रारम्भ कर दिये हैं । ऐसी परिस्थिति में यह आशा की जाती है कि साहस, धैर्य एवं बुद्धिमत्तापूर्ण नियोजित कार्य करने से हमारे जूट उद्योग की समस्याय सुलभ जायेगी । तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत ६५ लाख गॉठ कच्चा पटसन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है । इससे हम जूट उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धि के विषय में बहुत कुछ निश्चित हो जायेंगे । इस प्रकार जूट उद्योग को पूर्णरूपेण प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब भारत को विश्व में जूट उत्पादन एकाधिकार पुनः प्राप्त हो जायेगा ।

STANDARD QUESTIONS

1. Discuss briefly the effects of partition on India's Jute Mill Industry. How have they been tackled? What are your suggestions in this connection?
2. Write a brief essay on the present position and problems of Indian Jute Industry.

अध्याय ६४

भारतीय लौह एवं स्पात उद्योग

(Indian Iron & Steel Industry)

प्रारम्भिक—

आज के युग में किसी देश की औद्योगिक उन्नति की कसौटी यह है कि वहाँ कितना इस्पात बनता है और उपयोग में आता है। विश्व के आधारभूत उद्योगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा एवं इस्पात उद्योग है। वर्तमान युग यन्त्रीकरण का युग है, क्योंकि चाहे कोई भी उद्योग हो, सभी में यन्त्रों के प्रयोग द्वारा उत्पादन एवं विकास किया जाता है और यन्त्रीकरण लौह एवं इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। किसी देश की आर्थिक प्रगति, विवास एवं राजनैतिक सुरक्षा के लिए भी इस उद्योग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। लोहे की महिमा के सम्बन्ध में ऐसा कहते हैं कि :—'सोना महल की रानी के लिए आवश्यक है, चाँदी महल की दासी के लिए और ताँबा एक साधारण कारीगर के लिए, किन्तु लोहा इन सभी धातुओं का स्वामी है।'

इस उद्योग में अमरीका का प्रथम स्थान है, जहाँ १० करोड़ टन से भी अधिक इस्पात बनता है। इस में ५ करोड़ टन एवं ब्रिटेन तथा जर्मनी में २-२ करोड़ टन प्रति वर्ष इस्पात का उत्पादन होता है। यह उद्योग भारत में बहुत तीव्र गति में विस्तार कर रहा है। उद्योग के लिये आवश्यक वस्त्रा मात देश में पर्याप्त मात्रा में है। योरोपीय देशों में स्वीडन को छोड़कर अन्य कोई ऐसा देश नहीं जहाँ भारत के समान सख कोटि का लोहा एवं कोयला मिलता हो। हमारे देश में लोहे के भण्डार साधारण नहीं हैं, केवल सिन्ध भूमि क्षेत्र में ही १ हजार करोड़ टन से भी अधिक लोहा है, जिसका प्रयोग यदि वर्तमान गति से हो, तो भी यह २,००० वर्ष तक चल सकता है। भारत ने द्वितीय योजना के अन्त तक ६० लाख टन प्रति वर्ष इस्पात तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उद्योग का अतीत एवं विकास—

लोह एवं इस्पात उद्योग भारत का अति प्राचीन उद्योग है। आज से ६-७ हजार वर्ष पूर्व भी भारतीय लौह का उपयोग जानते थे। भारतीय इस्पात का माल

विदेशों में भी जाता था एवं अपनी सुन्दरता के लिए लोकप्रिय था। दिल्ली का लोह स्तम्भ हमारे देश के प्राचीन इन्जीनियरी की कला का जीता-जागता उदाहरण है। इस उद्योग की प्राचीनता पर प्रकाश डालते हुये प्रोफेसर विल्सन ने लिखा है कि—
“लोहे की ढलाई तो इङ्ग्लैण्ड में थोड़े ही वर्षों से प्रारम्भ की गई है, परन्तु हिन्दू लोग लोहा गलाने, ढालने तथा इस्पात बनाने की कला का ज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल से रखते हैं।”

आधुनिक समय में हम उद्योग का इतिहास विगत १५० वर्षों का है। इसके पूर्व कुछ योरोपियों ने इस उद्योग को चलाने का प्रयत्न किया, पर वे सफल न हो सके। इन प्रयत्नों में सन् १७७७ में भरिया की कोयले की खान के निकट एक लोहे एवं इस्पात का कारखाना खोला गया, जो दो वर्ष के बाद बन्द हो गया। इसके बाद सन् १८५७ में बारकपुर आयरन स्टील कम्पनी की स्थापना की गई, ६ वर्षों तक यह कारखाना कार्य करता रहा, फिर इसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने खरीद लिया। दो वर्ष के बाद इस कारखाने का नाम बदलकर “दी बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी” रखा एवं कारखाने का आधुनिकीकरण भी किया गया। यह कारखाना इस्पात उत्पादन में तो असफल रहा, किन्तु इसमें आधुनिक पद्धति से पिग आयरन का उत्पादन किया जाने लगा।

आधुनिक काल में लोह एवं इस्पात उद्योग की नींव डालने का श्रेय श्रीजमशेद जी नौसेरवान जी टाटा को है, जिन्होंने सन् १८०४ में जर्मनी एवं अमेरिकन विशेषज्ञों द्वारा देश के मध्य-प्रान्त की जाँच करवाई। सरकारी विभाग से स्वीकृति लेकर विदेशों में भ्रमण करके एवं अन्य अनेकानेक कठिनाइयों को पार करने के पश्चात् कारखाना प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है, किन्तु यह कारखाना जिस स्थान पर स्थापित करना था, वह कोयले एवं लोहे की खानों से समान दूरी पर था, अतः अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री पी० एन० बसु की सहायता से निरीक्षण आदि करा कर मयूरभञ्ज (उड़ीसा) में सन् १८११ में जिस स्थान पर कारखाने का प्रारम्भ किया गया, वही स्थान आज जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इस कारखाने का नाम “दी टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी” (TISCO) रखा गया। इस कारखाने में कार्य प्रारम्भ होने के बाद सन् १८१२ में इस्पात तैयार होने लगा। ‘टिस्को’ (TISCO) आज भारत ही नहीं बल्कि एशिया का गौरव है।

प्रथम महायुद्ध में उद्योग की स्थिति—

सन् १८१४ में योरोपीय महासमर का प्रारम्भ लोह-इस्पात उद्योग के लिए स्वर्ण अवसर लाने वाला सिद्ध हुआ। इस समय देश की माँग में वृद्धि हुई एवं विदेशों से लोह-इस्पात का आयात कम हो गया। इस समय टाटा द्वारा अत्यधिक लाभ कमाये गये, टाटा की प्रगति से प्रभावित हो सन् १८१८ में हीरापुर नामक स्थान पर ‘इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी’ की तथा सन् १८२१ में मुम्बई में ‘युनाइटेड स्टील

कॉर्पोरेशन ऑफ एशिया' और सन् १९२३ में मद्रास में 'मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स' की स्थापना हुई।

इस काल में भारतीय बड़ी हुई माँग एवं विदेशों की युद्ध के कारण उत्पन्न हुई माँग को पूरा करने के लिये, उद्योग द्वारा काफी उत्पादन हुआ एवं इस उद्योग का देश में विकास हुआ। प्रशुल्क मण्डल के अनुसार सन् १९१६-१७ में टाटा कम्पनी का उत्पादन क्रमशः १,४७,४९७ टन बच्चा लोहा एवं १,३९,४३३ टन इस्पात व ९८,७२९ टन धक्का इस्पात उत्पन्न हुआ। परन्तु युद्धोपरान्त आर्थिक मन्दी के कारण उद्योग को हानि उठानी पड़ी। माँग एवं मूल्य गिर जाने से एवम् मजदूरी ऊँची होने से तथा कोयले की अँहगई के कारण उत्पादन व्यय कम हो गया। सन् १९२३ में प्रशुल्क सभा की नियुक्ति की गई, परिणामतः सन् १९२४ में उद्योग को तीन वर्ष के लिये संरक्षण दिया गया, यह संरक्षण "इस्पात संरक्षण कानून" के अन्तर्गत दिया गया, जिसकी अवधि बाद में ७ वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई। संरक्षण के फलस्वरूप ही उद्योग सन् १९२९-३० की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी का सामना सफलतापूर्वक कर सका। "इस्पात संरक्षण कानून" के अन्तर्गत उद्योग को आर्थिक सहायता भी दी गई। आरम्भ में यह सहायता ५० लाख रुपये की थी, किन्तु बाद में यह राशि बढ़ा दी गई। सन् १९३४ में सप्त वर्षीय संरक्षण का काल समाप्त हो गया, इस समय तक उद्योग यथेष्ट उन्नति कर चुका था। सन् १९३५ तक पिग आयरन का उत्पादन १३,४३,००० टन हो गया था। इस समय संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु सरकारी भाय में कमी जाने के भय से संरक्षण जारी रखा गया।

द्वितीय महायुद्ध की उद्योग स्थिति—

दूसरे महायुद्ध का प्रारम्भ उद्योग की समृद्धि का एक नया युग लेकर आया। देश के कई भागों में नये-नये कारखाने खुले एवं विद्यमान कारखानों के कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। विदेशी यातायात के बन्द हो जाने से, फौजी आवश्यकताओं में वृद्धि हो गई, अतः उद्योग में मूल्य, लाभ एवम् उत्पादन सब ऊँचे हो गये। इस्पात का उत्पादन दो वर्ष में ही ५ प्रतिशत बढ़ गया। अत्यधिक माँग वृद्धि के कारण सरकार की सर्व साधारण के उपभोग पर भी नियन्त्रण लगाना पड़ा। सरकार ने सन् १९३८ में टाटा के तत्पश्चात् अन्य कम्पनियों से युद्ध कार्य हेतु आवश्यक स्टील के मूल्य के विषय में समझौते किये, जो वर्तमान में भी किसी न किसी रूप में चल रहे हैं। सन् १९४१ में युद्ध की माँग की पूर्ति करने के लिये टाटा ने जमशेदपुर में स्टील टायर एण्ड एक्जिल प्लांट की स्थापना की, जिसमें रेल के पहियों का निर्माण होने लगा। सन् १९४६ में पूर्ण मंत्रालय द्वारा बताया गया कि वार्षिक उत्पादन २५ लाख टन होना चाहिये, मूल्य पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये एवं उद्योग को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिये। सरकार ने उद्योग को निम्न रूप से उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता दी— टाटा को १० करोड़ रु०, बङ्गाल स्टील कॉर्पोरेशन को ३ करोड़ व इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को १ करोड़ रु० ऋण के रूप में दिया गया।

युद्धोत्तर काल में उद्योग का उत्पादन गिर गया एवम् निर्यात कम हो गया । इसके प्रत्येक कारण हैं, जैसे—कोयला प्राप्त करने में कठिनाई, मजदूरी बढ़वाने के लिए श्रमियों द्वारा हड़तालें आदि और यातायात की असुविधा, इत्यादि । फलतः देश में विदेशी विनिमय को हानि उठानी पड़ी । देश के अन्तर प्रांतीय कोटे कम कर दिये गये, व विकास की योजनाएँ खटाई में पड़ गयी ।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में उद्योग—

देश के विभाजन के बाद हमारे देश में नयी राष्ट्रीय सरकार ने लौह एवम् इस्पात उद्योग की उन्नति एवम् विकास का भार अपने ऊपर ले लिया । प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने उद्योग को विशेष सहायता देने का यत्न किया । योजनानुसार सरकार ने सन् १९५६ तक सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में ३० करोड़ रु० खर्च करने एवम् निजी उद्योगपतियों को उनकी विकास योजनाएँ कार्यान्वित करने के लिए ४३ करोड़ रु० देने का निश्चय किया । सरकार को उद्योग की उत्पत्ति निम्न ढङ्ग से बढ़ने की आशा थी—

सन् १९५०-५१ में उत्पत्ति

लगा हुआ लोहा—१७ ८ लाख टन

तैयार स्पात— १० ७५ „ „

सन् १९५५-५६ में उत्पत्ति

१९५ लाख टन

१२ ८ „ „

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सरकार द्वारा, ५ लाख टन इस्पात पिण्ड तैयार करने की क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया था, किन्तु उस समय विदेशी सहयोग प्राप्त करना कठिन था । अतः सन् १९५३ में दो जर्मनी की क्रुप्स व डेमिंग फर्मों के सम्मिलित सहयोग से एक कारखाने के निर्माण का समझौता किया गया । यह कारखाना 'हिन्दुस्तान स्टील लि०' के नाम से प्रारम्भ हुआ तथा इस पर १० करोड़ रु० व्यय किया गया । सरकार द्वारा, देश में लोहे एवम् इस्पात का उत्पदन बढ़ाने के लिए १ जनवरी सन् १९५३ को स्टील वॉरपोरेशन ऑफ बङ्गाल तथा इण्डियन धायरन एण्ड स्टील कम्पनी का एकीकरण (IISCO and SCOB Merger) किया गया ।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में उद्योग—

भारत की विकास योजनाओं के साथ ही साथ देश में लोहे एवम् इस्पात की माँग में भी वृद्धि हुई, अतः भारत सरकार ने उद्योग के महत्त्व को समझकर इसे द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया । इस उद्योग पर ४३१ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया । इस योजना के अन्तर्गत उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा नये कारखाने खोलने का भी निश्चय किया गया । देश में लोहे एवम् इस्पात की स्वयं सरकार ने तीन नये कारखाने खोले हैं—प्रथम रुर्केला (उड़ीसा), द्वितीय मिलाई (मध्य प्रदेश) एवम् तृतीय दुर्गापुर (पश्चिमी बङ्गाल) । मिलाई का कारखाना रुस सरकार की सहायता से स्थापित किया गया है । रुर्केला इस्पात कारखाने की

प्रथम धमन भट्टी का कार्य ३ फरवरी सन् १९५६ को एवम् भिलाई इस्पात कारखाने की धमन भट्टी का कार्य दिनांक ४ फरवरी सन् १९५६ को प्रारम्भ हो गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाने को धातु कर्म सम्बन्धी बढ़िया किस्म का कोयला उपलब्ध कराने के लिये पश्चिमी बङ्गाल द्वारा स्थापित कोयला भट्टी सयन्न का मार्च सन् १९५६ में उद्घाटन हुआ।

योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्थापित नवीन कारखाने

(१) रूरकेला (उड़ीसा)—

कलकत्ता से २५७ मील दूर शम्भू और कोयल नदियों के संगम पर स्थित रूरकेला, जहाँ से कलकत्ता बम्बई रेल लाइन जाती है, एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पर सरकार द्वारा इस्पात का कारखाना बनाया जा रहा है, जिसमें १० लाख टन इस्पात बनाया जायेगा, किन्तु इसके यन्त्रों में थोड़ा सा विस्तार करके इसका उत्पादन १५ लाख टन तक किया जा सकेगा। योजनानुसार इसकी उत्पादन क्षमता २० लाख टन रखी गई है। ३ फरवरी सन् १९५६ को रूरकेला इस्पात कारखाने की प्रथम धमन भट्टी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा था कि “रूरकेला, भिलाई एवम् अन्य योजनाएँ हमारी महत्वाकांक्षायो की प्रतीक हैं। हमने हितकारी राज्य की स्थापना का सफल किया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर हो और उसे पर्याप्त भोजन तथा कपड़ा मिले। ये भारी उद्योग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम प्रयास हैं। मुझे आशा रूरकेला कारखाने के उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे आशा है कि इस कारखाने से हमें अपने हितकारी राज्य का स्वप्न पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी।” राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में खनिज काफी मात्रा में हैं। रूरकेला और अन्य छोटे कारखानों में इसका उपयोग होगा। राष्ट्रपति ने आशा प्रगट की कि कुछ समय बाद यह जर्मनी के प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्र रूट का मुकाबला करने लगेगा। रूरकेला कारखाने एवं हीराकुण्ड बाँध से इस क्षेत्र के लोगों की उन्नति होगी। यही नहीं, बल्कि इससे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। रूरकेला कारखाने के समीप ही पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। खनिज लोहा प्राप्त करने के लिये यहाँ से ४५ मील दूर बरसुआ में नई खान खोदी जा रही है। इस कारखाने के लिये कोयला बिहार की करगली, बोकारो एवं झरिया की खानों से प्राप्त किया जावेगा। करगली में कोयला खाने का कारखाना भी स्थापित किया जायेगा। इसके अलावा कारखाने के लिये चूने के पत्थर की व्यवस्था हाथीबाड़ी और बीरभित्रपुर से की जा रहा है, जो कारखाने से १५ मील दूर है।

(२) भिलाई (मध्य-प्रदेश)—

दिनांक ४ फरवरी सन् १९५६ को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने भिलाई कारखाने की धमन भट्टी का उद्घाटन करते हुए कहा कि—“कारखाने का यह प्रारम्भ देश की आर्थिक स्थिति को बदलने तथा अपने अनन्त प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके लोगों

रहते-सहते के स्तर को ऊँचा उठाने की हमारी आशाओं का प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं, जब देश के लोगो के ये प्रयत्न फलदायी होंगे। उन्होंने कहा कि यह विशाल कारखाना उज्जवल भविष्य के प्रति देश के विश्वास और बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने का निश्चय प्रतीक है। भारी उद्योग खड़े करने के हमारे कार्यक्रम में इन इस्पात कारखानों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल में खरकेला का उद्घाटन किया और आज इस भिलाई कारखाने का उद्घाटन कर रहा हूँ। ये दोनों दिन भारत के औद्योगीकरण के इतिहास में अविस्मरणीय रहेंगे।"

नागपुर से १५६ मील दूर बम्बई कलकत्ता की मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है भिलाई। भिलाई कारखाने में ७,७०,००० टन इस्पात की सिलें तैयार की जायेंगी, जिनमें रेल की पटरियाँ और स्लीपरें, इमारतों में काम आने वाला सामान तथा चद्दरें आदि बनाई जायेंगी। योजनानुसार कारखाने का विस्तार कर इसकी उत्पादन क्षमता को २५ लाख टन इस्पात की सिलों तक बढ़ाया जा सकता है। इस कारखाने के लिये राजहठा की खानों से खनिज लोहा भँगाया जायेगा, यह भिलाई से ६० मील दूर है। कोयला बिहार की करगली, बुकारो एव झरिया तथा मध्य प्रदेश की कोयला की खानों से आयेगा। लूने का पत्थर भिलाई से १२ मील दूर गन्वनी की खानों से लिया जायेगा। भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से खोला गया है। रूस के द्वारा इस कारखाने को आर्थिक तथा शिल्पिक सहायता दी जा रही है।

(३) दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल)—

दुर्गापुर का इस्पात कारखाने का निर्माण अन्य दोनों कारखानों के बाद प्रारम्भ हुआ, फिर भी काम विधिवत एव अत्यन्त शीघ्रता से चल रहा है। इस कारखाने के निर्माण में कुछ ब्रिटिश फर्मो भी सहयोग दे रही हैं। दुर्गापुर कारखाने की लागत के लिये ब्रिटेन के बंको की एक सिण्डिकेट ११५ लाख पौण्ड और ब्रिटिश सरकार १५० लाख पौण्ड दे रही है। दुर्गापुर कारखाने के लिये वारकर तथा झरिया की खानों का कोयला उपयोग में लाया जायेगा। लूने का पत्थर बीरमिन्नपुर तथा हाथी बाड़ी क्षेत्र से भँगाया जायेगा। दुर्गापुर का दामोदर चाटी निगम १ लाख ५० हजार किलोवाट क्षमता का एक ताप बिजलीघर बना रहा है। इसके अलावा कारखाने का अपना १५ हजार किलोवाट की क्षमता का ताप बिजलीघर काम करेगा।

उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य—

देश में लौह एव इस्पात के लगभग १३६ कारखाने बिहार, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में केन्द्रित हैं। इस उद्योग में लगभग ८६ हजार श्रमजीवी कार्य करते हैं। इस समय निजी क्षेत्र में, हमारे देश में टिस्को, 'इस्को' तथा स्काब की संयुक्त संस्था एव 'मंसूर आयरन वर्क्स मद्रास'—तीन प्रमुख कारखाने लोहे एव इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। इन सबकी उत्पादन क्षक्ति १८,७८,००० टन बाला हुआ लोहा व १०,५०,००० टन इस्पात है। इन उत्पादकों की पूँजी ६४ करोड़ ४० है।

उत्पादन—

निम्न तालिका में लीह एवं स्पात का वर्तमान उत्पादन दिखलाया गया है —

लोहा और इस्पात

वर्ष	कच्चा लोहा (००० टन)	सीपी डलाई (००० टन)	लीह मिश्रित घासु (००० टन)	इस्पात के विण्ड और डलाई (००० टन)	अधूरा लोहार इस्पात (००० टन)	लोहार स्पात (००० टन)
१९५२	१,६८४.८	१२६.६	४०.८	१,४७८.०	१,३०८.०	१,१०२.८
१९५३	१,६४४.८	११४.२	७२	१,४०७.२	१,२३०.०	१,०२३.६
१९५४	१,७६२.८	१२७.२	४०.८	१,६८४.८	१,४४२.०	१,२४३.२
१९५५	१,७४६.८	१२६.०	१२०	१,७०४.०	१,४४६.८	१,२६०.०
१९५६	१,८०७.२	१२२.४	२८.८	१,७३७.६	१,४४४.४	१,३३८.०
१९५७	१,७८६.२	११२.८	६६	१,७१४.८	१,४४०.०	१,३४६.४
१९५८	२,०११.२	७२.०	२६.४	१,८१३.२	१,४६६.६	१,२६६.६
१९५९	२,६६४.०	४४.४	२१.६	२,४४३.६	२,२२०.०	१,७३६.४
१९६०	४,१४६.६	३६.०	७२	३,२८६.८	३,४६३.२	२,२०८.०
१९६१ जनवरी	४११.०	६१	०.८	३४१.३	१००.७	२३८.७
फरवरी		३६	०.७	२६४.१	६२.३	२२२.३

उद्योग की समस्याएँ—

भारतीय सौह एव इस्पात उद्योग की निम्नलिखित मुख्य समस्याएँ हैं—

(१) वित्त—इस उद्योग को नई मशीनें लगाने तथा पुरानी मशीनों को ठीक करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है । इस कार्य के लिये ३ १५ करोड़ डालर का एक ऋण विश्व बैंक से प्राप्त किया गया है ।

(२) श्रम—उद्योग के सम्मुख दूसरी मुख्य समस्या श्रम की है । श्रमिक कार्य तो करना चाहते हैं, परन्तु वे ऊँची मजदूरी लेकर कार्य करने को तैयार होते हैं । श्रम की कार्यक्षमता में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(३) सरकारी नीति—सरकार की इस उद्योग के प्रति कोई सन्तोषजनक नीति नहीं है । सरकार निजी पूँजी को अधिक प्रोत्साहित नहीं करना चाहती, वह उसकी ओर धका की दृष्टि से देखती है । इस कारण से उद्योगपति अपना धन उद्योग में लगाने से डरते हैं ।

(४) श्रैष्ठ कोयले का अभाव—उद्योग के लिये आवश्यक श्रैष्ठ कोयले का अभाव है । भारत में श्रैष्ठ कोयला (कोकिंग) बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है । साथ ही, यहाँ पर अच्छे कोयले का प्रयोग रेलगाड़ियों को चलाने में भी किया जाता है ।

(५) कर्मचारियों का प्रशिक्षण—नव निर्मित इस्पात के प्रत्येक कारखाने के लिये ६७० इन्जीनियर तथा अन्य उच्च निरीक्षक एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसके साथ ही ६,३०० कारीगर एवं शिक्षित मजदूर भी चाहिये । भारत में योग्य कारीगरों, इन्जीनियरों, श्रमिकों, कर्मचारियों का अभाव है, क्योंकि इस उद्योग का विकास हुए यहाँ अधिक समय नहीं हुआ है । अतः उद्योग के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी महत्वपूर्ण समस्या है ।

इस समस्या के हल के लिये निजी क्षेत्र में प्रयत्न जारी हैं । सरकार की ओर से २४१ इन्जीनियर रूस में प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजे गये हैं, कुल ६८३ इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देना है । कर्नेला एवं दुर्गापुर कारखानों के लिये फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से अमेरिका में बहुत से इन्जीनियरों को प्रशिक्षण दिया जावेगा । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन में भी ३०० इन्जीनियरों को दुर्गापुर कारखाने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

जमशेदपुर में भी प्रशिक्षण का एक विशाल केन्द्र चल रहा है, जिसमें विदेशों को जाने के पूर्व इन्जीनियरों का प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस प्रकार सरकार इस समस्या की ओर पूरा ध्यान दे रही है ।

(६) उत्पादन की लागत—इन कारखानों में निर्माण पर जो अधिक खर्च पड़ रहा है, उससे तैयार इस्पात की लागत भी अधिक पड़ेगी । इन कारखानों में पूँजी अधिक लगने के कारण उत्पादन लागत अधिक पड़ेगी । किन्तु इस समस्या को

संचालन लागत कम करके हल किया जा सकता है। नये कारखानों में नये यन्त्रों को चलाने से कम मनुष्यों की आवश्यकता होगी। इनका अच्छा संगठन होने की आशा है, फलतः पूँजीगत लागत अधिक होने पर भी उत्पादन लागत के बराबर ही पड़ेगी।

(७) विवेकीकरण एवं आधुनिकीकरण—उत्पादन की लागत की समस्या को सुलझाने के लिये उद्योग का विस्तार एवं नवीनीकरण किया जाना चाहिये। उत्पादन व्ययों में अभिनवीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध के द्वारा भी कमी की जा सकती है। हमारी औद्योगिक नीति भी ऐसी होनी चाहिये, जिससे उद्योग का पर्याप्त विकास हो सके। फोर्ड फाउण्डेशन को रिपोर्ट के अनुसार बिना विवेकीकरण के भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता एवं दक्षता का अनावश्यक रूप से ह्रास होता है। आधुनिकीकरण के अभाव में वे वर्तमान टेक्नोलॉजी का सदुपयोग नहीं कर पाते। फलतः अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी टिकना कठिन हो सकता है। आधुनिकीकरण के विरोध में श्रम सघों की जो दलीले हैं वे पूर्णतः यथोक्ति प्रतीत होती हैं और उनका हटता के साथ सामना किया जाना चाहिये। हाँ, यह अवश्य है कि विवेकीकरण के परिणामस्वरूप जिन श्रमिकों की छंटनी हो जाये, उनको रोजगार देने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।

(८) कर की समस्या—गणनछुम्बी करारोपण ने भी भारतीय उद्योग-पतियों को निरस्तसाहित किया है। सन् १९४८ की अपेक्षा आज भारत सरकार ने सम्पत्तियों पर मूल्य-ह्रास की दर को काफी बढ़ा दिया है और इसके लिये भारत सरकार बर्धाई की पात्र है, परन्तु फिर भी हमारे उद्योगपति यह अनुभव करते हैं कि आय कर व सुपर टैक्स की दरें बहुत ऊँची हैं, जिसके कारण वे विस्तार व आधुनिकीकरण से सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी का संचय नहीं कर पाते।

लौह-इस्पात परामर्शदाता समिति—

६ फरवरी सन् १९६० को लौह एवं इस्पात परामर्शदाता समिति की प्रथम बैठक हुई, जिसमें देश के विभिन्न इस्पात उद्योगपतियों ने इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। एसोसियेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सर वाल्टर मिचेल मोरा (Sir Walter Michelmora) ने श्रृंखला किसिम के कोयले एवं विद्युत के अभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने सकेत किया कि रेलों के विद्युतीकरण से लौह एवं इस्पात उद्योग के लिये 'शक्ति' की समस्या अत्यन्त गहन हो जायेगी, क्योंकि उत्पादित विद्युत शक्ति का उपयोग रेलों में अधिक किया जायेगा। 'टिस्को' के श्री स्लीटस (Mr. Sleetus) ने यह सुझाव दिया कि इस्पात के मूल्यों में कुछ कमी की जानी चाहिये। उन्होंने इस बात की भी सिफारिश की कि देश के इस्पात उद्योग की उचित प्रगति के लिये एक उच्च स्तरीय वैधानिक बोर्ड स्थापित किया जाये। इण्डियन गवर्नमेंट एण्ड स्टील के श्री कपूर (Mr. Kapoor) ने सुझाव दिया कि देश में इस्पात के उपभोग की प्रवृत्ति का अध्ययन करने से भी बहुत लाभ हो सकता है। मद्रास के स्वामी एम० एल० ए० ने बतलाया कि भारत के दक्षिण में इस्पात की

बहुत कमी है, अतएव इसके उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिये। फंडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर एण्ड कॉमर्स इण्डस्ट्रीज के थी जी० एल० बन्सल (Mr G. L. Bansa) ने इस्पात के वितरण पर से नियन्त्रण हटाने का सुझाव दिया।

तृतीय पंच-वर्षीय योजना में उद्योग—

इसमें १०२ लाख टन इस्पात के ढोके और १५ लाख टन बिक्री के लिए लोहा बनाने का लक्ष्य है। निजी उद्योग का हिस्सा ३२ लाख टन इस्पात होगा। इस समय निजी उद्योगों की क्षमता ३० लाख टन की है। २ लाख टन इस्पात, निजी क्षेत्र में कतरनों और पुराने लोहे को मलाने वाली बिजली की भट्टियों में बनेगा। इसी तरह निजी क्षेत्र के कारखानों में बिक्री के लिए ३ लाख टन लोहा भी बनेगा। सरकारी क्षेत्र में सबसे जरूरी काम होगा कि दूसरी योजना में जो इस्पात कारखाने कायम हुए हैं उनमें पूरी क्षमता से उत्पादन कराना। तीसरी योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने के विस्तार का और बोकारो में नया इस्पात कारखाना लगाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा नैबेली के लिगनाइट से चलने वाला लोहे का कारखाना भी खोला जायगा। बोकारो में २० लाख टन इस्पात के ढोके बनाने का लक्ष्य है, पर प्रारम्भ में १० लाख टन बनाने की मशीन लगायी जाएगी। सरकारी क्षेत्र में इस्पात बनाने के इन कार्यक्रमों पर कुल ५२५ करोड़ ४० लाख रुपये का अनुमान है। थोड़े तौर पर अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में देश में २४० लाख टन तैयार इस्पात बनेगा। इसमें ३ लाख सन् १९६५-६६ में बोकारो के कारखाने में बनने की आशा है।

इसके अनिश्चित १३ मिलियन टन पिग आयरन के उत्पादन की आशा है, जिसका उपयोग बिक्रय के लिए किया जायेगा।

उपसंहार—

६ फरवरी सन् १९६० को हुई लोह-इस्पात परामर्शदाता समिति की प्रथम बैठक में केन्द्रीय इस्पात एवम् ईंधन मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने बतलाया कि देश में लोह एवम् इस्पात उद्योग का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। उन्होंने यह सकेत किया कि निकट भविष्य में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जायेगा, जो निजी व राजकीय क्षेत्र के इस्पात के कारखानों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं (विशेषतः कच्चे माल की पूर्ति से सम्बन्धित) की सतुष्टि का ध्यान रखेगा।

उसी अवसर पर उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने बतलाया कि अभी एक-दो वर्ष तक हमारे पास इस्पात का आधिक्य नहीं होगा। क्योंकि हमारे निजी आवश्यकताएँ ही बहुत हैं। यदि थोड़ा बहुत आधिक्य होगा भी तो उसके लिए हमको निश्चय बाजार मिल जायगा। जिन जिन देशों से भारत के व्यापारिक सम्बन्ध हैं, उनमें से अनेक ने ५-५, ७-७ वर्ष के लिए लोह इस्पात आयात करने की इच्छा प्रकट की है। इससे उद्योग के उज्ज्वल भविष्य का आभास मिलता है।

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the origin, progress, present position and problems of the Iron and Steel Industry.
2. Discuss the principal problems of the Indian Iron and Steel Industry and suggest remedies to solve them.

अध्याय ६५

भारतीय चीनी उद्योग

(Indian Sugar Industry)

प्रारम्भिक—

भारत के संगठित उद्योगों में सूती कपड़े के बाद चीनी उद्योग ही प्रमुख उद्योग है। यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। जब विश्व के अन्य देश इस वस्तु के मामले में अनभिज्ञ थे, उस समय भारत इसमें परिचित था। ईसा के चार शताब्दी पहले कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में गन्ने के द्वारा चीनी बनाने तथा बीरे से मध्यसार निकालने की विधियों का उल्लेख किया है। १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सूरत व कालीकट से बहुतसी सफेद चीनी और खाद्य निर्यात की जाती थी। बनारस की निमित्त चीनी विदेशों में बड़ी प्रसिद्ध थी और देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इससे होती थी। आज भी हमारे देश में ससार की कुल गन्ने की उपज का २६% भाग होता है। सरकार को इस उद्योग से लगभग ८५ करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। उद्योग की कार्यशील पूँजी भी १०० करोड़ रुपये से अधिक है।

उद्योग का विकास—

भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की नींव सन् १८६६ में पड़ी; जबकि सरकार ने चीनी के आयात पर कर लगा दिया। इस प्रतिबन्ध को भाड़ में चीनी के आधुनिक कारखाने उत्तरी भारत में खोले गये, परन्तु शताब्दी के प्रारम्भ में प्रायः यह कुटीर-उद्योग अवनति कर रहा था। उत्पादन के ढंग अर्धज्ञानिक थे, जिससे कीमत

अधिक होती थी और भारत अन्य देशों की स्पर्धा में लड़खड़ा रहा था । प्रथम युद्ध तक आते-आते भारत इसके उपभोग के लिये आयात पर निर्भर हो गया । सन् १९०१-१९२० के मध्य भारतीय गन्ने की नस्ल सुधारने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये । सन् १९०१ में गन्ने के सुधार के लिए एक अनुगन्धान केन्द्र खोला गया । सन् १९१६-२० में एक चीनी समिति भी स्थापित की गई । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप गन्ने का उत्पादन बढ़ा ।

उद्योग की संरक्षण—

सन् १९२६ में चीनी समिति ने सिफारिश की कि आधुनिक ढंग के चीनी के कारखाने खोलने पर विचार किया जाय और विदेशों से चीनी आयात करने में करोड़ों रुपयों की हानि को रोका जाय । फलतः भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए टैरिफ बोर्ड नियुक्त किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इस उद्योग को सन् १९३१ से १५ वर्षों के लिए संरक्षण देना स्वीकार किया । संरक्षण के लिए चीनी के आयातों पर पहले सात वर्षों के लिए ७५ प्रति हन्डरवेट के हिसाब से संरक्षण कर लगाया । सन् १९३१ में चीनी का आयात १० लाख टन था, जो सन् १९३६-३७ में १६ हजार टन रह गया । आयात के कम होने से जो हानि हुई उसकी पूर्ति के लिए आधनारी कानून के अन्तर्गत २१) प्रति हन्डरवेट की दर से कर लगाया गया । गन्ने के क्षेत्र में भी वृद्धि की गई । सन् १९-१-३२ में भारत में कुल ३२ चीनी मिलें थी, किन्तु अगले पाँच वर्षों में ही संख्या ३२ से बढ़कर १३० हो गई । निम्न-लिखित तालिका से चीनी उद्योग का आभास मिलता है—

चीनी उद्योगों का विकास

वर्ष	मिलों की संख्या	गन्ने का उत्पादन (हजार टनो में)
१९३१-३२	३२	१,६०
१९३८-३९	१३२	६,४२
१९४५-४६	१३८	६,२३
१९५०-५१	१३९	११,१६
१९५५-५६	१४३	१८,५६
१९५६-५७	१६६	२०,३९
१९५७-५८	—	२०,०६
१९५९	—	२०,८४

उत्पादन बढ़ने ही चीनी का मूल्य बहुत बढ़ गया तथा पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ने लगी ।

सन् १९३७ में भारतीय चीनी संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा दूर करना, बिक्री का नियमन एवं उद्योगों को सङ्गठित करना था। इसके प्रयत्नों से चीनी बाजार की दशा में सुधार हुआ। सरकार ने कुछ कानून बनाये, जिसे सब मिलें इस सघ की सदस्य बन जायें। जब मूल्य अनुचित रूप से बढ़ने लगे, तो सरकार ने इससे मान्यता हटा ली। फलतः अधिकांश मिलें इस सघ से हट गईं और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा फिर बढ़ गई। सन् १९४० में उद्योगपतियों की प्रार्थना पर सरकार ने सघ को फिर मान्यता दे दी, किन्तु निम्न शर्तों का पालन आवश्यक कर दिया— सघ केवल बिक्री एजेंट का कार्य करेगा, प्रत्येक मिल के लिए उत्पादन-कोटा निश्चित किया जायगा और सघ को एक चीनी आयोग की देख-रेख में काम करना पड़ेगा। एक चीनी आयोग नियुक्त हुआ, जिसका कार्यवाहक एक सरकारी अफसर था।

द्वितीय महायुद्ध एवं इसके बाद—

द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होते ही चीनी का मूल्य बढ़ने लगा। देश में चीनी का उत्पादन इतना कम हो गया था कि देश की भीतरी माँग भी पूरी न हो सकी। सन् १९४२ में सरकार ने चीनी के मूल्य और वितरण पर नियन्त्रण लगा दिया। नगरो में चीनी का राशनिंग चालू किया गया। चीनी बन्दोबस्त गन्ने और चीनी का मूल्य निश्चित करता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में चीनी का आयात भी नियन्त्रित हो गया। गन्ने की स्थिति में सुधार करने के लिए सन् १९४४ में एक भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति स्थापित की गई। फिर भी चीनी का उत्पादन कम होता चला गया और आयात न होने के कारण देश में चीनी की कमी हो गई, कीमत ५ गुनी बढ़ गई और चोरबाजारी का प्रकोप हो गया। नियन्त्रण सन् १९४७ तक चलता रहा, किन्तु बाद की गान्धीजी के प्रयत्नों के कारण इसे हटा लिया गया। नियन्त्रण हट जाने से उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, किन्तु चीनी उद्योग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, अतः सरकार को फिर नियन्त्रण चालू करना पड़ा। सरकार ने मूल्य, वितरण तथा उत्पादन के नियमन का उत्तरदायित्व अपने अन्तर्गत कर लिया। चीनी का उत्पादन बढ़ने के कारण सरकार ने चीनी सघ के परामर्श से चीनी का मूल्य ३५।३३) मन निश्चित किया और गन्ने का मूल्य उत्तर-प्रदेश में १।) मन से बढ़ाकर २) मन कर दिया। इस प्रकार नियन्त्रण अधिक व्यापक हो गया।

सन् १९५० में १८ वर्ष पुराना सरक्षण समाप्त कर दिया गया और सन् १९५०-५१ में भारत सरकार ने एक 'मुक्त-चीनी' योजना बनाई, जिसके अनुसार चीनी मिलें अपना अधिकतम कोटा उत्पन्न करने के बाद अपनी फालतू चीनी खुले बाजार में बेच सकती थी। परिणामतः उत्पादन बढ़ने लगा। सन् १९५०-५१ में १२ लाख टन उत्पादन था, जो सन् १९५१-५२ में १४.६ लाख टन हो गया। ३० जून सन् १९५६ तक चीनी की उत्पाति १८.३ लाख टन हो गई। देश में चीनी की खपत इस समय १८ लाख टन है। इस प्रकार आज हम केवल आत्म-निर्भर ही नहीं, विदेशों को निर्यात करने की स्थिति में भी हैं।

चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति—

भारत में चीनी-उद्योग एक प्रमुख वृहत उद्योग है। देश में आजकल १५८ चीनी मिलें हैं। गन्ने की उत्पत्ति करने में २ करोड़ किसान लगे हुए हैं और उद्योग में ७७,००० मजदूर काम करते हैं। देश में केवल २५% गन्ना चीनी बनाने के काम आता है, बाकी का गुड़ बनाया जाता है। देश में हर साल लगभग ८८ करोड़ रुपये की चीनी व १ अरब रुपये का गुड़ तैयार होता है। दक्ष में ईख के क्षेत्र का भार्व से अधिक भाग (२०,४६,००० एकड़) उत्तर-प्रदेश में है। इसके बाद पंजाब में ६,२४,००० एकड़ में, बिहार में ३ लाख एकड़ में, बम्बई में १,६२,००० एकड़ में, मद्रास में १ लाख १७ हजार एकड़ में, आन्ध्र में १,१३,००० एकड़ में, हैदराबाद में ६२ हजार एकड़ में, बेंगलूर में ५७ हजार एकड़ में, पश्चिमी बंगाल में ४७ हजार एकड़ में और मध्य प्रदेश में १४,००० एकड़ में ईख बोई जाती है। उत्तरी भारत में ईख की उपज बढ़ाने का यत्न किया जा रहा है। इसके लिये उत्तर-प्रदेश, बिहार और पंजाब के किसानों को रासायनिक खाद उधार दी जा रही है, जिसे फसल के बाद चुकाया जा सकता है। भारत सरकार इन तीन राज्यों में गन्ने की उपज बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है, जिससे देश आत्म निर्भर हो सके। इसके अलावा एक विशेषज्ञ समिति समस्त देश के ईख क्षेत्र के साभार्थ योजना तैयार कर रही है। उन्नति का कार्य मद्रास, आन्ध्र, पश्चिमी बंगाल में भी किया जा रहा है।

उत्पादन—

निम्न आंकड़ों से चीनी के वर्तमान उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है—

वर्ष	उत्पादन (हजार टनो में)
१९५३	१,२६१२
१९५४	१,००२०
१९५५	१,५६४८
१९५६	१,८५६४
१९५७	२,००७६
१९५८	२,००७६
१९५९	१,६१६०
१९६०	२,४४४०
१९६१—	
जनवरी	५४१३
फरवरी	५२१८

पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उद्योग—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सरकार ने सन् १९५५-५६ तक उत्पादनक्षमता लक्ष्य १.५५ मि० टन रखा था तथा प्रति व्यक्ति उपभोग का लक्ष्य ८.७ पौण्ड रखा था, जबकि युद्ध-पूर्व का उपभोग औसत ६.६ पौण्ड था। गन्ने का अतिरिक्त उत्पादन-लक्ष्य ७,०३,००० टन (गुड) रखा गया था। योजना के प्रथम वर्ष में गन्ने की ऊँची कीमत के कारण गन्ने के उत्पादन तथा खेती में बड़ी वृद्धि हुई और चीनी का उत्पादन लगभग १५ लाख टन हुआ, परन्तु सन् १९५१-५२ में १.४० १२ आना प्रति मन से सन् १९५२-५३ में १.४० ५ आना तथा सन् १९५३-५४ में १.४० ७ आना गन्ने का मूल्य हो जाने से खेती तथा पैदावार दोनों में कमी हो गई थी। तीसरी योजना में प्रतिवर्ष ३५ लाख टन चीनी बनाने का लक्ष्य है। आशा है कि इसका २५% सहकारी कारखानों में दमेगा। देश की जरूरत पूरी होने के बाद कुछ चीनी बच रहेगी जो निर्यात की जायेगी।

चीनी-उद्योग की विशेष समस्याएँ—

चीनी-उद्योग के सामने निम्न समस्याएँ हैं, जो इसकी प्रगति में बाधक हैं—

(१) प्रति एकड़ पैदावार में कमी—उत्तरी भारत में प्रति एकड़ लगभग १४-१५ टन और दक्षिणी भारत में २० टन गन्ना उगाया जाता है, जबकि जावा तथा हुआई द्वीपों में यह क्रमशः ५६ और ६२ टन है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण भाई देश के अधिकतर गन्ने का गुड बना लेते हैं। इससे चीनी उद्योग को पर्याप्त क्षति होती है।

(२) गन्ने की निम्न कीटि—भारतीय गन्ने की किस्म में बहुत खराब है। गन्ने में चीनी की मात्रा कम होती है। सन् १९४७-४८ में गन्ने से केवल ८.५% चीनी निकलती थी, जबकि जावा, फारमूसा और व्हीलैण्ड में क्रमशः ११.४६, १२.०५ और १४.२२% निकलती है।

(३) गन्ने का अधिक मूल्य—भारत में सरकार गन्ने का मूल्य निश्चित करती है, जो चीनी की कुल लागत का ६०% होता है, अतः मिल मालिकों का कथन है कि उनकी कुछ भी बचत नहीं होती। गन्ने का इतना अधिक मूल्य इसलिए है कि भारत में चीनी मिलों के पास अपने बड़े-बड़े खेत नहीं हैं, बरन् किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उसे छोटे-छोटे अनाधिक खेती पर उगाते हैं। मूल्यों के सम्बन्ध में एक समस्या यह भी है कि गन्ने का मूल्य केवल तेल के आधार पर तय किया जाता है, किस्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसमें मिलों को काफी हानि होती है।

(४) त्रुटिपूर्ण स्थानीयकरण—देश की अधिकांश मिलें उत्तरी भारत में स्थिति है, जहाँ गन्ना बहुत कम होता है और उनमें पारस्परिक स्पर्धा बढ़ जाती है, लेकिन मद्रास में जहाँ पर्याप्त गन्ना उत्पन्न होता है, मिलों की कमी है।

(५) ऊँचे कर—भारत में चीनी पर उत्पादन कर केन्द्रीय सरकार लगाती है और गन्ने पर उप-कर (Cess) राज्य सरकारें लगाती हैं। इन करों की आय का बहुत सा घन दूसरे कामों में लगा दिया जाता है।

(६) उत्तोत्पाद का अभाव—चीनी के उद्योग के सहारे अल्कोहल तथा पट्टे के उद्योग भी चल सकते हैं, परन्तु अभी तक इस प्रकार के उद्योग बहुत कम चलाये गये हैं। चीनी से और भी बहुत सी चीजें बनाने की सम्भावना है, जैसा कि डाक्टर एच० बी० हेस (यू० एस० सुगर रिसर्च फाउन्डेशन के अध्यक्ष) ने कहा था—“यदि हमारा धन चलेगा तो एक दिन तुम चीनी पहनाओगे, चीनी से सफाई करोगे, चीनी को रंगों व प्लास्टिक के काम में लाओगे, अपने पौधों पर छिड़कोगे, अपने पशुओं को खिलाओगे।”

(७) ई धन की कमी—ई धन की कमी को दूर करने के हेतु वाष्प के प्रयोग में मितव्ययिता करने की आवश्यकता है, जिससे उत्पादन व्यय कम हो कर कीमत भी गिरें।

उन्नति के लिए सुझाव—

उद्योग की प्रगति के लिए उक्त समस्याओं का हल करना आवश्यक है। चीनी के उद्योग के सुधार के लिए योजना आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं :—

- (अ) नई मिलों की स्थापना करने की अपेक्षा पुरानी मिलों के विस्तार का प्रयत्न करना चाहिए।
- (आ) जो मिलें गन्ने की पूति के स्थानों से दूर बसी हैं उनकी अपनी स्थिति बदलनी चाहिए, जिससे भाटे में बचत हो।
- (इ) गन्ने के उप-कर को गन्ने के अनुसन्धान पर खर्च किया जाय।
- (ई) उद्योग को मशीनें प्राप्त करने की सुविधा दी जाय, जिससे वे घिसी हुई पुरानी मशीनों को हटा सकें।
- (उ) सरकार को समय-समय पर चीनी के उत्पादन पर नियन्त्रण, गुड व चीनी के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर विचार करते रहना चाहिए, जिससे उद्योग की उचित उन्नति हो सके।
- (ऊ) किसान के गन्ने का मूल्य वजन के अनुसार न दिया जाय, बरन् गन्ने में चीनी की मात्रा के अनुसार दिया जाय, जिससे किसान गन्ने की किस्म को सुधारने का प्रयत्न करे।

चीनी उद्योग की विकास सभा के सुझाव पर भारत सरकार ने एक प्रतिनिधि मण्डल आस्ट्रेलिया व इण्डोनेशिया भेजा था, जिसकी रिपोर्ट सन् १९५६ में प्रस्तुत हुई। इसमें चीनी-उद्योग की उन्नति के लिए निम्न सुझाव दिए गये हैं :—

- (१) चीनी के मूल्य पर कन्ट्रोल न लगाया जाय, क्योंकि भारत तथा आस्ट्रेलिया का अनुभव है कि इनके कारण उद्योग के विकास में बाधा पड़ती है।
- (२) चीनी व गुड की वित्री के लिए कोई केन्द्रीय सभा नियुक्त न की जाय।
- (३) चीनी के मूल्य तथा वेंटवारे पर जो नियन्त्रण है तथा सरकार जो २५% चीनी को नियन्त्रित मूल्य पर खेचने का अधिकार रखती है और चीनी को विदेशों में मंगाकर उसकी निश्चित मूल्य पर बेचती है, उस नीति को वर्तमान में कायम रखा जाय।
- (४) सरकार को

चाहिए कि हर वर्ष गुड की न्यूनतम कीमत निश्चित करे, जिससे गुड व चीनी के मूल्य तथा उत्पत्ति में समन्वय रहे । यदि गुड का मूल्य बाजार में निश्चित मूल्य से कम हो, तो स्वयं उसे खरीदे तथा गुड के खरीदने के लिए गुड के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ स्थापित करे । (५) गन्ने का मूल्य निश्चित करने में परामर्श देने के लिए सरकार को एक स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त करनी चाहिये, जिसमें गन्ना उगाने वाले व मिलों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि हों और जिसका सभापति एक जज हो । (६) गन्ना उगाने वालों को गन्ने का मूल्य उनके गुण के अनुसार दिया जाय । (७) गन्ने की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किये जायें—

(अ) गन्ने का उन्नत बीज होना तथा गन्ने को बीमारियों से बचाना, (आ) प्रास्ट्रेलिया तथा जावा से बढ़िया गन्ने का आयात करना और उसे भारत में उत्पन्न करने का प्रयत्न करना । गन्ने के विभिन्न प्रकारों को अलग-अलग मिट्टियों तथा जलवायु में उगा कर देखना व किसानों को उगाने के लिए देना, (इ) चीनी उत्पन्न करने के विषय में एक अखिल भारतीय पत्रिका चालू करना, (ई) एक से अधिक मिलों वाले क्षेत्रों में गन्ने के कीड़े तथा रोगों को रोकने वाले बोर्ड स्थापित करना । (ए) शीरे पर अनुभव करके देखना कि वह कहाँ तक पशुओं के उपयोग में काम आ सकता है, उससे शक्ति उत्पादन की सम्भावनाएँ देखना व खोई से पट्टा बनाना । शीरे का उचित बँटवारा करने के लिए उसे केन्द्रीय सरकार के आधीन खाना । (१) गन्ने के मोम को साफ करने के लिए अनुसन्धान करना, जिससे वह बहुत से उद्योगों के काम आ सके । (१०) प्रास्ट्रेलिया की भाँति गन्ना उगाने तथा चीनी बनाने वालों की संस्थाएँ स्थापित करना । (११) भारतीय ट्रेड मिशनो तथा दूतावासों द्वारा विदेशों में गुड के बाजार तलाश करना । (१२) चीनी अनुसन्धान की स्थापना करना व अनुसन्धान करने वाले लोगों को विदेशों में भेजना । (१३) फल वाली वस्तुओं तथा दूध वाले उद्योगों को कम मूल्य पर चीनी देना । (१४) वर्तमान मिलों को बढ़ाना, न कि नई मिलें स्थापित करना । (१५) विदेशों से खेती के औजार तथा चीनी उत्पन्न करने वाली मशीनों को बिना किसी आयात कर लगाये भेजना ।

अध्याय ६६

भारतीय कोयला उद्योग

(Indian Coal Industry)

प्रारम्भिक—

‘काला हीरा’ अर्थात् कोयला आधुनिक उद्योग का जन्मदाता है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधनों में से एक है। सारे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भारत दूसरे नम्बर का एवं विश्व में आठवें नम्बर का उत्पादक है। कोयला निकालने के सम्बन्ध में सबसे पहला अधिकृत बर्लान सन् १७७४ ई। है, जबकि चार्ल्स हेस्टिंग्स ने मैसर्स सैमनर एण्ड व्हीटले को बङ्गाल में कोयले की खानों से कोयला निकालने की आज्ञा प्रदान की। यह प्रयत्न असफल रहा और इसके बाद सन् १८१४ तक अन्य कोई प्रयत्न न हुआ। इसी वर्ष रानीगंज के निकट कोयला निकालने का काम पुनः आरम्भ किया गया। सन् १८६० तक वार्षिक उत्पादन ३,००,००० टन हो गया। सन् १८५५ में कलकत्ते की ई० आई० रेल्वे ने इस क्षेत्र का उपयोग किया और इस प्रकार उद्योग का भविष्य सुरक्षित हो गया। सन् १८६८ के बाद कोयले के उत्पादन में प्रशस्तनीय प्रगति हुई। निम्नलिखित आँकड़े इस बात के साक्षी हैं—

कोयले का उत्पादन*

वर्ष	उत्पादन (लाख टनो में)
१८६८	५
१८८०	१०
१८९०	२२
१९००	६१
१९१०	१२०
१९२०	१८०
१९२०	२३८

१९४०	२५१
१९४६	२६०
१९५०	३२०
१९५५	३८२
१९५६	३९४
१९५७	४३५
१९५८	४५३
१९५९	४७०
१९६०	५१३

सन् १८७१ में रेलवे ने गिरडीह क्षेत्र में प्रवेश किया और शताब्दी के आरम्भ से इस क्षेत्र का उत्पादन ३० लाख टन हो गया। झरिया के क्षेत्र में भी विकास हुआ। डाल्टनगंज क्षेत्र, रीवा राज्य, मध्य प्रान्त, हैदराबाद, आसाम और विलोचिस्तान के क्षेत्र भी विकसित हुए। सन् १९००-०१ में आयात १,४२,४६७ टन, निर्यात ५,४२,०२३ टन और उत्पादन ६१,१८,६६२ टन था, जिसका लगभग ६०% बंगाल व बिहार से प्राप्त हुआ। सन् १९१४ तक कुल उत्पादन बढ़कर २६० लाख टन हो गया।

प्रथम महायुद्ध और उद्योग—

बड़ी हुई औद्योगिक कार्यवाहियों के दबाव से कोयले की माँग उसकी पूर्ति से अधिक हो गई और इस अवधि भर उद्योग का यह प्रयत्न रहा कि यह बढ़ती हुई माँग के साथ अपनी गति कायम रखे। उत्पादन तेजी से सन् १९१८ में २०० लाख टन हो गया। इसका ८५% उत्पादन रानीगंज और झरिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ। कोकिंग कोल की माँग एक दम बढ़ गई थी, अतः बोकारो के कोयला क्षेत्र का अत्यधिक विकास किया गया। कोक के यन्त्र कुल्टी में और झरिया क्षेत्र की खोदना कोयला खान के पास लगाये गये। यही नहीं, कोयला-क्षेत्रों का विद्युतीकरण तेजी से किया गया और दो केन्द्रीय विद्युत स्टेशन बनाये गये।

लेकिन युद्ध-काल का यह विकास सीमित था और मशीन एवं यन्त्र मिलने की कठिनाई के कारण जारी न रह सका। वृद्धि का क्रम सन् १९१९ में अपने सर्वोच्च बिन्दु पर पहुँच गया और इसके बाद उत्पादन में कमी आरम्भ हुई। आकावादी प्रबन्धकों ने अपने लाभों को भी उद्योगों में ही विनियोग कर दिया। युद्धोत्तर-काल की घटती इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा भट्टियाँ बनाया था, जिन्होंने सन् १९२२ से कार्य आरम्भ किया। माँग में कमी होने के साथ यह कठिनाई भी हुई कि अम सस्ते हुए और निर्यात व्यापार में तेजी से कमी आई। सरकार की नीति के कारण स्थिति में सन् १९३६ तक कोई सुधार नहीं हो सका। आर्थिक मंदी का तत्कालीन प्रभाव मूल्य गिराना था और वास्तव में इस गिरावट के कारण ही उत्पादन में अधिक कमी हुई। सन् १९३६ के बाद औद्योगिक बाजारों में तीव्रता से वृद्धि हुई, जिसका प्रभाव यह हुआ कि कोयले की माँग पुनः बढ़ने लगी।

द्वितीय महायुद्ध के बाद—

द्वितीय महायुद्ध ने, जो सितम्बर सन् १९३९ में आरम्भ हुआ, कोयला उद्योग को पिछले दो दशान्दों में हुई गम्भीर निराशा से उभरने की सामर्थ्य प्रदान की। माँग बढ़ने से मूल्यों में सुधार हुआ। कोयले की कमी घटती हुई यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों और कोयले के घिरते हुये आयात के कारणों और भी अधिक अनुभव होने लगी। फिर सैनिक योजनाओं में थमिकों को अधिक अच्छा काम मिलने लगा, अतः उत्पादन में बड़ी कमी आ गई। अन्त में, सन् १९४४ के मध्य तक मूल्यों पर बड़ा नियन्त्रण रखना आवश्यक हो गया। इस बात का भी प्रबन्ध किया गया कि आवश्यक उपभोक्ताओं को कोयला एक योजनाबद्ध क्रम से ही प्राप्त हो। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिये कोयला क्षेत्रों से बाहर अमिकों की भरती करके, बीनस, ह्रास और प्रतिरिक्त लाभ-कर के सम्बन्ध में रियायतों के रूप में आर्थिक प्रलोभन देकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न भी किया। इन उपायों से उत्पादन में वृद्धि हुई।

पच-वर्षीय नियोजन के अन्तर्गत कोयला उद्योग—

प्रथम पच-वर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था; अतः सन् १९५५ में केवल ३८१,३० लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ। किन्तु द्वितीय योजना में ६ करोड़ टन कोयला खोदने का लक्ष्य रखा गया था। पर्याप्त सन् १९५५ के उत्पादन से २ करोड़ २० लाख टन अधिक। इसमें से १ करोड़ २० लाख टन सरकारी खानों के जिम्मे रखा गया और शेष १ करोड़ टन निजी खानों के। जो सरकारी निजी खानें पहले से चल रही थी, उनके उत्पादन को बढ़ाने में तो कठिनाई नहीं हुई, किन्तु नई खानों के विकास में काफी कठिनाइयाँ पड़ीं। खानों का पता लगाने और उन्हें प्राप्त करने में काफी समय लगा। इसने अलावा विदेशी मुद्रा और खनन कार्य में दक्ष कर्मचारियों की भी कमी थी। इसलिए सन् १९६०-६१ से ५ करोड़ ४६ लाख २० हजार टन का ही उत्पादन हो सका, जबकि लक्ष्य ६ करोड़ टन का था। परन्तु सन् १९६०-६१ वर्ष की अन्तिम तिमाही में जिस गति से कोयला खोदा गया है उससे वार्षिक उत्पादन ६ करोड़ टन से अधिक हो जायेगा। सन् १९५० में ३ करोड़ २३ लाख १० हजार टन कोयला खोदा गया था, जबकि सन् १९५५ में ३ करोड़ ८२ लाख ३० हजार टन और सन् १९६०-६१ में ५ करोड़ ४६ लाख २० हजार टन कोयला खोदा गया।

सन् १९५२ में कोयला खान सुरक्षा और नवाम कानून बनाया गया, जिससे सरकार को कोयला भण्डारों की बरबादी रोकने का अधिकार मिला। खानों में छुदाई के बाद पीसी जगहों को भरना अनिवार्य बना दिया गया, लोहा बनाने के काम करने वाले कोयले की शुद्धि पर नियन्त्रण किया गया, ताकि इसकी बरबादी न हो। अर्थात् कोयले को धो कर अच्छा बनाने के लिये ४ केन्द्रीय धुलाई करखाने खोले गये और एक दुर्गापुर के इस्पतल कारखाने में खोला गया। दूसरी योजना में ६४ लाख टन कोयले की धुलाई का लक्ष्य था। इसमें से २४ लाख टन की क्षमता के धुलाई-खाने

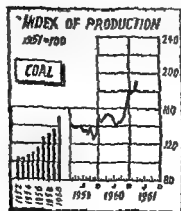
क्राफ्त हो गये हैं और बाकी तीसरी योजना के शुरू के वर्षों में तैयार हो जायेंगे। कोयले की बरबादी रोकने के लिए, गैर जरूरी कामों में कोकिंग या भ्रष्ट कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगायी गई और खानों को विशेष सहायता दी गई, जिनमें खुदाई बहुत गहराई में होती है या जिनमें गैस अधिक है। इसके अलावा छोटी छोटी और घाटे पर चलने वाली खानों को मिलाकर एक प्रबन्ध में लाने की कार्यवाई भी की जा रही है।

वर्तमान उत्पादन—

निम्नलिखित तालिका व मानचित्र से कोयले के वर्तमान उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है —

(In million tons)

Year	Private sector	Public sector			Total
		N	C	D C	
		Singareni			
1955	33 83		2 ९6	1 52	38 21
1956	34 76		2 99	1 68	39 43
1957	38 20		3 38	1 92	43 50
1958	39 54		3 66	2 11	45 31
1959	40 33		4 48	2 22	47 03
1960	43 34		5 95	2 48	51 78
1961			3 88	0 86	20 42
upto April 1961	15 68				(million tonnes)
upto June					29 20 (million tonnes)



तृतीय पंच-वर्षीय योजना में कार्यक्रम—

घनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक १७० लाख टन की मांग होगी । इसका अर्थ यह है कि दूसरी योजना के लक्ष्य से, जो ६ करोड़ टन था, ३७० लाख टन कोमला और बनाना होगा । यद्यपि दूसरी योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, पर लक्ष्यानुसार क्षमता उत्पन्न हो गयी है । तीसरी योजना में जितने अधिक कोयले की जरूरत है उसको निकालने के लिए सरकारी क्षेत्र में बहुत-सी नई खानें खोदनी पड़ेंगी । सन् १९६० में बढ़िया किस्म का कोकिंग कोयला १३० लाख टन निकाला गया था और २० लाख टन ऐसा था जो मिलाकर (ब्लेंड) काम आ सकता था । धातु उद्योग के लिये तीसरी योजना के अन्त तक कम से कम १०० लाख टन कैंकिंग कोयला और २० लाख टन स्लेडेबुल या मिसवां कोयला की मांग होगी । रेलों के लिए और अन्य उद्योगों के लिए करीब १०० लाख टन बढ़िया किस्म के गैर-कोकिंग कोयले की जरूरत होगी । इसलिए तीसरी योजना में मुख्य काम यह होगा कि इस्पात कारखानों की और रेलों आदि अन्य उद्योगों को उपयुक्त कोटि का कोयला मध्यम मात्रा में मिलता रहे ।

सरकार की नीति यह है कि नयी खानें सरकारी क्षेत्र में खोली जायें और निजी क्षेत्र में केवल वर्तमान खानों के विस्तार की ओर इससे लगी हुई खानों को खोदने की अनुमति दी जाए । इसलिये सरकारी क्षेत्र को २०० लाख टन और निजी क्षेत्र को १७० लाख टन कोयला और खोदने का काम सौंपा गया ।

सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम—सरकारी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश की सिंगारेण्टी खानों का उत्पादन ३० लाख टन बढ़ाया जाये और बाकी १७० लाख टन, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अन्य खानों से निकालेगा । निजी क्षेत्र की खानों में ११० लाख टन का भतिरिक्त उत्पादन वर्तमान खानों से और उन नयी खानों से होगा जो पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में हैं ।

सुरक्षा—अपने देश में कोकिंग कोयले का भण्डार केवल २८० करोड़ टन है । पर बढ़िया किस्म के लाहे का भण्डार बहुत अधिक है । इसलिए एक ओर तो कोकिंग कोयले की बरखादी रोकनी होगी और दूसरी ओर उसकी खानों की रक्षा करनी होगी और घटिया कोयले की धुलाई या बढ़िया के साथ दूसरा कोयला मिलाकर इसका भण्डार बढ़ाना होगा । बढ़िया कोयले की बरखादी रोकने के लिए कोयला परिषद की ईंधन कमेटी ने यह तय कर दिया है कि किसी उद्योग को किस किस्म का कोयला कितनी मात्रा में दिया जाये ।

खानों में भरवाई—तीसरी योजना में खानों की घोलि जगह की भरने पर अधिक जोर दिया जायेगा, क्योंकि इनमें से और कोयला खोदा जाएगा । खानों में भरने के लिए दामोदर नदी से बालू भेजी जाएगी । बालू ले जाने के लिए भरिया की खानों तक तार द्वारा पम्पवहन की चार लाइनें और रानीगंज की खानों तक ३ लाइनें लगाई जायेंगी, जिन पर बाल्टियों में बालू ले जाया जाएगा ।

परिवहन—कोयले की अधिकांश खानें बङ्गाल और बिहार में हैं। इसलिए इनके परिवहन में दिक्कत होती है। तीसरी योजना में अन्य क्षेत्रों में भी कोयला निकालने की कोशिश की जाएगी। साथ ही ट्रकों और जहाजों के जरिये भी कोयला भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

कोयला धुलाई के कारखाने—तीसरी योजना में इस्पात के अधिक उत्पादन के लिए १२७ लाख टन कोयले की धुलाई का और इन्तजाम करना पड़ेगा। जो धुलाई-खाने अभी हैं या जो बन रहे हैं उनमें ३२ लाख टन और कोयले की धुलाई हो सकेगी। बाकी के लिए नए धुलाई-खाने खोलने पड़ेंगे। इन धुलाई-खानों में रेलवे की जरूरत का गैर-कोईंग कोयला भी धोया जाएगा और खानों के कोयले की जाँच करके देखा जाएगा कि उनकी धुलाई हो सकती है या नहीं।

नैवेली लिगनाइट योजना—मद्रास के दक्षिण भरकाट जिले में नैवेली में भूरे कोयले का जो भण्डार है उसके विकास के लिए दूसरी योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम थे :—

(१) ३५० टन भूरा कोयला निकाला जाये जिससे

(क) २५० मे० वा० बिजली बनाने के कारखाने की आवश्यकता पूरी हो जाए,

(ख) यूरिया के रूप में ७० हजार टन नत्रजन-युक्त खाद बनाने के कारखाने की जरूरत को पूरा किया जाए, और

(ग) भूरे कोयले को फूँक कर ३ लाख ८० हजार टन कोयले के पिण्ड तैयार हो सकें।

(२) एक मिट्टी-धुलाई का कारखाना खुले, जिसमें प्रति वर्ष ६ हजार टन सफेद भीमी मिट्टी बन सके।

तीसरी योजना में उपर्युक्त कार्यक्रम पूरे किये जाएंगे। बिजलीघर की क्षमता १५० मे० वा० और बढ़ायी जाएगी तथा लिगनाइट का उत्पादन ३५० लाख टन से बढ़ाकर ४८० लाख टन किया जाएगा, जो बिजलीघर में काम आएगा।

कोयला उद्योग की समस्याएँ—

भारतीय कोयला उद्योग के सम्बन्ध में अनेक समितियाँ और बोर्ड कायम हुए तथा उनकी रिपोर्टें सरकार की आलमारियों में समाती जा रही हैं। वास्तव में द्वितीय महायुद्ध ने ही कोयले के उत्पादन, वितरण और मूल्यों पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से समझाया। वर्तमान कोयला उद्योग की निम्न समस्याएँ उल्लेखनीय हैं—

(१) श्रेष्ठ कोयले के भण्डार सीमित—कोक बनाने के कोयले के हमारे भण्डार सीमित हैं। मैटालर्जिकल कोल कन्जर्वेशन कमेटी के अनुसार, उच्च कोटि के कोयले का भण्डार केवल ३,२६६ लाख टन है, जो भारत की आवश्यकताओं को देखने हमें उम है। अगले वर्षों में इसकी खपत और बढ़ने की सम्भावना है, क्योंकि

देश में तीन नये स्पात कारखाने खुल रहे हैं। सही स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार भूगर्भ सर्वे विभाग द्वारा पुनः कोयला भण्डारों की खोज करा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकारों ने बढ़िया कोयले के इन भण्डारों को अधिक से अधिक समय तक चलाने के लिये निम्न कदम उठाये हैं—(१) बढ़िया कोयले का उत्पादन सीमित करना और धातु-शोधन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में इस कोयले का प्रयोग रोकना, (२) कोयले की धुलाई को प्रोत्साहित करना, जिससे उसमें राख का प्रश कम हो जाय और पहल व दूसरे ग्रैंड का घोंपा हुआ कोयला धातु शोधन के कार्य में प्रस्तुत किया जा सके और (३) जो खाने कोयला निकालने के बाद खाली हो गई हैं, उन्हें रेल मादि से भरना, जिससे शेष कोयला सुगमता से निकाला जा सके।

(२) रेलों की व्यवस्था—यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन में से कोयला इधर से उधर जाने की व्यवस्था रेलों कर भी सकेंगी या नहीं। कोयला अधिक ढालने की सामर्थ्य बढ़ा लेना कोई खिलवाड़ नहीं है। रेल प्रशासन की एक कठिनाई यह भी है कि जब किसी उद्योग को देश के दुर्गम भाग में स्थापित करने की योजना बनाई जाती है, तो रेल विभाग से यह सलाह नहीं ली जाती कि रेल आवश्यक परिमाण में बिना कठिनाई के उस उद्योग के लिये कोयला मादि पहुँचा भी सकेगी या नहीं।

(३) कोयला उद्योग का युक्तियुक्त संगठन—तृतीय पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य है कि कोयले का चिर प्रतीक्षित युक्तियुक्त संगठन करना, जिसकी आवश्यकता एक तो कोयले के प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से भी है और दूसरे, धातु शोधन के लिए श्रेष्ठ कोयले को सुरक्षित रखने की भी दृष्टि से है। कोयले के प्रादेशिक उत्पादन में वृद्धि होने से रेलें निकटस्थ कोयला क्षेत्र में माल को निर्दिष्ट स्थान तक जल्दी पहुँचा सकेंगी और रेल कोल बनाने का बढ़िया कोयला बचा सकेंगी, क्योंकि रेलें बढ़िया कोयला या तो लम्बे सफर में भाप बनाने के लिये प्रयोग करती हैं अथवा दुर्गम प्रदेशों में जाने पर। जब कम दूर माल ढाना होगा, तो वे योग्यमानुसार बढ़िया कोयला ही जलाने लगेंगी। इस प्रकार कोयला उत्पादन की तृतीय योजना के अनुसार भले ही निर्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति में एक या दो वर्षों का विलम्ब हो जाये, फिर भी इससे कोयला उद्योग का काफी सीमा तक युक्तियुक्त पुनर्गठन हो सकेगा।

(५) कोयला उद्योग का यन्त्रीकरण—भारत में प्रति व्यक्ति पाली उत्पादन २.७ टन है, जब कि संयुक्त राज्य में ६.२६ टन, जर्मनी में ८.६६ टन और अमेरिका में २१.६८ टन है। इसमें प्रगट होता है कि प्रति पाली उत्पादन भारत में बहुत कम है। कोयले के मूल्य का ७५% श्रमिकों को, १५ से २०% करो को और बेवल ५.१०% मालिकों को प्राप्त होता है। इसका कारण ढूँढने के लिये दूर जाने आवश्यकता नहीं है। उद्योग इस बात की बड़ी आवश्यकता में है कि उत्पादन का तक तार के विस्तृत प्रयोग में विवेकीकरण किया जाय। सन् १९५० में कोयला जायेंगी, भिन्न दिया था कि भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये

मशीनों का प्रयोग करना परम आवश्यक है। यह भी सिफारिश की गई थी कि यन्त्रीकरण का काम एक अवधि पर फैला दिया जाय और एक कोयला खान से दूसरी कोयला खान में धीरे-धीरे किया जाय, जिससे परिवर्तन अब सुधार सरल हो जाय। भारत सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और कोल बोर्ड को यह पता लगाने का आदेश दिया है कि विद्यमान कोयला खानों में बिना अधिक बेकारी उत्पन्न किये विद्युतीकरण किस सीमा तक किया जा सकता है। साथ ही, एक ऐसी शर्त भी लगा दी गई, जिससे मालिकों को यह अनिवार्य हो गया है कि जब नई खान खोलने की आज्ञा मिले, तो समस्त नये विकास-कार्यक्रम, कोयला खोदने और ले जाने में मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे।

(५) राष्ट्रीयकरण का प्रश्न—राष्ट्रीयकरण के बारे में भी बहुत अधिक चर्चा है। हमें विश्वास है कि सरकार केवल राष्ट्रीयकरण की ही खातिर वर्तमान कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी, किन्तु जब सरकार यह देखे कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कोयले के भण्डारों को सुरक्षित रखने के लिये क्षति पूर्ति करके कोयला खानों का प्राधिग्रहण आवश्यक है अथवा ५०० टन प्रति घन्टा धीमे धीमे विशाल कारखानों में, जिसकी लागत एक करोड़ रुपये से अधिक होगी और जिसे स्थापित करना निजी पूँजीपतियों के बश की बात न होगी, प्रयोग करने के लिये कोयले का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है अथवा जब सरकार बेची जाने वाली ऐसी भूमि खरीदे, जिसमें बढ़िया कोयले की खानें हों और जिन्हें उसके मालिक प्रति-योगितापूर्वक न खोद सकें या उन्हें खोदने में इतना खर्चा हो, जो उनके साधनों से बाहर हो तो सरकार द्वारा खानें अपने अधिकार में लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(६) श्रमिकों की समस्या—खानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा भी खराब है, जिसके सुधार के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। एक नये अधिनियम के अनुसार अब कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों से ४८ घण्टे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। इसमें भूमि के ऊपर कार्य करने वालों के लिये ६ घण्टे प्रति दिन तथा भूमि के नीचे कार्य करने वालों के लिये ८ घण्टे प्रति-दिन का कार्य निर्धारित किया गया है।

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the origin, progress, present position and problems of the Indian Coal Industry.
2. Discuss the principal problems of the Indian Coal Industry and suggest remedies to solve them

प्लास्टिक उद्योग

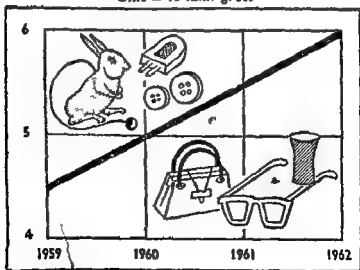
(Plastic Industry)

प्रारम्भिक—

देश के औद्योगिक विकास में प्लास्टिक उद्योग को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस उद्योग में आज २५ करोड़ रु० के विनियोजन का अनुमान लगाया जाता है, जो प्रति वर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे करीब २५,००० श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। भव्य भवन से लेकर साधारण कुटिया तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक प्लास्टिक की विविध वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक की कुछ लोकप्रिय वस्तुओं के उदाहरण निम्न हैं—खिलौने, बच्चे, साबुनदानियाँ, बालों में लगाने की क्लिप्स, घूँडियाँ, बटन, पर्स, बैग, हेन्ड-बैग, झट्टियाँ, पी० बी० सी० की चादरें और फिल्में, चश्मों के फ्रेम, दाँतों के ब्रश, फाउन्टेन पेन, बिजली का सामान, पेपर वेड, ऐश-ट्रे, पैकिंग का सामान, काकरी, पाइप, इत्यादि। कुरूप को सुरुपा बनाने में भी इसका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव एवं लाभप्रद उपयोग के कारण चिकित्सा विज्ञान में “प्लास्टिक सर्जरी” एक विशिष्ट शाखा बन गई है। इन विविध विशेषताओं के कारण वर्तमान युग को यदि “प्लास्टिक युग” कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी। निम्न ग्राफ से प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग का अनुमान लगाया जा सकता है —

Estimated Rise in Domestic Demand for Plastics

Unit = 10 lakh gross



कच्चे माल का उत्पादन—

भारत में प्लास्टिक उद्योग ने कच्चे माल तैयार करने में भी काफी प्रगति की है। भारत में फेनोल फार्मल्डीहाइड मोल्डिङ्ग पाउडर, पोलिस्टीरिन तथा पोलिथिलीन मोल्डिङ्ग पाउडर पहले से ही तैयार किया जा रहा है। सेल्युलोज एसिटेट मोल्डिङ्ग पाउडर, पी० वी० सी० रेजिन और प्लास्टीसीजर बनाने के कारखाने खड़े किये जा रहे हैं। कुछ अर्द्ध-तैयार वस्तुएँ भी बनाई जा रही हैं, जैसे पी० वी० सी० की चादरे, ट्यूबें, पोलिथिलीन के पाइप और नाइलोन के कड़े बाल इत्यादि। ये सारी चीजें नवीनतम सयन्थों और उपकरणों से बनायी जाती हैं, जो बड़े ऊँचे स्तर की होती हैं। देश में ही कच्चा माल तैयार करने के क्षेत्र में विकास हो जाने से आया की जाती है कि इस उद्योग द्वारा जो माल तैयार किया जायगा वह विदेशी बाजारों में जो माल आता है उससे अच्छी तरह मुकाबला कर सकेगा।

संक्षिप्त इतिहास—

भारतीय प्लास्टिक उद्योग का विकास द्वितीय महासमर के पश्चात् हुआ। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसके इतिहास को तीन खण्डों में विभक्त किया जा सकता है—I. सन् १९४५-४६, II. सन् १९४०-४५ और सन् १९५६ से आज तक।

प्रारम्भिक इतिहास—

द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर सरकार ने इस उद्योग के विकास के हेतु एक प्लास्टिक तथा सेल्युलोज औद्योगिक पैनल की नियुक्ति की तथा इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये एक विकास समिति की नियुक्ति की गई। इस उद्योग के विकास तथा देखभाल के लिये एक पृथक निरीक्षण विभाग स्थापित किया गया। इसके विकास के लिये एक त्रिसूत्री योजना बनाई गई—(i) विभिन्न साधनों द्वारा औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण का विस्तार करना, (ii) आयात किये हुये रसायन तथा देश में उपलब्ध कच्चे माल से नकली प्लास्टिक का निर्माण करना, और (iii) उद्योग में प्रयोग होने वाले आवश्यक रसायनों का निर्माण करना। सन् १९४६ में भारत सरकार ने प्लास्टिक बनाने वालों का एक प्रतिनिधि मण्डल अमेरिका तथा इङ्ग्लैण्ड का दौरा करने के लिये भेजा, जिसका उद्देश्य उन देशों द्वारा प्लास्टिक के क्षेत्र में की गई प्रगति का अध्ययन करना था।

संरक्षण के पश्चात्—

तत्कालीन आयोग ने पी० एफ० मोल्डिङ्ग पाउडर तथा बेकोलाइट का बिजली का सामान बनाने के लिये सन् १९४६ में संरक्षण दिया। ऐसे रसायनों पर जो पी० एफ० मोल्डिङ्ग पाउडर बनाने के काम आते हैं, दो हुई झुट्टी लौटाने के लिए तथा कुछ ऐसे प्लास्टिक के कच्चे माल पर जो उपयोगी सामान बनाने के काम आता है, आयात कर कम करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के तैयार माल का आयात

बहुन सीमित कर दिया गया तथा उनके निर्माण को बढ़ावा देने के विचार से उन्हें बनाने की मशीनों, खाल बनाने तथा अन्य सामान बनाने व साधनों का भाषान सुलभ कर दिया गया। इन कारणों से परिष्करण करने के उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की। सन् १९४८-४९ में खोल बनाने का पाउडर का आयात २० ५८ लाख रुपये का हुआ था। परत से बने सामान का उत्पादन सन् १९४८ के ३ लाख ७० हजार के उत्पादन से बढ़कर सन् १९४९ में १० लाख २० हजार हो गया तथा पोलिसटाइरीन का उपयोग बढ़कर १,००० टन हो गया। प्लास्टिक से बने सामान तथा कच्चे प्लास्टिक का मूल्य जो सन् १९४५ में मुश्किल से ५० लाख रु० का था, सन् १९४९ में बढ़कर १ करोड़ ५० लाख रु० का हो गया था।

सन् १९५०-५५ की अवधि—

सन् १९५० से प्रारम्भ होने वाले दशक में औद्योगिक माल के उत्पादन की ओर ध्यान दिया गया। उस समय दैनिक आवश्यकता के सामान का एक-तिहाई केवल कच्चे होते थे, जबकि औद्योगिक सामान का दो-तिहाई केवल बोतलों की डाटे होती थी, लेकिन लोहर कलाश, इन्सुलेटिड, केबिस, तार तथा आसानी से मुड़ने वाले अन्य पदार्थ भी इस समय एक भली प्रकार बनने प्रारम्भ हो गये थे। उस समय से वी० पी० सी० के प्रयोग के इन दोनों विभागों ने काफी प्रगति की, जिसके कारण देश में बने प्लास्टिक की काफी खपत होने लगी। सन् १९५४-५५ में कच्चे माल का आयात १,९४१ टन हुआ, जिसका मूल्य १८५ ६१ लाख रुपये का था तथा प्लास्टिक के बने हुये माल तथा कच्चे प्लास्टिक का माल जो सन् १९५० के प्रारम्भ में १॥ करोड़ रुपये का था, सन् १९५५ के अन्त तक बढ़कर ७ करोड़ रु० का हो गया था और प्लास्टिक से बने सामान का निर्यात जो उस समय केवल ९ लाख रुपये का था, बढ़कर १५ लाख रुपये का हो गया था। प्लास्टिक का सामान बनाने के औजार तैयार करने के काम में भी एक प्रविधिक ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति की देखरेख में काफी प्रगति की है। इस विशेषज्ञ की सेवाएँ सयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर भारत सरकार ने इस उद्योग को उपलब्ध करा दी थी।

सन् १९५५-६१ तक होने वाली महत्वपूर्ण प्रगति—

सन् १९५० के दशक के दूसरे अर्द्ध भाग में भी यह उद्योग निरन्तर प्रगति करता रहा। इसके विकास में एक महत्वपूर्ण घटना पोलिसटाइरीन के उत्पादन के प्रारम्भ होने की थी। इस उद्योग द्वारा सन् १९५१ में बड़े पैमाने पर थर्मो प्लास्टिक वज्रा माल परिष्करण द्वारा प्रयोग किया गया था। सन् १९५८ में यू० एफ० मोलिडिज़ पाउडर तथा सन् १९५९ में पोलिमिलीन बननी प्रारम्भ हुई। इसी समय दो बलैण्डरिंग प्लाटो से पी० वी० सी० बिना सहायता वाली फिल्मों का उत्पादन हुआ। इसी समय पोलिथिन का प्रयोग इन्जेक्शन बनाने के लिये तथा फूक कर साचे बनाने के लिये

काफी लोकप्रिय हुआ और पोलिथिलीन पाईपिंग के उत्सारण का कार्य भी शुरू हो गया। इस समय पोलिथिलीन से बनी बड़े आकार की चीजें जैसे—कारबाप, वाल्टियाँ तथा टोकरियाँ इत्यादि बननी प्रारम्भ हो गई। इसके बाद स्लोल निर्माताओं का ध्यान स्टीयरिंग व्हील तथा रेफीजरेटर के हिस्से जैसी बड़ी बड़ी चीजें बनाने की ओर आकर्षित हुआ। इस समय कच्चे माल का आयात दुगुना हो गया और सन् १९६० में कुल आयात ६ करोड़ रुपये का हुआ। प्लास्टिक का सामान तथा इससे बनी अन्य चीजों का मूल्य भी इस समय में बढ़कर १६ करोड़ रुपये हो गया। इसी काल के दौरान इस उद्योग के लिये मानक भी बनने प्रारम्भ हो गये तथा एक प्लास्टिक के सामान के निर्यात को उत्साहित करने के लिये निर्यात सम्बन्धी समिति ने भी कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस समिति ने इस उद्योग द्वारा बनाई जाने वाली चीजों की विस्तृत सूचना को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में स्लप के आधार पर इन चीजों का विभागीयकरण करना था। विदेशी बाजारों की तदीनतम आवश्यकताओं की जानकारी हासिल करने के लिये इस समिति ने, तीन प्रतिनिधिमण्डल भेजे, जिन्होंने मध्यपूर्व तथा सुदूरपूर्व के देशों का दौरा किया, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक के सामान विशेषकर सेवर कनाथ के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई और प्लास्टिक से बनी चीजों का कुल निर्यात ५० लाख से अधिक का हुआ।

विकास के दस वर्ष—

इस उद्योग के विकास के दस वर्ष तथा इसकी वर्तमान अवस्था निम्नांकित सारिणी में दिखलाई गई है :—

सारिणी सख्या—१

वर्ष	दबाव द्वारा राह (क्षमता टनो में)	इन्वेकशन माउल्टिप्ल (क्षमता औंसो में)	रिसने का कार्य करने वाली मशीनें (सख्या)
१९४५	३,३६३	४	—
१९५०	७,०७४	४०३	३२
१९५५	११,२००	५५०	५५
१९६०	१७,४४५	७४८	६५

समरिणो संख्या-२

विधिवत् तैयार किया हुआ माल (नामता और उत्पादन)

२०

मद	इकाई	उत्पादन		प्रतिष्ठापित क्षमता
		१९५०	१९५५	१९६०
१. फैनोसिक लैमाइनेट	टनो मे	—	१८३	५६७
२. पी० वी० सी० प्रनसपोटिट बाइरे	टनो मे	—	१५१	८६१
३. पोलिथीन फिल्म तथा दुर्बिग	टनो मे	—	३८०	१,२४१
४. लंदर कलाष	हजार गजो मे	८३०	२,६००	६,०८१
५. सांचो द्वारा बनाया गया सामान	मिल घास मे	२२६	२५०	५५७
६. उपभोक्ताओं का	मिल पीस	—	५२०	११७०
(क) वातों के ब्रूश	मिल पीस	०३५	०८०	२३०
(ख) बरमों के फ्रेम	मिल पीस	३२३	६००	२५०
(ग) पाउन्टेल पेन	हजार बीस मे	—	१,२३२	५,७७६
(घ) प्लास्टिक के बटन				३,०३२ एक शिपट मे

सारणी संख्या-३

कच्चा माल, क्षमता और उत्पादन

मद	१९५०		१९५५		१९६०		कुल प्रतिष्ठापित क्षमता १९६० (टन)
	इकाइयों की संख्या	उत्पादन (टनो में)	इकाइयों की संख्या	उत्पादन (टनो में)	इकाइयों की संख्या	उत्पादन (टनो में)	
१. पी० एफ० मोल्टिड्यू पाउडर	३	३२५	३	७१५	४	२,०४१	३०० (२ थिएट्र)
ग्रू० एफ० मोल्टिड्यू पाउडर	—	—	—	—	४	३५३	२५० (समाप्तार काम करके)
पोलिसटाइरीम	—	—	—	—	१	३,७०८	५,४०० (समाप्तार काम करके)
पोलिविलीन	—	—	—	—	२५	३,३६१	६,२०० (समाप्तार काम करके)
पी० डी० सी०	—	—	—	—	१०	—	२,८८० (समाप्तार काम करके)

== निकट भविष्य में ही उत्पादन प्रारम्भ होने का सम्भावना है ।

२. ५० की क्षमता की एक इकाई निकट भविष्य में ही उत्पादन करना प्रारम्भ कर देगी ।

तीसरी योजना मे आधारभूत लक्ष्य—

भगामी तीसरी तथा चौथी योजना को ध्यान मे रखते हुये हम कह सकते हैं कि देश मे औद्योगिक क्रान्ति अपनी पूर्ण शक्ति के साथ चल रही है। सन् १९६० का दशक प्लास्टिक उद्योग के भविष्य के निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। अतः इस उद्योग के भावी कार्यक्रम को तय करने का कार्य काफी महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा घाट प्लास्टिक औद्योगिकी का एक प्रतिनिधि मण्डल सन् १९५६ मे इङ्ग्लैंड, अमेरिका, इटली तथा जापान वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भेजा, जो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य रहा। इस प्रतिनिधि मण्डल ने इन सभी उन्नत देशों मे इस उद्योग द्वारा तेजी से की गई उन्नति के कारणों का अध्ययन किया, जिससे भारतीय उद्योग योजना के लिए उचित नीति तथा लक्ष्य निर्धारित हो सके। दूसरा उद्देश्य उन सभी गुप्त बातों का अध्ययन करना था जिनके कारण इस उद्योग मे उन्नत देशों मे आवश्यकतम उन्नति की है, ताकि हमारी योजना की प्रारम्भिक आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

इस प्रतिनिधि मण्डल के सुझावों के आधार पर इस उद्योग के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है — (१) एक सम्पूर्ण स्वदेशी साधन से कच्चा माल बनाने का एक प्लांट लगाया जाये। (२) स्थानीय जोड़कर बनाई हुई मशीनें तथा कन्वर्टर के लिये औजार आसानी से सुलभ हो जायें तथा (३) उद्योग के अन्दर ही प्रायोगिकीय और प्रथम श्रेणीय कामों के लिए काफी मनुष्य शक्ति का विकास हो जाये। संक्षेप मे, स्वाभाविक साधनों से घरेलू सामान का विकास, स्वदेशी उपकरण और औजार, स्थायी ज्ञान तथा देश मे और बाहर स्थित बाजारों का विकास प्लास्टिक योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। सार समय प्लास्टिक उद्योग की साधन, परत तथा मशीन मिलने की कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तीसरी योजना मे निर्धारित उद्देश्य अनेक ढङ्ग का एक नया उद्देश्य है तथा उसका लक्ष्य प्लास्टिक उद्योग के लिए अनन्त साधन उपलब्ध करना तथा प्लास्टिक के सामान के लिए नये बाजारों को ढूँढना है और विशेष रूप से बिचाई तथा खेती और निर्माण तथा उद्योग आदि के लिए इसमे एक ही स्वावट जो बीच मे आती है वह है स्वदेश तथा विदेश दोनों मे इस प्रकार के सामान की भारी माँग का होना।

न्यूनतम लक्ष्य—

तीसरी योजना का उद्देश्य दूसरे विकसित देशों में बने प्लास्टिक के माल के मुकाबले का माल बनाना है। योजना मे यह तथ्य ध्यान मे रखा गया है कि यह उद्योग अभी विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे है तथा अन्य विकसित राष्ट्रों की अवस्था तक पहुँचने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। प्लास्टिक के सामान के लिए लक्ष्य निर्धारित करने मे प्रति व्यक्ति को होने वाली आय, जनसंख्या मे बढ़ोतरी तथा औद्योगिक उत्पादन के स्तर में चढ़ाव को ध्यान मे रखा गया था तथा इङ्ग्लैंड, अमेरिका, इटली

और जापान जैसे अग्रिक विकसित देशों में भारी प्लास्टिक के सामान के निर्माण के रास्ते में आने वाले मुख्य मोड़ों को ध्यानपूर्वक देखा गया था। इसके अतिरिक्त उनके भावी कार्यक्रम तथा ऐसे नये सामान जिनके नेजी से विकास की आशा है उनका भी अध्ययन किया गया है। इन सारी ही बातों का सार यह है कि ऐसे सुझाव रखे गये हैं जिनका उद्देश्य दूसरी पंच-वर्षीय योजना (सन् १९६१) के काल में उत्पादन क्षमता को २०,००० टन से तीसरी पंच-वर्षीय (सन् १९५६) योजना में ८५,००० टन तक लगभग ३५ से ४० करोड़ के मूल्य पर आगे बढ़ा देना है। योजना में १५,००० टन की वर्तमान खपत के मुकाबले में ७४,००० टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से कम से कम १०,००० टन प्लास्टिक के सामान का निर्यात किया जायेगा। तीसरी योजना के अन्त तक लगभग १२,००० टन थर्मो सेट, मुख्यतः फॉनोलिक्स मूरिया तथा पोलिइस्टर और ६२,००० टन थर्मो-प्लास्टिक जिसमें से ५०,००० टन पोलिप्रोपिलेन, पोलिसटाइरीन तथा १०० बी० सी० फ़ाइब्रेट, नाइलोन-६, एल्युलोज एक्वेट तथा पोलिविनाइल एक्वेट होगा, का निर्माण होना है।

उत्पादन एवं निर्यात—

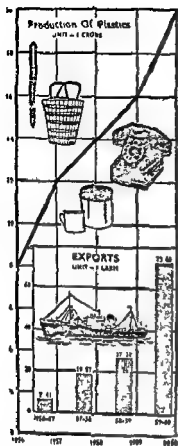
प्लास्टिक उद्योग के वर्तमान उत्पादन एवं निर्यात का अनुमान नीचे के आँकड़ों से लगाया जा सकता है :—

प्लास्टिक का उत्पादन

वर्ष	करोड़ रु०
१९५६	८
१९५७	१२
१९५८	१४
१९५९	१६
१९६०	२०

निर्यात

वर्ष	लाख रु०
१९५६-५७	७४
१९५७-५८	१९ ८७
१९५८-५९	२७ २८
१९५९-६०	७३-६६



निर्यात बढ़ाने के क्षेत्र में उद्योग को बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसने उन पर विजय प्राप्त की। भारत को हाथकांग जैसे—उन्नत बन्दरगाह, जापान तथा औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े पश्चिमी देशों के बाजारों से निर्यात के मामले में मुकाबिला करना पड़ता है। प्लास्टिक की बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये हमारे यहाँ कोई सुव्यवस्थित व्यापार के साधन नहीं हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं का विदेशों के बाजारों में व्यापार जमाने के लिये हमें न केवल मूल्यों को कम करना होगा बल्कि उनकी किस्म में सुधार करना होगा, उनकी पैकिंग और लेबलों को अधिक आकर्षक बनाना होगा तथा बिक्री की उदार शर्तें रखनी होंगी। हमें विदेशी खरीदारों में किस्म, मूल्य और माल देने व समय के बारे में विश्वास उत्पन्न करना है। इन उद्देश्यों को ध्यान

में रखते हुये सरकार ने प्लास्टिक निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना करने की प्रोत्साहन दिया है। इस परिषद् से उद्योग, निर्यात व्यापार तथा सरकार सभी का सम्बन्ध रहता है। निर्यात किये गये माल में जो कच्चा माल लगता है उस पर अब आयात शुल्क की वापसी दी जाती है। निर्यात करने वाले निर्माताओं को जितने कच्चे माल की जरूरत होती है उसके लिए उन्हें आयात के लाइसेन्स भी दिये जाते हैं। निर्यात करने वाले निर्माताओं को जितने देशों कच्चे माल की जरूरत होती है वह उनको रियायती दामों पर दिये जाते हैं। ऐसा करने से निर्यात बढ़ाने में काफी सहायता मिली है।

निर्यात बढ़ाने के उपाय—

देश के प्लास्टिक की बनी वस्तुओं के प्रति विद्वान और रचि पैदा करने के लिये परिषद् ने इनका निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में निम्न उपाय किये हैं—

- (१) विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना ।
- (२) भारत सरकार के विदेश स्थित प्रदर्शक-कक्षों को नमूने भेजना ।
- (३) प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माताओं और निर्यातकों की निर्देशिका प्रकाशित करना ।
- (४) सदस्यों के उत्पादनों का सूची-पत्र तैयार करना ।
- (५) मासिक बुलेटिन प्रकाशित करना ।
- (६) विदेश व्यापार का सर्वेक्षण करना ।
- (७) प्लास्टिक की नवीन वस्तुओं का प्रमाणीकरण करने में सहायता करना ।
- (८) जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ किस्म के स्तर की जाँच करना ।
- (९) शिकायतें सुनना और जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ मध्यस्थता का सहारा लेना ।
- (१०) निर्यात व्यापार सम्बन्धी जानकारी और ग्राँवडे एकत्र करना तथा देना ।
- (११) विदेशों की व्यापारियों के प्रतिनिधि भण्डल भेजना ।
- (१२) निर्यातकों की सामान्य रूप से सहायता करना और उनका मार्ग प्रदर्शन करना ।

भविष्य—

देश के प्लास्टिक उद्योग का रुझान पहले ही निर्यात की ओर है। इस उद्योग के कौने-कौने में उत्पादनशीलता को बढ़ाने के प्रति दिलचस्पी है। यह आशा की जाती है कि वर्तमान उत्पादनशीलता के स्तर को निम्न रखने वाले बादल शीघ्र ही हट जायेंगे। अब इस तथ्य को भी समझा जाने लगा है कि इस उद्योग का संचालन इंजीनियरी तथा प्राविधिक ज्ञान से पूर्ण व्यक्तियों द्वारा होना है, न कि वित्त विशेषज्ञों द्वारा। दक्ष मानव-शक्ति के विकास की योजनाएँ बनाने की आवश्यकता को अब अनुभव किया जाने लगा है तथा इस तेजी से बढ़ने वाले उद्योग के लिए अत्यधिक आवश्यक, इस दक्षता के सकेत भी मिलने प्रारम्भ हो गये हैं। कच्चे माल के निर्माताओं के द्वारा घर में तथा बाहर नये-नये बाजारों की खोज प्रारम्भ कर दी गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस उद्योग का भविष्य काफी उज्ज्वल है। ऐसी अवस्था में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सन् १९६१ से प्रारम्भ होने वाले दशक में यह उद्योग पूर्णरूपेण आत्म-निर्भर हो जायगा तथा उस अवस्था में यह उद्योग बिना किसी बाहरी सहायता के दिन प्रति दिन उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता चला जायगा।

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the origin, growth and present position of Indian Plastic Industry

अध्याय ६८

भारतीय कागज उद्योग

(Indian Paper Industry)

प्रस्तावना—

ज्ञान सचदान का आधार स्वल्प कागज-बनाने का काम सम्भवतः सबसे पहले चीन में आरम्भ हुआ। यद्यपि कागज ईसा से ३०वीं शताब्दी पूर्व भारत में प्रयोग में आने लगा था, किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण ८वीं शताब्दी के बाद ही मिलते हैं। उस समय कागज हाथ से बनाया जाता था। चीन के सम्पर्क से ही कई सदियों पूर्व भारत को भी हाथ से कागज बनाने की प्रेरणा मिली। भारत में मशीन से कागज बनाना सन् १८७० में आरम्भ हुआ, जब हुगली के तट पर सर्व प्रथम कारखाने में उत्पादन आरम्भ हुआ। हमारे देश में कागज उद्योग का विकास विशेष महत्त्व रखता है। भारत में कागज की प्रति शक्ति खपत २ पीण्ड है, जबकि अमरीका में ४१२ पीण्ड और योरोपियन देश तथा जापान में १०० व २२२ पीण्ड तक है।

संक्षिप्त इतिहास—

१९वीं शताब्दी के अन्त में डा० केरे ने बंगाल में आधुनिक कागज के मिल की स्थापना की, किन्तु इस उद्योग की वास्तविक स्थापना सन् १८६८ में बंगाल के बाली मिल (Bally Paper Mills) के निर्माण के साथ हुई। इस मिल का निकटवर्ती क्षेत्र आज भी कागज उद्योग का प्रधान भाग है। भारत का दूसरा प्रमुख कागज का कारखाना टीटागढ कागज मिल सन् १८८२ में आरम्भ हुआ था और सन् १९०३ में इम्पीरियल कागज मिल का भी इसमें सम्मिश्रण हो गया। सन् १९०० तक देश में सात कागज के कारखाने स्थापित हो चुके थे, जिनमें प्रति वर्ष १६ हजार टन कागज तैयार होता था। इसके बाद देशी उद्योग को सस्ते विदेशी कागज से कड़ी प्रतिद्वन्दिता करनी पड़ी। फिर भी सन् १९२४ तक कागज का उत्पादन ३३ हजार टन तक हो गया और कागज मिलों की संख्या ६ हो गई।

युद्धोपरान्त बाल में विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योग को भारी क्षति पहुँची, अतः सन् १९२४ में ठटकर आयोग के सम्मुख आवेदन-पत्र सरक्षणार्थ रखा गया। सन् १९२५ में इस उद्योग को ठटकर सरक्षण प्राप्त होगया और आयात किये जाने

वाले कई प्रकार के कागज पर २५ प्रतिशत शुल्क लगा दिया गया। ऐसा करने का एक उद्देश्य यह भी था कि यह उद्योग अधिक से अधिक देशी कच्चा माल प्रयोग करने लगे। सन् १९२५ से सन् १९३३ तक की अवधि में कागज का उत्पादन निरन्तर बढ़ता गया। सन् १९३२-३३ में ४४ हजार टन कागज का वार्षिक उत्पादन हुआ था, जो सन् १९३८-३९ में बढ़ कर ५९ हजार टन हो गया। पञ्जाब पेपर मिल्स (१९२५), स्टार पेपर मिल्स (१९३६), ओरिएण्टल पेपर मिल्स (१९३६) आदि अनेक नई मिलों की स्थापना हुई। सन् १९२३ में आयात की लुगदी में ३१ ३% प्रयोग की जाती थी; सन् १९३१ में यह संख्या ५५% हो गई। सन् १९३२ में दूसरे सटकर बोर्ड ने छापने और लिखने के कागज पर लगने वाला शुल्क बढ़ा कर १८ ७% कर दिया और प्रस-वारी कागज तथा पुराने अखबारों पर यह आयात शुल्क २५% कर दिया। आयात की हुई लकड़ी की लुगदी पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया गया। सन् १९३८ से लकड़ी की लुगदी पर तो आयात शुल्क घटा दिया गया, किन्तु लिखने व छपाई के कागज पर शुल्क बढ़ाकर २५% और अखबारी कागज पर शुल्क बढ़ाकर ३०% कर दिया गया।

सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ने से कागज उद्योग ने बहुत प्रगति की। सन् १९४१ तक देशी कागज के काम आयात किये गये कागज से कम थे, उन दिनों कागज की कमी अनुभव होने लगी थी। सन् १९४२ में सरकार ने मूल्य नियन्त्रण लागू कर दिया, जो सन् १९५१ में ही समाप्त हुआ। इस अवधि में कागज उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की। सन् १९५१ में उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम के बनने से कागज उद्योग का नियमन योजना के अनुसार होने लगा। नीचे दी हुई तालिका से कागज उद्योग की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है :—

वर्ष	मिलों की संख्या	क्षमता (हजार टनों में)	कुल उत्पादन (हजार टनों में)
१९१३	५	३४	२७
१९२३	६	३७	२६
१९३७	१०	—	४८
१९४८	१६	१०५	६८
१९४९	१६	११०	१०३
१९५०	१६	११४	१०६
१९५२	१८	१४७	१३६
१९५४	१९	१५५	१५४
१९५७	१९	२५०	२१०
१९६०	२०	२६१	२१५

वर्तमान स्थिति—

इस समय हमारे देश में कागज बनाने की २० मिलें हैं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २९१ हजार टन है। इनमें से ४ मिलें बंगाल में, २-२ मिलें उत्तर-प्रदेश और मसूर में तथा बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मध्य-प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मद्रास और केरल में एक-एक मिलें हैं तथा महाराष्ट्र में भी ४ मिलें हैं। आसाम, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कागज के नये कारखाने खोलने के लिये भी अनुज्ञापत्र प्राप्त हो चुके हैं। इन विस्तार योजनाओं के क्रियान्वित होने तथा नये कारखाने स्थापित हो जाने पर देश की कागज उत्पादन की क्षमता ३,५०,००० टन कागज बनाने की हो जायेगी। इस समय हमारा कागज उद्योग लिखने के कागज का ८०%, लपेटने का ३०%, विशेष कागज का २०% तथा बत्तों का ६५% की आवश्यकता पूर्ति करना है, शेष कमी कागज का आयात करके पूरी की जाती है।

अम एच पूंजी—सन् १९५५ तक स्थायी रूप से कागज उद्योग में २७,५०० श्रमिक कार्य करते थे। अनुमान है कि सन् १९६२ तक ३४।१ हजार नये स्थायी श्रमिक हो जायेंगे। सन् १९२३ के पूर्व अधिकांश पूंजी विदेशी थी, सन् १९५३ में इस उद्योग में ६५% पूंजी भारतीय थी। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में ६६ करोड़ रु० की पूंजी विनियोग का आयोजन था, यह पूंजी मुख्यतः निजी क्षेत्र में लगाई गई।

पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति

प्रथम पंच वर्षीय योजना जब प्रारम्भ हुई थी, उस समय देश में १० मिलें कार्य कर रही थी। इन मिलों में कागज एवं कागज के शर्तों का उत्पादन १ लाख १४ हजार टन था। अख्त्यारी कागज का उत्पादन नहीं के बराबर था। स्ट्रॉ-बोर्ड का उत्पादन २२ हजार टन के लगभग था। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के कागजों के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये—(i) कागज एवं कागज बोर्ड २ लाख टन; (ii) अख्त्यारी कागज २७ हजार टन, (iii) स्ट्रॉ-बोर्ड ५२ हजार ६०० टन। जहाँ तक कागज एवं कागज के शर्तों के उत्पादन के लक्ष्य का प्रश्न है, हम उस पर पहुँच गये हैं, किन्तु अख्त्यारी कागज व स्ट्रॉ-बोर्ड का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कागज तथा कागज के शर्तों का उत्पादन लक्ष्य ४,५०,००० टन रखा गया था। अख्त्यारी कागज तथा स्ट्रॉ बोर्ड का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः ६०,००० व ४०,००० टन रखा गया था। ये लक्ष्य काफी सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं।

तृतीय योजनावधि के अन्त तक ७ लाख टन अख्त्यारी और अन्य कागज की माँग होगी। इस समय कागज उद्योग की क्षमता ४ लाख १० हजार टन है, जिसे बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त तक ८ लाख २० हजार टन कर दिया जायगा। अख्त्यारी कागज की क्षमता ३० हजार टन से बढ़ाकर १३ लाख टन करने का प्रस्ताव है। कागज बनाने में अधिकतर गन्ने की खेई का प्रयोग करना होगा।

करोड़ और जारी शुदा पूँजी १५ करोड़ रु० थी और यह मध्य-प्रदेश में मलबारी कागज का कारखाना खोलने के उद्देश्य से लगाई गई थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने १० लाख रु० के हिस्से खरीदे तथा कम्पनी को दिये गये अधिकारों और रियायतों के बदले में उसे १० लाख रु० के पूरी तौर पर मूल्य चुकता हिस्से आवंटित किये गये थे। कम्पनी के प्रवक्त निजी विनिमयकों के हाथ मुश्किल से ५० से ६५ करोड़ रु० के हिस्से बेच सके थे। इस कारण मध्य-प्रदेश की सरकार ने ५० लाख रु० के मूल्य के और हिस्से खरीदे। इस कारखाने की वर्तमान पूँजी रचना इस प्रकार है :—

रु०

आवेदित तथा निजी हिस्सेदारों द्वारा	
भुगतान की गई पूँजी	६२,४८,५००
आवेदित तथा मध्य-प्रदेश सरकार	
द्वारा भुगतान की गई पूँजी	१,६६,७२,६००
आवेदित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा	
भुगतान की गई पूँजी	२,५५,००,०००
जम्मा किये गये हिस्सों की पूँजी	१२,७८,६००
	<hr/>
योग	५,००,००,०००

नेपा के कारखाने में देशी बास की लुग्दी से आधुनिक स्तर पर उत्पादन सन् १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष से शुरू हो गया था। तब से उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता ही रहा है, जैसा निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है।

१९५६-५७	१३,५३४ टन
१९५७-५८	१४,१४३ टन
१९५८-५९	२१,८३७ ७५ टन
१९५९-६०	२२,४११ टन

कागज उद्योग की समस्याएँ

कागज उद्योग की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं —

(१) कच्चे माल का अभाव—हमारे देश में कागज उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में बच्चा माल उपलब्ध नहीं है। रेयन थ्रेडों की लुग्दी, जिसकी बिसकोस मूत, स्टेपल फाइबर तथा सेलोफेन कागज बनाने के लिए आवश्यकता होती है, वर्ष में लगभग ४०,००० टन आयात की जाती हैं और इसमें लगभग ४ करोड़ रु० का बहुमूल्य विदेशी विनिमय व्यय होता है। तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक रेयन थ्रेडों की लुग्दी की आवश्यकता लगभग १,१०,००० टन की होगी। स्वेडन, वियना तथा कनाडा के देशों में रेयन थ्रेडों की लुग्दी के उत्पादन में जिस कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वे देवदार व सरो के

वृक्ष की छाल है। इस प्रकार के प्रसाधन भारत में उपलब्ध नहीं हैं। इस कार्य के हेतु सख्त लकड़ी का उपयोग करने की दिशा में काफी प्राविधिक उन्नति हुई है। भारत में अधिकतर बांस का उपयोग किया जाता है। केरल राज्य में रेयन अंणी की लुग्दी प्रतिदिन १०० टन पैदा करने की योजना क्रियान्वित हो रही है। मंसूर राज्य में उत्तरी कानरा के वनों में प्राप्त बांस के प्रसाधनों पर आधारित दूसरी योजना भी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। बांस से लुग्दी बनाने की एक अन्य योजना भी सरकार के विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत कुछ जापानी साथों के सहयोग से आसाम के बांस प्रसाधनों पर आधारित १०० टन प्रतिदिन लुग्दी पैदा करने वाली इकाई स्थापित की जाने वाली है। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर, जहाँ तक रेयन अंणी की लुग्दी का प्रश्न है, सन् १९६३ तक देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। कच्चे माल के प्रभाव की समस्या को सुलझाने की दिशा में निम्न अन्य सुझाव भी दिए जा सकते हैं :—

(१) बांस के उत्पादन का सुनियोजित एवं क्रमबद्ध कार्य राज्य के वन-विभागों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

(११) बांस के वनों में रेल एवं सड़कों का विकास किया जाना चाहिए।

(१११) बांस के मूल्य का निर्धारण अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए।

(११२) बिछड़े, पटे-पुराने कपड़े तथा अन्य वस्तुओं का उपयोग इस उद्योग में किया जाना चाहिए।

(१२) गन्ने के छिलके का उपयोग भी किया जा सकता है।

कच्चे माल की समस्या का दूसरा स्वरूप रासायनिक पदार्थों की कमी है। विदेशों मुद्रा की कठिनाई और आयात पर प्रतिबन्ध भी इस समस्या को उत्तेजित करते हैं। अतः सरकार को आयात सम्बन्धी नीति में संशोधन करना चाहिए। कागज उद्योग के लिए सोडियम सल्फेट की भी कमी अनुभव की जा रही है। उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों में इसका कारखाना स्थापित किया जा सकता है।

(२) आर्थिक कठिनाई—कागज उद्योग के विकास, विस्तार व अभिनवीकरण के लिए धन राशि की आवश्यकता होगी, जिसकी पर्याप्त व्यवस्था करना इस उद्योग की प्रमुख समस्या है।

(३) अभिनवीकरण एवं यन्त्रीकरण—कागज उद्योग में अधिकतर पुरानी मशीनें ही कार्य कर रही हैं। जब तक आधुनिक यन्त्रों व उत्पादन विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उत्पादन क्षमता एक न्यूनतम सीमा तक नहीं पहुँच सकती। आज कागज की काफी मात्रा में पूँजी लगान तथा देश में मशीनों के जो पुर्जे नहीं मिलते, उनको अपने पास अतिरिक्त मगाकर रखने के लिए काफी चालू पूँजी की आवश्यकता होगी। यहाँ यह बात जल्लखनीय है कि अधिकांश मशीनों तथा कागज वन में प्रयोग होने वाली कुछ चीजों तक का आयात करना होता है, इसलिए हमारे इंजीनियरी उद्योग को शीघ्र से शीघ्र कागज बनाने की मशीनें तैयार करने में लगाना चाहिए। विदेशों में कागज उद्योग में बढ़िया उत्पादन-प्रणाली

के कारण जितनी कार्यकुशलता प्राप्त कर ली है, उसकी तुलना में भारतीय उद्योग को कागज की किसम से और कच्चे माल से रसायनिक पदार्थ प्राप्त करने में काफी सुधार करना होगा, जिससे उत्पादन लागत में काफी कमी हो सके।

(४) गवेषणा कार्यों में समुचित समन्वय का अभाव—देहरादून में भारतीय वन गवेषणाशाला में सेलूलोज तथा कागज की एक शाला है। इस गवेषणाशाला ने बांस से लुग्दी बनाने की एक प्रक्रिया निकाली है। हाल ही में कागज बनाने की एक आधुनिक मशीन तथा अन्य उपकरण भी इस गवेषणाशाला में लगा दिये गये हैं। बहुत से प्रगतिशील कागज मिलों में अपनी अनुसंधानशालाएँ हैं, किन्तु दुर्भाग्य से उनके कार्यों में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। भारत के कागज उद्योग के व्यापक हित की दृष्टि से इनके गवेषणा कार्यों में समुचित समन्वय होने की आवश्यकता है, जिससे इस उद्योग की विभिन्न समस्याओं को हल किया जा सके।

(५) तान्त्रिक प्रशिक्षण का अभाव—कागज उद्योग की उन्नति के लिए प्रशिक्षित जन शक्ति की आवश्यकता है। अतः विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को प्राविधिक प्रशिक्षण देने की योजना बनाना आवश्यक है।

(६) करो का अत्यधिक भार—करो का भार भी कागज उद्योग के लिए असहनीय होता जा रहा है। शिक्षा प्रसार के हेतु उचित मूल्य पर कागज दिलवाना सरकार का वत्तर्ध है। अतः सरकार को चाहिए कि उद्योग को करो के भार से मुक्त करे।

(७) कागज की दरो की समस्या—कुछ कागज व्यवसायियों के मतानुसार, कागज की वर्तमान दरें, कच्चे माल एवं श्रम को देखते हुए, बहुत कम हैं। सन् १९५० के बाद कागज के प्रमुख पदार्थ कोयले में ३०% की वृद्धि, चाइना वालो में ६०% की वृद्धि तथा श्रमिकों की लागत में ३०% की वृद्धि हुई है, जबकि कागज के मूल्यों में केवल १२% की वृद्धि हुई है। साथ-ही साथ मिन मालिकों का यह भी कहना है कि उत्पन्न होने वाले कागज का ३०% से ४०% माल सरकार द्वारा लागत मूल्य पर ही लिया जाता है। अतः इस भाग पर कागज उद्योग को कुछ भी लाभ नहीं होता है। सरकार का कथन है कि कच्चे माल तथा मजदूरी की वृद्धि को देखते हुए कागज मिल २ नए पैसे प्रति पौंड की दर से मूल्य बढ़ा सकते हैं, किन्तु मिल वाले ३५ नए पैसे प्रति पौंड की दर से वृद्धि करना चाहते हैं। कागज के उचित मूल्य निर्धारण के लिए सितम्बर सन् १९५८ में प्रशुल्क परिषद की स्थापना की गई। आशा है परिषद इस समस्या को सुचारु रूप में हल कर सकेगा।

उपसंहार—

उपयुक्त समस्याओं के हल होने पर निश्चय ही भारतीय कागज उद्योग का विकास होगा। एक अनुमान के अनुसार भविष्य में कागज की माँग १५% तक बढ़ेगी। इसी अनुमान के आधार पर माँग उप समिति ने सन् १९६५-६६ के अन्त

तक उत्पादन का लक्ष्य ७,२०,००० टन और उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य ९,००,००० टन कर दिया है। इन लक्ष्यों को देखकर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि कागज उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है।

STANDARD QUESTION

- 1 Briefly trace the history, present position and problems of the Indian Paper Industry

अध्याय ६६

सीमेन्ट उद्योग

(Cement Industry)

प्रारम्भिक—

किसी देश के औद्योगीकरण के लिये कोयला, स्टील तथा सीमेन्ट अत्यन्त आवश्यक पदार्थ हैं। अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। देश की सामाजिक व आर्थिक प्रगति भी बहुत कुछ इन्हीं उद्योगों पर निर्भर करती है। यद्यपि ये तीनों ही महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु सीमेन्ट का महत्त्व अद्वितीय है। सीमेन्ट उद्योग की गणना भारत के प्रमुख संगठित उद्योगों में की जाती है। यह उन उद्योगों में से है, जो बिना सरक्षण के प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्रुत गति से विकसित हुये हैं। इसने अपने उत्पादन को पिछले १६ वर्षों में तिगुना कर दिया है। आजकल सीमेन्ट के ३२ कारखाने क्रियाशील हैं। उत्पादन-क्षमता लगभग ८५*७ लाख टन है, ज. सन् १९६०-६१ तक ९३*७ लाख टन हो जाने की आशा है। कारखानों की सहाय्य भी बढ़ कर ३४ हो जावेगी। उद्योग की प्रगति का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :—

वर्ष	उत्पादन
१९१४	१
१९१८	८४
१९२०	५,६३
१९४०	१७,१२
१९४७	१४,४७
१९५०	२६,१०
१९५५	४४,८७
१९५६	४९,२८
१९५७	५६,०२
१९५८	६०,६८
१९५९	६८,१४
१९६० (अस्थायी)	७७,००

विकास का संक्षिप्त इतिहास—

भारत में संगठित ढंग से पहली बार सीमेन्ट तैयार करने का श्रम मद्रास को है। वही सन् १९०४ से मुख्यतः समुद्री सीपियों से सीमेन्ट बनाने का कारखाना खोला गया, परंतु कारखाना चला नहीं। यह सचमुच बड़ा आश्चर्य की बात है कि यद्यपि भारत में सीमेन्ट के उपयोग के लिये विशाल आन्तरिक बाजार है और इसके निर्माण के हेतु सभी सुविधायें तथा अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, किन्तु फिर भी सन् १९१४ तक इस उद्योग ने हमारे देश में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की। सीमेन्ट की किस्म भी ज्यादा अच्छी नहीं। प्रथम महासमर के पूर्व भी भारत एक बड़ी मात्रा में सीमेन्ट का आयात करता था (लगभग १,८०,००० टन प्रति वर्ष)। वास्तव में माग तो सन् १९१४ के महामुद्र से बढ़ी। बड़ी मात्रा पर सीमेन्ट का उत्पादन सन् १९१२-१३ से प्रारम्भ हुआ, जबकि तीन कम्पनियाँ स्थापित हुईं—'इण्डियन सीमेन्ट कम्पनी, पोर्ट-बंदर, बंदी सीमेन्ट तथा इन्डस्ट्रियल कम्पनी और बूंदेल पाटलण्ड सीमेन्ट कम्पनी। प्रथम में मुद्र के युग में उस उद्योग का प्रोत्साहन मिला। सीमेन्ट के उत्पादन का अधिकांश भाग तो भारत सरकार ने ही क्रय किया। अनेक कम्पनियाँ और स्थापित हुईं। पुराने तीन कम्पनियों ने अपना उत्पादन दुगुना कर दिया और सन् १९२३ तक ६ नई कम्पनियाँ खुल गईं। प्रगति बड़ी तेजी से हुई और उत्पादन की मात्रा ६४५ टन (सन् १९१४ में) से २,३६,५४३ टन (सन् १९२४ में) हो गई। आयात की मात्रा घट

गई। सन् १९३२-३३ में उत्पादन ५,९३,००० टन हो गया और सन् १९३७-३८ में तो लगभग दुगुना हो गया। सीमेन्ट की किस्म भी काफी सुधर गई।

सीमेन्ट कम्पनियों की सख्या में वृद्धि के साथ-साथ पारस्परिक स्पर्धा भी तेज होती गई। इससे उद्योग को काफी चोट पहुँची, यहाँ तक कि इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। सन् १९३० में "सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी" का जन्म हुआ और इस कम्पनी को सदस्यों के द्वारा उत्पन्न की हुई कुल वस्तुओं को, सस्ते मूल्य पर बेचने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक सदस्य फैक्टरी को उत्पादन के लिये एक निश्चित मात्रा दी गई। भिन्न-भिन्न रेलवेज पर भाड़ों की व्यवस्था की गई। तेज भाड़ों को रोका गया और बाजार में भिन्न-भिन्न नमूनों के सीमेन्टों के ढेर लग गए।

सन् १९३६ में सीमेन्ट कम्पनियों का सम्मिश्रण—

सन् १९३६ में उद्योग की युक्तिपूर्ण प्रगति के हेतु एक ठोस कदम उठाया गया, जिसके अनुसार समस्त विद्यमान सीमेन्ट कम्पनियों का एकीकरण कर दिया गया और 'एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज लिमिटेड' (A. C. C.) के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। देश की प्रधान दस कम्पनियों के इस महत्वपूर्ण सम्मिश्रण से उद्योग की दशा बहुत सुधर गई। पारस्परिक स्पर्धा का अन्त हो गया तथा तात्त्विक विकास सम्भव हुआ।

द्वितीय महासमर और उद्योग—

सन् १९३९ में महायुद्ध के प्रारम्भ होने से सीमेन्ट उद्योग को और भी प्रोत्साहन मिला। सीमेन्ट की माँग बहुत बढ़ गई, उत्पादन भी काफी बढ़ा। सीमेन्ट का मूल्य भी बढ़ गया। साधारण जनता को सीमेन्ट प्रदाय करना भी कठिन हो गया, क्योंकि अधिकतर युद्ध सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी हो रही थीं। एक उल्लेखनीय बात यह भी हुई कि ए० सी० सी० तथा डालमिया कम्पनियों के समूह में एक समझौता भी हुआ, जिससे आन्तरिक स्पर्धा पर और भी अधिक नियन्त्रण लगा दिया गया।

देश का विभाजन—

अगस्त सन् १९४७ में देश का विभाजन होने पर १८ कारखाने, जिनकी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता २१ १५ लाख टन थी, भारत में रह गये। पाँच कारखाने पाकिस्तान में रहे। देश में सीमेन्ट की माँग इतनी अधिक रही है कि कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई और सन् १९५०-५१ के अन्त तक भारतीय कारखानों की स्थापित उत्पादन क्षमता में १० लाख टन की और वृद्धि हो गई।

पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सीमेन्ट उद्योग—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट उद्योग सम्बन्धी विभिन्न लक्ष्य इस प्रकार थे—

	१९५०-५१	१९५५-५६
कारखानों की संख्या	२१	२७
वास्तविक वार्षिक उत्पादन (हजार टन)	३,२८०	५,२०६
कुल उत्पादन (हजार टन)	२,६६२	४,८००
निर्यात (हजार टन)	२६	३००

प्रथम पंच वर्षीय योजना के पूर्ण हो जाने से वार्षिक उत्पादन क्षमता ७० लाख टन तक हो गई है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने सीमेण्ट का वार्षिक उत्पादन १३० लाख टन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस योजना काय में इस संयोग के विस्तार की निम्न रूपरेखा बनाई गई—वर्तमान २८ कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और ३१ नये सीमेण्ट कारखाने खोलने की व्यवस्था करना। वर्तमान कम्पनियों द्वारा ६ नये कारखानों और नये लोगों द्वारा १८ नये कारखाने खोलने के लिये सरकार स्वीकृति दे चुकी है। इस विस्तार के फलस्वरूप सीमेण्ट उद्योग की स्थिति इस प्रकार हो जाने की आशा है—

(लाख टनों में)

वर्ष	कारखानों की संख्या	वर्तमान कारखानों की वार्षिक क्षमता	नये कारखानों की क्षमता	योग (वार्षिक उत्पादन)
१९५६	४२	८०.३२	१४.८६	१०५.२२
१९६०	४४	९१.७१	२८.५३	१२०.२४
१९६१	५३	९६.५६	४६.६८	१४३.२७
१९६२	५५	९८.५६	५२.६८	१५१.२४

तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९६५-६६ के लिये सीमेण्ट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर १५ मि० टन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह द्वितीय योजना के अन्त तक होने वाले उत्पादन का ढ़ीढ़ा है। सीमेण्ट के लिये माग की प्राधुनिक प्रवृत्तियों से यह अनुमान लगता है कि सन् १९६०-६१ के लिये आवश्यक मात्रा का जो अनुमान लगाया गया है वह कुछ कम है। अगले वर्षों में इस पर पुन. विचार किया जायेगा। इस तरह यह सम्भावना है कि उक्त लक्ष्य को बढ़ाना पड़ेगा।

सीमेण्ट का मूल्य—

पहली नवम्बर सन् १९६१ से भारत सरकार ने तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक तमाम देश में सीमेण्ट की विक्री के मूल्य में १३ रु० प्रति टन की वृद्धि की है। सीमेण्ट का विक्री मूल्य अब १२२ रु० ६० न० पैसे से बढ़कर १३५ रु० ६० न० पैसे हो जायेगा। सरकार ने ऐसा तटवर आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया है।

उद्योग की समस्याएँ एवं उनके हल—

(१) सीमेण्ट की कमी की समस्या—एक वर्ष पूर्व भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे सीमेण्ट स्टाकिस्टों को लाइसेंस देना बन्द करें। उस सलाह का कारण यह बताया गया कि सीमेण्ट के वितरण पर उन्ना नियन्त्रण रखना जरूरी नहीं रहा, जितना लाइसेन्सिंग प्रणाली लागू करने के समय था, क्योंकि पूर्ति आवश्यकता से अधिक होने लगी है। एक ओर यह स्थिति सामने आई और दूसरी ओर गत दो वर्ष से जम्बई में सीमेण्ट की कमी की समस्या बनी हुई है। वह उत्तरोत्तर विकट बनती गयी है। उसका भवसर भव सारे महाराष्ट्र राज्य पर ही नहीं, बरन् देश के अनेक भागों में दिखाई देने लगा है। उड़ीसा सरकार ने फिर सीमेण्ट के वितरण के लिए परमिट-प्रणाली दो महीने पूर्व जारी कर दी है। दिल्ली में भी सरकार को सीमेण्ट के वितरण में हस्तक्षेप करना पड़ा है।

ऐसा भालूम होना है कि गत नौ-दस महीनों में निजी क्षेत्र में निर्माण की गति बढ़ी है। शायद सरकारी क्षेत्र में भी सीमेण्ट की आवश्यकता अधिक हो गई है। बाढ़ों से जो क्षेत्र प्रभावित हो गये थे, उनमें मरम्मत के लिए भी सीमेण्ट की आवश्यकता में आकस्मिक वृद्धि हुई। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (राज्य व्यापार निगम), जिसका सीमेण्ट के वितरण पर नियन्त्रण है, छः माह पूर्व यह तर्क दे सकता था कि आवश्यकता में आकस्मिक वृद्धि से वह भ्रमण नहीं था। अब उसमें आकस्मिकता का तत्व नहीं रह गया है।

सीमेण्ट की माग में जो वृद्धि हुई है, उसका सामना करना कठिन नहीं होना चाहिए। सीमेण्ट-उद्योग में वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने योग्य क्षमता है ही। वह थोड़ा समय मिलने पर भी उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में है। पता लगाया जाना चाहिए कि क्या कारखानों का उत्पादन आवश्यकता के अनुसार न बढ़ने की वजह रा० व्या० निगम की भयंकी लेना है अथवा रेल वगैरों के अभाव के कारण उन्हें कोयला पर्याप्त परिमाण में न मिलना।

इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। ऐसी हालत में सीमेण्ट की आवश्यकता का तेजी से बढ़ना अपरिहार्य ही है। यदि उसकी पूर्ति न हुई, तो इस्पात के उत्पादन में वृद्धि से सामान्वित होना सम्भव न होगा। अनेक औद्योगिक योजनाएँ कार्यान्वित होती जा रही हैं। आवास-निर्माण का काम भी तेजी पर ही है। पंच-वर्षीय योजना की कार्यान्वित करने वालों को ये सम्भावनाएँ ध्यान में शायद नहीं आई थीं। यह तो इस बात से ही भ्रमकता है कि दूसरी योजना का सीमेण्ट-उत्पादन लक्ष्य १ करोड़ ६० लाख टन से घटाकर डेढ़ करोड़ टन कर दिया गया। इसके अलावा जो लाइसेंस जारी हुए, वे १ करोड़ ४० लाख टन के ही हैं। उनमें से भी केवल उतने का ही उपयोग दूसरी योजना के अन्त तक हो सकेगा, जितने से उत्पादन अधिक से अधिक १ करोड़ १० लाख टन तक पहुँच सकेगा। यदि सरकार अब भी समस्या के प्रति भयंकी लेने की नीति त्याग दे एवं उद्योग संचालकों को आवश्यक क्षमता बढ़ाने

में मदद देने के उपाय करे, तो स्थिति की विकटता धीरे-धीरे दूर हो सकेगी। सीमेण्ट कारखान बनाने के लिए कल-भुर्जे देश में ही प्राप्त करने पर जो अत्यधिक बल दिया जा रहा है, उसमें कमी न होने पर लाइसेन्स बेकार ही पड़े रहेंगे।

(२) सरकार की उपेक्षा—सरकार की इस उद्योग के प्रति विशेष उत्साहबद्धक नीति नहीं रही है, जैसी कि इस्पात उद्योग आदि के प्रति है। समस्त भारत के लिये सीमेण्ट का मूल्य भी समान नहीं है। इससे उद्योग के सम्मुख एक खलभल आ गई है।

(३) यातायात की समस्या—इसके अतिरिक्त देश में यातायात के साधनों की कमी है, यद्यपि हाल ही में इस दिशा में काफी सुधार हुआ है, किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। यह आवश्यक है कि रेल भाड़ा नीति ऐसी हो जिसमें कि सभी स्थानों पर सीमेण्ट को बिना मूल्य बढ़ाये आसानी से पहुँचाया जा सके।

(४) बिक्री कर एवं उत्पादन कर—सरकार सीमेण्ट पर लगे बिक्री कर तथा उत्पादन कर को वसूल करने के लिये बड़ी सरुनीस काम लेती है। प्रत्येक सीमेण्ट के कारखाने पर ४-५ कर्मचारी रहते हैं, जो सीमेण्ट की पैकिंग तथा उसके प्रेषण (Despatch) पर कड़ी निगाह रखते हैं। इससे कारखानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(५) सीमेण्ट की सरकारी बिक्री—सरकार ने १ जुलाई सन् १९५६ से सीमेण्ट को स्वयं बेचने का निश्चय किया है तथा सारे भारत के लिए सीमेण्ट का एक मूल्य १०२ रु० ५० नये पैसे रखा है। इसमें सीमेण्ट के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

(६) उत्पादन व्ययों की समस्या—भारतीय सीमेण्ट उद्योग का उत्पादन व्यय भी अधिक है। हमारी कुछ इकाइयाँ प्रसामान्य भी हैं।

उक्त समस्याओं को मुलभूत के लिये योजना कमिशन ने निम्न सुझाव दिये हैं—(अ) वर्तमान कारखानों का प्रसार करके उनके उत्पादन में वृद्धि करना। (आ) कार्यक्षमता में वृद्धि करने तथा लागत व्यय को कम करने के उद्देश्य से उद्योग को अपनी मशीनों का अभिनवीकरण करना चाहिए। (इ) राज्य सरकारों को चाहिये कि वे दीर्घकालीन पट्टे देकर इस उद्योग की उन्नति में सहायता दें। (ई) देश में फालतू सीमेण्ट की मात्रा को ध्यान में रखकर विदेशों में भारतीय सीमेण्ट के लिए बाजारी की खोज करनी चाहिये। (उ) प्रसामान्य कारखानों का कम से कम एक न्यूनतम लाभकारी आकार तक प्रसार करना चाहिये।

उद्योग का भविष्य—

सीमेण्ट उद्योग का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। देश में जितना सीमेण्ट बनता है उसकी अपेक्षा माँग अधिक रहती है। जिस तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं उसे देखते हुये अभी बहुत दिनों तक माँग की यही दशा बनी रहेगी। इससे सिवाय भाकड़ा, नागल,

हीराकुण्ड, भवानी, भोयार, दामोदर घाटी योजना, कोयना, कोसी आदि बांध बनाने के काम भी अभी चलेंगे, जिनके लिए बहुत अधिक सीमेंट की आवश्यकता होगी। देश की सबसे बड़ी समस्या खाद्य की है। इस समस्या को केवल वर्तमान आवादी को देखते हुए ही नहीं बल्कि भावी-जन-संख्या को भी ध्यान में रखते हुए हल करना है। एक ओर तो देश के कुछ भागों में सूखा पड़ता है और दूसरी ओर बाढ़ से विनाश होता है। बाढ़ वाली नदियों का नियन्त्रण करना आवश्यक है, जल जल बिद्युत तथा सिंचाई योजना चलाकर ही किया जा सकता है। यह कार्य सीमेंट के बिना नहीं हो सकता। देश को बढ़िया सड़कों की आवश्यकता है। साथ ही अच्छे ढंग के मकान, अस्पताल और स्कूल भी बनाये जाने हैं। इनके अतिरिक्त नागरिक तथा सैनिक दोनों ही कार्यों के लिये हवाई अड्डे भी बनाये जायेंगे। इन सभी कार्यों के लिये सीमेंट की आवश्यकता होगी।

अध्याय ७०

भारतीय जहाजरानी

(Indian Shipping)

प्रस्तावना—

इमरसन का यह कथन कि 'सम्राट के सबसे प्रगतिशील वे देश हैं जो सबसे अधिक नाविक होते हैं, बिल्कुल सत्य है। वास्तव में जिसका समुद्र पर अधिकार है, उसका विश्व के व्यापार पर भी अधिकार होता है। प्राचीन युग में भारतवर्ष 'पूर्वीय सागरों की रानी' के नाम से विख्यात था। अतीत काल में जहाज निर्माण कला में भी यहाँ के निवासी बड़े चतुर थे। प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपान करने से पता लगता है कि भारत में बने मजबूत और सुन्दर जहाजों द्वारा ही ईरान, अरब, पूर्वी अफ्रीका, मलाया, पूर्वीय द्वीपों इत्यादि देशों से व्यापारिक सम्बन्ध थे और जहाजरानों की सहायता से ही मसाले तथा विभिन्न प्रकार के अन्न सामान इन देशों को भेजे जाते थे। डा० मुर्जी ने इस विषय में लिखा है कि भारत की प्राचीन सम्पत्ता इसलिए विश्व के कोने-कोने तक पहुँची कि इसे बड़ी सामुद्रिक शक्ति प्राप्त थी। इतिहास से पता चलता है कि जब सिक्न्दर महान् अपने देश को वापस जा रहा था, तब २ हजार

भारतीय जहाजों पर ही उसकी सेना तथा सामान लदा हुआ था। मुगल शासन-काल में भी जहाजरानी उद्योग विकास की ओर बढ़ रहा था। इस उद्योग की प्रशंसा करते हुए बावरी फायर ने लिखा है कि 'उम समय भारत में मजबूत जहाज बनाये जाते थे। योरोपीय देशों में इतने विदात जहाजों का अभाव था'। शिवाजी के पास भी मजबूत जहाजी बेटा था, जिससे अंग्रेजों को सदैव भय रहता था। उसके बाद के काल में भी जहाजरानी की दशा अच्छी रही, परन्तु २०वीं शताब्दी में प्रारम्भ होते ही यह उद्योग भ्रवणित करता गया, जिसका मुख्य कारण था अंग्रेजों का भारत पर शासन स्थापित होना।

भारतीय जहाजरानी का संक्षिप्त इतिहास—

भारत में रेल-यातायात की स्थापना हो जाने के बाद रेल तथा समुद्री यातायात में प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई। अंग्रेज सरकार ने इस प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि जब कभी भारतीय कम्पनियों ने समुद्र में अपने जहाज चलाने के प्रयत्न भी किए तब उनको विदेशी जहाजी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिससे उनकी काफी हानि का सामना करना पड़ा। यह प्रतिस्पर्धा दो प्रकार से लड़ी जाती थी— एक तो, भाड़ा कम करके और दूसरे, विलम्बित कटौती प्रथा द्वारा।

प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीयों में जागृति का संचार हुआ और उन्होंने इस बात की मांग की कि भारतीय जहाजरानी उद्योग को अपना विकास करने का अवसर प्रदान किया जाय। सन् १९२३ में इण्डियन मर्कन्टाइल तथा मॅरिन कमेटी की नियुक्ति की गई। इसने निम्न सुझाव दिये —(१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के लिए अनिवार्य अफसरों की प्रशिक्षा हेतु सरकार द्वारा बम्बई में जलयान प्रशिक्षण की स्थापना की जानी चाहिए। (२) तटीय व्यापार लाइसेन्स प्राप्त जहाजों के लिए सुरक्षित रखा जाय। (३) भारतीय कम्पनियों की व्यापार हेतु अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जाये। (४) कलकत्ता को स्वतः चालित जलयानों के निर्माण का केन्द्र बनाया जाये। (५) भारतीयों को विदेशी कम्पनियों में ट्रेनिङ दी जाय। सिवाय इसके इफरिन में जहाजी कर्मचारियों की शिक्षा की व्यवस्था हो गई। सिफारिश को नहीं माना गया। इसके बाद सन् १९२८ में श्री हाजी साहब ने अमेम्बली में तटीय यातायात भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने के हेतु एक बिल पेश किया, किन्तु वह अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद सन् १९३६ में हाजी साहब ने विलम्बित बट्टे के अन्त के लिये प्रस्ताव रखा, परन्तु इसमें भी सफलता न मिल सकी।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय जहाजरानी के विकास के लिये जो भी प्रयत्न किये गये, वे सब असफल रहे। युद्ध काल में अंग्रेजों सरकार को भारतीय नौ सेना के भर्त्स का पना चल गया जहाजरानी की सम्पत्ती पर विचार करने के लिए सर सी० पी० रामस्वामी ऐय्यर की अध्यक्षता में एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण उप-मिति की नियुक्ति की गई, जिसने अपनी विज्ञप्ति सन् १९४७ में पेश

की, जिसमें सरकार की नीति की आयोजना की गई। इसने सिफारिश की कि भारतीय जहाजरानी उद्योग की क्षमता २० लाख टन कर दी जाय। दूसरे, भारत के तटीय व्यापार का १००%, निवृत्तवर्तीय देशों के साथ होने वाले व्यापार का ७५%, दूरवर्तीय देशों के साथ होने वाले व्यापार का ५०% तथा जर्मनी आदि शत्रु राष्ट्रों के खोये हुये व्यापार का ३०% भाग भारतीयों के हाथ में पाँच से सात वर्ष तक आ जाना चाहिए, परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने जहाजी कम्पनियों को सहायता देने का निश्चय किया। उपरोक्त लक्ष्य पर पहुँचने के लिये शिपिंग एक्ट सन् १९४७ में पास किया गया, जिसके द्वारा जहाजों का लाइसेन्सिंग किया गया। इसके बाद एक सम्मेलन द्वारा जहाजी निगमों की स्थापना का निर्णय किया गया। इन निगमों का उद्देश्य भारतीय जहाजों की टन क्षमता तथा जहाजी यातायात में वृद्धि करना है। ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन आज पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व में है।

भारतीय जहाजरानी की स्थिति—

स्वाधीनता के बाद राष्ट्रीय सरकार अपने जहाजी व्यापार के विकास के लिए काफी प्रयत्न कर रही है। नवीन बन्दरगाहों का निर्माण जारी है और योजनाएँ बनाई जा रही हैं। भारत सरकार अब इस बात को भली-भाँति जानती है कि भारतीय जलयानों की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तथा राष्ट्र की रक्षा में बड़ा कार्य करना है। इसके लिए वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में बम्बई में एक डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय जलयान नीति का एकीकरण करना है। विजयापट्टम बन्दरगाह को सरकार अधिक सहायता भी प्रदान कर रही है। सरकार ने यह भी निश्चय कर लिया है कि भविष्य में भाड़े आदि के सघर्ष के कारण भारतीय जहाजरानी या जलयान उद्योग की कोई हानि नहीं होनी पायेगी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय जलयान कम्पनियाँ भारत, यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के बीच अठ्ठी सेवाएँ कर रही हैं। भारत सरकार ने सन् १९५१ में अंग्रेजी प्रभुत्व के जहाजी सम्मेलन के स्थान पर एक नया भारतीय तटीय सम्मेलन की स्थापना की, जिसके द्वारा सारा तटीय व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता है। जहाजरानी को इतना प्रोत्साहित करने के बाद भी भारतीय जहाजरानी पूर्ण विकसित नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार का कुल ५% भाग भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता है, जबकि लक्ष्य ५०% था। इस प्रकार जहाजरानी के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। यह अनुमान है कि भारतीय जहाजी कम्पनियों का समुद्रीय व्यापार कुल समुद्रीय व्यापार का ६% है तथा पड़ोसी व्यापार का ८% भाग है। प्रथम योजना के अन्त में ६,००,७०७ जी० आर० टी० के जहाज थे और द्वितीय योजना के अन्त में ६,०१,७०७ जी० आर० टी० के जहाजों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर सन् १९५६ के अन्त में ७,३६ लाख जी० आर० टी० के १५७ जहाज

वे, जिनमें से २ ७४ लाख जी० ग्रा० टी० के ८६ जहाज सटीप व्यापार में तथा ४ ६५ जी० ग्रा० टी० के ६८ जहाज विदेशी व्यापार में लगे थे। ८०,८०० जी० ग्रा० टी० के जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, जो द्वितीय योजना काल के पूर्व ही प्राप्त हो जाएंगे। द्वितीय योजना काल में प्रस्तावित ३ लाख जी० ग्रा० टी० के जहाजों के निर्माण के लक्ष्य में विदेशी विनिमय की कमी तथा आन्तरिक वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण कटौती कर दी गई। भारत सरकार की नीति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भारतीयों का हिस्सा ५०% तक बढ़ाना है।

भारतीय जहाजरानी की कुछ प्रमुख समस्याएँ—

(१) जहाजी सम्मेलनों का प्रभुत्व—अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय व्यापार में अनेक जहाजी सम्मेलन हैं, जिनमें विदेशी जहाजी कम्पनियों का प्रभुत्व है। इन सम्मेलनों में भारतीय जहाजी कम्पनियों को सदस्यता नहीं दी जाती है, जिससे वे इन सम्मेलनों के मार्ग पर अपना व्यापार नहीं कर पाती। विदेशी जहाजों की इस बढ़ती हुई गति के कारण भारतीय जहाजी कम्पनियों को बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। देशी जहाज खाली चलने हैं, जबकि विदेशी जहाज भरे जाते हैं। राष्ट्रीय जहाजी बेंच की शक्तिशाली बनाने के लिये हमारी जन प्रिय सरकार को चाहिए कि वह इस अनावश्यक विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिये कटिबद्ध हो जाय। सुरक्षण की कोई ऐसी योजना निकाली जाय, जिसके द्वारा राष्ट्रीय जहाजी बेड़ा फने-फूले एवं प्रतिযোগिता में भी सकल हो।

(२) तडाग जहाजों (Tanker Tonnage) का अभाव—अभी तक भारत के पास अपने निजी तडाग जहाज नहीं हैं, तथापि भारत सरकार ने ऐसे जहाज सेत का निश्चय कर लिया है। हमारे जहाजी बेंच की यह बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि देश में ३ तैल शोधनशालायें (Oil refineries) बनाई जा रही हैं, जिनके लिये हमें लगभग ३८ लाख टन कच्चा तेल बाहर से मँगाना पड़ेगा। शोधनशाला में भी बाहर से तेल लाने के हेतु ही नहीं, बल्कि परिशोधित तेल को देश के विभिन्न भागों में समुद्री मार्ग से भेजने के लिए तडाग जहाजों की आवश्यकता पड़ेगी। इस समस्या पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

(३) यात्री जहाजों का अभाव—देश की प्रतिष्ठा के हेतु एवं यात्रियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए यात्री जहाजों का होना आवश्यक है। ऐसे जहाजों के सञ्चालन में बहुधा व्यय अधिक होता है, अतएव अन्य अनेक देशों में ऐसी सेवाएँ राजकीय सहायता के बल पर चलती हैं। हमारे देश में भी भारत और ब्रिटेन के बीच सिधिया कम्पनी कई वर्षों तक इन यात्री सेवा प्रदान करती रही कि सरकार उमें ऐसे कार्य में प्रोत्साहित बरेगी, परन्तु सरकार ने इधर लेशमात्र भी ध्यान न दिया। परिणामस्वरूप इन् सेवा समाप्त करनी पड़ी। इससे केवल देश के यात्रियों को ही कठिनाई नहीं हुई, बल्कि विदेश से आने वाले अमणवारियों को भी बड़ी असुविधा उठानी पड़ी।

(४) उपयुक्त बन्दरगाहों के लिए सुविधाओं का अभाव—भारतीय समुद्रतट ४००० मील लम्बा होते हुये भी इस पर उपयुक्त बन्दरगाहों के लिए सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि किनारे सपाट हैं, कटे-फटे नहीं। कृत्रिम सुविधायें जुटाने पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया, अतः हमारे देश में अच्छे बन्दरगाहों का अभाव है। इस कारण भी भारतीय शिपिङ्ग अधिक प्रगतिशील नहीं है।

(५) जहाजों की मरम्मत—स्वायत्तता के बाद भारतीय व्यापारिक जहाजों वेडों की टन क्षमता में जो उन्नति हुई है, उसमें एक और समस्या पैदा कर दी है। यह समस्या है देश में ही जहाजों की मरम्मत को सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता। आजकल हमारे देश में ८ ऐसे कारखाने हैं, जिनमें जहाजों की मरम्मत होती है। परन्तु टन क्षमता के विस्तार की दृष्टि से ये सुविधायें जहाजों वेडों को समुचित दशा में रखने के लिए कम हैं।

(६) रेल जहाजों प्रतियोगिता—भारत के तटीय यातायात में कुछ ऐसी वस्तुओं का समावेश है (जैसा नमक, कोयला) जिनका परिमाण कुल तटीय-यातायात (२५ लाख टन) में लगभग १७५ लाख टन होता है। परन्तु ऐसी वस्तुओं के तटीय-यातायात में रेलवे की ओर से जहाजों कम्पनियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रेल-यातायात माल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाड़े की आवश्यकतानुसार कम कर देता है, जो जहाजों यातायात में सम्भव नहीं होता। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने जून सन् १९५५ में रेल-समुद्र सामंजस्य समिति की नियुक्ति की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। इसमें जहाजों तटीय यातायात की भाड़ा दरें बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है, जिसे भारत सरकार ने कुछ अपवादों के साथ लागू कर दिया है।

(७) देश में जहाज निर्माण कारखानों की कमी—हमारे देश में जहाज बनाने का एक ही कारखाना है, जिसकी विकास योजना की पूर्ति पर वह सन् १९५६ के लगभग ४ जहाज वार्षिक बना सकेगा। अतः भारत को विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है।

(८) आर्थिक साधनों की कमी—जहाजों टन क्षमता बढ़ाने के लिए देशी एवं विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। जहाजों कम्पनियों को देशी मुद्रा में ऋण देने की सुविधा के लिए भारत सरकार ने सन् १९५८ में एक म्यामी जहाज विकास ऋण का १ करोड़ रुपये से निर्माण किया है। परन्तु विदेशी विनिमय की कमी जहाजों टन क्षमता बढ़ाने के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस कठिनाई का दूर करने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है।

(९) गोदी कर्मचारियों की समस्या—गोदी कर्मचारियों की समस्या के उस रूप का परिचय भारतीय जनता का १५ जून सन् १९५८ को आरम्भ होने वाली गोदी कर्मचारियों की हड़ताल से मिला। यह हड़ताल निम्न मांगों की पूर्ति के लिए हुई थी :—(१) प्रोवोकेट पण्ड एवं अचुपटी के सम्बन्ध में तत्काल निर्णय की

माँग, (घा) घटाई से सम्बन्धित अन्य विषयों तथा स्थानीय भाँगों पर बन्दरगाह स्तर पर तत्काल कार्रवाई की माँग। गोदी कर्मचारी भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिनका समुचित हल न होना हमारे नव-विकसित उद्योग को खतरे में डाल सकता है।

पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत भारतीय जहाजरानी—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना—योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रथम योजना में जहाजी उद्योग की टन शक्ति ६ लाख टन बढ़ाने की थी, जिसके लिए जहाज खरीदने के लिए १६.५ करोड़ रुपये की सहायता देने की सिफारिश थी। योजना में पूर्वी कॉरपोरेशन के लिए इतनी धन राशि का आयोजन किया था कि वह ६०,००० टन के जहाज खरीद सके। योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार इस उद्योग को आर्थिक सहायता प्रदान करे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा था कि जहाजी बड़े की विकास योजना को 'दी हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशालापट्टन' की योजना से मिला देना चाहिए, जिससे अधिक उन्नति हो सके। यह भी आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाये, जिसके लिए भाड़े उचित और एक समान होने चाहिए। सरकार ने उपरोक्त सभी सुझावों को मान्यता प्रदान की और हर प्रकार से इस उद्योग के विकास में सहयोग प्रदान कर रही है।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना—द्वितीय योजना में जहाजरानी के विकास के लिये ४५ करोड़ ६० का आयोजन किया गया (इसमें ८ करोड़ ६० की पहली योजना की शेष धन राशि भी सम्मिलित है)। प्रथम योजना में ६ लाख टनेज के पूरा होने में कुछ कमी रह गई थी। दूसरी योजना ने अन्तर्गत ६०,००० टन के जहाज बढ़ाये जाने थे। टनेज का लक्ष्य १,००,००० टन रखा गया। यह आशा है कि द्वितीय योजना के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय जहाजों का भाग १५% हो जायेगा। बड़े बन्दरगाहों के विकास पर ५८.३१ करोड़ रुपये, प्रकाश गृह के ऊपर ४ करोड़ ६०, छोटे बन्दरगाहों के विकास पर ४ करोड़ ६० व्यय किये गये। उत्पादन की वृद्धि के लिये दूसरा शिपयार्ड कोचीन में बनाया गया है।

सरकार ने मार्च सन् १९५२ में विशालापट्टनम शिपयार्ड मिथिया स्टीम शिपयार्ड मैदीगेश्वर कम्पनी से ग्रहण कर लिया था तथा प्रबन्ध का कार्य हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया, जिसमें ३ पूँजी सरकार की थी और ३ पूँजी मिथिया कम्पनी की थी। यह शिपयार्ड अब ४ आधुनिक डोजल संचालित जहाज प्रति वर्ष बना सकता है। पहला जहाज सन् १९४८ में बनाया गया। कुछ प्रमुख जहाज जो इस यार्ड में बन कर समुद्र पार भेजे गये, निम्नलिखित हैं :—

जहाज का नाम व वजन	स्वामियों का नाम
१. जगरानी \ C १०८	(८,००० DWT)
	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि०

२. जल प्रपात VC १११	"	सिंधिया स्टीम नेवी- गेशन कं० लि०
३ जल पुष्पा	"	"
४. भारत रत्न	"	भारत लाइन लि०
५ जल पुत्र VC ११५	"	सिंधिया स्टीम नेवी- गेशन कं० लि०
६ जल विहार VC ११६	(७०० DWT)	"
७ जल विजय	"	"
८. जल विष्णु VC ११६	"	"
९ स्टेट प्रॉक कच्छ VC ११८	(८,००० DWT)	ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन
१० कोर्ट नोजल टग VO १२४		मद्रास पोर्ट
११. ग्रन्डमन VC १३५	(४,००० DWT)	गृह मंत्रालय
१२ स्टेट प्रॉक उडीसा VC १२०	(८,००० DWT)	ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन
१३ जल विक्रम VC १२१	(७,००० DWT)	सिंधिया स्टीम नेवी- गेशन कं० लि०
१४. जल वीर		"

अब तक उक्त शिपयार्ड ने २४ समुद्र पार जाने वाले जहाज और २ छोटे क्राफ्ट व एक सूरिंग वैसल (कुल G R T १,१६,६४३) बनाये हैं। शिपयार्ड के विकास के लिये २६० करोड़ की लागत से एक योजना भी कार्यान्वित की जा चुकी है। द्वितीय योजना के अंत में इसकी उत्पादन क्षमता ५०,००० से बढ़ा कर ७५,००० से ८०,००० GRT तक करने का प्रस्ताव था।

भारतीय जहाजरानी देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिकाधिक योग दे रही है। इसका अनुमान नीचे दी हुई तालिका से लगाया जा सकता है, जिसमें भारतीय ध्वजगाहों से विदेशों को माल लेकर जाने वाले जहाजों का टनेज दिया गया है।—

	जाने वाले जहाजों का माल सहित टनेज	जाने वाले जहाजों का माल सहित टनेज
१९४८-४९	३५०	४०१
१९४९-५०	५८२	७५०
१९५०-५१	७८३	१,४१६
१९५१-५२	६६३	१,३६७
१९५२-५३	७८८	१,८४५
१९५३-५४	७७०	२,४११
१९५४-५५	९४४	१,६७०

जहाजरानी उद्योग का भविष्य—

जहाजरानी के विकास का कार्यक्रम अधिकतर इस काम के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा पर निर्भर करता है। अभी हम इस ओर धीरे धीरे बढ़ना है। तीसरी योजना में जहाजरानी के लिए ५५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहाजरानी विकास निधि के ४ करोड़ रुपये और जहाजरानी कंपनियों के अपने साधनों से ७ करोड़ रुपये और इस कार्यक्रम में लगेंगे। साथ ही कुछ अधिक राशि निजी क्षेत्र में और शेष सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगमों के कार्यक्रम में लगेगी। आशा है कि इस योजना की अवधि में ५७ जहाज खरीदे जायेंगे, जिनकी क्षमता १,७५,००० टन होगी। इसमें से १,६४,००० टन क्षमता तो पुराने जहाजों को बदलने में लगेगी और शेष १,८१,००० टन क्षमता बढ़ जायेगी। इस प्रकार कुल क्षमता ११ लाख टन हो जायेगी। लगभग २,१६,००० टन के जहाज निजी कंपनियों द्वारा और शेष १,५६,००० टन के जहाज सार्वजनिक क्षेत्र में आयेंगे। इसमें से १,३२,५०० टन के जहाज तटवर्ती व्यापार के लिए और शेष २४२,००० टन जहाज विदेशी व्यापार के काम आयेंगे। तटवर्ती व्यापार के लिए योजना की अवधि में अधिकांश काम पुराने जहाजों की जगह नए लाने का है। जहाजरानी के और तीन कार्यक्रम में चार सेलवाही जहाज भी खरीदे जायेंगे, जिनमें से एक तटवर्ती व्यापार के लिए विदेशी व्यापार के लिये होने।

बन्दरगाह—मौजूदा बड़े बन्दरगाहों के लिये जो कार्यक्रम तीसरी योजना में बनाए गए हैं, उनका प्रमुख ध्येय यहाँ उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना है। यह अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त में बड़े बन्दरगाहों की क्षमता ४६ करोड़ टन हो जायेगी। योजना में कलकत्ता बन्दरगाह के रख रखाव की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल किये गए हैं। पहला हलदिया में सहायक बन्दरगाह बनाने का और दूसरा फरक्का पर गंगा पर एक बांध बांधन का। हलदिया कलकत्ते से ५ मील नीचे की तरफ होगा। यहाँ कोयला, लाहा, भनाज आदि बड़ी मात्रा वाला माल उनारा चढ़ाया जाएगा। गंगा पर बांध बनाना हुगली नदी की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक समझा गया है। कलकत्ता बन्दरगाह के कार्यक्रमों के साथ ही बेलारी चैनल के सुधारने का काम भी शामिल है। बम्बई बन्दरगाह के कार्यक्रम में मुख्य बन्दरगाह के समीपवर्ती समुद्र को गहरा करने, प्रिसस और विन्टरिया गोदियों के आधुनिकीकरण और वैंलाड पायर के विकास का कार्यक्रम है। मद्रास में कायला और लोहा आदि सामान के लिए याद बनान और इन्हें उतारने-चढ़ाने के लिए मशीनें आदि खरीदन की व्यवस्था है। विशाखापत्तनम के कार्यक्रम में कच्चा धातु सादने की मशीनें स्थापना का कार्यक्रम है। और नवरो के अस्पाय फाउल में दो अतिरिक्त बंधें पुरा करने का कार्यक्रम है। बड़े बन्दरगाहों के कार्यक्रमों में तूतीकोरण और मंगलोर के छोटे बन्दरगाहों को सब मौसमों में काम आन वाला बनाना भी शामिल है।

बन्दरगाह विकास कार्यक्रम पर कुल ११५ करोड़ ६० लाख रुपये होंगे। इसमें से

८० करोड़ ६० बड़े बन्दरगाहों पर, २५ करोड़ ६० फरवका के बाघ पर और १० करोड़ ६० मशीन और तूतीकोरण के नए बन्दरगाहों के विकास पर खर्च होगा।

योजना में छोटे बन्दरगाहों के कार्यक्रमों पर १५ करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम बिचोलिया बन्दरगाह विकास समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। तीसरी योजना में शामिल कार्यक्रमों के पूरा होने पर छोटे बन्दरगाहों की क्षमता ६० लाख से बढ़ कर ६० लाख टन हो जाएगी।

प्रकाश-स्तम्भों और प्रकाश अद्वाजों के विकास के लिए ६ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। नए कार्यक्रमों में एक प्रकाश स्तम्भ खरीदने की भी बात है, जिस पर १४० लाख रुपये व्यय होगा।

अध्याय ७१

मशीन टूल्स उद्योग

(Machine Tools Industry)

भूमिका—

विश्व के विभिन्न औद्योगिक देशों में मशीन टूल्स उद्योग की गत १८५ वर्षों में अनेक परिवर्तन देखने पड़ हैं। उद्योग का जन्म सन् १७७५ के लगभग हुआ, जबकि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन और विलकिन्सन ने वाट के इंजन का सिलिंडर बनाया। पिछले महायुद्ध में एच इसके बाद इस उद्योग की इतनी अधिक प्रगति हो गई है कि आधुनिक युद्ध के अनुसार मशीन टूल्स उद्योग की शुद्धता के कार्य के लिये एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा स्वचालन के लिये उपयोगी समझा जाने लगा है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व विश्व में केवल कुछ ही देशों (जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और रूस) में मशीन टूल्स उद्योग का अस्तित्व था। वास्तव में, इंग्लैंड और अमेरिका मशीन टूल्स के निर्माण में अग्रणी थे। प्रारम्भिक मशीन औजार (जैसे वरिंग मशीनें) इंग्लैंड में सर्व प्रथम बनाये गये थे। विलकिन्सन ने सन् १७७५ में ब्रिग मशीन का आविष्कार किया। इस आविष्कार की सहायता से बोल्टन और वाट ने अपने स्टीम इंजनों में बहुत सुधार कर लिया। अठारहवीं शताब्दी में फ्रांसिस्को

विश्व के सर्वश्रेष्ठ मिश्रितिक थे। किन्तु इस पर भी मोड्सले को अपनी स्लीटिंग और प्लानिंग मशीन आदि का आविष्कार करने में बहुत समय लगा।

विदेशों में मशीन दूल उद्योग की भाँकी—

अमेरिका के मशीन औजार निर्माताओं ने मशीन औजारों का निर्माण १९वीं शताब्दी के आरम्भ में शुरू किया। उनका प्रयास विशेष उद्देश्यों वाली मशीनें बनाने का रहा। प्राट, विटने और नार्थ के प्रयासों से ही अमेरिका वर्तमान शताब्दी में मशीन औजारों के निर्माण में अग्रणी बन सका है। जर्मनी का मशीन दूल उद्योग नया-नया ही विकसित हुआ है, किंतु कुछ ही समय में यह अपने कई पुराने प्रतिस्पर्धियों से भागे निकल गया। स्विट्जरलैंड भी निर्माताओं का देश है। उसे उच्चकोटि की शुद्धता वाले यन्त्रों व औजारों की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्वचालित यंत्र व उपकरण बनाये और उसमें वह काफी सफल रहा। सोवियत रूस का मशीन औजार उद्योग कुछ समय पूर्व ही स्थापित हुआ था, लेकिन ४० वर्ष की अल्प अवधि में ही इसने काफी प्रगति कर ली है। इन सब देशों में मशीन औजारों का उत्पादन द्वितीय महायुद्ध की अवधि में काफी बढ़ गया था और युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण मशीन औजारों के निर्माण में क्रान्तिकारी टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हुये। युद्ध के पश्चात् इन टेक्निकल परिवर्तनों को बहुत बढ़ कर लिया गया है और उनका प्रयोग साधुनिवृत्त मशीन औजार बनाने में किया जाता है। औद्योगिक देशों में मशीन औजार उद्योग की टेक्नोलॉजिकल प्रगति दो दशकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है—प्रथम, हाई स्पीड कटिंग और द्वितीय ओटोमेशन। Numerical control की प्रगतिशील टेक्नीक के प्रचलन ने तो मशीन औजार-उद्योग को पूर्णतः स्वचालित (automatic) बना दिया।

भारत में मशीन दूल उद्योग

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में हिन्दुस्तान मशीन टूल लि० की प्रगति अनेक मामलों में उल्लेखनीय है। इसने प्रति वर्ष अपने उत्पादन के केवल नये रिकार्ड ही स्थापित नहीं किये बल्कि अनेक नयी वस्तुओं का उत्पादन भी किया है। छोटी सी अवधि में ही इसने काफी मुनाफा भी दिखाया है और साथ ही ऐसी नीतियाँ भी अपनाई हैं जिनमें कि आयात की गई मशीनों की तुलना में अपने मशीनी औजार सस्ते मूल्य पर देचे जा सकें। इस कम्पनी की एक और विशेषता यह है कि अपनी ही कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसने अपने ही विकास और विस्तार के हेतु भी लगाया है।

मशीनी औजारों को अक्सर 'जननी मशीनें' भी कहा जाता है, जो अन्य मशीनों को जन्म देती हैं और इस प्रकार वे किसी देश के औद्योगिक विवास के मूल-आधार की नींव रखती हैं। हमारे देश में बढ़ते हुए औद्योगिककरण के कारण मशीनी औजारों की मांग काफी बढ़ गई है। गणना की गई है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह मांग प्रतिवर्ष ५५ से ६० करोड़ रु० के आस-पास तक हो जायगी। उद्योग मन्त्री श्री

मनुमोई शाह ने अभी हाल में ही कहा था कि तीसरी योजना की अवधि में भारत की प्रतिवर्ष ४५ करोड़ रु० के मूल्य के मशीनी औजार बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

यहां यह बता देना आवश्यक नहीं होगा कि सन् १९६० में मशीनी औजारों का उत्पादन लगभग १० करोड़ रु० का होने का अनुमान लगाया गया है, लगभग ६ से ७ करोड़ रु० का विशाल उद्योगों द्वारा और लगभग ३ से ४ करोड़ का लघु उद्योगों द्वारा। उक्त उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत सरकारी कारखानों द्वारा किया बताया जाता है। हाल ही में मशीनी औजारों के आयात में काफी वृद्धि हो गई है। जो आयात सन् १९५१ में २५ करोड़ रु० था वह सन् १९५६ में बढ़कर ८३७ करोड़ रु० हो गया। दूसरी योजना की अवधि में, औद्योगिक विस्तार के चरणों की गति बढ़ जाने के कारण यह अंक और भी बढ़ गया था। सन् १९५८ और सन् १९५९ में ये आयात क्रमशः १५३१ करोड़ रु० और १७०० करोड़ रु० रहा।

एच० एस० टी० की प्रगति—

मशीनी औजारों के उत्पादन करने में, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का स्थान प्रथम है। इसका कारण है कि जो कुछ लोगों द्वारा अभी अनिश्चित प्रकार का सार्वजनिक विनियोग माना जाता था, अब यह सफलता का एक आदर्श बन गया है। आरम्भ के दिनों में इसकी प्रगति अनेक कारणों से कुछ धीमी सी थी। स्विट्जरलैंड स्थित ज्यूरिख के प्रसिद्ध मैसर्स ओरलिकन मशीन टूल्स वर्क्स के साथ हुए सहयोग-करार के फलस्वरूप यह प्रायोजना सन् १९५६ के उत्तरार्द्ध में प्रगति में आई।

मै० ओरलिकन मशीन टूल्स वर्क्स के साथ परामर्श करके कम्पनी के उत्पादन का आरम्भिक कार्यक्रम सन् १९६०-६१ तक ४०० मशीनें प्रतिवर्ष बनाने का रखा गया था। जबसे द्वितीय योजना आरम्भ हुई है तब से अनेक उपाय किये गये हैं जैसे अनेक गारिया चलाना, अतिरिक्त कर्मचारियों की आपत्तिकालीन भर्ती, प्रशिक्षण की अधिकाधिक सुविधाएं देना, आवश्यकतानुसार पुर्जों और कच्चे माल की आपत्तिकालीन खरीदों और कारखाने में लगे कर्मचारियों की अधिकाधिक देखभाल तथा बुझलता में उत्प्रेरणा—इनके परिणामस्वरूप इस कारखाने में मशीनी औजारों के उत्पादन में ठोस वृद्धि हुई है।

मासिक और आयोजित उत्पादन के आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	वास्तविक उत्पादन	दूसरी योजना का लक्ष्य
१९५६-५७	१३५	१७
१९५७-५८	४०२	१३१
१९५८-५९	५५२	२३८
१९५९-६०	७०१	३१४
१९६०-६१	१,०००	४००

अपने उत्पादन में अनेकरूपता लाने की दृष्टि से हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि० ने दो प्रसिद्ध जर्मन फर्मों अर्थात् मैसर्स फिट्ज वानर के साथ जनवरी सन् १९५७ में और कोयलिन के मैसर्स हरमन कोल्ब के साथ जून सन् १९५८ में प्रविधिक सहायता करार किये। इन करारों के अनुसार कारखाने में हारीजोण्टल, वर्टिकल और यूनिवर्सल मिलिंग मशीनें (आकार २ तथा ३) और दस प्रकार की रेडियल बर्मा मशीनें बननी आरम्भ हो गई हैं। कम कीमत की खरादें बनाने के लिये फास के मैसर्स सोसाईटि एच० एनल्टि डेटिंगोल्स के साथ जून सन् १९५९ में एक अग्र करार पर हस्ताक्षर किये गये। १६ प्रकार की बेलनाकार घिसाई मशीनें बनाने के लिये इटली के मैसर्स आफीसियाना मैकसानिका मोलिवेट्टी के साथ अक्टूबर सन् १९६९ में एक और करार किया गया, जो तीन साल के भीतर पांचवा करार था। इन मशीनों की पट्टी खेप सन् १९६० के मध्य में बाजार में आई, जिनकी कीमते १५,००० और इससे ऊपर थी, किन्तु उसी किस्म की बाहर से मगाई गई मशीनों के बच्चे पर पड़े हुए मूल्य से कम ही थी।

सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें भविष्य में काफी सम्भावनाएं हैं वह है विदेशी फर्मों के साथ बतमान करारों को करने के बजाय कम्पनी द्वारा मशीनों की रूपरेखा स्वयं ही तैयार करने का प्रयत्न। इसका परिणाम है रूपरेखा और विकास विभाग की स्थापना। इस विभाग ने एक नवीन उच्च गति वाली शुद्ध मापक खराद की रूपरेखा तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। भारी ड्यूटी वाली टैरेट खरादें और बड़े आकार के रेडियल बरमा की रूपरेखाएँ बनाने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

उत्पादन की किस्में—

हिंदुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादनो की किस्म अधिक ॥ अधिक अच्छे स्तर पर रखने की काशिश की गई। अब कम्पनी नीचे लिखे ६० प्रकार के विभिन्न मशीनों का बाजार बमगती है।

- (१) १४ प्रकार की उच्चगति वाले शुद्ध मापक केन्द्र खरादें, जिनकी ऊँचाई २२५ मिली मी० से २६० मिली मी० और केन्द्र का अन्तर १,००० मिली मी० से ५,००० मिली मी० है।
- (२) ६ प्रकार की घिसाई मशीनें—होरीजोण्टल, यूनिवर्सल और वर्टिकल प्रत्येक दो आकारों में।
- (३) १० प्रकार के घुमावदार बरमे, हत्ये की लम्बाई १,०५० मिली मी० से २,२०० मि० मी० और डले ताहे की क्षमता ५० मि० मी० से ६० मि० मी०।
- (४) ४४ प्रकार की कम कीमत वाली डेटिंगोल्स प्रकार की खरादें, केन्द्र ऊँचाई १७० मि० मी० ॥ २८५ मि० मी० तक।
- (५) १६ प्रकार की शुद्ध मापक ढोलाकार की घिसाई मशीन, जो यूनीवर्सल ग्राइव्शन और प्लज प्रकार की है और जिनकी केन्द्र ऊँचाई १३०

मि० मी० से १७० मि० मी० और केन्द्र का अन्तर ४०५ मि० मी० से २,१५० मि० मी० तक ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सबसे अच्छे ग्राहक क्रमानुसार निजी उद्योगपति, सरकारी निगम, राज्य सरकारें और भारत सरकार हैं, जिनमें रेलें भी शामिल हैं ।

स्वयं वित्त-पोषण द्वारा विस्तार

इसके विकास के लिये आरम्भ में लगभग एक करोड़ रुपये का जो भारी खर्च करना पड़ा था वह अब लाभ में से पूरा किया जा चुका है, किन्तु अब छोटी सी अवधि में ही कम्पनी ने काफी धन कमा लिया है, जिसके कारण अब कम्पनी अपनी क्षमता दुगुनी करके २,००० मशीनों प्रति वर्ष तक बढ़ाने में समर्थ हो सकी है । इसके विस्तार कार्यक्रम के लिये खर्च की कुल लागत २८१ करोड़ ६० घाने का अनुमान है और विस्तार का यह कार्यक्रम अगले साल के शुरू तक पूरा हो जाने की आशा है । ३,००० टन क्षमता वाली जो फाउण्ड्री तैयार की जा रही है उसकी क्षमता दुगुनी करके ६,००० टन की जा रही है । इस कारखाने को बढ़ा कर दुगुना करने के लिये जरूरी मशीनों की री-तिहाई सख्या कम्पनी द्वारा ही बनाई गई सरादो, घिसाई मशीनों, घुमावदार बरमो, पीसने वाली और अन्य मशीनों में से पूरी की जायगी ।

इनके अलावा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० एक उद्योग-बस्ती का प्रवर्तन करके सहायक-पूरक उद्योगों के विकास प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करता रहा है । मशीनी धोजारों के निर्माण के लिये, १,००० मशीनें प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता के साथ साथ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को २० साल अधिक विभिन्न प्रकार के पुर्जों के हिस्से प्रतिवर्ष बनाने पड़ते हैं । जैसा कि अभी हो रहा है, इन पुर्जों का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के मुख्य कारखाने में ही निर्माण करने के बजाय उद्योग बस्ती में इस प्रकार के अनेक सहायक पूरक लघु उद्योगों की स्थापना का विचार है, जिनका स्वामित्व और प्रबन्ध श्रमिक स्वामी प्रकार के लघु उद्योगिकों के हाथ में हो और उन्हें सरल प्रकार के पुर्जों के छोटे-छोटे ठेके दिये जायें, जिनके लिये भारी उपकरणों और बहुत उच्च स्तर की कुशलता और तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती । आशा है हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की उद्योग बस्ती १८ एकड़ क्षेत्र घेरेंगी और इसमें ५० कारखाने होंगे । सहायक पूरक उद्योगों को बढ़ावा देकर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपनी मशीनों का उत्पादन और बढ़ाने की स्थिति में हो जायगा ।

इन उपायों के फलस्वरूप मशीनी धोजारों का उत्पादन पहले ही काफी बढ़ गया है । मार्च सन् १९६१ में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने १३१ मशीनों का अभूतपूर्व उत्पादन किया था, जबकि मार्च सन् १९६० में सबसे अच्छा उत्पादन १२६ मशीनों का हुआ था । सन् १९६०-६१ के राजकोषीय वर्ष में १,००० का उत्पादन हुआ, जबकि आयोजना का लक्ष्य ४०० मशीनों का रखा गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि सितम्बर सन् १९६० से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स १०० अथवा इससे अधिक मशीनें प्रति मास बनाता रहा है । विस्तार पूरा हो जाने के बाद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा

उत्पादनों का मूल्य ७ करोड़ रु० तक हो जायगा। बंगलौर के कारखाने की क्षमता के बराबर का एक अन्य कारखाना पंजाब में स्थापित करने की योजना भी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बनाई जा रही है।

प्रागा टूल्स कारपोरेशन—

मशीनी औजारों के उत्पादन में अधिक सोच लाने के लिये भारत सरकार ने हैदराबाद स्थित प्रागा टूल्स कारपोरेशन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। मई सन् १९४३ में स्थापित हुई इस कम्पनी ने अनेक उत्तार चढ़ाव दिये हैं। इस समय यह कम्पनी अनेक प्रकार के बढ़िया किट के मशीनी औजार, मशीन औजारों के पुर्जे, शुद्ध मापक औजार, आटोमोबाइल्स और डीजल इंजनों के हिस्से, रेलों के पुर्जे आदि का निर्माण करती है।

विविध प्रकार के मशीनी औजारों का उत्पादन करने के लिये इस कारखाने का विस्तार किया जा रहा है। प्रविधिक सहयोग के लिए तीन ब्रिटिश फर्मों के साथ करार किया जा चुका है। पहला करार ससेक्स स्थिति होके मैसर्स कीने एण्ड ट्रैक्टर सी० डी० ए० लि० के साथ उनके प्रसिद्ध ड्रिल चको का भारत में निर्माण करने के लिए किया गया है। दूसरा है हलीफाक्स के मैसर्स एफ० ग्रैंट एण्ड क० लि० के साथ, इसके अधीन वे कम्पनी विभिन्न प्रकार की खराद चकें, म्यूमेटिक चक और मैग्नेटिक ला और म्यूमेटिक जॉर्क आदि का निर्माण भारत में करेंगे। इस प्रकार के औजारों का स्थापना-परिष्करण उद्योग के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि इन औजारों के बिना मशीनी औजार स्वयं भी पर्याप्त नहीं हो सकते। तीसरा करार लीसेंस्टर के मै० ए० ए० रोन्स एण्ड शिपमैन के साथ अपने कटाई और घिसाई औजारों का भारत में निर्माण करने के लिए किया गया है।

मशीनी औजार उद्योग के विस्तार के लिये पालिश सरकार द्वारा एक करोड़ रु० का जो ऋण स्वीकार किया गया है उसका उपयोग करके प्रागा टूल्स कारपोरेशन का उत्पादन बढ़ाकर १२० लाख रु० तक कर देने का प्रस्ताव है। ऊपर बताये गये तथ्यों के परिणामस्वरूप आशा है कि आगामी महीनों में देश में मशीनी औजारों का उत्पादन काफी बढ़ जायगा।

उद्योग का भविष्य—

सधुर्माने के क्षेत्र से प्राप्त होने वाले लगभग ५ करोड़ रु० के उत्पादन के अतिरिक्त मशीन औजारों के उत्पादन का लक्ष्य सन् १९६५-६६ तक ३० करोड़ रु० का रखा गया है, जबकि द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष का उत्पादन लगभग ७ करोड़ रु० का था। यद्यपि उत्पादन में तीन गुनी वृद्धि हो जायेगी तथापि वह तीसरी योजना के अन्त तक मशीन औजारों की सम्भावित भाग—५० करोड़ रु० प्रति वर्ष—से बहुत कम रहेगा। कुशल श्रम की कमी के कारण अधिक बढ पैमाने पर उत्पादन करना अभी सम्भव नहीं है। विदेशी मुद्रा की जो व्यवस्था की गई है उसके अनुरूप

जवाहरी के हिन्दुस्थान मशीन टूल्स (H. M. T) एव प्राया टूल्स हैदराबाद का विकास किया जायेगा तथा रावी के निकट एक नया भारी मशीन औजार कारखाना तथा पञ्जाब में भी H. M. T के सदस्य एक नया कारखाना खोला जायेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में इन मशीन औजार कारखानों का सम्मिलित उत्पादन तथा रक्षा मन्त्रालय की प्रोटोटाइप फैक्टरी (घम्बरनाथ) का उत्पादन कुल १५ करोड़ तक बढ़ जायेगा। प्राइवेट क्षेत्र में विद्यमान कार्यरत मार्क-जनिक क्षेत्र की योजनाओं के पूरक होंगे।

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the history, present position and future prospects of the Machine Tools Industry in India

अध्याय ७२

ऑटोमोबाइल उद्योग

(Automobile Industry)

प्रारम्भिक—

शान्ति तथा युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में मोटरों की आवश्यकता होती है। मोटर निर्माण के लिए लोहे तथा कोयले की आवश्यकता होती है और ये दोनों वस्तुएँ भारत में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, किन्तु फिर भी अभी तक हमारे देश में विदेशों से मोटरों का सामान आयात किया जाता है। भारत में लगभग ४६ लाख मोटर गाड़ियाँ हैं। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है, देश के विस्तार और जन-संख्या को देखने हुए, अन्य देशों की तुलना में यह बहुत कम है —

प्रति मोटर पीछे जन-संख्या का अनुपात

देश	जन संख्या
ग्रेट ब्रिटेन	१५
कनाडा	८
सं० रा० अमेरिका	३
फ्रांस	१४
न्यूजीलैण्ड	४७
भारत	१,२६६

भारतीय जनता की आय कम होने तथा उनका रहन-सहन का स्तर नीचा होने के कारण यहाँ मोटर गाड़ियों की माँग कम है। इसके अतिरिक्त दो अन्य अमुविधाएँ भी हैं—उत्पादन का अधिक मूल्य और सड़कों की हीन व पिछड़ी दशा। भारत सरकार की ओर से इस उद्योग की संरक्षण मिला है। किन्तु फिर भी इसकी आशाजनक प्रगति नहीं हो पाई है, क्योंकि विदेशों से आयात की गई मोटर गाड़ियों तथा डीजल इंजन के टूकों से भी भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

उद्योग के प्रमुख केन्द्र—

गत कुछ समय से ही बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में विदेशों से सामान आयात करके और फिर उसका एकत्रीकरण करके मोटर गाड़ियाँ तैयार करने का उद्योग शुरू किया गया। इस समय हमारे देश में निम्नलिखित १२ कारखाने हैं, जिनमें ८,००० व्यक्ति लगे हुए हैं तथा ४२ करोड़ की पूँजी लगी हुई है।

(अ) महाराष्ट्र में—

- (१) जनरल मोटर्स लिमिटेड।
- (२) फोर्ड मोटर कम्पनी।
- (३) प्रीमियर मोटोमोबाइल लिमिटेड।
- (४) महेन्द्र एण्ड महेन्द्र लि०।
- (५) हट्स ग्रुप।

(ब) मद्रास में—

- (१) एडीसन एण्ड क०।
- (२) स्टैंडर्ड मोटर क०।
- (३) अशोक मोटर्स।

(स) प० बंगाल (कलकत्ता) में—

- (१) हिन्दुस्तान मोटर्स लि०।
- (२) फ्रेञ्च मोटर कम्पनी।
- (३) पैनिनसुला मोटर कॉरपोरेशन।
- (४) देवास गैरेज एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स।

उक्त राज्यों के अलावा बनारस व जमशेदपुर केन्द्रों में भी इस उद्योग के विकास के लिए काफी सुविधाएँ हैं। ये दोनों ही केन्द्र लोह क्षेत्रों के मध्य स्थित हैं। दूसरे, यहाँ आयात की हुई मशीनों व मोटर के भागों की आसानी से लाया जा सकता है। देश के प्रमुख इन्जीनियरिंग केन्द्र होने के कारण यहाँ कृशल श्रम भी उपलब्ध है। ऐसा अनुमान है कि निकट भविष्य में यह उद्योग मोटर सम्बन्धी ८०% कल पूरे भारत में ही बनाने लगेगा। अभी भारत में पूरी मोटर गाड़ी का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। अनुमान है कि तृतीय योजना के अन्तर्गत ३० हजार सवारी गाड़ियाँ, ६० हजार व्यापारी गाड़ियाँ और १० हजार जीपें आदि प्रति वर्ष बनने लगेंगी। सम्भवतः सन् १९६३ तक सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत सस्ती जनता मोटर गाड़ियाँ बनने लगगी, जिनका मूल्य ५,००० व ७,००० रु० के मध्य होगा।

उत्पादन—

गत कुछ वर्षों में मोटर गाड़ियों एवं साइकिलों का उत्पादन इस प्रकार रहा है—

मोटर गाड़ियाँ (सख्या)

हिस्से

(मूल्य ००० रुपये)

पूरी तैयार
(सख्या)

योग

सवारों

गाड़ियाँ

बार जीप तथा लैंडरोवर

गाड़ियाँ

स्टेशन बैगन तथा

अस्पतालो गाड़ियाँ

ट्रक

वर्ष

वर्ष	बार जीप तथा लैंडरोवर गाड़ियाँ	स्टेशन बैगन तथा अस्पतालो गाड़ियाँ	ट्रक	सवारों गाड़ियाँ	योग	पूरी तैयार (सख्या)	हिस्से (मूल्य ००० रुपये)
१९५२	६,६४८	—	—	—	१४,२८८	१,६३,६५३	८,२४७.३
१९५३	४,६३२	—	—	—	१३,६२०	२,३४,१६८	१०,१६४.०
१९५४	५,४३६	—	—	—	१४,४६०	३,७२,३३०	१३,०८०.०
१९५५	६,४६२	—	—	—	२३,०८८	४,६१,१७२	१३,४१६.८
१९५६	१२,६८४	७६८	६,४४६	३,०३६	३२,१३६	६,६३,६७३	२३,२२४.८
१९५७	११,४०४	६५४	११,८६२	३,७५६	३१,६३२	८,००,८३२	२७,६४४.६
१९५८	११,४०४	३००	११,०२८	४,१०४	२६,७६६	६,१२,६२४	२३,०१६.०
१९५९	७,८१२	१२	१०,७२८	४,८४८	४१,१७२	६,६०,८१६	३८,०४०.०
१९६०	११,७१२	—	२०,६६४	६,१०८	४१,६१०	१०,४०,७४४	५०,७६७.२
१९६१	१६,०७२	—	—	४,८८६	४,६८६	६०,३४३	३,२७१.६
१९६२	२,०४०	—	—	४,६६६	४,१५३	६४,०८०	३,४४०.०
१९६३	२,२१३	—	—	४,०१२	४,३४४	६६,४६६	३,६१५.६
१९६४	२,३७०	—	—	३,८८८	४,७६४	१,००,१८४	—
१९६५	१,६८२	—	—	३,६१४	४,७१६	—	३,६०६.७
१९६६	१,७३१	—	—	१,६१४	४,६४४	—	—

[ए] सन् १९४८ से सन् १९५३ तक के वर्गों के अङ्को मे पूरी साइकिल बनाने वाली फर्मों द्वारा तैयार किए गये हिस्से

तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योग का भविष्य—

तीसरी योजना के लिए उत्पादन के लक्ष्य निम्न रखे गये हैं :—

	संख्या
पैसिन्जरकार	३०,०००
कॉमर्सियल व्हीकलें	६०,०००
जीप एवं स्टेशन बैगन	१०,०००
मोटर साइकिलें, स्कूटर और तीन पहिये वाली गाड़ियाँ	६०,०००

विदेशी मुद्रा के साधनों पर अधिक दबाव न पड़ने पाये, इसके लिए यह आवश्यक है कि ८५% पुर्जों देश में ही बनाये जायें, जबकि अभी ६०% पुर्जों देश में बन रहे हैं। नए नई इकाइयों की स्थापना या पुरानी इकाइयों के विस्तार के पूर्व देशों पुर्जों का निर्माण करने में उद्योगों में विनियोग की वृद्धि करनी होगी। व्यापारिक व्हीकलों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जावेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में छोटी कारों के निर्माण में विदेशों से सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा हो रही है। यूरोप और जापान के प्रसिद्ध कार निर्माताओं के प्रस्तावों पर पांडे वमेटी ने विचार किया है और कीमतों पर यह वमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देंगे। डाक्टर बी० डी० कालेलकर (भारत सरकार के सीनियर औद्योगिक परामर्शदाता) ने यूरोप का दौरा करते समय ५० जर्मनी के निर्माताओं में भी बातचीत की थी।

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the present position and future prospects of the Indian Automobile Industry
2. Write a short note of the manufacture of Small car in the sector.

अध्याय ७३

रासायनिक उद्योग

(Chemical Industry)

महत्त्व—

रासायनिक उद्योग किसी भी राष्ट्र के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि रासायनिक व यान्त्रिक उद्योगों के विकास पर ही देश का औद्योगिक विकास निर्भर करता है। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिये रसायनों का उत्पादन आवश्यक है, जैसे कपड़ा, रेयन, शीशा, रबर, कागज, माबुन, सिरामिक, उर्वरक, रंग, औषधियाँ, पेठ, चार्ज, वनस्पति, प्लास्टिक, जानवरो के तेल, पेट्रोलियम, आदि। सामान्यतः रासायनिक उद्योगों के अन्तर्गत उन उद्योगों का समावेश किया जाता है जो अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में वे उद्योग भी आते हैं, जिनमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं। इम्पीरियल रासायनिक उद्योग के अध्यक्ष के अनुसार, "यह उद्योग सभी उद्योगों में सबसे अधिक बहु पति वाला उद्योग है, क्योंकि यह रसायन वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, इंजीनियरों आदि की सहकारिता पर निर्भर करता है।"

रासायनिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं —

(१) भारी रासायनिक उद्योग (Heavy Chemicals)—इनके अन्तर्गत गन्धक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शोरे का तेजाब, विभिन्न प्रकार के सल्फेट, कार्बिक सोडा, सोडा एस, अमोनिया, स्क्विग पाउडर, बलारिन, पोन्डिशियम क्लोरेट और रासायनिक सादे, जैसे—अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, शोरा आदि का उत्पादन सम्मिलित है।

(२) कीमती व हल्के रासायनिक पदार्थ (Fine Chemicals)—इनके अन्तर्गत फोटोग्राफी में काम आने वाले रसायन, दवाइयाँ, रंग और रोगन आदि शामिल किए जाते हैं।

पुद्गोत्तर विकास—

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व हमारे भारी रासायनिक उद्योगों की स्थापना हुए अधिक दिन नहीं हुए थे। उस समय केवल गन्धक का तेजाब और उससे बनने वाली

वस्तुयें ही बनाई जाती थी, किन्तु धुइ बाल मे विदेशी से रासायनिक पदार्थों के न मिलने के कारण इनका उत्पादन देश मे ही किया जाने लगा । सुनियोजित प्रयत्नो और सरक्षण के लिये किये गये उपायो के फलस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों से देश मे श्रीमीन, कैल्शियम कार्बाइड, कारबनडाइ सल्फाइड, डी०डी०टी, वेजीन हैक्साक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, विशेष लवण, रंग, प्लास्टिक आदि बनाये जा रहे हैं ।

विशेषतायें—

भारत मे इस उद्योग की निम्न विशेषतायें हैं :—

(१) रासायनिक पदार्थों को तैयार करने के लिए साधारणतः छोटे-छोटे कारखाने हैं ।

(२) आधारभूत रासायनिक पदार्थों का मुख्य अधिक पडता है ।

(३) हमारे रासायनिक उद्योग अभी बड़ी पिछड़ी दशा मे हैं । अन्य रासायनो की तो बात ही नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा एश जैसी जहरी चीजों का उत्पादन भी हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता ।

(४) रासायनिक पदार्थों की पूर्ति के लिये हमे विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पडता है ।

(५) रासायन उद्योगों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी है ।

(६) रासायनिक पदार्थों का उत्पादन व्यय भी बहुत अधिक पडता है । उत्पादन मूल्यों को घटाने से ही दूसरे उद्योगों मे इन पदार्थों की खपत बढ़ाई जा सकती है । इसका मुख्य उपाय यही है कि इन्हे तैयार करने वाले कारखानों के आकार बढ़ाये जायें और उद्योग ऐसे स्थानों पर कायम किये जायें, जहाँ कच्चे माल, विद्युत आदि की सुविधायें हों ।

उद्योग के मुख्य केंद्र—

इस उद्योग के मुख्य केन्द्र बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, भागरा, अमृतसर, अम्बाला कानपुर, डालमियानगर, जमशेदपुर, अहमदाबाद, थाना, मद्रास, मेदूर, मद्रावती, बंगलौर, त्रावनकोर इत्यादि हैं । समस्त देश मे छोटे-बड़े कुल मिला कर १५० कारखाने हैं । सिन्दरी मे रासायनिक खाद बनाई जाती है । बंगाल मे तेजाब और बडोदा मे मिटनकोट स्थान पर सोडा एश तथा कास्टिक सोडा बनाया जाता है । त्रावनकोर तथा मेसूर मे भी खाद बनाने के कारखाने हैं । बङ्गाल केमिकल कम्पनी, कलकत्ता, बंगाल इम्पूनिटी कम्पनी, कलकत्ता तथा अलेम्बिक केमिकल कम्पनी, बडोदा मे अम्लेजी दवाइयाँ तथा इन्जेक्शन बनाने हैं । पेनिसिलीन तथा गन्धक की औषधियाँ बनाने के लिए बम्बई मे एक कारखाना २३ करोड़ ६० की लागत से बनाया गया है ।

नये विकास—

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल मे अग्रलिखित तीन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स बनाये गये हैं ।

(१) नगल प्रोजेक्ट—फर्टिलाइजर्स प्रोजेक्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने यह प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका कार्य मार नगल फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी के हाथ में है। इसकी उत्पादन क्षमता ७०,००० टन (घमोनियम नाइट्रेट) प्रति वर्ष होगी और साथ ही हैवी वाटर भी बनाया जाता है।

(२) रुकेला फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट—इस प्रोजेक्ट द्वारा ८०,००० टन नाइट्रोलाइम स्टोन प्रति वर्ष बनता है।

(३) नवेली प्रोजेक्ट—यह प्रोजेक्ट दक्षिण में बनाया गया है और लिगनाइट प्रोजेक्ट का एक भाग है। यह प्रति वर्ष ७०,००० टन सलफेट नाइट्रेट और गूरिया की खाद बनाता है।

तृतीय योजना में रासायनिक उद्योग—

उर्वरक—अनुमान है कि सन् १९६५-६६ तक १० लाख टन नत्रजनयुक्त और ४ लाख टन पी२ आ२ युक्त उर्वरक की जरूरत होगी। नत्रजनी खाद मिश्रित रूप से बनाई जाएगी, ताकि फास्फेट की जरूरत भी कुछ हद तक इसमें पूरी हो सके। नत्रजनी खाद के कारखाने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र में खोले जायेंगे। सरकारी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता तीसरी योजना के अन्त तक ७ लाख ३० हजार टन हो जायगी। निजी क्षेत्र में भी ५ नये कारखानों की बढ़ाने की और एक कारखाने का विस्तार करने की इजाजत दे दी गई है। इनमें करीब ४ लाख टन नत्रजन पैदा होगा। सुपरफास्फेट बनाने के जिन कारखानों की अनुमति दे दी गई है उनके और सरकारी तथा निजी कारखानों में बनने वाले मिश्रित उर्वरकों से सन् १९६५-६६ तक ४ लाख टन फास्फेट उपलब्ध होने की आशा है, जो हमारी जरूरत के लिए काफी है।

गंधक का तेजाब, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश—तीसरी योजना में सन् १९६५-६६ तक गंधक का तेजाब १७ लाख ५० हजार टन, कास्टिक सोडा ४ लाख टन और सोडा ऐश ५ लाख ३० हजार टन बनाने का लक्ष्य है। कास्टिक सोडा और सोडा ऐश दोनों में तीसरी योजना के अन्त तक हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

कार्बनिक रसायन—इन क्षेत्र में भी बहुत विकास होगा। प्लास्टिक, रंग और दवाओं के उद्योगों के विकास के कारण कार्बनिक रसायन उद्योग के लिए बहुत गुंजाइश हो गई है और करीब ४० ऐसे रसायनों को बनाने का इन्तजाम किया जायगा जिनका कुल उत्पादन २५,१६० टन होगा और इसमें १५ हजार टन की और वृद्धि करने की भी व्यवस्था है।

दवायें—भारत-प्रदेश में सनत नगर में कृत्रिम (सिंथेटिक) दवाओं का बॉर-खाना, श्रृणिकेश के पास एण्टी-बायोटिक दवाओं का कारखाना और केरल में फोटो कैमिकल कारखाना खोला जायगा। इनके अलावा निजी कारखानों में जो दवायें बनें वो उनको मिलाकर तीसरी योजना के अन्त तक हमारा देश मुख्य-मुख्य दवाओं में प्रायः आत्म-निर्भर हो जायगा।

STANDARD QUESTIONS

1. Write a note on the present position and future prospectus of Chemical Industry

अध्याय ७४

चमड़ा उद्योग

(Leather Industry)

महत्त्व —

चमड़ा उद्योग भारत का बड़ा प्रगतिशील उद्योग है। यह दो वस्तुओं पर निर्भर करता है—(१) जानवरों की छाल, और (२) चमड़ा कमाने की वस्तुयें। दुनियाँ से सबसे अधिक चीपाये हमारे देश में ही हैं, अतः छालों की यहाँ अधिकता है। चमड़ा कमाने का सामान भी यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दक्षिणी भारत के कुछ प्रदेशों में (विशेषतः मैसूर, हैदराबाद तथा मद्रास) तुखार वृक्ष (Acacia) की छाल चमड़ा कमाने के प्रयोग में आती है। उत्तरी भारत में बबूल की छाल का प्रयोग किया गया है। मायरोबालान तो भारत के सभी धनो में पाये जाते हैं। इसके फल की भी चमड़ा कमाने के प्रयोग में आते हैं। बड़ेछा की छाल भी इस हेतु प्रयोग की जाती है। इनके अलावा रासायनिक पदार्थों की सहायता से भी चमड़ा कमाया जाता है।

हमारे देश में छूते बनाने के दो बड़े कारखाने हैं—कूपर ऐलन एण्ड कम्पनी, कानपुर और बाटा शू कम्पनी, बाटा नगर (कलकत्ता)। कानपुर में सरकारी कारखाना—घोड़े की जीन आदि भी बनाना है। अन्य मुख्य केन्द्र घाघरा, लखनऊ, कलकत्ता, मुमबई, मद्रास तथा बंगलौर हैं। कानपुर में इस उद्योग का केन्द्रीयकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

- (१) यहाँ अंग्रेजों ने इस व्यवसाय की नींव डाली एवं राज्य सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया।
- (२) धनी जन संख्या के कारण यहाँ का श्रमिक सस्ता है।
- (३) चमड़ा कमाने के लिए बबूल की छाल प्रचुर मात्रा में मिल जाती है।

- (४) यहाँ यातायात के सभी साधनों का बहुल्य है ।
 (५) युद्ध-युग में यहाँ के कारखानों को विशेष प्रोत्साहन मिला ।
 (६) मार्ग के लिए भी यहाँ विस्तृत बाजार है ।

कानपुर, मद्रास तथा कलकत्ते में क्रोम चमड़ा बनाया जाता है । भारत से कच्चे चमड़े का अधिक निर्यात किया जाता है । भारतीय चमड़े से सुन्दर-सुन्दर वस्तुय बनाकर हम अपने निर्यात बढ़ा सकते हैं तथा देश को भी धनी कर सकते हैं ।

उत्पादन—

निम्न आँकड़ों से चर्म उद्योग के उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है—

वर्ष	पश्चिमी ढंग के छूने ('००० जोड़)	देशी ढंग के छूने (००० जोड़)	क्रोम से कमाया गया (०००)	वनस्पतियों से कमाया गाम का चमड़ा ('०००)	चमड़े जैसा कपड़ा ('००० गज)
१९४३	३,३४८ ०	२,२०४ ४	७०० ८	१,२९८ ४	९८५ २
१९४४	३,२६७ ६	२ ०६- ८	६६८ ४	१,३७० ४	१,२६१ २
१९४५	३ २४२ ४	२,३०२ ८	६७६ ४	१,६३६ ६	२,६२३ २
१९४६	३,६२० ४	२,९११ २	७४१ ६	१,६८३ ६	२,६४० ०
१९४७	४,३६९ २	३ ०३८ ४	६३० ०	१,७९१ ६	३,६५६ ४
१९४८	४,२७६ ८	३,२८६ ८	६७८ ०	२,०६७ ६	४,२४३ २
१९४९	४,१४० ०	४,१०२ ८	६५० ४	२ ४६६ ०	५,४४४ ४
१९६०	६,४१८ ४	३,७७७ ६	७९४ ४	२,६७८ ४	५,८४६ ४
१९६१					
जनवरी	५१५ २	३३० ३	६२ ०	२२० ०	६४५ ४
फरवरी	४८२ ८	३२८ ५	७३ ९	२३३ ५	५५९ ०
मार्च	४२१ ०	३२० ०	६४ ३	२२८ ०	५८३ ३
अप्रिल	४६१ ६	३४८ ४	६३ ०	२१० ०	५८७ १
मई	४०९ ५	३७३ २	७२ ५	१८३ ९	—

STANDARD QUESTION

Write a short note on the Indian Leather Industry

अध्याय ७५

काँच उद्योग

(Glass Industry)

प्रारम्भिक—

भारतीय शीशे तथा काँच के उद्योग का योजनावद्ध विकास करने का तथा इसे अन्य उद्योगों के स्तर पर लाने का प्रयास पिछले दशक के कुछ वर्षों में ही किया गया है। औद्योगिक निर्माण उद्योग ने काँच उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है, क्योंकि दवाइयों तथा अन्य रासायनिक पदार्थों को बढ़ा करने के लिये बोतलों तथा काँच के सामान की आवश्यकता पड़ती है। काँच उद्योग के प्रारम्भिक विकास की अवस्था में बहुत उपयोगी तथा अर्द्ध-स्वचालित ढङ्ग की मशीनों से उत्पादन होता था। उद्योग का सर्व प्रथम अर्द्ध-स्वचालित ढङ्ग का शीशे का कारखाना जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से पंजाब में शुरू किया गया था। यद्यपि यह बहुत थोड़ा समय तक ही चल सका, किन्तु फिर भी इसने भविष्य में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता व द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थापित होने वाले शीशे के उद्योगों के लिए एक आधार प्रस्तुत किया। यही कारण था कि सन् १९१८ तक देश में १४ शीशे के कारखाने चालू हो गये थे। सन् १९२० के द्वितीय स्वदेशी आन्दोलन से उद्योग को बहुत बल मिला। लेकिन सन् १९३६ तक यह उन्नति सीमणित से नहीं हो सकी। काँच की चूड़ियाँ बनाने वाले कारखाना समेत शीशे का सामान बनाने वाले कारखानों की संख्या सन् १९३६ की केवल ८० से बढ़कर सन् १९५० में २०० हो गई तथा उत्पादन ४०,००० टन वार्षिक से बढ़कर ८५,००० टन हो गया। शीशे के सामान के निर्माण के ढङ्ग में तेजी से परिवर्तन हुए। मुँह से फूँक मार कर सामान बनाने के ढङ्ग का स्थान अधिक सस्ती तथा अर्द्ध-स्वचालित मशीनों ने ले लिया। इस प्रकार निर्माण में अधिक वैज्ञानिक ढङ्ग को स्थान मिला।

संक्षिप्त इतिहास—

काँच उद्योग की प्रगति का सरकार द्वारा सर्वेक्षण सर्व प्रथम सन् १९३१ में हुआ। तत्पश्चात् प्रायोग ने सर्वेक्षण देने के हेतु इस उद्योग की जाँच की तथा पुनः सन् १९४५ में पुराने योजना तथा विकास विभाग द्वारा नियुक्त ग्लास पैनल ने इस उद्योग का निरीक्षण किया। इस पैनल ने उद्योग के विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण सिफा-

रिश्ते की। इसके बाद सन् १९५३ में एक बार फिर सरकार ने उस उद्योग की अवस्था की जाँच करने तथा इसके भावी विकास के लिए सिफारिश करने के हेतु एक तदर्थ समिति नियुक्त की। इस समिति के अनुसार उद्योग की प्रगति तथा उत्पादन का स्तर यद्यपि सन्तोषजनक था तथापि मानव तथा भ्रष्ट-स्वचालित मशीनों द्वारा उत्पादन होने के कारण इसका सङ्गठन कुछ ऊँचे स्तर की मजदूरी वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त शीशा गलाने की भट्टियाँ तथा पानी चढ़ाने का तरीका भी ऊँचे स्तर का उत्पादन करने के लिए अनुपयुक्त था और उसमें कोयला भी अधिक परिमाण में जलता था। यह समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुँची कि वस्तु के उत्पादन से पूर्व इसके रासायनिक सम्मिश्रण के तरीके पर उसके स्थाई उपयोग के दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता। इसने उद्योग का ध्यान बेकार पड़ी हुई अधिक क्षमता की ओर तथा एक सीमित सख्या में नई चीजें बनाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया। ग्राम प्रयोग के शीशे के बर्तन बनाने की आवश्यकता से बेकार पड़ी हुई क्षमता का होना इस उद्योग के फैलाव में खराब सङ्गठन के परिणाम-स्वरूप था। सन् १९५६ में कुल १:४ चीशे का सामान बनाने के कारखाने थे, जिनका वार्षिक उत्पादन ३४ टन था। लेकिन इनमें से कुल ६२ कारखाने चाकू अवस्था में थे जिनका कुल उत्पादन २.५ टन वार्षिक का था। इस प्रकार वास्तविक उत्पादन वास्तविक क्षमता का केवल आधा ही था। स्थापित क्षमता से कहीं कम उत्पादन की इस असन्तोषजनक स्थिति में तथा शीशे और चीशे के बर्तनों के भारी आयात के कारण सन् १९५७ में एक बार फिर इस उद्योग का प्राविधिक दृष्टि से निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षक दल ने लगभग सभी कारखानों का दौरा किया तथा कार्यस्थल पर उनकी जाँच करके उनका काम करने का ढङ्ग तथा उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये सभी सम्भव सिफारिशें की।

पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इस उद्योग का विकास यन्त्रों द्वारा उत्पादन वाले विभाग में ही अधिक रहा है।

आजकल कुल १४० कारखाने काम कर रहे हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता चार लाख टन वार्षिक की है। इनमें से ६८ कारखाने जिनकी उत्पादन क्षमता ३.७ लाख टन वार्षिक की है, निरन्तर उत्पादन में रत हैं। वर्तमान वास्तविक उत्पादन २.५ लाख टन वार्षिक का है, जिसमें यन्त्रों द्वारा उत्पादन क्षमता का अधिक से अधिक तथा भ्रष्ट-स्वचालित क्षेत्रों में आशातीत प्रयोग हो रहा है। मंदों के अनुसार उत्पादन की क्षमता इस प्रकार है।

मंद	स्थापित क्षमता
शीट ग्लास	१२०.६६
ग्लास शील	४३.१८
बोतल तथा फाइल	१७४.०५६
सैंवोरेटरी में प्रयोग होने वाले शीशे का सामान	८,३८४

लैम्पवेयर	४२,८१६
टेबल तथा प्रस्ट वेयर	१४,४७४
वैक्युम प्लास्क	२६
शीशे का विविध सामान	१०,४१०

दूसरी पंच वर्षीय योजना में, अर्थात् सन् १९६०-६१ तक उत्पादन का लक्ष्य २,३०,००० टन बाण्ड का था। अतः यह स्पष्ट है कि शीशे के उद्योग में निश्चित समय से बहुत पहले ही उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इस उद्योग की क्षमता भी वास्तव में कटेनर तथा पैसिनिन बाइल को छोड़कर माग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। इन चीजों में भी कभी इनके पूर्ण रूप में स्वचालित मशीनों पर निर्मित होने के कारण ही है। हाल ही में औद्योगिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में की गई जाच से पता चलता है कि सम्पूर्ण माग का पूरा करने के लिये कम से कम ६४ अतिरिक्त अर्द्ध-स्वचालित मशीनों की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान कारखानों का विस्तार करके पूरी की जा सकती है।

तीसरी योजना का लक्ष्य ६२ लाख टन है। मचों के हिसाब से उनके एक नीचे दिए जा रहे हैं।

संख्या	मद	तीसरी योजना में लक्ष्य
(१) बोतल तथा बाइल	(टन में)	२,८०,०००
(२) टेबल तथा प्रैस्ट वेयर	(टन में)	१,१४,०००
(३) शीट ग्लास	(लाख स्क्वेयर टन में)	२,०००
(४) लैम्पवेयर	(टन में)	४०,०००
(५) लैम्बरेटरी ग्लास वेयर	(टन में)	२१,५००
(६) थर्मोम प्लास्क	(दर्जन में)	३,२०,०००
(७) ग्लास शॉल, बिजली के लिए	(लाख की संख्या में)	१,१००
(८) शीशे का बना विविध सामान	(टन में)	३६,०००

तीसरी योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिये ३५ लाख टन की अतिरिक्त क्षमता को प्रारम्भ किया गया है।

हाल के विकास क्रम में वैक्यूम ग्लास तथा सिरेमिक रिसच इस्टीमेट कलकत्ता में चरमो के शीशे, रंगीन शीशे की चादरें तथा शीशे की मोटी चादरें, तबली पदार्थ उचित मात्रा में मिश्रित तथा परत चढ़ाए हुए सुरक्षात्मक शीशे, शीशे की धमकीली गोलियाँ, इमारतों के खोलल ब्लॉक, ग्लास बूस तथा शीशे के रेशे, आदि बनने लगे हैं। निकट भविष्य में जो चीजें इस उद्योग द्वारा बनाई जाएँगी वे इस प्रकार हैं। शीशे के इन्सुलेटर, ग्लास कारवाय, भाँखों पर प्रयोग होने वाले शीशे,

(इनका निर्माण पब्लिक सेक्टर में यू० एस० एम० आर० के सहयोग से होगा) पिट्स बर्ग प्रक्रिया द्वारा शीट ग्लास, अकिन तथा शीशे के रेशे इत्यादि। इस आवश्यकता के प्रति ध्यान होना जा रहा है कि शीघ्र उत्पादन के तरीकों का ईंधन की दृष्टि वाले जो तरीकों का तथा श्रेष्ठ निष्पन्न प्रणाली को प्रयोग करके सस्ता या उच्च स्तर का शीशे का सामान बनाया जाए। शीशे को गलाने तथा उस पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया में भी नए प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं।

कच्चा माल--

शीशा बनाने के लिये मुख्य रूप से कच्चे माल में रेत, बिल्वोर पत्थर, फ्लैटपरायतु, चूना अथवा चूने का पत्थर, डोलोमाइट, सोडा ऐश बोरेक्स तथा सिलिये के अक्षिरिक्त और कई रसायन और भास्पाइड जिनका प्रयोग तरल पदार्थों के रूप में होता है, रंग चढ़ाने वाले पदार्थ तथा रंग को साफ करने वाले पदार्थ आते हैं।

इस उद्योग के सामने आने वाली बड़ी कठिनाई यह है कि सोडा ऐश के अभाव और सभी कच्चा माल परिमाण तथा आकार में भिन्न-भिन्न होता है। भारतीय मानक सभा ने कुछ कच्ची धातुओं के मानक तैयार किए हैं, लेकिन उन मानकों के आधार पर अभी समुचित रूप से कच्चे माल की विकसित नहीं किया गया है। रेत इस उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल का ७० प्रतिशत होता है तथा सारे देश में और विशेषतः उत्तर प्रदेश के शहरगढ़ जिले में काफी अधिक परिमाण में मिलता है। दक्षिण भारत में कारखाने सिलिका के लिये बिल्वोर पत्थर का प्रयोग करते हैं। उत्तर-प्रदेश सरकार न रेत को साफ करने का तथा उच्च स्तर निश्चित करने के लिए एक कारखाना स्थापित किया है, जिसके कारण उत्पादकों को अब स्वच्छ किया हुआ रेत मिलने लगता है। अभी हाल में ही कुछ उत्पादकों ने रेत साफ करने के अपने प्लांट खोले लिए हैं।

चूने का पत्थर डोलोमाइट, फ्लैटपरा भी काफी परिमाण में उपलब्ध है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये बारेक्स, सिलिया तथा सोडा ऐश (विशेषकर भारी सोडा ऐश) का आयात करना पड़ता है। भारी सोडा ऐश का देश में उत्पादन करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं तथा यह अनुमान है कि सन् १९६२-६३ तक इस उद्योग की भारी सोडा ऐश की आवश्यकता की भी पूर्ति देश में ही हो सकेगी। इसकी वर्तमान आवश्यकता ७०,००० टन वार्षिक की है।

मानक तथा खोज--

काँच, काँच के बर्तन, काँच की चादरें, गोनन, लेजोरेटरा में प्रयुक्त होने वाला काँच का सामान, काँच के ग्लास तथा अन्य इसी प्रकार के सामान के मानक भारतीय मानक सभा ने बनाए हैं।

कलकत्ते के काँच तथा चीनी मिट्टी खोज संस्थान ने जिमकी स्थापना सन् १९५० में हुई थी, चीशे के प्रविधिक ज्ञान के सम्बन्ध में संवैधानिक तद

व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोज की है तथा देश के इस उद्योग की आवश्यकताओं को पहिले स्थान दिया है। इसने प्रयत्नों को सभी क्षेत्रों में फैलाने की वजाय कुछ विशेष क्षेत्रों में केन्द्रित करने का प्रयास किया है। कच्चे माल, कंटेनर तथा दुर्लभ कच्चे माल के स्थान पर स्थानीय साधनों से मिलने वाले कच्चे माल का प्रयोग और आयात होने वाली चीजों को इसके द्वारा को जाने वाली जाँच विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इसके द्वारा खोज किए गए ऑप्टिकल ग्लास आ रेल के सिगनलों में प्रयुक्त होते हैं तथा प्रसोम ग्लास की जिनकी भाग देश में बहुत अधिक है सभी में मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। धाम विवास कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जामनी के लिए यह सस्या एक कुलेटिन प्रकाशित करती है।

निर्यात—

चाँच तथा काँच का सामान काफी सस्या में पड़ोसी देशों को निर्यात किया जा रहा है, जिसे सरकार और अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वर्तमान काल में शीशे का सामान का निर्यात २५ लाख रुपये वार्षिक का है। उनसे सम्बन्धित सामान की निर्यात सम्बन्धी समिति ने ४० लाख रुपये निर्यात के लिये निश्चित किए हैं। आजकल देश के बाजार में माँग बढ़ जाने के कारण बड़ी सस्या में निर्यात शायद सम्भव नहीं है। निर्यात के लायक की चीजें आवश्यकता से अधिक हैं। वे इस प्रकार हैं : शीशे की बोतलें, चूड़ियाँ, लैंप का सामान, घमकाई हुई टाइल, मकली पत्थर, नकली मोती, शीशे तथा काँच का बना सजावट का सामान इत्यादि।

राष्ट्रीय ग्रंथ व्यवस्था को श्रेष्ठतर बनाने में शीशे के उद्योग का महत्वपूर्ण भाग है। यह उपभोक्ताओं की बहुत सी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रतिरिक्त औद्योगिक उपभोक्ताओं की भी जरूरतों को पूरा करता है। इसी उद्योग ने बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार अपने में परिवर्तन किया है तथा अगले दशक में इससे राष्ट्रीय विकास में और अधिक सहायता की आशा की जाती है।

उपरोक्त सब बातों को देखते हुए यह कहना एक भूल होगी कि इस उद्योग की अपनी समस्याएँ नहीं हैं। ईंधन की समस्या इसके लिये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बढ़िया किस्म का कोयला इस उद्योग को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके प्रतिरिक्त भट्टियों में लगाने की ईंटों को प्राविधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों की कमी तथा देशीय साधनों के उपकरण तथा उनके औजारों का न मिलना आदि भी इस उद्योग के सम्मुख प्रमुख समस्याएँ हैं। शीशे का सामान बनाने वाले कुल कारखानों न ईंधन का प्रयोग (जैसे फरनेस का तेल) शुरू भी कर दिया है तथा अपन विशेषज्ञों को विदेशों में प्रशिक्षित किया है। जब कि सरकार द्वारा विदेशी प्राविधिक जानकारी के सम्बन्ध में इस उद्योग को पूरी सहायता दी जा रही है, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए इस उद्योग ने स्वयं ही एक परामर्श-दात्री सर्विस की स्थापना कर ली है। अभी हाल में चाँच की भट्टियों की ईंटें तथा ग्लास हाउसों की भट्टियाँ की ईंट बनाने के कार्यों में

काफी दिलचस्पी दिखाई गई है तथा सचि और उनके हिस्से, बोल बनाने की मट्टियाँ तथा आधुनिक ढङ्ग की नाँव बनाने की मट्टियों के निर्माण की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इस बात की पूरी आशा है कि श्रमले कुछ वर्षों में ही इस उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों और उनके पुर्जों की आवश्यकताएँ भारतीय साधनों से ही पूरी हो जाएँगी।

STANDARD QUESTION

1. Briefly describe the present position and future prospects of the Indian Glass Industry.

अध्याय ७६

पेट्रोलियम उद्योग (Petroleum Industry)

प्रारम्भिक—

औद्योगिक ईंधनों में पेट्रोलियम का विशेष महत्त्व है। 'पेट्रोलियम' लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है—'पेट्रा' + 'ओलियम', जिनका अर्थ है 'खदान का तेल'। पेट्रोल का प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है, अतः विश्व के राष्ट्रों में इसका उत्पादन बढ़ाने और इसके स्रोतों पर आधिपत्य प्राप्त करने की स्पर्धा चल रही है। पेट्रोल की रचना 'हाइड्रोजन' और 'कार्बन' के रासायनिक मिश्रण से होती है, जो अन्य खनिजों की तरह संसार में अनियमित रूप से वितरित है। इसकी उत्पत्ति के लिये स्थिर भूभागों में दूर छिड़ले समुद्र एवं विशाल मात्रा में कार्बनिक द्रव और मृदु शिलायें सर्वोत्तम वातावरण प्रस्तुत करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग का जन्म तो आधुनिक युग में हुआ है किंतु इसके प्राचीनतम भण्डार लगभग ५,००,००,००० वर्ष पहले निर्मित हो चुके थे। किसी क्षेत्र में तेल का होना या न होना केवल कूप खोदने पर ही निश्चित होता है। इसमें बरौंदा रुपये और दीर्घकालीन अनुसन्धान की आवश्यकता होती है। अनुभव बताता है कि २०-

में से वेदत १ कुंघा ही प्रायः कार्य योग्य होता है। खनिज तेल के उत्पादन में अमरीका सबसे आगे है, इसके बाद रूस और फिर ईरान, अरब, मैक्सिको आदि का स्थान है। भारत में देश की आवश्यकता का केवल ८% उत्पादन होता है। तेल उत्पादन का सबसे अधिक श्रेय आसाम को है। पंजाब व सौराष्ट्र में भी काफी तेल मिलता है। अनुसन्धान द्वारा तेल उत्पादन क्षेत्र की सीमायें विस्तृत की जा रही हैं। आशा है कि हमारे आयात दिनों दिन कम होते जायेंगे।

भारत में तेल की खोज का इतिहास—

भारत में तेल का पहला कुंघा सन् १८६० में जैपुर (अ. म. म.) में खोदा गया था। भारत सरकार ने सन् १८६१ में तेल की खोज के प्रयत्न रिये। आसाम आयल कम्पनी ने डिगबोई के तेल कूपों में सन् १८८३ में कार्य आरम्भ किया। उसे सन् १८९२ में सफलता मिली। इस समय इस कम्पनी के कब्जे में १० से अधिक तेल कूप हैं, जो देश की तेल—आवश्यकता की ८% पूर्ति करते हैं।

तेल शुद्धि का पहला कारखाना भी आसाम आयल कम्पनी द्वारा खोला गया था। इसकी स्थापना ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। बाद में देश में ही बहुत सी कम्पनियाँ खोली गईं, जिनमें निम्न के नाम उल्लेखनीय हैं—(i) बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी (१९२८), (ii) स्टैंडर्ड बेकुम आयल कम्पनी (१९३३), (iii) इन्डो-बर्मा पेट्रोल क० (१९०९), (iv) ब्रिटिश बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि० (१९१०), एव (v) कालटेक्स इण्डिया लि० (१९५७)।

ये कम्पनियाँ देश में पेट्रोल की खोज व तत्सम्बन्धी अन्य कार्य करती हैं। तेल उद्योग में पाइप लाइनों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्राप्ति कोष से तेल को सचालयों में पहुँचाती है। विभिन्न उचित स्थानों पर लगे शक्तिशाली पम्पों द्वारा तेल एक स्थान से अन्य स्थान को पहुँचाया रहता है। सचालयों में वैज्ञानिक रीतियों से इसकी वृद्धि की जाती है। यह कार्य देश में निम्न कम्पनियों द्वारा किया जाता है :—

(१) बर्मा-शैल रिफाइनरीज लिमिटेड—जो सन् १९५२ में २५ करोड़ रु० की पूँजी से स्थापित हुई। तेल शोधक कारखाना ट्राम्बे में ४५४ एकड़ भूमि के क्षेत्र में बनाया गया है। सचालय में १०,००० बैरल तेल प्रतिदिन संचय करने की क्षमता है। इसमें २,००० कमचारी कार्य करते हैं। यहाँ मोटर स्प्रीट, केरोसीन, हाई-स्पीड डीजल, फरनेस आयल, वाइड्युमेन तथा लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस तैयार की जाती है। इस रिफाइनरी के कार्य से देश को ७३ करोड़ विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष बचती है।

(२) स्टैंडर्ड बेकुम रिफाइनिंग ऑफ इण्डिया लि०—इस कम्पनी का तेल शुद्धि सचालय ट्राम्बे में १०३ करोड़ रु० की लागत से बनाया गया है। इसमें ७३० कर्मचारी हैं। इसने सन् १९५४ में कार्य आरम्भ किया और अब यह लिक्वीफाइड पेट्रोलियम एव गैस तथा वाइड्युमेन का उत्पादन कर रही है।

(३) कालटेक्स आयल रिफाइनिंग इण्डिया लि०—यह सन् १९५५ में

६ करोड़ ६० की पूँजी से स्थापित हुई। इसका संचालन १५ करोड़ ६० की लागत से विशालापटनम में बनाया गया है और सन् १९५७ से कार्य आरम्भ हो गया है। यहाँ विशुद्ध पेट्रोल, केरोसीन, डीजल तेल व ईंधन तेलों का उत्पादन होता है।

तेल की खोज में विदेशी सहायता—

हमारे देश में कुशल भूनाटिको, पर्याप्त भू-भौतिक सूचना एवं भू-भौतिक सर्वेक्षण की कमी रही है। पूँजी का अभाव भी बहुत खटकने वाला है। अतः तेल की खोज के सम्बन्ध में विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। स्वतन्त्र भारत में विदेशी सहायता का विवरण इस प्रकार है :—

(१) अमेरिका—टेक्नीकल कोऑपरेटिव मिशन (T. C. M.) के तरवाधान में एक अमेरिकन भूगर्भवेत्ता ने तेल खोज का कार्य किया और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट सन् १९५६ में दी।

(२) रूस—रूसी विशेषज्ञों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का सन् १९५५-५६ में भ्रमण किया और अपनी रिपोर्ट में पञ्जाब व राजस्थान में तेल की खोज पर ध्यान देने के लिये बल दिया। इस सिफारिश को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने मान लिया है।

(३) प० जर्मनी—जर्मनी की जियोलाॅजिकल सर्वे के डायरेक्टर डाक्टर ब्रिन्ज ने तेल खोज के परामर्श कार्य के लिये भारत का भ्रमण किया और कई क्षेत्रों का विस्तृत परीक्षण करने का सुझाव दिया।

(४) कनाडा से कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प० राजस्थान व गंगा की घाटी में ऐरो मैग्नेटिक सर्वेक्षण की सहायता मिली। फ्रांस ने Refinery Location Committee के लिये एक विशेषज्ञ की सेवाएँ प्रदान की हैं और भूगर्भ शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ तथा छात्रवृत्तियाँ दी हैं। रूमानिया ने तेल कूपों की गहराई खुदाई का पन्ना और भारत में इसका उपयोग मिखाने के लिये विशेषज्ञ भेजे हैं। ब्रिटेन ने भी कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक तेल विशेषज्ञ की सेवाएँ भारत को दी हैं।

भारत में इस समय लगभग १०० विदेशी तेल विशेषज्ञ तेल कूप खोदने की कला व सर्वेक्षण कार्य में सहायता कर रहे हैं और ५० से अधिक भारतीय तेल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उनसे आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

तेल उद्योग के वर्तमान एवं सम्भावित क्षेत्र—

भारत में तेल उत्पादन के वर्तमान क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान असम राज्य का है, जहाँ अधिक से अधिक कुंघे खोदे जा चुके हैं। तेल विशेषज्ञों के सर्वेक्षण और अनुमान के आधार पर तेल प्राप्ति के कुछ सम्भावित क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

क्षेत्र	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीलो में)
(१) असम क्षेत्र (त्रिपुरा व मनीपुर सहित)	३०,०००
(२) प० बंगाल बेसिन (नदीय उद्दीया व सुन्दरवन सहित)	३०,०००
(३) पूर्वी पञ्जाब (हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू काश्मीर सहित)	५०,०००
(४) राजस्थान	४६,५००
(५) लम्बान-कच्छ	६८,५००
(६) गंगा-घाटी	१,४२,०००
(७) मद्रास-तट	१७,०००
(८) आन्ध्र तट	६,५००
(९) द्रावणकोर-तट	६,०००
(१०) अण्डमान एव नीकोबार द्वीप समूह	३,०००

यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में लगभग ४,००,००० वर्ग मील क्षेत्र तेल की खोज के लिये अनुकूल है ।

पेट्रोलियम उद्योग सम्बन्धी सरकारी नीति—

विदेशी शासन ने भारत में पेट्रोलियम उद्योग की प्रगति में कोई उरसाह नही दिखाया । किन्तु द्वितीय महायुद्ध में तत्कालीन आवश्यकताओं से विवश होकर उसने सन् १९४५ में भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग में एक पेट्रोल भूगर्भ वेत्ता की नियुक्ति की । इसने तत् क्षात के लिये पञ्जाब का सर्वेक्षण कराया । अप्रैल सन् १९४८ में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसके अनुसार सरकार ने कुछ आधारभूत उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली । किन्तु पेट्रोलियम उद्योग का सरकारी क्षेत्र में नही लिया गया । सन् १९५१ में प्रथम पंच वर्षीय योजना प्रारम्भ होने पर खनिज तेल के उत्पादन व खोज को अधिक महत्व दिया जाने लगा । सन् १९५५ में प्राकृतिक गैस एव तेल निदेशनालय की स्थापना हुई । सन् १९५६ में एक तेल एव प्राकृतिक गैस कमीशन कायम हुआ, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के खान एव तेल मन्त्री (Minister of Mines and Oils) हैं । कमीशन के मुख्य कार्य निम्न हैं :—

(१) केन्द्रीय सरकार को खनिज तेल की खोज, उत्पादन और उसकी शुद्धि के सम्बन्ध में सलाह देना, (ii) भूगर्भीय एव भू-भौतिक सर्वेक्षण करना, (iii) सम्भावित तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में कार्य करके कुछ अनुमान और परिणाम निश्चिन करना, (iv) खनिज तेल में कार्य करने वाली कम्पनियों के साथ प्रमाणित ढंग से कार्य कराने की योजनायें बनाना, (v) भू-गर्भीय, रसायनिक एव भू-भौतिक प्रयोगशालायें व इन्जिनियरी कारखानों की स्थापना करना, (vi) विश्व और भारत में तेल व प्राकृतिक

गैस के उत्पादन और उसे संग्रहीत व प्रकाशित करना एवं व्यापार सम्बन्धी सूचना संग्रहीत व प्रकाशित करना, (११) प्राकृतिक गैस व खनिज तेल सम्बन्धी परियोजनाएँ प्रकाशित करना ।

प्राधुनिक प्रवृत्तियाँ—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने स्टैंडर्ड डेक्कम कम्पनी के सहयोग से १० बंगाल के क्षेत्र में तेल-खोज का निश्चय किया । प्रारम्भ में २३ करोड़ रु० सरकार ने व्यय करने का प्रस्ताव किया । सन् १९५६ की औद्योगिक नीति के फलस्वरूप खनिज तेल का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में आया । द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र में तेल की खोज के लिये ११५ करोड़ रु० निर्दिष्ट किये गये । बाद में यह राशि ३०*५४ करोड़ रु० कर दी गई । गैर सरकारी क्षेत्रों में लगाये गये अनुमान के अनुसार राष्ट्र के तेल-स्रोतों की खोज और विकास के लिये सन् १९७६ तक १,५०० करोड़ रु० की आवश्यकता का अनुमान है । देश में पेट्रोलियम की बढ़ती हुई माँग, राष्ट्रीय उत्पादन और विदेशों से तेल के आयात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा संचालित तेल व प्राकृतिक गैस कमिशन ने तीसरी योजना में तेल विकास कार्यक्रम के लिये ४०० करोड़ रु० की योजना बनाई है ।

इस योजना के आधार पर सन् १९६७ तक १० मि० टन प्रति वर्ष तेल की प्राप्ति, शुद्धि एवं विपणन का कार्य किया जायेगा । इसके लिये ४५ नये तेल कूप खोदने वाले ड्रिलों की आवश्यकता होगी । कई तेल शुद्धि संचालनशालाएँ (Refineries) भी स्थापित करनी होंगी । अमेरिकी व रूसी विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त करना होगा । २,००० मील लम्बी पाइप लाइन तैयार की जायेगी, जिस पर ४० करोड़ रु० व्यय होगा । तेल शुद्धि संचालनशाला नूनमती (गोहाटी), बरोनी (बिहार) एवं खम्भात क्षेत्र में कार्य में लगे जा रहे हैं । १२ करोड़ रु० की पूँजी से भारत तेल कम्पनी की स्थापना हुई है, जो सरकारी क्षेत्र में स्थापित शुद्धि संचालनशालाओं के उत्पादित तेल का वितरण और विपणन करेगी । भारत सरकार के तेल मन्त्री श्री केशवदेव मालवीय तेल खोज व तेल आयात नीति में आवश्यक परिवर्तन का विचार कर रहे हैं । कर्मचारियों का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने के लिये तेल गैस आयोग ने पेट्रोलियम उद्योग के कर्मचारियों को अनेक सुविधायें देने का निश्चय किया है, जिनका लाभ ६,६०० से अधिक लोग उठावेंगे ।

STANDARD QUESTION

1. Trace the development of Petroleum Industry in India.

अध्याय ७७

फिल्म उद्योग

(Film Industry)

प्रारम्भिक—

फिल्म उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा नम्बर है। यद्यपि इस उद्योग को प्रारम्भ हुए केवल ३० वर्ष हुए हैं। किन्तु जिस गति से इसका विकास हुआ है, वह सचमुच सराहनीय है। इस उद्योग में ३३ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है, ८५,००० व्यक्तियों को काम मिला हुआ है और राज्य को प्रति वर्ष २१ करोड़ रुपये कर के रूप में मिलता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रति वर्ष ४३० फ़िल्में बनती हैं, भारत में ३००, जापान में १०३, फ्रांस में १०६ और इङ्ग्लैण्ड में केवल ७१। द्वितीय महायुद्ध के बाद से फिल्म उत्पादन दुगुना हो गया है।

संक्षिप्त इतिहास—

७ जुलाई सन् १८९६ को लुमेरे भाइयों ने बम्बई के एस्प्लेनेड मैन्शन के एक कमरे में भारत में पहली बार सिनेमा दिखाया। दादा साहब फाल्के का 'राजा हरिश्चन्द्र' भारत की पहली फिल्म है, जो १७ मई सन् १९१३ को बम्बई के कोरोनेशन थियेटर में दिखाई गई। सन् १९१७ में जे० एफ० मदन ने कलकत्ता में पहली फिल्म कम्पनी बनाई और बंगाल में पहली फिल्म 'लल दमयन्ती' बनी। पहली बोलती फिल्म 'भालम भारा' १४ मार्च सन् १९३१ को बम्बई के मॅजिस्टिक सिनेमा में दिखाई गई। इस फिल्म को ए० एम० ईरानी ने बनाया था। सन् १९३२ में मोहन पिक्चर सोसायटी (फिल्म संघ) ऑफ इण्डिया स्थापित की गई। दो साल बाद इसे रजिस्टर कराया। इसने २० फरवरी सन् १९३५ को अखिल भारतीय फिल्म सम्मेलन किया। अप्रैल-मई सन् १९३६ में बम्बई फिल्म उद्योग की रजत जयन्ती मनाई गई। उस समय इसका भारत के उद्योगों में आठवाँ और सत्तर के फिल्म उद्योगों में चौथा स्थान था।

केन्द्रीय सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ाने के लिए बाल चित्रपट समिति, फिल्म वित्त निगम और फिल्म जिल्मिन्को की शिक्षा के लिए फिल्म सस्था को स्थापित किया। फिल्म सस्था पूना में है और इसके लिये सरकार ने प्रभाव स्टूडियो से लिया है। अच्छी फिल्मों की रचना को बढ़ावा देने के लिये सन् १९५४ में राजकीय फिल्म पुरस्कार शुरू किया गया। सर्वोत्तम कथाचित्र और वृत्त चित्र को राष्ट्रपति के स्वर्ण-

पदक और बच्चों की सबसे अच्छी फिल्म को प्रधान मंत्री का स्वर्णपदक दिया जाता है। इनके अलावा इन श्रेणियों की द्वितीय और तृतीय फिल्मों को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार की फिल्म डिवीजन सरकारी समाचार चित्र और वृत्त चित्र बनाती है। फिल्म डिवीजन ने सन् १९६० में ८७ वृत्त चित्र बनाये, जिनमें १७ रङ्गीन थे। हर हफ्ते नया समाचार चित्र दिखाया जाता है। २२ जनवरी सन् १९६० से अंग्रेजी और १२ भारतीय भाषाओं में समाचार चित्र बनाये जा रहे हैं।

फिल्म बनाने में सप्ताह भर में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जापान का है। अनुमान है कि देश में २६० फिल्म कम्पनियाँ, १,१८० फिल्म विनरक और ४,३०० सिनेमाघर हैं। फिल्म उद्योग के तीन प्रधान केन्द्रों में स्टूडियो और पनोरो (मम्बई) की सहाय इस प्रकार है—मम्बई ३० स्टूडियो और ६९ पनोरो, कलकत्ता ११ स्टूडियो एवं ३० पनोरो तथा मद्रास २७ स्टूडियो एवं ७२ पनोरो। सन् १९६० में ११५ फिल्में बनाई गईं। सबसे अधिक ११५ हिन्दी की थी। तामिल में ६२, तेलगू में ५४, बङ्गाली में ३६, मराठी में १५, कन्नड़ में १२, मलयालम में ६, उडिया में ५, पंजाबी में ४, उर्दू में ३, गुजराती में २ और सिंधी में १ बनी।

फिल्मों के निर्माण से सन् १९५६ से १ करोड़ ५३ लाख रु० की विदेशी मुद्रा मिली। लङ्का, मलाया, बर्मा, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, थाई देश, वियतनाम, भूटान, फारस की खाड़ी के बन्दरगाह, ईरान, लेबनान, ब्रिटिश पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका, घाना, ताजिकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, ब्रिटिश वेस्ट इण्डोनेज, फीजी, मारिशस, उच्च गायना, ब्रिटेन और हाँग कांग में भारतीय फिल्मों की काफी मांग है।

फिल्म कला की शिक्षा—

इस साल पहले थी सदाशिव कान्होजी पाटिल की अध्यक्षता में फिल्म जॉब समिति नियुक्त हुई थी। उसकी रिपोर्ट में ऐसी सस्था खोलने की सिफारिश की गई थी जहाँ फिल्म कला की शिक्षा दी जाए। भारतीय फिल्मों का स्तर सुधारने के लिए यह जरूरी है कि इनके बनाने में योग्य और प्रशिक्षित शिल्पिक काम करें। इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षित और प्रतिभा सम्पन्न युवकों को फिल्म कम्पनियों में आने का मौका मिले। अस्तु इसी उद्देश्य से भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने पूना में फिल्म सस्था खोली। १६ अगस्त सन् १९६१ को यहाँ फिल्म कला का वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ाई का पहला सत्र शुरू हुआ, जिसमें ४१ युवक दाखिल हुए। ये लोग आगे चलकर फिल्म निर्माण का स्तर सुधारने में कौशल काम करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। किन्तु इस पढ़ाई की शुरुआत से, भारतीय फिल्मों के इतिहास में एक नया अध्याय अवश्य शुरू हुआ है।

वास्तव में यह सस्था मार्च सन् १९६१ में ही चालू हो गई थी। उस समय यहाँ ध्वनि रिकार्डिंग, फिल्म फोटोग्राफी और फिल्म सम्पादन का तीन मास का पुनर्भास शुरू हुआ। इसमें वे लोग लिये गए, जो फिल्मों में तीन साल से काम कर रहे थे। इन विषयों के विशेषज्ञों ने अभ्यासियों को शिक्षा दी। देश के विभिन्न भागों से इन विषयों

के विशेषज्ञ भी भाषण करने के लिए यहाँ बुलाये गये। फ्रांस की फिल्म सस्था के निर्देशक, श्री टेस्सोनो भी यहाँ दो सप्ताह रहे और अपनी सलाह तथा बहुमूल्य सुझाव दिये।

शिक्षार्थियों को अनेक फिल्में दिखाई गयी और उनके शिल्प पर विचार विमर्श हुये। इस सस्था के काम में फिल्म निर्माण भी बड़ा सहयोग दे रहे हैं। कई फिल्म निर्माताओं ने पाटिल जाच समिति से कहा था कि देश में ऐसी सस्था होनी चाहिए। अब उनकी यह इच्छा पूरी हो रही है।

आजकल इस सस्था में चार विषयों की शिक्षा दी जा रही है— फिल्म निर्देशन और पट यथा (स्क्रिप्ट) लेखन, चल फोटोग्राफी, ध्वनि भ्रूण और ध्वनि विरूप और फिल्म सम्पादन। सस्था में जो शिक्षार्थी हैं, वे सभी कालेजों से सीधे मिलते स्नातक हैं और उन्हें फिल्म कला का कोई अनुभव नहीं है। प्रकाश को फिल्मों में काम करने का चाव है, जो आजकल प्रायः युवकों को होता है। किन्तु इनमें यह भाव पैदा किया जा रहा है कि इन्हें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना होगा और भारी दायित्व सम्भालना होगा।

कहते हैं कि कलाकार बनाए नहीं जा सकते बल्कि उनमें जन्मजात प्रतिभा होती है। किन्तु प्रश्न यह है कि आज फिल्म उद्योग में ऐसी प्रतिभा काले कितने व्यक्ति हैं और क्या प्रातमावान् व्यक्तियों को शिक्षा की जरूरत नहीं? वास्तव में शिक्षा से तो प्रतिभा और निखरती है। अध्ययन से मनुष्य की कला दृष्टि व्यापक होती है। प्रतिभा की बिगारी को भी अग्रशस्त्र और शिक्षा की पूक चाहिए। तभी वह प्रज्वलित होती है। अब फिल्म उद्योग में प्रवेशेच्छुओं की कलहरमय प्रतिभा को निखारने में यह सस्था बड़ा योग देगी।

फिल्म वित्त निगम—

फिल्म वित्त निगम का मुख्य ध्येय बढ़िया फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना है। उसका अभिप्राय है कि फिल्में मनोरंजक होने के साथ ही शिक्षाप्रद भी हो और उनमें जीवन की वास्तविक भाँकी मिले। दूसरे शब्दों में ये फिल्में यथार्थवादी हों, जिनमें दशक को पात्रों, परिस्थितियों और समस्याओं में अपने ही जीवन का प्रतिबिम्ब दिखाई दे। यह बात सामाजिक व ऐतिहासिक या आध्यात्मिक पर आधारित दोनों प्रकार की फिल्मों पर लागू होती है।

फिल्म वित्त निगम से सहायता पाने वाली फिल्में साधारण फिल्मों से भिन्न होगी। उनमें सड़क सड़क, अतिशय भावुकता व अवास्तविकता नहीं होगी। उनमें सस्ता मनोरंजन व मजाक भी नहीं होगा। निगम ऐसी फिल्मों को भी बढ़ावा देगा, जिनमें ऊँचे आदर्शों की प्रतिष्ठा हो। यदि फिल्म में एक भी पात्र ऊँचे आदर्शों की प्रेरणा देता हो या दो-चार सम्वाद भी ऐसे हों जो दशकों की सद्बुद्धि को जगावें तो वह फिल्म निगम की सहायता को प्राप्त हो सकती है। प्रस्तुत निगम राष्ट्रीय विषयों पर आधारित या सामाजिक, सांस्कृतिक, फिल्मों तथा सावजनिक महत्त्व की फिल्मों को

सहायता देगा। परन्तु इसके माने यह नहीं है कि निगम सुधार का काम करना चाहता है या फिल्मों में पूँजी लगाने वाले महाजनो का स्थान लेना चाहता है। निगम तो केवल ऐसी फिल्में बनाने में मदद देने का प्रयत्न करेगा जो कला की दृष्टि से ऊँचे दर्जे की हों और जिनमें ऐसे विचारों व भावों का प्रतिपादन हो जिनसे राष्ट्र और जाति ऊँची उठे। निगम इस बात की अवहेलना नहीं कर सकता कि उससे सहायता पाने वाली फिल्में घाटा न दें। पर वह ऐसी फिल्मों को कदापि सहायता नहीं देगा, जिसने राष्ट्रीय चरित्र का अपघटन हो।

निगम फिल्म उद्योग के खर्चों को भी बढ़ाना नहीं चाहता। आजकल चोटी के कलाकार तथा प्रसिद्ध स्टूडियो बहुत ऊँची दर पर लिए जाते हैं, ताकि उनके नाम से सिनेमाघरों में खूब भीड़ हो। पर फिल्म कहीं फैन हो गई तो निर्माता का दिवाला पिट जाता है। निगम ऐसी फिल्म के निर्माण में सहायता देगा, जिनमें खर्च कम हो और होनहार कलाकार हों। इससे निगम दो उद्देश्य सिद्ध करेगा। एक तो वह फिल्म उद्योग की उन्नति में योग देगा, दूसरे नये कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर देगा।

फिल्म उद्योग को सरकारी सहायता देने का विचार नया नहीं है। ब्रिटेन में पिछले दस वर्ष से भी अधिक समय में राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम काम कर रहा है। इटली में फिल्म निर्माण में सहायता देने का काम एक बैंक को सौंपा गया है और फ्रांस में राष्ट्रीय-सिनेमाटोग्राफी-केन्द्र यह काम करता है। देश में फिल्म वित्त निगम पिछले साल मार्च में स्थापित किया गया, पर इसने अपना काम इस साल फरवरी से शुरू किया। अक्टूबर के मध्य तक इसके पास कुल ६४ लाख ७० हजार २० के ऋण के लिए २२ अर्जियाँ आयीं। इनमें से ५ आवेदकों को कुल १० लाख २० स्वीकार किया गया। ३ आवेदकों को ६ लाख ४० हजार २० दिया जा चुका है, १० अर्जियाँ अस्वीकार कर दी गयी हैं और ७ अर्जियों पर विचार किया जा रहा है।

निगम सरकारी लिमिटेड कम्पनी है और इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ २० है। इसकी चुकना पूँजी २० लाख २० है, जो समाप्त प्रायः है। अब निगम शीघ्र ही २४ लाख २० की पूँजी और एकत्र करने वाला है और तब यह फिल्मों को और ऋण दे सकेगा।

फिल्म को ऋण—

निगम ने ऋण देने के लिए सिद्धान्त निश्चित कर दिए हैं। निगम फिल्म निर्माण का पूरा खर्च नहीं उठाता। फिल्म पर होने वाले खर्च का एक-चौथाई निर्माता देता है और निगम का निर्देशक-मण्डल एक फिल्म को ३ लाख ५० हजार २० तक ऋण दे सकता है। इससे अधिक के लिये सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। निगम ने ब्याज की दर बहुत कम रखी है। ७।५ से ६ प्रतिशत तक और यदि ऋण नियमित तौर से चुकाया जाए तो कुछ छूट भी दे दी जाती है। फिल्म-निर्माण पर भी निगम का नियन्त्रण रहना है। यदि फिल्म निश्चित अवधि में पूरी न हो तो, निर्देशक-मण्डल

को अधिकार है कि वह धरा लेने वाले से पूरा धरा जो दिया गया है, मर गया के मर ले, या फिल्म का निर्माण अपने हाथ में ले ले या किसी अन्य निगम से बनवाए, निगम को फिल्म के कथानक को भी जीवने का अधिकार है, ताकि उसे मकीन हो जाए कि फिल्म उसके सिद्धान्तों के अनुकूल बनेगी। निगम का शीघ्रसे अच्छा हुआ है। सोवियत फिल्मों का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता, पर फिल्म उद्योग ने निगम जैसा स्वायत्त विद्या है, उसमें पता चलता है कि इसका भविष्य उज्ज्वल है।

अपसंहार—

बच्ची फिल्मों के निर्माण के लिए एक कारखाना मद्रास राज्य में लटकमण्ड के निकट फ्रांस की एक फर्म Baughet et Cie के टेक्नीकल सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र में खोला जा रहा है। माशा की जानी है कि उद्योग की बच्ची फिल्म सम्पत्ती समस्या घब्र हो जायगी।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Trace the history, present position and future prospects of Film Industry in India.

अध्याय ७८

दियासलाई उद्योग

(Match Industry)

दियासलाई प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तु है, जिसका प्रयोग दरिद्र तथा धनी सभी व्यक्ति करते हैं। इस उद्योग के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है—(१) मुलायम लकड़ी, (२) सस्ता थर्मिक धीर (३) रासायनिक पदार्थ। भारत में लकड़ी तथा थर्मिक का तो कोई अभाव नहीं है, किन्तु रासायनिक पदार्थों का बाहर से आयात करना पड़ता है।

गत कुछ वर्षों में दियासलाई का उत्पादन इस प्रकार रहा है—

वर्ष	दियासलाई ('००० पेटियाँ)
१९५२	६१६२
१९५३	६१८०
१९५४	६२६२
१९५५	६१५६
१९५६	६२५२
१९५७	५७८३
१९५८	६१४४
१९५९	७००७
१९६० (११ माह)	५६८५

STANDARD QUESTION

- 1 Attempt a lucid note on the Indian Match Industry

अध्याय ७६

उद्यान उद्योग

(Plantation Industry)

प्रारम्भिक—

उद्यान उद्योगों में पेय पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग चाय, कहवा और कोको प्रमुख हैं और इनमें भी चाय उद्योग का एक विशेष स्थान है। प्रस्तुत अध्याय में उक्त तीनों उद्योगों के विकास पर प्रकाश डाला गया है।

चाय उद्योग (Tea Industry)

संक्षिप्त इतिहास—

चाय अत्यधिक नम और गरम मानसूनी प्रदेशों का पौधा है, इसके लिये ५०° फा० से ८०° फा० तक तापक्रम और ६०" से १००" तक वर्षा चाहिये। वायु-व्यवसाय के लिये सस्ते और अधिक सख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि चाय पीने का प्रचार सबसे पहले चीन में हुआ था। यह ससार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद भारत का नम्बर आता है। मई प्रथम सन् १८२० में आसाम में चाय के जंगली पौधों की खोज हुई थी और इसके बाद ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी का ध्यान उस पर गया। सन् १८३५ में कम्पनी ने अपना बगीचा प्रारम्भ किया। प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा संचालित एवं पोषित उद्योगों में चाय उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रारम्भ से ही यह निरन्तर प्रगति कर रहा है। भारत में सम्पूर्ण उत्पादन की ८७% चाय केवल आसाम और बंगाल में ही पैदा होती है। चाय के उत्पादन का दूसरा क्षेत्र दक्षिणी भारत में नीलगिरि पहाड़ियों का है जहाँ भारत की १६% चाय होती है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में भी चाय पैदा की जाती है। भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप चाय उत्पादन की लगभग ७४,००० एकड़ भूमि पाकिस्तान में चली गई। विभाजन के बाद भारत में ७'७५ लाख एकड़ भूमि रह गई, जिसमें ५६० करोड़ बीघे चाय उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय सरकार ने चाय उत्पादन के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि का प्रयास किया है।

चाय उद्योग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ एवं भविष्य—

६. विश्व में भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातकर्ता है। यह स्थिति उसे तब से प्राप्त हुई जबकि १९वीं शताब्दी में चीन से चाय का निर्यात कम हो गया। यहाँ इस समय ८ लाख एकड़ भूमि पर चाय की पैदावार होती है तथा उत्पादन ७०० मि० गैल से भी अधिक है। विश्व के बाजार में घाने वाली चाय की पूर्ति का आधा भाग भारत भेजता है। चाय उद्योग देश के सबसे बड़े संगठित उद्योगों में से है। इसमें १ मि० से भी अधिक लोगों को काम मिला हुआ है। यह भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक अकेला उद्योग है। स्पष्ट है कि इस उद्योग की उन्नति एवं प्रगति के साथ हमारे विदेशी मुद्रा की समस्या का हल जुड़ा हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि इस उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रत्येक प्रयास करना चाहिये।

दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से चाय का निर्यात गिरता जा रहा है, जैसा कि निम्न तालिका से भी प्रगट होता है :—

वर्ष	मात्रा (००० पौंड में)	मूल्य (लाख रु० में)
१९५०	४,०३,२३६	७१,६१
१९५१	४,५४,१०८	६८,०१
१९५२	४,१४,८३६	८०,६१
१९५३	५,००,६५५	१,०४,२२
१९५४	४,४७,६६०	१,३०,७५
१९५५	३,६७,५२३	१,१३,६१
१९५६	५,२३,५५७	१,४२,८२
१९५७	४,४२,६५१	१,२३,३६
१९५८	५,०५,६६१	१,३६,५४
१९५९	४,७२,४५५	१,२६,३६
१९६०	४,३०,१४७	१,२१,०५

निर्यात घटने का प्रधान कारण यह है कि अन्य देशों ने विश्व बाजार में अपनी पूर्ति बढ़ा दी है। यह बात निम्न तालिका से प्रगट हो जाती है :—

Share of Different Producing Countries in Total World Exports

Exporting Countries	1950	Quantity of export in thousand lbs.				
		1955	1956	1957	1958	1959
India	403,236 (45.8)	367,523 (37.0)	523,557 (44.4)	442,651 (34.2)	505,961 (40.9)	472,475 (39.9)
Pakistan	16,760 (1.9)	12,900 (1.3)	23,524 (2.0)	9,836 (0.9)	12,698 (1.0)	12,900 (1.1)
Ceylon	298,099 (33.9)	362,235 (36.5)	348,129 (29.6)	357,732 (32.6)	4,0773 (33.2)	383,495 (32.4)
Indonesia	63,010 (7.2)	72,290 (7.3)	80,514 (6.8)	85,657 (7.6)	83,182 (6.7)	71,300 (6.0)
Br East	28,835 (3.3)	38,992 (3.9)	46,539 (4.0)	49,041 (4.3)	52,669 (4.3)	59,603 (5.0)
Africa*						
China	26,000 (3.0)	70,000 (7.1)	83,000 (7.0)	82,000 (7.3)	99,000 (8.0)	101,000 (8.5)
Formosa	16,643 (1.9)	17,127 (1.7)	23,507 (2.0)	26,444 (2.3)	26,295 (2.1)	31,685 (2.7)
Japan	15,793 (1.7)	31,113 (3.2)	21,803 (1.9)	23,566 (2.1)	15,869 (1.3)	16,939 (1.4)
Malaya	1,660 (0.2)	2,896 (0.3)	2,664 (0.2)	2,803 (0.2)	3,063 (0.3)	3,788 (0.3)
Other Countries	9,559 (1.1)	16,724 (1.7)	21,863 (2.1)	39,771 (3.5)	26,700 (2.2)	32,115 (2.7)
Total	879,600 (100.0)	991,800 (100.0)	1,178,100 (100.0)	1,129,500 (100.0)	1,236,200 (100.0)	1,185,300 (100.0)

*Includes Nyasaland

Note Figures in brackets relate to Percentage Share to World Exports.

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि भारत का शेयर सन् १९५० में ४५.८% से घटकर सन् १९५६ में केवल ३६.६% रह गया है। लका का शेयर ३३% के लगभग स्थायी बहुत घुट रहा है। पूर्वी अफ्रीका का शेयर सन् १९५० में ३३% से बढ़कर सन् १९५६ में ५०% हो गया है। चीन का शेयर भी ३०% से बढ़ कर ८५% बढ़ गया है। इस प्रकार चीन और पूर्वी अफ्रीका के बढ़ते हुये शेयर के कारण भारत का शेयर घट रहा है। लका भी, जो कि विश्व में दूसरे नम्बर का बड़ा निर्यातक है, भारत के लिये एक प्रबल प्रतिद्वन्दी प्रमाणित हो रहा है। लका, पूर्वी अफ्रीका और चीन धीरे-धीरे बढ़ता हुआ उत्पादन एवं निर्यात भारतीय चाय के भविष्य के लिये एक चुनौती है। इंडोनेशिया में भी, जहाँ कि चाय उद्योग गत महायुद्ध में बहुत ही घबस हो गया था, अब धीरे धीरे प्रगति हो रही है। उसका चाय निर्यात सन् १९५० में ८३२ मि० पौंड से बढ़ कर सन् १९५६ में ८३२ मि० पौंड हो गया है। अफ्रीका चीन और लका में चाय का निर्यात बढ़ाने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन सबका परिणाम भारतीय चाय के निर्यात लिये शुभ न होगा।

क्या इस दशा से बचने के लिये कुछ नहीं किया जा सकता ? इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व हमें यह विचार करना चाहिए कि ऐसी दशा क्यों हुई है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारतीय चाय के मूल्य अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं। भारत के कुल चाय का उत्पादन का ६०% भाग विलकुल उन्हीं किस्मों का है जिनका उत्पादन इंडोनेशिया, अफ्रीका और चीन द्वारा किया जाता है। चूंकि भारतीय किस्मों के मूल्य अधिक हैं इसलिये विदेशी क़ता अन्य देशों से ही चाय खरीदना पसन्द करने हैं क्योंकि उन्हें कम मूल्य पर समान किस्म की चाय प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि विश्व के सभी प्रमुख चाय उपभोगी देशों को (जैसे अमरीका, इंग्लंड, कनाडा, ग्रायर्संड, ईरान आदि) भारत से चाय का निर्यात अभी हाल में कम हो गया है। भारतीय चाय का मूल्य अधिक क्यों है ? इसका कारण यह है कि हमारे देश में उत्पादन की लागत एवं करों का भार अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। उत्पादन लागत बढ़ने का एक प्रमुख कारण मजदूरी में वृद्धि होना है, जिसकी व्यवस्था नये बगीचा कानूनों ने की है। इस सम्बन्ध में हम केवल यही सुझाव दे सकते हैं कि चूंकि चाय उद्योग का विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से एक विशेष महत्व है, इसलिये हम थम लागतों में अनावश्यक वृद्धि नहीं होने देनी चाहिये। उत्पादन लागत बढ़ने का दूसरा कारण है निर्यात एवं उत्पादन कर। इन करों का भार विभिन्न चाय क्षेत्रों में इस प्रकार है :—

प्रथम क्षेत्र	५७ ५ न० पै० प्रति कि० ग्रा०
द्वितीय क्षेत्र	६२ न० पै० प्रति कि० ग्रा०
तृतीय क्षेत्र (घ)	७१ न० पै० प्रति कि० ग्रा०
तृतीय क्षेत्र (ब)	८० न० पै० प्रति कि० ग्रा०

इस भारी करारोपण का चाय के मूल्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है, जिससे भारतीय चाय की प्रतिद्वन्दिता शक्ति विश्व बाजार में बहुत कम हो गई है। इसके विपरीत इंडोनेशिया, चीन व अफ्रीका में कोई निर्यात कर नहीं लगा है। लक्का में निर्यात कर लग होने पर भी वहाँ की चाय भारत की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। सरकार करारोपण के दुष्प्रभाव से परिचित है। इसी कारण उसने सन् १९६१-६२ के बजट में कुछ कमियों की घोषणा भी की थी। अब करारोपण का भार इस प्रकार हो गया है :—

प्रथम क्षेत्र	५४ न० पै० प्रति कि० ग्रा०
द्वितीय क्षेत्र	५६ न० पै० प्रति कि० ग्रा०
तृतीय क्षेत्र (घ)	६६ न० पै० प्रति कि० ग्रा०
तृतीय क्षेत्र (व)	७६ न० पै० प्रति कि० ग्रा०

किन्तु चाय उद्योग की कठिनाइयों को देखते हुए यह राहत बहुत कम है। फिर भी इसका चाय के निर्यात पर कुछ सुप्रभाव अवश्य होगा। कैंरो की कमी के सम्बन्ध में हमको यह ध्यान रखना चाहिये कि कर इस प्रकार कम किये जायें कि विदेशी क्रेता भारतीय चाय अधिक मात्रा में खरीदे और साथ ही कैंरो के कम होने पर मूल्य घटने से विदेशी मुद्रा की भाय में कमी न होने पाये। वास्तव में हमारे निर्यात का उद्देश्य अधिक विदेशी मुद्रा कमाना है, त कि अधिक वस्तु निर्यात करना। सरकार सन्तुलन कायम रखने की भरसक चेष्टा कर रही है।

सन् १९६१-६२ के बजट में दी गई राहतों के कारण भारत में उपभोग के लिये चाय महंगी हो जायेगी, जिसका फल यह होगा कि साधारण चाय की माँग बढ़ेगी और बढ़िया चाय की माँग कम हो जायेगी, जिससे बढ़िया चाय निर्यात के लिये अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी।

हमारी विकास योजनाओं के लिए चाय का कितना अधिक महत्त्व है, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में चाय उत्पादन एवं निर्यात के लक्ष्य क्रमशः ६०० मि० पीण्ड एवं ६०० मि० पीण्ड रखे गये हैं। यह उत्पादन लक्ष्य तभी पूरा होगा जबकि निम्न उपाय किये जायें:—(१) प्रमोशनियम सलफेट के रूप में उद्योग को पर्याप्त छूट उपलब्ध किया जाय, (११) उद्योग की चाय की पुरानी भाडियों को प्रतिस्थापित करने के लिए सहायता-भूत दिये जायें और (१११) अन्त-सम्बन्ध शान्तिपूर्ण रहे। हर्ष का विषय है कि सरकार इस मोर ध्यान दे रही है।

यह बधा जाता है कि सन् १९६५-६६ तक निर्यात का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह चाय के निर्यात में घटोतीरी की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए सुगम नहीं जान पड़ता। किन्तु स्थिति के कुछ उज्ज्वल पहलू भी हैं। ५० एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में चाय का उपभोग बढ़ने का पर्याप्त क्षेत्र विद्यमान है। इनमें भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये विदेशों में भारतीय चाय के उपभोग को प्रोत्साहन देना होगा और उभयपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral trade agreements) करने होंगे।

चाय बोर्ड की एक निर्यात प्रोत्साहन कमेटी है, जिसमें चाय व्यापार के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इसकी सहायता के लिए छ' निर्यात प्रोत्साहन परिषदें भी हैं। भारत सरकार ने अभी हाल में इङ्ग्लैण्ड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और मिथ्र में चाय-परामर्शदाता (Tea Advisors) नियुक्त किये हैं, जिनका काम स्थानीय चाय व्यवसायियों से सम्पर्क बढ़ाना है, ताकि वहाँ भारतीय चाय का निर्यात बढ़े। कैंरो में एक चाय केन्द्र खोला गया है जो मध्य-पूर्व में भारतीय चाय का प्रचार करेगा। सरकार ने कई देशों से उभय पक्षीय व्यापार समझौते भी किये हैं।

कहवा (Coffee)

प्रारम्भिक—

कहवा ३ बीसीनिधा की मूल उपज है। इसने लिए गर्म और नम जलवायु

चाहिये, औसत तापक्रम ७०° फा० होना आवश्यक है, भूमि ढालू और उपजाऊ होनी चाहिए। ज्वालामुखी के लावे से बनी मिट्टी कहूँ के लिए उत्तम होती है। इसके लिए अधिक श्रम भी आवश्यक होता है। भारत में यह पौधा तेरहवीं शताब्दी में लाया गया था, किन्तु इसका नियमित उत्पादन सन् १८३० से आरम्भ हुआ। यह भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं पड़ता, इसलिये देश में यह अधिक लोकप्रिय नहीं है।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ—

भारत में लगभग ५०% कहूँ क्षेत्र भारतीयों के तथा ३०% क्षेत्र योरोपियों के अधिकार में है। दक्षिण भारत में लगभग ५,००० से अधिक कहूँ के बगीचे हैं, जिनमें अकेले मैसूर में ४,६०० बगीचे हैं। यहाँ ५०% उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन का आधा भाग देश में ही प्रयोग हो जाता है और शेष भाग इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम तथा आस्ट्रिया को निर्यात कर दिया जाता है। भारत का कहूँ उत्पादन और निर्यात विश्व के उत्पादन व निर्यात की अपेक्षा बहुत कम है।

गत वर्षों में भारतीय कहूँ समिति को निर्यात सम्बन्धी कठिनाई अनुभव हुई है। फिर भी कहूँ उगाने वाले क्षेत्रों में विकास की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। यह आवश्यक है कि कहूँ के नये बाग उन्हीं भागों में लगाये जायें जहाँ बहुत अधिक अच्छे उत्पादन और रोग मुक्त पौधे उगने की आशाएँ हैं। चूँकि विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से कहूँ उद्योग का महत्त्व बहुत कम है इसलिए उत्तम तो यह होगा कि इस उद्योग में श्रम व पूँजी बढ़ाने के बजाय उसको चाय उद्योग में लगाया जाय।

रबड़ (Rubber)

उद्यान उद्योगों में रबड़ का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक रबड़ के पेड़ जङ्गली अवस्था में उगे हुए पाये जाते हैं। अब जङ्गली रबड़ का उत्पादन कम होकर वाणिजी रबड़ का उत्पादन बढ़ रहा है। भारत में सर्व प्रथम सन् १६०२ में ट्रावणकोर में पेरियार नदी के किनारे रबड़ के बगीचे लगाये गये। सन् १६२६ तक इनका पर्याप्त विकास हुआ, परन्तु मन्दी काल में उत्पादन गिर गया। द्वितीय महायुद्ध की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर इसे पुनः बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब भी उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में सबसे पिछड़ा हुआ है। देश के औद्योगिक विकास तथा सुरक्षा में रबड़ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः इसके लिये अन्य देशों पर निर्भर होना उचित नहीं है। योजना आयोग ने भारत में रबड़ का उत्पादन कम होने का कारण बगीचों का छोटा व पुराना होना बताया है। अतः राष्ट्रीय विकास समिति ने इनक १५ वर्षीय पुनरुद्धार की योजना बनाई, जिसमें काफी सफलता मिली है। सरकार की ओर उद्यान पुनर्स्थापन सम्बन्धी सहायता भी दी गई। भविष्य में रबड़ उद्योगों के लगाने के लिए अच्छी किस्म के बीज व पौधों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।

आधुनिक युग में रबड़ से अनेक वस्तुएँ जैसे टायर, ग्युब, बेल्टिंग, पंपों के पट्टे, रेलवे ब्रेक, फिटिंग्स, प्रतिरक्षा की अनेक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। रबड़ निर्माण एवं रबड़ बगीचा उद्योग दोनों मिलकर देश के हजारों लोगों को रोजी व रोटी देत है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ रबड़ की मांग उत्पादन से अधिक बढ़ी है। अतः प्रति वर्ष अधिवाधिक मांग से कच्ची रबड़ बाहर से मँगानी पड़ी है। यह बात निम्न प्रांकडों में स्पष्ट है :—

वर्ष	उत्पादन (टन)	उपभोग (टन)
१९५०	१५,५६६	१७,७३५
१९५१	१७,१४८	२२,४२७
१९५२	१६,८६३	२१,०६१
१९५३	२१,१३६	२२,३७३
१९५४	२१,४६३	२५,४८७
१९५५	२२,४८१	२७,५४३
१९५६	१३,४४४	२८,६६६
१९५७	२३,६७६	३१,७६५
१९५८	२४,३८८	३४,७५६
१९५९	२३,३६८	३८,६६३

सन् १९६० में उत्पादन २६,४०० टन आका गया है जो सन् १९६६ तक ५०,८०० टन हो जाना चाहिये। सन् १९५९ के अंत तक रबड़ वृक्षों का क्षेत्र ३,०५,४५२ एकड़ था जिसमें से केवल केरल में ही २,८८,४५० एकड़ क्षेत्र है और कुल ५५,२६७ उद्यानों में से ५४,८८२ उद्यान वहाँ पाये जाते हैं। यह आवश्यक है कि भारत के रबड़ के उत्पादन में जल्द आरम्भ निभर हो जाय अथवा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भारी लक्ष होना। उत्पादन बढ़ाने के लिये पुराने क्षेत्रों में नये वृक्ष लगाने और अधिक पैदावार वाले वृक्षों को रोपना जरूरी है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक उपयुक्त योजना भी बनाई है। यह योजना सन् १९५५ में प्रारम्भ की गई थी। सन् १९५५ के अंत में एक रबड़ अनुसन्धान संस्था और रबड़ अनुसन्धान केंद्र की स्थापना भी की गई। सन् १९५७ से पुनरा रोपण के लिये छोटे उत्पादकों को आर्थिक सहायता की योजना भी चालू की गई है।

तीसरी योजना में रबड़ कोष द्वारा निम्न कार्यक्रम बनाया गया है —

- (१) विद्यमान रबड़ उद्यानों से ही तीसरी योजना के अंत तक सभी सम्भव उपायों द्वारा अधिक से अधिक ५४,००० टन रबड़ का उत्पादन करना।
- (२) प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन की लागत घटाने के लिये पुराने और अलामकर रबड़ के वृक्षों के स्थान में नये व अधिक पैदावार वाले वृक्ष लगाना।
- (३) आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से रबड़ उद्यान उद्योग का विस्तार करना।
- (४) सामान्य उपभोग के निम्ने देश में ही २०,००० से ३०,००० टन तक कृत्रिम रबड़ का उत्पादन।
- (५) १५,००० टन पुन प्राप्त रबड़ का उत्पादन करना।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Briefly trace the recent trends and prospects of our Tea Industry
- 2 Write a short essay on (a) Rubber or (b) Coffee production in India

क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। सन् १९५६-६० के अन्त में इनके बकाया ऋण १४१७ करोड़ रु० थे।

सन् १९५६ के अन्त तक औद्योगिक साख एवं विनियोग नियमों में, जिसकी स्थापना जनवरी सन् १९५५ में माइन्ट क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाओं की सहायता करने के लिये हुई थी, प्रत्येक प्रकार के उद्योगों को कुल २०४० करोड़ रु० की वित्तीय सहायता देना स्वीकृत किया। वास्तविक रूप से दिये गये ऋण ६०१ करोड़ रु० थे। फल पाने वाले मुख्य-मुख्य उद्योग निम्न हैं—रायज, रसायन, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिंग, वस्त्र, चीनी, धातु, लौह व गोपेड का निर्माण आदि।

उद्योगों के पुनर्निर्माण के लिये स्वयंसेवक सन् १९५५ में हुई थी। इसका उद्देश्य यह होना था कि उद्योगों के पुनर्निर्माण के लिये दिये गये ऋणों के विवरण पुनर्निर्माण प्रयत्नों की सुविधा प्रदान करना है। पुनर्निर्माण प्रयत्नों की सुविधा पाने के हेतु यह जरूरी है कि ऋण ३ से ७ वर्ष की अवधि के हों तथा उनकी राशि भी मध्यम प्रकार की हो कि ५० लाख से अधिक न हो। ये सुविधा केवल उन्हीं उद्योगों को उपलब्ध होगी जिनकी दत्त पूँजी एवं शेष निम्नकर २५ करोड़ रु० से अधिक न हो। मार्च सन् १९६० तक पुनर्निर्माण प्रयत्नों की सुविधा ४१६ करोड़ रु० की दी गई।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नियम सन् १९५४ में स्थापित किया गया था। वह सूचीबद्ध एवं छूट उद्योगों के पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण के लिये तथा मशीन द्वारा उद्योगों के विस्तार के लिये विशेष ऋण देने के हेतु सरकार के एजेंट का कार्य भी करता है। मार्च सन् १९६० तक इसने उन उद्योगों को १४७६ करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत किये।

सरकार आवश्यक कच्चे माल तथा आधारभूत अर्थ निर्मित मालों के आयात को सुविधाजनक बना कर आरम्भ उद्योगों को प्रारम्भिक वर्षों में कर सस्ती सुदृढ़ देकर तथा सुरक्षण प्रदान करके भी प्राइवेट सेक्टर का सहायता पहुँचानी है। अन्तः राष्ट्रीय टैकनीकल सहायता योजना के अन्तर्गत या प्रत्यक्ष वाता द्वारा विश्व के विभिन्न औद्योगिक देशों से टैकनीकल सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया है।

(V) नई औद्योगिक नीति सन् १९५६—

औद्योगिक (विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम सन् १९५१, प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारम्भ एवं सफल समाप्ति भारतीय सचिवालय का परिचालन तथा लक्ष्य किए हुए सशोधन इत्यादि ऐसे परिवर्तित हुए जिन्होंने देश में एक नई औद्योगिक नीति को अपना देने के लिए बाध्य किया। भारतीय संसद द्वारा समाज की यह व्यवस्था पद्धति की स्वीकृत तथा उसकी आवश्यकताओं और समुचित कार्यसमय अधिवर्षों में पुष्टि एवं अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुभ आरम्भ इसी घटनाक्रम है जिनकी पृष्ठभूमि में औद्योगिक नीति को पुनः सशोधित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, अतः ३०

अप्रैल सन् १९५६ को प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार वे सभी उद्योग जो आधारभूत उद्योग हैं तथा देश की सुरक्षा की दृष्टि से जिनका महत्त्व है अथवा वे उद्योग जो सार्वजनिक हित के उद्घात हैं, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है। इसके अतिरिक्त वे सभी उद्योग जिनकी स्थापना के लिये बहुत मात्रा में पूँजी की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान स्थिति में केवल सरकार ही प्रदान कर सकती है। इस प्रकार के सभी उद्योगों के भविष्य के विकास का उत्तरदायित्व सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक क्षेत्र और अधिक व्यापक बना दिया गया है।

इस नीति के अनुसार सभी उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं—

(१) प्रथम श्रेणी में १७ उद्योग शामिल किए गये हैं जिनके भावी विकास का उत्तरदायित्व पूरी तरह सरकार पर निभेगा। इनमें हथियार, गोला बारूद, अणु शक्ति, लोहा तथा इस्पात, भारी मशीनरी कोयला, खनन तथा तेल यातायात आदि शामिल हैं। इन उद्योगों का उद्योग प्रयोगक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव की 'अ' सूची में किया गया है।

(२) दूसरी श्रेणी में वे उद्योग आने हैं जो धीरे धीरे सरकार के स्वामित्व में आते जायेंगे। इस प्रकार के नये गारखानों का लगाने में सरकार अधिक रुचि रखेगी, किन्तु सरकार के साथ निजी पूँजी को भी सहयोग देने का अवसर मिलेगा। इस श्रेणी में १२ उद्योग हैं जिनका वलून औद्योगिक प्रस्ताव 'ब' सूची में किया गया है।

(३) शेष सभी उद्योग तीसरी श्रेणी में रखे गये हैं, जो निजी क्षेत्र में रहेंगे, किन्तु सरकार उन पर आवश्यक निरीक्षण रख सकती है।

इस नई औद्योगिक नीति ने भी सरकार के कुत्सीर तथा जटिल पैमाने के उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया है। सरकार इन बातों का प्रयत्न करेगी कि बड़े पैमाने के उद्योगों की प्राप्ति तथा का मुबाशिरा करने के लिए छोटे उद्योगों की शक्ति बढ़ाई जाय।

(IV) पंच वर्षीय योजनाएँ—

भारत सरकार ने अपनी सन् १९४८ का औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद ही देश के औद्योगिक विकास की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य सरकारी नियन्त्रण में सन्तुलित अर्थ व्यवस्था बनाना था। हमारे देश की प्राथमिक समृद्धि की प्रथम पंच वर्षीय योजना सन् १९५० में बनाई गई और दूसरी सन् १९५६ में। ये दोनों ही योजनाएँ काफी सफल हुई हैं और इनकी सफलता का विस्तृत विवरण तृतीय पुस्तिका में दिया गया है। आजकल तृतीय पंच वर्षीय योजना चल रही है। तृतीय योजना काल का आलोचनात्मक परीक्षण भी तृतीय पुस्तिका के १२वें अध्याय में दिया गया है।

(VII) औद्योगिक उत्पादकता आन्दोलन —

भारतीय उत्पादकता शिफ्टमण्डल (Indian Productivity delegation), जोकि अक्टूबर-नवम्बर सन् १९५६ में जापान गया था की सिफारिशों के आधार पर फरवरी सन् १९५८ में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council) का स्थापना की है। इस परिषद में सरकार, सेवायोजक, थ मकान तथा अन्य वर्गों के सदस्य हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य सारे देश में उत्पादकता सम्बन्धी जागृत पैदा करना है। इसका ध्येय यह है कि राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि के लिए नवीनतम साधनों उत्पादन विधिया, आधुनिक यन्त्रा व नई टेक्निक का प्रयोग होना चाहिये। इसी हेतु प्राय औद्योगिक केन्द्रों में ४१ स्थानीय उत्पादकता परिषदा (Local Productivity Councils) की स्थापना की गई है तथा ५ क्षेत्रीय उत्पादकता डाइरेक्टोरेट (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर तथा बंगलौर) की स्थापना भी की गई है। आशा है कि इसके प्रयत्नों से औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।

(VIII) अन्य प्रयत्न —

इस प्रकार उक्त सभी राजकीय व गैर सरकारी प्रयत्नों के फल स्वरूप हमारा देश औद्योगीकरण के मार्ग पर प्रगति करता चला जा रहा है। यद्यपि अभी हमें मनोवांछित सफलता नहीं मिली है। फिर भी आज हमारा देश विश्व की आठवीं औद्योगिक शक्ति माना जाने लगा है। भारत सरकार ने केवल विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन पर हा जोर नहीं दिया, बल्कि निर्यात को प्रोत्साहित करने का भी प्रयत्न किया। जब कभी विदेशी प्रतस्पर्धा के कारण निर्यात में बाधा पड़ती है, तभी निर्यात कर में या तो भारी कमी कर दी जाती है अथवा उसे बिल्कुल हटा दिया जाता है। निर्यात किए जाने वाले माल में प्रयोग की जाने वाली कच्ची वस्तुओं के आयात शुल्क में भी कमी करके उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वयं अनेक आधारभूत उद्योगों की स्थापना की है जैसे रासायनिक खादों के निर्माण के लिए सिन्दूर या ५१२ खाना जलपान बनाने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड, दी गनीम हूल् फौजदारी नेशनल इन्स्टीट्यूट्स फौजदारी इत्यादि। बिहार में ४ करोड़ ६० की अधिकृत पूँजी से इण्डियन एक्सप्लोरेटिव के नाम से एक नई कम्पनी ग्गेली गई है। भिलाई, रूरवेला और दुमपुर के लौह व स्पात के कारखाने हमारी औद्योगिक सफलता के जीते-जागते उदाहरण हैं। रुपनारायणपुर की टेलीफोन कॉबिल फैक्ट्री में भी उत्पादन बढ़ रहा है। चित्तोजन में रेल के इंजिन व डिब्बों के उत्पादन में आगा से अधिक उत्पादन हुआ है। इनके अतिरिक्त साईकिल की चैन, पम्प, थरमन की बोतल व नकली मोती बनाने के उद्योग भी प्रगति के पथ पर हैं।

(IX) औद्योगिक उत्पादन—

जैसा कि आगे दी हुई तालिका से प्रगट होता है हमारा औद्योगिक उत्पादन काफी बढ़ गया है—

औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक (१९५१—१००)

वर्ष	सूचक-अंक	पहले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
१९५२	१०३.६	३.६
१९५३	१०५.६	१.९
१९५४	११२.९	६.९
१९५५	१२२.४	८.४
१९५६	१३२.६	८.३
१९५७	१३७.३	३.५
१९५८	१३९.७	१.७
१९५९	१५१.९	८.७
१९६०	१६७.५	११.७

इस समय औद्योगिक उत्पादन सन् १९५१ की अपेक्षा लगभग ६७ अधिक हो रहा है। सन् १९५५ से इसमें ३७% में भी अधिक वृद्धि हुई है। सन् १९५१ से नौ वर्षों की अवधि में उपभोक्ता वस्तु उद्योग-समूह के अन्तर्गत उत्पादन में लगभग ४५% की वृद्धि हुई, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं और पूँजीगत सामान का उत्पादन लगभग ८५% बढ़ा है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में इन उद्योगों के दोनों समूहों का लगभग बराबर ही महत्त्व है, फिर भी सूचक अंक में लगभग दो-तिहाई वृद्धि मध्यवर्ती वस्तुओं और पूँजीगत सामान के कारण हुई।

औद्योगिक उत्पादन के वास्तविक आंकड़

	इकाई	वास्तविक उत्पादन	
		१९५८	१९५९
कोयला	लाख टन	४,५३	४,७०
कच्चा लोहा	लाख टन	५७,१२	७७,५२
चीनी	हजार टन	२०,०४	१९,२०
चाय	लाख पौड	७१,४०	७०,५६
नमक	लाख मन	११,२५	८,५२
वनस्पति तेल प्रोडक्ट्स	हजार टन	२,६५	३,१७
सिगरेट	करोड़	२६,८४	३२,१४

सूती वस्त्र—

सूत	लाख थोड	१,६८,४८	१,७२,३२
बपडा	लाख गज	४,६२,७२	४,६२,६०
जूट टेक्सटाइल्स—			
हेसियत	हजार टन	४ ०८	४,५६
सैकिय	हजार टन	५,८८	५,०४
फुटबोयर (चमड़ा)	लाख जोडे	७६	८२
कागज एव पेपर बोर्ड	हजार टन	२,५३	२,६४
फुटबोयर (रबड़)	लाख जोडे	३,७२	३,६६
टायर	हजार	१०,०८	११,४०
सल्फ्यूरिक एसिड	हजार टन	२,२७	२,८१
कार्बोनिक् सोडा	हजार टन	५७	७०
ब्लीचिंग पाउडर	टन	६५ ०४	५१,८४
एमोनियम सल्फेट	हजार टन	३,८४	३,७६
पेन्ट एव वार्निश	हजार टन	४८	५५
दियासलाई	हजार बाक्स	६,२४	६,४८
साबुन	हजार टन	१,२३	१,२५
रेयन	हजार टन	२,८८	३,७०
ग्लास एव ग्लास का सामान	लाख बग गज	७,३६	८,०६
सीमेन्ट	लाख टन	६१	६८
सीरेमिक्स	हजार टन	४,३२	४,६२
लोहा व स्पात—			
पिंग आयरन	हजार टन	२१,००	३०,६०
तैयार स्पात	हजार टन	१२,६६	१७,४०
नान फेरस मेटल—			
अल्युमीनियम	हजार टन	१,३३ ४४	१,५६,७२
कॉपर	टन	३१,५६	२६ ७६
ब्रास	हजार टन	२ ०४	२,१५
सोना	हजार ग्राम	१,७०	१,६५
हरीकेन लास्टेन	हजार	३३,८४	३६,१२
इनेमिल वेयर	लाख टुकड़	१,६२	१,४६
डीजल इंजन	संख्या	३०	३६
सीने की मशीन	हजार	२,०५	२,५२
शुष्क सैल	लाख	१६,८०	१८,७२
स्टोर बैट्रियां	हजार	३,६०	४,४४
इलेक्ट्रिक लैम्प	लाख	३,०५	३,४८
इलेक्ट्रिक पम्प	हजार	६,३६	७,३२
घरेलू रेफ्रिजरेटर	संख्या	२६,१६	३६,६०
ऑटोमोबाइल	संख्या	२,६७,६६	३,६२,२४
बाइसकिल	हजार	६,१२	६,६६

STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the development of industries in India since independence
 2. Mention the special features of progress made in the field of Industrial Progress since independence with special reference to prospects under the Third Five Year Plan.
 3. Write a brief note on—
 - (a) Indian Standards Institute.
 - (b) Special features of progress in the field of Industrial Finance since independence
-

अध्याय १०

प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में औद्योगिक प्रगति

(Industrial Progress under the First Five Year Plan)

प्रारम्भिक—

स्वाधीनता प्राप्त होने से पहले हमारे देश के औद्योगिक विकास की गति मन्द थी। औद्योगिक दृष्टि से देश का विकास करने के लिए जम कर कोई प्रयास नहीं किया गया। जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार को सन् १९४७ में सत्ता हस्तांतरण होने के बाद से भारत के औद्योगिक विकास की आवश्यकता नए सिरे से प्रकाश में आई। नई सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में अपनी नीति में सबसे पहले जो परिवर्तन किए वे औद्योगिक विकास सम्बन्धी थे। सन् १९४८ के औद्योगिक नीति सक्ल्प में इस बात

के महत्व पर जोर दिया गया कि अथ-व्यवस्था उत्पादन में सतत वृद्धि कर सकने योग्य हो जाय। उसमें यह बात भी कही गई कि उद्योगों के विकास में सरकार को धीरे-धीरे सक्रिय भाग लेना चाहिये। औद्योगिक विकास में विदेशी पूँजी का महत्व स्वीकार करते हुए, एक वर्ष बाद प्रधान मन्त्री नेहरू ने विदेशी पूँजी के प्रति सरकार की नई नीति घोषित की। अनेक अवसरों पर विदेशी पूँजी को देशी पूँजी के समान ही समझे जाने का आश्वासन भी दिया गया। मूल पूँजी तथा उससे अर्जित मुनाफा स्वदेश ले जाने की छूट देने का भी आश्वासन दिया गया।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना

प्रथम पंच-वर्षीय योजना की विशेषताएँ—

देश के सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए सन् १९५० में भारत सरकार द्वारा प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए एक पंच-वर्षीय योजना तैयार की जा अप्रैल सन् १९५१ से मार्च सन् १९५६ तक के लिए थी।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जोर दिया गया था क्योंकि इसी पर काफी सीमा तक राष्ट्रीय आय का स्तर, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग—सूती वस्त्र तथा जूट उद्योगों—के कच्चे मालों की उपलब्धि तथा भारत के व्यापारिक सतुलन को पक्ष में रखने का भार था। प्रथम योजना में उद्योग धन्यों के विकास पर विशेष जोर नहीं दिया गया। योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं—दाम्बल में इनके बीच किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं है। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व केवल उन्हीं उद्योगों का विकास किया जाय जो निजी क्षेत्र की सामर्थ्य से बाहर हों। योजना में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक विकास तथा उत्पादन के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ८५ करोड़ रु० के नवीन विनियोग की व्यवस्था थी किन्तु केवल ६० करोड़ रु० ही वास्तुतः विनियोग किया गया। प्राइवेट क्षेत्र के नए प्रोजेक्टों व विस्तार कार्यक्रमों पर २३३ करोड़ रु० के विनियोग का अनुमान था और इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। प्राइवेट क्षेत्र में

प्लान्ट व मशीनरी के प्रतिस्थापन एवं आधुनिकीकरण पर व्यय अनुमान (२३० करोड़ रु०) से कम (अर्थात् केवल १०५ करोड़ रु०) हुआ। कुल मिला कर, आधुनिकीकरण व प्रतिस्थापन के अलावा, नवीन विनियोग ३२७ करोड़ रु० के लक्ष्य की तुलना में २६३ करोड़ रु० के लगभग हुआ। इसका विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है :—

प्रथम योजना में उद्योगों पर व्यय

(करोड़ रु० में)

	आयोजित	वास्तविक
मेटलर्जीकल उद्योग (लोह व स्पात, अल्यूमीनियम, आदि)	८५.०	६१.०
पेट्रोल साफ करने के उद्योग	६४.०	४४.०
रासायनिक उद्योग (हैवी केमिकल्स एवं उर्वरक, ड्रग आदि)	२६.०	२७.०
इजीनियरिंग उद्योग (स्थूल एवं हल्का)	५३.०	४६.०
सूती वस्त्र	६.०	२०.०
चीनी	०.१	५.०
रेयन वस्त्र	१६.५	८.०
सीमेन्ट	१७.७	१७.५
कागज (प्लूज प्रिन्ट आदि)	७.४	१२.०
इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन एवं वितरण (ग्राइवेट क्षेत्र)	१६.०	३२.६
अन्य	३२.३	१८.६
कुल	३२७.०	२६३.०

प्रथम योजना की औद्योगिक सफलताएँ—

प्रथम पंच-वर्षीय योजना अवधि में व निजी क्षेत्रों में कुल २६३ करोड़ रु० विनियोग किया गया। इस राशि में से निजी क्षेत्र का विनियोग २३३ करोड़ रु० था। अतः स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र का विनियोग निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही हुआ, किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में लक्ष्य से कम विनियोग हो सका।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में कुल औद्योगिक उत्पादन में ३८% की वृद्धि हुई, जिसमें विभिन्न वर्गों के उद्योगों का भाग इस प्रकार था—

विवरण

वृद्धि की प्रतिशत
(१९५०-५१ स १९५५-५६ तक)

(अ) पूँजीगत पदार्थ (Capital Goods)—

डिजल इंजन	८७	} ७०%
मशीनों के औजार	१३३	
ब्रैगन	१००	
ऊत रिग व स्पिनिंग फ म	२३०	
ग्राइन्डिंग वोल	१३४	
घोटोमोबाइल	५३	
रेलवे लोकोमोटिव	६६०	

(ब) मध्यवर्ती पदार्थ (Intermediate Goods)—

सूत	३६	} ३४%
जूट का माल	२८	
प्लाइवुड	१०६	
गन्धक का तेजाब	६५	
कार्बिक सोडा	२११	
सोडा ऐस	८०	
रेयन फिलामेंट	१८७	
पिग फ्रायरन	१४	
सीयर इस्पात	३०	
अल्यूमिनियम	६६	
सीमेन्ट	७१	

(स) उपभोक्ता पदार्थ (Consumers' Goods)—

सूती कपड़ा	३७	} ३४%
रबर फुट वीयर	६५	
साबुन	३७	
वनस्पति	८०	
इनामल वेयर	१८५	
बाइसिकल	४०८	
कागज	६४	
चीनी	६०	

औद्योगिक उत्पादन में कुल वृद्धि

३८%

प्रथम योजना काल में कुछ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान नीचे दी हुई तालिका से लगाया जा सकता है:—

तालिका II

औद्योगिक उत्पादन	१९५०-५१	१९५५-५६	प्रतिशत वृद्धि
१—कच्चा लोहा (हजार टन)	१५७२	१७८७	१३.७
२—तैयार इस्पात („ „)	६७६	१२७४	३०.५
३—सीमेन्ट („ „)	२६८६	४५६२	७०.८
४—अमोनियम सल्फेट („ „)	४६	३६४	७५६.५
५—रेलवे इंजन (Locomotives)	३	१७६	
की सख्या			
६—डिजल इंजन की सख्या	५५३६	१०१६६	८७.३
७—मैशिन टूल्स (मूल्य लाख रुपये में)	३२.६४	७८.५४	१३३.५
८—अल्युमिनियम (टन)	३६७७	७३३३	६६.४
९—सूती-बस्त्र उद्योग			
(क) सूत (दस लाख पौंड)	११७६	१६३३	३६.०
(ख) मिल का कपड़ा (दस लाख गज)	३७१८	५१०२	३७.२
(ग) हस्त वर्धा का कपड़ा („ „)	८१०	१४४६	७६.०
१०—जूट उद्योग (हजार टन)	८२४	१०५४	२८.०
११—चीनी („ „)	१०६४	१७०१	५६.६
१२—कागज तथा पेपर बोर्ड („ „)	११४	१८७	६४.०

उपर्युक्त तालिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रथम योजना अवधि में उद्योग-धन्धों की पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनेक उद्योगों में तो उत्पादन की वृद्धि लक्ष्य से भी कहीं अधिक हुई। इस अवधि में अनेक नई-नई वस्तुओं का भी उत्पादन शुरू किया गया, जिनमें वायुयान, पैनिसिलीन, डी० डी० टी०, रेल के डिब्बे, अमोनियम क्लोराइड आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में चित्तूरजन का कारखाना, सिन्द्री का रासायनिक खाद का कारखाना, इनटैंगल कोच फैक्ट्री, इण्डियन कोच फैक्ट्री, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज की प्रगति काफी सन्तोषजनक रही।

STANDARD QUESTION

- (1) Briefly summarise the principal objectives and industrial achievements of the First Five Year Plan

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में औद्योगिक प्रगति

(Industrial Progress Under the Second Plan)

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में प्राथमिकता क्रम—

द्वितीय योजना में पूँजी एवं उत्पादक वस्तु उद्योगों के विकास पर मुख्य बल दिया गया, जिससे कि औद्योगिक प्रगति की नीवें दृढ़ता से पड़ जायें। प्राथमिकताओं का निम्न क्रम निर्धारित हुआ —

- (१) लौह व स्पात तथा हवी कैमोकेल्स (नाइट्रोजन उर्वरक सम्मिलित करते हुये) का उत्पादन बढ़ाना और हवी इंजीनियरिंग एवं मशीन-निर्माण उद्योगों का विकास करना ।
- (11) अन्य विकासार्थक वस्तुओं और उत्पादक-सामानों (जैसे अल्युमीनियम, सीमेन्ट, कैमोकेल्स पल्प, डाइस्टफ आदि) तथा आवश्यक दवाइयों के सम्बन्ध में क्षमता का विस्तार करना ।
- (111) राष्ट्रीय उद्योगों (जैसे फूट, सूती वस्त्र एवं चीनी उद्योग) का आधुनिकीकरण एवं नव मुसज्जन ।
- (1V) जिन उद्योगों में क्षमता और उत्पादन के बीच भारी अन्तर है उनमें विद्यमान उत्पत्ति क्षमता का पूर्ण उपयोग करना ।
- (V) सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रमों तथा उद्योग के विकेंद्रित सेक्टर के उत्पादन सक्षमों का ध्यान रखते हुये उपभोग वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाना ।

द्वितीय योजना अवधि में समकालित उद्योगों पर १,०६४ करोड़ रु० के नवीन विनियोग की आशा थी—५२४ करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र में (राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा विनियोजित ३५ करोड़ रु० इससे गृथक हैं) और ५३५ करोड़ रु० प्राइवेट क्षेत्र में । सार्वजनिक क्षेत्र का यह व्यय मुख्यतः निम्न उद्योगों के विकास पर होना था— लौह एवं स्पात (३५० करोड़), उर्वरक (३७ करोड़), हवी इलेक्ट्रीकल प्लांट (२०

करोड़), लिगनाइट प्रोजेक्ट (५२ करोड़) और हिन्दुस्तान शिपयार्ड (६८ करोड़)। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न पर व्यय किया जाना था—सूती एवं जूट टेक्सटाइल उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिये सहायता, हैवी फाउन्ड्रीज, रिफ्रेक्टरीज, न्यूजप्रिन्ट आदि के विकास कार्यक्रम। उसे अल्पमौनियम के लिये एक नई इकाई की स्थापना तथा मिट्टी हटाने तथा खानों के लिये भारी मशीनें व साज सामान के निर्माण को भी प्रोत्साहन देना था।

कुल अनुमानित व्यय एवं वास्तविक का सावजनिक एवं प्राइवेट क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों पर वितरण निम्न तालिका में दिखाया गया है—

द्वितीय योजना में उद्योगों पर व्यय

	करोड़ रु० में व्यय का लक्ष्य	कुल विनिर्माण का प्रतिशत	वास्तविक व्यय
मेटलर्जिकल उद्योग	५०२.५	४५.६	७७०
इंजीनियरिंग उद्योग	१५०.०	१३.७	१७५
कैमीकल इन्डस्ट्रीज	१३२.०	१२.०	१४०
मीनेन्ट, इलेक्ट्रिक पोरसीलेन एवं रिफ्रेक्टर्स	६३.०	८.५	६०
पेट्रोलियम सफाई	१०.०	०.६	३०
पेपर, न्यूज प्रिन्ट	५४.०	५.०	४०
चीनी	५१.०	४.७	५६
सूती, जूट, ऊनी, रेशमी सूत व कपड़ा	३६.३	३.३	५०
रेयन	२४.०	२.२	२४
अन्य	४१.५	३.८	११५

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य—

द्वितीय योजना काल में विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में निम्न वृद्धि की आशा की गई थी :—

	वृद्धि का प्रतिशत (१९५५-५६ से १९६०-६१ तक)
(अ) पूँजी एवं उत्पादक पदार्थों के उद्योग—	
तैयार स्वान	२३१
अल्यूमीनियम	२३३
फैरो मैंगनीज	—
नाइट्रोजन उर्वरक	२७७
फास्फेटिक उर्वरक	५००
सोडा एश	१८८
कास्टिक सोडा	२७५
प्लास्टिक बनाने का पाउडर	१,३६२
ड्राईस्टफ	४५०
पावर अलकोहल	१००
सीमेन्ट	१८३
रिफ्रेक्टरीज	१८६
लोकोमोटिव	१२५
इलेक्ट्रिक ट्रान्सफार्मर्स	११६
औद्योगिक मशीनरी	४७१
(ब) उपभोक्ता माल उद्योग—	
चीनी	२४
रेयन	२४६
सूती वस्त्र :—	
सूत	१६६
कपड़ा	२६२
ऊनी वस्त्र —	
सूत	२५०
कपड़ा	३४२
ग्लास एवं ग्लास का सामान	६००
बाइसकिल	८१८
साबुन	५००
वनस्पति	४८१
पेपर एवं पेपर बोर्ड	७५०

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत हुई औद्योगिक प्रगति का विवरण —

पिछले दशब्द में भारत में एक औद्योगिक क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ। इस अवधि के भीतर उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण बहुत आश्चर्यजनक गति से हुआ है। इस अल्प अवधि में ही १-१ मि० टन की क्षमता वाले तीन नये स्पात-कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में पूरे किये गये हैं और प्राइवेट क्षेत्र के दो विद्यमान स्पात कारखानों में नूना विस्तार कर लिया है ताकि उनकी क्षमता भी क्रमशः २ और १ मि० टन हो जाय। हैवी इलेक्ट्रिकल और हैवी मशीन टूल इन्डस्ट्रीज, हैवी मशीन बिल्डिंग एण्ड हैवी इंजीनियरिंग की अन्य शाखाओं का विकास की बुनियादे रख दी गई हैं। सीमेंट एवं कागज के उद्योगों के लिये मशीनों के उत्पादन का कार्य प्रथम बार प्रारम्भ हुआ। कौमीकल उद्योगों के क्षेत्र में नो काफी प्रगति हुई है जिससे आधारभूत कौमीकल (जैसे नाइट्रोजन उर्वरक, कास्टिक सोडा, मोडा एण्ड एव मल्स्यूरिक एसिड) की उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हो गई है। कई नये पदार्थ (जैसे अमोनियम फास्फेट, पेनिसिलीन, औद्योगिक निस्फोटक, न्यूजप्रिन्ट आदि) भी बनने लगे हैं। अन्य अनेक उद्योगों की उत्पत्ति भी काफी बढ़ गई है, जैसे बाइस्किल, सीने की मशीनें, टेलीफोन, बिजली का सामान, वस्त्र एवं चीनी मशीनरी। कर्मचारियों ने नये कार्य सीख लिये हैं, उनकी कुशलता में काफी वृद्धि हो गई है तथा औद्योगिक मैनेजरो का एक नया वर्ग विकसित हो रहा है। सब कुल मिलाकर पिछले १० वर्षों में औद्योगिक उत्पादन लगभग दूना हो गया है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, जो सन् १९५०-५१ में १०० माना गया था, सन् १९६०-६१ में १९४ तक बढ़ गया।

किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी सफलताएँ अधिक होते हुये भी जनता की सामान्य व। पर कोई विशेष प्रभाव डालने में या अर्थ व्यवस्था के स्वरूप में कोई भारी परिवर्तन करने में पर्याप्त प्रमाणित नहीं हुई है। यही नहीं, देश ने अपने सम्मुख जो औद्योगिक लक्ष्य रखे थे उनमें कहीं-यही भारी कमियाँ रह गई हैं। उदाहरण के लिये, तीन नये स्पात कारखानों का उत्पादन लक्ष्य २ मि० टन था, जबकि वास्तविक उत्पादन केवल ०.६ मि० टन ही रहा। इसी प्रकार, टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स का उत्पादन भी लक्ष्य (१.२ मि० टन) की तुलना में कम (अर्थात् ४.५ मि० टन) रहा। उर्वरकों के क्षेत्र में, सिन्दरी के सरकारी खाद कारखाने का विस्तार तथा अमोनियम फ्लोराइड के प्राइवेट प्रोजेक्ट (वाराणसी) का विकास निर्दिष्ट तिथि के १२ में १८ महीने बाद पूर्ण हो पाया। नागल, नैवेली एवं रुरेला के तीन नये सरकारी उर्वरक कारखाने भी एक-दो वर्ष देर से पूरे हो पायेगे। इन कामों में देरी लगने का मुख्य कारण विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं। यही बात भूपाल के हैवी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट को लागू होती है। किन्तु हैवी मशीनरी, माइनिंग मशीनरी तथा फाउन्ड्री प्रोजेक्टों के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। उत्पादन के प्रारम्भ करने की बात तो दूर उनकी स्थापना का कार्य भी अभी असम्पूर्ण है।

कुछ दगाओ में देर होने का कारण बनेगी महयोगरताया स वार्ता लम्बी खिचना है । इन त्रुटियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले में नियोजन कर लेना कितना लाभदायक है ।

जिन मुख्य औद्योगिक लक्ष्यों का पूर्ति नहीं हुई है वे निम्न में सम्बन्ध रखते हैं—लोह एवं स्पात उधरक कुछ विशेष प्रकार की औद्योगिक मशीनरी (जैसे वागज सीमेन्ट) अल्यूमीनियम ग्रेजिट वही फिल्म सोडा एण्ड कास्टिक सोडा सीमेन्ट आदि । दुर्भाग्य से कुछ ऐसे उद्योगों में लक्ष्य अपूर्ण रह गये हैं जो कि अत्यन्त महत्त्व के थे तथा वृत्ताय पंच वर्षीय योजना के आरम्भ के समय निभर रहे जा सकते थे । पून रह जाने वाल उक्त लक्ष्य निम्न है —

	कुवाई	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
तैयार स्पात	मि० टन	४३	२२
नाइट्रोजन उधरक	००० टन	२६००	११००
फास्फटिक उधरक	००० टन	१२००	५५०
टैंकस्टाइल मशीनरी	करोड़ रु०	१७०	६०
सीमेन्ट मशीनरी	करोड़ रु०	२०	०६
पेपर मशीनरी	करोड़ रु०	४०	—
अल्यूमीनियम	००० टन	२५०	१८५
ग्रेजिट	००० टन	६००	२५०
कैमीकल्स	टन	३०००००	—
सोडा एण्ड	००० टन	२३००	१४५०
कास्टिक सोडा	००० टन	१३५०	१०००
आईस्टफ	मि० पीन्	२२०	११५
सीमेन्ट	मि० टन	१३०	८५

अन्य उद्योगों के लक्ष्य लगभग पूर्ण हो गये एवं कुछ में तो लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन हुआ है जैसे—पावर डबिन पम्प डीजल इंजन इलक्टिक मोटर्स केबिल इलक्टिक पैन रेडियो रिस्वीवर व चीनी । मोट तौर पर यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक प्रगति इतनी काफी हुई है कि अथ व्यवस्था विकास की दिशा में आत्म निर्भर हो जाय ।

गत दस वर्षों में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में काफी सफलता मिली है । तीव्र नये स्पात कारखानों हेवी मशानरा प्लांट (राचा) और हेवी इलक्टिकल प्रोजेक्ट (भूपाल) के लिये स्थान का चुनाव इस बात का प्रमाण है । पिछड़ हुये क्षेत्रों को सावजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी गई है । प्राइवेट उद्योगों के विकास के लिये साइसेस देने में भी इस बात का ध्यान रखा गया है ।

STANDARD QUESTIONS

- 1 Briefly summarize the principal achievements in the field of Industry during the Second Five Year Plan
- 2 Write an essay on Industrial Progress under the two Plans

अध्याय १२

तृतीय पंच-वर्षीय योजना में उद्योग

(Industries Under the Third Plan)

उद्देश्य—

सन् १९६१-६६ की अवधि के लिए, जो औद्योगिक कार्यक्रम बनाया गया है उसका उद्देश्य अगले १५ साल में तेजी से औद्योगीकरण की नींव डालना है।

औद्योगिक नीति—

उद्योगों का विस्तार अप्रैल सन् १९५६ की उद्योग नीति के सकल्प के अनुसार होगा। दूसरी योजना की तरह इस योजना में भी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों को एक दूसरे के सहायक और पूरक की तरह काम करना होगा।

औद्योगिक प्राथमिकता—

- (१) ऐसे उद्योगों को पूरा करना जो दूसरी योजना में शुरू किये गये थे या जिन्हें विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण सन् १९५७-५८ में रोक देना पड़ा था।
- (२) भारी इन्जीनियरी और मशीन बनाने के कारखानों का विस्तार, जैसे गढ़ाई और ढलाई मिश्रित धातु और विशेष किस्म के स्पात, लोहा और स्पात और लोह-मिश्रित धातु उत्पादन कारखाने। उधरक और पेट्रोल के कारखानों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा और इनसे नई नई चीजें बनाने का उद्योग शुरू करना होगा।
- (३) अलमूनियम, खनिज नल, धुलने वाली लुगड़ी, मूल कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और पेट्रोल के रसायन तथा नव उद्योगों में काम आने वाले रसायन आदि के कारखानों का उत्पादन बढ़ाना होगा।

(४) दवा, कागज कपड़ा, चीनी, तेल और इमारती सामग्री आदि के उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना होगा ।

औद्योगिक विकास के व्यय का अनुमान—

तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं खनिजों के लिये जो विकास कार्यक्रम बनाया गया है उस पर २८६५ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है । विदेशी मुद्रा की आवश्यकता १३३८ करोड़ रु० कृता गई है । व्यय का धीरा इस प्रकार है—

(करोड़ रु० में)

	सावजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सावजनिक तथा प्राइवेट क्षेत्र	
	कुल	विदेशी विनिमय	कुल	विदेशी विनिमय	कुल	विदेशी विनिमय
(अ) नवीन विनियोग						
(1) खनिज विकास	४७८	२००	६०	२८	५३८	२२८
(11) औद्योगिक विकास	१,३३०	६६०	१,१२५	४५०	२४५५	१,११०
कुल	१ ८०८	८६०	१,१८५	४७८	२९९३	१,३३८
(ब) प्रतिस्थापन			१५०	५०	१५०	५०

उक्त व्यय की तुलना में उपलब्ध साधनों के कम पड़ने की सम्भावना है । सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खानों के अलावा जो खपटा रखा गया है और निजी क्षेत्र के लिये जितने स्पर्ध उपलब्ध होने का अनुमान है उनकी राशि २,५७० करोड़ रु० होती है । १,४७० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र के लिए और १,१०० करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए । इसके अनिवारित यह राशि की जाना है कि उन कारखानों की मशीनें बदलने और उनमें आधुनिक मशीन लगाने के लिये १५० करोड़ रु० उपलब्ध हो सकेंगे जो कि द्वितीय महायुद्ध के पहले के हैं ।

इन अनुमानों में यह मनेत मिलता है कि दाना ही क्षेत्रों में कई कार्यक्रम भी हो जायेंगे पर फलान पड़ेंगे । चोकि अभी तक कुछ प्रोजेक्ट प्रगति की अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में पड़ेंगे हैं विदेशी मुद्रा मिलना अनिश्चित है तथा हैवी इन्डस्ट्रीज की दशा में विकास की अवस्था काफी लम्बी है । कौन से प्रोजेक्ट पूरे हो सकेंगे और कौन से पूरे नहीं हो सकेंगे इस बारे में अभी निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम—

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक एवं खनिज कार्यक्रमों (डिफेंस उद्योगों एवं रेलवे तथा यातायात व संचार मन्त्रालयों के निजी आवश्यकता पूर्ति के कार्यक्रमों को छोड़कर) की लागत १,८८२ करोड़ रु० कूती गई है, जबकि उनके लिये कुल १,५२० करोड़ रु० का आयोजन किया जा सका है—१,४५० करोड़ केन्द्र में तथा ७० करोड़ रु० राज्यों में। अतः यह सम्भव है कि इन कार्यक्रमों के पूरा होने में ५ वर्ष से भी अधिक समय लग जाय। केन्द्रीय सरकार के प्रोजेक्टों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:—(१) द्वितीय योजना के अगूरे प्रोजेक्ट (२) नये प्रोजेक्ट, जिनके लिए विदेशी ऋणों का आश्वासन मिल चुका है तथा (३) नये प्रोजेक्ट, जिनके लिए अभी विदेशी ऋणों का प्रबन्ध नहीं हो पाया है। प्रथम श्रेणी के सभी प्रोजेक्ट तो पूरे ही हो जायेंगे, द्वितीय श्रेणी के अनेक प्रोजेक्ट भी पूरे हो सकेंगे किन्तु तीसरी श्रेणी के प्रोजेक्टों की पूर्ति में सबसे अधिक अनिश्चितता है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक कार्यक्रम लौह एवं स्पाइन, औद्योगिक मशीनरी, हैवी इलैक्ट्रिक इन्विपमेंट, मशीन टूल्स, उर्वरक, बेसिक कैमीकल्स, आवश्यक दवाइयों व पेट्रोलियम शोधन से सम्बन्धित है।

प्राइवेट क्षेत्र के कार्यक्रम—

सन् १९५६ के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के अन्तर्गत, अ अनुसूची के उद्योगों को छोड़ कर जो कि राज्य के लिये सुरक्षित हैं, शेष उद्योगों के सम्बन्ध में प्राइवेट उपक्रम के लिये बहुत ही विस्तृत कार्य क्षेत्र उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि गत ५ वर्षों में सरकारी क्षेत्रों में जो उन्नति हुई है उससे प्राइवेट उपक्रमों को अपने तृतीय योजनावधि के विकास में बड़ी सुविधा हो गई है तथा तृतीय योजनावधि में सार्वजनिक क्षेत्रों में जो विकास होगा वह भी इसी प्रकार प्राइवेट उपक्रमों के लिये चौथी योजनावधि के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनायेगा। किन्तु यह आवश्यक है कि प्राइवेट उपक्रम अपने विकास-कार्यक्रम को औद्योगिक विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुसार समायोजित कर लें। विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रभाव के कारण प्राइवेट क्षेत्र के स्वतन्त्र विकास पर कुछ प्रतिबन्ध लगने की सम्भावना है। घरेलू साधनों, यातायात, शान्ति पूर्ति, कुशल कर्मचारियों, प्राथमिकता-क्रम आदि परिस्थितियों को ध्यान में रख कर औद्योगिक लक्ष्यों में कुछ परिवर्तन भी करने पड़ सकते हैं। उत्पादन-लक्ष्य निश्चित करने में योजना आयोगों ने सम्बन्धित उद्योगों, विकास परिषदों तथा प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक सङ्गठनों से विचार विमर्श कर लिया था।

सार्वजनिक एवं प्राइवेट क्षेत्र के उपक्रमों का अर्थ-प्रबन्धन—

सार्वजनिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोजेक्टों के लिये अधिकांश कोष सरकार को ही जुटाना होगा। हाँ, कुछ समस्याएँ अपने आन्तरिक साधनों से भी वित्त व्यवस्था कर लेंगी। अनुमान लगाया गया है कि आन्तरिक साधनों से ३०० करोड़ रु० का प्रबन्ध हो

जायेगा। राज्य-सरकारों को व केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक प्रोजेक्टों के लिये धन की व्यवस्था करते समय अन्य कार्यों के लिये धन जुटाने के अपने दायित्वा को भी ध्यान में रखना पड़ा है।

प्राइवेट क्षेत्र में निम्न साधना स कुल १२५० करोड़ रु० के अर्थ-प्रबन्धन का अनुमान है—संस्थागत एजेंसियाँ १३० करोड़ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष सहायता २० करोड़ नवीन अंश निगमन २०० करोड़ आन्तरिक साधन ६०० करोड़, विदेशी सहयोग पूँजी में ३०० करोड़ रु०। कुल धन्य १,३५० करोड़ रु० प्रस्तावित है। इस प्रकार १०० करोड़ रु० की कमी पड़ती है। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की समस्या भी जटिल है।

औद्योगिक कार्यक्रम को मुख्य विशेषताएँ—

प्रारम्भिकताओं का निर्धारण करने में यह ध्यान रखा गया है कि जो उद्योग विदेशी विनिमय का अजन करने में या विदेशी विनिमय का खर्च बचाने में (आयात कम करके) सहायक हो उन्हें अन्य उद्योगों की अपेक्षा विकास का प्रथम अवसर दिया जाय। तीसरी योजना में प्रमुख उद्योगों के विकास कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(I) मेटलर्जिकल उद्योग—

(१) लौह एवं स्पात—इस उद्योग के लिये स्पात पिंडों (Steel ingots) की उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य १०२ मि० टन तथा पिग आयरन की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य १५ मि० टन रखा गया है। यह लक्ष्य विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिये लौह एवं स्पात की भारी मांग का आधार पर निर्धारित किये गये हैं। स्पात सम्बन्धी लक्ष्य में प्राइवेट क्षेत्र का भाग ३२ मि० टन है। क्षमता की वृद्धि के लिये स्क्रैप बेस की इलेक्ट्रिक फर्नेसज लगाई जावगी। पिग आयरन के लक्ष्य में प्राइवेट क्षेत्र का भाग ०३ मि० टन है। तावजनिक क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नवीन स्पात कारखानों पर भरसा किया गया है। लौह एवं स्पात की योजना में नये विकास झिलाई, दुर्गापुर एवं रुड़केला के स्पात कारखाना के तथा मैसूर आयरन एवं स्टील कारखानों के विस्तार से श्रीर बोकारो में नये स्टील प्लांट की स्थापना से सम्बन्धित है। नैवेली में एक पिग आयरन प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव भी है। तीसरी योजना अवधि की समाप्ति पर कुल स्टील उत्पादन २४१ मि० टन के लगभग हो जायेगा। योजना के प्रारम्भिक वर्षों में उत्पादन कम होने से मांग की पूर्ति में कुछ कठिनाई होना स्वाभाविक है, किन्तु योजना की प्रगति के साथ साथ यह कठिनाई कम होती जायेगी।

(२) दूध, अलाय एवं स्टेनलेस स्टील—दुर्गापुर में एक अलाय एवं दूध स्टील प्लांट खोलने का निश्चय किया गया है जिसका वार्षिक उत्पादन ४८,००० टन होगा। इजीनियरिंग उद्योगों के लिए इन कच्चे मालों का बड़ा महत्त्व है। अभी तक इनका

प्राप्यत किया जाता रहा है, जिससे बड़ी कठिनाई अनुभव की गई थी। उक्त प्रोजेक्ट में आधुनिकतम साज सामान व विधियों का प्रयोग होगा।

(३) अल्यूमीनियम—नॉन फेरस धातुओं के क्षेत्र में अल्यूमीनियम का महत्त्व सर्वोपरि है। सन् १९६५-६६ के लिये इसके उत्पादन का लक्ष्य ८७,५०० टन रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये निम्न योजना बनाई गई है—हीराकुण्ड की इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी के प्लान्ट का १०,००० टन से तथा अल्वेई प्लान्ट का ५,००० टन में विस्तार, रिहान्ड व कोयना पर २०-२० हजार टन के स्मेलटरो की स्थापना तथा अल्यूमिनियम कॉरपोरेशन आफ इन्डिया के प्लान्ट का ५,००० टन वार्षिक विस्तार।

(४) ताँबा—इन्डियन कॉपर कारपोरेशन द्वारा घाटशिला में एक इकाई स्थापित करने पर तृतीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में ही इलेक्ट्रोलेटिक कॉपर का उत्पादन होने लगेगा।

(५) जस्ता—राजस्थान की जवार खानों में पाये जाने वाले जस्ते के आधार पर जिनक स्मेलटर स्थापित होने पर भारत में पहली बार जस्ते का उत्पादन होने लगेगा। इस प्लान्ट की क्षमता १५,००० टन प्रति वर्ष होगी।

(II) इन्जीनियरिंग उद्योग—भारी एवं हल्के—

पिग आयरन एवं स्टील की पूर्ति बढ़ने, मशीन-निर्माण पर बल देने तथा विनियोग की अपेक्षा अधिक रोजगार मिलने की सम्भावनाओं के कारण इस क्षेत्र में बड़े पैमाने के विकास का प्रस्ताव है। सार्वजनिक क्षेत्र हैवी मशीनरी और हैवी मशीन बिल्डिंग का उत्पादन करने वाले प्रोजेक्टों पर मुख्य ध्यान देगा। शेष कार्य प्राइवेट उपक्रम के सुपुर्द किया गया है, जो कृषि मशीनरी, ट्रक, डीजल इंजन, रोड रॉयल, डम्पर, ट्रान्सफार्मर, इलेक्ट्रिक केबिल एवं तार घरो में लगने वाले मीटर, लोकोमोटिव्स, बैंगन, पैमेन्जर कोचेज, बसें एवं ट्रक, चीनी, कागज, सीमेंट और वस्त्र उद्योग तथा वैमिकल उद्योगों के लिए पूर्ण प्लान्ट, पैसिन्जर कारे, सीने की मशीनें, साइकिलें, बिजली के पम्प आदि बनावेगा। नीचे इन्जीनियरिंग उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है:—

(१) फाउन्ट्री एवं फोर्ज शाप—मशीनरी-निर्माण कार्यक्रमों के लिए फाउन्ट्री एवं फोर्ज शापों (Foundry and forge shops) का बड़ा महत्त्व है। इस क्षेत्र में तृतीय योजना के लक्ष्य निम्न है—ग्रै आयरन कास्टिंग १.२ मि० टन, स्टील कास्टिंग एवं फोर्जिंग प्रत्येक के लिए २,००,००० टन। कास्टिंग एवं फोर्जिंग की आवश्यकतायें ओटोमोबाइल उद्योग के विकास तथा वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज एवं अन्य पूंजी माल बनाने वाले उद्योगों के लिए मशीनरी बनाने के विकास के साथ-साथ बढ़ती जायेगी।

(२) औद्योगिक मशीनरी—इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रोजेक्ट निम्न हैं—हैवी मशीनरी प्लान्ट (रांची), खान सम्बन्धी मशीनरी प्रोजेक्ट (दुर्गापुर), हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लान्ट (भोपाल) पर दो अन्य हैवी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, जिनका स्थान अभी विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है। रांची का हैवी मशीनरी प्लान्ट प्रति वर्ष ८०,००० टन की उत्पादन-क्षमता रखेगा तथा स्पात बनाने की क्षमता को प्रति वर्ष १ मि० टन की दर से बढ़ाने के लिये आवश्यक साज-सामान की अधिकांश पूर्ति कर सकेगा। दुर्गापुर के मशीनरी प्रोजेक्ट का विकास इस प्रकार आयोजित किया जायेगा कि वह प्रति वर्ष ४५,००० टन के लगभग साज सामान बना सके। तीनों हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोजेक्ट्स बिजली-उत्पादन के लिये आवश्यक विविध प्रकार का अधिकांश साज सामान तैयार करेंगे, ताकि बिजली का उत्पादन प्रति वर्ष २ मि० किलो-वाट की दर से सन् १९७१ के बाद बढ़ाया जा सके। ये हैवी मोटर्स, रेक्ट्रीफायर्स और कान्ट्रोल इक्विपमेंट भी बनावेंगे। जैकोस्लोवाकिया की सहायता से एक हैवी इन्जीनीयरिंग प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना भी है, जिसका उद्देश्य हाई प्रेसर के बॉयलर तैयार करना है।

प्राइवेट क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के मिलों के लिए पूर्ण प्लान्ट बनाने के लक्ष्य रखे गये हैं। इनमें अधिकतर देशी सामग्री का प्रयोग होगा। सीमेंट मिलों के लिए ६ या ७ प्लान्ट (मूल्य = ४ से ५ करोड़ रु०) कागज मिलों के लिये ८ छोटे बड़े प्लान्ट (मूल्य = ६५ से ७० करोड़ रु०), चीनी मिलों के लिये १४ प्लान्ट (मूल्य १० करोड़ रु०), सूती वस्त्र मिलों के लिये मशीनरी (मूल्य २० करोड़ रु०) तथा सलफ्यूरिक एसिड के १० प्लान्ट (मूल्य १०३ करोड़ रु०) बनाने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों का पूरा होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन पर ही अन्य क्षेत्रों में प्रगति निर्भर करती है।

(३) मशीन टूल्स—लघु पैमाने के क्षेत्र द्वारा ५ करोड़ रु० मशीन टूल्स का उत्पादन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने के क्षेत्र में सन् १९६५-६६ तक मशीन-टूल्स के उत्पादन का लक्ष्य २० करोड़ रु० रखा गया है, जबकि वर्तमान उत्पादन ३ करोड़ रु० के मशीन टूल्स है। यह लक्ष्य तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक बढ़ी हुई मांग के अनुमान (= ५० करोड़ रु० मूल्य के मशीन टूल्स) से बहुत कम रहता है। किन्तु कुशल कारीगरों की कमी रहने से इससे अधिक लक्ष्य रखना सम्भव नहीं है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना का विस्तार किया जायेगा तथा पंजाब व बिहार में एक-एक नया हैवी मशीन टूल कारखाना स्थापित किया जायेगा। प्राइवेट क्षेत्र में जो विकास होगा वह सार्वजनिक क्षेत्र का विकास का पूरक होगा, ताकि मशीन औजारों सम्बन्धी बड़ी हुई मांग को पूरा करने में सहायता हो।

(४) रेलवे रोलिंग स्टॉक—इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम चितरजन लोकोमोटिव कारखाने में इलैक्ट्रिक इंजनों के निर्माण में सम्बन्धित है। इन इलैक्ट्रिक इंजनों के लिए टूबेशन मोटर्स का निर्माण नूपाल के हवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने में किया जावेगा। रेलवे योजना में डीजल इलैक्ट्रिक और डीजल हाइड्रोलिक इंजनों के निर्माण का जो प्रोजेक्ट सम्मिलित है वह रेलवे को अपने साज-सामान के सम्बन्ध में बहुत सीमा तक आत्म निर्भर बना देगा। १० करोड़ ६० की लागत से स्थापित होने वाला डीजल इंजन प्रोजेक्ट १४० इंजन प्रति वर्ष बनायेगा, जिनका विक्रय मूल्य १० करोड़ के लगभग है। डीजल हाइड्रोलिक इंजनों के निर्माण में एक सुधरे हुए डिजाइन का प्रयोग किया जायेगा, जिसे हाल में भारतीय रेलवे के एक इंजीनियर ने विकसित किया है। प्राइवेट क्षत्र बैंगन, मोटर गेज के स्टीम इंजन तथा इलैक्ट्रिकल मल्टीपल कोचेज का निर्माण करता रहेगा।

(५) जहाज-निर्माण—इस शीर्षक के अन्तर्गत जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें विशाखापटनम में एक ड्राइडक बनाने तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० का विस्तार करने का प्रस्ताव सम्मिलित है। इन विकासों के पूर्ण होने पर विशाखापटनम शिप-यार्ड प्रतिवर्ष कुल ५०-६० हजार टन के जहाज बना सकेगा। काचीन में एक और शिपयार्ड बनाना तथा समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण करना भी सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम में सम्मिलित है। इनका लागत व्यय क्रमशः २० करोड़ एवं ५ करोड़ बनेगा। तटीय एवं नदी-यातायात के लिए छोटे जहाज, नाव, प्रोपेलिंग मशीनरी आदि बनाने का काम प्राइवेट क्षेत्र में चलता रहेगा।

(६) औद्योगिक एवं शक्ति सम्बन्धी बायस्कर—पावर प्लांटों के लिये तथा विभिन्न उद्योगों की भाप बनाने की आवश्यकता-पूर्ति के लिये बायस्करों का उत्पादन बढ़ाने की एक योजना प्राइवेट क्षेत्र के लिये बनाई गई है। सन् १९६५-६६ में बायस्करों के उत्पादन का मूल्य २५ करोड़ ६० होने की आशा है।

(७) ओटोमोबाइल एवं सम्बन्धित उद्योग—इन उद्योगों के लिये जो विकास-लक्ष्य रखे गये हैं वे ओटोमोबाइल उद्योग की एडहूक कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप हैं। विभिन्न मदों के लक्ष्य इस प्रकार हैं पैसेंजर कारे ३०,०००, व्यापारिक बड़ी किले ६०,०००, जीप एवं स्टेजन बैगन १०,००० एवं मोटर साइकिल स्कूटर्स एवं तीन पहिये वाली टैम्पो ६०,०००, विदेशी विनिमय पर अधिक बोझ न पड़ने पावे, इसके लिये यह आवश्यक है कि देशी सामग्री का प्रयोग अब (६०%) की अपेक्षा सन् १९६५-६६ में ८५% कर दिया जाय। व्यापारिक बड़ीकिलों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(८) अन्य इंजीनियरिंग उद्योग—सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित प्रोजेक्टों को छोड़कर 'अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों' के शीर्षक के अन्तर्गत क्षमता के विस्तार का भार प्राइवेट उपक्रम पर डाला गया है—(१) प्रिंसीजन इन्स्ट्र्यूमेण्ट्स प्रोजेक्ट,

(२) प्रिंसीजन इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स फॅक्टरी लखनऊ का विस्तार, (३) रूपनरायनपुर की हिन्दुस्तान केविल्स का विस्तार, (४) बगलौर के सरकारी इलेक्ट्रिक कारखाने का विस्तार, (५) हैवी इम्प्रोवर्स एव पम्प प्रोजेक्ट, (६) बान एव रोलर विद्यारिण प्रोजेक्ट, (७) सर्जिकल इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स प्रोजेक्ट्स। भावी विकास के दृष्टिकोण से प्रिंसीजन इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स प्रोजेक्ट का विशेष महत्त्व है।

(III) केमिकल एवं सम्बन्धित उद्योग—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे बड़ा एवं सबसे महत्त्वपूर्ण विनियोग उर्वरकों के क्षेत्र में किया जायेगा। कृषि कार्यक्रम के सम्बन्ध में नाइट्रोजन उर्वरकों की माँग बहुत बढ़ गई है। माँग के बढ़ने तथा पेट्रोलियम हाथक कारखानों की आवश्यकताओं की उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर उनका निर्माण करना आवश्यक एवं सरल हो गया है। नैपथा (Naphtha) में भी आर्गेनिक केमिकल इन्स्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया है, जिन्हें अब तक अक्षकोहल पर मुख्यतः निर्भर रहना पड़ता था। आर्गेनिक हाइड्रोकार्बनों के प्राप्त होने से आर्गेनिक इन्टरमीडियेटों का उत्पादन करने के हेतु एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगया है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुछ प्रमुख उद्योगों का विकास कार्यक्रम नीचे दिया जाता है—

(अ) इनऑर्गेनिक केमिकल्स (Inorganic Chemicals)—

(१) उर्वरक (Fertilisers)—नाइट्रोजन युक्त एवं फास्फेट युक्त उर्वरकों की माँग क्रमशः १ मि० टन तथा ४,००,००० टन तक बढ़ने की आशा है। द्वितीय योजना काल के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने के अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव है कि सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के लिये अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जाय। ६,००,००० टन तक सरकारी क्षेत्र में तथा २,००,००० टन तक प्राइवेट क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है, तभी १ मि० टन का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। गुजरात व मैसूर में उर्वरक कारखानों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। दुर्गापुर में भी एक कारखाना बंगाल सरकार द्वारा प्राइवेट उपक्रम के सहयोग से खोला जायगा। मद्रास, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में भी कारखाने खुलेंगे। फास्फेट युक्त उर्वरकों के सम्बन्ध में २,००,००० टन की क्षमता का आयोजन किया जा चुका है। इसमें अधिक अभी कुछ नहीं किया जाना है। उर्वरक विकास-कार्यक्रम पर कुल-विनियोग २२५ करोड़ रु० होगा, जिसमें १०० करोड़ रु० विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी।

(२) सल्फ्यूरिक एसिड—इसके लिये १७५ मि० टन का लक्ष्य रखा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन उर्वरक-उत्पादन के साथ-साथ बढ़ेगा। यह आशा की जाती है कि सन् १९६५-६६ तक सल्फ्यूरिक एसिड की माँग सार्वजनिक क्षेत्र में अथ (१,५०,००० टन) की अपेक्षा ५,५०,००० टन हो जायेगी। सल्फ्यूरिक एसिड

का प्रयोग उर्वरको, स्पात कारखानो, रेयन, सल्फेट, पेट्रोलियम शोधन व अन्य विविध उद्योगो मे किया जाता है। अब तक सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन सलफर के आधार पर होता था, लेकिन तृतीय पंच-वर्षीय योजना मे पिराइट्स (Pyrites) व स्मैल्टर गैसों की सहायता से भी उत्पादन किया जावेगा।

(३) सलफर (Sulphur)—यह अनुमान लगाया गया है कि सलफर का उपभोग सन् १९६०-६१ मे १,७५,००० टन से बढ़ कर सन् १९६५-६६ मे लगभग ६,००,००० टन हो जायेगा। विदेशो मे सलफर की पूर्ति के नये श्रोतो का विकास होने से इस आधारभूत औद्योगिक कच्चे माल की आयात-कीमत मे कोई विशेष वृद्धि होने की संभावना नहीं है। फिर भी इसका कोई देशी श्रोत होना भी आवश्यक है। अतः योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र मे Pyrites से सलफर बनाने का एक प्रोजेक्ट सम्मिलित किया गया है।

(४) कास्टिक सोडा एवं सोडाएश—यह लक्ष्य रखा गया है कि सन् १९६५-६६ तक इन वस्तुओं की सम्पूर्ण भाग देशी उद्योगो द्वारा ही पूरी होने लगे। इस लक्ष्य की पूर्ति का अधिकतर भार प्राइवेट उपक्रम को सौंपा गया है। सरकारी क्षेत्र मे तो दो ही विकास कार्यक्रम रखे गये हैं।

(ब) आर्गेनिक कॅमीकल्स (Organic Chemicals)—

लगभग सर्वप्रथम आर्गेनिक कॅमीकल्स के क्षेत्र मे बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रम बनाये गये हैं। पिछले दशाब्द मे सम्बन्धित कॅमीकल इन्डस्ट्रीज मे जो उन्नति हुई है उसके फलस्वरूप उक्त भंदो की भाग कई गुना बढ़ गई है। नीचे तीन प्रमुख भंदो से सम्बन्धित अस्थायी लक्ष्य दिये गये हैं:—

Phthalic anhydride	15,000 टन
Phenol	15,000 टन
Methanol	40,000 टन

(IV) पेट्रोलियम का शोधन (Petroleum Refining)—

शोधित पेट्रोलियम वस्तुओं के क्षेत्र मे प्रायः सम्पूर्ण विकास सार्वजनिक क्षेत्र मे ही किया जायेगा। बरौनी और नूनमटी मे बन रहे शोधक कारखानो (Refineries) को पूर्ण करने के अतिरिक्त गुजरात मे भी एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव है, जिसकी क्षमता २ मि० टन के लगभग होगी। इस कारखाने के लिये विदेशी आर्थिक एवं टेक्नीकल सहायता का आश्वासन मिल चुका है। यह ३५ मि० टन कच्चा तेल शोधित कर सकेगा। अन्य देशो की भांति भारत को गैसोलीन के अभाव का सामना करना पड़ेगा। अभी तक मोटर स्प्रीट की अतिरिक्त पैदावार निर्यात कर दी जाती थी लेकिन पड़ोसी देशो मे भी शोधक कारखाने खुल जाने से निर्यात मे कठिनाई अनुभव की जायेगी। असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिये निम्न उपाय करने होंगे:—

(१) टेक्नोलॉजिकल उपाय, जिनमे middle distillates का उत्पादन बढ़ जाय;

(२) उपयुक्त प्राशुत्विक उपाय जो कि हाई स्पीड के डीजल तेल का उपभोग बढ़ने में रोकेंगे, (३) मिश्रित ईंधनों का प्रयोग प्राप्ताहित करना जिसमें H. S. D. के लिये मांग कम हो कर गेमालिन की बिक्री बढ़ जाय तथा (४) मोटर स्पिट के उत्पादन में कमी करने के लिये नैप्या का प्रयोग मोटर स्पिट में न करने अन्य उत्पादक प्रयोगों में बढ़ाया जाय ।

(५) द्रव आदि (Pharmaceuticals and Drugs)—

द्वितीय योजना में आवश्यक दवाइयों के उत्पादन में विविधीकरण लाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया गया था । 'हेन्दुस्थान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्माण तथा बम्बई की दो फर्मों द्वारा विटामिन ए का निर्माण इसका उदाहरण है । अब इस क्षेत्र में नवीन विकासों का लक्ष्य आवश्यक दवाइयाँ देशी बच्चे माल के प्रयोग से बना कर यथामभव उचित मूल्य पर उपलब्ध करना है । इस कार्य के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में २७ ३ करोड़ रु० रखे गये हैं ।

(VI) प्लास्टिक (Plastics)—

प्लास्टिक के सामान के लिये ८५,००० टन का लक्ष्य रखा गया है । आवश्यकता पड़ने पर इस लक्ष्य को संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि कुछ प्लास्टिक सामग्री रबर व थमड जैसी न्यून पूर्ति वाली सामग्री का अच्छा स्थानापन्न है ।

(VII) सौफ्ट कोक (Soft coke)—

मेवली में प्रति वर्ष ३,८०,००० टन की दर से लिगनाइट से सौफ्ट कोक का निर्माण किया जा रहा है । जंगलों के काटे जाने को कम करने के लिये इस प्रकार के कोयले का उत्पादन बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है । इस हेतु नीचे तालिका वाले कार्बोनाईजेशन प्लांटों की स्थापना करने का प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया है ।

(VIII) सीमेन्ट—

सीमेन्ट के लिये सन् १९६५-६६ तक उत्पादन क्षमता को १५ मि० टन तक बढ़ा देने का लक्ष्य रखा गया है । यह लक्ष्य वर्तमान उत्पादन क्षमता पर ५०% वृद्धि का सूचक है । यदि निर्माण कार्यों पर नियन्त्रण ढीला किया गया, तो सीमेन्ट की माँग बढ़ने की सम्भावना है । सीमेन्ट उद्योग की आवश्यकतानुसार चूने के पत्थर का उत्पादन बढ़ाने में जो कठिनाइयाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुये स्टील कारखानों के स्लैग पदार्थ के प्रयोग पर अधिक ध्यान देना चाहिये । द्वितीय योजना में इस बात की उपेक्षा कर दी गई थी ।

(IX) ग्लास एवं ग्लास का सामान—

इस उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण विकास है आप्टीकल ग्लास (Optical glass) का निर्माण होना । यह ग्लास इन्स्ट्रुमेन्ट्स इन्डस्ट्री के लिये बहुत महत्व का है । इसका निर्माण तृतीय पंच-वर्षीय योजना में आरम्भ हो जायेगा तथा काउन्सिल ऑफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च की सैन्ड्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक संस्था द्वारा

इसमें टैकनीकल सहायता दी जावेगी। Ophthalmic glass का निर्माण दुर्गापुर में रूस के सहयोग से किया जावेगा।

(X) कच्ची फिल्म (Raw films)—

इस क्षेत्र में एव महत्वपूर्ण प्लान्ट स्थापित होने वाला है, जो भरवारी प्रोजेक्ट में मद्रास राज्य में उटकमड के निकट कच्ची फिल्म, एक्सरे फिल्म आदि का निर्माण करेगा। इसे फ्रांस की एक प्रसिद्ध फर्म M/s. Bauchet et Cie में टेक्नीकल सहयोग प्राप्त होगा।

उपभोक्ता सामान वाले उद्योग

संगठित उद्योगों में प्रत्यक्ष विनियोग के दृष्टिकोण से सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योगों का विकास कार्यक्रम कम महत्व रखता है। दवाइयों का निर्माण ही इसका एक मात्र अपवाद है। घड़ियों और कैमरों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र में जापान के टैक्नीकल सहयोग से किया जायेगा। कैमरों के निर्माण में कलकत्ते की नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी भी सहयोग देगी। सहकारी संस्थाओं को उपभोक्ता सामान वाले उद्योगों की स्थापना करने में विशेष सुविधाये दी जावेंगी। प्रमुख उपभोक्ता सामान वाले उद्योगों का विकास क्रम निम्न प्रकार है :—

(१) सूती वस्त्र (Cotton Textiles)—यह अनुमान लगाया गया है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति पर ८,४५० मि० गज कपड़ा आन्तरिक उपभोग के लिये और ८५० मि० गज कपड़ा निर्यात के लिये आवश्यक होगा। सन् १९६०-६१ में कपड़े की आन्तरिक मांग ७,००० मि० गज कूती गई थी, जबकि उस वर्ष उपभोग के लिये केवल ६,७५० मि० गज कपड़ा ही उपलब्ध था। संभवतः पूर्ति में इतनी कमी १९५९-६० में फसल के खराब होने से कच्ची कपास की कमी के कारण रही थी। अतः आन्तरिक उपभोग के लिये सूती वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य कुछ अधिक नहीं है। निर्यात का लक्ष्य भी उस औसत स्तर से विशेष अधिक नहीं है जो कि पिछले वर्षों में प्रचलित था। ६,२०० मि० गज सूती वस्त्र के कुल लक्ष्य का ३,५०० मि० गज हाथ करपा, शक्ति करपा व खादी उद्योग के सुपुर्द किया गया है, जबकि मिल उद्योग को ५,८०० मि० गज कपड़े के उत्पादन का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान स्तर से ८०० मि० गज अधिक कपड़ा बनाने के लिये मिलों में २५,००० ओटोमैटिक करघे तृतीय योजनावधि में लगाये जायेंगे। ६,३०० मि० गज कपड़े के उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति के लिये व अन्य कामों में प्रयोग के लिये भी सूत का उत्पादन लक्ष्य २,२५० मि० पौंड रखा गया है।

(२) रेयन (Rayon)—रेयन उद्योग के कार्यक्रम में क्षमता को द्वितीय योजना की समाप्ति पर २१५ मि० पौंड से बढ़ा कर तृतीय योजना के अन्त तक १०० मि० पौंड करना निश्चित किया गया है। इस उद्योग में विनियोग को कई अवस्थाओं में इस प्रकार फैलाया गया है कि विदेशी विनिमय की कठिनाई प्रस्तुत न होने पावे।

(३) पेपर एव न्यूजप्रिन्ट—इस उद्योग के विकास कार्यक्रम का लक्ष्य आत्म निर्भरता प्राप्त करना है। सन् १९६५-६६ तक अनुमानित मांग ७ ००,००० टन होने की आशा है, जिसे पूरा करने के लिये उद्योग की वर्तमान क्षमता (४,१०,००० टन) को बढ़ा कर ८,२०,००० टन करने का प्रस्ताव है। अनिश्चित क्षमता की प्राप्ति के लिये तीसरी योजनावर्ष में छोटे-छोटे नागज मिल स्थापित किये जायेंगे, जो कि स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करेंगे। होशंगाबाद में १ ५०० टन की वार्षिक क्षमता का एक दस्तावेजी कागज बनाने वाला मिल स्थापित किया जायगा। आजकल इस प्रकार का कागज विदेशों से मगाने में काफी विदेशी विनिमय व्यय करना पड़ता है। न्यूजप्रिन्ट की दशा में वर्तमान उत्पादन क्षमता (३०,००० टन) को ५ गुना बढ़ाया जायेगा। इसके लिये नेपा मिल का विस्तार करना होगा। कुछ नये मिल भी मुलायम लकड़ी, (जो कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है) का प्रयोग करके कागज बनाने के हेतु स्थापित किये जायेंगे। चीनी मिलों में गन्ने के प्रयोग से बचने वाले अवशिष्ट पदार्थ का प्रयोग करके भी कागज बनाने पर बल दिया जायेगा। आजकल यह पदार्थ शक्कर मिलों में ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है।

(४) चीनी (Sugar)—तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही देश चीनी के मामले में आत्म निर्भर हो गया है। चीनी मिल उद्योग की अधिक उन्नति करने के लिये उपलब्ध गन्ने की पूर्ति को बढ़ाना होगा। प्रस्तुत योजना में गन्ने का उत्पादन बढ़ा कर १०० मि० टन कर देने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति एकड़ पैदावार को सुधार कर प्राप्त की जायेगी। अन्य प्रयोगों में काम आने वाले गन्ने को निकाल कर चीनी उत्पादन के लिये २५ मि० टन गन्ना बचता है। इतनी मात्रा में गन्ना पेशने की सुविधा को बढ़ाने के लिये क्षमता को ३ ५ मि० टन प्रति वर्ष तक बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का सहयोग २५% तक बढ़ जायेगा। सरकार ने सहकारी चीनी कारखानों की श्रेयर पूँजी में भाग लेने के हेतु ६ करोड़ रु० का आयोजन किया है। घरेलू उपभोग से बचने वाली शक्कर निर्यात कर दी जायेगी।

(५) वनस्पति तेल (Vegetable Oils)—वनस्पति तेलों की दशा में अब अधिक विकास पांच प्रमुख तिलहनो के कृषि कार्यक्रमों पर निर्भर है। इन तिलहनो का उत्पादन सन् १९६०-६१ में ७ १ मि० टन से बढ़ा कर सन् १९६५-६६ तक ६० मि० टन कर दिया जायेगा। यह अनुभव किया जाता है कि आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् निर्यात के लिये खाने के काम में आने वाले तेल अधिक मात्रा में बचेंगे। अतः वनस्पति तेलों की पूर्ति बढ़ाने के लिये निम्न प्रस्ताव रखे गये हैं (1) कपास के बीज के तेल का उत्पादन १ लाख टन प्रति वर्ष तक बढ़ाना, (11) खली से निकलने वाले तेल की वर्तमान मात्रा (४०,००० टन) को बढ़ा कर १,६०,००० टन प्रति वर्ष करना, तथा (111) चावल से तेल का उत्पादन बढ़ाना। कपास के बीज से तेल का

उत्पादन बढ़ा कर मूगफली के तेल पर जोर कम दिया जायेगा तथा खली के अतिरिक्त तेल-उत्पादन का प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक कार्यों के लिये होगा ।

औद्योगिक विकास से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ—

सीसरी पञ्च-वर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के जिस उच्च स्तर की कल्पना की गई है वह सार्वजनिक एवं प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों के लिये, अपनी विविधमुखी समस्याओं के कारण एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है । प्रसाधन एवं विदेशी निनिमय की समस्याएँ ही नहीं वरन् अन्य कई समस्याएँ भी उद्योगों को अपने पिछले अनुभव से सुलभाती हैं । नीचे कुछ प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है—

(१) डिजाइन डेवेलपमेन्ट एवं प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की समस्याएँ—मशीन बिल्डिंग क्रियाओं तथा मशीन निर्माण के लिये डिजाइन के विकास एवं प्रोजेक्टों के इंजीनियरिंग की विषय समस्या है । प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (N I D C) ने जिम्मेदारी ग्रहण कर ली है । उसने सन् १९६०-६१ में एक टेक्नोलॉजिकल परामर्शदाता ब्यूरो स्थापित किया है, जिसके निम्न कार्य होंगे—उद्योगों के स्थापना-स्थलों का प्रारम्भिक अध्ययन, जाँच पड़ताल एवं चुनाव; प्रोजेक्ट से सम्बन्धित विस्तृत रिपोर्टें (detailed project reports) की तैयारी तथा रचना सम्बन्धी डिजाइन बनाना (designing of structures) । डिजाइन-विकास के सम्बन्ध में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि देशी डिजाइनों के आधार पर औद्योगिक मशीनरी निकट भविष्य में तैयार की जाने लगे, यद्यपि प्रारम्भ में आयातित डिजाइनों पर निर्भर रहा जा सकता है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये बगलौर में एक केन्द्रीय डिजाइन इन्स्टीट्यूट स्थापित किया जायेगा ।

(२) उत्पादकता घटाने तथा लागत घटाने की समस्याएँ—चूँकि औद्योगिक क्षेत्र को निर्यात वृद्धि में बहुत योग देना है, इसलिये यह आवश्यक है कि न केवल उत्पादन का विस्तार करने पर वरन् उत्पादकता बढ़ाने वाले तथा लागत व्यय कम करने वाले सभी घटकों पर ध्यान दिया जाय । जहाँ तक उत्पादन-लागतों का सम्बन्ध है, ऊँची लागत होने के कारणों को कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है, यदि स्थापित होने वाले प्लान्टों का साइज 'अनुकूलतम' रखा जाय तथा व्यय पदार्थों व सह-पदार्थों के आर्थिक प्रयोग का प्रयत्न किया जाय । इसी प्रकार यदि लगाई हुई क्षमता (Installed Capacity) का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगे, तो उपरिच्यवों (Overhead) में काफी भ्रितव्ययिता हो सकती है । इन पहलुओं पर विकास परिषदों को विचार करना चाहिये ।

(३) पर्याप्त जल की पूर्ति एवं खराब पानी की निकासी की समस्याएँ—अनेक हैवी इन्डस्ट्रीज़ (जैसे स्टील प्लान्ट, पेट्रोलियम शोधक कारखाने) के विकास के लिये उत्पादन कार्य में बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी । जिन विशेषज्ञ

समितियों को उद्योगों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान के चुनाव का कार्य सौंपा गया था, उनकी रिपोर्टों में जल की उपलब्धता पर काफी जोर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि कुछ स्थानों में जहाँ कि अन्य सब सुविधायें उपलब्ध थीं, उद्योगों की स्थापना का सुभाव केवल इस कारण रद्द करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न था। इन स्थानों में जल पूर्ति के दीर्घकालीन नियोजन बिना उनका औद्योगीकरण सदा खतरे में रहेगा। इसके अतिरिक्त, कौमीकल एवं सम्बन्धित उद्योगों के खराब पानी की निचामी की समस्या भी बड़ी विषट है। नदियों में यह पानी छोड़ा जाने से नदी का जल खराब हो जाने का भय है। यह जन स्वास्थ्य के लिये पुष्कलान्-देह प्रमाणित हो सकता है।

सन् १९६५-६६ में योजना की समाप्ति पर औद्योगिक विकास के लाभ—

तीसरी पंच-वर्षीय योजना की पूर्ति पर औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष लाभ होने की आशा की जाती है—(१) सावजनिक क्षेत्र के विनियोग एवं उत्पादन की तेज वृद्धि से हम अपने समाजवादी उद्देश्य के लक्ष्य की पूर्ति में बड़ी सहायता मिलेगी, (२) अर्थ व्यवस्था के कुछ अत्यावश्यक अंगों (जैसे कृषि, बिजली, रेलें, मोटर वाहनादि) की निर्भरता विदेशों में साज सामान व आयात पर कम हो जायेगी, (३) औद्योगिक क्षेत्र में भी हवी इन्जीनियरिंग एवं मशीन-बिल्डिंग का विकास होने से, उद्योगों के लिए आवश्यक पूँजीगत साज सामान काफी मात्रा में देश के प्रन्दर ही तैयार होने लयेगा। (४) वसिक्त कच्चे मालों का उत्पादन देश में ही होने लगने में कई महत्वपूर्ण उद्योगों के रख रखाव (Maintenance) के लिये आवश्यक आयातों में कमी हो जायेगी। इस प्रकार, तृतीय पंच-वर्षीय योजना के कार्यक्रम पूरे होने पर देश की अर्थ व्यवस्था बहुत सीमा तक आत्म निर्भर हो जायेगी। औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक, जो कि प्रगति का परम्परागत सूचक है, ३२६ तक पहुँच जायेगा (आधार वर्ष १९५०-५१ = १००) जबकि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति पर वह १९४ और प्रथम पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति पर १३६ था।

STANDARD QUESTIONS

1. Describe the aim, policy and priorities of the Industrial development under the Third Five Year Plan. Examine its financial implications.
2. What are the special features of the industrial programmes as envisaged by the Third Plan? Give only brief description under different heads.
3. Point out the difficulties and problems which have to be faced in course of Industrial development as outlined in the New Plan.

APPENDIX

PUBLIC SECTOR PROJECTS

UNDER THIRD PLAN

(I) Industrial projects of Central Government

name of the scheme	location	total investment (Rs crores)	foreign exchange component (Rs crores)	capacity in 1965-66 (final capacity in the case of expansion)
A projects under execution and carried over from the Second Plan (a)				
1 completion of the three steel plants	Rourkela Bhilai Durgapur Rourkela	50.0	20.0	3 million tons of steel ingots and 700,000 tons of pig iron for sale
2 Rourkela fertiliser factory	Rourkela			120,000 tons of nitrogen
3 heavy machinery plant	Ranchi	80.0	55.0	45,000 tons of finished machinery
4 foundry forge shop	Ranchi			94,000 tons of castings and forgings
5 mining machinery plant	Durgapur	16.0	7.0	30,000 tons of mining machinery
6 heavy electrical plant	Bhopal			Rs 12.5 crores worth of electrical equipment

name of the scheme location total foreign investment exchange capacity in 1965-66 (final) (Rs crores) component capacity in the case of expansion (Rs crores)

1 drug projects				
(a) synthetic drugs plant	Sanatnagar (Andhra Pradesh)			Rs 6.4 crores worth of drugs
(b) antibiotics plant	Rashikesh (Uttar Pradesh)			Rs 25.8 crores worth of antibiotics
(c) phytochemicals plant	Munnar (Kerala)	30.0	15.0	Rs 77 lakhs worth of phytochemicals
(d) surgical instruments plant	Gundy Madras			Rs 2.4 crores worth of instruments
8 organic intermediates plant	Near Panvel (Maharashtra)	11.0	6.0	25,000 tons of organic intermediates
9 expansion of Hindustan antibiotics	Pimpri (Maharashtra)	0.5	neg	45,000 kg. of streptomycin & 1.5 tons of tetracyclines
10 Trombay fertiliser factory	Trombay (Maharashtra)	25.0	13.0	90,000 tons of nitrogen
11 Nahorkatiya Fertiliser factory	Nahorkatiya (Assam)	12.0	7.0	32,500 tons of nitrogen
12 Neiveli fertiliser factory	Neiveli Madras	15.68	11.56	70,000 tons of nitrogen
13 briquetting and carbonisation plant		13.84	8.61	380,000 tons of carbonized briquettes
14 Neiveli thermal power plant	Nunmati (Assam) Barauni (Bihar)	9.67	5.86	250 MW
15 Nunmati oil refinery		8.5	4.9	0.75 million tons of crude oil
16 Barauni oil refinery		23.0	7.5	2.0 million tons of crude oil
		295.19	161.4	

B new projects for which external credits are already assured, wholly or partly

17 expansion of heavy machinery plant Ranchi	140	11 0	80 000 tons of finished machinery
18 expansion of foundry forge Ranchi	100	5 5	153,000 tons of castings and forgings
19 expansion of mining machinery plant Durgapur	150	10 0	45 000 tons of mining machinery
20 second and third heavy electrical projects not yet decided	69 0	45 0	scope yet to be finally decided in the case of the third project
21 heavy machine tool project Ranchi	11 0	9 0	Rs 3 4 crores worth of machine tools
22 precision instruments project not yet decided	8 0	6 0	Rs 20 crores worth of instruments
23 ophthalmic glass project Durgapur	2 6	2 0	300 tons of ophthalmic glass
24 raw film project Ootacamund	8 0	5 0	6 3 million sq meters of raw films, photographic paper etc
25 watch factory Bangalore	2 5	1 5	360,000 watches
26 expansion of Bhilai steel plant Bhilai	138 0	56 0	2 5 million tons of steel ingots and 300 000 tons of pig iron for sale
27 expansion of Durgapur steel plant Durgapur	56 0	27 0	1 6 million tons of steel ingots and 300 000 tons of pig iron for sale
28 expansion of Rourkela steel plant Rourkela	90 0	50 0	1 8 million tons of steel ingots
29 expansion of Hindustan Machine Tools Bangalore	3 0	2 0	Rs 7 crores worth of machine tools
30 basic refractories project Bhilai	3 0	1 5	Scope yet to be decided
31 new machine tool works in Punjab	5 0	3 0	1000 machine tools (Rs 3 5 crores)
32 Gujarat oil refinery	30 0	15 0	2, million tons of crude oil
33 expansion of Praga Tools Secunderabad (Andhra Pradesh)	1 0	0 5	Rs 1 crore worth of machine tools

Name of the scheme	Location	total investment (Rs crores)	foreign exchange component (Rs crores)	capacity in 1965-66 (final capacity in the case of expansion)
34 heavy structural works	not yet decided	60	@ 40	10,000 tons of heavy structurals on single shift basis
35 heavy plate and vessel work	not yet decided	180	80	80,000 tons of chemical plant machinery on single shift basis
36 Gorakhpur fertiliser factory	Gorakhpur	55	40	1,500 tons of security paper
37 Security paper mill	Hoshangabad (Madhya Pradesh)	35	12	2,000 miles of dry core cables and 500 miles of plastic insulated city cables on double shift basis
38 expansion of Hindustan Cables	Rupnarayanpur (West Bengal)	499.1	267.2	
39 Bokaro steel project	Bokaro	200.0	100.0	one million tons of steel ingots and 350,000 tons of pig iron for sale
40 alloy and tool steels plant	Durgapur	50.0	20.0	48,000 tons of finished products
41 expansion of Bhopal heavy electrical plant	Bhopal	19.0	8.0	Rs 25 crores worth of electrical equipment

According to the latest estimates these projects will cost Rs 10.1 crores and will need foreign exchange expenditure of Rs 6.4 crores

42	expansion of Hindustan Shipyard (expansion and subsidy)	Visakhapatnam	100	15
43	dry dock project of the Hindustan Shipyard.	Visakhapatnam	20	05
44	second shipyard	Cochin	200	50
45	expansion of FACT	Alwaye (Kerala)	80	56
46	expansion of Nepa mills	Nepanagar (Madhya Pradesh)	40	30
47	salt development		30	08
48	heavy compressors & pumps project	not yet decided	150	100
49	ball and roller bearing project	not yet decided	80	60
50	additional capacity for machine tools	not yet decided	150	100
51	second heavy structural works			scope yet to be decided
52	second plate & vessel works	not yet decided	30	15
53	marine diesel engine factory			
54	expansion and modernisation of the Govt alkalioid factory	Ghaziipur (Uttar Pradesh)	0.4	neg
55	lubricating oil plant		120	60
56	low temperature carbonisation plants		220	151
57	Neyveli lignite high temperature carbonisation plant and connected facilities for pig iron production	Neyveli (Madras)	250	130
58	townships	at project sites	500	1 million tons of lignite
			466.4	205.9
			1260.69	634.5
		total		

(II) Industrial projects of State Governments

name of the scheme	location	total investment (Rs crores)	foreign exchange component (Rs crores)	annual capacity in 1965-66 (final capacity in the case of expansion)
Schemes with a total outlay of Rs. 50 lakhs or more				
A projects spilling over from the Second Plan (1)				
1 expansion of Andhra Paper Mills Rajamundry (Andhra Pradesh)		4 00	2 49	18 000 tons of paper
2 expansion of Mysore Iron and Steel Works Bhadravali (Mysore)				
(a) steel expansion programme		2 00*	3 50	100 000 tons of steel in 1965-66
(b) expansion of the ferro silicon plant		0 95	0 37	20 000 tons of ferro silicon
3 expansion of Government electric Bangalore (Mysore) factory		0 90	0 48	electric transformers 200 000 KVA electric motors 60 000 h.p. switchgear and switch boards worth Rs. 40 lakhs
4 Durgapur coke ovens	Durgapur (West Bengal)	2 25	7 5	million cft of gas per day
(a) gas grid		0 50	0 17	100 tons of tar per day
(b) tar distillation plant				coke 650 000 tons
(c) doubling of coke ovens and by products plant		4 20		benzene 0 725 million gallons toluene 0 235 million gallons naphthalene : 1200 tons, and road tar

* Made up of Rs. 5 crores in the Central Plan and Rs. 2 crores in the State plan

B new projects included in the Third Plan (b)

5 natural gas distribution	(Assam)	1 65	0 30	
6 gas fractionation and transmission scheme	(Assam)	1 50	0 50	
7 expansion of Bihar superphosphate factory	Sindri (Bihar)	0 50	0 15	46 000 tons of superphosphate
8 expansion of high tension insulator factory	Ranchi (Bihar)	0 58	0 17	4 000 tons of insulators
9 fertiliser project*		20 00	10 00	80 000 tons of nitrogen
10 cotton spinning mill	Samba (Jammu and Kashmir)	0 50	0 25	12 000 spindles
11 pilot iron and steel plant	(Madras)	0 75		
12 steel rolling mill	(Madras)	1 00		20 000 tons of rolled products
13 distribution of gas in Bombay	(Bombay)	0 50		20 million c ft of gas per day
14 reorganisation of the workshop at Nangal	Nangal (Punjab)	0 50		
15 refractories plant	Chark (Uttar Pradesh)	0 85	0 30	24 000 tons of refractories
16 expansion of the precision instruments factory	Lucknow (Uttar Pradesh)	0 69	0 22	
17 organic chemicals scheme	Durgapur (West Bengal)	4 00	2 00	caustic soda 6 600 tons phenol 6 600 tons chlorine 5 500 tons

* Provisionally indicated in the state sector

Final decision about location and agency are yet to be taken
Private participation on a minority basis in the equity capital of the project is envisaged

(III) Industrial projects of

200

name of the scheme	location	total investment (Rs crores)	foreign exchange component (Rs crores)	annual capacity in 1965-66 (final capacity in the case of expansion)
18 cotton spinning mill miscellaneous schemes costing less than Rs 50 lakhs each	(West Bengal)	0.65	0.09	phthalic anhydride 6 600 tons formaldehyde 5000 tons pentachlorophenol 1000 tons
grand total		15.61	4.00	
		64.08	24.98	

PROJECTS UNDER THIRD PLAN

PRIVATE SECTOR PROJECTS

name of industry	unit	1950-51		1955-56		1960-61		1965-66		fixed investment during 1961-66 of fixed investment (Rs. crores)	foreign exchange component
		production	production	production	production	production	production				
A metallurgical industries											
iron and steel	million tons	1.4	1.7	6.0	3.5	10.2	9.2	6.8	1.5	640.0	305.0
(i) steel ingots	"	0.98	1.3	4.5	2.2	7.5					
(ii) finished steel	"	0.35	0.38	0.9	0.9	1.5					
(iii) pig iron for sale	"			4.0	4.0	2.00	2.00				
(iv) alloy tool and special steel (finished)	000 tons			n.i.	n.d.	1.2	1.2				
(v) grey iron castings	million tons			0.10	0.05	0.20	0.20			30.0 (a)	15.0 (a)
(vi) steel castings	"			6.0	3.5	2.00	2.00				
(vii) steel forging	000 tons										
chromium manganese, ferro thermal	"	nil	nil	15.0	10.0	22.0	20.0			2.5	2.0
ferro silicon	"	n.i.	n.i.	5	6	4.0	4.0			2.0	1.2
aluminium	"	3.7	7.3	18.2	18.5	87.5	80.0			65.0	32.0
copper (fire refined and electrolytic)	"	6.6	7.5	9.0	8.9	22.0	20.0			0.6 (b)	0.4 (b)

(II) Industrial projects o

rimenta

22
21

name of industry	unit	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	estimated capacity production	capacity production	fixed investment during 1961-66	foreign exchange component of fixed investment (Rs crores)
6 lead	000 tons	0.8	2.1	7.1	5.5	3.5	9.0	7.3	2.7
7 zinc	,			nil	1.5	1.1	1.5	1.5	
8 tungsten carbide	tons			5.0	6.9	4.0	7.5	1.0	0.5
B mechanical engineering industries									
9 industrial machinery (I)									
i cotton textile machinery	Rs crores	1.7	4.0	10.0	22.0	9.0	20.0	5.0	3.0
ii cement machinery			0.34 c)	1.1	4.5	0.6	4.5	3.0	2.0
iii sugar machinery			0.19	10.5	11.0 to 12.0	3.3	10.0		
iv paper machinery	Rs crores			0.7	5.5		6.5 to 7.0	7.0	4.0
v dairy machinery				0.25	2.5	Net	2.5	0.5	
vi industrial boilers				3.7	29.0	0.4	25.0	10.0(d)	5.0(d)
vii cranes	000 tons			2.5	6.0	1.5	6.0		

ix heavy machinery building (steel and chemical machinery) 000 tons	90	(c)	119 0	81.5
x coal mining machinery "	45	30		
xi heavy plate and vessel works (pressure vessels, heat exchangers & other types of chemical plants and equipment) 000 tons	40	30	20 0	12.0
10 structural fabrication (including heavy structural shop) 000 tons	1100	1000	25 0	10.0
11 precision instruments, industrial and scientific Rs crores	23	12	9 0	6 5
12 surgical instruments million pieces	25	25	27	2 0
13 watches 000 nos	360(f)	240(f)	40	5
14 railway rolling stock and components			20	1 0
1 locomotives	100	1175 (g)		
steam	na	434 (g)		
diesel	60	232 (g)		
electric				
ii wagons (in terms of 4 wheelers)	26000	20000	33500	109866 (g)
iii. passenger coaches	1300	1210	1420	7837 (g)
15 automobile and ancillary industries				
i passenger cars 000 nos	20	20	30	85.0
ii commercial vehicles	28	24	60	40 0
iii jeeps and station wagons	5 5	5 5	10	

name of industry	unit	1950 51 production	1955-56 production	1960 61 estimated capacity production	1965 66 estimated capacity production	fixed investment during component 1961 66 of fixed (Rs investment crores) (Rs crores)	
						investment	foreign exchange
14 automobile ancillaries including trailers	000 nos			0.7	na	5	2.5
15 motor cycles and scooters		1.5		2.4	18	48 to 60	50
16 ball and roller bearings	million nos	0.08	0.9	1.6	2.9	10.0	14.0(h)
17 earth moving equipment							
1 crawler tractors	nos					600	500
11 dumpers and scrapers						600	500
111 shovels						125	100
18 road rollers				800	400	300	700
19 agricultural implements and machinery				184	90	184	150
1 power driven pumps	000 nos	34	37				
11 diesel engines (stationery)		5.5	10	62	40	72	66
111 tractors				1.05	0.6	12.0	10.0
20 bicycles	million nos	0.10	0.51	2.2	1.05	2.2	2.0(h)
21 sewing machines	000 nos	33	111	268	297	700	700(h)
22 welding electrodes	million r feet			600	350	1080	900
						21.0	18.0

23 ship building (expansion of Hindustan shipyard, dry dock and second ship yard) 000 GRT 50(g) 20 20 50 to 60 70 to 60 32.0 7.0

C electrical engineering industries

24 electric transformers (below 33kv)	million kva	0.18	0.63	2.2	1.2	4.0	3.5
25 electric motors (200 h p & below)	million h p.	0.10	0.27	1.25	0.7	3.0(k)	2.5(k)
26 electric cables & wires	000 tons	1.7	8.7	28	22	55	44
27 i a c s r							
28 i i v i r and plastic coated	million yds	39.4	86.9	500	220	800	600
29 i i i paper insulated	miles			1000	750	4500	4000
30 i i v dry core cables	miles		525	470(l)	1077	2000 to 2500	2000
31 v coaxial cables	miles			300	200	300	300
32 27 electric fans	million nos.	0.19	0.29	1.8	0.98	2.8	2.5
33 23 house service meters	"		0.25(c)	0.6	0.46	2.5	2.1
34 29 electric lamps							
35 (1) G.L.S. and others	million nos	15.0	25.03	43.13(l)	38.05	76.0	68.0
36 (ii) fluorescent tubes	million nos	Nil	0.75	1.20(l)	1.46	7.0	6.0
37 30 radio receivers							
38 (organised sector)	000 nos	49.0	102.0	279.18(l)	254.0	900.0	800.0
39 31 storage batteries	000 nos	200.0	258.08	379.3(l)	509.0	900.0	800.0
40 32 dry batteries	million nos	136.3	161.1	224.50(l)	200.0	400.0	350.0

33 heavy electrical equipment in the public sector

Rs crores 800 104.0 60.0

name of industry	unit	1950 51	1955 56	1960 61	1965 66	fixed investment during component 1961 66 of fixed investment (Rs crores) (Rs crores)	foreign exchange
		production	production	estimated capacity production	capacity production		

D chemical and allied industries

34 fertilisers						225 0	100 0
i Nitrogenous (in terms of nitrogen) 000 tons	9	79	248	110	1000	500	
ii phosphatic (in terms of P_2O_5)	9	12	60	55	500	400	
35 heavy chemicals							18 0
i sulphuric acid	90	164	476	263	1750	1500	
ii soda ash	45	81	265	145	530	450	
iii caustic soda	11	35	124	100	400	240	
iv calcium carbide		3(c)	17	10	67	60	
v sodium hydro-sulphite							
vi hydrogen peroxide			23	0.6	12	10	
36 miscellaneous chemicals products			3	1.2	9.5	8	
i carbon black					30	30	15 0
ii industrial explosives - (a) blasting explosives			5	6	20	20	5 0

(b) liquid oxygen explosives	2	2	9	9
(c) safety fuses	7	2	250	250
(d) detonators			80	80
iii rubber chemicals	2	na	3	3
37 coke				
i soft coke (low tem			20	18
perature carbonisation)			1160	1100
ii hard coke by product	620	500		420
38 dyestuffs & organic intermediates				292
i dyestuffs	40	115	224	280
ii intermediates			25000	180
39 drug and pharma ceuticals				25000
i sulpho drugs	330	150	1000	393
ii penicillin	45	40	205	120
iii streptomycin			150	150
iv penicillin	145	100	400	400
v anti dysentery drugs				
vi anti dysentery	60(c)	30	75	75
vii phytochemicals	10(c)	30	100	100
viii ddt	284	2800	764	764
40 plastics (polyethy lene p v c, polys tyrene and others)	07	100	850	740
41 i soap (2)	102	150	254	500
ii synthetic detergents	72	15	200	200
				105

name of industry	unit	1950 51		1955 56		1960 61		1965 66		fixed investment during component 1961 66 of fixed (Rs investment crores) (Rs crores)
		production		production		estimated capacity production		capacity production		

42 raw films cinematographic etc	million sq metres							100	100	90	55	
43 rubber manufactures								37	30	115	50	
i automobile tyres	million nos	0.9	1.61			1.35						
ii bicycle tyres	million nos	5.8	16.9			11.0		38.6	31.0			
44 synthetic rubber	000 tons							50	50	250	125	
45 i paper and paper board	000 tons	114						820	700	1000	350	
ii newsprint	000 tons			187	410	350		150	120			
iii security paper	000 tons			4.2	30	25		1500	1500	55	40	
46 cement	million tons	2.7	9.0	4.6		8.5		150	130	600	120	
47 refractories	million tons		0.87	0.28		0.52		20	16	220	100	
48 electric porcelain (h t & l t insulators)	000 tons			4.3	12.5	8.4		30	24	30	22	
49 glass & glassware (including ophthalmic glass)	000 tons	92.0		125	370	225		615	440	110	35	
50 i petroleum products	million tons			3.6	6.02	5.67		10.77	9.86			
ii lubricating oils	000 tons						(crude oil)	100	100	73.5	33.4	
51 power and industrial alcohol	million gallons	8.6		15.2	40	22		72	60	40	0.4	
52 industrial gases	million cft							2300	1650	110	65	
i oxygen					1000	700						

cellulose	million cft	156	90	250	200	325	110
B textile industries							
cotton	million lb	1640	2100	2250	2250		
yarn	million yds	5102	5300	5800	5800		
cloth (mill made)	million yds	1150	1200	1200	1100		
textile	000 tons					150	450
linen and staple fibre	million lb	160	523	1400	1400		
linen filament	million lb	140	480	750	750		
staple fibre	million lb			1000	900		
chemical pulp	000 tons					20	10
woollen manufactures							
woollen and worsted	million lb	217	67	67	52		
yarn	million yds	150	48	48	35		
woollen cloth	million lb		10	315	315		
wool tops							
F food industries							
salt	million tons	30	39	65	54	90	20
sugar (3)	million tons	186	225	35	35	1000	120
vegetable oils							
solvent extraction	000 tons		550	2000	160		
oil cakes			(cake)	(oil)	(oil)		
			180(m)	850	100	100	25
cotton seed oil	000 tons		(seed,)	(seed)	(oil)		
			434	550	500		
rapeseed	000 tons	276			160(m)		430
cellulosic industries							
total				24546		11099	

Capacity for engineering industries is estimated on the basis of double shift operation (1) Except in the case of cotton textile machinery, capacity and production under this head are related to the demands for original equipment

(2) Excepting for the production figure in 1965-66 the figures relate to the organised sector only

(3) Figures relate to crop year

(a) Over and above the expenditure envisaged under Foundry/Forge (included under item 9 (ix) in the table) Mining Machinery Project and steel castings foundry of Chittaranjan Locomotive Works

(b) Investment on the capacity under the public sector is shown under the outlay on Minerals

(c) Relates to calendar year

(d) Expenditure envisaged on private sector schemes only Expenditure envisaged in the public sector are included under items (10) and (33) in the table

(e) Actual production will be linked by and large with the programme for expansion of steel capacity.

(f) Relates to the public sector only

(g) Relates to five year period

(h) By working the capacity on three shifts

(i) An additional 0.5 million bicycles are expected to be produced in the small scale sector

(j) An additional 150000 sewing machines are expected to be produced in the small scale sector

(k) These figures are for 300 h p and below

(l) Single shift capacity

(m) Figures relate to organised sector only

(n) Including Rs. 50 crores for townships and Rs. 470 crores for other public sector projects not covered under above industries

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत सरकार की औद्योगिक नीति

(India's Industrial Policy Prior To Independence)

पराधीन-भारत की औद्योगिक नीति—

ब्रिटिश शासन-काल में देश के औद्योगिक विकास के लिये कभी भी कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जमाने में उन भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया, जिन पर इसका नियति व्यापार निर्भर करता था, किन्तु कुछ दिनों बाद वह इंग्लैंड के निर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने का एक साधन समझा जाने लगा।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की समाप्ति के बाद यद्यपि भारत का शासन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था, तो भी हमारे देश के प्रति ब्रिटिश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह स्वतन्त्र व्यापार (*Laissez Faire*) का युग था और भारत को भी इस नीति का अनुकरण करना पड़ा। उस समय उद्योगों के विकास के लिए नियम बनाना विनाशकारी और उसकी सहायता करना व्यर्थ समझा जाता था। इस प्रकार गत १०० वर्षों में स्वतन्त्र व्यापार नीति का ही बोलबाला रहा। कभी-कभी सरकार ने देश के औद्योगिक विकास के प्रति अपनी सहानुभूति अवश्य दिखाई लेकिन इंग्लैंड के अधिकारियों ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि सरकार ऐसी कार्यवाहियों से दूर रहे।

प्रथम विश्व-युद्ध (सन् १९१४-१८) के छिड़ने से इस नीति में थोड़ा परिवर्तन हुआ। कच्चे माल के लिए योरोपीय बाजार बन्द हो गया। युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी प्रकार उत्पादन बढ़ाना आवश्यक समझा गया। परिणामस्वरूप, सरकार को स्वतन्त्र व्यापार की नीति छोड़नी पड़ी और इसका स्थान राजकीय प्रोत्साहन ने ले लिया। सर्वप्रथम सन् १९१६ में भारतीय औद्योगिक कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने देश में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं की जाँच की और उद्योगों को राजकीय सहायता देने की सिफारिश की। उन उद्योगों में भी, विशेषकर रासायनिक, विद्युत और यान्त्रिक-उपकरण उद्योग की सहायता पर विशेष जोर दिया। सन् १९१७ में भारतीय प्रसाधनों पर नियन्त्रण करने एवं उनको दिवसित करने के उद्देश्य से इण्डियन म्युनीशन्स

बोर्ड नियुक्त किया गया, किन्तु इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि जो भी उद्योग युद्धकाल में आरम्भ किये गये थे, वे विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का सामना न कर सके और अन्त में नष्ट हो गये।

सन् १९१६ में भारतीय मन्त्रिधान में जो मसौदा प्रेषित किया गया, उसने अनुसार उद्योग एक प्रांतीय विषय बन गया और प्रांतीय सरकारों को औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को सहायता देने का अधिकार मिला गया। प्रांतीय सरकारों ने इस दिशा में जो सक्रिय प्रयत्न किए उनका मशिक्षित स्वरूप इस प्रकार है —

(१) उद्योगों की राजकीय सहायता—सन् १९२२ में मद्रास सरकार ने उद्योग राजकीय सहायता अधिनियम (State Aid to Industries Act) पास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कुटीर तथा अन्य उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इसके बाद क्रमशः इस विधान बिहार में सन् १९२३ में, बंगाल में सन् १९३१ में, मध्य प्रान्त में सन् १९३४ में, पंजाब और संयुक्त-प्रान्त में सन् १९४३ में पास किये गये किन्तु इन प्रयत्नों का कोई आशाजनक परिणाम नहीं हुआ। वरन् उद्योगों को अवश्य थोड़ा लाभ मिला, किन्तु कुटीर एवं लघु उद्योगों को इन सुविधाओं का पाना अत्यन्त कठिन हुआ।

(२) औद्योगिक शिक्षा—सन् १९२६ में बनारस का भारतीय खनिज विद्यालय अत्यन्त जातिनिरपेक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए खोला गया। अन्य तान्त्रिक संस्थाएँ भी खोली गईं, जैसे बम्बई की टैक्सटाइल टैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, लुधियाना इंस्टीट्यूट भागलपुर सिल्क इंस्टीट्यूट और गुलजारीबाग कॉटन इण्डस्ट्रीज इंस्टीट्यूट। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जो किंचित प्रयास किये गये थे नगण्य थे।

(३) प्रशुल्क नीति—उद्योगों को प्राशुल्क सहायता देने के लिए सन् १९२१ में एक प्रशुल्क कमिशन की नियुक्ति भी की गई, जिसने विवेचनात्मक संरक्षण (J) discriminating Protection) देने की सिफारिश की।

(४) औद्योगिक अनुसन्धान—सन् १९३५ में इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो की स्थापना हुई थी, जिसकी अनुसन्धान शाखा अलीपुर में खोली गई। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित थे — औद्योगिक भूचलाओं का एकत्रीकरण और प्रसार, औद्योगिक अनुसन्धान में उद्योग के साथ सहकारिता एक पत्रिका में औद्योगिक सूचना का प्रकाशन और औद्योगिक प्रदर्शनियों के संगठन में सहायता। युद्ध-काल में अनुसन्धान करने के लिए बोर्ड आफ साइन्टिफिक एंड इण्डस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना भी की गई।

(५) स्टोर क्रेप नीति (Stores Purchase Policy)—औद्योगिक कमिशन की मिश्र शक्ति पर एक स्टोर क्रेप समिति नियुक्त की गई। कलकत्ता व बम्बई में स्थानीय क्रेप एजेन्सीज का निर्माण किया गया और बम्बई, मद्रास, कानपुर, कराँची तथा दिल्ली में इन्सपेक्टिङ्ग एजेन्सीज भी कार्यरत की गई।

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश काल के औद्योगिक विकास के लिए कभी भी कोई विस्तृत योजना नहीं बनाई गई। सन् १९१४-१८ के युद्ध की अपेक्षा सन् १९३९ के द्वितीय महासमर के आरम्भ होने में औद्योगिक उत्पादन की माँग बहुत बढ़ी। यह अनुभव किया गया कि युद्ध के सफलतापूर्वक चलान के लिए भारत को एक हथियारघर (Arsenal) के रूप में विकसित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्टर्न ग्रुप कान्फेन्स के लिए ग्रेडी मिशनस तथा अन्य समितियों की नियुक्ति भी की गई, किन्तु ये सब युद्ध के उपाय (War Measures) समझे जा सकते हैं, जिनका प्रधान उद्देश्य युद्ध के प्रयत्नों का समन्वय करना है। ब्रिटिश सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे युद्धकालीन विकास एक स्थायी आधार पर आ जाता।

द्वितीय युद्ध के उपरान्त भारत सरकार की औद्योगिक नीति—

युद्ध समाप्त होने (सन् १९४५) के दो-तीन वर्ष पहले से युद्धोपरान्त आर्थिक पुर्ननिर्माण योजनाओं की चर्चा हो रही थी। भारत सरकार ने सन् १९४३ के लगभग २९ औद्योगिक समितियाँ (Penals) नियुक्त की और एक योजना तथा विकास विभाग (Planning & Development Department) का भी निर्माण किया। (सन् १९४६ में यह विभाग समाप्त कर दिया गया और इसके कार्य डिपार्टमेंट आफ इण्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाय को ट्रान्सफर कर दिये गये)। अप्रैल सन् १९४५ में सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति घोषित की। नई नीति का उद्देश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक और आर्थिक साधनों का अधिकतम उपयोग करके राष्ट्रीय धन में वृद्धि, देश की सुरक्षा का अच्छा प्रबन्ध और रोजगार के ऊँचे स्थायी स्तर की स्थापना करना था। इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने स्वेच्छावाद की नीति को छोड़ कर उद्योगों के संरक्षण की नीति अपनाई। कुछ मूलभूत एवं स्थूल उद्योगों को विकसित करने तथा आर्डीनेन्स फैक्ट्रियों, जन उपयोगिताओं और रेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्त्व के आधार पर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त निम्न उपायों से भी उद्योगों की सहायता करने की धोपणा की —

- (१) महत्त्वपूर्ण औद्योगिक सस्याओं को ऋण दान अथवा पूँजी का अंश देना।
- (२) न्यूनतम लाभांश की गारन्टी देना।
- (३) अनुसन्धान सगठनों को आर्थिक सहायता देना।
- (४) भारतीय औद्योगिक उत्पादन को क्रय करना।
- (५) औद्योगिक विनियोग निगम आदि का प्रवर्तन करना।
- (६) सामाजिक न्याय और औद्योगिक विकास दोनों के समतुलित हित की दृष्टि से कर-नीति कार्यान्वित करना।

(७) औद्योगिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को विदेशों से मगाने की व्यवस्था करना ।

उद्योगों के केन्द्रीयकरण को रोकने तथा नियमित विकास करने के हेतु लाइसेंसिंग प्रथा जागी करने का निश्चय भी किया । साथ ही, ऐसे उपायों को व्यवहार में लाने का निश्चय भी किया, जिससे औद्योगिक श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊँचा हो, व्यक्तिगत पूँजीपतियों की जेबा में अत्यधिक लाभों का जाना सके, भारतीय माल में लोगों का विश्वास बढ़े, इन-गिन लोगों के हाथ में सम्पत्तियों का केन्द्रीयकरण न हो और औद्योगिक शिक्षा की प्रगति हो ।

अक्टूबर सन् १९४६ में एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड नियुक्त किया गया । इसने अपनी रिपोर्ट में दश के विभिन्न भागों में उद्योग-धन्यों के विवेन्द्रीयकरण का सुझाव दिया, ताकि सभी भागों का समुल्लिखित विकास हो सके । अगस्त सन् १९४७ में दश स्वतन्त्र हुआ और इसके शासन की वागडोर राष्ट्रीय सरकार के हाथ में आई । उद्योगों की घटती हुई उत्पादकता पर विचार करने के लिये इसने सन् १९४७ में एक उद्योग सम्मेलन किया, जिसने पब्लिक और प्राइवेट उपक्रमों की भूमिकाओं के स्पष्ट करने पर बल दिया तथा धर्म एवं पूँजी के बीच सम्भावना स्थापित करने का सुझाव दिया ।

STANDARD QUESTION

1. Write a full note on India's Industrial Policy Prior to Independence.

अध्याय १४

सन् १९४८ की औद्योगिक नीति

(Industrial Policy of 1948)

औद्योगिक नीति, १९४८ क सक्ष्य एव उसकी विधिपताये—

स्वर्गीय डा० रामाप्रसाद मुकुर्जी ने ६ अप्रैल सन् १९४८ को संसद में राष्ट्रीय सरकार की औद्योगिक नीति को पेश की। इस नीति में निम्न सामान्य लक्ष्य थे

(i) एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना जिसे 'याय व उन्नति के सुअवसर सबको बराबर बराबर प्राप्त हों' (ii) जीवन स्तर में तजी से वृद्धि करना और इसके लिये देश के सुप्त प्रसाधनों का शोषण करना (iii) उत्पादन में वृद्धि करना और (iv) सबको रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसकी निम्नलिखित विधिपताय है —

- (१) गहन एव बारूद का निर्माण एव शक्ति का उत्पादन एव नियंत्रण रेल मातायात के स्वामित्व एव प्रबंध पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण एकाधिकार होगा।
- (२) प्रांतीय या केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यक्तिगत साहस के साथ कार्य कर सकेंगी—कोयला लोहा एव इस्पात, जहाज निर्माण, हवाई जहाज निर्माण, मशीनरी एव वायुमलस एंजिन का निर्माण तथा पेट्रोल तेल। इस क्षेत्र के वर्तमान कारखाने १० बर तक अपना विकास करत रहेगे। परकार उनका सहायता करेगी लेकिन इस अवधि के बाद उनकी रियति का निरीक्षण किया जायगा। सरकारी उद्योगों का प्रबंध सार्वजनिक निगमा (Public Corporations) द्वारा किया जायगा।
- (३) विद्युत शक्ति का निर्माण एव वितरण पर सार्वजनिक नियंत्रण प्रबल रहेगा।
- (४) निम्नलिखित उद्योग सरकारी नियंत्रण एव नियंत्रण में रहेगे—चमक मोटर व ट्रैक्टर बिजली इन्जीन निर्माण मशीन औजार भारी रसायन तथा खाद फार्मोसी की औषधिया व दवाइया व बिजली रासायनिक उद्योग लोहा हीन धातु खड निर्माण शक्ति तथा औद्योगिक